

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

प्रिय मित्र

स्व० श्री रामकुमार गुप्त

की

पुण्य स्मृति

में

सादर समर्पित

प्रस्तुत संस्करण की भूमिका

नियोजित आर्थिक विकास के साथ-साथ भारतीय मौद्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। देश में एक ऐसी मुद्रा-नीति का निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी मद्दत हो सके। आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप कुछ नई मौद्रिक समस्याएँ देश में उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें सुलझाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा प्रसार का बढ़ता हुआ दबाव तथा विदेशी विनिमय संकट इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। भारतीय बैंकों को एक नये वातावरण में तथा अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों के लिये कार्य करना है। रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक के सम्मुख नये कर्तव्य एवं समस्याएँ हैं। आर्थिक विकास के लिये वित्त की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समस्याएँ स्थापित की जा रही हैं। इस बदलती हुई पृष्ठ-भूमि में मौद्रिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था का समुचित ज्ञान प्राप्त करके इन समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दें। इस दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करने के उद्देश्य में ही यह पुस्तक लिखी गई है।

पुस्तक का नया संस्करण निकलना इस बात का प्रमाण है कि पुस्तक विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है। साथी प्राध्यापकों द्वारा भेजे गये सुझावों का यथास्थान संशोधन एवं परिवर्द्धन के द्वारा नये संस्करण को और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ तक सम्भव हो सका है आधुनिकतम परिवर्तनों को इस संस्करण में सम्मिलित कर दिया गया है।

लेखक उन सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का आभारी हैं जिनके विचारों के आधार पर इस पुस्तक को लिखना सम्भव हो सका है। लेखक अपने स्वर्गीय मित्र श्री रामकुमार गुप्त का अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा, आवश्यक सुविधायें एवं बहुमूल्य परामर्श प्रदान किया। यह पुस्तक उनकी देन है और उन्हें सादर समर्पित है।

अर्थशास्त्र विभाग
एस. डी. कालिज
मुजफ्फरनगर।

लेखक
प्रार. एल. गोयल

मूमिका

आज के आर्थिक जीवन में मौद्रिक समस्याएँ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। किसी देश की आर्थिक प्रगति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि उस देश में मुद्रा व बैंकिंग सम्बन्धी किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों से अल्प-विकसित देशों में नियोजित आर्थिक विकास का युग आरम्भ हो जाने से मौद्रिक नीति की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। मुद्रा तथा बैंकिंग सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन काफी समय से किया जा रहा है किन्तु आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इन समस्याओं का अध्ययन करने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार का अध्ययन आज की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक प्रतीत होता है। इस पुस्तक में मौद्रिक समस्याओं को आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है।

आज अल्प-विकसित देशों के सामने मुद्रा, बैंकिंग तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी अनेक समस्याएँ उपस्थित हैं जिन्हें सुलझाने के लिये यह देश प्रयत्नशील हैं। मुद्रा को हम किस प्रकार आर्थिक विकास के अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यह अल्प-विकसित देशों की एक प्रमुख समस्या है। इन देशों में केन्द्रीय बैंक के क्या नये उत्तरदायित्व उत्पन्न हो गये हैं और उन्हें वे किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? आर्थिक विकास के महान् कार्य में संलग्न इन देशों में विदेशी व्यापार सम्बन्धी क्या नीति होनी चाहिये तथा यह देश किस प्रकार विदेशी विनिमय की स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक विकास कर सकते हैं? यह कुछ मौलिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर मौद्रिक अर्थशास्त्र के द्वारा दिया जाना है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिये मुद्रा, बैंकिंग तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्तों का आधार-भूत ज्ञान होना आवश्यक है। इन सिद्धान्तों को भली प्रकार समझे बिना उचित आर्थिक नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस पुस्तक में इन सिद्धान्तों का सरल तथा वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है। यदि यह पुस्तक अल्प-विकसित देशों की मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को विद्यार्थी-वर्ग के सम्मुख सरल भाषा में प्रस्तुत करने में कुछ भी सहायता करती है तो मैं अपने इस प्रयत्न को सफ़ल समझूंगा।

पुस्तक मुख्यतः भारतीय विश्वविद्यालयों की बी. ए. कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है और मुद्रा, बैंकिंग तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं समस्याओं को एक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती है। पुस्तक का उद्देश्य मौद्रिक अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को सरल तथा आम बोलचाल की भाषा में समझाना है। इस विषय पर अन्य पुस्तकें होते हुये भी इस पुस्तक को

प्रस्तुत करने का उद्देश्य मौद्रिक अर्थशास्त्र की नवीन प्रवृत्तियों को पाठकों तक पहुँचाना तथा उनमें वर्तमान मौद्रिक समस्याओं को समझने की क्षमता उत्पन्न करना है। यह पुस्तक इसी विषय की अन्य पुस्तकों से किस बात में भिन्न है अथवा इसकी क्या उपयोगिता है इसका निर्णय स्वयं पाठक करेंगे। पुस्तक में विभिन्न सिद्धान्तों के विश्लेषण के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक विचारों का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निधी गई पुस्तक के विषय में मौलिकता का दावा तो नहीं किया जा सकता किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह पुस्तक आर्थिक विकास से सम्बन्धित मौद्रिक समस्याओं को समझने में सहायता करेगी।

मैं उन सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का आभारी हूँ जिनके विचारों के आधार पर इस पुस्तक का लिखना सम्भव हो सका है। लेखक उन सब लोगों का आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक के लिखन में सहयोग दिया है। प्रकाशक मुत्पत धन्यवाद के पाल हैं क्योंकि उन्होंने इन कम समय में इस पुस्तक को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है।

अर्थशास्त्र विभाग
एस्. डी. कॉनिज
मुजफ्फरनगर

रतन लाल गोयल

विषय-सूची

मुद्रा का विकास ✓

Evolution of Money

वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, वस्तु मुद्रा, सिक्के ।

मुद्रा की परिभाषा तथा कार्य ✓

१७

Definition and Functions of Money

प्रकृति; परिभाषा; मुद्रा के कार्य; मुद्रा का महत्व, मुद्रा से उद्योक्ताओं को लाभ
मुद्रा के दोष; मुद्रा और आर्थिक विकास ।

मुद्रा का वर्गीकरण ✓

४६

Kinds of Money

वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, विधि ग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा, धातु-
मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के और उनकी ढलाई, मुद्रण प्रणालियाँ ।

मुद्रा मान ✓

७१

Monetary Standard

एक धातुमान, द्वि-धातुमान; मिश्रित धातुमान, ग्रेशम का नियम; एक धातुमान
में नियम, नियम की सीमाएँ ।

स्वर्ण मान

८२

Gold Standard

स्वर्णमान के कार्य, स्वर्णमान का इतिहास, स्वर्णमान के विभिन्न रूप; स्वर्ण
चलन मान के दोष, स्वर्ण धातुमान की विशेषताएँ, स्वर्ण धातुमान के लाभ,
स्वर्ण विनिमय मान, दोष, लाभ, स्वर्णमान के नियम, अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान ।

पत्र मुद्रा तथा पत्र मुद्रा मान

१३१

Paper Money and Paper Money Standard ✓

पत्र मुद्रा का विकास; लाभ, दोष, नोट निर्गम सिद्धान्त, बैंकिंग सिद्धान्त, नोट
निर्गम की विधियाँ; नोट निकासी का सही सिद्धान्त ।

मुद्रा का मूल्य और उसका निर्धारण ✓

१६६

Value of Money and its Determination

मुद्रा का मूल्य निर्धारण, मुद्रा की माग, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा का चलन वेग;
मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, परिमाण सिद्धान्त का समीकरण, परिमाण सिद्धान्त
का महत्व; सिद्धान्त का वर्तमान रूप, बचत और विनियोग सिद्धान्त ।

- ८ मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन १८७
 Inflation and Deflation
 मुद्रा प्रसार का अर्थ, मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूप, मुद्रा प्रसार के कारण; उत्पत्ति की मात्रा में कमी होना, सरकार व करदाना, मुद्रा-स्फीति, मुद्रा-अपस्फीति; मुद्रा प्रसार तथा आर्थिक विकास ।
- ९ निर्देशांक २२५
 Index Numbers
 निर्देशांक के प्रकार, आधार वर्ष का चुनाव, माघारण निर्देशांक की निर्माण विधि, संचार निर्देशांक, निर्देशांक के प्रयोग, निर्देशांक की सीमाएँ ।
- १० भारतीय मुद्रा का इतिहास २५५
 History of Indian Currency
 रजत मान, बँदिगटन स्मिथ कमिटी; हिस्टन यंग कमिशन, स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना, भारत में विदेशी विनिमय नियन्त्रण, माद्राज डालर कोष, भारत की स्टर्लिंग विधि ।
- ११ भारतीय मुद्रा का इतिहास २६०
 History of Indian Currency
 पौंड पावनों के जमा होने के कारण, पौंड पावनों का भुगतान, सन् १९४७, ४८, ४९ तथा ५२ के समझौते, युद्धोत्तर काल में भारतीय रुपया, रुपये का अवमूल्यन, अवमूल्यन के आर्थिक परिणाम; रुपये का पुनर्मूल्यन का प्रश्न; पुनर्मूल्यन के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क ।
- १२ भारतीय रुपये का अवमूल्यन २७५
 Devaluation of the Indian Rupee
 अवमूल्यन का अर्थ, रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न, पुनर्मूल्यन के विपक्ष में तर्क ।
- १३ भारतीय पत्र-मुद्रा प्रणाली २८६
 Indian Paper Currency System
 अनुपातिक कोष प्रणाली की स्थापना; भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली; नई प्रणाली के गुण, नई मुद्रा प्रणाली तथा आर्थिक विकास ।
- १४ भारत में मुद्रा प्रसार २८८
 Inflation in India
 युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण, मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय, युद्धोत्तर कालीन मुद्रा-स्फीति, सरकार की मुद्रा प्रसार विरोधी नीति, १९५२ के मुद्रा प्रसार विरोधी उपाय; वर्तमान मुद्रा-स्फीति ।

- १५ भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली ३१६
 Decimal Currency System in India
 भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता; भारत में दशमिक प्रणाली का इतिहास; भारत की नई सिक्का प्रणाली; दशमिक मुद्रा प्रणाली के लाभ व दोष ।
- १६ साख तथा साख पत्र ३२७
 Credit and Credit Instrument
 साख का अर्थ; साख का आधार, साख का वर्गीकरण; साख की माला की प्रभावित करने वाली बातें, साख की उपयोगिता तथा उसके कार्य, साख की हानियाँ, क्या साख पूँजी है ? साख का मूल्य; साख-पत्र ।
- १७ बैंकों के कार्य तथा व्यवस्था ३४७
 Functions and Organisation of Banks
 बैंकिंग का विकास, बैंक की परिभाषा, बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक, बैंकों के द्वारा साख का निर्माण; बैंक कितनी साख निर्माण कर सकता है; कर्तन का विरोध, साख निर्माण की सीमाएँ, बैंकों का आर्थिक महत्व, विभिन्न प्रकार के बैंक ।
- १८ बैंक की कार्य विधि ३७०
 The Banking Operations
 बैंक की पूँजी के साधन; धन का विनियोग; बैंक के विनियोग, नकद कोष की निर्धारित करने वाली बातें, लाभ पूर्ण विनियोग; बैंकों का चिट्ठा, बैंक के आदेय ।
- १९ केन्द्रीय बैंकिंग ४००
 Central Banking
 केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता; केन्द्रीय बैंक की परिभाषा, केन्द्रीय बैंक की विशेषताएँ, केन्द्रीय बैंक के कार्य; केन्द्रीय बैंक और साख नियन्त्रण; साख नियन्त्रण की विधियाँ ।
- २० भारतीय मुद्रा बाजार ४३७
 Indian Money Market
 आर्थिक विकास में मुद्रा बाजार का महत्व; भारतीय मुद्रा बाजार के अंग; भारतीय मुद्रा बाजार के दोष तथा दूर करने के उपाय; भारत में बिल बाजार के विकास के लिये सुझाव ।
- २१ भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ४५५
 Indian Banking System
 बैंकों के टूटने के कारण; द्वितीय महायुद्ध का बैंकिंग पर प्रभाव, युद्धोत्तर काल में भारतीय बैंकिंग; भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंक; व्यापारिक बैंकों के कार्य ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

४८६

Reserve Bank of India ✓

स्थापना की आवश्यकता, रिजर्व बैंक का विधान, प्रबन्ध, भारत में आधुनिक बैंकिंग का विधान, बैंकिंग के टूटने के कारण, द्वितीय महायुद्ध का बैंकिंग पर प्रभाव, युद्धोत्तर काल में भारतीय बैंकिंग, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति, व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने के उपाय, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण के विषय में तर्क ।

२३ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

५१६

State Bank of India

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न, स्थापना का कारण, स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, स्टेट बैंक की प्रगति ।

२४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

५३०

International Trade

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार का भेद, आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागती का अन्तर, तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्राचीन रूप—प्राचीन सिद्धान्त के दोष, तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का वर्तमान रूप—सीमान्त उत्पादन लागतों के आधार पर व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हानियाँ—निष्कर्ष ।

२५ भुगतान संतुलन

५५५

Balance of Payments

व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन का एक विवरण, अनुकूल तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन का अर्थ आयातों तथा निर्यातों में समान होने की प्रवृत्ति, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने की आवश्यकता; निर्यात प्रोत्साहन, आयातों पर प्रतिदण्ड, जवमूत्पन, मुद्रा संकुचन, विदेशी विनिमय नियन्त्रण ।

२६ मुक्त व्यापार एवं संरक्षण

५६६

Free Trade and Protection

मुक्त व्यापार तथा संरक्षण का अर्थ, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क, संरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, संरक्षण देने की रीतियाँ, भारतीय तट कर नीति—१९२१ के वित्त आयोग की सिफारिशें—विवेचनात्मक संरक्षण के प्रभाव एवं आलोचनाएँ, युद्ध काल में तट कर नीति, १९५० का वित्त आयोग तथा उसकी सिफारिशें, तट कर आयोग १९५१ ।

२७ भारत का विदेशी व्यापार

५८३

The Foreign Trade of India

भारतीय विदेशी व्यापार का द्वितीय युद्ध तक का संक्षिप्त इतिहास; द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रभाव; युद्धोत्तर काल में विदेशी

व्यापार का विभाजन का प्रभाव—अवमूल्यन के प्रभाव, भारत की मुख्य निर्यात तथा आयात; व्यापार की दिशाएँ—भारत का व्यापार सतुलन—युद्धोत्तरकालीन स्थिति—विभाजन के पश्चात् व्यापार सतुलन में विपक्षता—पञ्चवर्षीय योजनाएँ तथा व्यापार सतुलन—प्रतिकूल व्यापार सतुलन को ठीक करने के उपाय ।

खण्ड — २

विदेशी विनिमय

१

Foreign Exchange

विदेशी विनिमय का अर्थ, विदेशी विनिमय की समस्याएँ, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की रीतियाँ, विदेशी विनिमय बिल, विनिमय बिल के कार्य, बैंकर्स ड्राफ्ट, विदेशी विनिमय दर, स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दर स्वर्ण धिन्दु, पल-मुद्रा मान में विनिमय दर, वृद्ध शक्ति समता सिद्धांत, सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व, विदेशी विनिमय का भुगतान सतुलन सिद्धान्त, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन, विनिमय दर में परिवर्तनों की सीमाएँ ।

विनिमय नियन्त्रण

३०

Exchange Control

विनिमय नियन्त्रण का विकास, अर्थ, उद्देश्य व रीतियाँ, भारत में विनिमय नियन्त्रण ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

४५

International Monetary Fund

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, मुद्रा कोष की पूँजी, स्वर्ण समता दरों का निर्धारण, मुद्रा कोष के साधनों का प्रयोग, दुर्लभ मुद्रायें, मुद्रा कोष का प्रबन्ध, मुद्रा कोष में सोने का स्थान, क्या मुद्रा कोष एक स्वर्णमान योजना, मुद्रा कोष की सफलताएँ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आलोचनाएँ, भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष — मुद्रा कोष से प्राप्त सहायता, मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को लाभ ।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

६२

International Bank for Reconstruction and Development

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य, विश्व बैंक की पूँजी, बैंक की कार्य विधि, ऋण देने की विधि, तकनीकी सहायता, बैंक का प्रबन्ध तथा व्यवस्था, बैंक की सफलताएँ, बैंक की आलोचनाएँ, भारत और विश्व बैंक — यातायात के विकास के लिये, औद्योगिक विकास के लिये, वन्दरगाहों के विकास के लिये, अन्य ऋण, भारत सहायता बल, टेक्नीकल सहायता, आलोचनाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय

वित्त निगम, मदस्यता तथा व्यवस्था, उद्देश्य-कार्य वाहन, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ—उद्देश्य, ऋण सम्बन्धी नीति, कार्य-वाहन, भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ ।

५ राष्ट्रीय आय

८५

National Income

राष्ट्रीय आय का अर्थ, मार्शल के विचार, पीगू का दृष्टिकोण, फिशर का दृष्टिकोण, कॉसिन क्लार्क का मत, राष्ट्रीय आय को मापने की रीतियाँ, राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व, भारत की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समिति, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय आय और आर्थिक नियोजन, भारत की राष्ट्रीय आय की अन्य देशों में तुलना ।

६ वचत विनियोग और पूर्ण रोजगार

१०२

Savings, Investment & Full Employment

कीन्स का रोजगार-सिद्धान्त, वचत, विनियोग, पूर्ण रोजगार का विचार, राज्य और पूर्ण-रोजगार, पूर्ण रोजगार की नीति, केन्ज की ऋणात्मक व्यय नीति के दोष, भारत में पूर्ण रोजगार ।

राजस्व की विषय सूची पृष्ठ ३ के आरम्भ में देखें



मुद्रा का विकास

EVOLUTION OF MONEY

प्रत्येक विकसित समाज की अर्थ-व्यवस्था अनिवार्य रूप से मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था होती है। समाज पूँजीवादी हो या समाजवादी, नियोजित हो अथवा अनियोजित, प्रत्येक दशा में अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुद्रा का होना अनिवार्य है। यद्यपि पूँजीवादी समाज में मुद्रा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किन्तु समाजवादी अर्थ-व्यवस्था भी मुद्रा के बिना ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है। वास्तव में मुद्रा आज के आर्थिक जीवन का केन्द्र बन गई है। बड़े पैमाने का उत्पादन, श्रम विभाजन, बाजारों का विकास, बैंक तथा आर्थिक नियोजन, यह सब कुछ मुद्रा के कारण ही सम्भव हो सका है। यदि हमारे जीवन से मुद्रा को अकस्मात् हटा दिया जाये तो हमारी आर्थिक क्रियाएँ रुक जायेंगी और सम्पूर्ण आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा। मुद्रा को मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कहा जा सकता है। मुद्रा के प्रयोग के द्वारा ही व्यापार तथा विनिमय को सुविधापूर्ण बनाया जा सका है तथा आधुनिक ढंग से उत्पादन करना सम्भव हो सका है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि आज का आर्थिक संगठन व्यवसायिक वर्गीकरण, श्रम विभाजन पर आधारित वर्तमान उत्पादन व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास केवल मुद्रा की देन है किन्तु मुद्रा के आविष्कार ने इस प्रकार के विकास को सम्भव बनाने में काफी योगदान दिया है।

मुद्रा ने विकास की दशाये उत्पन्न करके मानव समाज को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। यदि मुद्रा का आविष्कार न हुआ होता तो आज भी मानव समाज काफी पिछड़ी हुई दशा में रहता। आज हम आर्थिक विकास की ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं कि हमारे लिए मुद्रा-रहित समाज की कल्पना करना भी सम्भव नहीं है किन्तु एक समय ऐसा भी था जब मुद्रा नहीं थी और वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। मानव समाज की प्रगति के साथ-साथ इस प्रकार की वस्तु-विनिमय प्रणाली को छोड़कर मुद्रा-विनिमय प्रणाली

को अपना लिया गया। प्रत्यक्ष विनिमय में होने वाली विभिन्न भ्रमुविधाओं के कारण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के विकास का यह इतिहास हमें उसकी प्रवृत्ति तथा आर्थिक जीवन में उसके महत्व को समझने में काफी सहायता कर सकता है। मुद्रा क्या है? इसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम उन दशाओं का अध्ययन करना होगा, जिनके कारण मुद्रा का आविष्कार किया गया।

विनिमय का आरम्भ—

मानव समाज की आर्थिक प्रगति विनिमय प्रणाली के विकास के साथ ही आरम्भ होती है। विनिमय व्यवस्था के पूर्व आर्थिक जीवन बहुत ही सरल तथा पिछड़ी हुई दशा में था। मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी सीमित थी कि वह स्वयं ही उन्हें पूरा कर लेता था। इसे आरम-निर्भरता का युग कहा जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वयं साधन जुटाने पड़ते थे। इस प्रकार का सरल आर्थिक जीवन अधिक समय न चल सका। मानव समाज के विकसित होने के साथ-साथ आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगी और वे पहले की अपेक्षा अधिक जटिल होनी गईं। अब मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता था और उन्हें एक दूसरे के सहयोग के द्वारा पूरा किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने इसे परस्पर निर्भरता का युग कहा है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का आपस में विनिमय किया जाने लगा और इस प्रकार आरम-निर्भरता के युग ने परस्पर निर्भरता के युग को स्थान दिया। विनिमय के विकास के साथ-साथ मानव समाज प्रगति के एक नये पथ पर अग्रसर हुआ। व्यावसायिक विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन तथा बाजारों का विकास होने लगा जिसके कारण उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। जैसे-जैसे समाज प्रगति करता गया वैसे-वैसे विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत होता गया और आर्थिक जीवन में विनिमय ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आज का समाज पूर्णतया विनिमय पर आधारित है और उसे आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है।

विनिमय दो प्रकार का होता है—(अ) प्रत्यक्ष विनिमय (Direct Exchange) या वस्तु-विनिमय (Barter) तथा (ब) परोक्ष विनिमय (Indirect Exchange) या मुद्रा-विनिमय (Money Exchange)। मुद्रा के विकास के पूर्व विनिमय का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, किन्तु इस प्रकार के विनिमय में अनेक कठिनाइयाँ होने लगी और विनिमय मुद्रा के माध्यम के द्वारा किया जाने लगा। कोई भी आधुनिक समाज वस्तु-विनिमय के द्वारा अपनी अर्थ-व्यवस्था का नहीं चला सकता है। कुछ एक पिछड़े हुए वर्गों को छोड़कर आज की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्थाएँ मुद्रा-विनिमय पर आधारित हैं।

(अ) वस्तु-विनिमय

(Barter)

मानव समाज में विनिमय का प्रारम्भ सर्वप्रथम वस्तु-विनिमय के रूप में हुआ। क्राउथर (Crowther) के अनुसार, "एक व्यावसायिक प्राणी के रूप में, मनुष्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था में जो भी कुछ व्यापार करता था वह वस्तु-विनिमय के रूप में था।"¹ वस्तु-विनिमय का युग साधारण विनिमय का युग था। उस समय मानव आवश्यकताएँ कम थीं और विनिमय का क्षेत्र इतना सीमित था कि वस्तुओं की सीधी बदल-बदल के द्वारा ही लोग अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे। आज के विस्तृत समाज में वार्टर प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है किन्तु कुछ पिछड़े हुए भागों में अभी भी इस प्रणाली के आधार पर विनिमय किया जाता है। वस्तु-विनिमय के अन्तर्गत विनिमय का माध्यम न होने के कारण, वस्तुओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से होता है। टॉमस के अनुसार, "एक वस्तु के, दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदले जाने को ही वस्तु-विनिमय कहा जाता है।"² जेवन्स (Jevons) के शब्दों में, "तुलनात्मक रूप से कम आवश्यक वस्तु के साथ अधिक आवश्यक वस्तु के बदलने को वस्तु-विनिमय कहते हैं।"³ वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को पहले किसी मध्यवर्ती वस्तु के साथ नहीं बदला जाता है वरन् उसे सीधा उसी वस्तु अथवा सेवा के साथ बदल लिया जाता है, जिसकी आवश्यकता होती है। एक किसान अपने अतिरिक्त गेहूँ को देकर उसके बदले में अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा तथा अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर लेता था और बर्द अपने द्वारा बनाये गये औजारों को कपड़े तथा गेहूँ के साथ बदल लेता था। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं को आपस में बदलकर विभिन्न मानव आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था।

✓ वस्तु-विनिमय की सफलता की दशाये—

वस्तु-विनिमय प्रणाली केवल कुछ दशाओं में ही सफल हो सकती है। प्रत्यक्ष विनिमय की सफलता के लिए मानव आवश्यकताओं का साधारण तथा सीमित होना अनिवार्य है। विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत नहीं होना चाहिए और वह केवल एक गाँव अथवा आस-पास के कुछ गाँव तक ही सीमित रहना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था केवल समाज की प्रारम्भिक दशाओं में ही सम्भव हो सकती है इसीलिए

1 "In the earliest stages of Man as a commercial animal, his trading consisted entirely of barter."
—Geoffrey Crowther.

2 "..... direct exchange of one commodity for another is termed barter."
—S. E. Thomas.

3 "Exchange is the barter of the comparatively superfluous with the comparatively necessary."
—Jevons.

प्राचीन सामाजिक व्यवस्था वस्तु-विनिमय पर आधारित थी। समाज के पिछड़े होने के कारण मनुष्य का रहन-सहन सादा था और उसकी आवश्यकतायें इतनी कम थी कि उन्हे वस्तु-विनिमय के द्वारा पूरा किया जा सकता था। सम्भ्रता के विकास के साथ-साथ मानव आवश्यकतायें बढ़ने लगी और वे पहले की अपेक्षा अधिक जटिल होती गई। बाजारों का विस्तार होने के कारण विनिमय का क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता गया और वस्तु-विनिमय के लिए उपयुक्त वातावरण समाप्त हो गया। ऐसी दशाओं में वस्तु-विनिमय नहीं चल सकता था और विनिमय का कार्य ठीक प्रकार चलाने के लिए मध्यवर्ती वस्तु की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। धीरे-धीरे समाज मुद्रा पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा।

आज भी समाज के अल्प-विकसित भागों में तथा पिछड़ी हुई जातियों में वस्तु-विनिमय देखने को मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर अभी तक वस्तु-विनिमय के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित है। भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी कुछ किसान घनाज के बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुयें तथा सेवार्य प्राप्त करते हैं किन्तु अब धीरे-धीरे यह प्रणाली लुप्त होती जा रही है और उसके स्थान पर मुद्रा के द्वारा विनिमय को अधिक सुविधापूर्ण समझा जाने लगा है। प्रगतिशील समाज का वस्तु-विनिमय को त्याग कर मुद्रा को अपनाकर एक स्वाभाविक घटना थी। वस्तु-विनिमय प्रणाली दोषयुक्त होने के कारण प्रगतिशील समाज की विनिमय की आवश्यकताओं को पूरा न कर सकी और उसके स्थान पर अधिक कुशल तथा सुविधापूर्ण मुद्रा प्रणाली को अपना लिया गया। आज हम आर्थिक विकास की एक ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं कि हमारा आर्थिक जीवन पूर्णतया मुद्रा पर आधारित हो गया है और वह हमारी आर्थिक क्रियाओं का मुख्य केन्द्र बनती जा रही है।

वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ—

वस्तु-विनिमय के लिए उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय अनुविधापूर्ण हो गया और उसमें विशेष कठिनाइयाँ अनुभव की जाने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ और धीरे-धीरे मुद्रा प्रणाली ने वस्तु-विनिमय का स्थान ले लिया। वस्तु-विनिमय की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित थी—

(१) आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincidence of Wants)—वस्तु-विनिमय की सफलता के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष विनिमय केवल दो ऐसे व्यक्तियों में ही हो सकता है जिनके पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुयें हों और जो उनका आपस में विनिमय करने के लिए तैयार हों। वस्तुओं की सीधी बदल-बदल करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है जिसके

पाम वह वस्तु फालतू हो जिसकी पहले को आवश्यकता है और जो उस वस्तु को लेने के लिए तैयार हो जो पहले व्यक्ति के पाम फालतू है। यदि दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताओं में इस प्रकार का दोहरा संयोग नहीं है तो वस्तु-विनिमय नहीं हो सकेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई किसान अपने गेहूँ को बदल कर कपड़ा प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरा ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो कपड़ा देकर गेहूँ लेना चाहता हो। यदि उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है और जो व्यक्ति उसे मिलता है वह कपड़ा तो देता चाहता है, किन्तु उसे गेहूँ की आवश्यकता नहीं है और वह कपड़े के बदले लकड़ी के अजार प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वस्तु-विनिमय तब तक नहीं हो सकेगा जब तक उन्हें कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा न मिल जायें जो गेहूँ के बदले में अजार देने को तैयार हो।

आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को प्राप्त करने में लोगों को बड़ी श्रमविधा होनी थी और कभी-कभी उनके अभाव के कारण वस्तु-विनिमय नहीं हो पाता था। जब तक विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कम थी और विनिमय का क्षेत्र सीमित था उस समय तक पारस्परिक जान के द्वारा आवश्यकताओं में दोहरे संयोग को स्थापित करना सम्भव था। आर्थिक विकास के साथ मानव आवश्यकतायें बढ़ने लगी और विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया जिसके कारण आवश्यकताओं में दोहरे संयोग को स्थापित करना काफी कठिन होता गया। आज के विकसित समाज में तो विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में इस प्रकार के संयोग का मिलना असम्भव है। जार्ज हार्म ने इसी कठिनाई के सम्बन्ध में लिखा है—“वस्तु-विनिमय करने वाले व्यक्तियों की समस्त इच्छाओं का वस्तुओं की श्रेणी, गुण, मात्रा एवं मूल्य के सम्बन्ध में संयोग बैठना लगभग असम्भव है, विशेषतया आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में जहाँ एक ही दिन में लाखों व्यक्ति लाखों प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करते हैं।”² आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई के कारण विनिमय के माध्यम की खोज आरम्भ हुई और मुद्रा के आविष्कार के साथ वस्तु-विनिमय का स्थान मुद्रा-विनिमय ने ले लिया।

(२) मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव (Lack of Common Measure of Value)—वस्तु-विनिमय की दूसरी कठिनाई मूल्य के माप के अभाव के कारण पैदा होती है। वस्तु-विनिमय प्रणाली में कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापा जा सके। मूल्य का सर्वमान्य माप न होने के कारण प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रत्येक दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से

2 "It is next to impossible that all wishes of bartering individuals should coincide as to the kind, quality, quantity and value of things which are mutually desired, especially in a modern economy in which on a single day millions of persons may exchange millions of commodities and services."

निर्धारित करना होता है। प्रत्यक्ष विनिमय के लिए यह जानना अनिवार्य है कि एक वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाय। गेहूँ और कपड़े का विनिमय तभी सम्भव हो सकता है जब हमें यह मासूम हो कि गेहूँ की एक निश्चित मात्रा कपड़े की कितनी मात्रा के बराबर है। वही बार इस प्रकार के विनिमय अनुपातों को निश्चित करने में बड़ी कठिनाई होती थी। यह कठिनाई उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक होती थी जिनका बर्तन-कभी विनिमय किया जाता था। यदि किसी प्रकार विनिमय दरो को निश्चित भी कर लिया जाता था तो एक अन्य समस्या यह पैदा होती थी कि इतनी अधिक विनिमय दरो को किस प्रकार याद रखा जाय। प्रत्येक विनिमय करने वाले व्यक्ति को अपनी वस्तु के विनिमय अनुपात उन सब वस्तुओं के सम्बन्ध में याद रखने होते थे जिनके साथ उसे बदला जा सकता था। आरम्भ काल में विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या इतनी कम थी कि उनकी विनिमय दरो को याद रखना सम्भव था किन्तु समय के विकास के साथ-साथ विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या निरन्तर बढ़ती गई और उनमें सम्बन्धित असंख्य विनिमय दरो को याद रखना असम्भव हो गया। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसी ऐसी सामान्य वस्तु को खोज आरम्भ हुई जिसके द्वारा अन्य सब वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को नापा जा सके।

(३) विभाजन की कठिनाई (Difficulty of Sub division)—वस्तु-विनिमय में एक अन्य कठिनाई वस्तुओं का विभाजन न हो सकने के कारण पैदा होती है। ऐसी वस्तुओं का विनिमय करना अत्यन्त कठिन होता है जिनका विभाजन मूल्य को नष्ट किए बिना नहीं किया जा सकता। मूल्य विभाजन का कोई साधन न होने के कारण अधिक मूल्यवान् वस्तुओं को कम मूल्य वाली वस्तुओं के साथ बदलने में विशेष कठिनाई होती है। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके टुकड़े करने पर उसका मूल्य नष्ट हो जाता है अथवा बहुत कम रह जाता है तो ऐसी वस्तु को कम मूल्य वाली वस्तु के साथ बदलना सम्भव नहीं होता है। यदि किसी किसान के पास एक बैल है और वह उसके बदले में कुछ कपड़ा, चीज, औजार तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में विनिमय करना एक समस्या बन जाती है। ऐसे व्यक्ति का मिलना सम्भव नहीं होता है जिसे बैल की आवश्यकता हो और जिसके पास वे सब वस्तुएँ हों जिनको किसान लेना चाहता है। किसान अपने बैल का विभाजन करके उसके बदले में अलग-अलग लोगों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने में उसके बैल का मूल्य नष्ट हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में विनिमय नहीं हो सकेगा। मुद्रा के प्रयोग से द्वारा ही इस प्रकार की कठिनाई को दूर किया जा सकता है।

(४) मूल्य संचय के साधन का अभाव (Lack of Store of Value)—वस्तु-विनिमय प्रणाली के समय में मूल्य संचय का कोई साधन न होने के कारण

भविष्य के लिए धन को इकट्ठा करना सम्भव न था। वस्तुओं के रूप में क्रय शक्ति को संचय करने में बहुत कठिनाई होती थी क्योंकि वस्तुएँ शीघ्र नष्ट हो जाने वाली होती थी तथा उसके मूल्य में सामयिक परिवर्तन होते रहते थे। ऐसी दशा में समाज में जो कुछ भी पैदा किया जाता था उसे वर्तमान प्रयोग में ही ले लिया जाता था और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना सम्भव न था। समाज में बचत न होने के कारण पूँजी संचय तथा विनियोग नहीं हो सक्ता था। यही कारण था कि वस्तु-विनिमय के युग में देश इतने प्रगतिशील न थे जितने कि आजकल हैं। मुद्रा के आविष्कार से ही समाज में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हुआ।

(५) स्थगित भुगतानों में कठिनाई (Difficulty in deferred payments)—वस्तु-विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतानों (Deferred payments) को व्यक्त करने तथा निबटाने का कोई उचित साधन नहीं होता था जिसके कारण ऋणों का लेन-देन अथवा दीर्घकालीन सौदों को करने में काफी कठिनाई होती थी। मुद्रा की अनुपस्थिति में इस प्रकार के भुगतानों को वस्तुओं के रूप में ही निश्चित करना होता था किन्तु ऐसी वस्तुएँ बहुत कम थी जिनके रूप में ऋणी तथा ऋण-दाता लेन-देन कर सकें। वस्तुओं में गुण-भेद होने के कारण उन्हें दीर्घकालीन भुगतानों को व्यक्त करने तथा निबटाने के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, उनमें सामान्य स्वीकृति का अभाव तथा टिकाऊपन की कमी के कारण स्थगित भुगतानों को वस्तुओं के रूप में निबटाने में काफी कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में लेन-देन तथा स्थगित भुगतानों के आधार पर किये जाने वाले सौदे केवल सीमित मात्रा में ही हो सकते थे।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण वस्तु-विनिमय प्रणाली अधिक समय तक न चल सकी और उसका स्थान मुद्रा-विनिमय ने ले लिया। वस्तु-विनिमय की असुविधाओं से तग आकर मनुष्य ने ऐसी सर्वमान्य वस्तु की खोज आरम्भ की जो विनिमय के माध्यम का कार्य कर सके तथा जिनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को सरलता से नापा जा सके। अत्यन्त प्राचीन काल से ही समाज में किसी ऐसी मध्यवर्ती वस्तु को निश्चित कर लिया गया होगा जिसे वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में हर समय स्वीकार किया जा सके और जो मूल्य के मापक का कार्य भी कर सके। ऐसी मध्यवर्ती वस्तु का विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना ही मुद्रा प्रणाली का आरम्भ था।

वर्तमान समाज में वस्तु-विनिमय—

आज का युग मुद्रा का युग है और मुद्रा ही हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं की मुख्य संचालक है। फिर भी हम वस्तु-विनिमय से बहुत अधिक दूर नहीं हैं। वर्तमान समाज में भी हमें कभी-कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

वस्तु-विनिमय का महारा लेना पड़ता है। आज केवल असम्य तथा पिछड़ी हुई जातियाँ ही वस्तु-विनिमय पर निर्भर नहीं हैं अपितु कभी-कभी प्रगतिशील देश भी आपस में वस्तु-विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुयें प्राप्त करते हैं। हमारे देश का अपने द्वारा पैदा किया हुआ जूट देकर दूसरे देश से गेहूँ प्राप्त करना अथवा कच्चे लोहे के बदले में मशीनें प्राप्त करना वस्तु-विनिमय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार अन्य देशों के बीच होने वाले व्यापार में भी वस्तु-विनिमय का सीमित प्रयोग किया जाता है। वस्तु-विनिमय प्रणाली के इस प्रकार जीवित रहने का मुख्य कारण इस प्रणाली की सरलता है। समाज में जब भी इस प्रणाली को कार्य रूप में लाने के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है तब ही लोग प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करना प्रारम्भ कर देते हैं और इस प्रकार वे मुद्रा प्रणाली से उत्पन्न होने वाले दोषों से बचने का प्रयत्न करते हैं।

आधुनिक समाज में वस्तु विनिमय को अपनाने के दो मुख्य कारण रहे हैं—

(१) मुद्रा के मूल्य में अधिक परिवर्तन होना तथा (२) विदेशी मुद्रा की दुर्लभता। यदि किसी मुद्रा का मूल्य बड़ी तेजी के साथ गिरने लगता है तो लोगों का विश्वास उस मुद्रा के प्रति कम हो जाता है और ऐसी दशा में लोग वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय करने लगते हैं। कीमतों के बहुत अधिक बढ़ जाने पर मजदूर वस्तुओं के रूप में मजदूरी लेना पसन्द करते हैं, पिछले विश्व-युद्ध काल में जर्मनी की मुद्रा मार्क (Mark) का मूल्य अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण इतनी तेजी से गिर रहा था कि लोग मुद्रा के बदले में अपनी वस्तुयें बेचना नहीं चाहते थे और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष विनिमय पसन्द किया जाता था। प्रमरीका में १९३२-३३ में आर्थिक मन्दी के बुरे प्रभाव के कारण छोटे-छोटे वस्तु-विनिमय समाज बन गये थे। विदेशी विनिमय की कमी के कारण भी वर्तमान समाज में वस्तु-विनिमय का प्रयोग बढ़ रहा है और बहुत से देशों के द्वारा आपस में वस्तुओं को बदलने के सम्बन्ध में समझौते किये गये हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते (Bilateral Trade Agreements) किये जाते हैं वे वस्तु-विनिमय का एक संशोधित रूप है।

इन सब प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट होता है कि जब भी मानव समाज में मुद्रा की कमी होती है अथवा उसका मूल्य तेजी के साथ बदलता है तो वस्तु-विनिमय के आधार पर विनिमय किया जाने लगता है। मुद्रा प्रणाली में कुछ ऐसे दोषों का पैदा हो जाना स्वाभाविक है जो वस्तु-विनिमय काल में नहीं थे। यदि आज के सामाजिक जीवन से मुद्रा को हटा दिया जाय तो वर्तमान समाज की बहुत सी आर्थिक समस्याएँ स्वयं सुलभ जायेंगी। किन्तु क्या ऐसा करना सम्भव है? आज का समाज मुद्रा के बिना नहीं चल सकता है। मुद्रा एक ऐसा यन्त्र है जिसकी अनुपस्थिति में वर्तमान समाज की आर्थिक मशीन का चलना असम्भव प्रतीत होता।

है। अतः यह कहना कि वर्तमान समाज धीरे-धीरे वस्तु विनिमय का ओर बढ़ रहा है, अधिक उचित नहीं है। मुद्रा प्रणाली दोषयुक्त होते हुए भी हमारे आर्थिक जीवन का आधार बन चुकी है। इस प्रणाली में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिनके कारण उसने वस्तु विनिमय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। प्रत्यक्ष विनिमय के द्वारा आज का समाज अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा अथवा समाज से मुद्रा को हटाना संभव होगा, यह सन्देहपूर्ण है।

(ब) मुद्रा-विनिमय (Money Exchange)

मुद्रा-विनिमय के अन्तर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समाज में विनिमय का कार्य इसी प्रणाली के आधार पर होता है। मुद्रा के प्रयोग ने विनिमय के तरीके को विल्कुल बदल दिया है। मुद्रा-विनिमय प्रणाली में विनिमय प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से किया जाता है। वस्तु-विनिमय के युग में कोई माध्यमिक वस्तु नहीं होती थी। किन्तु मुद्रा प्रणाली में वस्तुओं को पहले मुद्रा के साथ बदला जाता है और फिर मुद्रा को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ बदलने हैं। इस प्रकार मुद्रा मध्यवर्ती वस्तु का कार्य करती है और विभिन्न वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। विनिमय का कार्य दो भागों में बँट जाता है—(अ) वस्तुओं को बेचना तथा (ब) वस्तुओं को खरीदना। पहले वस्तुओं को मुद्रा के साथ बदला जाता है और फिर मुद्रा को अन्य वस्तुओं के साथ बदल लिया जाता है। यदि समाज में गेहूँ और कपड़े का विनिमय किया जाता है तो पहले गेहूँ के उत्पादक उसे बेचकर रुपया प्राप्त कर लेते हैं और फिर उस रुपये के बदले में बाजार से कपड़ा खरीद लेते हैं। अतः वस्तुओं का विनिमय प्रत्यक्ष न होकर मुद्रा के माध्यम के द्वारा परोक्ष रूप से होता है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग होने से वस्तु विनिमय की सब कठिनाईयाँ दूर हो गई हैं और आर्थिक विकास के एक नये युग का आरम्भ हुआ है। मुद्रा में ऐसे गुण पाये जाते हैं जिनके कारण वह विनिमय का उपयुक्त माध्यम बन सकी है। सर्वमान्यता के गुण के कारण सभी लोग मुद्रा को अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य आसानी से मुद्रा के द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं। अधिक टिकाऊ होने के कारण मुद्रा के माध्यम से धन का संचय भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा का विभजन बिना मूल्य ह्रास के करना सम्भव है। इन्हीं सब कारणों से मुद्रा-विनिमय व्यवस्था (Money Economy) को वस्तु विनिमय-व्यवस्था (Barter Economy) से अच्छा समझा जाता है। आज के प्रगतिशील समाज में इसी प्रकार का विनिमय प्रचलित है और यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-विनिमय ने वस्तु विनिमय का स्थान काफी सीमा तक ले लिया है।

‘मुद्रा का प्रारम्भ—

मुद्रा का इतिहास बहुत कुछ काल्पनिक है और उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि मुद्रा का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ। केन्स (Keynes) ने ठीक ही कहा है—‘मुद्रा सबसे कही अधिक प्राचीन सस्था है जितना कि हमें बताया जाता रहा है। इसका उद्गम अतीत के कोहरे में लुप्त हो गया है।’³ फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में ही मानव समाज में मुद्रा का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता रहा है। सम्पत्ता के विकास की प्रारम्भिक दशाओं में मनुष्य ने प्रत्यक्ष विनिमय की कठिनाइयों से तंग आकर किसी ऐसी सामान्य वस्तु की खोज प्रारम्भ कर दी होगी जो विनिमय के माध्यम का कार्य कर सके और जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं के मूल्य को नापा जा सके। विनिमय का विस्तार होने के कारण वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ बढ़ती गईं और विनिमय के माध्यम की खोज प्रारम्भ हो गई। विभिन्न जातियों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से विनिमय के माध्यम का कार्य लेना प्रारम्भ कर दिया। मुद्रा का विकास सप्ताह के सब जातियों द्वारा मिलकर किसी निश्चित काल में नहीं किया गया। विभिन्न देशों में अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मुद्रा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और इसीलिए प्रारम्भ काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जा चुका है।

मुद्रा के विकास के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मुद्रा का विकास अपने आप ही हो गया और किसी ने भी उसकी खोज नहीं की। यह लोग मुद्रा के आकस्मिक विकास के सिद्धान्त (Theory of Spontaneous Growth) में विश्वास रखते हैं। स्पैलडिंग (Spalding) और उसके साथी इसी सिद्धान्त के मानने वाले हैं। इन लोगों के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रा का विकास अपने आप हो गया और उसके लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ा। विनिमय का विस्तार होने के साथ-साथ किसी न किसी वस्तु को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार मुद्रा का अभ्युदय सर्वप्रथम विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ। धीरे-धीरे यही विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक तथा लेखे की इकाई के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मुद्रा का उदय अपने आप ही हो गया और उसके लिए मनुष्य को किसी प्रकार की खोज नहीं करनी पड़ी है।

3 ‘Money, like certain other essential elements in civilization, is far more ancient institution than we were taught to believe some few years ago. Its origins are lost in the mists’

इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के मानने वालों के अनुसार मुद्रा का आविष्कार विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। वस्तु-विनिमय के युग में सबसे बड़ी कठिनाई वस्तुओं के मूल्य को नापने में होती थी। इसलिए सर्वप्रथम मूल्य के मापक की खोज आरम्भ हुई और मुद्रा का प्रयोग मूल्य नापने की इकाई के रूप में किया जाने लगा। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग बाद में किया गया। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा स्वयं पैदा नहीं हुई बल्कि वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों से तग आकर मनुष्य ने अपनी विवेकशीलता से मुद्रा की खोज की। हेन्सन (Hanson) के अनुसार 'मुद्रा का उद्गम वस्तु-विनिमय से सम्बन्धित कठिनाइयों में है।'^४ अतः मुद्रा का आविष्कार वस्तु-विनिमय की असुविधाओं को दूर करने के लिए किया गया। क्राउथर (Crowther) ने भी मुद्रा को एक आविष्कार माना है जो मनुष्य की विवेकशीलता का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि 'यह निश्चित रूप में एक आविष्कार था। साधारण वस्तु-विनिमय से मुद्रा के द्वारा हिसाब करने की अवस्था में आने के लिए मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा होगा।' ^५ इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुद्रा मनुष्य की निरन्तर खोज का परिणाम है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग मूल्य की इकाई के रूप में हुआ।

मुद्रा का आविष्कार किया गया अथवा उसका विकास अपने आप हो गया तथा मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग मूल्य के मापक के रूप में हुआ अथवा विनिमय के माध्यम के रूप में, यह विषय अभी भी विवादग्रस्त है। दोनों विचारधाराओं के पक्ष तथा विपक्ष में काफी तर्क दिये जा सकते हैं किन्तु इस प्रकार के वाद-विवाद से हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते हैं। वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास इतना भ्रूरा तथा काल्पनिक है कि मुद्रा के उद्गम के विषय में अधिक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। केवल यही कहना उचित होगा कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही मुद्रा मानव समाज की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। समाज की प्रगति के साथ-साथ मुद्रा की प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहा है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरने के पश्चात् मुद्रा का वर्तमान रूप विकसित हो सका है।

वस्तु मुद्रा (Commodity Money)—

सर्वप्रथम मुद्रा का विकास वस्तु मुद्रा के रूप में हुआ। किसी उपयोगी वस्तु को मूल्य नापने की इकाई तथा विनिमय के माध्यम के रूप में निश्चित कर लिया

4 "Money, therefore, had its origin in the difficulties associated with barter."

—J. L. Hanson: Monetary Theory and Practice, P. 4.

5 "And it undoubtedly was an invention, it needed the conscious reasoning power of man to make the step from simple barter to money accounting."

—Crowther An Outline of Money, P. 3.

जाता था और उसके द्वारा ही मुद्रा का काम किया जाता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अत्यन्त प्राचीन काल में मध्य जातियाँ किसी न किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करती थी। भारतीय सभ्यता के प्राचीन युग में वस्तु मुद्रा के प्रयोग किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। रोम और यूनान के प्राचीन समाज में पशु ही व्यक्ति का धन समझे जाते थे और उनके द्वारा ही अन्य वस्तुओं के मूल्य नापे जाते थे। इसी प्रकार अन्य प्राचीन जातियों में भी किसी न किसी वस्तु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता रहा है। जो वस्तु जिस समाज के लिए अधिक उपयोगी होती थी वही मुद्रा का कार्य करने लगती थी। तम्बाकू, अनाज, चाय, मीषियाँ, कौड़ी, भेड़, बकरी तथा घैल व गाय, जानवरों को खाने, पत्थर, औजार तथा अगणित अन्य प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग विभिन्न देशों अथवा विभिन्न काल में मुद्रा के रूप में किया गया।

प्राथमिक विकास की भिन्न-भिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ। किसी समाज में मुद्रा के रूप में प्रायः उस वस्तु का प्रयोग किया जाता था जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती थी और जो सब लोगों को मान्य होती थी। शिकारी प्रवस्था में जानवरों की खालें तथा औजारों को मुद्रा के रूप में काम में लाया जाना स्वाभाविक था। पशुपालन के युग में पशुओं का महत्व बढ़ जाने के कारण भेड़, बकरी, बैल इत्यादि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कृषि पर आधारित समाज में लोगों के द्वारा गेहूँ, चावल, तम्बाकू तथा अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसी प्रकार प्राथमिक विकास के साथ-साथ मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएँ भी बदलती गईं।

मुद्रा के विकास के प्रारम्भिक काल में जिन वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया वे इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त न थी, इसलिए एक-एक करके उन्हें छोड़ दिया गया। अनुभव ने यह बताया कि पशु, अनाज, खालें, औजार इत्यादि मुद्रा का कार्य करने के लिए अच्छी वस्तुएँ नहीं हैं क्योंकि उनमें अच्छी मुद्रा वस्तु के अधिकांश गुण नहीं पाये जाते। विशेषतया पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते समय विंशेष अशुविधा होती थी। प्रायः इनमें प्रमाणीकरण (Standardisation) का अभाव होता था क्योंकि सब बकरियाँ अथवा गाय एक प्रकार की नहीं हो सकती हैं। यह निश्चित करना काफी कठिन था कि किस प्रकार की गाय अथवा बकरी को मुद्रा का कार्य करने के लिए प्रमाणिक माना जाय और फिर यह भी निश्चित करना होता था कि अन्य गाय तथा बकरियाँ उन प्रमाणिक पशुओं की तुलना में कितनी अच्छी अथवा बुरी हैं। इन कठिनाई को बतलाने हुए लार्ड केन्स (Lord Keynes) ने लिखा है कि युगेण्डा में (Uganda) में जिलाधीश का

अधिकांश समय तथा शक्ति इस बात का निराकरण करने में लग जाती है कि कोई भेड ऋण का भुगतान करने के लिए प्रमाणिक भेड है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त पशुओं को धन का संचय करने के साधन के रूप में प्रयोग करना भी सुविधापूर्ण नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से सचित करने वाले व्यक्ति का धन कभी भी घट-वृद्धि नहीं करता था। पशुओं में बीमारी फैल जाने की दशा में मनुष्य के सचित धन में भारी कमी हो जाती थी तथा प्रजनन काल में उमर में काफी वृद्धि होने की सम्भावना रहती थी। पशुओं के स्वामी को इस प्रकार के धन को जीवित तथा स्वस्थ रखने के लिए काफी व्यय भी करना होता था। एक अन्य कठिनाई इस पशु-मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में होती थी। इन असुविधाओं के कारण मुद्रा के रूप में पशुओं का प्रयोग धीरे-धीरे बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार घनाज, खाले, भोजार, बाय आदि भी मुद्रा के रूप में अधिक सफल न हो सकी। इन वस्तुओं में भी प्रमाणीकरण का अभाव था, वे अधिक समय तक सचित करके नहीं रखी जा सकती थी तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना कठिन होता था या ऐसा करने में अधिक व्यय करना पड़ता था। इन वस्तुओं का मूल्य भी स्थिर नहीं रहता था जिसके कारण वे मुद्रा का कार्य अच्छी प्रकार कर सकती थी।

इन सब दोषों के कारण इन वस्तुओं के स्थान पर धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। सम्यता के साथ-साथ वस्तु मुद्रा का प्रयोग कम होता गया और उसका स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग सबसे पहले उन देशों में आरम्भ हुआ जिन्होंने धातुओं को निकालने का कार्य सबसे पहले किया। दुरु-दुरु में धातुओं के विभिन्न आकार तथा विभिन्न वजन के टुकड़ों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था, किन्तु विकास के साथ-साथ सिक्कों का उदय हुआ। आरम्भ में लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी तथा अन्य सभी प्रकार की धातुओं के टुकड़े मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाते थे। किन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि सोने और चांदी के अतिरिक्त अन्य धातुओं में स्वल्पता का गुण नहीं पाया जाता है। अतः वे मुद्रा के रूप में अधिक उपयुक्त नहीं हैं। स्वल्पता की दृष्टि से सोने व चांदी के टुकड़े अन्य धातुओं के टुकड़ों से श्रेष्ठ थे इसलिए अन्य धातुओं के स्थान पर केवल इन दो धातुओं ने मुद्रा का स्थान ले लिया। आरम्भ में सोने की अपेक्षा चांदी का प्रयोग अधिक किया जाता था किन्तु सोने का उत्पादन बढ़ जाने पर सोने का प्रयोग मुद्रा के रूप में अधिक किया जाने लगा।

सिक्के (Coinage)—

धातु सिक्के का विकास तथा प्रयोग मुद्रा के इतिहास में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटना थी। सर्वप्रथम सिक्के का प्रयोग कब और कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर काफी वाद-विवाद रहा है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन में ईसा से ११वीं शताब्दी पूर्व सिक्के का चलन आरम्भ हो गया था, एशिया

मार्इनर में ७ वीं शताब्दी पूर्व तथा भारत में चौथी शताब्दी पूर्व सिक्को का प्रयोग किया जाता था। आरम्भ में लोहे तथा तांबे के सिक्को का प्रयोग किया गया, किन्तु शीघ्र ही उनका स्थान सोने तथा चांदी के सिक्को ने ले लिया। अब मनुष्य को सोने और चांदी के रूप में एक उत्तम मुद्रा वस्तु मिल गई थी। यह बहुमूल्य धातुयें सर्वमान्य होने के साथ-साथ जल्दी नष्ट होने वाली न थी। इनका मूल्य भी प्रायः निश्चित रहता था। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था तथा इनके विभाजन में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। इन्हीं गुणों के कारण लगभग सभी देशों में सोने और चांदी को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया।

सिक्को का वर्तमान रूप एक सभ्य विकास का परिणाम है। प्रारम्भिक सिक्के भट्टी जिसमें वे धातु टुकड़े होने थे जिन पर किसी प्रकार की मोहर लगी होती थी। इन सिक्को को काट कर अथवा अन्य विधियों से उनमें धातुओं की मात्रा अथवा शुद्धता कम की जा सकती थी। उन पर लगी हुई मोहर इस बात का प्रमाण नहीं होती थी कि वे निश्चित वजन अथवा निश्चित शुद्धता के हैं। लोग इस प्रकार के सिक्को को स्वयं भी ढाल लेते थे जिसके कारण बाकी मात्रा में बुरी मुद्रा चलन में रहती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए सिक्को में सुधार किया गया जिससे कि छोटे सिक्को को चलन में डालने की सम्भावना कम हो जाय। सिक्के निश्चित आकार, वजन तथा शुद्धता के बनाये जाने लगे, उनके किनारे विशेष प्रकार से काटे जाते थे तथा उनके दोनों ओर सरकारी मोहर लगाई जाती थी। इस प्रकार सिक्को ने धीरे-धीरे अपना आधुनिक रूप प्राप्त किया। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणिक सिक्को के साथ-साथ भावैतिक सिक्के भी चलाये जाने लगे।

पत्र मुद्रा (Paper Money) —

आर्थिक विकास के साथ व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार होने लगा और मुद्रा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती गई किन्तु बहुमूल्य धातुओं की मात्रा सीमित थी। मानव समाज के लिए मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को धातु मुद्रा के द्वारा पूरा न किया जा सका और ऐसी वस्तु की खोज आरम्भ हुई जो उनके स्थान पर मुद्रा का कार्य कर सके। धातु मुद्रा का ढलाई व्यय अधिक होता था उसका चलन व्यय भी बहुत अधिक था क्योंकि मूल्यवान सिक्को की धिमादट के कारण सरकार को प्रतिवर्ष बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त धातु मुद्रा की पूर्ति मनुष्य के हाथों में न होकर प्रकृति पर निर्भर रहती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए तथा सोने चांदी की बचत करने के उद्देश्य से पत्र मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ। बैंको का विकास हो जाने के कारण तथा शक्तिशाली और विश्वसनीय राज्यों की स्थापना हो जाने पर वाणिज्य मुद्रा को चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हो गया। बहुमूल्य धातुओं की कमी के कारण तथा पत्र मुद्रा के अधिक सुविधाजनक होने के कारण समार के सब देशों ने उसे अपना लिया।

प्रारम्भ में पत्र मुद्रा को केवल धातु मुद्रा के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया गया और लोगों ने कागजी नोटों को लेना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें किसी भी समय धातु मुद्रा में बदला जा सकता था। नोटों को परिवर्तनीय रखने के लिए उनके पीछे शतप्रतिशत कोष रखा जाता था। धीरे-धीरे जनता का विश्वास पत्र मुद्रा में बनता गया और दूसरे विश्व-युद्ध काल में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चलाई गई। जनता ने उसे भी निस्कोच स्वीकार कर लिया क्योंकि उसमें सर्वमान्यता का गुण था। अब लोगों को यह भी अनुभव होने लगा कि मुद्रा स्वयं कोई महत्व नहीं रखती है, वह तो केवल आवश्यकता पूर्ति का साधन मात्र है। इसलिए मुद्रा का मूल्यवान् वस्तु का बना होना कोई अनिवार्य नहीं है। इन दशावस्थाओं में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का विकास हुआ और पत्र मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले धातु कोष की मात्रा को कम कर दिया गया। आजकल अधिकांश देशों में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा चलाई जाती है। इसके साथ-साथ उगतिशील देशों में साख मुद्रा का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अमरीका, इंग्लैंड आदि देशों में तो साख मुद्रा का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि वह नकद मुद्रा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

साख मुद्रा (Credit Money)—

पत्र मुद्रा के विकास के साथ-साथ साख मुद्रा का प्रयोग भी निरन्तर बढ़ता रहा है। यद्यपि साख पत्रों का प्रयोग काफी प्राचीन समय से होता आया है किन्तु आधुनिक बैंकों के विकास ने साख मुद्रा के प्रयोग में काफी वृद्धि की है। प्रारम्भिक काल में बैंकों के द्वारा जारी किये जाने वाले नोट भी एक प्रकार की साख मुद्रा थी क्योंकि उसे बैंकों की साख के आधार पर ही स्वीकार किया जाता था। इन बैंक नोटों का स्थान धीरे-धीरे वर्तमान करन्सी नोटों ने ले लिया जो सरकार या केन्द्रीय बैंक के द्वारा जारी किये जाते हैं और कानूनी विधिग्राह्य (Legal Tender) होते हैं। आजकल चैक (Cheque) बिल ऑफ एक्सचेंज (Bill of Exchange) तथा बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) आदि साख पत्रों की सहायता से साख मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। साख पत्रों का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक व्यापार तथा उद्योगों की मुद्रा के लिए बढ़ती हुई मांग को बहुत कुछ साख मुद्रा के द्वारा पूरा किया जाता है। वह एक प्रकार से कानूनी मुद्रा की पूरक है। बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार साख का विस्तार करके व्यापार तथा उद्योगों की मुद्रा की मांग को पूरा करते रहते हैं।

साख मुद्रा की प्रकृति अन्य प्रकार की मुद्राओं से भिन्न होती है। यह मुद्रा कानूनी विधिग्राह्य (Legal Tender) नहीं होती है, इसलिए इसे स्वीकार करना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार की मुद्रा केवल सुरक्षित करने वाले की साख के आधार पर स्वीकार की जाती है। मुदतान लेने वाले को साख पत्र जारी

वरने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर कितना विश्वास है इस बात पर ही साख मुद्रा की स्वीकृति निर्भर होती है। साख मुद्रा के बढ़ते दृष्टे प्रयोग का मुख्य कारण उसका अधिक सुविधाजनक होना है। साख मुद्रा पत्र मुद्रा से भी अधिक सुविधापूर्ण होती है। उसके द्वारा बड़े भुगतानों को तथा दूर के भुगतानों को बड़ी आसानी से निबटाया जा सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि अनियन्त्रित साख मुद्रा समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि आवश्यकता से अधिक साख बैंकों के द्वारा जारी की जाती है तो वह अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता को समाप्त कर सकती है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) मुद्रा का विकास कैसे हुआ ? मुद्रा कितने प्रकार की होती है और वह क्या कार्य करती है ? (भागरा बी० काम १९५६ s)
- (२) मुद्रा अर्थ-व्यवस्था एवं वस्तु-विनिमय अर्थ-व्यवस्था से भेद कीजिए। (भागरा बी० काम १९५८ s)
- (३) हमारे समाज में मुद्रा का क्या महत्व है ? इस पर प्रकाश डालिये। क्या आज का आर्थिक समाज बिना मुद्रा के रह सकता है ? (राजस्थान बी० ए० १९५९)
- (४) 'वस्तु विनिमय व्यवस्था' तथा 'मुद्रा व्यवस्था' के लाभ और दोषों को बतलाइये। क्या संसार फिर से वस्तु-विनिमय की ओर लौट रहा है ? (राजस्थान बी० ए०)
- (५) स्पष्ट समझाइये कि किस प्रकार एवं किस सीमा तक विनिमय व्यवहारों में मुद्रा का प्रयोग करने से वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं ? (राजस्थान बी० काम १९५८)
- (६) मुद्रा का मानव जाति के आर्थिक विकास में क्या स्थान रहा है ? इस पर प्रकाश डालिये और बताइये कि क्या अब मुद्रा की उपयोगिता समाप्त हो गई है ? (सागर बी० काम १९५५)
- (७) वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के विकास के महत्व को समझाइये। उसके आर्थिक व सामाजिक प्रभाव क्या हुये हैं ? (पटना १९५५ s)
- (८) मुद्रा के आविष्कार ने बहुत सीमा तक आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया है। विवेचन करिये। (बिहार बी० काम १९५९)

मुद्रा की परिभाषा तथा कार्य

DEFINITION AND FUNCTION OF MONEY

यद्यपि मुद्रा का प्रयोग काफी प्राचीन काल से होता आया है, किन्तु उसकी प्रकृति के बारे में अधिकांश लोगों का ज्ञान अधूरा है। निरन्तर प्रयोग करते रहने पर भी हम लोग उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। व्यवहारिक जीवन में सभी लोग यह अनुभव करते हैं कि वे मुद्रा को भन्नी प्रकार समझते हैं किन्तु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुद्रा की प्रकृति के बारे में सही ज्ञान रखते हैं अथवा जो उसकी ठीक परिभाषा कर सकते हैं। मुद्रा के बारे में हमारी अज्ञानता के सम्बन्ध में क्रॉथर (Crowther) ने ठीक ही कहा है—‘व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुद्रा क्या है किन्तु बहुत कम लोग उसकी तुरन्त परिभाषा करने के लिए तैयार होंगे जिसमें कि उसे अन्य वस्तुओं से अलग किया जा सके।’^१ केंट (Kent) के अनुसार, ‘यद्यपि मुद्रा हमारे विचारों में बहुत अधिक रहती है, यद्यपि वह हमारी बहुत सी क्रियाओं को प्रभावित करती है किन्तु फिर भी हमें, निश्चित रूप से यह बताने में कि वह क्या है, काफी कठिनाई होती है।’^२ आज हम आर्थिक विकास की ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं, जिसमें मुद्रा हमारी क्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालती है तथा वह हमारे विचारों का मुख्य केन्द्र बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में मुद्रा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। मुद्रा का सही प्रयोग बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम उसे ठीक प्रकार से पहचानते हैं अथवा नहीं। मुद्रा के प्रयोग से पूरा लाभ उठाने के लिए हमें उसकी प्रकृति का सही ज्ञान होना चाहिए। रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए आरम्भ से ही यह आवश्यक है कि वह मुद्रा के उस आवरण (Monetary Veil)

1 “Everybody knows in practice what constitutes money, but few people would be prepared at a moment’s notice to define money, to indicate precisely what differentiates money from other articles or commodities.”

—G. Crowther : An Outline of Money, P. 1.

2 “Though money is much in our thoughts and though it conditions many of our actions we encounter great difficulty in attempting to state precisely what it is?”

—P. Kent : Money & Banking, P. 1.

को, जिसमें अधिकांश व्यापारिक सौदे लिपटे रहते हैं, हटाकर यह देखने का प्रयत्न करे कि वास्तविक वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में क्या हो रहा है जिससे कि वह लोगों के वास्तविक त्याग तथा उन्हें प्राप्त होने वाले वास्तविक सन्तोष को समझ सके।³

मुद्रा की प्रकृति—

मुद्रा की प्रकृति के सम्बन्ध में एक बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वयं कोई उपयोगी वस्तु नहीं है। वह केवल उपयोगी वस्तुमें प्राप्त करने का साधन है। मुद्रा का अपना कोई महत्व नहीं है, उमका महत्व इस बात में है कि उसमें अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति पाई जाती है। जब तक मुद्रा में यह शक्ति है तब तक वह उपयोगी है किन्तु यदि मुद्रा की क्रय-शक्ति समाप्त हो जाये तो वह हमारे लिए ध्वंस की वस्तु रह जायेगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा उद्देश्य (End) नहीं है, वह केवल उद्देश्य पूर्ति का साधन (Means) मात्र है। वह स्वयं कोई उपयोगी वस्तु नहीं है, केवल विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का प्रत्यक्ष प्रयोग करके सन्तुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसके बदले में उन वस्तुओं को अवश्य प्राप्त किया जा सकता है जिनमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है। मुद्रा के बारे में यह जान लेना आवश्यक है कि वह केवल विनिमय का साधन है और वह हमारा लक्ष्य नहीं बन सकती है।

क्योंकि मुद्रा केवल विनिमय के लिए है इसलिए उसमें सर्वमान्यता का गुण होना अनिवार्य है।⁴ कोई भी वस्तु जो समाज में सर्वमान्य न हो, वह विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं कर सकती है। मुद्रा का एकमात्र गुण है कि वह समाज में सामान्यतः स्वीकृत की जाती हो, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लेने को तैयार हो। क्योंकि मुद्रा वस्तु के रूप में उपयोगी नहीं है और उससे केवल विनिमय का कार्य लिया जाता है, इसलिए उसका बहुमूल्य होना अनिवार्य नहीं है। समाज में कोई भी वस्तु मुद्रा का कार्य कर सकती है यदि उसे सर्वमान्यता प्राप्त है। इसीलिए आजकल मूल्यवान् वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग न करके उसके स्थान पर कागज जैसी कम मूल्यवान् वस्तु का प्रयोग किया जाने लगा है। जब हमें मुद्रा में विनिमय का ही काम लेना है तो क्या यह जरूरी है कि विनिमय का माध्यम मूल्यवान् ही हो। कम मूल्य वाली वस्तुयें भी इस कार्य को अपनी प्रकार से कर सकती हैं।

मुद्रा स्वयं धन को पैदा नहीं करती, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से धन के उत्पादन में बड़ी सहायता करती है क्योंकि उसमें विनिमय के कार्य को सुविधापूर्वक बनाने

3 "It is necessary for the economic student to try from the start to pierce the monetary veil in which most business transactions are shrouded, and see what is happening in terms of real goods and services; indeed so far as possible he must try to penetrate further, and to see what is happening in terms of real sacrifices and satisfactions."

तथा विनिष्ठीकरण को सम्भव करने की शक्ति पाई जाती है। आदम स्मिथ ने मुद्रा की प्रकृति के विषय में बतलाते हुए कहा है कि मुद्रा न तो स्वयं कोई धन है और न वह प्रत्यक्ष रूप से धन पैदा करती है, वह तो धन पैदा करने में सहायक होती है और इसी कारण उसका विशेष महत्व है। जिस प्रकार किसी क्षेत्र में से जाने वाली सड़क धन के उत्पादन में सहायक होती है क्योंकि उस पर से होकर कुल क्षेत्र की फसल मण्डी को जाती है, किन्तु सड़क पर कुछ पैदा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मुद्रा स्वयं धन पैदा न करके भी धन के उत्पादन में सहायक होती है। प्रो० कोल (G. D. H. Cole) के अनुसार मुद्रा स्वयं कोई उत्पादन नहीं करती है वह तो केवल उत्पत्ति और विनिमय को सरलतापूर्वक चलाने में सहायता देती है। जिस प्रकार मशीन को भली प्रकार चलाने में तेल (Lubricating oil) सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा हमारी आर्थिक क्रियाओं को सरलतापूर्वक चलाने में सहायता देती है।

मुद्रा की परिभाषा—

मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में विचारों का मतभेद पाया जाता है कि उसकी कोई एक परिभाषा निश्चित रूप से नहीं दी जा सकती। कुछ लेखकों ने तो मुद्रा की परिभाषा करने की आवश्यकता ही नहीं समझी और इनके अनुसार मुद्रा को केवल उसके वर्णन के द्वारा ही समझा जा सकता है।* किन्तु यह दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक नहीं है। किसी भी वस्तु को हम उसकी परिभाषा के द्वारा ही पूर्णतः समझ सकते हैं। अतः मुद्रा की परिभाषा करना अनिवार्य हो जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं किन्तु इनमें से अधिकतर परिभाषायें केवल मुद्रा के कार्यों का वर्णन ही करती हैं। कुछ लेखकों का मत है कि मुद्रा की एक अच्छी परिभाषा वही है जो उसके समस्त कार्यों का वर्णन करे। इनके दूसरी ओर कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा करते समय उसकी प्रकृति को बतलाने का प्रयत्न किया है। इनमें कौनसा विचार ठीक है, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मुद्रा की अधिकांश परिभाषायें वर्णनात्मक हैं।

मुद्रा की परिभाषा करते समय उसका क्षेत्र निश्चित करने में विशेष कठिनाई होती है। कुछ लेखकों ने मुद्रा शब्द का प्रयोग सकुचित अर्थ में किया है। इनके अनुसार केवल धातु मुद्रा ही मुद्रा में सम्मिलित की जानी चाहिए, अन्य प्रकार के विनिमय के माध्यम मुद्रा नहीं है। राबर्टसन इसी विचारधारा के मानने वाले हैं। उनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो भुगतानों को निबटाने के लिए विस्तृत रूप से समाज में स्वीकार की जाती हो क्योंकि सोने और चाँदी के सिक्के ही किसी देश में विस्तृत रूप से स्वीकार किये जा सकते हैं, इसलिए केवल धातु मुद्रा ही मुद्रा में

सम्मिलित की जानी चाहिए। वर्तमान अर्थशास्त्री इतने मरुचित अर्थ में मुद्रा शब्द का प्रयोग किए जाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने से बहुत से विनिमय के माध्यम जैसे करेसी नोट अथवा बैंक जमा मुद्रा होते हुये भी मुद्रा नहीं कहे जा सकते हैं।

कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है और इनके अनुसार मुद्रा के अन्तर्गत सब प्रकार के विनिमय के माध्यम आ जाते हैं। इस प्रकार के लेखकों में हार्टले विदर्स (Hartlay Withers) का नाम सर्वप्रथम आता है। इनके अनुसार सब प्रकार के विनिमय के माध्यम को मुद्रा में सम्मिलित किया जा सकता है। 'कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है मुद्रा है।' इस प्रकार धातु मुद्रा (Coins), करेसी नोट (Currency notes), बैंकों में जमा रकम (Bank Deposits) तथा अन्य प्रकार के सात पत्र जो मुद्रा का कार्य करते हैं, सब मुद्रा में सम्मिलित किये जाने चाहिए। मुद्रा शब्द का प्रयोग इतने विस्तृत अर्थ में किया जाना भी उचित नहीं है क्योंकि बहुत से विनिमय के माध्यम ऐसे हैं जिन्हें मुद्रा नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया है। उन्होंने मुद्रा शब्द का प्रयोग नहीं तो विस्तृत रूप में किया है और न उसका सङ्कुचित अर्थ ही लगाया है, बल्कि उसका 'उचित क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। मार्शल, ऐली, कोल इत्यादि अर्थशास्त्री इसी वयं में सम्मिश्रित हैं। इनके अनुसार यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा धातु की ही बनी हो। कोई भी वस्तु जिसे समाज में विनिमय के माध्यम रूप में अथवा ऋणों के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कही जा सकती है। मुद्रा का एक ही अनिवार्य गुण है कि उसका स्वतन्त्रता-पूर्वक हस्तांतरण होता हो। इन लेखकों के अनुसार धातु सिक्के (Coins), करेसी नोट (Currency Notes) और बैंक जमा (Bank Deposits) तो मुद्रा हैं किन्तु अन्य प्रकार के विनिमय के माध्यम मुद्रा नहीं हैं। आजकल अधिकतर लोग इसी विचारधारा से सहमत हैं।

मुद्रा की परिभाषाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- (अ) वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Descriptive Definitions)
- (ब) वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)
- (स) सर्व ग्रहणीयता पर आधारित परिभाषाएँ (Definitions based on General Acceptability).

(अ) वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Descriptive Definitions)—

इस वर्ग में वे परिभाषाएँ आ जाती हैं जिनमें मुद्रा की परिभाषा के स्थान पर उसके कार्यों के वर्णन पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार की परिभाषाएँ

यह नहीं बताती कि मुद्रा क्या है, वे केवल उसके कार्यों का वर्णन करती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा की परिभाषा केवल उसके कार्यों के द्वारा की जा सकती है। वाकर (F. A. Walker), हार्टले विदर्स (Hartley Withers), सिजविक (Sidgwick) तथा थॉमस (Thomas) इसी वर्ग के अर्थशास्त्री हैं। इन लेखकों के अनुसार मुद्रा की समझने से लिए यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा का विकास क्यों हुआ और वह समाज में क्या करती है। इसीलिए इन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्यों के आधार पर उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। वाकर (Walker) से अनुसार 'मुद्रा वह है जो मुद्रा करती है'।^५ अर्थात् कोई भी वस्तु जो मुद्रा के कार्य करती है। यह कार्य मुख्य रूप से चार हो सकते हैं—विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक कार्य का करना तथा मूल्य के संचय करने और स्थगित भुगतानों को निवटाने की सुविधाएँ प्रदान करना। जो भी वस्तु इन कार्यों को करती हो वही मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा कोई वस्तु विशेष नहीं है। कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है यदि उसमें मुद्रा के कार्यों को करने की क्षमता पाई जाती है। इसी प्रकार हार्टले विदर्स (Hartley Withers) ने मुद्रा उस वस्तु को बतलाया है जिसके द्वारा हम वस्तुयें बेचते और खरीदते हैं।^६ थॉमस (Thomas) के अनुसार "मुद्रा एक वस्तु है जो मूल्य मापक तथा अन्य वस्तुओं से बीच विनिमय माध्यम का कार्य करने के लिए एकमत होकर चुन ली जाती है"।^७ इसी प्रकार कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा की वर्णनात्मक परिभाषाएँ दी हैं। इस प्रकार की परिभाषायें सरल हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी भी हैं किन्तु वे तर्कों की कसौटी पर सही नहीं उतरती हैं क्योंकि उनमें वे गुण नहीं पाये जाते हैं जो तर्कों की दृष्टि से एक अच्छी परिभाषा में होने चाहिएँ। यह परिभाषायें केवल मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती हैं, उसकी प्रकृति के बारे में हमें कुछ नहीं बताती हैं। किसी वस्तु के कार्यों की व्याख्या केवल उसका वर्णन हो सकती है, परिभाषा नहीं। एक अच्छी तथा वैज्ञानिक परिभाषा को वस्तु विशेष का वर्ग (Genus) तथा अन्य वस्तुओं से प्रयत्न करने वाले उसके गुणों (Differentia) की व्याख्या अवश्य करनी चाहिए। इन परिभाषाओं में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। अतः उन्हें मुद्रा की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं कहा जा सकता है।

(ब) वैज्ञानिक परिभाषायें (Legal Definitions)—

कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा करते समय इसके वैधानिक पक्ष पर विशेष जोर दिया है। इनके अनुसार मुद्रा वही है जिसे वैधानिक रूप से मुद्रा घोषित

5. 'Money is that money does' —Francis Walker : Money in its Relations to Trade & Industry (1889) P. 1.

6. 'Money, then is, the stuff with which we buy and sell things' —Hartley Withers : The Meaning of Money. P 267.

7. 'Money is a commodity chosen by common consent to be a measure of value and a means of exchange between all other commodities.' —Thomas : Elements of Economics.

पर दिया गया हो। किसी वस्तु को मुद्रा बनाने के लिए वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा की वैधानिक परिभाषाये मुद्रा के राज्य मिद्धान्त (State Theory of Money) पर आधारित है। इस मिद्धान्त के अनुसार सरकार कुछ विशेष वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाने की घोषणा करती है। केवल उन वस्तुओं को ही मुद्रा कहा जा सकता है जिन्हें इस प्रकार की वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। क्योंकि राज्य की दृष्टि में ऋणों का भुगतान आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जिसे राज्य के द्वारा ऋणों का भुगतान करने का साधन घोषित कर दिया हो। जर्मन अर्थशास्त्री नैप (William Knapp) तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हाट्टे (R. G. Hawtrey) इसी विचारधारा के मानने वाले हैं। नैप के अनुसार "कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है।" नैप (Knapp) का यह विचार, कि सरकार द्वारा घोषित की हुई वस्तु ही मुद्रा कहलाती है, बहुत कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। आजकल अधिकांश मुद्रा सरकार के द्वारा चलाई जाती है और समाज में केवल ये वस्तु ही मुद्रा का कार्य करती हैं जिन्हें राज्य की ओर से वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। राज्य द्वारा घोषित वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। जब तक उनके पीछे कानूनी दबाव होता है तब तक कोई भी उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई उन्हें मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी दबाव के द्वारा मुद्रा की सामान्य स्वीकृति प्राप्त की जाती है। विशेषकर कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में नैप का विचार अधिक सही प्रतीत होता है क्योंकि पत्र मुद्रा का निःसर्वास्वीकार किया जाना उसकी वैधानिक मान्यता पर आधारित है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, उसे समाज में मुद्रा के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि राज्य के द्वारा उसे मुद्रा घोषित कर दिया गया है और उसके पीछे वैधानिक दबाव है। यदि यह वैधानिक दबाव हटा लिया जाये और कागजी मुद्रा का निःसर्वास्वीकरण (Demonetisation) कर दिया जाय तो कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसमें यह ज्ञात होता है कि वर्तमान मुद्रा का निःसर्वास्वीकार किया जाना कानूनी दबाव के कारण है, न कि उसकी अपनी शक्ति अथवा गुणों के कारण। अतः मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण राज्य के द्वारा पैदा किया जाता है।

व्यवहारिक दृष्टि से उचित होते हुये भी नैप की परिभाषा को ठीक नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी वस्तु का, मुद्रा का कार्य करने के लिए, वैधानिक रूप से स्वीकार किया जाना अनिवार्य नहीं है। कई बार समाज में ऐसी वस्तुयें भी मुद्रा के रूप में ग्रहण कर ली जाती हैं जिन्हें राज्य ने मुद्रा घोषित नहीं किया है। इस प्रकार की मुद्रा की सामान्य स्वीकृति राज्य की घोषणा पर आधारित नहीं होती, वह उसके निजी गुणों के कारण होती है। ऐसा प्रायः धातु मुद्रा के सम्बन्ध में होता

है। इसके दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता कि जिस वस्तु को राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह अवश्य ही मुद्रा का कार्य करती रहेगी। यदि जनता का विश्वास किसी मुद्रा में नष्ट हो जाय तो वैधानिक मान्यता होत हुए भी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् जर्मनी में इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। अधिक मुद्रा प्रसार के कारण जनता का विश्वास वहाँ की मुद्रा में नष्ट गया और कानूनी दबाव होते हुए भी लोगों ने कागजी मुद्रा लेने से इन्कार कर दिया। सरकार ने मुद्रा की मान्यता को बनाये रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया। मुद्रा को स्वीकार न करने वालों को मृत्यु-दण्ड भी दिया गया किन्तु जनता का विश्वास मुद्रा में न लौट सका। अन्त में विवश होकर सरकार ने कागज के नोटों को भूमि के टुकड़ों में परिवर्तित करने की घोषणा की और तब फही लोगों ने पत्र मुद्रा को लेना आरम्भ किया। इस घटना से निमित्त होता है कि मुद्रा की सामान्य स्वीकृति केवल राज्य की घोषणा के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में उसी समय तक स्वीकार की जाती है जब तक जनता का विश्वास उसमें रहता है। इसके अतिरिक्त नैप की परिभाषा में एक और दोष भी पाया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है और विनिमय का कार्य स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक होना चाहिए। यदि मुद्रा की स्वीकृति कानूनी दबाव के कारण होती है तो विनिमय ऐच्छिक तथा स्वतन्त्र नहीं रहता है। इन सब कारणों से नैप की परिभाषा को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। हाट्ट (Hawtrey) ने नैप की परिभाषा के दोषों का ध्यान में रखकर मुद्रा की वैधानिक परिभाषा में सुधार करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने मुद्रा को विधिप्राप्त (Legal Tender) होने के साथ-साथ हिसाब की इकाई (Unit of Account) भी माना है और इस प्रकार उनकी परिभाषा नैप की परिभाषा से भिन्नी है।

(स) सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ

(Definitions based on General Acceptability)---

इस वर्ग में वे परिभाषाएँ आ जाती हैं जिनमें सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक विशेष गुण माना गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार वह है मुद्रा जो वस्तुओं के मूल्य चुवाने, ऋणों का भुगतान करने तथा अन्य प्रकार के लेन-देन के सौदों को निवटाने के लिए समाज में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती हो। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है किन्तु उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं है तो वह मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। मुद्रा का कार्य करने के लिए किसी वस्तु का सर्वमान्य होना अनिवार्य है। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषायें वैधानिक तथा चरित्रात्मक परिभाषाओं की अपेक्षा कम दोषपूर्ण हैं। राबर्टसन, मार्शल, पीगू, कोल, केन्स, क्राउथर तथा ऐली आदि ने इसी प्रकार की परिभाषायें दी हैं। यद्यपि इन परिभाषाओं में परस्पर काफी अन्तर पाया जाता है किन्तु वे सब

ही सामान्य स्वीकृति के सिद्धान्त पर आधारित हैं। राबर्टसन (Robertson) के अनुसार 'मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने या अन्य प्रकार के व्यवसायिक भुगतानों को निवटाने के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है।'^८ इस परिभाषा में राबर्टसन ने सामान्य स्वीकृति पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु उम समय तक मुद्रा का कार्य नहीं कर सकती है जब तक उसे समाज में सामान्य रूप से स्वीकार न किया जाता हो। यदि किसी सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में चलाये जाने वाले करेसी नोट सामान्य स्वीकृति खो दें और भुगतानों को निवटाने के लिए ग्राम तौर से स्वीकार न किये जायें तो वे नोट मुद्रा होते हुए भी मुद्रा का कार्य न कर सकेंगे, इसलिए उन्हें मुद्रा नहीं कहा जा सकता है। इसके दूसरी ओर यदि ऐसी वस्तुएँ जैसे सम्बाहू, बंस, इत्यादि जिनसे हम मुद्रा का कार्य नहीं लेना चाहते, भुगतानों को निवटाने के लिए सामान्यतः स्वीकार की जाने लगे तो मुद्रा न होते हुये भी वे मुद्रा का कार्य करने लगती हैं। इस प्रकार सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक अनिवार्य गुण है। नीचे दी गई सभी परिभाषायें मुद्रा की सामान्य स्वीकृति पर विशेष जोर देती हैं।

डा० मार्शल के अनुसार—“मुद्रा में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं, जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना मदेह अथवा विशेष जाँच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने अथवा अन्य भुगतानों को निवटाने के साधन के रूप में ग्रहण की जाती हैं।”^९

एली (Ely) ने मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार की है। “मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरित की जाती हो और जिसे ऋणों के अन्तिम भुगतान के लिए सामान्यतः स्वीकार किया जाता हो।”^{१०}

जे० एम० केन्स (J. M. Keynes) के अनुसार—“मुद्रा वह है जिसको देखकर ऋण तथा मूल्य सम्बन्धी भुगतानों को निवटारा जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय-शक्ति को संचय किया जाता है।”^{११}

8. “Money is any thing which is widely accepted in payment for goods, or in discharge of other kinds of business obligations.”

—Robertson, Money, P. 2.

9 “All those things which are (at any time and place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraying expenses.”

—Marshall

10 “Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange, and is generally received in final discharge of debts.”

—Ely Elementary Principles of Economics.

11 “Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held.”

—Keynes: A Treatise on Money, vol. I, P. 1.

क्राउथर (Crowther) के शब्दों में—“मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो और उसके साथ ही वह मूल्य के मापक तथा उसे संवय करने का कार्य भी करती हो।”^{१२}

सैलिगमैन के अनुसार—“मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।”^{१३}

कैन्ट ने भी मुद्रा के सम्बन्ध में बताते समय सामान्य स्वीकृति हो उसका सर्वप्रथम गुण माना है। उसके अनुसार “मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम या मूल्य के मापक के रूप में साधारणतः प्रयोग की जाती हो और सामान्य रूप से ग्रहण कर ली गई हो।”^{१४}

उपरोक्त सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि सामान्य स्वीकृति मुद्रा का सर्वप्रथम गुण है। यद्यपि इनमें से कुछ परिभाषायें मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य पर अधिक जोर देती हैं तथा कुछ उसे विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में समझने का प्रयत्न करती हैं। कुछ अन्य परिभाषायें मुद्रा के ऋणों के अन्तिम भुगतान के साधन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण समझती हैं। इस मतभेद के होते हुए भी यह सब परिभाषायें मुद्रा की सर्वमान्यता के सम्बन्ध में एकमत हैं। कोई वस्तु मुद्रा का कार्य उसी समय कर सकती है जब उसे समाज में मुद्रा के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता हो। मुद्रा कोई विशेष वस्तु नहीं है। कोई भी वस्तु जिसे समाज में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और जिसे मुद्रा के रूप में निःसकोब स्वीकार किया जाने लगता है, मुद्रा हो जाती है। अतः मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जिसे या तो वैधानिक दबाव के कारण अथवा रिवाज के तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य चुकाने तथा ऋणों का अन्तिम भुगतान करने के लिए सामान्यतः स्वीकार किया जाता हो।

मुद्रा के कार्य

(Functions of Money)

मुद्रा को हम उसके कार्यों के द्वारा समझ सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से हमें मुद्रा के कार्यों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हो जाता है, किन्तु मुद्रा को पूर्णतया समझने के लिए हमें उसके कार्यों का विधिवत् अध्ययन तथा विश्लेषण करना

12 “Money can be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time acts as a measure and as a store of value”
—Crowther : An Outline of Money, P. 20

13 “Money is one thing that possesses general acceptability”

—Seligman.

14 “Money is anything which is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value.”

—P. Kent : Money and Banking. P. 4.

चाहिए। अधिकांश परिभाषाओं ने अनुसार मुद्रा दो प्रमुख कार्य करती है—वह विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है। इनके अतिरिक्त मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य सचय के साधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है, जो उसने गौण कार्य हैं। इस प्रकार मुद्रा के चार कार्य माने जाते हैं—विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान तथा मूल्य सचय करने का साधन। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कुछ और कार्य भी बतलाये हैं जो उसे विशेष प्राथिक व्यवस्था में करने होते हैं। मुद्रा के कार्यों को सामान्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

- (क) मुख्य कार्य (Primary Functions)
- (ख) सहायक कार्य (Derived Functions)
- (ग) आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)

(क) मुख्य कार्य (Primary Functions)—

मुद्रा के मुख्य कार्य वे हैं जो उसे प्राथिक विकास की प्रत्येक अवस्था में करने होते हैं। ये मुद्रा के आधारभूत कार्य हैं जो वह प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से करती है। विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक का काम करना, मुद्रा के दो मुख्य कार्य हैं। प्रारम्भ काल से मुद्रा इन दोनों कार्यों को करती आई है और आगे भी करती रहेगी। चाहे मुद्रा के रूप में कोई भी वस्तु क्यों न प्रयोग की जाय, उसे समाज में विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक का कार्य अवश्य करना होता है। वास्तव में मुद्रा का आविष्कार ही इन दोनों कार्यों को करने के लिए किया गया था। इसीलिए इन्हें मुद्रा के आधारभूत अथवा मौलिक कार्य भी कहा जाता है।

(१) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)—मुद्रा का सर्वप्रथम कार्य विनिमय को सरल तथा सुविधापूर्ण बनाना है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करके प्रत्यक्ष विनिमय की कठिनाई को दूर करती है। वस्तु-विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव के कारण जो कठिनाई होती थी, वह मुद्रा के प्रयोग में दूर हो जाती है। अब हम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं को सीधा वस्तुओं के साथ न बदल कर, वस्तुओं को पहले मुद्रा के साथ बदलते हैं और फिर मुद्रा को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ बदला जाता है। विनिमय का कार्य प्रत्यक्ष नहीं होकर मुद्रा के माध्यम के द्वारा किया जाता है। मुद्रा के प्रयोग के कारण विनिमय का कार्य दो भागों में बँट जाता है—(i) वस्तुओं का बेचना तथा (ii) वस्तुओं का खरीदना। एक बार हम वस्तुओं अथवा सेवाओं देकर उनके बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं जिसे वस्तुओं का बेचना कहा जाता है और फिर उस मुद्रा को देकर अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं प्राप्त की जाती हैं जिसे वस्तुओं

का खरीदना कहते हैं। मुद्रा व्यवस्था में बेचने वाले को अपनी वस्तुओं के बदले में जो मुद्रा प्राप्त होती है, उसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के खरीदने पर तुरन्त व्यय करना आवश्यक नहीं है। बेचने वाला यदि चाहे तो उस मुद्रा को कुछ समय पश्चात् खर्च कर सकता है, उसका कुछ भाग खर्च कर सकता है और कुछ बचा सकता है। इस प्रकार वस्तुओं का बेचना और खरीदना दोनों एक दूसरे से घृष्क क्रियामें हो जाती है। विनिमय के माध्यम का कार्य करते समय मुद्रा केवल एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में स्वीकार की जाती है। उसकी प्रत्यक्ष उपयोगिता कुछ भी नहीं होती है और वह केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को सरलतापूर्वक कराने का एक माध्यम है। डच (Dutch) अर्थशास्त्री एन० जी० पियर्सन ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की तुलना रेलवे स्टेशन के शटिङ्ग करने वाले इजन से की है जो कभी डिब्बों की एक पंक्ति को खींचता है और कभी दूसरी को ढकेलता है। इस इञ्जन का काम प्रत्येक डिब्बे को सही पटरियों पर लाना होता है जिससे कि वे निदिचित स्थान पर पहुँच सकें। किन्तु इञ्जन स्टेशन से कभी नहीं जाता है।¹⁵

विनिमय के माध्यम का कार्य करते समय मुद्रा समाज में सामान्य धन-शक्ति (General Purchasing Power) के रूप में कार्य करती है क्योंकि उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के बदले में अपनी वस्तुयें तथा सेवायें देने को तैयार रहता है। मुद्रा के साथ कोई भी वस्तु बदली जा सकती है और किसी भी वस्तु के साथ मुद्रा बदली जा सकती है। व्यक्ति अपनी वस्तुयें बेचकर मुद्रा के रूप में सामान्य धन-शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी आवश्यकता की वस्तुयें खरीदने में प्रयोग कर सकता है। मुद्रा की सहायता से वह तब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुयें तथा सेवायें ले सकता है। मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना उत्पत्ति में भी बहुत सहायक होता है। उत्पादक के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह अपनी शक्ति केवल उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने में ही लगा सके और इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग उसकी कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है।

(२) मूल्य का सामान्य माप (Common Measure of Value)—मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मांकना है। आधुनिक समाज में मुद्रा मूल्य के सामान्य सूचक (Common denominator of Value)

15 "The well known Dutch economist, N. G. Pierson, has very happily likened money to a shunting locomotive at a railway station 'at one moment it pulls one line of trucks, at the next it pushes another, its function being to bring each truck on to the right rails in order that it may be able to reach its destination. But the locomotive never leaves the station'"

Quoted by Wickseil: Lectures on Political Economy, vol. II, P. 19.

का कार्य करती है और मूल्य नापने का एकमात्र साधन है। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य मुद्रा में नापे जाते हैं जिसके कारण विनिमय का कार्य बहुत सरल हो जाता है। जिस प्रकार एक मीटर (Meter) निश्चित लम्बाई को बताता है अथवा एक किलोग्राम (Kilogram) निश्चित वजन को, ठीक उसी प्रकार मुद्रा की एक इकाई निश्चित मूल्य को बताती है। मुद्रा मूल्य नापने के एक पैमाने का काम करती है जिसका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के मूल्य नापने तथा उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। क्रॉउथर (Crowther) के शब्दों में 'वह एक लेखे की इकाई का काम करती है। वह मूल्य के माप-दण्ड अथवा सर्वमान्य मापक के रूप में कार्य करती है जिसके साथ अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है।'^{१६} वस्तु विनिमय के युग में मूल्य का सामान्य सूचक न होने के कारण प्रत्येक वस्तु का मूल्य उन सब वस्तुओं में नापना होता था जिनके साथ वह बदली जाती थी जिसके कारण असम्यक् विनिमय दरों (Exchange Ratios) याद रखना आवश्यक था। एक सौ वस्तुओं को आपस में बदलने के लिए ४,९५० विनिमय दरों का प्रयोग करना पड़ेगा। मुद्रा के प्रयोग से यह कठिनाई दूर हो गई है क्योंकि अब सब वस्तुओं का मूल्य केवल एक वस्तु (मुद्रा) के रूप में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा के द्वारा एक सौ वस्तुओं का विनिमय करने के लिए केवल ९९ विनिमय दरों की ही आवश्यकता होगी। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य के मापक का कार्य करके विनिमय को काफी सरल बना देती है।

यद्यपि मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नापने के लिए किया जाता है किन्तु वह मूल्य नापने का आदर्श साधन नहीं है। मूल्य के मापक के रूप में वह दोषपूर्ण है क्योंकि उसका अपना मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा समाज में मूल्य के मापक का कार्य करती है किन्तु उसका अपना मूल्य बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लम्बाई नापने वाले पैमाने की अपनी लम्बाई कभी बढ़ जाय और कभी कम हो जाय। दोषपूर्ण होते हुए भी, मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि मूल्य नापने का उससे अच्छा साधन उपलब्ध नहीं है।

मुद्रा के उपरोक्त दोनों कार्यों में इतना गहरा सम्बन्ध है कि उन्हें प्रायः एक दूसरे से भलग करना सम्भव नहीं है। विनिमय के माध्यम और मूल्य-मान के कार्य इस प्रकार एक दूसरे में मिल-जुल रहे हैं कि यह बताना कठिन हो जाता है कि कब मुद्रा एक कार्य को समाप्त करती है और कब दूसरा आरम्भ होता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य सभी कर सकती है जब पहले उसके द्वारा वस्तुओं के

16 "It serves as a unit of account. It acts as a yardstick on standard measure of value to which all other things can be compared."

मूल्य को आंक लिया गया हो। इस प्रकार मुद्रा मूल्य मान का कार्य किये बिना विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं कर सकती। मुद्रा के द्वारा मूल्यमान तथा विनिमय के माध्यम के कार्य प्रायः एक साथ किये जाते हैं।

विनिमय-माध्यम तथा मूल्यमान का अलग-अलग होना सम्भव है—

यद्यपि मुद्रा मूल्यमान तथा विनिमय-माध्यम का कार्य सामान्यतः एक साथ करती है किन्तु कभी-कभी वह केवल मूल्य के मापन का कार्य ही करती है और विनिमय के माध्यम का कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाता है। जार्ज हॉलम (George N. Halm) के अनुसार “विनिमय के माध्यम तथा मूल्यमान का एक ही वस्तु के रूप में होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक केवल यह है कि विनिमय के माध्यम की इकाइयों को मूल्यमान की इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सके।”¹⁷ विनिमय के माध्यम तथा मूल्यमान के लिए दो प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। यह सम्भव है कि एक मुद्रा केवल मूल्यमान का कार्य ही करती हो और विनिमय के माध्यम के रूप में किसी अन्य मुद्रा का प्रयोग किया जाता हो किन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब इतने दोनो प्रकार की मुद्राओं में किसी प्रकार एक विनिमय अनुपात निश्चित कर लिया जाय।¹⁸ इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जब विनिमय के माध्यम और मूल्यमान के लिए अलग-अलग वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जब जर्मन मार्क (Mark) का मूल्य मुद्रा प्रसार के कारण तेजी से गिरने लगा तो वहाँ के लोगों ने वस्तुओं के मूल्य नापने के लिए अमरीकन डालर (Dollar) तथा अन्य विदेशी मुद्राओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया क्योंकि इन मुद्राओं का मूल्य मार्क (Mark) की अपेक्षा अधिक स्थिर था। इस प्रकार जर्मनी में दो मुद्राएँ काम कर रही थी—एक मूल्य नापने के लिए और दूसरी विनिमय के माध्यम के रूप में। वस्तुओं के मूल्य तो डालर (Dollar) तथा अन्य मुद्राओं में नापे जाते थे किन्तु भुगतान जर्मन मार्क (Mark) में किया जाता था। इसी प्रकार इंग्लैंड में कुछ समय तक गिनी (Guinee) का प्रयोग वस्तुओं के मूल्य नापने के लिए होता था, किन्तु विनिमय का माध्यम पाँड (£) था। भारतवर्ष में भी आजकल ऐसी ही स्थिति है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य अभी भी आने और पैसे (annas and pices) में नापे जाते हैं किन्तु भुगतान नये पैसे में किया जाता है।

17 'The medium of exchange and the standard of value need not be represented by the same good. It is only necessary for the units of the medium of exchange to be expressed in the units of the standard of value.'

—George N. Halm : Monetary Theory, P. 2.

18 "It is possible ... for two units to be different, provided that an exchange ratio between them can somehow be established."

—Benham : Economics, P. 424.

जब मुद्रा का प्रयोग हिमाव की इकाई (unit of account) के रूप में लिया जाता है तो वह केवल मूल्य मान का कार्य करती है। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसायिक फर्म का हिमाव-किताब मुद्रा में रखा जाता है और उसकी सम्पत्ति (मशीन, भवन, भूमि इत्यादि) का मूल्य मुद्रा में बतलाया जाता है किन्तु फर्म का विचार इन्हें बेचने का बिल्कुल नहीं होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने ममान का मूल्य बताते समय कह सकता है कि उसका ममान तीस हजार ३०,०००) रु० का है किन्तु वह उसे इस मूल्य पर बेचना नहीं है। अतः कभी-कभी मुद्रा केवल मूल्यमान का कार्य करती है और विनिमय के माध्यम का कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) सहायक कार्य (Derived Functions)—

सहायक कार्य मुद्रा के वे कार्य होते हैं जो उसके मुख्य कार्यों के कारण पैदा होते हैं। यद्यपि उनके ऊपर आधारित होते हैं। ये कार्य मुद्रा के द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में नहीं किये जाते थे। कुछ आर्थिक विकास हो जाने के पश्चात् ही मुद्रा इन कार्यों को करना प्रारम्भ करती है। स्थगित भुगतान के मान का कार्य करना तथा मूल्य सचय के माधन के रूप में प्रयोग किया जाना, मुद्रा के इसी प्रकार के कार्य हैं। क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है, इसलिए उसे स्थगित भुगतानों को निबटाने के लिए तथा धन सचय करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

(१) स्थगित भुगतानों का मान (Standard of Deferred Payments)—

आज के व्यवसायिक जीवन में ऋणों का लेन-देन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज में बहुत से भुगतान ऐसे होते हैं जिन्हें वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है। इस प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए एक ऐसी इकाई का होना अनिवार्य है जिसके द्वारा ऋणों को बताया जा सके तथा उनका भुगतान किया जा सके। मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान के रूप में इस कार्य को करती है। ऋण मुद्रा में बताये जाते हैं और मुद्रा के द्वारा ही उनका भुगतान होता है। मुद्रा केवल वर्तमान व्यवसायिक भुगतानों के लिए ही मूल्य मान का कार्य नहीं करती है, बल्कि वह भविष्य में किये जाने वाले स्थगित भुगतानों का मान (Standard) भी होगी है। स्थगित भुगतानों के मान के रूप में मुद्रा को इसलिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि अन्य सब वस्तुओं की अपेक्षा उसके मूल्य में सबसे कम परिवर्तन होता है और लोग यह समझते हैं कि मुद्रा में लेन-देन करने से उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होने की सम्भावना नहीं है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण उसकी आवश्यकता हर समय बनी रहती है। किसी भी समय मुद्रा को देकर उसके बदले में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। यह गुण अन्य वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा

मुद्रा में टिकाऊपन भी अधिक होता है। इन सब कारणों से ही मुद्रा विलम्बित भुगतानों के भान के रूप में स्वीकार की जाती है। स्थगित भुगतानों के भान का कार्य करके मुद्रा समाज में लेन-देन की व्यवस्था पैदा करती है जिस पर वर्तमान समाज का आर्थिक विकास निर्भर है। साख्त का सम्पूर्ण ढाँचा मुद्रा के इसी कार्य पर आधारित है।

मुद्रा विलम्बित भुगतानों के भान के रूप में भी दोषपूर्ण है क्योंकि स्वयं मुद्रा के मूल्य में भारी परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा का मूल्य स्थिर न रहने के कारण कभी ऋणी को और कभी ऋण-दाता को हानि उठानी पड़ती है। ऋण लेने वाला उतनी ही रकम लौटाता है जितनी उसने उधार ली थी किन्तु यदि इस बीच में मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो जाय तो ऋणदाताओं को उतनी क्रय-शक्ति नहीं लौटती है जितनी उन्होंने उधार दी थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है कि मुद्रा के विलम्बित भुगतान के कार्य में अधिक लोच होनी चाहिए और ऋणों की रकम मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार घटा-बढ़ा देनी चाहिए।

(२) मूल्य संचय का साधन (Store of Value)—मुद्रा समाज में मूल्य संचय करने के साधन का कार्य भी करती है। मुद्रा की सहायता से धन को भविष्य के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। मुद्रा-रहित समाज में धन संचय करने में बड़ी कठिनाई होती थी क्योंकि उपयोगी वस्तुओं को बहुत अधिक समय तक इकट्ठा करके रखना सम्भव न था। बहुत सी वस्तुओं का मूल्य बदल जाता था और बहुत सी नाशवान् होने के कारण समय व्यतीत होने पर बेकार हो जाती थी। इन कठिनाइयों के कारण वस्तु विनिमय के युग में धन संचय और पूँजी का निर्माण सम्भव न था। किन्तु जब में मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ है, मनुष्य को एक ऐसा साधन मिल गया है जिसके द्वारा वह भविष्य के लिए क्रय-शक्ति का संचय कर सकता है। वस्तुएँ और सेवाएँ बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है, उसका कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया जाता है और शेष भविष्य के लिए जमा कर लिया जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के रूप में धन संचय न करके मुद्रा के रूप में क्रय-शक्ति को संचय किया जाता है, जिसका आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में धन संचय करना अधिक सुविधापूर्ण है क्योंकि मुद्रा की माँग हर समय बनी रहती है और उसका मूल्य अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा प्रायः सोने, चाँदी, कागज इत्यादि टिकाऊ वस्तुओं की बनाई जाती है जिसके कारण उसे मूल्य में हानि हुए बिना लम्बे समय तक रखा जा सकता है। इन्हीं गुणों के कारण मुद्रा क्रय-शक्ति संचय करने का एक अच्छा साधन है। किन्तु कभी-कभी जब मुद्रा के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो वह क्रय-शक्ति संचय करने का अच्छा साधन नहीं रहती है।

क्योंकि मुद्रा का मूल्य बदलने के कारण संचित धन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है।

वर्तमान समाज में मुद्रा का क्रय-शक्ति संचय करने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रा बचत को सम्भव बनाती है और बचत से पूँजी का निर्माण होता है जो आज के आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। जब तक क्रय-शक्ति का संचय सम्भव न था, पूँजी का निर्माण नहीं हो सकता था और समाज पिछड़ी हुई दशा में था। किन्तु जब मुद्रा के प्रयोग के द्वारा क्रय-शक्ति का संचय सम्भव हो गया तो पूँजी का निर्माण होने लगा और समाज आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जाना इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में की जाने वाली बचत की मात्रा हमारी आर्थिक क्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। लार्ड केन्स (Lord Keynes) के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है बल्कि लोग उसे बचाकर भविष्य के लिए क्रय-शक्ति का संचय कर लेते हैं। इस प्रकार मुद्रा वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ती है। लोगों के द्वारा की जाने वाली बचत समाज की वर्तमान आर्थिक क्रियाओं के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। केन्स (Keynes) के शब्दों में “मुद्रा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि वह वर्तमान तथा भविष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी है।”¹⁹

(३) मूल्य हस्तान्तरित करने का कार्य (Transfer of Value)—मुद्रा समाज में मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का कार्य भी करती है। जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता गया, विनिमय का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और मूल्य को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण उसके द्वारा मूल्य को हस्तान्तरित किया जाने लगा। आज जब हम अपना धन एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना चाहते हैं तो वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। अपनी वस्तुओं तथा सम्पत्ति को एक स्थान पर देकर मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और मुद्रा को अपने साथ ले जाते हैं तथा उसके द्वारा दूसरे स्थान पर सम्पत्ति व अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जब धन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना होता है तो वस्तुओं को देना आवश्यक नहीं है। केवल मुद्रा को हस्तान्तरित करने से ही क्रय-शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग क्रय-शक्ति के हस्तान्तरण की सुविधा प्रदान करता है और कुछ लोगों के पास पड़ी बेकार क्रय-शक्ति अन्य लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है।

19 “For the importance of money essentially flows from its being a link between the present and the future”

—J. M. Keynes. The Theory of Employment Interest & Money, P-293.

(ग) आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)—

प्रो० किन्ले ने मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्यों का वर्णन किया है जो उसे विशेष आर्थिक व्यवस्था में करने होते हैं। आर्थिक जीवन का अधिक विकास हो जाने के कारण मुद्रा को कुछ नये कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हें उसके आकस्मिक कार्य कहा जा सकता है। आजकल मुद्रा बहुत से ऐसे कार्य करती है जो केवल वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के कारण ही उसे करने होते हैं। यह कार्य आर्थिक विकास की अन्य अवस्थाओं में मुद्रा के द्वारा नहीं किये जाते थे। सामाजिक आय का वितरण करना, साख के आधार का कार्य करना, पूँजी को तरसता प्रदान करना तथा सीमान्त उपयोगिता समान करने में सहायता देना आदि मुद्रा के इसी प्रकार के कार्य हैं।

(१) सामाजिक आय का वितरण (Distribution of Social Income)—

वर्तमान समाज में धन का उत्पादन सामूहिक रूप से होता है। वस्तुमें किसी एक व्यक्ति अथवा साधन के द्वारा पैदा न होकर उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा सम्मिलित रूप से पैदा की जाती है। सामूहिक उत्पादन को उन सब साधनों में बाँटना होता है जिन्होंने उसके उत्पादन में सहयोग दिया है। धन सामूहिक उत्पत्ति के कारण वितरण की समस्या पैदा होती है। मुद्रा संयुक्त उत्पत्ति को विभिन्न साधनों में बाँटने में सहायक होती है। मुद्रा के अभाव में संयुक्त उत्पत्ति को विभिन्न साधनों में बाँटना कठिन होता है किन्तु मुद्रा की सहायता से यह कार्य बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। विभिन्न उत्पत्ति के साधनों का हिस्सा मुद्रा में निश्चित कर लिया जाता है और उसका भुगतान वस्तुओं के रूप में न करके मुद्रा के रूप में होता है। उत्पादित वस्तुमें बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है और मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न स्थानों को भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में बड़ी सहायता करती है।

(२) मुद्रा साख का आधार है (Money forms the basis of Credit)—

वर्तमान समाज में अधिकतर भुगतान बैंक, ट्रेजरी, विदेशी विनिमय पत्र तथा अन्य प्रकार के साख पत्रों के द्वारा निबटाये जाते हैं। मुद्रा के स्थान पर साख का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उन्नत देशों में तो साख मुद्रा का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि भुगतानों को निबटाने के लिए नकद मुद्रा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। साख मुद्रा का निर्माण बैंकों के द्वारा किया जाता है। बैंक साख द्रव्य को जारी करते समय उसके पीछे एक निश्चित अनुपात में नकद मुद्रा रखते हैं। साख मुद्रा के पीछे नकद कोष इसलिए रखा जाता है जिससे बैंक, माँग होने पर साख मुद्रा को नकद मुद्रा में बदल सकें और जनता का विश्वास बैंक मुद्रा में बना रह सके। बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली साख की मात्रा उनके पास नकद मुद्रा की मात्रा के द्वारा सीमित होती है। सरकार के द्वारा जो पत्र मुद्रा चलाई जाती है, उसकी परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए भी नकद कोष रखा जाता है।

निश्चित अनुपात में नकद कोष रखकर ही पत्र मुद्रा जारी की जाती है, जिसे कि जनता का विश्वास उस प्रकार की मुद्रा में बना रह सके। यद्यपि वर्तमान समय में नकद कोषों की मात्रा बहुत कम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उनका महत्व घटता जा रहा है, फिर भी साख का निर्माण नकद कोष के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा साख के आधार का कार्य करके हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में सहायता देती है।

(३) पूँजी को सामान्य रूप प्रदान करना (Giving a general form to Capital)—मुद्रा सब प्रकार की पूँजी व सम्पत्ति को एक सामान्य रूप प्रदान करती है। पूँजी के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न वस्तुओं को अब हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। व्यक्ति अपनी आय को मुद्रा के रूप में बचाता है और इस प्रकार समाज में पूँजी का सचय मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। मुद्रा के रूप में संचित पूँजी को पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय करके उसका विनियोग किया जाता है। पूँजी को मुद्रा के रूप में रखने से उसमें तरलता (Liquidity) तथा गतिशीलता (Mobility) के गुण पैदा हो जाते हैं, जो वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में अनिवार्य हैं। इन गुणों के कारण पूँजी को नित्य नये प्रयोगों में लाया जा सकता है और उसे एक प्रयोग अथवा स्थान से हटाकर किसी अन्य प्रयोग अथवा स्थान पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा पूँजी को सामान्य रूप प्रदान करके पूँजी के सचय तथा उसके विनियोग में बड़ी सहायता प्रदान करती है।

(४) सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादकता में समानता लाना (Equalisation of marginal utility and marginal productivity)—मुद्रा उपभोक्ताओं को सम सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहायता देती है। मुद्रा द्वारा ही उपभोक्ता के लिए यह सम्भव होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न सदों पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो सके। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना सम्भव हो जाता है। उत्पात्ति के क्षेत्र में मुद्रा विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली सीमान्त उत्पादकता को समान करने में सहायता देती है। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादक विभिन्न साधनों को ठीक अनुपात में मिलाता है और उनसे सम सीमान्त उत्पात्ति प्राप्त करके अधिकतम उत्पादन करने में सफल होता है।

(५) मुद्रा शोधन क्षमता को गारन्टी करती है (Money is a Guarantee of Solvency)—केंट (Kent) के अनुसार मुद्रा हमें ऋणों का भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। जब तक किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा होती है वह अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता रखता है किन्तु मुद्रा की कमी होने पर उसकी यह शोधन क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक फर्म अपनी शोधन क्षमता (Solvency) को बनाये रखने के लिए काफी मात्रा में नकद मुद्रा अपने पास

रखती है। जब किसी फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा नहीं होती तो उसकी ऋणों का भुगतान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और फर्म को दिवालिया (Insolvent) घोषित कर देते हैं, चाहे उसके पास अन्य सम्पत्ति कितनी भी क्यों न हो। इस प्रकार मुद्रा शोधन क्षमता को बनाये रखने में सहायक होती है।

(६) मुद्रा का तरल सम्पत्ति के रूप में प्रयोग (Money as Liquid Asset)—केन्स (Keynes) ने मुद्रा का तरल सम्पत्ति के रूप में प्रयोग किया जाना उसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। मुद्रा में अन्य सम्पत्ति की अपेक्षा सबसे अधिक तरलता (Liquidity) पाई जाती है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार रहता है। मुद्रा का यह गुण ही उसे तरलता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म को आय एक निश्चित समय के पश्चात् ही प्राप्त होती है किन्तु व्यय उसे हर समय करते रहना पड़ता है। इस व्यय के लिए उसे अपनी आय का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना होता है। अपनी पूँजी को लोभ तरल रूप में इसलिए भी रखना चाहते हैं कि वे उसके द्वारा आकस्मिक व्यय को निबटा सकें। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सट्टे के दृष्टिकोण (Speculative Motive) से भी पूँजी को तरल रूप में रखना पसन्द करते हैं। इस तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म अपनी आय का एक भाग मुद्रा के रूप में रखते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। मुद्रा का तरल सम्पत्ति के रूप में प्रयोग किया जाना वर्तमान समाज के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(७) मुद्रा निर्णय का वाहक है (Money is a bearer of Option)—प्रो० ग्राहम (Graham) ने मुद्रा को निर्णय का वाहक माना है। व्यक्तियों के द्वारा मुद्रा का संचय किया जाना उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे वे कभी भी वस्तुयें तथा सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा के रूप में लोग भविष्य के लिए क्रय-शक्ति का संचय करते हैं। संचय करने वाला व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अपनी क्रय-शक्ति का एक विशेष ढंग से प्रयोग कर सकता है जिससे उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। मुद्रा की अनुपस्थिति में ऐसा करना सम्भव न था। मुद्रा के रूप में क्रय-शक्ति का संचय होने के कारण ही यह सम्भव हो सका है कि मनुष्य संचित मुद्रा का मनचाहे ढंग से व्यय कर सके।

मुद्रा का महत्व (Significance of Money)

आज का युग मुद्रा का युग है। हमारे आर्थिक जीवन के लिए मुद्रा इतनी अधिक आवश्यक है कि उसे वर्तमान समाज का जीवन रक्त कहा जा सकता है। आर्थिक जीवन के लिए मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विनिमय आज के जीवन का आधार है और वह मुद्रा की सहायता के

बिना नहीं किया जा सकता है। वडे पैमाने का उत्पादन, श्रम विभाजन, बाजारों का विस्तार, यातायात का विकास, बैंक तथा आर्थिक योजनाएँ, यह सब मुद्रा के बिना असम्भव हैं। इसीलिए प्रो० मार्शल ने मुद्रा को आर्थिक जीवन का केन्द्र माना है। उनके अनुसार 'मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ-विज्ञान केन्द्रित है। १२० आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। वह बहुत अधिक सीमा तक हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है और आर्थिक प्रगति के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोत्साहन देती है। उसके बिना हमारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन मुबारक रूप से नहीं चल सकता है। उसे अर्थ-शास्त्र का एक महान् आविष्कार कहा जा सकता है। क्रॉथर (Crowther) के अनुसार—'मुद्रा मनुष्य के समस्त अनुसन्धानों में आधारभूत है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने-अपने मूल अनुसन्धान हैं। जिस प्रकार यन्त्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में वोट आचार स्तम्भ हैं इसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यवसायिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा आवश्यक आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें आधारित हैं।' १२१

किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ की मुद्रा प्रणाली के सुव्यवस्थित होने पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। जब तक मुद्रा ठीक प्रकार से काम करती रहती है समाज में आर्थिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण रहता है और हम स्थिरता के साथ प्रगति करते चले जाते हैं। किन्तु यदि किसी देश की मुद्रा प्रणाली बिगड़ जाती है तो उस देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है और वह अवनति की ओर जाने लगता है। राबर्टसन (Robertson) के अनुसार 'मुद्रा प्रणाली एक यन्त्र की भाँति है। जब तक वह ठीक चलती रहती है तब तक हमारा अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करती है किन्तु जब उसमें कोई खराबी आ जाती है तो हम उसकी ओर काफी ध्यान देने लगते हैं।' १२२ प्रत्येक देश यह प्रयत्न करता है कि वह अपनी मुद्रा प्रणाली को नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित रखे, क्योंकि ऐसा करने से ही आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए अनुकूल दगायें उत्पन्न हो सकती हैं।

20 'It is the pivot round which the economic science clusters'

— Alfred Marshall

21 'Money is one of the most fundamental of all Man's inventions. Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In mechanics it is the wheel, in science fire, in politics the vote. Similarly, in economics, in the whole commercial side of Man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based.'

— Geoffrey Crowther : An Outline of Money, II. 4.

22 'For a monetary system is like a liver : it does not take up very much of our thoughts when it goes right, but it attracts a deal of attention when it goes wrong.'

— D. H. Robertson : Money, P. 2.

मुद्रा के इतना उपयोगी होते हुए भी कुछ अर्थशास्त्री उसे समाज के आर्थिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। वे केवल उसे आर्थिक क्रियाओं को अधिक तेजी के साथ तथा सुविधापूर्ण ढंग से करने का साधन मानते हैं। जे० एस० मिल (J. S. Mill) के अनुसार 'किसी समाज की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा से कम महत्व की वस्तु नहीं हो सकती है। यह केवल श्रम तथा नमय की वचन करने में सहायता करती है। यह उन कार्यों को सीधेता तथा सरलता से सम्पन्न करने का एक यन्त्र है जिन्हें मुद्रा के बिना कठिनाई से तथा विलम्ब से किया जा सकता है।' ¹²³ राबर्टसन (Robertson) के विचार में 'मुद्रा इतना अधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना की उसे सामान्यतः समझा जाता है किन्तु फिर भी वह अर्थ-शास्त्र के अध्ययन की एक रचिपूर्ण तथा उपयोगी शाखा है।' ¹²⁴ इन लेखकों ने मुद्रा को समाज में आवश्यकता में अधिक महत्व देने के खतरे की ओर संकेत किया है। वास्तव में, मुद्रा आधुनिक समाज के लिए कितनी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, इसे जानने के लिए हमें मुद्रा से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों का अध्ययन करना होगा। मुद्रा के महत्व को उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के क्षेत्रों में स्वीकार किया जाता है। वह वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करके वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को अधिक कार्यक्षमता के साथ चलाने में सहायक होती है। चाहे पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था हो या समाजवादी, नियोजित अर्थ-व्यवस्था हो या मिश्रित, सभी प्रकार के समाजों में मुद्रा एक विशेष महत्व रखती है। कोई भी आधुनिक समाज मुद्रा के बिना नहीं चल सकता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के महत्व का विश्लेषण करके हम वर्तमान समाज में मुद्रा की उपयोगिता को भली प्रकार समझ सकते हैं।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का महत्व

(Importance of Money in a Capitalist Society)—

मुद्रा को पूँजीवादी समाज का आधार कहा जा सकता है। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था मुद्रा पर आधारित होती है और प्रत्येक प्रकार के आर्थिक निर्माण मुद्रा की सहायता से किये जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) के द्वारा उत्पादन व्यवस्था का निर्देशन करते हैं। जिन वस्तुओं को वे अधिक खरीदना चाहते

23 'There cannot intrinsically be a more insignificant thing in the economy of a society than money except in the character of a contrivance of sparing time and labour. It is a machine for doing quickly and commodiously, what would be done though less quickly and commodiously without it.'

—J. S. Mill : Principles of Political Economy, Book III chap. VII.

24 'Money is not such a vital subject as is often supposed; nevertheless it is an interesting and important branch of study of Economics.'

—D. H. Robertson : Money, P. 1.

हैं, उनके लिए अधिक मूल्य देकर वे उत्पादकों को इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिन वस्तुओं के मूल्य नीचे रहते हैं उनका उत्पादन नहीं किया जाता है। इस प्रकार मूल्य-यन्त्र के द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था को नियन्त्रित किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न प्रयोगों में वितरण भी उन्हें दिये जाने वाले मूल्य के आधार पर हो जाता है। समाज में उत्पादित वस्तुओं का वितरण मूल्य-यन्त्र की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) का एक विशेष महत्व है और मूल्य-यन्त्र मुद्रा की सहायता के बिना नहीं चल सकता है। एरिक रोल (Eric Roll) के अनुसार 'मुद्रा उस यन्त्र का अनिवार्य अंग है जो अनियोजित समाज को नियन्त्रित करता है'।²⁵ मूल्य के द्वारा उपभोक्ता अपनी मांग को सूचित करते हैं और मूल्य की सहायता से उत्पादक यह निश्चय करते हैं कि उन्हें क्या पैदा करना है। मूल्य-यन्त्र, उत्पत्ति, उपभोग, बचत, विनियोग तथा अन्य सभी आर्थिक क्रियाओं को निश्चित करता है। ए० पी० लर्नर (A. P. Lerner) ने मूल्य-यन्त्र के महत्व को बतलाते हुए कहा है—'किसी भी जटिल अर्थ-व्यवस्था के लिए मूल्य-यन्त्र के बिना सामान्य क्षमता के साथ चलना असम्भव है'।²⁶ वर्तमान समाज में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में निश्चित किये जाते हैं इसलिए मुद्रा पूँजीवादी समाज का मुख्य आधार है और उसे हमारी अर्थ-व्यवस्था का रक्त कहा जा सकता है। पॉल ट्रेसकोट (Paul Trescott) के अनुसार—'मुद्रा यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था का हृदय नहीं है तो वह उसका रक्त प्रवाह प्रणाली है'।²⁷ आधुनिक पूँजीवादी समाज में मुद्रा के प्रयोग से प्राप्त होने वाले कुछ निश्चित लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ—मुद्रा क्रय-शक्ति को सामान्य रूप प्रदान करती है जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वे अपने धन को जिस प्रकार चाहे व्यय करें। मुद्रा की अनुपस्थिति में मनुष्यों को कुछ वस्तुयें आवश्यकता से अधिक और कुछ कम लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था, किन्तु अब वे मुद्रा की सहायता से ठीक अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुयें प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वस्तुओं का अपव्यय काफी सीमा तक बच जाता है। समाज के द्वारा इस बात का अनुमान लगाया सम्भव हो गया है कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं। रावर्टसन के अनुसार

25 Thus money is 'indispensable part of the mechanism which regulates an otherwise planless society' —Eric Roll, *About Money*, P 33-34.

26 'It is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency without a price-mechanism.' —A. P. Lerner.

27 'If money is not the heart of our economic system, it can certainly be considered its blood stream.'

—Paul B. Trescott *Money, Banking and Economic Welfare*, P. 3

‘मुद्रा अर्थ-व्यवस्था का होना समाज को इस बात का पता लगाने में सहायता करता है कि लोग क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं तथा इस बात का निश्चय करने में कि क्या पैदा किया जायगा और कितना जिससे कि वह अपनी सीमित उत्पादन शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग कर सके।’^{२८} मुद्रा के रूप में उपभोक्ता के पास ऐसी सामान्य क्रय-शक्ति आ गई है जिसके द्वारा उसे प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने का अधिकार मिला जाता है और वह विभिन्न स्थानों पर वनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। वस्तुओं को खरीदी जाये, कहाँ से खरीदी जाये तथा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और गुण के बारे में मुद्रा उपभोक्तानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करती है। मुद्रा की सहायता से मनुष्य अपने व्यय से अधिक से अधिक सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता अपनी आय को मुद्रा के रूप में सम-सामान्त उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय करके अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। मुद्रा समाज के प्रत्येक सदस्य को यह अवसर देती है कि वह सन्तुष्टि के उपलब्ध साधनों से अधिक से अधिक वास्तविक लाभ उठा सके।

(२) मुद्रा से उत्पादकों को लाभ—वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादकों के लिए मुद्रा विशेष महत्व रखती है। मुद्रा के प्रयोग के द्वारा उत्पादक के लिए यह सम्भव हो सका है कि वह अपना समस्त ध्यान उत्पादन सम्बन्धी बातों पर ही केन्द्रित रखे जिससे कि समाज में अधिक वस्तुओं तथा सेवायें पैदा की जा सकें। अब उसे अपना समय उत्पत्ति के साधनों का भ्रुगतान करने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करने में लपट नहीं करना पड़ता है क्योंकि समस्त भ्रुगतान मुद्रा के द्वारा निबटाया जाते हैं। मुद्रा की सहायता से उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की ऐसी व्यवस्था करना सम्भव हो सका है जिससे कि अधिकतम उत्पादन किया जा सके। एच० जी० मोल्टन (H. G. Moulton) के अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्रित करने के लिए मुद्रा एक अनिवार्य आवश्यकता है।^{२९} मुद्रा के कारण ही

28 ‘The existence of a monetary economy helps society to discover what people want and how much they want it; and so to decide what shall be produced and in what quantities and to make the best use of its limited productive power.’
—D. H. Robertson : Money, P. 5.

29 “Money is the indispensable pre-requisite to the assembling of the concrete instruments of production. The businessman uses money, or its equivalent to purchase materials for the construction of his factory; he uses money in buying the supplies and materials necessary for its equipment; he bids competitively in the markets of the world for the raw materials used in the process of manufacturing, and employs money as a means of attracting to his organisation the requisite labour force and corps of administrative officials.”

—H. G. Moulton : The Financial Organisation of Society, 3rd ed. P. 3.

श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण सम्भव हो सका है जिससे अधिक और सस्ती वस्तुयें पैदा की जाती हैं। बेन्हाम (Benham) के अनुसार 'विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना असम्भव है।'³⁰ राबर्टसन (Robertson) ने भी मुद्रा को श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लिए आवश्यक माना है। उनके अनुसार 'यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकांश समय उत्पादित वस्तुओं की अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के साथ बदलने में नष्ट करना पड़ता है तो विशिष्टीकरण तथा श्रम-विभाजन, जिन पर हमारा आर्थिक जीवन आधारित है, असम्भव हो जायेंगे।'³¹ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज की उत्पादन प्रणाली में मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुद्रा के द्वारा श्रमिकों तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों का भुगतान किया जाता है, उनकी सहायता से बचत तथा विनियोग करना आसान हो गया है और वह वर्तमान सात व्यवस्था का आधार है।

(३) मुद्रा ऋणों के लेन-देन तथा अग्रिम भुगतानों को सुविधापूर्ण बनाती है—आज की उत्पादन व्यवस्था ऋणों के लेन-देन तथा अग्रिम भुगतानों (Advance Payments) पर आधारित है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व काफी धन की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह मशीनें तथा कच्चा माल खरीदता है, श्रमिकों को काम पर लगाता है और अपने उद्योग के दैनिक भुगतानों को निभटाता है। यह सब धन अधिकांश रूप से ऋणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन भी एक प्रकार का अग्रिम भुगतान है जो उन्हें पूँजीपति उन वस्तुओं के बदले में देता है जो उनके द्वारा पैदा की जा रही हैं। इस प्रकार के अग्रिम भुगतान मुद्रा की सहायता के बिना सम्भव नहीं हैं। मुद्रा की अनुपस्थिति में ऋणों का लेन-देन इतनी अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता था। मुद्रा ऋणों के लेन-देन को सम्भव करके वर्तमान समाज की आर्थिक मशीन को सुचारु रूप से चलाने में बड़ी सहायता करती है।

(४) मुद्रा पूँजी को गतिशीलता प्रदान करती है—आजकल पूँजी का विनियोग मुद्रा के रूप में किया जाता है और उस पर शान्त होने वाले ध्याज का भुगतान भी मुद्रा के द्वारा ही होता है। मुद्रा एक तरल सम्पत्ति है जिसे आसानी से बैंकों में जमा किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के विनियोगों में लगाया जा सकता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलतापूर्वक हस्तान्तरित किया जा

■ "Modern economic life which is founded on specialisation would not be possible without money" —Benham Economics, P 427

31 "The specialisation and division of labour on which our economic structure is founded would be impossible if every man had to spend a large part of his time and energies in bartering his products for the materials of his industry and the goods which he requires for his own consumption"

—D. H. Robertson : Money, P 7

सकता है। मुद्रा के रूप में पूँजी का होना उसे गतिशीलता प्रदान करता है जिसके कारण पूँजी को एक विनियोग से हटाकर दूसरे विनियोग में आसानी से लगाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। विनियोग करने वाला जब चाहे अपनी पूँजी को विनियोग से निकाल सकता है। पूँजी की इस गतिशीलता के कारण समाज को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मुद्रा केवल पूँजी को गतिशीलता ही प्रदान नहीं करती है बल्कि वह समाज में वचन तथा विनियोग को भी प्रोत्साहित करती है। लोग आसानी से मुद्रा के रूप में अपने धन को बचा सकते हैं तथा उसे लाभपूर्ण विनियोग में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा आर्थिक विकास की आधारभूत दशायें उत्पन्न करती है।

(५) मुद्रा आर्थिक विकास की दशायें उत्पन्न करती है—मानव समाज की आर्थिक प्रगति मुद्रा के विकास के साथ सम्बन्धित रही है। मुद्रा के आविष्कार तथा विकास के साथ ही आर्थिक प्रगति का युग आरम्भ होता है। मुद्रा रहित समाज प्रायः पिछड़ी हुई दशा में रहते थे। मुद्रा ने समाज में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा किया है तथा लोगों को प्रगति करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन (Economic Incentive) भी दिया है। आज की जटिल अर्थ-व्यवस्था तथा प्रगतिशील उत्पादन प्रणाली मुद्रा के बिना असम्भव प्रतीत होती है। अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखने तथा उसमें स्थिरता स्थापित रखने के लिए मुद्रा एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी देश की मुद्रा प्रणाली का वहाँ के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा को आर्थिक विकास का सूचक (Index) भी माना जा सकता है। किसी देश की मुद्रा प्रणाली को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह देश आर्थिक विकास की किस अवस्था में है। आधुनिक एवं सुसंगठित मुद्रा प्रणाली का होना देश के प्रगतिशील होने का सूचक है।

(६) मुद्रा आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्वतन्त्रताएँ मुद्रा के कारण ही सम्भव हो सकी हैं। उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा श्रमिकों की विभिन्न स्वतन्त्रताएँ मुद्रा के बिना संभव नहीं हो सकती हैं। उपभोग सम्बन्धी स्वतन्त्रता तथा उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता (Sovereignty of the Consumer) मुद्रा के कारण ही स्थापित की जा सकी है। उत्पादन प्रणाली का स्वतन्त्र रूप भी बहुत कुछ मुद्रा की देन है। डा० मार्शल के अनुसार 'मुद्रा अर्थ-व्यवस्था के विकास में ही आज की स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली को सम्भव किया है।' श्रमिकों की व्यवसाय चुनने की आजादी भी मुद्रा के कारण सम्भव हो सकी है। आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ मुद्रा ने सामाजिक स्वतन्त्रता को स्थापित करने में भी बड़ा योग दिया है। दास प्रथा का अन्त तथा श्रमिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ मुद्रा की देन है। जब तक लगान और मजदूरी का मुगलान वस्तुओं के रूप में होता था, श्रमिकों तथा किसानों को पूँजीपतियों व भू-स्वामियों के अधीन रहना पड़ता था किन्तु

अब लगान और मजदूरी मुद्रा के रूप में दिये जाने के कारण इन वर्गों को सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई।

समाजवादी समाज और मुद्रा (Money in a Socialist Society)—

समाजवादी व्यवस्था केन्द्रीय निर्देशन एवं नियोजन पर आधारित होती है। उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार होता है और उनका प्रयोग जनहित के लिए किया जाता है। कोनसी वस्तुएँ पैदा की जानी है और कितनी मात्रा में उनकी उत्पादन किया जाना है इसका निर्णय मूल्य-यन्त्र के द्वारा न होकर सरकार के द्वारा किया जाता है। अतः समाजवादी समाज में मूल्य-यन्त्र का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है जितना की पूँजीवादी व्यवस्था में है किन्तु फिर भी समाजवादी व्यवस्था मूल्य-यन्त्र की सहायता के बिना नहीं चल सकती है। मुद्रा प्रणाली और समाजवादी व्यवस्था परस्पर विरोधी नहीं हैं। कुछ समाजवादी लेखकों के अनुसार पूर्ण समाजवाद में मुद्रा का कोई स्थान नहीं है और समाजवाद की स्थापना के साथ मुद्रा की समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि समाज को मुद्रा के दोषों से मुक्त किया जा सके। कुछ समाजवादी देशों में मुद्रा को समाप्त करने के प्रयत्न भी किये गये किन्तु वे अधिक सफल नहीं हो सके हैं।

अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि समाजवादी व्यवस्था भी मुद्रा के बिना कुशलतापूर्वक नहीं चल सकती है। आधुनिक समाजवादी लेखकों के अनुसार समाजवाद में भी आर्थिक निर्णय करने के लिए मूल्य-यन्त्र की आवश्यकता होती है। यद्यपि मूल्य-यन्त्र आर्थिक व्यवस्था का नियन्त्रक नहीं होता है किन्तु उसका प्रयोग एक उपयोगी यन्त्र के रूप में अवश्य किया जा सकता है। समाजवादी समाज में भी नियोजन सत्ता (Planning Authority) के सम्मुख चुनाव की समस्या रहती है। अल्प साधनों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाँटना होता है, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य निश्चित करने होते हैं तथा साधनों के बटवारे की विभिन्न योजनाओं की तुलना करनी होती है। यह सब कुछ मूल्य-यन्त्र की सहायता से ही किया जाना है। साधनों के विवेकपूर्ण तथा आदर्श उपयोग के लिए आर्थिक हिसाब (Economic Calculation) आवश्यक है जो केवल मुद्रा तथा मूल्य-यन्त्र की महामता से ही सम्भव है। समाजवादी नियोजन में मुद्रा की प्रतिधार्यता को ट्रॉट्स्की (Trotsky) ने भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार, “सरकारी कार्यालयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं (blueprints) को भी अपनी आर्थिक उपयुक्तता व्यवसायिक गणनाओं (Commercial Calculations) के द्वारा स्थापित करनी चाहिए। एक स्थिर मौद्रिक इकाई के बिना इस प्रकार की गणनाएँ समाज में केवल अव्यवस्था को बढ़ा सकती हैं।”³² लैनिन (Lenin) जैसे महान् साम्यवादी नेता भी समाजवादी

32 “The blueprints produced by offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculation. Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos.”

अर्थ-व्यवस्था के लिए मुद्रा को आवश्यक समझते थे। इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्री भी एक मत हैं कि आर्थिक हिसाब (Economic Calculation) के बिना कोई भी जटिल अर्थ-व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है और आर्थिक हिसाब के लिए मुद्रा का होना आवश्यक है। हॉम (Halm) ने समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा के महत्व को बताते हुये लिखा है कि "यदि उत्पादन सख्य एक डिक्टेटर (Dictator) के द्वारा निश्चित किये जायें तब भी इन लक्ष्यों के अनुसार साधनों का बंटवारा मूल्य-यन्त्र (Price mechanism) के द्वारा ही किया जायेगा क्योंकि उसकी सहायता से ही विभिन्न प्रयोगों में उपलब्ध साधनों की उपयोगिता की तुलना की जा सकती है।" 33 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी समाज में भी मुद्रा की उपयोगिता कम नहीं है और उसे एक सामपूर्ण सस्था के रूप में जारी रखा जा सकता है। यही कारण है कि रूस, युगोस्लेविया, पोलैंड तथा चीन जैसे समाजवादी देशों में भी मुद्रा तथा मूल्य-यन्त्र का प्रयोग बराबर किया जा रहा है।

मुद्रा के दोष (Evils of Money)—

उपरोक्त कथन से प्रतीत होता है कि मुद्रा प्रत्येक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह आज के आर्थिक जीवन की मुख्य चालक शक्ति है। यद्यपि मुद्रा मनुष्य मात्र के लिए एक बहुत बड़ी देन है किन्तु उसका प्रयोग दोषरहित नहीं है। जब कभी भी वह नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो हमारा आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और प्रगति रुक जाती है। इसलिए कभी-कभी यह कहा जाता है कि मुद्रा समाज में घुराई का प्रतीक है। मुद्रा के कारण समाज में बहुत से आर्थिक तथा सामाजिक दोष उत्पन्न होते हैं। मुद्रा समाज के लिए तभी तक उपयोगी है जब तक कि हम उसकी बुराइयों से बच सकते हैं किन्तु यदि वह हमारे ऊपर अपना बुरा प्रभाव डालने में कामयाब हो जाती है तो वह समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। मुद्रा समाज में निम्नलिखित दोषों को उत्पन्न कर सकती है—

(१) मुद्रा एक बहुत बड़ा धोखा है—प्रायः लोग मुद्रा और क्रय-शक्ति में भेद नहीं कर पाते हैं और मुद्रा के टुकड़ों की ही वस्तुयें तथा सेवायें समझ बैठते हैं जबकि वे केवल उन्हें प्राप्त करने का साधन मात्र हैं। मुद्रा प्रणाली में हमारी आर्थिक क्रियायें मुद्रा के पर्दे से इस प्रकार छुपी रहती हैं कि हम उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते हैं। ऋणों का लेन-देन, बचत तथा विनियोग की क्रियायें सब मुद्रा

33 "Even if the aims of production should be determined by a dictator, the allocation of resources according to these aims would have to be the result of the working of a pricing process by means of which it is possible to compare the usefulness of the available resources in different fields of employment."

—George N. Halm : Monetary Theory, 2nd ed. P. 13.

की सहायता से की जाती हैं जिसके कारण कभी-कभी विशेष बुराई पैदा हो जाती है। कई बार ऐसी वस्तुएँ उधार दे दी जाती हैं जिनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। मुद्रा प्रसार के समय में ऐसा ही होता है। मुद्रा की मात्रा वस्तुओं की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ती है, मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती है किन्तु वस्तुएँ प्राप्त न होने के कारण विशेष कठिनाई होती है।

(२) मुद्रा का मूल्य निश्चित नहीं रहता है—मुद्रा के प्रयोग से सबसे बड़ा दोष उसका मूल्य निश्चित न रहने के कारण पैदा होता है। यद्यपि मुद्रा मूल्य मान तथा ऋणों के अन्तिम भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है किन्तु अपना मूल्य स्थिर न रहने के कारण वह इन कामों को भली प्रकार नहीं कर पाती है। यदि मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का सब लोगो पर एक-सा प्रभाव पड़े तो कोई बुराई नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है और मुद्रा के मूल्य परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न लोगो पर भिन्न-भिन्न पड़ता है। कुछ लोगों को आकस्मिक लाभ होते हैं और कुछ को अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। समाज में धन का वितरण बदल जाता है और इन प्रकार मुद्रा के प्रयोग से सामाजिक अन्याय का जन्म होता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का उत्पात्ति के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा सकुचन के कारण उत्पादन का गिरना तथा बेकारी की समस्या पैदा हो जाती है और मुद्रा प्रसार के समय अत्यधिक उत्पादन, गिरती हुई वास्तविक माप तथा आवश्यकता से अधिक विनियोग के कारण अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा का मूल्य जल्दी-जल्दी बदलने से आर्थिक जीवन में अनिश्चिन्ता पैदा होती है जिसका आर्थिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(३) मुद्रा के कारण व्यापार-चक्र आते हैं—मुद्रा रहित समाज में जो कुछ बचत की जाती थी उस सबका विनियोग कर दिया जाता था और किसी प्रकार के असंतुलन का भय नहीं रहता था। किन्तु वर्तमान समाज में मुद्रा का प्रयोग होने के कारण समस्या बहुत जटिल हो गई है। बचत और विनियोग मुद्रा के रूप में किया जाता है और बचत तथा विनियोग करने वाले व्यक्ति अलग-अलग होने हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कभी विनियोग की मात्रा बचत की अपेक्षा अधिक हो जाती है और कभी बचत की मात्रा विनियोग से अधिक। इस प्रकार के असंतुलन के कारण ही व्यापार-चक्र आते हैं जो आज के आर्थिक जीवन का अभिशाप बन गये हैं।

(४) मुद्रा ने पूँजीवाद की दोषपूर्ण प्रणाली को जन्म दिया है—वर्तमान पूँजीवाद का विकास बहुत कुछ मुद्रा के कारण ही सम्भव हो सका है। घट. मुद्रा पूँजीवादी व्यवस्था के समस्त दोषों के लिए भी जिम्मेदार है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पात्ति के साधन कुछ लोगों के हाथों में ही एकत्रित हो जाते हैं। आर्थिक क्रियामें केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है और समाज में धन का वितरण असमान रहता है और अधिकांश लोगों के साथ सामाजिक न्याय

नहीं किया जाता है। यह सब दोष मुद्रा के प्रयोग के कारण ही पैदा हुये हैं। एक मुद्रा रहित समाज पूँजीवाद के इन दोषों से प्रायः मुक्त रहता था। मुद्रा के कारण ही विभिन्न प्रकार के पूँजीवादी शोषण सम्भव हो सके हैं।

(५) मुद्रा के सामाजिक दोष—मुद्रा केवल आर्थिक घुसाइयों के लिए ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि हमारा सामाजिक तथा नैतिक पतन भी बहुत कुछ मुद्रा के कारण ही हुआ है। मुद्रा ने हमारा ध्यान लक्ष्यों से हटाकर साधनों पर केन्द्रित कर दिया है। प्राचीन नैतिक विचारों का स्थान अधिक मुद्रा कमाने ने ले लिया है। आज मनुष्य मुद्रा का उपासक बन गया है और उसे प्राप्त करने के लिए चोरी, जालसाजी, बेईमानी तथा अन्य प्रकार के अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा आज वस्तुओं तथा सेवाओं को ही नहीं मापती है बल्कि व्यक्तियों का माप भी बन गई है। मुद्रा पर आधारित आज की सभ्यता सामाजिक तथा नैतिक भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई है। रस्किन (Ruskin) के अनुसार 'मुद्रा दानव ने आत्माओं पर अधिकार कर लिया है और कोई भी धर्म तथा दर्शनशास्त्र उसे बाहर निकालने की शक्ति रखता हुआ प्रतीत नहीं होता है।'³⁴ मुद्रा के सामाजिक तथा नैतिक दोषों की व्याख्या करते हुए वॉन मीजेज (Von Mises) ने लिखा है कि 'मुद्रा को चोरी, हत्या, छल तथा प्रतिज्ञा भंग करने का कारण माना जा सकता है। जब वैश्या अपना शरीर भ्रष्टा न्यायाधीश अपना न्याय बेचता है तो मुद्रा को ही दोष दिया जाता है। चरित्रवादी जब अत्यधिक भौतिकवाद की आलोचना करना चाहता है तो वह मुद्रा का विरोध करता है। प्रत्येक प्रकार के लालच को मुद्रा-प्रेम कहा जा सकता है तथा सब घुसाइयों को लालच से उत्पन्न हुआ मानना काफी ठीक है।'³⁵

मुद्रा का नियन्त्रण (Control of Money) —

उपरोक्त दोषों के आधार पर कभी-कभी यह कह दिया जाता है कि मुद्रा मनुष्य के लिए अभिशाप बन गई है। वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश दोष मुद्रा के दुरुपयोग के कारण पैदा होते हैं। यदि मुद्रा का उचित प्रयोग किया जाय तो वह मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मुद्रा के दोष उससे प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा बहुत कम हैं और उन्हें मुद्रा के सही प्रबन्ध के द्वारा दूर किया जा सकता है। मुद्रा कोई स्वयं दोषपूर्ण वस्तु

34 'The devil of money has come to possess their souls. No religion or philosophy seems to have the power of driving it out.' —Ruskin.

35 'Money is regarded as the cause of theft and murder, of deception and betrayal. Money is blamed when the prostitute sells her body and when the bribed judge perverts the law. It is money against which the moralist declaims when he wishes to oppose excessive materialism. Significantly enough avice is called the love of money and all evil is attributed to it.'

—Ludwig Von Mises : The Theory of Money and Credit, P. 93.

नहीं है। किन्तु यदि हम ठीक प्रकार में उमका प्रबन्ध नहीं करते हैं तो वह नियन्त्रण से बाहर हो जाती है और उमके कारण समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रा का सही प्रबन्ध किया जाय तथा उसे उचित नियन्त्रण में रखा जाय। ऐसा करने में मुद्रा को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। मुद्रा का नियन्त्रण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इतिहास इस बात का माक्षी है कि मुद्रा कभी भी नियन्त्रण से बाहर हो सकती है और समाज के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 'मुद्रा एक अच्छा सेवक है किन्तु बुरा स्वामी'।³⁵ अनियन्त्रित मुद्रा समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है। राबर्टसन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'मुद्रा जो मानव समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, यदि हम उसे अनियन्त्रित नहीं करते हैं तो वह अव्यवस्था तथा कठिनाइयों का कारण भी बन सकती है'।³⁶ जब तक मुद्रा को नियन्त्रण में रखा जाता है तब तक वह आर्थिक जीवन में एक उपयोगी सत्ता का काम देती है किन्तु नियन्त्रण से बाहर होते ही वह समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। मुद्रा के दोषों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की मात्रा पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाय। मुद्रा का उचित प्रबन्ध तथा नियन्त्रण मुद्रा अधिकारियों का काम है क्योंकि मुद्रा अपना प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकती है।³⁷ अतः यह कहा सकता है कि मुद्रा को उसके दोषों के कारण त्यागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उमका सही प्रबन्ध होने की आवश्यकता है जिससे कि उसके दोषों से बचा जा सके।

मुद्रा और आर्थिक विकास—

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को निष्क्रिय माना है। उनके अनुसार वह केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और समाज में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकती है। वर्तमान अर्थशास्त्री इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार मुद्रा केवल आर्थिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलने में सहायता ही नहीं करती है बल्कि वह उन्हें सीधा प्रभावित भी कर सकती है। आज के समाज में इस गतिशील कार्य (Dynamic Role) के कारण मुद्रा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समाज में मुद्रा उत्पत्ति तथा रोजगार की मात्रा को प्रभावित कर सकती है। मुद्रा की सहायता से समाज में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, रोजगार के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं तथा लोगों की आय में वृद्धि कर सकते

35 'Money is a good servant but a bad master.'

37 'Money which is a source of so many blessings to mankind, becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion.'

—D. H. Robertson . Money, P. 16

38 'Money will not manage itself.'

—Walter Bagehot.

है। इस प्रकार मुद्रा हमारी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को सीधा प्रभावित कर सकती है।

आजकल मुद्रा को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। स्त्रोपतया पत्र मुद्रा का प्रयोग अल्प विकसित देशों के विकास के लिए किया जा सकता है। यद्यपि पत्र मुद्रा स्वयं पूँजी नहीं है किन्तु वह समाज में पूँजी को कार्य-शील करती है। उसके द्वारा बेकार साधनों को काम में लगाया जा सकता है और उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। जिन देशों में उत्पत्ति के साधन बेकार पड़े हैं वहाँ पर कागजी मुद्रा का विस्तार करके इन साधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि नई मुद्रा का प्रयोग कारखाने लगाने, विकास योजनाओं को बनाने अथवा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह मुद्रा का गतिशील कार्य (Dynamic Role) है। बेकार साधनों के काम में लगाने से उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है, लोगों को अधिक रोजगार मिलता है तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार पत्र मुद्रा का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है किन्तु मुद्रा के इस प्रकार के प्रयोग में मुद्रा स्फीति का भय रहता है इसलिए आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का विस्तार नियन्त्रित तथा नियमित गति से किया जाना चाहिए।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) "मुद्रा एक अच्छा सेवक है किन्तु बुरा स्वामी है।" व्याख्या कीजिये।
(आगरा बी० ए० १९६४, सागर बी० ए० १९५७)
- (२) "मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है।" इस कथन को पूर्णतः समझाइये। यदि अचानक ही मुद्रा लुप्त हो जाय तो इसका क्या परिणाम होगा?"
(आगरा बी० ए० १९६३ व १९५६, पटना १९५५, आगरा बी० काम० १९५६)
- (३) समाज में मुद्रा के आर्थिक महत्व को समझाइये।
(आगरा बी० ए० १९६२)
- (४) मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का स्पष्ट वर्णन कीजिये। उन्हें आकस्मिक क्यों कहा जाता है तथा मुद्रा के अन्य कार्य क्या हैं?
(आगरा बी० काम० १९६०)
- (५) मुद्रा की आलोचनात्मक परिभाषा कीजिये तथा उसकी प्रकृति को समझाइये।
(आगरा बी० काम० १९५६)

- (६) मुद्रा से घाय क्या समझते हैं ? एक प्राधुनिक समाज में इसके मुख्य कार्यों पर प्रकाश डालिये । (भागरा बी० काम० १९५८)
- (७) मुद्रा के आर्थिक प्रभावों का विवेचन करिये । (राजस्थान बी० ए० १९५८)
- (८) मुद्रा की परिभाषा करिये और उसके कार्यों पर प्रकाश डालिये ? (राजस्थान बी० ए० १९५६)
- (९) डच अर्थशास्त्री एन० जी० पिपर्सन ने मुद्रा की उपमा किसी स्टेशन पर शान्तिग कर रहे इन्जिन से दी है, जो एक समय डिब्बों की किसी पंक्ति को खींचता है और दूसरे समय दूसरी पंक्ति को ढकेलता है, इसका काम प्रत्येक डिब्बे को सहो-सहो पटरों पर लाना होता है, ताकि वह अपने स्थान पर पहुँच जाय । इसकी व्याख्या कीजिये और मुद्रा के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये । (सागर बी० काम० १९५५)
- (१०) मुद्रा के कार्यों को पूर्ण व्याख्या कीजिये । उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को इसके लाभों को पूर्णतया समझाइये । (विक्रम बी० ए० १९५६, भागरा बी० ए० १९६०)
- (११) “मुद्रा के आविष्कार ने बहुत सीमा तक आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया है ।” विवेचन कीजिये । क्या आप प्राधुनिक युग में एक निष्पक्ष मुद्रा की कल्पना कर सकते हैं ? (बिहार बी० काम० १९५६)
- (१२) एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के कार्य तथा उसके महत्व को समझाइये । (राजस्थान बी० ए० १९५४)
- (१३) वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के महत्व को बतसाइये । (असोवर्ग बी० ए० १९५६)
- (१४) मुद्रा की परिभाषा कीजिये । तरल सम्पत्ति में रूप में उसके महत्व की व्याख्या कीजिये । (भागरा बी० ए० १९६० स)
- (१५) मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण एवं विवेचन करिये और यह दिखाइये कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा उत्पादन एवं विनिमय किस प्रकार आसान हो गये हैं ? (बिहार बी० काम० १९५८)



मुद्रा का वर्गीकरण

KINDS OF MONEY

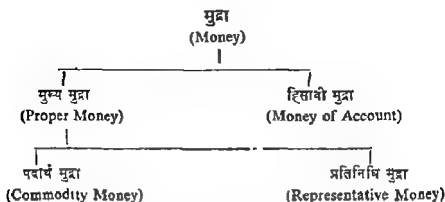
मुद्रा की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मुद्रा के वर्गीकरण के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है तथा अनेक प्रकार की मुद्रा की प्रकृति एवं गुण क्या हैं ? विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोणों से किया है। मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण निम्नलिखित हैं—

- (अ) वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा (Actual Money and Money of Account) ।
- (ब) विधिग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा (Legal Tender Money and Optional Money) ।
- (स) धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा (Metallic Money and Paper Money) ।

(अ) वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा

(Legal Tender Money and Money of Account)

लार्ड केन्स (Lord Keynes) ने वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा में सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण भेद किया है। उनके अनुसार मुद्रा दो प्रकार की हो सकती है—(i) मुख्य मुद्रा (Money Proper) तथा (ii) हिसाबी मुद्रा (Money of Account)। प्रो० सेलिगमैन (Seligman) ने उन्हें वास्तविक मुद्रा तथा आदर्श मुद्रा (Ideal Money) कहा है और बेनहाम (Benham) के अनुसार उन्हें चलन की इकाई (Unit of Currency) तथा हिसाब की इकाई (Unit of Account) कहा जा सकता है। केन्स (Keynes) के अनुसार दिया गया मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है—



मुख्य मुद्रा (Proper Money)—प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार वास्तविक मुद्रा वह है जिसको देकर सब प्रकार के भुगतानों को निबटाया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है।¹ जितने प्रकार की मुद्रा चलन में होती है वह सब ही वास्तविक मुद्रा है। जिस मुद्रा के देने से ऋणों को चुकाया जाता है अथवा वस्तुओं के मूल्यों का भुगतान होता है, उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। भारतवर्ष में रुपये तथा पैसे के समस्त सिक्के एवं चलन में रहने वाले विभिन्न प्रकार के करसी नोट वास्तविक मुद्रा हैं। इसी प्रकार अमेरिका में डालर तथा सेंट के सिक्के और डालर नोट वास्तविक मुद्रा है। अतः वास्तविक मुद्रा वह है जिसका विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए वास्तव में प्रयोग किया जाता हो।

हिसाबी मुद्रा (Money of Account)—हिसाबी मुद्रा वह है जो चलन में नहीं रहती है और जिसका प्रयोग केवल लेखे की इकाई के रूप में किया जाता है। इस मुद्रा के रूप में वस्तुओं के मूल्य बताये जाते हैं तथा ऋणों का हिसाब-किताब रखा जाता है। केन्स (Keynes) के अनुसार 'हिसाबी मुद्रा वह है जिसमें ऋणों, कीमतों तथा सामान्य क्रय-शक्ति को व्यक्त किया जाता है।'² हिसाबी मुद्रा का प्रयोग केवल हिसाब-किताब रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की मुद्रा का वास्तविक रूप से चलन में रहना आवश्यक नहीं है। हिसाबी मुद्रा वास्तविक मुद्रा का वर्णन मात्र है। वास्तविक मुद्रा वह वस्तु है जो इस वर्णन की व्यावहारिक रूप देती है।³ जब यह कहा जाता है कि अमुक वस्तु का मूल्य २५ रुपये है अथवा

1 "Money itself is that by delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged, and in the shape of which a store of General Purchasing Power is held"—J. M. Keynes. A Treatise on Money, vol I, P. 3.

2 "Money-of-Account is that in which Debts and General Purchasing Power are expressed." —J. M. Keynes. A Treatise on Money, vol. I, P. 3.

3 "Money of account is the description or title and the money is the thing which answers to the description"

—J. M. Keynes. A Treatise on Money, vol I, P. 4.

अमुक व्यक्ति को १०० रुपये का ऋण देना है तो यहाँ पर रुपया हिसाबी मुद्रा का कार्य करता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही नेखे की इकाई के रूप में रुपया, आने, पाई का प्रयोग होता रहा है किन्तु धन उसके स्थान पर रुपये और पैसे का प्रयोग आरम्भ हो गया है।

वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा का अन्तर इतना सूक्ष्म है कि साधारण व्यक्ति के लिए उसे समझना कठिन है। वास्तविक मुद्रा से तो हम सब लोग परिचित हैं कि हिसाबी मुद्रा केवल एक सैद्धान्तिक तथ्य है। हिसाबी मुद्रा वास्तविक मुद्रा का केवल एक वर्णन मात्र है। वास्तविक मुद्रा चलन में रहने वाली मुद्रा का व्यवहारिक रूप है और हिसाबी मुद्रा उसका सैद्धान्तिक रूप है। वास्तविक मुद्रा में परिवर्तन हो सकता है। उसका वजन, आकार तथा उसमें पाई जाने वाली वस्तु बदल सकती है किन्तु हिसाबी मुद्रा में परिवर्तन नहीं होता है। भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से हिसाबी मुद्रा रुपया खली आ रही है किन्तु चलन में रहने वाली वास्तविक मुद्रा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। बहुत समय पहले रुपया शुद्ध चाँदी का होता था, फिर धीरे-धीरे चाँदी की मात्रा कम होती गई और आज रुपया कागज अथवा गिल्ट का होता है। साधारणतः प्रत्येक देश में जिस मुद्रा का प्रयोग विनिमय माध्यम के रूप में तथा अर्थ सचय के लिए किया जाता है, वही मुद्रा हिसाब-किताब रखने के काम में भी लाई जाती है। परन्तु कभी-कभी हिसाबी मुद्रा और वास्तविक मुद्रा पृथक् भी हो सकती है। इंग्लैंड में बहुत समय तक वस्तुओं का मूल्य गिन्नी में बताने का रिवाज था और वह हिसाबी मुद्रा का कार्य करती थी पर वास्तव में गिन्नी का सिक्का चलन में नहीं था और पौड वास्तविक मुद्रा का कार्य करता रहा है। प्रथम युद्ध के पश्चात् जर्मनी में फ्रैंक (Frank) अथवा अमेरिकन डॉलर (Dollar) हिसाब-किताब की मुद्रा थी किन्तु वास्तव में भुगतान निवटाने के लिए जर्मन मार्क का ही प्रयोग किया जाता था।

वास्तविक मुद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है। (i) वस्तु मुद्रा (Commodity money) तथा (ii) प्रतिनिधि मुद्रा (Representative money)। वस्तु मुद्रा को पूर्ण मुद्रा (Full bodied money) भी कहा जाता है। वस्तु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी धातु की बनी हो और जिसका धातु मूल्य उस पर लिखित मूल्य के बराबर हो। प्रत्येक सिक्के में उस पर अंकित मूल्य के बराबर धातु पाई जाती है। सोने, चाँदी तथा अन्य धातुओं के बने सम्पूर्ण सिक्के जिनका आन्तरिक और बाहरी मूल्य लगभग बराबर हो, पूर्ण-मुद्रा कहलाते हैं। वस्तु मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है और मूल्यवान होने के कारण धन वा सचय भी उसी-के रूप में किया जाता है।

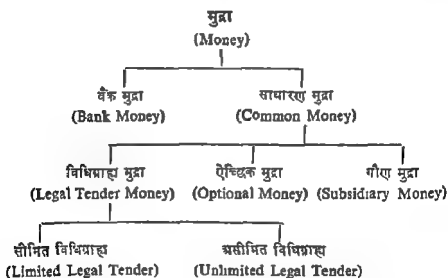
प्रतिनिधि मुद्रा (Representative money) वह मुद्रा है जो स्वयं मूल्यवान नहीं होती है किन्तु मूल्यवान मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वह समस्त मुद्रा

सम्मिलित है जो स्वतन्त्रतापूर्वक विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है किन्तु उसमें मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता है। सब प्रकार की कागजी मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा है। इस प्रकार की मुद्रा को प्रायः वस्तु मुद्रा के बदलने में सुविधा दी जाती है। यद्यपि वह मुद्रा स्वयं मूल्य के संचय का कार्य नहीं करती है किन्तु वह मूल्य का सूचक तथा प्रतिनिधि होती है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उसे पदार्थ मुद्रा में बदला जा सकता है।

(ब) विधिप्राप्त मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा

(Legal Tender Money and Optional Money)

प्रो० डी० एच० राबर्टसन (D. H. Robertson) ने बैंक मुद्रा (Bank Money) तथा सामान्य मुद्रा (Common Money) में भेद किया है। सामान्य मुद्रा को भी उन्होंने कानूनी स्वीकृति के आधार पर तीन वर्गों में बाँट दिया है। राबर्टसन के द्वारा दिया गया मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है—



विधिप्राप्त मुद्रा (Legal Tender Money)—वह मुद्रा है जिसके द्वारा देश के भीतर हर प्रकार के भुगतान किये जा सकते हैं। इस मुद्रा को भुगतान के साधन के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त होती है व लोगों को कानूनन इसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए स्वीकार करना होता है। इस मुद्रा को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार करता है तो उसे कानून के द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। हमारे देश में रुपये का सिक्का, वरन्सी नोट तथा अन्य प्रकार के सिक्के विधिप्राप्त मुद्रा हैं किन्तु किसी बैंक पर लिखा गया चेक (cheque) विधिप्राप्त मुद्रा नहीं है। अतः विधि-प्राप्त मुद्रा वह

मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में सरकारी तथा वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है।

विधिप्राप्त मुद्रा दो प्रकार की हो सकती है— सीमित विधिप्राप्त तथा असीमित विधिप्राप्त। सीमित विधिप्राप्त मुद्रा देश की उस मुद्रा को कहते हैं जिसे विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए केवल एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है। इस सीमा के पश्चात् उसे लेने से इन्कार किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा किसी भी सीमा तक लेने के लिए लोगों को विवश नहीं किया जा सकता है। भारतवर्ष में १ पैसे से लेकर २५ पैसे तक के सभी सिक्के सीमित विधिप्राप्त हैं क्योंकि उन्हें निश्चित सीमा तक ही लोगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वह मुद्रा असीमित विधिप्राप्त होती है जिसे किसी भी सीमा तक भुगतान निबटाने के लिए लोगों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होता है। इस प्रकार की मुद्रा स्वीकृति की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। चाहे कितना भी बड़ा भुगतान क्यों न हो उसे वैधानिक रूप से इस मुद्रा के द्वारा निबटाया जा सकता है। भारतवर्ष में ५० पैसे तथा एक रुपये के सिक्के और समस्त करसी नोट असीमित विधिप्राप्त हैं।

ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money)—विधिप्राप्त मुद्रा के अतिरिक्त देश में कुछ ऐसी मुद्रा भी चलती है जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होती है और लोग उसे केवल अपनी इच्छा से ही स्वीकार करते हैं। इस मुद्रा को लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है और इसकी स्वीकृति लेने वालों की इच्छा पर निर्भर होती है। यद्यपि इस प्रकार की मुद्रा को भुगतान निबटाने के लिए आम तौर से प्रयोग किया जाने लगा है किन्तु यदि कोई चाहे तो इसे लेने से इन्कार कर सकता है। इस प्रकार की मुद्रा का चलन-क्षेत्र सीमित होता है और उसकी स्वीकृति लोगों की व्यक्तिगत साल के ऊपर निर्भर होती है। यदि लेने वाले को भुगतान करने वाले पर विश्वास है तो वह उसके द्वारा दी जाने वाली ऐच्छिक मुद्रा को स्वीकार कर लेता है अथवा नहीं।

गौण मुद्रा (Supplementary Money)—इसमें 'सली', 'यतु' के 'घो', 'हुए' के 'सिक्के' सम्मिलित होते हैं जो प्रमाणिक सिक्कों की सहायता के लिए चलाये जाते हैं। ये साधारणतया छोड़ी कीमत के सिक्के होते हैं और छोटे-भुगतानों को निबटाने के लिए काम में लाये जाते हैं। गौण मुद्रा प्रायः साकेतिक होती है और उसका अंकित मूल्य आन्तरिक मूल्य से बहुत अधिक होता है। इनकी दलाई स्वतन्त्र नहीं होती और ये सिक्के मरदा ही सीमित विधिप्राप्त होते हैं। इन सिक्कों का देश की प्रमाणिक मुद्रा से निश्चित सम्बन्ध रहता है। हमारे देश में नये पैसे के समस्त सिक्के तथा अन्य प्रकार की रेजगारी गौण मुद्रा हैं।

(स) धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा

(Metallic Money and Paper Money)

मुद्रा का यह वर्गीकरण उस वस्तु के आधार पर किया गया है जिसकी यह बनी हुई होती है। मुद्रा वस्तु को प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(i) धातु मुद्रा तथा (ii) पत्र मुद्रा। प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता रहा है किन्तु आजकल मुद्रा या तो कागज की बनती है या किसी धातु की। वर्तमान युग में धातु मुद्रा का स्थान धीरे-धीरे पत्र मुद्रा ने ले लिया है और धातु के सिक्के केवल गौण मुद्रा (Subsidiary Money) के रूप में ही चलाये जाते हैं। मुद्रा बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं का प्रयोग कम होता जा रहा है और उनके स्थान पर प्रायः सस्ती धातुओं के सिक्के बनाये जाते हैं।

धातु मुद्रा

(Metallic Money)

वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी हो धातु मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार की मुद्रा को पूर्ण मुद्रा (Fullbodied Money) भी कहा जाता है। हमारे देश में चलने वाला रुपये का सिक्का तथा नये पैसे के समस्त सिक्के धातु मुद्रा हैं। धातु मुद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है—(क) प्रमाणिक मुद्रा तथा (ख) साकेतिक मुद्रा।

(क) प्रमाणिक मुद्रा (Standard Money)—

वह मुद्रा है जो देश में मूल्य मान का कार्य करती है और जिसके द्वारा देश में चलने वाली अन्य सब प्रकार की मुद्राओं का मूल्य नापा जाता है। यह देश की मुख्य मुद्रा होती है और प्रायः सोने और चाँदी की बनाई जाती है। प्रमाणिक मुद्रा की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(१) प्रमाणिक सिक्कों की मुक्त ढलाई की जाती है—जनता को यह स्वतन्त्रता होती है कि वे किसी भी मात्रा में अपना सोना या चाँदी टुकड़ाल पर ले जाकर उसे सिक्को में ढलवा सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रा की माग और पूर्ति में अपने आप संतुलन बनता रहता है और किसी प्रकार के सरकारी प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिक्को की ढलाई कभी नि:शुल्क की जाती है और कभी उसके लिए कुछ खर्च लिया जाता है।

(२) प्रमाणिक सिक्के देश की मुख्य मुद्रा होते हैं—सब प्रकार की मुद्राओं को निबटाने के लिए मुख्यतः प्रमाणिक सिक्को का प्रयोग किया जाता है। अन्य सब प्रकार की मुद्राएँ केवल उसकी सहायता के लिए चलाई जाती हैं और उनका मूल्य भी प्रमाणिक मुद्रा के द्वारा ही नापा जाता है।

(३) प्रमाणिक सिक्कों का अंकित मूल्य तथा आन्तरिक मूल्य बराबर होता है—इन सिक्कों में एक निश्चित शुद्धता वाली धातु निश्चित वजन में पाई जाती है। प्रत्येक सिक्के में उतने ही मूल्य की धातु पाई जाती है जितना मूल्य उस पर अंकित है। यदि इन्हें गलाकर धातु के रूप में बेचा जाय तो उतना ही मूल्य मिल जाता है जितने मूल्य का वह सिक्का है। अतः प्रमाणिक मुद्रा के निहित मूल्य और अंकित मूल्य में कोई अन्तर नहीं होता है।

(४) प्रमाणिक सिक्के असीमित विधियुक्त होते हैं—प्रमाणिक सिक्के को किसी भी सीमा तक विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। इन सिक्कों को प्रत्येक व्यक्ति को असीमित मात्रा तक लेने के लिए कानूनन मजबूर किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें लेने से इन्कार करता है तो उसे दण्ड दिया जाता है।

(ख) सांकेतिक मुद्रा (Token Money)—

इस मुद्रा के अन्तर्गत वे सब सिक्के आ जाते हैं जिनका अंकित मूल्य उनके आन्तरिक मूल्य से अधिक होता है। यह सिक्के सस्ती धातुओं के बनाये जाते हैं और इनमें पाई जाने वाली धातु का मूल्य सिक्के के अंकित मूल्य से बहुत कम होता है। ऐसे सिक्कों का मूल्य उनमें पाई जाने वाली धातु के आर निर्भर नहीं होता है, बल्कि सरकारी आदेश के द्वारा निश्चित किया जाता है। इसीलिए इन्हें प्राविष्ट मुद्रा (Fiat Money) भी कहा जाता है। इन सिक्कों की स्वतन्त्र दलाई नहीं की जाती है और सरकार केवल एक निश्चित मात्रा में इन्हें जारी करती है। यह देश की मुद्रा नहीं होती है और इसे केवल प्रमाणिक मुद्रा की सहायता के लिए चलाया जाता है। इस प्रकार की मुद्रा केवल एक निश्चित सीमा तक ही विधिप्राप्त होती है।

सांकेतिक मुद्रा मुख्यतः दो उद्देश्यों में चलाई जाती है—(१) बहुमूल्य धातुओं की बचत करने के लिए। जब सरकार के पास बहुमूल्य धातुओं की कमी होती है और अधिक मुद्रा जारी करना अनिवार्य होता है तो सरकार सांकेतिक सिक्के चला कर इस कमी को पूरा करती है। ऐसा करने से बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है और सोने व चांदी की थोड़ी मात्रा से बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा जारी कर दी जाती है। (२) कभी-कभी सांकेतिक सिक्कों को जारी करने का उद्देश्य जनता के द्वारा सिक्कों को गलाये जाने की प्रवृत्ति को रोकना भी होता है। जब सिक्कों में पाई जाने वाली धातु का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि सिक्के का अंकित मूल्य उसके निहित मूल्य से कम रह जाता है तो लोग इन सिक्कों को पिघला डालते हैं और साम उठाते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार सिक्कों में पाई जाने वाली धातु की शुद्धता को कम करके उन्हें सांकेतिक सिक्का बना देती है।

इस सम्बन्ध में भारतीय रुपये की स्थिति विचित्र है। न तो उसे पूर्णतया प्रमाणिक सिक्का ही कहा जा सकता है और न सांकेतिक ही। जब तक भारतीय

रुपये में लगभग एक रुपये के मूल्य की चाँदी पाई जाती थी वह प्रमाणिक सिक्का था। १८६३ से पहले भारतीय रुपये का अंकित मूल्य और धातु मूल्य बराबर होता था और प्रत्येक रुपये में १६ आने के मूल्य की चाँदी होती थी। रुपये की स्वतन्त्र ढलाई होती थी और टकसाल जनता के लिए खुली थी। इस समय तक रुपया पूर्णतया प्रमाणिक सिक्का था। १८६३ के पश्चात् रुपये का अंकित मूल्य उसके आन्तरिक मूल्य से अधिक रक्खा जाने लगा, टकसाल जनता के लिए बन्द कर दी गई और रुपये को सांकेतिक सिक्का बना दिया गया। वर्तमान मिलट का रुपया प्रमाणिक सिक्का नहीं है क्योंकि उसका आन्तरिक मूल्य उस पर अंकित मूल्य से बहुत कम है। उसकी मुक्त ढलाई भी नहीं की जाती है। इन्हीं कारणों से भारतीय रुपये को सांकेतिक सिक्का कहा जा सकता है। किन्तु वह सांकेतिक सिक्का होते हुए भी प्रमाणिक मुद्रा का कार्य करता है। रुपया ही हमारे देश की मुख्य मुद्रा है और समस्त मूल्य उसके द्वारा नापे जाते हैं। वह असीमित विधिग्राह्य भी है। इसीलिए कुछ लेखकों ने भारतीय रुपये को प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का (Standard Token Coin) माना है।

पत्र मुद्रा (Paper Money)

आजकल धातु मुद्रा के साथ-साथ पत्र मुद्रा का प्रयोग भी किया जाता है। पत्र मुद्रा ही वर्तमान समाज में मुख्य मुद्रा का कार्य करती है और धातु मुद्रा उसकी सहायक मात्र रह गई है। यद्यपि पत्र मुद्रा का प्रयोग पिछले ५० वर्षों में ही बढ़ा है किन्तु आज वह विनिमय का मुख्य माध्यम बन गई है। विनिमय की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत करने के उद्देश्य से पत्र मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ था। पत्र मुद्रा के प्रयोग में विशेष सुविधा रहती है क्योंकि उसके द्वारा बड़े-बड़े गुणतानों को आसानी से निबटाया जा सकता है तथा उसे सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। धातु मुद्रा के चलन में रहने से जो सिक्की की विसावट आदि के कारण नुकसान होता था, वह पत्र मुद्रा में नहीं होता है। पत्र मुद्रा का प्रयोग होने से सौने और चाँदी की बहुत अधिक बचत करना सम्भव हो सका है। इन सब सुविधाओं के कारण ही पत्र मुद्रा का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है और प्रगतिशील देशों में तो उसका प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि धातु मुद्रा का महत्व लगभग समाप्त हो चुका है। आरम्भ में पत्र मुद्रा को जारी करने का अधिकार केवल सरकार को होता था किन्तु अब यह काम देश के केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाने लगा है।

पत्र मुद्रा मुख्यतः चार प्रकार की हो सकती है—(i) प्रतिनिधि पत्र मुद्रा (Representative paper money); (ii) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible

paper money); (iii) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible paper money) और (iv) प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat money)।

(i) प्रतिनिधि पत्र मुद्रा (Representative Paper Money)—

आरम्भ काल में नोट जारी करने का मुख्य उद्देश्य मूल्यवान धातुओं की घिसावट के कारण होने वाली हानि को रोकना था और पत्र मुद्रा केवल सुरक्षित कोप में रखे सोने व चांदी के प्रतिनिधि के रूप में काम करती थी। जनता को यह विश्वास दिलाया जाता था कि वास्तविक मुद्रा तो सोना और चांदी ही है, पत्र मुद्रा तो केवल उसकी ही प्रतिनिधि है। पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए तथा अत्यधिक निकासी को रोकने के लिए नोटों के पीछे उनके मूल्य के बराबर सोना व चांदी सुरक्षित कोप में रखा जाता था। जब नोटों के पीछे क्षतप्रतिक्षत मूल्य का सोना अथवा चांदी सुरक्षित कोप में रखी जाती है तो इस प्रकार की पत्र मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। इसे प्रतिनिधि मुद्रा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह सुरक्षित कोप में रखे सोने व चांदी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा पूर्णतया सोने और चांदी में परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह अपनी मुद्रा के बदले सोना अथवा चांदी प्राप्त कर सके। कुछ समय तक अमरीका में प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के प्रमाण-पत्र (Gold and Silver Certificates) चलाये जाते थे। अमरीकन सरकार इन प्रमाण-पत्रों के पीछे पूरे मूल्य का सोना तथा चांदी कोषागार में जमा रखती थी और उन्हें किसी भी समय सोने और चांदी में बदलने की गारन्टी देती थी।

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के लाभ—

(१) प्रतिनिधि मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस प्रकार की पत्र मुद्रा में जनता का बहुत अधिक विश्वास होना है क्योंकि नोटों को किसी भी समय सोने और चांदी में बदलने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह जब चाहे अपने नोटों के बदले में सोना व चांदी प्राप्त कर सकता है। (२) प्रतिनिधि मुद्रा के प्रयोग से सोने और चांदी की बचत हो जाती है। बहुमूल्य धातुओं की चलन में नहीं रखा जाता है और वे केवल सुरक्षित कोप के रूप में केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार के पास रहती हैं। इस प्रकार सिकको की घिसावट आदि के कारण होने वाली हानि से सरकार बिल्कुल बच जाती है। (३) प्रतिनिधि मुद्रा सबसे अधिक सुरक्षित होती है। इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रसार का भय बिल्कुल नहीं होता है। नोटों के पीछे क्षतप्रतिक्षत धात्विक कोप रखना अनिवार्य होता है, इसलिए अत्यधिक निकासी की सम्भावना समाप्त हो जाती है।

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के दोष—

इन सब गुणों के होते हुए भी प्रतिनिधि मुद्रा का प्रयोग बहुत कम किया गया है। उसमें कुछ ऐसे दोष पाये जाते हैं जिनके कारण उसका प्रयोग अधिक

मुद्राजनक नहीं होता है। (१) प्रतिनिधि मुद्रा में बहुत अधिक ध्वय करना होता है। नोटों के पीछे शतप्रतिशत कोप रखने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी बन्द करके रखना होता है, जिन्हें किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। (२) इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली में तोच का गुण नहीं पाया जाता है। मुद्रा की आवश्यकता बढ़ने पर अधिक मुद्रा जारी करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक जारी किये जाने वाले नोट के पीछे उसके बराबर मूल्य का सोना रखना होता है। संकट काल में इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली का टूट जाना अनिवार्य है क्योंकि ऐसे समय में अधिक सोना और चांदी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। (३) गरीब देशों के लिए प्रतिनिधि मुद्रा अनुपयुक्त है। ऐसे देशों के लिए, बहुमूल्य धातुओं के पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण, प्रतिनिधि मुद्रा जारी करना सम्भव नहीं होता है।

(ii) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money)—

जिस पत्र मुद्रा के बदले में सरकार एक निश्चित दर में सोना या चांदी देने की गारंटी करती है, उसे परिवर्तनीय मुद्रा कहा जाता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के दोषों को दूर करने के लिए इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। यह अनुभव किया गया कि नोटों के पीछे शतप्रतिशत स्वर्ण निधि रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब नोट एक साथ परिवर्तन के लिए नहीं आ सकते हैं। जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा के पीछे केवल एक निश्चित अनुपात में ही सोना और चांदी रख कर उनकी परिवर्तनीयता को बनाये रखा जा सकता है। इस प्रणाली में, चलन में रहने वाली पत्र मुद्रा के केवल एक भाग के पीछे सोने और चांदी का सुरक्षित कोप रखा जाता है और शेष मुद्रा के पीछे केवल कागजी प्रतिभूतियाँ होती हैं। पत्र मुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धात्विक कोप होता है, उसे रक्षित मुद्रा (Covered Issue) कहा जाता है और जिस भाग के पीछे सोना नहीं होता है और जो प्रतिभूतियों के आधार पर जारी की जाती है उसे विश्वासाश्रित मुद्रा (Fiduciary Issue) कहा जाता है। विदेशी भ्रूणतानों को निबटाने के लिए सरकार सोने या चांदी का एक कोप रखती है। सरकार इस बात की गारंटी देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने नोटों को एक निश्चित दर पर सोने या चांदी में बदल सकता है।

परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के लाभ—

(१) इस प्रणाली में बहुमूल्य धातुओं की काफी बचत हो जाती है। पत्र मुद्रा के पीछे शतप्रतिशत धातु कोप नहीं रखा जाता है और नोटों की कीमत से बहुत कम कीमत का सोना व चांदी सुरक्षित कोप में रहता है। इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बहुत बचत हो जाती है। (२) यह प्रणाली बहुत लोचदार है। आवश्यकता पड़ने पर नोटों की मात्रा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रणाली में थोड़े से धात्विक कोप के आधार पर कई गुनी अधिक पत्र मुद्रा जारी की

जा सकती है। जनता का विश्वास भी इस प्रकार की पत्र मुद्रा में बना रहता है। नोटों को किसी भी समय धातु मुद्रा में बदला जा सकता है और लोग विदेशी मुग़तानों के लिए सरकार से सोना अथवा चाँदी प्राप्त कर सकते हैं। गरीब देश भी इस प्रकार की पत्र मुद्रा को जारी कर सकते हैं क्योंकि इस प्रणाली में अधिक सोने और चाँदी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। (४) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण रहता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की अपेक्षा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि उसमें अत्यधिक निकासी का भय कम रहता है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के इस गुण को बताते हुए क्राउथर (Crowther) ने लिखा है कि "जब तक परिवर्तनशीलता का दायित्व रहता है, यह पत्र मुद्रा जारी करने वाली संस्था पर कठोर प्रतिबन्ध रखती है।

परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के दोष—

(१) मुद्रा प्रसार का भय। क्योंकि नोटों के मूल्य के बराबर सोना उनके पीछे नहीं रखा जा सकता है इसलिए अत्यधिक निकासी का भय बना रहता है सरकार इस प्रकार की पत्र मुद्रा का दुरुपयोग कर सकती है। यदि प्रतिभूतियों के आधार पर सरकार बहुत अधिक मात्रा में नोट जारी कर देती है तो मुद्रा प्रसार के कारण देश का आर्थिक व सामाजिक जीवन दूषित हो जाता है। (२) प्रतिनिधि मुद्रा की अपेक्षा इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास कम होता है। नोटों के पीछे केवल आंशिक कोष ही रखा जाता है जिसके कारण सकट काल में जनता का विश्वास मुद्रा में बनाये रखना कठिन हो जाता है। (३) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा केवल अनुकूल परिस्थिति में ही सम्भव है। युद्ध-काल में जब सरकार को अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करना आवश्यक हो जाता है तो मुद्रा की परिवर्तनशीलता को समाप्त करना पड़ता है। यह सम्भव हो सकता है कि सरकार में जनता का विश्वास कम हो जाने के कारण खोप पत्र मुद्रा के बदले में अधिक सोने की माँग करने लगे, जिसे पूरा करना सरकार के लिए सम्भव नहीं होता है और ऐसी स्थिति में मुद्रा की परिवर्तनशीलता समाप्त हो जाती है।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अधिकांश देशों में इसी प्रकार की पत्र मुद्रा चलती थी। १९२५ में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली को अपनाया। सरकार नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए पत्र मुद्रा के बदले में एक निश्चित दर पर सोना बेचती थी। भारतवर्ष में १९२७ में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) की सिफारिश पर पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने नोटों के बदले में कम से कम ४० तोले की सोने की सलाखें २१ रुपये ७ आने १० पाई प्रति तोला के हिसाब से

4 "So long as the obligation to convert remains, it imposes a severe restraint upon the note issuing authority."

सरकार से ले सकता था। सन् १९३१ में लगभग सब देशों ने स्वर्णमान को त्याग दिया और उसके साथ ही परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का भी अन्त हो गया।

(iii) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money)—

जिस पत्र मुद्रा के बदले में सरकार सोने व चांदी देने की कोई गारंटी नहीं देती है, उसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। परिवर्तनीय मुद्रा का अन्त हो जाने पर लगभग सभी देशों में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। अब पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास इतना बन चुका था कि नोटों के पीछे बहुत मामूली सुरक्षित कोप रखता जा सकता था। मुद्रा की आवश्यकता बढ़ जाने से तथा बहुमूल्य धातुओं की कमी के कारण नोटों के पीछे अनुपातिक धात्विक कोप रखना सम्भव नहीं था और पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। इस प्रकार की पत्र मुद्रा केवल सरकार की साख के आधार पर जारी की जाती है और उसके पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप नहीं रखता जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य साख पत्रों की आड़ पर ही इस मुद्रा को जारी किया जाता है। अपरिवर्तनीय मुद्रा केवल सीमित मात्रा में ही जारी की जाती है किन्तु समय-समय पर सरकार उसकी मात्रा को बढ़ाती रहती है। आरम्भ में इस प्रकार की मुद्रा को केवल सवट काल में ही जारी किया जाता था। इसलिए कुछ लेखकों ने इसे सड़ककारी मुद्रा भी कहा है। किन्तु अब तो इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग स्वाभाविक समझ जाने लगा है।

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के लाभ—

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में कुछ ऐसे लाभ हैं जिनके कारण उसका प्रचलन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा से मिलने वाले मुख्य लाभ इन प्रकार हैं—(१) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में मितव्ययिता का गुण पाया जाता है। नोटों के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप नहीं रखना पड़ता है जिसके कारण बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में काफी बचत हो जाती है। प्रतिनिधि तथा परिवर्तनीय मुद्राओं की अपेक्षा यह प्रणाली अधिक मितव्ययितापूर्ण है। (२) यह प्रणाली बहुत अधिक लोचदार है। पत्र मुद्रा के अपरिवर्तनीय हो जाने पर आवश्यकता के अनुसार कितनी भी मात्रा में नोट चलाये जा सकते हैं। इस प्रणाली में नोटों की मात्रा का सुरक्षित कोप के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है और मुद्रा का विस्तार बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। एक प्रगतिशील समाज के लिए इस प्रकार की मुद्रा विशेष उपयुक्त है क्योंकि उसके द्वारा समाज की मुद्रा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। (३) इस मुद्रा का व्यवहारिक महत्व अधिक है। सोने व चांदी की कमी के कारण प्रतिनिधि एवं परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का व्यवहारिक महत्व बहुत कम रह गया है। अधिकांश देश इस प्रकार मुद्रायें चलाने की स्थिति में नहीं है और उनके लिए अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को स्वीकार करना अनिवार्य हो गया है।

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के दोष—

(१) मुद्रा प्रसार का भय बहुत बढ़ जाता है—सुरक्षा की दृष्टि से अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को अच्छी मुद्रा नहीं कहा जा सकता है। अन्य प्रकार की पत्र मुद्राओं की अपेक्षा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रसार का भय सबसे अधिक होता है। नोटों के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप रखना आवश्यक नहीं रहता है, जिसके कारण सरकार मनमाने ढंग से मुद्रा का विस्तार कर सकती है। आवश्यकता से अधिक मुद्रा हो जाने पर मूल्य-स्तर बढ़ जाता है और उसके कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। विभिन्न देशों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं। क्रॉथर (Crowther) के अनुसार “मौद्रिक इतिहास में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का लगभग प्रत्येक अनुभव मौद्रिक अस्थिरता के साथ सम्बद्ध रहा है।”^५ जब भी परिवर्तनशीलता को हटाया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करने का लोभ काफी बढ़ जाता है जिसके कारण अपरिवर्तनशीलता और अत्यधिक निकासी साथ-साथ चलते हैं। टॉमस (Thomas) ने भी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के इस दोष की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार ‘अपरिवर्तनीय मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें ऐसा कोई निश्चित तथा स्वयं संचालित तरीका नहीं होता है जिससे कि वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए केवल पर्याप्त मुद्रा ही जारी की जाय और मुद्रा प्रसार को दूर रख कर समाज को अपनी सामान्य आर्थिक क्रियाओं एवं प्रगति के लिए पर्याप्त मुद्रा दी जा सके।’^६ (२) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखना बहुत कठिन होता है। नोटों की धातु मुद्रा में न बढ़ता जाने के कारण लोग आरम्भ काल में इस प्रकार की मुद्रा को भार स्वरूप मानते थे और केवल शक्तिशाली सरकार ही इसका प्रयोग कर सकती थी। जनता का विश्वास मुद्रा में न होने के कारण किसी भी समय इस प्रणाली के टूट जाने का भय रहता था। किन्तु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि पत्र मुद्रा के पीछे सुरक्षित कोप रखकर उसे परिवर्तनीय बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित निधि केवल इसलिए रखनी चाहिए कि सकट काल में विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। सुरक्षित कोप में और नोटों की मात्रा में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण होते हुए भी आजकल यह प्रणाली लगभग सब देशों में अपना ली गई है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा से पूर्ण

5 “Nearly every experience of inconvertible bank notes known to monetary history has been associated with monetary instability”

—Crowther : An Outline of Money, P. 17.

■ “The great disadvantage of an inconvertible currency is that there is no certain automatic method of ensuring that only sufficient money is issued to satisfy current demands and that while inflation is avoided the community is provided with sufficient money for its normal economic activity and progress.”

—S. E. Thomas : Elements of Economics, P. 336.

साम उठाने के लिए अनिवार्य है कि मुद्रा का प्रवण्य इस प्रकार किया जाय कि अत्यधिक निवासी न होने पाये और मुद्रा के मूल्य में स्थिरता को बनाये रखा जा सके ।

(iv) प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Money)—

प्रादिष्ट पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में कोई विशेष भेद नहीं है । प्रादिष्ट मुद्रा अपरिवर्तनीय मुद्रा का एक विशेष रूप है । जब अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा सफट बाल में जारी की जाती है तो उसे प्रादिष्ट मुद्रा कहते हैं । इस प्रकार की मुद्रा के पीछे कोई वास्तविक कोष नहीं होता है और ये नोट सिक्के या धातु में नहीं बदले जा सकते हैं । इनकी परिवर्तनीयता के विषय में सरकार किसी प्रकार की गारन्टी नहीं देती है । इसे प्रादिष्ट मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सरकारी आदेश के द्वारा लोगों को लेने के लिए बाध्य किया जाता है । इस प्रकार की मुद्रा को लोग इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वह स्वयं मूल्यवान है अथवा मूल्यवान धातुओं में बदली जा सकती है बल्कि इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसे सरकारी मान्यता प्राप्त होती है । जब सरकार किसी विशेष कठिनाई में होती है तो वह इस प्रकार की पत्र मुद्रा जारी किया करती है क्योंकि इसके द्वारा सरकार अपने ऋणों को तथा अन्य प्रकार के भुगतानों को सामान्य से निबटा सकती है । इस प्रकार की मुद्रा जनता में जबर्जस्ती लिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण है जिस पर व्याज नहीं दिया जाता है । इस प्रकार की मुद्रा की कंट (Kent) के अनुसार तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं—

- (i) प्रादिष्ट मुद्रा का वस्तु मूल्य बहुत कम अथवा धूम्र के बराबर होता है
- (ii) उसे किसी भी सामान्य मूल्य वाली वस्तु के साथ नहीं बदला जा सकता है तथा
- (iii) उसकी क्रय-शक्ति को सोना आदि किसी वस्तु के मूल्य के साथ सम्बन्धित नहीं रखा जाता है ।

इस प्रकार की पत्र मुद्रा में अपरिवर्तनीय मुद्रा के सब दो पाये जाते हैं । प्रादिष्ट मुद्रा यदि बहुत अधिक मात्रा में जारी कर दी जाय तो मुद्रा प्रसार के रूप में उसके अत्यधिक परिणाम हो सकते हैं । किन्तु यदि मुद्रा का सही प्रवण्य कर लिया जाय तो उसके दोषों से बचा जा सकता है । क्रय की क्रांति के अवसर पर जारी किये गये ऐमाइनेट (Assignats) तथा अमेरिकी गृह-युद्ध (American Civil War) काल में जारी किये गये ग्रीनबैक (Greenback) प्रादिष्ट पत्र मुद्रा (Fiat Money) के मुख्य उदाहरण हैं । प्रथम महायुद्ध में जारी किये गये जर्मन मार्क (German Mark) तथा दूसरे विश्व-युद्ध में चलाई गई समस्त पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय थी ।

सिक्के और उनकी छलाई

(Coins and Coinage)

“धातु मुद्रा अथवा सिक्के एक निश्चित धुंधना तथा वजन के धातु के उन टुकड़ों को कहते हैं जिनके दोनों ओर देश की सरकार की मोहर लगी होती है और

जो मुद्रा के रूप में चलाये जाते हैं।" अच्छे सिक्कों में पाये जाने वाले कुछ आवश्यक गुण इस प्रकार हैं—(१) वे सुविधाजनक आकार के होने चाहिए। (२) वे इन प्रकार बनाये गये हों कि टूट-फूट तथा पिसावट की सम्भावना कम से कम हो। (३) उनका आकार ऐसा होना चाहिए कि नकली सिक्के बनाना भयवा सिक्कों के किनारे काटना सम्भव न हो सके। (४) उन पर सुन्दर सरकारी मोहर लगी होनी चाहिए। वर्तमान सिक्के इन सब विशेषताओं को पूरा करते हैं इसलिए उन्हें पूर्ण सिक्के कहा जाता है। आज के सिक्कों का विकास काफी लम्बे काल में हुआ है और उनमें काफी सुधार करने के पश्चात् ही उन्हें वर्तमान रूप दिया जा सका है। यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि सिक्कों का प्रयोग कब आरम्भ हुआ किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि बहुत प्राचीन काल से उनका प्रयोग होता आ रहा है। ऐतिहासिक खोज के आधार पर पता चलता है कि सर्वप्रथम लिडिया (Lydia) देश में सिक्कों का प्रयोग किया गया। मिश्र तथा अन्य देशों ने भी सिक्कों को ढालने की कला के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

धातु मुद्रा को वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा है। सर्वप्रथम जब वस्तु-विनिमय को त्याग कर धातु मुद्रा को अपनाया गया तो धातु के विभिन्न आकार तथा वजन के टुकड़ों एवं सलाखों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। जिस धातु को मुद्रा के लिए निश्चित किया जाता था उसके विभिन्न प्रकार के टुकड़े चलन में रहते थे और विनिमय के माध्यम का कार्य करते थे। इन टुकड़ों का वजन, शुद्धता तथा आकार समान न होने के कारण प्रत्येक बार स्वीकार करने से पूर्व उनकी जाँच की जाती थी। धातु के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने में विशेष असुविधा होती थी क्योंकि प्रत्येक बार लेते समय उनकी शुद्धता की जाँचना पड़ता था और उन्हें तोलना होता था।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए निश्चित आकार, वजन तथा प्रमाणित शुद्धता वाले धातु के टुकड़ों का प्रयोग आरम्भ हुआ। इन धातु के टुकड़ों का वजन तथा शुद्धता सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती थी जिसके लिए उन पर सरकारी मोहर लगाई जाती थी। अब इन सिक्कों की प्रत्येक बार जाँच करने की आवश्यकता नहीं होती थी और इस प्रकार एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो गई। किन्तु अभी धातु मुद्रा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता था क्योंकि जाली सिक्के बनाने, सिक्कों के किनारे काट लेने तथा अन्य प्रकार की जालसाजी का भय रहता था। इस दोष को दूर करने के लिए सरकार ने सिक्कों पर जटिल आकृति (Design) बनाने तथा उनके किनारे कटे-फटे बनाने आरम्भ कर दिये। इसका उद्देश्य नकली सिक्कों को बनाने से रोकना था। प्रत्येक सिक्के पर राजा की तस्वीर अथवा सरकारी मोहर लगाई जाती थी। इस प्रकार सिक्कों को वर्तमान रूप दिया गया।

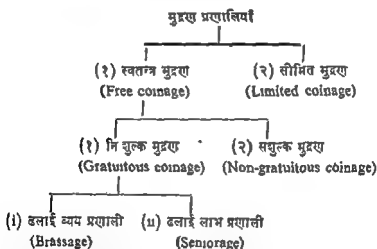
आज के सिक्कों को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण कहा जा सकता है। उनमें वे सब गुण पाये जाते हैं जो अच्छे सिक्कों में होने चाहिए। वर्तमान सिक्के ऊपरोक्त विभिन्न

अवस्थाओं में से गुजरने के पश्चात् ही पूर्ण हो पाये हैं। १८ वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों का निर्माण होने लगा था जिन्हें प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण कहा जा सकता है। सिक्कों सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उन्हें समान रूप प्रदान करने तथा अच्छे और सुन्दर सिक्कों का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार ने सिक्कों की ढलाई का काम अपने हाथ में ले लिया। आरम्भ काल में सिक्कों की बनाने का काम व्यक्तिगत टक्कालों के द्वारा किया जाता था किन्तु धीरे-धीरे सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। शुरू-शुरू में सिक्कों के अंकित मूल्य की धातु उनमें होती थी किन्तु बाद में सिक्कों का अंकित मूल्य उनके निहित मूल्य से अधिक रक्क़ा जाने लगा और टक्क़ा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सिक्कों की जारी करना सरकार का एकमात्र अधिकार कर दिया गया।

मुद्रण प्रणालियाँ

(Systems of Coinage)

सिक्के ढालने की दो प्रमुख प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं—(१) स्वतन्त्र मुद्रण तथा (२) सीमित मुद्रण।



(१) स्वतन्त्र मुद्रण (Free Coinage)—इसका अभिप्राय टक्क़ा की उस प्रणाली से है जिसमें किसी भी सीमा तक सिक्के ढाले जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह किसी भी मात्रा में मुद्रा धातु को टक्क़ाल पर देकर उसके बदले में सिक्के प्राप्त कर सकता है। टक्क़ाल जनता के लिए खुली होती है और मुद्रा की ढलाई जनता की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। मुद्रण की यह व्यवस्था तभी तक सम्भव थी जब तक सिक्कों का आन्तरिक मूल्य उनके अंकित मूल्य के बराबर होता था। सांकेतिक सिक्कों का चलन आरम्भ होने पर स्वतन्त्र

मुद्रण के स्थान पर सीमित मुद्रण को अपना लिया गया। १९ वीं शताब्दी में स्वतन्त्र मुद्रण की प्रथा संसार के बड़े-बड़े देशों में प्रचलित थी। हमारे देश में १८६३ तक रुपये का स्वतन्त्र मुद्रण किया जाता था तथा इंग्लैंड में १९३१ तक पौंड की स्वतन्त्र ढलाई होती थी।

(२) सीमित मुद्रण (Limited Coinage)—जब सिक्के केवल सरकार के लिए ही तैयार किये जाते हैं और जनता को सिक्के ढलवाने की स्वतन्त्रता नहीं होती है तो उसे सीमित मुद्रण कहा जाता है। एकसाल जनता के लिए बन्द कर दी जाती है और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार धातु के बदले में एकसाल से सिक्के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन सिक्कों का अंकित मूल्य उनके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है उनकी स्वतन्त्र ढलाई नहीं की जा सकती है और इसलिए सरकार उनकी सीमित ढलाई करती है। इस प्रणाली में सरकार स्वयं धातु खरीद कर जनता की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार सिक्के बनाती है। आजकल संसार के सभी देशों में सिक्कों की सीमित ढलाई की जाती है। भारतवर्ष में १८६३ में हर्शेल (Herschell) कमेटी की सिफारिश पर रुपये की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी गई और उसके स्थान पर सीमित ढलाई प्रणाली को अपना लिया गया।

मुद्रण व्यय—सरकार मुद्रण व्यय जनता से लेती है अथवा नहीं इसके आधार पर सिक्का ढलाई दो प्रकार की हो सकती है—(क) निःशुल्क मुद्रण तथा (ख) सःशुल्क मुद्रण। सिक्कों की ढलाई में सरकार को कुछ खर्च करना पड़ता है। यदि सरकार ढलाई के इस खर्च को जनता से नहीं लेती है तो उसे निःशुल्क ढलाई (Gratuitous Coinage) कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्कों की ढलाई प्रायः निःशुल्क की जाती थी। सिक्के बनाना सरकार का कर्तव्य समझा जाता था और उस पर आने वाला व्यय सरकारी खजाने से पूरा किया जाता था। जब तक सिक्कों की आवश्यकता बहुत कम थी, सरकार के लिए उनकी निःशुल्क ढलाई करना सम्भव था किन्तु उनकी आवश्यकता बढ़ जाने पर निःशुल्क ढलाई बन्द कर दी गई और सरकार ने सिक्के बनाने का व्यय जनता से लेना आरम्भ कर दिया। जब सरकार मुद्रण व्यय जनता से लेती है तो उसे सःशुल्क ढलाई (Non-gratuitous Coinage) कहा जाता है।

सःशुल्क ढलाई (Non-gratuitous Coinage) भी दो प्रकार की हो सकती है—(१) ढलाई व्यय प्रणाली (Brassage) तथा (२) ढलाई लाभ प्रणाली (Seniorage)। यदि सिक्का ढलाई से सरकार किसी प्रकार का लाभ नहीं बनाना चाहती है और जनता से केवल उतना ही शुल्क लेती है जितना वास्तव में सिक्के बनाने पर व्यय आता है तो उसे ढलाई व्यय प्रणाली (Brassage) कहा जाता है। कुछ समय तक सरकारें मुद्रण से लाभ प्राप्त करना उचित नहीं समझती थी और केवल ढलाई व्यय ही जनता से लिया जाता था। किन्तु इसके पश्चात् यह

सोचा गया कि मुद्रण से सरकार लाभ प्राप्त कर सकती है और दलाई-लाभ-प्रणाली (Seniorage) को अपना लिया गया। जब सरकार मुद्रण व्यय के रूप में जनता से उससे अधिक लेती है जो वास्तव में सिक्के बनाने पर खर्च आता है तो उसे दलाई-लाभ प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली को अपनाने का उद्देश्य सिक्कों को गलाने की प्रवृत्ति को रोकना तथा मुद्रण से लाभ प्राप्त करना होता है।

सरकार के द्वारा मुद्रण व्यय लेने की दो रीतियाँ होती हैं। सरकार सिक्के में पाई जाने वाली धातु में मिलावट करके उसकी शुद्धता कम कर देती है और इस प्रकार मुद्रण व्यय निकास लिया जाता है। यह तरीका अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें सरकार को मुद्रण व्यय लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। दूसरा तरीका यह होना है कि सरकार सिक्के की शुद्धता अथवा वजन में किसी प्रकार की कमी नहीं करती है किन्तु जब लोग अपनी धातु को सिक्कों में बदलवाने के लिए लाते हैं तो उनसे मुद्रण व्यय अलग लिया जाता है।

यह कहना कठिन है कि इनमें कौनसी मुद्रण प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक प्रणाली के पक्ष तथा विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। स्वतन्त्र दलाई प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि इस प्रणाली में मुद्रा आवश्यकता के अनुसार ही जारी की जाती है जिससे अत्यधिक निकासी का भय नहीं रहता है और मुद्रा प्रसार की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। इसके दूसरी ओर सीमित दलाई प्रथा के पक्ष में यह कहा जाता है कि इस प्रणाली में सरकार साकेतिक सिक्के बना कर सोने और चाँदी की बचत कर सकती है तथा धातुओं का मूल्य बढ़ जाने पर उन्हें जनता के द्वारा गलाने का भय नहीं रहता है। निश्चय दलाई के समर्थकों का कहना है कि सिक्के जारी करना सरकार का कर्तव्य है इसलिए दलाई व्यय उसे स्वयं वर्दाश्त करना चाहिए और उसे जनता से नहीं लेना चाहिए। इसके दूसरी ओर स शुल्क दलाई के पक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस प्रणाली में सरकार को टक्कन व्यय अपनी आय में से नहीं देना पड़ता है। इसमें यदि सरकार चाहे तो टक्कन लाभ भी प्राप्त कर सकती है और सरकारी आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब सरकार मुद्रण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सिक्के चलाती है तो सिक्कों को गलाने से कोई लाभ न होने के कारण इसका भय समाप्त हो जाता है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रणाली उपयुक्त हो सकती है। अतः किसी भी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है।

अच्छी मुद्रा वस्तु के गुण (Qualities of Good Money Material)—

वस्तु मुद्रा का इतिहास हमें बतलाता है कि आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया है। समाज में जो भी वस्तु सामान्य रूप से उपयोगी होती थी वही विनिमय के माध्यम का कार्य करने लगती थी। शिकारी अवस्था में जानवरों की खालें,

पशु-पालन अवस्था में गाय, बकरी तथा अन्य जानवर और कृषि अवस्था में विभिन्न प्रकार के अनाजों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। इनके अतिरिक्त तम्बाकू, चाय, सूखी मछलियाँ, कौड़ियाँ, पत्थर तथा विभिन्न प्रकार की दूसरी वस्तुएँ भी किसी न किसी देश अथवा काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग की गई हैं। कुछ समय तक इन वस्तुओं का प्रयोग करने के पश्चात् यह अनुभव होने लगा कि इनमें से अधिकांश वस्तुएँ मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकती हैं। धीरे-धीरे इन वस्तुओं को त्याग कर इनके स्थान पर धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा। सोने और चाँदी को लगभग सब देशों में मुद्रा वस्तु के रूप में अपना लिया गया क्योंकि वे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकती थीं।

किसी भी मुद्रा में अच्छी मुद्रा वस्तु बनने के लिए कुछ विशेष गुण पाये जाने चाहिए जिससे कि वह मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। प्रो० जीवन्स (Jevons) ने एक अच्छी मुद्रा वस्तु में पाये जाने वाले निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया है—

(१) उपयोगिता अथवा सर्वमान्यता (Utility or General Acceptability)—कोई भी वस्तु मुद्रा का कार्य तभी कर सकती है जब लोग सामान्यतय उसे अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में निःसकोच लेने को तैयार हों। सामान्या स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए मुद्रा वस्तु का उपयोगी होना अनिवार्य है। मुद्रा क्योंकि मूल्यवान् वस्तुओं के साथ बदली जाती है इसलिए उसे स्वयं भी मूल्यवान् होना चाहिए। वह ऐसी वस्तु ही बनी हो जिसकी समाज में निरन्तर माग हो और जिसे किसी भी समय आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ बदला जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि वह वस्तु मुद्रा के अतिरिक्त अन्य रूप में भी लोगों के लिए उपयोगी हो। यदि कोई वस्तु ऐसी है जो मुद्रा के अतिरिक्त दूसरे लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है तो लोग उसे निश्चयपूर्वक स्वीकार करना पसन्द करेंगे। इस दृष्टि से सोना और चाँदी अच्छे मुद्रा पदार्थ हैं क्योंकि वे स्वयं मूल्यवान् होते हैं और हर समय प्रत्येक व्यक्ति उन्हें लेने को तैयार रहता है। आजकल कागज के नोटों का प्रयोग किया जाने लगा है क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त होने के कारण उनमें सामान्य स्वीकृति का गुण पैदा हो गया है। यद्यपि कागज के नोटों का मुद्रा के अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं है, फिर भी उन्हें स्वीकार किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य लोग भी उन्हें स्वीकार कर लेंगे।

(२) वहनीयता (Portability)—एक अच्छी मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि सुगमतापूर्वक उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सके। यदि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में बहुत अधिक खर्च आता है अथवा श्रमविधा होती है तो वह वस्तु मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी। मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसकी थोड़ी मात्रा में ही बहुत अधिक मूल्य निहित हो जिससे उसे कम खर्च से तथा सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकेगा।

गेहूँ तथा गाय अर्द्धी मुद्रा वस्तुयें नहीं है क्योंकि उनमें वहनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। सोने और चांदी की थोड़ी मात्रा में ही बहुत अधिक मूल्य होने के कारण, वे अर्द्धे मुद्रा पदार्थ माने जाते हैं। इस दृष्टि से कागज और भी अर्द्धी वस्तु है क्योंकि उसमें वहनीयता का गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।

(३) टिकाऊपन (Durability)—मुद्रा का प्रयोग क्रय-शक्ति संचय करने के लिए किया जाता है इसलिए वह ऐसी वस्तु की बनी होनी चाहिए जो बहुत अधिक टिकाऊ हो। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुयें मुद्रा का कार्य नहीं कर सकती हैं। मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि यदि उसे काफी लम्बे समय तक रखा जाय तो न उसका वजन ही कम हो और न उसका मूल्य नष्ट हो। इस दृष्टि से सोना और चांदी प्रादर्श वस्तुयें हैं क्योंकि वे शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं। अनुमान लगाया गया है कि सोने के सिक्के ८००० वर्षों में पूर्णतया नष्ट होते हैं। चांदी में भी बहुत अधिक टिकाऊपन पाया जाता है। गेहूँ, पशु, चाय इत्यादि शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण अर्द्धी मुद्रा वस्तुयें नहीं कहो जा सकती हैं।

(४) विभाज्यता (Divisibility)—मुद्रा को कम मूल्य वाली वस्तुओं का विनिमय करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसलिए मुद्रा वस्तु में विभाज्यता का गुण होना अनिवार्य है। मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसका मूल्य नष्ट किये बिना ही उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जा सके। इसका इस प्रकार विभाजन करना सम्भव होना चाहिए कि सब छोटे-छोटे टुकड़ों का मूल्य मिलाकर कुल के मूल्य के बराबर हो। हीरे को अर्द्धा मुद्रा पदार्थ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विभाजन करने पर उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। सोना और चांदी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अर्द्धे मुद्रा पदार्थ हैं क्योंकि मूल्य को कम किये बिना उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना सम्भव है।

(५) मूल्य की स्थिरता (Stability of Value)—मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके मूल्य में जल्दी-जल्दी और बहुत अधिक परिवर्तन न होते हों। मुद्रा मूल्य के मापक तथा स्थगित भुगतानों के मान का कार्य करती है और उसके रूप में भविष्य के लिए क्रय-शक्ति संचय की जाती है इसलिए उसके मूल्य में स्थिरता का होना अनिवार्य है। जिन वस्तुओं का मूल्य जल्दी-जल्दी बदलता रहता है वे अर्द्धी मुद्रा वस्तुयें नहीं हो सकती हैं। मुद्रा वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण ऋणों के भुगतान में विशेष कठिनाई होती है तथा क्रय-शक्ति का संचय भी ठीक प्रकार में नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुद्रा वस्तु का मूल्य प्रायः स्थिर रहना चाहिए और यदि कभी उसका मूल्य बदलता भी है तो यह परिवर्तन केवल नाममात्र को होना चाहिए। सोने और चांदी के मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिरता पाई जाती है और वे इस दृष्टि से अर्द्धी मुद्रा वस्तुयें हैं।

(६) परिच्यता (Congnoscibility)—मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसे भासानी से पहचाना जा सके और अन्य प्रकार की वस्तुओं से भ्रम निया जा सके।

मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आती-जाती रहती है, इसलिए आवश्यक है कि उसे केवल देखकर ही पहचाना जा सके और लेते समय उसकी किसी विशेष जाँच की आवश्यकता न हो। यदि प्रत्येक बार जाँच करने के लिए उसे विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ता है, तो वह अच्छी मुद्रा वस्तु नहीं है। सोने और चाँदी के सिक्कों को देखकर अथवा बजाकर उनकी जाँच आसानी से की जा सकती है।

(७) **अनुरूपता (Homogeneity)**—मुद्रा पदार्थ में एकरूपता का गुण पाया जाना चाहिए। उसके विभिन्न टुकड़ों की शुद्धता समान होनी चाहिए तथा एक ही वजन के टुकड़ों का मूल्य भी एक होना चाहिए। उस वस्तु के बने हुए सिक्के एक ही प्रकार के होने चाहिए। एक सिक्का दूसरे सिक्के से किसी भी प्रकार उत्तम नहीं होना चाहिए जिससे विभिन्न सिक्कों में किसी प्रकार के छोटने की प्रायदयकता पड़े। गैहूँ तथा पशुओं में एकरूपता का गुण न पाया जाने के कारण वे अच्छी मुद्रा वस्तु नहीं हैं किन्तु सोने और चाँदी में यह गुण बहुत अधिक सीमा तक पाया जाता है।

(८) **ढाले जाने की क्षमता (Malleability)**—मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से गलाकर विभिन्न आकार तथा वजन के सिक्के बनाये जा सकें और उन पर सरकारी चिन्ह अथवा मोहर अंकित की जा सके। मुद्रा पदार्थ न तो बहुत सख्त होना चाहिए और न बहुत मुलायम ही होना चाहिए। उसमें सुविधा-पूर्वक ढाले जाने की क्षमता होनी चाहिए जिससे उसे आसानी से गलाकर सिक्कों का निर्माण किया जा सके। सोना, चाँदी इस दृष्टि से भी पूर्ण मुद्रा वस्तु है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितनी भी वस्तुएँ अभी तक मुद्रा के लिए प्रयोग की गई हैं उनमें सोना और चाँदी उत्तम है। इन धातुओं में वे सब गुण पाये जाते हैं जिनका एक अच्छी मुद्रा वस्तु में होना अनिवार्य है। यही कारण है कि अन्य सब धातुओं को त्याग कर सोना चाँदी को ही मुद्रा के रूप में अपनाया गया है। लगभग सब देशों में यह वस्तुएँ बहुत अधिक समय तक मुद्रा का कार्य करती रही हैं। बहुमूल्य धातुओं की बचन करने के उद्देश्य से इनके स्थान पर अथ कागज का प्रयोग किया जाने लगा है। बहुमूल्य धातुओं का पर्याप्त मात्रा में न होना तथा उनकी अन्य प्रयोगों के लिए बचत करने की आवश्यकता के कारण यह परिवर्तन अनिवार्य था।



परीक्षा प्रश्न

- (१) मुद्रा का विकास कैसे हुआ ? मुद्रा कितने प्रकार की होती है ? मुद्रा क्या कार्य करती है ? (भागरा बी० ए० १९५६)
- (२) निम्न से आप क्या समझते हैं—
 (क) चलन की इकाई और हिसाब की इकाई ।
 (ख) प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपये की स्थिति बताइए । (भागरा बी० काम १९६०)
- (३) मुद्रा पदार्थ अपनी दुर्लभता के कारण चुना जाता है, मूल्य के आधार पर नहीं ।” व्याख्या कीजिये । (भागरा बी० काम १९५६)
- (४) निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
 (अ) सीमित दिधिग्राह्य ।
 (ब) मुद्रण लाभ (Seigniorage) (भागरा बी० काम १९५८)
- (५) “आधुनिक युग ने धातु मुद्रा का महत्व समाप्त हो गया है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिये । (भागरा बी० काम १९५७)
- (६) “भारतीय रुपये प्रमाणिक तथा सांकेतिक सिक्के का विचित्र मिश्रण है ।” इसे समझाइये । (भागरा बी० काम १९५६)
 (अ) वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा ।
 (ब) पदार्थ मुद्रा एवं प्रतिनिधि मुद्रा ।
 (स) विधिग्राह्य मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा । (राजस्थान बी० काम १९६०)
- (८) प्राविष्ट मुद्रा पर टिप्पणी लिखिये । (राजस्थान बी० काम १९६०)
- (९) टिप्पणियाँ लिखिये ।
 (क) निःशुल्क टंकन ।
 (ख) प्रतिनिधि पत्र मुद्रा । (विहम बी० काम १९६०)
- (१०) परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में भेद कीजिये । (राजस्थान बी० ए० १९५६)



मुद्रामान

MONETARY STANDARDS

मुद्रा मान की आवश्यकता मुद्रा इकाई के मूल्य को नियन्त्रित करने के लिए होती है। प्रत्येक देश की मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ-साथ मूल्यमान (Standard of Value) का कार्य भी करती है और उसके द्वारा ही विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य व्यक्त किये जाते हैं। एक अच्छे मूल्यमान का कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य में अनावश्यक परिवर्तन न होने दिये जायें। सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उचित व्यवस्था एवं नियन्त्रण के द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को किसी न किसी प्रकार के मुद्रामान की व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। मुद्रा की इकाई, जिसमें देश की सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है, मूल्यमान (Standard of Value) कहलाती है किन्तु जिस वस्तु के द्वारा मुद्रा इकाई के मूल्य को व्यक्त किया जाता है अथवा जिस व्यवस्था के द्वारा मूल्यमान के मूल्य को स्थिर रखा जाता है, उसे मुद्रामान (Monetary Standard) कहते हैं। मुद्रामान तथा मूल्यमान एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। मुद्रामान अधिक विस्तृत है जिसके अन्तर्गत मूल्यमान के अतिरिक्त उसे स्थिर रखने की व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जिस वस्तु अथवा पद्धति के द्वारा मुद्रा की क्रय-शक्ति को व्यक्त किया जाता है उसे मुद्रामान कहते हैं।^१ हॉम (Halm) ने मुद्रामान की परिभाषा इस प्रकार की है—“अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य को नियन्त्रित करने की प्रमुख विधि को मुद्रामान कहा जा सकता है।”^२ यह परिभाषा केवल मुद्रा नियन्त्रण की विभिन्न पद्धतियों को ही मुद्रामान के अन्तर्गत सम्मिलित करती है।

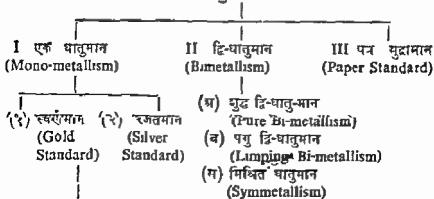
1. “Any object or system in terms of which the purchasing power of money is expressed is known as monetary standard”

2. “We may define monetary standard from the view point of economics as the principal method of regulating the quantity and the exchange value of standard of definitive money.”

वास्तव में मुद्रामान अधिक विस्तृत शब्द है और उसके अन्तर्गत मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम, व्यवस्थायें तथा व्यवहारों को सम्मिलित किया जा सकता है।

मुद्रा को श्रय-शक्ति को व्यक्त करने तथा उसके मूल्य को नियन्त्रित करने की विभिन्न विधियाँ हो सकती हैं। सबसे प्रमुख विधि मुद्रा के मूल्य को मूल्यवान धातुओं (सोना अथवा चाँदी) के द्वारा व्यक्त करने की रही है। किसी एक धातु को मुद्रामान के रूप में निश्चित कर लिया जाता है और मुद्रा इकाई के मूल्य को उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्वर्णमान में सोना तथा रजतमान में चाँदी मुद्रामान का कार्य करती थी। एक से अधिक धातुओं को भी मुद्रामान के रूप में प्रयोग किया गया है। द्वि-धातुमान (Bimetallism) इसी प्रकार का मुद्रामान है। वर्तमान समय में मुद्रा के मूल्य को धातुओं के द्वारा व्यक्त करने की पद्धति समाप्त हो गई है और केवल मौद्रिक प्रवन्ध के द्वारा ही मुद्रा की मात्रा तथा उसके मूल्य को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति को प्रवन्धित मुद्रामान (Managed Currency Standard) कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों में से प्रत्येक देश को अपने लिए एक उपयुक्त मुद्रामान चुनना होता है। किसी भी देश के लिए मुद्रामान का चुनाव एक महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि उसकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति बहुत कुछ मुद्रामान पर निर्भर होती है। एक अच्छा मुद्रामान मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करके अनिश्चितता को दूर करता है तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता है। मुद्रामान का दोषपूर्ण होना आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न करता है तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक व सामाजिक दोषों को जन्म देता है। प्रत्येक देश को ऐसा मुद्रामान अपनाना चाहिए जो मुद्रा की माग तथा पूर्ति में सतुलन स्थापित कर सके और जिसके द्वारा मूल्य-स्तर की स्थिरता को बनाये रखा जा सके। मुद्रामान से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का अध्ययन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों की प्रकृति तथा उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित ज्ञान प्राप्त किया जाय। मुद्रामानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

मुद्रामान



।

- (अ) स्वर्ण मुद्रामान
(Gold Currency Standard)
(ब) स्वर्ण पाट मान
(Gold Bullion Standard)
(स) स्वर्ण विनिमय मान
(Gold Exchange Standard)

एक धातुमान (Monometallism)

एक-धातुमान से अभिप्रायः उस मुद्रामान से है जिसमें एक धातु (सोना अथवा चाँदी) मूल्यमान का कार्य करती है और देश की मुद्रा का मूल्य इस धातु के मूल्य के साथ सम्बन्धित कर दिया जाता है। या तो इस धातु के सिक्के बनाये जाते हैं और उन्हें चलन में रखा जाता है, या देश में चलने वाली मुद्रा को एक निश्चित दर पर इस धातु में परिवर्तनीय कर दिया जाता है। एक-धातुमान प्रायः दो प्रकार का हो सकता है—स्वर्णमान अथवा रजतमान। जब सोने को मूल्यमान के रूप में स्वीकार किया जाता है और एक निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले सोने के सिक्के चलन में रहते हैं या देश में चलने वाली मुद्रा को एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनीय कर दिया जाता है तो इस प्रणाली को स्वर्णमान कहते हैं। स्वर्णमान में प्रमाणिक सिक्का सोने का होता है, उसकी स्वतन्त्र डलाई की जाती है तथा वह अपरिमित कानूनी मुद्रा होती है। देश में अन्य साकेतिक सिक्के अथवा नोट चल सकते हैं किन्तु उन सबका मूल्य प्रमाणिक सिक्के के साथ सम्बन्धित होता है। यदि सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते हैं तो देश में चलने वाली मुद्रा को एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनीय रखा जाता है। जब चाँदी मूल्यमान का कार्य करती है और प्रमाणिक सिक्के चाँदी के बनाये जाते हैं अथवा उन्हें एक निश्चित दर पर चाँदी में परिवर्तनीय रखा जाता है तो इस प्रणाली को रजतमान कहते हैं। दोनों में से स्वर्णमान ही अधिक प्रचलित रहा है और १९३६ से पूर्व ससार के सब बड़े देशों ने स्वर्णमान को अपनाया हुआ था केवल कुछ देशों में जैसे चीन, मेक्सिको, स्पेन और भारत ने रजतमान था।

एक धातुमान के लाभ—

एक धातुमान में कुछ विशेष लाभ पाये जाते हैं जिनके कारण वह बहुत अधिक समय तक ससार का प्रमुख मुद्रामान रहा है। इस मुद्रामान के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) यह प्रणाली साधारण है और लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं—एक धातुमान में एक ही धातु को मूल्यमान के रूप में प्रयोग किया जाता है

इसलिए साधारण व्यक्ति को भी इस प्रणाली के समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सोने और चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं के सिक्कों के चलन में रहने के कारण लोगों का विश्वास भी इस प्रणाली में बहुत अधिक होता है।

(२) प्रेशम के नियम के लागू होने की सम्भावना कम रहती है—इस प्रणाली में केवल एक ही धातु की मुद्रा चलन में होती है जिसके कारण प्रेशम के नियम के कार्यशील होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत द्वि-धातुमान में इस नियम के लागू होने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा रहती है—यदि संसार के अधिकांश देशों के द्वारा एक धातुमान को अपना लिया जाता है तो विदेशी भ्रगतानों की बड़ी सुविधापूर्ण ढंग से निवटाया जा सकता है। एक धातुमान वाले देशों में विदेशी विनिमय दरें आसानी से निश्चित हो जाती हैं और वे प्रायः स्थिर रहती हैं।

(४) मूल्य स्तर की स्थिरता—एक धातुमान में मुद्रा को सोने अथवा चांदी से सम्बन्धित करके उसकी मात्रा में होने वाले अनावश्यक परिवर्तनों को रोका जा सकता है जिससे कारण मूल्य-स्तर तथा मुद्रा की क्रय-शक्ति में अधिक स्थिरता आ जाती है।

एक धातुमान के दोष

इन गुणों के साथ-साथ एक धातुमान में कुछ दोष भी पाये जाते हैं जिनके कारण यह प्रणाली असतोषजनक रही है। कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

(१) एक धातुमान संसार के सब देशों के द्वारा एक साथ नहीं अपनाया जा सकता है—मोने अथवा चांदी में से जिस धातु को भी मूल्यमान के रूप में अपनाया जाता है उसकी कुल पूर्ति सब देशों की मुद्रा बनाने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है। अतः कुछ देशों को मुद्रा धातु की कमी के कारण एक धातुमान को छोड़ना पड़ेगा। संसार में मोने की मात्रा पर्याप्त न होने के कारण ही स्वर्णमान को त्यागकर उसके स्थान पर पत्र मुद्रामान को अपनाने की आवश्यकता अनुभव हुई है। यह ऐसा मुद्रामान है जिसे केवल वे देश ही अपना सकते हैं जिनके पास सोना व चांदी पर्याप्त मात्रा में हो। निर्धन देशों के द्वारा इस प्रकार के मुद्रा-मान अपनाया जाना सम्भव नहीं है।

(२) इस प्रणाली में मुद्रा के मूल्य की स्थिरता को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है—जिस धातु की मूल्यमान के रूप में अपनाया जाता है उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण मुद्रा की मात्रा बदलती रहती है और उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि स्वर्णमान के युग में सोने की मात्रा घट या बढ़ जाने के कारण समय-समय पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते थे।

(३) मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव रहता है—एक धातुमान में मुद्रा प्रणाली बहुत कम लोचदार होती है जिसके कारण मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता के अनुसार घटाना-बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। मुद्रा की मात्रा का घटाना-बढ़ाना मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार न होकर धातु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार होता है। इस प्रकार के मुद्रामान में आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए अधिक सोने व चाँदी की आवश्यकता पड़ती है। विशेषतया सकट काल में अधिक मात्रा में सोना या चाँदी प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है। इसी कारण प्रथम महायुद्ध में अधिकांश देशों को स्वर्णमान स्थगित करना पड़ा था।

द्वि-धातुमान (Bi-metallism)

द्वि-धातुमान उस मुद्रा प्रणाली को कहते हैं जिसमें दो धातुएँ एक साथ मूरयमान का कार्य करती हैं। दोनों धातुओं के बने हुए सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में चलाये जाते हैं और उन्हें एक निश्चित दर पर एक दूसरे के साथ बदलने की व्यवस्था होती है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से कोई भी दो धातुएँ मुद्रामान का कार्य कर सकती हैं किन्तु व्यावहारिक रूप में सोने और चाँदी का प्रयोग ही इस कार्य के लिए किया गया है। द्वि-धातुमान में सोने तथा चाँदी दोनों की स्वतंत्र बलाई की जाती है और उनके एक निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले सिक्के बनाये जाते हैं। दोनों प्रकार के सिक्के असीमित विधिग्राह्य होते हैं। दोनों मुद्रामे माय-साथ चलाई जाती हैं और उनकी आपसी विनिमय दर सरकार के द्वारा निश्चित कर दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को शुद्ध द्वि-धातुमान (Pure Bi-metallism) कहा जाता है। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार 'यदि दो धातुओं का प्रमाणिक मुद्रा के रूप में स्वतंत्र टकण हो सकता है और यदि दोनों ही धातुओं के मूल्य में अनुपात लेखे की इकाई के रूप में विधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है जिसमें केवल एक प्रमाणिक इकाई तथा कीमतों की एक व्यवस्था हो जाती है तो इस प्रकार के मुद्रामान को द्वि-धातुमान अथवा दोहरा मान कहते हैं।'³

द्वि-धातुमान का इतिहास—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक द्वि-धातुमान सत्तार का प्रमुख मुद्रामान था। द्वि-धातुमान को अपनाने का मुख्य कारण सोने की कमी थी। सबसे पहले इंग्लैंड ने १७१७ में रजतमान को त्याग कर द्वि-धातुमान को अपनाया। १७६२ में अमेरिका ने इस मान को अपनाया और १८७३ तक यह

3. "If two metals can be coined freely as standard money and if the ratio between the value of the two metals in terms of the units of account is fixed by law, so that there is only one standard unit and only one system of prices, then we have a bi-metallic standard or double standard."

मुद्रामान वहाँ प्रचलित रहा। १८०३ में फ्रांस ने द्वि-धातुमान को अपना लिया और सोने व चाँदी का विनिमय अनुपात १ : १५ $\frac{1}{2}$ निश्चित कर दिया गया। सन् १८४८ तक यह प्रणाली बिना किसी कठिनाई के चलती रही किन्तु १८४८-५० के बीच में सोने की नई खानों का पता लग जाने के कारण सोने की पूर्ति बढ गई और उसका मूल्य गिरने लगा। ऐसी दशा में प्रेशम के नियम के लागू होने के कारण द्वि-धातुमान का चलना कठिन हो गया और इस कठिनाई को दूर करने के लिए सोने और चाँदी का विनिमय अनुपात बदलना पड़ा। १८६५ में इटली, बेल्जियम, स्विटजरलैंड तथा कुछ अन्य यूरोप के देशों ने मिलकर सामूहिक रूप से द्वि-धातुमान को चलाने का प्रयत्न किया किन्तु १८७४ में चाँदी के मूल्य में भारी गिरावट आ जाने के कारण सोने और चाँदी के विनिमय अनुपात को नहीं बनाये रखा जा सका और द्वि-धातुमान टूट गया। सन् १९०० में द्वि-धातुमान की सदैव के लिए त्याग दिया गया। द्वि-धातुमान के पतन के मुख्य कारण, सोने की पूर्ति का बढ जाना, प्रेशम के नियम का बार-बार क्रयशील होना तथा इस प्रकार के मुद्रामान की अन्य व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी।

द्वि-धातुमान की विशेषतायें (Characteristics of Bi metallism)—

द्वि-धातुमान की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(१) द्वि-धातुमान में देश की मुद्रा इकाई के मूल्य को सोने और चाँदी की एक निश्चित मात्रा के द्वारा व्यक्त करना होता है। सन् १७९२ में अमेरिकन डॉलर (Dollar) के मूल्य को २४ \cdot ७५ ग्रेन सोने अथवा ३७१ \cdot २५ ग्रेन चाँदी के बराबर निश्चित किया गया। इसी प्रकार अन्य द्वि-धातुमान वाले देशों के द्वारा भी अपनी मुद्रा के मूल्य को सोने और चाँदी की निश्चित मात्रा के साथ सम्बन्धित कर दिया गया। इस प्रकार के मुद्रामान में या तो सोने व चाँदी के प्रमाणिक सिक्के चलाये जाते हैं और उनकी स्वतन्त्र ढलाई होती है या देश में चलने वाली पत्र मुद्रा को निश्चित दरो पर सोने व चाँदी में परिवर्तनशील रखा जाता है।

(२) सरकार द्वारा दोनों धातुओं के बीच एक विनिमय दर (Exchange Ratio) निश्चित कर दी जाती है जिसके अनुसार सोने व चाँदी को आपस में स्वतन्त्रतापूर्वक बदला जा सकता है। अमेरिका में सन् १७९२ में सोने व चाँदी की विनिमय दर को १ : १५ निश्चित किया गया जिसके अनुसार सोने की एक इकाई को चाँदी की १५ इकाई के साथ बदला जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा सोने और चाँदी के मूल्य में एक निश्चित सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो जाता है।

(३) मुद्रा अधिकारी निश्चित मूल्यों पर किसी भी सीमा तक सोने और चाँदी को बेचने की व्यवस्था करते हैं जिसके कारण इन धातुओं के बाजारी मूल्य सरकारी मूल्य से अधिक ऊपर या नीचे नहीं रह सकते हैं।

द्वि-धातुमान के लाभ (Advantages of Bi-metallism)—

द्वि-धातुमान के समर्थकों ने इस मान को एक-धातुमान की अपेक्षा अधिक उपयुक्त बतलाया है। उनके अनुसार इस प्रकार के मुद्रामान से निम्नलिखित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं—

(१) कीमतों में अधिक स्थिरता (Greater Stability of Prices)—

द्वि-धातुमान में एक-धातुमान की अपेक्षा कीमतों में अधिक स्थिरता रहती है। दो प्रकार की मुद्राएँ चलन में होने के कारण मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं और उनकी क्रय-शक्ति प्रायः निश्चित बनी रहती है। जब केवल एक धातु मुद्रामान का कार्य करती है तो उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण मुद्रा का मूल्य बदलता रहता है किन्तु द्वि-धातुमान में यह दोष बहुत सीमा तक दूर हो जाता है। सोने और चांदी की मुद्रायें एक साथ चलने के कारण मुद्रा धातु (money metal) की कुल पूर्ति प्रायः निश्चित रहती है और मुद्रा के मूल्य में स्थिरता आ जाती है। एक धातु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन दूसरी धातु की पूर्ति में विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तनों के साथ सन्तुलित हो जाते हैं। यदि देश में सोने की पूर्ति बढ़ती है तो उसके साथ यह सम्भव हो सकता है कि चांदी की पूर्ति कम हो जाये और देश में मुद्रा धातु (money metal) की कुल पूर्ति में कोई परिवर्तन न हो। इसी प्रकार सोने की पूर्ति के कम होने पर चांदी की पूर्ति बढ़ सकती है। ऐसी दशा में मुद्रा का मूल्य स्थिर बना रहता है। प्रो० जीवन्स (Jevons) ने इस बात को समझने के लिए दो शराबियों का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि दो शराबी यदि हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं तो वे अधिक स्थिरता के साथ चल सकते हैं। उनमें से यदि एक दाईं ओर गिरता है और दूसरा बाईं ओर तो वे दोनों एक दूसरे के साथ सन्तुलित हो जाते हैं। किन्तु यदि वे अलग-अलग चलते हैं तो उनमें से प्रत्येक के गिरने की सम्भावना बढ़ जाती है। द्वि-धातुमान में दो धातुओं के साथ-साथ चलने के कारण इसी प्रकार की स्थिरता स्थापित होती है। यदि एक धातु की पूर्ति बढ़ने के कारण उसका मूल्य गिरता है तो दूसरी धातु का मूल्य पूर्ति घटने के कारण बढ़ सकता है। इस प्रकार दोनों धातुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के साथ सन्तुलित हो जाते हैं और दोनों धातुओं के कुल कोष के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए जीवन्स (Jevons) ने एक और उदाहरण भी दिया है। उनके अनुसार 'यदि हम पानी की ऐसी दो टंकियों की कल्पना करें जिनमें से प्रत्येक पर पानी की मांग और पूर्ति का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है और यदि उन्हें जोड़ने वाला नल नहीं है तो उनमें से प्रत्येक टंकी में पानी का स्तर अपने ही परिवर्तनों से प्रभावित होगा किन्तु यदि दोनों को जोड़ने वाले नल को खोल दिया जाये तो दोनों टंकियों में पानी एक औसत स्तर पर आ जायेगा और पानी की अधिक मांग अथवा पूर्ति का प्रभाव दोनों टंकियों

पर समान रूप से वितरित हो जायेगा।^४ यदि जीवनस द्वारा बताये गये इस क्षति-पूरक प्रभाव (Compensatory Action) को स्वीकार कर लिया जाये तो द्वि-धातुमान में मुद्रा के मूल्य की स्थिरता की सम्भावना काफी अधिक हो जाती है। प्रो० फिशर (Fisher) ने भी इस मत का समर्थन किया है और उनके अनुसार—“द्वि-धातुमान ही मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने की एक ऐसी योजना है जिसे पर्याप्त सामान्य स्वीकृति मिली है।”^५ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विशेष परिस्थितियों में द्वि-धातुमान कीमतों में अधिक स्थिरता कायम कर सकता है।

(२) द्वि-धातुमान में सोने की कमी दूर हो जाती है—यदि ससार के सब देश स्वर्णमान को अपनाते हैं तो सोने की कुल पूर्ण मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी और सोने की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु द्वि-धातुमान में यह कठिनाई बिल्कुल दूर हो जाती है क्योंकि चाँदी का प्रयोग होने के कारण मुद्रा धातु की पूर्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके द्वारा मुद्रा की आवश्यकता को अपनी प्रकार पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार द्वि-धातुमान सोने की कमी को दूर करके मुद्रा विस्तार की उपयुक्त सुविधायें प्रदान करता है।

(३) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करता है—इस प्रकार के मुद्रामान में देश की मुद्रा का मूल्य सोने और चाँदी में एक साथ बतलाया जाता है, जिसके कारण स्वर्णमान तथा रजतमान वाले देशों के साथ विनिमय दरों को निर्धारित करना तथा उनकी स्थिरता को बनाये रखना आसान हो जाता है। विभिन्न देशों के बीच सोने और चाँदी का स्वतन्त्र निर्यात तथा आयात होता है जिसके कारण दोनों धातुओं का विनिमय अनुपात सब देशों में एक रहने की प्रवृत्ति रहती है और विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं। विनिमय दरों के स्थिर रहने के कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न देशों के बीच पूँजी का विनियोग बढ़ता है।

(४) इस प्रकार के मुद्रा मान में उत्पादक तथा श्रद्धालु वर्ग के लोगों को लाभ रहता है—द्वि-धातुमान में मुद्रा की मात्रा काफी होती है और उसमें वृद्धि भी तेजी के साथ होती है जिसके कारण कीमतों के धीरे-धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती

4 “Imagine two reservoirs of water each subject to independent variation of supply and demand. In the absence of any connecting pipe the level of water in each will be subject to its fluctuations only. But if we open a connection, the water in both will assume a certain mean level and the effects of any excessive supply or demand will be distributed over the whole area of both reservoirs.”

—*Jessons Money & the Mechanism of Exchange*, P. 140.

5 “Bi-metallism is the only scheme for securing stability of the standard of value which has received any substantial measure of popular support”

—*Fisher : The Purchasing Power of Money*.

है। मूल्य-स्तर के ऊँचा होने के कारण उत्पादकों के लाभ बढ़ते हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ऋणियों को भी लाभ होता है क्योंकि उनके लिए ऋण का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत एक धातुमान में सोने की कमी के कारण, मुद्रा की कमी रहती है और वस्तुओं के मूल्य नीचे रहते हैं जिससे उत्पादकों को लाभ कम होते हैं तथा ऋणों का भार बढ़ जाता है।

द्वि-धातुमान के दोष (Disadvantages of Bi-metallism)—

(१) सोने और चांदी के टकसाली अनुपात (Mint Ratio) को बनाये रखना कठिन होता है—द्वि-धातुमान का एक बड़ा दोष यह है कि बाजार में सोने व चांदी की माग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण सोने और चांदी के टकसाली अनुपात को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है। जब दोनों धातुओं का टकसाली अनुपात बाजारी अनुपात से भिन्न हो जाता है तो दैनिक भुगतानों को निबटाने में विशेष कठिनाई होती है। भुगतान लेने वाले मंहेंगी धातु के सिक्कों में भुगतान लेना चाहते हैं और देने वाले सस्ती धातु के सिक्के में भुगतान करना पसन्द करते हैं, जिसके कारण काफी असुविधा होती है। यदि दोनों धातुओं में से किसी एक का सापेक्षिक मूल्य बाजार में बढ़ जाता है तो उस धातु को कोई भी सिक्के बनवाने के लिए नहीं लायेगा और टकसाल पर केवल सस्ती धातु ही सिक्के बनाने के लिए प्रस्तुत की जायेगी। ऐसी दशा में सरकार के लिए विशेष कठिनाई पैदा हो जाती है और उसे मजबूर होकर टकसाली अनुपात को बाजारी अनुपात के बराबर करना पड़ता है।

(२) प्रेशम के नियम का कार्यशील होना—द्वि-धातुमान का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें प्रेशम के नियम के लागू होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब भी टकसाली दर (Mint Ratio) और बाजारी दर (Market Ratio) में अन्तर होता है तब ही प्रेशम का नियम काम करने लगता है। जो धातु बाजार में टकसाल की अपेक्षा मंहेंगी होती है उसके सिक्के चलन से गायब हो जाते हैं और केवल सस्ती धातु के सिक्के ही चलन में रह जाते हैं। ऐसी दशा में एक धातु का आयात अथवा निर्यात लाभदायक हो जाता है और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए या तो सरकार को टकसाली दर कम करनी होती है या द्वि-धातुमान को त्याग देना पड़ता है। जब तक ससार के सब देश मिलकर द्वि-धातुमान को न अपनायें और सब देशों में सोने व चांदी के विनिमय अनुपात को एक न रखवा जाये तब तक प्रेशम के नियम को कार्यशील होने से नहीं रोका जा सकता है। यही कारण है कि कुछ एक देशों में चलने वाला द्वि-धातुमान सफल नहीं हो सकता है।

(३) द्वि-धातुमान में वस्तुओं के मूल्य स्थिर नहीं रह सकते हैं—आलोचकों के अनुसार द्वि-धातुमान में सदा वस्तुओं के मूल्य स्थिर नहीं रहते हैं और इस

मुद्रामान में भी कीमतों में परिवर्तन हो सकते हैं। यह ठीक है कि कुछ समय तक द्वि-धातुमान वाले देशों में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि द्वि-धातुमान में हमेशा ऐसा ही होता है। यह सम्भव हो सकता है कि सोने और चांदी की पूर्ति में एक साथ वृद्धि अथवा कमी होने लगे। ऐसी दशा में मुद्रा के मूल्य में भी भारी परिवर्तन हो सकते हैं और कीमतों की स्थिरता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के मुद्रामान में कीमतों की स्थिरता तब तक ही रहती है जब तक एक धातु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन दूसरी धातु की पूर्ति में होने वाले विपरीत परिवर्तनों के द्वारा सन्तुलित होते रहते हैं। किन्तु सर्वत्र ऐसा ही होगा, इसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। अतः द्वि-धातुमान में मुद्रा के मूल्य की स्थिरता का पाया जाना अनिवार्य नहीं है।

द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक कार्य

(Compensatory Action of Bi metallism)—

द्वि-धातुमान के समर्थकों का कहना है कि इन मान में कुछ ऐसी क्षतिपूरक शक्तियाँ काम किया करती हैं जिनके प्रभाव से मूल्य स्तर में स्वयं स्थिरता स्थापित हो जाती है। जब कभी भी सोने व चांदी के टंकसाली अनुपात और बाजारी अनुपात में अन्तर होता है तो क्षतिपूरक शक्तियाँ उन दोनों को बराबर बाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यदि चांदी बाजार की अपेक्षा टंकसाल पर महंगी है तो प्रत्येक व्यक्ति सिक्के बनवाने के लिए चांदी ही लायेगा। सोने का भाव बाजार में अधिक होने के कारण सोने के सिक्कों को पिघलाने की प्रवृत्ति पाई जायेगी। इस प्रकार चांदी बाजार से टंकसाल पर जाने लगेगी और सोना टंकसाल से बाजार में आयेगा। बाजार में चांदी की कमी हो जायेगी और सोने की पूर्ति बढ़ेगी जिसके कारण चांदी का मूल्य बढ़ने लगेगा और सोने का मूल्य गिरेगा। इस प्रकार सोने व चांदी का बाजारी विनिमय अनुपात (Market Ratio) टंकसाली अनुपात (Mint Ratio) के समीप आ जायेगा और मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनी रहेगी। बाजार में एक धातु के मूल्य के गिरने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि होने लगती है वह इसलिए एक जाती है क्योंकि दूसरी धातु के मूल्य के बढ़ने का प्रभाव मूल्य स्तर को गिराने का होता है। इस प्रकार परस्पर सन्तुलन के द्वारा कीमतों में स्थिरता बनी रहती है।

यह क्षतिपूरक शक्तियाँ कभी-कभी इतनी कमजोर होती हैं कि वे मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को नहीं रोक पाती हैं और मुद्रा की कय-शक्ति की स्थिरता समाप्त हो जाती है। यदि दोनों धातुओं में से किसी एक की पूर्ति के बढ़ने या घटने की बहुत तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है तो क्षतिपूरक शक्तियाँ भी उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं रोक सकेंगी और बाजारी अनुपात तथा टंकसाली अनुपात का अन्तर बराबर बना रहेगा। उदाहरणार्थ यदि नई खानों के खुलने के कारण

बाजार में चांदी की पूर्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तो लोगो के द्वारा टकसाल पर अधिक चांदी प्रस्तुत करने पर भी चांदी के मूल्य में गिरावट आना स्वाभाविक है और इस प्रकार चांदी और सोने का बाजारी भाव सरकारी भाव से भिन्न रहने की प्रवृत्ति रहेगा। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब सोने और चांदी के मूल्य में एक साथ ही दिशा में परिवर्तन हुए हैं और जिनके परिणामस्वरूप मुद्रा के मूल्य में भी भारी परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रकार यह कहना उचित न होगा कि क्षतिपूर्क क्रियाओं के द्वारा द्वि-धातुमान में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन बिल्कुल दूर हो जाते हैं।

द्वि-धातुमान की सफलता की दशायें—

अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वि-धातुमान एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में ही सफल हो सकता है। कुछ एक देशों के द्वारा अपनाया गया द्वि-धातुमान, प्रेशम के नियम के कार्यशील होने के कारण, टूट जाने की प्रवृत्ति रखता है। यदि बहुत से देश एक साथ द्वि-धातुमान को स्वीकार करते हैं और सोने तथा चांदी के विनिमय अनुपात को निश्चित रखा जाता है, तो प्रेशम के नियम को कार्यशील होने से रोका जा सकता है और द्वि-धातुमान को बनाये रखना सम्भव होता है। जितने अधिक देश एक निश्चित विनिमय अनुपात पर द्वि-धातुमान को अपनाते हैं उतनी ही क्षतिपूर्क शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं और द्वि-धातुमान की सफलता की सम्भावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय द्वि-धातुमान सम्भव नहीं है और केवल बहुत से देशों के द्वारा एक निश्चित विनिमय अनुपात पर, सामूहिक रूप से अपनाया जाने वाला द्वि-धातुमान ही व्यवहारिक रूप से चल सकता है। द्वि-धातुमान की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ही टकसाली अनुपात (Mint Ratio) की स्थिरता को स्थापित करना सम्भव हो सकता है। प्रो० हॉम (Prof. Halm) के अनुसार “यदि द्वि-धातुमान को एक ही टकसाली दर पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना लिया जाता है तो दोनों धातुओं का विनिमय अनुपात किसी प्रकार स्थिर हो ही जाता है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व के लिए टकसाली अनुपात व बाजारी अनुपात में भिन्नता होना असम्भव है।”^६

द्वि-धातुमान का भविष्य (Future of Bi-metallism)—पिछली शताब्दी के समाप्त होने के साथ ही द्वि-धातुमान भी सदैव के लिए समाप्त हो चुका है। सन् १८७८ और १८८२ के मुद्रा सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान को स्थापित करने के लिए कुछ प्रयत्न किये गये किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव के कारण इस प्रकार का मुद्रामान स्थापित न किया जा सका। सन् १९२६-३० में अमरीका

6 “Assuming . . . the international adoption of bi-metallism on a common mint ratio, the unit ratio would be secured any how, since divergencies between market and mint ratio would now be impossible for the world as a whole”

—Halm : Monetary Theory, P. 111.

में कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा द्वि-धातुमान का समर्थन किया गया किन्तु उसे व्यवहारिक रूप देना सम्भव न हो सका। आजकल द्वि-धातुमान के समर्थक बहुत कम रह गये हैं और उसका कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है। वर्तमान समाज धातुमान को छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है और सभी देशों ने उसके स्थान पर पथ मुद्रामान को अपना लिया है। धातुमान का अब किसी भी रूप में अपनाया जाना सम्भव नहीं है। ससार में अब तक जितने भी प्रयत्न धातुमान को फिर से स्थापित करने के लिए किये गये हैं वे सभी असफल रहे हैं। ऐसी दशाओं में द्वि-धातुमान सम्बन्धी वाद-विवाद निरर्थक प्रतीत होता है और उसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है।

पंगु द्वि-धातुमान (Limping Bi-metallism)—यह द्वि-धातुमान का अशुद्ध रूप है। इस प्रणाली में भाँ दोनो धातुओं (सोना और चाँदी) के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं और दोनो प्रकार के सिक्के अपरिमित कानूनी मुद्रा होते हैं तथा उनकी आपसो विनिमय दर सरकार के द्वारा निश्चित कर दी जाती है। किन्तु दोनो में से केवल एक की स्वतन्त्र ढलाई की जाती है। प्रायः चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती है और उसके सिक्के केवल सीमित मात्रा में ही चलाये जाते हैं। इस प्रणाली को पंगुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस धातु की स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती है वह बठिनाई के साथ चलती है। इस प्रकार का मुद्रा मान कुछ समय के लिए फ्रांस में अपनाया गया था। उस समय वहाँ पर सोने और चाँदी के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में चलते थे। दोनो प्रकार के सिक्के अपरिमित कानूनी मुद्रा थे और निश्चित दर पर आपस में बदले जाते थे परन्तु चाँदी के सिक्को की स्वतन्त्र ढलाई नहीं की जाती थी।

मिश्रित धातुमान

(Symetallism)

दोनों धातुओं को मिलाकर मुद्रामान के रूप में प्रयोग करने की विधि को मिश्रित धातुमान कहते हैं। इस प्रणाली में सोने और चाँदी के अलग-अलग सिक्के नहीं चलते हैं, बल्कि दोनों धातुओं की मिलाकर ऐसी सलाखें (Bars) बनाई जाती हैं जो भूख्यमान का कार्य करती हैं। द्वि-धातुमान में सबसे बड़ा दोष प्रेशम के नियम के लागू होने के कारण पैदा होता है। इस दोष को दूर करने व द्वि-धातुमान के अनेक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य में प्रो० माशॉल ने १८८१ में मिश्रित मान को अपनाने का सुझाव दिया था। उनका सुझाव था कि देश में सोने और चाँदी के अलग-अलग सिक्के नहीं चलाये जाने चाहिए और देश की मुद्रा को सोने तथा चाँदी में बदलने की सुविधा भी नहीं देनी चाहिए। मुद्रामान का कार्य करने के लिए ऐसी सलाखों (Bars) का निर्माण करना चाहिए जिनमें सोना और चाँदी एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया हो। देश की मुद्रा एक निश्चित दर पर इस

प्रकार की सलाखों (Bars) में परिवर्तनीय होनी चाहिए। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें ग्रेशम के नियम के लागू होने का भय विलुप्त समाप्त हो जाता है। क्योंकि सोने और चाँदी की मिश्रित सलाखें मुद्रामान का कार्य करती हैं इसलिए सोने और चाँदी के मूल्यों में होने वाले अनुपातिक परिवर्तनों का इस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो पाता है। इसके साथ-साथ इन प्रणाली में द्वि-धातुमान के सब गुण पाये जाते हैं। इन सब गुणों के होते हुए भी इस प्रकार का मुद्रामान कभी किसी देश में नहीं अपनाया गया है और इसका महत्व केवल एक सैद्धान्तिक विचार के रूप में ही है। व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार का मुद्रामान सम्भव नहीं है।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

किसी देश में जब दो प्रकार की मुद्रायें एक साथ चलती हैं तो अच्छी मुद्रा चलन से गायब हो जाने की प्रवृत्ति रखती है और केवल बुरी मुद्रा ही चलन में रहती है। ग्रेशम का नियम इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि टॉमस ग्रेशम ने ही इस प्रवृत्ति का सबसे पहले पता लगाया किन्तु यह नियम उनके नाम से ही जाना जाता है। प्राचीन आर्थिक विचारों में भी इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है किन्तु उसे एक नियम का रूप देने का कार्य टॉमस ग्रेशम के द्वारा ही किया गया। इसीलिए यह नियम उनके नाम से प्रसिद्ध है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में बहुत से पुराने तथा कम वजन के सिक्के चलन में थे क्योंकि उनसे पहले ट्यूडर शासकों के द्वारा बहुत से निकृष्ट सिक्के चलन में डाल दिये गये थे। महारानी एलिजाबेथ ने देश की मुद्रा में सुधार करना चाहा और इस उद्देश्य से बहुत से नये तथा पूरे वजन के सिक्के चलन में डाले गये। उनका विचार था कि नई और अच्छी मुद्रा के चलन में आने से लोग केवल उसका ही प्रयोग करेंगे और निकृष्ट सिक्के सरकारी कोष में वापस आ जायेंगे किन्तु परिणाम इसके विपरीत हुआ। जैसे ही नये सिक्के चलन में डाले जाते थे वे ही वे गायब हो जाते थे और पुराने तथा निकृष्ट सिक्के ही चलन में रहते थे। नई मुद्रा को चलन में रखने का यह प्रयत्न कई बार किया गया किन्तु प्रत्येक बार उसमें असफलता ही मिली। महारानी को इस बात से बड़ी निराशा हुई और उन्होंने इस असफलता का कारण जानना चाहा। सर टॉमस ग्रेशम जो उस समय के एक बहुत बड़े व्यापारी तथा महारानी के आर्थिक सलाहकार थे, उनके सामने यह समस्या रखी गई। उन्होंने यह बतलाया कि ऐसा होता वित्तीय दृष्टिकोण से स्वाभाविक है क्योंकि "बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति रखती है, किन्तु अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं निकाल सकती है।"⁷

7 "Bad money drives out good money but good money cannot drive out bad."

प्रेषण के नियम के अनुसार, "अन्य बातें समान रहने पर जब किसी देश में दो (या अधिक) प्रकार की मुद्रायें एक ही समय में चलती हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की चलन से बाहर निकाल देती है।"^८ यदि किसी देश में अच्छी और बुरी मुद्रायें एक साथ चलती हैं और यदि दोनों ही असीमित विधिप्राप्त हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की चलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति रखती है। आरम्भ में इस नियम की व्याख्या केवल एक धातुमान के दृष्टिकोण से ही की गई थी किन्तु बाद के अर्थशास्त्रियों ने नियम का विस्तार करके उसे द्वि-धातुमान तथा पत्र मुद्रामान के सम्बन्ध में भी लागू किया है। प्रो० मार्शल ने इस नियम की व्याख्या इस प्रकार की है—“यदि हीन मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं है, तो वह अच्छी मुद्रा की प्रचलन से बाहर निकाल देती है।”^९

इस नियम के सम्बन्ध में हमें अच्छी और बुरी मुद्रा का भेद भली प्रकार समझ लेना चाहिए। बुरी मुद्रा का अभिप्राय हमेशा छोटे तथा कटे हुए सिक्कों से नहीं है, बल्कि बुरी मुद्रा का अर्थ उन मुद्राओं से होता है जिनका धातु मूल्य हल्का और सस्ता हो। एक धातुमान (Monometallism) में पुराने, धिसे हुए तथा कम वजन के सिक्के ही बुरी मुद्रा होते हैं, किन्तु द्वि-धातुमान में बुरी मुद्रा वह होती है जो घटिया और सस्ती धातु की बनी हो। यदि पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा एक साथ चलती हैं तो पत्र मुद्रा बुरी तथा धातु मुद्रा अच्छी मुद्रा होगी। यह स्मरण रहे कि प्रेषण के नियम में अच्छी और बुरी मुद्रा शब्द का प्रयोग सापेक्षिक रूप में किया जाता है। एक मुद्रा दूसरी मुद्रा की अपेक्षा अच्छी या बुरी हो सकती है। यदि ऐसा हो तो केवल बुरी मुद्रा ही चलन में रहती है और अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है।

अच्छी मुद्रा चलन से बाहर क्यों हो जाती है ?

प्रेषण के नियम के लागू होने की दशा में अच्छी मुद्रा के चलन से बाहर निकल जाने के निम्नलिखित कारण बताये गये हैं—

(१) अच्छी मुद्रा का सग्रह (Hoarding of Good Money)—लोगों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे केवल नये और पूरे वजन के सिक्कों का ही सग्रह करते हैं क्योंकि ऐसा करने में उन्हें लाभ रहता है। पुरानी और बुरी मुद्रा को लोग जमा के रूप में नहीं रखना चाहते हैं और उसे केवल चलन में ही रखा जाता है। इस प्रकार चलन में डाली जाने वाली नई और अच्छी मुद्रा का कुछ भाग लोगो

8 "Other things being equal, when in a country two (or more) kinds of money circulate at the same time, bad money drives good money out of circulation."

9 "An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency." —Alfred Marshall : Money, Currency and Credit.

के द्वारा जमा कर लिया जाता है और उसे तिजोरियों में बन्द करके यद्यदा जमीन में गाड़ कर रख दिया जाता है ।

(२) अच्छे सिक्कों को पिघला देना (Melting of Good Coins)—जो लोग सिक्को को पिघला कर उनमें से धातु प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल नये और पूरे वजन के सिक्को को ही पिघलाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अधिक धातु प्राप्त होती है । पिघलाने के लिए घिसे हुए और कम वजन के सिक्को को नहीं चुना जाता है । अच्छी मुद्रा की काफी बड़ी मात्रा चन्नन से इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि उसे सर्राफों तथा अन्य लोगों के द्वारा पिघला डाला जाता है ।

(३) अच्छे सिक्कों का निर्यात (Export of Good Coins)—यापारियों के द्वारा अच्छे और पूरे वजन के सिक्को का विदेशी भुगतान निबटाने के लिए निर्यात कर दिया जाता है । क्योंकि एक देश के सिक्के दूसरे देश में मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किये जाते हैं और उन्हें तोलकर धातुओं के रूप में लिया जाता है, इसलिए व्यापारियों को नये और पूरे वजन के सिक्को को बाहर भेजने में लाभ रहता है ।

बुरी मुद्रा चलन में क्यों रहती है ?

बुरी मुद्रा चलन में इसलिए रहती है क्योंकि विनिमय का कार्य करने के लिए अच्छी और बुरी मुद्रा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है । बुरी मुद्रा भी विनिमय का कार्य उतनी ही अच्छी प्रकार से करती है जितनी की अच्छी मुद्रा । इसलिए लोग बुरी मुद्रा को विनिमय का कार्य करने के लिए बराबर प्रयोग करते रहते हैं और वह चन्नन से बाहर नहीं होती है । इसका दूसरा कारण लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसके आधीन वे अच्छी मुद्रा को अपने पास रखते हैं और बुरी मुद्रा को भुगतानों में देते हैं । अच्छी और नई मुद्रा को लोगों के द्वारा रोक लिया जाता है और केवल बुरी मुद्रा ही चलन में रह जाती है । व्यापारी लोग भी बुरी मुद्रा को चलन में रखने में सहायता देते हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों को प्रसन्न रखने के लिए ऐसी बुरी मुद्रा को स्वीकार कर लेते हैं जिसे वे भागे चला सकें । इन्हीं सब कारणों से बुरी मुद्रा चलन में रहने की प्रवृत्ति रखती है ।

नियम का क्षेत्र (Scope of the Law)—

यद्यपि प्रेशम के नियम की व्याख्या एक धातुमान तथा द्वि-धातुमान के सम्बन्ध में ही की जाती है किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह नियम पत्र मुद्रामान में भी कार्यक्षेत्र हो सकता है । नियम का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों के सम्बन्ध में उसका अध्ययन किया जाये ।

एक धातुमान में नियम (Law under Monometallism)—

एक धातुमान प्रणाली में यह नियम दो दशाओं में लागू होता है । (अ) यदि देश में केवल प्रमाणिक मुद्रा ही चलती हो—ऐसी दशा में जो सिक्के पुराने हो गए

हैं और घिस जाने अथवा कट जाने के कारण उनका वजन कम हो गया है, वे बुरी मुद्रा होने के कारण चलन में रहने की प्रवृत्ति रखेंगे और नये तथा पूरे वजन के सिक्के लोगों के द्वारा जमा कर लिए जायेंगे अथवा उन्हें गला दिया जायेगा।

(घ) यदि देश में प्रमाणिक और सांकेतिक सिक्के एक साथ चलते हों। ऐसी दशा में सांकेतिक सिक्के ही चलन में रहेंगे क्योंकि उनका घात्विक मूल्य प्रमाणिक सिक्कों की अपेक्षा कम होता है। प्रमाणिक सिक्के अधिक घात्विक मूल्य होने के कारण गला दिये जायेंगे अथवा लोग उन्हें अपने पास रोक लेंगे। इस प्रकार दोनों ही दशाओं में प्रेशम का नियम कार्यशील होगा। भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की स्थिति तब पैदा हुई जब महारानी विक्टोरिया और जार्ज षष्ठम के दो प्रकार के रुपये चलन में थे। लोगों ने विक्टोरिया के रुपये में अधिक चाँदी होने के कारण उन्हें गला डाला और केवल जार्ज षष्ठम के धटिया रुपये ही चलन में रह गये।

द्वि-धातुमान में प्रेशम का नियम—

द्वि-धातुमान में प्रेशम के नियम के लागू होने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है और वह द्वि-धातुमान की असफलता का मुख्य कारण बनता जाता है। जब भी दोनों में से किसी एक धातु का बाजारी मूल्य टक्काली मूल्य की अपेक्षा अधिक हो जाना है तो उस धातु के सिक्के चलन से गायब हो जाते हैं। द्वि-धातुमान में सोने और चाँदी के सिक्के एक साथ चलाने जाते हैं और उनका विनियम अनुपात सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है, जिसे टक्काली अनुपात (Mint Ratio) कहते हैं। इसी प्रकार सोने और चाँदी का एक बाजारी अनुपात (Market Ratio) होता है, जिसके अनुसार सोना और चाँदी बाजार में एक दूसरे के साथ बदलते जाते हैं। जब तक बाजारी अनुपात टक्काली अनुपात के बराबर होता है तो प्रेशम का नियम लागू नहीं होता है, किन्तु जैसे ही इन दोनों में अन्तर पड़ा जाता है वैसे ही नियम कार्यशील होने लगता है। टक्काली अनुपात प्रायः निश्चित रहता है किन्तु बाजारी अनुपात सोने और चाँदी की माँग और पूर्ति में परिवर्तन होने के साथ बदलता रहता है। यह सम्भव हो सकता है कि बाजार में एक धातु के मूल्य में दूसरी धातु की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ परिवर्तन हो जायें। ऐसी दशा में एक धातु टक्काली दर में सस्ती और बाजार में महंगी हो जाती है। जिस धातु का बाजारी मूल्य टक्काली मूल्य की अपेक्षा अधिक होना है उसके सिक्के अच्छी मुद्रा होने के कारण चलन से गायब हो जाते हैं और जो धातु बाजार में सस्ती होती है, उसके सिक्के बुरी मुद्रा होने के कारण चलन में रहते हैं।

उदाहरणार्थ यदि किसी देश में सोने और चाँदी की सरकारी दर (Mint Ratio) १ : १६ निश्चित की गई है तो कोई भी टक्काली में १६ चाँदी के सिक्को के बदले में सोने का सिक्का प्राप्त कर सकता है। यदि सोने और चाँदी का बाजारी अनुपात भी १ : १६ है तो प्रेशम का नियम कार्यशील नहीं होगा, किन्तु यदि सोने

का बाजारी मूल्य चाँदी की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है और बाजारी अनुपात (Market Ratio) बदलकर १ : १७ हो जाता है तो यह नियम काम करने लगेगा। अब लोगों के लिए सोने के सिक्को को पिघलाना लाभदायक हो गया है। वे १६ चाँदी के सिक्को के बदले में एक सोने का निकास टकसाल से लाकर उसे बाजार में १७ चाँदी के सिक्को के बदले में बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सोने के समस्त सिक्के पिघला दिये जायेंगे और केवल चाँदी के सिक्के ही चलन में रह जायेंगे। भारतवर्ष में जब सोने और चाँदी के सिक्के एक साथ चलन में डाले गये तो सोने के सिक्के चलन में डालते ही गायब हो गये। ब्रिटिश सरकार ने समझा कि भारतवासी सोने की मुद्रा पसन्द नहीं करते हैं किन्तु सोने के गायब हो जाने का वास्तविक कारण ग्रेशम के नियम का कार्यशील होना था।

जब धातु और पत्र मुद्रा का चलन साथ-साथ हो—

जब देश में धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा एक साथ चलती हैं, तो धातु के सिक्के चलन से बाहर हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु मुद्रा पत्र मुद्रा की अपेक्षा अच्छी मुद्रा समझी जाती है क्योंकि उसका वस्तु के रूप में भी कुछ मूल्य होता है किन्तु पत्र मुद्रा का वास्तविक मूल्य शून्य होता है। लोग धातु मुद्रा को जमा करने की प्रवृत्ति रखेंगे तथा उसे धातु निकालने के लिए गलाया भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में पत्र मुद्रा धातु मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। प्रायः ऐसा तब होता है जब धातु मुद्रा का बाजारी मूल्य काफी अधिक बढ़ जाता है।

पत्र मुद्रामान के नियम—

पत्र मुद्रामान की स्थिति में भी ग्रेशम का नियम लागू हो सकता है। यदि देश में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा तथा परिवर्तनीय पत्र मुद्रायें साथ-साथ चलती हैं तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा थोड़ा होने के कारण चलन से बाहर हो सकती है। जब परिवर्तनीय पत्र मुद्राएँ एक साथ चलती हैं तो लोग परिवर्तनीय मुद्रा को जमा कर सकते हैं और केवल अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चलन में रह सकती है। एक ही प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में होने पर लोग गन्दे तथा फटे नोटों को चलन में रखने की प्रवृत्ति रखते हैं और नये तथा साफ नोटों को जमा किया जा सकता है। किन्तु पत्र मुद्रामान में ग्रेशम के नियम का लागू होना अधिकांश रूप से काल्पनिक है। वास्तव में इस नियम का महत्व केवल धातुमान में ही है और पत्र मुद्रामान की व्यवस्था के अन्तर्गत यह नियम कोई विशेष वाधा उत्पन्न नहीं करता है।

नियम की सीमाएँ—

यद्यपि प्रत्येक प्रकार के मुद्रामान में ग्रेशम का नियम लागू होने की प्रवृत्ति रखता है किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। प्रो० मार्शल ने इस नियम की ररिभाषा करते समय उसकी सीमाओं की ओर भी ध्यान आकषिप्त किया है। उनके अनुसार यदि बुरी मुद्रा का चलन सीमित होता है तो ऐसी दशा में नियम के

कार्यशील होने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में प्रेशम का नियम कार्यशील नहीं होता है—

(१) जब मुद्रा की कुल मात्रा आवश्यकता से कम हो—यदि मुद्रा की कुल मात्रा, अच्छी और बुरी मुद्रा को मिलाकर, देश की व्यापार तथा व्यवसायिक आवश्यकता से कम रह जाती है तो ऐसी दशा में यह नियम कार्यशील नहीं होगा। वास्तव में प्रत्येक देश के लिए विनिमय के कार्य को ठीक प्रकार चलाने के लिए मुद्रा की एक न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है। यदि मुद्रा की कुल मात्रा इस आवश्यक मात्रा से कम रह जाती है तो विनिमय कार्य में भारी प्रभुविधा होने लगती है और ऐसी दशा में लोग अच्छी मुद्रा का संचय नहीं करेंगे। दोनों प्रकार की मुद्राओं का विनिमय कार्य करने के लिए प्रयोग किया जायेगा और प्रेशम का नियम लागू नहीं हो सकेगा। इसीलिए मार्शल ने कहा है कि प्रेशम का नियम तब लागू होता है जब निष्कृष्ट मुद्रा अभीमित मात्रा में जमाई जाती है।

(२) जब लोग बुरी मुद्रा का बहिष्कार करने लगे—यदि सब लोग मिलकर बुरी मुद्रा को न स्वीकार करने का निश्चय कर लेते हैं तो प्रेशम का नियम कार्यशील नहीं होगा। यदि बुरी मुद्रा इतनी निष्कृष्ट हो गई है अथवा उसका मूल्य इतना अधिक गिर गया है कि लोग उसे अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं के बदलने में स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में बुरी मुद्रा स्वयं चलन से बाहर हो जायगी और प्रेशम का नियम कार्यशील नहीं हो सकेगा।

(३) जब विभिन्न मुद्राओं का कार्य-क्षेत्र अलग-अलग हो—यदि देश में चलने वाली प्रमाणिक तथा सांकेतिक मुद्राओं का कार्य-क्षेत्र अलग-अलग निश्चित कर दिया जाता है और वे भिन्न-भिन्न प्रकार की भाग को पूरा करती हैं, तो यह नियम कार्यशील नहीं होगा और दोनों प्रकार की मुद्राएँ चलन में रहेंगी। ऐसी दशा में सांकेतिक मुद्रा के बुरी मुद्रा होते हुए भी प्रमाणिक सिक्कों को चलन से बाहर नहीं निकाल सकेंगे।

(४) बैंकिंग का पर्याप्त विकास हो जाने की दशा में—बैंकों का विकास तथा साख मुद्रा का प्रयोग भी प्रेशम के नियम को कार्यशील होने से रोकता रहता है। जब लोग अपने धन को बैंकों में जमा रखने के अभ्यस्त हो जाते हैं और अधिकांश भुगतान बैंकों के द्वारा निबटाये जाने लगते हैं तो ऐसी दशा में लोगों के द्वारा अच्छी मुद्रा के संग्रह किये जाने का प्रयत्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में भुगतानों को निबटाने के लिए बैंक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है और बैंक मुद्रा में अच्छी और बुरी मुद्रा का भेद नहीं किया जा सकता है। इसी कारण वर्तमान समाज में इस नियम के कार्यशील होने की समस्या लगभग समाप्त हो गई है।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान की दशा में—यदि द्वि-धातुमान को सत्कार के अधिकांश देशों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में अपना लिया जाता है

और सभी देशों में सोने व चांदी का विनिमय अनुपात एक रखा जाता है तो ऐसी दशा में क्षतिपूरक प्रभाव (Compensatory Action) के कारण प्रेशम के नियम के कार्यशील होने की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुमान की स्थिति में क्षतिपूरक शक्तियाँ टकसाली अनुपात (Mint Ratio) तथा बाजारी अनुपात (Market Ratio) में समानता स्थापित करके प्रेशम के नियम की प्रवृत्तियों को अत्यन्त कमजोर कर देती है।

अन्य प्रकार के मुद्रामान

(Other Types of Monetary Standard)

एक धातुमान तथा द्वि-धातुमान के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के मुद्रामान भी हो सकते हैं। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार के मुद्रामान अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से उनका अध्ययन आवश्यक है। इनमें से कुछ मुद्रामान इस प्रकार हैं—

(१) बहु-धातुमान (Multimetallism)—बहु-धातुमान उस मुद्रा प्रणाली को कहते हैं जिसमें कई धातुओं एक साथ मूल्यमान का कार्य करती हैं। इस प्रकार के धातुमान में विभिन्न प्रकार की धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में चलाये जाते हैं, उनका स्वतन्त्र मुद्रण किया जाता है तथा उनमें से प्रत्येक धातु के सिक्कों का विनिमय अनुपात अन्य धातुओं के सिक्कों के साथ निश्चित होता है। प्रत्येक धातु के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा होते हैं और ऋणदाता को किसी भी धातु के सिक्को में ऋण चुकाने का अधिकार होता है। व्यावहारिक दृष्टि से इस मुद्रामान में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। विभिन्न धातुओं के मूल्यों में तुलनात्मक परिवर्तन हो जाने के कारण उनके विनिमय अनुपातों को बनाये रखना असम्भव हो जाता है और ऐसी दशा में इस प्रकार का मुद्रामान टूट जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिक्कों के एक साथ चलन में होने से भ्रुणतानों की निवटाने में काफी असुविधा हो सकती है। इन्हीं कारणों से बहु-धातुमान को कभी भी किसी देश के द्वारा नहीं अपनाया गया है।

(२) समानान्तर मान (Parallel Standard)—इस प्रकार के मुद्रामान में द्वि-धातुमान की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं किन्तु दोनों धातुओं का विनिमय अनुपात सरकार के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है और अग्रे, निश्चित, होते के लिए बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। समानान्तर मुद्रामान में दो धातुओं के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं और वे असीमित विधिग्राह्य होते हैं किन्तु उनका आपसी विनिमय अनुपात सरकार निश्चित नहीं करती है। जब सोने व चांदी की मुद्राओं को स्याई रूप से चलन में रखना आवश्यक समझा जाता है तो दोनों प्रकार के सिक्कों का विनिमय अनुपात बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है और सरकार उन्हें प्रचलित दैनिक दर पर स्वीकार करती है। इस प्रकार का

मुद्रा मान नू १६६३ में डगलैंड में अपनाया गया था किन्तु विशेष अनुविधाओं के कारण उसे छोड़ दिया गया। इस मुद्रामान में व्यापारियों को भुगतान निवटाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें अग्याई गजारी मूल्य वाले सिक्के में अपने हिसाब को निवटाना होता है।

(३) सूचीबद्ध अथवा सूचक अंक मान (Tabular or Index Number Standard) — इस प्रकार के मुद्रामान का मुभाव प्रो० फिशर (Fisher) के द्वारा दिया गया था। उनका अनुसार यह आवश्यक है कि मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन किये जायें। मुद्रा के मूल्य को सामान्य सूचक अंक के साथ सम्बन्धित कर दिया जाना है और सूचक अंक के बढ़ने तथा घटने पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किये जाने हैं। इस उद्देश्य के लिए एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है और इस वर्ष के मूल्यों के आधार पर सूचक अंक बनाने जाते हैं। सूचक अंक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार भविष्य में मुद्रा का मूल्य निर्दिष्ट किया जाता है। सूचक अंक के बढ़ने पर सरकार अपनी सोन की दर का उम्मी अनुपात में कम कर देगी है जिसके कारण कम सोन मुद्रा बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और मुद्रा संकुचन के कारण मुद्रा का मूल्य गिरन नहीं पाना है। इस प्रकार सूचक अंक में कोई भी परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्य को उसके अनुसार ठीक कर लिया जाता है।

इस प्रकार के मुद्रामान में मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य मूल्य-स्तर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है और यह इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। किन्तु व्यावहारिक रूप में यह प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है — सर्वप्रथम तो सही सूचक अंक बनाना ही सम्भव नहीं होता है। सूचक अंकों के द्वारा मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को ठीक प्रकार से ननाय करने के कारण इस प्रकार के मुद्रामान पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। द्वितीय इस उद्देश्य के लिए सरकार को बार-बार सूचक अंक बनाने पड़ते हैं तथा उनसे अनुसार मुद्रा के मूल्य को बदलना होता है जो बहुत अनुविधापूर्ण है। तृतीय, निर्देशानुसार मूल्य-स्तर की भूतकालीन स्थिति को बतलाते हैं और उनके आधार पर मुद्रा के वर्तमान अथवा भविष्य के मूल्य में स्थिरता लाने का प्रयत्न अधिक सफल नहीं हो सकता है। इन कठिनाइयों के कारण ही सूचक अंक मुद्रामान किसी भी देश में नहीं अपनाया गया।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) 'जय अर्चये और बुरे सिक्के एक साथ प्रचलन में होते हैं और दोनों में से किसी से भी ऋण का भुगतान किया जा सकता है, तो अच्छे सिक्कों को लोग या तो गला लेते हैं और या ऋणों को चुकाने अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए देश से बाहर भेज देते हैं और इस प्रकार केवल बुरे सिक्के ही चलन में रह जाते हैं।' ऊपर लिखित नियम की विवेचना कीजिए।
(आगरा बी० ए० १९५७)
- (२) द्वि-धातुमान के क्षतिपूर्क कार्य पर एक नोट लिखिये।
(आगरा बी० काम १९५६ स, गोरखपुर बी० काम १९५६)
- (३) द्वि-धातुमान की मुख्य विशेषतायें बताइये। मूल्य द्वि-धातुमान में अधिक स्थिर रहते हैं अथवा एक धातुमान में? (आगरा बी० काम १९५५)
- (४) मुद्रा सम्बन्धी प्रेशम के नियम की आलोचनापूर्ण विवेचना कीजिए। भारतीय चतान प्रणाली के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
(राजस्थान बी० काम १९५६)
- (५) एक धातुमान तथा द्वि-धातुमान में अन्तर कीजिए।
(राजस्थान बी० ए० १९५६)
- (६) द्वि-धातुमान चलन पद्धति की व्याख्या कीजिए एवं उसके गुण और दोष बताइये। (विक्रम बी० ए० १९५६, आगरा बी० काम १९५६ स)
- (७) द्वि-धातुमान और एक धातुमान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए और बताइये कि क्या द्वि-धातुमान एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य-स्तर को स्थाई रखता है।
(आगरा बी० काम १९६१)
- (८) द्वि-धातुमान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये और इसके गुण-दोष बताइये।
(गोरखपुर बी० काम १९५६)
- (९) द्वि-धातुमान का क्या अर्थ है? इसमें प्रेशम का नियम किस प्रकार कार्यशील होता है?
(सागर बी० काम १९५६)
- (१०) प्रेशम के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। क्या इस सिद्धान्त के कुछ अर्थवाद हैं?
(जदलपुर बी० काम १९५८)

स्वर्णमान

GOLD STANDARD

एक धातुमान (Monometallism) के दो प्रचलित रूप रहे हैं—स्वर्णमान (Gold Standard) तथा रजतमान (Silver Standard) इन दोनों में से स्वर्णमान का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लम्बे समय तक सत्तार के प्रमुख देशों ने स्वर्णमान की व्यवस्था रही है। यद्यपि एक समय ऐसा था जब चाँदी को प्रमुख मुद्रा धातु समझा जाता था। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक न रह सकी और स्वर्णमान का विकास होने पर रजतमान लगभग समाप्त हो गया। काफी प्राचीन समय से सोने का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता आया है। मोना ही एक ऐसी वस्तु है जिसे प्रत्येक देश तथा काल में आम लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। इस सामान्य स्वीकृति के कारण ही स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया। आरम्भ में केवल कुछ एक घनी देशों ने उसे अपनाया किन्तु धीरे-धीरे स्वर्णमान का क्षेत्र विस्तृत होता गया और अन्य देशों ने भी उसे अपना लिया। २०वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वर्णमान ने सत्तार के प्रमुख मुद्रामान का स्थान ले लिया। केवल कुछ एक देशों को छोड़ कर (चीन, भारत, स्पेन आदि) अन्य सभी देशों में स्वर्णमान प्रचलित था और इन देशों ने अपनी मुद्रा को सोने के साथ सम्बन्धित किया हुआ था।

स्वर्णमान की परिभाषा (Definition of Gold Standard) —

स्वर्णमान का अभिप्राय उस मुद्रामान से होता है जिसमें या तो सोने के सिक्के चलाये जाते हैं अथवा देश की मुद्रा को सोने में परिवर्तनीय रखा जाता है। इस प्रकार के मुद्रामान में सोना मूल्यमान का कार्य करता है और सब प्रकार के मूल्य उसके द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। देश की मुद्रा की इकाई की क्रय-शक्ति को सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर कर दिया जाता है। वास्तविक मुद्रा या तो एक निश्चित वजन और शुद्धता वाले सोने की बनी होती है अथवा उसे एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनीय रखने की सुविधा दी जाती है।

स्वर्णमान का मुख्य उद्देश्य मुद्रा के मूल्य को सोने के साथ सम्बन्धित करके उसे स्थिर रखना होता है। विभिन्न मुद्रा शास्त्रियों के द्वारा स्वर्णमान की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई हैं। कुछ परिभाषाओं में स्वर्णमान की व्याख्या सङ्कुचित अर्थ में की गई है किन्तु अधिकांश परिभाषाएँ उसके विस्तृत रूप पर आधारित हैं। हैबरलर (Haberler) ने स्वर्णमान की परिभाषा सङ्कुचित अर्थ में की है। उनके अनुसार "स्वर्णमान सकीर्ण अर्थ में ऐसी मुद्रा प्रणाली है जिसमें प्रमाणिक स्वरूप वाले सोने के सिक्के अथवा स्वर्ण पत्र चलाये जाते हैं और उनके पीछे शत प्रतिशत सोना रखा जाता है।"^१ स्वर्णमान की यह परिभाषा अत्यन्त सङ्कुचित है क्योंकि प्रत्येक प्रकार के स्वर्णमान में स्वर्ण मुद्रा का चलन अथवा मुद्रा के पीछे १००% स्वर्ण कोष का होना अनिवार्य नहीं है। राबर्टसन, कौलबोर्न तथा कैमरर आदि अर्थशास्त्रियों ने स्वर्णमान की परिभाषा अधिक विस्तृत अर्थ में की है। राबर्टसन (Robertson) के अनुसार "स्वर्णमान वह अवस्था है जिसमें एक देश अपनी मुद्रा की इकाई के मूल्य को और सोने के निश्चित वजन के मूल्य को एक दूसरे के बराबर बनाये रखता है।"^२ कौलबोर्न (Coulborn) ने स्वर्णमान की परिभाषा इस प्रकार की है—"स्वर्णमान वह व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुद्रा की मुख्य इकाई एक निश्चित प्रकार के सोने की निश्चित मात्रा के साथ बदली जा सकती है।"^३ कैमरर (Kemerrar) के अनुसार "स्वर्णमान वह मुद्रा प्रणाली है जिसमें मूल्य की इकाई, जिसके द्वारा कीमतें, मजदूरी तथा श्रमों को व्यक्त किया जाता है और चुकाया जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार में सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर हो।"^४ इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक देश स्वर्णमान पर तब होता है जब उस देश की मुद्रा इकाई का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखा जाता हो और वहाँ की सरकार देश की मुद्रा की एक निश्चित दर पर सोने अथवा सोने के सिक्कों में बदलने की जिम्मेदारी लेती हो।

1 "A gold standard, "in narrower sense signifies monetary system under which gold coins of standard specifications of gold certificates with 100% gold backing form the circulating medium."
—Haberler

2 "Gold Standard is a state of affairs, in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another."
—Robertson D. H. : Money, P. 64.

3 "The Gold Standard is that arrangement whereby the chief piece of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality."
—W. A. L. Coulborn : A Discussion of Money, P. 117.

4 "Gold Standard is a money system where the unit of value in which prices, wages and debts are customarily expressed and paid, consist of the value of a fixed quantity of gold in a free gold market."

—Kemerrar : Gold and Gold Standard, P. 135-136.

स्वर्णमान की विशेषतायें (Features of Gold Standard)—

पूरे स्वर्णमान की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(१) देश की मुद्रा इकाई का सोने के साथ निश्चित सम्बन्ध होता है—

प्रत्येक स्वर्णमान वाले देश को अपनी प्रमाणित मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में व्यक्त करना होता है। मुद्रा का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखा जाता है। इसके लिए देश में या तो निश्चित वजन और शुद्धता वाले सोने के सिक्के चलाये जाते हैं या देश की मुद्रा को निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनीय रखा जाता है। मुद्रा इकाई के मूल्य को सोने के साथ सम्बन्धित रखना स्वर्णमान का आधार माना जाता है। हार्ट्रे (Hartrey) के अनुसार “स्वर्णमान का आधार सोने के मूल्य को निश्चित करके मुद्रा इकाई के मूल्य को सोने के मूल्य के साथ बांध देना है।”^५

(२) निश्चित दरों पर सरकार सोने को बेचने और खरीदने का काम करती है—स्वर्णमान में सरकार को निश्चित दरों पर अपरिमित मात्रा में सोने को बेचने तथा खरीदने की व्यवस्था करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि सोने के भाव में स्थिरता बनी रहे और वह सरकारी भाव से ऊपर या नीचे न जा सके।

(३) सोने का स्वतन्त्र आयात तथा निर्यात किया जाता है—स्वर्णमान वाले देशों में सोने के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है। किसी भी मात्रा में सोना देश से बाहर भेजा जा सकता है यद्यपि बाहर से देश में मगाना जा सकता है। सोने का स्वतन्त्र आयात तथा निर्यात होने के कारण विभिन्न देशों में सोने के भाव में एक होने की प्रवृत्ति रहती है।

स्वर्णमान के कार्य (Functions of Gold Standard)—

स्वर्णमान का सर्वप्रथम कार्य मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करना है।^६ प्रत्येक प्रकार के स्वर्णमान में मुद्रा को सोने के साथ सम्बन्धित रखा जाता है और इस सम्बन्ध के द्वारा मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित किया जाता है। आन्तरिक क्षेत्र में स्वर्णमान मुद्रा की मात्रा को स्वर्ण कोषों की मात्रा के साथ सम्बन्धित रखता है और सोने की मात्रा के घटने-बढ़ने पर मुद्रा की मात्रा में भी अनुपातिक परिवर्तन कर दिये जाते हैं। प्रत्येक देश में मुद्रा सम्बन्धी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके अनुसार वह मुद्रा स्वर्ण कोष के आधार पर जारी की जाती है। वह मुद्रा के

5 “The foundation of the Gold Standard is the tying of the value of the monetary unit to the value of gold by fixing of the price of gold”

—Hawtrey.

6 “The modern gold standard serves two functions which can be clearly distinguished. In the first place it is a method of controlling the volume of currency.”

—Crawford, Croffrey. An Outline of Money, P. 281.

पीछे रखे जाने वाले स्वर्ण कोष का अनुपात भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है किन्तु उसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करके अत्यधिक निदासा को रोकना होता है। जब तक मुद्रा का सम्बन्ध सोने के साथ होता है उसका अनावश्यक विस्तार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सोने की पूर्ति में सामयिक (Seasonal) परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए मुद्रा व मास की मात्रा सीमित हो जाती है और मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। आन्तरिक दृष्टि में मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करना स्वर्णमान का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कार्य है।

स्वर्णमान का दूसरा कार्य विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में सोने व मूल्य को निश्चित सीमाओं के भीतर रक्खा जाता है और सोने का आयात तथा निर्यात स्वतन्त्र रखा जाता है। प्रत्येक स्वर्णमान वाले देश की सरकार एक निश्चित दर पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने के लिए तैयार रहती है और सोने की माग होने पर किसी भी सीमा तक सोना बेचने को तैयार रहती है। सरकार के बाजार में सोने के इतने बड़े क्रेता तथा विक्रेता के रूप में प्रस्तुत होने के कारण सोने के भाव प्रायः निश्चित रहते हैं और वे कभी भी सरकारी दरों से ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में भी सोने के भाव को सरकारी दरों से अधिक या कम नहीं होने दिया जाता है। सोने के स्वतन्त्र आयात और निर्यात के द्वारा विभिन्न देशों में सोने के भाव में समता स्थापित की जाती है। इस प्रकार स्वर्णमान वाले देशों में सोने के भावों को नियन्त्रित करके विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्णमान के विदेशी विनिमय स्थिर रखने के कार्य को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता कि कुछ एक अर्थशास्त्रियों ने तो स्वर्णमान को विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने का साधन माना है।⁷

स्वर्णमान के यह दोनों कार्य एक दूसरे से विलकुल भिन्न हैं और उनका अलग-अलग अध्ययन किया जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन की सुविधा के लिए स्वर्णमान के दो रूप माने हैं—(१) आन्तरिक स्वर्णमान (Domestic Gold Standard) और (२) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard)। यद्यपि अधिकतर देशों में स्वर्णमान यह दोनों कार्य एक साथ करता है किन्तु फिर भी उसके इन दोनों पक्षों को पृथक् किया जा सकता है। स्वर्णमान का मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करने का कार्य उसके विदेशी विनिमय को स्थिर रखने के कार्य से विलकुल भिन्न है। यह सम्भव हो सकता है कि एक देश आन्तरिक क्षेत्र में अपनी मुद्रा को नियन्त्रित करने के लिए स्वर्ण कोष के साथ उसकी मात्रा को

7 "The gold standard can best be regarded as a device for maintaining the stability of the exchange rates."

सम्बन्धित रखते किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्णमान को त्याग दे। सन् १९३१ में इंग्लैंड में ऐसा ही किया गया। सरकार ने सोने को निश्चित दरो पर खरीदना और बेचना बन्द कर दिया किन्तु पत्र-मुद्रा के पीछे अब निश्चित अनुपात में स्वर्णकोप रखने की व्यवस्था को जारी रखा गया। यह भी सम्भव हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्णमान को बनाये रखा जाय और आन्तरिक क्षेत्र में उसे छोड़ दिया जाय। इन्हीं कारणों से स्वर्णमान के आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों का अध्ययन अलग-अलग किया जा सकता है। स्वर्णमान के आन्तरिक मूल्य-स्तर को स्थिर रखने का कार्य उसके आन्तरिक पक्ष में सम्बन्धित है और विदेशी विनिमय दरो को स्थिर रखना उसके अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष को दलता है। आन्तरिक स्वर्णमान मुख्यतः मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करके उसके मूल्य को स्थिर रखने का कार्य करता है। इसके दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सम्बन्ध मुद्रा के विदेशी मूल्य से है और वह विदेशी विनिमय दरो को स्थिर रखने का प्रयत्न करता है।

स्वर्णमान का इतिहास (History of Gold Standard)—

सर्वप्रथम इंग्लैंड के द्वारा १८१६ में स्वर्णमान को अपनाया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अन्य देशों ने भी डि-वातुमान को त्याग कर उसके स्थान पर स्वर्णमान को अपना लिया। फ्रांस ने १८६५ में तथा जर्मनी ने १८७१ में इस प्रकार के मुद्रामान को अपनाया। सन् १९०० के पश्चात् अमेरिका में भी स्वर्णमान को अपना लिया गया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में स्वर्णमान ससार का प्रमुख मुद्रामान बन गया और सभी महत्वपूर्ण देशों ने अपनी मुद्रा को सोने के साथ सम्बन्धित कर दिया। सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने तक स्वर्णमान का यह महत्वपूर्ण स्थान बना रहा और वह बिना किसी कठिनाई के चलता रहा। आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरो प्रायः स्थिर रहती थी। स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाना था और विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग था। सन् १९१४ से पूर्व स्वर्णमान माने देशों में सोने की मुद्रा चलाई जाती थी और सोना मुख्यतः तथा विनिमय के माध्यम का कार्य करता था। सोने का आयात तथा निर्यात स्वतन्त्र रखा जाता था और स्वर्ण कोपी की मात्रा में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तित कर दिया जाता था। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक न रह सकी, युद्धकालीन दशाओं में स्वर्णमान का चलन असम्भव हो गया।

स्वर्णमान का स्थगित किया जाना (Suspension of the Gold Standard)— प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने पर स्वर्णमान की सफलता की दशाएँ एक-एक करके समाप्त होने लगीं। विभिन्न देशों में सोने के निक्कों का मुद्रण बन्द कर दिया गया, सोने के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये और प्रत्येक देश सोने को संचय करने का प्रयत्न करने लगा। विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग समाप्त हो गया। प्रत्येक देश में मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वर्ण कोप की

स्वर्णमान

ध्यान में रखते बिना भारी मात्रा में पत्र-मुद्रा जारी की जाने लगी। स्वर्णमान के होते हुए मुद्रा का इतना विस्तार सम्भव न था। इसलिए सभी देशों के द्वारा स्वर्णमान छोड़ दिया गया।

स्वर्णमान का पुनर्स्थापन (Restoration of Gold Standard)—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्णमान फिर से स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ। विदेशी विनिमय दरों में भारी परिवर्तन हो रहे थे जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार रुक गया था। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए फिर से स्वर्णमान को स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। सन् १९२० में ब्रुसेल्स (Brussels) के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में तथा १९२२ के जेनेवा (Geneva) सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि स्वर्णमान को फिर से स्थापित किया जाय। प्रत्येक देश को अपने बजट को संतुलित करने तथा अपनी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य को निश्चित करने की सलाह दी गई। युद्ध काल में इतनी अधिक पत्र मुद्रा जारी की जा चुकी थी कि भ्रष्ट विभिन्न देशों के लिए अपनी संपूर्ण पत्र-मुद्रा के पीछे १००% स्वर्णकोप रखकर फिर से स्वर्ण चलन मान अपनाना सम्भव न था। इसलिए उसके स्थान पर स्वर्ण धातुमान को अपनाया गया। सर्वप्रथम इंग्लैंड ने सन् १९२५ में स्वर्ण धातुमान को अपनाया। सन् १९२७ में भारतवर्ष में तथा १९२८ में फ्रांस में इसी प्रकार का स्वर्णमान स्थापित किया गया। धीरे-धीरे अमेरिका को छोड़कर अन्य सब देशों ने स्वर्ण धातुमान अपना लिया। अमेरिका में स्वर्ण चलन मान को ही बनाये रखा गया।

स्वर्णमान का पतन (Decline of Gold Standard)—युद्धोत्तर काल में स्वर्णमान को चलाने में विशेष कठिनाई उत्पन्न हुई। विभिन्न देशों के बीच पुराना औद्योगिक सहयोग समाप्त हो चुका था और प्रत्येक देश सोने का सग्रह करने के लिए प्रयत्नशील था। विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता समाप्त हो चुकी थी। ऐसी दशाओं में स्वर्णमान का चलना असम्भव हो गया और सन् १९३० के पश्चात् स्वर्णमान हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। एक-एक करके विभिन्न देशों की मुद्राओं का सम्बन्ध सोने के साथ टूट गया। सन् १९३० में आरम्भ होने वाली सप्ताह की भारी आर्थिक गन्दी स्वर्णमान के लिए घातक सिद्ध हुई और उसे सदैव के लिए छोड़ दिया गया। सितम्बर १९३१ में इंग्लैंड ने स्वर्णमान को छोड़ दिया। मार्च १९३३ में फ्रांस के द्वारा तथा सितम्बर १९३६ में अमेरिका के द्वारा स्वर्णमान को त्याग दिया गया। इनके साथ अन्य देशों ने भी स्वर्णमान को छोड़कर उसके स्थान पर पत्र मुद्रामान को अपना लिया।

स्वर्णमान के विभिन्न रूप

(Types of Gold Standard)

स्वर्णमान मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है—

(अ) स्वर्ण चलन मान (Gold Currency Standard)।

(ब) स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard) ।

(न) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) ।

(अ) स्वर्ण चलन मान (Gold Currency Standard)—

स्वर्ण चलन मान या पूर्ण स्वर्णमान (Full Gold Standard) एक ऐसी मुद्रा प्रणाली को कहते हैं जिसमें चलने वाली समस्त मुद्रा सोने की होती है या वह नोटों के साथ बराबर चलती है।^८ प्रथम महायुद्ध से पूर्व इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा मोरुग के अन्य देशों में स्वर्ण चलन मान प्रचलित था। अमेरिका में तो १९३३ तक इस प्रकार के मुद्रामान का प्रयोग किया जाता रहा। स्वर्णमान वाले देशों में एक निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले सोने के निक्के चलाये जाते थे। सोना मूल्यमान का कार्य करता था और उसकी स्वतन्त्र ढलाई की जाती थी। चलन में रहने वाली पत्र-मुद्रा का मूल्य भी सोने के द्वारा निश्चित होता था और उसे सोने में पूर्णतया परिवर्तनशील रखा जाता था। स्वर्ण चलन मान की निम्नलिखित मुख्य विशेषतायें बतलाई जाती हैं—

(१) प्रमाणिक सिक्के का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित कर दिया जाता है—निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले सोने के सिक्कों को चलन में रखा जाता है। जब कोई देश स्वर्णमान को अपनाता है तो सर्वप्रथम उसे अपनी मुद्रा इकाई में पाई जाने वाली सोने की मात्रा निश्चित करनी होती है और इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को सोने के साथ सम्बन्धित कर दिया जाता है। इंग्लैंड में १९१४ से पहले सोने का सोवरेन (Sovereign) चलाया जाता था जिसका वजन १२३ २७४४७ ग्रेन होता था और शुद्धता ९२ होती थी। इस प्रकार एक सोवरेन में ११३ ६६३ ग्रेन शुद्ध सोना रहता था। अमेरिकन स्वर्ण डालर में १९३२ से पूर्व २५ शुद्ध सोना वाला २५ ८ ग्रेन सोना होता था। इसी प्रकार अन्य स्वर्णमान वाले देशों की प्रमाणिक मुद्रा में पाई जाने वाली सोने की मात्रा निश्चित होती थी। देश में चलने वाली अन्य प्रकार की मुद्राओं को निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनशील रखा जाता था।

(२) सरकार निश्चित दर पर सोना बेचने और खरीदने के लिए बाध्य होती है—सोने की स्वतन्त्र ढलाई की जाती है और कोई भी व्यक्ति सोने के बदले में टकमाल में किसी भी सीमा तक सोने के निक्के प्राप्त कर सकता है। सोना बेचने और खरीदने की सरकारी दरों में मामूली अन्तर हो सकता है। इंग्लैंड में सरकार ३ पौंड १७ शिल्लिंग ६ पैसे प्रति औंस के हिसाब से सोना खरीदती थी और ३ पौंड १७ शिल्लिंग १० पैसे प्रति औंस की दर पर बेचती थी। इन नियत दरों पर सरकार किसी भी सीमा तक सोना बेचने और खरीदने का काम करती थी जिसका

8 'A currency system in which gold coins either form the whole circulation or else circulate equally with notes is known as the 'full gold standard.'

—Crosby, Geoffrey: An Outline of Money, P. 279.

परिणाम यह होता था कि बाजार में सोने का भाव इन दरों से अधिक या कम नहीं हो सकता था। इस प्रकार एक निर्धारित मूल्य पर सोने के क्रय-विक्रय के द्वारा सरकार प्रमाणिक सिक्के के अंकित मूल्य और आन्तरिक मूल्य में समानता स्थापित करती थी।

(३) सोने का स्वतन्त्र आयात और निर्यात—स्वर्णमान की सफलता के लिए स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार का होना अनिवार्य है। विभिन्न देशों के बीच सोने के आने-जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। सोने के स्वतन्त्र आयात और निर्यात के कारण विभिन्न देशों में सोने का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति रखेगा। केंट (Kent) के अनुसार “इस सम्बन्ध में सोने के आयात और निर्यात की स्वतन्त्रता एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोने के स्वतन्त्र आने-जाने के कारण समस्त समार में उसका मूल्य समान हो जाता है।”^१ जिस देश में सोने का मूल्य अधिक होया वहाँ पर अन्य देशों से सोना आने-जाने लगेगा और सोने का भाव गिरकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जायगा। सोने के स्वतन्त्र आयात और निर्यात के द्वारा विभिन्न देशों में मूल्य स्तर में भी समानता बनी रहती है। यदि किसी देश का मूल्य-स्तर अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा हो जाता है तो उस देश में आयात की मात्रा बढ़ जायेगी और विदेशी भुगतानों के लिए सोना देश में बाहर जाने लगेगा। सोने की मात्रा कम हो जाने के कारण मुद्रा की मात्रा घट जायेगी और मूल्य-स्तर गिर जायगा।

स्वर्ण चलन मान के लाभ

(Advantages of Gold Currency Standard)—

स्वर्ण चलन मान के इतना अधिक प्रचलित होने का मुख्य कारण उससे प्राप्त होने वाले बहुत से लाभ हैं। स्वर्णमान के समर्थकों के अनुसार एक देश इस प्रकार के मुद्रामान से निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकता है—

(१) स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान स्थापित करता है—स्वर्ण चलन मान का एक बड़ा लाभ यह है कि एक देश में चलने वाली स्वर्ण मुद्रा अन्य देशों में भी स्वीकार कर ली जाती है जिससे विदेशी भुगतानों में विशेष सुविधा होती है। सोना क्योंकि सब देशों में स्वीकार किया जाता है इसलिए स्वर्ण मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का काम करती है जिसके कारण विदेशी व्यापार के विस्तार तथा पूँजी के आयात और निर्यात के लिए उभयुक्त सुविधायें पैदा होती हैं। केवल स्वर्णमान ही एक ऐसा मुद्रामान है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

9 “In this regard, the freedom to import export gold is of special importance, since the free flow of gold across the international boundaries makes for a uniformity in its value throughout the world.”

(२) मूल्य-स्तर में स्थिरता—स्वर्णमान के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता था कि इस प्रकार के मुद्रामान में आन्तरिक मूल्य-स्तर प्रायः स्थिर रहता है और मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं। स्वर्णमान मुद्रा के अनुचित विस्तार को रोकता है और मुद्रा प्रसार की सम्भावना को कम करता है। केंट (Kent) के अनुसार, “वह लम्बे समय में मूल्य-स्तर की सामान्य स्थिरता को सम्भव करता है।”^{१०} देश में मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा पर निर्भर रहती है और सोने की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। अतः मुद्रा की मात्रा निश्चित रहती है। सोने की पूर्ति लगभग निश्चित रहने के कारण उसके मूल्य में सामयिक परिवर्तन (Seasonal fluctuations) नहीं होते हैं जिसके कारण उसके साथ सम्बन्धित मुद्रा की क्रय-शक्ति भी निश्चित रहती है।

(३) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता—यदि ससार के अधिकांश देशों के द्वारा स्वर्णमान की अपनाया जाता है तो विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्णमान की स्थिति कर देने के कारण जो विनिमय दरों में भारी परिवर्तन हुए, वे इस बात का प्रमाण थे कि स्वर्णमान की अनुपस्थिति में विनिमय दरों की स्थिरता को नहीं बनाये रखा जा सकता है। स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दरें प्रायः निश्चित रहती हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन स्वर्ण बिन्दुओं (Gold Points) के बीच में ही सीमित रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक देश की मुद्रा एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनशील होती है इसलिए विभिन्न देशों की मुद्राओं में आपस में निश्चित दरों पर ही बदली जाती हैं। विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता से व्यापार की जोखिम कम हो जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होता है तथा विभिन्न देशों के बीच पूर्ण जी के आयात और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) स्वयं संचालनता (Automatic Working)—स्वर्ण चलन मान का एक विशेष गुण उसकी स्वयं संचालकता है। स्वर्णमान एक स्वयं-संचालित मुद्रामान है। इस प्रकार के मुद्रामान में किसी प्रकार के मौद्रिक प्रदब्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सरकारी हस्तक्षेप विल्कुल नहीं होता है। मुद्रा की माग और पूर्ति में अपने आप सन्तुलन बनता रहता है। जब लोगो की अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अधिक सोना टक्काल पर सिक्के बनवाने के लिए ले जाते हैं और इस प्रकार मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रा की आवश्यकता कम हो जाने पर लोग मुद्रा को पिघला कर सोना निकाल लेते हैं। इन प्रकार मुद्रा की मात्रा आवश्यकता के अनुसार अपने आप घटती-बढ़ती रहती है। विभिन्न देशों के बीच मुद्रातान सन्तुलन (Balance of Payment) भी स्वयं सन्तुलित हो जाता है। यदि किसी देश का

10 “It makes possible a reasonable degree of stability in the price level over a long period of time”

भुगतान सन्तुलन विपक्ष में होता है तो वहाँ से सोना बाहर जाने लगता है जिसके कारण मूल्य-स्तर गिर जाता है, निर्यात बढ़ता है, आयात कम हो जाता है और भुगतान सन्तुलन ठीक हो जाता है ।

(५) जनता में विश्वास पैदा करता है (Inspires Public Confidence)—स्वर्णमान जनता में मुद्रा के प्रति विश्वास पैदा करता है । इस प्रकार के मुद्रामान में सोने की मुद्रा चलाई जाती है जो स्वयं मूल्यवान होती है । केंट (Kent) के अनुसार, 'स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली में इसलिए विश्वास स्थापित करता है क्योंकि सोने को सभी देशों में पसन्द किये जाने के कारण उसका मौद्रिक प्रयोग के अतिरिक्त आन्तरिक मूल्य भी होता है ।' 'सोने की मुद्रा को लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उसका आन्तरिक मूल्य अवित्त मूल्य के बराबर रखा जाता है । इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास इसलिए बना रहता है क्योंकि सोने को अन्य प्रयोगों में भी लाया जा सकता है । यदि सोने के सिक्कों का मुद्रा के रूप में चलना स्थगित हो जाये तो उन्हें सोने के रूप में काम में लाया जा सकता है । इसके विपरीत पत्र मुद्रा में यह बात नहीं पाई जाती है क्योंकि उसका आन्तरिक मूल्य कुछ नहीं होता है और यदि इस प्रकार की मुद्रा का विमुद्रीकरण हो जाये तो उसका मूल्य समाप्त हो जाता है । स्वर्ण मुद्रा में जनता का अधिक विश्वास होने का एक कारण यह भी है कि स्वर्ण मुद्रा की मात्रा स्वर्णकोष की मात्रा के ऊपर निर्भर होती है । सोने की मात्रा में वृद्धि किये बिना मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार अत्यधिक निकासी का भय समाप्त हो जाता है । स्वर्णमान में लोगों का विश्वास केवल स्वर्ण मुद्रा के प्रति ही नहीं होता अपितु देश में चलने वाली पत्र मुद्रा तथा अन्य प्रकार की मुद्राओं में भी उनका विश्वास बना रहता है क्योंकि इस प्रकार की समस्त मुद्रायें सोने की मुद्रा में परिवर्तनीय होती हैं ।

स्वर्ण चलन मान के दोष

(Defects of Gold Currency Standard)—

प्रथम महायुद्ध काल में स्वर्ण चलन मान को बनाने रखने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके कारण बहुत से देशों ने इसे त्याग दिया । स्वर्णमान में कुछ दोष अनुभव किये गये और उसकी आलोचना की जाने लगी । आलोचकों के अनुसार स्वर्ण चलन मान के निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—

(१) कीमती में स्थिरता नहीं रहती है—स्वर्णमान में मूल्य-स्तर स्थिर नहीं रहता है और समय-समय पर मुद्रा का मूल्य बदलता रहता है । यदि सोने का उत्पादन निरन्तर बढ़ता है अथवा कम होता है तो मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की

11 'The gold standard promotes confidence in the monetary system, it is claimed, because gold, being universally desirable, has value in itself aside from its monetary use.' —Kent, Raymond P : Money & Banking, P. 21.

स्थिति पैदा हो सकती है। स्वर्ण चलन मान में मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा के ऊपर निर्भर रहती है। खानों से सोना अधिक मात्रा में निकलने पर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और उसका मूल्य गिर जाता है। इसी प्रकार सोने का उत्पादन कम होने पर, मुद्रा की मात्रा घट जाती है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। समाज में सोने की मात्रा स्थिर न रहने के कारण, मुद्रा की मात्रा बदलती रहती है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य-स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं। स्वर्ण चलन मान की इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुये फ्राउडर ने कहा है कि मुद्रा को सोने के साथ सम्बन्धित करके भी उसकी मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से उसे अनिवार्य रूप से नहीं बचाया जा सकता है।^{१२} समाज का मौद्रिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वर्ण के साथ सम्बन्धित मुद्रा की मात्रा में भी स्थिरता स्थापित करना सम्भव नहीं होता है। मन् १८४६ से लेकर १८७४ तक मूल्यों में इसलिए घृष्टि हो गयी थी क्योंकि सोने की नई खानों का पता लग जाने से समाज में सोने का उत्पादन बढ़ गया था। १८७४ में लेकर १८९६ तक सोने का उत्पादन कम हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य गिर रहे थे।

इस प्रकार स्वर्णमान में मुद्रा का मूल्य प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर हो जाता है। मुद्रा का मूल्य सोने के मूल्य के साथ बढ़ जाता है और सोने के मूल्य के घटने-बढ़ने के साथ घटना-बढ़ना है। सोने के मूल्य के बदलने के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे खानों से अधिक या कम मात्रा में सोने का निकलना, नई खानों का पता लगना अथवा पुरानी खानों का बन्द हो जाना, सोना निजालने की विधि में परिवर्तन हो जाना तथा सोने की माग का घट बढ़ जाना। स्वर्णमान वाले देशों का यह अनुभव रहा है कि मुद्रा के मूल्य को सोने के साथ बाँधने से उसमें अधिक उतार-चढ़ाव आते हैं।

(२) स्वर्णमान केवल अनुकूल परिस्थिति में ही ठीक प्रकार चल सकता है—सोने के साथ मुद्रा की मात्रा को सम्बन्धित करने से मुद्रा प्रणाली बेओचदार हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। युद्ध अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट काल में जब मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है तो स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन किये बिना मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है और स्वर्णमान की स्वयं-मर्यादकता समाप्त हो जाती है। विभिन्न देश अपने निजी हित में स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय के कारण स्वर्णमान का चलना असम्भव हो जाता है। जब कोई संकट काल आता है तो स्वर्णमान के प्रति जनता का विश्वास भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए स्वर्णमान को अनुकूल परिस्थिति मित्र (Fair Weather Friend) कहा

12 "There is thus no warrant for believing that to tie the currency to gold will be to secure it from arbitrary fluctuations in volume."

जाता है। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्णमान ठीक प्रकार चलता रहता है किन्तु आर्थिक संकट काल में वह हमारा साथ छोड़ देता है। क्राउथर (Crowther) के अनुसार, “स्वर्णमान की व्यवस्था केवल सामान्य स्थिति के लिए है। वह तब ही काम करती है जब अन्य बातें समान रहती हैं।”^{१३} प्रो० केंट (Kent) ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार, “स्वर्णमान स्मृति, अच्छी मजदूरी तथा पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति में ही आन्तरिक मुद्रा व्यवस्था की स्थिरता में विश्वास पैदा करता है।”^{१४}

(३) विदेशी विनिमय की स्थिरता को बनाये रखने के लिए मूल्य-स्तर की स्थिरता को ध्यान दिया जाता है—स्वर्णमान में मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है और आन्तरिक स्थिरता को भुला दिया जाता है। स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दरें तो स्थिर रहती हैं किन्तु इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मूल्य-स्तर की स्थिरता को खोना पड़ता है। जब यह समस्या पैदा होती है कि विदेशी विनिमय की स्थिरता अथवा मूल्य-स्तर की स्थिरता में से किसे प्राप्त किया जाय तो प्रायः विदेशी विनिमय की स्थिरता को अधिक महत्व दिया जाता है और विनिमय दरों को स्थिर बनाये रखने के लिए मूल्य-स्तर को घटने-बढ़ने दिया जाता है। आन्तरिक मूल्य-स्तर को देश के हित में न रखकर अन्य देशों के मूल्य के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया जाता है जिसके कारण आन्तरिक स्थिरता विलुप्त हो जाती है।

(४) स्वर्णमान राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को सीमित करता है—स्वर्णमान की सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रत्येक देश को स्वर्णमान के नियमों का पालन करना पड़ता है। स्वर्णमान वाले सभी देशों को एक साथ चलना होता है, इसलिए इन देशों को मौद्रिक मामलों में अपनी स्वतन्त्रता की त्यागना पड़ता है। कोई भी देश अपनी स्वतन्त्र मौद्रिक नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। जैसा अन्य देश करते हैं वैसे ही उसे भी करना होता है चाहे इस प्रकार की नीति उसके आर्थिक हितों केतिकूल ही क्यों न हो।

(५) स्वर्णमान में सोने का अग्रग्रह होता है—स्वर्णमान में मुद्रा बनाने के लिए अथवा सुरक्षित बोप में रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है। स्वर्ण मुद्रा की चलन में रखने से सरकार को प्रतिवर्ष सिककों की घिसावट

13 'The gold standard mechanism must therefore be regarded as one for normal times, as working only if other things are equal.'

—Crowther, *An Outline of Money*, P. 303.

14 'A gold standard, say the critics, promotes confidence in the stability of an internal monetary system only in times of "normalcy"—of prosperity, good wages and full employment.'

—Kert, *Raymond P. Money and Banking*, P. 24.

के कारण काफी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार स्वर्णमान में सोने का बहुत अधिक अपव्यय होता है जो विलुप्त अनावश्यक है क्योंकि हमें केवल विनिमय के माध्यम की आवश्यकता है, यह अनिवार्य नहीं कि वह सोने का ही बना हो।

(६) मूल्य-स्तर तथा विदेशी विनिमय की स्थिरता के लिए स्वर्णमान अनिवार्य नहीं है—बहुत समय तक स्वर्णमान को विदेशी विनिमय तथा मूल्य-स्तर की स्थिरता स्थापित करने का एकमात्र माध्यम माना जाता था किन्तु स्वर्णमान के कुछ प्रालोचकों ने इस गणत धारणा का विरोध किया है। उन्होंने बतलाया कि उपरोक्त प्रकार की स्थिरता को स्थापित करने के लिए प्रवर्धित मुद्रामान (Managed Currency Standard) स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है क्योंकि उसमें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग अधिक सफल हो सकता है। इसके प्रतिरिक्त भन यह भी अनुभव किया जान लगा कि कीमतों की स्थिरता अथवा विदेशी विनिमय की स्थिरता स्वयं कोई अच्छी बात नहीं है। मूल्य-स्तर में लोच का होना अनिवार्य है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कीमतों को घटाया-बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार विदेशी विनिमय की स्थिरता भी दोषपूर्ण हो सकती है यदि वह देश की आर्थिक प्रगति में बाधक होती है। प्रो० कैन्स (Keynes) जो स्वर्णमान के पक्ष में थे, उन्होंने भी मुद्रा से पूर्व बातें स्वर्णमान का विरोध किया है। उन्होंने कहा, “मैं स्वर्णमान को मुद्रा से पहले वाले टग पर अपनाये जाने की नीति को अस्वीकार करता हूँ। मैं कीमतों, साज और रोजगार की स्थिरता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। मुझे इस बात का विलुक्त विश्वास नहीं है कि पुराने टग का स्वर्णमान कभी भी बेसी स्थिरता ला सकेगा, जो यह लगाना करता था।” उनका विचार था कि पुराने टग का स्वर्णमान देशों की आर्थिक प्रगति के रास्ते में रुकावट है। इसीलिए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा प्रवर्धित मुद्रामान पर विशेष जोर दिया।

(७) स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard)—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अपनाये जाने वाले स्वर्णमान का मुख्य रूप स्वर्ण धातुमान था। युद्ध-काल में सभी देशों में स्वर्ण-मुद्रा चलन से हटा दी गई और स्वर्णमान को स्थगित कर दिया गया। युद्ध के पश्चात् विदेशी विनिमय की स्थिरता को बनाये रखने के लिए फिर से स्वर्णमान को अपनाने की आवश्यकता हुई किन्तु पुराने ढङ्ग का स्वर्णमान अपनाना अब सम्भव न था। विभिन्न देशों में पत्र मुद्रा का इतना अधिक विस्तार हो चुका था कि इन देशों के द्वारा अपनी समस्त पत्र मुद्रा के पीछे १००% स्वर्ण कोष रखकर फिर से स्वर्ण चलन मान को स्थापित किया जाना असम्भव था। स्वर्णमान के एक संशोधित रूप को स्वीकार किया गया और उन सब देशों ने, जिनके पास पर्याप्त स्वर्ण कोष थे, स्वर्ण धातुमान को अपना लिया। स्वर्ण धातुमान अधिक सुविधापूर्णा इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत अधिक स्वर्ण कोषों की आवश्यकता नहीं होती थी और स्वर्णमान के सब लाभ प्राप्त हो जाते थे। सन्

१९२५ में इङ्ग्लैंड ने तथा उसके पश्चात् अन्य यूरोपीय देशों ने स्वर्ण धातुमान को अपना लिया। भारतवर्ष में सन् १९२७ में इसी प्रकार का स्वर्णमान स्थापित किया गया।

स्वर्ण धातुमान की विशेषतायें

(Features of Gold Bullion Standard)—

स्वर्ण धातुमान स्वर्ण चलन मान का ही एक संशोधित रूप है। इस प्रकार के स्वर्णमान में स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा कम मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है। स्वर्ण धातुमान की कुछ मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं—(i) सोने का मुद्रण घट कर दिया जाता है और वह केवल सुरक्षित कोयों में रखा जाता है। स्वर्ण धातुमान में सोना केवल मूल्यमान का कार्य करता है, विनिमय के माध्यम के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। स्वर्ण चलन मान की भाँति इस मुद्रा-मान में सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते हैं किन्तु सब प्रकार की मुद्राओं का मूल्य सोने में ही माँका जाता है। मुद्रा की इकाई को सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर घोषित कर दिया जाता है और मुद्रा के इस स्वर्ण मूल्य को स्थिर रखा जाता है। देश में वास्तविक मुद्रा के रूप में कागज के नोट, चाँदी के सिक्के तथा अन्य सांकेतिक सिक्के चलाये जाते हैं जिन्हें निश्चित दर पर सोने की सलाखों में परिवर्तनीय रखा जाता है। देश में चलने वाली पत्र मुद्रा का परिवर्तन सोने के सिक्कों में न होकर, सोने की सलाखों में होता है, इसीलिए इसे स्वर्ण धातुमान कहा जाता है।

(ii) स्वर्ण धातुमान में सरकार एक निश्चित दर पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने के लिए तैयार रहती है और माग होने पर किसी भी मात्रा में सोना बेचने की व्यवस्था करती है। क्रॉउथर (Crowthier) ने स्वर्ण धातुमान की परिभाषा इस प्रकार की है—“जब सोने के सिक्के चलन में नहीं होते हैं किन्तु निश्चित दर पर तथा असीमित मात्रा में मुद्रा के बदले में सोना देने की केन्द्रीय बैंक की वैधानिक जिम्मेदारी होती है तो उसे स्वर्ण धातुमान कहा जाता है क्योंकि मुद्रा सोने के सिक्कों में परिवर्तित नहीं होती है और उसे स्वर्ण धातु में बदला जा सकता है।”¹⁵ सरकार स्वर्ण कोष के रूप में निश्चित वजन और शुद्धता वाली सोने की सलाखें रखती है और देश की मुद्रा को सोने की इन सलाखों में निश्चित दर पर परिवर्तनीय रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी मुद्रा के

15 “When gold coins do not circulate, but the Central Bank is nevertheless under legal obligation to buy and sell gold in exchange for currency at a fixed rate and in unlimited amounts (sometimes with a minimum amount fixed but never a maximum) it is known as the ‘gold bullion standard’, as the currency is then convertible not into gold coins but into gold bullion.”

बदले में अब चाहे सोने की मलाखे प्राप्त कर सकता है। सोने को बेचने और खरीदने की दर सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है और सरकार इन दरों पर किसी भी मात्रा में सोना बेचने और खरीदने की व्यवस्था करती है। इसका प्रभाव यह होता है कि बाजार में सोने का भाव सरकारी दरों में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। इंग्लैंड में कागज के नोटों को ४०० ग्राँस वाली सोने की मलाखों में ३ पाँइ १७ शिलिंग १० ३/४ पेंस प्रति ग्राँस के हिसाब से बदला जा सकता था। सरकार की सोना खरीदने की दर ३ पाँइ १७ शिलिंग १ पेंस प्रति ग्राँस थी। आन्तर्वर्ष में जब स्वर्ण धातुमान अपनाया गया तो देश में चलने वाली पत्र मुद्रा की ४० तौल वाली सोने की मलाखों में २१ ४० ७ आने १० पाँइ प्रति तौला के हिसाब से परिवर्तनीय कर दिया गया। इस प्रकार वास्तविक मुद्रा की सोने में परिवर्तनीय करके मुद्रा के स्वर्ण मूल्य को निश्चित रखा जाता है।

(iii) विभिन्न देशों में सोने के मूल्य में समानता लाने के लिए सोने का आयात और निर्यात स्वतन्त्र रखा जाता है। सोने के आन-जान पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है और इस प्रकार सोने का स्वतन्त्र बाजार स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। निदर्शा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए सोने के स्वतन्त्र बाजार (Free Gold Market) का होना अनिवार्य है। सोने का स्वतन्त्र आयात और निर्यात होने से विभिन्न देशों में सोने का भाव एक होने की प्रवृत्ति रहता है।

स्वर्ण धातुमान के लाभ

(Advantages of Gold Bullion Standard)—

स्वर्ण चलन मान को छोड़कर स्वर्ण धातुमान के अपनाये जाने का मुख्य कारण उसमें प्राप्त होने वाले कुछ विशेष लाभ हैं। इस प्रकार के स्वर्णमान में स्वर्ण चलन मान से प्राप्त होने वाले सभी लाभों के प्रतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए कुछ लेखकों ने स्वर्ण धातुमान को स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा अच्छा मुद्रामान माना है। स्वर्ण धातुमान से प्राप्त होने वाले कुछ विशेष लाभ इस प्रकार हैं—

(१) सोने के प्रयोग में बचत—मितव्ययिता (Economy) की दृष्टि से स्वर्ण धातुमान को स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा अच्छा मुद्रामान कहा जा सकता है। इस मुद्रामान में सोने के सिक्के नहीं चलते हैं और केवल कागजी मुद्रा अथवा घटिया धातु के सिक्के ही चलाये जाते हैं, इसलिए सोने के प्रयोग में बहुत बचत हो जाती है। सोने के सिक्कों का मुद्रण व्यय बच जाता है और स्वर्ण मुद्रा को चलन में रखने के कारण होने वाली हानि से भी सरकार बच जाती है। स्वर्ण धातुमान को चलाने के लिए कम मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है और मुद्रा के बावों से बचे हुए सोने को अन्य प्रयोगों में लाया जा सकता है।

(२) देश में स्वर्ण कोषों का केन्द्रीकरण हो जाता है—स्वर्ण चलन मान में जो सोना सिक्कों के रूप में व्यक्तियों के कोषों में रहता है, स्वर्ण धातुमान में

वही सोना एक स्थान पर सरकारी कोप में इकट्ठा हो जाता है। सोने के व्यक्तियों के पास स्वर्ण मुद्रा के रूप में रहने से कोई विशेष लाभ नहीं है और उसे केवल व्यक्तिगत हितों के लिए ही काम में लाया जा सकता है किन्तु स्वर्ण कोपों के केन्द्रीय बैंक के पास इकट्ठा हो जाने से देश में आर्थिक दृढ़ता बढ़ती है और आपत्ति काल में इन स्वर्ण कोपों का प्रयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सकता है। विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता के लिए सोने के प्रचलन में रहने की अपेक्षा मुद्रा संचालक के पास सुरक्षित निधि के रूप में रहना अधिक उपयोगी होता है। साधारण परिस्थिति में जनता नोट अथवा अन्य प्रकार के साकेतिक सिक्कों का ही प्रयोग करती है और केवल असाधारण परिस्थिति में ही उन्हें सोने में बदलवाया जाता है, इसलिए स्वर्ण मुद्रा को चलन में रखने में कोई विशेष लाभ नहीं होता है। किन्तु यदि सोना सरकारी कोपों में केन्द्रित रहता है तो उसके कारण जनता का विश्वास भी मुद्रा में बढा रहता है और आदस्यकता पडने पर उसे अन्य प्रयोगों में भी लाया जा सकता है।

(३) मुद्रा प्रणाली लोचदार होती है—स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा स्वर्ण धातुमान में मुद्रा प्रणाली अधिक लोचदार रहती है। इस प्रणाली में न तो स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती है और न नोटों के पीछे अतः प्रतिशत स्वर्ण कोप ही रखा जाता है, इसलिए मुद्रा की मात्रा को घटाना-बढ़ाना कुछ आसान हो जाता है क्योंकि सब मुद्रा एक साथ सोने में परिवर्तनशीलता के लिए नहीं आती है इसलिए सरकार स्वर्ण कोपों की मात्रा से कुछ अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी कर सकती है। मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा से प्रभावित तो होती है किन्तु वह विस्तृत उस पर निर्भर नहीं रहती है। आवश्यकता पडने पर मुद्रा की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है किन्तु बहुत अधिक परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि पत्र मुद्रा को सोने में बदलाने की सरकार की जिम्मेदारी होती है।

(४) कम स्वर्ण कोप वाले देश भी इसे अपना सकते हैं—स्वर्ण चलन मान को अपनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण कोप की आवश्यकता होती है और केवल धनी देश ही उसे अपना सकते हैं। किन्तु स्वर्ण धातुमान को स्थापित करने के लिए कम मात्रा में स्वर्ण कोपों की आवश्यकता होती है इसलिए वे देश जिनके पास बहुत अधिक सोना नहीं है स्वर्ण धातुमान को अपनाने सकते हैं। इसलिए स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा स्वर्ण धातुमान के अपनाये जाने की सम्भावना काफी अधिक हो जाती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्ण कोपों की कमी के कारण अफ्रीका देश स्वर्ण चलन मान को स्थापित न कर सके किन्तु स्वर्ण धातुमान को स्थापित करना उनके लिए सम्भव था।

(५) स्वर्ण धातुमान में स्वयं-संचालकता का गुण रहता है—स्वर्ण चलन मान की भांति ही स्वर्ण धातुमान भी एक स्वयं-संचालित मान (Automatic

Standard) है और यदि स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाय तो मुद्रा की माग और पूर्ति अपने आप समतुलित होती रहती है। जब मुद्रा की पूर्ति उसकी माग की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो लोग अधिक मात्रा में मुद्रा सोने में बदलने के लिए प्रस्तुत करते हैं और सरकार के पास स्वर्ण कोष घट जाता है जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति कम होकर उसकी माग के समीप आ जाती है। इसी प्रकार मुद्रा की माग अधिक हो जाने पर लोग अधिक सोना बेचते हैं, सरकारी स्वर्ण कोष बढ़ जाता है और मुद्रा का विस्तार हो सकता है।

(६) विनिमय की दरों की स्थिरता—स्वर्ण धातुमान में विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं और यह परिवर्तन केवल स्वर्ण बिन्दुओं (gold points) के बीच में ही सीमित रहते हैं। सोने के स्वतन्त्र आयात और निर्यात के द्वारा इस प्रकार के स्वर्ण मान में भी विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखा जा सकता है। विदेशी विनिमय की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इस प्रकार के स्वर्णमान को स्थापित करने का निश्चय किया गया।

स्वर्ण धातुमान के दोष

(Disadvantages of Gold Bullion Standard)—

(१) स्वर्णमान की स्वयं-संचालकता कम हो जाती है—स्वर्ण धातुमान में स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा कम स्वयं-संचालकता होती है। इस प्रकार के मुद्रामान में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है और सरकार मौद्रिक प्रयत्न के द्वारा मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है। सोने की स्वतन्त्र दलाई न होने के कारण स्वर्णमान की स्वयं-संचालकता बहुत कम रह जाती है। स्वर्ण धातुमान में मुद्रा की माग और पूर्ति अपने आप समतुलित नहीं होती है बल्कि सरकार के द्वारा मुद्रा की मात्रा को निश्चित किया जाता है और सरकार ही उसमें परिवर्तन करने का निश्चय करती है। इस प्रकार स्वर्णमान की स्वयं-संचालकता में प्राप्त होने वाले लाभ स्वर्ण धातुमान में नहीं मिलते हैं।

(२) मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाता है—स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में न होने के कारण स्वर्ण धातुमान में जनता का विश्वास कम होता है। जनता को ऐसी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण मुद्रा में नहीं बदला जा सकता है इसलिए साधारण लोग इस मुद्रामान को स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा कम अच्छा समझते हैं। यद्यपि पत्र मुद्रा को सोने की मलाई में बदला जा सकता है किन्तु इस परिवर्तनशीलता से साधारण व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि सरकार एक निश्चित मात्रा से कम में मोना नहीं बेचती है। साधारणतया लोगों के पास इतना रपया नहीं होता है कि वे ४०० ग्रॉस अथवा ४० तोले वाली

सोने की सलाखे सरकार से खरीद सकें। इन लोगों के लिए स्वर्ण धातुमान पत्र मुद्रामान की भांति ही होता है।

(३) अनुकूल परिस्थितियों में स्वर्ण धातुमान सफलतापूर्वक चल सकता है—स्वर्ण चलन मान की भांति यह मुद्रामान भी अनुकूल परिस्थितियों का मित्र (Fair Weather Friend) है। सकट काल में इसे बनाये रखना काफी बठिन हो जाता है। युद्ध-काल अथवा अन्य प्रकार के सकट-काल में जब पत्र मुद्रा का अधिक विस्तार किया जाता है तो स्वर्ण कोषों की जमी के कारण स्वर्ण धातुमान हट जाता है। अल्प विकसित देशों के लिए भी इस प्रकार का मुद्रामान उपयुक्त नहीं है क्योंकि स्वर्ण धातुमान में आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ प्रवन्ध (Deficit Financing) के द्वारा मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है।

(४) यह मुद्रामान अधिक मितव्ययितापूर्ण नहीं है—स्वर्ण धातुमान में पत्र मुद्रा को सोने में परिवर्तनीय रखने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण कोष रखना पड़ता है। इस प्रकार के स्वर्ण कोषों में बन्द सोने का कोई अन्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः स्वर्ण धातुमान में भी सोने का काफी अपव्यय होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के स्वर्णमान का प्रवन्ध करने के लिए सरकार को बहुत व्यय करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से स्वर्ण धातुमान मितव्ययिता की दृष्टि से अच्छा मुद्रामान नहीं है।

(स) स्वर्ण विनिमय मान Gold Exchange Standard)—

स्वर्ण विनिमय मान ससार के उन देशों के द्वारा अपनाया गया था जिनके पास स्वर्ण धातुमान स्थापित करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष नहीं थे। इस प्रकार के स्वर्णमान में न तो सोने की मुद्रा चलाई जाती है और न देश में चलने वाली मुद्रा को सोने में बदला जा सकता है। केवल विदेशी मुग्तानों के लिए सरकार निश्चित दरो पर सोना अथवा सोने पर आधारित विदेशी मुद्रा देने के लिए बाध्य होती है। क्रौडर (Crowther) के अनुसार “स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की वैधानिक जिम्मेदारी मुद्रा को सोने में बदलने की गही होती है बल्कि किसी अन्य ऐसी मुद्रा में बदलने की होती है जो स्वयं सोने में परिवर्तनीय होती है।”^{१६} स्वर्ण विनिमय मान को स्थापित करने के लिए बहुत कम सोने की आवश्यकता होती है और इसीलिए यह मुद्रामान निधन देशों के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है।

स्वर्ण विनिमय मान सर्वप्रथम हॉलैंड (Holland) में सन् १८७७ में स्थापित किया गया था। सन् १८६२ में रूस के द्वारा इसे अपनाया गया और १९०७-०८

16. “A third form is the ‘gold exchange standard,’ under which the legal obligation resting upon the Central Bank is to redeem the currency not in gold itself but in some other currency which is itself convertible into gold.”

—Crowther : An Outline of Money, P. 280.

मे लिन्डसे (A. M. Lindsay) योजना मे अन्तर्गत भारतवर्ष मे इस प्रकार का मुद्रामान स्थापित कर दिया गया । प्रथम महायुद्ध से पूर्व कुछ अन्य पूर्वी देशो मे भी स्वर्ण विनिमय मान का विकास हो चुका था किन्तु इसका प्रयोग केवल कुछ देशो तक ही सीमित था । प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्ण विनिमय मान अधिक प्रचलित हो गया और जो देश सोने की कमी के कारण स्वर्ण धातुमान को नहीं अपना सकते थे, उन्होंने स्वर्ण विनिमय मान को अपना लिया । जेनेवा सम्मेलन (Geneva Conference) मे छोटे और निर्धन देशो के द्वारा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने जाने का सुझाव दिया गया । यह डर था कि यदि ममार के मध्य देश स्वर्ण धातुमान को अपनाने हैं तो ममार में सोने की कुल मात्रा मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगी । जेनेवा सम्मेलन की मिफारिसो के अनुसार बहून् से देशो ने, जो स्वर्णमान के साथ प्राप्त करना चाहते थे किन्तु उनके स्वर्ण को उठाने की क्षमता उनमें नहीं थी, स्वर्ण विनिमय मान को अपना लिया । भारतवर्ष के अनिश्चित डेनमार्क, चिली, पोलैंड, जर्मनी, इक्वेडोर, खोलीविया, पैनामा, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, तथा फिलिप्पाइन्स आदि देशों मे स्वर्ण विनिमय मान किसी न किसी रूप मे अपनाया गया था ।

स्वर्ण विनिमय मान की विशेषतायें

(Features of Gold Exchange Standard)—

यद्यपि स्वर्ण विनिमय मान वाले देशो को स्वर्णमान के अधिकांश लाभ मिल जाते हैं किन्तु स्वर्ण विनिमय मान की कार्य प्रणाली अन्य दोनो प्रकार के स्वर्णमानो से भिन्न है । इस प्रकार के स्वर्णमान की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं—

(i) स्वर्ण विनिमय मान मे न तो सोने की मुद्रा चलाई जाती है और न देश की मुद्रा को सोने मे परिवर्तनीय रखा जाता है । केवल विदेशी भुगतानों को निवटाने के लिए मुद्रा के बदले मे सोना अथवा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकता है । देश मे केवल अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा तथा घटिया धातु के सांकेतिक निष्के चलाये जाते हैं । विदेशी विनिमय के लिए देश की मुद्रा के मूल्य को सोने की निश्चित मात्रा के बराबर रखा जाता है । मुद्रा के स्वर्ण मूल्य को बनाये रखने लिए सरकार निश्चित दर पर किसी भी सीमा तक विदेशी विनिमय को बेचने की जिम्मेदारी लेती हैं । भारतवर्ष मे प्रथम महायुद्ध से पूर्व रुपये के विदेशी मूल्य को १ सिलिंग ४ पेंस के बराबर निश्चित कर दिया गया था और सरकार इस दर पर किसी भी सीमा तक सोना अथवा स्टनिंग नन्दन मे उरलब्ध करती थी ।

(ii) स्वर्ण विनिमय मान अपनाने वाला देश अपनी मुद्रा एक निश्चित दर पर किसी ऐसे देश की मुद्रा के साथ सम्बन्धित कर देता है जो स्वर्णमान पर हो । इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने पर स्वर्ण विनिमय मान वाले देश को भी स्वर्णमान के साथ प्राप्त हो जाने हैं । उसी मुद्रा का विदेशी मूल्य निश्चित रहना

है क्योंकि उसे निश्चित दर पर स्वर्णमान वाली मुद्रा के साथ बाँध दिया गया है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत से देशों ने अपनी मुद्राओं को इंग्लैंड के पौंड स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित किया हुआ था और इस प्रकार इन देशों में स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) स्थापित हो गया था। कुछ अन्य देशों की मुद्राएँ अमेरिका के डॉलर के साथ सम्बन्धित थीं और इन देशों में डॉलर विनिमय मान (Dollar Exchange Standard) प्रचलित था।

(iii) मुद्रा का विदेशी मूल्य निश्चित रखने के लिए स्वर्ण विनिमय मान वाले देश को विदेशों में स्वर्ण कोष रखना होता है। जिस देश की मुद्रा के साथ वह अपनी मुद्रा का सम्बन्धित करता है उस देश में विदेशी विनिमय कोष रखना अनिवार्य होता है। यदि मुद्रा के विदेशी मूल्य में गिरावट आती है तो इस कोष में से सोना निकाल कर घाटे को पूरा किया जाता है। अपने देश में भी सरकार एक कोष रखती है जिसमें विदेशी विनिमय अथवा विदेशी मुद्रायें रखी जाती हैं। भारतवर्ष में जब स्वर्ण विनिमय मान था तो सरकार लन्दन में विदेशी विनिमय कोष (Foreign Exchange Reserve) रखती थी। उसके साथ एक मुद्रा कोष भारत में भी रहता था।

स्वर्ण विनिमय मान के लाभ

(Advantages of Gold Exchange Standard)—

स्वर्ण विनिमय मान से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) विदेशी विनिमय दरें स्थिर रहती हैं—इस प्रकार के स्वर्णमान का एक मुख्य लाभ विदेशी विनिमय की स्थिरता है। सरकार विनिमय दरों के घटने और बढ़ने की अधिकतर तथा न्यूनतम सीमायें निश्चित कर देती है और इन सीमाओं के भीतर ही विनिमय दरों को रखा जाता है। सरकार निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय को खेचकर और खरीदकर विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को रोकती है और उन्हें स्थिर रखा जाता है।

(२) सोने के प्रयोग में बहुत अधिक बचत होती है—विभिन्न प्रकार के स्वर्णमानों में विनिमय मान सबसे मस्ती मुद्रा प्रणाली है क्योंकि इसमें सोने का प्रयोग बहुत कम होता है। प्रो० केंट (Kent) के अनुसार “स्वर्ण विनिमय मान का विशेष लाभ सोने की मांग को कम करना तथा उसके प्रयोग में बचत करना था।”^{१७} कम मात्रा में स्वर्ण कोष रखकर ही इस प्रकार के स्वर्णमान को स्थापित किया जा सकता है। सोने की मुद्रा चलन में न होने के कारण ढलाई व्यय तथा सोने के सिक्कों की घिसावट के कारण होने वाली हानि से सरकार बच जाती है। इस प्रकार के

17 “The gold exchange standard, therefore, was held to be particularly advantageous in reducing the demand for gold and in providing an “economy” in its use.”

स्वर्णमान में सोने का बहुत कम खर्च होता है और बचे हुए सोने को अन्य प्रयोग में लाया जा सकता है।

(३) मुद्रा प्रणाली अधिक लोचदार हो जाती है—स्वर्ण विनिमय मान में मुद्रा की मात्रा सोने पर आश्रित नहीं होती है और उसे आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है जिसके कारण मुद्रा प्रणाली काफी लोचदार हो जाती है। क्योंकि आन्तरिक कामों के लिए मुद्रा के बदले में सोना देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है इसलिए मुद्रा का विस्तार आसानी से किया जा सकता है।

(४) निधन देशों के द्वारा अपनाया जा सकता है—निधन देशों के लिए स्वर्ण कोष की कमी के कारण स्वर्ण धातुमान अथवा स्वर्ण चलन मान को अपनाता सम्भव नहीं होता है किन्तु ऐसे देश स्वर्ण विनिमय मान को आसानी से अपना सकते हैं। अतः स्वर्ण विनिमय मान के द्वारा निधन देश भी स्वर्णमान के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी मुद्रा का विदेशी मूल्य स्थिर रखा जा सकता है।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष

(Defects of Gold Exchange Standard)—

(१) स्वर्णमान की स्वयं संचालकता समाप्त हो जाती है—इस प्रकार के मुद्रामान में मुद्रा विस्तार तथा संकुचन अपने आप नहीं होता है बल्कि उसे सरकार के द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। मुद्रा की मात्रा पर सरकारी नियन्त्रण रहता है और मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा सरकार मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। इस प्रकार के मुद्रामान में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है और स्वर्णमान की स्वयं संचालकता का गुण समाप्त हो जाता है।

(२) यह प्रणाली अधिक मितव्ययितापूर्ण (Economical) नहीं है—स्वर्ण विनिमय मान को चलाने के लिए बहुत बड़ी सोना विदेशों में जमा रखना पड़ता है जिसे देश के औद्योगिक विकास के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है। विदेशों में जमा सोने का प्रयोग देश के हित में करना सम्भव नहीं होता है। देश में भी विभिन्न प्रकार के कोष खले जाते हैं जिससे इस मान को चलाने का खर्च बहुत बढ़ जाता है।

(३) असामान्य काल में इस प्रकार के स्वर्णमान का चलना कठिन हो जाता है—सामान्य काल में तो यह मान ठीक प्रकार चलता रहता है किन्तु संकट-काल में जब मुद्रा का विस्तार किया जाता है तो स्वर्णकोष विदेशी विनिमय की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो जाते हैं और ऐसी दशा में स्वर्ण विनिमय मान टूट जाता है। लोन का अभाव होने के कारण इस प्रकार के स्वर्णमान में मुद्रा को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना सम्भव नहीं होता है।

(४) इस प्रकार के मुद्रामान में एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाता है—स्वर्ण विनिमय मान की सफलता आधार-देश में स्वर्णमान के ठीक प्रकार चलने पर निर्भर होती है। जब तक आधार देश की मुद्रा स्वर्णमान पर होती है तो उसके साथ सम्बन्धित मुद्रा भी स्वर्णमान पर रहती है किन्तु जैसे ही आधार देश (Planet Country) स्वर्णमान छोड़ता है स्वर्ण विनिमय मान वाले देश की मुद्रा का सम्बन्ध भी सोने के साथ टूट जाता है। सन् १९३१ में भारतवर्ष को स्वर्णमान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड के पाँड का सम्बन्ध सोने के साथ टूट चुका था।

(५) आधार देश (Planet Country) की मुद्रा प्रणाली प्रसुरक्षित हो जाती है—यदि किसी देश की मुद्रा के साथ बहुत स्वर्ण विनिमय मान वाले देश अपनी मुद्राओं को सम्बन्धित कर लेते हैं तो ऐसी दशा में आधार देश की मुद्रा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आधार देश के पास भी स्वर्ण कोष सीमित मात्रा में होता है और इस सीमित कोष की सहायता से वह सभी सम्बन्धित देशों की सोने की आवश्यकता को पूरा करता है। यदि किसी समय सम्बन्धित देशों की सोने की माग इतनी अधिक हो जाती है कि उसे आधार देश अपने स्वर्ण कोष से पूरा नहीं कर सकता है तो ऐसी दशा में उसकी अपनी मुद्रा प्रणाली मकट में पड़ जाती है।

(६) जनता का विश्वास कम होता है—देश में चलने वाली मुद्रा का आन्तरिक कामों के लिए सोने में परिवर्तनीय न होना, मुद्रा में जनता के विश्वास को कम करता है। इस प्रकार के स्वर्णमान की कार्य प्रणाली इतनी जटिल है कि साधारण व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता है और इसलिए भी उसका विश्वास मुद्रा में कम रहता है। सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्वर्णमान पत्र मुद्रामान से अच्छा नहीं है क्योंकि उसे ऐसी पत्र मुद्रा का प्रयोग करना होता है जिसे सोने में नहीं बदला जा सकता है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के स्वर्णमान के अतिरिक्त स्वर्णमान के दो और रूप भी बतलाये जाते हैं—(१) स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard) तथा (२) स्वर्ण समता मान (Gold Parity Standard)। यद्यपि इन दोनों प्रणालियों को पूर्णतया स्वर्णमान नहीं कहा जा सकता है किन्तु इसमें स्वर्णमान की कुछ विशेषतायें अवश्य पाई जाती हैं। इन प्रणालियों को स्वर्णमान का आंशिक रूप कहा जा सकता है।

स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard)—

स्वर्णमान के पतन के पश्चात् इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विटजरलैंड तथा अमरीका के द्वारा इस प्रकार की मुद्रा व्यवस्था को अपनाया गया। अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को स्थिर रखने के लिए इन देशों में विनिमय समानिकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) स्थापित कर दिये गये जो मौद्रिक कामों के

लिए आपस में सोने का आयात तथा निर्यात कर सकते थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन् १६३२ में विनिमय दर में स्थिरता बनाये रखने के लिए विनिमय समानिकरण कोष स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने १९३४ में तथा फ्रांस ने १९३६ में इस प्रकार के कोषों की स्थापना की। सन् १९३६ में इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस के बीच एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता (Tripartite Monetary Agreement) किया गया जिसके द्वारा इन देशों में स्वर्ण निधिमान की स्थापना हुई। कुछ समय पश्चात् बेल्जियम, हॉलैंड तथा स्विटजरलैंड भी इस समझौते में सम्मिलित हो गये। प्रत्येक देश अपने विनिमय समानिकरण कोष की सहायता से अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को स्थिर रखने की व्यवस्था करता था। इस कोष में देश की मुद्रा की काफी मात्रा रखी जाती थी, जिससे वह विदेशी मुद्रा को खरीदता था। इसके अतिरिक्त कोष में पर्याप्त मात्रा में सोना भी होता था। इन कोषों का उद्देश्य विदेशी दरों में होने वाले परिवर्तनों को कम करना था। विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए ये कोष विदेशी मुद्रा को बेचने और खरीदने का काम करते थे। जब किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाने के कारण उसका मूल्य बढ़ने लगता था तो उस देश का विनिमय समानिकरण कोष विदेशी विनिमय को बेचने लगता था जिससे विनिमय दर में होने वाली वृद्धि रुक जाती थी। इसी प्रकार यदि किसी मुद्रा की पूर्ति अधिक होने के कारण उसका मूल्य गिरने लगता था तो यह कोष उस मुद्रा को खरीदकर उसके मूल्य को गिरने से रोकता था। इस प्रकार इन कोषों के द्वारा विदेशी विनिमय की स्थिरता को प्राप्त किया जाता था।

इन कोषों में एक आपसी समझौते के द्वारा यह निश्चय हो गया था कि वे एक दूसरे की मुद्रा देकर उसके बदले में सोना प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी देश के कोष के पास दूसरे देश की मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाती थी तो वह कोष उस देश के केन्द्रीय बैंक से मुद्रा देकर सोना प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार इन देशों के बीच एक कोष से दूसरे कोष में सोने का हस्तांतरण होना रहता था। किन्तु सोने का यह आयात व निर्यात केवल सरकारी खातों में ही हो सकता था और मौद्रिक कार्यों के लिए ही ऐसा करना सम्भव था। व्यक्तिगत व्यापार क्षेत्र में सोने का स्वतन्त्र आयात तथा निर्यात नहीं किया जा सकता था। विभिन्न देशों में सोने का सीमित आयात तथा निर्यात होने की सुविधा के कारण ही इस प्रणाली को स्वर्ण निधिमान कहा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था को स्वर्णमान तो नहीं कहा जा सकता है किन्तु इसमें स्वर्णमान के कुछ गुण अवश्य पाये जाते हैं।

इस प्रकार की मुद्रा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में अथवा मूद्र की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन बिना ही विदेशी विनिमय की अधिकतम स्थिरता प्राप्त की जा सकती थी। यद्यपि स्वर्ण निधिमान के लिए विदेशी विनिमय में होने वाले परिवर्तनों को एक प्रतिशत के भीतर

सीमित रखना सम्भव न था, जैसा कि स्वर्णमान में होता था किन्तु विनिमय दरो में होने वाले बड़े परिवर्तनों को रोका जा सकता था। विनिमय समानिकरण कोषों की क्रियाओं को बिल्कुल गुप्त रखा जाता था और बाजार में यह पता नहीं होता था कि कब और कितनी मात्रा में कोष कौनसी मुद्रा को बेच अथवा खरीद रहा है। इस प्रकार की गुप्त व्यवस्था ने इस प्रणाली की कार्यक्षमता को बढ़ाने में बड़ी सहायता दी। इस प्रकार की व्यवस्था सन् १९३६ तक सफलतापूर्वक चलती रही किन्तु युद्ध आरम्भ होते ही टूट गई और विभिन्न देशों को विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए विनिमय नियन्त्रण का सीधा तरीका अपनाना पड़ा।

स्वर्ण समता मान (Gold Parity Standard) —

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की स्थापना के पश्चात् विभिन्न देशों में एक नई मौद्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों को अपनी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य निश्चित करना होता है और विनिमय दरो को इन स्वर्ण मूल्यों के बराबर रखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विदेशी विनिमय दरे स्थिर रहती हैं। कुछ लेखकों के अनुसार इस प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था भी एक प्रकार का स्वर्णमान ही है। क्योंकि विनिमय दरो में और मुद्रा के स्वर्ण-मूल्य में समता रखी जाती है इसलिए इस प्रकार के मुद्रामान को स्वर्ण समता मान कहा गया है। स्वर्ण समता मान में न तो सोने के सिक्के चलाये जाते हैं और न मुद्रा को सोने में परिवर्तनशील रखा जाता है। केवल सरकार को मुद्रा के विदेशी मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखना होता है। यद्यपि इस प्रकार के मुद्रामान में स्वर्णमान का कुछ अंश पाया जाता है किन्तु इसे स्वर्णमान कहना बहुत ठीक नहीं है क्योंकि इस मौद्रिक व्यवस्था में विभिन्न मुद्राओं के स्वर्ण मूल्य बिल्कुल निश्चित नहीं होते हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच सोने का स्वतन्त्र आयात तथा निर्यात भी नहीं होता है। केवल सुविधा की दृष्टि से मुद्राओं के मूल्य को सोने में निश्चित कर दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से इस प्रणाली को यदि पत्र मुद्रामान का विशेष रूप कहा जाय तो अधिक ठीक होगा।

इस प्रकार की मुद्रा व्यवस्था को स्वर्णमान कहना कहाँ तक उचित होगा, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद रहा है। लार्ड केन्स (Lord Keynes) ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना को स्वर्णमान मानने से इन्कार किया है। उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था को स्वर्णमान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसके अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरो को सदैव के लिए निश्चित नहीं किया जाता है बल्कि उनमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि केन्स (Keynes) के द्वारा दिये गये तर्क काफी महत्वपूर्ण हैं किन्तु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा

कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना में सोने की काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रो० हॉलम (Halm) ने इस बात को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार—“कोष के स्वर्ण सम्बन्धी नियम केवल दिखावा नहीं है। कोष की सबसे तरल सम्पत्ति के रूप में तथा सदस्य देशों की मुद्राओं के सामान्य आधार के रूप में सोना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है।”¹⁸ वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में स्वर्णमान का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी उसे स्वर्णमान कहना अधिक उचित नहीं होगा। केवल यही कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना के अन्तर्गत एक ऐसा मुद्रामान स्थापित कर दिया गया है जिसमें स्वर्णमान के दोष काफी सीमा तक दूर हो गये हैं किन्तु सदस्य देश स्वर्णमान के कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।

स्वर्णमान के नियम (Rules of the Gold Standard)—

स्वर्णमान के सफलतापूर्वक चलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिस प्रकार किसी भी खेल को खेलने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को उस खेल के नियमों का पालन करना होता है, उसी प्रकार स्वर्णमान को चलाने के लिए प्रत्येक देश को स्वर्णमान के नियमों का पालन करना होता है। जब तक स्वर्णमान वाले देश इन नियमों का पालन करते हैं, स्वर्णमान ठीक प्रकार चलता रहता है किन्तु यदि कोई भी देश इनका उल्लंघन करता है तो स्वर्णमान की स्वयं मचालकता समाप्त हो जाती है और उसका चलना कठिन हो जाता है। स्वर्णमान के नियमों के महत्व को बतलाते हुए क्रॉडर (Crowther) ने लिखा है कि “स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देवता है। यह तभी कार्य करता है जब उसकी एकमात्र साधना की जाती है।”¹⁹ स्वर्णमान की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि कहां तक देश का केन्द्रीय बैंक उसके प्रति वफादार रहता है, अर्थात् वह किम सीमा तक स्वर्णमान के आधारभूत नियमों का पालन करता है। स्वर्णमान के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं—

(१) स्वर्ण कोषों में परिवर्तन के साथ-साथ मुद्रा और साख की मात्रा में परिवर्तन।

(२) स्वर्ण कोषों के बदलने पर विभिन्न प्रकार के मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन।

(३) स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पालन करना।

(४) स्वर्ण कोषों में परिवर्तन होने पर मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन करना—स्वर्णमान वाले देशों को बाहर से सोने का आयात होने पर साख का

18 “The Fund's gold provisions are not just window dressing. Gold plays a really important role as the Fund's most liquid asset and as a common anchorage for the member currencies.”
—Halm.

19 “Gold Standard is a jealous God. It will work provided it is given exclusive devotion.”
—Crowther : An Outline of Money, P. 306.

विस्तार करना चाहिए और देश से सोना बाहर जाने पर उसी अनुपात में साख की मात्रा कम कर देनी चाहिए। क्राउथर (Crowther) के अनुसार यह नियम स्वर्णमान का आधारभूत नियम कहा जा सकता है और इसके पालन करने पर ही स्वर्णमान की सफलता निर्भर होती है। उनके अनुसार “स्वर्णमान का स्वर्ण नियम है—सोने के देश में आने पर साख का विस्तार करो और उसके बाहर जाने पर साख का संकुचन करो।”²⁰ इस नियम का पालन करने से ही स्वर्णमान एक स्वयं संचालित मुद्रामान के रूप में स्थापित किया जा सकता है। सोने के स्वतन्त्र आयात और निर्यात के द्वारा स्वर्णमान विभिन्न देशों में सोने का समान वितरण करता है तथा उनके मूल्य-स्तर में समानता लाता है। जब किसी देश में सोने का अधिक आयात होने के कारण स्वर्णकोष की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर साख का विस्तार किया जाता है जिसके कारण उस देश का मूल्य-स्तर ऊँचा उठ जाता है। अन्य देशों की अपेक्षा वस्तुओं का मूल्य ऊँचा होने के कारण उन देश का आयात अधिक और निर्यात कम हो जाता है। भुगतान समुलन (Balance of Payment) उस देश के विपक्ष में हो जाता है और सोना देश से बाहर जाने लगता है। सोने का निर्यात होने के कारण देश में सोने की मात्रा कम हो जाती है, साख की मात्रा घट जाती है और मूल्य-स्तर गिर कर सामान्य स्तर पर आ जाता है। इस प्रकार स्वर्णमान वाले देशों में स्वर्ण कोष की मात्रा के बढ़ने पर साख का विस्तार होना चाहिए और उसके घटने पर साख की मात्रा स्वयं कम हो जानी चाहिए।

(२) स्वर्ण कोषों के घटने पर विभिन्न प्रकार के मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन—स्वर्णमान वाले देशों को अपने स्वर्ण कोषों में परिवर्तन होने पर मूल्य-स्तर तथा मजदूरी की दरों में परिवर्तन होने देना चाहिए। देश में स्वर्ण का आयात होने पर मूल्य-स्तर बढ़ जाना चाहिए तथा उसके निर्यात किये जाने की दशा में वह घट जाना चाहिए। हॉलम (Halm) के अनुसार “जब सोने के आयात तथा निर्यात के मौद्रिक दबाव पड़ते हैं तो मूल्य-स्तर उसी प्रकार बढ़ना तथा घटना है जिस प्रकार नहर के संचित पानी का स्तर।”²¹ स्वर्णमान वाले देशों की अर्थ-व्यवस्था इतनी लोचपूर्ण होनी चाहिए कि सोना बाहर से आने पर विभिन्न प्रकार के मूल्यों को तुरन्त बढ़ाया जा सके और सोने के बाहर जाने पर उन्हें कम किया जा सके। यदि इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होने दिये जाते हैं तो स्वर्णमान की स्वयं-संचालकता समाप्त हो जाती है और विभिन्न देशों के मूल्य-स्तरों में समानता स्थापित नहीं की जा सकेगी। प्रथम महायुद्ध से पूर्व स्वर्णमान के इस नियम का पूरी तरह से पालन किया जाता था किन्तु युद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों ने नियम का उल्लंघन करना

20 “Thus the golden rule of the gold standard is : expand credit when gold is coming in; contract credit when gold is going out.”

—Crowther : ‘An Outline of Money’, P. 304.

21 “When the monetary pressures of gold movements are exerted, the price levels are supposed to rise or fall like water in the lock.” —Halm.

आरम्भ कर दिया जिसके कारण स्वर्णमान का चलना कठिन हो गया। अमरीका में सोना भारी भारों में आ रहा था किन्तु उसे जमा कर लिया गया और उसके अनुपात में साख का विस्तार नहीं किया गया। इस प्रकार स्वर्णकोषों के बढ़ने का प्रभाव मूल्य-स्तर पर नहीं पड़ने दिया जाता था। इंग्लैंड में भी सोने के बढ़ते हुए कोषों को पूरी तरह मूल्यों पर प्रभाव नहीं डालने दिया जाता था। इन देशों के द्वारा स्वर्णमान के आधारभूत नियम का उल्लंघन किये जाने के कारण स्वर्णमान ठीक प्रकार से न चल सका।

(३) स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पालन करना—उपयुक्त आधारभूत नियमों के ठीक प्रकार क्रियशील होने के लिए स्वर्णमान वाले देशों को स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पालन करना चाहिए। किसी भी देश को वस्तुओं के आयात और निर्यात पर नियन्त्रण नहीं लगाना चाहिए। स्वतन्त्र व्यापार के द्वारा ही स्वर्णमान विभिन्न देशों के व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) को ठीक रख सकता है तथा इन देशों में सोने का समान वितरण सम्भव हो सकेगा। स्वर्णमान को ठीक प्रकार से चलाने के लिए विभिन्न देशों में सोने का आयात तथा निर्यात भी स्वतन्त्र होना चाहिए। यदि कुछ देश अपने उद्योग-धन्धों को संरक्षण देने के लिए अथवा आर्थिक राष्ट्रीयवाद के अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण लगाते हैं तो ऐसी दशा में स्वर्णमान ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगा। स्वतन्त्र व्यापार की अनुपस्थिति में स्वर्णमान व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) की दृष्टियों को ठीक नहीं कर सकेगा और विभिन्न देशों के मूल्य-स्तर में इतना अधिक अन्तर हो जायगा कि उसे सोने के आयात और निर्यात के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार भुगतान सन्तुलन (Balance of Payment) को ठीक रखने के लिए तथा विभिन्न देशों के मूल्य-स्तर में समानता लाने के लिए, स्वतन्त्र व्यापार की नीति का होना अनिवार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान

(International Gold Standard)

स्वर्णमान का अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष उसके आन्तरिक पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आन्तरिक मुद्रा व्यवस्था के आधार के रूप में सोने का अधिक महत्व नहीं रहा है। उसका प्रमुख महत्व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान तथा विनिमय के माध्यम के रूप में रहा है।²² अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय दरो में स्थिरता स्थापित करना होता है। क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सम्बन्ध मुद्रा के विदेशी मूल्य से तथा विदेशी विनिमय की

22 'The principal significance of gold has been not its use as a basis for the domestic monetary systems of nations but rather its employment as an international standard of value and medium of exchange'

स्थिरता स्थापित करने की समस्या से है।²³ अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश की मुद्रा के भ्रान्तरिक मूल्य को स्थिर रखने के लिए उसकी मुद्रा का सोने पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। किन्तु विभिन्न देशों की मुद्राओं से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तथा उनके विदेशी मूल्य को स्थिर रखने के लिए, मुद्राओं का सोने के साथ सम्बन्धित होना आवश्यक है। इसीलिए स्वर्णमान का प्रमुख महत्व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में रहा है। विभिन्न देशों में सोने के भुगतानों को निबटाने के माध्यम तथा मुद्रामान के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में विशेष उपयुक्त रहा है। भ्रान्तरिक मुद्रामान के रूप में स्वर्णमान का महत्व तब तक ही था जब तक लोग या तो सोने की मुद्रा चाहते थे अथवा अपनी मुद्रा को सोने में परिवर्तनीय रखना पसन्द करते थे। किन्तु यह स्थिति प्रथम महायुद्ध के पश्चात् समाप्त हो गई थी। अब लोगों का विश्वास पत्र मुद्रा में स्थापित हो चुका था और मुद्रा के रूप में सोने का प्रयोग अनावश्यक समझा जाने लगा था। सोने को मुद्राओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियन्त्रित करने का काम सौंप दिया गया। ऐसी दशाओं में भ्रान्तरिक स्वर्णमान का पतन स्वाभाविक था किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में उसका महत्व बराबर बना रहा। क्रॉउथर (Crowther) ने भ्रान्तरिक स्वर्णमान के पतन तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के महत्व के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है—“भ्रान्तरिक स्वर्णमान वास्तव में अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और सोने का अधिकाधिक रूप से मुद्राओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियन्त्रित करने का काम रह गया है।”²⁴ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोने का महत्व विशेषतया उसकी सर्वमान्यता के कारण है। पत्र मुद्रा को देश में स्वतन्त्र रूप से स्वीकार किया जा सकता है किन्तु विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए वह उपयोगी नहीं है और हमें इस प्रकार के भुगतानों को निबटाने के लिए स्वर्ण अथवा स्वर्ण पर आधारित मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जबतक सम्भव हो सका स्वर्णमान को बनाये रखने का प्रयत्न किया गया। प्रथम महायुद्ध काल में स्वर्णमान को स्थगित कर दिया गया किन्तु युद्ध के पश्चात् विदेशी विनिमय की स्थिरता को स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा फिर से अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को अपना लिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के लाभ

(Advantages of International Gold Standard)—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से प्राप्त होने वाले कुछ विशेष लाभ निम्न प्रकार हैं—

23 “This international gold standard is concerned with the external value of the currency and with the problem of maintaining the stability of the foreign exchanges.”

—Crowther : An Outline of Money, P. 297.

24 “The domestic gold standard, in fact, is dying a natural death, and gold is increasingly being left to its task of regulating the international relationships of currencies.”

—Crowther : An Outline of Money, P. 296.

(१) सोना अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तयः झूल्यमान का कार्य करता है—विभिन्न देशों में सोने के निःसकोच स्वीकार किए जाने के कारण स्वर्ण मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का कार्य करती है। कैंट (Kent) के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सबसे प्रत्यक्ष लाभ सोने वा समस्त मनार में विनिमय के माध्यम तथा मूल्यमान के रूप में निःसकोच स्वीकार किया जाना है”।^{२५} स्वर्ण मुद्रा ही एक ऐसी मुद्रा है जिसे राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी स्वीकृति प्राप्त होती है। उसके द्वारा विदेशी मुग़तानों को ग्रामानी से निवटाया जा सकता है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होता है तथा विभिन्न देशों के बीच पूँजी का आयात व निर्यात सुविधापूर्वक किया जा सकता है। स्वर्णमान वाले देशों के पास सोने के रूप में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे सब देशों में स्वीकार किया जाता है तथा जिसके द्वारा विभिन्न देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को नापा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान होने के कारण सोने के द्वारा विभिन्न देशों में स्थित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जा सकती है।^{२६}

(२) विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विदेशी विनिमय की स्थिरता स्थापित करना है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की व्यवस्था में विदेशी विनिमय दरें प्रायः स्थिर रहती थीं और उनमें बहुत कम परिवर्तन होते थे। विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन केवल स्वर्णमान बिन्दुओं (Gold Points) की सन्तुलित सीमाओं के भीतर ही रहते थे। कैंट (Kent) के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में, स्वर्णमान का सबसे प्रमुख लाभ विदेशी विनिमय दरों में लगभग पूर्ण स्थिरता को सम्भव करना है।”^{२७} विदेशी विनिमय की स्थिरता के कारण व्यापारिक जोखिम बहुत कम हो जाया है और विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न होती हैं। विदेशी विनिमय की स्थिरता अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का स्वाभाविक गुण है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु विदेशी विनिमय की स्थिरता को स्थापित करने के लिए मुद्रा सोने में स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय होनी चाहिए। काउथर

25 ‘The most obvious advantage of the international gold standard is found in the unlimited acceptability of gold throughout the world as a medium of exchange and a standard of value’

—Kent, Raymond Money and Banking, P. 38.

26 ‘In serving as an international standard of value, gold makes possible the precise comparison of the worth of goods located in different countries’

—Kent, Raymond Money and Banking, P. 38.

27 ‘From the international point of view the pre-eminent advantage of the gold standard lies in the fact that it makes possible almost perfect degree of stability in foreign exchange rates’

—Kent, Raymond Money and Banking, P. 38.

(Crowther) के अनुसार "मुद्रा को सोने में और सोने की मुद्रा में स्वतन्त्र परिवर्तन-शीलता के बिना स्वर्णमान विदेशी विनिमय की स्थिरता स्थापित करने की गारन्टी नहीं दे सकता है।"^{२८}

(३) विभिन्न देशों के मूल्य-स्तरों में समानता—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान विभिन्न देशों के मूल्य स्तरों में समानता स्थापित करता है। स्वर्णमान की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी देश का मूल्य-स्तर अन्य देशों के मूल्य-स्तरों की अपेक्षा ऊँचा या नीचा नहीं रह सकता है। इस प्रकार की असमानता सोने के स्वतन्त्र आयात तथा निर्यात के द्वारा स्वयं समाप्त हो जाती है। केंट (Kent) के अनुसार विभिन्न देशों के बीच सोने का प्रवाह मूल्य-स्तरों को इस प्रकार घटाता-बढ़ाता है कि ये स्वर्णमान वाले समस्त देशों में एक सतुलन की स्थिति में आ जाते हैं।^{२९} जब किसी देश का मूल्य-स्तर दूसरे देशों से ऊँचा हो जाता है, तो उस देश के निर्यात तथा आयात अधिक होने के कारण सोना देश से बाहर जाने लगता है। देश में स्वर्ण कोष कम हो जाते हैं, मुद्रा संकुचन होना है तथा मूल्य-स्तर गिर कर सामान्य स्तर पर आ जाता है। इसके विपरीत यदि किसी देश का मूल्य-स्तर अन्य देशों की अपेक्षा कम होता है तो उस देश में बाहर से सोना आने के कारण मुद्रा विस्तार होता है और मूल्य-स्तर बढ़ जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के दोष

(Disadvantages of International Gold Standard)—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से पैदा होने वाले कुछ दोष इस प्रकार हैं—

(१) विदेशी विनिमय की स्थिरता को बनाये रखने के लिए मूल्य-स्तर की स्थिरता को त्यागना पड़ता है—यद्यपि स्वर्णमान वाले देशों में विदेशी विनिमय दरे स्थिर रहती हैं। किन्तु इन्हें स्थिर रखने के लिए इन देशों को अपने मूल्य-स्तर में समय-समय पर परिवर्तन करने होते हैं, जिनका इनकी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक देश में मूल्य-स्तर गिरता है और यदि दूसरे देश के साथ उसकी विनिमय दर को नहीं बढ़ता जा सकता है तो ऐसी दशा में दूसरे देश को अनिवार्य रूप से अपने मूल्य-स्तर को कम करना होगा चाहे उसकी अर्थ-व्यवस्था पर इसका कितना भी बुरा प्रभाव क्यों न हो। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में विदेशी विनिमय की स्थिरता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए मूल्य-स्तर की स्थिरता को त्याग दिया जाता है। वर्तमान

28 "Without free convertibility of money into gold, and to gold into money, the gold standard cannot guarantee stability of exchange rates."

—Crowther : An Outline of Money, P. 299.

29 "The flow of gold from country to country causes price levels to rise and fall in such manner that they are brought in equilibrium among all the nations which maintain gold standard."

—Kent, Raymond : Money and Banking, P. 40.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार आन्तरिक आर्थिक स्थिरता को त्याग दिया जाता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार आन्तरिक आर्थिक स्थिरता विदेशी विनिमय की स्थिरता से अधिक महत्वपूर्ण है और आवश्यकता पड़ने पर एक देश को अपनी आन्तरिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए विदेशी विनिमय दरो में परिवर्तन कर लेना चाहिए।

(२) सोने के आयात और निर्यात के द्वारा एक देश की आर्थिक भुराईयाँ दूसरे देशों में पहुँच जाती हैं—प्रो० केंट (Kent) के अनुसार सोना एक अत्यन्त प्रभावशाली वाहक का कार्य करता है जिसके द्वारा कुछ देशों में अनुभव किये जाने वाले आर्थिक सबट तुरन्त दूसरे देशों में भी पहुँच जाते हैं।³⁰ सोने का स्वतन्त्र आयात व निर्यात होने की दशा में कोई भी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को दूसरे देशों के बुरे प्रभावों में नहीं बचा सकता है। यदि किसी देश में कोई आर्थिक आपत्ति आती है तो सोने के आयात तथा निर्यात के द्वारा उसमें बुरे परिणाम अन्य देशों में भी पहुँच जाते हैं। ऐसी दशाओं में कोई भी देश अपनी निजी तथा स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था दूसरे देशों की अर्थ-व्यवस्था के साथ सम्बन्धित हो जाती है। इसके बुरे परिणाम १९३० की आर्थिक मन्दी काल में स्पष्ट रूप से अनुभव किये गये जबकि अमेरिका में आरम्भ होने वाली भारी आर्थिक मन्दी सोने के प्रवाह के द्वारा स्वर्णमान वाले सभी देशों में फैल गई।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता की दशाये

(Requisites of International Gold Standard)—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के सफलतापूर्वक चलने के लिए विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान बहुत प्रचण्डी प्रकार में चलता रहा क्योंकि उस समय के सब देशों में मौजूद थी जो स्वर्णमान की सफलता के लिए अनिवार्य है। युद्ध के पश्चात् इनमें से बहुत सी देशों के न होने के कारण स्वर्णमान केवल बटिनाई के साथ ही चल सका और अन्त में टूट गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के ठीक प्रकार से चलने के लिए निम्न-लिखित दशाओं का होना अनिवार्य है—

(१) प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का स्वर्णमान होना चाहिए—

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को स्थापित करने के लिए मसाल के अधिकांश देशों में किसी न किसी प्रकार का स्वर्णमान होना आवश्यक है। यदि बहुत से देशों में पत्र मुद्रामान या किसी अन्य प्रकार के मुद्रामान को अपनाया गया है और केवल कुछ एक देशों में ही स्वर्णमान है तो ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। अपनी मुद्रा व्यवस्था को सोने के साथ सम्बन्धित करने वाले देशों की

0 "Gold serves, as it were a highly efficient conductor through which the economic shocks felt in particular countries are quickly passed on to other countries."

—Kent, *Rimond Money and Banking*, P. 42.

संख्या जितनी अधिक होती है, उतना ही सोना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान तथा विभिन्न देशों के माध्यम के रूप में अधिक उपयोगी होता है। यद्यपि विभिन्न देशों को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वे जिस प्रकार का स्वर्णमान चाहें अपने देश में स्थापित करें किन्तु फिर भी अधिकांश देशों के द्वारा स्वर्ण मुद्रामान अथवा स्वर्ण धातुमान का अपनाया जाना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए एक आवश्यक दशा है।

(२) पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोषों का होना तथा विभिन्न देशों में उनका समान वितरण—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को चलाने के लिए संसार में सोना इतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे कि विभिन्न देशों को मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सोने की कमी की दशाओं में स्वर्णमान को नहीं चलाया जा सकता है। संसार में स्वर्ण कोषों के पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ उनका विभिन्न देशों में समान वितरण भी होना चाहिए। यदि कुछ एक देशों में तो सोना बहुत अधिक है किन्तु अन्य देशों में सोने की कमी है तो स्वर्णमान नहीं चल सकेगा।

(३) स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अपनाया जाना—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए विभिन्न देशों को स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपनाना चाहिए। इन देशों को वस्तुओं के आने-जाने पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं लगाना चाहिए। स्वतन्त्र व्यापार के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में भुगतान संतुलन (Balance of Payment) को ठीक रखा जा सकता है। यदि विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं तो स्वर्णमान की स्वयं-संचालकता समाप्त हो जाती है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की भांति कम से कम रक्खा जाये—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को ठीक प्रकार चलाने के लिए विदेशी ऋणों की मात्रा को कम से कम रखना चाहिए। यदि किसी देश में विदेशी ऋणों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसकी निर्यात का बहुत बड़ा भाग ऋणों के भुगतान में अथवा उन पर दिये जाने वाले मूद्र के रूप में व्यय हो जायेगा और वह देश स्वर्ण कोषों का निर्माण नहीं कर सकेगा। यदि किसी कारण उसकी निर्यातों की मात्रा गिर जाती है तो ऐसी दशा में उसे स्वर्ण कोष से सोना निकाल कर निर्यात करना होगा और वह अपने यहाँ स्वर्णमान को नहीं बनाये रख सकेगा।

(५) स्वर्णमान वाले देशों की अर्थ-व्यवस्था सौचदार होनी चाहिए—स्वर्णमान के नियमों का पालन करने के लिए विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था इतनी सौचपूर्ण होनी चाहिए कि बाहर से सोना आने पर मूल्यों तथा मजदूरों की दरों को बढ़ाया जा सके और सोना बाहर जाने पर उन्हें कम किया जा सके। यदि मूल्य-स्तर तथा मजदूरी की दरों को सोने के आयात व निर्यात के अनुसार घटने-बढ़ने नहीं दिया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान नहीं चल सकेगा।

(६) राजनैतिक स्थिरता (Political Stability)—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सम्पत्ता के लिए राजनैतिक स्थिरता का होना अनिवार्य है। विभिन्न देशों के प्राप्ति सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए तथा उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। व्यक्तिगत देशों में राजनैतिक आन्दोलन तथा स्थानीय झगड़े नहीं होना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का पतन और उसके कारण

(Causes of the Breakdown of International Gold Standard)—

प्रथम महायुद्ध काल में कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण स्वर्णमान स्थगित कर दिया गया किन्तु युद्ध के पश्चात् विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए उसे फिर से एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान के रूप में स्थापित किया गया। सन् १९२६ तक सत्तार के लगभग सब देशों ने किसी न किसी रूप में स्वर्णमान को अपना लिया था किन्तु युद्ध के पश्चात् का स्वर्णमान अधिक सफलतापूर्वक न चल सका और १९३१ में उसका पतन आरम्भ हो गया। सितम्बर १९३१ में इंग्लैंड ने स्वर्णमान को छोड़ दिया। सन् १९३२ में अमेरिका के डालर का सम्बन्ध सोने के साथ टूट गया और १९३६ तक सब देशों ने स्वर्णमान को सदैव के लिए त्याग दिया। स्वर्णमान के इस पतन के निम्नलिखित कारण थे—

(१) आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास (Development of Economic Nationalism)—प्रथम महायुद्ध के कारण बहुत से देशों में आर्थिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ और इन देशों ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए निर्जा स्वार्थ की नीति को अपना लिया। युद्ध के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना के पैदा हो जाने के कारण प्रत्येक देश अपने औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील था। सभी देशों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को छोड़कर उसके स्थान पर संरक्षण की नीति को अपना लिया था। अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए इन देशों में विदेशी व्यापार पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाये गये। आयात नियंत्रण, असमय प्रणाली (Quota System) तथा निर्यात शुल्क आदि स्वर्णमान वाले देशों की व्यापारिक नीति का मुख्य अंग बन गये थे। मुख्यतः फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने संरक्षण की नीति को अपनाकर स्वर्णमान के नियम का उल्लंघन किया। स्वतन्त्र व्यापार न होने के कारण विभिन्न देशों के मूल्य-स्तर में इतना अधिक अन्तर हो गया कि उसे सोने के आयात तथा निर्यात के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता था। प्रो० वीन (G. D. H. Cole) ने स्वर्णमान की प्रकृति के बारे में ठीक ही लिखा है—“स्वर्णमान आवश्यक रूप में एक स्वतन्त्र मान है। इसमें आर्थिक प्रवृत्ति की उन विधियों का, जिनका उद्देश्य विदेशी विनिमय सम्बन्धी मोटों पर रोक लगाना होता है, कोई स्थान नहीं है।”³¹

31 "The gold standard is essentially a laissez faire standard. It rules out such methods of economic management as involve restrictions on exchange transactions."

(२) स्वर्णमान के उद्देश्यों को पूर्णरूप से स्वीकार न किया जाना—प्रथम महायुद्ध से पूर्व स्वर्णमान वाले देश विदेशी विनिमय की स्थिरता स्थापित करना अपना प्रमुख कर्त्तव्य समझते थे किन्तु युद्ध के पश्चात् स्थिति इसने भिन्न थी और सत्तार के अधिकांश देश स्वर्णमान के इस प्रमुख उद्देश्य के प्रति उदासीन हो गये थे । सत्तार के मुद्रा अधिकारी अब पूर्णरूप से स्वर्णमान के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे । क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार, “विदेशी विनिमय के स्थाय पर मूल्यों की स्थिरता प्राप्त करना मुद्रा अधिकारियों का प्रमुख कर्त्तव्य समझा जाता था ।”³² स्वर्णमान के प्रमुख उद्देश्य के प्रति इस प्रकार की उदासीनता ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता की सम्भावना को कम कर दिया ।

(३) स्वर्णमान के नियमों का परित्याग—युद्ध के पश्चात् बहुत से देशों ने स्वर्णमान के आधारभूत नियमों का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया जिसके कारण स्वर्णमान की स्वयं-मचातकता समाप्त हो गई थी । क्रॉउथर ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “युद्ध उपरान्त स्वर्णमान के पतन का तीव्र कारण यह था कि केन्द्रीय बैंक अपनी विभाजित निष्ठा तथा ध्ववहारिक कठिनाइयों के आभास के कारण, स्वर्ण नियम का पालन करने में असमर्थ रहे ।”³³ सबसे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन किया और विदेशी आयातों तथा सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । इंग्लैंड तथा अमेरिका में मूल्य-स्तर एवं रोजगार की स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाने लगा और इन देशों में सोना अधिक मात्रा में आने पर भी सात का विस्तार नहीं किया गया तथा विदेशों ने आने वाले सोने को आसबित बोर्डो (Hoards) के रूप में जमा कर लिया गया । इस प्रकार स्वर्ण बोर्डो का प्रभाव मूल्य-स्तर पर नहीं पड़ने दिया जाता था ।

(४) स्वर्ण कोषों का असमान वितरण—युद्ध के कारण विभिन्न देशों में सोने का वितरण बहुत असमान हो गया था और कुछ बड़े देशों के पास सोने की भारी कमी थी । कुछ देशों के पास (जैसे अमेरिका और फ्रांस) सोना बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गया था जबकि इंग्लैंड व जर्मनी में सोने की बहुत कमी थी । अमेरिका तथा फ्रांस ने युद्ध में हारने वाले देशों को सडवाई के जुर्मनि सोने के रूप में भुगतान करने के लिए बाध्य किया जिसके कारण इन देशों के पास सत्तार का ८०% सोना जमा हो गया और जर्मनी तथा पूर्वी योरोप के देशों में सोने की इतनी अधिक कमी हो गई कि वे स्वर्णमान को बनाये रखने में सफल न हो सके ।

32 “To seek for stability of prices, rather than of exchanges was the primary duty of the monetary authorities”

—Crowther : An Outline of Money, P. 316.

33 “The third reason for the downfall of the postwar gold standard was that the Central Banks, torn by the divided loyalties and aware of great technical difficulties, failed to observe the golden rule”

—Crowther : An Outline of Money, P. 319.

(५) बहुत से देशों के द्वारा स्वर्ण दिनिमय मान का अपनाया जाना—युद्ध के पश्चात् लगभग सभी देशों ने स्वर्ण मुद्रामान को त्याग दिया और उसके स्थान पर स्वर्ण धातुमान अथवा स्वर्ण विनिमय मान को अपना लिया गया । अधिकांश देशों के द्वारा स्वर्ण विनिमय मान अपनाये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान कमजोर हो गया । इन देशों के बीच सोने के आयात तथा निर्यात की आवश्यकता समाप्त हो गई और अधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण स्वर्णमान न चल सका ।

(६) आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव—युद्ध के कारण बहुत से देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में हड़ता आ गई थी और लोच के अभाव के कारण इन देशों में मूल्य स्तर तथा मजदूरी की दरों को स्वर्ण कोषों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार घटाना-बढ़ाना सम्भव न था । व्यापारिक सघों, बड़ी-बड़ी कार्पोरेशन तथा मजदूर सघों के स्थापित हो जाने के कारण मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में परिवर्तन करना कठिन हो गया था । ऐसी दशाओं में सोने का आयात तथा निर्यात देश की अर्थ-व्यवस्था पर अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाते थे ।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा में वृद्धि—युद्ध के कारण विदेशी ऋणों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी जिसके कारण स्वर्णमान के सुविधापूर्वक चलने में कठिनाई होने लगी । लड़ाई के जुमानों का भुगतान करने के लिए तथा युद्ध सम्बन्धी ऋणों की किरतें देने के लिए ऋणी देशों से सोना निकनकर अमेरिका और फ्रांस में जमा हो रहा था, जहाँ पर पहले से ही बहुत अधिक सोना था । सोने के इस अनावश्यक हस्तान्तरण के कारण स्वर्णमान ठीक प्रकार से न चल सका । क्राउथर ने इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए कहा है कि, “जब अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जैसा की युद्ध उपरांत काल में था तो स्वर्णमान का कार्य उम्मी सीमा तक अधिक कठिन हो जाता है ।”³⁴

(८) शरणार्थी पूँजी के भयंकर परिणाम (Havoc caused by Refugee Capital)—प्रथम महायुद्ध से पूर्व विभिन्न देशों में पूँजी का अल्पकालीन विनियोग किया जाता था । किन्तु युद्ध काल में तथा युद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों ने विदेशी पूँजी पर नियन्त्रण लगा दिये और पूँजी की वापसी तथा उस पर दिये जाने वाले ब्याज का भुगतान स्थगित कर दिया गया जिसके कारण काफी देवेंतों फँस गई और पूँजी कुछ देशों से हटकर अधिक सुरक्षित देशों में जाने लगी । पूँजी का यह आवागमन इतना तीव्र तथा आकस्मिक था कि बहुत से देश इसके भयंकर परिणामों से न बच सके । सन् १९३१ में फ्रांस के द्वारा भारी मात्रा में अपनी पूँजी का इंग्लैंड से हटाया जाना, इंग्लैंड में स्वर्णमान के टूटने का प्रमुख कारण था ।

34 'When international indebtedness is large as it was in the postwar era the task of the gold standard is to that extent more difficult of accomplishment.'
—Crowther An Outline of Money, P 319.

(६) राजनैतिक स्थिरता का अभाव—यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका था किन्तु युद्ध का वातावरण अभी बना हुआ था। विभिन्न देशों में आपसी विश्वास न होने के कारण एक प्रकार का तनाव रहता था और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव था। राजनैतिक आन्दोलन, घरेलू झगडों तथा सरकारों के स्थिर न होने के कारण इन देशों की मौद्रिक व्यवस्था सुरक्षित न थी। मुद्रा में जनता का विश्वास न होना, बैंकों पर रुपये की अधिक माग तथा देश से भारी मात्रा में पूँजी का भागना, उस समय की स्वाभाविक घटनाएँ थी। इन कठिनाइयों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान ठीक प्रकार से न चल सका।

(१०) महान् आर्थिक मन्दी के घुरे प्रभाव (Evils of Great Economic Depression)—सन् १९२९ में महान् आर्थिक मन्दी के कारण ऐसी दशाएँ पैदा हो गईं जिनके परिणामस्वरूप स्वर्णमान को अनिवार्य रूप से स्थगित कर देना पड़ा। सबसे पहले अमेरिका की वाल स्ट्रीट (Wall Street) से यह सबूट प्रारम्भ हुआ और स्वर्णमान होने के कारण सब देशों में दौध्रता के साथ फैल गया। कीमतें तथा राजदूरी की दूरे गिरने लगी और अति-उत्पादन तथा बेरोजगारी की दशाएँ पैदा हो गईं। बैंकों पर मुद्रा की परिवर्तनशीलता के लिए इतनी अधिक माग की गई वे उसे पूरा न कर सकें और बहुत से बैंक इस कारण फेल हो गये। इन देशों को अपनी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को स्थगित करना पड़ा और स्वर्णमान टूट गया।

स्वर्णमान के पतन के पश्चात्

(After the Decline of Gold Standard)—

सन् १९३१ में स्वर्णमान के पतन के पश्चात् विभिन्न देशों में पत्र मुद्रा प्रणाली को अपना लिया गया जिसके कारण विदेशी विनिमय की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो गया। स्टर्लिंग (Sterling) तथा अन्य मुद्राओं का मूल्य सोने के सम्बन्ध में तेजी के साथ गिरने लगा जिसके कारण बहुत सी आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो गईं। कुछ देशों ने अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य का स्थिर रखने के लिए विनिमय समानोकरण कोषों (Exchange Equalisation Funds) को स्थापित किया और कृत्रिम तरीकों से विदेशी विनिमय में होने वाले परिवर्तनों को रोका गया। यह व्यवस्था केवल कुछ वर्षों तक ही चल सकी और युद्ध की अनान्य दशाओं में टूट गई। द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ जाने पर सभी देशों में काफी बड़ी मात्रा में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा जारी कर दी गई जिसके कारण विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करना बटिन हो गया और इन देशों के मूल्य-स्तरों में भी काफी परिवर्तन होने लगे। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक योजनाएँ बनाई गईं। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या स्वर्णमान को फिर से स्थापित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान का विकास किया जाय? संयुक्त राष्ट्र सभ के सभी देश इस बात पर लगभग सहमत थे

कि किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान को स्थापित किया जाय जिसमें पुराने स्वर्णमान के कुछ गुण हों और वह उसकी अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण हो ।

उस समय की प्रचलित दशाग्रो में प्राचीन प्रकार के स्वर्णमान को पुनः स्थापित करना असम्भव था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए अनिवार्य दशायें लगभग समाप्त हो चुकी थीं । यह बात निःसंदेह स्वीकार की जाती थी कि भविष्य का मुद्रामान किसी प्रकार का पत्र मुद्रामान हो हो सकता है चाहे उसमें विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्वर्णमान का कुछ अंश सम्मिलित रहे । प्रो० केन्स (Keynes) तथा कैसल (Cassel) का दृढ़ विश्वास था कि नियन्त्रित पत्र मुद्रामान (Managed Paper Currency System) ही भविष्य में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि मूल्य की अस्थिरता के कारण सोने में वर्तमान क्षेत्रों में अपना महत्व नष्ट कर दिया था । क्राऊथर (Crowther) ने भी वर्तमान राष्ट्रीय तथा स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के युग में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था की स्थापना करना असम्भव बनलाया है ।³⁵ आज की सरकारें न तो दृढ़ विदेशी विनिमय दरों में विश्वास रखती हैं और न वे स्वर्ण कोषों में परिवर्तन होने पर मुद्रा का विस्तार अथवा संकुचन करने को तैयार हैं । शीत युद्ध-नीति (Cold War Policy) के कारण राजनैतिक अस्थिरता की दशायें उत्पन्न हो गई हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावना पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गई है । प्रो० हॉल (Prof. Halm) ने ठीक ही कहा है कि इन दशाग्रो में स्वर्णमान के समर्थक चाहे कितना भी उसे स्थापित करने का प्रयत्न करें किन्तु प्राचीन रूप में स्वर्णमान का स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है ।³⁶ इन्हीं सब कारणों से स्वर्णमान के पतन के पश्चात् विभिन्न देशों के द्वारा नियन्त्रित पत्र मुद्रा प्रणाली (Managed Paper Standard) स्थापित की गई । किन्तु विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता थी जिसे प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) की योजना के अन्तर्गत एक नई मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ । कुछ लेखकों ने इसे स्वर्ण समता मान (Gold Parity Standard) कहा है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत सदस्य देशों को अपनी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य निश्चित करना होता है । यद्यपि इस स्वर्ण मूल्य में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किये जा सकते हैं, किन्तु सामान्यतः इन देशों को अपनी विनिमय दरें अपनी मुद्राओं के स्वर्ण मूल्यों के

35 "It is impossible to have an international financial system alongside a commercial system that is fiercely and jealously national"

—Crowther : An Outline of Money, P. 319.

36 "No matter how badly some friends of gold standard want it reintroduced, they must see that the case for it in its orthodox form is hopeless when some of the major countries refuse to be into the strait jacket of gold."

—Halm : Monetary Theory, P. 207.

अनुसार निश्चित करनी होती है। इस प्रकार इस योजना में स्वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है और सोना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को निश्चित करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इस नई मुद्रा व्यवस्था को पूर्णतया स्वर्णमान नहीं कहा जा सकता है किन्तु इसमें स्वर्णमान का कुछ अंश अवश्य मौजूद है।

रजतमान

(Silver Standard)

एक धातुमान (Monometallic Standard) या तो सोने पर आधारित हो सकता है या चाँदी पर। उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व मुद्रा धातु के रूप में चाँदी का प्रयोग अधिक किया जाता था, उन्नीसवीं शताब्दी में सोना और चाँदी दोनों ही मुद्रा धातु का कार्य करती थी; किन्तु इस शताब्दी के अन्त तक इन धातुओं का प्रयोग धीरे-धीरे कम होने लगा। यद्यपि स्वर्णमान की भाँति रजतमान अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है किन्तु फिर भी कुछ देशों में चाँदी काफी समय तक मूल्यमान का कार्य करती रही है। सैद्धान्तिक रूप से रजतमान भी तीन प्रकार का हो सकता है किन्तु व्यवहार में केवल रजत मुद्रामान (Silver Currency Standard) ही अपनाया गया है। इस प्रकार के मुद्रामान में चाँदी मूल्यमान का काम करती है और निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले चाँदी के प्रमाणिक सिक्के देश में चलाये जाते हैं। चाँदी के सिक्कों का स्वतन्त्र मुद्रण किया जाता है और वे असंमित विधिग्राह्य मुद्रा होते हैं। देश में चलने वाली अन्य प्रकार की मुद्रायें निश्चित दरों पर चाँदी के सिक्कों में परिवर्तनीय रखी जाती हैं। चीन की मुद्रा प्रणाली दीर्घ काल तक रजतमान पर आधारित रही है। भारतवर्ष में रजतमान सन् १८३५ से १८६३ तक रहा जिसके अन्तर्गत चाँदी का रुपया देश की प्रमाणिक मुद्रा था जिसका भार १८० ग्रेन होता था और उसमें १/२ भाग शुद्ध चाँदी होती थी। चाँदी की मुद्रा की स्वतन्त्र ढलाई की जाती थी। सन् १८७४ तक भारत में रजतमान ठीक प्रकार चलता रहा किन्तु इसके उपरान्त मैक्सिको में चाँदी की नई खानों का पता लग जाने के कारण चाँदी के भाव गिरने लगे और भारत सरकार को चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द करना पड़ा। सन् १८६३ में भारतवर्ष के द्वारा रजतमान को त्याग दिया गया क्योंकि चाँदी के भाव में अधिक परिवर्तन होने के कारण रजतमान मुद्रा व्यवस्था में स्थिरता स्थापित करने में असमर्थ था। चीन में रजतमान सन् १९३५ तक चलता रहा और उसके उपरान्त इसे त्याग दिया गया।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से रजतमान और स्वर्णमान की कार्य-प्रणाली में कोई विशेष अन्तर नहीं है। रजतमान के द्वारा भी उन लाभों को प्राप्त किया जा सकता है जो स्वर्णमान में उपलब्ध हैं। इसके अनिश्चित, रजतमान निर्धन देशों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि चाँदी का मूल्य सोने की अपेक्षा बहुत कम होता है।

किन्तु अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चांदी के मूल्य में अपेक्षा-कृत कम स्थिरता रहने के कारण रजतमान मुद्रा के मूल्य में उतनी स्थिरता स्थापित नहीं कर सकता है, जितनी कि स्वर्णमान के द्वारा स्थापित की जा सकती सकती है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-प्रणाली की प्रालोचनात्मक व्याख्या कीजिये। इस कार्य-प्रणाली में Council Bill तथा Reverse Councils के महत्व पर प्रकाश डालें। (आगरा बी० ए० १९६०)
- (२) स्वर्णमान क्या है? स्पष्ट कीजिये। अन्य मानों की अपेक्षा यह किस प्रकार उत्तम है। उदाहरण सहित समझाइये। (आगरा बी० ए० १९५८ त)
- (३) "स्वर्णमान की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वर्णमान के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।" इस कथन की व्याख्या कीजिये। (आगरा बी० ए० १९५६)
- (४) स्वर्णमान ने किस प्रकार कार्य किया, इसकी विवेचना करिये। इसकी असफलता के कारण बताइये। (आगरा बी० काम० १९५६)
- (५) स्वर्णमान से आप क्या समझते हैं? वह किन दशाओं में अच्छी प्रकार काम कर सकता है? (राजस्थान बी० ए० १९५८)
- (६) स्वर्णमान के कार्यों पर प्रकाश डालिये। क्या प्रवर्धित पत्र चलन मान इससे अच्छा है? कारण दीजिये। (राजस्थान बी० काम० १९५८)
- (७) स्वर्णमान के कार्य-संचालन एवं उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिये। (राजस्थान बी० काम० १९५८)
- (८) क्या बिना स्वर्ण करेसी के स्वर्णमान स्थापित किया जा सकता है? कारण सहित बताइये और ऐसे मान के गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये। (सागर बी० ए० १९५८)
- (९) मौद्रिक क्षेत्र में स्वर्ण की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या स्वर्णमान पुनः लौटाया जा सकता है? (बिहार बी० ए० १९५६)
- (१०) स्वर्णमान के संचालन में किन-किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? यह बताइये कि इन नियमों का पालन न करने से किस प्रकार सन् १९३१ में स्वर्णमान टूट गया? (विक्रम बी० काम० १९६०)
- (११) स्वर्णमान की प्रमुख विशेषतायें बताइये। उन कारणों की व्याख्या कीजिये जिनसे सन् १९२५ में पश्चात् यह मान टूट गया। (बिहार बी० काम० १९६०)
- (१२) आपके विचार में स्वर्णमान की सफलता के लिए क्या दशाएँ आवश्यक हैं? विभिन्न देशों के द्वारा स्वर्णमान को क्यों त्याग दिया गया। (राजस्थान बी० ए० १९५७)

पत्र मुद्रा तथा पत्र मुद्रामान

PAPER MONEY AND PAPER STANDARD

पत्र मुद्रा का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से होता आया है। इतिहासकारों का मत है कि सर्वप्रथम चीन में पत्र मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ। ६वीं शताब्दी में चीन के सम्राट हेसेनटुङ्ग (Hsientung) के राज्य-काल में पत्र मुद्रा जारी किये जाने के ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। उस समय से लेकर १७वीं शताब्दी तक वहाँ पर पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाता रहा। चीन के पश्चात् जापान तथा पर्सिया (Persia) में पत्र मुद्रा का कार्य किया जाने लगा। कुछ विद्वानों का मत है कि बैबीलोन, एसोरिया तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता के युग में भी किसी न किसी रूप में पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाता था किन्तु प्राचीन समय में प्रयोग की जाने वाली पत्र मुद्रा वर्तमान कागजी नोटों से बिल्कुल भिन्न होती थी। वर्तमान प्रकार की पत्र मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले यूरोप में हुआ। १८वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पत्र मुद्रा काफी प्रचलित थी। धीरे-धीरे वहाँ से पत्र मुद्रा का प्रयोग अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। प्रथम महायुद्ध काल में कागजी नोटों के चलन को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस समय यूरोप के देशों में सड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता थी जिसे नोट छाप कर पूरा किया गया। सन् १९३१ में स्वर्णमान के पतन के पश्चात् पत्र मुद्रा का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया और आज वह ससार की एकमात्र मुद्रा बन गई है।

पत्र मुद्रा का प्रयोग मुख्यतया धातु मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। जिस जमाने में सोने और चाँदी के सिक्के चलाये जाते थे उस समय चाँदी और सोने की खानों का विशेष महत्व था। सोने की नई खानों के मालूम हो जाने पर सोने की मात्रा के बढ़ जाने के कारण मुद्रा का विस्तार होता था तथा सोने का उत्पादन कम हो जाने पर मुद्रा की मात्रा को अनिवार्य रूप से कम करना पड़ता था। अतः धातु मुद्रामान के युग में मुद्रा की मात्रा बहुसूतय धातुओं की अनिश्चित प्रति पर निर्भर रहती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत समय से किसी ऐसी वस्तु की खोज की जा रही थी जो सोने के स्थान

पर मुद्रा का कार्य कर सके और मुद्रा वस्तु के लिए प्रवृत्ति पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके। पत्र मुद्रा के रूप में एक ऐसी मुद्रा को प्राप्त कर लिया गया जिसकी मात्रा को घटाना-बढ़ाना मनुष्य के हाथ में था और इस प्रकार प्रवृत्ति के ऊपर निर्भरता को कम कर दिया गया। इसके अतिरिक्त समाज की विनिमय के लिए बटती हुई मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए भी पत्र मुद्रा की आवश्यकता थी। आर्थिक प्रगति के साथ मुद्रा की आवश्यकता तेजी के साथ बढ़ रही थी जिसे सोने की सीमित पूर्ति के द्वारा पूरा करना असम्भव था। मुद्रा की इस बटती हुई मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य था। सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की बचन करने के लिए भी पत्र मुद्रा की उपयोगिता की आवश्यकता पड़ी। धात्विक मुद्रा बहुत कमती होती थी, उनके स्थान पर किसी सस्ती मुद्रा की आवश्यकता थी। उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का विकास किया गया और उसका प्रचलन होने लगा।

पत्र मुद्रा का विकास (Evolution of Paper Money)—

पत्र मुद्रा का विकास तथा उसका प्रयोग समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पत्र मुद्रा ने समाज को धातु मुद्रा प्रणाली की कठिनाइयों से ही मुक्त नहीं किया बल्कि आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दशाओं पैदा करने में बड़ी सहायता दी है। आजकल तो यह माना जाने लगा है कि पत्र मुद्रा स्वयं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। इस उपयोगी पत्र मुद्रा का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि धीरे-धीरे विभिन्न अवस्थाओं में से होकर वर्तमान पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके ही हम उसके विकास को समझ सकते हैं। पत्र मुद्रा के विकास के सम्बन्ध में अत्यंत ही चार अवस्थाएं बनलाई जाती हैं।

(१) लिखित पत्रों की अवस्था—सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का उदय लिखित पत्रों के रूप में हुआ जो स्वयं मुद्रा नहीं थे किन्तु मुद्रा के स्थान पर उनका प्रयोग किया जाता था। धातु मुद्रा की चोरी हो जाने के भय से लोग अपनी मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए किसी विश्वसनीय सर्राफ़ अथवा बैंकर के पास जमा कर देते थे जो उसके बदले में उन्हें उसी रकम का लिखित पत्र दे देता था। विशेषकर व्यापारी जब दूसरे शहरों से सामान लेने जाते थे तो वे नकद रुपया अपने साथ न ले जाकर केवल इन लिखित पत्रों को ले जाते थे जो इस बात का प्रमाण होने थे कि उन पर लिखित रकम बैंकर के पास जमा है और वहाँ से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इन लिखित पत्रों के लो जाने पर किसी की हानि नहीं उठानी पड़ती थी।

(२) बैंक नोटों की अवस्था—धीरे-धीरे इन लिखित पत्रों ने बैंक नोटों का रूप धारण कर लिया। इन सर्राफ़ों ने देखा कि उनके लिखित पत्रों में से बहुत कम नकदी में बदलने के लिए आते हैं। उनका प्रयोग केवल मुद्रा के स्थान पर ही नहीं

किया जाता है यत्कि वे स्वयं मुद्रा का कार्य करने लगे हैं। अब ये प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति विशेष के नाम में न लिखे जाकर वाहक (Bearer) के नाम में लिखे जाने लगे और निश्चित तथा सुविधापूर्ण रकम के होते थे। इस प्रकार लिखित पत्रों ने बैंक नोटों का रूप ले लिया। जो व्यक्ति जितनी मुद्रा बैंक के पास जमा करता था उसे उतने ही मूल्य के बैंक नोट दिये जाते थे जिन्हें वह विभिन्न व्यक्तियों की सुविधापूर्वक हस्तांतरित कर सकता था।

(१) अनुपातिक कोष रखने की अवस्था—यह बैंक नोट इतने अधिक प्रचलित हो गये कि लोग उन्हें बहुत कम धात्विक मुद्रा में बदलने के लिए लाते थे। बैंक नोट बहुत लम्बे समय तक चलन में रहते थे और भुगतान निपटाने में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते रहते थे। बैंकर्स ने जब यह देखा कि उनके प्रोनोट ही मुद्रा का कार्य करने लगे हैं तो उन्होंने अपने पास जमा रकम से अधिक मात्रा में नोट जारी करने प्रारम्भ कर दिये। इस प्रकार नोटों के पीछे अनुपातिक कोष रखने की प्रणाली का जन्म हुआ। इस युग में अधिकांश नोट बैंक के द्वारा जारी किये जाते थे।

(४) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की अवस्था—धीरे-धीरे पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य केन्द्रीय बैंको ने लिया। सरकारों के शक्तिशाली हो जाने के कारण पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ना गया और पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता की समस्या लगभग समाप्त हो गई। अब नोटों के पीछे अनुपातिक कोष रखना भी अनावश्यक समझा जाने लगा और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा जारी की जाने लगी।

पत्र मुद्रा के लाभ (Advantages of Paper Money)—

यद्यपि पत्र मुद्रा प्रणाली दोषरहित नहीं है किन्तु फिर भी उसे धातु मुद्रा प्रणाली की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है। पत्र मुद्रा के प्रयोग से कुछ ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जो धातु मुद्रा के युग में नहीं मिलते थे। इनमें से मुख्य-मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत—पत्र मुद्रा के प्रयोग से धातु मुद्रा की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है और सिक्कों के बनाने में प्रयोग किये जाने वाले सोने व चांदी की बचत होती है। इस प्रकार बचे हुए सोने व चांदी का प्रयोग औद्योगिक तथा कलात्मक कामों के लिए किया जा सकता है। सोने और चांदी के उत्पादन में लगे हुए श्रम व पूँजी को अन्य कामों में लाया जा सकता है। एडम स्मिथ ने पत्र मुद्रा की तुलना आकाश मार्ग से की है जिसके नीचे की भूमि का प्रयोग भी किया जा सकता है और उस पर अन्न आदि उत्पन्न करके मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है।^१

(२) पत्र मुद्रा अधिक भित्तव्यधितापूर्ण है—धातु मुद्रा की अपेक्षा पत्र मुद्रा का उत्पादन व्यय बहुत कम आता है। सरकार को पत्र मुद्रा के पीछे उसके मूल्य के बराबर धातु कोष भी नहीं रखना पड़ता है और काफी मात्रा में नोट बिना किसी धातु कोष के ही चलाये जाते हैं। इस प्रकार सरकार बहुत बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त करने तथा उसे मौद्रिक कोष के रूप में रखने के व्यय से बच जाती है। जिस देश में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रयोग की जाती है, वहाँ इस प्रकार की वचत बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती है।

(३) सिक्कों की घिसावट के कारण होने वाली हानि बच जाती है—धातु मुद्रा प्रणाली में सरकार को प्रति वर्ष सिक्कों के घिस जाने तथा कट जाने के कारण काफी हानि उठानी पड़ती थी किन्तु पत्र मुद्रा प्रणाली में इस प्रकार की हानि बहुत कम हो जाती है। कागजी नोट धातु मुद्रा का स्थान ले लेते हैं और चलन में सिक्कों की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इस प्रकार सिक्कों की घिसावट के कारण होने वाली हानि से सरकार बच जाती है।

(४) पत्र मुद्रा अधिक सुविधापूर्ण है—पत्र मुद्रा के द्वारा बड़े-बड़े भुगतानों को आसानी से निबटाया जा सकता है क्योंकि उसे गिनने में तथा उसका हिसाब लगाने में बड़ी सुविधा रहती है। पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में भी बड़ी सुविधा होती है क्योंकि मूल्य के अनुपात में उसका भार बहुत कम होता है और उसमें सहनीयता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। धातु मुद्रा को अधिक भार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में बड़ी असुविधा होती थी किन्तु कागज के नोटों के रूप में कितनी भी मुद्रा की बिना किसी कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है।

(५) पत्र मुद्रा देश की मुद्रा प्रणाली में सौच का गुण पंदा करती है—पत्र मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है जिसके कारण मुद्रा की माग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करने की सम्भावना बढ़ जाती है। बहुमूल्य धातुओं की पूर्ति सीमित होने के कारण धातु मुद्रा का विस्तार करना सम्भव नहीं होता था जिसके कारण मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रहती थी, किन्तु पत्र मुद्रा में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। सौच का गुण होने के कारण पत्र मुद्रा की मात्रा को आसानी से नियन्त्रित किया जा सकता है तथा उसकी माग और पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखा जा सकता है। अतः उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा पत्र मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

(६) बुरे समय में पत्र मुद्रा सरकार की सहायता करती है—संकट काल में जब अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो सरकार अधिक मात्रा में नोट छाप कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती है। युद्ध आदि के व्यय को पूरा करने के लिए नई पत्र मुद्रा का प्रयोग सगम्य सभी देशों में किया गया है। अधिक नोट छाप कर

सरकार जनता से भारी मात्रा में अप्रत्यक्ष ऋण ले सकती है जिस दूपर उन्हें किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा मुसीबत के समय में सरकार की बड़ी सहायता करती है। आपत्ति काल में कागज के अधिक नोट छाप कर सरकार अपने देश को सवट से बचा सकती है।

(७) पत्र मुद्रा आर्थिक विकास में सहायता करती है—पत्र मुद्रा को भाजकल देश में पूर्ण रोजगार तथा अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। उसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग करने में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमती रोबिंसन (Mrs. Robinson) के अनुसार स्वर्णमान की प्रवृत्ति मुद्रा सञ्चयन की ओर होती है जिसके कारण देश में बेरोजगारी होती है तथा उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। पत्र मुद्रा का न्योग होने के कारण मुद्रा की कमी की समस्या लगभग दूर हो गई है और प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का प्रवन्ध इस प्रकार कर सकता है कि देश के आर्थिक साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। पत्र मुद्रा समाज को केवल मुद्रा सञ्चयन की बुराई में ही मुक्त नहीं करती है बल्कि वह आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दसायें भी पैदा करती है। विशेषकर अल्प-विकसित देशों में पत्र मुद्रा पूँजी के निर्माण तथा आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। हीनार्ध-प्रवन्ध (Deficit Financing) के द्वारा विरामशील देश अपने अविकसित साधनों को प्रयोग में लाकर आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं।

पत्र मुद्रा के दोष (Disadvantages of Paper Money)—

यद्यपि पत्र मुद्रा धातु मुद्रा की अपेक्षा अधिक घबड़ी मानी जाती है और लगभग सभी देशों ने पत्र मुद्राभान को अपना लिया है किन्तु फिर भी उसे दोष-रहित नहीं कहा जा सकता है। यदि उसका सही प्रवन्ध न किया जाय तो यह समाज में बहुत सी बुराइयों को उत्पन्न कर सकती है। पत्र मुद्रा के प्रयोग में निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो सकते हैं—

(१) अत्यधिक निकासी का भय—पत्र मुद्रा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष अत्यधिक निकासी के कारण पैदा होता है। पत्र मुद्रा की मात्रा सरकार की दृष्टि के ऊपर निर्भर रहती है जिसके कारण आवश्यकता में अधिक मात्रा में नोट जारी करने की सम्भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा राज्य में दण प्रकार का भय वित्कुल नहीं था; परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रणाली में अत्यधिक निकासी की जा सकती है किन्तु बहुत कम मात्रा में। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली में अत्यधिक निकासी का भय बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि दण प्रणाली में मुद्रा का रिहा किसी भी मात्रा में किया जा सकता है। वर्तमान पत्र मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रणाली

का भय हर समय बना रहता है और केवल उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा ही इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

(२) पत्र मुद्रा का मूल्य अधिक अनिश्चित तथा अस्थिर होता है—स्वर्णमान में मुद्रा का मूल्य सोने की मात्रा पर आधारित होने के कारण बहुत कम बदलता था किन्तु पत्र मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा पर निर्भर होता है जिसके कारण वह बहुत अधिक बदलता रहता है। क्योंकि पत्र मुद्रा की मात्रा में सरकार की इच्छा के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है और वह समय-समय पर बदलता रहता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के कारण मूल्य-स्तर बदलता है तथा समाज में अन्य आर्थिक बुराईयाँ पैदा हो जाती हैं। मुद्रा के मूल्य की इस अनिश्चितता का देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यापार तथा उत्पादन अनियमित हो जाते हैं।

(३) विदेशी विनिमय दरें स्थिर नहीं रहती हैं—पत्र मुद्रामान में विदेशी विनिमय दरों में अधिक परिवर्तन होने हैं और विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दरों में बहुत कम परिवर्तन होते थे और इन परिवर्तनों की सीमाये निश्चित होती थी किन्तु पत्र मुद्रामान में विदेशी विनिमय दरें अधिक बदलती हैं और उनमें होने वाले परिवर्तनों की कोई सीमा नहीं होती है। विदेशी विनिमय की इस अनिश्चितता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और विभिन्न देशों के बीच पूँजी के आवागमन में रुकावट पैदा होती है।

(४) पत्र मुद्रा का चलन क्षेत्र सीमित होता है—कागजी मुद्रा का चलन क्षेत्र राष्ट्रीय होता है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक देश की पत्र मुद्रा उस देश की सीमाओं के भीतर ही विधिबद्ध होती है और विदेशियों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। पत्र मुद्रा का सीमित चलन होने के कारण विदेशी मुग्तानों में विशेष कठिनाई होती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में रुकावट पड़ती है। धातु मुद्रा का प्रयोग विदेशी मुग्तानों को निबटाने के लिए भी किया जा सकता था किन्तु पत्र मुद्रा में यह गुण नहीं पाया जाता है।

(५) पत्र मुद्रा का कुछ भी निहित मूल्य नहीं होता है—पत्र मुद्रा का वस्तु के रूप में कोई मूल्य नहीं होता है और वह तब तक ही मूल्यवान रहती है जब तक उसे मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि बाणज के नोटों का विमुद्रिकरण (Demonetisation) कर दिया जाय तो पदार्थ के रूप में उनका कुछ भी मूल्य नहीं होगा और वे बाणज के टुकड़े मात्र रह जायेंगे। पत्र मुद्रा में कोई निहित मूल्य न होने के कारण इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास देर से बनता है।

(६) पत्र मुद्रा व्यापार-चक्रों को जन्म देती है तथा सट्टे (Speculation) को प्रोत्साहित करती है—पत्र मुद्रा पर आर्थिक जीवन को अनियमित करने का आरोप लगाया जाता है। पूँजीवादी देशों में व्यापार-चक्रों (Trade Cycles) के आने का महत्वपूर्ण कारण पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा की अत्यधिक निकासी का होना बतलाया जाता है। पत्र मुद्रा समाज में सभी प्रकार की सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है। कुछ लेखकों ने पत्र मुद्रा के इस दोष को एक भयंकर बीमारी बतलाया है। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को जितना कष्ट दे सकती है, पत्र मुद्रा के कारण समाज को उससे अधिक कष्ट होता है। कुछ ग्रंथशास्त्रियों ने इसी कारण पत्र मुद्रा को सामाजिक धोखा (Social Fraud) कहा है।

(७) सरकार को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रवृत्ति प्रदान करती है—सरकारें प्रायः पत्र मुद्रा जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखती हैं। पत्र मुद्रा का अत्यधिक विस्तार करके सरकार जितनी मात्रा में चाहे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकती है किन्तु इस प्रकार के अनावश्यक मुद्रा प्रसार के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। विशेषतया युद्ध काल में सरकार की प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करने की होती है। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी का भयंकर मुद्रा प्रसार इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। पत्र मुद्रा सरकार के हाथों में प्रसीमित मात्रा में मुद्रा जारी करने की शक्ति दे देती है जिसका किसी भी समय दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सरकार को पत्र मुद्रा पर प्रभावशाली नियन्त्रण करने से पूर्व स्वयं अपने पर नियन्त्रण करना चाहिए।

पत्र मुद्रा के उचित प्रबन्ध की आवश्यकता

(Proper Management of Paper Money)—

वर्तमान समाज पत्र मुद्रा प्रणाली पर आधारित है और हमने पत्र मुद्रा को अपने आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करने का काम सौंप दिया है। हमारी आर्थिक प्रगति बहुत कुछ पत्र मुद्रा के सही व्यवहार पर निर्भर है। पत्र मुद्रा का सही प्रबन्ध न होने के कारण आर्थिक जीवन अनियमित हो जाता है और आर्थिक विकास तेजी के साथ नहीं हो पाता है। यद्यपि पत्र मुद्रा को सभी देशों ने अपना लिया है किन्तु उसके दोषों को दूर करने में अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। आज भी समाज में पत्र मुद्रा के दुरुपयोग के कारण बहुत सी बुराइयाँ पैदा होती हैं। पत्र मुद्रा के सही प्रबन्ध के द्वारा ही हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं और पत्र मुद्रा को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

पत्र मुद्रा स्वयं कोई बुरी दस्तु नहीं है। उसमें दोष इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम उसका ठीक प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। यदि पत्र मुद्रा का उचित प्रबन्ध किया जाय तथा उसके साथ साख की मात्रा को भी नियन्त्रित रखा जाय तो समाज

पत्र मुद्रा प्रणाली के दोषों से बच सकता है। पत्र मुद्रा का सबसे बड़ा दोष अत्यधिक निकासी के कारण पैदा होता है जिसे मुद्रा की मांग को आवश्यकता के अनुसार नियन्त्रित करके बहुत सीमा तक दूर किया जा सकता है। वर्तमान समाज में मुद्रा सम्बन्धी दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय पत्र मुद्रा का सही प्रबन्ध करना है। मुद्रा के प्रबन्ध की जिम्मेदारी सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक पर आती है। सरकार को चाहिए कि वह पत्र मुद्रा का प्रबन्ध इस प्रकार करे कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखा जा सके और आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त की जा सके। इसके लिए अनिवार्य है कि सरकार मुद्रा की मांग में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाये रखे। इस प्रकार उचित प्रबन्ध के द्वारा पत्र मुद्रा को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है विशेषतया अल्प-विकसित देशों में जहाँ पर पत्र मुद्रा का प्रयोग आर्थिक प्रगति के लिए किया जा रहा है, उचित मौद्रिक प्रबन्ध की आवश्यकता और भी अधिक है।

पत्र मुद्रामान (Paper Standard)—

एक प्रकार के मुद्रामान को प्रबन्धित पत्र चलन मान (Managed Paper Currency Standard) भी कहा जा सकता है क्योंकि पत्र मुद्रामान प्रकृति से ही प्रबन्धित मुद्रामान है। इस प्रकार के मुद्रामान में स्वयं सञ्चालयता का गुण नहीं पाया जाता और सरकार मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा मुद्रा की मांग व पूर्ति को संतुलित करती है। पत्र मुद्रामान में देश की प्रमुख मुद्रा बाजार की बनी होती है और उसे सामान्यतः सोने अथवा चाँदी में परिवर्तनीय नहीं रखा जाता है। पत्र मुद्रा का मूल्य सोने अथवा चाँदी के द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता है बल्कि मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा उसे स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाता है। विदेशी बाजारों में मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति के आधार पर निश्चित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना से पूर्व विदेशी मुद्राओं के लिए कुछ स्वर्ण कोष रखा जाता था किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना के अन्तर्गत स्वर्ण कोषों का महत्त्व बहुत कम रह गया है। विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य देश अपनी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य (Gold Parity) को निश्चित करके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचित करता है और फिर उस देश का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को सामान्य दशाओं में उभी स्तर पर स्थिर रखे किन्तु असाधारण परिस्थिति में वह अपनी मुद्रा की स्वर्ण समता (Gold Parity) को बदल सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पत्र मुद्रामान के अन्तर्गत मुद्रा का आन्तरिक मूल्य सोने के द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसने मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखा जाता है। प्रबन्धित पत्र मुद्रामान (Managed Paper Currency Standard) की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) पत्र मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है—पत्र मुद्रामान में पत्र मुद्रा देश की प्रमुख तथा अपरिमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इस प्रकार के मुद्रामान में किसी भी धातु को मुद्रा का आधार नहीं बनाया जाता है। प्रमुख मुद्रा की सहायता के लिए घटिया तथा कम मूल्य वाली धातु के सिक्के चलाये जाते हैं किन्तु उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अधिकार भुगतान पत्र मुद्रा के द्वारा ही निवटारे जाते हैं। पत्र मुद्रा का निर्गमन सरकार प्रथवा केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। नोटों के पीछे किसी प्रकार का स्वर्ण कोष रखना अनिवार्य नहीं होता है किन्तु कुछ देशों में मुद्रा कोष के रूप में सोना रखा जाता है।

(२) पत्र मुद्रा का मूल्य सोने प्रथवा चांदी के मूल्य पर निर्भर नहीं होता है—पत्र मुद्रामान में मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है और वह मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता है। मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने के लिए उसे सोने के साथ सम्बन्धित नहीं किया जाता है। सामान्यतः पत्र मुद्रा सोने में अपरिवर्तनीय होती है। पत्र मुद्रा का मूल्य सोने प्रथवा चांदी के द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जाता है बल्कि उसे मौद्रिक प्रवन्ध के द्वारा स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार मुद्रामान में मुद्रा का सम्बन्ध सोने के साथ बिल्कुल टूट जाता है।

(३) पत्र मुद्रामान एक प्रबन्धित मुद्रामान है—पत्र मुद्रामान स्वर्ण मान की भांति स्वयं संचालित (Automatic) नहीं होता है। सरकारी निपन्त्रण एवं प्रवन्ध इस मुद्रामान की प्रमुख विशेषता है। सरकार मौद्रिक प्रवन्ध के द्वारा मुद्रा की माग व पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करती है और उसके मूल्य में स्थिरता स्थापित की जाती है। माग के बढ़ जाने पर मुद्रा अधिकारी अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है और माग कम होने पर मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है। सरकारी हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण अधिक होने के कारण इस मुद्रामान को प्रबन्धित मुद्रामान कहा जाता है।

(४) विदेशी भुगतानों के लिए स्वर्ण कोष आवश्यक नहीं है—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित हो जाने के पश्चात् अब व्यक्तिगत देशों को विदेशी भुगतानों को निवटारने के लिए किसी प्रकार के स्वर्ण कोष नहीं रखने पड़ते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए अब सोने का महत्व लगभग समाप्त होता जा रहा है।

पत्र मुद्रामान के लाभ—

प्रबन्धित पत्र मुद्रामान से निम्नलिखित लाभ होते हैं—

(१) उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग—पत्र मुद्रामान में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा कर उत्पत्ति के बेकार साधनों को काम में लाया जा सकता है जिससे देश में धन का उत्पादन बढ़ता है। स्वर्ण मान के युग में प्रायः मुद्रा की कमी रहती थी जिसके कारण उत्पत्ति के बहुत से साधन बेकार पड़े रहते थे। यह दोष पत्र मुद्रामान

में वित्तुल दूर हो गया है क्योंकि प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा जारी कर सकता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ मुद्रा प्रसार की स्थिति बनी रहे और पत्र मुद्रामान में इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रायः रहती है इसलिए उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अधिक अनुकूल बना जा सकता है।

(२) मूल्य-स्तर में अधिक स्थिरता सम्भव है—पत्र मुद्रामान में मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता के अनुसार घटाना-बढ़ाना सम्भव होता है जिसके कारण मुद्रा की मांग व पूर्ति में अधिक सतुल्य स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार का सतुल्य स्वरूपमान में स्थापित करना सम्भव नहीं था। पत्र मुद्रामान में सरकार उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थिरता स्थापित कर सकती है।

(३) मौद्रिक प्रबन्ध की स्वतन्त्रता—पत्र मुद्रामान में सरकार को मुद्रा का प्रबन्ध करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। पत्र मुद्रा के पीछे न तो किसी प्रकार का स्वरूप कोप रखा जाता है और न ही उसे सोने में परिवर्तनीय रखा जाता है जिसके कारण मुद्रा अधिकारी मौद्रिक प्रबन्ध अधिक स्वतन्त्रता के साथ कर सकता है। सरकार अपनी इच्छा के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है और इस सम्बन्ध में वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों से भी मुक्त होती है।

(४) लोच का गुण—पत्र मुद्रामान में इतनी अधिक लोच पाई जाती है कि आपत्ति काल में मुद्रा की मात्रा में कितनी भी वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार पत्र मुद्रामान स्वरूपमान की भांति अनुकूल परिस्थिति का मित्र नहीं है बल्कि वह दुरे समय में भी सरकार की सहायता करता है। मुद्रा व्यय पूरा करने के लिए अथवा अधिक विकास के लिए अधिक मुद्रा की व्यवस्था करने में पत्र मुद्रामान काफी सहायक होता है।

पत्र मुद्रामान के दोर—

(१) अत्यधिक निकासी का भय—पत्र मुद्रामान की व्यवस्था में सरकारों की प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा जारी करने की होती है जिसके कारण देश में भयंकर मुद्रा प्रसार हो सकता है। प्रायः देखा गया है कि युद्ध के अवसर पर सरकार अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा चलन में डाल देती है जिसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी तक का अनुभव यही बतलाता है कि पत्र मुद्रा पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण करना सम्भव नहीं हो सका है और सरकारों की प्रवृत्ति प्रायः अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा को जारी करने की होती है।

(२) विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करना कठिन होता है—विदेशी विनिमय की स्थिरता के दृष्टिकोण से पत्र मुद्रामान को अच्छा मुद्रामान नहीं कहा

जा सकता है। पत्र मुद्राभान की विदेशी विनिमय दरें बहुत अधिक बदलती रहती हैं, जिसके कारण विदेशी व्यापार का विस्तार सम्भव नहीं हो पाता है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्णमान को दशाभो में विदेशी विनिमय दरें अधिक स्थिर रहती थीं किन्तु जब से स्वर्णमान को छोड़कर पत्र मुद्राभान को अपनाया गया है तब से विदेशी विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों की सम्भावना बहुत बढ़ गई है और विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रवन्ध तथा नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में कठिनाई—पत्र मुद्राभान किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान अथवा विनिमय माध्यम प्रदान नहीं करता है। इस मुद्राभान में चलने वाली पत्र मुद्रा को विदेशों में स्वीकार नहीं किया जाता है जिसके कारण विदेशी भुगतानों में कठिनाई होती है तथा विभिन्न देशों में मुद्राओं में ठीक-ठीक सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन होता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विदेशी विनिमय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था स्थापित करनी होती है।

(४) विश्वास का अभाव—पत्र मुद्राभान में मुद्रा का सम्बन्ध सोने व चांदी के ताप न होने के कारण, इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास देर से बनता है। पत्र मुद्रा प्रणाली के जटिल होने के कारण भी इस प्रकार के विश्वास का अभाव रहता है।

प्रादिष्ट मान (Fiat Standard)—

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राभान तथा प्रादिष्ट मान में कोई विशेष अन्तर नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि प्रादिष्ट मुद्रा सकटकालीन स्थिति का परिणाम होती है किन्तु अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के विषय में ऐसा अनिवार्य रूप से नहीं कहा जा सकता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा किस स्थिति में चलाई गई है, इसके आधार पर ही प्रादिष्ट मुद्रा को सामान्य पत्र मुद्रा से अलग किया जा सकता है। यदि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा सकट काल में चलाई जाती है तो वह प्रादिष्ट मुद्रा हो जाती है क्योंकि उसकी स्वीकृति वानुनी दबाव के कारण होती है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रादिष्ट मान सरकार की स्याई नीति के परिणामस्वरूप भी अपनाया जा सकता है।

प्रो० केंट (Kent) ने प्रादिष्ट मुद्रा की तीन मुख्य विशेषतायें बतलाई हैं—

- (i) इस प्रकार की मुद्रा का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है अर्थात् प्रादिष्ट मुद्रा का वस्तु मूल्य कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की मुद्रा प्रायः कागज की बनी होती है जिसका वस्तु मूल्य बहुत मामूली होता है। (ii) प्रादिष्ट मुद्रा को किसी ऐसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसका मूल्य मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बराबर हो। इस प्रकार की मुद्रा अपरिवर्तनीय होती है और उसे सोने या अन्य मूल्यवान् धातुओं में नहीं बदला जा सकता है। (iii) इस मुद्रा की क्रय-शक्ति को

सोने अथवा किसी अन्य वस्तु के मूल्य के बराबर नहीं रखा जाता है। प्रादिष्ट प्रमाणिक मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रादिष्ट मान के पक्ष में तर्क—वर्तमान समय में अधिकांश मुद्रा शास्त्री इस बात से सहमत होते जा रहे हैं कि प्रादिष्ट मुद्रा का प्रयोग अस्थायी तथा सकटवालीन न होकर, स्थायी सरकारी नीति का भाग हो सकता है। प्रादिष्ट मुद्रामान के समर्थक प्रायः वे ही लोग हैं जो धात्विक मुद्रामान की आलोचना करते हैं, इसलिए धातुमान के विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों का प्रयोग प्रादिष्ट मान के पक्ष में किया जाता है। प्रादिष्ट मान के समर्थकों का कहना है कि समाज में मुद्रा की आवश्यकता ऐसी बातों पर निर्भर होती है जैसे व्यापार की मात्रा, उद्योगों की व्यवस्था, यातायात व संचालन के साधनों का विकास, बैंकिंग प्रणाली तथा साख्त व साख्त पत्रों का विकास। इनमें से कोई भी स्वर्ण कोषों की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं है अतः स्वर्ण कोषों पर आधारित मुद्रा प्रणाली अधिक वास्तविकताओं से बहुत दूर हो जाती है। यदि उत्पत्ति के साधनों को काम में लाने के लिए मुद्रा की अधिक पूर्ति की आवश्यकता होती है तो अतिरिक्त मुद्रा की निष्कासी अवश्य की जानी चाहिए, चाहे उपलब्ध स्वर्ण कोषों के आधार पर इस प्रकार का विस्तार करना सम्भव हो अथवा नहीं। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति माग से अधिक है तो उसे अनिवार्य रूप से कम किया जाना चाहिए, चाहे स्वर्ण कोष कितना भी अधिक क्यों न हो। इसलिए प्रादिष्ट मान के समर्थक मौद्रिक प्रबन्ध को धातुमान की स्वयं संचालकता से कहीं अच्छा समझते हैं। प्रादिष्ट मान इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें देश की सरकार को स्वतन्त्रतापूर्वक मुद्रा का प्रबन्ध करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के प्रबन्ध के द्वारा मुद्रा की माग व पूर्ति में अच्छा सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत अच्छे प्रकार की बैंकिंग सुविधायें मिल सकती हैं तथा इस प्रकार का मुद्रामान आर्थिक अव्यवस्था को जन्म देने के स्थान पर आर्थिक विकास में सहायता देता है।

प्रादिष्ट मान के विपक्ष में—इस सम्बन्ध में प्रादिष्ट मान की दो प्रकार की आलोचनाएँ दी जाती रही हैं—(१) यदि सब देशों के द्वारा प्रादिष्ट मान अपना लिया जाये तो विदेशी व्यापार में काफी अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि प्रादिष्ट मुद्रा का सम्बन्ध बहुमूल्य धातुओं से विलुप्त नहीं होता है, इसीलिए वह अन्य देशों की मुद्रा व्यवस्थाओं के साथ सीधा सम्बन्धित नहीं होती है। घरेलू मुद्रा इकाई के मूल्य में और विदेशी मुद्राओं के मूल्यों में कोई निर्दिष्ट सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिए विभिन्न देशों की विदेशी विनिमय दरें किसी भी सीमा तक स्वतन्त्रतापूर्वक बदल सकती हैं। इसका प्रभाव यद्यपि नरद भुगतान वाले वर्तमान सौदों पर नहीं पड़ता है, किन्तु स्थगित भुगतानों वाले दीर्घकालीन सौदों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ii) प्रादिष्ट मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भय निरन्तर बना रहता है। धातु मुद्रामान के विपक्ष में चाहे जो कुछ भी कहा जाय किन्तु उसमें एक गुण अवश्य था कि वह मुद्रा की निकासी की अधिकतम सीमा निश्चित कर देता था जो अत्यधिक निकासी की प्रवृत्ति के लिए एक बहुत बड़ी रूकावट होती थी किन्तु प्रादिष्ट मुद्रामान में इस प्रकार की कोई भी रूकावट नहीं होती है। जब भी सरकार का व्यय उसकी सामान्य आय से बढ़ जाता है तो नई मुद्रा जारी करके इस घाटे को आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिसके कारण देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दृष्टि से प्रादिष्ट मुद्रामान को एक सुरक्षित मुद्रामान नहीं कहा जा सकता है।

पत्र मुद्रा का निर्गमन कौन करे (Who Should Issue Paper Money)

पत्र मुद्रा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि नोटों की निकासी का अधिकार किसको प्राप्त होना चाहिए। यद्यपि धात्विक मुद्रा को जारी करना सरकार का विशेष अधिकार समझा जाता रहा है किन्तु पत्र मुद्रा की निकासी प्रायः बैंको के द्वारा ही की जाती है। पत्र मुद्रा का विकास ही बैंको के द्वारा लिखित प्रामिसरी नोटो (Promissory Notes) के रूप में हुआ था और आरम्भ से ही नोट निकासी का अधिकार विभिन्न बैंको अथवा देश के केन्द्रीय बैंक के पास रहा है। नोट सरकार के द्वारा जारी किये जायें अथवा बैंको के द्वारा, इस सम्बन्ध में मुद्रा अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार नोट जारी करने का एकाधिकार सरकार के पास रहना चाहिए। इसके विपरीत बहुत से मुद्रा अर्थशास्त्री यह अधिकार बैंको को देना चाहते हैं। दोनों विचारधाराओं के पक्ष तथा विपक्ष में काफी कुछ कहा जा सकता है। अनुभव के आधार पर अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि नोट जारी करने का अधिकार चाहे किसी भी संस्था के पास क्यों न हो, उस पर सरकारी नियन्त्रण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन (Note Issue by the Government)—

सरकार को नोट निर्गमन का एकाधिकार देने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(१) अधिक विश्वास—सरकार के द्वारा जारी की गई पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास अधिक होता है। सरकार की साख अन्य किसी भी संस्था की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण सरकारी नोटो को बैंक नोटो की अपेक्षा अधिक स्वीकृति प्राप्त होती है और उसे लोग निःसंकोच स्वीकार कर लेते हैं। बैंको के द्वारा जारी की जाने वाली अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास देर से

बनता है किन्तु सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा को भी लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक की अपेक्षा सरकार में अधिक विश्वास होता है। वास्तव में यह तर्क अधिक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक के द्वारा निर्गमित पत्र मुद्रा में भी जनता का उतना ही विश्वास रहता है जितना कि सरकार द्वारा निर्गमित पत्र मुद्रा में।

(२) मुद्रा प्रणाली का उचित प्रबन्ध—सरकार बैंकों की अपेक्षा पत्र मुद्रा प्रणाली का अधिक अच्छा प्रबन्ध कर सकती है। सरकार ही व्यापार तथा उत्पादन के हितों को भली प्रकार समझ सकती है तथा उनकी मांग के अनुसार नोट जारी करती है, जिनके कारण अत्यधिक निकासी का भय बहुत कम हो जाता है। सरकार अधिक साधन होने के कारण बड़े-बड़े विशेषज्ञ रख सकती है जो विभिन्न प्रकार की मौद्रिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देते हैं। कोई भी व्यक्तिगत बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। सरकार अपनी वैधानिक शक्ति के द्वारा साल की मात्रा पर भी अधिक अच्छा नियन्त्रण कर सकती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि पत्र मुद्रा के निर्गमन तथा नियन्त्रण का कार्य व्यक्तिगत संस्थाओं को नहीं देना चाहिए।

(३) नोट निर्गमन से प्राप्त लाभ का उपयोग सार्वजनिक हित में होता है—नोट निर्गमन के परिणामस्वरूप जारी लाभ प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सार्वजनिक हितों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा तब ही हो सकता है जबकि नोट जारी करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता हो। यदि व्यक्तिगत बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले लाभ को सार्वजनिक हित के लिए धन्य नहीं किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि नोट निर्गमन सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(४) मुद्रा नीति के निर्माण में सरकार का काफी हस्तक्षेप रहता है—देश की मौद्रिक नीति प्रायः सरकार के द्वारा ही निर्मित की जाती है। यदि पत्र मुद्रा की निकासी व्यक्तिगत बैंकों के द्वारा भी की जाती है तब भी मुद्रा नीति का निर्माण सरकार करती है और इन बैंकों को मुद्रा का प्रबन्ध सरकारी आदेशों के अनुसार करना पड़ता है। ऐसी दशा में सरकार यदि स्वयं मुद्रा निर्गमन के कार्य को करे तो यह मुद्रा नीति का नियन्त्रण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकेगी।

(५) सरकार की मौद्रिक नीति राष्ट्र के हित में होती है—नोट जारी करने का काम राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए समाज के हित में यह कार्य सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हितों को अधिक अच्छी प्रकार समझ सकती है और अपनी मौद्रिक नीति को उसके अनुकूल बना सकती है। नोट निर्गमन का कार्य किसी भी ऐसी संस्था पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जो

व्यक्तिगत हितों में मौद्रिक नीति को चलाने का प्रयत्न करे। इस खतरे से बचने के लिए यह आवश्यक है कि नोट जारी करने का काम सरकार स्वयं करे।

सरकार के द्वारा नोट जारी किये जाने के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(१) सरकारी विभागों का व्यापार तथा उद्योगों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है, जिसके कारण सरकार समाज में मुद्रा की माग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार द्वारा निर्गमित नोटों की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं रहती है जो देश के आर्थिक जीवन में भारी असन्तुलन पैदा कर सकती है।

(२) सरकार के द्वारा नोटों की निवासी उचित मौद्रिक नीति से इतना प्रभावित नहीं होती है जितना कि वह राजनैतिक उद्देश्यों तथा सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। जब भी सरकार को अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो मौद्रिक नीति के सिद्धान्तों का उत्सर्जन करके भी मुद्रा का विस्तार किया जाता है जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

(३) सरकारी व्यवस्था प्रकृति से ही धीरे चलने वाली होती है। जिसके कारण सभी विभागों में कार्य सुस्ती के साथ होता है। मुद्रा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में तनिक भी देरी देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि सरकार मौद्रिक प्रबन्ध के लिए उचित संस्था नहीं है।

(४) सरकारी कर्मचारी जो राजनैतिक समस्याओं को सफलता के साथ हल कर लेते हैं, वित्तीय तथा मौद्रिक समस्याओं को सुलभाने में इतने कार्यकुशल नहीं होते हैं। इन लोगों के हाथों में मौद्रिक प्रबन्ध का कार्य देना देश के आर्थिक हित में नहीं है। मौद्रिक प्रबन्ध तथा मौद्रिक समस्याओं को सुलभाने के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो अपनी विशेष शिक्षा तथा अनुभव के द्वारा यह कार्य अधिक कुशलता के साथ कर सकते हैं।

(५) सरकार के द्वारा नोट जारी करने में मुद्रा प्रसार का भय निरन्तर बना रहता है। अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नोट जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी में नोटों की अत्यधिक निकासी करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। अतः सरकार द्वारा नोटों की निकासी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है।

बैंक द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क

(Arguments in Favour of Note Issue by the Bank)—

वर्तमान विचारधारा के अनुसार नोट जारी करने का काम बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि बैंक सरकार की अपेक्षा पत्र मुद्रा का अच्छा प्रबन्ध कर

सकता है। यह विचारधारा काफी प्रभावशाली रही है और इसीलिए अधिकार देना में नोट निर्गमन का कार्य बैंक करते हैं। सरकार के द्वारा नोट निकासी से उत्पन्न होने वाले विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नोट जारी करने का अधिकार बैंक को दिया जाय। बैंक के द्वारा निर्गमन के पक्ष में निम्न-लिखित तर्क दिये जाते हैं—

(१) अधिक लोच (Greater Elasticity)—बैंक के द्वारा नोट जारी करने में मुद्रा प्रणाली अधिक लोचदार रहती है। यदि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बिलों (Commercial Bills) तथा पत्र प्रतिभूतियों की आड़ पर नोट जारी करता है तो वह उन्हें आवश्यकता के अनुसार आसानी से घटा-बटा सकता है। बैंकों का व्यापार तथा उद्योगों से मीधा सम्पर्क रहता है जिसके कारण वे मुद्रा की आवश्यकता का सही अनुमान लगा सकते हैं और उनके अनुसार नोटों की मात्रा को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बैंक के द्वारा नोट निर्गमन होने से मुद्रा की मांग व पूर्ति में अधिक अचछा समन्वय हो सकता है।

(२) बैंक पत्र मुद्रा का अधिक अचछा प्रबन्ध करता है (Better Monetary Management)—सरकार पत्र मुद्रा का इतना अचछा प्रबन्ध नहीं कर सकती है जितना की बैंक के द्वारा किया जा सकता है। बैंक विशेष रूप में मौद्रिक सस्था होने के कारण मौद्रिक नीति तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं का अचछा ज्ञान रखती है और अपने विशेषज्ञों की सलाह से वह उचित मौद्रिक नीति का अनुसरण कर सकती है। सरकार की प्रपेक्षा वह अधिक सतर्क होने के कारण मुद्रा समस्याओं को मुलभूत के लिए तुरत बंदम उठाती है। इन्हीं कारणों से बैंक सरकार की प्रपेक्षा पत्र मुद्रा का अधिक अचछा प्रबन्ध कर सकता है।

(३) बैंक की मौद्रिक नीति का आधार अधिक स्वस्थ होना है (Healthy Basis of the Monetary Policy)—बैंक की मौद्रिक नीति राजनैतिक कारणों से प्रभावित नहीं होती है और उसका आधार स्वस्थ आर्थिक विचारों पर रहता है जिसके कारण बैंक अधिक अचछी मौद्रिक नीति का निर्माण कर सकता है मौद्रिक नीति का निर्माण करते समय बैंक का एकमात्र उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता कायम करना होता है, अन्य उद्देश्य उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। सरकार की मौद्रिक नीति पर राजनैतिक दलों का प्रभाव पड़ सकता है तथा उसका प्रयोग अल्पकालीन एवं अनावश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बैंक के द्वारा नोट निर्गमन किये जाने पर इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता है।

(४) बैंकिंग के नियमों का पालन—बैंकिंग पत्र मुद्रा का निर्गमन करते समय बैंकिंग के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है जबकि सरकार आवश्यकता पड़ने पर इन नियमों का उल्लंघन भी कर सकती है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारें अपने नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने में असमर्थ

रही हैं। आपत्ति काल में सरकार की प्रवृत्ति नोटों की अधिक निकासी करके अपने अतिरिक्त व्यय को करने की होती है जिसके कारण मुद्रा प्रसार का भय बराबर बना रहता है बैंक के द्वारा नोटों की निकासी किये जाने पर यह खतरा बहुत कम हो जाता है क्योंकि बैंक कभी भी बैंकिंग सिद्धान्तों का उल्लंघन करके नोटों का विस्तार करना पसन्द नहीं करता है। अतः बैंक के द्वारा नोटों का निर्गमन होने पर मुद्रा प्रसार का भय काफी कम हो जाता है।

(५) जनता का विश्वास (Public Confidence)—बैंक के द्वारा जारी किये जाने वाले नोटों में भी जनता का विश्वास उतना ही रहता है जितना की सरकार द्वारा निर्गमित नोटों में होता है। जनता के विश्वास की दृष्टि से बैंक नोट सरकारी नोटों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के नहीं होते हैं। यदि नोटों का निर्गमन एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बैंक के द्वारा किया जाता है जो नोटों के पीछे पर्याप्त कोप रखता है, तो इस प्रकार के नोटों में जनता का विश्वास काफी रहता है।

(६) नोट निर्गमन से प्राप्त होने वाला लाभ सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है—सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि सरकार नोटों की निकासी से प्राप्त होने वाले लाभ को सार्वजनिक हित में व्यय करती है किन्तु यह तर्क अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह सम्भव हो सकता है कि नोट जारी करने का काम तो बैंक करे किन्तु उससे प्राप्त होने वाला लाभ सरकार को हस्तांतरित पर दिया जाय। ऐसा करने से पत्र मुद्रा का अच्छा प्रबन्ध भी हो सकता है और नोट निर्गमन से प्राप्त लाभ को जन हित में खर्च किया जा सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नोट जारी करने का अधिकार बैंक को ही दिया जाना चाहिए। सरकार की अपेक्षा बैंक नोट निर्गमन की जिम्मेदारी को अधिक अच्छी प्रकार उठा सकता है। व्यापार, उद्योग तथा करदाताओं के हित में यही है कि सरकार नोट जारी करने के अधिकार को बैंक के पक्ष में छोड़ दे। बैंक के द्वारा नोट निर्गमन होने से ही एक अच्छी मौद्रिक नीति का निर्माण हो सकता है तथा पत्र मुद्रा का अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है एवं समाज को अत्यधिक निकासी के भय से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार एक ऐसी जिम्मेदारी से बच जाती है जिसके लिए वह विशेष योग्यता नहीं रखती है और जो उसकी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं है।

एक अथवा अनेक बैंकों द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन
(Single versus Multiple Note Issue)—

यह निश्चय करने के पश्चात् कि नोटों का निर्गमन बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए, एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि यह कार्य किमी एक बैंक के द्वारा किया जाय अथवा देश के अनेक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार दे दिया जाय।

आरम्भ में अधिकांश देशों में नोटों की निकासी का अधिकार अनेक बैंकों को दिया गया किन्तु यह प्रयोग अधिक सफल न हो सका और धीरे-धीरे अनेक बैंकों के द्वारा नोट निर्गमन की नीति को त्याग कर केवल केन्द्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन की नीति को स्वीकार कर लिया गया। अनेक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार देने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो गये थे। विभिन्न बैंकों के नोट जारी करने से पत्र मुद्रा में एकरूपता नहीं रहती थी और अलग-अलग प्रकार के बैंक नोट चलन में रहते थे जिसके कारण भ्रष्टानों के लेन-देन में काफी असुविधा होती थी। इसके अतिरिक्त नोट जारी करने वाले बैंकों से आपसी प्रतियोगिता रहती थी कि जतना किस बैंक के नोटों की अधिक माँग करती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता जन-हित के विरुद्ध थी। अनेक बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाने पर मितव्ययिता का अभाव भी रहता था क्योंकि प्रत्येक बैंक अपने नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने लिए पर्याप्त मात्रा में कोष रखता था। इस प्रणाली का एक और दोष यह था कि प्रत्येक बैंक की नोट निकासी के सम्बन्ध में अलग-अलग नीति रहती थी जिसके कारण देश में एक मौद्रिक नीति वा विकास नहीं हो सकता था। इन सब दोषों के कारण ही अनेक बैंकों के द्वारा नोट जारी करने की नीति को त्याग दिया गया और प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार दे दिया गया। एक बैंक के द्वारा नोट निकासी की नीति के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

(१) पत्र मुद्रा में एकरूपता—नोट देश की प्रमुख मुद्रा होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि चलन में रहने वाली समस्त मुद्रा एक ही प्रकार की हो। यह तब ही सम्भव हो सकता है जब की देश में नोटों का निर्गमन केवल एक बैंक के द्वारा किया जाय। यदि अनेक बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाते हैं तो विभिन्न बैंक नोटों की आकृति तथा आकार अलग-अलग होगा जिसके कारण वास्तविक तथा जाली नोटों में भेद करना कठिन हो जाता और जनता को काफी असुविधा होती है। पत्र मुद्रा में एकरूपता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि नोट निर्गमन का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही दिया जाय।

(२) मुद्रा प्रणाली को नियन्त्रित करने की सुविधा—एक बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार देने से सरकार के लिए मुद्रा प्रणाली पर नियन्त्रण करना आसान हो जाता है। विभिन्न बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाने की व्यवस्था में सरकार मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा नीति पर उचित नियन्त्रण नहीं कर सकती है। एक बैंक के द्वारा नोटों की निकासी किये जाने की दशा में मुद्रा प्रणाली पर सरकार वा नियन्त्रण अधिक व्यापक तथा प्रभावशाली होता है।

(३) मुद्रा कोषों का केन्द्रीकरण—एक बैंक के द्वारा नोटों का निर्गमन करने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि समस्त देश वा वास्तविक कोष एक बैंक के

पास इकट्ठा हो जाता है जो इस केन्द्रित कोष का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। इसके अतिरिक्त घात्विक कोष रखने में काफी भित्तिव्ययिता भी होती है यदि विभिन्न बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाते हैं तो उनमें से प्रत्येक बैंक अपना अलग कोष रखता है जिससे बहुमूल्य धातुओं का अपव्यय होता है। केन्द्रीय बैंक के द्वारा नोट जारी करने पर केवल एक ही कोष रखा जाता है जो काफी भित्तिव्ययितापूर्ण होता है।

(४) पत्र मुद्रा में अधिक विश्वास—केन्द्रीय बैंक के द्वारा नोट जारी किये जाने पर इस पत्र मुद्रा का प्रथक अस्तित्व हो जाता है। केन्द्रीय बैंक एक प्रतिष्ठित संस्था होने के कारण उसके नोटों में जनता का विश्वास अधिक रहता है। केन्द्रीय बैंक की यह प्रतिष्ठा संकट काल में पत्र मुद्रा की रक्षा करती है।

(५) आर्थिक स्थिरता—केन्द्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन किये जाने की दशा में मुद्रा की मांग व पूर्ति में अधिक अन्ध्रा सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है जिससे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अनेक बैंकों के द्वारा नोट जारी किये जाने पर मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रित करना काफी कठिन हो जाता है और उसे मुद्रा की मांग के बराबर करना सम्भव नहीं होता है। व्यक्तिगत बैंक अपने लाभ के उद्देश्य से नोटों का निर्गमन करते थे और प्रायः आवश्यकता से अधिक नोट जारी कर देते थे, किन्तु केन्द्रीय बैंक मुनाफा बनाने वाली संस्था न होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता है और उसकी मुद्रा नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता कायम करना होता है।

उपयुक्त विद्वेषण के आधार पर यह कह जा सकता है कि नोट निर्गमन का कार्य एक बैंक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त संस्था केन्द्रीय बैंक है क्योंकि उसे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का ज्ञान होता है तथा वह लाभ के उद्देश्य से चलने वाली संस्था नहीं होती है। सत्तर के अधिकांश देशों में यह कार्य केन्द्रीय बैंक ही कर रहा है और अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अन्य किसी भी संस्था की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक नोट निर्गमन के कार्य को अधिक अच्छी प्रकार कर सकता है।

नोट निर्गमन के सिद्धान्त (Principles of Note Issue)

इंग्लैंड में नोटों की निकासी के सम्बन्ध में दो विपरीत विचारधाराएँ रही हैं। इन विचारधाराओं के मानने वालों ने नोट निर्गमन के दो अलग-अलग सिद्धान्त चलाये हैं। दोनों ही के समर्थक अपने-अपने सिद्धान्तों को पत्र मुद्रा जारी करने का उचित आधार मानते हैं। यह सिद्धान्त इस प्रकार है—

(१) चलन सिद्धान्त (Currency Principle)

(२) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle)

(१) चलन सिद्धान्त (Currency Principle)—

इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार पत्र मुद्रा इसलिए चलाई जाती है क्योंकि वह सोने के सिक्कों की अपेक्षा सस्ती होती है। बाणजी नोट बहुमूल्य मिनकों के सस्ते स्थानापन्न (Substitute) का कार्य करते हैं। बहुमूल्य धातुओं को चलन में न रखकर उन्हें कोषों के रूप में रखा जाता है और उनके स्थान पर पत्र मुद्रा का प्रयोग होता है। बाणजी नोट कोष में रखी हुई मुद्रा का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए उन्हें सोने में पूर्णतया परिवर्तनशील रखना चाहिए। इस परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए मुद्रा निपट्रक को नोटों के पीछे १००% सोना अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। ऐसा करने से ही पत्र मुद्रा प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार पत्र मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोष की मात्रा के द्वारा नियन्त्रित की जानी चाहिए। नोट चलाने वाली सत्ता के पास जितना सोना हो उसे उतनी ही मात्रा में नोट चलाने चाहिए। देश के अन्दर सोने की मात्रा के घटने-बढ़ने पर नोटों की मात्रा भी उसी अनुपात में घटती-बढ़ती रहनी चाहिए। देश में सोना बाहर से आने पर अथवा देश से बाहर सोना जाने पर पत्र मुद्रा की मात्रा में अपने आप परिवर्तन होने रहने चाहिए। इस प्रकार नोटों की मात्रा सरकार की इच्छा पर निर्भर न होकर स्वर्ण-कोषों की मात्रा के ऊपर आधारित हो जाती है। इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली एक प्रकार से स्वयं संचालित हो जाती है। देश में बाहर से सोना आने पर स्वर्ण कोष बढ़ जाता है और पत्र मुद्रा का विस्तार होता है। देश से सोना बाहर जाने पर स्वर्ण कोष कम हो जाता है और मुद्रा सकुचन होता है। यह सिद्धान्त केवल प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जारी किये जाने के पक्ष में है जिसके कारण देश में मुद्रा प्रसार का भय बहुत कम हो जाता है।

चलन सिद्धान्त के गुण (Merits of Currency Principle)—

(१) सुरक्षा—इस सिद्धान्त के आधार पर नोट जारी करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मुद्रा प्रणाली विलुप्त सुरक्षित हो जाती है। क्योंकि नोटों की मात्रा स्वर्ण कोष पर आधारित होती है इसलिए अत्यधिक निकासी का भय विलुप्त नहीं रहता है। समस्त पत्र मुद्रा के पीछे १००% सोने की आड़ रखनी पड़ती है जिसके कारण सरकार के लिए अधिक पत्र मुद्रा जारी करना सम्भव नहीं होता है।

(२) जनता का विश्वास—इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास बहुत अधिक होता है क्योंकि नोटों को कभी भी सोने में बदला जा सकता है। नोटों के पीछे उत प्रतिशत स्वर्ण कोष रखा जाता है इसलिए समस्त पत्र मुद्रा पूर्णतया सोने में परिवर्तनीय रहती है।

चलन सिद्धान्त के दोष (Demerits of the Currency Principle)—

उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी चलन सिद्धान्त में कुछ दोष पाये जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) साख के प्रयोग की उपेक्षा—इस सिद्धान्त ने साख का अर्थ भली प्रकार नहीं समझाया है। धातु मुद्रा के स्थान पर साख का प्रयोग बड़ी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है किन्तु यह सिद्धान्त साख के प्रयोग को कोई महत्व नहीं देता है।

(२) मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव—इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव रहता है। मुद्रा की मात्रा के स्वर्ण कोष के साथ सम्बन्धित होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को घटाना-बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली सबट काल में प्रायः टूट जाने की प्रवृत्ति रखती है। यह सिद्धान्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मुद्रा प्रणाली के लोच के गुण को त्याग देता है।

(३) मितव्ययिता का अभाव—इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में सोने और चांदी का बहुत अपव्यय होता है क्योंकि समस्त पत्र मुद्रा के पीछे दात प्रतिशत धात्विक कोष रखना अनिवार्य होता है। मितव्ययिता की दृष्टि से चलन सिद्धान्त को एक अच्छा मुद्रा सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता है।

(२) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle)—

यह सिद्धान्त चलन सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। इस सिद्धान्त के मानने वालों के अनुसार पत्र मुद्रा बैंकों के द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रकार की साख है। यह सिद्धान्त मुद्रा प्रणाली के लोचदार होने पर अधिक जोर देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार पत्र मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोष के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए और नोटों की पूर्ति उनकी मांग के अनुसार घटती-बढ़ती रहनी चाहिए। बैंकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे आवश्यकता के अनुसार जितनी मात्रा में चाहे पत्र मुद्रा जारी कर सकें किन्तु यह मुद्रा मांग किये जाने पर धातु मुद्रा में परिवर्तनीय होनी चाहिए। बैंकिंग सिद्धान्त के अनुसार नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए उनके पीछे पूरे मूल्य का धात्विक कोष रखना अनिवार्य नहीं है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब नोट एक साथ परिवर्तनशीलता के लिए नहीं आते हैं इसलिए नोटों के पीछे केवल अनुपातिक कोष रखकर ही काम चलाया जा सकता है। जारी किये गये नोटों का बहुत कम प्रतिशत ही धात्विक सिक्कों में बदलने के लिए आता है, इसलिए यदि उचित मात्रा में सोना रखा जाय तो नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखा जा सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रचलित नोटों की कीमत का केवल एक भाग ही सोने अथवा

चाँदी के रूप में रखना जाना चाहिए। पत्र मुद्रा के पीछे १००% धात्विक कोष रखना आवश्यक नहीं है। मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण बनाये रखने के लिए मुद्रा अधिकारी को नोटों की मात्रा को घटाने-बढ़ाने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वर्तमान समय में अधिकांश देशों के द्वारा बैंकिंग सिद्धान्त के आधार पर ही पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। चलन सिद्धान्त वर्तमान स्थिति में प्रव्यवहारिक प्रतीत होता है।

बैंकिंग सिद्धान्त के गुण (Merits of the Banking Principle)—

(१) अधिक लोच—इस सिद्धान्त पर आधारित पत्र मुद्रा प्रणाली अधिक लोचदार होती है। मुद्रा की मात्रा धात्विक कोष की मात्रा पर निर्भर नहीं रहती है इसलिए उसे आसानी से घटाया-बढ़ाया जा सकता है। मुद्रा अधिकारी के लिए औद्योगिक एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करना सम्भव होता है। इसीलिए यह सिद्धान्त वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल है।

(२) सोने व चाँदी की वृद्धि—इस प्रकार की पत्र मुद्रा प्रणाली अधिक मितव्ययितापूर्ण होती है क्योंकि बैंकिंग सिद्धान्त के अनुसार पत्र मुद्रा के पीछे अधिक मात्रा से सोना या चाँदी सुरक्षित कोष के रूप में रखना आवश्यक नहीं है। केवल अनुपातिक कोष रख कर ही काम चल जाता है जिसके कारण बहुमूल्य धातुओं की वृद्धि वृद्ध होती है।

बैंकिंग सिद्धान्त के दोष (Demerits of the Banking Principle)—

बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित पत्र मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—

(१) सुरक्षा का अभाव—इस सिद्धान्त के अनुसार नोट जारी करने से मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा का अभाव रहता है। नोटों की मात्रा सुरक्षित कोष से नियन्त्रित न होने के कारण किसी भी समय नोटों की अत्यधिक निकासी (Over issue) की जा सकती है जिससे देश में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है।

(२) जनता के विश्वास की कमी—पत्र मुद्रा के पीछे शून्य प्रतिशत धात्विक कोष न रहने के कारण इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास कम रहता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा प्रसार का भय भी मुद्रा में जनता के विश्वास को कम करता है।

दोनों सिद्धान्तों में कौन अच्छा है ?—

उपरोक्त दोनों सिद्धान्त हमारे सामने दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। एक मुद्रा प्रणाली की सुरक्षा पर जोर देता है तो दूसरा उसके लोचदार होने को

अधिक आवश्यक समझता है। दोनों ही विचारधारओं में कुछ गुण तथा दोष पाये जाते हैं। यह कहना कठिन है कि दोनों में से कौनसा सिद्धान्त अधिक उपयुक्त है। दोनों ही मुद्रा प्रणाली के दो महत्वपूर्ण गुणों पर प्रकाश डालते हैं। किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि चलन सिद्धान्त की अपेक्षा बैकिंग सिद्धान्त अधिक प्रगतिशील तथा व्यवहारिक है और इसलिए उसे आजकल अधिक मान्यता प्रदान की जाती है। चलन सिद्धान्त के आधार पर नोट जारी करना सिद्धान्तिक दृष्टि से ठीक हो सकता है किन्तु इसमें व्यवहारिकता का गुण नहीं पाया जाता है। कोई भी देश आजकल अपने नोटों के पीछे १००% सुरक्षित निधि नहीं रख सकता है। चलन सिद्धान्त के आधार पर नोट जारी करने से मुद्रा प्रणाली में लोच का प्रभाव रहेगा और आवश्यकता के अनुसार मुद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकेगी। आधुनिक युग में स्वर्ण कोपों की कमी के कारण चलन सिद्धान्त के अनुसार पत्र मुद्रा जारी करना सम्भव नहीं है। इसीलिए अधिकांश देशों ने अपनी मुद्रा प्रणाली का निर्माण बैकिंग सिद्धान्त के आधार पर किया हुआ है। यद्यपि पत्र मुद्रा प्रणाली का लोचवार होना अनिवार्य है किन्तु उसका सुरक्षित होना भी आवश्यक है जिससे कि मुद्रा के मूल्य में होने वाले अनावश्यक परिवर्तनों को रोका जा सके और मौद्रिक स्थिरता प्राप्त की जा सके। एक अच्छी मुद्रा प्रणाली वही है जिसमें सुरक्षा व लोच दोनों ही गुण पाये जाते हों। समुचित नियन्त्रण के द्वारा बैकिंग सिद्धान्त पर आधारित पत्र मुद्रा प्रणाली में यह दोनों गुण प्राप्त किये जा सकते हैं। इसीलिए अधिकांश देशों में पत्र मुद्रा जारी करने का आधार बैकिंग सिद्धान्त को ही बनाया गया है।

नोट निर्गमन की विधियाँ

(Methods of Note Issue)

नोट निर्गमन को नियमित करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्धतियाँ इस प्रकार हैं—

- (१) निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली (Fixed Fiduciary System)
- (२) अधिकतम विश्वासाश्रित प्रणाली (Maximum Fiduciary System)
- (३) अनुपातिक निधि प्रणाली (Proportional Reserve System)
- (४) आंशिक अनुपात प्रणाली (Percentage Reserve System)
- (५) साधारण निधि प्रणाली (Simple Deposit System)
- (६) न्यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Reserve System)
- (७) कोषागार विपत्र निधि प्रणाली (Bonds Deposit System)

(१) निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली (Fixed Fiduciary System)—

इस प्रणाली में जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा का एक निश्चित भाग विश्वासाश्रित (Fiduciary) होता है जिसके पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप

नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जारी की जाने वाली समस्त पत्र मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत (१००%) स्वर्ण कोष रखा जाता है। केन्द्रीय बैंक को एक निश्चित सीमा तक बिना किसी धात्विक कोष के रखे हुए पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। नोट निर्गमन के इस-भाग को विश्वासाश्रित निर्गमन (Fiduciary Issue) कहा जाता है और इन नोटों के पीछे केवल सरकारी प्रतिभूतियाँ (Securities) रखी जाती हैं। इस मात्रा से अधिक जितने भी नोट जारी किये जाते हैं उनके पीछे मुद्रा अधिकारी को १००% मूल्य का स्वर्ण कोष रखना होता है। आवश्यकता पड़ने पर विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा को सरकार की आज्ञा से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष की व्यवस्था करना है।

सबसे पहले इस प्रणाली का प्रारम्भ इंग्लैंड में सन् १८८४ के बैंक चार्टर एक्ट के अधीन किया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड को १.४ करोड़ पाँड के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर जारी करने का आदेश दे दिया गया। इस मात्रा से अधिक जारी किये जाने वाले नोटों के पीछे बैंक को उनके मूल्य के बराबर सोना सुरक्षित निधि के रूप में रखना होता था। विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा को दो साल के लिए ट्रेजरी (Treasury) की अनुमति से बढ़ाया जा सकता था किन्तु दो साल से अधिक के लिए समद (Parliament) की आज्ञा लेनी आवश्यक थी। इंग्लैंड में विश्वासाश्रित निर्गमन की यह सीमा देश की आवश्यकता के अनुसार बदलती रही है। सन् १९२८ में इसे बढ़ा कर २६ करोड़ पाँड कर दिया गया और १९३६ में यह सीमा ३० करोड़ पाँड थी। सन् १९४२ में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा ६५ करोड़ पाँड कर दी गई किन्तु युद्ध के पश्चात् १९५० में उसे घटा कर केवल १३ करोड़ पाँड रखा गया। इंग्लैंड के अतिरिक्त नार्वे और जापान में भी इस पद्धति का प्रयोग किया गया है। सन् १८६१ से लेकर १९२० तक भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर भारतीय सरकार २० करोड़ रुपये के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर चला सकती थी।

गुण (Merits)—(१) नोटों की परिवर्तनशीलता—इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ पत्र मुद्रा को सोने में परिवर्तनशील बनाये रखना है। यद्यपि कुछ नोटों के पीछे धात्विक कोष विल्कुल नहीं होता है किन्तु फिर भी उन्हें माग करने पर सोने में बदला जा सकता है। अधिकांश नोटों के पीछे शनप्रतिशत स्वर्ण कोष रहता है जिसके कारण समस्त मुद्रा सोने में परिवर्तनीय हो जाती है। नोटों के सोने में परिवर्तनीय होने के कारण मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा का गुण उत्पन्न हो जाता है।

(२) अत्यधिक निकासी पर नियन्त्रण—इस प्रणाली में पत्र मुद्रा को बहुत अधिक मात्रा में जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक

को जारी किये जाने वाले अधिकांश नोटों के पीछे शतप्रतिशत स्वर्ण कोप रखना पड़ता है। इस प्रकार अत्यधिक निकासी का भय लगभग समाप्त हो जाता है।

(३) जनता का विश्वास—इस प्रणाली के अधोधार पर जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बहुत अधिक होता है। समस्त पत्र मुद्रा सोने में परिवर्तनीय होती है जिसके कारण लोग उसे स्वर्ण मुद्रा की भाँति ही अचूक समझते हैं।

होष (Demerits)—(१) लोच का अभाव—नोटों की मात्रा को स्वर्ण कोपों के साथ सम्बन्धित कर दिये जाने के कारण मुद्रा प्रणाली बेलोचदार हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त मात्रा में नई मुद्रा जारी करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए नोटों के पीछे शतप्रतिशत स्वर्ण कोप रखना अनिवार्य होता है।

(२) सोने व चाँदी का अभाव—इस प्रणाली में सोने व चाँदी को बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा कोप के रूप में बन्द करके रखना होता है जिसका कोई अन्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा कम रखी जाती है तो सोने का बहुत अधिक अवन्यय होता है। अतः यह प्रणाली केवल उन देशों में ही सफल हो सकती है जिनके पास सोना अधिक मात्रा में हो अथवा जिनकी साख व्यवस्था काफी विकसित हो। इंग्लैंड में इस प्रणाली की सफलता का यही कारण था किन्तु भारत में इन दशाओं के न होने के कारण इसे छोड़ देना पड़ा।

(२) अधिकतम विश्वासाश्रित प्रणाली

(Maximum Fiduciary System)—

इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में नोट निर्गमन की एक अधिकतम सीमा सरकार के द्वारा निश्चित कर दी जाती है। इस निर्धारित सीमा तक नोट बिना किसी धातु कोप के चलाये जा सकते हैं किन्तु इससे अधिक मात्रा में नोट बिल्कुल नहीं जारी किये जा सकते हैं। निश्चित अधिकतम सीमा के भीतर केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाती है और वह नोटों की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटा-बटा सकता है। नोटों की मात्रा और स्वर्ण कोप में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखा जाता है। देश में जारी की जाने वाली समस्त पत्र मुद्रा विश्वासाश्रित होती है और उसके पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप रखना अनिवार्य नहीं होता है। किन्तु निश्चित अधिकतम सीमा से ऊपर नोट नहीं चलाये जा सकते हैं चाहे केन्द्रीय बैंक के पास उसके पीछे रखने के लिए कितना भी सोना क्यों न हो। नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा देश में व्यापार तथा उद्योग की सामान्य आवश्यकताओं से कुछ ऊँची निर्धारित की जाती है। यह अधिकतम सीमा बिल्कुल निश्चित नहीं होती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि व्यापार और उद्योग का विस्तार होने के कारण मुद्रा

की आवश्यकता बढ़ती है तो सरकार उसी के अनुसार विश्वामाश्रित निर्गमन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाती रहती है और इस प्रकार मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाये रखा जाता है। इस प्रकार की नोट निर्गमन प्रणाली फ्रान्स में मन् १९२८ तक चलती रही जिसके पश्चात् वहाँ पर अनुपानिक कोप प्रणाली को अपना लिया गया। इंग्लैंड में भी मैकमिलन समिति (Macmillan Committee) के द्वारा इस प्रणाली के अपनाये जाने की सिफारिश की गई थी।

गुण (Merits)—(१) सुरक्षा—इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें अत्यधिक निकासी का भय बहुत कम हो जाता है। सरकार देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निश्चित करती है और इस अधिकतम सीमा तक ही नोट जारी किये जा सकते हैं। ऐसी दशा में पत्र मुद्रा की अत्यधिक निकासी नहीं हो सकती है और मुद्रा प्रसार का भय लगभग समाप्त हो जाता है।

(२) लोच का गुण—मुद्रा के साथ-साथ इस प्रणाली में लोच का गुण भी पाया जाता है क्योंकि मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोपों के साथ सम्बन्धित नहीं होती है। इस प्रणाली में अधिकतम सीमा के भीतर नोटों की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। इसके अनिश्चित आवश्यकता पड़ने पर सरकार नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा सकती है।

(३) सोने व चाँदी के प्रयोग में बचत—इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली काफी मितव्ययितापूर्ण होती है क्योंकि उसमें बहुमूल्य धातुओं का अपव्यय नहीं होता है। इस पद्धति में सोने को आवश्यक कोपों के रूप में बन्द करके नहीं रखना होता है जिसके कारण सोने व चाँदी के प्रयोग में काफी बचत हो जाती है।

दोष (Demerits)—(१) सरकार द्वारा दुरुपयोग की सम्भावना—यदि सरकार केवल अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा को बार-बार बढ़ाती रहती है तो मुद्रा प्रसार की दशाएँ उत्पन्न हो जानी हैं और मुद्रा प्रणाली की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। अतः आपत्ति काल में सरकार के द्वारा इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली में लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने ऊपर नियन्त्रण रखे।

(२) लोच का अभाव—यदि आवश्यकता पड़ने पर नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा को नहीं बढ़ाया जाना है तो मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव हो जाता है और मुद्रा की मात्रा उद्योग पूँजी में सन्तुलन स्थापित करना सम्भव होता है।

(३) अधिकतम सीमा का ठीक प्रकार निश्चित न किया जाना—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है। प्रायः अधिकतम सीमा को निर्धारित करते समय व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है और उसे मनमाने

ढंग से निश्चित कर लिया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि यह सीमा आवश्यकता की अपेक्षा या तो बहुत ऊँची निश्चित हो जाती है या बहुत नीची रह जाती है।

(३) अनुपातिक निधि प्रणाली (Proportional Reserve System)—

नोट निर्गमन की यह प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित रही है। प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार, 'वर्तमान समय में इसका सबसे अधिक प्रचलन है।'² ससार के सभी बड़े-बड़े देशों के केन्द्रीय बैंकों ने इस प्रणाली को नोट निर्गमन का आधार बनाया हुआ है। सर्वप्रथम इस प्रणाली को सन् १६२८ में अमेरिका, फ्रांस तथा जर्मनी के द्वारा अपनाया गया किन्तु इसके पश्चात् लगभग सभी देशों ने इसे अपना लिया। भारतवर्ष में हिल्टन-यंग कमिशन (Hilton Young Commission) की सिफारिशों के आधार पर अनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया गया था और द्वितीय विश्व-युद्ध के आरम्भ होने तक रिजर्व बैंक इस पद्धति के अनुसार नोट निर्गमन का कार्य करता था।

इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक को जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत धात्विक कोष के रूप में रखना होता है तथा शेष अरक्षित नोटों के पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य प्रकार के ऋण-पत्र रखे जाते हैं। किसी भी समय धात्विक कोष की मात्रा इस निश्चित अनुपात से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। स्वर्ण निधि का अनुपात सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है। धात्विक कोष का अनुपात प्रायः २५ से लेकर ४० प्रतिशत तक होता है। अमेरिका में ४०% स्वर्ण कोष रखकर पत्र मुद्रा जारी करने की प्रथा रही है। बैंक ऑफ फ्रांस के द्वारा पत्र मुद्रा के पीछे ३५% सुरक्षित कोष रखा जाता है तथा रूस में यह अनुपात २५% रहा है। भारतवर्ष में अप्रैल १९३८ तक ४०% सुरक्षित कोष रखकर नोट जारी किये जाते थे।

गुण (Merits)—(१) अत्यधिक लोच—इस प्रणाली में लोच का गुण बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि नोटों की मात्रा को स्वर्ण कोष में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। स्वर्ण कोष में थोड़ी सी वृद्धि होने पर उससे कई गुना मात्रा में पत्र मुद्रा जारी की जा सकती है। उदाहरणार्थ यदि पत्र मुद्रा के पीछे ४०% सुरक्षित निधि रखने का नियम है तो स्वर्ण कोष में १०० रुपये के मूल्य का अधिक सोना आ जाने पर २५० रुपये की नई पत्र मुद्रा जारी की जा सकेगी। इस प्रणाली में पत्र मुद्रा का विस्तार करना बहुत आसान रहता है और आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

(२) परिवर्तनशीलता—इस प्रणाली में पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखा जा सकता है। यदि सरकार धात्विक कोष का अनुपात लोच-समझ कर

निश्चित करती है और उसे पूर्णरूप से बनाये रखा जा सकता है तो ऐसी दशा में समस्त पत्र मुद्रा परिवर्तनशील बनी रहती है।

दोष (Demerits)—इस प्रणाली में अनेक दोष भी पाये जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सब प्रणालियों के दोष इसमें इकट्ठे हो गये हैं। प्रो० केम्स ने अनुपातिक कोष प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार इस प्रणाली का कोई उचित आधार नहीं है। इस प्रणाली में सोने का बहुत अधिक अपव्यय होता है क्योंकि एक बड़ी मात्रा में सोना भौतिक कोष के रूप में बन्द करके रखना होता है जिसका कोई अन्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रणाली के कुछ मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—

(१) सुरक्षा का अभाव—इस प्रणाली में पत्र मुद्रा का विस्तार करने के लिए बहुत कम धात्विक कोष रखना पड़ना है जिसके कारण मुद्रा विस्तार आसानी से किया जा सकता है। सरकार किसी भी समय अधिक धन प्राप्त करने के लिए मुद्रा विस्तार कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार धात्विक कोष के अनुपात को भी कम कर सकती है।

(२) मितव्ययिता का अभाव—मितव्ययिता की दृष्टि से भी यह प्रणाली अच्छी नहीं है क्योंकि एक बड़ी मात्रा में सोना व चाँदी धात्विक कोष के रूप में बन्द करके रखना होता है जिसका अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(३) मुद्रा सङ्कुचन में कठिनाई—इस प्रणाली में लोच अधिक होने के कारण मुद्रा सङ्कुचन के समय में बड़ी कठिनाई होती है। यदि देश में किसी कारण स्वर्ण कोष की मात्रा कम होने लगती है तो बहुत बड़ी मात्रा में पत्र मुद्रा को नष्ट करना पड़ना है। ४०% सुरक्षित कोष रखने की स्थिति में, स्वर्ण कोष में १०० रु० के मूल्य का सोना कम हो जाने पर २५० रु० के नोट चलन में हटाने होंगे।

(४) आंशिक अनुपात प्रणाली (Percentage Reserve System)—

यह प्रणाली अनुपातिक कोष प्रणाली का एक संशोधित रूप है। इस प्रणाली में नोट निर्गमन के एक निश्चित अनुपात में सुरक्षित कोष रखा जाता है किन्तु इस सुरक्षित निधि का कुछ भाग सोने और चाँदी के रूप में रहता है और कुछ विदेशी विनिमय के रूप में रखा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः द्वितीय विश्व-युद्ध काल में किया गया और बहुत से देशों ने सोने व चाँदी के पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण, पत्र मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले अनुपातिक कोष का एक अंश विदेशी विनिमय के रूप में रखना आरम्भ कर दिया। इस प्रणाली में केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह नोटों के पीछे रखे जाने वाले सुरक्षित कोष का एक निश्चित अनुपात विदेशी मुद्राओं, विदेशी प्रतिभूतियों तथा विदेशी बैंकों में जमा रकम के रूप में रख सकता है। भारतवर्ष में इस प्रणाली को द्वितीय विश्व-युद्ध काल में अपनाया गया और रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया—

किं वह नोटों के पीछे रखी जाने वाली ४०% सुरक्षित निधि का ६०% स्टलिंग प्रतिभूतियों के रूप में रख सकता है तथा शेष ४०% धात्विक कोप के रूप में होना चाहिए किन्तु किसी भी समय सुरक्षित कोप में ४० करोड़ रुपये से कम मूल्य का सोना नहीं रहना चाहिए। स्वर्ण कोप का मूल्य निर्धारित करने के लिए सोने की कीमत २१ रु० ३ आने १० पाई प्रति तोला निश्चित की गई।

गुण व दोष (Merits & Demerits)—इस प्रणाली का एक विशेष लाभ यह है कि इसमें सोने व चांदी के प्रयोग में बहुत अधिक बचत हो जाती है और बहुत कम मात्रा में धात्विक कोप रखकर अधिक नोट चलाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में सोच का गुण भी अधिक पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर नोटों की मात्रा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। किन्तु इस प्रणाली में अनुपातिक कोप प्रणाली के सब दोष पाये जाते हैं। यह प्रणाली मुख्यतया उन देशों के लिए उपयुक्त है जिनके पास सोना व चांदी की मात्रा सीमित हो और जो विदेशी मुद्रा के द्वारा अपनी मुद्रा में विश्वास बनाये रखना चाहते हो।

(५) साधारण निधि प्रणाली (Simple Deposit System)—

इस प्रणाली में केन्द्रीय बैंक को जारी की जाने वाली समस्त पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर सोना व चांदी धात्विक कोप के रूप में रखना पड़ता है। सम्पूर्ण पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा होती है और उसके पीछे १००% धात्विक कोप रहता है। समस्त पत्र मुद्रा को धात्विक मुद्रा अथवा सोने व चांदी में बदला जा सकता है।

सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि अत्यधिक निजासी की सम्भावना लगभग समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास अधिक रहता है क्योंकि उसे किसी भी समय सोने या चांदी में बदला जा सकता है। किन्तु इस प्रणाली में सोच का अभाव रहता है और आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा का विस्तार करना सम्भव नहीं होता है। मितव्ययिता की दृष्टि से भी यह प्रणाली अच्छी नहीं है क्योंकि इसे कार्य रूप में लाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण कोपों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रणाली को आधुनिक तथा प्रगतिशील प्रणाली भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें साख मुद्रा के प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(६) न्यूनतम विधि प्रणाली (Minimum Reserve System)—

नोट जारी करने की यह प्रणाली अधिक प्रगतिशील मानी जाती है और वर्तमान समय में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रणाली में नोटों की मात्रा और स्वर्ण कोप की मात्रा में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता है और केवल एक न्यूनतम धात्विक कोप पत्र मुद्रा के पीछे रखा जाता है। धात्विक निधि की न्यूनतम मात्रा सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है और केन्द्रीय बैंक का यह कर्तव्य होता है कि वह कभी भी धात्विक कोप की मात्रा को इस न्यूनतम सीमा से नीचे न गिरने

दे। केन्द्रीय बैंक के लिए इस न्यूनतम मात्रा में स्वर्ण कोप रखना अनिवार्य होता है। नोट जारी करने के सम्बन्ध में बैंक की पूरी स्वतन्त्रता होती है और वह उन्हें आवश्यकता के अनुसार घटा-बढ़ा सकता है। न्यूनतम मात्रा में धात्विक कोप रख कर बैंक कितनी भी मात्रा में नोट जारी कर सकता है। धात्विक निधि को रखने का उद्देश्य नोटों की मात्रा को नियन्त्रित करना नहीं होता है बल्कि कोप में सोना इसलिए रखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर भुगतान समुत्पन्न (Balance of Payment) के घाटे को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सके तथा मुद्रा के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखा जा सके।

इस प्रणाली में लोच का गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और धात्विक कोप में किसी प्रकार की वृद्धि किये बिना ही अधिक पत्र मुद्रा जारी की जा सकती है। केन्द्रीय बैंक के लिए व्यापार तथा उद्योग की मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना आसान होता है। यह प्रणाली पितृव्यविता की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत अधिक सोना कोप में नहीं रखना पड़ता है। यह प्रणाली केवल प्रगतिशील समाज के लिए ही उपयुक्त है और समृद्धि (Prosperity) काल में तो इसे ठीक प्रकार से चलाया जा सकता है किन्तु संकट काल में इसे बनाये रखना कठिन हो जाता है।

भारतवर्ष में आजकल इसी प्रणाली के आधार पर नोट चलाये जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय को मुक्त करने के लिए सरकार ने आसिक्त अनुपातिक निधि प्रणाली को त्याग दिया और उसके स्थान पर न्यूनतम कोप प्रणाली को अपना लिया गया। पत्र मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले सुरक्षित कोप की न्यूनतम सीमा सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर दी गई। सन् १९५७ में रिजर्व बैंक एक्ट में एक संशोधन के द्वारा पत्र मुद्रा कोप की न्यूनतम मात्रा ४१५ करोड़ रुपये निर्दिष्ट की गई किन्तु २५ अक्टूबर १९५७ को इस न्यूनतम सीमा को घटा कर २०० करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें मोना और विदेशी प्रतिभूतियाँ दोनों ही सम्मिलित हैं। इस कोप में ११५ करोड़ रुपये का सोना तथा ८५ करोड़ रुपये की स्टलिंग प्रतिभूतियाँ रहेंगी। रिजर्व बैंक इस न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित कोप रखकर आवश्यकता के अनुसार कितनी भी पत्र मुद्रा जारी कर सकता है।

(७) कोपागार विपत्र निधि प्रणाली (Bonus Deposit System)—

इस प्रणाली में नोटों के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोप नहीं रखा जाता है और केवल सरकारी बॉण्ड्स (Bonds) तथा कोपागार-विपत्रों (Treasury Bills) के आधार पर नई पत्र मुद्रा जारी की जाती है। यह कोपागार-विपत्र सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र होते हैं जो केन्द्रीय बैंक को दे दिये जाते हैं और वह उन्हें प्रतिभूतियाँ मानकर इनके आधार पर पत्र मुद्रा जारी करता है। जब

सरकार नोटों की मात्रा में वृद्धि करना चाहती है तो उसे पहले कोषागार-विपत्रों की मात्रा में वृद्धि करनी होती है और तब केन्द्रीय बैंक इन विपत्रों के आधार पर नई मुद्रा जारी करता है। इस प्रणाली में नोटों की मात्रा सरकारी कोषागार-विपत्रों की मात्रा के ऊपर निर्भर होती है। इस प्रणाली में अत्यधिक निकासी का भय कम हो जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में नोट जारी करने के लिए बैंक को अधिक मात्रा में कोषागार-विपत्रों तथा अन्य प्रकार की संचारी प्रतिभूतियों को खरीदना पड़ता है। यदि बैंक इन्हें बहुत अधिक मात्रा में खरीदता है तो इनका मूल्य बढ़ जाने के कारण इन पर प्राप्त होने वाला व्याज कम हो जाता है और बैंक को नुकसान होता है। इस प्रकार अधिक नोट जारी करना बैंक के लिए लाभपूर्ण नहीं होता है। यद्यपि इस प्रणाली में मुद्रा प्रसार की सम्भावना बहुत कम हो जाती है किन्तु लोच का अभाव होने के कारण विशेष कठिनाई होती है और आवश्यकता के अनुसार नोटों की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। भारतवर्ष में नोट जारी करने की इस पद्धति को सन् १९०२ में अपनाया गया था किन्तु सन् १९०५ में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बहुत अधिक गिर जाने के कारण सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ी। अमेरिका में भी सन् १९१३ में इस प्रणाली को अपनाया गया और कुछ समय तक इन पद्धति के आधार पर नोट जारी किये जाते रहे।

नोट निकासी का सही सिद्धान्त (Right Principle of Note Issue)—

नोट निर्गमन की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन करने के पश्चात् यह जानना आवश्यक है कि इनमें से किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी किये जाने चाहिए? उपर्युक्त सभी प्रणालियों में कुछ लाभ और दोष हैं और उनमें से किसी को भी पूर्णतया उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यदि करेंसी सिद्धान्त (Currency Principle) के अनुसार नोट जारी किये जाते हैं तो मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा रहती है किन्तु लोच के अभाव के कारण मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) के आधार पर नोट जारी करने से मुद्रा प्रणाली लोचदार तो हो जाती है किन्तु उसमें सुरक्षा का अभाव रहता है। एक अच्छी नोट निर्गमन प्रणाली में लोच और सुरक्षा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में पाये जाने चाहिए। समाज की मुद्रा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पत्र मुद्रा प्रणाली का लोचदार होना आवश्यक है। मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए नोटों का परिवर्तनीय होना भी अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त पत्र मुद्रा प्रणाली में मितव्ययिता (Economy) का गुण भी होना चाहिए जिसमें बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत की जा सके और इन्हें अन्य प्रयोगों में लाया जा सके। इस प्रकार एक अच्छी पत्र मुद्रा प्रणाली में लोच (Elasticity), सुरक्षा (Security) और मितव्ययिता (Economy) के गुणों का

होना अनिवार्य है। किसी भी नोट निर्गमन पद्धति की, जो पत्र मुद्रा प्रणाली में इन गुणों को पैदा कर सकती हो, नोट निर्गमन की अच्छी पद्धति कहा जा सकता है। उपर्युक्त पद्धतियों में से कोई भी इन दशाओं को पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं करती है। इन प्रणालियों में मुबार के द्वारा ही एक अच्छी नोट निर्गमन प्रणाली का विकास किया जा सकता है।

एक अच्छी नोट निर्गमन प्रणाली के सम्बन्ध में दो मुख्य प्रश्न पैदा होते हैं—
(१) नोटों की मात्रा में और सुरक्षित कोप की मात्रा में किसी प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए अथवा नहीं? (२) नोटों के पीछे कितनी मात्रा में सुरक्षित कोप रखा जाय? वर्तमान विचारधारा के अनुसार नोट निर्गमन का सुरक्षित कोप की मात्रा के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। एक अच्छी नोट निर्गमन प्रणाली में केन्द्रीय बैंक को नोटों की मात्रा में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। नोटों की मात्रा को स्वर्ण कोप के अनुसार नियन्त्रित न करके, उसे मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार घटाते-बढ़ाते रहना चाहिए। इस प्रकार पत्र मुद्रा को स्वर्ण कोप के प्रतिबन्ध से मुक्त करके मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाये रखा जा सकता है तथा बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत की जा सकती है। अत्यधिक निकानी के भय से बचने के लिए सरकार को नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में नोट जारी नहीं किये जाने चाहिए। यह अधिकतम सीमा व्यापार तथा उद्योग की सामान्य आवश्यकता से कुछ ऊँची निश्चित करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाना सम्भव होना चाहिए। ऐसा करने से मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा का गुण पैदा किया जा सकेगा। जनता का विश्वास मुद्रा में बनाये रखने के लिए पत्र मुद्रा के पीछे एक न्यूनतम मात्रा में स्वर्ण कोप का होना भी अनिवार्य है। सरकार के द्वारा स्वर्ण कोप की न्यूनतम मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए और केन्द्रीय बैंक के लिए इस न्यूनतम मात्रा में स्वर्ण कोप रखना अनिवार्य होता चाहिए। किसी भी समय स्वर्ण कोप की मात्रा न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इस न्यूनतम कोप के द्वारा मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखा जा सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर नोटों का प्रयोग विदेशी मुद्राओं की निबटाने के लिए भी किया जा सकेगा।

अच्छी मुद्रा प्रणाली के गुण

(Essentials of a Good Monetary System)—

विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों का अध्ययन करने के पश्चात् यह प्रश्न पैदा होता है कि इनमें से कौन सा मुद्रामान अपनाया जाय? प्रत्येक देश को ऐसा मुद्रामान अपनाना चाहिए जिसमें अच्छे मुद्रामान के सभी गुण पाये जाते हों। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अच्छे मुद्रामान में निम्नलिखित गुण पाये जाने चाहिए—

(१) आन्तरिक स्थिरता (Internal Stability)—मुद्रामान ऐसा होना चाहिए जो मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित कर सके। मूल्य-स्तर में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं होने चाहिए जिससे मुद्रा के मूल्य को वस्तुओं और सेवाओं के सम्बन्ध में स्थिर रखता जा सके। एक अच्छा मुद्रामान देश में मूल्य-स्तर की स्थिरता स्थापित करके, उत्पत्ति, उपभोग तथा विनिमय सम्बन्धी क्रियाओं को सरलतापूर्वक चलाने में सहायता देता है। आन्तरिक स्थिरता के दृष्टिकोण से स्वर्णमान को अच्छा मुद्रामान कहा जा सकता है किन्तु उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा पत्र मुद्रामान में भी इस गुण को पैदा किया जा सकता है।

(२) विदेशी विनिमय की स्थिरता (Foreign Exchange Stability)—मुद्रामान ऐसा होना चाहिए जो विदेशी विनिमय की स्थिरता बनाये रख सके। मुद्रा के विदेशी मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए। विदेशी विनिमय की स्थिरता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छा मुद्रामान यही होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। पत्र मुद्रामान की अपेक्षा स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दरें अधिक स्थिर रहती थी, इसलिए विदेशी विनिमय की स्थिरता की दृष्टि से स्वर्णमान एक अच्छा मुद्रामान है।

(३) मुद्रा प्रणाली लोचदार होनी चाहिए (Elasticity)—एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण पाया जाता चाहिए। मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सके। लोच के अभाव के कारण समाज में मुद्रा की मात्रा को व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकता के अनुसार घटाना-बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण होना आवश्यक है। स्वर्णमान की अपेक्षा पत्र मुद्रामान में लोच का गुण अधिक पाया जाता है।

(४) मितव्ययिता (Economy)—एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में मितव्ययिता का गुण भी पाया जाना चाहिए। मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुमूल्य धातुओं का दुरुपयोग न होता हो और उनकी अधिक से अधिक बचत की जा सके। आजकल उसी मुद्रा प्रणाली को अच्छा माना जाता है, जिसमें सोने व चाँदी का कम से कम प्रयोग किया जाता हो। मितव्ययिता की दृष्टि से पत्र मुद्रामान स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक अच्छा है।

(५) सरलता (Simplicity)—मुद्रामान इतना साधारण होना चाहिए कि उसे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। उसे समझने के लिए किसी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुद्रा प्रणाली के जटिल होने से उसका प्रबन्ध करने का व्यय बढ़ जाता है तथा इस प्रकार की प्रणाली में जनता का विश्वास भी देर से बनता है। इसीलिए एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में सरलता का

गुण होना आवश्यक है। पत्र मुद्रामान की अपेक्षा स्वर्णमान अधिक मरल है, इसीलिए लोग सामान्यतः उसे अधिक पसन्द करते हैं और उसमें जनता का विश्वास भी अधिक रहता है।

(६) जनता का विश्वास (Public Confidence)—एक अच्छी मुद्रा प्रणाली वही है जो मुद्रा में जनता के विश्वास को बनाये रख सके। यदि जनता का विश्वास मुद्रा में नहीं रहता है, तो वह मुद्रा प्रणाली अधिक समय तक नहीं चल सकेगी। किसी भी मुद्रामान की सफलता के लिए उसमें जनता का विश्वास होना अनिवार्य है। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए मुद्रा प्रणाली अधिक मैक्रातिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें व्यावहारिकता अधिक होनी चाहिए। स्वर्णमान एक अच्छा मुद्रामान है क्योंकि उसमें जनता का विश्वास आसानी से बन जाता है। पत्र मुद्रा को धात्विक मुद्रा में परिवर्तनीय रख कर, पत्र मुद्रामान में भी जनता के विश्वास को बनाये रखा जा सकता है।

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर स्वर्णमान अधिक उपयुक्त मुद्रामान प्रतीत होता है, किन्तु आज स्वर्णमान की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है। उसमें पाये जाने वाले कुछ आधारभूत दोषों के कारण वर्तमान समाज में उसे सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। कुछ एक देशों में पत्र मुद्रा के सफलतापूर्वक चलाये जाने के कारण, प्रबन्धित मुद्रामान को स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाने लगा है। किन्तु अभी भी कुछ लोगों का विचार है कि प्रबन्धित पत्र मुद्रामान में राजनीतिज्ञों तथा मुद्रा अधिकारियों के हाथों में बहुत अधिक शक्ति रहती है जिसका वे दुरुपयोग कर सकते हैं।

भविष्य में बौनमा मुद्रामान मसाल का प्रमुख मुद्रामान रहेगा, इस बात का जवाब देना प्रामाण्य नहीं है। किन्तु एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि पुराने ढंग के स्वर्णमान के फिर से अपताये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। भविष्य में समार के अधिकांश देशों के द्वारा किसी न किसी प्रकार का प्रबन्धित पत्र मुद्रामान ही अपनाया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के द्वारा एक नये मुद्रामान का विकास किया गया है, जिसमें स्वर्णमान के कुछ गुण पाये जाते हैं किन्तु उसके दोषों से बह मुक्त है तथा उसमें लोच व मितव्ययिता भी पाई जाती है। इसी प्रकार का मुद्रामान वर्तमान स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) प्रदग्धित मुद्रामान से आप क्या समझते हैं ? उसके लाभ और दोषों का वर्णन कीजिये । (आगरा बी० ए० १९५६)
- (२) नोट निर्गमन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं ? उनके लाभ तथा दोष बतलाइये । नोट निर्गमन की सही पद्धति क्या होनी चाहिए ? (आगरा बी० ए० १९५६)
- (३) नोट निर्गमन की विभिन्न रीतियाँ बतलाइये । इनमें से आप किसे अच्छी समझते हैं ? कारण बतलाइये । (आगरा बी० ए० १९६० स)
- (४) नोट निर्गमन के करेन्सी सिद्धान्त बनाम बैंकिंग सिद्धान्त पर एक टिप्पणी लिखिये । (आगरा बी० ए० १९५४)
- (५) पत्र मुद्रा के संचालन को नियन्त्रित करने के विभिन्न उपायों (Methods) का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये । इनमें से किसे हमारे देश में अपनाया है और क्यों ? (आगरा बी० काम १९५६ स)
- (६) बहुत से बैंकों द्वारा नोट निर्गमन प्रणाली पर नोट लिखिये । (आगरा बी० काम १९५६)
- (७) नोट निर्गमन के करेन्सी सिद्धान्त एवं बैंकिंग सिद्धान्त में अन्तर समझाइये । (आगरा बी० काम १९५७)
- (८) सरकार द्वारा नोट निर्गमन और बैंक द्वारा नोट निर्गमन के सापेक्षिक लाभों को बतलाइये । (सागर बी० काम १९५६)
- (९) पत्र मुद्रा की अनुपातिक पद्धति स्पष्ट कीजिये । भारत के दृष्टिकोण से इस पद्धति के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए । (नागपुर बी० ए० १९६०)
- (१०) किसी देश में नोटों के निर्गमन पर नियन्त्रण रखने वाले सिद्धान्तों का विवरण दीजिये । भारत की नोट निर्गमन प्रणाली का आलोचनात्मक विवरण दीजिये । (सागर बी० ए० १९५६)
- (११) पत्र मुद्रा के निर्गमन का नियमन करने वाली विभिन्न पद्धतियों के गुण-दोषों की विवेचना कीजिये । भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन की कौनसी प्रणाली अपनाई गई है । (इलाहाबाद बी० ए०)
- (१२) एक अच्छी मुद्रा प्रणाली की विशेषताएँ बतलाइये । भारतीय मुद्रा प्रणाली में ये विशेषताएँ कहाँ तक पाई जाती हैं ? (आगरा बी० काम १९५७)

मुद्रा का मूल्य और उसका निर्धारण

VALUE OF MONEY AND ITS DETERMINATION

मुद्रा के मूल्य का अध्ययन मौद्रिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतः हम बात की खोज करना स्वाभाविक है कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है तथा वह क्यों बदलता है और इन परिवर्तनों का समाज के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन समस्याओं का अध्ययन करने से पूर्व हमें मुद्रा के मूल्य के अर्थ को भली-भाँति समझ लेना चाहिए। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय-शक्ति (Purchasing Power) से होता है। मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त होती हैं, वही उसका मूल्य है। रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार “मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा में होता है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है।”¹ मुद्रा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना जा सकता है। उसे जानने के लिए हमें यह पता लगाना होता है कि उसके बदले में वस्तुओं तथा सेवाओं की कितनी मात्रा प्राप्त होती है। यदि मुद्रा के बदले में अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं तो मुद्रा का मूल्य अधिक होता है और यदि उनके बदले में मिलने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा कम होती है तो मुद्रा का मूल्य भी कम होता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति पर निर्भर होता है। जॉर्ज हॉम (Halm) के अनुसार—“मुद्रा का मूल्य विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर होता है जो मुद्रा की एक इकाई के द्वारा खरीदी

1 “By the value of money . . . we mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money.”

—Robertson, D. H : Money, P. 17.

जा सकती है। अतः वह इन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य पर आधारित होता है।^२

मुद्रा स्वयं कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। उसका महत्व तो उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के कारण होता है। क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार—“मुद्रा स्वयं बेकार हो सकती है, उसका मूल्य केवल इसलिए होता है क्योंकि उसे विनिमय में स्वीकार किया जाता है।”^३ हम मुद्रा की माग इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं कोई उपयोगी वस्तु है बल्कि इसलिए करते हैं कि उसके बदले में हमें उपयोगी वस्तुएँ तथा सेवाएँ मिल सकती हैं। अतः मुद्रा की उपयोगिता मुख्यतः उसके विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किये जाने के कारण होती है। जार्ज हॉम (Halm) ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि मुद्रा का कोई उपयोग मूल्य (value in exchange) नहीं होता है। उनके अनुसार “यदि विनिमय का माध्यम कोई उपभोग अथवा उत्पादन सम्बन्धी वस्तु है तो उसका उपयोग मूल्य (value in exchange) अवश्य होता है किन्तु जब वह मुद्रा का कार्य करती है तो उसका यह गुण समाप्त हो जाता है या उस समय उसका कोई महत्व नहीं रहता है क्योंकि मुद्रा के रूप में वह मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती है।”^४ अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रा स्वयं उपयोगी नहीं होती है, उसका मूल्य उसके बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के कारण होता है। मुद्रा की अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने की शक्ति को उसकी क्रय-शक्ति कहा जाता है और मुद्रा का मूल्य इसी क्रय-शक्ति पर निर्भर होता है। मुद्रा की एक इकाई का मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके बदले में किसी समय विशेष पर प्राप्त की जा सकती है। अतः मुद्रा के मूल्य को उसकी क्रय-शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। मुद्रा की क्रय-शक्ति के घटने-बढ़ने पर उसका मूल्य भी बदल जाता है।

मुद्रा के मूल्य को हम अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की भाँति नहीं नाप सकते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को नापने में हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है क्योंकि मुद्रा के रूप में मूल्य नापने की एक सामान्य इकाई उपलब्ध

2 “The value of money depends on the amount of different goods and services which can be purchased with a unit of money and therefore, on the prices of these goods and services.”

—Halm, George N Economics of Money and Banking, P. 67.

3 “Money in itself may be quite useless its only value arises out of its acceptability in exchange.”

—Crowther, Geoffrey : An Outline of Money, P. 83.

4 “If the medium of exchange is a commodity (a consumer's or producer's good), it does of course have value in use. But it loses this quality or, at least, this quality is not relevant for the time during which it is used as money. For as money it does not directly satisfy human wants.”

—Halm : Monetary Theory, P. 14.

होती है। किन्तु मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए इस प्रकार की कोई सामान्य इकाई हमारे पास नहीं है। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के द्वारा बतलाया जाता है किन्तु मुद्रा के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में नहीं बतला सकते हैं।^५ प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके बदले में प्राप्त होने वाली मुद्रा के बराबर होता है। किसी वस्तु के बदले में जितनी अधिक मुद्रा प्राप्त हो सकती है, वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। किन्तु ऐसी कोई एक वस्तु नहीं है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य को मापा जा सके। इसलिए मुद्रा के मूल्य को हम उसने बदले में प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के द्वारा बतलाते हैं। मुद्रा की क्रय-शक्ति को सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) के द्वारा जाना जा सकता है।^६ मुद्रा के मूल्य को किसी एक वस्तु अथवा सेवा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है बल्कि उसे हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर के द्वारा व्यक्त करते हैं।^७ लार्ड केन्स (Lord Keynes) के अनुसार “मुद्रा की क्रय-शक्ति किसी विदोष स्थिति में वस्तुओं तथा सेवाओं को उस मात्रा पर अधाधित होती है जो मुद्रा की एक इकाई के द्वारा खरीदी जा सकती है इसलिए उसे एक ऐसी सम्पूर्ण वस्तु (composite commodity) के मूल्य के द्वारा मापा जा सकता है जिसमें अनक प्रकार की वस्तुएँ तथा सेवाएँ अपने महत्त्व के अनुपात में सम्मिलित हों।”^८ प्रो० सैलिगमैन (Seligman) ने मुद्रा के मूल्य के विचार को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है और इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर में जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।” मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य-स्तर से विपरीत दिशा में बदलता है। सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि होने पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और उसने कम हो जाने पर बढ़ जाता है। प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) ने मुद्रा की क्रय-शक्ति और मूल्य-स्तर के सम्बन्ध को इस प्रकार व्यक्त किया है—“मुद्रा की क्रय-शक्ति मूल्य-स्तर से विपरीत होती है और इसीलिए मुद्रा की क्रय-शक्ति का अध्ययन तथा मूल्य-स्तर का अध्ययन एक ही बात है।”^९

5 “But a difficulty arises from the fact that we are in the habit, for the sake of convenience, of expressing the value of bread or cloth in terms of money, whereas obviously we cannot express the value of money in terms of itself”
—Robertson, Money, P. 17.

6 “Since the purchasing power of money in a given context depends upon the quantity of goods and services which a unit of money will purchase, it follows that it can be measured by the price of a composite commodity made up of various individual goods and services in proportion corresponding to their importance as objects of expenditure”
—J. M. Keynes, A Treatise on Money, vol. I.

7 “The purchasing power of money is the reciprocal of the level of prices, so that study of the purchasing power of a price is identical with the study of price levels.”

—Irving Fisher, The Purchasing Power of Money, P. 14.

मुद्रा का मूल्य निर्धारण—

मुद्रा के मूल्य निर्धारण का प्रश्न मौद्रिक अर्थशास्त्र का आधारभूत प्रश्न रहा है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य में जल्दी-जल्दी परिवर्तन न हो और वह स्थिर बना रहे। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन सामाजिक अन्याय तथा अन्य प्रकार की आर्थिक बुराइयों को जन्म देते हैं। इसीलिए मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने की समस्या पैदा होती है। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा का मूल्य किन शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है और वह क्यों बदलता है। प्राचीन समय से ही अर्थशास्त्री उन कारणों की खोज में रहे हैं जो मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं और उसमें परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। मुद्रा के मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी कई सिद्धान्त दिये गये हैं किन्तु उनमें सबसे प्राचीन तथा अधिक प्रचलित मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त रहा है। यह सिद्धान्त माग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक विशेष रूप है। यद्यपि आधुनिक समय में परिमाण सिद्धान्त में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं किन्तु आज तक भी वह मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का आधार माना जाता है।

मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भांति माग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। यदि विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाय तो मुद्रा भी एक प्रकार की वस्तु ही है। किसी समय विशेष पर उसकी भी एक निश्चित माग व पूर्ति हुआ करती है और माग व पूर्ति के साम्य के द्वारा ही उसका मूल्य निश्चित होता है। रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार “अनेक आर्थिक वस्तुओं में से मुद्रा भी एक है। उमका मूल्य प्रारम्भिक रूप से ठीक उन्ही दो शक्तियों अर्थात् उसकी माग की दशाओं तथा उमकी उपलब्ध मात्रा के द्वारा निश्चित होता है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करती है।”⁸ मूल्य का सामान्य सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उसकी माग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निश्चित होता है। जिस बिन्दु पर माग और पूर्ति की शक्तियाँ साम्य की दशा में होती हैं वही पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाता है। किसी वस्तु की माग अथवा पूर्ति में परिवर्तन होने पर उमके मूल्य में भी परिवर्तन आते हैं—माग के बढ़ जाने पर उसके मूल्य की बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और पूर्ति के बढ़ने पर घटने की। मूल्य के इस सामान्य सिद्धान्त को मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए हमें किसी पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है, अन्य वस्तुओं के मूल्य की भांति माग और पूर्ति

⁸ “Money is only one of many economic things. Its value therefore is primarily determined by exactly the same two factors as determine the value of any other thing, namely, the conditions of demand for it, and the quantity of it available”

की शक्तियाँ ही उसके मूल्य को निश्चित करती हैं और वह माग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण ही बदलता है। यदि मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी माग बढ़ जाने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है और कम होने पर घट जाता है। इसी प्रकार यदि मुद्रा की माग निश्चित रहे तो उसकी पूर्ति में वृद्धि होने पर उसका मूल्य घट जाता है और कमी होने पर बढ़ जाता है। क्रौथर (Crouther) के अनुसार, "मुद्रा की माग में वृद्धि होने पर, यदि उसकी पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो उसका मूल्य बढ़ जायगा और सामान्य मूल्य-स्तर गिर जायगा। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर, यदि उसकी माग में वृद्धि नहीं होती है, तो उसका मूल्य भी गिर जायगा और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जायगी।"⁹

यद्यपि मुद्रा का मूल्य उसकी माग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है किन्तु मुद्रा की माग व पूर्ति की वृद्धि अपनी विशेषतायें हैं जो उसे अन्य वस्तुओं से पृथक् कर देती है और जिनके कारण मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में हमें इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही उसकी माग व पूर्ति का विश्लेषण करना होता है। मुद्रा के मूल्य-निर्धारण को भली प्रकार समझने के लिए हमें मुद्रा की माग व पूर्ति के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए।

मुद्रा की माग—

मुद्रा की माग अन्य वस्तुओं की माग से बिल्कुल भिन्न होती है, किसी वस्तु की माग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं बैठती है। मुद्रा की माग हम इसलिए नहीं करते हैं कि वह स्वयं कोई उपयोगी वस्तु है बल्कि उसकी माग इसलिए की जाती है कि उसके द्वारा हम अन्य उपयोगी वस्तुओं तथा सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा की उपयोगिता हमारे लिए प्रत्यक्ष न होकर केवल परोक्ष है। मुद्रा का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वह तो केवल विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। मुद्रा की माग एक प्रकार की उत्पादित माग (Derived Demand) है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करने की आवश्यकता के कारण पैदा होती है। मुद्रा की माग तब ही होती है जब हमें उसने द्वारा कुछ विनिमय करना होता है। यतः किसी समय विशेष में मुद्रा की माग समाज में किये जाने वाले विनिमय की मात्रा (Volume of

9 "An increase in the demand for money, unaccompanied by any increase in the supply of money, will lead to an enhancement of its value—that is, to a fall in the general price level. Similarly an increase in the supply of money, without an increase in the demand for it, will lead to a fall in its value—that is, a rise in the general price level"

Exchange) पर निर्भर होती है। यदि अधिक विनिमय किया जाता है तो मुद्रा की माग अधिक होती है और यदि किये जाने वाले विनिमय की मात्रा कम होती है तो मुद्रा की माग कम हो जाती है। विनिमय की मात्रा बाजार में विक्री के लिए आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा के ऊपर निर्भर होती है। मुद्रा के द्वारा विनिमय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा देश के उत्पादन स्तर पर निर्भर रहती है। यदि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो विनिमय की मात्रा अधिक होती है और मुद्रा की माग बढ़ जाती है। उत्पादन की मात्रा कम होने पर विनिमय की मात्रा कम हो जाने के कारण मुद्रा की माग गिर जाती है। किसी निश्चित समय में मुद्रा की माग का अनुमान लगाते समय हमें उन वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो उत्पादकों द्वारा स्वयं प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि वे मुद्रा की माग उत्पन्न नहीं करती हैं। किसी समय विशेष पर मुद्रा की माग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की उस मात्रा पर निर्भर होती है जो बाजार में विक्री के लिए आती है। इस प्रकार मुद्रा की माग उसके द्वारा किये जाने वाले व्यापारिक सौदों की मात्रा (Volume of Trade Transactions) के द्वारा निश्चित होती है। व्यापारिक सौदों की मात्रा के बढ़ जाने पर मुद्रा की माग बढ़ जाती है और उनके कम होने पर घट जाती है।

मुद्रा की माग की उपरोक्त धारणा को, जो इरविंग फिशर (Fisher) के द्वारा दी गई है, मार्शल, पीगू, राबर्टसन, हांडरे आदि अर्थशास्त्रियों ने दोषपूर्ण माना है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की माग विनिमय के माध्यम के लिए नहीं की जाती है बल्कि उसे तरल रूप में रखने के लिए की जाती है। किसी समय-विशेष पर मुद्रा की माग समाज में नकदी की कुल माग के बराबर होती है जो लोगों की तरलता पसंदगी (Liquidity Preference) पर निर्भर रहती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की माग व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं है बल्कि वह इस बात पर निर्भर होती है कि जनता व विभिन्न संस्थायें अपना काम चलाने के लिए कितनी नकद मुद्रा की माग करते हैं। मुद्रा की माग का आधुनिक विचार इस बात पर आधारित है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं करती है बल्कि उसे धन संचय के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लोग मुद्रा की माग केवल व्यापारिक सौदों को निबटाने के लिए अर्थात् मुद्रा को खर्च करने के लिए ही नहीं करते हैं बल्कि वे भविष्य के लिए धन जमा करने के लिए भी उसकी माग करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के आधीन धन की तरल रूप में रखने के लिए लोगो को जो मुद्रा की आवश्यकता होती है वही मुद्रा की माग है।

मुद्रा की पूर्ति—

मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय किसी समय विशेष मुद्रा की उस कुल मात्रा से होता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करने के लिए उपलब्ध होती है।

मुद्रा की वह मात्रा जो चलन में नहीं रहती है और जिसे लोग संचय (Hoard) कर लेते हैं वह मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित नहीं करती है। किसी एक क्षण पर मुद्रा की पूर्ति चलन में रहने वाली कुल मुद्रा की मात्रा के बराबर होती है। चलन में रहने वाली मुद्रा की मात्रा प्रायः तीन प्रकार की मुद्राओं से मिल कर बनती है— (i) धात्विक मुद्रा की मात्रा (ii) पत्र मुद्रा की मात्रा तथा (iii) चेक मुद्रा की वह मात्रा जिसे चेक (Cheque) के द्वारा निकाला जा सकता है। इन तीनों का योग चलन में मुद्रा की कुल मात्रा को निर्दिष्ट करना है। किसी एक क्षण पर मुद्रा की पूर्ति चलन में मुद्रा की कुल मात्रा के बराबर होती है किन्तु किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति को जानने के लिए हम उसका चालन वेग (Velocity of Circulation) को भी सम्मिलित करना होता है। मुद्रा की कुल पूर्ति, चलन में मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के चालन वेग से मिल कर बनती है। उदाहरणार्थ यदि हम एक वर्ष में मुद्रा की कुल पूर्ति को जानना चाहते हैं तो हमें समाज में प्रयोग की जाने वाली समस्त मुद्रा की मात्रा तथा उस काल में मुद्रा के औसत चालन वेग का पता लगाना पड़ेगा और दोनों को गुणा करके इस काल में मुद्रा की कुल पूर्ति को जाना जा सकता है।

मुद्रा का चालन वेग—

मुद्रा इकाई जिस गति के साथ विनिमय के मोक्षों को निवटाने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना है, उस मुद्रा का चालन वेग कहते हैं। यदि एक निश्चित समय में मुद्रा इकाई १५ बार विनिमय का कार्य कराने के लिए हस्तान्तरित की जाती है तो मुद्रा का चालन वेग १५ हो जाता है। किन्तु मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने के लिए हम मुद्रा की प्रत्येक इकाई के चालन वेग को नहीं लेते बल्कि मुद्रा के औसत चालन वेग (Average velocity of circulation of Money) का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बार जब मुद्रा चलती है तो वह उन ही काम कर लेती है जितना कि मुद्रा को एक नई इकाई के द्वारा किया जा सकता है। यदि एक रुपया दिन भर में दस बार विनिमय के मोक्षों को निवटाना है तो वह अकेला रुपया दस रुपये के बराबर काम करता है और मुद्रा की पूर्ति को निकालने समय हम उसे एक रुपया न गिन कर दस रुपये गिनना चाहिए। मिकका व नागज के मोक्षों के चालन वेग के अनिश्चित माख मुद्रा का चालन वेग भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है।

चालन वेग की अधिकता के कारण एक मामूली मूल्य का मित्र भी बहुत अधिक मूल्य के विनिमय के मोक्षों को निवटाने सकता है। राबर्टसन (Robertson) ने अपनी पुस्तक में एक मनोरंजक कहानी के द्वारा मुद्रा के चालन वेग के इस महत्व को स्पष्ट किया है। डब्लो की मुद्रा के अवसर पर बॉब (Bob) और जो (Joe) दो मित्रों ने कुछ व्यापार करके लाभ पैदा करने का निश्चय किया। उन्होंने एक

बीयर (Beer) शराब का पीपा बाजार से खरीदा और उसे लेकर घुड़दौड़ के मैदान की ओर चल पड़े। उनका विचार था कि वे वहाँ पर ६ पैसे प्रति गिलास के हिसाब से बीयर बेचेंगे और जो लाभ होगा उसे आधा-आधा बांट लेंगे। गर्मी बहुत होने के कारण रास्ते में बॉब (Bob) को बहुत प्यास लगी। उसकी जेब में ३ पैसे का एक सिक्का बाकी था। उसने एक गिलास बीयर लेकर पी ली और जो (Joe) को उसके हिस्से के बदले में वह ३ पैसे का सिक्का दे दिया। कुछ आगे चलने पर जो (Joe) को भी प्यास लगी और उसने वही ३ पैसे का सिक्का बॉब (Bob) को देकर एक गिलास बीयर पी ली। कुछ समय बाद फिर बॉब (Bob) को प्यास लगी और उसने वही तीन पैसे देकर एक और गिलास बीयर का पी लिया। इस प्रकार वह ३ पैसे का झकेला सिक्का बार-बार हस्तान्तरित होता रहा और दौड़ के मैदान तक पहुँचते-पहुँचते बीयर का पीपा खाली हो गया और ३ पैसे का सिक्का विनिमय का इतना अधिक कार्य करने के पश्चात् वापिस बॉब (Bob) की जेब में पहुँच गया। इस कहानी के द्वारा राबर्टसन (Robertson) ने यह स्पष्ट किया है कि चलन वेग के कारण ही तीन पैसे के मामूली सिक्के ने इतने अधिक मूल्य के विनिमय के सौदों को निबटा लिया। मुद्रा के चलन वेग का महत्व का इससे अधिक रोजक उदाहरण नहीं हो सकता है।

मुद्रा के चलन वेग को निर्धारित करने वाले तत्व

(Factors Determining the Velocity of Money)—

समाज में मुद्रा का चलन वेग बदलता रहता है। जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। कभी मुद्रा विनिमय के सौदों को निबटाने के लिए तेजी के साथ चलने लगती है और उसका चलन वेग बढ़ जाता है और कभी उसके धीमा चलने के कारण चलन वेग कम हो जाता है। मुद्रा का चलन वेग अधिक होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और चलन वेग कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

(१) समाज में मुद्रा की मात्रा—मुद्रा का चलन वेग स्वयं उसकी मात्रा पर निर्भर होता है। यदि किसी समय समाज में चलने वाली कुल मुद्रा की मात्रा लोगों की आवश्यकता से कम होती है तो प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा से अधिक से अधिक काम लेने का प्रयत्न करता है और मुद्रा को विनिमय के सौदों को निबटाने के लिए जल्दी-जल्दी चलना पड़ता है जिसके कारण उसका चलन वेग बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग मुद्रा का सग्रह भी कम करते हैं और अधिकांश मुद्रा सक्रिय रूप से चलन में रहती है जिसका प्रभाव भी चलन वेग में वृद्धि करने का होता है। इसके विपरीत यदि चलन में मुद्रा की मात्रा लोगों की आवश्यकता से अधिक होती है तो मुद्रा धीरे-धीरे

विनिमय का कार्य करती है और उसका चलन वेग कम हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा के साथ-साथ उसका चलन वेग भी बदलता है।

(२) बैंक तथा अन्य साख्त संस्थाओं का विकास—देश में बैंको तथा अन्य प्रकार की साख्त संस्थाओं के विकास का भी मुद्रा के चलन वेग पर प्रभाव पड़ता है। इन संस्थाओं के अधिक विवर्धित होने पर उधार लेने व देने तथा व्यय करने की सुविधायें बढ़ जाती हैं जिसके कारण मुद्रा का अधिक हस्तान्तरण होता है और मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि हो जाती है। यदि बैंक तथा साख्त संस्थाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तो मुद्रा का चलन वेग कम रहता है।

(३) खर्चता की उपभोग तथा बचत सम्बन्धी आदतें—लोगों की बचत व उपभोग सम्बन्धी आदतें भी मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करती हैं। यदि लोग अधिक खर्च करते हैं और कम बचत करते हैं तो मुद्रा का चलन वेग कम होता है और यदि उनमें बचत करने की आदत अधिक है और बचत कम की जाती है तो मुद्रा के विवर्धन का समय कम हो जाता है और उसका चलन वेग बढ़ जाता है। केम्स (Keynes) के अनुसार उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) अधिक होने की दशा में मुद्रा का चलन वेग अधिक होता है। इसके विपरीत वचन की प्रवृत्ति (Propensity to Save) बढ़ने पर चलन वेग कम हो जाता है।

(४) समाज में भुगतान निबटाने के तरीके—समाज में विभिन्न भुगतान विधि प्रकार निबटाने जाते हैं, इसका भी मुद्रा की चलन गति पर प्रभाव पड़ता है। यदि अधिकांश सौदों का भुगतान जल्दी तथा नकद रूप में किया जाता है तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होता है और यदि सौदों का भुगतान नकद रूप में नहीं होता है अथवा देर से किया जाता है तो मुद्रा का चलन वेग कम रहता है। अधिको को भुगतान कितनी अधिक के पश्चात् किया जाता है, इसका प्रभाव भी मुद्रा के चलन वेग पर पड़ता है। मजदूरी भुगतान की अवधि अितनी लम्बी होगी उतनी ही अधिक नकद मुद्रा मजदूर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये रखेंगे, जिसके कारण मुद्रा का चलन वेग कम हो जायगा। मजदूरी का भुगतान दैनिक अथवा मासिक होने की दशा में मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा।

(५) मुद्रा की एक स्थान से दूसरे स्थान की भेजने की सुविधायें—यदि यातायात व सन्देशवाहक के साधन इतने विवर्धित हैं कि रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में बहुत कम समय लगता है तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होता है क्योंकि वह बहुत कम समय के लिए निश्चिन्त रहती है। इसके अतिरिक्त यातायात व सन्देशवाहन के साधनों के विवर्धित होने से विनिमय का क्षेत्र विस्तृत होता है और वस्तुओं का क्रय-विक्रय अधिक होने के कारण मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है।

(६) देश की आर्थिक उन्नति—देश की आर्थिक उन्नति का भी मुद्रा के चलन वेग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एक उन्नत समाज में आर्थिक क्रियायें तेजी

के साथ चलती है और मुद्रा के द्वारा किये जाने वाले सौदों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण मुद्रा की तेजी के साथ कार्य करना पड़ता है और उसका चलन वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत कम उन्नत समाज में मुद्रा को कम काम करना पड़ता है इसलिए उसका चलन वेग कम होता है।

(७) लोगों की तरलता पसन्दगी (Liquidity Preference)—जब लोगों की तरलता पसन्दगी अधिक होती है तो वे अपने पास अधिक मात्रा में नकद रक्कद रखते हैं जिसके कारण मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है। तरलता पसन्दगी कम होने की दशा में मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है।

(८) प्रायः, वस्तु तथा कीमतों सम्बन्धी मावों अनुमान—भविष्य में कीमतों की प्रवृत्ति वर्तमान व्यापार की दशाओं को प्रभावित करती है जिसके कारण मुद्रा के चलन वेग में भी परिवर्तन होता है। यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की आशा होती है तो वस्तुओं का क्रय-विक्रय अधिक तेजी के साथ होने लगता है जिसके कारण मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। यदि भविष्य के बारे में लोगों के अनुमान निराशापूर्ण होते हैं तो व्यापारिक सौदों की मात्रा घटती है और मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है।

(९) जनता में नकद माल खरीदने की आदत—यदि लोगों में नकदी के बदले में माल खरीदने की आदत होती है तो वे जल्दी-जल्दी भुगतान निबटाते हैं और मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि वस्तुओं को साख के आधार पर खरीदा जाता है तो उनका भुगतान देर से होता है और मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है।

मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होने का ठीक वही प्रभाव पड़ता है जो मुद्रा की मात्रा के बढ़ने का होता है। चलन वेग के बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और कम होने पर घट जाती है। इस प्रकार मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मात्रा तथा चलन वेग दोनों पर आधारित होती है। जबकि अन्य वस्तुओं की पूर्ति को केवल उनकी मात्रा में वृद्धि न करके ही बढ़ाया जा सकता है मुद्रा की पूर्ति उसके चलन वेग में वृद्धि होने के कारण भी बढ़ सकती है। यह मुद्रा की पूर्ति की एक ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य वस्तुओं से भिन्न करती है। मुद्रा के परिमाण को उसके चलन वेग से गुणा कर देने पर हमें मुद्रा की कुल पूर्ति मालूम हो जाती है अर्थात् मुद्रा की कुल पूर्ति = मुद्रा का परिमाण × मुद्रा का चलन वेग (Total supply of Money = Quantity of Money × Velocity of Money) यदि मुद्रा के परिमाण को 'म' (M) में व्यक्त करें और मुद्रा के चलन वेग को 'व' (V) से, तो मुद्रा की पूर्ति 'म व' (MV) के बराबर होती है।

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त—

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त काफी प्राचीन है किन्तु समय-समय पर अर्थ-शास्त्रियों के द्वारा इसमें संशोधन किये जाते रहे हैं जिसके कारण सिद्धान्त का

वर्तमान रूप उसके प्राचीन रूप से भिन्न हो गया है। परिमाण सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि १६ वीं शताब्दी में एक इटैलियन लेखक दवन्जैत्ती (Davanzzatti) के द्वारा यह सिद्धान्त सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् लॉक (Locke) व ह्यूम (Hume) ने इसका विकास किया तथा मिल (Mill) के द्वारा इस सिद्धान्त में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। वर्तमान युग में फिशर (Fisher) और कैमरर (Kemmerer) ने परिमाण सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या की है।

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त माग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक विशेष रूप है। यद्यपि इस सिद्धान्त के समर्थकों ने यह माना है कि मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति उसकी माग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है किन्तु उनका विचार है कि मुद्रा की माग निश्चित रहने के कारण मुद्रा का मूल्य केवल उसकी पूर्ति पर आधारित हो जाता है। मुद्रा की माग एक निश्चित समय में स्थिर रहती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने दे। माग निष्क्रिय रहने के कारण मुद्रा के मूल्य को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करती है और वह केवल मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर रहता है। इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए इस सिद्धान्त को मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कहा जाता है।

यह सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा तथा उसके मूल्य में सम्बन्ध स्थापित करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर होता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के परिमाण के बढ़ जाने पर उसका मूल्य उन्हीं अनुपात में गिर जाता है और कम होने पर उन्हीं अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य में तथा उसके परिमाण में विपरीत एवं अनुपातिक सम्बन्ध है। सिद्धान्त यह भी बतलाना है कि मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य स्तर में सीधा सम्बन्ध है। अन्य बातें समान रहने पर, मुद्रा के परिमाण के बढ़ जाने पर मूल्य-स्तर बढ़ जाता है और कम होने पर घट जाता है। उदाहरणार्थ यदि समाज में १०० ६० प्रचलन में हैं और विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या भी १०० है तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य १ रुपये होगा। किन्तु यदि वस्तुओं की संख्या बढ़ी रहती और प्रचलन में रुपये की मात्रा बढ़ कर २०० ६० हो जाती है तो अब प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ कर २ ६० हो जायगा। इसी प्रकार यदि प्रचलन में रुपये की मात्रा को घटा कर ५० ६० कर दिया जाय तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य गिर कर आठ आने रह जायगा। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य-स्तर में सीधा एवं अनुपातिक सम्बन्ध है।

परिमाण सिद्धान्त हमें बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर यदि बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है तो

मूल्य-स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा के कम होने पर मूल्य-स्तर गिर जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा की मात्रा में और मूल्य-स्तर में केवल सीधा सम्बन्ध ही नहीं है बल्कि यह सम्बन्ध अनुपातिक भी है। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती-घटती है ठीक उसी अनुपात में मूल्य-स्तर भी बढ़ता-घटता है। यदि माग निश्चित रहे और मुद्रा की पूर्ति दुगुनी हो जाय तो मूल्य-स्तर भी दुगुना हो जायगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति के आधा रह जाने पर मूल्य-स्तर आधा हो जाता है और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायगा। जॉन स्टुअर्ट मिल (J. S. Mill) ने सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की है—“अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का मूल्य अपने परिमाण से उलटी दिशा में बदलता है, परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में कम कर देती है और प्रत्येक कमी उसे ठीक उसी अनुपात में बढ़ा देती है।”^९ प्रो० टॉमिंग (Tausig) ने इसी सिद्धान्त को इस प्रकार बतलाया है—“अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाये तो वस्तुओं के मूल्य पहले की अपेक्षा दुगुने हो जायेंगे और मुद्रा का मूल्य आधा, और यदि मुद्रा के परिमाण को आधा कर कर दिया जाये तो वस्तुओं के मूल्य पहले से आधे रह जायेंगे और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायेगा।”^{१०} विवर्धन मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को स्पष्ट करने, हुए लिखते हैं “मुद्रा का मूल्य अथवा उसकी क्रय-शक्ति उसके परिमाण से विपरीत अनुपात में बदलती है। जिससे कि मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी, अन्य बातें समान रहने पर अन्य वस्तुओं के रूप में उसकी क्रय-शक्ति में अनुपातिक वही अथवा वृद्धि करेगी और इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों में भी उतनी ही वृद्धि अथवा कमी होगी।”^{११} राबर्टसन के अनुसार “मुद्रा की माग की दशाएँ निश्चित रहने पर उसका मूल्य उसकी उपलब्ध मात्रा से विपरीत दिशा में बदलता है। दूसरे शब्दों में सामान्य मूल्य-स्तर मुद्रा की उपलब्ध मात्रा के सीधे

9 “The value of money, other things being the same varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent”

—J. S. Mill Political Economy, vol II, 1862, P. 15,

10 “Double the quantity of money and, other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one half. Halve the quantity of money and, other things being equal, prices will be half of what they were before and the value of money double.”

—Tausig.

11. “The value or purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices”

—Knut Wicksell, : Lectures on Political Economy, vol, II, P. 141.

अनुपात में बदलता है।”^{१२} उपर्युक्त विक्षेपण के आधार पर दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—प्रथम, मुद्रा की मात्रा और उसके मूल्य में विपरीत एवं अनुपातिक सम्बन्ध है। द्वितीय, मुद्रा की मात्रा और सामान्य मूल्य-स्तर में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक सम्बन्ध होता है।

परिमाण सिद्धान्त का समीकरण

आरम्भ में ही अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को समझाने के लिए गणित विधि का प्रयोग किया है। मुद्रा के परिमाण तथा मूल्य-स्तर के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए समीकरण का प्रयोग किया गया है। परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में दिये जाने वाले समीकरण में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया जाने वाला समीकरण इस प्रकार था, $P = M/T$ । इस समीकरण में M किसी समय-विशेष पर चलन में मुद्रा की मात्रा को बतलाना है तथा T बाजार में बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं को सूचित करता है और P सामान्य मूल्य-स्तर के लिए प्रयोग किया गया है। प्राचीन अर्थशास्त्री मुद्रा की पूर्ति का अर्थ देश में चलन की कुल मात्रा से लगाते थे और मुद्रा के चलन वेग को उसमें सम्मिलित नहीं करते थे। मुद्रा की मात्रा में भी केवल धात्विक मुद्रा की मात्रा को ही सम्मिलित किया जाता था और साख मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता था।

प्रो० मिल (Mill) तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने सिद्धान्त के उपरोक्त रूप को दोषपूर्ण बतलाया और उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किये। इन लोगों का मत था कि मुद्रा की पूर्ति केवल उसकी मात्रा के द्वारा ही निश्चित नहीं होती है बल्कि उस पर मुद्रा के चलन वेग का भी प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार किसी समय में मुद्रा की पूर्ति उसकी मात्रा तथा चलन वेग को गुणा करके निकाली जा सकती है। मिल (Mill) के द्वारा दिया गया समीकरण निम्नलिखित है—

$$वच = मच \text{ अथवा } PT = MV$$

$$\text{या } क = \frac{\text{मच}}{\text{व}} \text{ अथवा } P = \frac{M \cdot V}{T}$$

इस समीकरण में—

म (M) = मुद्रा की चलन में कुल मात्रा

व (V) = मुद्रा का चलन वेग

व (T) = व्यापारिक सौदों की कुल मात्रा

क (P) = सामान्य मूल्य-स्तर

12 “Given the conditions of demand for money, its value varies inversely as the quantity available or in other words the general level of prices varies directly as the quantity available.”

ऊपर दिये गये समीकरण में च (V) और व (T) को निश्चित मान लिया गया है अर्थात् न तो मुद्रा के चलन वेग में कोई परिवर्तन होता है और न मुद्रा की मात्रा ही बदलती है। ऐसी दशा में सामान्य मूल्य-स्तर मुद्रा के परिमाण पर निर्भर होता है। परिमाण के बढ़ने पर वह बढ़ जाता है और घटने पर कम हो जाता है।

फिशर का समीकरण

अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर ने उपरोक्त समीकरण को दोषपूर्ण बतलाया है क्योंकि इस समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है। उनके अनुसार यह समीकरण एक सन्ध तथा विकसित समाज के लिए अनुपयुक्त है। वर्तमान समाज में विनिमय का कार्य करने के लिए नकद मुद्रा के साथ साख मुद्रा का प्रयोग भी किया जाता है। आर्थिक उन्नति के साथ साख मुद्रा का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है और कुछ एक देशों में तो साख मुद्रा नकद मुद्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसी दशा में मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा और उसके चलन वेग को सम्मिलित करना आवश्यक है। प्रो० फिशर का विचार है की कुल पूर्ति को हम केवल नकद मुद्रा की मात्रा और उसके चलन वेग के द्वारा नहीं जान सकते हैं बल्कि उसमें साख मुद्रा और उसका चलन वेग भी सम्मिलित होना चाहिए। उपरोक्त सिद्धान्त में सशोधन करने के पश्चात् डा० फिशर ने निम्नलिखित समीकरण दिया है—

$$कव = मच + सचा \text{ अथवा } PT = MV + M'V' \text{ अथवा } कव = मच + सचा$$

$$\therefore क = \frac{मच + सचा}{व} \text{ अथवा } = P \frac{MV + M'V'}{T} \text{ अथवा } क = \frac{मच + सचा}{व}$$

इस समीकरण में क (P) = सामान्य मूल्य-स्तर

म (M) = नकद मुद्रा की मात्रा

व (V) = नकद मुद्रा का चलन वेग

स (M') = साख मुद्रा की पूर्ति

चा (V') = साख मुद्रा का चलन वेग

व (T) = व्यापारिक सौदों की मात्रा

प्रो० फिशर के अनुसार अल्पकाल में च, चा (V, V') तथा व (T) स्थिर रहते हैं तथा म (M) और स (M') की मात्रा में एक निश्चित सम्बन्ध होता है जिसके कारण मूल्य-स्तर क (P) केवल नकद मुद्रा की मात्रा म (M) से ही प्रभावित होता है। मुद्रा का चलन वेग च (V) और चा (V') इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि वह लोगों की आदतों तथा उनके व्यापार करने के तरीकों पर निर्भर होता है जिनमें अल्पकाल के कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यापारिक सौदों की मात्रा व (T) इसलिए स्थिर रहती है क्योंकि अल्पकाल में न तो जनसंख्या बदलती है और न उत्पात्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन निश्चित रहता

है। उत्पत्ति के तरीके तथा लोगों की उपभोग सम्बन्धी आदतें भी प्रायः स्थिर रहती हैं। इन कारणों से मुद्रा की माग निश्चित रहती है और उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही मूल्य-स्तर बदलता है। M (M) और S (M') में निश्चित सम्बन्ध इसलिए रहता है क्योंकि बैंकों को साल मुद्रा का निर्माण करने के लिए एक निश्चित मात्रा में नकद मुद्रा उसके पीछे रखनी होनी है। उपरोक्त विश्लेषण के द्वारा प्रो० फिशर ने दो निरर्थक निष्कर्ष निकाले हैं (१) मूल्य-स्तर इसलिए बदलता है क्योंकि मुद्रा की माग बदलती है—जिसे अन्य कारण से नहीं। (२) मूल्य स्तर में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलती है। इस प्रकार प्रो० फिशर ने बतलाया कि सामान्य मूल्य-स्तर K (P) और मुद्रा के परिमाण M (M) में सीधा तथा अनुपातिक सम्बन्ध होता है।

परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाएँ

प्रो० फिशर के परिमाण सिद्धान्त की वर्तमान अप्रसन्नताओं के द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि 'अपनी मान्यताओं के होने हुए, परिमाण सिद्धान्त एक बेकार का मत्स्य है।'¹³ सिद्धान्त की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि अन्य बातें समान रहती हैं किन्तु वास्तव में अन्य बातें समान नहीं रहती हैं। सिद्धान्त की अधिकांश मान्यताएँ अवास्तविक हैं जिनके कारण उनका व्यवहारिक महत्व बहुत कम रह जाता है। परिमाण सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि मुद्रा की माग w (T) निश्चित रहती है और उस पर मूल्य-स्तर w (P) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु वास्तविक जीवन में मुद्रा की माग निश्चित नहीं रहती है और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। देश में उत्पत्ति की मात्रा बदलती रहती है तथा लोगों की उपभोग सम्बन्धी आदतों में भी परिवर्तन होते हैं। उत्पादन रीतियों में वैज्ञानिक सुधार हो सकते हैं तथा बेकार माधनों का प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सब कारणों से मुद्रा की माग में परिवर्तन होते रहते हैं। केवल पूर्ण रोजगार बिन्दु (*Full Employment Point*) पर ही वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है और वह भी केवल थोड़े समय के लिए। इनके अनिश्चित व्यापारिक सौदों की मात्रा w (T), मुद्रा की मात्रा M (M) तथा मूल्य-स्तर K (P) में होने वाले परिवर्तनों से भी प्रभावित होती है और उसे उनसे स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता है। मूल्य-स्तर K (P) के बढ़ने पर व्यापारिक सौदों की मात्रा w (T) बढ़ जाती है और कम होने पर घट जाती है। इसी प्रकार मुद्रा के चलन वेग w (V) और w (V') को न तो निश्चित ही माना जा सकता और न वह M (M) मुद्रा की मात्रा तथा K (P) मूल्य-स्तर

13 "With the qualifications, 'other things remaining the same' it is a useless truism."

से स्वतन्त्र ही होता है मूल्य-स्तर के ऊँचे होने पर अधिक व्यापारिक क्रियाएँ होने के कारण मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है और उसे जल्दी-जल्दी सौदों को निबटाना पड़ता है। इसके दूसरी ओर मुद्रा सङ्कुचन की स्थिति में व्यापारिक क्रियाएँ कम होने के कारण मुद्रा का चलन वेग घट जाता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणों से भी मुद्रा के चलन वेग में परिवर्तन हो सकते हैं।

प्रो० फिशर की यह मान्यता भी गलत है कि नकद मुद्रा M और साख मुद्रा M' की मात्रा में एक निश्चित सम्बन्ध होना है। यद्यपि बैंक साख जारी करने समय उसके पीछे एक निश्चित अनुपात में नकद मुद्रा कोष के रूप में रखते हैं किन्तु वे इस नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन करके नकद रुपये की मात्रा में कोई वृद्धि हुए बिना ही साख की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार नकद रुपये M की मात्रा में और साख मुद्रा M' की मात्रा में कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं रहता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिमाण सिद्धान्त जिन बातों को स्थिर मानता है वे वास्तविक जीवन में स्थिर नहीं रहती हैं।

(२) मुद्रा की मात्रा के बदलने पर मूल्य-स्तर में अनुपातिक परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रो० फिशर के अनुसार मूल्य-स्तर ठीक उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बदलती है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह तो ठीक है कि मुद्रा की मात्रा बदलने पर मूल्य-स्तर बदलता है किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि वह उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा घटती-बढ़ती है। यह हो सकता है कि मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से कम या अधिक अनुपात में हों। इसीलिए यह कहा जाता है कि 'मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यदि एक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है तो वह ठीक है, किन्तु यदि वह हमारे सामने गणित का एक निश्चित सूत्र रखना चाहता है तो उसका महत्त्व समाप्त हो जाता है।' केवल विशेष दशाओं में ही यह सम्भव होता है कि मुद्रा की मात्रा के दुगुना होने पर मूल्य-स्तर भी दुगुना हो जाय और आधा होने पर मूल्य-स्तर आधा रह जाय। यदि देश में बेकार साधन हैं अथवा देश वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा प्रणाली को अपना रहा है तो ऐसी दशा में मुद्रा की मात्रा के बढ़ाये जाने पर मूल्य-स्तर बहुत कम बढ़ेगा या बिल्कुल नहीं, क्योंकि नई मुद्रा का प्रयोग बेकार साधन को काम में लाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा और मूल्य-स्तर में अनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता है।

(३) मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का एकमात्र कारण मुद्रा की मात्रा का बदलना नहीं है। परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मूल्य-स्तर के घटने-बढ़ने का एकमात्र कारण मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि होना है। यह तो ठीक है कि मुद्रा की मात्रा मूल्य-स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है किन्तु वह उसके बदलने का

एकमात्र कारण नहीं है। मूल्य-स्तर अन्य कारणों से भी बदल सकता है। मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालने वाले बहुत से कारण हैं और उनमें से मुद्रा की मात्रा केवल एक है। आय, व्यय, बचत, विनियोग आदि का प्रभाव भी मूल्य-स्तर पर होता है। यदि मूल्य-स्तर केवल मुद्रा की मात्रा पर आधारित होता तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके अवसाद (Depression) को रोकना सम्भव होना चाहिए। किन्तु अनुभव विस्तृत इसके विपरीत रहा है और यह देखा गया है कि अवसाद काल में मूल्य-स्तर मुद्रा की मात्रा में किसी विशेष कमी के न होते हुए भी गिरने लगता है और मुद्रा की मात्रा के बढ़ाने पर भी मूल्य-स्तर में वृद्धि नहीं होती है। वास्तव में यह सिद्धान्त मूल्य-स्तर में होने वाले उन परिवर्तनों को समझाने में असफल है जो व्यापार चक्रों के कारण पैदा होते हैं।

(४) परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा का बढ़ना कारण है और मूल्य-स्तर का बढ़ना उसका परिणाम किन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी मूल्य-स्तर के बढ़ने के कारण भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। ऊँची कीमतें व्यापारिक छानावाद को जन्म देती हैं, जिसके कारण व्यवसायी अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए व्यापार तथा उद्योग का विस्तार करते हैं और नया विनियोग करने के लिए बैंकों में रुपये की माग करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की इस माग को पूरा करने के लिए नई मात्रा का निर्माण करते हैं और इस प्रकार मुद्रा की मात्रा चलन में बढ़ जाती है। ऐसी दशा में मूल्य-स्तर का बढ़ना कारण हो जाता है और मुद्रा की मात्रा का बढ़ना उसका परिणाम। किन्तु शालोचकी का यह तर्क बहुत अधिक ठीक नहीं है क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि पहले मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और उसके पश्चात् मूल्य-स्तर में वृद्धि होती है।

(५) यह सिद्धान्त इस बात को बताने में असमर्थ है कि मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार मूल्य-स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं। सिद्धान्त हमें केवल इतना बतनाता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मूल्य-स्तर बदल जाता है किन्तु यह सब कैसे होता है, इसका उत्तर नहीं देता है। डा० हेयक (Hayek) तथा हाट्ट्रे (Hawtrey) का मत है कि मुद्रा परिमाण के परिवर्तन मूल्य-स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं डालते हैं। उनका प्रभाव सर्वप्रथम ब्याज की दर के ऊपर होता है और फिर ब्याज की दरों में परिवर्तन उत्पादन में पूँजी के विनियोग को प्रभावित करने है और अन्त में उनका प्रभाव मूल्य-स्तर तथा उत्पत्ति की मात्रा पर पड़ता है। परिमाण सिद्धान्त के इसी दोष को बतलाते हुए विह्टेकर (Whittaker) ने कहा है कि “परिमाण सिद्धान्त मूल्य-स्तर की कार्य विधि की व्याख्या के रूप में असमर्थ है किन्तु कारणों की व्याख्या के सम्बन्ध में इसमें भयंकर दोष पाये जाते हैं।”^{१४} श्रीमती जॉन राविनसन (Joan Robinson) के

14 “The quantity theory is admirable as an elucidation of the mechanism involved in the price level, but as an explanation of causation, it has serious shortcomings.”
—Whittaker.

अनुसार यह सिद्धान्त इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि वह मुद्रा सिद्धान्त को व्याज के सिद्धान्त से पृथक् करने का प्रयत्न करता है और मुद्रा की मांग के व्याज की दरो पर होने वाले प्रभावों को नहीं बतलाता है।

(६) प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय-शक्ति को नहीं नापता है और केवल नकद सौदों के औसत मूल्य को बतलाता है। इस सिद्धान्त में जिन व्यापारिक सौदों को लेकर हम मुद्रा के मूल्य को निर्दिष्ट करते हैं उनमें से अधिकांश औद्योगिक, व्यापारिक तथा वित्तीय सौदे होते हैं जबकि मुद्रा की क्रय-शक्ति उपभोग के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के सौदों पर निर्भर होती है। इस प्रकार प्रो० फिशर का समीकरण मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने में बिल्कुल असमर्थ है। वह केवल मुद्रा के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न सौदों के औसत मूल्य को बतलाता है। प्रो० केन्स के अनुसार परिमाण सिद्धान्त केवल नकद सौदों का माप (Cash Transaction Standard) प्रस्तुत करता है।

(७) सिद्धान्त केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाता है। प्रो० केन्स (Keynes) ने परिमाण सिद्धान्त को इसलिए भी दोषपूर्ण बतलाया है क्योंकि वह मूल्य-स्तर में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों के विषय में तो बतलाता है किन्तु यह नहीं बतलाता कि अल्पकाल में मूल्य-स्तर क्यों बदलता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन हमारे आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए उनके विषय में जानना अधिक आवश्यक है। इस दृष्टि में सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व बहुत कम हो जाना क्योंकि वह मूल्य-स्तर के अल्पकालीन परिवर्तनों का कोई विश्लेषण नहीं करता है। प्रो० केन्स के अनुसार दीर्घकालीन अध्ययन का कोई लाभ नहीं है क्योंकि 'दीर्घकाल में तो हम सब मर जायेंगे'। अल्पकाल में मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में जानना अधिक आवश्यक है किन्तु परिमाण सिद्धान्त इस विषय में कुछ नहीं बतलाता है।

(८) इस सिद्धान्त में मुद्रा की पूर्ति पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। यद्यपि यह सिद्धान्त मांग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक विशेष रूप है किन्तु इनमें मुद्रा की मांग को निर्दिष्ट मानकर, उसके मूल्य-स्तर पर होने वाले प्रभावों को सुना दिया गया है और मूल्य-स्तर को केवल मुद्रा के परिमाण पर आधारित कर दिया गया। वास्तव में मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों ही उसके मूल्य को प्रभावित करती हैं और उनमें से किसी एक के आधार पर मुद्रा के मूल्य का विश्लेषण करना उचित नहीं है। मुद्रा की मांग भी मूल्य-स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और किसी भी सम्पूर्ण मौद्रिक सिद्धान्त की मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियों का विश्लेषण करके मुद्रा के मूल्य निर्धारण को समझना चाहिए। प्रो० हेयक (Hayek) के अनुसार परिमाण सिद्धान्त ने बिना किसी उचित कारणों के ही मुद्रा सिद्धान्तों में एक केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है और इस दृष्टिकोण से वह अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा है। उनके विचार में "इस सिद्धान्त का एक गहन

हानिकारक प्रभाव यह है कि उसने मुद्रा के सिद्धान्त को सामान्य आर्थिक सिद्धान्त से अलग कर दिया है।”

(६) व्यापार चक्रों के कारण मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को इस सिद्धान्त के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मूल्य-स्तर के घटने-बढ़ने का एकमात्र कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होना है किन्तु समृद्धि (Prosperity) अथवा अवसाद (Depression) काल में मूल्य-स्तर, मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन हुए बिना ही बदलता है। मूल्य-स्तर में इस प्रकार का परिवर्तन क्यों होता है, इसका जवाब परिमाण सिद्धान्त नहीं देता है। क्रॉउथर (Crowther) ने परिमाण सिद्धान्त के इस दोष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि परिमाण सिद्धान्त व्यापार चक्र के कारणों को बतलाने में असमर्थ है। उनके अनुसार सामान्य लम्बे काल में मुद्रा का परिमाण मूल्य-स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है किन्तु व्यापार चक्र के अन्य काल में वह मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को नियंत्रित कर भी सकता है और नहीं भी।”^{१४}

परिमाण सिद्धान्त का महत्व—

उपरोक्त आलोचनाओं के देखने से पता चलता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त काफी दोषपूर्ण है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त को अवास्तविक तथा अमूल्योपजनक बतलाया है। प्रो० हैयक (Hayek) तो इसे सिद्धान्त मानने में भी इन्कार करते हैं और अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों में इसे कोई महत्व नहीं देते हैं। प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार यह सिद्धान्त काल्पनिक तथा अधूरा है क्योंकि यह केवल मौद्रिक सौदों के औपत मूल्य को ही बतलाता है और मुद्रा की सामान्य क्रय-शक्ति के विषय में हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं देता है। किन्तु इन सब दोषों के होते हुए भी परिमाण सिद्धान्त में सत्य का अंश पाया जाता है और उसे हम बेकार का सिद्धान्त नहीं कह सकते हैं। डा० फिजर का यह सिद्धान्त आजकल पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है किन्तु फिर भी इस सिद्धान्त का महत्व है क्योंकि इसमें सामान्य मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालने वाले सभी कारणों की एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। परिमाण सिद्धान्त आज भी मुद्रा के मूल्य निर्धारण का आधार माना जाता है। यद्यपि यह सिद्धान्त गणित-आत्मक दृष्टि से बहुत अधिक सही नहीं है किन्तु एक प्रवृत्ति के द्योतक के रूप में यह काफी महत्वपूर्ण है।

परिमाण सिद्धान्त इस सत्य को बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर मूल्य-स्तर में वृद्धि होती है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब भी मुद्रा की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ाया गया है तो मूल्य-स्तर में भी वृद्धि हुई है। सन्

१९१४-१८ के युद्ध काल में जर्मनी में कागजी मुद्रा का अत्यधिक प्रसार होने के कारण वस्तुओं के मूल्यो में बहुत अधिक वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व-युद्ध काल में भारतवर्ष तथा अन्य देशों में मूल्य-स्तर के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण कागजी नोटों का अधिक मात्रा में जारी किया जाना था। व्यावहारिक दृष्टि से भी सिद्धान्त काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मुद्रा की अत्यधिक निकासी के भय की ओर संकेत करता है और मौद्रिक अधिकारियों के लिए एक प्रकार के खतरे के निशान का कार्य करता है। परिमाण सिद्धान्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को स्थिर रखने में सहायता देता है और कीमतों को नियन्त्रित रखने का एक अच्छा उपाय बतलाता है। मूल्य-स्तर पर नियन्त्रण करने के लिए इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की मात्रा को घटाकर मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोक़ा जाता है तथा उसे बढ़ाकर मूल्य-स्तर को ऊँचा उठाया जाता है। रॉबर्टसन (Robertson) ने परिमाण सिद्धान्त के महत्व को बतलाते हुए कहा है—“मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य को समझने के लिए एक विचित्र राश्व है। यह एक ऐसा सत्य है जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमत के सम्पर्क को समझने के लिए आवश्यक है।”

सिद्धान्त का वर्तमान रूप—केम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation)—

केम्ब्रिज स्कूल के अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का निर्माण एक नये दृष्टिकोण से किया है। इन लोगों के द्वारा दिये गए सिद्धान्त को ‘नकद जमा परिमाण’ (cash balance type of quantity theory) कहते हैं। इस सिद्धान्त के मुख्य निर्माता मार्शल, पीगू, हॉटेल तथा रॉबर्टसन आदि हैं। केम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation) इंग्लैंड तथा यूरोप में अधिक प्रचलित रहा है, किन्तु अमेरिका में फिशर के सिद्धान्त को अधिक माना जाता है।

मुद्रा की माग के सम्बन्ध में केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का विचार प्रो० फिशर से बिल्कुल भिन्न है। फिशर के अनुसार मुद्रा की माग केवल विनिमय के माध्यम वा कार्य करने के लिए की जाती है। मुद्रा केवल एक रेलवे टिकट के समान है, जिसकी माग उसे इकट्ठा करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि एक निश्चित स्थान तक पहुँचने के लिए की जाती है। इससे दूसरी ओर केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की माग क्रय-शक्ति को सचय करने के साधन के रूप में भी की जाती है। मुद्रा केवल रेल के टिकट की तरह ही प्रयोग नहीं की जाती है, बल्कि लोग उसे नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। इस प्रकार मुद्रा की माग इस बात पर निर्भर होती है कि लोग अपने पास कितना नकद रूपमा रखना चाहते हैं। केम्ब्रिज स्कूल के अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की माग क्रय-विक्रय के लिए आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि वह लोगों की तरलता पसन्दगी (Liquidity Preference) पर निर्भर होती है। इसी विचारधारा

को लेकर कैम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation) का निर्माण किया गया है।

कैम्ब्रिज स्कूल (Cambridge school) के अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्मा एक निश्चित समय पर मुद्रा का मूल्य नकद रूपों की माग तथा पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। मुद्रा की माग विनिमय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर होती है कि कितने लम्बे समय के मौदों को मुद्रा के द्वारा निबटारा जाना है। जितने अधिक लम्बे समय के मौदों को निबटारना होता है, उतनी ही अधिक मात्रा में नकद मुद्रा की माग की जाती है। यदि बहुत छोटे समय के व्यापारिक मौदों को निबटारना है तो नकदी (cash) की माग बहुत कम होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास उतनी नकद मुद्रा रखता है जो एक निश्चित काल में उसकी आवश्यकता की वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए पर्याप्त हो। यदि लोगों में लम्बे समय के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद मुद्रा रखने की आदत है तो मुद्रा की अधिक माग की जायेगी और यदि कम समय की आवश्यकता के लिए नकदी रखी जाती है तो मुद्रा की माग कम होती है। इस प्रकार मुद्रा की माग लोगों के द्वारा की जाने वाली नकदी (cash) की माग पर आधारित होती है। मुद्रा की माग वस्तुओं की उस मात्रा पर निर्भर नहीं होती है जिनको मुद्रा के बदले में बेचा जाना है बल्कि वह लोगों की नकद मुद्रा रखने की इच्छा तथा योग्यता पर निर्भर होती है। किसी निश्चित समय में लोग अपने पास जितनी नकद मुद्रा रखना चाहते हैं, वही मुद्रा की माग है।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग नकद रूप में रखना चाहता है, जिससे वह दुबारा आय प्राप्त होने तक अपने खर्चों को चला सके तथा विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटा सके। रॉबर्टसन के अनुसार—“प्रत्येक व्यक्ति अपने पास कुछ नकद मुद्रा रखना चाहता है, जिससे कि वह अपने दैनिक जीवन के व्यवसायिक कार्यों को सुविधापूर्वक कर सके तथा आकस्मिक आपत्ति काल में उसका सहारा ले सके।”^{१६} इसी प्रकार उत्पादकों तथा व्यापारियों को भी अपने व्यवसाय के चालू खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा रखनी होती है। समाज में सब लोगों की नकदी (cash) की माग मिलकर मुद्रा की कुल माग को बनाती है। किसी समाज में प्राप्त होने वाली कुल आय का केवल कुछ भाग ही नकदी के रूप में रखा जाता है और शेष का विनियोग कर दिया जाता है। आय को नकद रूप में रखने से व्यवसाय में बड़ी सुविधा होती है तथा निजी

16 “It will be readily granted that the ordinary person likes to keep ready to his hand a little pool of money, partly for the sake of convenience in conducting the ordinary business of life and partly as a margin to fall back on in unforeseen contingencies.” —D. H. Robertson : Money, P-34.

खर्चों को आसानी से निबटारा जा सकता है। किन्तु नकद मुद्रा अपने पास रखने से कुछ हानि भी होती है, क्योंकि नकद रूप में रखी हुई मुद्रा से किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। बहुत अधिक मात्रा में नकद मुद्रा अपने पास रखने में व्याज की हानि उठानी पड़ती है और बहुत कम मात्रा में रखने से असुविधा होती है। लोगों के द्वारा माग की जाने वाली नकदी (cash) की मात्रा न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम। यह ठीक आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति नकदी को पास रखने से प्राप्त होने वाले लाभ तथा हानियों की तुलना करने के पश्चात् यह निश्चय करता है कि कुल आय का कितना भाग नकद रूप में रखा जाये।

समाज में नकद मुद्रा की माग आय प्राप्त होने की अवधि, वस्तुओं के मूल्य तथा व्यापार की दशाओं पर निर्भर होती है। आय प्राप्त होने तथा उसके व्यय किये जाने के बीच जितना अधिक सम्पत्ति समय होता है, उतनी ही अधिक मुद्रा की माग की जाती है। इससे विपरीत यदि लोगों को जल्दी-जल्दी आय प्राप्त होती है, तो वे कम नकद मुद्रा की माग करेंगे। वस्तुओं के मूल्य अधिक होने पर नकदी (cash) की माग बढ़ती जाती है, क्योंकि लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा की जरूरत होती है। मूल्य-स्तर नीचा होने पर नकदी की माग घट जाती है। व्यापार की दशाओं का भी नकदी की माग पर प्रभाव पड़ता है। समृद्धि काल (Prosperity phase) में नकद मुद्रा की माग कम हो जाती है, क्योंकि उसका व्यापार में विनियोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समय में लोग अपने पास कम मुद्रा रखते हैं और विनियोग अधिक किया जाता है। मंदी काल (Depression) में लाभपूर्ण विनियोग की सम्भावना कम हो जाने के कारण लोग अपने पास अधिक नकद मुद्रा रखते हैं और मुद्रा की माग बढ़ जाती है। इनके अतिरिक्त जनसंख्या का आकार तथा भुगतान निबटाने के तरीकों का भी मुद्रा की माग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या बढ़ने पर मुद्रा की माग बढ़ती है और कम होने पर घटती है। यदि अधिकांश सौदों का भुगतान नकद रूप में किया जाता है तो नकदी (cash) की माग भी अधिक होती है, किन्तु यदि भुगतानों को निबटाने के लिए साख का अधिक प्रयोग किया जाता है तो नकद मुद्रा की माग कम हो जाती है।

.. किसी निश्चित समय पर जो रकम लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं, वह मुद्रा की माग है। मुद्रा की पूर्ति में अभिप्राय नकदी की पूर्ति (Supply of cash) से है जो सिक्कों की मात्रा, कागज के नोटों तथा बैंकों की जमा से मिलकर बनती है। मुद्रा की पूर्ति सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर आधारित होती है और इसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। किन्तु मुद्रा की माग समय-समय पर बदलती रहती है, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य बदलता

है। केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपने इस सिद्धान्त को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा समझाया है—

$$k = \frac{M}{\text{अ र}} \quad \text{अथवा} \quad P = \frac{M}{KR}$$

क (P) = मूल्य-स्तर (Price level)

म (M) = मुद्रा की मात्रा (Quantity of Money)

र (R) = मभाज की वार्षिक वास्तविक आय (Real Income)

अ (K) = आय का वह अनुपात जो नकद रूप में रखा जाता है

(Percentage of Income kept in the form of cash)

इस समीकरण में अ र (KR) मुद्रा की कुल मात्रा म (M) के मूल्य के बराबर है, इसलिए मुद्रा की प्रत्येक इकाई का मूल्य $\frac{KR}{M}$ अथवा $\frac{\text{अ र}}{म}$ के बराबर होता है और मूल्य-स्तर क (P) के बराबर होना है $\frac{म}{\text{अ र}}$ अथवा $\frac{M}{KR}$ ।

केम्ब्रिज विचारधारा तथा फिशर की विचारधारा का अन्तर—

केम्ब्रिज सिद्धान्त फिशर के सिद्धान्त में कई बातों में अधिक अच्छा है। फिशर के सिद्धान्त में मांग की शक्तियों की निश्चित मान लिया गया है, किन्तु केम्ब्रिज समीकरण मुद्रा की मांग को परिवर्तनशील मानकर चलता है और मुद्रा के मूल्य पर उसके प्रभावों का विश्लेषण करता है। फिशर का सिद्धान्त केवल मुद्रा के दीर्घकालीन मूल्य के विषय में ही बतलाता है, किन्तु केम्ब्रिज समीकरण अल्प काल में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को बताता है और इस दृष्टि से इस सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व अधिक है। फिशर का सिद्धान्त मुद्रा की कुल मात्रा पर आधारित है जो देश में व्यापार के लिए आवश्यक है, किन्तु केम्ब्रिज विचारधारा उस नकदी पर आधारित है जिसकी मांग किसी समय विशेष पर की जाती है।

इन सब गुणों के होते हुए भी केम्ब्रिज समीकरण में सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें साख मुद्रा की मात्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रो० केन्स (Keynes) तथा प्रो० पीगू (Pigou) ने इस समीकरण में कुछ संशोधन किये हैं। प्रो० केन्स (Keynes) ने निम्नलिखित समीकरण प्रस्तुत किया है—

$$n = k (\text{अ} + \text{र मा}) \quad \text{अथवा} \quad n = p (k + r k')$$

न (n) = नकद मुद्रा की कुल मात्रा

क (p) = सामान्य मूल्य-स्तर

अ (k) = उपभोग की वे इकाइयाँ (Consumption units) जिनके लिए चलन के रूप में क्रय-शक्ति को संचित किया जाता है।

या (k') = उपभोग की वे इकाइयाँ जिनके लिए साख मुद्रा में क्रय शक्ति का मन्चय किया जाता है (वैक जमा का वह भाग जिसे बैंक के द्वारा निकाला जा सकता है)।

र (r) = बैंक के नकद कोष तथा जमा रकम का अनुपात।

केन्स (Keynes) के समीकरण का मुख्य गुण यह है कि उसमें साख मुद्रा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और मूल्य-स्तर पर उसके होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

प्रो० पीगू ने परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित समीकरण दिया है—

$$k = \frac{अ र}{म} \{म + ह (१ - स)\} \text{ अथवा } P = \frac{KR}{M} \{c + h (1 - c)\}$$

इस समीकरण में P, K, R तथा M का अर्थ वही है, जो केम्ब्रिज समीकरण में है। स (c) नकदी के उस भाग को बतलाता है, जो जनता विविप्राह्य मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहती है तथा ह (h) बैंकों द्वारा जमा किये हुए निक्षेपों का विविप्राह्य भाग है। इस समीकरण में भी साख मुद्रा के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है।

केम्ब्रिज समीकरण की आलोचनायें

(Criticisms of the Cambridge Equation)—

यद्यपि केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त फिशर (Fisher) के सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक अच्छा है क्योंकि वह बहुत सी उन बातों का जवाब देता है जिनके बारे में फिशर का सिद्धान्त कुछ नहीं बतलाता है किन्तु फिर भी केम्ब्रिज समीकरण को मुद्रा के मूल्य का सन्तोषजनक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है। उसमें घनक दोष पाये जाते हैं जिनके आधार पर इस सिद्धान्त की आलोचना की गई है। कुछ प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं—

(१) इस सिद्धान्त में उन उद्देश्यों का विश्लेषण नहीं किया गया है जिनके कारण लोग मुद्रा को अपने पास जमा कर लेते हैं। विशेषतया केम्ब्रिज सिद्धान्त सट्टे के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रा की माग (Speculative Demand) को भुला देता है जो नकद मुद्रा की माग को निश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। सट्टे के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रा की माग को महत्वपूर्ण स्थान न देने के

कारण यह सिद्धान्त भी मुद्रा सिद्धान्त को व्याज के सिद्धान्त के साथ सम्बन्धित करने में सफल नहीं हो सका है।

(२) यह सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा पर आवश्यकता से अधिक जोर देता है जिससे यह प्रतीत हो न लगता है कि मुद्रा की मात्रा ही समाज में आर्थिक परिवर्तन का एकमात्र अथवा सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार का विचार अन्य प्रकार की फलत धारणाएँ उत्पन्न कर सकता है। विलेपतया अल्पकाल में मूल्यों तथा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में काफी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अपने आधुनिक रूप में भी केवल औसत मूल्य-स्तर के दीर्घकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अल्पकालीन तथा व्यापार-चक्रों के कारण उत्पन्न होने वाले भारी परिवर्तनों के लिए किसी अन्य सिद्धान्त की सोज करना आवश्यक है।^{१७}

(३) यह सिद्धान्त कीमत-स्तर को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देता है जिससे कि यह प्रतीत होने लगता है कि किसी अर्थ-व्यवस्था के लिए कीमतों में होने वाले परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व है। इस मूलतः धारणा के आधार पर सिद्धान्त यह निर्णय प्रस्तुत करता है कि व्यापारिक क्रियाओं के सामान्य स्तर में होने वाले समस्त परिवर्तन कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। हमारे शब्दों में सिद्धान्त हमें हम अवामुखिक परिवर्तन पर ले जाता है कि कीमतों के परिवर्तन व्यापार-चक्रों को जन्म देते हैं। वास्तव में, व्यापार-चक्रों के कारण कीमत स्तर बदलता है।

(४) केम्ब्रिज दृष्टिकोण एक ऐसा उपयुक्त मुद्रा सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं करता है जिसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था में कीमतों के प्रवैगिक व्यवहार को समझा जा सके। अतः यह कहा जा सकता है कि केम्ब्रिज समीकरण भी स्थिर दशाओं का ही विश्लेषण करता है।

(५) यह सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा की लोच को इकाई के बराबर मानता है किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस प्रकार की मान्यता से सहमत नहीं है। आधुनिक विचार के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा के द्वारा, सृष्टी दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अतः मुद्रा की मात्रा-लोच इकाई (Unity) के बराबर केवल स्थिर (Static) दशा में ही हो सकती है, प्रवैगिक (Dynamic) दशा में नहीं।

17 "The Quantity Theory might be relegated to the position of explaining the longer secular movements in the average price level, while some other explanation was sought for the shorter and more violent swings of the trade cycle."

—Cronther, An Outline of Money, p. 123.

वचत और विनियोग सिद्धान्त (Saving and Investment Theory)

ग्रथवा

आय तथा व्यय सिद्धान्त (Income and Expenditure Theory)

इन दोषों के कारण मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का उचित सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य का विश्लेषण समाज में प्राप्त होने वाली आय तथा उसके व्यय के आधार पर किया है। इन लोगों के द्वारा एक नये मुद्रा सिद्धान्त का निर्माण किया गया है जिसे आय सिद्धान्त (Income Theory) या वचत और विनियोग का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के मुख्य निर्माता लार्ड केन्स (Lord Keynes) हैं किन्तु हैपक (Hayak), क्राउथर (Crowther) तथा हेबरलर (Haberler) ने भी इस सिद्धान्त पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। आय सिद्धान्त के महत्व को बतलाते हुए क्राउथर ने लिखा है—“मुद्रा का मूल्य वास्तव में आयों के कुल योग का परिणाम है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। हमें कुल आय में होने वाले परिवर्तनों के कारणों की खोज करनी चाहिए।”^{१८}

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के विभिन्न रूपों से असन्तुष्ट होकर केन्स (Keynes) ने यह विचार प्रस्तुत किया कि कीमतों तथा उत्पादन-स्तर में परिवर्तन आय-स्तर (Level of Income) में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। आय-स्तर में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं जैसे वचत तथा विनियोग के स्तर में परिवर्तन, लाभ की आशा, व्यय, मुद्रा का सग्रह तथा साख व मुद्रा का विस्तार इत्यादि। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी निश्चित काल में मुद्रा का मूल्य समाज में प्राप्त होने वाली द्राव्यिक आय (Money Income) और लोगों के द्वारा उसकी व्यय की जाने वाली मात्रा तथा बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर होता है। मुद्रा का मूल्य आय प्राप्त करने वालों के इस निर्णय पर निर्भर होता है कि वे अपनी आय का कौन सा भाग वस्तुयों खरीदने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यदि वस्तुयों खरीदने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा घट जाती है, किन्तु वस्तुओं की मात्रा यथा स्थिर रहती है तो उपभोग सम्बन्धी तथा पुँजीगत वस्तुओं के मूल्य गिर जायेंगे और मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा। इसी प्रकार यदि वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली आय यथा स्थिर रहती है किन्तु वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है, तो सामान्य मूल्य-स्तर गिरने लगेगा। इसके विपरीत यदि व्यय की जाने वाली आय की मात्रा बढ़ती है और वस्तुओं की मात्रा यथा स्थिर रहती है तो सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ जायगा और मुद्रा का मूल्य गिर जायगा।

18 "The value of money in fact, is a consequence of the total of incomes rather than of the quantity of money. It is the causes of fluctuations in the total incomes of which we must go in search"

—Crowther : An Outline of Money, P. 124.

इस प्रकार मुद्रा का मूल्य व्यय की जाने वाली आय की मात्रा के बदलने पर तथा वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन होने पर बदलता रहता है।

आय का कौन सा भाग वस्तुओं पर व्यय करने के लिए प्रस्तुत किया जायगा, यह लोगों की विनियोग तथा वचत सम्बन्धी आदतों पर निर्भर होता है। यदि लोग अपनी आय का अधिक भाग बचाने का निश्चय करते हैं तो वस्तुओं पर कम व्यय किया जायगा और यदि कम बचाते हैं तो व्यय अधिक होगा। अधिक बचत आय की व्यय की जाने वाली मात्रा को कम करती है, वस्तुओं की मांग गिर जाती है तथा उनका मूल्य कम होने लगता है और मन्दी की दशाएँ पैदा हो जाती हैं। अधिक विनियोग आय की व्यय की जाने वाली मात्रा को बढ़ाता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उनके मूल्य बढ़ने लगते हैं। इस बात को अधिक अच्छी प्रकार समझने के लिए हमें समस्त आर्थिक व्यवस्था को एक प्रकार का प्रवाह-चक्र (circular flow) समझ लेना चाहिए जिसमें मुद्रा बराबर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। जब कोई बचत की जाती है तो मुद्रा इस आय-चक्र (Income stream) में से निकाल ली जाती है और विनियोग (Investment) करने में मुद्रा इस प्रवाह में डाली जाती है। यदि किसी समय बचत की मात्रा विनियोग में अधिक है तो वह इस बान को दलसलता है कि प्रवाह में से बहुत अधिक मुद्रा निकाल ली गई है और उतनी मात्रा में उसे वापस नहीं लौटाया गया है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कम हो जाती है। यदि विनियोग (Investment) बचत (Savings) की अपेक्षा अधिक होता है तो आय तथा व्यय का प्रवाह निरन्तर घटता चला जाता है और वस्तुओं के लिए अधिक मुद्रा प्रस्तुत की जाने लगती है।

प्रो० केन्स (Keynes) ने अनुमान किसी भी समाज में बचत तथा विनियोग की मात्रा अनिवार्य रूप से एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यदि बचत विनियोग की अपेक्षा अधिक होती है तो मांग कम होने के कारण वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरने लगते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत विनियोग की बचत से अधिक होने की दशा में वस्तुओं के मूल्य ऊपर उठते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। सन्तुलन की स्थिति वह होती है जिसमें बचत और विनियोग दोनों एक दूसरे के बराबर हों। इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए केन्स ने निम्न-लिखित समीकरण प्रस्तुत किया है—

आ = उ + वि	अथवा	Y = C + I
∴ आ = उ + व	अथवा	Y = C + S
∴ वि = व	अथवा	I = S

इस समीकरण में Y कुल आय को सूचित करता है, C उपभोग को; I विनियोग तथा S बचत को। समाज में प्राप्त होने वाली आय दो प्रकार की आयों का योग होती है—उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त आय तथा विनियोग की वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त आय। इसलिए $Y = C + I$ । अब हम जानते हैं कि प्राप्त होने वाली आय को या तो व्यय किया जा सकता है या उसे बचाया जा सकता है। अर्थात् $Y = C + S$ । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि विनियोग और बचत एक दूसरे के बराबर होने चाहिए अर्थात्

$$I = S$$

इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय के सम्बन्ध के द्वारा निर्धारित होता है। मौद्रिक आय की मात्रा तथा इसका प्रवाह कुल मुद्रा की मात्रा तथा आय की भ्रमण-गति (Income Velocity) पर निर्भर होता है। मुद्रा की कुल मात्रा मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली पर आधारित होती है तथा आय की भ्रमण-गति उत्पादकों की लाभ सम्बन्धी आशा, उत्पादन के समय तथा लोगों के अपनी आय को व्यव करने के निष्णों के द्वारा प्रभावित होती है। वास्तविक आय पर भी विभिन्न बातों का प्रभाव पड़ता है जैसे देश में साधनों की मात्रा तथा आर्थिक उन्नति की अवस्था इत्यादि। यद्यपि बचत की मात्रा विनियोग के बराबर होनी चाहिए किन्तु किसी निश्चित समय में यह आवश्यक नहीं कि कुल बचत की मात्रा, कुल विनियोग की मात्रा के बराबर ही हो। यदि लोग अपनी आय का कुछ भाग उपभोग अथवा विनियोग में न लगा कर अपने पास सग्रह (Hoarding) कर लेते हैं तो ऐसी दशा में बचत की मात्रा विनियोग से अधिक हो जायगी जिसके परिणामस्वरूप मूल्य गिरने लगने हैं। इसके विपरीत यदि बैंकों के द्वारा साख का विस्तार किये जाने से विनियोग की मात्रा बचत से अधिक हो जाती है तो मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य के बदलने का कारण मुद्रा की मात्रा का बदलना नहीं है बल्कि बचत तथा विनियोग के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण मुद्रा का मूल्य बदला करता है। बचत और विनियोग पर व्याज की दर का प्रभाव भी पड़ता है इसलिए व्याज की दर भी मुद्रा के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

आय तथा व्यय सिद्धान्त के गुण

(Merits of Income and Expenditure Theory)—

द्रव्य का आय तथा व्यय सिद्धान्त यद्यपि सर्वथा दोष रहित नहीं है किन्तु फिर भी वह परिमाण सिद्धान्त से निश्चित रूप से उत्तम है। इस सिद्धान्त के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

(१) यह सिद्धान्त व्यवहारिक क्षेत्र में आर्थिक नीतियों का प्रवृत्ति प्रदर्शन कर सकता है। प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-प्रसार तथा मूल्य वृद्धि का कारण समझा जाता था। वर्तमान सिद्धान्त इस भ्रम को दूर करता है। केन्स (Keynes) का सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण मुद्रा-प्रसार का भय केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात् ही उत्पन्न होता है। जब तक देश में बेकार माघन मौजूद होते हैं तब तक मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि गणित को बढ़ाती है, कीमतों को नहीं। निम्न पूर्ण रोजगार की स्थिति पहुँच जान व पश्चात् मुद्रा की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-प्रसार को उत्पन्न करती है। इस प्रकार का विश्लेषण वास्तविकता के अधिक समीप प्रतीत होता है। अतः यह सिद्धान्त एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिस पर आर्थिक क्रियाओं तथा रोजगार को ऊँचे स्तर पर बनाये रखने की मार्गजनिनी नीति का निर्माण किया जा सकता है।

(२) वचन तथा विनियोग सिद्धान्त इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह ऐसी बहुत सी बातों का जवाब देता है जिनके बारे में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कुछ नहीं बतलाता है। यह सिद्धान्त इस बात का जवाब देता है कि मुद्रा की मात्रा को कम करने में समृद्धि काल (Prosperity Phase) में मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोकना क्यों सम्भव होता है और अवसाद काल (Depression Phase) में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पर मूल्य-स्तर क्यों नहीं बढ़ता है। प्रो० क्रॉडर ने व्यापार-चक्रों के विश्लेषण के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त के महत्व को बतलाते हुए कहा है—“यह इस विचित्र तत्व को समझाता है कि अवसाद काल में कभी-कभी जब नई मुद्रा का निर्माण किया जाता है तो उसका विनियोग की मात्रा पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है और जब विनियोग वचन से अधिक हो जाता है तो इसके विपरीत प्रभाव क्यों काम करने लगते हैं।”^{१९}

(३) वचन और विनियोग सिद्धान्त मुद्रा के चलन वेग (Velocity of Circulation of Money) के विचार को पूर्णतया समझने में सहायता करता है। यह सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि मुद्रा के चलन वेग पर व्यापार चक्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। जब वचन की मात्रा विनियोग से अधिक होती है तो लोग अधिक मुद्रा अपने पास रखते हैं और मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है। इसके विपरीत विनियोग के वचन से अधिक होने की दशा में मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है।

19 “This explains the puzzling phenomenon that when money is created at the bottom of a depression, it sometimes has no effect on the volume of investment. When investment exceeds savings the contrary influences come into play.”

(४) यह विश्लेषण मुद्रा सिद्धान्त का अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों के साथ एकीकरण करता है। मुद्रा का प्राचीन सिद्धान्त मुद्रा को तटस्थ (Neutral) मानकर उसके मूल्य का विश्लेषण करता है किन्तु केन्स (Keynes) के सिद्धान्त में यह दोष नहीं है। आय व्यय सिद्धान्त के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मुद्रा का प्रभाव समाज में उत्पादन, रोजगार तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा सिद्धान्त मूल्य सिद्धान्त तथा उत्पत्ति सिद्धान्त के साथ सम्बन्धित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस विश्लेषण के द्वारा मुद्रा सिद्धान्त को व्याज के सिद्धान्त के साथ भी सम्बन्धित कर दिया गया है क्योंकि यह सिद्धान्त व्याज की दरों के मुद्रा के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बतलाता है।

यद्यपि मुद्रा के मूल्य के अल्पकालीन परिवर्तनों के विश्लेषण के रूप में वचत तथा विनियोग सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ है किन्तु फिर भी मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का अपना महत्व है। दोनों ही सिद्धान्त अपने-अपने स्थान पर काफी महत्वपूर्ण हैं। वचत और विनियोग सिद्धान्त मूल्य-स्तर के अल्पकालीन परिवर्तनों के विषय में बतलाता है और मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मूल्य-स्तर की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता है। मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें दोनों सिद्धान्तों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रो० क्राउथर (Crowther) ने ठीक ही कहा है—
“मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त सागर के सामान्य स्तर का विश्लेषण करता है और वचत तथा विनियोग सिद्धान्त ज्वार भाटे की तीव्रता को बतलाता है।”^{२०}

परीक्षा-प्रश्न

- (१) द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) को संक्षेप में समझाइये और उसकी सीमाएँ बताइये। (आगरा बी० ए० १९६४)
- (२) बतलाइये द्रव्य के मूल्य को निश्चित करने में माँग और पूर्ति के नियम किस प्रकार लागू होते हैं? (आगरा बी० ए० १९६३)
- (३) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। (आगरा बी० ए० १९६२)
- (४) मुद्रा की मात्रा तथा देश के सामान्य मूल्य-स्तर के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण कीजिये। (आगरा बी० ए० १९६१)

20 “The Quantity Theory of Money explains, as it were the average level of the sea, the Savings and Investment theory explains the violence of the tides.”

—Crowther - An Outline of Money, P. 147.

- (५) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। वह कहां तक मूल्यों के घटने-बढ़ने के कारणों को ठीक-ठीक समझ पाता है।
(आगरा बी० काम १९५८, १९६२)
- (६) 'मुद्रा मात्रा सिद्धान्त' की आलोचना करिये। आधुनिक वर्षों में क्या परिवर्तन हो गये हैं ?
(राजस्थान बी० ए० १९५६)
- (७) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये, जैसा कि सार्ड केन्स ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धान्त किसके दृष्टिकोण की तुलना में किस प्रकार श्रेष्ठ है ?
(राजस्थान बी० काम १९५६)
- (८) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। किसी देश के मूल्य-स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन बातों का प्रभाव पड़ता है ?
(सागर बी० ए० १९५६)
- (९) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मुद्रा की चलन गति (Velocity of Circulation) के कौन-कौन से मुख्य कारण हैं ?
(सागर बी० काम १९५७)
- (१०) 'वास्तव में मुद्रा मूल्य सब आयों (Total Incomes) का ही परिणाम है, न कि मुद्रा की मात्रा (Quantity of Money) का।' (काउयर) व्याख्या कीजिए।
(सागर बी० काम १९५५)
- (११) मुद्रा की मात्रा तथा देश के सामान्य मूल्य-स्तर की बीच का सम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।
(विक्रम बी० ए० १९६०)
- (१२) मुद्रा की चलन गति से आप क्या समझते हैं ? इसे निर्धारित करने वाले तत्वों का विवेचन करिये।
(पटना बी० ए० १९५७)
- (१३) "आधुनिक विचारधारा की प्रवृत्ति यह है कि यह मुद्रा की मात्रा को मुद्रा मूल्य का निर्धारण करने वाला घटक नहीं मानता।" विवेचना कीजिये।
(बिहार बी० काम १९५६)
- (१४) "मुद्रा अनेक आर्थिक वस्तुओं में से एक है; अतः इसका मूल्य जहाँ दो शक्तियों द्वारा मुख्यतः निर्धारित होता है जो कि अन्य वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करती है।" (राबर्टसन) इस कथन की विवेचना कीजिये।
(गोरखपुर बी० ए० १९५६ Part I)

मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन

INFLATION AND DEFLATION

मुद्रा का क्रय-शक्ति का समय-समय पर बदलते रहना पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। इन देशों के आर्थिक जीवन में एक निश्चित क्रम के अनुसार समृद्धि (Prosperity) तथा मन्दी (Depression) के काल आते रहने हैं, जिनके कारण मूल्य-स्तर में परिवर्तन होते हैं और मुद्रा की क्रय-शक्ति बदल जाती है। मुद्रा के मूल्य का बदलना केवल सामाजिक अन्त्याय (Social Injustice) को ही जन्म नहीं देता है बल्कि उत्पत्ति की मात्रा तथा रोजगार की स्थिति पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी समाज के दीर्घकालीन हित में यही होता है कि वह मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन की स्थिति से अपने आप को बचाये रखे जिससे उसका आर्थिक जीवन नियमित गति से चल सके। किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि मूल्य-स्तर में होने वाले इन परिवर्तनों को आसानी से नहीं रोका जा सकता है। प्रत्येक देश को उनके बुरे परिणामों को सहना पड़ता है। यद्यपि अर्थशास्त्रियों ने मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को रोकने के कुछ उपाय खोज निकाले हैं और पहले की अपेक्षा अब उन्हें रोकना अधिक सम्भव हो गया है किन्तु फिर भी पूर्णतया सफल उपाय अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन पर नियन्त्रण करना तथा आर्थिक जीवन में स्थिरता लाना वर्तमान अर्थशास्त्र की एक मुख्य समस्या है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन के काल क्यों आते हैं और उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है।

मुद्रा-प्रसार का अर्थ—

मुद्रा-प्रसार की वास्तविक प्रकृति के बारे में काफी मतभेद पाया जाता है। लगभग प्रत्येक अर्थशास्त्री ने मुद्रा-प्रसार की अपनी अलग परिभाषा दी है किन्तु इन में से कुछ एक परिभाषाओं का अध्ययन करने से हम मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन

के सही अर्थ को समझ सकते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का उसके पीछे रखे जाने वाले धात्विक कोष के अनुपात से अधिक माना में विस्तार किया जाना, मुद्रा-प्रसार होता था। किन्तु धीरे-धीरे धात्विक कोषों का महत्व कम होने लगा और स्वयंमान के पतन के पश्चात् विस्तृत सभापत हो गया। इसके साथ ही मुद्रा-प्रसार की परिभाषा में भी परिवर्तन किये गये।

वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति की मात्रा के अनुपात से अधिक मात्रा में मुद्रा का विस्तार किया जाना मुद्रा-प्रसार है। जब भी मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके दूसरी ओर जब मुद्रा की पूर्ति की, उसकी मांग में किसी प्रकार की कमी स्थिति बिना, घटाया जाता है तो सामान्य मूल्य-स्तर गिर जाता है और मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। क्राउथर (Crowther) के अनुसार "मुद्रा-प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो अर्थात् मूल्य-स्तर बढ़ रहा हो और मुद्रा-संकुचन वह स्थिति हो जाती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो अथवा वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हों।" मुद्रा-प्रसार तब होता है जब मुद्रा की मात्रा को इतना अधिक बढ़ाया जाय कि मूल्य-स्तर बढ़ने लगे और मुद्रा का मूल्य गिर जाय। इसमें विलकुल विपरीत स्थिति को मुद्रा-संकुचन कहते हैं। क्राउथर (Crowther) की यह परिभाषा बहुत ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मूल्य-स्तर का घटना मुद्रा-प्रसार का सूचक माना गया है। मूल्यों में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता है। केवल एक विशेष स्थिति में जब मूल्य-स्तर बढ़ता है तो उसे मुद्रा-प्रसार कहते हैं। अवनाद काल (Depression) के पश्चात् जब धीरे-धीरे मूल्य बढ़ने लगे तो उसे मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता है। मुद्रा-प्रसार तब ही होता है जब मुद्रा की मात्रा को इतना अधिक बढ़ा दिया जाय कि वह व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकता से अधिक हो जाय। ऐसी दशा में जो मूल्य स्तर बढ़ता है केवल उसे ही मुद्रा-प्रसार कहते हैं। किसी अन्य कारण से मूल्य-स्तर का घटना मुद्रा-प्रसार नहीं होता है। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में द्वितीय विश्व-युद्ध काल में मुद्रा की मात्रा को इतना अधिक बढ़ाया गया कि उसकी मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो गई। युद्ध से पूर्व मितम्बर १९३९ में केवल १७२ करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में थी किन्तु युद्ध के पश्चात् मई १९५१ में इसकी मात्रा बढ़ कर १३०७ करोड़ रुपये हो गई। देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को इस अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि मूल्य-स्तर बढकर पहले की अपेक्षा कई गुणा हो गया और मुद्रा की क्रय-शक्ति बहुत कम हो गई। ऐसी स्थिति को मुद्रा-प्रसार कहते हैं।

1 "Inflation is a state in which the value of money is falling, i.e. prices are rising and deflation becomes a state in which the value of money is rising i.e. prices are falling."

कैमरर (Kemmerer) ने मुद्रा-प्रसार की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक ढंग से की है। उनके अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तो इस स्थिति को मुद्रा-प्रसार कहा जाता है। कैमरर ने मुद्रा-प्रसार की परिभाषा इस प्रकार की है—“मुद्रा-प्रसार तब हुआ करता है जब मुद्रा तथा चेक्स (cheques) के द्वारा प्रचलित बैंक जमा की पूर्ति विनिमय के माध्यम की कुल मांग से इस प्रकार बढ़ जाय कि सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ने लगे।”² यह परिभाषा मुद्रा-प्रसार की व्याख्या मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक मात्राओं के आधार पर करती है। मुद्रा की पूर्ति का उसकी मांग की अपेक्षा अधिक बढ़ जाना मुद्रा-प्रसार है और उसकी पूर्ति का मांग से कम रह जाना मुद्रा-संकुचन की स्थिति को पैदा करता है। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-प्रसार नहीं है। यदि मुद्रा की मांग के बढ़ जाने पर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो सामान्य मूल्य-स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी और मुद्रा की पूर्ति में होने वाली इस प्रकार की वृद्धि को हम मुद्रा-प्रसार नहीं कह सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी समाज में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण या आर्थिक विकास के कारण मुद्रा की अधिक मांग की जाने लगनी है और इस बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा जारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में किसी प्रकार का असन्तुलन पैदा नहीं होता है इसलिए हम इसे मुद्रा-प्रसार न कह कर मुद्रा-विस्तार (Expansion of Currency) कहते हैं। मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-संकुचन मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति के बीच असन्तुलन की दशा को बताता है। मुद्रा की पूर्ति का उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाना मुद्रा-प्रसार तथा पूर्ति का मांग की अपेक्षा कम रह जाना मुद्रा-संकुचन कहलाता है। यद्यपि कैमरर (Kemmerer) की परिभाषा सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक मानी जा सकती है किन्तु इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। मुद्रा की पूर्ति कब उसकी मांग से अधिक है इस बात को जानने का कोई उचित तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा उसके चतन वेग का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। यदि सामान्य मूल्य-स्तर की वृद्धि को मुद्रा-प्रसार का सूचक माना जाय तो परिभाषा दोषपूर्ण हो जाती है क्योंकि मूल्य-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता है। केवल मूल्य-स्तर का बढ़ना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि देश में मुद्रा की पूर्ति व्यपसाय की आवश्यकता से अधिक हो गई है। कुछ अन्य कारणों से भी मूल्य-स्तर में वृद्धि हो सकती है।

2 'Inflation is said to occur "whenever the supply of money and bank deposits circulating through cheques, so called 'deposit currency' increases relatively to the demand for media of exchange in such a way as to bring about a general rise in the price level."

प्रो० पीगू (Pigou) के द्वारा दी गई मुद्रा-प्रसार की परिभाषा अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। उनके अनुसार “मुद्रा-प्रसार की स्थिति तब पैदा होती है जबकि मौद्रिक आय (Money Income) धन उपार्जन की क्रियाओं (Income Earning Activity) से अधिक तेजी के साथ बढ़ती है।”³ अर्थात् मुद्रा-प्रसार तब होता है जब किसी समाज की मौद्रिक आय उसकी वास्तविक आय (Real Income) से अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगती है। जब किसी देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाना है तो उससे कारण लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और वे अधिक वस्तुओं की माग करने लगते हैं। इस बढ़ी हुई माग को पूरा करने के लिए उत्पादन अधिक मात्रा में वस्तुएं पैदा करते हैं। उत्पादन के साधनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगता है और धीरे-धीरे वह समाज पूर्ण रोजगार (Full Employment) के स्तर पर पहुँच जाता है। जब तक पूर्ण रोजगार बिन्दु नहीं पहुँचता है तब तक समाज की मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय दोनों ही बढ़ती हैं किन्तु पूर्ण रोजगार पर पहुँचने के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। मौद्रिक आय तो बढ़ती है किन्तु आय उपार्जन की क्रियाओं को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुद्रा की पूर्ति को और अधिक बढ़ाया जाना है तो मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार मूल्य-स्तर की वृद्धि मुद्रा-प्रसार का आवश्यक लक्षण है। जब मौद्रिक आय के वास्तविक आय में तेजी से साथ बढ़ने के कारण मूल्य-स्तर बढ़ता है तो उसे मुद्रा-प्रसार कहा जाता है।

हॉट्टे (Hawtrey) के अनुसार ‘मुद्रा-प्रसार आर्थिक जीवन की वह दशा है जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो।’⁴ कॉलबर्न (Coulborn) ने मुद्रा-प्रसार उस स्थिति को बतलाया है जब बहुत सी मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रही हो। उनके अनुसार “मुद्रा प्रसार आम की पूर्ति से अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न होता है।”⁵ पॉल एन्जिग (Paul Einzig) ने मुद्रा-प्रसार को असन्तुलन की स्थिति बतलाया है। उन्होंने मुद्रा-प्रसार की परिभाषा इस प्रकार की है— “मुद्रा-प्रसार असन्तुलन की वह स्थिति है जिसमें क्रय-शक्ति का विस्तार कीमत-स्तर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखता है या वह उसका परिणाम होता है।”⁶

3 “Inflation exists when Money Income is expanding more than in proportion to Income Earning Activity.”

—A. C. Pigou - Types of War Inflation, Economic Journal Dec, 1941, P 409.

4 Hawtrey associates inflation with ‘the issue of too much currency’

5 “Inflation arises from demand outrunning supply.”

—W. A. L. Coulborn : A Discussion of Money, ¶ 156

6 Inflation is “a state of disequilibrium in which an expansion of purchasing power tends to cause, or is the effect of, an increase of price level.”

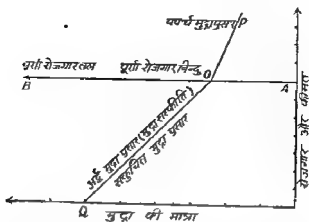
—Paul Einzig

मुद्रा-प्रसार पर केन्स (Keynes) के विचार—

उपर्युक्त परिभाषाओं में से अधिकांश मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त पर आधारित है किन्तु लार्ड केन्स (Lord Keynes) ने मुद्रा-प्रसार की व्याख्या पूर्ण रोजगार के दृष्टिकोण में की है। उनके अनुसार मुद्रा-प्रसार सप्रभाब मांग (Effective Demand) की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है और वास्तविक मुद्रा-प्रसार की स्थिति पूर्ण रोजगार बिन्दु के पश्चात् ही आरम्भ होती है। यद्यपि केन्स पूर्ण रोजगार से पूर्व कीमतों के बढ़ने से इन्कार नहीं करते हैं किन्तु उन्होंने इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि को अर्ध-मुद्रा-प्रसार (Semi-Inflation) की स्थिति कहा है। उनके अनुसार 'जब तक बेरोजगारी होती है, रोजगार उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है किन्तु जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो कीमतें उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिसमें मुद्रा की मात्रा बदलती है।'⁷ यदि पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो उसका कुछ प्रभाव तो उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करेगा और कुछ उत्पादन-सामग्री तथा मूल्यों को बढ़ायेगा जिसके कारण अर्ध-मुद्रा-प्रसार (Semi-inflation) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार से पूर्व भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर मूल्य-स्तर बढ़ सकता है और मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा तब होता है जब नई मुद्रा का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने तथा बेकार साधनों का प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाता है और उसे वर्तमान वस्तुओं तथा सेवाओं पर ही व्यय कर दिया जाता है। देश में उचित प्रकार के थमिकों का न मिलना, पूँजी की कमी, मशीनों का उपलब्ध न होना तथा उत्पादन सम्बन्धी अन्य बाधाओं के कारण उत्पादन को बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी दशा में कीमतें बढ़ेंगी और अर्ध-मुद्रा-प्रसार उत्पन्न हो जायगा। जब किसी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति पहुँच जाती है और बेकार साधन समाप्त हो जाते हैं तो ऐसी दशा में मुद्रा की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि शुद्ध मुद्रा-प्रसार (Pure Inflation) को पैदा करती है। अतः केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार से पूर्व हमें मुद्रा-प्रसार का भय बहुत कम होता है क्योंकि जब तक बेकार मानवीय तथा भौतिक साधन होते हैं तब तक मुद्रा की वृद्धि रोजगार को बढ़ाती है। मुद्रा-प्रसार का वास्तविक भय पूर्ण रोजगार के पश्चात् आरम्भ होता है। लार्ड केन्स के इस विचार को आगे दिये गये चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र में A B रेखा पूर्ण रोजगार के स्तर को तथा O पूर्ण रोजगार बिन्दु को दिखाता है। चित्र के देखने से स्पष्ट है कि यद्यपि कीमत-स्तर का बढ़ना

7 "So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money, and when there is full employment, prices will change in the same proportion as the quantity of money."



○ बिन्दु के पहुँचने से पहले ही प्रारम्भ हो जाता है किन्तु उसे शुद्ध मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जाता है बल्कि वह अर्ध-मुद्रा-प्रसार (Semi-inflation) की स्थिति है। जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं पहुँचता है तब तक मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि रोजगार को बढ़ाती है और केवल पूर्ण रोजगार-स्तर पहुँचने के पश्चात् ही मुद्रा की वृद्धि वास्तविक अथवा शुद्ध मुद्रा-प्रसार उत्पन्न करती है जैसा कि O P रेखा से विदित है।

मुद्रा-प्रसार के विभिन्न रूप—

मुद्रा-प्रसार को रोकने के उपायों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्रा-प्रसार में भेद करना आवश्यक है। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा-प्रसार के विभिन्न रूप बतलाये हैं और उनमें से प्रत्येक को रोकने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उपाय हो सकते हैं। किसी देश में मुद्रा-प्रसार को रोकने की नीति का निर्माण करने में पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा-प्रसार किस प्रकार का है और उसे रोकने के लिए कौन से उपाय अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। प्रो० वेन्स के अनुसार मुद्रा-प्रसार तीन प्रकार का हो सकता है—

- (१) वस्तु मुद्रा-प्रसार (Commodity Inflation)
- (२) चलन मुद्रा-प्रसार (Currency Inflation)
- (३) लाभ मुद्रा-प्रसार (Profit Inflation)

एक साधारण प्रकार के मुद्रा-प्रसार को जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हों, वस्तु मुद्रा-प्रसार (Commodity Inflation) कहते हैं। चलन मुद्रा-प्रसार (Currency Inflation) तब होता है जब सरकार किसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अथवा युद्ध आदि के व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करती है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा-प्रसार की दशाएँ पैदा हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति सरकार

स्वयं पैदा करती है। युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार इस प्रकार का ही मुद्रा-प्रसार था। लाभ-मुद्रा-प्रसार (Profit Inflation) तब होता है जब उत्पादन-लागतों के गिरने के कारण उत्पादकों के लाभ अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। जब उत्पादन-ध्वंस घट रहा हो किन्तु सरकार कृत्रिम उपायों से वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाये रखे और उन्हें नीचे न गिरने दे तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों को बहुत अधिक लाभ होने लगते हैं। इस लाभ का अधिकांश भाग उत्पादकों द्वारा स्वयं रखा जाता है और उसे अन्य साधनों में नहीं बाँटा जाता है, इसलिए केन्स (Keynes) ने इसे लाभ-मुद्रा-प्रसार (Profit Inflation) कहा है।

प्रो० पीगू (Pigou) ने दो प्रकार के मुद्रा-प्रसार में भेद किया है—

(i) पूर्ण मुद्रा-प्रसार (Full Inflation) तथा (ii) आंशिक मुद्रा-प्रसार (Partial Inflation)। उनके अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँचने के पश्चात् यदि उत्पत्ति की अपेक्षा मौद्रिक आय अधिक तेजी के साथ बढ़ती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। वस्तुओं के मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि को पूर्ण मुद्रा-प्रसार (Full Inflation) कहते हैं। किन्तु पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँचने से पहले यदि मौद्रिक आय वास्तविक आय से तेजी के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार की स्थिति को आंशिक मुद्रा-प्रसार (Partial Inflation) कहते हैं।

हीनार्थ प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार (Deficit Induced Inflation)—

सरकार की हीनार्थ प्रवृत्ति (Deficit financing) की नीति के कारण सामान्य मूल्य-स्तर में जो वृद्धि होती है उसे हीनार्थ प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार कहते हैं। जब सरकार का व्यय किन्हीं असामान्य कारणों से बढ़ जाता है और सरकार अपने बजट के घाटे को करो अथवा सार्वजनिक ऋणों के द्वारा पूरा करने में असमर्थ होती तो उसे नई मुद्रा का निर्माण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में इस प्रकार की वृद्धि से कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का मुद्रा-प्रसार प्रायः युद्ध-व्यय को पूरा करने अथवा आर्थिक विकास के लिए साधन प्राप्त करने का परिणाम होता है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों में इसी प्रकार का मुद्रा-प्रसार देखने को मिलता है।

मजदूरी प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार (Wage Induced Inflation)—जो मुद्रा-प्रसार मजदूरी की दरों के तेजी के साथ बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है उसे मजदूरी प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार कहा जाता है। यदि सरकार को थम सघों के दबाव के कारण मजदूरी की दरों में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ती है किन्तु उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के मुद्रा-प्रसार को मजदूरी प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार (Wages Induced Inflation) कहते हैं।

छुता मुद्रा-प्रसार (Open Inflation) तथा दबा हुआ मुद्रा-प्रसार (Suppressed Inflation)—यदि सरकार बढ़ते हुए मूल्यों पर किसी प्रकार का

नियन्त्रण नहीं लगानी है और मुद्रा-प्रसार को स्वतन्त्रतापूर्वक बढ़ने देती है तो इस प्रकार के मुद्रा प्रसार को खुला मुद्रा-प्रसार (Open Inflation) कहते हैं। खुले मुद्रा-प्रसार (Open Inflation) के नियन्त्रण से बाहर निकल जाने का बहुत अधिक भय रहता है। इसीलिए आजकल इस प्रकार के मुद्रा-प्रसार को अर्थ-व्यवस्था का भयकर रोग माना जाता है। यदि मुद्रा-प्रसार को नियमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो मुद्रा-प्रसार बहुत जल्दी एक विषम चक्र (Vicious circle) का रूप धारण कर लेता है। यदि मूल्यों को बिना किसी रुकावट के बढ़ने दिया जाता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जबकि मूल्य इतने अधिक बढ़ गये होंगे कि मूल्य-स्तर, मजदूरी की दरें तथा उत्पादन लागतें एक दूसरे का पीछा करने लगनी हैं जिसके परिणामस्वरूप इन सबमें निरन्तर वृद्धि होती जाती है। एक के बढ़ने के कारण दूसरे में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि आर्थिक नियन्त्रणों के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोका जाता है और मुद्रा-प्रसार को दबाकर रक्खा जाता है तो उसे दबाया हुआ मुद्रा प्रसार (Suppressed Inflation) कहते हैं। आजकल इस प्रकार के मुद्रा-प्रसार के उदाहरण बहुत मिलते हैं। विशेषतया युद्ध काल में सरकार ऊँची कीमतों के बुरे प्रभावों से जनता को बचाने के लिए मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग की नीति को अपनाती है जिसके द्वारा मुद्रा-प्रसार प्रवृत्ति को दबा कर रखा जाता है।

घिसटता हुआ मुद्रा-प्रसार, चलता हुआ मुद्रा-प्रसार तथा भागता हुआ मुद्रा-प्रसार (Creeping Inflation, Walking Inflation & Galloping Inflation)—मुद्रा-प्रसार की तीव्रता के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि सरकार मुद्रा-प्रसार पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाती है और उसे बढ़ने देती है तो वह भयकर रूप धारण कर लेता है। बढ़ता हुआ मुद्रा-प्रसार इन अवस्थाओं में गुजरता है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देता है। प्रारम्भ में खुला मुद्रा-प्रसार (Open Inflation) मध्यम ग्रेडी का होता है और कीमतें धीरे-धीरे बढ़ती हैं। कीमतों में इस प्रकार की वृद्धि को घिसटता हुआ मुद्रा-प्रसार (Creeping Inflation) कहते हैं। समय के साथ-साथ कीमतों की वृद्धि में कुछ तीव्रता आ जाती है और घिसटता हुआ मुद्रा-प्रसार (Creeping Inflation) चलते हुए मुद्रा-प्रसार (Walking Inflation) की स्थान दे देता है। यदि फिर भी सरकार कीमतों को रोकने के लिए कुछ नहीं करती है तो कीमतें अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं और भागते हुए मुद्रा-प्रसार (Galloping Inflation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि मुद्रा-प्रसार को बिना किसी रुकावट के बढ़ने दिया जाता है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि कीमतें, मजदूरी की दरें या उत्पादन लागतें एक दूसरे का पीछा करने लगनी हैं और एक प्रकार का विषम चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना अत्यन्त कठिन होता है। इस प्रकार के

मुद्रा-प्रसार को अर्थशास्त्रियों ने अत्यधिक मुद्रा-प्रसार अथवा भागता हुआ मुद्रा-प्रसार (Hyper Inflation or Galloping Inflation) कहा है। इस प्रकार के मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण करना बहुत कठिन होता है और वह स्वयं शक्तिशाली होता जाता है। बहुत जल्दी ही वह भयंकर रूप धारण कर लेता है और जनता का विश्वास मुद्रा में से उठ जाता है।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी में होने वाला मुद्रा-प्रसार इसी प्रकार का था। कीमतों में होने वाली वृद्धि का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है—दो भाइयों ने उत्तराधिकार में समान धन राशि प्राप्त की। एक ने अपने रुपये को बैंक में जमा करके बैंक बेंचेंस बढ़ाया। दूसरा भाई शराबी था, उसने अपनी धनराशि को शराब पर व्यय कर डाला किन्तु शराब की खामी बोतलें वह जमा करता गया। जब जर्मनी में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार हुआ तो शराबी ने अपनी खाली बोतलों को बेचकर उससे अधिक धन-राशि प्राप्त कर ली जितनी उसके भाई की बैंक में जमा थी। उस समय जर्मनी में इतना अधिक मुद्रा-प्रसार था कि वहाँ लोग कहा करते थे कि “पहले हम दुकानों पर जाते समय रुपया अपनी जेबों में ले जाते थे और खाने का सामान टोक़रियों में लाते थे किन्तु अब रुपया टोक़रियों में ले जाते हैं और खाने का सामान जेबों में ले आते हैं।”^१

मुद्रा-प्रसार के कारण—

मुद्रा-प्रसार के दोषों से समाज को मुक्त करने के उपायों पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि किन कारणों से समाज में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा-प्रसार को जन्म देने वाले दो प्रकार के कारण हो सकते हैं—(अ) नैसर्गिक कारण (Natural Causes) तथा (ब) कृत्रिम कारण (Artificial Causes)।

(अ) नैसर्गिक कारण (Natural Causes)—

कभी-कभी मुद्रा-प्रसार ऐसे प्राकृतिक कारणों से भी पैदा हो सकता है जैसे खानों से निकलने वाली बहुमूल्य धातुओं के उत्पादन में अचानक वृद्धि हो जाना, नई सोने व चांदी की खानों का मान्य होना तथा इन धातुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जाना। इस प्रकार के कारणों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता है इसीलिए इन्हें नैसर्गिक कारण कहा गया है। धात्विक मुद्रा काल में मुद्रा-प्रसार इन्हीं कारणों से पैदा होते थे। जब भी किसी देश में किसी भी कारण से मुद्रा धातु की पूर्ति बढ़ती थी तो चलन में मुद्रा की मात्रा का बढ़ना स्वाभाविक होता था और अत्यधिक मुद्रा हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते थे

1 “We used to go to the stores with money in our pockets and came back with food in our baskets. Now we go with money in baskets and return with food in our pockets.” —Quoted by P. Samuelson : Economics, P. 283.

और मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती थी। सन् १८६६ से लेकर १९११ तक मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण बहुमूल्य धातुओं के उत्पादन में वृद्धि होना था। इस काल में दक्षिणी अफ्रीका में सोने की नई खानों का पता लगने के कारण सोने का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था।

(व) कृत्रिम कारण (Artificial Causes)—

मुद्रा-प्रसार को जन्म देने वाले ये वे कारण हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है। इन कारणों से पैदा होने वाला मुद्रा-प्रसार एक प्रकार का ऐच्छिक मुद्रा-प्रसार (Deliberate Inflation) होता है। वर्तमान समाज में अधिकांश मुद्रा-प्रसार कृत्रिम कारणों से ही पैदा होते हैं। कृत्रिम कारणों में प्रमुख निम्न-लिखित हैं—

(१) हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financing)—सरकार के द्वारा घाटे का बजट बनाकर हीनार्थ प्रबन्ध करना वर्तमान समय में मुद्रा-प्रसार का प्रमुख कारण बन गया है। पिछले ५० वर्षों में उत्पन्न होने वाले मुद्रा-प्रसार मुख्यतया सरकार की हीनार्थ प्रबन्ध की नीति के कारण ही पैदा हुए। हीनार्थ प्रबन्ध की नीति के अन्तर्गत सरकार घाटे के बजट बनाती है और अपनी सामान्य आय से अधिक व्यय करती है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अधिक करारोपण तथा सार्वजनिक ऋणों के द्वारा अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। किन्तु इन साधनों से सरकार की आय में पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। नये तथा अधिक करो करो जनता पसन्द नहीं करती है। बहुत अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋण लेना सम्भव नहीं होता है और उमके लिए सरकार को काफी व्यग्र करना होता है। ऐसी स्थिति में सबसे आसान तथा सस्ता तरीका नई पत्र मुद्रा छापकर अतिरिक्त आय प्राप्त करना होता है। सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है और केन्द्रीय बैंक इस काम को पूरा करने के लिए अधिक पत्र मुद्रा जारी करता है। नई मुद्रा जारी होने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती है।

सरकार के द्वारा हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financing) की नीति के अपनाने के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। आय किसी बड़े युद्ध के व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा हीनार्थ प्रबन्ध की नीति को अपनाया जाता है। युद्ध के कारण सरकार को बहुत अधिक खर्च करना होता है जिसे आय के सामान्य साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर सरकार को नई मुद्रा जारी करके इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करना पड़ता है आजकल बहुत से अल्प-विकसित देश अपनी विकास योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए भी हीनार्थ प्रबन्ध की नीति को अपना रहे हैं। युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिए किया जाने वाला हीनार्थ प्रबन्ध काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसके फलस्वरूप उत्पत्ति की

मात्रा में बहुत कम वृद्धि होती है किन्तु आर्थिक विकास के लिए किया जाने वाला हीतार्थ प्रबन्ध इतना भयंकर नहीं होता है क्योंकि उसमें पैदा होने वाला मुद्रा-प्रसार कुछ समय पश्चात् अपने आप ठीक हो जाता है ।

(२) सरकार की मुद्रा विस्तार की नीति—(Policy of Monetary Expansion)—सरकार की मुद्रा विस्तार की नीति के कारण भी देश में मुद्रा-प्रसार की दशाएँ पैदा हो सकती हैं । कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार मुद्रा-विस्तार की नीति को अपना सकती है । जैसे देश को अवसाद (Depression) से बाहर निकालने के लिए अथवा आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध साधन जुटाने के लिए । यदि देश में अवसाद (Depression) की स्थिति के कारण मूल्य बहुत नीचे हैं और आर्थिक क्रियाएँ बहुत धीमी गति से चल रही हैं तो ऐसी दशा में सरकार आर्थिक उत्थान (Economic Recovery) के लिए मुद्रा तथा साख का विस्तार करने की नीति को अपनाती है । बैंक दर कम कर दी जाती है और सरकार तथा बैंकों के द्वारा अधिक मुद्रा व साख का निर्माण किया जाता है । यदि उत्पादन की मात्रा उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती है । आजकल सरकारें आर्थिक विकास के लिए भी मुद्रा-विस्तार की नीति को अपनाती हैं जिसके कारण अस्थायी (temporary) मुद्रा-प्रसार पैदा हो जाता है ।

(३) मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि (Increased Velocity of Money)—मुद्रा-प्रसार प्रायः मुद्रा की अत्यधिक निकासी के कारण पैदा होता है किन्तु कभी-कभी मुद्रा की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना भी मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो सकती है । ऐसा तब होता है जब मुद्रा की मात्रा में तो कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है किन्तु उसका चलन वेग बढ़ जाता है । लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) के बढ़ जाने के कारण या पूँजी की सीमान्त उत्पादनशीलता में वृद्धि होने पर अथवा लोगों की तरलता पसन्दगी (Liquidity Preference) कम हो जाने के कारण यदि मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है तो उसके परिणामस्वरूप भी मुद्रा-प्रसार की दशाएँ पैदा हो सकती हैं । आजकल साख मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होना मुद्रा-प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है । संवृद्धि काल में साख मुद्रा का चलन वेग अधिक होने के कारण ही मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि हुआ करती है ।

उत्पत्ति की मात्रा में कमी होना—

वस्तुओं की पूति का पर्याप्त मात्रा में न होना भी मुद्रा प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है । यदि किसी समाज में उत्पत्ति की मात्रा स्थिर रहती है अथवा वह उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में उसकी मांग बढ़ रही है तो ऐसी दशा में वस्तुओं की कमी के कारण मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो

जाती है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उत्पत्ति की मात्रा गिरने के कारण वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाय। उत्पत्ति के गिरने अथवा उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे— (i) उत्पत्ति के साधनों की दुर्लभता (ii) औद्योगिक झगड़े (iii) विशिष्ट प्रकार के श्रम का न मिलना (iv) सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति तथा (v) प्राकृतिक आपत्तियाँ। इन सब कारणों से उत्पादन-स्तर में गिरावट आ सकती है और मुद्रा-प्रसार की दशाएँ पैदा हो सकती हैं।⁹

मुद्रा-संकुचन (Deflation)—

मुद्रा-संकुचन कीमतों के गिरने की स्थिति होती है। कीमतों में यह गिरावट सप्रभाविक माग (Effective Demand) के कम होने के कारण आती है। जब चलन में मुद्रा अथवा साख की मात्रा कम हो जाती है, तो लोगों की आमदनी गिरती है और वे वस्तुओं की कम माग करने लगते हैं, जिसके कारण सप्रभाविक माग गिरती है और कीमतें कम होने लगती हैं। प्रो० पीगू के अनुसार जब समाज की वास्तविक आय उसकी मौद्रिक आय की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ने लगती है, तो मुद्रा-संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति या तो मुद्रा की मात्रा कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है या वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाने का परिणाम होती है। मुद्रा-संकुचन की स्थिति में वस्तुओं की अधिकता होती है, बेरोजगारी फैलती है, उत्पादन की प्रवृत्ति गिरने की होती है, विनियोग कम होता है, बचत बढ़ती है और कीमतें गिरती जाती हैं। कीमतों में होने वाली प्रत्येक गिरावट को मुद्रा-संकुचन नहीं कहा जा सकता है। जब सप्रभाविक माग (Effective Demand) के कम होने के कारण कीमतें गिरती हैं, तो उस स्थिति को मुद्रा-संकुचन कहते हैं।

मुद्रा-संस्फीति (Reflation) तथा मुद्रा-असंस्फीति (Disinflation)

मुद्रा-संस्फीति (Reflation)—

मुद्रा-प्रसार से मिलती-जुलती एक और स्थिति भी हो सकती है, जिसे मुद्रा-संस्फीति कहा जाता है। दोनों में ही मूल्य-स्तर बढ़ता है, किन्तु दोनों के उद्देश्य तथा प्रभाव अलग-अलग होते हैं। मुद्रा-संस्फीति (Reflation) तथा मुद्रा-स्फीति (Inflation) से बिल्कुल भिन्न होती है। मुद्रा-संस्फीति (Reflation) उस दशा को कहते हैं जब देश को मन्दी से बाहर निकालने के लिए वहाँ की सरकार ऐच्छिक मुद्रा-प्रसार करती है।¹⁰ किसी भी देश को अवसाद (Depression) से बाहर निकालने के लिए समाज में अधिक मौद्रिक आय का होना आवश्यक है। मन्दी की दशाओं को दूर करने के लिए सरकार मुद्रा-प्रसार की नीति को अपनाती है, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य ऊपर उठने लगते हैं और आर्थिक उत्थान (Economic

9 "Reflation is inflation deliberately undertaken to relieve depression."

—G. D. H. Cole.

recover!) आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार की मुद्रा विस्तार की नीति को सस्फीति कहते हैं।

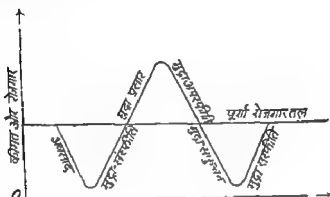
मुद्रा-स्फीति (Inflation) देश के लिए घातक होती है और उसे आर्थिक जीवन का भयंकर रोग माना जाता है किन्तु सस्फीति (Reflation) देश के हित में होती है, क्योंकि वह मन्दी की दशाओं को दूर करने में सहायता देती है। मुद्रा-सस्फीति निर्णयात्मक होती है किन्तु मुद्रा-स्फीति राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में बाधाएं पैदा करती है। मुद्रा-स्फीति की दशा में वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ते हैं और वे एक दूषित चक्र का रूप धारण कर लेते हैं किन्तु मुद्रा-सस्फीति में मूल्य धीरे-धीरे तथा नियमित गति से बढ़ते हैं। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब किसी देश को बेकार पूँजी तथा वृत्तिहीन श्रमिकों को काम में लाने के लिए मुद्रा-प्रसार किया जाता है, तो उसे मुद्रा-सस्फीति कहते हैं किन्तु यदि साधनों का पूर्ण उपयोग होने पर मुद्रा-प्रसार किया जाता है तो उसे मुद्रा-स्फीति कहा जायेगा।

मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation)—

जब किसी देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं, तो सरकार मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation) की नीति के द्वारा देश के मूल्य-स्तर पर मुद्रा-प्रसार के दबाव को कम करने का प्रयत्न करती है। मुद्रा-प्रसार की दशाएं पैदा हो जाने पर सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह मुद्रा विस्तार को रोकने तथा साख व मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों (Economic control) के द्वारा साख व मुद्रा की मात्रा को सीमित करके सरकार मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोकती है। मुद्रा-स्फीति के दोषों को दूर करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है, उसे मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation) कहते हैं। इसके अन्तर्गत वे सब उपाय तथा क्रियाएँ आ जाती हैं, जो मुद्रा-स्फीति के बँग को कम करने के लिए की जाती हैं। जिस प्रकार अवसाद (Depression) को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मुद्रा विस्तार की नीति को सस्फीति (Reflation) कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मुद्रा-सकुचन की नीति को अपस्फीति (Disinflation) कहते हैं। मुद्रा-अपस्फीति की नीति के द्वारा मूल्यों को बढ़ने से रोका जाता है और उन्हें धीरे-धीरे गिरने दिया जाता है, जो देश के हित में होता है।

पूर्ण रोजगार-स्तर के द्वारा मुद्रा-सस्फीति तथा मुद्रा-अपस्फीति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। प्रो० ब्रज नारायण ने इन स्थितियों में इस प्रकार भेद दिया है—“हम कह सकते हैं कि आदर्श सन्तुलन बिन्दु तक मुद्रा-सस्फीति (Reflation) की स्थिति होती है और उसके पश्चात् मुद्रा-प्रसार

(Inflation) की ओर यदि हम आदर्श बिन्दु से ऊपर जाते हैं तो वहाँ वापिस लौटने के लिए मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation) बरनी आवश्यक होगी और यदि हम विपरीत दिशा में नीचे की ओर जाते हैं, तो उसे मुद्रा-संकुचन (Deflation) कहा जाता है।¹⁰ कीमतों को बढ़ने तथा गिरने की इन सब व्यवस्थाओं को नीचे दिये गए चित्र के द्वारा समझा जा सकता है—



मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन के प्रभाव (Effects of Inflation and Deflation)—

मुद्रा के मूल्य परिवर्तन के भयंकर आर्थिक व सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। जब मुद्रा का मूल्य बढ़सना है तो समाज में उत्पत्ति की मात्रा तथा विभिन्न वर्गों को प्राप्त होने वाली आय में परिवर्तन होता है, जिसके कारण रोजगार की मात्रा भी बदल जाती है। मुद्रा-प्रसार को तो आर्थिक जीवन का क्षय रोग कहा गया है, जो धीरे-धीरे समाज की आर्थिक शक्ति को कमजोर कर देता है और एक बीमा के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था की प्रगति विनष्ट हो सकती है। मुद्रा-संकुचन के परिणाम हमें भी भयंकर होते हैं, जिनके कारण उत्पत्ति व रोजगार की मात्रा तथा समाज की वास्तविक आय बराबर गिरनी चली जाती है। यदि मुद्रा को अपने कामों को ठीक प्रकार करना है, तो उसके मूल्य में पर्याप्त स्थिरता का होना आवश्यक है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन आर्थिक क्रियाओं के भली प्रकार चलने में रुकावट पैदा करते हैं। उनके कारण समाज में कुछ लोगों को अनुचित लाभ होने हैं तथा दूसरों को अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। यदि मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का सब तथ्यों पर समान प्रभाव पड़ता, तो उनके

10 "We might say, that it is *reflation* upto the point of optimum equilibrium, and *inflation* after that and that if you go over the optimum, you have got to have *disinflation* to get back there, and if you go beyond in a downward direction then it is *deflation*."

कारण समाज में किसी प्रकार की असुविधा न होनी। किन्तु मुद्रा के मूल्य परिवर्तन विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को उनसे लाभ होता है और कुछ को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा के मूल्य परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को अध्ययन के लिए निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) उत्पत्ति की मात्रा तथा रोजगार पर प्रभाव (Effects on Production and Employment)।

(ब) धन के वितरण पर प्रभाव (Effects on the Distribution of Wealth)।

(अ) उत्पत्ति की मात्रा तथा रोजगार पर प्रभाव—मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन समाज में रोजगार की मात्रा तथा वास्तविक धन के उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति की मात्रा लाभ की आशा पर निर्भर होती है। जब लाभ की आशा अधिक होती है तो व्यवसायी अधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और अधिक विनियोग करते हैं, जिससे उत्पादन व रोजगार दोनों में वृद्धि होती है। किन्तु जब लाभ की आशा कम होती है तो उत्पादन व रोजगार दोनों ही कम हो जाते हैं। अधिक लाभ के समय में समाज की वास्तविक आय अधिकतम होती है किन्तु यदि लाभ की आशा नहीं है अथवा हानि की सम्भावना है, तो ऐसी दशा में समाज की वास्तविक आय गिरने लगती है और काफी कम हो जाती है।

पूर्ण रोजगार का बिन्दु पहुँच जाने के पश्चात् मुद्रा-प्रसार का प्रभाव उत्पादन पर लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बेकार साधन न होने के कारण उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। किन्तु पूर्ण रोजगार से पूर्व होने वाला मुद्रा-प्रसार उत्पादन को बढ़ान का प्रभाव रखता है। मुद्रा-प्रसार के समय में वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के कारण उत्पादक वर्ग को अधिक लाभ होने लगता है क्योंकि उत्पादन लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ते हैं। अधिक लाभ होने के कारण उत्पादकों को नये-नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उत्पत्ति की मात्रा तथा रोजगार दोनों ही बढ़ते हैं। इसीलिए मुद्रा-प्रसार का समय उत्पत्ति तथा रोजगार की दृष्टि से अच्छा होता है। लोगों की आय बढ़ती है तथा उन्हें अधिक रोजगार मिलता है। किन्तु यह स्मृति (Prosperity) अस्थायी होती है और इसके पश्चात् मंदी (Depression) का आना अनिवार्य होता है। मुद्रा-प्रसार में लोग इतने अधिक आशावादी हो जाते हैं कि वे निरन्तर विनियोग को बढ़ाते चले जाते हैं और एक समय के पश्चात् अधिक ढाँचा अपने ही भार के कारण टूट जाता है। मुद्रा-प्रसार के कारण रहन-सहन का व्यय इतना अधिक बढ़ जाता है कि अधिक वर्ग असंतुष्ट हो जाता है, जिसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

मन्दी काल (Depression) तो उत्पादन व रोजगार दोनों के लिए ही बुरा होता है। वस्तुओं के मूल्य कम होने के कारण लाभ कम हो जाते हैं, उत्पादक विनियोग की हुई पूँजी को निकालने लगते हैं। उत्पत्ति का विस्तार रुक जाता है, कारखाने बन्द होने लगते हैं, उत्पादन गिरता है और रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-प्रसार के समय में उत्पादन व रोजगार दोनों बढ़ते हैं और समाज की वास्तविक आय अधिकतम होती है, किन्तु मुद्रा-संकुचन के समय में उत्पादन कम हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है तथा समाज की वास्तविक आय बहुत कम हो जाती है।

(ब) धन के वितरण पर प्रभाव—मुद्रा के मूल्य परिवर्तन के प्रभाव केवल उत्पत्ति व रोजगार तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे समाज में धन के वितरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मुद्रा की क्रय-शक्ति का बदलना समाज में धन का पुनर्वितरण करता है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बदलते हैं। उन लोगों को अधिक लाभ होता है जिनकी वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बदलते हैं, किन्तु जिनकी वस्तुओं के मूल्य कम बदलते हैं उन्हें हानि उठानी पड़ती है। समाज में धन का वितरण इसलिए भी बदल जाता है क्योंकि श्रमों का भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है, जिसका मूल्य बदलता रहता है। मूल्यों के बदलने पर समाज में धन का वितरण किस प्रकार बदलता है, इसे जानने के लिए हमें विभिन्न वर्गों पर मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।

(१) मूल्य परिवर्तन और उत्पादक वर्ग (Price Changes and Producers)—मुद्रा-प्रसार के कारण जनता के पास अधिक क्रय-शक्ति हो जाती है और वे अधिक मात्रा में वस्तुओं की माग करने लगते हैं। वस्तुओं के उत्पादन को उसी तेजी के साथ बढ़ाना सम्भव नहीं होना है और वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। बढ़ते हुए मूल्य व्यापारियों के लाभ को बढ़ाते हैं और उन्हें अधिक व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने हैं। अचानक वे देखते हैं कि उनके माल के स्टॉक का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है, क्योंकि वस्तुओं की माग अधिक होने के कारण वे उन्हें अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं। मुद्रा प्रसार के समय में उत्पादक वर्ग भी बहुत अधिक लाभ पेंदा करता है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें तो अधिक होती हैं, किन्तु उनका उत्पादन व्यय उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। कच्चा माल पहले से ही सस्ते भाव पर खरीदा हुआ होता है, मजदूरी की दरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। पूँजी पर दिए जाने वाले व्याज व भूमि का किराना तथा अन्य प्रकार के स्थायी खर्चें लगभग स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उत्पादन लागतें मूल्यों में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा कम तेजी के साथ बढ़ती हैं। जिसके कारण लाभ की दर ऊँची हो जाती है और उत्पादक ऊँची लाभ की दर में फायदा उठाने के लिए

उत्पादन बढ़ते हैं। चारों ओर एक प्रकार का व्यवसायिक आशावाद (Business optimism) फैल जाता है। किसानों को और भी अधिक लाभ होता है, क्योंकि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य अन्य प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार के कारण धन का वितरण उत्पादकों के पक्ष में हो जाता है।

मुद्रा-संकुचन का समय उत्पादकों के लिए आपत्ति का समय होता है। उनके लाभ कम हो जाते हैं तथा उनकी आय गिन्ने लगनी है। मुद्रा-संकुचन के समय में मूल्य उत्पादन लागत की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ गिरते हैं, जिसके कारण उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है। व्यवसायी वर्ग में एक प्रकार की निराशा फैल जाती है और उत्पादन कम होने लगता है। मूल्य कम होने के कारण उत्पादकों के लाभ समाप्त हो जाते हैं और वे मजदूरी की दरों को घटाते हैं तथा श्रमिकों को काम से निकालने लगते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी फैलती है। उपको को और अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी के साथ गिरते हैं।

(२) विनियोगी वर्ग (Investors)—विनियोगी वर्ग में अभिप्राय उन लोगों से है जो व्यवसाय तथा उद्योग में अपनी पूँजी लगाकर आय प्राप्त करते हैं। यह लोग वास्तव में जोखिम उठाने वाले होते हैं और साहसी का कार्य करते हैं। इस वर्ग को दो भागों में बाटा जा सकता है—(१) वे, जिन्हें निश्चित आय प्राप्त होती है तथा (२) वे, जिनकी आय परिवर्तनशील होती है। निश्चित आय वाले विनियोगी वे होते हैं, जिन्हें एक निश्चित दर पर अपनी पूँजी पर व्याज अथवा आय प्राप्त होती है। इन्हें व्यवसाय में होने वाले लाभ तथा हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों में ऋण-पत्र अधिकारी (Debenture holders) इसी प्रकार के विनियोगी होते हैं। निश्चित आय वाले विनियोगियों को मुद्रा-स्फीति बाल में हानि होती है, क्योंकि इनकी विनियोग से होने वाली आय तो निश्चित रहती है, किन्तु वस्तुओं के मूल्य ऊँचा होने के कारण प्राप्त होने वाली आय की क्रय-शक्ति बहुत कम हो जाती है। बहुत अधिक मुद्रा-प्रसार लोगों की बचत करने की शक्ति को कम करता है तथा मुद्रा में विश्वास कम हो जाने के कारण बचत करने की इच्छा को भी कम करता है। इसके दूसरी ओर परिवर्तनशील आय वाले विनियोगियों की मुद्रा-प्रसार में लाभ होना है, क्योंकि वे उद्योग के लाभ तथा हानि में हिस्सेदार होते हैं। व्यवसाय को यदि अधिक लाभ होता है तो इन लोगों को प्राप्त होने वाला लाभअंश (Dividend) भी समुचित उसी अनुपात में बढ़ जाता है। मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के साधारण हिस्सेदार (Ordinary Shareholders) इसी प्रकार के विनियोगी होते हैं। मुद्रा-प्रसार का समय व्यवसायिक समृद्धि का बाल होता है। ऊँचे मूल्यों के कारण व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और परिवर्तनशील आय वाले विनियोगियों की आय

तेजी के साथ बढ़ने लगती है। इस प्रकार अधिकांश विनियोगियों को मुद्रा-प्रसार का लाभ काफी लाभ होने है।

मुद्रा-सकुचन का विनियोगी वर्ग के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। केवल निश्चित आय वाले कुछ विनियोगियों को छोड़कर शेष सभी विनियोगियों की आय कम हो जाती है। व्यवसाय तथा उद्योगों में हानि होने के कारण इन लोगों को भी हानि होने लगती है। निश्चित आय वाले विनियोगियों को लाभ रहता है क्योंकि उनकी आय तो यथास्थिर रहती है किन्तु मूल्य-स्तर कम होने के कारण उस आय की क्रय-शक्ति अधिक हो जाती है। इस काल में लोगों को बचत करने का प्रोत्साहन मिलता है किन्तु आय का सामान्य स्तर कम होने के कारण लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो जाती है।

(३) श्रमिक तथा निश्चित आय वाला वर्ग (Labour & Fixed Income Groups)—मुद्रा-प्रसार काल में श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि मजदूरी की दरें न तो मूल्यों के साथ बढ़ती हैं और न वे उस अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में मूल्य-स्तर बढ़ता है। यह देखा गया है कि 'मजदूरी की दरें सबसे धीरे से बढ़ती हैं', जिसके कारण मजदूरी हमेशा बीमारी से पीछे रह जाती है। यद्यपि श्रम सब श्रमिकों की मजदूरी में कुछ वृद्धि करा लेते हैं किन्तु मजदूरी में वृद्धि उतनी तेजी के साथ नहीं होती है जितनी तेजी के साथ मूल्य बढ़ते हैं। इसलिए श्रमिक वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। एक ओर तो श्रमिकों की आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है और दूसरी ओर मूल्यों के बढ़ने के कारण उनका रहन-सहन का खर्च (Cost of Living) निरन्तर बढ़ता जाता है। ऐसी दशा में श्रमिकों के लिए अपने आवश्यक व्यय को पूरा करना भी सम्भव नहीं होता है। वे या तो पहली बचत को निवाल कर व्यय करने लगते हैं या उन्हें ऋण लेना पड़ता है। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण श्रमिकों का रहन-सहन का स्तर गिरने लगता है। मुद्रा-प्रसार ने श्रमिकों को लाभ भी होता है। रोजगार की मात्रा अधिक होने के कारण बेरोजगारी समाप्त हो जाती है और सभी श्रमिकों को काम मिल जाता है। श्रम परिवारों की मौद्रिक आय बढ़ती है क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का काम मिल जाता है।

निश्चित आय वाले वर्ग को भी मुद्रा-प्रसार के कारण बहुत हानि उठानी पड़ती है। सरकारी कर्मचारी, मजान, मालिक तथा भूमिपति इसी वर्ग में आते हैं। इन लोगों की आय में तो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है किन्तु रहन-सहन का खर्च निरन्तर बढ़ता रहता है, जिसके कारण निश्चित आय वाला वर्ग बहुत परेशानी में रहता है। मध्यम वर्ग तो लगभग बिन्दु पर समाप्त हो जाता है। यद्यपि श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों को कुछ महंगाई का भत्ता दिया जाता है किन्तु वह मूल्य-स्तर की वृद्धि की तुलना में बहुत कम होता है।

मुद्रा-सकुचन काल में श्रमिक वर्ग को लाभ रहता है क्योंकि मजदूरी की दरें उनकी तेजी के साथ नहीं गिरती हैं जितनी तेजी से वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं,

निश्चित आय वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होता है। इस वर्ग के लोगों की आय तो निश्चित रहती है किन्तु मूल्य गिरने के कारण रहन-सहन का व्यय कम हो जाता है। इन लोगों की वचत करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा इनके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है। रोजगार की दृष्टि से श्रमिकों को मुद्रा-सकुचन काल में हानि रहती है क्योंकि रोजगार की मात्रा कम होने के कारण इन लोगों को कम काम मिलता है। श्रम परिवारों के बहुत से सदस्य बेकार हो जाते हैं जिसके कारण पारिवारिक आय में कमी हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा-सकुचन काल में भी श्रमिकों की मुद्रा की क्रय-शक्ति के बढ़ जाने से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें बहुत से बेकार हो जाते हैं।

(४) उपभोक्ता वर्ग (Consumers)—उपभोक्ताओं पर मुद्रा-प्रसार का धुरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं की तो बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। इन लोगों की आय की अपेक्षा वस्तुओं के मूल्य अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं। वस्तुएँ और सेवाएँ दुर्लभ हो जाती हैं और उनके मूल्य में तेजी के साथ वृद्धि होती है। बढ़ते हुए मूल्य उपभोक्ताओं के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो आय उन्हें प्राप्त होती है उससे वे अपने आवश्यक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उनका रहन-सहन का स्तर गिरने लगता है। वे ऋण लेकर अथवा अपनी वचत को खर्च करते हैं, इस प्रकार मुद्रा-प्रसार घन के वितरण को उपभोक्ताओं के विपक्ष में तथा उत्पादकों के पक्ष में कर देता है।

मुद्रा-सकुचन का काल उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है क्योंकि उन्हें कम मूल्य पर वस्तुएँ प्राप्त होने लगती हैं। मूल्यों के गिरने के कारण वे अपनी आय से अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीद सकते हैं। उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाता है तथा वे कुछ वचत भी कर लेते हैं। किन्तु परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है क्योंकि बेरोजगारी तथा उत्पादन कम होने के कारण उनकी आय काफी गिर जाती है।

(५) ऋणी तथा ऋणदाता (Debtors & Creditors)—वर्तमान समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति या तो ऋणी होता है या ऋणदाता और उनमें से प्रत्येक दशा में मूल्य परिवर्तनों का उस पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-प्रसार काल में ऋणी को लाभ रहता है और ऋणदाता को हानि उठानी पड़ती है। इसके दूसरे और मुद्रा-सकुचन काल में ऋणी को बहुत नुकसान होता है और ऋणदाताओं को लाभ रहता है। मुद्रा-प्रसार काल में मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो जाने के कारण ऋणों का भार कम हो जाता है और ऋणी वर्ग को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए कम क्रय-शक्ति का त्याग करना पड़ता है। ऋणी अपने ऋणों का भुगतान मुद्रा में करते हैं जिसकी क्रय-शक्ति ऋण लिए जाने के समय की अपेक्षा बहुत कम रह जाती है। मुद्रा के रूप में तो वे उतना ही लौटाते हैं किन्तु क्रय-शक्ति के रूप में

कम लौटाया जाता है। ऋणदाताओं को हानि रहती है क्योंकि उन्हें दिये गये ऋणों के बदले में कम क्रय-शक्ति वापस मिलनी है। उदाहरणार्थ यदि १९३६ में उधार लिए गये १००) ६० को १९५० में लौटाया जाता है जबकि वस्तुओं के मूल्य १९३६ की अपेक्षा चार गुणा बढ़ चुके थे। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण १९५० में १००) ६० केवल उतना सामान खरीदते थे जितना १९३६ में २५) ६० के द्वारा खरीदा जा सकता था। इस प्रकार १९५० में ऋणी १००) ६० के ऋण को लौटाने में केवल २५) ६० की क्रय-शक्ति ही वापिस लौटाता है जिसके कारण ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि।

इसकी दूसरी ओर जब वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं तो ऋणी-वर्ग को हानि रहती है और ऋणदाताओं को लाभ होता है। ऋणी अपने ऋणों को चुकाने के लिए उसनी ही मुद्रा वापस देने हुए अधिक क्रय-शक्ति हस्तान्तरित करते हैं। मन्दी काल (Depression) में ऋणों का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऋणी वर्ग को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसीलिए सरकार अवसाद काल में इन लोगों के ऋणों की मात्रा को कम करके तथा अन्य तरीकों से इनकी सहायता करती है। ऋणदाताओं को मन्दी काल में लाभ रहता है क्योंकि उन्हें ऋणों के बदले में अधिक क्रय शक्ति वापस मिलती है।

(६) सरकार व करदाता (Govt and Tax Payers)—मूल्य परिवर्तनों का करदाताओं तथा सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हुए मूल्यों के समय में करदाताओं को लाभ रहता है क्योंकि वह कर (Tax) मुद्रा के रूप में देना है जिसका मूल्य पहले की अपेक्षा काफी कम होता है। यद्यपि करदाताओं को कुछ अधिक कर देने होते हैं किन्तु वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में वे सरकार को कम देते हैं। मुद्रा-प्रसार काल में करों का भार कम हो जाता है और करदाताओं को कर देने में कम त्याग करना पड़ता है। इसके दूरी ओर सरकार को हानि रहती है क्योंकि उन्हें करों के रूप में कम क्रय-शक्ति प्राप्त होनी है। मुद्रा के रूप में तो उन्हें उतने ही कर प्राप्त होते हैं किन्तु वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में कम मिलता है। क्रय-शक्ति कम होने के कारण, प्राप्त होने वाली आय बाजार से कम सामान खरीद पाती है और सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए अधिक कर लगाने होते हैं।

मुद्रा-संकुचन काल में करदाताओं को हानि रहती है और सरकार को लाभ रहता है। करदानाओं को कर में उतना ही रुक्या देना होता है जितना कि वे पहले दे रहे थे किन्तु अब वे वस्तुओं के रूप में अधिक देते हैं। सरकार को लाभ होना है क्योंकि मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाने के कारण अब उन्हें वस्तुओं के रूप में अधिक कर प्राप्त होते हैं।

मूल्य परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव—

अभी तक हमने मूल्य परिवर्तनों के आर्थिक प्रभावों पर विचार किया है। मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन के सामाजिक प्रभाव भी कुछ कम भयकर नहीं होते हैं। मूल्य परिवर्तन का समय सामाजिक अशांति तथा मुसीबत का समय होता है। जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो श्रमिक अपनी मजदूरी की दरों में वृद्धि की मांग करते हैं क्योंकि मूल्य-स्तर के ऊँचा हो जाने के कारण उनका रहन-सहन का व्यय बढ़ जाता है। इसीलिए मुद्रा-स्फीति काल में हड़तालें बहुत अधिक हुआ करती हैं और श्रमिक वर्ग असंतुष्ट रहता है। श्रमिक मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं किन्तु पूँजीपति मजदूरी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं जिसके कारण श्रमिकों तथा पूँजीपति वर्ग में संघर्ष होना है जो सामाजिक अशांति उत्पन्न करता है। इससे अतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के कारण समाज में धन का वितरण अमीर लोगों के पक्ष में तथा गरीब लोगों के विपक्ष में हो जाता है जिसके कारण भी सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। मुद्रा-प्रसार के कारण अमीर उद्योगपति तथा पूँजीपति लाभ उठाते हैं और गरीब तथा मध्यम श्रेणी के लोगों की आय कम होती जाती है। धन के वितरण की बढ़ती हुई असमानताये वर्ग संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाती है। आर्थिक व सामाजिक दोनों के साथ-साथ मुद्रा-प्रसार लोगों का नैतिक पतन भी करता है। समाज में धन का वितरण अन्व्याप्तपूर्ण हो जाने के कारण लोगों का विद्वत्ता सरकार तथा नैतिकता के प्रति उठ जाता है। जल्दी अमीर होने की प्रवृत्ति के कारण व्यवसायिक नैतिकता अत्यधिक निम्न स्तर पर होती है। जर्मनी तथा फ्रांस के उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वहाँ मुद्रा-प्रसार काल में किस प्रकार लोगों का नैतिक पतन हुआ।

मुद्रा-संकुचन के कारण जब मूल्य गिरते हैं तो उत्पादक मजदूरी की दरों में कमी करना चाहते हैं तथा मजदूरों को काम से हटाते हैं। श्रमिक इसका विरोध करते हैं और मजदूरी की दरों में कमी नहीं होने देने जिसके कारण सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। मन्दी काल में मिल मालिकों की ओर से ताता बन्दो (Lock out) होती है जिसके कारण उत्पादन गिरता है तथा श्रमिकों को कष्ट उठाने पड़ने हैं। इस प्रकार मूल्य परिवर्तनों के सामाजिक प्रभाव भी उतने ही बुरे होते हैं जितने की आर्थिक प्रभाव।

मुद्रा-स्फीति तथा विस्फीति दोनों बुरी हैं—

अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति (Inflation) तथा मुद्रा-विस्फीति (Deflation) दोनों ही हानिकारक तथा अनावश्यक हैं। दोनों का ही समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दोनों को रोकना आवश्यक है किन्तु इन दोनों में से मुद्रा-स्फीति कम खराब है तथा विस्फीति अधिक बुरी है। प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार—“मुद्रा-प्रसार अनिष्ट है तथा मुद्रा-संकुचन अत्यावहारिक

है। दोनों में से सम्भवतः मुद्रा-मनुचन अधिक घृण है।^{११} प्रो० लेविगर्मन के अनुसार “बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है जिसके कारण कृषि, व्यापार तथा उद्योग की स्थिति डाँवाडोल हो जाती है और समाज के विभिन्न वर्गों को विषम अनुपात में लाभ तथा हानि होती है। अतः वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए।” मुद्रा-प्रसार के कारण देश की उत्पादन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि आरम्भ में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है और लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है किन्तु यह स्मृद्धि अस्थायी होती है क्योंकि इसे अधिक समय तक बनाये नहीं रखा जा सकता है। इस स्मृद्धि में आने वाले अवसाद (Depression) के कौटारण्य मौजूद होते हैं।

मुद्रा-स्फीति इसलिए अनुचित होती है क्योंकि वह समाज में बनावटी सम्पन्नता पैदा करती है जो कुछ समय पश्चात् स्वयं समाप्त हो जाती है। उसके कारण उत्पादन की क्रियाओं में असामान्य वृद्धि होती है जिसे अधिक डाँचा सम्भालने में असमर्थ रहता है और जल्दी ही अवसाद की दशा में पड़ा हो जाता है। समाज में व्यवसायिक आधावाद के कारण अत्यधिक व्यापार, अत्यधिक उत्पादन तथा अत्यधिक विनियोग की दशा में पड़ा हो जाती है। मुद्रा-प्रसार का बुरा प्रभाव केवल उत्पादन व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि उसके कारण समाज में धन का वितरण बदलकर व्यापारी तथा उत्पादक वर्ग के पक्ष में हो जाता है और श्रमिकों तथा निश्चित आय वालों के विपक्ष में रहता है। प्रो० केम्स (Keynes) ने मुद्रा-प्रसार को अग्यायपूर्ण कहा है क्योंकि उसके कारण समाज में धन के वितरण की अनमानता में बढ़ जाती है क्योंकि वह एक अनिवार्य कर की भाँति गरीबों की आय को कम कर देता है तथा व्यवसायिक वर्ग की आय को बढ़ाता है। प्रो० सी० एन० वकील ने मुद्रा-प्रसार की तुलना एव डाकू से की है। उनके अनुसार दोनों ही हमारा धन छूटते हैं, अन्तर केवल इतना है कि डाकू दिखलाई देता है परन्तु मुद्रा-प्रसार अदृश्य रहता है, डाकू एक समय में कुछ व्यक्तियों को ही छूटता है किन्तु मुद्रा-प्रसार नमस्त राष्ट्र को छूटता है तथा डाकू पर मुकदमा चलाया जा सकता है किन्तु मुद्रा-प्रसार वैधानिक है।^{१२} इस प्रकार मुद्रा-प्रसार अनुचित भी है और अग्यायपूर्ण भी।

11 “Inflation is unjust, deflation is inexpedient of the two, deflation is worse.”
—Keynes

12 “Inflation may be compared to a robber. Both deprive the victim of some possession with the difference that robber is visible inflation is invisible; the robber's victim may be one or a few at a time, the victim of inflation is the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal.”
—C. N. Vakil Financial Burden of War on India.

प्रो० केन्स (Keynes) ने मुद्रा-संकुचन (Deflation) को इसलिए अनुपयुक्त कहा है क्योंकि समाज को उससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। समाज का कोई भी वर्ग उससे स्थाई लाभ की आशा नहीं कर सकता है। मुद्रा-प्रसार तो कुछ विशेष दशाओं में समाज के लिए लाभपूर्ण भी हो सकता है किन्तु मुद्रा-संकुचन से हानि के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। देश में आर्थिक विकास के लिए अथवा युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को चालू रखने के लिए मुद्रा-प्रसार का प्रयोग लाभपूर्ण हो सकता है किन्तु मुद्रा-संकुचन किसी भी दशा में समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार की स्थिति पर नियन्त्रण करने में वह कुछ सहायता दे सकता है, किन्तु इसके अनिरिक्त उसका और कोई प्रयोग नहीं है। मुद्रा-संकुचन समाज में भयङ्कर आर्थिक बुराइयाँ पैदा करता है। उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा के ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं के मूल्यों के गिरने के कारण व्यापारिक निराशा पैदा होती है, उद्योग बन्द होने लगते हैं, उत्पादन कम हो जाता है तथा बेरोजगारी फैलती है। उत्पत्ति कम होने में तथा बेकारी के कारण लगभग सभी लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। विशेषकर उत्पादक वर्ग के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लाभ समाप्त हो जाने के कारण उनकी आय कम हो जाती है। अवसाद काल में समाज की वास्तविक आय भी गिर जाती है। इन्हीं सब कारणों से मुद्रा-संकुचन को अव्यवहारिक बतलाया गया है।

मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन दोनों ही आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से बुरे हैं। मुद्रा-प्रसार बनावटी सम्पन्नता पैदा करता है तथा धन के वितरण की असमानताओं को बढ़ाता है। मुद्रा-संकुचन उत्पादन को कम करता है तथा बेकारी को बढ़ाता है। दोनों ही आर्थिक प्रगति के रास्ते में भारी बाधाएँ पैदा करते हैं। किन्तु दोनों की तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों में से मुद्रा-संकुचन अधिक बुरा है। क्योंकि वह उत्पादन को कम करके उत्पत्ति की दशाएँ सन्तुष्ट कर देता है और बेकारी के कारण लोगों को असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। मुद्रा-संकुचन इसलिए भी अधिक बुरा है क्योंकि उस पर नियन्त्रण की सम्भावना बहुत कम है। मुद्रा-स्फीति को सफल आर्थिक नीति के द्वारा रोका जा सकता है किन्तु अवसाद (Depression) में फँसे हुए देश को निकालना बहुत कठिन होता है। प्रत्येक देश को ऐसी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए जिससे वह अपनी अर्थ-व्यवस्था को मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संकुचन दोनों ही से बचा सके। आर्थिक स्थिरता मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए।

मुद्रा-प्रसार को रोकने के उपाय (Methods to Check Inflation)—

मुद्रा-प्रसार के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन उन उपायों की खोज करना है जिनके द्वारा समाज में मुद्रा-प्रसार के दोषों को दूर किया जा सकता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि में मूल्यों में स्थिरता का होना अनिवार्य है। अधिक

विकास के लिए न तो मुद्रा-स्फीति और न विस्फीति ही अच्छी होती है। दोनों ही आर्थिक जीवन के भयंकर रोग हैं और दोनों पर नियन्त्रण करके समाज को उनमें मुक्त करना आवश्यक है। उचित मौद्रिक नीति के द्वारा समाज को इन दोनों में मुक्त किया जा सकता है। इसीलिए आजकल मौद्रिक प्रबन्ध (Monetary Management) का प्रथम उद्देश्य आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) माना जाता है।

मुद्रा-प्रसार मुख्यतः दो कारणों से पैदा होता है—अत्यधिक मुद्रा-विस्तार तथा उत्पादन का गिरना। इसलिए मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए दो प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जा सकता है—(अ) वे उपाय जिनके द्वारा मुद्रा के विस्तार को रोका जा सकता है तथा (ब) वे उपाय जिनके द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

मुद्रा-विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जा सकता है—

(i) मुद्रा व साल की मात्रा को कम करना—केन्द्रीय बैंक उचित मौद्रिक नीति के द्वारा देश में मुद्रा व साल की मात्रा को बढ़ने से रोक सकता है तथा उसे कम कर सकता है। बैंक-दर में वृद्धि करके तथा खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा मुद्रा व साल की मात्रा को बढ़ने से रोका जा सकता है किन्तु अल्प विवर्धित देशों में उपयुक्त दशाये न होने के कारण बैंक-दर नीति तथा खुले बाजार की क्रियाएँ अधिक प्रभावशाली नहीं होती हैं। इन दोनों में बैंकों के कोषों में परिवर्तन करके तथा प्रत्यक्ष नियन्त्रण के द्वारा साल की मात्रा को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। यदि मुद्रा-प्रसार भयंकर रूप धारण कर लेता है तो उसे रोकने के लिए सरकार को कुछ अत्यवहारिक तरीकों का प्रयोग भी करना पड़ता है। किसी विशेष प्रकार की मुद्रा को चलन से हटा लेना तथा प्रचलित मुद्रा को बढ़ करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना और पुरानी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा कम मात्रा में देना इसी प्रकार के कुछ उपाय हैं जिनका प्रयोग मुद्रा आदि काल में किया जाता है।

(ii) करों में वृद्धि करना तथा नये कर लगाना—मुद्रा-स्फीति काल में लोगों के पास अधिक मात्रा में क्रय-शक्ति होती है जिसके कारण वे वस्तुओं की अधिक माँग करते हैं और उनके मूल्य बढ़ने लगते हैं। जनता के पास क्रय-शक्ति को कम करना मुद्रा प्रसार को रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। सरकार वर्तमान करों में वृद्धि करके तथा नये कर लगा कर लोगों के पास से अतिरिक्त मुद्रा निकाल लेती है जिससे कारण उपभोक्ताओं के पास कम क्रय-शक्ति रह जाती है। जनता की आय कम होने से वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग कम हो जाती है और मुद्रा-प्रसार का दबाव कम होने लगता है।

(iii) अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋण लेना—सरकार सार्वजनिक ऋण सन्धियों नीति में परिवर्तन करके भी मुद्रा-प्रसार को बढ़ने में रोक सकती है।

अधिक मात्रा में जनता से ऋण लेकर सरकार लोगो की क्रय-शक्ति को कम कर सकती है। जब जनता के पास व्यय करने के लिए कम मुद्रा रह जाती है तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रुक जाती है।

(iv) आर्थिक नियन्त्रणों का प्रयोग—सरकार विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों (Economic controls) के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोक सकती है तथा अल्प पूति वाली आवश्यक वस्तुओं के उचित बँटवारे का प्रबन्ध कर सकती है। इसके लिए मूल्य नियन्त्रण (Price control) तथा राशनिंग (Rationing) की नीति को अपनाया जाता है। लोगो की आय को कम करने के लिए सरकार लाभ अंश नियन्त्रण (Dividend control) भी कर सकती है। यदि देश में मजदूरी प्रोत्साहित मुद्रा-प्रसार (Wage Induced Inflation) है तो सरकार मजदूरी की दरों पर नियन्त्रण करके उसे रोक सकती है। इसके अतिरिक्त भविष्य में विनियोग की मात्रा को कम करने के लिए सरकार के द्वारा विनियोगों पर भी नियन्त्रण किया जा सकता है।

(v) बचत को प्रोत्साहन देना—मुद्रा-प्रसार को रोकने का एक और प्रभावशाली तरीका लोगो के द्वारा की जाने वाली बचत को बढ़ाना है। यदि लोग अपनी आय का अधिक भाग बचाने लगते हैं तो वे कम व्यय करेंगे और मुद्रा-स्फीति की प्रगति रुक जायगी। बचत बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे सकती है और यदि आवश्यक हो तो अनिवार्य बचत योजना भी चालू की जा सकती है।

देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूति को बढ़ाना—मुद्रा-प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना है। विशेषतया आवश्यक वस्तुओं जैसे खाना, कपड़ा, मकान इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि होने का प्रभाव मूल्य-स्तर को कम करने का होता है। यदि देश में उत्पत्ति की मात्रा को भी उसी तेजी के साथ बढ़ाया जाता है जिस तेजी से मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो मुद्रा-प्रसार का भय समाप्त हो जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की पूति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(i) उद्योग-धर्मों तथा कृषि की प्रोत्साहन देना—नये-नये उद्योग-धर्म स्थापित किये जाने चाहिए तथा वर्तमान उद्योगों की कार्य-क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में वस्तुएं पैदा की जा सकें। कृषि उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में अनाज तथा कच्चा माल उपलब्ध हो सके। इस प्रकार देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूति को बढ़ाकर मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है।

(ii) वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात करना—देश में वस्तुओं की पूति को बढ़ाने के लिए विदेशों से अधिक वस्तुएं मँगानी चाहिए तथा देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को कम कर देना चाहिए। निर्यातों पर प्रतिबंध

लगाने चाहिए तथा आयातों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करने से देश में वस्तुओं की पूर्ति बट जायगी और वस्तुओं के मूल्य गिरने लगेंगे।

(iii) सरकार के द्वारा उत्पादन किया जाना—सरकार को उत्पादन बढ़ाने में प्रत्यक्ष भाग लेना चाहिए। जिन उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जा सकता उन्हें सरकार को स्वयं स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार कृषि-क्षेत्र में भी सरकारी खेती के द्वारा कृषि उपज को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुद्रा-संकुचन को दूर करने के उपाय—

यद्यपि मुद्रा-प्रसार की अपेक्षा मुद्रा-संकुचन को रोकना अधिक कठिन होता है किन्तु फिर भी अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ ऐसे उपायों की खोज कर ली गई है जिनके द्वारा समाज को मुद्रा-संकुचन की बुराई से मुक्त किया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल मुद्रा-संकुचन का भय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। मुद्रा-संकुचन के उत्पन्न होने के मुख्य कारण मुद्रा की बसी भयवा वस्तुओं की अधिकता होती है इसलिए सरकार को ऐसे उपाय काम में लाने चाहिए जिनके द्वारा मुद्रा व साख की मात्रा में वृद्धि की जा सके तथा विभिन्न प्रकार के विनियोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। मुद्रा-संकुचन को रोकने के लिए सरकार को देश में मुद्रा व साख की मात्रा का नियन्त्रण करना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के विनियोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। मुद्रा व साख को बढ़ाने के लिए बैंक-दर को कम कर देना चाहिए तथा केन्द्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी धंको को अधिक मात्रा में साख का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किन्तु अनुभव यह बतलाता है कि किसी देश को अवसाद काल से बाहर निकालने के लिए मौद्रिक उपाय अधिक सफल नहीं होते हैं। व्यवसायिक निराशावाद के कारण विनियोग की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। केवल सूद की दर को कम कर देने से विनियोग नहीं बढ़ता है इसलिए लार्ड केन्स (Keynes) ने यह सुझाव दिया कि अर्थ-व्यवस्था में गति उत्पन्न करने के लिए सरकार को स्वयं विनियोग करना चाहिए और सार्वजनिक हित के कामों को अपने हाथ में लेना चाहिए। इस प्रकार सरकारी विनियोग के द्वारा मुद्रा-संकुचन को रोकने में काफी सहायता मिल सकती है। सरकार को करो की मात्रा कम कर देनी चाहिए जिससे लोगों के पास अधिक क्रय-शक्ति बच सके और जिनके द्वारा वे वस्तुओं की अधिक मांग करें। सार्वजनिक ऋणों की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। घाटे के बजट अवसाद को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सरकार को लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए तथा रोजगार को बढ़ाने के लिए नव्य विनियोग करना चाहिए। नई निर्माण योजनाओं पर तथा जनहित कार्यों में अधिक व्यय किया जाना चाहिए। इसके अनिर्दिष्ट आयातों को कम करन तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने से भी अवसाद की दशाओं पर नियन्त्रण करने में सहायता मिलती है।

मुद्रा-प्रसार तथा आर्थिक विकास—

आजकल अल्प विकसित देशों में मुद्रा-प्रसार को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। अल्प विकसित देशों में प्रायः पूँजी कम होने के कारण आर्थिक विकास की योजनाओं को कार्य रूप में लाना सम्भव नहीं होता है जिसके कारण इन देशों के बहुत से साधन बेकार पड़े रहते हैं। वर्तमान अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार इन देशों में नियन्त्रित मुद्रा प्रसार की नीति को अपनाकर इन बेकार साधनों को काम में लाया जा सकता है। यदि नव निर्मित मुद्रा का प्रयोग बेकार साधनों को काम में लाने के लिए किया जाता है तो कुछ समय पश्चात् देश में उत्पादन बढ़ने लगता है और मुद्रा-प्रसार स्वयं ठीक हो जाता है। प्रो० लेविस (Lewis) के अनुसार 'आर्थिक विकास के लिए किया जाने वाला मुद्रा-प्रसार स्वयं ठीक होने वाला (Self-correcting) होता है जिससे इन देशों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।

यद्यपि सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली नई मुद्रा स्वयं पूँजी नहीं होती है किन्तु वह पूँजी के निर्माण में सहायता दे सकती है क्योंकि उसके द्वारा बेकार साधनों को उत्पत्ति कार्य में लगाया जा सकता है। इस प्रकार देश में पूँजी-गत वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा-प्रसार समाज में पूँजी के संचय में भी सहायता देता है क्योंकि उसके द्वारा देश में बचत की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा-प्रसार समाज में धन के वितरण को उन लोगों के पक्ष में करता है जिनमें बचत करने की आदत अधिक होती है। वस्तुओं के मूल्य कम होने के कारण सामान्य उपभोक्तृओं को अनिवार्य रूप से उपभोग कम करना पड़ता है। उत्पादक तथा व्यवसायिकों को अधिक लाभ मिलते हैं जिसका अधिक भाग वे बचाते हैं और इस प्रकार समाज में पूँजी का संचय अधिक होता है। किन्तु यह तब ही सम्भव होता है जब मुनाफा प्राप्त करने वाले वर्ग के व्यय को बढ़ने दिया जाय और उन्हें अतिरिक्त लाभ को बचाने के लिए प्रोत्साहन दिये जायें।

आर्थिक विकास के लिए मुद्रा-प्रसार का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक मुद्रा-प्रसार आर्थिक विकास के आधार को समाप्त कर देता है। आर्थिक विकास के लिए मुद्रा-प्रसार को प्रयोग करने समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

(१) मुद्रा की मात्रा को धीरे-धीरे तथा नियमित गति से बढ़ाना चाहिए।

(२) नवनिर्मित मुद्रा का प्रयोग केवल उत्पादक कार्यों में ही किया जाना चाहिए और उसे वर्तमान उपभोग पर व्यय नहीं करना चाहिए।

(३) नव-निर्मित मुद्रा को उत्पादन सम्बन्धी ऐसी योजनाओं में लगाना चाहिए जिनसे नया उत्पादन बोल प्राप्त किया जा सके।

(४) विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों के द्वारा सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना चाहिए।

(५) अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डार सरकार के पास काफी मात्रा में होने चाहिए जिससे कि वह इन वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोक सकें।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) मुद्रा-स्फीति किसे कहते हैं ? इसके प्रभावों की विवेचना कीजिये। इसे कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है ? (आगरा बी० ए० १९६२)
- (२) "मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण तथा असमतापूर्ण है और मुद्रा-स्फीति अनुपयुक्त है।" इस कथन की विवेचना कीजिये।
(आगरा बी० ए० १९६१, विक्रम बी० ए० १९६०, जबलपुर बी० काम १९५५, गोरखपुर बी० काम १९५६)
- (३) मुद्रा के मूल्य परिवर्तन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ? इस पर प्रकाश डालें। (आगरा बी० ए० १९६०)
- (४) मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन में क्या अन्तर है ? स्पष्ट कीजिए। देश की आर्थिक उन्नति के लिए किन-किन परिस्थितियों में मुद्रा-प्रसार लाभदायक हो सकता है ? (आगरा बी० ए० १९५८)
- (५) "मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का उत्पादन और वितरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है और यह परिवर्तन अधिक सामाजिक महत्व रखते हैं।" व्याख्या कीजिए। (आगरा बी० ए० १९५७)
- (६) मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (आगरा बी० काम १९६०)
- (७) मुद्रा-स्फीति किसे कहते हैं ? किन परिस्थितियों में और किस सीमा तक इसे उचित माना जा सकता है ? (आगरा बी० काम० १९५६ स)
- (८) ऐसा किम प्रकार हो सकता है कि सरकार अधिक मुद्रा की निकासी करके भी कीमतों की वृद्धि को रोक सके ? (राजस्थान बी० ए० १९६०)
- (९) मुद्रा-प्रसार को वरारोपण का सबसे बुद्धि रूप क्यों समझा जाता है ? स्पष्ट कीजिए। (बिहार बी० ए० १९५६)
- (१०) मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन लाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इन परिवर्तनों को कम से कम करने के लिए आप क्या करेंगे ?
(बिहार बी० काम १९५६)
- (११) "घाटे की ग्रंथ प्रबन्ध से मुद्रा-प्रसार होता है।" आप मुद्रा-प्रसार पर कैसे नियन्त्रण कर सकते हैं ? (पटना बी० ए० १९५७)

मुद्रा के मूल्य में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के स्थिर न रहने के कारण, मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन होते हैं और उसका मूल्य बदल जाता है। मुद्रा के मूल्य में होने वाले इन परिवर्तनों का हमारे आर्थिक व सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके कारण देश में उत्पत्ति की मात्रा, रोजगार का स्तर तथा धन का वितरण बदलता रहता है। देश में वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पन्न की जायगी तथा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा और उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को कितना रोजगार मिलेगा, यह सब कुछ मूल्य-स्तर की स्थिति पर निर्भर होता है। मूल्य-स्तर के बदलने पर धन का उत्पादन तथा वितरण दोनों ही बदलते हैं। पूँजीवादी समाज में तो मूल्य-यन्त्र उत्पादन की प्रवृत्ति तथा मात्रा को निर्धारित करने वाली शक्ति होता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों की प्रवृत्ति का अध्ययन किये बिना ऐसे समाज में उत्पादन सम्बन्धी निर्णय करना असम्भव होता है। मुद्रा के मूल्य परिवर्तन के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का सही-सही अनुमान लगाने के लिए हमें मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न समय में मुद्रा की क्रय-शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करके ही हम किसी देश की सही आर्थिक दशा को जान सकते हैं तथा आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते हैं और उस देश के लिए उचित आर्थिक नीति का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को नापना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति पर आधारित होता है और सामान्य मूल्य-स्तर के बदलने पर बदलता रहता है। मूल्य-स्तर के बढ़ जाने पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है और उसके घटने पर बढ़ जाता है। इसलिए मुद्रा के मूल्य को नापने

के लिए हमें सामान्य मूल्य-स्तर का अध्ययन करना होता है। सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन ही मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को सूचित करते हैं। मुद्रा के मूल्य को जानने के लिए हमें सामान्य मूल्य-स्तर ज्ञात होना चाहिए। किन्तु किसी भी समय पर मूल्य स्तर का जानना आसान नहीं है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य विभिन्न दिशाओं में बदलते रहते हैं। सब वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में एक साथ तथा एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होते हैं। जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं तो अन्य कुछ वस्तुओं के मूल्य गिर सकते हैं और इस प्रकार यह परिवर्तन विविध दिशाओं में हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य एक-दूसरे की नीवता के साथ नहीं बदलते हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी के साथ बदलते हैं और कुछ के कम तेजी के साथ। इन सब भिन्नताओं के कारण सामान्य मूल्य-स्तर को नापना काफी कठिन हो जाता है और उसका सही-सही माप सम्भव नहीं है। यद्यपि व्यक्तिगत कीमतों के परिवर्तन प्रति-विरोधी हो सकते हैं किन्तु फिर भी इस प्रकार के परिवर्तनों में एक सामान्य प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की सामान्य प्रवृत्ति के द्वारा ही मूल्य-स्तर को नापा जा सकता है। मूल्य परिवर्तनों की इस केन्द्रीय प्रवृत्ति को निर्देशांक के द्वारा नाप सकते हैं। अतः निर्देशांक मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को नापने का एक-मात्र माधन है। निर्देशांक जब बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जब गिरता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

निर्देशांक मुद्रा के मूल्य का निपेक्ष (Absolute) माप प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनके द्वारा केवल मुद्रा के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों (Relative changes) को नापा जा सकता है तथा विभिन्न समय के मूल्य-स्तर की तुलना की जा सकती है। किसी निश्चित समय पर मूल्य-स्तर कितना है, इसे निर्देशांक के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है किन्तु वह किसी दूसरे समय की अपेक्षा कितना बढ़ गया है या कम हो गया है, इसे हम सूचक अंकों की सहायता से जान सकते हैं। मुद्रा के मूल्य का निपेक्ष माप सम्भव नहीं है और न उसकी कोई आवश्यकता ही है क्योंकि हम केवल किसी निश्चित काल में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ही जानना चाहते हैं। इन परिवर्तनों को निर्देशांकों के द्वारा नापा जा सकता है।

मुद्रा की क्रय-शक्ति को उन वस्तुओं के मूल्यों के द्वारा जाना जा सकता है जिन पर मुद्रा को सामान्यतः व्यय किया जाता है। किन्तु मुद्रा के बदले में खरीदी और बेची जाने वाली समस्त वस्तुओं के मूल्यों का अध्ययन करना सम्भव नहीं है। इसलिए उनमें से कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्यों का औसत निकाला जाता है। यह वस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए जिन पर लोग अपनी आय खर्च करते हैं। जिन वस्तुओं तथा सेवाओं पर मुद्रा को खर्च किया जाता है उनके मूल्यों के औसत

(Average) को मूल्य-स्तर (Price level) कहा जाता है और एक से अधिक वर्षों के मूल्य-स्तरों के समूह (Series of Price levels) को निर्देशांक कहते हैं। जब विभिन्न समय के मूल्य-स्तरों को एक तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जाये कि वे वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को सूचित कर सकें तो उन्हें निर्देशांक कहते हैं। चैंडलर (Chandler) के अनुसार “कीमतों का निर्देशांक आधार वर्ष की औसत कीमतों की ऊँचाई की तुलना में किसी अन्य समय पर उनकी ऊँचाई को प्रकट करने वाली सख्या होता है।”^१ इस प्रकार निर्देशांक के द्वारा हम किसी समय के मूल्य-स्तर की तुलना आधार वर्ष के मूल्य-स्तर के साथ करके यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में कीमतें आधार वर्ष की अपेक्षा कितनी बढ़ गई हैं अथवा कम हो गई हैं। निर्देशांक को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य परिवर्तनों को सूचित करने वाले सांख्यिकी औसत (Statistical Average) कहा जाता है। उनके द्वारा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है।

निर्देशांक के प्रकार (Types of Index Numbers)—

निर्देशांक विभिन्न उद्देश्यों को लेकर बनाये जाते हैं। उनके द्वारा हम केवल मुद्रा की क्रय-शक्ति को ही नहीं नापते हैं बल्कि उनकी सहायता से आर्थिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को नापा जा सकता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशांक का निर्माण किया जाता है जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) सामान्य मूल्य निर्देशांक (General Price Index)—इन निर्देशांकों का निर्माण मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के निर्देशांक को बनाने के लिए उन वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो लोगों के द्वारा सामान्यतः उपभोग की जाती हैं। विभिन्न वस्तुओं को उन पर व्यय की जाने वाली आय के अनुपात में भार दिया जाता है। इनका निर्माण करते समय, उपभोग की जाने वाली समस्त वस्तुओं को सम्मिलित करना सम्भव नहीं होता है, इसलिए इन्हें केवल प्रतिनिधि वस्तुओं के आधार पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार के निर्देशांक बनाते समय मुख्यतया थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बनाना काफी कठिन होता है और इनकी उपयोगिता भी सीमित होती है क्योंकि ये मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का सही अनुमान नहीं दे पाते हैं।

1 “An index number of prices = a figure showing the height of average prices at one time relative to their heights at some other time that is taken as base period”

—L. V. Chandler : An Introduction to Monetary Theory, P. 10.

(२) श्रमिकों के जीवन-निर्वाह व्यय निर्देशांक (Working class cost of living Index Numbers)—यह निर्देशांक मजदूरी के रहन-सहन के व्यय में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए बनाये जाते हैं। आजकल इस प्रकार के निर्देशांक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इनकी सहायता से हम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः इनका प्रयोग मजदूरी की दगों को रहन-सहन के व्यय के बराबर करने के लिए किया जाता है। रहन-सहन व्यय निर्देशांक बनाने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को लिया जाता है जिन पर श्रमिक वर्ग प्रायः अपनी आय खर्च करता है। विभिन्न वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। वस्तुओं के दिये जाने वाले भार किसी विशेषज्ञ-मण्डल द्वारा निश्चित किये जाते हैं। इन्हें बनाते समय फुटकर मूल्यों का प्रयोग किया जाता चाहिए।

(३) थोक कीमतों के निर्देशांक (Wholesale Price Index)—इस प्रकार के निर्देशांक वस्तुओं के थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए बनाये जाते हैं। इन्हें बनाने समय कच्चे माल, अर्ध-निर्मित वस्तुओं तथा तैयार माल के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को देश की अर्थ-व्यवस्था में उनके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भार दिया जाता है जो उत्पत्ति गणना (Production census) के आधार पर निश्चित किये जाते हैं। इन निर्देशांकों का प्रयोग भी मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने के लिए किया जाता है किन्तु इस कार्य के लिए वे पूर्णतया सतोषजनक नहीं होते हैं। वे केवल थोक मूल्यों के आधार पर बनाये जाते हैं जबकि उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को फुटकर मूल्य पर खरीदते हैं, इस लिए वे उपभोक्तानों के लिए मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नहीं बता सकेंगे हैं।

(४) औद्योगिक निर्देशांक (Industrial Index Numbers)—इन निर्देशांकों का प्रयोग देश की औद्योगिक स्थिति तथा विभिन्न उद्योगों की प्रगति को जानने के लिए किया जाता है। प्रायः विभिन्न उद्योगों की उत्पत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उन्हें बनाया जाता है। सर्वप्रथम आधार वर्ष में भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और फिर अन्य वर्षों की उत्पत्ति के आँकड़े इकट्ठा करते हैं। आधार वर्ष के उत्पादन को १०० मान कर अन्य वर्षों के उत्पादन की उसमें तुलना की जाती है। उत्पादन निर्देशांक में जितने प्रतिशत वृद्धि होती है उन्हीं अनुपात में उस उद्योग का उत्पादन बढ़ा है।

उपरोक्त प्रकार के निर्देशांकों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के निर्देशांक भी होते हैं जैसे घाय निर्देशांक, आर्थिक स्थिति के निर्देशांक, अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशांक इत्यादि। वास्तव में निर्देशांकों का प्रयोग प्रत्येक आर्थिक घटना के तुलनात्मक परिवर्तनों को नापने के लिए किया जा सकता है।

निर्देशांकों की निर्माण विधि

(Method of Constructing Index Number)—

सामान्य कीमतों के निर्देशांक का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है—

(१) आधार वर्ष का चुनाव (Selection of the Base Year)—सर्वप्रथम हमें एक ऐसे आधार वर्ष को निर्दिष्ट करना होता है जिसके साथ वर्तमान मूल्य-स्तर की तुलना की जाती है। निर्देशांक जिस उद्देश्य के लिए बनाये जा रहे हैं इस बात को ध्यान में रखकर ही आधार वर्ष का चुनाव करना चाहिए। आधार वर्ष सामान्य आर्थिक क्रियाओं का वर्ष होना चाहिए। वह वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक ऊँचे अथवा नीचे न हों। यह वर्ष युद्ध अथवा अन्य प्रकार की आर्थिक आपत्तियों का काल भी नहीं होना चाहिए। क्राऊथर (Crowther) ने आधार वर्ष के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है—“निर्देशांक के आधार वर्ष, जिसमें अन्य वर्षों की तुलना की जाती है, का वही महत्व है जो एक नक्शे में स्वीकृत रेखा (Datum Line) का होता है जिसके द्वारा अन्य ऊँचाइयों को स्पष्ट किया जा सकता है।”^२ क्योंकि आधार वर्ष के मूल्य अन्य वर्षों के मूल्य परिवर्तनों की तुलना का आधार होते हैं इसलिए उसके चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें आर्थिक क्रियाएँ सामान्य गति से चल रही हों। जहाँ तक सम्भव हो सके यह वर्ष मुद्रा-संकुचन (Deflation) के समाप्त होने के बाद तथा मुद्रा-प्रसार आरम्भ होने से पूर्व का वर्ष होता चाहिए। आजकल अधिकांश निर्देशांक बनाने के लिए १९२६ को आधार वर्ष माना जाता है क्योंकि वह वर्ष ऐसा वर्ष था जब अर्थ-व्यवस्था के ऊपर मंदी का प्रभाव समाप्त हो चुका था और तेजी का प्रभाव आरम्भ नहीं हुआ था। युद्धोत्तर काल में प्रायः १९५० को आधार वर्ष मान कर निर्देशांक बनाये जाते हैं।

(२) प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव (Selection of Representative Commodities)—निर्देशांक बनाने के लिए हमें कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं तथा सेवाओं को चुनना होता है। क्योंकि सब वस्तुओं के मूल्यों को लेकर निर्देशांक बनाना सम्भव नहीं है इसलिए कुछ ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को चुन लिया जाता है जो मुद्रा की क्रय-शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकें। इन वस्तुओं को चुनने से पूर्व हमें यह निश्चय करना होता है कि निर्देशांक किस वर्ग के लिए बनाये जा रहे हैं और उनका क्या उद्देश्य है। भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए हमें भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिनिधि

2 “Any period will do, but it is necessary to have some base in which later prices can be compared just as every map-maker must have a datum-line to which he can refer altitudes”

वस्तुओं को चुनना होता है। जिस वर्ग के लिए निर्देशांक बनाये जाने हैं उस वर्ग के लोग जिन वस्तुओं पर अपनी आमदनी को प्रायः खर्च करते हों, उन्हीं वस्तुओं में से प्रतिनिधि वस्तुएँ चुनी जानी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के खर्च में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए निर्देशांक बनाने हैं तो हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को लेना चाहिए जो श्रमिकों के द्वारा प्रयोग की जाती हो। हमें मोटरकार, पेट्रोल तथा कीमती फर्नीचर आदि के मूल्यों को इनमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

वस्तुओं के चुनाव सम्बन्धी समस्या यही पर समाप्त नहीं हो जाती है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी निश्चय करना होता है कि निर्देशांक बनाने के लिए कितनी प्रतिनिधि वस्तुएँ चुनी जायें? इस बारे में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि अधिक वस्तुओं के आधार पर बनाये गये निर्देशांक अच्छे होते हैं किन्तु बहुत अधिक समस्या में वस्तुओं को लेने से किसी विशेष लाभ की आशा नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रो० फिशर (Fisher) ने स्पष्ट रूप से लिखा है—'जब तक वस्तुओं की संख्या २० से अधिक न हो तब तक निर्देशांक कोई विशेष व्यवहारिक महत्व नहीं रखते हैं। यदि यह संख्या ५० तक हो तो और भी अच्छा है किन्तु ५० के पश्चात् वस्तुओं की संख्या अधिक करने से होने वाला लाभ मामूली होता है और २०० के पश्चात् तो संख्या बढ़ाने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।'^३ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निर्देशांक बनाने के लिए वस्तुओं की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम।

(३) वस्तुओं के मूल्यों को इकट्ठा करना (Collection of Prices)—प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव के पश्चात् हम इनके मूल्यों को इकट्ठा करना होता है। आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में इन वस्तुओं की मूल्य-सूची तैयार की जाती है। मूल्यों को इकट्ठा करने समय यह सवाल पैदा होता है कि थोक मूल्यों (Wholesale Prices) को लेकर निर्देशांक का निर्माण किया जाय अथवा पुटकर मूल्यों (Retail Prices) का प्रयोग किया जाय। सामान्यतः निर्देशांक को बनाने समय थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस प्रकार की मूल्य सूची इकट्ठा करना आसान होता है। अविकसित निर्देशांक थोक मूल्य के आधार पर ही बन होते हैं किन्तु उस प्रकार के निर्देशांक बहुत अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वे मुद्रा की

1 "Seldom are index numbers of much value unless they consist of more than 20 commodities, and 50 is much better. After 50, the improvement obtained from increasing the number of commodities is gradual and it is doubtful if the gain from increasing the number beyond 200 is ordinarily worth the extra trouble and expense."

—Irving Fisher The Making of Index Numbers, P. 340.

क्रय-शक्ति के होने वाले परिवर्तनों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। फुटकर मूल्यों (Retail Prices) के आधार पर बनाये गये निर्देशांक अधिक अच्छे होते हैं। किन्तु उन्हें बनाना बहुत कठिन होता है क्योंकि फुटकर मूल्यों का इकट्ठा करना आसान नहीं है। कौनसे मूल्यों को लेकर निर्देशांक बनाये जायें, यह इस बात पर निर्भर होता है कि वे किस उद्देश्य के लिए बनाये जा रहे हैं। मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को नापने वाले निर्देशांक बनाने समय थोक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु रहन-सहन व्यय सम्बन्धी निर्देशांक (Cost of Living Index Numbers) बनाने के लिए फुटकर मूल्यों (Retail Prices) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(४) औसत निकालना (Averaging)—प्रतिनिधि वस्तुओं को इकट्ठा करने के पश्चात् उनका औसत निकाला जाता है। इस सम्बन्ध में यह समस्या पैदा होती है कि कौन-सी विधि से औसत निकालने जायें क्योंकि औसत कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश निर्देशांक गणितात्मक औसत (Arithmetic Average) के आधार पर बनाये जाते हैं किन्तु कभी-कभी गुणोत्तर औसत (Geometric Average) का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अलग-अलग दशाओं में विभिन्न प्रकार के औसत का प्रयोग किया जाता है।

साधारण निर्देशांक की निर्माण विधि

(Construction of Simple Index Numbers)—

उपयुक्त सब बातों को निश्चित करने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिनिधि वस्तु के आधार वर्ष के मूल्यों को, प्रतिशत निकालने के लिए, १०० के बराबर कर लिया जाता है और उन सबको जोड़कर वस्तुओं की संख्या में भाग दे देते हैं। इस प्रकार आधार वर्ष के मूल्यों का गणितात्मक औसत (Arithmetic Average) आ जाता है जो आधार वर्ष का निर्देशांक होता है। आधार वर्ष का निर्देशांक प्रत्येक दशा में १०० आता है। इसके पश्चात् वर्तमान वर्ष के मूल्यों को लेकर उनके मूल्य-सम्बन्धी (Price Relatives) निकाले जाते हैं जो वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों को आधार वर्ष के मूल्यों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। मूल्य-सम्बन्धी निकालने की विधि इस प्रकार है—यदि सन् १९५० को आधार वर्ष माना जाता है और १९६४ के मूल्यों की उस वर्ष के मूल्यों के साथ तुलना करने के लिए निर्देशांक बनाने हैं तो प्रत्येक वस्तु के १९५० के मूल्य को १०० के बराबर मान लेते हैं और इन वस्तुओं के १९६४ के मूल्यों को उनके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ यदि १९५० में चावल का मूल्य ६०) रु० प्रति कुन्तल था तो उसे १०० के बराबर माना जाता है और १९६४ में उसका मूल्य १२०) रु० प्रति कुन्तल हो जाने पर उसे २०० के बराबर माना जाता है। इसे मूल्य-सम्बन्धी (Price Relatives) कहते हैं। इस विधि से सब वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों को उनके आधार वर्ष के मूल्यों के साथ सम्बन्धित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले सब वस्तुओं के मूल्य-

सम्बन्धियों (Price Relatives) को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं और वर्तमान वर्ष का औसत मूल्य-स्तर अथवा निर्देशांक निकल आता है। वर्तमान वर्ष के निर्देशांक की आधार वर्ष के निर्देशांक के साथ, तुलना करने से हमें मूल्य-स्तर में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का पता लग जाना है।

निर्देशांक बनाने की इस विधि को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

साधारण निर्देशांक (Simple Index Numbers)

वस्तु संख्या	प्रतिनिधि कीमतें	आधार वर्ष सन् १९५०		सन् १९६४	
		कीमतें	कीमत सम्बन्धी	कीमतें	कीमत सम्बन्धी
१	गेहूँ	२५ रु० प्रति कुन्तल	१००	१०० रु० प्रति कुन्तल	४००
२	बाजल	४० " "	१००	१२० " "	३००
३	दाल	३० " "	१००	६० " "	२००
४	कपड़ा	१ रु० प्रति मीटर	१००	२५० रु० प्रति मीटर	२५०
५	ईंधन	३ रु० प्रति कुन्तल	१००	६ रु० प्रति कुन्तल	२००
६	कृष	४० पैस प्रति लीटर	१००	६० पैस प्रति लीटर	१५०
			६००—६ =१००		१६००÷१ =२६६.७

कीमत परिवर्तन + १६६.७ प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका में पता चलता है कि आधार वर्ष (१९५०) का निर्देशांक यदि १०० या तो वर्तमान वर्ष (१९६४) का निर्देशांक २६६.७ है जो इस बात को बतलाना है कि १९६० में वस्तुओं का कीमत-स्तर १९५० के कीमत-स्तर की तुलना में १६६.७% बढ़ गया है और मुद्रा का मूल्य उन्नीस गुनात में कम हो गया है। हमारे ग्रन्थों में यह कहा जा सकता है कि १९६४ का कीमत-स्तर १९५० की अपेक्षा ढाई गुना से कुछ अधिक हो गया है।

साधारण निर्देशांक के दोष (Defects of Simple Index Numbers)—

साधारण निर्देशांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ठीक-ठीक नहीं बताते हैं और वे हमें धोखा दे सकते हैं। साधारण निर्देशांक का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्हें बनाने समय प्रत्येक वस्तु को समान महत्व (Equal Importance) दिया जाता है। किन्तु वास्तव में उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु व्यय की दृष्टि

से समान महत्व नहीं रखती है। कुछ वस्तुएँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ कम। उपभोक्ता सब वस्तुओं पर समान व्यय नहीं करता है। कुछ वस्तुओं पर वह अपनी आय का अधिक भाग खर्च करता है और कुछ पर बहुत कम। जिन वस्तुओं पर आय का अधिक भाग खर्च होता है उनके मूल्य में जरा सी वृद्धि होने पर उपभोक्ता के लिए मुद्रा की क्रय-शक्ति काफी कम हो जाती है क्योंकि अब इन वस्तुओं पर उसे अपनी आय का बहुत अधिक भाग व्यय करना पड़ता है। इसके दूसरी ओर जिन वस्तुओं पर आय का कम भाग व्यय किया जाता है उनके मूल्य में होने वाली वृद्धि उपभोक्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि उन पर दिया जाने वाला व्यय बहुत कम बढ़ना है। उदाहरणार्थ गेहूँ, चावल तथा कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के मामूली परिवर्तन, चाकलेट तथा आइसक्रीम जैसी कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बड़े परिवर्तनों की अपेक्षा हमें कम प्रभावित करते हैं। साधारण निर्देशांक इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें आवश्यक तथा कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को समान महत्व दिया जाता है। इसलिए साधारण निर्देशांक हमें मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का सही ज्ञान नहीं देते हैं। इस दोष को सभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers) बना कर दूर किया जा सकता है।

सभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers)—

यदि निर्देशांक बनाते समय प्रत्येक वस्तु को उसके महत्व के अनुसार भार (weight) दे दिया जाय तो इस विधि से अच्छे प्रकार के निर्देशांक का निर्माण किया जा सकता है। जब वस्तुओं तथा सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार भार (weight) देकर निर्देशांक बनाये जाते हैं तो उन्हें सभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers) कहते हैं। इस प्रकार के निर्देशांक मूल्य परिवर्तनों का अधिक अच्छा अनुमान दे सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं को भार (weight) देते समय हमें यह देखना होता है कि कौनसी वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का कितना भाग खर्च करता है। जिस वस्तु पर आय का जितना अधिक भाग व्यय किया जाता है वह उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होती है और उसे अधिक भार (weight) दिया जाता है। जिन वस्तुओं पर आय का कम भाग व्यय किया जाता है वे कम महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें कम भार दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को उन पर किये जाने वाले व्यय के अनुपात में भार (weight) दिया जाता है। उदाहरणार्थ गेहूँ तथा कपड़े पर लोग सामान्यतः अपनी आय का बहुत अधिक भाग व्यय करते हैं इसलिए निर्देशांक बनाते समय इनका अधिक महत्व होता है और इन्हें अधिक भार दिया जाता है। इसके दूसरी ओर तम्बाकू, चाय, नमक, चाकलेट आदि वस्तुओं पर आय का बहुत कम भाग व्यय किया जाता है इसलिए उन्हें कम भार (weight) दिया जाता है। सभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers) आगे दी हुई विधि से बनाये जाते हैं।

सभार निर्देशांक बनाने के लिए प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष के मूल्य को १०० के बराबर मान लेने है और फिर उस वस्तु के लिए निश्चित भार (weight) से इसे गुणा कर देने है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्य प्रतिशत तथा उनके भार के जो गुणनफल आते हैं उन्हें जोड़कर भार की कुल संख्या (total number of weights) में भाग दे देते हैं और इस प्रकार आधार वर्ष का निर्देशांक १०० या जाता है। इसके पश्चात् वर्तमान वर्ष के कीमत सम्बन्धी (price relatives) निर्वात लिए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक को उस वस्तु के भार (weight) से गुणा कर देते हैं। प्राप्त होने वाले मूल्य सम्बन्धियों तथा भार के गुणनफल (price relatives \times weights) को जोड़ दिया जाता है और उसे भार की कुल संख्या (total number of weights) में भाग दे देते हैं जिसमें वर्तमान वर्ष का निर्देशांक प्राप्त हो जाता है।

आगे पृष्ठ पर तालिका को देखने से पता चलता है कि १९६४ का सभार निर्देशांक ३१६.१३ जो इस बात का सूचक है कि १९६४ का मूल्य-स्तर १९५० की अपेक्षा २१६.१३ प्रतिशत बढ़ गया है जबकि आधार वर्ष निर्देशांक केवल १६६.७ प्रतिशत की ही वृद्धि दिखाना है। यह अस्ममानता इसलिए पाई जाती है क्योंकि व्यय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं का मूल्य कम महत्वपूर्ण वस्तुओं की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है।

निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ (Difficulties in the Construction of Index Numbers)—निर्देशांक की बनाते समय कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, जिन्हें दूर किये बिना मही निर्देशांक का निर्माण करना सम्भव नहीं होता है। इनमें से प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(१) आधार वर्ष को चुनने में कठिनाई—आधार वर्ष का चुनाव करने समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह वर्ष एक सामान्य वर्ष हो और उसमें किसी प्रकार की असामान्य घटनाएँ न घटी हो। जहाँ तक सम्भव हो सके एक औसत दर्जे का साल ही आधार वर्ष के तौर पर लिया जाना चाहिए। यदि आधार वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है तो ऐसी दशा में निर्देशांक मूल्य-स्तर के उतार-चढ़ाव को ठीक-ठीक सूचित नहीं कर सकेंगे। उदाहरणार्थ यदि हम आज के मूल्यों की तुलना युद्ध काल के ही किसी वर्ष में करते हैं तो हमें मालूम होगा कि मूल्य-स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, किन्तु यदि उनकी तुलना युद्ध से पूर्व के किसी सामान्य वर्ष के साथ की जाये तो ज्ञात होगा कि मूल्य-स्तर पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। मुद्रा के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा आधार वर्ष लेना चाहिए जो न तो तेजी का वर्ष हो और न मंदी का, बल्कि दोनों के बीच में पड़ता हो। इस प्रकार के आधार वर्ष का चुनाव काफी मुश्किल होता है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि कौन-सा साल तेजी का है, अथवा मंदी का है या सामान्य है।

संभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers)

वस्तु संख्या	वस्तुएँ	भार	आधार वर्ष सन् १९५०		सन् १९५४	
			कीमते	भार युक्त कीमत सम्बन्धी	कीमते	भार युक्त कीमत सम्बन्धी
१	गेहूँ	१०	२५ ६० प्रति कुन्तल	$१०० \times १० = १०००$	१०० ६० प्रति कुन्तल	$४०० \times १० = ४०००$
२	चावल	५	४० ६० प्रति लीटर	$१०० \times ५ = ५००$	१२० ६० प्रति कुन्तल	$३०० \times ५ = १५००$
३	दाल	१	३० ६० प्रति कुन्तल	$१०० \times १ = १००$	६० ६० प्रति कुन्तल	$३०० \times १ = ३००$
४	कपडा	४	१ ६० प्रति मीटर	$१०० \times ४ = ४००$	२.५० प्रति मीटर	$२५० \times ४ = १०००$
५	ईंधन	२	३ ६० प्रति कुन्तल	$१०० \times २ = २००$	६ ६० प्रति कुन्तल	$२०० \times २ = ४००$
६	दूध	१	४० ५० प्रति लिटर	$१०० \times १ = १००$	६० ५० प्रति लिटर	$१५० \times १ = १५०$
				२३००		७३५०
				$२३०० \div २३ = १००$		$७३५० \div २३ = ३१९.१३$

निर्देशांक

(२) प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव की कठिनाई—निर्देशाको की उपयोगिता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि कौनसी वस्तुओं को लेकर उन्हें बनाया गया है। जहाँ तक वस्तुओं की मर्यादा का सम्बन्ध है इस विषय में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है किन्तु अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने बनाये गये निर्देशाक मूल्य-स्तर का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं की मर्यादा न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम। क्योंकि यह वस्तुओं को लेकर निर्देशाक नहीं बनाये जा सकते हैं इसलिए उनमें से प्रतिनिधि वस्तुओं का एक समूह चुन लिया जाता है और इन वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर निर्देशाक बनाये जाते हैं। इस कार्य के लिए ऐसी वस्तुएँ चुनी जानी चाहिए जो किसी वर्ग विशेष के लिए मुद्रा की क्रय-शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकें।

प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव काफी कठिन काम है क्योंकि विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर अपनी भाव रखते हैं। एक वस्तु जो किसी एक वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण होनी है वही वस्तु दूसरे वर्ग के लिए महत्वहीन हो सकती है। उदाहरणार्थ मोटरकार तथा पेट्रोल व मूल्य में वृद्धि हो जाना अमीर वर्ग को काफी प्रभावित कर सकता है किन्तु श्रमिकों पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही वर्ग में भिन्न-भिन्न लोग अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं पर अपना धन व्यय करते हैं। माँस तथा मछली के मूल्य में होने वाले परिवर्तन माँस-हारी श्रमिकों के लिए मुद्रा की क्रय-शक्ति को बढ़ा देते हैं किन्तु शाकाहारी श्रमिकों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल यही नहीं बल्कि एक परिवार के विभिन्न सदस्य भी भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। वास्तव में तो हमें प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार के लिए अलग-अलग निर्देशाक बनाने चाहिए क्योंकि रजि, गिवाज तथा परिवार के आकार में काफी भिन्नता पाई जाती है। वस्तुओं को चुनते समय हम बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में एक ही प्रकार की वस्तुओं को लेकर निर्देशाक बनाये जाये। यदि इनमें भिन्नता रहती है तो निर्देशाको का महत्व समाप्त हो जाता है।

(३) मूल्यों को इकट्ठा करने में कठिनाई—प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्यों को इकट्ठा करने में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। सर्वप्रथम यह निश्चित करना होता है कि कौन-से मूल्यों को लेकर निर्देशाक बनाये जाये। थोक मूल्यों के आधार पर बनाये गये निर्देशाक उनमें विलुप्त भिन्न परिणाम देते हैं जो फुटकर मूल्यों के आधार पर बनाये गए निर्देशाको में प्राप्त होते हैं। सामान्यता निर्देशाकों को बनाने के लिए थोक मूल्यों (Wholesale Prices) का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। किन्तु अस्वाभाविक उपभोक्ता वस्तुओं को फुटकर मूल्य पर ही खरीदते हैं, इसलिए थोक मूल्यों के आधार पर

बनाये गए निर्देशांक मुद्रा की कय-शक्ति को ठीक-ठीक नहीं माप सकते हैं। आजकल फुटकर मूल्यों के आधार पर निर्देशांक बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है। कीमतों को इकट्ठा करने में भी हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि फुटकर मूल्य लिए जाने हैं तो सभी वस्तुओं के फुटकर मूल्य लिए जाने चाहिए। कुछ वस्तुओं की कीमतें थोक बाजार में और कुछ की फुटकर बाजार से नहीं लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की कीमतें किसी विश्वमनीय जगह अथवा मम्बा से लेनी चाहिए।

(४) भार देने की कठिनाई (Difficulty in Giving Weights)—मभार निर्देशांक को बनाने के समय विभिन्न वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार देना काफी कठिन होता है। उपभोग में किसी भी वस्तु के महत्व को निश्चित करना आसान नहीं है। यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि किस वस्तु को कितना भार (weights) दिया जाये। एक ही वस्तु एक वर्ग के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है और दूसरे वर्ग के लिए कम महत्वपूर्ण। उदाहरणार्थ खाद्य सामग्री पर किया जाने वाला व्यय भूमिक वर्ग के बजट (Budget) में अधिक महत्व रखता है और अमीर वर्ग के लिए कम। इस प्रकार एक ही वस्तु को अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग भार (weight) देना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का महत्व निरन्तर बदलता रहता है। एक समय में जो वस्तुएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, दूसरे समय में वे ही कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए वस्तुओं को दिये जाने वाले भार (weights) में समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। इन सब सावधानियों के होते हुए भी विभिन्न वस्तुओं को दिये जाने वाले भार केवल अनुमानजनक ही हो सकते हैं। यही कारण है कि मभार निर्देशांक (Weighted Index Numbers) का प्रयोग कम किया जाता है।

(५) विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग की जा सकती हैं—समय के साथ लोगों की उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन हो जाने के कारण निर्देशांक का निर्माण करने में काफी कठिनाई होती है। निर्देशांक बनाते समय हमें आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में एक ही प्रकार की वस्तुओं को लेना चाहिए किन्तु कई बार ऐसा करना सम्भव नहीं होता है। जब गुनना का समय लम्बा होना है तो इस बीच में लोगों के उपभोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ बिल्कुल नई वस्तुएं उपभोग की जाने लगती हैं तथा पुरानी वस्तुओं का उपभोग घट हो जाता है। एक ही परिवार जो पहले चाय के विषय में जानता भी नहीं था वही आज चाय का आदी हो सकता है। उसी प्रकार लोग नुद घी के स्थान पर बेजिटेबिल घी का प्रयोग आरम्भ कर सकते हैं। ऐसी दशा में प्रथम बात में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य का औसत वर्तमान काल में मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को सूचित नहीं कर सकेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रो० मार्शल ने श्रृंखलाकारी निर्देशांक (Chain Index Numbers) के बनाने का सुझाव दिया

है। इस प्रकार के निर्देशांको में प्रत्येक वर्ष के मूल्यों की तुलना उससे अगले वर्ष के मूल्यों के साथ की जाती है। इन निर्देशांको को केवल उन्ही वस्तुओं के आधार पर बनाया जाता है जो दोनों वर्षों में प्रयोग की जाती हो। प्रयोग में आने वाली नई वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ शृङ्खलाकारी निर्देशांको (Chain Index Numbers) में सन् १९०० के मूल्य-स्तर की तुलना १९०१ के मूल्य-स्तर के साथ की जाती है। इस तुलना के लिए केवल उन्ही वस्तुओं को लिया जाता है जो १९०० व १९०१ दोनों वर्षों में प्रयोग की जाती हो। सन् १९०१ में प्रयोग में आने वाली नई वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है। फिर इसी प्रकार १९०१ के मूल्य-स्तर की तुलना १९०२ के मूल्य-स्तर के साथ की जाती है। इस बार १९०१ में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को तो सम्मिलित कर लिया जाता है किन्तु १९०२ में प्रयोग में आने वाली नई वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है। सन् १९०२ के मूल्य-स्तर की तुलना १९०३ के मूल्य-स्तर के साथ की जाती है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। शृङ्खलाकारी निर्देशांको साधारण निर्देशांको की अपेक्षा कुछ अच्छे अवश्य होते हैं किन्तु ये उपर्युक्त कठिनाई को बहुत अधिक सीमा तक दूर नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कठिनाईयों के अतिरिक्त निर्देशांक बनाने समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी करने होते हैं। निर्देशांको का सही होना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होता है कि मूल्यों व औसत निकालने के लिए कौनसी विधि का प्रयोग किया गया है। औसत कई प्रकार के होते हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न रीतियों से निकाला जा सकता है। सामान्यतया निर्देशांक बनाने समय गणितात्मक औसत (Arithmetic Average) का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसे निकालने का तरीका बहुत सरल है। किन्तु इस प्रकार में बनाये गए निर्देशांक बहुत सन्तोषजनक नहीं होते हैं क्योंकि ये मूल्य-स्तर की कमी व दृढ़ि को आवश्यकता से अधिक दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस दोष को ज्यामैट्रिक औसत (Geometric Average) का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार से बनाये गए निर्देशांक मूल्य परिवर्तनों को आवश्यकता से कम दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के औसत (Averages) का प्रयोग करने की सलाह दी है। निर्देशांक बनाने समय यह निर्णय करना होता है कि कौनसे औसत का प्रयोग किया जाना चाहिए।

निर्देशांको के प्रयोग (Uses of Index Numbers)—

निर्देशांक हमारे आर्थिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को मापने का मुख्य यन्त्र माने जाते हैं। किसी भी आधुनिक सरकार को आर्थिक नीति (Economic policy) के निर्माण में वे बड़ी सहायता देने हैं। उनके बिना उचित आर्थिक नीति का निर्माण करना सम्भव नहीं है। निर्देशांको के द्वारा यह जाना जा सकता है

कि मुद्रा के मूल्य में कब और कितने परिवर्तन हुए हैं। उनकी सहायता से ही एक उचित मौद्रिक नीति का निर्माण किया जा सकता है। देश में उत्पादन सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञान भी उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। वे श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी निर्धारण करने में सहायता देते हैं। उनके द्वारा ही देश में ठीक प्रकार की कर नीति (Tax Policy) का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार निर्देशांक आज के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्थिक नियोजन (Economic Planning) के लिए निर्देशांक का प्रयोग अनिवार्य है। उनके बिना आर्थिक नियोजन तथा दीर्घकालीन आर्थिक नीति का निर्माण सम्भव नहीं है। मुख्यतः निर्देशांक के निम्नलिखित प्रयोग हो सकते हैं—

(१) मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नापना—सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। उनके बढ़ने व घटने से मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। निर्देशांक के अध्ययन के द्वारा यह जाना जाता है कि मुद्रा की क्रय-शक्ति में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। जिस अनुपात में निर्देशांक में वृद्धि होती है ठीक उसी अनुपात में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि निर्देशांक घटता है तो मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तन समाज के आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। निर्देशांक की सहायता से इन परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करके ही उचित मूल्य सम्बन्धी नीति का निर्माण किया जा सकता है।

(२) विभिन्न समय में किसी वर्ग विशेष की आर्थिक स्थिति की तुलना—रहन-सहन व्यय सम्बन्धी निर्देशांक (Cost of Living Index Numbers) की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन-सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। निर्देशांक की तुलना के द्वारा यह जाना जा सकता है कि किसी निश्चित काल में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। यदि हम केवल यह बतलाया जाता है कि श्रमिकों की मजदूरी मन् १९३९ की अपेक्षा दुगुनी हो गई है तो हम इसके आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि श्रमिकों की आय दुगुनी हो जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है किन्तु इस बारे में सही-सही अनुमान लगाने के लिए हमें उनकी वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को देखना होगा। केवल मौद्रिक आय किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति का सही सूचक नहीं हो सकती है। श्रमिकों की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को निर्देशांक के द्वारा जाना जा सकता है। यदि उन्ही काल में निर्देशांक १०० में बढ़कर ४०० हो जाता है तो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, मजदूरी दुगुनी होने पर

भी पहले की अपेक्षा खराब हो गई है और उनका रहन-सहन का स्तर गिर गया है। किन्तु यदि निर्देशांक १०० से बढ़कर केवल १५० हुआ है तो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधरी है और उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया है। निर्देशांक ही हमें किसी वर्ग की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को बताते हैं और वास्तविक आय ही किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति को नापने का ठीक आधार है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति तथा रहन-सहन की तुलना करते वें लिए भी निर्देशांक का प्रयोग किया जा सकता है।

(३) मजदूरी की दरों को रहन-सहन व्यय के अनुसार करना—सामाजिक न्याय की दृष्टि से मजदूरी की दर और रहन-सहन व्यय साथ साथ चलने चाहिए किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मजदूरी की दर रहन-सहन व्यय से प्रायः पीछे रह जाने की प्रवृत्ति रखती है। जब मूल्य-स्तर बढ़ता है तो मजदूरी उस तेजी के साथ नहीं बढ़ती है। इस असमानता को दूर करने के लिए मजदूरी में वृद्धि की जाती है अथवा महंगाई भत्ता दिया जाता है। मजदूरी की दरों को कितना बढ़ाया जाय, यह हम निर्देशांक की सहायता से जान सकते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से रहन-सहन व्यय निर्देशांक जिस अनुपात में बढ़ता है मजदूरी की दरों को उसी अनुपात में बढ़ा देना चाहिए और जब वह घटता है तो मजदूरी को उसी अनुपात में घटा देना चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक जीवन में यह समता प्राप्त नहीं की जा सकती है किन्तु जहाँ तक सम्भव हो सके मजदूरी और रहन-सहन व्यय के अन्तर को कम से कम रहना चाहिए। ऐसा करने में निर्देशांक हमारी बहुत सहायता करते हैं।

(४) ऋणों के म्यापवूरां भुगतान करने का आधार—मूल्य-स्तर के बढ़ने के कारण या तो ऋणों अथवा ऋणदाता को हानि होती है किन्तु सामाजिक न्याय की दृष्टि से इन दोनों में से किसी भी वर्ग को लाभ अथवा हानि नहीं होनी चाहिए। यह तब सम्भव हो सकता है जब मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ऋणों की मात्रा में भी परिवर्तन कर दिये जायें। यह निर्देशांक की सहायता से किया जा सकता है। जिस अनुपात में निर्देशांक की वृद्धि होती है उसी अनुपात में ऋणों की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए और जब निर्देशांक गिरता है तो ऋणों की मात्रा में भी कमी कर देनी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि सन् १९६६ में १०० र० का ऋण लिया गया था और उसका भुगतान १९६४ में किया जाता है जब निर्देशांक पहले की अपेक्षा बढ़कर पाँच गुणा हो गया है तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से ऋणों को १०० र० के स्थान पर ५०० र० वापस लौटाने चाहिए। किन्तु वास्तविक जीवन में ऋणों की मात्रा में इस प्रकार के परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिए प्रयोग—निर्देशांक की सहायता से विभिन्न प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ करना सम्भव है। विशेषतया यदि हम यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति में किसी निश्चित काल

में क्या परिवर्तन हुए है तो निर्देशांक हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि यह मात्तूम करना है कि युद्धकाल में इंग्लैंड के पौंड तथा भारतीय रुपये के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ है तो इस काल में इन देशों के निर्देशांकों की तुलना करके यह जाना जा सकता है। यदि इस काल में इंग्लैंड के निर्देशांक में जितनी वृद्धि हुई है उसकी अपेक्षा भारतीय निर्देशांक अधिक बढ़ा है तो वह इस बात को बतलाता है कि पौंड की अपेक्षा रुपये का मूल्य अधिक गिरा है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में लोगों के रहन-सहन की तुलना करने के लिए भी निर्देशांकों का प्रयोग किया जा सकता है।

(६) देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का अनुमान लगाना — उत्पादन सम्बन्धी निर्देशांकों से हम यह जान सकते हैं कि किन-किन उद्योगों का उत्पादन बढ़ रहा है और कौन-कौन से उद्योगों का उत्पादन घट रहा है। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर सरकार अपनी औद्योगिक नीति का निर्माण करती है। विदेशी व्यापार सम्बन्धी निर्देशांक हमें विदेशी व्यापार की स्थिति का ज्ञान कराते हैं। इसी प्रकार निर्देशांकों की सहायता से देश में पूँजी तथा विनियोग की मात्रा, व्यापारिक प्रवृत्तियों तथा लाभ व ध्याज सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रो० फिजर ने निर्देशांकों की उपयोगिता को बतलाते हुए कहा है “वस्तुओं का कीमत-स्तर स्थाई रखने तथा व्यापार में स्थिरता स्थापित करने के लिए निर्देशांक बहुत ही उपयोगी है। इनकी सहायता से आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्त सम्बन्धी सभी समस्याओं को समझने में आसानी होती है।”

निर्देशांकों की सीमाये (Limitations of Index Numbers)—

यद्यपि निर्देशांकों का प्रयोग आजकल बहुत अधिक होता है किन्तु फिर भी वे आर्थिक क्रियाओं का सही माप प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनके बनाने में चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न करती जाये किन्तु फिर भी हम उनके ऊपर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह सकते हैं। निर्देशांकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

(१) निर्देशांक मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का बिल्कुल सही माप प्रस्तुत नहीं करते हैं—मुद्रा की क्रय-शक्ति का सही माप असम्भव है। निर्देशांक बहुधा अनुमान-जनक होते हैं क्योंकि वे केवल सामान्य प्रवृत्ति की ओर सचेत करते हैं। राबर्टसन के अनुसार “मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को ठीक-ठीक नापना न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ही सम्भव है और न व्यवहार में। इतना अवश्य है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं और काफी सावधानी करती जाये तो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उसकी माप ठीक रीति से की जा सकती है।”^१ इसी प्रकार प्रो० मार्शल का विचार है कि,

१ “The conclusion then is that neither in practice nor perhaps in theory is it possible to measure accurately changes in the value of money.

“कृय-शक्ति का निश्चित माप केवल असम्भव ही नहीं है बल्कि अविचारणीय भी है।”^२ अतः सूचक अथवा मुद्रा की कृय-शक्ति को ठीक-ठीक नहीं माप सकते हैं।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना करना कठिन होता है—निर्देशांक की सहायता से दो देशों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तुलना करना काफी कठिन है क्योंकि निर्देशांक की निर्माण विधि, उनका आचार वषं तथा प्रतिनिधि वस्तुओं की सूची विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होती है। अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए एक ही आधार वषं तथा एक ही प्रकार की प्रतिनिधि वस्तुओं को लेकर एक ही विधि से बनाये गये निर्देशांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। किन्तु व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार के निर्देशांक का निर्माण करना सम्भव नहीं होता है।

(३) विभिन्न समय में तुलना करना कठिन होता है—निर्देशांक की सहायता से विभिन्न समय की आर्थिक दशाओं की तुलना करना इसलिए सम्भव नहीं होता है क्योंकि लोगों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपभोग बन्द हो जाता है तथा कुछ शिल्कुल नई वस्तुएँ उपभोग में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों समय में एक ही प्रकार की वस्तुओं को लेकर तुलना करना सम्भव नहीं है।

(४) निर्देशांक केवल वर्ग विशेष के लिए ही मूल्य परिवर्तनों को माप सकते हैं—उनके द्वारा सामान्य मूल्य-स्तर का माप सम्भव नहीं है। एक वर्ग के लिए बनाये गये निर्देशांक दूसरे वर्ग के लिए वैध नहीं होते हैं। जिस उद्देश्य के लिए निर्देशांक बनाये जाते हैं वे केवल उसी उद्देश्य के लिए काम में आ सकते हैं उन्हें अन्य उपयोगों में लाना सम्भव नहीं होता है। सम्पूर्ण समाज के लिए परिवर्तनों को मापने के लिए निर्देशांक नहीं बनाये जा सकते हैं।

(५) भार निर्धारण अवैज्ञानिक होता है—भार निर्देशांक बनाने के लिए विभिन्न वस्तुओं को जो भार दिये जाते हैं वे प्रायः काल्पनिक होते हैं। वस्तुओं को भार देने का कोई भी वैज्ञानिक तरीका अभी तक मालूम नहीं हो सका है जिसके कारण एक ही प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न विशेषज्ञ अलग-अलग भार देने की प्रवृत्ति रखते हैं। भार निर्धारण अवैज्ञानिक होने के कारण इस प्रकार के निर्देशांक की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। वस्तुओं को दिये जाने वाले भार में भिन्नता हो जाने से निर्देशांक भिन्न-भिन्न परिणाम देने हैं। अतः उनके आधार पर निकाले गये परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं।

Nevertheless there is no doubt that the value of money does change, and, if sufficient care is taken, measures accurate enough for some practical purposes can be found and used.”
—Robertson, D. H. Money, P. 27

2 “A perfectly exact measure of purchasing power is not only unattainable but even unthinkable.”
—Marshall

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि निर्देशांक बहुत उपयोगी तथा आवश्यक है किन्तु फिर भी उनका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए अन्यथा वे हमें गलत निर्णयों पर ले जा सकते हैं। निर्देशांक का प्रयोग आँख बन्द करके नहीं किया जा सकता है किन्तु यदि उनका सही निर्माण किया जाता है और उनका प्रयोग सावधानी से होना है तो वे आर्थिक क्रियाओं को नापने का एक सुविधाजनक यन्त्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि उनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को बहुत सही-सही नहीं माप सकते हैं किन्तु किसी अन्य सही माप की अनुपस्थिति में उनका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। वे मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को नाप कर हमें मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के निर्धारण में सहायता दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में हॉलम (Halm) का विचार है कि “कीमत-स्तर और निर्देशांक जिनके द्वारा उसे सुविधापूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है, मुद्रा नीति के कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।”³ मुद्रा नीति के प्रतिरिक्त वे हमें अन्य प्रकार की आर्थिक नीतियों जैसे जनसंख्या, ऋण, उद्योग, कृषि तथा मूल्यों सम्बन्धी नीति के निर्माण में भी सहायता देने ह। एक नियोजित समाज (Planned Society) में तो उनका महत्व और भी अधिक है। विभिन्न प्रकार के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों को निश्चित करने, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समता स्थापित करने तथा अन्य प्रकार के सामाजिक व आर्थिक निर्णयों को लेने में वे हमें काफी सहायता दे सकते हैं। आज कोई भी समाज उनके बिना नियोजन नहीं कर सकता है। निर्देशांक हमारी आर्थिक क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों को नापने का महत्वपूर्ण साधन बन गये हैं। उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनका निर्माण अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाय और उनके निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों को यथासम्भव दूर कर दिया जाये।

3 'Price levels and index numbers by means of which they are conveniently expressed, can be useful for some purposes of monetary policy.'

—Halm . Monetary Theory, p 95.

परीक्षा-प्रश्न

- (१) निर्देशांक क्या है ? उसके क्या लाभ हैं ? सरल निर्देशांक की एक सारिणी बनाइये ।
(आगरा बी० ए० १९६१)
- (२) साधारण निर्देशांक क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है ? निर्देशांकों के प्रयोगों को बतलाइये ।
(आगरा बी० ए० १९५४)
- (३) एक साधारण निर्देशांक और समार निर्देशांक में अंतर बतलाइये । निर्देशांकों का महत्व क्या है ?
(आगरा बी० कॉम १९६०)
- (४) निर्देशांक बनाने के उद्देश्य तथा तरीके का वर्णन कीजिए । 'समार सूचक अंक' क्या होते हैं और उन्हें क्यों बनाया जाता है ?
(आगरा बी० कॉम १९५७)
- (५) निर्देशांकों के लाभ क्या हैं ? निर्देशांक कैसे बनाये जाते हैं ?
(राजस्थान बी० ए० १९६०)
- (६) सूचनाकों के बनाने में भार देने के उद्देश्यों एवं महत्व का विवेचन करिए । इसके निर्माण की विधि को भी ससझाइये । (राजस्थान बी० कॉम १९५८)
- (७) सूचनांक से श्राप क्या समझते हैं ? यह कैसे बनाये जाते हैं ? श्रायिक समस्याओं के अध्ययन में इनके उपयोगों पर प्रकाश डालिये ।
(सागर बी० ए० १९५८)
- (८) निर्देशांक किस प्रकार बनाये जाते हैं ? इनके निर्माण की कठिनाइयों को बतलाइये ।
(सागर बी० कॉम १९५९)
- (९) मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार नाये जाते हैं । सूचनांक प्रणाली में क्या दोष हैं ? किसी सीमा तक इन्हें सुधारा जा सकता है ?
- (१०) सूचनांक क्या होता है ? सरल सूचनांक की एक सारिणी बनाइये । ऐसी सारिणी बनाते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए ?
(विक्रम बी० ए० १९६०)



भारतीय मुद्रा का इतिहास

HISTORY OF INDIAN CURRENCY

भारतीय मुद्रा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतवर्ष में मुद्रा का प्रयोग काफी प्राचीन काल से होता आया है। प्राचीन हिन्दू राजाओं के काल में ही धात्विक सिक्कों का निर्माण तथा उनका प्रयोग आरम्भ हो गया था। मुगल-काल में धात्विक मुद्रा का प्रयोग काफी विस्तृत रूप से किया जाने लगा तथा सिक्कों की निर्माण विधि में बहुत सुधार किये गये किन्तु वर्तमान मुद्रा का इतिहास ब्रिटिश काल से ही आरम्भ होता है। अकबर के समय से उत्तरी भारत में सोने की मोहर तथा चाँदी का रुपया चलता था और दोनों का वजन १७५ ग्रेन होता था। इनके अतिरिक्त तांबे का सिक्का (दाम) भी चलन में रहता था और सोने व चाँदी के सिक्के एक निश्चित दर पर 'दाम' के भाव बदले जाते थे। दक्षिण भारत में स्वर्ण मुद्रा का अधिक प्रचलन न था क्योंकि वहाँ पर कभी भी मुगलों का पूर्ण शासन स्थापित नहीं हो सका। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् समस्त देश में बहुत से छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य बन गये जिन्होंने अपने अलग-अलग सिक्के जारी कर दिये। इन सिक्कों का वजन तथा शुद्धता बिल्कुल भिन्न होती थी। उस समय देश में लगभग ६६४ प्रकार के विभिन्न वजन तथा शुद्धता वाले सोने व चाँदी के सिक्के चलन में थे।

रजतमान (Silver Standard) १८३५-१८६८—

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम अपने आधीन क्षेत्रों में चलने वाली मुद्राओं में अनुसूचता लाने का प्रयत्न किया। सन् १८३५ में पहला करसी अधिनियम पार किया गया जिसके अन्तर्गत भारतवर्ष में रजतमान (Silver Standard) स्थापित कर दिया गया। कम्पनी ने निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले चाँदी के रुपये चलन में डाल दिये। सन् १८३५ में १८० ग्रेन वजन तथा $\frac{3}{4}$ शुद्धता वाला चाँदी का रुपया समस्त भारत में असीमित विधिग्राह्य घोषित कर दिया गया। चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण किया जाने लगा। चाँदी के रुपये के आन्तरिक मूल्य को उसके

साक्षेतिक मूल्य (Face Value) के बराबर रक्का जाता था। इस अधिनियम में आवश्यकता पड़ने पर सोने के सिक्कों को जारी करने की व्यवस्था भी की गई थी। सन् १८४१ में एक घोषणा के अनुसार सोने की मोहर को भुगतानों को निवटाने के लिए सरकारी खजानों में १५ १ के अनुपात में स्वीकार किया जाने लगा।

सन् १८७४ में चांदी के स्वर्ण मूल्य के गिर जाने के कारण रजतमान के चलाने में विशेष कठिनायियाँ उत्पन्न हो गईं। चांदी का उत्पादन घट जाने तथा उसकी मांग के कम हो जाने से चांदी का मूल्य बहुत अधिक गिर गया। यूरोप के देशों के द्वारा चांदी का निरुत्पन्न किये जाने के कारण भारतवर्ष में बहुत अधिक मात्रा में चांदी आने लगी। विभिन्न देशों से यह सुभाव रक्का गया कि चांदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया जाय किन्तु १८७८ तक सरकार ने इस प्रकार के सुभावों को मानन में इन्कार कर दिया। सन् १-७८ में सरकार ने यह सुभाव रक्का कि स्वर्णमान को स्थापित करने के लिए कुछ निश्चित बंदम उड़ाये जायें किन्तु संसदी आफ स्टेट फॉर इण्डिया ने इस सुभाव को मानन में इन्कार कर दिया। चांदी का मूल्य निरन्तर गिरता गया जिसके कारण भारतीय रुपये की स्थिति और अधिक खराब हो गई। सन् १८७३ से लेकर १८८२ तक चांदी का मूल्य लगभग ४०% कम हो गया। इसका भाग्य की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ा। चलन में सिक्कों की मात्रा घट जाने के कारण मूल्य-स्तर में वृद्धि होने लगी। भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य गिर कर केवल १ शिलिंग ३ पैसे रह गया जिसका विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

सन् १८८२ में मुद्रा तथा विनिमय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार ने हर्शेल कमेटी (Herschell Committee) नियुक्त की। इस कमेटी के सुभाव पर भारतीय सरकार ने १८८३ में एक अधिनियम के द्वारा चांदी व सोने की स्वतन्त्र डलाई बन्द कर दी यद्यपि सरकार स्वयं आवश्यकता के अनुसार चांदी के रुपये जारी रख सकती थी। कमेटी ने यह सुभाव दिया कि रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शिलिंग ४ पैसे पर निश्चित कर दिया जाय और उसे चांदी के मूल्य से स्वतन्त्र रक्का जाय। भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को बढ़ाने के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया गया, जिसके कारण देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो गई। एकमात्र पर सोने के बदले में १ शिलिंग ४ पैसे की दर पर चांदी के रुपये देन की व्यवस्था की गई। सरकार ने करो तथा अन्य प्रकार के भुगतानों के रूप में सोने के सिक्कों को लेना आरम्भ कर दिया। यह सब कुछ भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में वृद्धि करने, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने तथा लोगों को सोने के सिक्कों के प्रयोग से परिचित करने के उद्देश्य से किया गया। इनके परिणामस्वरूप भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य बढ़ गया और १८८८ में उस सोने के साथ सम्बन्धित करना सम्भव हो सका।

स्वर्ण-विनिमय मान १८६८-१९२५—

सन् १८६८ में भारत सरकार ने पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस सम्बन्ध में मुभाव देने के लिए एक कमेटी सर हेनरी फाउलर (Sir Henry Fowler) की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। इस कमेटी ने भारतवर्ष में स्वर्णमान स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सिफारिशें की—

(१) भारतीय टकसालों पर सोने के सोवरेन तथा अर्ध सोवरेन (Sovereigns and half sovereigns) की स्वतन्त्र ढलाई आरम्भ कर दी जाय तथा चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया जाय।

(२) ब्रिटिश सोवरेन (Sovereign) को गारन में अपरिमित विधिग्राह्य घोषित कर देना चाहिए तथा सोवरेन की ढलाई और उसका प्रचलन इङ्ग्लैंड तथा भारत दोनों देशों में किया जाना चाहिए।

(३) रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शिलिंग ४ पैसे पर निश्चित कर दिया जाय।

(४) चाँदी का रुपया असीमित विधिग्राह्य रक्खा जा सकता है किन्तु यह केवल एक साकेतिक (Token) सिक्के के रूप में ही चलाया जाय।

(५) सरकार को एक निश्चित दर पर सोने के बदले में रुपये को देने की व्यवस्था को जारी रखना चाहिए किन्तु रुपयों के बदले में सोना देने के लिए सरकार को बाध्य नहीं होना चाहिए।

(६) चाँदी के मुद्रण में होने वाले लाभ को एक प्रथक स्वर्ण-कोष में जमा कर दिया जाय जो एक विशेष निधि (Special Reserve) का कार्य करेगा।

(७) जब व्यापार मतुलन विपक्ष में हो तो सरकार को निर्यात करने के लिए सोने का प्रवन्ध करना चाहिए।

सरकार ने फाउलर कमेटी की सभी सिफारिशों को मान लिया और मितम्बर सन् १८६९ में सोवरेन को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया। उसके साथ चाँदी के रुपये को भी असीमित विधिग्राह्य रक्खा गया। सन् १९०० में रुपये के मुद्रण से प्राप्त होने वाले लाभ में स्वर्णमान कोष स्थापित किया गया। यद्यपि फाउलर कमेटी ने भारत में स्वर्ण मुद्रामान स्थापित करने की सिफारिश की थी किन्तु ब्रिटिश ट्रेजरी ने शाही टकसाल की शाखा भारत में स्थापित करने में इनकार कर दिया जिसके कारण भारतवर्ष में केवल स्वर्ण विनिमय मान ही स्थापित हो सका। इस स्वर्ण विनिमय मान की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी—(i) देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं था और केवल बाणज के नोट तथा चाँदी की मुद्रा ही चलन में रक्खी गई। (ii) केवल विदेशी भुगतानों के लिए ही रुपया १ शिलिंग ४ पैसे की दर पर सोने में परिवर्तनीय था। (iii) स्वर्ण विनिमय मान को चलाने के लिए दो प्रकार के कोष रक्खे जाते थे। रुपये का कोष भारतवर्ष में रहता था

ग्रोर स्टर्लिंग कोष इन्डनैड में। (iv) रुपये का अधिकतम स्वर्ण मूल्य १९३३ पेंस तथा न्यूनतम मुद्रय १५३३३ पेंस निश्चित कर दिया गया। (v) रुपया सैकैनिक सिक्का होते हुये भी मूल्य गान का कार्य करता था।

फाउलर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्थापित स्वर्ण विनिमय मान की कड़ी आलोचना की गई क्योंकि इस मुद्रामान में रुपये के विदेशी मूल्य में तो स्थिरता स्थापित हो गई किन्तु कीमतों की स्थिर न रखी जा सका। इन घानोचनाओं पर विचार करने के लिए सरकार ने सन् १९१३ में चैम्बरलेन आयोग (Chamberlain Commission) नियुक्त किया जिसने १९१४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चैम्बरलेन आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थी—

(i) इस आयोग ने भारत में स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने की सिफारिश की और यह बतलाया कि स्वर्ण मुद्रा भारत के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि लोगों में उसे जमा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है।

(ii) भारत में स्वर्ण मुद्रा ढालन के लिए किसी प्रथक टक्काल की आवश्यकता नहीं है किन्तु उसक सीमित मुद्रण का प्रबन्ध बम्बई टक्काल पर किया जा सकता है।

(iii) मुद्रा प्रणाली को अधिक सौचदार बनाने के लिए कर्मागन ने मोटो के अरक्षित भाग (Fiduciary Issue) को बढ़ाने की सिफारिश की।

(iv) सरकार को १ मिलियन ५३३ पेंस प्रति रुपये के हिमाय से रिवर्स फाउन्डिल बिल (Reverse Council Bills) को बेचने की गारन्टी देनी चाहिए।

सन् १९१४ में विश्व-युद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार चैम्बरलेन आयोग की सिफारिशों को कार्य-रूप में नहीं ला सकी।

स्वर्ण विनिमय मान का पतन (१९१४-१८)

स्वर्ण विनिमय मान प्रथम युद्ध आरम्भ होने तक अच्छी प्रकार चलता रहा किन्तु १९१४-१८ के युद्ध काल में टूट गया। युद्ध के कारण लोगों का पत्र मुद्रा में विश्वास उठने लगा और भारी मात्रा में नोट बाँटने के रुपये में बदलने के लिए प्राप्तु किया जाने लगे। लोगों ने चाँदी तथा सोने के सिक्कों को भारी मात्रा में जमा करना आरम्भ कर दिया और पत्र मुद्रा के बढ़ने में रुपये के सिक्कों तथा सोने की माग बहुत अधिक बढ़ गई। ५ अगस्त १९१४ को सरकार ने प्रादेवत व्यक्ति को सोना देना बन्द कर दिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए स्वर्णमान स्थगित कर दिया गया। कुछ ही समय पश्चात् मुद्रा में जनता का विश्वास फिर से स्थापित हो गया। वाम्तविक कटिगार्ट १९१६ में आरम्भ हुई जिसके कारण स्वर्णमान निलुप्त हो गया। सरकार भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर को स्थिर नहीं रख सकी क्योंकि व्यापार मतुलन पक्ष में होने के कारण भारतीय रुपये की माग बहुत अधिक बढ़ गई थी। भारतीय निवर्तों का भुगतान करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

फॉर इण्डिया को बहुत बड़ी मात्रा में से काउन्सिल बिल्स (Council Bills) को बेचना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष में उसी अनुपात में चाँदी के मुद्रण को बढ़ाया गया। चाँदी की माग अधिक होने के कारण उसका मूल्य बाजार में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था। चाँदी का मूल्य जो १९१६ में ४३ पैसे प्रति औंस था बढ़कर १९२० में ८६ पैसे हो गया। अब लोगों के लिए चाँदी के रुपये को पिघला कर बेचना लाभपूर्ण हो गया था। सरकार को महंगे भाव पर चाँदी खरीद कर १ शिलिंग ४ पैसे की दर पर रुपया बेचना बहुत बठिन हो गया। इस कठिनाई को दूर करने करने के लिए सरकार ने रुपये की विदेशी विनिमय दर को घटा कर १ शि० ५ पैसे कर दिया और इस प्रकार स्वर्णमान टूट गया।

बैबिंगटन स्मिथ कमेटी (Babington Smith Committee)—

मुद्रा के पश्चात् भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने लगे। सरकार ने भारतीय मुद्रा प्रणाली की जाँच करने के लिए सन् १९१६ में बैबिंगटन स्मिथ कमेटी बैठाई। इस समिति ने भारत में स्वर्णमान स्थापित करने तथा रुपये की विदेशी विनिमय दर २ शि० पर निश्चित करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त वम्बई में सावरेन तथा अर्घ सोवरेन की ढलाई के लिए एक टक्काल स्थापित करने तथा सोने के आयात व निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने और व्यक्तिगत हिसाब में चाँदी का आयात करने की आज्ञा देने की सिफारिश भी की गई। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को मान लिया और फरवरी सन् १९२० में सोवरेन (Sovereign) को विविप्राप्त मुद्रा घोषित कर दिया गया। रुपये की विदेशी विनिमय दर को २ शि० पर स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया गया किन्तु उसमें सफलता न मिली। विदेशी विनिमय दर को स्थगन छोड़ दिया गया और वह १९२१ में गिर कर १ शि० ३३/४ पैसे हो गई। इसका व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा किन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया। सरकार की चुप रहने की नीति की कड़ी आलोचना की गई।

हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission)—

सरकार ने सन् १९२५ में करमी तथा विदेशी विनिमय की जाँच करने के लिए श्री हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस कमीशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) स्वर्ण विनिमय मान की कार्यप्रणाली की जाँच करना तथा देश में एक उचित मुद्रा प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करना, (ii) रुपये की विदेशी विनिमय दर को निश्चित करने के सम्बन्ध में सुझाव देना, (iii) चलन व बैकिंग पद्धति में सम्बन्ध स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करना तथा केंद्रीय बैंक को स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव देना। इस कमीशन ने भारत की मुद्रा प्रणाली को विस्तृत जाँच करने के पश्चात् जुलाई सन् १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सर्वप्रथम कमीशन ने भारत में प्रचलित स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-प्रणाली की जाँच की और उसमें निम्नलिखित दोषों को बतलाया—

(१) यह प्रणाली साधारण नहीं थी क्योंकि इसमें रुपये के मूल्य की स्थिरता का आधार सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इस प्रणाली में दो प्रकार की गणकेतिक मुद्रा (नोट तथा चाँदी का रूप) चलती थी जिनके कारण मुद्रा प्रणाली काफ़ी जटिल हो गई थी। उनमें से रजत मुद्रा के क्रिमी भी समय चलन के बाहर निकल जाने का भय रहता था। साधारण व्यक्ति इस प्रणाली को नहीं समझ सकता था क्योंकि इसकी कार्य-विधि कॉमिल बिलो और रिबरम कॉमिल बिलो के क्रय-विक्रय पर आधारित थी।

(२) इस प्रणाली में लोच का अभाव था और मुद्रा के विस्तार तथा सङ्कुचन स्वयं नहीं होता था। इस मुद्रा प्रणाली में सरकारों हस्तक्षेप भी बहुत अधिक रहता था।

(३) मोने का स्वतन्त्र आयात व निर्यात न होने के कारण विनियम दूरों में अपने आप ठीक होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी।

(४) इस प्रणाली में अनावश्यक तौर पर दो प्रकार के कोष रखने पड़ते थे। पत्र मुद्रा कोष भारत में रखा जाना था और स्वर्णमान कोष लन्दन में रहता था जिनके कारण बहुत-सा सोना कोषों में बेकार पड़ा रहता था।

(५) इस प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भारत को इङ्गलैंड पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि रुपये का मूल्य सोने के साथ सम्बन्धित न होकर स्टलिंग के साथ सम्बन्धित था। इङ्गलैंड के आर्थिक परिवर्तनों का अभाव भारतीय मुद्रा की स्थिरता पर पड़ता था।

उपयुक्त दोषों के कारण हिटन यंग कमीशन ने स्वयं विनियम मान को भारत के लिए अनुपयुक्त बताया। कमीशन की राय में स्वर्ण मुद्रामान भी इस देश में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए भारत में पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं था तथा इस प्रणाली में सोने का बहुत अधिक अप्रत्यक्ष होने की सम्भावना थी। आयोग का विश्वास था कि बिना सोने के सिक्के चलाने हुए भी स्वर्णमान स्थापित किया जा सकता है। कमीशन ने स्वयं विनियम मान तथा स्वर्ण मुद्रामान की आलोचना करने के पश्चात् भारत में स्वर्ण धातुमान स्थापित करने का सुझाव दिया। हिटन यंग कमीशन की निष्कारिशी निम्नलिखित थी—

(१) कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत में प्रचलित स्वर्ण विनियम मान को समाप्त कर देना चाहिए और मुद्रा में अनुराग का विश्वास पैदा करने के लिए मुद्रा तथा सोने में वास्तविक और मद्दत सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कमीशन ने इङ्गलैंड के नमूने पर भारत में स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard) स्थापित करने की सिफारिश की क्योंकि इस प्रणाली में सोने के सिक्के का चलन न होने हुए भी मुद्रा को प्रत्यक्ष रूप में सोने के साथ

सम्बन्धित रखा जा सकता था। कमीशन के द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण धातुमान की विशेषताये निम्नलिखित थी—(i) सोने के सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रहेंगे और उन्हें चलन से हटा लिया जायेगा। चलन में केवल चाँदी का रुपया तथा कागज के नोट रहेंगे। (ii) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए पत्र मुद्रा को सोने में परिवर्तनशील रखा जायेगा। सरकार निश्चित दरों पर किसी भी सीमा तक १०० ग्रांस वाली सोने की सजाखों को बेचने व खरीदने का कार्य करेगी। (iii) देश में एक रुपये वाले नोट जारी किये जायेंगे जो पूर्णतया विधिग्राह्य होंगे किन्तु उन्हें चाँदी के रुपयों में नहीं बदला जा सकेगा।

(२) कमीशन ने यह सिफारिश की कि भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शि० ६ पैसे पर स्थिर कर दिया जाये क्योंकि देश के लिए यही सधसे उपयुक्त दर है।

(३) स्वर्णमान कोष तथा पत्र मुद्रा कोष को मिलाकर एक कोष स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें ४० प्रतिशत स्वर्ण तथा स्वर्ण-प्रतिभूतियाँ रखी जायें और ६० प्रतिशत में भारतीय सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ तथा व्यापारिक विल होने चाहिए।

(४) मुद्रा का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण एक केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाये। भारत में साल व मुद्रा सम्बन्धी नीति में सहयोग व समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की। रिजर्व बैंक सरकारी बैंक तथा बैंकों के बैंक का कार्य करेगा और उसे नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होगा। रुपये के विदेशी मूल्य को बनाये रखने की जिम्मेदारी भी इस केन्द्रीय बैंक की होगी और वह देश में एक उपयुक्त साख नीति का विकास करेगा।

(५) एक रुपये के नोट को फिर से जारी करना चाहिए और वह भसीमित विधिग्राह्य होना चाहिए। बड़े मूल्य के नोट छोटे मूल्य के नोटों में अथवा चाँदी के रुपयों में परिवर्तनीय रखे जायें।

सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन की सभी सिफारिशों को मान लिया और सन् १९२७ में एक करेसी अधिनियम के द्वारा भारत में स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard) स्थापित कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य १ शि० ६ पैसे पर निश्चित कर दिया गया। सरकार ने २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति तोला के हिमाव से वम्बई टंकाल पर किसी भी सीमा तक ४० तोले से अधिक मात्रा में सोना खरीदना आरम्भ कर दिया। कागजी मुद्रा के बदले में लोग २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति तोला के हिमाव से सरकार से १०२५ तोला से अधिक मात्रा में सोने अथवा उमी मूल्य का स्टैटिजल सन्धन में तुरन्त भुगतान के लिए खरीद सकते थे। स्टैटिजल को बेचने की

दर १ सि० ५४ $\frac{1}{2}$ पैस प्रति रुपया निश्चित कर दी गई। सरकार ने सोवरेन तथा ग्रैंड सोवरेन को चलन से हटा लिया। इस एकट के अन्तर्गत भारत में स्वर्ण धातु-मान के स्थान पर स्टैलिड विनिमय मान ही स्थापित हो सका क्योंकि भारतीय रुपया सोने में परिवर्तनीय न होकर इंग्लैंड के स्टैलिड के साथ बदला जाता था। इस प्रकार १९०७ में कमिशन की महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्य-रूप में लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु उसमें बहुत अधिक सफलता न मिल सकी। कमिशन ने जिस प्रकार के स्पर्शमान की आलोचना की थी, समझ उसी प्रकार का स्पर्शमान फिर से स्थापित हो गया। देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में भी एक बिल प्रस्तुत किया गया किन्तु भावी रिजर्व बैंक के सविधान के सम्बन्ध में इतना अधिक वाद-विवाद पैदा हो गया कि वह पाम न हो सका। इस प्रकार कमिशन की रिजर्व बैंक सम्बन्धी सिफारिश को भी कार्य-रूप में नहीं लाया जा सका।

विनिमय दर सम्बन्धी वाद विवाद—

हिल्टन ग्रैम कमिशन की स्पर्श धातुमान तथा केन्द्रीय बैंक के स्थापन सम्बन्धी मुद्दों का महर्षि स्वागत किया गया किन्तु रुपये की विनिमय दर को १ सि० ६ पैस पर निश्चित करने का कटा विरोध किया गया। कमिशन के एक सदस्य सर पुरुषोत्तम दाम ठाकुरदास ने इस विनिमय दर की आलोचना की और यह बतलाया कि १ सि० ६ पैस की दर भारत के आर्थिक हित में नहीं है। उनके अनुसार रुपये की विनिमय दर को १ सि० ४ पस पर निश्चित करना भारत के आर्थिक हित में होगा। किन्तु कमिशन के अधिनाश सदस्य इस मत में सहमत नहीं थे और उनके विचार में १ सि० ६ पैस की दर अधिक उपयुक्त थी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क दिये गए।

१ निम्नलिखित ६ पैस दर के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क—

भारत सरकार के जून सदस्य सर बसिल ब्लैकेट (Sir Basil Blackett) ने १ सि० ६ पैस की विनिमय दर के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये—

(१) पिछले कई वर्षों में रुपये की विदेशी विनिमय दर १ सि० ६ पैस पर स्थिर रही है जो इस बात का प्रमाण है कि यही दर प्राकृतिक है और इसे बनाये रखना ही देश के हित में है। देश की अर्थ व्यवस्था का इस दर पर समायोजन हो चुका है और वस्तुओं में मूल्य, भजदूरी तथा व्याज की दरें इस विनिमय दर के अनुसार निश्चित हो चुकी हैं। विनिमय दर में निम्नी प्रवार का परिवर्तन करना मनुजों को भग कर देगा और उसके परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार में अनिश्चितता फैल जायेगी।

(२) इस दर पर भारतीय मूल्यों का समार के मूल्यों के साथ काफी समायोजन हो चुका है। उसे बदलने का अभिप्राय होगा फिर से समायोजन स्थापित

करना जो काफी कष्टपूर्ण हो सकता है। रुपये की दर को १ शि० ४ पैम करने का परिणाम यह होगा कि भारतीय कीमतें अन्य देशों की अपेक्षा नीची हो जायगी और उन्हें ऊँचा उठाने के लिए देश में मुद्रा प्रसार करना होगा।

(३) कमीशन के अनुसार १ शि० ४ पैस की दर कृत्रिम होगी और उसे केवल मुद्रा प्रसार के द्वारा ही बनाये रखना जा सकेगा। कमीशन ने बताया कि विनिमय दर को १ शि० ४ पैम करने पर मूल्य-स्तर को कम से कम १२½% ऊँचा करना होगा जिसके कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जायेगी और औद्योगिक प्रशांति फैलेगी।

(४) विदेशी विनिमय दर को १ शि० ६ पैस से घटाकर १ शि० ४ पैम करने का परिणाम यह होगा कि भारत की इंग्लैंड को देनदारी बढ जायेगी। इसमें लगभग १२½% की वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(५) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बजट इस विनिमय दर के आधार पर बनाये जाते रहे हैं। इस दर से बदलने से सरकारी बजट का सन्तुलन बिगड़ जायेगा और सरकार को घाटा पूरा करने के लिए अधिक कर लगाने पड़ेंगे।

१ शिलिंग ४ पैस के पक्ष में दिये जान वाले तर्क—

उपर्युक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिस्टन एवं कमीशन ने विदेशी विनिमय दर को १ शि० ६ पैम पर बनाय रखने के लिए जोर दिया। सरकारी वर्ग का विचार बिल्कुल कमीशन के पक्ष में था और उन्होंने विदेशी विनिमय दर को १ शि० ४ पैम पर निश्चित करने का विरोध किया किन्तु गैर-सरकारी दृष्टि-कोण इसके बिल्कुल विपरीत था। औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्ग के लोगों ने १ शि० ४ पैम की दर को अधिक वास्तविक तथा लाभपूर्ण बतलाया और १ शि० ६ पैम की दर का विरोध किया। मुख्यतः सर पुरपोत्तम दास ठाकुरदास ने १ शि० ६ पैम की दर के विरोध में निम्नलिखित तर्क रखे—

(१) १ शि० ६ पैम की दर को प्राकृतिक दर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने पहले काफी समय तक विनिमय दर १ शि० ४ पैम ही रही है। केवल पिछले दो वर्षों में ही कुछ अच्छी फसलों के आधार पर १ शि० ६ पैम की विनिमय दर को बनाये रखना सम्भव हो सका है इसलिए उसे वास्तविक दर नहीं कहा जा सकता है।

(२) १ शि० ६ पैस की दर इनके कम समय तक प्रचलित रही है कि उनके साथ मूल्य-स्तर, मजदूरी तथा व्याज की दरों का किसी प्रकार का सन्तुलन नहीं हुआ है। अतः १ शि० ४ पैस की दर को अपनाने पर किसी प्रकार का असन्तुलन पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(३) यदि १ शि० ४ पैस की दर स्थापित करने पर वस्तुओं के मूल्यों में १२½% की वृद्धि होना स्वाभाविक है तो यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार

१ शि० ६ पेंस की दर को बनाये रखकर ब्रिटिश उद्योगों को १२% की मद्दत देना चाहती है जिसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड का तैयार माल भारत में १२½% कम मूल्यों पर बेचा जा सकेगा। ऐसी दशा में सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली सरक्षण की नीति बेकार हो जायगी।

(४) भारतवर्ष मुख्यतः कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात करता है। इन वस्तुओं के विदेशी बाजारों को बनाये रखने के लिए उन्हें कम मूल्यों पर बेचना आवश्यक है। १ शि० ४ पेंस की दर ऐसा करने में सहायक होगी।

(५) निर्यातों का मुख्य आयातों के मूल्य की अपेक्षा अधिक होने के कारण भारत का व्यापार समतुलन पक्ष में है किन्तु १ शि० ६ पेंस की ऊँची दर को स्थापित करने में यह व्यापार अधिक्य समाप्त हो जायगा और उसके स्थान पर व्यापार समतुलन में घाटा होने लगेगा जिसके कारण देश की सोने का निर्यात करना पड़ेगा।

(६) १ शि० ६ पेंस की दर कृत्रिम दर है और उसे बनाये रखने के लिए देश में मुद्रा सङ्कुचन करना होगा जिसके कारण उत्पादन तथा आर्थिक उन्नति धीमी पड़ जायगी और अभिवृद्धि मजदूरी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(७) भविष्य में मोनो का मूल्य गिर जाने के कारण भारतवर्ष के लिए १ शि० ६ पेंस की ऊँची दर को बनाय रखना सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर सर पुण्योत्तम दास ठाकुरदास ने यह प्रदर्शित किया कि ६ शि० ४ पेंस की विनिमय दर ही भारत के आर्थिक हितों के अनुकूल है और उसे ही स्थापित किया जाना चाहिए। समस्त व्यवसायिक वर्ग १ शि० ६ पेंस की दर के विरोध में था। किन्तु इस विरोध के होते हुए भी सरकार ने स्टिलिंगमन की सिफारिशों को मान लिया और रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शि० ६ पेंस पर निश्चिन्त कर दिया गया।

स्टिलिंग्ज विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) सन् १९३१ से सन् १९४७ तक—

सन् १९२७ के करारी अविनियम के अन्तर्गत जिस स्वर्ण धातुमान को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, वह पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सका। २१ मिनम्बर सन् १९३१ को इंग्लैंड ने स्वर्णमान छोड़ दिया और स्टिलिंग्ज का सम्बन्ध मोनो में टूट गया। इसका प्रभाव भारतीय रुपये की स्थिति पर भी पड़ा। स्वर्णमान टूट जाने के कारण स्टिलिंग्ज मोने में परिवर्तनशील नहीं रहा और उसका मूल्य गिरने लगा। भारतीय सरकार को यह निश्चय करना था कि रुपये की सोने में परिवर्तनशील रखी जाये अथवा स्टिलिंग्ज में। सन् १९२७ के अविनियम के अनुसार भारतीय रुपये को मोने में परिवर्तनशील कर दिया गया था किन्तु सरकार को यह छूट दी गई थी कि यदि वह चाहे तो रुपये के बदले में स्टिलिंग्ज दे सकती

है। सन् १९३१ तक तो कोई समस्या पैदा न हुई क्योंकि स्टर्लिंग सोने में परिवर्तनशील था किन्तु १९३१ में स्टर्लिंग की मोने में परिवर्तनशीलता स्थगित हो जाने के कारण एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। इंग्लैंड के स्वर्णमान को छोड़ देने में भारतीय रुपये का सम्बन्ध सोने के साथ अपने आप टूट गया और इस प्रकार भारत में जो स्वर्ण धातुमान स्थापित करने का प्रयत्न किया गया वह सफल न हो सका और वास्तव में उसके स्थान पर स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) ही स्थापित किया जा सका। २१ मितम्बर १९३१ को गवर्नर जनरल ने १९२७ के अधिनियम की उन धारा को स्थगित कर दिया जिसके अन्तर्गत सरकार रुपये के बदले में सोना अथवा स्टर्लिंग देने के लिए बाध्य थी। किन्तु इसके साथ ही रुपये के मूल्य को १ सि० ६ पैस ८४ बनाये रहल ही घोषणा कर दी गई। २४ सितम्बर को एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार सरकार ने सीमित मात्रा में केवल प्रमाणित बैंकों को सोने के बदले में स्टर्लिंग देने की जिम्मेदारी दी किन्तु यह केवल उचित व्यापारिक सीधों के लिए ही दिया जा सकता था।

स्टर्लिंग विनिमय मान के पक्ष में तर्क

(Arguments in favour of Sterling Exchange Standard) —

भारत के रुपये को स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये गए—

(१) इसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर में स्थिरता स्थापित की जा सकेगी। स्टर्लिंग में सम्बन्धित हो जाने पर रुपये के विदेशी मूल्य में अधिक परिवर्तन नहीं होगा, जिसमें विदेशी व्यापार का विस्तार होगा।

(२) इंग्लैंड में स्वर्णमान टूट जाने के कारण स्टर्लिंग का अन्य स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में अवमूल्यन हो गया था। यदि रुपये को स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित रखा जाता है तो उनका भी अवमूल्यन उन्हीं अनुपात में हो जाता है, जिसमें भारत के विदेशी व्यापार को लाभ हो सकता है।

(३) भारत का अधिकांश व्यापार स्टर्लिंग देशों के साथ होता था तथा भारत सरकार को प्रति वर्ष बहुत बड़ी रकम गृह खर्चों के रूप में इंग्लैंड भेजनी पड़ती थी। इस दृष्टि से भी रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध आवश्यक था।

स्टर्लिंग विनिमय मान के विपक्ष में तर्क

(Arguments against Sterling Exchange Standard) —

(१) रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित रहना हमारे देश की राजनैतिक दासता का प्रतीक है। इसके द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था के साथ सम्बन्धित हो जायेगी और स्टर्लिंग के मूल्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन

रुपये के मूल्य की अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा। इस प्रकार की आर्थिक आधीनता राष्ट्र के हित में नहीं है। अतः इस प्रकार के सम्बन्ध को जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाय उतना ही अच्छा होगा।

(२) स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित किये जाने के कारण भारतीय रुपये का मूल्य स्वर्णमान वाले देनों के साथ ३०% कम हो जायगा और हम अपने आयातों के लिए अधिक मूल्य देना पड़ेगा।

(३) भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान स्थापित होने में रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो जायगा जिसके कारण भारत में सोने का भारी मात्रा में निर्यात किया जाने लगेगा।

(४) इस प्रकार का सम्बन्ध इन्टन यम कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नहीं था। कमीशन ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था की पूर्ण जीव करने के पश्चात् स्वर्ण पाठ मान की स्थापना की सिफारिश की थी जो देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल था। इन्टन यम कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना देश के हित में नहीं थी।

स्टर्लिंग विनिमय मान के परिणाम

(Effects of Sterling Exchange Standard)—

(१) सोने का निर्यात—स्वर्णमान को छोड़ने का तुरन्त परिणाम यह हुआ कि रुपये के सम्बन्ध में सोने का मूल्य २१ रु० १३ आने ३ पाई प्रति तोला में ब्रह्मर २६ रु० २ आने प्रति तोला हो गया। सोने का मूल्य बढ़ जाने के कारण लोगों ने सोना बेचना भारम्भ कर दिया जिस भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाने लगा। अक्टूबर सन् १९३१ से लेकर मार्च १९३२ तक भारत से लगभग ३५ करोड़ रुपये का सोना विदेशों को भेजा गया। सन् १९४० तक निर्यात किये जाने वाले सोने का मूल्य लगभग ३-३ करोड़ रुपये था। सोने के इस निर्यात के यद्यपि कुछ और कारण भी थे किन्तु स्टर्लिंग के साथ रुपये का सम्बन्धित किया जाना प्रमुख था। सरकार ने सोने के इस भारी निर्यात को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय व्यापारियों ने सोने के अत्यधिक निर्यात की कड़ी आलोचना की और उसे रोकने के लिए सरकार से प्रार्थना की किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

(२) विनिमय दर में स्थिरता—स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना का एक परिणाम यह हुआ कि रुपये की विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पैस पर बनाये रखा जा सके। भारत से सोने का भारी मात्रा में निर्यात हो जाने के कारण व्यापार मन्तुलन पक्ष में हो गया और स्टर्लिंग की मांग गिर गई। ऐसी दशा में सरकार के लिए रुपये के विदेशी मूल्य को १ शिलिंग ६ पैस पर बनाये रखना आसान हो गया। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् उसकी यह वैधानिक जिम्मेदारी

कर दी गई कि वह १ शिलिंग ६ पैसे पर किसी भी सीमा तक रुपये के बदले में स्टैलिङ्ग देगा । इस प्रकार रुपये का सम्बन्ध स्टैलिङ्ग के साथ दृढ़ कर दिया गया ।

भारतीय चलन पद्धति का विकास हिट्लर यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नहीं हुआ । यद्यपि सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों को मान लिया और उन्हें कार्य-रूप में लाने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु फिर भी कमीशन की सिफारिशों का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । सरकार ने १९२७ के अधिनियम के अन्तर्गत देश में स्वर्ण धातुमान स्थापित कर दिया । रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पैसे पर निश्चित कर दिया गया और उसे बनाये रखने के लिए सरकार ने भरमक प्रयत्न भी किया । यहाँ तक कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश से बहुत बड़ी मात्रा में सोना व चाँदी भी बाहर भेज दिया गया । सन् १९३५ में रिजर्व बैंक को स्थापित करके साख व मुद्रा के नियन्त्रण का कार्य भी एक संस्था को सौंप दिया गया ।

यद्यपि कुछ होते हुए भी भारत में मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन की इच्छाओं के अनुसार न हो सका । यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से स्वर्ण धातुमान (Gold Bullion Standard) स्थापित कर दिया गया था किन्तु कार्य-रूप में वह केवल स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) ही था । कमीशन की सिफारिशों का उद्देश्य रुपये और सोने में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना था किन्तु यह सम्बन्ध कभी भी स्थापित न हो सका । भारतीय रुपया सोने के साथ स्टैलिङ्ग के द्वारा सम्बन्धित था और इस प्रकार रुपये और सोने का सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष था । सन् १९३१ के पड़वान् डगलैड के द्वारा स्वर्णमान को त्याग देने के कारण तो यह परोक्ष सम्बन्ध भी टूट गया और भारत में केवल स्टैलिङ्ग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) ही रह गया । इस प्रकार भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन की इच्छाओं के अनुसार नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त, कमीशन ने कभी भी यह सुझाव नहीं दिया था कि रुपये के मूल्य को किसी भी दशा में १ शिलिंग ६ पैसे ही रखा जाय । यहाँ तक कि स्टैलिङ्ग का मूल्य हास होने पर भी उसे न बढ़ाया जाय । किन्तु वास्तव में यही किया गया और सरकार ने स्टैलिङ्ग का मूल्य कम हो जाने पर भी रुपये के विदेशी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जिसके भयकर आर्थिक परिणाम हुए ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना—

यद्यपि हिट्लर यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक को स्थापित करने की सिफारिश की किन्तु इस सिफारिश को कार्य-रूप में नहीं लाया जा सका और उस समय केन्द्रीय बैंक को स्थापित करने के प्रश्न को स्थगित कर दिया गया । सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग एंक्वायरी समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बहुत अधिक जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप ६ अप्रैल

सन् १९३४ को रिजर्व बैंक एक्ट पास कर दिया गया और १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय मुद्रा व बाह्य दोनों का नियन्त्रण रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया और उसे केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी सभी कार्य दे दिये गये। रिजर्व बैंक की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो इस प्रकार हैं—

(१) नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया गया और सरकार के द्वारा जारी किये जाने वाले नोटों का स्थान रिजर्व बैंक के नोटों ने ले लिया। धीरे-धीरे देश में चलने वाली समस्त मुद्रा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाने लगी।

(२) रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने पर मुद्रा व बाह्य का नियन्त्रण एक ही केन्द्रीय संस्था के हाथों में आ गया क्योंकि नोट निर्गमन तथा बाह्य नियन्त्रण का कार्य रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। ऐसा करने से भारतीय मुद्रा प्रणाली का एक बड़ा दोष दूर हो गया।

(३) रुपये के विदेशी मूल्य को १ शिलिंग ६ पैस पर स्थिर रखने का दायित्व रिजर्व बैंक को दे दिया गया जिसके लिए वह १ शिलिंग ६ $\frac{3}{4}$ पैस प्रति रुपये के हिसाब से किसी भी सीमा तक स्टर्लिंग बेचता था और १ शिलिंग ५ $\frac{1}{4}$ पैस प्रति रुपये के हिसाब से उसे खरीदने का कार्य करता था।

(४) रिजर्व बैंक की स्थापना का एक परिणाम यह हुआ कि देश में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों का केन्द्रीयकरण कर दिया गया। पत्र मुद्रा कोष तथा स्वयंमान कोष मिला दिये गये तथा बैंकिंग व्यवस्था के समस्त कोष भी रिजर्व बैंक के पास केन्द्रित हो गये।

(५) इन कार्यों के अनिरिक्त रिजर्व बैंक को बैंकों के बैंक तथा सरकारी बैंक का काम भी सौंप दिया गया और इस प्रकार वह देश में पूर्ण रूप से एक केन्द्रीय बैंक का कार्य करने लगा।

सन् १९३१-३६ के बीच विनिमय दर—

सन् १९३१ में भारतीय रुपये स्टर्लिंग के साथ १ शिलिंग ६ पैस की दर पर सम्बन्धित था और सरकार ने इस विनिमय दर को किसी भी कीमत पर बनाये रखने का निश्चय किया। सन् १९३३-३४ तक भारत के विदेशी व्यापार में काफी गिरावट आ गई थी जिसका रुपये के विनिमय दर पर बुरा प्रभाव पड़ा। अगस्त सन् १९३५ में श्री मनु मूवेदार ने भारतीय रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन करने की मांग की किन्तु भारतीय सरकार के वित्त मन्त्र ने उसे मानने से इन्कार कर दिया और रुपये की दर को १ शिलिंग ६ पैस पर स्थिर रखने का निश्चय किया गया। सन् १९३६ में फिर स्थिति में परिवर्तन हुआ। फ्रांस तथा अन्य स्वयंमान वाले देशों

ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था। भारत में भी रुपये के अवमूल्यन की मांग की जाने लगी और अक्टूबर सन् १९३६ में इस प्रश्न को विधान सभा में उठाया गया किन्तु इस बार भी सरकार ने रुपये की विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया। सन् १९३८ में भारत का व्यापार सतुलन फिर विपक्ष में जाने लगा और विनिमय दर कमजोर हो गई। इस बार भारतीय कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी ने रुपये के अवमूल्यन की मांग की। इस समिति का विचार था कि १ शिलिंग ६ पेंस की दर होने से भारतीय किसानों की बड़ी हानि उठानी पड़ी है और विदेशी आयातों को एक प्रकार का अनावश्यक लाभ प्राप्त होता है। समिति के अनुसार १ शिलिंग ६ पेंस की विनिमय दर को बनाये रखना सम्भव नहीं था। किन्तु सरकार ने इस समिति की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके द्वारा अवमूल्यन के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क अधिक दृढ़ नहीं थे। सन् १९३६ में युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण भारत के व्यापार सतुलन में तेजी के साथ सुधार होने लगा और विनिमय दर सम्बन्धी वाद-विवाद का महत्व समाप्त हो गया।

परीक्षा प्रश्न

- (१) १८३५ से १८६८ तक रजतमान की समझाइये।
- (२) बैंकिंगटन स्मिथ कमेटी के सुझावों पर प्रकाश डालिए।
- (३) १९२५ से १९३६ तक भारतीय मुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिये।
(गोरखपुर व विक्रम श्री० काम० १९५६)

भारतीय मुद्रा का इतिहास

HISTORY OF INDIAN CURRENCY

द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ होने के समय भारतवर्ष में स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) था। भारतीय रुपया स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित था और उसकी विदेशी विनिमय दर १ गिलिंग ६ पैस पर निश्चित थी। रुपया देश का प्रामाणिक निष्का होने हुए भी सांकेतिक था। उसे विदेशी भुगतानों के लिए निश्चित दर पर स्टर्लिंग में बदला जा सकता था। रुपये के भिक्को, अटर्नी तथा नोटों की असीमित विधिव्यवस्था प्राप्त थी। विदेशी बाजार में रुपये का कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं था और वह स्टर्लिंग के माध्यम के द्वारा ही अन्य मुद्राओं के साथ बदला जा सकता था। व्यापार मन्तुलित पक्ष में होने के कारण भारतीय रुपये की माग काफी थी और १ गिलिंग ६ पैस की दर को सुविधापूर्वक बनाये रखा जा सकता था। किन्तु यह सब वृद्ध होने हुए भी भारतीय मुद्रा प्रणाली दोषपूर्ण थी। उसका सबसे बड़ा दोष तो यह था कि वह स्टर्लिंग पर आधारित थी और रुपये का कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं था। इसके अनिश्चित इन मुद्रा प्रणाली में लोन का भी अभाव था और किसी भी अनामान्य परिस्थिति में उसका हट जाना स्वाभाविक था।

द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय मुद्रा पर प्रभाव

(Effects of II World War on Indian Currency)—

३ मिनम्बर मन् १९१६ को द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ जिसके कारण योरोप के लगभग सभी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को युद्धकालीन दशाओं के अनुकूल बनाने में लग गये। भारतवर्ष यद्यपि लन्डार्न का केन्द्र नहीं था किन्तु फिर भी उसकी समस्त अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। साथी देशों को युद्ध जीतने के लिए भारत ने पूरी-पूरी महायत्ना दी। युद्ध के कारण हमारे देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति पैदा हो गई जिसका मुख्य कारण बहुत बड़ी मात्रा में नई मुद्रा का जारी किया जाना था। व्यापार और उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हुई किन्तु वह मुद्रा

विस्तार की अपेक्षा कम थी जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे। सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए तथा विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों का प्रयोग किया। युद्ध काल भारतीय मुद्रा प्रणाली के लिए भी एक परीक्षा का समय था और उसे बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ा। भारतीय मुद्रा प्रणाली ने युद्ध के दबाव को बहुत अच्छी प्रकार सहन किया और माधारणतया मुद्रा में जनता के विश्वास को बनाये रखा जा सका। यद्यपि कुछ समय के लिए युद्ध के कारण नोटों को मितकों में बदलने की मांग काफी प्रबल हो गई थी किन्तु कुछ ही समय पश्चात् मुद्रा में जनता का विश्वास फिर से स्थापित हो गया। युद्ध काल में रुपये का मूल्य स्टर्लिंग के साथ तो स्थिर बना रहा किन्तु डॉलर (Dollar) तथा यें (Yen) आदि के सम्बन्ध में उसका मूल्य गिर गया। युद्ध के कारण भारतीय मुद्रा प्रणाली पर जो प्रभाव पड़े उनमें से निम्नलिखित प्रमुख है—

(१) मुद्रा व साख का विस्तार (Expansion of Currency & Credit)—द्वितीय विश्व-युद्ध काल में भारतवर्ष में मुद्रा की माया व तेजी के साथ वृद्धि हुई। युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में नई पत्र मुद्रा जारी करनी पड़ी। भारत ने इंग्लैंड को बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जिसका भुगतान तुरन्त नहीं किया गया और उनके बदले में हमें केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ प्राप्त हुईं। सरकार ने इन स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर नये नोट जारी कर दिये और इस प्रकार चलन में मुद्रा की मात्रा पहले की अपेक्षा कई गुणा हो गई जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे और देश में मुद्रा-प्रहार की स्थिति पैदा हो गई। सन् १९३६ में पत्र मुद्रा की कुल मात्रा १८० करोड़ रुपये थी जो अक्टूबर १९४५ में बढ़कर १५६.८५ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार ६ वर्ष के इस समय में लगभग ६८० करोड़ रुपये की नई मुद्रा जारी की गई। इस काल में केवल नकद रुपये की मात्रा ही नहीं बड़ी बल्कि माय की मात्रा में भी तेजी के साथ वृद्धि हुई और इसी काल में साख मुद्रा की मात्रा लगभग दुगुनी हो गई। मुद्रा व साख के इस विस्तार व कारण वस्तुओं के मूल्यों में तेजी के साथ वृद्धि होने लगी और मूल्य सूचक अंक (१९३६=१००) बढ़कर ८०० से भी अधिक हो गया।

(२) नोटों की रुपये में बदलने की भारी मांग (Excessive Demand for conversion of Notes)—युद्ध आरम्भ होने ही जनता में एक प्रकार की वैचैनी फैल गई। लोगों ने अपने रुपये बैंकों में निकालने आरम्भ कर दिये, सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची जाने लगी तथा डाकखाने के कैंज मर्टिफिकेट बदले जाने लगे। इन सवका बारण था रुपये में जनता के विश्वास का कम हो जाना। सन् १९४० के मध्य में, योरोप में नज़ा की स्थिति खराब हो जाने के कारण, लोगों ने बहुत बड़ी

मात्रा में नोटों के बदले में सिक्कों की मांग करनी आरम्भ कर दी। सरकार ने रुपये में जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए काफी मात्रा में सिक्कों की मांग को पूरा किया किन्तु यह मांग निरन्तर बढ़ती ही गई। सामान्यतः नोटों के बदले में रिजर्व बैंक से प्रति सप्ताह १ करोड़ रुपये के सिक्कों की मांग की जाती थी किन्तु अब यह मांग बढ़कर ४ से ५ करोड़ रुपया हो गई। सरकार के लिए चाँदी के सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना सम्भव न हो सका और सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में सिक्कों का जमा करना जुर्म करार दे दिया। नोटों को सिक्कों में बदलने पर प्रतिबन्ध चाँदी की कमी के कारण नहीं लगाया गया बल्कि इसलिए लगाया गया कि भारतीय दशसाले इतनी अधिक मात्रा में सिक्के ढालने में असमर्थ थी। रुपये की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक रुपये वाले नोट जारी कर दिये और उन्हें असीमित विधिग्राह्य घोषित कर दिया गया। २४ जून सन् १९४० को यह घोषणा कर दी गई कि एक रुपये का नोट एक रुपये के सिक्कों के समान ही होगा और वह प्रत्येक कार्य के लिए प्रामाणिक सिक्का समझा जायगा। अन्य समस्त नोटों को एक रुपये के नोटों में परिवर्तनीय कर दिया गया। फरवरी सन् १९४३ को दो रुपये वाले नोटों का प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया गया।

(३) भारतीय सिक्कों में चाँदी की मात्रा कम कर दी गई (Reduction in the silver content of the coins)—सरकार ने चाँदी की बचत करने के लिए रुपया, आठ घान तथा चार घाने के सिक्कों में चाँदी की मात्रा को घटा दिया। सभी चाँदी के सिक्कों की शुद्धता कम कर दी गई और उनमें घटिया धातु की मात्रा बढ़ा दी गई। अप्रैल सन् १९४० में सरकार ने चवथी व अठथी की शुद्धता को $\frac{2}{3}$ से घटा कर $\frac{1}{2}$ कर दिया। २३ दिसम्बर १९४० से रुपये की शुद्धता में भी इसी प्रकार की कमी कर दी गई। कुछ समय पश्चात् निकिल (Nickel) तथा अन्य घटिया धातुओं के सिक्के चलन में डाल दिये गये। यह सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि सरकार देश में चाँदी के सीमित स्टॉक से अधिक से अधिक काम लेना चाहती थी।

(४) अधिक चाँदी वाले सिक्कों को चलन से हटा लिया गया—चाँदी के प्रयोग में बचत करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिक चाँदी वाले पुराने सिक्कों को चलन में हटा लिया। ११ अक्तूबर सन् १९४० को एक सरकारी आदेश के द्वारा महारानी विक्टोरिया के रुपये, अठथी व चवथी के सिक्कों का विमुद्राकरण कर दिया गया और उन्हें १ अप्रैल सन् १९४१ तक सरकार ने वापस मांग लिया। इसी प्रकार ४ नवम्बर सन् १९४१ को एडवर्ड सप्तम के रुपये, अठथी व चवथी के सिक्कों को बन्द कर दिया गया। १ नवम्बर सन् १९४३ को जार्ज पंचम तथा जार्ज षष्ठ्य के $\frac{2}{3}$ शुद्धता वाले रुपये व अठथियों को भी चलन से हटा लिया गया और उनके स्थान पर $\frac{1}{2}$ शुद्धता वाले नये चाँदी के सिक्के जारी कर दिये गये।

(५) रेजगारी की कमी—युद्ध काल में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे मूल्य के सिक्कों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। सरकारी टकसालों से इतनी बड़ी मात्रा में रेजगारी जारी करना सम्भव न हो सका जिसके कारण देश भर में रेजगारी की बहुत कमी हो गई और लोगों की काफी कठिनाई उठानी पड़ी। रेजगारी की इतनी अधिक कमी थी कि लोगों की डाकखाने के टिनट तथा अन्य प्रकार के घुपन रेजगारी के स्थान पर प्रयोग करने पड़े। सरकार ने रेजगारी की इस कमी को दूर करने के लिए बड़ी मात्रा में नई रेजगारी का टंकन आरम्भ कर दिया और कुछ ही समय में रेजगारी की इस कमी को पूरा कर दिया गया। १७ अप्रैल सन् १९४३ को सरकार ने एक आदेश के द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में रेजगारी इकट्ठा करना अपराध घोषित कर दिया। सन् १९४३ में सरकार ने ३० ग्रेन-वजन वाला एक नया पैसा जारी किया तथा अन्य छोटे सिक्कों में भी धातुओं की मात्रा कम कर दी गई।

(६) बड़े मूल्य वाले नोटों का विमुद्रीकरण—सरकार ने चोर बाजारी तथा अन्य प्रकार से प्राप्त अवैधानिक आय को रोकने के लिए बड़े मूल्य वाले नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। सन् १९४६ में ५०० रु०, १००० रु० तथा १०,००० रु० वाले नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। इन नोटों को छोटे नोटों में तभी बदला जा सकता था जबकि उनका मालिक इस बात का काफी प्रमाण दे कि वह चोर-बाजार की आय नहीं है किन्तु सरकार को अपने इस उद्देश्य में बहुत कम सफलता मिल सकी।

भारत में विदेशी विनिमय-नियन्त्रण—

विदेशी विनिमय नियन्त्रण की मुख्य विशेषता यह होती है कि सरकार निश्चित दरों पर विदेशी मुद्रा को बेचने व खरीदने के लिए हर समय तैयार रहती है। भारतवर्ष में विदेशी विनिमय नियन्त्रण का कुछ अंश सन् १८६३ से मौजूद था जिस समय रुपये की एक सांकेतिक सिक्का बनाया गया और उसके विदेशी मूल्य को १ गिलिंग ४ पैस पर निश्चित कर दिया गया। उस समय से सरकार कौन्सिल बिल्ल (Council Bills) तथा रिवर्स कौन्सिल बिल्ल (Reverse Council Bills) को बेचने व खरीदने की विधि के द्वारा रुपये के विदेशी मूल्य को १ गिलिंग ४ पैस पर स्थिर रखती थी। कुछ समय पश्चात् रुपये की विदेशी दर को बढ़ा कर १ गिलिंग ६ पैस कर दिया गया। सन् १९३० के पश्चात् व्यापार सन्तुलन विपक्ष में होने के कारण रुपये की विदेशी विनिमय दर को बनाये रखना कठिन हो गया और सोने के भारी निर्यात के द्वारा ही उसे बनाये रखा जा सका। सन् १९३८ में स्थिति और अधिक खराब हो गई। सोने का निर्यात गिरने लगा और व्यापार सन्तुलन भी निरन्तर विपक्ष में जा रहा था। किन्तु युद्ध आरम्भ होने पर स्थिति में सुधार हुआ। भारत का व्यापार सन्तुलन पक्ष में हो गया और रतलिंग जमा होने लगा। अब

१ शिचिंग ६ पैंग की दर को बनाये रखना ग्यस्तान था। रुपये की विनिमय दर स्टलिंग के साथ निश्चित थी किन्तु स्टलिंग का मूल्य डालर के साथ तेजी के साथ गिर रहा था। ब्रिटिश सरकार ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण के द्वारा स्टलिंग के मूल्य को £1 = \$4 02 की दर पर निश्चित कर दिया।

इंग्लैंड के साथ-साथ भारतवर्ष में भी द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ होने पर विदेशी विनिमय नियन्त्रण की नीति को अपना लिया गया। सन् १९३६ में भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत गवर्नर जनरल को अग्रतिष्ठित अधिकार दे दिये गये—

- (i) विदेशी विनिमय के खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार।
- (ii) विदेशी विनिमय को खरीदने का अधिकार।
- (iii) प्रतिभूतियों के पसीदन तथा उनके निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार।
- (iv) विदेशी प्रतिभूतियों को खरीदने का अधिकार।

गवर्नर जनरल ने विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी समस्त अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को दे दिये। विनिमय नियन्त्रण को चलाने के लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण विभाग की स्थापना की और उसे विनिमय नियन्त्रण का कार्य सौंप दिया गया। भारतवर्ष में विनिमय नियन्त्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाय गये—

(१) विदेशी विनिमय के सौदों पर प्रतिबन्ध—रिजर्व बैंक ने एक प्रादेश के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया कि विदेशी विनिमय के सौदे केवल अधिकृत व्यापारियों के द्वारा ही किये जा सकेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विदेशी विनिमय बैंकों तथा मित्रित पूँजी वाले बैंकों को लाइसेन्स (License) दे दिये गये। सामान्यतः ब्रिटिश साम्राज्य वाले देशों की मुद्राओं के बेचने तथा खरीदने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता था किन्तु अल्प पूर्ति वाली मुद्राएँ (Hard Currencies) वास्तविक व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए तथा अनिवार्य व्यक्तिगत भुगतानों के लिए केवल सीमित मात्रा में ही दी जाती थी। स्टलिंग क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होती थी। मार्च सन् १९४० में विनिमय नियन्त्रण और अग्रिम हट कर दिया गया और निर्यातों के वदले में प्राप्त अल्प-पूर्ति वाली मुद्राओं के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। निर्यात नियन्त्रण की इस योजना के अन्तर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया कि निर्यातों के वदले में प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय का प्रयोग रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त ढग से ही किया जा सकेगा। निर्यातों के वदले में प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय को रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से बेचना होता था और उसके वदले में निश्चित दर पर देश की मुद्रा दे दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत लोगों की डॉलर जमा तथा विदेशी प्रतिभूतियों को लेकर साम्राज्य डॉलर कोष

(Empire Dollar Pool) में जमा कर दिया गया और उनके बदले में रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये दे दिये। इस योजना का उद्देश्य यह था कि प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्राओं को बाहर के देशों में न खर्चा जा सके और उन्हें अनिवार्य रूप से भारत में ले आया जाय।

(२) प्रतिभूतियों के खरीदने तथा उनका निर्यात करने पर प्रतिबन्ध—विदेशी विनिमय नियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत विदेशियों से प्रतिभूतियाँ खरीदने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना इस प्रकार की प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकता था। भारतवर्ष से प्रतिभूतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक की आज्ञा लेना आवश्यक था। केवल रिजर्व बैंक में लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति ही प्रतिभूतियों का निर्यात कर सकते थे जिसमें शर्त यह होती थी कि उनके बदले में प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय को अनिवार्य रूप से सरकार को बेचना होगा। इस प्रकार के प्रतिबन्धों का उद्देश्य देश से पूँजी के निर्यात को रोकना तथा विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी कम करना था।

(३) आयात नियन्त्रण (Import Control)—विदेशी विनिमय नियन्त्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने २० मई सन् १९४० से आयात नियन्त्रण की नीति को अपना लिया। विदेशी विनिमय का उचित प्रयोग करने के उद्देश्य से आयातों को लाइसेन्स करने की योजना प्रपनार्ह गई। इस योजना के अन्तर्गत स्टलिंग क्षेत्रों में बाहर वाले देशों से बिना लाइसेन्स के कोई भी सामान नहीं मंगाया जा सकता था। विदेशी विनिमय केवल लाइसेन्स प्राप्त निर्यातों के लिए ही दिया जाता था। सन् १९४० से उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं का आयात केवल स्टलिंग क्षेत्र से ही हो सकता था। विनाशिता की वस्तुओं के आयात पर कड़ा नियन्त्रण लगा दिया गया। आयात नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य अल्प पूर्ति वाली मुद्राओं का उचित प्रयोग करना तथा व्यापार सतुलन को विपक्ष में होने से रोकना था।

(४) सोने के निर्यात तथा आयात पर प्रतिबन्ध—कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की आज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी रूप में सोना भारतवर्ष से बाहर नहीं ले जा सकता था। एक निश्चित मात्रा से अधिक आभूषणों को देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। सोने का आयात करने के लिए भी लाइसेन्स लेना होता था। स्टलिंग क्षेत्र से सोना मगाने की आज्ञा आमानी से मिल जाती थी किन्तु डालर प्रतिबन्धों का मुख्य उद्देश्य स्टलिंग क्षेत्र में बाहर वाले देशों से सोने के आयात को कम करना था।

(५) मुद्रा के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध—सन् १९४० के पश्चात् कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना भारतीय मुद्रा देश से बाहर नहीं ले

जा सकता था। देश से बाहर मिकों तथा करेसी नोटों को ले जाने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त करना होता था। विदेशी मुद्राओं को देश में लाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सितम्बर सन् १९४३ से भारतीय पन मुद्रा को छोड़कर अन्य सब प्रकार की मुद्राओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

पुद्धोत्तर-काल में विदेशी विनिमय-नियन्त्रण

(Foreign Exchange Control in the Post War Period)—

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर भारत की विदेशी विनिमय स्थिति काफी अच्छी थी किन्तु फिर भी विदेशी विनिमय नियन्त्रण की जारी रखना गया और उसके क्षेत्र को अधिक व्यापन कर दिया गया। इसका मुख्य कारण देश में वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई मांग तथा इङ्ग्लैंड की स्टर्लिंग मुक्त करने में असमर्थता थी। युद्ध ही समय पश्चात् भारत के भुगतान अनुदान में घाटा होने लगा और यह आवश्यक हो गया कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी सौदों पर अधिक से अधिक नियन्त्रण लगाये जायें। सन् १९४७ में स्टर्लिंग क्षेत्र के साथ होने वाले सौदों को विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत ले प्राया गया और १९५१ में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ होने वाले सौदों को भी नियन्त्रित कर दिया गया।

सन् १९४७ के विनिमय नियमन अधिनियमन (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) के अन्तर्गत भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को निम्नलिखित प्रकार के सौदों को नियन्त्रित करने का अधिकार दिया गया—(i) विदेशी विनिमय एवं विदेशी प्रतिभूतियों में होने वाले सौदे। (ii) भारत से बाहर रहने वाले लोगों को किये जाने वाले भुगतान। (iii) करेसी नोट सौदा, बहुमूल्य धातुओं आदि का निर्यात। (iv) विदेशियों को प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण। इस प्रकार के सौदे प्रायः रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त बैंकों के द्वारा किये जाते हैं। अधिकृत व्यापारियों के अनिश्चित अन्य लोगों के द्वारा किये जाने वाले विदेशी विनिमय के सौदों तथा भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्राओं के साथ रिजर्व बैंक की अधिकृत दरों के अनिश्चित दरों पर बदले जाने को निश्चित रूप से वर्जित कर दिया गया है।

भारत में निवेशन आरम्भ होने पर विदेशी विनिमय नियन्त्रण की प्रवृत्ति तथा उद्देश्य दोनों ही बदल गये हैं। अब वह योजना सम्बन्धी प्रोग्राम की कार्यरूप में लाने का एक साधन बन गया है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में हमारे देश ने लगभग समस्त स्टर्लिंग निधि को खर्च कर लिया है और हमारे विदेशी विनिमय कोष तेजी के साथ गिर रहे हैं। विकास के कामों के लिए देश ने काफी बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण लिए हुए हैं जिनके भुगतान सम्बन्धी उत्तरदायित्व को हमें उठाना है। हमें बहुत बड़ी मात्रा में विकास सम्बन्धी आयातों का प्रबन्ध भी करना है। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विदेशी विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किया

जाना है। ऐसी कठिन दशाओं में विनिमय नियंत्रण ही हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति को ठीक रखने में सहायता कर सकता है। इसीलिए योजना काल में विदेशी विनिमय नियंत्रण का प्रयोग इस प्रकार किया जा रहा है जिससे कि विदेशी पूँजी के आने तथा विकास सम्बन्धी आयातों में किसी प्रकार की कमी न होने दी जाये और इसके साथ ही अनावश्यक आयातों को रोक कर भुगतान सन्तुलन पर दबाव को कम किया जाये।

साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool)—

युद्ध से पूर्व लगभग सभी देश अपने विदेशी विनिमय कोषों को स्टर्लिंग के रूप में जमा रखने थे क्योंकि स्टर्लिंग सब देशों की मुद्राओं में पूर्णतया परिवर्तनशील था। कोई भी देश अपने स्टर्लिंग कोषों का प्रयोग जब चाहे कर सकता था क्योंकि स्टर्लिंग को अन्य देशों की मुद्राओं में बदलन की पूरी सुविधाएँ दी जाती थी। किन्तु युद्ध आरम्भ होने पर यह स्थिति बदल गई और स्टर्लिंग की स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया; युद्ध के कारण डालर तथा कुछ अन्य देशों की मुद्राओं की भारी कमी हो गई और स्टर्लिंग को इन दुर्लभ मुद्राओं में बदलने में बड़ी कठिनाई होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तथा दुर्लभ मुद्राओं का उचित प्रयोग करने के उद्देश्य से स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों ने मिलकर सन् १९३९ में एक साम्राज्य डालर कोष की स्थापना की। इस डालर कोष में ब्रिटिश साम्राज्य वाले देशों का विदेशी विनिमय जमा रहता था और उन्हें आवश्यकानुसार इस कोष में से दुर्लभ मुद्राएँ व्यय के लिए दी जाती थी। यद्यपि इस कोष में विभिन्न देशों की मुद्राएँ जमा रहती थी किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्रा डालर थी। इसीलिए इसे डालर कोष के नाम से जाना जाना था। इस कोष का प्रबन्ध तथा संचालन बैंक ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश ट्रेजरी के द्वारा किया जाता था।

स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों ने अपने पास विदेशी विनिमय रखने के अधिकार को त्याग दिया और ये देश दुर्लभ मुद्राओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तैयार हो गये। स्टर्लिंग क्षेत्र की तमाम विदेशी विनिमय आय साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दी जाती थी और प्रत्येक सदस्य देश को इस कोष में से डालर निकालने का अधिकार रहता था। यद्यपि डालर के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोटा (Quota) निर्दिष्ट नहीं किये गये थे किन्तु विभिन्न देशों ने आपस में यह निश्चित कर लिया था कि वे डालर निधि का अपव्यय नहीं करेंगे और इसके सर्वोत्तम प्रयोग में पूरा सहयोग देंगे। स्टर्लिंग देशों को जितना भी डालर प्राप्त होता था वे उसे साम्राज्य डालर कोष में जमा करके उसके बढ़ने में स्टर्लिंग जमा (Sterling Balances) प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार समस्त स्टर्लिंग क्षेत्र का डालर इस कोष में जमा रहता था और प्रत्येक देश आवश्यकता पड़ने पर कोष में से डालर निकाल

वर व्यय कर मचना था। कोष में विदेशी विनिमय की मात्रा सीमित होने के कारण प्रत्येक देश केवल उतना ही डालर निकाल सकता था जितना कि उसके लिए विलुप्त अनिवार्य होता था।

भारत भी साम्राज्य डालर कोष का सदस्य बन गया और १९३६ में लेकर १९४४ तक भारत ने इस कोष में अधिक डालर जमा किये और कम निकाले। इस काल में भारत के द्वारा कोष में ४०५ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय जमा किया गया और केवल २६१ करोड़ रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय निकाल कर व्यय किया गया। इस प्रकार हमने व्यय करने के पश्चात् लगभग ११४ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय दिया। यही कारण था कि भारतवर्ष की डालर कोष की मददगार की कड़ी आलोचना की गई। लोगों का विचार था कि यदि भारत डालर कोष का मददगार नहीं होता तो हम अनिश्चित डालर को देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयोग कर सकते थे। किन्तु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक ही रही और कुछ समय पश्चात् भारतवर्ष डालर कोष में उसने अधिक मात्रा में डालर निकालने लगा जितना कि वह उसमें जमा करता था। इसका मुख्य कारण अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समुलन का प्रतिबल होना था। व्यापार समुलन के घाटे को पूरा करने के लिए भारतवर्ष को बहुत अधिक मात्रा में डालर कोष से डालर निकालने पड़े।

युद्ध के पश्चात् सदस्यो देशों के द्वारा साम्राज्य डालर कोष में से इतनी अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय निकाला जाने लगा कि केन्द्रीय कोष बहुत तेजी से साथ गिरने लगा और कोष को डालर निकालने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। अन्त-यह निर्दिष्ट कर दिया गया कि कोई भी देश १९४८ के व्यय के ७५% से अधिक मात्रा में डालर का व्यय नहीं करेगा।

भारत की स्टर्लिंग निधि (Sterling Balances)—

इंग्लैण्ड में भारतवर्ष की स्टर्लिंग निधि का बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाना एक महत्वपूर्ण युद्धकालीन घटना थी। युद्ध में पूर्व भी भारत का कुछ स्टर्लिंग इंग्लैण्ड में जमा रहना था किन्तु उसकी मात्रा बहुत कम थी। युद्ध आरम्भ होने के समय भारत की स्टर्लिंग निधि लगभग ६८ करोड़ रुपये थी किन्तु १९४५-४६ में इसकी मात्रा बढ़कर १७३३ करोड़ रुपये हो गई। युद्ध से पूर्व भारत पर प्रायः इंग्लैण्ड का ऋण रहता था किन्तु युद्धकाल में भारत के हिमाद में इतना अधिक स्टर्लिंग जमा हो गया कि उसने कदम अपने पुराने ऋणों का भुगतान ही नहीं कर दिया एवं एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टर्लिंग ऋण इंग्लैण्ड पर बाजित हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर नोट जारी करने का अधिकार था। युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था से पूरा-पूरा लाभ उठाया। इंग्लैण्ड भारतवर्ष में जो भी सामान खरीदता था उसके बदले में ब्रिटिश सरकार स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ ही देती थी और रिजर्व बैंक

इन प्रतिभूतियों के आधार पर नये नोट जारी कर देना था जिनके द्वारा इन वस्तुओं के भुगतान की निवृत्तियाँ जाँची जायें। इस प्रकार भारत के हिस्से में स्टर्लिंग जमा बढ़ती गई। आरम्भ में तो सरकार ने ऋणों का भुगतान किया किन्तु इन ऋणों का भुगतान कर देने के पश्चात् हमारी स्टर्लिंग जमा इङ्ग्लैंड के ऊपर ऋण के रूप में बाँट दी गई और भारतवर्ष, जो ऋणी था, युद्धकालीन दत्ताओं के कारण ऋणदाता बन गया।

पीछे पावने के जमा होने के कारण—युद्ध काल में भारत के पीछे-पावने के जमा होने के निम्नलिखित कारण थे—

(i) इंग्लैंड के साथ एक अतिरिक्त समझौते के अन्तर्गत भारतवर्ष की रक्षा सम्बन्धी व्यय को पूरा करने की जिम्मेदारी सीमित थी और इसमें अधिक जितनी भी मात्रा में सेनाओं आदि पर व्यय किया जाता था उसका भुगतान इङ्ग्लैंड के द्वारा किया जाता था। भारतीय सरकार ने साथी देशों की फौजों पर बहुत बड़ी मात्रा में व्यय किया जिसका अधिक भाग हमें इङ्ग्लैंड से स्टर्लिंग जमा के रूप में प्राप्त हुआ और उस प्रकार हमारी स्टर्लिंग निधि में निरन्तर वृद्धि होती गई।

(ii) ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में भारत से खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदी जिनके लिए रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग के रूप में भुगतान मिलता था और वह भारतीय जनता को उनका भुगतान रुपये में करता था। युद्ध काल में इंग्लैंड तथा अन्य साथी देशों के कारणों से युद्ध सामग्री का उत्पादन करने में लगे हुए थे, इसलिए उपभोग सम्बन्धी सामान के लिए उन्हें भारत पर निर्भर रहना पड़ता था। साथी फौजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग सम्बन्धी वस्तुएँ इङ्ग्लैंड तथा अन्य पड़ोसी देशों की भेजी जा रही थीं। इन वस्तुओं का भुगतान तुरन्त नहीं किया जाता था बल्कि उनके बदले में हमें स्टर्लिंग जमा प्राप्त होती थी।

(iii) युद्ध काल में भारत का व्यापार मनुष्य इङ्ग्लैंड के साथ पक्ष में रहता था। भारत में इङ्ग्लैंड जाने वाले सामान की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी किन्तु जहाजों की कमी तथा सामान उपलब्ध न होने के कारण इङ्ग्लैंड में बहुत कम सामान भारत आता था। व्यापार मनुष्य पक्ष में होने के कारण भारत की इंग्लैंड में बहुत सा भुगतान लेना होता था। यह सब भुगतान स्टर्लिंग जमा के रूप में किया जाता था।

(iv) रिजर्व बैंक ने भारतवासियों में दुर्लभ मुद्राएँ तथा डॉलर प्रतिभूतियों को रुपये के बदले में लेकर सामान्य डॉलर कोष में जमा कर दिया जिनके बदले में उसे स्टर्लिंग जमा प्राप्त हुई। अमेरिका ने भारतवर्ष में जो सामान खरीदा उसके बदले में प्राप्त होने वाले डॉलर को भी डॉलर कोष में जमा कर दिया गया और उसके बदले में हमें स्टर्लिंग दिया गया। इस प्रकार भारत को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति

डालर आय को साम्राज्य डालर कोष में रखता जाता था और ब्रिटिश सरकार उसके बदले में हमें स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ देती थी।

(v) युद्ध काल में भारतवर्ष में अमेरिकन सेनाओं काफ़ी समस्या में रहती थी जिनके लिए भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में धन्य करना पड़ता था। अमेरिकन सेनाओं पर किये जाने वाले इस व्यय के बदले में भारत को जो डालर प्राप्त होता था वह सब साम्राज्य डालर कोष में जमा कर लिया जाता था और उसके बदले में हमें केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ दी जाती थी।

उपरोक्त सब कारणों में भारत के हिमाय में बहुत बड़ी मात्रा में स्टर्लिंग जमा होना गया। यह सब स्थिति भुगतानों का परिणाम था। इंग्लैंड ने हमारी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए तुरन्त भुगतान न करके यह वायदा किया कि यह सब भुगतान युद्ध के पश्चात् निवृत्त दिये जायेंगे। भारत की यह स्टर्लिंग जमा भारत-वासियों के ह्वाग तथा उल्लिखन का परिणाम थी। भारतीय कारखानों से दिन-रात इतना अधिक काम लिया गया कि उनकी मशीनें घिस कर बेकार हो गईं। विदेशों को दत्तनी बड़ी मात्रा में उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए आन्तरिक उपभोग को कम करना पड़ा जिसके कारण लोगों को काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। भारतवर्ष में वस्तुओं की दत्तनी कमी हो गई कि लोगों को मजबूर होकर अपने उपभोग को स्थगित करना पड़ा। स्टर्लिंग निधि के जमा होने के कारण भारत में मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो गई जिसके बहुत बुरे परिणाम हुए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारी स्टर्लिंग सम्पत्ति हमारे बलिदानों व कष्टों का प्रतीक थी। वह एक प्रकार का अनिवार्य ऋण था जो हमें इंग्लैंड को देना पड़ा।

भारत के पौड पावनों की रकम युद्ध-काल में किम तीव्र गति से बढ़ी इसे नीचे दी गई तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सन् १९३६ में हमारे पौड पावनों की रकम केवल ६४ करोड २० के बराबर थी जो अप्रैल सन् १९४६ में १७३३ करोड रुपये की अधिकतम सीमा पर थी। पौड पावनों की प्रगति निम्न प्रकार थी—

वर्ष	पौड पावनों की रकम करोड रुपये में
अगस्त १९३६	६४
१९३६—४०	६१
१९४०—४१	१६६
१९४१—४२	२११
१९४२—४३	३६४
१९४३—४४	७५५
१९४४—४५	११८२
१९४५—४६	१५४६
१९४६—४७	१६६२

पौंड पावनों का भुगतान (Utilization of Sterling Balances)—

पौंड पावनों के भुगतान सम्बन्धी बातचीत युद्ध-काल में ही आरम्भ हो गई थी किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं हो पाया था। युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड की ओर से यह सुझाव दिया गया कि पौंड पावनों को कम कर दिया जाय। यह कहा गया कि युद्ध सम्बन्धी जो व्यय ब्रिटिश सरकार ने किया है उसका बोझ अकेले इंग्लैंड पर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि शत्रु को परास्त करने में भारत का हित भी उतना ही था जितना कि इंग्लैंड का। कुछ व्यक्तियों ने यह तर्क भी रखा कि भारतवर्ष ने अपनी वस्तुओं के लिए बहुत ऊँचे मूल्य लिए हैं जिसके कारण काफी अधिक मात्रा में स्टर्लिंग जमा हो गया है। अतः भारत की स्टर्लिंग निधि को कम कर दिया जाय। यह भी कहा गया कि इनमें बड़े ऋण को चुकाना इंग्लैंड की क्षमता के बाहर है इसलिए उसमें कमी करना आवश्यक है। किन्तु भारत ने अपनी स्टर्लिंग निधि में कमी किये जाने का विरोध किया और इन तर्कों का जवाब दिया गया। भारत की ओर से यह कहा गया कि इतना बड़ा ऋण भारत ने स्वेच्छा से नहीं दिया है बल्कि वह जबरदस्ती लिया गया है। अतः उसमें कमी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त भारत की स्टर्लिंग जमा के पीछे भारतवासियों के कष्ट तथा त्याग छिपे हुए हैं इसलिए उसे कम करना न्यायपूर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में सर्व-वितर्क चलता रहा और ब्रिटिश सरकार किसी न किसी बहाने से इनके भुगतान को टालती रही। भारतवर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी पौंड पावनों के भुगतान के प्रश्न को उठाना चाहा किन्तु कोष ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अन्त में इंग्लैंड ने यही निश्चय किया कि भारत की स्टर्लिंग जमा में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी किन्तु उसका भुगतान एकदम न होकर धीरे-धीरे किया जायेगा।

सन् १९४७ का समझौता—जनवरी सन् १९४७ को भारत और इंग्लैंड के बीच पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया किन्तु परिस्थिति परिवर्तन के कारण इस समझौते के अनुसार कार्य नहीं हो सका और १४ अगस्त १९४७ को एक नया समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत सीमित मात्रा में स्टर्लिंग मुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस समझौते के अनुसार पौंड पावनों को दो छातों में जमा किया गया। छाता नं० १ में ६०५ करोड़ पौंड जमा किये गये जिनका प्रयोग किसी भी देश से माल मगाने के लिए किया जा सकता था। छाता नम्बर २ में ११६ करोड़ पौंड जमा किये गये जिनका प्रयोग केवल पूँजीगत माल खरीदने के लिए किया जा सकता था। यह समझौता दिसम्बर १९४७ तक के लिए था किन्तु इसकी अवधि को ६ महीने और बढ़ा दिया गया।

जुलाई सन् १९४८ का समझौता—पहले समझौते की अवधि समाप्त होने पर जुलाई १९४८ को एक नया समझौता किया गया। इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें अप्रतिष्ठित थी—

(i) इंग्लैंड ने जो फौजी सामान तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति भारत में छोड़ी थी उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसके भावजों के रूप में ११३ करोड़ ६० का भुगतान इंग्लैंड को कर दिया गया। भावजों की यह रकम हमारी स्टलिंग जमा में से कम कर दी गई।

(ii) २२४ करोड़ रुपये की एक राशि भारत सरकार ने इंग्लैंड के पान जमा कर दी जिसमें से केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के अग्रज अधिकारियों को पेनशन का भुगतान किया जा सके। २२४ करोड़ रुपये की यह रकम हमारी स्टलिंग जमा में से कम कर दी गई।

(iii) इस समझौते में जून सन् १९५१ तक के तीन वर्षों में १०७ करोड़ रुपये के मूल्य के स्टलिंग को मुक्त करने की व्यवस्था की गई। पिछले समझौते में जो १११ करोड़ रुपये के स्टलिंग को मुक्त करने की व्यवस्था की गई थी उसमें से केवल ४ करोड़ रुपये का ही सामान मगाया जा सका था। इस समझौते में दोष १०७ करोड़ रुपये की यह रकम भी लक्ष की जा सकती थी। इस प्रकार १९४८ के समझौते के फलस्वरूप २१४ करोड़ रुपये के स्टलिंग को मुक्त करने की व्यवस्था की गई। इसके अनिश्चित पौंड पावनों में से १२६ करोड़ रुपया पाकिस्तान के हिस्से के रूप में निकाल दिया गया।

जुलाई सन् १९४६ का समझौता—इस समझौते की अवधि में दूसरा समझौता करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटेन को डालर की भारी कमी अनुभव हो रही थी जिसके कारण १९४८ के समझौते को पूरी तरह से कार्य रूप में नहीं लाया जा सका। नये समझौते के अन्तर्गत १९४८-४९ के लिए ३१ करोड़ रुपये तथा १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लिए ५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का स्टलिंग मिलना निश्चित हुआ। इसके अनिश्चित जुलाई १९४६ से पूर्व जो आर्डर जा चुके थे उनके भुगतान के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने स्टलिंग देना स्वीकार कर लिया। भारतवर्ष का डालर की कमी पूरा करने के लिए केन्द्रीय कोष से १४ व १५ करोड़ डालर देन का अधिकार दे दिया गया।

मार्च सन् १९५१ में हमारी स्टलिंग जमा ८८४ करोड़ रुपये रह गई थी। जुलाई सन् १९५१ में एक समझौते के अन्तर्गत इंग्लैंड ने ६ वर्ष के लिए प्रतिवर्ष ४७ करोड़ रुपये तक का स्टलिंग प्रयोग करने की अनुमति दे दी।

सन् १९५२ का समझौता—फरवरी सन् १९५२ में पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में एक और समझौता किया गया। अब भारतवर्ष की स्टलिंग जमा केवल ७६१ करोड़ रुपये रह गई थी। इस समझौते में सन् १९५७ तक प्रतिवर्ष ३५ करोड़ पौंड मुक्त करने की व्यवस्था की गई। इसके अनिश्चित २१ करोड़ पौंड की एक राशि मार्च नम्बर १ में जमा कर दी गई, जिसका प्रयोग भारत केवल सकट काल में ही कर सकता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने

२६० करोड़ रुपये की स्टलिङ्ग जमा का प्रयोग करने का निश्चय किया था किन्तु उससे बहुत कम खर्च किया जा सका और जून सन् १९५४ में हमारी स्टलिङ्ग निधि ७८४ करोड़ रुपये थी। नवम्बर सन् १९५६ में यह जमा घटकर ५३६ करोड़ रुपये रह गई और मई सन् १९५७ में केवल ५०० करोड़ रुपये का स्टलिङ्ग शेष था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश ने लगभग समस्त स्टलिङ्ग जमा का प्रयोग कर डाला है।

युद्धोत्तर-काल में भारतीय रुपया—

युद्धोत्तर-काल में भारतीय रुपये की स्थिति तथा उसके मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। युद्धोत्तर-काल की प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता, रुपये का अवमूल्यन, सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति तथा आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ-प्रबन्ध की व्यवस्था।

भारत में स्वर्ण-समता मान (Gold Parity Standard in India)—

सन् १९४५ में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वित्तीय मामलों में अधिक निकट सहयोग का युग प्रारम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank of Reconstruction & Development) की स्थापना हुई। मुद्रा कोष ने मार्च १९४७ में अपना कार्य प्रारम्भ किया। भारतवर्ष को मुद्रा कोष का सदस्य बनना चाहिए अथवा नहीं—इस विषय पर कुछ दिनों तक वाद-विवाद चलता रहा किन्तु अन्त में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना स्वीकार कर लिया और मुद्रा कोष की ओर से भारत का कोटा ४० करोड़ टांका निर्दिष्ट कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के साथ भारतवर्ष में एक नये मुद्रामान का प्रारम्भ हुआ। स्टलिङ्ग विनिमय मान का अन्त हो गया और उसके स्थान पर देश में स्वर्ण-समता मान (Gold Parity Standard) स्थापित कर दिया गया। अप्रैल सन् १९४७ को भारतीय रुपये और स्टलिङ्ग का वैधानिक सम्बन्ध टूट गया और रिजर्व बैंक की निर्दिष्ट दरा पर असीमित मात्रा में स्टलिङ्ग बेचने व खरीदने की जिम्मेदारी समाप्त कर दी गई। अब भारतीय रुपया एक स्वतन्त्र मुद्रा थी और उसका विदेशी मूल्य प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट होता था। रिजर्व बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों के साथ रुपये के मूल्य को बनाये रखना पड़ता था। इस प्रकार रुपये का सम्बन्ध अन्य मुद्राओं के साथ भी स्थापित हो गया। मुद्रा कोष की सदस्यता के कारण भारत सरकार को रुपये का स्वर्ण मूल्य घोषित करना पड़ा। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह सूचित किया कि रुपये का मूल्य ०.००८६३५७ ग्रीस शुद्ध सोने के बराबर होगा। रुपये का यह स्वर्ण मूल्य उस समय प्रचलित दर १ रुपया = १ शि० ६ पैसे के आधार पर निर्दिष्ट किया गया। रिजर्व बैंक इस दर को यथामुम्भव

बनाये रखने का प्रयत्न करेगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसमें मुद्रा कोष की अनुमति से परिवर्तन भी किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मददस्यता के साथ भारत में एक स्वतन्त्र मुद्रामान का जन्म हुआ।

परीक्षा प्रश्न

- (१) भारतीय मुद्रा प्रणाली पर द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभावों की विवेचना कीजिए।
(सामर बी० काम १९५७, दिक्क बी० ए० १९५६, आगरा बी० काम १९५५, १९५७ s)
- (२) सन् १९२७ से भारतीय मुद्रा प्रणाली के इतिहास की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए।
(आगरा बी० ए० १९५७ s)
- (३) गत महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने मुद्रा एवं विनिमय के सम्बन्ध में क्या कठिनाइयाँ अनुभव की थीं? उसने परिस्थिति का किस प्रकार सामना किया?
(आगरा बी० काम १९५८)
- (४) सन् १९२६ से भारतीय मुद्रा के इतिहास का वर्णन कीजिए। पिछले महा-युद्ध में किन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा?
(आगरा बी० काम १९५४)
- (५) डालर कोष पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। (राजस्थान बी० काम १९५६)
- (६) भारत के पौंड पावनों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए जो आपकी कापी के चार पृष्ठों से अधिक न हो।
(राजस्थान १९५५)
- (७) सन् १९२७-१९३६ के बीच भारतीय मुद्रा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिये।
(आगरा बी० ए० १९६०)
- (८) हिल्टन यंग कमीशन की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालो। भारत सरकार द्वारा उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया था।
(आगरा बी० ए० १९६३, विक्रम बी० काम १९५६, गोरखपुर बी० काम १९५६)
- (९) सन् १९२६ में हिल्टन यंग कमीशन ने रुपये का विनिमय मूल्य १ शि० ६ पेंस निर्धारित करने के समयन में जो तर्क दिये थे, वे लिखिये और उनकी आलोचना कीजिए।
(भागपुर बी० ए० १९५७)
- (१०) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना से लेकर वर्तमान युग तक भारतीय चलन प्रणाली पर प्रकाश डालिये।
(आगरा बी० काम १९५८)
- (११) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मददस्यता से भारतवर्ष में एक नये मुद्रामान का आरम्भ हुआ है। भारत की वर्तमान मुद्रा पद्धति का मनक परीक्षण कीजिए।
(आगरा बी० ए० १९५६)

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

DEVALUATION OF THE INDIAN RUPEE

स्वर्णमान की व्यवस्था में प्रतिदूषित भुगतान सतुलन स्वर्ण के निर्यात के द्वारा स्वयं ठीक होने की प्रवृत्ति रखता है। किन्तु विनिमय दरों में आधारभूत असतुलन हो जाने पर देश से इतनी बड़ी मात्रा में सोना बाहर जाने लगता है कि वहाँ की अर्थ-व्यवस्था उसे सहन करने में असमर्थ होती है। ऐसी दशा में विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन करके सोने के अनावश्यक निर्यात को रोका जा सकता है तथा भुगतान सतुलन के घाटे को दूर किया जा सकता है। व्यापार सतुलन में स्थाई असतुलन पैदा हो जाने की दशा में देशों को अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करना पड़ता है। मुद्रा के विदेशी मूल्य में इस प्रकार के परिवर्तन को अवमूल्यन कहते हैं। पत्र मुद्रामान में भुगतान सतुलन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कभी-कभी देशों को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है।

अवमूल्यन का अर्थ (Meaning of Devaluation)—

बिसी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य में कमी करने को अवमूल्यन कहा जाता है। प्रत्येक मुद्रा की स्वर्ण समता (Gold Parity) प्रायः निश्चित होती है किन्तु कभी-कभी भुगतान सतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए इस स्वर्ण समता को कम करना अनिवार्य हो जाता है। जब कोई देश स्वेच्छा से अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को गिरा देता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जिस मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है उसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कम हो जाता है और उसके बदले में पहले की अपेक्षा कम मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त होने लगता है। सन् १९२८ में जब फ्रांस में स्वर्णमान को फिर से स्थापित किया गया तो फ्रैंक (Franc) की स्वर्ण समता पहले की अपेक्षा कम निश्चित की गई। इसी प्रकार सन् १९३१ में इंग्लैंड में स्वर्णमान के स्थगित किये जाने पर पाउंड का स्वर्ण मूल्य गिर गया। सन् १९३४ में अमेरिका ने सोने के सम्बन्ध में डॉलर के मूल्य को कम कर दिया। सन् १९३६ में फ्रांस ने फिर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जो २५.२

और ३४ ३ प्रतिशत के बीच में था। सितम्बर १९४६ में इंग्लैंड के द्वारा अपने पाउंड के मूल्य को ३० ५ प्रतिशत कम कर दिया गया। इसके साथ ही भारत, पश्चिमी यूरोपीय देश, मिस्र व यूनान ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया।

अवमूल्यन के उद्देश्य (Objects of Devaluation)—

अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य व्यापार संतुलन के घाटे को दूर करना होता है। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन काफी लम्बे समय तक विपक्ष में चलता रहता है तो वह उस देश के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के कोषों को समाप्त कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। व्यापार संतुलन में स्थाई घाटे की दशा उत्पन्न होने की दशा में सरकार विभिन्न प्रकार के तरीकों से व्यापार संतुलन को ठीक करने का प्रयत्न करती है। मुद्रा-संकुचन (Deflation) के द्वारा व्यापार संतुलन के घाटे को दूर करने में सफलता मिल सकती है किन्तु इस प्रकार की नीति के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मुद्रा व सौत की मात्रा का कम करन से मूल्य गिर जाते हैं और निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम होत हैं जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन ठीक हो जाता है। किन्तु कीमती व कम होने से देश में बेरोजगारी फैल सकती है तथा उत्पादन कम होने लगता है। इसलिए कोई भी देश आजकल मुद्रा-संकुचन को पसन्द नहीं करता है। मुद्रा-संकुचन के द्वारा व्यापार संतुलन को ठीक करना सब उचित होता है जबकि व्यापार संतुलन का घाटा मुद्रा-प्रसार (Inflation) के कारण उत्पन्न हुआ हो। मुद्रा-संकुचन के अनिश्चित व्यापार संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग भी किया जा सकता है। किन्तु विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत आयातों पर कठोर प्रतिबंध लगाने होते हैं और उनकी मात्रा को बहुत अधिक कम करना होता है। ऐसा करना प्रायः देशों के लिए सम्भव नहीं होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मुद्रा के अवमूल्यन व अनिश्चित और दोहरे रास्ता नहीं रह जाता है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम हो जाते हैं क्योंकि मुद्रा का विदेशी मूल्य कम हो जाने से हमारी वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं और उनकी वस्तुएँ हमारे लिए महँगी हो जाती हैं। निर्यातों के बढ़ने तथा आयातों के कम होने से व्यापार संतुलन ठीक हो जाता है।

रूपों का अवमूल्यन—

अवमूल्यन में हमारा अभिप्राय किसी मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करने में होता है। मुद्रा अवमूल्यन विभिन्न उद्देश्यों में किया जा सकता है किन्तु सामान्यतः उनका प्रयोग भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी देश की विदेशी व्यापार में बराबर घाटा होता जाता है तो वह देश अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करके अपनी निर्यातों को प्रोत्साहन देता है। अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तुएँ दूसरे देशों के लिए सस्ती हो जाती हैं जिसके कारण उन

देश से निर्यात घटते हैं और व्यापार सन्तुलन का घाटा दूर हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इंग्लैंड तथा अन्य साम्राज्य देशों के सम्मुख डालर समस्या उपस्थित थी। संसार के अधिकांश देश अपनी आवश्यकताओं के लिए अमेरिका पर निर्भर थे और अमेरिका से सामान मगाने के लिए भारी मात्रा में डालर की मांग की जा रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों को डालर की भारी कमी अनुभव हो रही थी। निर्यात तथा इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी। अमेरिका के साथ इंग्लैंड का भुगतान सन्तुलन बिगड़ता जा रहा था और इसमें निरन्तर घाटा रहता था। साम्राज्य देशों का डालर कोष बराबर गिरता जा रहा था। इन मन् १९४८ में इंग्लैंड का डालर कोष घटकर केवल ४०६ मिलियन पाँड रह गया। प्रतिवर्ष भुगतान सन्तुलन में डालर का घाटा बढ़ता जाता था। मन् १९४९ में इस घाटे का अनुमान ६०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष लगाया गया। कुछ समय तक इंग्लैंड भुगतान सन्तुलन के घाटे को अमेरिका से मिलने वाली सहायता तथा ऋणों के द्वारा पूरा करता रहा। भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के भुगतान सम्बन्धी समझौते किये गए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक से ऋण भी लिये गए किन्तु ये अल्पकालीन उपाय बहुत अधिक सफल न हो सके और साम्राज्य देशों का डालर कोष निरन्तर गिरता गया। इस समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने का एक ही उपाय था कि इंग्लैंड में अमेरिका को होने वाले निर्यातों को बढ़ाया जाये। ऐसा करने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं को अमेरिका के लिए सस्ता करना आवश्यक था। अतः इंग्लैंड ने अपने भुगतान सन्तुलन के घाटे को दूर करने के लिए पाँड का अवमूल्यन करने का निश्चय किया।

१८ नवम्बर मन् १९४९ को इंग्लैंड ने पाँड के अवमूल्यन की आधिकारिक घोषणा की और अमेरिकन डालर के माध्यम में पाँड के मूल्य को ३० १/२% कम कर दिया गया। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पाँड का मूल्य ४.०३ डालर से घटकर २.८८ डालर रह गया। पाँड के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं को विदेशियों के लिए सस्ती करना था जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा सके और भुगतान सन्तुलन के घाटे को दूर किया जा सके। यद्यपि यह अनुभव किया जा रहा था कि इंग्लैंड पाँड डालर की इस ऊँची दर (£ 1 = \$ 4.03) को अधिक समय तक नहीं बनाये रख सकेगा और वित्तीय क्षेत्रों में पाँड के अवमूल्यन की प्रत्याशा की जा रही थी किन्तु पाँड का इनका अधिक अवमूल्यन वित्तीय आकस्मिक था। पाकिस्तान को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य सभी देशों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया। पाँड के अवमूल्यन से ब्रिटेन को काफी लाभ हुआ और भुगतान सन्तुलन का घाटा समाप्त हो गया किन्तु यह लाभ अस्थायी था।

पाँड का अवमूल्यन हो जाने पर भारत के नामने यह प्रश्न था कि उसे अपने रुपये का अवमूल्यन करना चाहिए अथवा नहीं। उस समय भारत की स्थिति इंग्लैंड जैसी ही थी और हमें भी भुगतान सन्तुलन विप्लव में होने के कारण डालर का बहुत

घाटा रहता था। ऐसी स्थिति में रुपये का अवमूल्यन भारत के आर्थिक हितों के अनुकूल था। भारतीय सरकार ने स्टलिंग का अवमूल्यन होने के २४ घंटों के अन्दर ही अपना निर्णय ले लिया और रुपये का भी उतना ही अवमूल्यन कर दिया गया जितना कि स्टलिंग का हुआ था। रुपये के डालर तथा स्वर्ण मूल्य को ३०.५०% कम कर दिया गया। रुपये का डालर मूल्य ३०.२२५ सेन्ट (Cents) से घटकर २१ सेन्ट रह गया और उसका स्वर्ण मूल्य ०.२६८०१ ग्राम से कम होकर ०.१८६६२१ ग्राम रह गया। अवमूल्यन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय वस्तुओं के मूल्य अमेरिका के लिए कम हो गये और अमेरिकन चीजें भारत वालों के लिए महंगी हो गईं।

रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया—

माधारण व्यक्ति यह समझता है कि रुपये स्टलिंग का प्राचीन सम्बन्ध होने के कारण पौंड का अवमूल्यन होने पर रुपये के विदेशी मूल्य को कम करना आवश्यक था। किन्तु वास्तव में यह बात नहीं थी और भारत ने रुपये का अवमूल्यन किसी दबाव के कारण नहीं किया। अवमूल्यन के समय भारतीय स्वयं स्वतन्त्र मुद्रा थी और स्टलिंग के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसी दशा में रुपये का अवमूल्यन करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं था। भारत की आर्थिक दशाओं को देखते हुए सरकार ने अपने स्वतन्त्र निर्णय के द्वारा ही रुपये के अवमूल्यन का निश्चय किया। यद्यपि उस समय भारत की आर्थिक दशाएँ ऐसी नहीं थी जिनके कारण रुपये का अवमूल्यन आवश्यक हो किन्तु इंग्लैंड के पौंड का अवमूल्यन हो जाने से ऐसी दशाएँ उत्पन्न हो गई थी जिनके कारण मजबूर होकर हमें भी रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता अनुभव की गई—

(१) स्टलिंग क्षेत्र के साथ अधिकांश व्यापार का होना—भारतवर्ष को अपने रुपये का अवमूल्यन इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत का ७५% व्यापार स्टलिंग क्षेत्र वाले देशों के साथ था। यदि रुपये का अवमूल्यन न किया जाता तो भारतीय सामान स्टलिंग देशों के लिए महंगा हो जाता जिसके कारण बहुत सा विदेशी व्यापार समाप्त हो जाने का भय था। ऐसी दशा में रुपये का स्टलिंग के साथ सम्बन्ध अनिवार्य था।

(२) भुगतान सन्तुलन का विपक्ष में होना—हमारे व्यापार सन्तुलन का निरन्तर विपक्ष में रहना भी रुपये के अवमूल्यन का एक महत्वपूर्ण कारण था। व्यापार सन्तुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक था कि आयातों को कम किया जाय और निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाय। सन् १९४६ के पश्चात् भारतवर्ष को भी डालर की भारी कमी अनुभव हो रही थी और डालर का घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा था। डालर के घाटे को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से डालर

उधार लिए गये तथा स्टर्लिंग निधि को डालर में परिवर्तित कराने का प्रयत्न किया गया। डालर समस्या को सुलभाने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि अमेरिका को निर्यात बढ़ाये जाये और वहाँ से होने वाली आयातों को कम किया जाय। रुपये के अवमूल्यन के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति भली प्रकार से की जा सकती थी। अतः रुपये का अवमूल्यन करने का निश्चय किया गया।

(३) हमारे मूल्य-स्तर का ऊँचा होना—भारतवर्ष में मूल्य अपेक्षाकृत बहुत ऊँचे थे जिसके कारण हमारी वस्तुओं की माग बहुत कम रहती थी। हमारा मूल्य-स्तर इंग्लैंड की अपेक्षा ऊँचा था और यदि हमने रुपये का अवमूल्यन स्टर्लिंग के बराबर न किया होता तो हमारा मूल्य नपडा तथा अन्य वस्तुयें ब्रिटिश वस्तुओं के साथ विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता न कर सकती। इसलिए रुपये का अवमूल्यन अपनी वस्तुओं के विदेशी बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। पौंड के अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय वस्तुयें साम्राज्य देशों के लिए और अधिक महंगी न हो जायें इसलिए भारतीय रुपये का भी स्टर्लिंग के बराबर ही अवमूल्यन कर दिया गया।

अवमूल्यन के आर्थिक परिणाम—

रुपये के अवमूल्यन का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार ही भारत के भुगतान सन्तुलन में सुधार हुआ तथा विदेशी विनिमय की समस्या कुछ सीमा तक सुलभ गई किन्तु इसके साथ ही हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अवमूल्यन के कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर अवमूल्यन के निम्नलिखित प्रभाव हुए—

(१) भुगतान सन्तुलन का घाटा दूर हो गया—अवमूल्यन के समय यह आशा की गई थी कि रुपये का विदेशी मूल्य कम हो जाने से भारत के भुगतान सन्तुलन में बाकी सुधार हो जायगा और निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ और रुपये के अवमूल्यन से हमारे व्यापार सन्तुलन में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। अवमूल्यन से डालर क्षेत्र को होने वाली निर्यातों को प्रोत्साहन मिला क्योंकि अब डालर भारत में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सामान खरीद सकता था। इसके दूसरी ओर अमेरिकन वस्तुओं के मूल्य हमारे लिए ३०.५% बढ़ गये जिसके कारण अमेरिका से होने वाली आयात की मात्रा घट गई। निर्यातों के बढ़ने तथा आयातों में कमी हो जाने के कारण भारत के व्यापार सन्तुलन का घाटा दूर हो गया। सन् १९४४-४६ में भारत व्यापार के सन्तुलन में १८३.४५ करोड़ रुपये का घाटा था। यह घाटा १९४६-५० में घट कर ११८.२६ करोड़ रह गया और १९५०-५१ में केवल २२ करोड़ रुपये था। इसके पश्चात् कुछ समय के लिए व्यापार सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया किन्तु यह सुधार अस्थायी था और १९५१-५२ में फिर व्यापार सन्तुलन विपक्ष में जाने लगा। रुपये के अवमूल्यन से डालर समस्या

को मुलमानों में भी बड़ी सहायता मिली। डालर देशों के साथ व्यापार सन्तुलन में होने वाला घाटा बहुत कम हो गया। सन् १९४८ में हमें डालर देशों के साथ ५३ करोड़ रुपये का घाटा था। १९५० में यह सब घाटा दूर हो गया और डालर देशों के साथ हमारे व्यापार सन्तुलन में २६ करोड़ रुपये की बचत थी। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापार सन्तुलन में होने वाला यह सुधार केवल रुपये के अव-मूल्यन के कारण हुआ किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतवर्ष की स्थिति को सुधारने में अवमूल्यन का बहुत बड़ा हाथ था।

(२) आर्थिक विकास में बाधा—रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अमेरिकन मशीनों तथा अन्य पूर्वीय वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और अब उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदना भारत के लिए सम्भव नहीं था। इन सरकार को बहुत सी विकास योजनाओं को स्थगित करना पड़ा जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। अमेरिका में आने वाले अनाज का मूल्य भी बढ़ गया जिसके कारण भारतवर्ष में खाद्य सामग्रियों की कमी हो गई। साथ सामग्रियों की बचती हुई कमी के कारण भी आर्थिक विकास में बाधा पड़ी। पाकिस्तान के रुपये का अवमूल्यन न होने के कारण वहाँ में शान्त होने के लिये सामान का मूल्य बढ़ गया और कच्चे माल की कमी के कारण हमारे जूट तथा कपड़ा उद्योग की प्रगति में बाधा पड़ी।

(४) भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव—अवमूल्यन के कारण भारत का पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार लगभग स्थगित हो गया और दोनों पड़ोसी देशों के सम्बन्ध विगड़ने लगे। पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जिससे कारण एक पाकिस्तानी रुपया भारत के १४६ रुपये के बराबर हो गया। इन प्रकार पाकिस्तानी वस्तुओं के मूल्य हमारे लिए ४६ प्रतिशत बढ़ गए। भारत सरकार ने इस नई विविध दर को मानने से इनकार कर दिया और उस पर विरोध प्रकट किया। इसके परिणामस्वरूप भारत पाकिस्तान व्यापार लगभग स्थगित हो गया। जूट तथा रुई के पाकिस्तान से परोक्ष मात्रा में आने के कारण भारतीय जूट तथा कपड़ा उद्योग कठिनाई में पड़ गये और कुछ मिलें तो कच्चा माल न मिलने के कारण बन्द हो गईं। सरकार ने मजबूर होकर पाकिस्तानी रुपये की नई विविध दर को स्वीकार कर लिया और एक व्यापारिक सम्झौता भी पाकिस्तान के साथ कर लिया गया।

(४) मूल्य में वृद्धि—रुपये के अवमूल्यन का एक बुरा प्रभाव यह हुआ कि हमारा मूल्य-स्तर जो पहले से ही काफी ऊँचा था उसमें और वृद्धि हो गई जिससे कारण जनता की कठिनाइयाँ बढ़ने लगीं। अवमूल्यन के समय मुद्रा-प्रसार के खर्चे को ओर सकेत किया गया था किन्तु उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि अवमूल्यन के कारण मूल्य-स्तर को नहीं बढ़ने दिया जायेगा किन्तु सरकार को इसमें सफलता न मिली और मूल्य-स्तर में पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि हो गई।

अवमूल्यन के समय जो सूचक अंक ३८२ था वह १९५१ से बढ़कर ४५७ हो गया । मूल्य-स्तर की इस वृद्धि के कारण लोगों का रहन-सहन व्यय बढ़ गया और मध्यम श्रेणी के लोगों को विशेष कठिनाई उठानी पड़ी ।

(५) डालर के सम्बन्ध में हमारी स्टर्लिंग जमा का मूल्य घट गया—अवमूल्यन के कारण हमारे पौड पावनों का मूल्य, जहाँ तक उन्हें अमेरिका में प्रयोग करने का सम्बन्ध था ३३% कम हो गया । स्टर्लिंग का मूल्य कम हो जाने के कारण अब हम अपनी स्टर्लिंग जमा से अमेरिका में कम सामान खरीद सकेंगे ।

(६) सरकारी बजट के ऊपर प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन का केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के बजट पर भी प्रभाव पड़ा । सन् १९४६-५० में वित्तीय मन्त्री के अनुसार अवमूल्यन के कारण केन्द्रीय सरकार के व्यय में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान था । अवमूल्यन के कारण सरकार के रक्षा सम्बन्धी तथा पूँजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई । अमेरिका से अनाज मगाने पर भी सरकार को अब अधिक व्यय करना होता था ।

रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न—

अवमूल्यन के पश्चात् भारत की आर्थिक दशा खराब होने लगी और देश के सामने मुद्रा-प्रसार को रोकने का प्रमुख समस्या उपस्थित थी । सन् १९४६ में रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण मूल्य-स्तर काफी ऊँचा हो गया था और मुद्रा-प्रसार एक भयंकर गण धारण करता जा रहा था । भारत सरकार ने मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए ५ अप्रैल सन् १९४६ को एक योजना घोषित की किन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशेष सफलता न मिल सकी । उसी समय कुछ लोगों के द्वारा मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए रुपये के पुनर्मूल्यन का सुझाव रखा गया । रुपये के पुनर्मूल्यन की चर्चा सितम्बर १९५० में आरम्भ हुई जब स्टर्लिंग के पुनर्मूल्यन की आशा भी की जा रही थी । डा० जान मैथाली (Dr. John Mathai) पुनर्मूल्यन के मुख्य समर्थकों में से थे और उन्होंने सन् १९५१ में रुपये के पुनर्मूल्यन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये—

पुनर्मूल्यन के पक्ष में तर्क—

(१) पुनर्मूल्यन के द्वारा मुद्रा-प्रसार को रोका जा सकेगा—रुपये के अवमूल्यन के कारण भारतवर्ष में जो मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके रोकने का एकमात्र उपाय रुपये का पुनर्मूल्यन करना था । पुनर्मूल्यन का प्रभाव यह होगा कि वस्तुओं के मूल्य कम होने लगेंगे और इस प्रकार मुद्रा-प्रसार के बढ़ने हुए घटने को रोका जा सकेगा । डालर देशों से अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को मंगाया जा सकेगा जिससे कारण वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जायगी और उनके मूल्य में होने वाली वृद्धि रुक जायगी । यद्यपि मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए अन्य उपाय भी काम में लाये जा सकते हैं किन्तु इस प्रकार के उपाय भारतवर्ष में अधिक

सफल नहीं हुए है जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय मुद्रा-प्रसार अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से पैदा हुआ है और केवल रुपये का पुनर्मूल्यन ही अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के इस घुरे प्रभाव को रोक सकेगा ।

(२) पुनर्मूल्यन डालर देशों से आने वाले वस्तुओं के मूल्यों को कम कर देगा—अमेरिका तथा अन्य डालर देशों से अधिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुएँ मगाई जा सकेंगी जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी तथा स्थिति योजनाओं पर फिर से काम आरम्भ किया जा सकेगा । अधिक मात्रा में अच्छी सामग्री का आयात किया जा सकेगा जिससे हमारे उद्योग-धंधों के विकास की दशाय उत्पन्न होगी ।

(३) भारतीय निर्यातों के लिए अधिक मूल्य मिल सकेगा—भारत से किये जाने वाले निर्यातों जैसे जूट, चाय, कपड़ा इत्यादि का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर स्थान है और उन्हें अवमूल्यन के रूप में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है । अतः रुपये का पुनर्मूल्यन करके हम अपने निर्यातों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे । इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से हमारे निर्यातों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनमें से अधिकांश की मांग बेलोचदार है ।

(४) पुनर्मूल्यन से अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भार कम हो जायेगा—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास धन के लिए गये ढालर ऋणों का भार कम हो जायेगा और भारतवर्ष को इन ऋणों का भुगतान करने के लिए कम रुपये देने पड़ेंगे ।

(५) भारत तथा पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्ध सुधर जायेंगे—अवमूल्यन के कारण जो भारत पाकिस्तान व्यापार स्थिति हो गया है उसे फिर से आरम्भ किया जा सकेगा । पुनर्मूल्यन करने में पाकिस्तानी वस्तुओं के मूल्य कम हो जायेंगे और उन्हें आसानी से मगाया जा सकेगा । व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने में दोनों देशों के आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्धों में भी सुधार होगा ।

(६) रुपये का अवमूल्यन मूल्यन भुगतान अनुदान की कठिनाइयों को दूर करने लिए किया गया था । अब व्यापार अनुदान देश के पक्ष में था और उसमें घाटे के स्थान पर वचन थी । ऐसी दशा में रुपये का पुनर्मूल्यन करके उसमें मिलने वाले घाटे में लाभों को प्राप्त किया जा सकता है ।

पुनर्मूल्यन के विपक्ष में—

यद्यपि डा० मेधाई और उनके अनुयायियों का मत था कि मुद्रा-प्रसार तथा अवमूल्यन के अन्य घुरे प्रभावों को रोकने के लिए रुपये का पुनर्मूल्यन आवश्यक है किन्तु कुछ अन्य लोगों ने पुनर्मूल्यन का विरोध किया । मुख्यतः भूतपूर्व वित्त-मंत्री श्री देवमुक्त ने रुपये के पुनर्मूल्यन का विरोध किया । पुनर्मूल्यन के विपक्ष में निम्न-लिखित तर्क दिये जाते थे—

(१) पुनर्मूल्यन से भारत की निर्यातों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा—भारतवर्ष की निर्यातों की मांग बेलोचदार नहीं है और उनके विदेशी बाजारों को बनाये रखने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता है। यह सहायता अवमूल्यन के द्वारा ही दी जा सकती है। यद्यपि मैंगनीज और अभ्रक में भारतवर्ष को एकाधिकार प्राप्त है किन्तु अन्य सभी वस्तुओं (जूट, चाय, कपड़ा इत्यादि) में हमें काफी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका तथा अन्य देशों के द्वारा सामान जमा करने की नीति के त्याग दिये जाने के कारण हमारे निर्यातों की सहायता की और भी अधिक आवश्यकता थी।

(२) पुनर्मूल्यन से भुगतान सतुलन विपक्ष में हो जायेगा—रुपये का पुनर्मूल्यन करने से हमारे निर्यात कम होंगे और आयात बढ़ जायेंगे जिसके कारण व्यापार सतुलन हमारे विपक्ष में हो जायेगा और देश अपनी ढालर समस्या को नहीं सुलझा सकेगा। श्री देशमुख के अनुसार रुपये के मूल्य में १५% की वृद्धि करने से हमारे भुगतान सतुलन का घाटा ५० करोड़ रुपये बढ़ जायेगा और ३०% की वृद्धि से भुगतान सतुलन के घाटे में १३५ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना थी। इस प्रकार रुपये का पुनर्मूल्यन भुगतान सतुलन को आवश्यक रूप से हमारे विपक्ष में कर देगा।

(३) निर्यात करों से होने वाली आय कम हो जायेगी—पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप निर्यात कम हो जायेगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को निर्यात करों को हटाना पड़ेगा अथवा उन्हें कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से निर्यात करों से होने वाली आय बहुत कम हो जायेगी।

(४) सस्ता आयात हमारे उद्योग-धन्धों पर बुरा प्रभाव डालेगा—पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ जायेगी और हमारे उद्योग-धन्धों की वस्तुओं का सुरक्षित बाजार समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार विदेशी प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण उद्योग-धन्धों को विशेष कठिनाई होगी और उनका विकास रुक जायेगा।

(५) रुपये के मूल्य की बार-बार बदलना ठीक नहीं है—यह भी कहा गया कि रुपये के लिए मूल्य में स्थिरता लाने के लिए तथा विदेशियों का विश्वास उसमें बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि अल्पकालीन लाभ प्राप्त करने के लिए रुपये के मूल्य में बार-बार परिवर्तन न किये जायें। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि रुपये के मूल्य सम्बन्धी जो भी नीति अपनाई जाये वह दीर्घकालीन होनी चाहिए।

(६) पुनर्मूल्यन से हमारी स्टॉक जमा कम हो जायेगी—जिस अनुपात में रुपये के मूल्य में वृद्धि की जायेगी उसी अनुपात में हमारे पीछे पावने कम हो जायेंगे और हम उनसे कम मात्रा में सामान खरीद सकेंगे।

रुपये का और अधिक अवमूल्यन किया जाना चाहिए ?—

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हमारे देश के भुगतान सतुलन की स्थिति काफी सुधर गई थी क्योंकि योजना के पाँच वर्षों में हमारे विदेशी विनिमय कोष में केवल १५८ करोड़ रुपये की कमी हुई। इसका मुख्य कारण हमारे देश में मानसून का अनुकूल होना तथा अमेरिका के द्वारा भारी मात्रा में कच्चे माल का खरीदा जाना था। किन्तु दूसरी योजना के साथ हमारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ आरम्भ हो गईं। योजना के प्रथम पन्द्रह महीनों में ही हमारे विदेशी विनिमय कोष में २७८ करोड़ रुपये की कमी हुई और इससे अतिशक्ति हम ६७ करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेना पड़ा। योजना के दोष काल में भी विदेशी विनिमय कोष तेजी के साथ गिरना गया और योजना के अन्त में वह केवल २८० करोड़ रुपये रह गया। विदेशी विनिमय की इस समस्या को मुलभूताने के लिए बहुत से सुझाव रखे गये और सरकार ने विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यय में बचत करने के लिए बहुत कुछ किया।

विदेशी विनिमय की कमी को दूर करने लिए यह सुझाव भी दिया गया कि रुपये का और अधिक अवमूल्यन करना चाहिए जिससे हमारी निर्यातों को प्रोत्साहन मिले और आयातों में कमी हो। लन्दन के कुछ आर्थिक क्षेत्रों का भी यही विचार था कि भारत को विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए रुपये का अधिक अवमूल्यन कर देना चाहिए। भारतवर्ष में प्रो० बी० आर० शिनोय (B. R. Shenoay) ने रुपये के अवमूल्यन का जोरदार समर्थन किया। उनके अनुसार रुपये का अवमूल्यन ही एक ऐसा उपाय था जो हमें विदेशी विनिमय संकट से बचा सकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कई तर्क दिये जिनमें कुछ इस प्रकार हैं—

- (i) भारतीय रुपये का मूल्य अधिक है। सन् १९५६ के मध्य तक भारत में रुपये की पूर्ति ७ गुणा से भी अधिक बची है जबकि इङ्ग्लैंड में यह वृद्धि केवल ३½ गुणा ही थी। इसके कारण रुपये का मूल्य पाँड़ के सम्बन्ध में अधिक हो गया इसलिए इसे कम करना आवश्यक है।
- (ii) सन् १९३७ में लेकर १९५६ के मध्य तक हमारे औद्योगिक उत्पादन की १००% की वृद्धि हुई और उद्योग उत्पादन में २०% की, किन्तु हमारा निर्यात उस समय १९३७ के स्तर पर भी नहीं पहुँच सका था जो इस बात का प्रमाण है कि रुपये की विनिमय दर अनुचित विनिमय दर से बहुत दूर है और उसका हमारे निर्यातों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- (iii) रुपये के विदेशी मूल्य का अधिक होना सोने के आन्तरिक तथा बाहरी मूल्य में भागी अन्तर होने में भी प्रमाणित होता है।

उपरोक्त सब बातों के आधार पर प्रो० शिनोय ने रुपये के अवमूल्यन विये जाने पर जोर दिया किन्तु सरकार ने उसे मानने में इन्कार किया। भारतीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार भी उस समय रुपये के अधिक अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं थी। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई केवल घग्घाई थी और विवाम योजनाओं

के कारण उत्पन्न हुई थी। अन्य तरीकों से उसे दूर किया जा सकता था और इसके लिए रुपये के मूल्य में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं। भारतीय प्रधान मंत्री ने भी कहा कि इस समय हम अपनी योजनाओं की सफलता के लिए रुपये में विदेशियों के विश्वास को बनाए रखना है और उसे प्राप्त करने के लिए रुपये के मूल्य में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। डा० वी० के० आर० वी० राव (Dr. V. K. R. V. Rao) ने भी रुपये के अधिक अवमूल्यन के सुझाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अवमूल्यन से किसी देश को तब ही लाभ हो सकता है जब उसकी निर्यातों की मांग की लोच अधिक हो। किन्तु हमारे निर्यातों के मूल्य घट जाने पर उनकी मांग में कोई विशेष वृद्धि की सम्भावना नहीं है, इसलिए अवमूल्यन से हमारे देश को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत हमारी आयातों की मांग प्रायः बेलोचदार है। हम अधिकांश मशीनरी तथा बच्चा मान मगाते हैं जिनमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। हमारा आयात योजनाओं की आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट होता है और उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में अवमूल्यन हमारे योजना व्यय को बढ़ा सकता है और उसमें हमें कोई लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः रुपये का और अधिक अवमूल्यन देश के आर्थिक हितों में नहीं है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) सन् १९४६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया? देश के आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या असर पड़ा? इसका विवेचन कीजिए।
(आगरा बी० ए० १९६२)
- (२) सितम्बर १९४६ में किन कारणों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ? इस अवमूल्यन से भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा?
(आगरा बी० ए० १९५६, नागपुर बी० ए० १९५६, इलाहाबाद बी० ए० १९५७, राजस्थान बी० काम० १९५६)
- (३) रुपये की विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है? सितम्बर सन् १९४६ में रुपये का अवमूल्यन करना कहाँ तक उचित था।
(राजस्थान बी० ए० १९५४)
- (४) मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? वर्तमान परिस्थिति में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। (आगरा बी० काम० १९५८)

भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली

INDIAN PAPER CURRENCY SYSTEM

पत्र मुद्रा का प्रयोग भारत में उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। उससे पूर्व हमारे देश में पूर्णतया धात्विक मुद्रा का प्रयोग होता था और लोग पत्र मुद्रा से बिल्कुल अपरिचित थे। सन् १८०६ में सर्वप्रथम बंगाल प्रेसीडेन्सी बैंक को नोट जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात् सन् १८४० में बैंक ऑफ बम्बई तथा सन् १८४३ में बैंक ऑफ मद्रास को भी नोट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। इन बैंकों के द्वारा नोट जारी करने की एक अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर दी गई। यह सीमा प्रेसीडेन्सी बैंक प्रत्येक से अधिक ५ करोड़ रुपये के नोटों को जारी कर सकते थे और उन्हें इन नोटों के पीछे २३ $\frac{1}{2}$ % वातु-निधि के रूप में रखना पड़ता था। सन् १८६१ में सरकार ने प्रेसीडेन्सी बैंकों का नोट निर्गमन अधिकार समाप्त कर दिया और नोट जारी करने का काम स्वयं ले लिया।

पत्र चलन एक्ट १८६१ (Paper Currency Act 1861)—

पत्र चलन एक्ट १८६१ के अन्तर्गत सरकार ने समस्त भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। पत्र मुद्रा जारी करने के लिए देश को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया और पत्र मुद्रा जारी करने के केन्द्र बलरुता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित किये गये। प्रत्येक क्षेत्र में जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा उसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर विविधग्राह्य होनी थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत में इङ्गलैंड के नमूने पर निर्दिष्ट अरक्षित पत्र मुद्रा प्रणाली (Fixed Fiduciary System) स्थापित की गई। आरम्भ में अरक्षित नोटों की मात्रा ४ करोड़ रुपये निर्दिष्ट की गई किन्तु सन् १९१६ में युद्धकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाकर २० करोड़ रुपये कर दिया गया।

निर्दिष्ट अरक्षित पत्र मुद्रा प्रणाली (Fixed Fiduciary System) भारत के लिए अधिक उपयुक्त न थी क्योंकि इसमें लोच का अभाव था। इस दोष को दूर करने के लिए सरकार अरक्षित चलन की मात्रा में समय-समय पर वृद्धि करती

रही। नोटों का सीमित चलन तथा अपने ही क्षेत्र में विधिग्राह्य होना इस प्रणाली का दूसरा बड़ा दोष था। इस दोष को दूर करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम सन् १९०३ में ५ रु० के नोट को समस्त भारत में विधिग्राह्य कर दिया। इसके पश्चात् समय-समय पर अन्य नोटों का भी चलन क्षेत्र व्यापक कर दिया गया। इस प्रणाली में स्वयं संचालकता का गुण भी नहीं पाया जाता था और इसकी सफलता अत्यधिक रूप से सरकार के प्रबन्ध पर आधारित थी। इन दोषों के होते हुए भी इस प्रणाली में सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता के गुण थे। सन् १९१३ में चैम्बरलेन कमीशन (Chamberlain Commission) ने भारत की पत्र मुद्रा प्रणाली में संशोधन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इन सुझावों का मुख्य उद्देश्य मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण पैदा करना था। प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण इस कमीशन के सुझावों को कार्य-रूप में नहीं लाया जा सका।

बैबिंगटन स्मिथ कमेटी (Babington Smith Committee)—

युद्ध के पश्चात् बैबिंगटन स्मिथ कमेटी ने यह सुझाव दिया कि रक्षित कोष की मात्रा कुल चलन का ४० प्रतिशत होनी चाहिए। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि रक्षित कोष में अधिकांश प्रतिभूतियाँ अल्पकालीन होनी चाहिए तथा सरकारी प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा २० करोड़ रुपये होनी चाहिए। अरक्षित पत्र मुद्रा की मात्रा, जो उस समय १२० करोड़ रुपये थी, कुछ और समय तक बनाये रखने की अनुमति दे दी गई। कमेटी की समस्त सिफारिशों को मान लिया गया और उन्हें कार्य-रूप में लाने के लिए सन् १९२० में एक अधिनियम पास कर दिया गया। यद्यपि बैबिंगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिशों का उद्देश्य पत्र मुद्रा प्रणाली को तोषदार बनाना था किन्तु कमेटी ने इस बात पर आवश्यकता में अधिक जोर देकर धात्विक कोष की मात्रा को बहुत कम कर दिया जिसके परिणामस्वरूप पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास किसी भी समय टूट सकता था।

हिल्टन यंग कमीशन, सन् १९२६

(Hilton Young Commission, 1926)—

कमीशन ने यह सिफारिश की कि नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया जाय, जिसकी स्थापना की उन्होंने सिफारिश की थी। नोटों को चाँदी के रुपये में बदलने की वैधानिक जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर उन्हें करमी अधिकारी की इच्छानुसार सोने की सलाखों में बदलने की व्यवस्था की जाय। पत्र मुद्रा कोष और स्वर्णमान कोष मिला दिये जायें और इस नये कोष की प्रकृति सरकारी नियम के द्वारा निश्चित की जाय। हिल्टन यंग कमीशन ने नोट निर्गमन की अनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) स्थापित करने की सिफारिश की। सुरक्षित कोष में सोने व सोने की प्रतिभूतियों का मूल्य कुल चलन का ४० प्रतिशत होना चाहिए। कमीशन ने एक

रुपये के नोट को फिर से जारी करने की सिफारिश भी की किन्तु उसे चांदी के सिक्कों में परिवर्तनीय न रखता जाय।

सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें कार्यक्रम में लाने के लिए सन् १९२७ का करन्सी अधिनियम पास कर दिया गया। पत्र मुद्रा को सोने व स्टैलिग में परिवर्तनीय किया गया। सोने की कम से कम मात्रा जो पत्र मुद्रा के बदले में सरकार ने ग्रहण की जा सकती थी, ४०० ग्राँम निश्चित की गई। सितम्बर सन् १९३१ में भारतीय पत्र मुद्रा सोने के स्थान पर स्टैलिग में परिवर्तनीय कर दी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना सन् १९३४ तक न की जा सकी।

अनुपातिक कोष प्रणाली की स्थापना

(Proportional Reserve System)—

सन् १९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत भारतवर्ष में अनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) के आधार पर नोट निर्गमन की व्यवस्था की गई। नोट निर्गमन का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया गया। रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित नोट समस्त देश में असीमित विधि-ब्राह्म होते थे और उनके पीछे सरकार की गारन्टी रहती थी। केवल १ रुपये तथा २ रुपये के नोट ही भारतीय वित्त विभाग (Indian Finance Department) के द्वारा जारी किये जाते थे। अन्य सब नोटों का प्रकाशन रिजर्व बैंक करता था। नोट निर्गमन की इस प्रणाली के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को जारी किये जाने वाले नोटों के पीछे ६०% सुरक्षित कोष रखना अनिवार्य होता था जिसमें मोना, सोने के सिक्के, विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्राएँ हो सकती थीं। सन् १९४८ के संशोधन से पूर्व विदेशी मुद्रा का अभिप्राय केवल स्टैलिग से होता था किन्तु इन संशोधन के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राएँ उसमें सम्मिलित की जा सकती थीं। इस ६०% सुरक्षित निधि में कम से कम ४० करोड़ रुपये के सोने के सिक्के अथवा मोना होना आवश्यक था। नोटों के दोष ६०% भाग के पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ स्वीकृत हुण्डियाँ, विनिमय बिल्ल, प्रतिज्ञा-पत्र अथवा रुपये के सिक्के रखे जा सकते थे किन्तु इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा किसी भी समय पत्र मुद्रा चलन निधि का २५% अथवा ५० करोड़ रुपये की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभावधारण परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर १०० करोड़ रुपये तक की सरकारी प्रतिभूतियाँ कोष में रखी जा सकती थीं। इस प्रकार १९३४ के रिजर्व बैंक एक्ट के अन्तर्गत भारत में बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) पर आधारित अनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) की स्थापना हुई। भारत में इस मुद्रा प्रणाली का

विकास अमेरिका के सब निधि बैंक अधिनियम (Federal Reserve Bank Act) के अनुसार किया गया ।

अनुपातिक कोष प्रणाली के गुण—

पत्र मुद्रा की इस प्रणाली में कुछ विशेष गुण होने के कारण ही उसे हमारे देश में अपनाया गया था । पूर्व प्रचलित निश्चित अरक्षित पत्र मुद्रा प्रणाली की अपेक्षा अनुपातिक कोष प्रणाली बहुत अच्छी थी और इससे प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार थे—

(१) मुद्रा प्रणाली में अधिक लोच—अनुपातिक कोष प्रणाली को अपना लेने पर भारत की पत्र मुद्रा प्रणाली काफी लोचदार हो गई थी । विदेशी प्रतिभूतियों को सुरक्षित निधि के रूप में रखे जाने की व्यवस्था के कारण इस प्रणाली में लोच का गुण अधिक पाया जाता था । इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत विनियम विलस तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की आड़ पर भी नोट जारी किये जा सकते थे जिसके कारण प्रणाली में और भी अधिक लोच उत्पन्न हो गई थी । आवश्यकता पड़ने पर नोटों की मात्रा को आसानी से घटाया-वढ़ाया जा सकता था जिसके कारण कृषि वस्तुओं की बिक्री के लिए सामयिक वित्त (Seasonal Finance) की व्यवस्था करना सम्भव था ।

(२) अधिक मितव्ययितापूर्ण—यह प्रणाली काफी मितव्ययितापूर्ण भी थी क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सोने को कोष के रूप में बन्द करके नहीं रखना होता था । रक्षित कोष का काफी बड़ा भाग पत्र प्रांतभूतियों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के रूप में हो सकता था जिसके कारण सोने के प्रयोग में बहुत बचत होती थी ।

(३) कोषों का केन्द्रीयकरण—इस प्रणाली में देश की समस्त चलन निधि को एक ही कोष में एकत्रित कर दिया गया था जिसके कारण कई प्रकार के कोषों को रखने से होने वाला व्यय समाप्त हो गया था । इस प्रणाली से पूर्व देश में दो कोष रहते थे—पत्र मुद्रा कोष तथा स्वर्णमान कोष । किन्तु नई व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों कोषों को मिलाकर एक मुद्रा कोष स्थापित किया गया ।

(४) जनता का विश्वास—अधिक लोचदार होने हुए भी यह प्रणाली पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास स्थापित कर सकती थी । नोटों के पीछे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित निधि का होना नोटों में जनता का विश्वास पैदा करता था ।

(५) असाधारण परिस्थितियों के अनुकूल—संकटकालीन स्थिति में निधि सम्बन्धी छूट दिये जाने की व्यवस्था होने के कारण यह प्रणाली असाधारण परिस्थितियों में काम करने की क्षमता अधिक रखती थी । इसी प्रकार की व्यवस्था होने के कारण यह प्रणाली द्वितीय विश्व-युद्ध की परिस्थिति में भी ठीक काम करती रही ।

अनुपातिक कोप प्रणाली के दोष—

उपर्युक्त सभी गुणों के होते हुए भी यह अनुपातिक कोप प्रणाली काफी दोषपूर्ण थी और उत्तम मुद्रार की आवश्यकता थी। इस प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न प्रकार थे—

(१) स्थाई मूल्यमान का अभाव—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें कोई निश्चित मूल्यमान नहीं था। रुपये का स्टैबिलिटी के साथ स्थायी सम्बन्ध होने के कारण स्टैबिलिटी के मूल्य का प्रत्येक परिवर्तन रुपये के मूल्य को भी प्रभावित करता था। रुपये के मूल्य की यह अस्थिरता देश के आर्थिक हित में नहीं थी। रुपये का विदेशी मूल्य पूर्णतया स्टैबिलिटी के मूल्य पर आधारित हो गया था जिसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था के बुरे प्रभाव पड़ सकते थे। आवश्यकता इस बात की थी कि भारतीय रुपये एक स्वतन्त्र मुद्रा हो और उसका मूल्य हमारे देश की आर्थिक स्थिति से ही प्रभावित होना चाहिए।

(२) मूल्य-स्तर की स्थिरता का अभाव—इस मुद्रा प्रणाली में आन्तरिक मूल्य स्तर की स्थिरता स्थापित करना भी सम्भव नहीं था क्योंकि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय की स्थिरता स्थापित करना था। समय-समय पर अत्यधिक निकासी का भय लगा रहता था। मुद्रा प्रणाली की इस प्रकृति के कारण ही द्वितीय मुद्रोत्तर काल में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की अनिश्चित मुद्रा प्रणाली देश के आर्थिक हित में नहीं थी।

(३) स्वयं संचालकता का अभाव—इस मुद्रा प्रणाली में स्वयं संचालकता का अभाव था और सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता था। व्यवसायिक आवश्यकताओं तथा विवामशील अर्थ-व्यवस्था के अनुसार मुद्रा की मात्रा स्वयं घट-बढ़ नहीं सकती थी। इस प्रकार के परिवर्तन सरकार के द्वारा ही किये जा सकते थे।

(४) लोच का अभाव—अनुपातिक कोप प्रणाली में पर्याप्त लोच का गुण भी नहीं था क्योंकि इसमें रक्षित कोप सम्बन्धी शर्तें बहुत कटी थीं। आवश्यकता पड़ने पर नोटों की मात्रा में विस्तार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए यह कहा गया है कि “इस प्रणाली में देश की समस्त प्रचलित मुद्रा तथा देश की आर्थिक आवश्यकता, उत्पादन-शक्ति और वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बीच विमोचन का सम्बन्ध नहीं रहता था। इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रणाली बिल्कुल अनुपयुक्त थी।” एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को इस प्रणाली के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। अतः इस प्रणाली में मुद्रार की अनन्त आवश्यकता थी।

(५) परिवर्तनशीलता का अभाव—नोटों की परिवर्तनशीलता के सम्बन्ध में भी यह प्रणाली अधिक अच्छी नहीं थी क्योंकि भारतीय नोट केवल स्टैबिलिटी में बढ़ने

जा सकते थे। स्टलिंग स्वर्ण सोने अथवा सोने की मुद्रा में परिवर्तनशील नहीं था इसलिए भारतीय पत्र मुद्रा भी अपरिवर्तनीय हो गई थी।

भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली (Present Monetary System in India)

द्वितीय विद्व-युद्ध के पश्चात् भारतीय मुद्रा-प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए और सन् १९४५ में हमारे देश में एक नये मुद्रामान का आरम्भ हुआ। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) की सदस्यता के फलस्वरूप देश में स्टलिंग विनिमय मान के स्थान पर अन्य देशों की भाँति स्वर्ण समता मान (Gold Parity Standard) स्थापित कर दिया गया। भारतीय रुपये तथा स्टलिंग का सम्बन्ध दृढ़ गया और रुपये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतन्त्र मुद्रा के रूप में कार्य करने लगा। भारतीय सरकार के द्वारा रुपये का स्वर्ण मूल्य निश्चित कर दिया गया और रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से रुपये के इस स्वर्ण मूल्य को बनाये रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। किसी भारी असन्तुलन की दशा में रुपये के इस स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के साथ ही हमारे देश में एक स्वतन्त्र मुद्रामान का जन्म हुआ। भारतीय मुद्रा प्रणाली के निश्चित मूल्यमान के अभाव के दोष को दूर कर दिया गया और देश में एक निश्चित मूल्यमान स्थापित हो गया। इस नये मुद्रामान में लोच तथा स्थिरता दोनों ही गुण पाये जाते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार नोटों का विस्तार किया जा सकता है और उसके साथ ही रिजर्व बैंक अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मौद्रिक प्रवन्ध तथा अन्य प्रकार के नियंत्रणों के द्वारा देश में मूल्य-स्तर की स्थिरता करने का प्रयत्न करता है। इस मुद्रामान में विदेशी मुद्रा दरो की स्थिरता को भी प्राप्त किया जा सकता है। नये मुद्रामान में एक ओर तो अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता जैसे स्वर्णमान के गुण पाये जाते हैं और दूसरी ओर यह स्वर्णमान के दोषों से मुक्त हैं।

न्यूनतम कोष प्रणाली की स्थापना (Minimum Reserve System)—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय नोट निर्गमन प्रणाली में कुछ आधार-भूत परिवर्तन किये गये। नोट निर्गमन प्रणाली को आर्थिक विकास की दशाओं के अनुकूल बनाने के लिए सन् १९२६ में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) की स्थापित किया गया। अनुपातिक कोष प्रणाली विभिन्न दोषों के कारण देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त हो गई थी और उसमें सुधार की आवश्यकता थी। यह अनुभव किया गया कि इस प्रणाली में देश के विदेशी विनिमय साधनों का एक बहुत बड़ा भाग पत्र मुद्रा कोष के रूप में बेकार पड़ा रहता है जबकि देश को आर्थिक विकास के लिए विदेशी विनिमय की अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसी दशा में सरकार ने भारत

के विदेशी विनिमय के अधिकांश भाग को प्रयोग के लिए मुक्त करना उचित समझा और सन् १९५६ में रिजर्व बैंक एक्ट के एक संशोधन के द्वारा मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले विदेशी विनिमय की मात्रा का कम कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियम सन् १९५६ [Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1956] के द्वारा भारत में नोट निर्गमन की प्रचलित अनुपातिक कोष प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली की स्थापना की गई। पूर्व प्रचलित नोट निर्गमन प्रणाली में नोटों के पीछे ४०% सुरक्षित कोष रखना अनिवार्य होना था जिसमें २१ रुपये १३ आने १० पा० प्रति तोला के हिसाब में कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना होना आवश्यक था तथा कोष का दोष भाग विदेशी विनिमय के रूप में रक्खा जा सकता था। इस संशोधन के द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नोटों के पीछे रखे जाने वाली सुरक्षित निधि की न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी गई। संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को नोटों के पीछे ४०० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना रखना अनिवार्य कर दिया गया। अब सोन का मूल्य ३५ डालर प्रति औंस (६२.५० रुपये प्रति तोला) के हिसाब में आँका जायगा। इस प्रकार कुल मिलाकर निर्गमन विभाग में ५१५ करोड़ रुपये का न्यूनतम कोष रखन की व्यवस्था की गई। नोटों के पीछे रखी जाने वाली विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि की आवश्यकता पड़ने पर घटा कर १०० करोड़ भी किया जा सकता था। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ३१ अक्तूबर सन् १९५७ को एक आदेश के द्वारा पत्र मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले न्यूनतम कोष की मात्रा ५१५ करोड़ रुपये में घटाकर केवल २०० करोड़ रुपये कर दी गई जिसमें ११५ करोड़ रुपये का सोना तथा दोष मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ रहेंगी।

वर्तमान निर्गमन प्रणाली के गुण

(Merits of the Present System of Note Issue)—

भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली एक प्रगतिशील प्रणाली है। उसमें एक पञ्चर्दी मुद्रा प्रणाली के अधिकांश गुण पाये जाते हैं तथा वह देश के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है। इस प्रणाली के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं—

(१) अधिक लोचदार—वर्तमान प्रणाली में लोच का गुण बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि न्यूनतम मात्रा में निधि रखकर ही रिजर्व बैंक जितनी मात्रा में चाहे नोट जारी कर सकता है। इस प्रणाली में नोटों की मात्रा तथा सुरक्षित निधि में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है और केन्द्रीय बैंक आवश्यकता के अनुसार नोटों की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। अधिक लोच का गुण होने के कारण ही यह प्रणाली प्रगतिशील समाज के लिए अधिक उपयुक्त है। एक प्रगतिशील समाज में मुद्रा की

आवश्यकता निरन्तर बढ़ती रहती है जिसे इस प्रणाली के अन्तर्गत आसानी से पूरा किया जा सकता है ।

(२) मितव्ययिता पूर्ण है—मितव्ययिता की दृष्टि से यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है क्योंकि इसके अन्तर्गत बहुत ही कम भागा में सुरक्षित कोप रखना आवश्यक होता है और बहुमूल्य धातुओं के अपव्यय की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । यह प्रणाली ऐसे देशों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनके पास मोना तथा विदेशी विनिमय भीमित मात्रा में है । भारतवर्ष की स्थिति इसी प्रकार की है ।

(३) विदेशी विनिमय की स्थिरता—देश में स्वर्ण समता मान होने के कारण इस प्रणाली के द्वारा विदेशी विनिमय दगों को स्थिर रखा जा सकता है । रिजर्व बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सहायता से रुपये के विदेशी मूल्य को उसके स्वर्ण मूल्य (Gold Parity) के अनुसार बनाये रखे ।

(४) मूल्य-स्तर की स्थिरता—उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा मूल्य-स्तर की स्थिरता भी प्राप्त की जा सकती है । रिजर्व बैंक मौद्रिक प्रबन्ध तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों के द्वारा कीमत स्तर को स्थिर रखने का प्रयत्न करता है । पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है और कीमतों के निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है ।

(५) जनता का विश्वास—इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा में जनता का विश्वास बना रहता है । यद्यपि पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता की कोई गारंटी नहीं होती है किन्तु फिर भी पत्र मुद्रा के पीछे न्यूनतम कोप होने के कारण मुद्रा में जनता का विश्वास स्थापित किया जा सकता है ।

(६) आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त—यह प्रणाली आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है । नोटों के विस्तार की सरलता के कारण इस प्रणाली में पत्र मुद्रा को आर्थिक विकास के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रणाली को अपनाकर ही देश के विदेशी विनिमय माधनों को आर्थिक विकास के कार्यों के लिए मुक्त किया जा सकता है ।

वर्तमान प्रणाली के दोष (Demerits of the Present System)—

यद्यपि भारत की वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली में उपर्युक्त सभी गुण पाये जाते हैं और वह पूर्व प्रचलित अनुपातिक कोप प्रणाली से अच्छी है किन्तु फिर भी उसमें कुछ दोष अवश्य हैं जिनके कारण इस प्रणाली का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए । प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(१) अत्यधिक निवासी का भय—वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली में अत्यधिक निवासी का भय बढ़ गया है । इस प्रणाली में न्यूनतम कोप रखने के पश्चात्

वितनी भी मात्रा में नोट जारी किये जा सकते हैं जिसके कारण किसी भी समय नोटों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो सकती है और देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा होने का भय रहता है। इस प्रणाली की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि रिजर्व बैंक कहीं तक मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा मुद्रा-प्रसार की शक्तियों पर नियन्त्रण कर सकता है। वर्तमान स्थिति में कुछ प्रतिकूल दशाओं के कारण रिजर्व बैंक को मूल्य-स्तर की स्थिरता को बनाये रखने में सफलता नहीं मिल रही है और कीमत-स्तर निरन्तर बढ़ रहा है।

(२) केवल समृद्धि (Prosperity) काल के लिए उपयुक्त—एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में इस प्रणाली की उपयोगिता अधिक होती है अन्यथा इससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की सम्भावना अधिक रहती है। भारतवर्ष में इस प्रकार के स्तरों की सम्भावना बाकी समय तक नहीं है क्योंकि हमारी आर्थिक प्रगति का क्रम आने वाले वर्षों में और अधिक तीव्र होने की आशा है।

(३) ग्यूनतम कोष के घटने की सम्भावना—इस प्रणाली में यह डर रहता है कि सरकार ग्यूनतम कोष की मात्रा को बहुत अधिक कम करके मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को समाप्त न कर दे। ग्यूनतम कोष के और अधिक कम करने से यह प्रणाली असुरक्षित हो सकती है।

इन दोषों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मुद्रा प्रणाली एक आदर्श मुद्रा प्रणाली के बहुत समीप है और वर्तमान दशाओं के अनुकूल है। यह प्रणाली आधुनिक मौद्रिक विचारधारा पर आधारित है और इसमें लोच तथा मितव्ययिता के दो बड़े गुण पाये जाते हैं। उचित मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा इसमें पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

नई मुद्रा प्रणाली तथा आर्थिक विकास—

आर्थिक विकास के लिए हम मुद्रा प्रणाली को अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है जिसमें विकासशील अर्थ-व्यवस्था को बढ़ती हुई मुद्रा की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जा सके तथा उसके साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को नियन्त्रित किया जा सके। अल्प विकसित देशों की प्राचीन मुद्रा प्रणालियाँ उनके आर्थिक विकास के रास्ते में रुकावट हैं। इन देशों में आर्थिक प्रगति की रफ्तार को तेज करने के लिए आवश्यक है कि प्राचीन मुद्रा प्रणालियों के स्थान पर प्रगतिशील मुद्रा प्रणाली की स्थापना की जाय जिसमें लोच तथा स्थिरता दोनों ही हों। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सुरक्षित निधि के बिना ही किन्हीं भी मात्रा में मुद्रा जारी की जा सकती है। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मौद्रिक साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। इस प्रणाली में नोटों की मात्रा तथा उसके पीछे रखी जाने वाली

मुरक्षित निधि में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना है और रिजर्व बैंक एक न्यूनतम कोष रखने के पश्चात् आवश्यकतानुसार कितनी भी मात्रा में पत्र मुद्रा जारी कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा का विस्तार तथा संकुचन मुरक्षित निधि के अनुसार न होकर व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की माय तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने की सम्भावना अधिक होती है।

आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से भी वर्तमान मुद्रा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि आर्थिक विकास के साथ-साथ उद्भादन में वृद्धि होने के कारण मुद्रा प्रसार की शक्तियाँ स्वयं क्षीण होने की प्रवृत्ति रखती हैं। अधिक मुद्रा कुछ ही समय पश्चात् अधिक उत्पादन के साथ सन्तुलित हो जाती है और मुद्रा प्रसार केवल अस्थायी ही होता है। अन्तरिम काल में मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए मौद्रिक प्रबन्ध तथा अन्य प्रकार के नियन्त्रणों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली आर्थिक विकास के लिए इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसमें देश के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष का प्रयोग विदेशों से पूँजीगत वस्तुओं मगाने के लिए किया जा सकता है। थोड़ी मात्रा में सोना तथा विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष के रूप में रखकर कोष का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। इसके अनिश्चित इस प्रणाली में विदेशी विनिमय दरें स्थिर रहने के कारण भारतीय रुपये में विदेशियों का विश्वास बना रहता है और हमें आर्थिक विकास लिए अधिक मात्रा में ऋण तथा विदेशी पूँजी प्राप्त हो सकती है। आन्तरिक क्षेत्र में भी रुपये में जनता का विश्वास होने के कारण विकास के लिए अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली देश के आर्थिक विकास में बड़ी सहायक हो सकती है किन्तु उसकी सफलता बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा कहाँ तक रुपये के आन्तरिक तथा विदेशी मूल्य में स्थिरता स्थापित करने में सफल होता है।

भारतीय मुद्रा प्रणाली की विशेषताये

(Features of Indian Currency System) —

आज की भारतीय मुद्रा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताये इस प्रकार हैं—

(१) रुपया भारत की प्रमुख मुद्रा इकाई है जिसे १०० पैसों में विभक्त किया हुआ है। १, २, ५, १०, २५ तथा ५० पैसे के दशमलव सिक्के चलाये जाते हैं। रुपया साकेतिक सिक्का है और निकल का बनाया जाता है जिसका वजन १८० ग्रेन के बराबर होता है। आठ आने, चार आने, दो आने तक, एक आने वाले पुराने सिक्के चलन से हटा लिए गये हैं और उनके स्थान पर केवल दशमलव सिक्के ही बाँट कर रहे हैं।

(२) पत्र मुद्रा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है और इस समय ₹, ५, १०, १००, १,००० ₹, १०,०००, १०,००० के नोट चलन में है। भारतीय सरकार के एक रुपये वाले विशेष नोट जो जुलाई १९४० में जारी किए गये थे अभी तक चलन में है। रिजर्व बैंक के निकासी विभाग (Issue Department) में जारी किये जाने वाले नोटों के पीछे सुरक्षित कोष रखा जाता है। सुरक्षित निधि की न्यूनतम मात्रा रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार २०० करोड़ रुपये निश्चित की गई है जिसमें ११५ करोड़ रुपये का सोना अथवा सोने के मिकके अनिवार्य रूप से रखने होते हैं।

विदेशी विनिमय के कामों के लिए रुपया १ बि० ६ पेंस के बराबर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण भारत ने अपने रुपये की स्वर्ण समता दर ०.१८६६२ ग्रेन शुद्ध सोने अथवा २०.६४ सेंट (अमेरिकन) के बराबर घोषित की हुई है। भारत में इस समय स्वर्ण समता मान है और रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह रुपये के विदेशी मूल्य को स्वर्ण समता दर के बराबर बनाये रखे।

डालर तथा कुलुम्ब मुद्राओं की बहुत एव भारी मात्रा में पूँजी के निर्यात को रोकने के उद्देश्य से भारत ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था को अपनाया हुआ है। विदेशी विनिमय सम्बन्धी सब सौदे रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित अधिकृत व्यापारियों के द्वारा किये जाते हैं। व्यक्तियों तथा फर्मों के द्वारा प्राप्त किया हुआ विदेशी विनिमय नियन्त्रित दरो पर रुपये के बदले में रिजर्व बैंक को बेचना होता है। विदेशी विनिमय केवल अधिकृत व्यापारियों से रिजर्व बैंक के परमिट के द्वारा खरीदा जा सकता है। विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को नियमित करने के लिए विदेशी भुगतान सम्बन्धी समस्त सौदों को नियन्त्रित कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण है। भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों के बेचने तथा खरीदने पर भी प्रतिबन्ध है। विदेशी प्रतिभूतियों का निर्यात वर्जित है।

भारत में मुद्रा पूर्ति (Money Supply in India) —

देश में मुद्रा पूर्ति चलन (Currency) एव बैंक जमा (Bank Deposits) से मिलकर बनती है। करभी के अन्तर्गत देश में चलने वाले समस्त मिक्के तथा पत्र मुद्रा सम्मिलित हैं। बैंक जमा के अन्तर्गत बैंकों के चासू खातों में जमा रकम (Demand Deposits) तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा को ही सम्मिलित किया जाता है। पिछले १५ वर्षों में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में तेजी के साथ वृद्धि हुई है जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है।

जनता के पास मुद्रा की पूर्ति' (Money Supply with the Public)

(करोड़ रुपये)

अन्त में	करंसी की मात्रा	बैंकों की जमा	कुल मुद्रा पूर्ति	परिवर्तन वृद्धि + कमी -
१९५१-५२	१२८५.५	५६२.७	१८४८.२	- १६०.०
१९५५-५६	१५७१.०	६४५.६	२२१६.६	+ २६२.२
१९५६-५७	१६२२.७	७१६.२	२३४१.६	+ १२४.६
१९५७-५८	१६७४.१	७३६.१	२४१३.२	+ ७१.३
१९५८-५९	१७६२.०	७३४.०	२५२६.०	+ ११२.६
१९५९-६०	१९३०.६	७८६.४	२७१७.२	+ १९४.२
१९६०-६१	२०६८.१	७७०.६	२८३८.६	+ १२६.२
१९६१-६२	२२०१.२	८४४.७	३०४५.३	+ १७७.२
१९६२-६३	२३७६.५	९३०.५	३३०६.६	+ २६४.२
१९६३-६४	२६०५.६	११४६.६	३७५२.६	+ ४४७.२
सित० १९६४	२५१५.३	१२०१.५	३७१६.७	- ४७.६

केवल सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों को छोड़कर मुद्रा व साख की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही है। सन् १९६४ के अन्तिम महीने में करंसी की मात्रा कुछ कम हुई है। ऊपर की तालिका को देखने से पता चलता है कि सन् १९५१-५२ में मुद्रा की कुल पूर्ति १८४८ करोड़ रुपये थी जो १९६३-६४ में बढ़कर ३७५२ करोड़ रुपये हो गई है। इससे स्पष्ट है कि विद्यमान १३ वर्षों में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति दुन्ने से भी अधिक हो गई है। इन वर्षों में नकद मुद्रा की मात्रा लगभग १३२० करोड़ रुपये बढ़ी है और साख मुद्रा की मात्रा में ५८४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अतः इस काल में मुद्रा की कुल मात्रा में १९०४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि सन् १९६३-६४ में हुई जबकि एक वर्ष में ही मुद्रा की मात्रा ४४२ करोड़ रुपये बढ़ गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मुद्रा की कुल मात्रा २३६४ करोड़ रुपये बढ़ी, द्वितीय योजना काल में ६५१.७ करोड़ रुपये तथा तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में यह वृद्धि ८८३.५ करोड़ रुपये की है। इन सब आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में मुद्रा व साख की मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है जो काफी सीमा तक बढ़ते हुए मूल्य-स्तर के लिए जिम्मेदार है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) भारत में सन् १९५६ में नोट जारी करने की विधि "प्रनुपातिक कोष प्रथा" (Proportional Reserve System) से बदल कर "निम्नतम कोष प्रथा" (Minimum Reserve System) क्यों की गई ? भारत के स्वतंत्र्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? (भागरा बी० ए० १९५६)
- (२) किसी देश में नोटों का निर्गमन करते समय किन बातों का पालन किया जाता है ? इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट के प्रादेशों का उल्लेख करो । (भागरा बी० ए० १९५६)
- (३) पत्र मुद्रा के संचालन हेतु अपनाये जाने वाले उपायों की प्रालोचनापूर्ण विवेचना कीजिये । उनमें से हमारे देश ने किसको अपनाया है और क्यों ? (भागरा बी० काम १९५६ s)
- (४) भारत की विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा संचालन प्रणाली (Fiduciary Issue System) एवं न्यूनतम कोष पद्धति (Minimum Reserve System) की विशेषताओं का विवेचन करिये । उनकी पुष्टि के लिए अपनी सुक्तियाँ दीजिये । (भागरा बी० काम १९५६)
- (५) भारतीय वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली की धारणा कीजिये । इस प्रणाली के गुण-दोष बताइये । (भागरा बी० काम १९६१)
- (६) नोट निर्गमन की एक प्रार्थना पद्धति की विशेषताएँ बताइये तथा यह भी स्पष्टाई कि भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली उन्हें कहाँ तक समुपद्र करती है ? (राजस्थान बी० काम १९५८)



भारत में मुद्रा-प्रसार

INFLATION IN INDIA

द्वितीय विश्व-युद्ध काल में तथा उसके पश्चात् मुद्रा-स्फीति भारतवर्ष की प्रमुख प्राथमिक समस्या रही है। यद्यपि आरम्भ में हमारे मूल्य-स्तर पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव बहुत कम था किन्तु धीरे-धीरे यह प्रभाव बढ़ता गया और १९४८ के पश्चात् भयंकर रूप धारण कर गया। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि युद्धोत्तर काल में मुद्रा-स्फीति हमारे देश में तीसरी अवस्था में पहुँच गई थी और उस समय मूल्य-स्तर में वृद्धि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि से कई गुणा हो रही थी। यद्यपि इस धारणा को बिलकुल सत्य नहीं माना जा सकता है किन्तु फिर भी यह कहना उचित होगा कि इस काल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार का काफी अधिक प्रभाव था। सन् १९३९ में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के ऊपर मन्दी का प्रभाव था किन्तु युद्ध आरम्भ होते ही देश में आर्थिक समृद्धि का एक नया युग आरम्भ हुआ। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे और उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी। आरम्भ में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि का स्वागत किया गया क्योंकि किसानों की दशा को सुधारने में उसने बड़ी सहायता दी। युद्ध के पहले कुछ महीनों में मूल्यों में होने वाली वृद्धि ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को मन्दी के प्रभाव से मुक्त कर दिया और आर्थिक विकास की नई शक्तियों को जन्म दिया किन्तु इसके पश्चात् हमारे मूल्य-स्तर में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि वह मुद्रा-स्फीति का रूप धारण कर गई। देश में मुद्रा व साक्ष की मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी जबकि वस्तुओं के उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि न की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप देश में बहुत-सी वस्तुओं की कमी हो गई और उनके मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे। विशेष-कर कृषि मूल्य अधिक तेजी के साथ बढ़ रहे थे।

भारतीय सरकार ने जुलाई सन् १९४२ तक इस बात को मानने से इन्कार किया कि भारतवर्ष में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिजर्व बैंक ने भी

मुद्रा-प्रसार की गम्भीरता को स्वीकार नहीं किया। सरकारी क्षेत्रों के अनुसार देश में मुद्रा की वृद्धि उसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए की जा रही थी और इसीलिए उसे मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता था। इसके अनिश्चित यह भी कहा गया कि देश में बेकार साधन काफी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग का बढ़ना मुद्रा-प्रसार की दशाओं को पैदा नहीं कर सकता है। सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना था कि यह स्थिति घाटे की धर्म-व्यवस्था (Deficit Financing) के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, अतः इसे मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता है। इन सब तर्कों के होते हुए भी वास्तविकता यह थी कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे थे और यह वृद्धि काफी तेजी के साथ हो रही थी। देश में बेकार साधन होते हुए भी उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि न हो सकी। मशीनों तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं की कमी, प्रशिक्षित श्रम के अभाव, सरकार की उदासीन औद्योगिक नीति तथा असहयोग के कारण भारत का औद्योगिकरण युद्ध काल में नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया किन्तु देश उममें लाभ न उठा सका और मुद्रा की वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न हुई। एक ओर मुद्रा की मात्रा सरकार के युद्धकालीन व्यय के कारण तेजी के साथ बढ़ रही थी और दूसरी ओर उत्पादन का अनुपात में नहीं बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में मूल्य-स्तर का बढ़ना तथा मुद्रा-प्रसार की दशाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था।

भारत सरकार ने यद्यपि मुद्रा-प्रसार की स्थिति को स्वीकार नहीं किया किन्तु उस समय तक रुपये के मूल्य में काफी गिरावट आ चुकी थी और भारतीय धर्म-शास्त्रियों के अनुसार उस समय देश में मुद्रा-प्रसार का पुण्य आरम्भ हो गया था। सर्वप्रथम प्रो० सी० एन० वकील (C. N. Vakil) ने अपनी पुस्तक *The Falling Rupee* में जनता तथा सरकार का ध्यान गिरते हुए रुपये की ओर आकर्षित किया। १९४४ में केन्द्रीय वित्त-मन्त्री ने भी यह मान लिया कि भारत में मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किन्तु उसे रोकने के लिए १९४८ से पूर्व कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। अगस्त सन् १९४५ में जब द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त हुआ तो थोड़ा मूल्यो का सूचक अंक बढ़ कर १४४.१ (१९३९=१००) हो चुका था। वह निरन्तर बढ़ता गया और नवम्बर १९४६ में २८६.५ हो गया। इसके पश्चात् एक वर्ष तक मूल्य लगभग स्थिर रहे। नवम्बर सन् १९४७ से मूल्य-स्तर ने फिर से बढ़ना आरम्भ किया और दिसम्बर १९४७ में सूचक अंक ३११.६ तथा अगस्त १९४८ में ३८३.० हो गया। इस प्रकार तेजी के साथ बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार ने अक्टूबर १९४८ में अपनी मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति की घोषणा की।

युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण (Causes of War-time Inflation)—

भारतवर्ष में युद्धकालीन मुद्रा स्फीति के निम्नलिखित कारण थे —

(१) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि—युद्ध काल में मुद्रा की मात्रा में तेजी के साथ विस्तार किया गया और चलन में मुद्रा की मात्रा कई गुणा हो गई। अगस्त मई १९३९ में चलन में नोटों की कुल मात्रा १७९ करोड़ रुपये से कुछ कम थी किन्तु मार्च १९४५ तक यह बढ़ कर १०८५ करोड़ रुपये हो गई। इस पांच वर्षों से कुछ अधिक समय में लगभग ९०५ करोड़ रुपये की नई पत्र मुद्रा चलन में डाली गई। इसके अतिरिक्त रुपये के सिक्कों तथा रेजगारी की मात्रा में भी तेजी के साथ वृद्धि हुई। इस काल में बँकों के द्वारा निर्मित साख की मात्रा भी काफी अधिक बढ़ गई और मार्च १९४५ तक लगभग ४६० करोड़ रुपये की नई साख का निर्माण किया गया। कुल मिला कर मार्च १९४५ तक सब प्रकार के विनिमय के माध्यम की मात्रा लगभग १५६५ करोड़ रुपये हो गई थी। केवल मुद्रा की मात्रा में ही वृद्धि नहीं हुई अब उसके चलन वेग में भी काफी वृद्धि हुई। मुद्रा की मात्रा तथा उसके चलन वेग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे। युद्ध काल में नोटों की मात्रा तथा मूल्य-स्तर में होने वाली वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफिकों से स्पष्ट है—

वर्ष	नोटों की संख्या (करोड़ रुपयों में)	वार्षिक सलाहकार का सूचकांक (१९३९=१००)
१९३९	१८०	१००
१९४०	२३८	१३३
१९४१	२४५	११४
१९४२	३५३	१४५
१९४३	५६३	१६५
१९४४	८८१	२३२
१९४५	१,०३४	२५०

(२) सरकारी व्यय में वृद्धि—युद्ध के कारण भारत सरकार का रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। यद्यपि भारतवर्ष लड़ाई का केन्द्र नहीं था किन्तु फिर भी भारतीय सरकार को ब्रिटिश तथा अन्य साथी देशों की फौजों के लिए भारतवर्ष में काफी धन व्यय करना पड़ा। इस प्रकार के व्यय का कुछ भाग हमें ब्रिटिश सरकार से स्टलिंग जमा के रूप में मिल जाता था किन्तु इस स्टलिंग जमा के बढ़ने में भारत सरकार को नई मुद्रा जारी करनी होती थी जिसके कारण मुद्रा-प्रसार की शक्तियाँ और अधिक तीव्र होती गईं। मार्च १९४५ तक भारत के लिए युद्ध का

प्रत्यक्ष व्यय लगभग २७०० और २६०० करोड़ रुपये के बीच में था। इतने बड़े व्यय को करो तथा सार्वजनिक ऋणों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था; अतः सरकार ने रिजर्व बैंक से ऋण लिया और रिजर्व बैंक ने इस भाग को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का निर्माण किया।

(३) भारत का इंग्लैंड को बड़ी मात्रा में वस्तु ऋण देना—युद्ध काल में इंग्लैंड तथा अन्य मित्र-राष्ट्रों ने भारतवर्ष से बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं को खरीदा जिनका भुगतान युद्ध के पश्चात् किया जाना था। जो मास भारत से जाता था उसका सुरक्षित भुगतान नहीं होता था बल्कि उसके बदले में हमें स्टलिंग प्रतिभूतियाँ दी जाती थी जिनकी आड़ पर रिजर्व बैंक उत्पादकों को भुगतान करने के लिए नई मुद्रा जारी करता था। इंग्लैंड ने भारत से बड़ी मात्रा में वस्तु ऋण लेकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को तो मुद्रा-प्रसार के खतरे से बचा लिया किन्तु भारत की अर्थ-व्यवस्था को भयंकर मुद्रा-प्रसार की स्थिति में डाल दिया। स्टलिंग प्रतिभूतियों के आधार पर किये जाने वाले मुद्रा विस्तार का अनुमान नीचे दिये गये आँकड़ों से लगाया जा सकता है—

वर्ष	पीण्ड पावनों की मात्रा करोड़ रुपये में	प्रचलन में मोटा करोड़ रुपये में
अगस्त १९३६	६४	१७६
१९३६-४०	६१	२०६
१९४०-४१	१६६	२४१
१९४१-४२	२११	३०७
१९४२-४३	३६४	५१३
१९४३-४४	७४५	७७७
१९४४-४५	११८२	६६६
१९४५-४६	१५४६	११६३
१९४६-४७	१६६२	१२२५

इस तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध काल में जैसे-जैसे पीण्ड पावनों की राशि बढ़ती गई, रिजर्व बैंक के द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा जारी की जाती रही। अतः यह कहा जा सकता है कि युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार का एक प्रमुख कारण स्टलिंग निधि की आड़ पर नोटों का विस्तार किया जाना था।

(४) व्यापार सन्तुलन का पक्ष में होना—युद्ध काल में व्यापार सन्तुलन निरन्तर भारतवर्ष के पक्ष में रहा। भारत से अधिकाधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा था जबकि वस्तुओं की उपलब्धि न होने तथा जहाजों की कमी के कारण हमारे आयात बहुत कम हो गये थे। व्यापार सन्तुलन पक्ष में होने के कारण हमें

स्टैलिंग बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रहा था और इन स्टैलिंग प्रतिभूतियों के आधार पर सरकार अधिकाधिक मात्रा में नई मुद्रा जारी करती गई जिसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था के ऊपर मुद्रा-प्रसार का दबाव बढ़ता गया ।

(५) वस्तुओं की दुर्लभता—युद्ध काल में एक ओर तो वस्तुओं की कमी थी और दूसरी ओर लोगों के पास क्रय-शक्ति बहुत अधिक थी जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे । वस्तुओं की दुर्लभता का मुख्य कारण उत्पत्ति में तेजी के साथ वृद्धि न होना तथा बहुत बड़ी मात्रा में आयाज्यकता की वस्तुओं का निर्यात किया जाना था । सन् १९३६ से १९४५ तक कृषि उत्पादन में केवल १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन में २५% की, जबकि इसी काल में मुद्रा की मात्रा बढ़ कर कई गुणा हो गई । औद्योगिक उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि न होने का कारण कच्ची सामग्री तथा मशीनों का अभाव था । कृषि उत्पादन कम होने के कारण देश में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई । एक ओर तो अनाज कम पैदा हो रहा था और दूसरी ओर उसे युद्ध-क्षेत्रों को भेजा जा रहा था । विदेशों की काफी मात्रा में सामान भेजे जाने के कारण भी देश में वस्तुओं की कमी हो गई थी । इसके अतिरिक्त लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात युद्धकालीन दशकों के कारण स्थगित हो चुका था । इन्हीं सब कारणों से देश में सभी प्रकार के सामान की भारी कमी हो गई थी जो मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण था ।

(६) सट्टे की प्रवृत्ति—वस्तुओं की पूर्ति अनिश्चित होने के कारण युद्धकाल में लोगों में सट्टे की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी । अधिक लाभ के उद्देश्य से व्यापारियों ने वस्तुओं का संग्रह करना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार वस्तुओं की दुर्लभता को और भी अधिक बढ़ा दिया गया । सट्टेबाजी की इस प्रवृत्ति ने भी वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने में सहयोग दिया ।

मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)—

युद्ध काल में मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से व्यापारी तथा उद्योगपति वर्ग को काफी लाभ पहुँचा । वस्तुओं की माग बढ़ जाने तथा उनका आयात बन्द हो जाने के कारण कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही थी और इस वर्ग के लोगों के मुनाफे भी तेजी के साथ बढ़ने लगे । अनाज के मूल्य ऊँचा होने के कारण किसानों को भी काफी लाभ हुआ । इन लोगों की आय बढ़ गई और लगभग सभी पुराने ऋणों को चुका दिया गया । औद्योगिक श्रमिकों के वेतन में कुछ वृद्धि हुई किन्तु तेजी के साथ बढ़ने लगे रहने-सहने व्यय की तुलना में यह वृद्धि अपर्याप्त थी । श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी पहले की अपेक्षा कम हो गई थी किन्तु उन्हें रोजगार अधिक मात्रा में मिलने लगा । बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई । मध्यम वर्ग के लोगों को तथा मुख्यतः निम्न आय वाले वर्गों को मुद्रा प्रसार के कारण विशेष कठिनाई अनुभव हुई । इस वर्ग के लोगों की आय प्रायः निश्चित थी

किन्तु रहन-सहन व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए अपने आवश्यक व्यय को पूरा करना भी सम्भव नहीं था। युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति का उत्पत्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा और लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाने लगा किन्तु इस समृद्धि का लाभ समाज के केवल कुछ वर्गों को ही प्राप्त हो सका। मुद्रा-स्फीति के कारण देश में धन का वितरण और अधिक असमान हो गया। धनी वर्ग और अधिक धनी होने लगा तथा निर्धन वर्ग अधिक कठिनाइयों में फँस गया।

मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय (Anti Inflationary Measures)—

यद्यपि सन् १९४८ से पूर्व मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए एक सुव्यवस्थित सरकारी नीति का निर्माण नहीं किया जा सका किन्तु फिर भी तेजी के साथ बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के सरकार ने कुछ उपाय किये जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(१) मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिय—सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए तथा अन्य पूर्ति वाली वस्तुओं के उचित वितरण के उद्देश्य से मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिय की नीति को अपनाया। युद्ध आरम्भ होने ही सरकार ने ऐसे नियम बना दिये जिनमें कि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में १०% से अधिक वृद्धि न हो सके। दिसम्बर सन् १९४२ से देश में अन्न के वितरण के लिए राशनिय व्यवस्था लागू कर दी गई। कपड़ा तथा कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण कर दिया गया। किन्तु सरकार की मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिय की नीति अधिक सफल न हो सकी। इसके परिणामस्वरूप देश में चोर-बाजारी तथा मुनाफाखोरी की बुराईयों पैदा हो गईं। इस नीति की असफलता का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार तथा उसे रोकने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त न होता था।

(२) करों में वृद्धि—जनता के पास से अतिरिक्त क्रय-शक्ति को निकालने के लिए सरकार ने कुछ नये कर लगाये तथा अर्तमान करों को बढ़ा दिया गया। आय-कर के ऊपर २५% का अतिरिक्त कर (Surcharge) लगा दिया गया जिसे १९४२ में बढ़ा कर ३३ $\frac{1}{3}$ % कर दिया गया। सन् १९४२ में अधिक लाभ-कर (Excess Profit Tax) में भी वृद्धि की गई। कुछ नई वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगा दिया गया। इस प्रकार करों के द्वारा सरकार जनता की अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करने में सफल हो सकी और अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार के भार को कम किया जा सका।

(३) अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋण—जनता के पास अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करने के लिए सरकार ने अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋण लिए।

डिफेंस सेविंस् एकाउन्ट तथा नेशनल सेविंस् सर्टिफिकेट्स के द्वारा सरकार ने जनता से काफी मात्रा में ऋण लिया ।

(४) सट्टेबाजी को बन्द करना—सरकार ने बहुत-सी वस्तुओं के भविष्य सम्बन्धी सौदे करने पर प्रतिबन्ध लगा दिये तथा सट्टेबाजी को बन्द करने के लिए प्रयत्न किया ।

(५) बचत की प्रोत्साहन—अतिरिक्त आय को बाजार में पहुँचने से रोकने के लिए सरकार ने छल्प बचत को प्रोत्साहन देने की योजना चलाई । इस प्रकार की बचतों पर दिये जाने वाले व्याज को बढ़ा दिया गया तथा इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार की सुविधायें भी दी गईं ।

(६) अधिक उत्पादन—सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न किया । विशेषकर अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' आरम्भ किया गया । औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने अन्य प्रकार के प्रोत्साहन दिये । नये उद्योगों को ५ वर्ष के लिए आय-कर से मुक्त कर दिया गया ।

उपयुक्त उपायों के अतिरिक्त सरकार ने अपने व्यय को कम करके बजट को सन्तुलित करने तथा आयान सम्बन्धी नीति को ढीला करके वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया । किन्तु इन सब उपायों के द्वारा मुद्रा-स्फीति को रोकने में सरकार को अधिन सफलता न मिल सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार अभी तक एक मुख्यवस्थित मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति का निर्माण नहीं कर सकी थी ।

युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति तथा उसके कारण

(Post-war Inflation & its Causes)—

यद्यपि यह आशा की जाती थी कि युद्ध की दशायें समाप्त हो जाने के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति की स्थिति का भी अन्त हो जायेगा किन्तु युद्धोत्तरकाल में भी मुद्रा-स्फीति का दबाव बराबर बना रहा और पहले से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर गया । जिन कारणों से युद्धकालीन स्फीति पैदा हुई थी वे तो धीरे-धीरे समाप्त होने लगे किन्तु उनके स्थान पर कुछ नये कारण पैदा हो गये जिन्होंने मुद्रा-स्फीति को बनाये रखने में सहायता दी । मुद्रा-स्फीति धीरे-धीरे भयंकर रूप धारण कर गई और सामान्य मूल्य-स्तर तेजी के साथ बढ़ने लगा । भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार का थोक मूल्यों का निर्देशांक, जो अगस्त १९४५ में १०४४.१ था, मार्च १९४८ में ४०२.४ हो गया । युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति के निम्नलिखित कारण थे—

(१) मुद्रा का विस्तार—जून सन् १९४६ के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के भारत में सैनिक व्यय को पूरा करने के लिए नये नोटों की छापने का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था । उसके पश्चात् भारतीय सरकार के घाटे को पूरा करने के

लिए हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing) की नीति को अपनाया गया। अगस्त सन् १९४७ के पश्चात् देश में विभाजन, शरणार्थियों को बसाने, काश्मीर युद्ध तथा हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के कारण भारत सरकार का घाटा बहुत अधिक बढ़ गया था। इस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में नोट चलाये गये और मार्च १९४८ में नोटों की मात्रा बढ़कर १३१६६ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति तो ब्रिटिश सरकार के घाटे के कारण पैदा हुई थी किन्तु युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण भारत सरकार का घाटा था।

(२) घाटे के बजट (Deficit Budgets)—यद्यपि केन्द्रीय सरकार के रक्षा व्यय में काफी कमी हो गई थी किन्तु फिर भी केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बजट असंतुलित थे। अनाज पर दी जाने वाली सहायता, शरणार्थियों पर किये जाने वाला व्यय तथा क्षामन प्रबन्ध सम्बन्धित व्यय में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बजट निरन्तर घाटे में चल रहे थे। बजट के इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक मात्रा में नई मुद्रा का निर्माण करना पड़ा जिसके कारण देश में मुद्रा-प्रसार का दबाव बढ़ता गया।

(३) मूल्य नियन्त्रण का हटा देना (Decontrol)—दिसम्बर सन् १९४७ में सरकार ने अनियन्त्रण की नीति को अपना लिया और अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की मूल्य नियन्त्रण में मुक्त कर दिया गया तथा राशनिंग व्यवस्था को भी तोड़ दिया गया। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया किन्तु सरकार ने परिणामों को न मोचने हुये १० दिसम्बर १९४७ को अनाज के अनियन्त्रण की घोषणा कर दी। अनियन्त्रण होते ही अनाज के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे और मुद्रा-प्रसार की शक्तियाँ और अधिक प्रभावशाली हो गईं।

(४) उत्पादन में कमी—युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण वस्तुओं के उत्पादन का गिरना था। युद्ध के पश्चात् वस्तुओं की मांग काफी बढ़ गई किन्तु कुछ कारणों से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा। सरकार की अनिश्चित औद्योगिक नीति, मशीनों की कमी, औद्योगिक मजदूरों तथा मजदूरों में वृद्धि कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था।

(५) अनाज की कमी—युद्धोत्तर काल में खाद्य स्थिति बहुत चिन्ताजनक हो गई और विशेषकर विभाजन के पश्चात् तो खाद्य समस्या एक भयंकर रूप धारण कर गई। सन् १९४६ में पंजाब, मद्रास तथा बम्बई में वर्षा की कमी के कारण फसल खराब हो गई और सरकार ने लगभग ६० लाख टन अनाज की कमी का अनुमान लगाया। विभाजन के पश्चात् खाद्य स्थिति और अधिक खराब हो गई क्योंकि अनाज पैदा करने वाला बहुत-सा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया जबकि वहाँ में बहुत-सी जनसंख्या भारतवर्ष आ गई।

(६) देश का विभाजन—सन् १९४७ में देश का विभाजन हो जाने से बहुत से शरणार्थी पाकिस्तान से भारतवर्ष में आ गये : इसके विपरीत भारत से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा लाये जबकि वे वस्तुएँ जिन पर इस मुद्रा को खर्च किया जाना था, पाकिस्तान में ही रह गईं। इस प्रकार देश में क्रय-शक्ति तो बढ़ी किन्तु उसके साथ वस्तुओं की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं के मूल्य और अधिक बढ़ गये।

(७) रुपये का अवमूल्यन—सन् १९४६ में स्टलिन का अवमूल्यन किये जाने पर रुपये का अवमूल्यन भी कर दिया गया। अवमूल्यन के कारण हमारी आयात बहुत कम हो गई तथा हमारे देश से अधिक मात्रा में सामान बाहर जाने लगा। देश में वस्तुओं की और अधिक कमी हो गई और उनके मूल्य बढ़ने लगे।

सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति

(Anti Inflationary Policy of the Government)—

युद्ध काल में भारत सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया किन्तु युद्ध के पश्चात् स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि सरकार के लिए बढ़ते हुए मूल्य-स्तर को रोकना आवश्यक हो गया। सन् १९४८ के मध्य में सरकार ने कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया और उनके द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर एक मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति का निर्माण किया गया। इस नीति की घोषणा अक्टूबर सन् १९४८ के प्रथम सप्ताह में की गई। इस नीति के दो प्रमुख आधार थे—प्रथम, चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना तथा द्वितीय, उत्पादन में वृद्धि करना। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने मुद्रा-प्रसार को रोकने के निम्नलिखित उपाय किए—

(१) अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर फिर से मूल्य नियन्त्रण—वस्तुओं पर से मूल्य नियन्त्रण हटाने के कारण जो मूल्यों में वृद्धि हो रही थी उसे रोकने के लिए मूल्य नियन्त्रण की नीति को दुबारा अपनाया गया। सरकार ने खाद्यान्नों के मूल्यों को एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़ने देने का निश्चय किया। अनाजों के अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये गये और इन वस्तुओं के मूल्यों को अधिक न बढ़ने देने के उद्देश्य से अधिक मात्रा में गेहूँ तथा अन्य प्रकार के अनाजों का आयात किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ एक औद्योगिक वस्तुओं में मूल्य तथा उनके वितरण पर भी नियन्त्रण कर दिया गया।

(२) सरकारी व्यय में कमी—बजट को संतुलित रखने के लिए सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने तथा व्यय को कम करने का प्रयत्न किया। फालतू कर्मचारियों को हटा दिया गया, शिक्षा व सामाजिक व्यय में कमी की गई तथा रक्षा सम्बन्धी व्यय को भी कम करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार मितव्ययिता की

नीति के द्वारा सरकारी बजट के घाटे को दूर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बजट के घाटे को पूरा करने के लिए कुछ नये कर लगाये गये। मुद्रा-स्फीति को दूर करने के लिए सरकार ने वचत वाते बजट बनाये। घाटे के बजटों के एक लम्बे समय के पश्चात् १९५१-५२ के बजट में ६१ ६१ करोड़ रुपये की वचत का अनुमान था। इस प्रकार कुछ समय के लिए सरकार ने होनार्थ-प्रबन्धन की नीति का परित्याग कर दिया।

(३) प्रचलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना—सरकार ने मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयत्न किया। कुछ नये कर लगाये गये तथा वर्तमान करों में वृद्धि की गई। सरकार ने अपने व्यय को कम किया और तीन वर्ष के लिए जमींदारों के भुग्तावजे तथा अन्य प्रकार के भुगतानों को रोक दिया गया। व्याज की ऊँची दर देकर सरकार ने अधिक मात्रा में सावर्जनिक ऋण प्राप्त किये। मुद्रा का अधिक विस्तार बन्द कर दिया गया। लोगों के पाम लाभ के रूप में अधिक आय न जा सके, इस उद्देश्य से लाभालाभ नियन्त्रण कानून लागू कर दिया गया, जिसके अन्तर्गत सम्पत्तियों के द्वारा दिये जाने वाले लाभांश पर ६०% की सीमा लगा दी गई।

(४) उत्पादन में वृद्धि—सरकार ने कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये। अच्छे बीज, अधिक खाद तथा सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' को सफल बनाने का प्रयत्न किया गया। अनाज के अतिरिक्त औद्योगिक कच्चे माल जैसे कपास, पटसन तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नये उद्योगों को तीन वर्ष के लिए आय-कर से छूट दे दी। निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को १० वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। उद्योग-धंधों के लिए अधिक मात्रा में कच्चा माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुएँ आपात करने का प्रवन्ध किया गया।

(५) वचत को प्रोत्साहन—लोगों की अतिरिक्त आय को बाजार में न पहुँचने देने तथा औद्योगिक पूँजी को बढ़ाने के उद्देश्य में जनता के द्वारा अधिक मात्रा में धपन करने पर विशेष जोर दिया गया। अल्प वचत योजना का विस्तार किया गया तथा उसे एक आन्दोलन का रूप दे दिया गया। अगस्त मन् १९४६ में अनिवार्य वचन योजना को लागू कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वचत इकट्ठा करने के लिए गाँव के डाकखानों में सेविंग बैंक खाते खोलने का प्रचार किया गया।

(६) मौद्रिक उपाय—मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार ने कुछ मुद्रा तथा बैंकिंग सम्बन्धी उपाय भी किए। सन् १९४६ में बैंकों के लिए अपनी जमा का २५% सरकारी प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य कर दिया गया। साख पर

नियन्त्रण करने के लिए नवम्बर सन् १९५१ में बैंक दर को ३% से बढ़ाकर ३२% कर दिया गया।

सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति के परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में कुछ स्थिरता आई और कीमतों की वृद्धि की गति धीमी हो गई किन्तु इस नीति को स्थायी सफलता न मिल सकी और कुछ समय पश्चात् ही मूल्य-स्तर में वृद्धि फिर से प्रारम्भ हो गई। डा० ब्राइट सिंह के अनुसार सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति इसलिए अधिक सफल न हो सकी क्योंकि सरकार ने अपनी दर, लोक ऋण तथा सार्वजनिक व्यय की नीति को मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण पाने की दृष्टि में बनाने का प्रयास नहीं किया। जून सन् १९५० के पश्चात् कोरियन युद्ध (Korean War) की दशाओं के कारण मूल्य सूचक अक तेजी से बढ़ने लगा और अप्रैल १९५१ में ४५७.५ हो गया। कोरियन युद्ध के पश्चात् भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कारणों ने मूल्य-स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति कुछ समय तक जारी रखी।

१९५२ के मुद्रा-प्रसार विरोधी उपाय

सन् १९५२ में सरकार ने बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण करने के लिए कुछ उपाय किए जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार थे—
(i) सरकारी व्यय को कम से कम रखा जाय, (ii) आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाना, (iii) प्रचलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना। सरकार ने साख नियन्त्रण, अधिक कर लगाकर तथा बचत को प्रोत्साहन देकर चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयत्न किया। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में काफी वृद्धि की गई तथा साख नियन्त्रण की नीति को अपनाया गया। सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति की कुछ सफलता मिली किन्तु वह उतनी नहीं थी जितनी की आशा की गई थी। अधिक सफलता न मिलने का मुख्य कारण यह था कि सरकारी नीति में मौद्रिक कारणों पर अधिक जोर दिया गया था जबकि भारतीय मुद्रा-स्फीति मुख्यतः मौद्रिक कारणों से उत्पन्न नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त इस नीति में साख मनुष्य तथा करों में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया गया जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन गिरने लगा और अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ गया। मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति इसलिए भी असफल रही क्योंकि सरकार को खेतजल, राज्यधीन व्यय के लिए हेतुार्थ-अव्यय की नीति को अत्यन्त 'पछा'।

किन्तु इन सब कमजोरियों के होने हुए भी मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति सफल रही और जुलाई सन् १९५२ में आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पुनोत्तर काल में प्रथम बार ऐसा लगा कि मुद्रा-स्फीति की दशाएँ समाप्त हो गई हैं। वस्तुओं के मूल्य गिरने की प्रवृत्ति दिखता रहे थे।

मई सन् १९५५ से मूल्यों ने फिर से बढ़ना प्रारम्भ कर दिया और थोके मूल्यों का सूचकचक्र जो मई सन् १९५५ में ३४२ या बढ़कर अक्टूबर १९५५ में

१९७२ हो गया और जुलाई सन् १९५६ में गिरकर ४०६ रह गया। अनाज के मूल्यों में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण सरकार की अनाज के मूल्य सम्बन्धी नीति थी जिसके अन्तर्गत गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि के भावों को गिरने से रोका गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने रुई, तेल के बीज तथा तेल, कॉफी आदि के निर्यात के कोटा में वृद्धि कर दी, कुछ वस्तुओं पर निर्यात-कर कम कर दिये गये अथवा उन्हें हटा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो गई। प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं पर बहुत बड़ी मात्रा में व्यय किये जाने के कारण मूल्य वृद्धि की यह प्रवृत्ति तीव्र हो गई और देश में फिर से मुद्रा-स्फीति की दृष्टि से उत्पन्न हो गई।

योजना काल में मुद्रा-प्रसार

(Inflationary Trends During the Plan Period)

भारतवर्ष में वर्तमान मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण हमारी विकास योजनाओं पर किया जाने वाला पूँजीगत व्यय है। इस समय हमारे देश में एक प्रकार का विकास सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार है जो युद्धकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार का मुद्रा-प्रसार प्रायः विकास की आरम्भिक अवस्था में उत्पन्न हो जाता करता है। ऐसा मुद्रा-प्रसार स्वयं ठीक होने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उत्पादन में होने वाली वृद्धि कुछ समय पश्चात् उसे अपने आप ठीक कर देती है। इस प्रकार का मुद्रा-प्रसार हमारे देश के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि युद्धकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-प्रसार था। यह मुद्रा-प्रसार हमारे आर्थिक विकास में सहायक भी हो सकता है यदि उस पर उचित नियन्त्रण रखा जाए। किन्तु नियन्त्रण से बाहर हो जाने पर यह मुद्रा-प्रसार भी देश की अर्थ-व्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचा सकता है। यदि कीमतों की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ने की रहती है और वे काफी तेजी के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार की स्थिति आर्थिक विकास के लिए हानिप्रद हो सकती है। कीमतों की अत्यधिक वृद्धि योजना व्यय को बढ़ा देती है तथा धन के वितरण की असमानताएँ उत्पन्न करती है। अतः योजना काल में कीमत-स्तर पर उचित नियन्त्रण रखना आवश्यक है। धीरे-धीरे बढ़ता हुआ मूल्य-स्तर आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है किन्तु तेजी के साथ बढ़ती हुई कीमतें भयंकर परिणाम पैदा कर सकती हैं।

प्रथम योजना काल में मूल्य सम्बन्धी स्थिति सतोषजनक थी। आर्थिक विकास पर अधिक व्यय किये जाने पर भी मूल्य-स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई और मूल्यों की प्रवृत्ति नीचे गिरने की थी। योजना काल में सरकार के द्वारा अपनाये जाने वाले मुद्रा-प्रसार विरोधी उपायों के कारण मूल्य-स्तर की वृद्धि रुक गई थी

और वस्तुओं के मूल्य गिरने की प्रवृत्ति दिखलाई रहे थे। प्रथम योजना के अन्त में कीमतें उसके आरम्भ की अपेक्षा १३% नीची थी जबकि इसी काल में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में लगभग १०% की वृद्धि हुई। इस योजना पर २००० करोड़ रुपये व्यय किये जाने पर भी कीमत-स्तर गिरने की प्रवृत्ति दिखलाई रहा था। यह एक आश्चर्यजनक बात थी। ऐसा लगता था कि अब मुद्रा-प्रसार का खतरा समाप्त हो गया है। इसी आशावाद के कारण सरकार ने दूसरी योजना में हीनाथ-प्रवन्धन का लक्ष्य काफी ऊँचा निश्चित किया। जबकि प्रथम योजना काल में केवल ४२० करोड़ रुपये का हीनाथ-प्रवन्धन किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए यह लक्ष्य १२०० करोड़ रुपये रखा गया।

दूसरी योजना काल में कीमतों की वृद्धि

(Price Rise During The Second Five Year Plan)—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय कीमतों में काफी स्थिरता थी और उस पर मुद्रा-प्रसार का दबाव बहुत कम हो गया था। दूसरी योजना में ४८०० करोड़ रुपये व्यय किए जाने का निश्चय किया गया। कीमतों की सतोप-जनक स्थिति को देखकर सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १२०० करोड़ रुपये का व्यय किए जाने का हीनाथ-प्रवन्धन करने का निश्चय किया। उस समय सरकार का विश्वास था कि इतना अधिक हीनाथ-प्रवन्धन होते हुए भी देश में मुद्रा-प्रसार का खतरा पैदा होने की सम्भावना नहीं है किन्तु वास्तविक अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा और दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में ही कीमतों ने बढ़ना आरम्भ कर दिया। अनाज की कीमतों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई और मुद्रा-प्रसार का खतरा फिर से उत्पन्न हो गया। दिसम्बर सन् १९५६ में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) को बढते हुए मूल्यों के कारण पैदा होने वाली स्थिति पर विचार करना पड़ा। मुद्रा-प्रसार का दुरा प्रभाव योजना के ऊपर भी पड़ा और यह अनुमान किया गया कि ४८०० करोड़ रुपये के स्थान पर योजना को पूरा करने के लिए ५५०० करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। योजना व्यय को निश्चिन्त सीमा के भीतर रखने के लिए १९५७ में योजना के लक्ष्यों को कम करने की बातचीत की जाने लगी। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हमारे देश में फिर से मुद्रा-प्रसार की दशाएँ उत्पन्न हो गईं। सरकार ने मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए कुछ उपाय भी किये किन्तु कीमत-स्तर निरन्तर बढ़ता गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मूल्य-स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका में विदित है।

उस तालिका को देखने से पता चलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कीमत-स्तर निरन्तर बढ़ता रहा है। यह वृद्धि सन् १९५८ के पश्चात् विशेष रूप से तेज हो गई है। दूसरी योजना के पाँच वर्षों में मूल्य-स्तर में लगभग २५% की

सामान्य कीमतों का निर्देशांक
(आधार १९५२-५३=१००)

वर्ष	निर्देशांक
१९५५-५६	६२५
१९५६-५७	१०५.३
१९५७-५८	१०८.४
१९५८-५९	११२.६
१९५९-६०	११७.१

वृद्धि हुई है। कीमत-स्तर के दबन की यह प्रवृत्ति तीसरी योजना काल में भी बराबर बनी रही है।

तीसरी योजना काल में कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति

(Rising Trend of Prices During III Five Year Plan)—

तीसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार का दबाव काफी बढ़ गया था। इस योजना पर १०,४०० करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। अर्थ-व्यवस्था में इतना अधिक विनियोग होने से तथा जनसंख्या के तेजी के साथ बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि हो गई है जबकि वस्तुओं की पूर्ति को इतनी अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप कीमत स्तर की प्रवृत्ति बढ़ते रहने की रही है। योजना के अन्तिम दो वर्षों में तो कीमतें इतनी अधिक बढ़ी हैं कि मुद्रा-प्रसार एक भयंकर रूप धारण कर गया है। यद्यपि तीसरी योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Financing) की मात्रा केवल ५५० करोड़ रुपये रखी गई है जो दूसरी योजना की तुलना में बहुत कम है किन्तु फिर भी कीमत-स्तर पर मुद्रा-प्रसार का दबाव निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। सितम्बर सन् १९६४ में कीमतें १९५९-६० की अपेक्षा लगभग ४२% ऊँची थी। पिछले पाँच वर्षों में कीमत-स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति अगले पृष्ठ पर दिये आंकड़ों से स्पष्ट है।

इस तालिका की देखने से पता चलता है कि कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि सन् १९६३ के पश्चात् हुई और सन् १९६४ के अन्तिम महीने में तो कीमतों की वृद्धि सब सीमाओं को लाघ गई है। वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने १९६५-६६ का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व अपने आर्थिक सर्वेक्षण में बतलाया कि सन् १९६२-६४ में थोक मूल्यों में ६१ प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले १० महीनों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सामान्य कीमतों का निर्देशांक
(आधार १९५२-५३=१००)

वर्ष	निर्देशांक
१९५६-६०	११७.१
१९६०-६१	१२४.६
१९६१-६२	१२५.१
१९६२-६३	१२७.६
१९६३-६४	१३५.३
सितम्बर १९६४	१५८.८
नवम्बर १९६४	१५९.८

योजना कालीन मुद्रा-प्रसार के कारण
(Causes of Plan Period Inflation)—

(१) अधिक मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन—आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन किया है जिसका प्रभाव कीमत-स्तर में वृद्धि करने का रहा है। विशेषतया दूसरी योजना काल में बहुत बड़ी मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन किया गया जो वर्तमान मुद्रा-प्रसार के लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। डा० कालडोर (Dr. Kaldor) ने सन् १९५६ में यह बतलाया था कि भारत की अर्थ-व्यवस्था अधिक से अधिक १५० करोड़ रुपये वार्षिक अथवा ५ वर्षों में ८०० करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन के भार को उठा सकती है। किन्तु दूसरी योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन का लक्ष्य १२०० करोड़ रुपये रखा गया और वास्तव में ६४८ करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन इस काल में किया गया जो बहुत अधिक था और जिसके कारण देश में मुद्रा व साख की मात्रा तेजी के साथ बढ़ी है। प्रचलन में मुद्रा की मात्रा जो सन् १९५६ में २१७८.७ करोड़ रुपये थी, सन् १९६१ में बढ़ कर २८७३.७ करोड़ रुपये हो गई और नवम्बर सन् १९६४ में यह मात्रा ३८४१.८६ करोड़ रुपये थी। मुद्रा की इस बढ़ती हुई मात्रा ने कीमतों पर अत्यधिक दबाव पैदा कर दिया है जिसके कारण उनकी प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ने की रही है।

(२) जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि—योजना काल में देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है जिसके कारण उद्योगों की वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ गई है। दूसरी और तीसरी योजना काल में जनसंख्या २% प्रतिवर्ष से भी अधिक दर से बढ़ी है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग में उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ वृद्धि हुई है और वस्तुओं की इस कमी के कारण कीमतें निरन्तर बढ़ती रही हैं।

(३) कृषि वस्तुओं के उत्पादन में कमी—सन् १९५७-५८ तथा १९५९-६० में फसलें अच्छी नहीं थी। सन् १९५९-६० में अनाज का उत्पादन पहले वर्ष की अपेक्षा ४० लाख टन कम था। रुई का उत्पादन १०% प्रतिशत कम था, जूट का १२% तथा तेल के बीजों का उत्पादन में ८% की कमी थी। सन् १९६१-६२ में अनाज का उत्पादन १९६०-६१ की अपेक्षा कुछ कम था तथा अन्य कृषि वस्तुओं की उपज में बहुत मामूली वृद्धि हुई। इस सबका प्रभाव कृषि वस्तुओं के मूल्यों को ऊँचा रखने का रहा है तथा सामान्य कीमत-स्तर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा।

(४) उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में कम वृद्धि—योजना नीति के अन्तर्गत उपभोग सम्बन्धी वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जिसके कारण देश में उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति बहुत कम तेजी के साथ बढ़ी है। दूसरी तथा तीसरी योजना में पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है तथा कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाया गया है। उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं की कमी के कारण कीमतें निरन्तर बढ़ती रही हैं।

(५) अधिक निर्यात—सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत अधिक मात्रा में उपभोग की वस्तुएँ तथा कच्चा माल विदेशों को भेजा जा रहा है जिसके कारण देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो गई है। इसके विपरीत उपभोग की वस्तुओं का आयात बहुत कम कर दिया गया है।

(६) कीमतें स्थिर रखने में सरकार की असफलता—मूल्य-नियन्त्रण तथा नियमन के द्वारा सरकार कीमतों को स्थिर रखने में असफल रही है। अभी तक भी सरकार एक उचित मूल्य नीति का निर्माण नहीं कर सकी है। सरकार की इस असफलता से व्यापारी वर्ग ने खूब लाभ उठाया है और वस्तुओं का सग्रह, चोर-बाजारी तथा मुनाफाखोरी के कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक ऊँचे उठ गये हैं।

मुद्रा-प्रसार विरोधी उपाय (Anti-Inflationary Measures)—

सरकार ने योजना कालीन मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये हैं जिनमें मौद्रिक (Monetary) तथा अमौद्रिक (Non-Monetary) दोनों ही प्रकार के उपाय सम्मिलित हैं। यद्यपि कीमतों की वृद्धि रोकने में अधिक सफलता नहीं मिली है किन्तु फिर भी इस दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं—

✓ (१) साख पर नियन्त्रण—कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने मुद्रा व साख की मात्रा को रोकने के विशेष प्रयत्न किये हैं। रिजर्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए साख के प्रयोग पर नियन्त्रण (Selective Credit Control) किया है। सन् १९५९-६० में रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंकों के सुरक्षित कोष के अनुपात में

परिवर्तन करने की नीति का प्रयोग किया। मई सन् १९१७ में बैंक-दर ३३ प्रतिशत से बढ़ा कर ४ प्रतिशत कर दी गई। सन् १९६३ में बैंक दर में फिर वृद्धि की गई और उसे ४३ प्रतिशत पर निश्चित कर दिया गया। सन् १९६४ में कीमतों की तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी साख नीति को और अधिक कड़ा करने का निश्चय किया और सितम्बर सन् १९६४ में बैंक दर को बढ़ा कर ५% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त साख के विस्तार को रोकने के लिए और भी उपाय किये गये। रिजर्व बैंक की साख-विस्तार विरोधी नीति कीमतों की वृद्धि को रोकने में अधिक सफल न हो सकी और कीमतें तेजी के साथ बढ़ती गईं। कीमत-स्थिति से चिन्तित होकर रिजर्व बैंक ने १७ फरवरी सन् १९६५ को फिर बैंक दर में वृद्धि की और उसे ६ प्रतिशत कर दिया गया। पिछले ४ महीनों में बैंक दर में दो बार वृद्धि होना इस बात का प्रमाण है कि देश में मुद्रा-प्रसार की शक्तियाँ अधिक तीव्र हो गई हैं और उन्हें नियन्त्रित करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने कुछ अन्य उपाय भी किये हैं जिससे कि व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में सस्ती साख का विस्तार न कर सकें। बैंकों का तरलता अनुपात (Liquidity Ratio) २८% से बढ़ाकर ३०% कर दी गई है।

(२) अधिक मात्रा में अनाज का आयात—देश में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए तथा अनाज की कीमतों को नीचा रखने के उद्देश्य से सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाज मंगाया है। सन् १९५८ में ३१.७ लाख टन गेहूँ, चावल तथा अन्य प्रकार के अनाजों का आयात किया गया। सन् १९५९ में आयात किये जाने वाले अनाज की मात्रा ३८.१ लाख टन थी। १३ नवम्बर सन् १९५९ को अमेरिका से गेहूँ, आटा तथा अन्य कृषि वस्तुएँ मँगाने के सम्मन्ध में समझौता किया गया। उसी वर्ष एक दूसरा समझौता १५ लाख टन चावल मँगाने के लिए भी किया गया। कनाडा से २.७ लाख टन गेहूँ तथा बर्मा से १.५ लाख टन चावल मँगाने का समझौता भी हुआ। सन् १९६० में एक लाख टन चावल संयुक्त प्रत्यक्ष गणराज्य से मंगाया गया। इस सब अनाज का प्रयोग कीमतों को स्थिर रखने के लिए किया जा रहा है।

(३) कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में वृद्धि—दूसरी योजना काल में सरकार ने कृषि वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्यों को ऊँचा कर दिया और अधिक खाद, अच्छे बीज, औजार तथा अन्य सुविधाएँ देकर अधिक मात्रा में अनाज पैदा करने का प्रयत्न किया गया। तीसरी योजना में अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य ऊँचे रखे गये हैं यद्यपि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है।

(४) उचित मूल्य वाली दुकानें (Fair Price Shops)—लोगों की सस्ते भाव पर अनाज तथा अन्य वस्तुएँ बेचने के लिए सरकार के द्वारा शहरों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित भाव वाली दुकानें खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने काफी बड़ी संख्या में उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी स्थापित किये हैं।

(५) अनाज का सरकारी व्यापार—सन् १९५६ में सरकार ने अनाज का सरकारी व्यापार करने की नीति को घोषणा की। इस नीति के अन्तर्गत अनाज के धोक व्यापार को धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र में ले आया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए अनाज व्यापार निगम (Foodgrains Trading Corporation) स्थापित कर दी गई है।

(६) कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण—सरकार ने सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कपड़े की कीमतों पर नियन्त्रण कर दिया है। कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी नियन्त्रित किये गये हैं।

(७) हीनार्थ-प्रबन्धन में कमी—मुद्रा-प्रसार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit financing) की मात्रा कम कर दी है। तीसरी योजना में केवल ५५० करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन ही किया जाना है जो दूसरी योजना में किये गये हीनार्थ-प्रबन्धन का आधा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निश्चय किया है कि चौथी योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन बिल्कुल नहीं किया जायेगा।

(८) अधिक करारोपण—उपभोग की मात्रा को कम रखने के लिए सरकार ने योजना काल में अधिक मात्रा में करारोपण किया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बहुत से नये कर लगाये हैं तथा वर्तमान करों की दरें बढ़ा दी गई हैं। सन् १९५५-५६ में सरकार को करों से कुल आमदनी ४८१ करोड़ रुपये थी जो सन् १९६३-६४ में बढ़ कर १२४६ करोड़ रुपये हो गई है। करों के द्वारा सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ा कर लोगों के पास क्रय-शक्ति को कम करने का प्रयत्न किया है।

आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन

(Deficit Financing and Economic Development)—

हीनार्थ-प्रबन्धन से अभिप्राय उस व्यवस्था से होता है जिसमें सरकार घाटे के बजट बनाती है और बजट के इस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी की जाती है। अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग केवल सङ्घकालीन स्थिति में ही किया जाना था, किन्तु अब अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। भारतवर्ष में हीनार्थ-प्रबन्धन का प्रयोग काफी समय से होना आया है। प्रथम महायुद्ध तथा द्वितीय विश्व-युद्ध काल में सैनिक-व्यय तथा अन्य प्रकार युद्धकालीन व्यय को पूरा करने के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन किया गया। युद्धोत्तर काल में सरकार ने अपने बड़े हुए शासन सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन का प्रयोग किया। आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन का प्रयोग भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर लगभग २२४६ करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसका अधिकांश भाग करारोपण, व्यक्तिगत तथा सरकारी बचत और

सार्वजनिक ऋणों के द्वारा पूरा किया गया। इनके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया कि १६५ करोड़ रुपये विदेशी सहायता तथा ४६० करोड़ रुपये हीनार्थ-प्रबन्धन से प्राप्त किया जा सकेगा। इस हीनार्थ-प्रबन्धन से किसी प्रकार के मुद्रा-प्रसार होने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि लगभग २०० करोड़ रुपये की रकम पौंड पावनों से प्राप्त होने की आशा थी। प्रथम योजना में केवल ४५० करोड़ का हीनार्थ प्रबन्धन ही किया जा सका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर सार्वजनिक क्षेत्र में ४८०० करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान लगाया गया जिसे पूरा करने के लिए योजना के पाँच वर्षों में १२०० करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में ४०० करोड़ रुपये का ऐसा व्यय था जिसके लिए साधन निश्चित नहीं किये जा सके थे और लोगों का अनुमान था कि इस व्यय को पूरा करने के लिए भी सरकार को हीनार्थ-प्रबन्धन का आश्रय लेना पड़ेगा। इस प्रकार कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार दूसरी योजना में १६०० करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन करने की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना थी। किन्तु सरकार के द्वारा हीनार्थ-प्रबन्धन की सीमा १२०० करोड़ रुपये ही निश्चित की गई। इसमें से लगभग २०० करोड़ रुपये की राशि पौंड पावनों से प्राप्त की जाने की सम्भावना थी और इस प्रकार केवल १००० करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन ही मूल्यों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव डाल सकता था। यद्यपि कुछ क्षेत्रों ने हीनार्थ-प्रबन्धन की इतनी अधिक मात्रा को खतरनाक बतलाया और उसका विरोध किया किन्तु सरकार अपने निर्णय पर स्थिर रही। सरकार का यह विश्वास था कि १२०० करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन भारतीय अर्थ-व्यवस्था सहन कर लेगी और उसके परिणामस्वरूप मुद्रा-प्रसार का खतरा बहुत अधिक नहीं बड़ेगा। किन्तु वास्तविक घटनाएँ इसके बिल्कुल विपरीत हुईं और दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में ही वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ना आरम्भ कर दिया और १९५६ तक हमारी अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि सरकार को उसे रोकने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ी। अब यह अनुभव किया जाने लगा था कि द्वितीय योजना काल में हीनार्थ-प्रबन्धन की मात्रा १२०० करोड़ रुपये से बढ़ जायेगी जिसके कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के प्रभाव का बढ़ना स्वाभाविक था। दूसरी योजना काल में कुल मिलाकर ६४८ करोड़ रुपये का हीनार्थ-प्रबन्धन किया गया किन्तु इसके कारण अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार का दबाव बढ़ गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीसरी योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन की मात्रा केवल ५५० करोड़ रुपये निश्चित की है और यह भी निश्चय किया है कि चौथी योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन नहीं किया जायेगा।

हीनार्थ-प्रबन्धन—इसके सम्बन्ध में मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं—(अ) क्या वर्तमान मात्रा में किया जाने वाला हीनार्थ-प्रबन्धन देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-प्रसार के दबाव को बढ़ा देगा? (ब) हीनार्थ-प्रबन्धन के कारण मुद्रा-स्फीति के

बढ़ने की सम्भावना है तो उसके विरोधी उपाय क्या होने चाहिए ? (स) वर्तमान स्थिति में हीनार्थ-प्रवन्धन की सुरक्षित सीमा क्या होनी चाहिए ? योजना कमीशन के अनुसार भारतवर्ष में वर्तमान हीनार्थ-प्रवन्धन की मात्रा अधिक नहीं है और यदि लाख के विस्तार पर नियन्त्रण रखा जाये तो वह देश के आर्थिक विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हीनार्थ-प्रवन्धन कहाँ तक मुद्रा-स्फीति के दबाव को बढ़ायेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को कितना बढ़ाया जा सकता है। हीनार्थ-प्रवन्धन के दुष्परिणामों से बचने के लिए योजना कमीशन ने निम्नलिखित उपाय बतलाये हैं—

(i) मूल्यों पर मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करने के लिए देश में अनाज का बहुत बड़ा भण्डार स्थापित किया जाना चाहिए। अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं की इतनी बड़ी पूर्ति सरकार के हाथों में होनी चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर उसे बाजार में ला सके।

(ii) खाद्य-सामग्री तथा कपड़े के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखा जाये क्योंकि वे हमारी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

(iii) करारोपण तथा अन्य विधियों से लोगों के अत्यधिक उपभोग को रोक जाना चाहिए। हीनार्थ प्रवन्धन के द्वारा लोगों की आय तथा लाभों में जो वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग करो के द्वारा निकाल लेना चाहिए।

(iv) आर्थिक नियन्त्रणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अल्प पूर्ति वाली वस्तुओं के उपभोग को एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़ने देने के लिए मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग का प्रयोग किया जा सकता है; यद्यपि आर्थिक नियन्त्रणों को हमारे देश में सीमित सफलता ही मिली है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किया है ? विवेचन कीजिए। (राजस्थान, बी० काम० १९५६)
- (२) अपने देश में द्वितीय विश्व-युद्ध के समय और उसके पश्चात् मुद्रा-स्फीति के कारणों का विवेचन कीजिए। राज्य द्वारा किये गये नियन्त्रण उपायों का वर्णन कीजिए। (भाषा, बी० काम० १९५६)
- (३) मुद्रा-प्रसार किसे कहते हैं ? युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के भारतीय कृषि पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (इलाहाबाद १९५४)
- (४) मुद्रा-प्रसार क्या है ? उसके क्या कारण होते हैं ? किसी देश की अर्थ-व्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ? भारतीय दशार्थों को ध्यान में रखते हुए विवेचना कीजिए। (राजस्थान, बी० काम० १९५४)
- (५) 'हीनार्थ-प्रवन्धन मुद्रा-प्रसार उत्पन्न करता है।' इस वाक्य का परीक्षण कीजिए। मुद्रा-प्रसार को कैसे रोका जा सकता है ?

(पटना, बी० ए० १९५७)

भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली

DECIMAL CURRENCY SYSTEM IN INDIA

संसार के लगभग सभी आधुनिक देशों ने अपनी मुद्रा प्रणाली का निर्माण दशमिक सिद्धान्त के आधार पर किया हुआ है। कुछ एक देशों में तोल और नाप के लिए भी दशमलव प्रणाली को अपना लिया गया है। इस समय संसार के १४० देशों में स्वतन्त्र मुद्राएँ हैं जिनमें से १०५ ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया हुआ है। सर्वप्रथम अठारहवीं शताब्दी के अन्त में (सन् १७८६-१७९२) अमेरिका ने दशमलव प्रणाली को अपनाया और डॉलर को इकाई मान कर उसे १०० भागों में बाँट दिया गया। सन् १७९९-१८०३ में फ्रांस तथा सेंटिन मेट्रिक सय के देशों ने भी दशमलव प्रणाली को अपना लिया। जर्मनी ने १८७३ में तथा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने १८७५ में दशमिक प्रणाली को अपनाया। सन् १८७१ में जापान ने तथा १८९७ में रूस ने भी दशमिक प्रणाली को अपना लिया। महत्वपूर्ण देशों में केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसने अभी तक दशमलव प्रणाली को नहीं अपनाया है। यद्यपि वहाँ पर भी इस प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई किन्तु कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उसे नहीं अपनाया जा सका है। पिछले कुछ दिनों में इंग्लैंड में भी मुद्रा के दशमलवीकरण की चर्चा आरम्भ हो गई है और इस प्रणाली को अपनाने के विषय में विचार किया जा रहा है। भारतवर्ष दशमलवीकरण की दृष्टि से अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे रह गया है। शून्य (Zero) के विचार का जन्मदाता होते हुए भी वह बहुत अधिक समय तक दशमलव प्रणाली को नहीं अपना सका है। यद्यपि हमारे देश में दशमिक प्रणाली की आवश्यकता काफी लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी किन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से उसे स्थापित नहीं किया जा सका। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय मुद्रा प्रणाली में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सका है।

दशमिक मुद्रा प्रणाली से अभिप्राय उस मुद्रा प्रणाली में होता है जिसमें प्रत्येक मुद्रा इकाई अपने से ऊपर की इकाई का दसवा भाग होती है। इस मुद्रा प्रणाली में एक मुद्रा इकाई को दस से गुणा करके अथवा भाग देकर दूसरी मुद्रा

इकाई को निकाला जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि प्रामाणिक सिक्का १ है तो उसमें बड़े सिक्के १०, १००, १००० आदि तथा छोटे सिक्के १/१०, १/१०० आदि हो सकते हैं। इस प्रणाली में बीच के सिक्के नहीं होते हैं किन्तु इस सिद्धान्त का पालन पूर्णतया नहीं किया जाता है और दाशमिक मुद्रा प्रणाली वाले देशों ने उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लिए हैं। सामान्यतः दाशमिक प्रणाली वाले देशों में प्रामाणिक सिक्के को १०० भागों में बांट दिया जाता है और सबसे छोटा सिक्का प्रामाणिक सिक्के का १/१०० भाग होता है। इसके बीच में सुविधानुसार विभिन्न मूल्यों के छोटे सिक्के चला लिए जाते हैं।

किसी भी देश के द्वारा दशमलव प्रणाली का अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक घटना है। दाशमिक प्रणाली अन्य प्रकार की मुद्रा प्रणालियों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि वह एक साधारण तथा आधुनिक प्रणाली है। दाशमिक प्रणाली वाले देशों का अनुभव यह बतलाता है कि हिसाब-किताब की दृष्टि से यह प्रणाली बड़ी सरल है और प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए किसी न किसी अवस्था में इस प्रणाली का अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था को चलाने में यह बड़ी सहायता देती है।

भारत में दशमलव प्रणाली की आवश्यकता—

वर्तमान व्यापार तथा वाणिज्य पद्धति काफी जटिल हो गई है और उसे भरी प्रकार से चलाने के लिए विभिन्न मुद्रा इकाइयों का एक दूसरे में आसानी से परिवर्तनीय होना अत्यन्त आवश्यक है। दाशमिक मुद्रा प्रणाली विभिन्न मुद्रा इकाइयों को एक दूसरे के साथ बदलने के कार्य को बहुत सरल कर देती है। दाशमिक मुद्रा प्रणाली आरम्भ होने से पूर्व भारत में प्रचलित मुद्रा प्रणाली बहुत अधिक जटिल तथा अनुविधाजनक थी। रुपये के प्रामाणिक सिक्के को १६ भागों में बांटा हुआ था और एक आना ४ पैसों तथा १२ पाइयों में बांटा हुआ था। इस प्रकार पैसे का सिक्का प्रामाणिक सिक्के का १/१६ होता था। इस प्रणाली में हिसाब-किताब लगाने में बड़ी कठिनाई होती थी और बहुत शक्ति तथा समय नष्ट होता था। मुद्रा प्रणाली में सरलता लाने के लिए हमारे देश में दाशमिक प्रणाली की अपनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके अतिरिक्त देश में आर्थिक विकास का युग आरम्भ होने के साथ-साथ यह अनुभव किया गया कि हमारी मुद्रा प्रणाली भी आधुनिक तथा प्रगतिशील होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा जटिल तथा विकसित व्यापार एवं औद्योगिक व्यवस्था को सरलतापूर्वक चलाया जा सके। मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से भारतवर्ष में दाशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता अनुभव की गई—

(अ) संसार के अधिकांश देशों में काफी समय से दाशमिक मुद्रा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा था। केवल इंग्लैंड को छोड़कर लगभग सभी विकसित तथा

प्रगतिशील देशों में दशमलव प्रणाली को अपना लिया गया है। भारतवर्ष भी अपनी मुद्रा प्रणाली का दशमलवीकरण करके इन देशों की सूची में सम्मिलित हो सकता है तथा उनके साथ निकट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

(ब) भारतवर्ष में औद्योगीकरण का आरम्भ हो रहा है और १०-१५ वर्षों में ही हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी जटिल हो जायेगी कि हमें हिसाब-किताब राशानों के लिए मशीनों का प्रयोग करना होगा। यदि हम इस समय दशमलव प्रणाली को अपना लेते हैं तो हमारी गणना प्रणाली बहुत अधिक सरल हो जायेगी और हम भविष्य की कठिनाइयों से बच सकेंगे।

(स) दशमिक मुद्रा प्रणाली के साथ-साथ हमें अन्य प्रकार की नाप व तोल प्रणालियों का भी दशमिक क्रम के आधार पर निर्माण करना होगा। यदि पहले मुद्रा प्रणाली का दशमलवीकरण कर दिया जाये तो उसके हमारे देश में पूर्णतया दशमिक प्रणाली को अपनाने में आसानी होगी।

(द) दशमिक मुद्रा प्रणाली बड़ी सरल तथा आधुनिक प्रणाली है और किसी भी प्रगतिशील देश के लिए उसे न अपनाना एक भारी भूल होगी। समार के सभी सम्म देशों में गणित के चिह्न दशमलवीय आधार पर बनाये गये हैं। ऐसी दशा में नाप व तोल की कोई भी प्रणाली जिसका दशमलवीय आधार न हो, हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। दशमिक प्रणाली बड़ी सरल तथा आधुनिक प्रणाली है और उसे अपनाना प्रत्येक प्रगतिशील देश के आर्थिक हितों में है।

भारत में दशमिक प्रणाली का इतिहास—

उपरोक्त सभी कारणों से हमारे देश में दशमलव प्रणाली को अपनाने की माग लगभग पिछले १०० वर्षों से की जा रही थी। सर्वप्रथम १८६७ में सरकार ने यह निश्चय किया कि भारत में धीरे-धीरे दशमलवीय सिक्कों का चलन आरम्भ कर दिया जाय। सन् १८७० में दशमिक प्रणाली को अपनाने के सम्बन्ध में एक निश्चित कदम उठाया गया और एक दशमिक अधिनियम (Metric Act of 1870) भी पास कर दिया गया किन्तु कुछ विशेष कारणों से इस अधिनियम को कार्य-रूप में नहीं लाया जा सका। इसके पश्चात् लगभग ७० वर्ष तक दशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। सन् १९४० में भारतीय दशमिक समिति (Indian Decimal Society) स्थापन की गई। इस संस्था ने भारत में दशमिक प्रणाली का प्रचार करने का कार्य आरम्भ किया और देश में दशमिक क्रम की स्थापना पर जोर दिया।

सन् १९४६ में मुद्रा के दशमलवीकरण की एक योजना बनाई गई और उसे कार्य-रूप में लाने के लिए केन्द्रीय विधान मन्त्रालय में एक बिल प्रस्तुत किया गया। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रुपये को १६२ पाई के स्थान पर १०० सेंट (cents) में बाँटने का मुकाम रखा गया। रुपये के अतिरिक्त ५० और २५ सेंट

के सिक्के चलाने की भी व्यवस्था की गई। छोटे सिक्कों के रूप में १०, ५, २, १ तथा ५ सेंट के सिक्के होंगे। किन्तु कुछ कारणों से यह बिल पास न हो सका और दशमिक प्रणाली को अपनाने का काम फिर स्थगित कर दिया गया। सन् १९४६ में भारतीय प्रतिमान संस्था (Indian Standard Institute) की एक विशेष समिति ने देश में दशमिक प्रणाली को अपनाने के सम्बन्धी समस्याओं की जाँच की। समिति ने दशमिक प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की किन्तु समिति के अनुसार यह काम धीरे-धीरे १० या १५ वर्षों में किया जाना चाहिए। समिति का विचार था कि देश में सर्वप्रथम दशमिक मुद्रा प्रणाली जारी की जानी चाहिए और फिर धीरे-धीरे तोल, नाप तथा अन्य क्षेत्रों में दशमिक क्रम को स्थापित किया जाये।

भारतीय सिक्का (संशोधन) अधिनियम १९५५ [Indian Coinage (Amendment) Act 1956]—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश के सामने जो बहुत-सी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ थी उनमें से मुद्रा प्रणाली का दशमलीकरण किया जाना एक महत्वपूर्ण समस्या थी। अब भारतीय मुद्रा प्रणाली के दशमलीकरण की समस्या को और अधिक समय के लिए स्थगित करना सम्भव नहीं था अतः भारत सरकार ने संसद के समक्ष सन् १९५५ में दशमिक प्रणाली को अपनाये जाने के सम्बन्ध में एक बिल प्रस्तुत किया। सितम्बर सन् १९५५ में इस बिल को भारतीय सिक्का (संशोधन) अधिनियम [Indian Currency (Amendment) Act 1955] के नाम से पास कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ही हमारे देश में दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया है। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) नई मुद्रा प्रणाली में भारत की प्रमुख मुद्रा इकाई रुपया ही रहेगी। रुपये को १०० सामान्य इकाइयों में बाँटा जायेगा और प्रत्येक इकाई का नाम 'पैसा' रहेगा किन्तु कुछ समय के लिए, जब तक नये और पुराने सिक्के साथ-साथ चलेंगे, इसे 'नया पैसा' कहा जायगा। एक रुपया १०० नये पैसे के बराबर होगा।

(२) रुपये और नये पैसे के अतिरिक्त ५० और २५ नये पैसे के दो सिक्के और चलाये जायेंगे जो वर्तमान ८ आने तथा ४ आने के सिक्कों के बराबर होंगे। इनके अनिश्चित १०, ५ व २ नये पैसे के सिक्के भी चलाये जायेंगे।

(३) १००, ५० और २५ नये पैसे के सिक्के शुद्ध गिल्ट के होंगे तथा १०, ५ और २ नये पैसे के सिक्के ताँबे और गिल्ट के मिश्रण के होंगे जिसमें ७५% ताँबा और २५% गिल्ट होगी।

(४) वर्तमान दो आने, एक आने, दो पैसे और एक पैसे के सिक्के भी कुछ समय तक साथ-साथ चलते रहेंगे, किन्तु धीरे-धीरे उनका विमुद्रीकरण किया जायगा। तीन वर्ष के पश्चात् पुराने सिक्के चलन से बिलकुल निकल जायेंगे तथा

पूर्ण रूप से नई मुद्रा चालू हो जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

(५) यह अधिनियम १ अप्रैल सन् १९५७ से देश भर में लागू कर दिया जायगा।

भारत की नई सिक्का प्रणाली—

भारतीय सिक्का (सशोधन) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत संसद भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपना लिया गया है। भारत में दशमिक आधार पर अपने सिक्को का निर्माण करके मुद्रा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त आवश्यक परिवर्तन किया है जिसके परिणामस्वरूप अब हमारा देश उन प्रगतिशील देशों की सूची में आ जाता है जिन्होंने दशमिक प्रणाली को अपनाया हुआ है। दशमिक सिक्को के चलन से हमारी विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए एक उपयुक्त हिसाब-किताब की इकाई हमें मिल जाती है तथा धीरे-धीरे देश में ऐसा वातवरण उत्पन्न हो जायगा जिससे नाप, तोल तथा अन्य क्षेत्रों में भी दशमिक क्रम को अपनाया जा सकेगा।

इस नई सिक्का प्रणाली में भारत का प्रमाणिक सिक्का रुपया ही है किन्तु अब वह शुद्ध गिल्ट का बनाया जाता है। रुपये का विभाजन अब १६ आने अथवा १६२ पाई में न होकर के १०० नये पैसे में किया गया है। देश में सबसे छोटा सिक्का 'नया पैसा' है जो रुपये का $\frac{1}{100}$ भाग है। रुपये का $\frac{1}{10}$ तथा $\frac{1}{20}$ भाग वाले सिक्के अब आने व ४ आने न होकर ५० नये पैसे तथा २५ नये पैसे हो गये हैं। इनके अतिरिक्त १, ५ और २ नये पैसे के सिक्के चलन में डाल दिये गये हैं। आरम्भ में केवल १, २, ५ व १० नये पैसे के सिक्के ही चलाये गये थे किन्तु कुछ समय पश्चात् ५० और २५ नये पैसे वाले सिक्के भी चालू कर दिये गये हैं। अब ३ पैसे का सिक्का भी चला दिया गया है।

भारतीय जनता को नई मुद्रा प्रणाली से परिचित करने तथा आकस्मिक परिवर्तन की कठिनाइयों से उन्हें बचाने के लिए सरकार ने तीन वर्षों की अवधि तक नये और पुराने दोनों प्रकार के सिक्को को चलन में रखने का निर्णय किया है। पुराने सिक्के दशमिक सिक्को में निश्चित दरों पर परिवर्तनीय हैं। २ आने तथा उसमें कम के पुराने सिक्को का तथा नये पैसे का पूरा-पूरा प्रतिमान नहीं होता है इसलिये वे निकटतम प्रतिमान के आधार पर बदले जाते हैं। इस अन्तरिम काल में पुराने सिक्को को सरकारी मान्यता प्राप्त रहेगी और लेन-देन में नये व पुराने दोनों प्रकार के सिक्को का प्रयोग किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति नये, पुराने अथवा नये व पुराने सिक्को को मिलाकर मुयतान कर सकता है। धीरे-धीरे दो आने तथा एक आने व आध आने वाले सिक्कों को चलन से निवाल लिया जायेगा। इस बीच में टक्कालों पर्याप्त मात्रा में नये सिक्को का निर्माण कर सकेंगी और अन्तरिम अवधि के अन्त तक केवल दशमिक सिक्के ही प्रचलन में रह जायेंगे।

दाशमिक मुद्रा को धीरे-धीरे हिसाबी मुद्रा का कार्य भी सौंप दिया जायगा । १ अप्रैल सन् १९५७ से सब सरकारी दफ्तरो में हिमाव-बिताव रुपये, घाने, पाई के स्थान पर रुपये और नये पैसों में रक्खा जाने लगा है । बैंकों में भी जमा रुपये तथा नये पैसों में प्राप्त की जाती है और उसे नये सिक्कों में ही निकाला जा सकता है । धीरे-धीरे अर्ध सरकारी संस्थाओं तथा बड़ी-बड़ी औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा भी रुपये तथा नये पैसों को हिमाव-बिताव की इकाई के रूप में अपनाया जा रहा है । इस प्रकार यह आशा है कि अन्तरिम काल के अन्त तक रुपये तथा नये पैसों को पूर्णतया हिसाबी मुद्रा के रूप में अपना लिया जायेगा ।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस नई प्रणाली को समझे तथा उसके सुगमतापूर्वक चलने में सहयोग दे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने नई मुद्रा प्रणाली के प्रचार पर बहुत जोर दिया है और जनवरी सन् १९५७ से दाशमिक प्रणाली का प्रचार समस्त देश में आरम्भ कर दिया गया है । मित्रा मन्त्रालय के एक कार्यक्रम के अनुसार दाशमिक मुद्रा प्रणाली का पाठ्य-पुस्तकों में समावेश कर दिया गया है तथा विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा दी जान लगी है । इसके अतिरिक्त समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, पोस्टर, फोल्डर, फिल्मों तथा रेडियो आदि के द्वारा सभी प्रमुख भाषाओं में दाशमिक प्रणाली का प्रचार किया जा रहा है, किन्तु ग्रामीण तथा अशिक्षित जनता में नई मुद्रा प्रणाली का प्रचार करने में विशेष कठिनाई अनुभव हो रही है ।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली के लाभ—

(i) यह एक आधुनिक मुद्रा प्रणाली है और ससार के अधिकांश देशों में अन्य प्रणालियों को हटा कर इसे अपना लिया गया है । ससार के लगभग सभी देशों में मुद्रा प्रणाली का निर्माण दाशमिक आधार पर किया जा चुका है । भारतवर्ष आन्तरिक मुद्रा प्रणाली को अपनाकर उन देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है जिन देशों में दाशमिक प्रणाली प्रचलित है ।

(ii) यह प्रणाली बहुत सरल तथा सुविधापूर्ण है । समार भर में दाशमिक प्रणाली को सरलतम प्रणाली माना गया है । इस प्रणाली में हिमाव-बिताव सरलता व शीघ्रता के साथ किया जा सकता है, जिसके कारण समय तथा शक्ति की बचत होती है ।

(iii) एक प्रगतिशील समाज में व्यापार तथा वाणिज्य की जटिल प्रणाली में सिक्कों की सरलता से अद्वय-बदल बहुत आवश्यक है । दाशमिक प्रणाली में एक मूल्य के सिक्के दूसरे मूल्य के सिक्कों में बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं जिसके कारण व्यापार तथा वाणिज्य के सरलतापूर्वक चलने में सहायता मिलती है ।

(iv) मूल्यों के छोटे-छोटे परिवर्तनों को भी दाशमिक प्रणाली में सही नापा जा सकता है । कई बार मूल्यों में इतने सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं कि उन्हें अन्य मुद्रा

प्रणालियों में नापना सम्भव नहीं होता है किन्तु दाशमिक प्रणाली होने से यह कठिनाई बिल्कुल दूर हो जाती है।

(v) विद्यार्थियों के लिए दाशमिक प्रणाली से अंकगणित सीखना बहुत आसान हो गया है और शिक्षा संस्थाओं में समय तथा श्रम की काफी बचत की जा सकी है।

(vi) इस मुद्रा प्रणाली का अन्तर्राष्ट्रीय आधार होने के कारण हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक सुविधा होगी। अधिकांश देशों में दाशमिक प्रणाली होने के कारण हमारे देश के आर्थिक सम्बन्ध इन देशों के साथ निकट होंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हिसाब-किताब आसानी से रक्खा जा सकेगा।

(vii) दाशमिक मुद्रा प्रणाली के जारी कर देने से नाप, तौल तथा अन्य क्षेत्रों में दाशमिक क्रम को अपनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार हो जायगा। दाशमिक सिक्कों का प्रयोग करने से लोभ धीरे-धीरे दाशमिक क्रम से परिचित हो जायेंगे और कुछ समय पश्चात् अन्य क्षेत्रों में भी दाशमिक क्रम को अपनाया जा सकेगा।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली के दोष—

उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी दाशमिक प्रणाली को जारी करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यह व्यावहारिक कठिनाइयाँ हमारे देश में और भी अधिक होंगी क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता अशिक्षित तथा खड़ीवादी है। किन्तु इन कठिनाइयों के होते हुए भी हमारे देश में दाशमिक मुद्रा का अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। सामान्यतः दाशमिक प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयाँ अनुभव की गई हैं—

(i) ग्रामीण लोगों के लिए इस नई प्रणाली को समझने में विशेष कठिनाई हो रही है और उन्हें दाशमिक प्रणाली से परिचित होने में काफी समय लगेगा। इस बीच में कुछ लोग उनकी अनभिज्ञता से अनुचित लाभ उठा सकते हैं। किन्तु इस प्रकार की कठिनाइयाँ प्रत्येक परिवर्तन में होती हैं।

(ii) लोग नई प्रणाली का विरोध केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ६० आ० पाई वाली प्रणाली बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। अधिकांश लोग इस प्रकार के परिवर्तन को पसन्द नहीं करते हैं और वे दाशमिक प्रणाली का विरोध केवल भावुकता के कारण करते हैं।

(iii) दाशमिक मुद्रा जारी होने से वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को निश्चित करने का आधार बदल गया है। अब सभी वस्तुओं के मूल्यों को दाशमिक सिक्कों में व्यक्त करना होगा जिसमें कुछ कठिनाई हो सकती है। किन्तु इस प्रकार की असुविधा केवल थोड़े समय के लिए ही है और नई मुद्रा के पूर्ण रूप से चलन में आने के पश्चात् यह कठिनाई स्वयं दूर हो जायगी।

(vi) नई और पुरानी मुद्रा के साथ-साथ चलने से काफी उलझन पैदा हो गई है। अधिकांश सौदों में अभी पुरानी मुद्रा मूल्य मान का कार्य करती है और

वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य अभी भी रुपये तथा आनों में व्यक्त किये जाते हैं किन्तु मुद्रातान के लिए या तो दशमिक और या मिले-जुले सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में जनता को बहुत असुविधा होती है।

वास्तव में यह सभी कठिनाइयाँ अल्पकालीन हैं। जैसे-जैसे लोग दशमिक मुद्रा प्रणाली से परिचित होते जायेंगे वैसे ही वैसे यह कठिनाइयाँ भी दूर हो जायेंगी। पुराने सिक्के अब चलन में निवाल लिए गये हैं और दशमिक सिक्के पूर्णतया चलन में आ गये हैं जिसके कारण बहुत-सी व्यवहारिक उलझनें दूर हो गई हैं। हमारे अतिरिक्त भारतीय सिक्का (संशोधन) अधिनियम १९६४ के अन्तर्गत १ जून सन् १९६४ से 'नया पैसा' शब्द के स्थान पर केवल 'पैसा' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है जिसके परिणामस्वरूप हिमाब-बिताब सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। इन परिघटनो के हो जाने से दशमिक मुद्रा प्रणाली की व्यवहारिक कठिनाइयाँ धीरे-धीरे समाप्त हो गई हैं और नई मुद्रा प्रणाली देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल होती जा रही है।

दशमिक मुद्रा प्रणाली से पूरा-पूरा सामंजस्य के लिए यह आवश्यक था कि माप व तोल की प्रणालियों का निर्माण भी दशमिक आधार पर किया जाय। सरकार ने यह निश्चय किया था कि सन् १९५८ के अन्त तक इन प्रणालियों को भी दशमिक क्रम के अनुसार कर दिया जायगा। सन् १९५६ में तोल व माप की दशमलवीय प्रणाली की आधारभूत इकाइयाँ निर्दिष्ट कर दी गईं और अक्टूबर सन् १९५८ से माप व तोल की दशमिक प्रणालियाँ देश भर में लागू कर दी गई हैं। यह प्रणाली धीरे-धीरे पुरानी प्रणाली का स्थान ले रही है। तीन वर्ष की अवधि तक नई व पुरानी माप-तोल साथ-साथ काम करेगी और उसके पश्चात् माप व तोल की दशमिक प्रणाली पूर्णतया स्थापित कर दी जायगी। तोल की आधारभूत इकाई किलोग्राम (Kilogram) रखी गई है जिसका वजन ८६ तोले अथवा पुराने १ सेर ६ तोले के बराबर है। माप की आधारभूत इकाई मीटर (Meter) निर्दिष्ट की गई है। इन प्रणालियों के पूर्णतया स्थापित हो जाने के पश्चात् हमारे देश में सब प्रकार का हिमाब-बिताब दशमलवीय आधार पर रक्खा जाने लगेगा जिससे आन्तरिक क्षेत्र में अधिक सुविधा के साथ विनिमय कार्य किया जा सकेगा और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुलनायें करना, विनिमय अनुपात निर्दिष्ट करना तथा विनिमय के स्रोतों की निश्चयना आसान हो जायगा।

परीक्षा प्रश्न

- (१) भारतवर्ष में दशमलव मुद्रा प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? हमारे देश में उससे क्या लाभ तथा हानियाँ हैं। (आगरा, बी० काम १९५९)
- (२) दशमिक मुद्रा प्रणाली क्या है? भारतीय दशाब्दों में उसके लाभ तथा हानियों को बतलाइये। (राजस्थान, बी० ए० १९५६)
- (३) भारतीय सिक्का (संशोधन) अधिनियम १९५५ की मुख्य धाराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

साख तथा साख-पत्र

CREDIT AND CREDIT INSTRUMENTS

साख को वर्तमान आर्थिक जीवन का आधार माना जाता है। आज की व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवस्था साख के बिना नहीं चल सकती है। हमारे समाज में व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियायें बहुत कुछ साख तथा साख-पत्रों के प्रयोग पर आधारित हैं। वस्तुओं का स्थिति भुगतान के आधार पर उधार बेचा जाना तथा समाज में प्रचलित ऋण-व्यवस्था, आर्थिक जीवन में साख के महत्त्व को बतलाते हैं। साख का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से होता आया है और लगभग प्रत्येक आर्थिक काल में वस्तुओं को उधार लेने तथा ऋणों के लेन-देन की व्यवस्था रही है। आरम्भ काल में साख संस्थाओं के अभाव तथा साख-पत्रों का उचित विकास न होने के कारण साख का प्रयोग बहुत कम किया जाता था किन्तु आर्थिक विकास के साथ-साथ साख संस्थाओं का संगठन तथा साख-पत्रों का विकास हुआ और मानव समाज अधिकाधिक साख पर आधारित होता गया। कोई देश जितना अधिक प्रगतिशील होता है उतना ही उस देश में साख का प्रयोग अधिक किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में विकसित देशों की अपेक्षा साख का प्रयोग कम किया जाता है। आज के वैश्वीकरण का साख के साथ इतना गहरा सम्बन्ध है कि उन्हें 'साख का व्यापारी' कहा जाता है। अतः बैंक का अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व साख की प्रकृति तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

साख का अर्थ (Meaning of Credit)—

साधारणतया 'साख' शब्द का अर्थ विश्वास अथवा भरोसे से होता है। किसी व्यक्ति पर लोग जितना अधिक विश्वास करते हैं उसकी साख-उत्तीर्ण ही अधिक होती है। साख का यह अर्थ बड़ा व्यापक है। धर्मशास्त्र में 'साख' शब्द का प्रयोग संबुद्धि अर्थ में किया जाता है और उससे हमारा अभिप्राय ऋण लौटाने

अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बाजार में साख अधिक है तो उसमें हमारा अभिप्राय यह होता है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों की अधिक विश्वास है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों की कम विश्वास होता है उसकी साख कम होती है। अतः साख किसी व्यक्ति की ऋणों का भुगतान करने की शक्ति में होने वाले विश्वास का प्रतीक है। प्रो० कैंट (Kent) ने साख की परिभाषा इस प्रकार की है—“माय किये जाने पर अथवा एक निश्चित काल के पश्चात्, वर्तमान समय में हस्तान्तरित वस्तुओं के बदले में भुगतान लेने के अधिकार अथवा भुगतान देने की जिम्मेदारी को साख कहते हैं।”^१ प्रो० जीड (Gide) के अनुसार साख “एक प्रकार का विनिमय कार्य है जो एक निश्चित वास्तविक समाप्ति के पश्चात्, भुगतान निबटाने पर पूरा होता है।”^२ प्रो० टामस (Thomas) के अनुसार “आजकल साख शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति की दीर्घन क्षमता अथवा भुगतान निबटाने की शक्ति में उस विश्वास से होता है जिसके आधार पर उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मूल्यवान वस्तु को दिया जा सकता है। यह मूल्यवान वस्तु मुद्रा, सेवार्थ अथवा स्वयं साख हो सकती है, जैसे कि उस दशा में होती है जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपने नाम अथवा व्यवसायिक ख्याति के प्रयोग का अधिकार देता है।”^३ प्रो० कोल (G. D. H. Cole) ने साख को बैंकों के द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रकार की क्रय-शक्ति माना है। उनके अनुसार, “साख उस क्रय-शक्ति को कहते हैं जो आय के द्वारा प्राप्त नहीं होती है बल्कि वैयक्तिक संस्थाओं के द्वारा या तो उस जमा का, जो उनके पास रखी होती है, प्रयोग करने के उद्देश्य से या कुल क्रय-शक्ति में वृद्धि करने के लिए उत्पन्न की जाती है।”^४

1 “Credit may be defined as ‘the right to receive payment on the obligation to make payment on demand or at some future time on account of the immediate transfer of goods.’”

—Raymond P. Kent Money and Banking, P. 199.

2 “It is an exchange, which is complete after the expiry of a certain period of time after payment”

—Gide.

3 “The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another, whether that ‘something’ consists of money, goods, services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation”

—S. E. Thomas Elements of Economics, P. 398

4 “Credit is purchasing power not ‘derived from income’ but created by financial institutions either as an offset to idle incomes held by depositors in the banks, or as a net addition to the total amount of purchasing power.”

—G. D. H. Cole Money, Its Present and Future, P. 303.

साख का आधार (Basis of Credit)—

सामान्यतया साख का आधार वह विश्वास होता है जो ऋणदाता को ऋण के भुगतान करने के सम्बन्धी वायदे को पूरा करने की क्षमता में होता है। कुछ लेखकों के अनुसार केवल विश्वास ही साख का आधार है क्योंकि ऋणदाता कभी भी विश्वास के प्रभाव में ऋण नहीं देगा। किन्तु कुछ लेखकों ने इस विचार का विरोध किया है। इनके अनुसार साख का आधार विश्वास न होकर, ऋण लेने वाले की सम्पत्ति है। ऋण देने वाला ऋण देते समय ऋणी की सम्पत्ति पर निगाह रखता है और उसके आधार पर ही उसकी शोषण क्षमता का अनुमान लगाता है। इसलिए साख का आधार व्यक्ति की सम्पत्ति है। कुछ अन्य लोगो का विचार है कि साख का वास्तविक आधार ऋण लेने वाले का चरित्र है। इन सभी विचारों में कुछ न कुछ सत्यता अवश्य पाई जाती है। यद्यपि इनमें से किसी एक को पूर्णतया साख का आधार नहीं माना जा सकता है किन्तु वे सब मिलकर किसी व्यक्ति की साख को निश्चित करते हैं। वास्तव में विश्वास, सम्पत्ति तथा चरित्र तीनों को ही साख का आधार माना जाना चाहिए। अतः किसी व्यक्ति की साख निम्नलिखित बातों पर आधारित होती है—

(१) विश्वास (Confidence)—जिस व्यक्ति के बारे में यह विश्वास होता है कि वह ऋणों को ठीक समय पर लौटा देगा, उस व्यक्ति की साख अधिक होती है और उसे बाजार में ऋण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु यदि ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास नहीं है तो ऐसी दशा में वह ऋण नहीं देगा और इस प्रकार के व्यक्तियों की साख बहुत कम होती है। अतः किसी व्यक्ति में ऋणदाता को ऋणों की वापसी के सम्बन्ध में जितना अधिक विश्वास होता है, उस व्यक्ति की साख उतनी ही अधिक होती है। चैंडलर (Chandler) के अनुसार—“किसी व्यक्ति, व्यवसायिक फर्म अथवा सरकारी संस्था की साख प्राप्त करने की क्षमता सम्भाव्य ऋणदाताओं के इस विश्वास पर आधारित होती है कि ऋणी, ऋण का भुगतान करने के लिए क्षम्य तथा तत्पर दोनों है।”⁵

(२) चरित्र (Character)—व्यक्ति का चरित्र भी उसकी साख को प्रभावित करता है। अच्छे चरित्र वालों की साख प्रायः अधिक होती है। यदि ऋणी अपनी सच्चाई के लिए प्रतिष्ठित है और उसने भूतकाल में अपने ऋणों को ठीक वायदे पर निबटारा है तो ऐसे व्यक्ति की साख बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत जिन लोगो के चरित्र के विषय में सन्देह होता है, क्योंकि वे अपने ऋणों को वायदे

5 “The ability of any person, business firm or government unit to get credit depends on potential creditor's faith that the borrower will be both able and willing to pay.”

—L. V. Chandler : The Economics of Money and Banking, P. 32.

के अनुसार नहीं लौटाने हैं, उन्हें ऋण नहीं मिलता है और उनकी साख कम होनी है।

(३) व्यक्ति की भुगतान करने की योग्यता (Capacity to Pay)—ऋण देने से पूर्व ऋणदाता ऋणी की भुगतान करने की योग्यता की जाँच करता है। जिन लोगों में ऋण लौटाने की योग्यता अधिक होती है, उन्हें ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है और बाजार में उनकी साख अधिक होती है। इसके विपरीत भुगतान निव्वटाने की योग्यता के कम होने पर व्यक्ति की साख कम हो जाती है। इस सम्बन्ध में ऋणी की शिक्षा व उसका अनुभव उसकी भुगतान करने की योग्यता को प्रभावित करता है। एक शिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति में ऋणों को लौटाने की क्षमता अधिक होती है। व्यक्ति को आय भी उसकी शोधन क्षमता का प्रतीक है। प्रायः अधिक आय वाले की साख अधिक होती है क्योंकि उनमें भुगतान करने की योग्यता अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत कम आय वालों की, भुगतान करने की योग्यता कम होने के कारण, साख कम होती है।

(४) सम्पत्ति (Property)—बड़े-बड़े ऋणों को देने के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति भी उसकी साख को प्रभावित करती है। विशेषतया बैंकों से ऋण प्राप्त करते समय व्यक्ति की सम्पत्ति तथा उसके आर्थिक साधन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऋण देने समय बैंक ऋणी की सम्पत्ति तथा उसके आर्थिक साधनों का पूरी तरह निरीक्षण करके उसकी मात्रा की मात्रा निश्चित करते हैं। अधिक सम्पत्ति वाली की साख अधिक होती है और कम सम्पत्ति वाले की साख कम।

(५) व्यक्ति की तरल सम्पत्ति (Liquidity)—किसी व्यक्ति की साख केवल उसकी सम्पत्ति के द्वारा ही निर्दिष्ट नहीं होती है बल्कि उसकी सम्पत्ति की तरलता पर भी आधारित होनी है। जिन व्यक्तियों की पूँजी तरल सम्पत्ति में लगी होती है उनकी साख प्रायः अधिक होती है। यदि ऋण लेने वाले के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रकार के तरल साधन हैं तो उसकी साख अधिक होगी और उसे आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेगा। यदि ऋणी के पास अचल सम्पत्ति है तो ऋण देने वाले को संकोच होगा।

(६) ऋण की अवधि (Period of Loan)—ऋण किनने लम्बे समय के लिए लिया जा रहा है, इस बात पर ऋणी की साख निर्भर होती है। ऋणदाता प्रायः दीर्घकालीन ऋण देने में संकोच करते हैं क्योंकि लम्बे समय में ऋणी के चरित्र, उसकी ऋण लौटाने की क्षमता तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने की सम्भावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त जमानत के तौर पर रखी गई सम्पत्ति अथवा प्रतिभूतियों का मूल्य भी बदल सकता है। अतः दीर्घकालीन ऋणों में जोखिम अधिक होती है जिसके कारण ऋण लेने वाले की साख कम रहती है।

साख का वर्गीकरण (Types of Credit)—

साख के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं—ऋणी की स्थिति के अनुसार, ऋणदाता की स्थिति के अनुसार, ऋण की अवधि के अनुसार तथा ऋण के उपयोग के अनुसार साख का वर्गीकरण किया जा सकता है। किन्तु इनमें सबसे उपयुक्त वर्गीकरण वह है जो ऋणी की स्थिति पर आधारित हो क्योंकि इस प्रकार का वर्गीकरण ही यह बता सकता है कि साख को विन-विन कामों में लाया जाता है। इसलिए अधिक प्रचलित रीति साख को उसके प्रयोगों के अनुसार वर्गीकृत करने की है। इस आधार पर साख को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(१) सार्वजनिक साख (Public Credit)

(२) व्यक्तिगत साख (Private Credit)

सार्वजनिक साख—

सार्वजनिक साख में अभिप्राय सरकारी साख से होता है। इस प्रकार की साख में वे ऋण सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न सरकारों के द्वारा भविष्य में भुगतान करने के वायदे पर प्राप्त किये जाते हैं। जब सरकार भविष्य में भुगतान करने के वायदे पर ऋण लेती है अथवा वर्तमान समय में इस वायदे पर वस्तुयें प्राप्त करती है कि उनका भुगतान भविष्य में कर दिया जायेगा तो उसे हम सार्वजनिक साख कहते हैं। वर्तमान सरकारें अपने पूँजीगत तथा अन्य प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में सार्वजनिक ऋण लेती हैं।

व्यक्तिगत साख—

समस्त गैर सरकारी ऋणियों के भविष्य में भुगतान करने के वायदे व्यक्तिगत साख कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संस्था भविष्य में भुगतान करने के वायदे पर ऋण लेती है तो उसे हम व्यक्तिगत साख कहते हैं। इस प्रकार की साख में व्यक्ति तथा संस्थाओं की साख सम्मिलित होती है। आजकल के व्यवसायिक युग में व्यक्तिगत साख का बड़ा महत्व है। वास्तव में यदि उसे आज के औद्योगिक तथा व्यवसायिक समाज का आधार कहा जाय तो अनुचित न होगा। व्यक्तिगत साख भी कई प्रकार की हो सकती है किन्तु उसके निम्नलिखित रूप महत्वपूर्ण हैं—

(घ) बैंक साख (Bank Credit)—बैंक साख के अन्तर्गत बैंकिंग संस्थाओं के विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के वायदे सम्मिलित होते हैं। बैंकों की चालू जमा (Demand Deposit) तथा निश्चित जमा (Times Deposit), बैंक नोट, ऋण पत्र (Debentures), बोंड्स (Bonds) तथा बैंकरो की स्वीकृतियाँ (Banker's Acceptances) आदि बैंक साख में सम्मिलित होते हैं। प्रायः बैंक-साख शब्द का प्रयोग सङ्कुचित अर्थ में किया जाता है जिसके अनुसार उसके अन्तर्गत केवल व्यापारिक बैंकों की चालू जमा (Demand deposits) ही सम्मिलित होती है

विस्तृत अर्थ में बैंक साख के अन्तर्गत बैंको की सभी प्रकार की साख सम्मिलित की जानी है। केन्द्रीय बैंक साख (Central Bank Credit) भी एक प्रकार की बैंक साख ही है जिसमें केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रवाहित नोट तथा अन्य प्रकार के माग-दायित्व (Demand liabilities) सम्मिलित होते हैं।

(ब) व्यवसायिक साख (Commercial Credit)—व्यवसायिक साख के अन्तर्गत व्यापारी तथा साहसी वर्ग के ऋण तथा भविष्य में भुगतान करने के वायदे सम्मिलित होते हैं। उद्योगपति को अपनी व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋणों की आवश्यकता होती है। ये ऋण भविष्य में भुगतान करने के वायदे पर प्राप्त किये जाते हैं। कच्चे माल को खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने, वस्तुओं के बिक्री व्यय आदि के लिए व्यवसायी को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक वर्ग के द्वारा अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त किये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों को व्यवसायिक साख में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की साख ६ भाग अथवा अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए हुआ करती है। उद्योग तथा व्यवसाय के पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त किये जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों को विनियोग साख (Investment Credit) कहते हैं। व्यवसायिक साख को व्यापारिक साख (Mercantile Credit), औद्योगिक साख (Industrial Credit) तथा कृषि साख (Agricultural Credit) में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यापारिक साख में थोक तथा फुटकर व्यापारियों के ऋण अथवा भविष्य में भुगतान के वायदे सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रयोग बिक्री के लिए वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक साख के अन्तर्गत उद्योगपतियों तथा अन्य उत्पादकों के ऋण सम्मिलित होते हैं। कृषि साख में किसानों तथा कृषि संस्थाओं के भविष्य में भुगतान करने के वायदे सम्मिलित होते हैं जो बीज तथा खाद खरीदने, खेत में मुधार करने तथा अन्य प्रकार के उत्पादन सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के कारण पैदा होते हैं।

(स) उपभोग साख (Consumption Credit)—उपभोग साख के अन्तर्गत वे सब ऋण आ जाते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा उपभोग सम्बन्धी धन्य पूरा करने के लिए प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों की एक विशेषता यह होती है कि इनसे ऋणों को किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। जब उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं को भविष्य में भुगतान करने के वायदे पर प्राप्त किया जाता है तो उसे उपभोग साख कहते हैं। उपभोग साख में दूकानदारों के द्वारा दिया गया उधार तथा साहूकारों के द्वारा दिये गये व्यक्तिगत ऋण सम्मिलित होते हैं।

साख की मात्रा को प्रभावित करने वाली बातें
(Factors Effecting Volume of Credit)—

किसी देश में साख की मात्रा वहाँ की औद्योगिक तथा व्यापारिक उर्ध्व पर निर्भर होती है। कोई देश औद्योगिक तथा व्यापारिक दृष्टि से जितना अधिक

उन्नत होता है उतना ही वहाँ पर साख का अधिक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में साख के विस्तार की सम्भावना बहुत कम होती है। साख का विस्तार ऋण देने वालों तथा ऋण लेने वालों के द्वारा भी निर्धारित होता है। ऋणदाता कितनी मात्रा में ऋण देने को तैयार हैं तथा ऋण लेने वाले कितना ऋण लेना चाहते हैं, इन बातों पर समाज में साख की मात्रा निर्भर होती है। मुख्यतः निम्नलिखित बातें साख की मात्रा को प्रभावित करती हैं—

(१) लाभ की आशा (Expectation of Profit)—समाज में विनियोग की मात्रा लाभ की आशा के ऊपर निर्भर होती है। प्रत्येक व्यवसायी विनियोग करने से पूर्व इस बात को देखता है कि उस विनियोग से उसे कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। विनियोगों पर लाभ की मात्रा जितनी अधिक होती है तथा विनियोग जितने अधिक सुरक्षित होते हैं उतना ही अधिक साख का विस्तार होता है। जब विनियोगों पर लाभ की दर ऊँची होती है तो विनियोगी वर्ग अधिक मात्रा में ऋण लेकर विनियोग करना चाहते हैं और ऋणदाता भी अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी दशा में साख का विस्तार अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत जब लाभ की दर कम होती है तो साख का विस्तार भी कम होता है।

(२) व्यापारिक दशाएँ (Trade Conditions)—यदि व्यापार की दशा अच्छी होती है तो विनियोगी-वर्ग अधिक मात्रा में विनियोग करना चाहते हैं और साख का विस्तार अधिक होता है। समृद्धि काल (Prosperity Period) में व्यापारिक तेजी के कारण व्यवसायी तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है तथा विनियोगों पर अधिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। ऐसी दशा में व्यवसायिक वर्ग अधिक मात्रा में ऋण लेकर अपने व्यापार तथा उद्योगों में लगाते हैं। बैंक इस बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तेजों के साथ साख का विस्तार करते हैं। व्यापारिक तेजी के कारण ऋणों की मांग अधिक होने से व्याज की दर भी बढ़ जाती है जिससे ऋणदाता अधिक मात्रा में ऋण देने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार समृद्धि काल में साख के विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। इसके विपरीत मन्दी-काल (Depression) में साख का संकुचन होता है। व्यापार की दशाएँ अच्छी न होने के कारण व्यवसायों को हानि होती है, उद्योग बन्द होने लगते हैं, उत्पादन गिरता है तथा व्यवसायिक वर्ग को हानि होती है। ऋणों की मांग बहुत कम हो जाती है और साख की मात्रा कम होने लगती है।

(३) राजनैतिक दशाएँ (Political Conditions)—साख का विस्तार होने के लिए राजनैतिक स्थिरता, सुरक्षा तथा शान्ति का होना आवश्यक है। देश में राजनैतिक स्थिरता होने से लोगों का आर्थिक जीवन भी स्थायी हो जाता है। राजनैतिक स्थिरता समाज में आर्थिक विभाग के लिए उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न करती है जिससे व्यवसाय तथा उद्योगों का विस्तार होता है, ऋणों की मांग बढ़ती है

और अधिक मात्रा में साख का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है, व्यापार तथा उद्योगों का विकास रुक जाता है, ऋणों की माग कम होती है तथा साख का संकुचन होता है।

(४) सट्टे की क्रियायें (Speculative Activity)—साख का विस्तार बहुत कुछ सट्टे की क्रियाओं पर निर्भर होता है। जब भविष्य में मूल्यों के बढ़ने की आशा होती है तो सट्टे की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। सट्टारिये वस्तुओं के अधिक सौदे करते हैं, ऋणों की माग बढ़ती है और साख का अधिक विस्तार किया जाता है। इसके विपरीत जब सट्टे बाजार में गन्दी होने के कारण सट्टारियों को हानि होने लगती है तो सट्टे की क्रियायें कम हो जाती हैं, ऋणों की माग कम होती है और साख की मात्रा कम हो जाती है।

(५) चलन की दशायें (Currency Conditions)—एक स्थिर चलन प्रणाली साख के विस्तार के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न करती है। जब चलन सम्बन्धी दशायें अनिश्चित होती हैं तो साख का संकुचन होता है। यदि देश की मुद्रा के मूल्य के कम होने का भय है अथवा सरकार की मुद्रा सम्बन्धी नीति अनिश्चित है तो ऐसी दशाओं में साख का विस्तार नहीं होगा। इसके विपरीत एक स्थिर तथा समुचित चलन प्रणाली के अन्तर्गत साख के विस्तार की सम्भावना अधिक होती है।

(६) बैंकों का विकास तथा बैंकिंग नीति (Development of Banks and Banking Policy)—वर्तमान समाज में अधिकांश साख का निर्माण बैंकों के द्वारा किया जाता है। किसी देश में बैंकों का विकास जितना अधिक होता है उतनी ही साख के विस्तार की सम्भावना बढ़ती है। बैंकिंग प्रणाली के विकसित होने से समाज में साख के विस्तार की दशायें उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत यदि बैंकों की संख्या कम है अथवा वे सुसंगठित नहीं हैं तो ऐसी दशाओं में साख का विस्तार नहीं हो सकेगा। सरकार की बैंकिंग सम्बन्धी नीति का भी साख की मात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि केन्द्रीय बैंक साख विस्तार की नीति को अपनाता है और बैंकों को साख का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन देता है तो ऐसी दशा में साख का विस्तार अधिक होगा। इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक की साख संकुचन नीति का परिणाम यह होता है कि बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण करते हैं और साख का संकुचन हो जाता है।

क्या साख पूँजी है (Is Credit Capital)—

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि साख पूँजी है और वह उत्पादन में वृद्धि करती है इसलिए उसे उत्पत्ति का पृथक् साधन माना जाना चाहिए। इस विचार का मुख्य आधार साख का मुद्रा की भाँति प्रयोग किया जाना है। आधुनिक समाज में

समस्त आर्थिक क्रियाये साख पर आधारित होती हैं। साख-पत्रों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है और विभिन्न प्रकार के साख-पत्र पूँजी की भाँति ही कार्य करते हैं। साख के प्रयोग से अधिक मात्रा में धन का उत्पादन करने में सहायता मिलती है इसलिए उसका उत्पादन व्यवस्था में पूँजी की भाँति ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब बातों के आधार पर ही साख को पूँजी माना गया है। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री श्री मैकलिओड (Macleod) इसी विचार के मानने वाले हैं। उनके अनुसार “मुद्रा व साख दोनों ही पूँजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूँजी है।”^६ किन्तु मैकलिओड का यह विचार बिल्कुल भ्रमात्मक है क्योंकि साख में पूँजी की विशेषताये नहीं पाई जाती हैं। साख केवल ऋणी को अन्य लोगों से पूँजी प्राप्त करने का अधिकार देती है, वह स्वयं पूँजी नहीं है।

पूँजी से हमारा अभिप्राय बचाये हुये धन के उस भाग से होता है जिसे और अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाय। इस दृष्टि से साख न तो पूँजी है और न वह पूँजी का निर्माण ही करती है। साख को उत्पत्ति का पृथक् साधन मानना भूल होगी। साख-पत्र केवल धन का हस्तान्तरण करने में सहायता देते हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की नई पूँजी का निर्माण नहीं होता है। साख के द्वारा समाज में धन तथा वस्तुयें उन लोगों में जो उनका उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों को हस्तांतरित हो जाती हैं जो उन्हें उचित प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार साख केवल धन को हस्तांतरित करने का साधन मात्र है। साख स्वयं उत्पत्ति में सहायक नहीं होती है बल्कि उसके बदले में प्राप्त होने वाले उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग में उत्पादन में वृद्धि होती है। साख स्वयं उपयोगी नहीं है बल्कि उसके बदले में उपयोगी वस्तुयें प्राप्त की जा सकती हैं।

इसके प्रतिरिक्त साख को उत्पत्ति का स्वतन्त्र साधन भी नहीं माना जा सकता है। साख उत्पत्ति का साधन नहीं है, वह केवल एक उत्पादन विधि है जिसके द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। जिस प्रकार हम श्रम विभाजन तथा विनिमय के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार साख भी एक उत्पादन विधि है जिससे उपयोगिता बढ़ती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साख न तो पूँजी है और न उसे उत्पत्ति का स्वतन्त्र साधन ही माना जा सकता है। प्रो० मिल ने इसी विचार का समर्थन किया है। उनके अनुसार, “ऋण देने से किसी प्रकार की नई पूँजी का निर्माण नहीं होता है। ऐसा करने से वह पूँजी जो पहले में ऋणदाता के पास थी, ऋणी को हस्तांतरित हो जाती है। साख तो केवल किसी दूसरे व्यक्ति की पूँजी का प्रयोग करने की आज्ञा है। उससे उत्पत्ति के साधनों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है वरन्

6 “Money and credit are both capital. Mercantile credit is Mercantile Capital.”

—Macleod: Elements of Banking, Chap. IV.

उनका केवल हस्तांतरण ही हो सकता है।”⁷ रिवाडों भी इसी मत से सहमत हैं और उनके अनुसार, “साख पूँजी का निर्माण नहीं करती है। वह केवल यह निश्चय करती है कि पूँजी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाना चाहिए।”⁸ अतः यह कहा जा सकता है कि साख पूँजी नहीं है और उसे उत्पत्ति का पृथक् साधन भी नहीं माना जा सकता है।

साख और कीमत-स्तर (Credit and Prices)—

साख का कीमतों में ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। कुछ लेखकों का विचार है कि साख का कीमत-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह नकदी का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन नहीं करती है। अमेरिकन अर्थशास्त्री वॉकर (Walker) तथा लैंगलिन (Langhlin) का यही मत है। उनके अनुसार साख कीमतों को प्रभावित नहीं करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि साख के द्वारा ऋणों का अन्तिम भुगतान नहीं किया जा सकता है। साख में क्रय-शक्ति तो होती है किन्तु उसमें निस्तारण शक्ति (Liquidating Power) नहीं होती है। सभी प्रकार के सौदों का तथा ऋणों का भुगतान अन्तिम रूप से नकद मुद्रा के द्वारा करना पड़ता है। इसलिए साख का कीमत-स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त साख मुद्रा के द्वारा किये जाने वाले क्रय-विक्रय में एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ सन्तुलित हो जाती है जिसके कारण साख कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाती है।

इसके विपरीत प्रो० मिल (Mill) का विचार है कि साख के विस्तार तथा सकुचन का वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर ठीक वही प्रभाव पड़ता है जो मुद्रा के विस्तार तथा सकुचन का होता है क्योंकि मुद्रा की भाँति साख में भी क्रय-शक्ति होती है और उसके द्वारा भी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। जब साख की मात्रा बढ़ती है तो लोगों के पास अधिक क्रय-शक्ति आ जाती है और वे वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक मांग करते हैं जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत साख का सकुचन होने से लोगों के पास क्रय-शक्ति कम हो जाती है, वे वस्तुओं की कम मांग करने हैं और कीमतें गिर जाती हैं। अतः साख मुद्रा के विस्तार तथा सकुचन का भी कीमतों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस विचार की सत्यता इस बात से विदित होती है कि केन्द्रीय बैंक अपनी साख नियन्त्रण की

7 “New capital is not created by the mere fact of lending, only the capital that was in the hands of the lender is now transferred to the hands of the borrower, credit being only the permission to use the capital of another person. The means of production cannot be increased by it but only be transferred”
—J M Mill: Principles of Political Economy.

8 “Credit does not create capital, it only determines by whom that capital should be employed”

—Ricardo: Principles of Political Economy and Taxation.

नीति के द्वारा कीमत-स्तर पर काफी प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि अधिकांश साख उत्पादन-कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है किन्तु उत्पादन बढ़ने में कुछ समय अवश्य लगता है और इस काल में साख क्रय-शक्ति में वृद्धि करके कीमतों को बढ़ा सकती है।

उपयुक्त दोनों विचारों में से किसी को भी पूर्णतया ठीक नहीं माना जा सकता है। वास्तविकता इन दोनों विचारों के बीच में है। इस सम्बन्ध में लार्ड केन्स (Keynes) का मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उनके अनुसार साख सामान्य कीमत-स्तर पर प्रभाव तो डालती है किन्तु उतना नहीं जितना कि नकद मुद्रा का होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि साख-पत्रों में सर्वमान्यता का वह गुण नहीं पाया जाता है जो नकद में है। अतः इन सभी साख-पत्रों का भुगतान नकदी में करना होता है। बैंकों को इस प्रकार के भुगतान निपटाने के लिए अपने पास नकद कोष रखने पड़ते हैं। बैंक जितना नकद कोष रखते हैं चलन में मुद्रा की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है। इस प्रकार साख मुद्रा का विस्तार होने पर दो प्रतिविरोधी शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं। साख-पत्रों की मात्रा में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं किन्तु वे उतना नहीं बढ़ती हैं जितना कि साख मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया गया है क्योंकि साख का निर्माण करते समय बैंकों को नकद कोष रखने होते हैं। बैंकों के द्वारा नकद कोष रखने का प्रभाव कीमतों को कम करने का होता है। ऐसी दशा में कीमतें बढ़ती तो हैं किन्तु वे उतना नहीं बढ़ती जितना कि साख बढ़ती है। यदि साख नकद मुद्रा का पूर्ण प्रतिस्थापन कर सकती तो कीमतों के ऊपर साख का वही प्रभाव पड़ना जो मुद्रा का होता है किन्तु मुद्रा का सही प्रतिस्थापन न कर सकने के कारण साख का कीमतों के ऊपर प्रभाव पड़ता तो है किन्तु उतना नहीं जितना कि नकद मुद्रा का पड़ता है।

साख-पत्र (Credit Instruments)—

साख-पत्रों से अभिप्राय उन सब प्रतिज्ञा-पत्रों से होता है जिनका प्रयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। इन साख-पत्रों में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार के द्वारा यह प्रतिज्ञा की जाती है कि उनमें लिखित रकम का भुगतान एक निश्चित समय के पश्चात् उस व्यक्ति-विशेष को कर दिया जायेगा जिसके पक्ष में वे लिखे गये हैं। आज के व्यावसायिक समाज में साख-पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाया जाता है तथा उनके आधार पर ही ऋणों का आदान-प्रदान किया जाता है। साख-पत्रों के द्वारा उत्पादकों तथा व्यापारियों को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वे हमारे व्यावसायिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने में बड़ी सहायता देते हैं। यद्यपि साख-पत्र विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं और उनके बढ़ने में वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है किन्तु फिर भी उन्हें मुद्रा

में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें विविधता प्राप्त नहीं होती है। समाज में भुगतानों को निबटाने तथा ऋणों का आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note) बैंक, ट्रेडर, विदेशी विनिमय-पत्र तथा ट्राफ्ट प्रमुख है—

(१) प्रतिज्ञा-पत्र अथवा खसका (Promissory Note)—प्रतिज्ञा-पत्र सबसे साधारण प्रकार का साधन-पत्र होता है। इसके लिखने वाला यह प्रतिज्ञा करता है कि वह एक निश्चित समय के पश्चात् उसमें लिखित रकम का भुगतान उसमें दिए गये व्यक्ति अथवा उसकी आज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहक (Bearer) को कर देगा। प्रत्येक प्रतिज्ञा-पत्र के सम्बन्ध में दो पक्ष होते हैं—एक प्रतिज्ञा-पत्र को लिखने वाला तथा दूसरा वह जिसके पक्ष में वह लिखा गया है। पहला पक्ष उसमें लिखित रकम का दूसरे पक्ष को भुगतान करने का वायदा करता है। यह प्रतिज्ञा-पत्र तीन प्रकार का हो सक्ता है—(i) व्यापारिक प्रतिज्ञा-पत्र (Commercial Promissory Notes)—इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रों का प्रयोग व्यावसायिक भुगतानों को निबटाने तथा व्यापारिक ऋणों का निस्तारण (Liquidate) करने के लिए किया जाता है। ऋणी इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र को लिखकर अपने ऋणदाता को देता है जिसमें भविष्य में भुगतान निबटाने का वायदा किया जाता है। व्यापारिक प्रतिज्ञा-पत्र मदैव ही एक निश्चित अवधि के लिए लिखे जाते हैं। (ii) बैंक प्रतिज्ञा-पत्र (Bank Promissory Note)—इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र केवल केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और उनका भुगतान तुरन्त ही माग करने पर कर दिया जाता है। केन्द्रीय बैंक के द्वारा जारी किये जाने वाले नोट इसी प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र होते हैं। (iii) चलन प्रतिज्ञा-पत्र (Currency Promissory Note)—इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र मुद्रा संचालक के द्वारा जारी किये जाते हैं और बैंक प्रतिज्ञा-पत्र की भाँति ही होते हैं। इनका भुगतान भी तुरन्त माग करने पर कर दिया जाता है। भारतवर्ष में एक रुपये के नोट इसी के प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रों का उदाहरण है।

(२) विनिमय-पत्र (Bill of Exchange)—यह भी एक प्रकार का साधन-पत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें लिखित रकम चुकाने का आदेश देता है। “विनिमय बिल एक लिखित-पत्र होता है जिसके लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बिना किसी शर्त के उसमें बताये गये व्यक्ति या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति या उसके वाहक को माग करने पर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात्, उसमें लिखित रकम का भुगतान कर दे।” विनिमय-पत्रों का प्रयोग आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निबटाने के लिए किया जाता है। विनिमय-पत्र के सम्बन्ध में तीन पक्ष होते हैं—(i) बिल को लिखने वाला (Drawer), (ii) बिल जिस के ऊपर लिखा जाता है (Drawee) तथा

(iii) बिल का भुगतान प्राप्त करने वाला (Payee) । प्रयोग के अनुसार विनिमय बिल दो प्रकार के हो सकते हैं—

(१) आन्तरिक विनिमय-पत्र (Inland Bills of Exchange)—यह वे विनिमय-पत्र होते हैं जिनका प्रयोग आन्तरिक व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निबटाने के लिए किया जाता है ।

(२) विदेशी विनिमय-पत्र (Foreign Bills of Exchange)—इस प्रकार के विनिमय-पत्रों का प्रयोग विदेशी व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निबटाने के लिए किया जाता है ।

(३) हुण्डी (Hundi)—हुण्डी एक प्रकार का आन्तरिक विनिमय-पत्र होता है जिसका प्रयोग देशी व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निबटाने के लिए किया जाता है । हुण्डियों का प्रयोग भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल में होता आया है । यह स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती है और इनकी स्वीकृति केवल रीति-रिवाज पर आधारित होती है । यद्यपि हुण्डियों पर भी विनिमय-पत्रों की भाँति टिकट लगाया जाता है किन्तु इन्हें कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है । हुण्डियाँ प्रायः देशी बैंकर तथा व्यापारियों द्वारा लिखी जाती हैं और इनके प्रयोग से आन्तरिक व्यापार को चलाने में बड़ी सहायता मिलती है । हुण्डियाँ कई प्रकार की होती हैं किन्तु उनमें से दो प्रकार की हुण्डियाँ अधिक प्रचलित हैं—(i) दर्शनी हुण्डी—वह हुण्डी जिसका भुगतान माग करने पर तुरन्त किया जाता है दर्शनी हुण्डी कहलाती है । (ii) मुहती हुण्डी—इस प्रकार की हुण्डी का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात् किया जाता है । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की हुण्डियाँ भी होती हैं जैसे (iii) धनी जोग हुण्डी—जिसका भुगतान उस व्यक्ति को होना है जिसका नाम हुण्डी में लिखा है, (iv) देखनहार हुण्डी—जिसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है । (v) शाहजोग हुण्डी—जिसका भुगतान किसी भादरणीय व्यापारी को ही हो सकता है । (vi) नाम जोग हुण्डी—जिसका भुगतान पाने वाले के आदेशानुसार किया जाता है । इन हुण्डियों का उद्देश्य माल जरीदने वाले को कुछ समय के लिए ऋण देना होता है ।

(४) चैक (Cheque)—आज के युग का सबसे अधिक प्रचलित साख-पत्र चैक है । चैक का प्रयोग विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाने तथा बैंक में एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में रुपये का हस्तान्तरण करने के लिए किया जाता है । चैक बैंक में रुपया जमा करने वाले का अपने बैंक के नाम एक लिखित आदेश होता है जिसके अनुसार बैंक उसके खाते में से रुपया निकालकर आदेश-प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहक को चैक पर अंकित रकम का भुगतान करता है । चैक सदैव बैंक के ऊपर लिखे जाते हैं और बैंक को उनका भुगतान माग करने पर तुरन्त करना पड़ता है । चैक के सम्बन्ध

में तीन पक्ष होते हैं—(i) बैंक के लिखने वाला (Drawer), (ii) जिसके ऊपर बैंक लिखा जाता है—बैंक (Drawee) तथा (iii) बैंक का भुगतान लेने वाला (Payee) ।

बैंक (Cheque) कई प्रकार के हो सकते हैं—(i) वाहक बैंक (Bearer Cheque)—यह सबसे साधारण प्रकार का बैंक होता है। इस प्रकार के बैंक का भुगतान आदेश प्राप्त व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जो उसे बैंक में प्रस्तुत करता है। वाहक बैंक का भुगतान लेने के लिए आदेश प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षरों का होना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार के बैंक पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय (Transferable) होते हैं। भुगतान पाने की सुविधा की दृष्टि से यह बैंक बहुत अच्छे होते हैं किन्तु इनमें सुरक्षा का अभाव रहता है। (ii) आदेश बैंक (Order Cheque)—इस प्रकार के बैंक का भुगतान केवल आदेश प्राप्त व्यक्ति को ही किया जा सकता है। बैंक का भुगतान लेते समय बैंक पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षरों का होना आवश्यक है जिसके पक्ष में बैंक लिखा गया है। आदेश बैंक का भुगतान करते समय बैंक इस बात की जाँच करता है कि बैंक का भुगतान ठीक व्यक्ति को ही किया जा रहा है। इस प्रकार के बैंक का भुगतान उस व्यक्ति को भी किया जा सकता है जिसने लिए बैंक के पीछे आदेश दिया गया हो। सुरक्षा की दृष्टि से आदेश बैंक बहुत अच्छे होते हैं। (iii) रेखांकित बैंक (Crossed Cheque)—यदि किसी बैंक के बाईं ओर ऊपरी हिस्से में दो आड़ी रेखाएँ खींच कर उनके बीच में & Co. शब्द लिख दिये जायें तो उसे रेखांकित बैंक कहते हैं। रेखांकित बैंक (Crossed Cheque) का भुगतान बैंक के काउण्टर (Counter) पर नकद रूप में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का बैंक केवल उस व्यक्ति अथवा मर्यादा के हिमाय में जमा किया जा सकता है जिसके पक्ष में वह लिखा गया। रेखांकित बैंक सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं और उनके द्वारा गलत भुगतान होने की सम्भावना बिल्कुल कम हो जाती है। रेखांकित बैंक भी कई प्रकार के होते हैं—(a) साधारण रेखांकित बैंक (General Crossed Cheque)—इस प्रकार के बैंक पर केवल दो आड़ी रेखाएँ खींच दी जाती हैं अथवा उनके बीच में & Co. या Not Negotiable शब्द लिख दिये जाते हैं। इस प्रकार के बैंक का भुगतान किसी भी बैंक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। (b) विशेष रेखांकित बैंक (Special Crossed Cheque) — इस प्रकार के बैंक का भुगतान केवल उन्हीं बैंक को किया जा सकता है जिसका नाम बैंक को रेखांकित (Cross) करते समय दोनों रेखाओं के बीच में लिख दिया गया है। विशेष रेखांकित बैंक का भुगतान लेने के लिए भुगतान लेने वाले का हिमाय उन्हीं बैंक में होना आवश्यक है जिसका नाम रेखाओं के बीच में लिखा है। इस प्रकार के बैंक और अधिक सुरक्षित होते हैं।

(५) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)—ड्राफ्ट एक प्रकार के विनिमय बिल होते हैं जो बैंक के द्वारा अपनी अन्य शाखाओं पर लिखे जाते हैं। ड्राफ्ट के द्वारा एक बैंक अपनी किसी अन्य शाखा को यह आदेश देता है कि ड्राफ्ट की रकम उस पर लिखे हुए व्यक्ति को दे दी जाये। ड्राफ्ट का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को रकम भेजने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने रुपये को किसी दूसरे स्थान पर भेजना चाहता है तो वह उस रुपये को बैंक की स्थानीय शाखा में जमा कर देता है। बैंक अपना कमीशन लेकर उस रकम के बदले में एक ड्राफ्ट अपनी उस शहर की शाखा के नाम लिख देता है। जब यह ड्राफ्ट बैंक की उस जगह में प्रस्तुत किया जाता है तो ड्राफ्ट के रुपये का भुगतान उस पर लिखित व्यक्ति अथवा संस्था को कर दिया जाता है। ड्राफ्ट के द्वारा रुपया भेजना अधिक सुरक्षित होता है तथा उस पर व्यय भी कम आता है।

(६) साख प्रमाण-पत्र (Letter of Credit)—साख प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक के द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का साख-पत्र होता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वह उसमें लिखित व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के भीतर एक निश्चित सीमा तक किसी भी मात्रा में साख-प्रदान कर दे। इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों का विदेशी व्यापार में बड़ा महत्व है। बैंकों के द्वारा लिखित साख प्रमाण-पत्रों के आधार पर एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से साख प्राप्त कर लेते हैं। साख प्रमाण-पत्र दो प्रकार के हो सकते हैं—(i) साधारण साख प्रमाण-पत्र जो किसी एक व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक के नाम लिखे जाते हैं। (ii) चलायमान साख प्रमाण-पत्र (Circular Letter of Credit) जारी करने वाले बैंक की शाखाओं, अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धी बैंकों को एक ही साथ लिखा जाता है। इन साख-पत्रों के आधार पर साख नकद रूप में अथवा विनिमय-पत्रों के रूप में प्राप्त की जा सकती है, वह बैंक की किसी भी शाखा, एजेंट अथवा सम्बन्धी बैंक से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त पत्रों की मात्रा साख-पत्र के पीछे अंकित कर दी जाती है। कुल प्राप्त साख उस सीमा के भीतर होनी चाहिए जो साख-पत्र में लिखी है।

(७) यात्री चेक (Traveller's Cheque)—इस प्रकार के चेक बैंकों के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जारी किये जाते हैं। विदेशी यात्रियों के लिए यह बैंक विशेषतः उपयोगी होते हैं। इन चेक करने प्रस्तुत करने पर जारी जारी करने वाले बैंक की किसी भी शाखा से चेक पर अंकित रकम प्राप्त कर सकता है। चेक जारी करते समय बैंक चेक के एक विशेष स्थान पर यात्री के हस्ताक्षर ले लेता है जो भुगतान करने वाले बैंक के लिए नमूने (Specimen) का काम करते हैं। भुगतान के समय बैंक यात्री के हस्ताक्षर चेक पर करता है और उन्हें पहले किये गये हस्ताक्षरों से मिला लेता है। इस प्रकार के चेक के खो जाने पर नुकसान हो जाने की सम्भावना बहुत कम रहती है क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इसका

भुगतान नहीं ले सकता है। जारी करने वाले बैंक की जितनी अधिक शाखाएँ होती हैं उतनी ही यात्रियों को अधिक सुविधा रहती है।

(८) कोषागार विपन्न (Treasury Bills)—कोषागार विपन्न सरकार के द्वारा अल्पकालीन साख प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किये जाते हैं। सरकार को प्रायः एक निश्चित समय पर आय प्राप्त होनी है किन्तु व्यय को उस समय तक के लिए नहीं रोका जा सकता है। अतः सरकार को व्यय करने के लिए आय प्राप्त होने से पूर्व ही धन की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा कोषागार विपन्न जारी किये जाते हैं। इनकी अवधि तीन, छ, नौ महीने बारह महीने की होती है। इस अवधि के उपरान्त इनका भुगतान सरकार से प्राप्त किया जा सकता है। कोषागार विपन्नो को जारी करने के हेतु सरकार टेंडर (Tenders) मांगती है। टेंडर देने वाले को उस व्याज का धोरा देना होता है जिस पर वह ऋण देने को तैयार है। सबसे कम व्याज वाले टेंडर को स्वीकार कर लिया जाता है। कोषागार विपन्नो पर ऋण व्याज की रकम काट कर लिया जाता है और भुगतान के समय विपन्नो पर अंकित पूरी रकम सौदा दी जाती है।

उपयुक्त साख-पत्रों के अतिरिक्त कुछ दीर्घकालीन साख-पत्र भी होते हैं जिनका प्रयोग लम्बे समय के लिए ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के साख-पत्रों में मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा जारी किये जाने वाले बाँड तथा ऋण-पत्र (Bonds and Debentures), सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) और कम्पनियों के अंश (Shares) आ जाते हैं।

साख की उपयोगिता तथा उसके कार्य

(Functions and Uses of Credit)—

वर्तमान समाज में साख एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाज का औद्योगिक तथा व्यवसायिक संगठन एक प्रकार से साख पर आधारित है। इसी कारण साख को व्यापार का जीवन-रक्त (Life blood) कहा जाता है। भाजकल सभी प्रकार के बड़े-बड़े आर्थिक भुगतान नकद मुद्रा में न होकर विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों के द्वारा किये जाते हैं। साख का प्रयोग आर्थिक जीवन के लिए बहुत बड़ी देन है। साख समाज में बहुत से उपयोगी कार्य करती है तथा आर्थिक समृद्धि के लिए उपयुक्त दशाये उत्पन्न करती है। डेनियल वेबस्टर (Daniel Webster) ने वर्तमान समाज में साख के महत्व को बतलाते हुए लिखा है—“साख ने राष्ट्रीय को धनी बनाने में ससार की समस्त खानों (Mines) से कई हजार गुणा अधिक काम किया है। साख ने श्रम को प्रोत्साहित किया है, उद्योगों को बढ़ावा दिया है, व्यापार को विदेशों में फैलाया है तथा ससार के प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक जाति

को एक दूसरे के समीप लाकर सच्चे आर्थिक सहयोग की भावना उत्पन्न की है।”^९ स्पष्ट है कि साख के प्रयोग से समाज को अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं जिनके कारण साख वर्तमान समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। साख के प्रयोग से प्राप्त होने वाले कुछ आर्थिक लाभ इस प्रकार हैं—

(१) साख नकद मुद्रा के प्रयोग में बचत करती है—साख का प्रयोग नकद मुद्रा के स्थान पर किया जाता है जिसके कारण नकद मुद्रा के प्रयोग में काफी बचत हो जाती है। आजकल हम बहुत से भुगतानों को साख-पत्रों के द्वारा निबटा लेते हैं जिनके लिए पहले धारित्रिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती थी। इस प्रकार साख-पत्रों के द्वारा धातु मुद्रा की बचत होती है और समाज में विनिमय के माध्यम की मात्रा बढ़ जाती है। विनिमय के माध्यम की मात्रा अधिक होने से व्यापार तथा व्यवसाय में सुविधा होती है।

(२) साख पूँजी को उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है—साख के प्रयोग के द्वारा पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है और बेकार पड़ी हुई पूँजी बैंकों के द्वारा उन लोगों तक पहुँच जाती है जो उसे उत्पादन कार्य में लगा सकते हैं। समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके पास रुपया होता है किन्तु वे उसका विनियोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी पूँजी समाज के लिए बेकार रहती है। साख-व्यवस्था के द्वारा इस प्रकार की पूँजी को कार्यशील किया जा सकता है जिससे समाज के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

(३) साख-पत्रों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को आसानी से निबटाया जा सकता है—मुख्यता विदेशी विनिमय पत्रों (Foreign Bills of Exchange) का प्रयोग विदेशी भुगतानों को निबटाने में बड़ी सहायता करता है। इनके द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे बिना ही विदेशी भुगतानों को निबटाया जा सकता है। इस प्रकार साख का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के चलाने तथा उसके विस्तार में बड़ी सहायता देता है।

(४) साख-पत्रों के द्वारा बड़े-बड़े भुगतानों की सुविधापूर्वक निबटाया जा सकता है—बड़ी रकम के भुगतानों को नकद मुद्रा के द्वारा निबटाने में बड़ी कठिनाई होती थी किन्तु आजकल बड़े से बड़े भुगतानों को भी चैक (Cheque) ड्राफ्ट (Draft), हण्डी तथा अन्य प्रकार के साख-पत्रों के द्वारा आसानी से निबटाया जा सकता है।

9 “Credit has done more—a thousand times more—to enrich nations than all the mines of the world. It has excited labour, stimulated manufacturers, pushed commerce to every sea and brought every nation every kingdom, and every small tribe among the races of man to be known to all the rest.”

—Daniel Webster Quoted by M. C. Vaish in *Mudra Ka Rup Rakhna*.

(५) मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को सुविधापूर्वक तथा कम व्यय पर भेजा जा सकता है—साख-पत्रों के प्रचलन से पूर्व मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में बड़ी असुविधा होती थी तथा बहुत अधिक व्यय करना पड़ता था। किन्तु अब यह काम साख-पत्रों की सहायता से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ऐसा करने से व्यय भी कम आता है और रुपये भेजने में सुरक्षा भी अधिक रहती है।

(६) साख के द्वारा बैंक छोटे से नगद कोष के आधार पर बहुत बड़ी रकम उधार दे सकता है—बैंकों के द्वारा निर्माण की जाने वाली साख वर्तमान उद्योगों तथा व्यवसाय को जीवन प्रदान करती है तथा बैंकों को अधिक लाभ पैदा करने का अवसर देती है। बैंकों के द्वारा साख का निर्माण करने से मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण पैदा होता है क्योंकि साख की मात्रा की आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

(७) साख का प्रयोग मूल्य-स्तर को स्थायी रखने में सहायता देता है—जब समाज में व्यापारिक क्रियायें अधिक होती हैं और मुद्रा की माग बढ़ती है तो इस बड़ी हुई माग को साख का विस्तार करके पूरा किया जाता है। इसके विपरीत मुद्रा की माग के कम हो जाने पर साख की मात्रा को घटा दिया जाता है। इस प्रकार साख की मात्रा में परिवर्तन करके मुद्रा की माग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य-स्तर स्थिर बना रहता है।

(८) साख बचत को प्रोत्साहन देती है—बैंक तथा अन्य प्रकार की साख संस्थायें छोटी-छोटी बचतों को जमा करके समाज में पूँजी के संचय को प्रोत्साहन देती हैं। ब्याज के लालच से लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति पैदा होती है जिससे देश में पूँजी की मात्रा बढ़ती है और आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

(९) साख की सहायता से आर्थिक संकटों का सामना किया जा सकता है—साख ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा सरकारें आर्थिक संकटों का सामना करती हैं। जब सरकार को अधिक धन की आवश्यकता होती है तो वह सार्वजनिक ऋण लेकर अथवा नई पत्र मुद्रा जारी करके अपनी आवश्यकता को पूरा करती है। यह सब कुछ सरकार की साख के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को संकट काल में अधिक धन की आवश्यकता होती है तो वह भी साख का सहारा लेता है।

साख की हानियाँ (Evils of Credit)—

यद्यपि साख समाज के लिए बहुत उपयोगी तथा आवश्यक साधन है किन्तु उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। साख एक बहुत ही कोमल तथा खतरनाक यन्त्र है जिसका प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साख के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली हानियाँ अप्रलिखित हैं—

(१) साख को अत्यधिक निकासी (Over-issue of Credit)—साख का सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक निकासी के कारण पैदा होता है। यदि सरकार मुद्रा-प्रसार की नीति को अपनाती है और बैंको के द्वारा भी अत्यधिक साख का निर्माण किया जाता है तो ऐसी दशा में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और आर्थिक जीवन में एक प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। साख विस्तार से उत्पन्न होने वाला मुद्रा-प्रसार आर्थिक विकास के रास्ते में रुकावट पैदा करता है।

(२) साख के कारण समाज में अपव्यय की प्रवृत्ति पैदा होती है—उधार ली गई रकम को लोग सावधानी के साथ व्यय नहीं करते हैं और उसमें काफी फिजूलखर्ची होती है। यदि लोगों को आसानी से ऋण मिल जाते हैं तो वे उनका अपव्यय करने की प्रवृत्ति रखते हैं। व्यवसायी ऋणों के आधार पर अधिक जोखिम तथा अनिश्चित भविष्य वाले व्यवसाय खोल देते हैं, जो कुछ समय चलने के बाद बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार के घस्यायी उद्योगों के कारण समाज की भी हानि होती है और व्यवसायी भी बर्बाद हो जाते हैं। साख सरकारी खर्चों में भी अपव्यय को जन्म देती है।

(३) साख पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है तथा धन के वितरण को असमान करती है—साख तथा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का विकास साथ-साथ ही हुआ है। साख एक प्रकार से पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का आधार है। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में सारा धन तथा आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठी हो जाती है। साख पर आधारित अर्थ-व्यवस्था में पूँजी कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाने से देश में एकाधिकारी संस्थाओं का निर्माण होने लगता है। एकाधिकार की यह प्रवृत्ति समाज के आर्थिक हितों के विरोध में कार्य करती है।

(४) साख समाज में सट्टे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है—साख का अधिक प्रयोग होने से लोगों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ती है। आसानी से प्राप्त किये गये ऋणों के द्वारा लोग भविष्य सम्बन्धी अधिक सौदे करते हैं, जिसके कारण वस्तुओं के कीमतों में अधिक परिवर्तन होते हैं।

(५) अत्यधिक उत्पादन का भय उत्पन्न हो जाता है—साख का अधिक विस्तार होने के कारण व्यवसायिक-वर्ग को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाते हैं। वे अधिक मात्रा में विनिर्गम करते हैं जिसके कारण उत्पादन तेजी के साथ होने लगता है और अत्यधिक उत्पादन की समस्या पैदा हो जाती है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) साख का अर्थ समझाइये तथा वर्तमान व्यापार में उसके महत्व को बतसाइये ।
(भागरा बी० काम १६५८)
- (२) साख क्या है और व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं ?
(राजस्थान बी० ए० १६५४)
- (३) विनिमय पत्रों (Bills of Exchange) पर एक टिप्पणी लिखिये ।
(राजस्थान बी० ए० १६५५)
- (४) क्या साख पूंजी का सृजन करती है ? परीक्षा कीजिए ।
(राजस्थान बी० काम १६५५)
- (५) [अ] एक अर्द्ध-विकसित समाज में चंकों का प्रयोग किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जा सकता है ?
[ब] आप यह कैसे मातुम करेंगे कि चंकों पर बेचान नियमित है ?
(इत्ताहाबाद बी० काम १६५७)



बैंकों के कार्य तथा व्यवस्था

FUNCTIONS & ORGANISATION OF BANKS

बैंक की परिभाषा (Definition of Bank)—

बैंक साख का व्यापारी होता है। जमा प्राप्त करना तथा ऋण देना उसके दो प्रमुख कार्य हैं। बैंक उन लोगों की जमा इकट्ठी करता है जिनके पास अतिरिक्त रुपया होता है तथा उन्हें ऋण देता है जिन्हें रुपये की आवश्यकता होती है। बैंक केवल उधार देने के लिए ही जमा प्राप्त करता है। बैंक की परिभाषा करना काफी कठिन है। यही कारण है कि बैंक की अधिकांश परिभाषाओं में उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। जैसे "बैंक वह संस्था है जहाँ मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त की जाती है, जिसे वापस लौटाना होता है, जहाँ पर ऋण दिये जाते हैं, बिल (Bills) भुनाये जाते हैं तथा अन्य प्रकार के वित्तीय सौदे किये जाते हैं।" किन्तु बैंक के कार्यों के आधार पर उसकी परिभाषा करना अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि बैंकों के कार्य समय-समय पर बदलते रहते हैं।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा बैंक की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी गई हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—सेयर्स (Sayers) के अनुसार, "बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो।"¹ हार्ट (Hart) ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार की है—"बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रुपया जमा करता है, जिसे वह उन व्यक्तियों के बैंक स्वीकार करके भुगतान करता है जिन्होंने यह रुपया जमा किया है अथवा जिनके खातों में यह रुपया जमा किया गया है।"² इस परिभाषा में बैंक के जमा प्राप्त करने के कार्य पर अधिक जोर दिया गया है किन्तु उसके अन्य कार्यों के विषय

1 "A bank is an institution, whose debts are widely accepted in settlement of other peoples debts to each other."
—Sayers.

2 "A banker is one who, in the ordinary course of his business, receives money which he repays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it."
—Hart.

में कुछ नहीं कहा गया है। बैंक की एक अच्छी परिभाषा Kinley ने की है। उनके अनुसार—“बैंक वह संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रख कर लोगों को धन उधार देती है तथा जब लोगों को धन की आवश्यकता नहीं होती है तो वे अपने अतिरिक्त धन को उसके पास जमा कर देते हैं।”³ इस परिभाषा में बैंक के जमा प्राप्त करने तथा ऋण देने वाले दोनों ही कार्यों को महत्व दिया गया है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट सन् १९४२ में बैंक की परिभाषा इस प्रकार की गई है—“बैंकिंग का अभिप्राय जनता से उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो माग पर अथवा किसी अन्य प्रकार में बैंक, ड्राफ्ट तथा आदेश आदि के द्वारा शोधनीय होते हैं।”⁴ इस परिभाषा में भी बैंकों के जमा प्राप्त करने तथा माग किये जाने पर उसे लौटाने के कार्य को अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। वाल्टर लीफ (Walter Leaf) के अनुसार—“बैंक वह व्यक्ति या संस्था है जो हर समय जमा के रूप में मुद्रा को लेने के लिए तैयार रहती हो और जो उसे जमा करने वालों के बैंकों के द्वारा लौटाने के लिए तैयार रहती हो।”⁵ फिण्डले शिर्राज (Findlay Shirras) ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार की है—“एक बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी है जिसके पास कोई ऐसा व्यापार स्थान हो जहाँ पर मुद्रा अथवा खसल की जमा के द्वारा साख के खाते खोले जाते हो जिनमें जमा रकम को ड्राफ्ट धनादेश अथवा आदेश के द्वारा सुगतान किया जाता हो अथवा जहाँ स्टॉक, बान्ड, धातु तथा विपन्नो की भाड़ पर मुद्रा उधार दी जाती हो अथवा जहाँ प्रतिज्ञा-पत्र बट्टे पर अथवा बेचने हेतु लिए जाते हो।”⁶ फिण्डले शिर्राज ने अपनी परिभाषा में बैंक के साख सम्बन्धी कार्यों पर अधिक जोर दिया है। इसी प्रकार कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी बैंक को साख का व्यापार करने वाली संस्था माना है। क्रॉउथर (Crowther) के

3 “Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use.” —Kinley.

4 “Banking refers to the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise.”

—The Indian Banking Companies Act, 1949.

5 “A bank is that institution or individual who is always ready to receive money on deposits to be returned against the cheques of their depositors.” —Walter Leaf

6 “A banker is a person, firm or company, having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency subject to be paid or remitted upon draft, cheques, order or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and B/E and I/N are received for discount or sale.”

—Findlay Shirras

अनुसार—“बैंकर अपने और अन्य लोगों के ऋणों का व्यासबाही होता है।”⁷ हरिस ह्वाइट ने बैंक को साख का निर्माणकर्ता और विनिमय की मुविधा प्रदान करने वाला यन्त्र कहा है।

इन परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि अधिकांश लेखकों ने बैंक की परिभाषा के स्थान पर उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। इस प्रकार की परिभाषाओं में से किसी को भी बैंक की सर्वमान्य परिभाषा नहीं कहा जा सकता है किन्तु फिर भी वे हमें बैंकों की प्रकृति तथा उनके कार्यों को समझने में बड़ी सहायता देती है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बैंक उस व्यक्ति या मस्या को कहते हैं जो मुद्रा अथवा साख का व्यापार करती हो। इस प्रकार की सस्थायें लोगों से कम व्याज पर रुपया जमा कराती हैं और उस जमा को अधिक व्याज पर उधार देती हैं। दोनों का अन्तर इन बैंकों का लाभ होता है।

बैंकिंग का विकास (Evolution of Banking)—

बैंकिंग का कार्य बहुत प्राचीन समय से होता आया है। भारत, बेबिलोन, यूनान तथा रोम की प्राचीन सभ्यताओं के काल में भी बैंकिंग के विकास के प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि बब से लगभग २००० वर्ष पूर्व बैंकिंग का कार्य किया जाता था। बैंकिंग का प्रारम्भ किसी निश्चित काल में नहीं हुआ बल्कि मायिक उन्नति के साथ साथ बैंकों का विकास भी होता गया। प्रारम्भ काल में बैंकिंग का कार्य सर्राफों (Goldsmiths) के द्वारा किया जाता था। यूरोप में मुद्रा परिवर्तक (Money Changers) भी बैंकिंग का कार्य करते थे। उस समय में धात्विक मुद्रा का प्रयोग होने के कारण मुद्रा को सुरक्षित रखने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की बड़ी समस्या रहती थी। जिन लोगों के पास धातुरिक्त मुद्रा होती थी, वे उसे सुरक्षित रखने के लिए उन सर्राफों (Goldsmiths) के पास अपनी मुद्रा जमा कर देते थे जिनमें उनका विश्वास होता था।

कुछ समय पश्चात् इन सर्राफों ने यह अनुभव किया कि वे अपने पास जमा रकम को उधार देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि ऋणों का भुगतान उस मुद्रा की वापसी की माग से पूर्व हो जाये। जमा की हुई रकम के बदले में यह लोग जमा करने वालों को जमा की रसीद देते थे। यद्यपि इस प्रकार की जमा का भुगतान माग करने पर तुरन्त करना होता था किन्तु बहुत कम लोग इन जमा रसीदों के बदले में नकद मुद्रा की माग करते थे। इन सर्राफों में जनता का विश्वास होने के कारण उनके द्वारा दी गई जमा की रसीदें ही मुद्रा के स्थान पर ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग की जाने लगी। धीरे-धीरे यह प्रथा बढ़ने लगी और इन रसीदों का प्रयोग वर्तमान बैंक नोटों की भाँति किया जाने लगा। इन सर्राफों के पास जमा

7 “.....a banker is a dealer in debts—his own and other people.”

—Cromther. An Outline of Money.

रकम को बहुत कम निकाला जाता था और लोग अपना कार्य सर्राफों के द्वारा दी गई जमा रसीदों से ही कर लेते थे। इन सर्राफों ने अपने अनुभव के आधार पर यह जान लिया कि उनके पास जमा रकम का बहुत थोड़ा भाग ही लोग वापस मांगते हैं। अतः उन्होंने जमा रकम का अधिकांश भाग उधार देकर उससे आय प्राप्त करना आरम्भ कर दिया।

जैसे-जैसे ऋण देने का व्यवसाय अधिक लाभपूर्ण होता गया, वैसे ही बैंक बैंकर्स ने जमा रकम पर ब्याज देना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे बैंकिंग का कार्य करने वालों में प्रतियोगिता होती गई और वे जमा को आकर्षित करने के लिए उस पर ब्याज देने लगे। ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर से कुछ कम ब्याज यह लोग जमा रकम पर देते थे और दोनों का अन्तर उनका लाभ होता था। कुछ समय पश्चात् बैंकों में रुपया निवासने के लिए चेक (Cheque) प्रणाली का प्रयोग दिया जाने लगा और इस प्रकार आधुनिक बैंकों का विकास हुआ।

आर्थिक विकास के साथ-साथ बैंकों की व्यवस्था में भी परिवर्तन होता गया और उनके प्रकार तथा कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई। आरम्भ काल में व्यक्तिगत बैंकर होते थे और वे ही लोगों की रकम को जमा करने तथा ऋण देने का कार्य करते थे। उस समय व्यवसायिक संगठन प्रारम्भिक होने के कारण बैंकर का कार्य साधारण होना था और उसे कम पूँजी से चलाया जा सकता था। धीरे-धीरे आर्थिक विकास हो जाने से बैंकर्स के कार्यों का भी विस्तार हुआ। अब इन लोगों से व्यवसाय में लगाने के लिये अधिक मात्रा में ऋणों की मांग की जाने लगी जिससे एक व्यक्तिगत बैंकर के निजी साधनों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। अतः बैंकों की सामूहिक व्यवस्था का जन्म हुआ और कई लोगो ने मिलकर सामेदारी के आधार पर बैंकिंग का कार्य करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार के बैंकर्स के पास पूँजी अधिक मात्रा में रहती थी और वे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर सकते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् बड़े पैमाने पर उद्योगों का प्रारम्भ हो जाने से यह सामेदारी वाले बैंक भी नई औद्योगिक व व्यापारिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा न कर सके और उनके स्थान पर मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) का विकास हुआ, जो बैंकों का वर्तमान रूप है।

आधुनिक बैंक के कार्य

(Functions of a Modern Bank)

प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं। देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियन्त्रण में रहता है और वे बैंक मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की उत्पादन व्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। बैंकों के आर्थिक महत्व को समझने के लिए हमें उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अध्ययन करना चाहिए।

वर्तमान समाज में व्यापारिक बैंक ही अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रचलित है और उनके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्य वर्तमान बैंक के कार्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था में बैंको के महत्व को समझने के लिए हमें व्यापारिक बैंको (Commercial Banks) के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। यद्यपि व्यापारिक बैंक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं किन्तु समाज में अधिकांश प्रकार के बैंकिंग कार्य उनके द्वारा ही किये जाते हैं। अतः व्यापारिक बैंको के कार्यों के अध्ययन के द्वारा ही हम वर्तमान बैंक के कार्यों को समझ सकते हैं।

व्यापारिक बैंक (Commercial Bank)—

व्यापारिक बैंक व्यापारियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देते हैं। एक व्यापारिक बैंक अल्पकालीन साख का व्यापारी होता है। वह समाज में लोगों से अतिरिक्त जमा प्राप्त करता है और व्यापार की अस्थायी (Temporary) आवश्यकताओं के लिए ऋण देता है। वह बचत करने वालों तथा विनियोग करने वालों के बीच का मध्यवर्ती होता है और इन दोनों वर्गों के बीच सम्पर्क स्थापित करके समाज में महत्वपूर्ण कार्य करता है। व्यापारिक बैंक की मुख्य विशेषताये इस प्रकार हैं—(i) व्यापारिक बैंक अल्पकालीन साख का व्यापार करने वाली संस्था होती है। वह केवल व्यापारियों को ऋण देती है और उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देती है। (ii) व्यापारिक बैंक लाभ प्राप्त करने वाली संस्था होती है। इन बैंकों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। वे कम व्याज पर लोगों की जमा को इकट्ठा करते हैं और कुछ अधिक व्याज लेकर उसे ऋण पर देते हैं। इन दोनों के अन्तर के कारण इन्हें लाभ प्राप्त होता है। (iii) अधिकांश व्यापारिक बैंकों का निर्माण मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों (Joint Stock Companies) के आधार पर किया जाता है। बैंको की पूँजी हिस्से बेचकर तथा जमा प्राप्त करके इकट्ठा की जाती है। यद्यपि कुछ व्यक्तिगत बैंकर भी होते हैं किन्तु आधुनिक बैंक मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियाँ ही होती हैं।

व्यापारिक बैंक के कार्य (Functions of a Commercial Bank)—

आधुनिक समाज में व्यापारिक बैंक निम्नलिखित कार्य करता है—

(१) जमा प्राप्त करना (Receiving Deposits)—व्यापारिक बैंक का प्रथम कार्य जनता की बचत को इकट्ठा करना तथा उसे उन लोगों के लिए उपलब्ध करना है जो उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। यह कार्य आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा प्राप्त करके करता है। बैंको के द्वारा जमा प्राप्त किये जाने से जनता को बड़ा लाभ होता है। उनके द्वारा बचाई हुई रकम बैंको में सुरक्षित रहती है तथा उस पर उन्हें कुछ व्याज भी मिल जाता है जिससे लोगों में बचत करने की इच्छा

को प्रोत्साहन मिलता है। बैंक लोगो की छोटी-छोटी बचतों को भी जमा के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं और उनका विनियोग करने देश के आर्थिक विकास में सहायता देते हैं। समाज में अधिकांश व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ बचाते हैं किन्तु वे उस बचत को उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाते हैं। या तो यह बचत बहुत कम मात्रा में होती है और या इन लोगो में जोखिम उठाने तथा विनियोग करने की क्षमता नहीं होती है। यदि समाज में इस बचत को इकट्ठा करने वाली कोई संस्था न हो तो इसमें से अधिकांश बचत बेकार पड़ी रहेगी। बैंक इस बचत को इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो विनियोग करने की क्षमता रखते हैं किन्तु उनके पास काफी बचत नहीं होती है। बैंक पहले वर्ग (बचत करने वालों) में जमा प्राप्त करता है और दूसरे वर्ग (विनियोग करने वालों) को ऋण देता है।

बैंक अपने ग्राहको से तीन प्रकार के खातों में जमा प्राप्त करता है—

- (i) धातू जमा खाता (Current Deposit)
- (ii) बचत जमा खाता (Savings Deposit)
- (iii) निश्चित जमा खाता (Fixed Deposit)

यदि रकम चालू खाते में जमा की जाती है तो बैंक उस पर किसी प्रकार का व्याज नहीं देता है किन्तु यह जमा किसी भी समय बैंक के द्वारा निकाली जा सकती है। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा रखने वालों के ऊपर अपना रुपया निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है। वे जब चाहे अपनी जमा का कोई भाग अथवा नुल रकम बैंक से निकाल सकते हैं। प्रायः व्यापारी लोग अपनी जमा चालू खाते में रखते हैं क्योंकि उन्हें बार-बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है। बचत जमा खाते (Savings Deposit Account) का उद्देश्य छोटी बचत वालों को बैंकिंग की सुविधायें देना होता है। इस खाते में जमा रकम पर बैंक कुछ व्याज भी देता है किन्तु इस खाते में से रुपया निकालने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। सामान्यतः इस खाते में से ग्राहक सप्ताह में एक बार अथवा दो बार ही रुपया निकाल सकते हैं और एक निश्चित सीमा तक ही रुपया निकाला जा सकता है। निश्चित सीमा से अधिक रुपया निकालने के लिए बैंक मैनेजर को पहले से सूचित करना होता है। जो रकम निश्चित जमा खाते (Fixed Deposit Account) में जमा की जाती है उस पर बैंक अच्छा व्याज देता है किन्तु इस प्रकार की जमा को निश्चित अवधि समाप्त हो जाने पर ही बैंक से निकाला जा सकता है। जितने अधिक समय के लिए रुपया जमा किया जाता है उसनी ही अधिक व्याज की दर होती है। इस प्रकार के खाते में वे लोग रुपया जमा करते हैं जिन्हें काफी लम्बे समय तक अपनी जमा को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार बैंक विभिन्न प्रकार के खातों में जमा प्राप्त करके प्रत्येक प्रकार के ग्राहको के लिए जमा की सुविधायें प्रदान करता है।

(२) ऋण देना (Advancing Loans)—बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देना है। बैंक ऋण देने के लिए ही लोगों से जमा प्राप्त करते हैं। वे कम व्याज पर लोगों से जमा प्राप्त करते हैं और उसे अन्य व्यक्तियों को अधिक व्याज पर उधार देते हैं। इन दोनों का अन्तर बैंक का लाभ होता है। ऋण देकर बैंक केवल अपने लिए ही लाभ पैदा नहीं करता है बल्कि यह समाज के लिए भी बहुत उपयोगी सेवा प्रदान करता है। इन ऋणों के द्वारा व्यापार तथा उद्योगों की पूर्ण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ऋण देकर बैंक समाज की बचत को उत्पादक कार्यों में लगाने में बड़ी सहायता देता है।

प्रत्येक बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि यद्यपि उसके पास जमा रकम को किसी भी समय निकाला जा सकता है, किन्तु वास्तव में कुल जमा का थोड़ा सा भाग ही लोगों के द्वारा किसी निश्चित समय में निकाला जाता है। अनुभव से यह यह पता लगा लेता है कि उसे अपने ग्राहकों की वापसी (withdrawals) की मांग को पूरा करने के लिए कितनी नकद जमा अपने पास रखनी चाहिए। शेष जमा को बैंक उत्पादकों तथा व्यापारियों को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। अपनी जमा का कितना भाग बैंक सुरक्षित रूप से उधार दे सकते हैं, यह भिन्न-भिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न होता है किन्तु सामान्यतः बैंक अपनी जमा का २० प्रतिशत नकद रूप में रख कर शेष उधार दे देते हैं। जिन देशों में बैंकिंग का अधिक विकास हो चुका है (इंग्लैंड, अमेरिका आदि) वहाँ पर नकद कोष का यह अनुपात कम किया जा सकता है। बैंक अधिकृत रूप से रक्षित ऋण (Secured Loans) ही देते हैं और अरक्षित ऋण (Unsecured Loans) की मात्रा बहुत कम रहती है। बैंक अपने ग्राहकों को सोना तथा जेवर, कम्पनियों के हिस्से, सरकारी प्रतिभूतियों तथा बॉन्ड्स, तैयार माल एवं बनाई जा रही वस्तुओं के आधार पर ऋण देते हैं। कभी-कभी वे कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत जमानत (Personal Security) के आधार पर भी ऋण दे देते हैं। किन्तु इस प्रकार के ऋण बैंक बहुत कम देता है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को देता है जिनकी ऋणों का भुगतान करने की क्षमता में बैंक की पूरा विश्वास होता है। बैंकों के द्वारा ऋण देने का सबसे प्रचलित तरीका अपने ग्राहकों की हण्डियों तथा व्यापारिक बिलों को धुनाना है। इस प्रकार से व्यापारियों को लगभग ३ मास के लिए ऋण प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक विभिन्न प्रकार की जमानत लेकर पूर्व निर्दिष्ट बाल के लिए भी ऋण देते हैं। कुछ बैंकों में अपने ग्राहकों को नकद साख की सुविधायें (Cash Credit Facilities) देने का प्रवन्ध भी होता है। इस प्रकार की सुविधाओं के अन्तर्गत बैंक ऋणों की साख सीमा (Credit Limit) निर्दिष्ट कर देता है और ऋणी इस सीमा तक बैंक से अपनी आवश्यकतानुसार ऋण ले सकता है। नकद साख सुविधा का सबसे बड़ा

साभ यह है कि व्यापारी को उतनी ही रकम का ब्याज देना पड़ता है जितनी कि वह प्रयोग में लाता है।

(३) बैंक विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करते हैं (Provides a cheap medium of Exchange)—वर्तमान समाज में सस्ते तथा सुविधापूर्ण विनिमय के माध्यम को प्रदान करने का कार्य भी बैंको का रहा है। इसके प्रमुख उदाहरण बैंक तथा नोट हैं। वर्तमान नोटों का विकास वकी की जमा रसीदों से ही हुआ है जो धीरे-धीरे समाज में बैंक नोटों की भांति प्रचलित हो गईं। यद्यपि आज नोट जारी करने का कार्य केवल केन्द्रीय बैंक ही करता है किन्तु कुछ समय पूर्व प्रत्येक बैंक को अपने-अपने बैंक नोट जारी करने का अधिकार होता था। इस प्रकार वर्तमान बाणज के नोटों का विकास बैंकों के द्वारा ही किया गया है। इनसे भी अधिक प्रचलित विनिमय का माध्यम बैंक है। बैंक की सुविधायें हमें बैंकों के कारण ही मिलती हैं। बैंकों ने समाज में नस्ते विनिमय के माध्यम का विकास करके विनिमय के कार्य को बहुत सरल बना दिया है।

(४) मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधायें प्रदान करते हैं (Facilitate the transfer of money from one place to another)—बैंकों की विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएँ होती हैं जिनके द्वारा वे मुद्रा को देश के एक भाग में दूसरे भाग को भेजने की सुविधायें देते हैं। बैंकों के विकास से पूर्व मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में ध्यय भी अधिक आता था और सुरक्षा का अभाव भी रहता था। किन्तु अब ये असुविधायें बिल्कुल दूर हो गई हैं और हम बैंकों के द्वारा अपनी रकम को कम समय में सुरक्षित तरीके पर तथा मामूली व्यय करके ही भेज सकते हैं। बैंक प्रायः यह कार्य ड्राफ्ट (Draft) तथा एकाउन्ट ट्रान्सफर (Account Transfer) के द्वारा करते हैं।

(५) एजेंसी कार्य (Agency Services)—आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य भी करता है। एजेंसी कार्य बैंक प्रायः अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें देने के लिए करता है। यद्यपि इनमें से अधिकांश सेवाएँ निःशुल्क होती हैं किन्तु कुछ एक के लिए बैंक मामूली कमिशन लेता है। बैंक विभिन्न प्रकार के एजेंसी कार्य करते हैं किन्तु उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

(i) ग्राहकों के विभिन्न प्रकार के साख पत्रों का भुगतान एकत्रित करना—बैंक अपने ग्राहकों के बैंक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा-पत्रों आदि के भुगतान एकत्रित करता है। व्यापार आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों को ग्राहक समय-समय पर अपने बैंक के पास जमा के लिए भेजते रहते हैं। बैंक इन पत्रों का रकबा एकत्र करके इन ग्राहकों के हिसाब में जमा कर देता है। (ii) ग्राहकों को और से रुपये का भुगतान करना बैंक अपने ग्राहकों में आदेश मिलने पर उनकी ओर से ऋणों की किस्तें, ब्याज, चन्दे, आद-कर तथा बीमे की किस्तें आदि

क भुगतान भी करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक मामूली कमीशन भी लेते हैं। (iii) ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना—बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार लाभात, व्याज, किराये आदि को एकत्र करके उनके हिसाब में जमा करने का कार्य भी करते हैं। (iv) प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय—बैंक अपने ग्राहकों से आदेश मिलने पर उनके लिए प्रतिभूतियों तथा कम्पनी के हिस्से आदि को खरीदने एवं बेचने का कार्य भी करता है।

(६) अन्य उपयोगी सेवाएँ (Other Services)—उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों के लिए कुछ अन्य उपयोगी सेवाएँ भी प्रदान करता है। यह सेवाएँ ग्राहकों के लाभ तथा सुविधा के लिए की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सेवाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सुविधा—प्रायः सभी बैंकों के द्वारा लॉकर (Locker) की सुविधाएँ दी जाती हैं जिसके लिए बैंक वार्षिक किराया लेता है। इन लॉकरों (Lockers) में ग्राहक अपने जेवर, सोना, चाँदी, दस्तावेज तथा अन्य कीमती वस्तुएँ रख सकते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए बैंक जिम्मेदार होता है। बैंकों के इस कार्य से ग्राहकों को काफी सुविधा हो गई है क्योंकि वे अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बैंक के पास रखकर उनकी सुरक्षा का निश्चित प्रबन्ध कर सकते हैं।

(ii) साख प्रमाण-पत्र जारी करना—बैंक अपने ग्राहकों के लिए साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit) तथा यात्री चैक (Traveller's Cheque) जारी करता है। साख प्रमाण-पत्रों के आधार पर विदेशी व्यापार करने में बड़ी सुविधा होती है और उनके द्वारा ग्राहकों को अपरिचित व्यापारियों से भी उधार वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। यात्री चैकस विदेशों को जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनकी सहायता से वे विभिन्न देशों में विदेशी मुद्राएँ प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों की स्वीकार करना—विनिमय बिल पर बैंक के हस्ताक्षर होने से दूसरों के द्वारा उनके स्वीकार किये जाने की सम्भावना बढ़ जाती है और व्यापारियों को बैंक द्वारा स्वीकृत बिलों के आधार पर आसानी से उधार मिल जाता है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के विनिमय बिलों की स्वीकार करने का काम भी करता है।

(iv) रिक्वा-पत्रों (Wills) तथा ट्रस्ट (Trust) आदि का प्रबन्ध करना—बैंक अपने ग्राहकों के रिक्वा पत्रों को कार्य में लाने तथा उनके द्वारा निमित्त ट्रस्ट आदि का प्रबन्ध करने की सुविधाएँ प्रदान करता है।

(v) ग्राहकों को एक दूसरे की साख के विषय में जानकारी देना—बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति से परिचित होता है और इसलिए वह उनकी साख

धमता (Credit Worthiness) के विषय में सही और विश्वसनीय सूचना प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर व्यापारी बिना अधिक जोखिम के आपस में लन-देन कर सकते हैं।

(vi) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय—बैंक अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्राएं बेचने तथा उनमें विदेशी मुद्रायें खरीदने का कार्य भी करता है। विदेशी विनिमय नियंत्रण की दशा में केवल लाइसेंस प्राप्त बैंक ही इस कार्य को कर सकते हैं।

(vii) वित्तीय सलाहों पर सलाह देना—बैंक अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) का कार्य भी करता है। रुपये का विनिमय किस प्रकार किया जाय, बोन में उद्योगों को स्थापित करना लाभपूर्ण होगा तथा किस सम्पत्तियों के हिस्सों (Shares) में रुपया लगाया जाय इत्यादि के विषय में बैंक अपने ग्राहकों को सलाह देता है।

(viii) व्यापार सम्बन्धी सूचनाओं तथा आँकड़ों को इकट्ठा करना—कुछ बड़े-बड़े बैंक व्यापार तथा उद्योगों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं और इस प्रकार की सूचनाएँ पूछने पर अपने ग्राहकों को दे देते हैं अथवा उन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है। विकसित देशों के बड़े-बड़े बैंकों में इस प्रकार की सूचनाओं तथा आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए पृथक् विभाग होने हैं।

बैंक के द्वारा साख निर्माण

(Credit Creation by the Bank)

बैंक साख का निर्माण करते हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद रहा है। हार्टले विथर्स (Hartley Withers), केन्स (J. M. Keynes), सैयर्स (Sayers), हॉल (Halm) आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार बैंक साख का निर्माण करते हैं और साख की मात्रा में परिवर्तन करके वे हमारी आर्थिक क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। किन्तु प्रो० कैनन (Cannan) तथा डॉक्टर वॉल्टर लीफ (Dr. Walter Leaf) ने इस मत का विरोध किया है। उनके अनुसार बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं और वे अपनी नकद जमा में अधिक रकम उधार नहीं दे सकते हैं। इस मतभेद के होने हुए भी अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि बैंक केवल साख का क्रय-विक्रय ही नहीं करते हैं बल्कि वे उसका निर्माण भी करते हैं। बैंकों के द्वारा साख का क्रय-विक्रय एक भाषावर्ण बात है किन्तु उनका इसमें भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है। आधुनिक बैंक साख का निर्माण करके समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके द्वारा निर्मित साख हमारे औद्योगिक तथा व्यवसायिक जीवन को चलाने में बड़ी सहायता करती है।

बैंक साख का निर्माण दो प्रकार से कर सकते हैं—(अ) नोट जारी करके तथा (ब) व्यापारियों को ऋण देकर।

पहले सभी बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार होता था और वे सब नोट निर्गमन के द्वारा साख का निर्माण करते थे। किन्तु अब केवल केन्द्रीय बैंक ही नोट निर्गमन का कार्य करता है। अतः नोट जारी करके साख का निर्माण केवल केन्द्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। बैंक अनुभव के आधार पर यह जानता है कि सब नोट एक साथ नकदी में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे इसलिए जारी किये जाने वाले नोटों का थोड़ा-सा प्रतिगम ही धात्विक कोष से रक्षित होता है और शेष नोटों के पीछे केवल प्रतिभूतियाँ ही रहती हैं। किन्तु यह सब नोट मुद्रा की भाँति चलते हैं क्योंकि लोगों को केन्द्रीय बैंक में विश्वास होता है। नोटों का वह भाग जिसके पीछे धात्विक कोष नहीं होता है, केन्द्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रकार की साख है। अतः नोट निर्गमन के द्वारा बैंक साख का निर्माण करते हैं। क्योंकि नोट निर्गमन का कार्य केवल केन्द्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है और केन्द्रीय बैंक देश के हित में कार्य करने वाली संस्था होती है इसलिए नोट निर्गमन के द्वारा निर्मित साख के सम्बन्ध में कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

केवल नोट निर्गमन करने वाले बैंक ही साख का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी साख का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देकर उनके पक्ष में जमा का निर्माण किया करता है जिसके कारण समाज में साख मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। आधुनिक बैंक केवल साख के व्यापारी ही नहीं होते हैं अब वे साख के निर्माता भी हैं। सेयर्स (Sayers) के अनुसार "बैंक केवल एक द्रव्य जुटाने वाली संस्थाएँ नहीं हैं बल्कि वे द्रव्य के निर्माता भी हैं।"^८

व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के पक्ष में जमा का निर्माण करके साख का सृजन करते हैं। बैंकों में जमा दो प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रथम जब लोग बैंक में नकद मुद्रा लाते हैं और उसे अपने धाने में जमा करा देते हैं। द्वितीय जब बैंक ग्राहकों को ऋण देकर उनके खाते में ऋण की रकम जमा करते हैं। प्रो० सी० ए० फिलिप्स (C. A. Phillips) के अनुसार पहली प्रकार की जमा को प्रारम्भिक जमा (Primary Deposits) तथा दूसरी प्रकार की जमा को उत्पादित जमा (Derived Deposits) कहा जा सकता है। साख निर्माण की दृष्टि से इन दोनों प्रकार की जमा में भेद करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रारम्भिक जमा से अभिप्राय उन निक्षेपों से होता है जो ग्राहकों के द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा जमा करने के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें नकद निक्षेप (Cash Deposit) भी कहा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति बैंक के पास किसी खाते में रकम जमा करता है तो बैंक में प्रारम्भिक निक्षेप

8 "Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense, manufacturers of money."
—Sayers.

की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की जमा से साख का निर्माण नहीं होता है किन्तु वह साख निर्माण के आधार का कार्य अवश्य करती है। उत्पादित जमा (Derivative Deposits) से अभिप्राय उन निक्षेपो से होता है जो बैंक के द्वारा ऋण देने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देकर उनके पक्ष में जमा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जमा को उत्पादित जमा (Derivative Deposits) कहते हैं। इस प्रकार की जमा के द्वारा ही बैंक साख का निर्माण करते हैं। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार 'उत्पादित निक्षेपो (Derivative Deposits) का निर्माण ही साख का सृजन है।'⁹ जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह ऋण की रकम को उसके हिमाव में जमा कर देता है और उसे उस सीमा तक स्वयं निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस प्रकार बैंक में नई जमा उत्पन्न होती है जो बैंक के द्वारा निर्माण की जाने वाली साख है। वर्तमान बैंक की अधिकांश जमा इसी प्रकार ग्राहकों को ऋण देकर उत्पन्न होती है।

बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करता है

(How Credit is Created)—

अपने ग्राहकों को ऋण देकर तथा उनके पक्ष में जमा उत्पन्न करके बैंक साख का निर्माण करता है। बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के कारण ही नई साख का जन्म होता है। कोई बैंक जितनी अधिक मात्रा में ऋण देता है वह उतनी ही अधिक साख का निर्माण करता है। बैंक जब किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह उस ऋण का मुग्तान नकद रूप में न करके ऋणी के जमा खाते में उस रकम को जमा कर देता है जो उसे आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है। वास्तव में बैंक ऐसी वस्तु उधार देता है जो उसके पास नहीं होती है। ऐसा इसलिए सम्भव है क्योंकि बैंक में लोगों का बहुत अधिक विश्वास होता है। वास्तव में अधिकांश बैंक नकद मुद्रा उधार न देकर केवल नकद मुद्रा देने के वायदे ही उधार देते हैं। प्रो० सेलिगमैन (Seligman) ने ठीक ही कहा है कि "पहले बैंक नकद निक्षेपो में व्यवसाय करते थे, आजकल वे प्रमुख रूप से साख निक्षेपो में व्यवसाय करने लगे हैं।"¹⁰

उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति किसी बैंक के पास ५००० रुपये का ऋण लेने के लिए जाता है तो सर्वप्रथम बैंक मैनेजर उस व्यक्ति की शोधन क्षमता (Solvency) के विषय में अपने को सन्तुष्ट करता है। ऋण के बदले में उचित जमाना प्राप्त

9 "The creation of derivative deposits is identical with what is commonly call the Creation of Credit"

—G. N. Halm : Monetary Theory.

10 "In former times . . . the banks dealt in cash deposits now-a-days they deal primarily in credit deposits"

—Seligman Principles of Economics.

करने के पश्चात् वह उस व्यक्ति को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है किन्तु जब ऋण की रकम के वास्तविक भुगतान का समय आता है तो बैंक मैनेजर ऋणी को सलाह देता है कि वह ५००० रुपये नकद ले जाने के स्थान पर अपने खाते में उसे जमा करा ले और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकालता रहे। ऋणी प्रायः इस सुझाव को मान लेता है और ऋण की रकम को अपने हिमाव में जमा करा देता है। इस प्रकार बैंक में ऋण लेने वालों की जमा बढ़ जाती है और उसके लिए किसी की भी जमा कम नहीं होती है। प्रायः रुपया बैंक से बाहर नहीं जाता है और साथ ही साथ बैंक की जमा में भी वृद्धि हो जाती है। यदि ऋणी अपना रुपया नकद रूप में भी ले जाता है तो वह जिन लोगों को भुगतान करता है वे उसे अपने बैंक के हिसाबों में जमा कर देते हैं। इस प्रकार रुपया फिर उसी बैंक में अथवा अन्य बैंकों में वापस आ जाता है।

बैंक के द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक ऋण बैंक में नई जमा उत्पन्न करता है। इसीलिए हार्टले विदम (Hartley Wuthers) ने कहा है कि “ऋण जमा का निर्माण करते हैं।” बैंक ऋणों के कारण उत्पन्न हुई इस जमा के आधार पर और अधिक ऋण दे देता है और इस प्रकार यह जमा नए ऋणों को उत्पन्न करती है। इसलिए यह कहा गया है कि ऋण जमा के कारण उत्पन्न होते हैं और जमा ऋणों के कारण उत्पन्न होती है। प्रो० केन्ज (Keynes) के शब्दों में “ऋण जमा की सन्तान है और जमा ऋणों की सन्तान है।”¹¹ इस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देकर साख का निर्माण करता है जो आज की अर्थ-व्यवस्था का जीवन-प्रवाह है।

ऋण देने के अनिश्चित कुछ अन्य तरीकों से भी बैंक साख का निर्माण करता है—(i) नकद साख (cash credit) तथा खाते में से अधिक रुपया निकालने (Overdraft) की सुविधा देकर, (ii) प्रतिभूतियों को खरीदकर। जब बैंक अपने ग्राहकों को नकद साख (cash credit) की सुविधायें देता है अथवा उन्हें ओवर-ड्राफ्ट (overdraft) की आज्ञा देता है तो भी ग्राहकों के खातों में जमा की वृद्धि होती है और बैंक के द्वारा साख का निर्माण होता है। इसके अनिश्चित जब बैंक प्रतिभूतियाँ (Securities) तथा अन्य प्रकार के आदेय (Assets) खरीदता है और उनके बेचने वालों को अपने ऊपर लिखित बैंक के द्वारा भुगतान करता है तो उसमें भी साख की मात्रा में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त सभी तरीकों से आधुनिक बैंक साख का निर्माण किया करते हैं। अपने द्वारा निमित्त साख को उधार देकर ही बैंक अपना अधिकांश लाभ प्राप्त करते हैं किन्तु इसमें उनकी स्थिरता के लिए बड़ा खतरा भी होता है। यदि कोई

11 “Loans are the children of deposits and deposits are the children of loans.”

बैंक लाभ के सालच में बहुत अधिक मात्रा में ऋण दे देता है और अपने ग्राहकों की माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी नहीं रखता है तो वह फेल हो सकता है।

बैंक कितनी साख का निर्माण कर सकता है

(Extent of Credit Creation) —

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कोई बैंक कितनी साख का निर्माण कर सकता है। साधारणतया प्रत्येक बैंक की साख निर्माण करने की सीमा उसके द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष के अनुपात से निश्चित होती है। प्रत्येक बैंक जानता है कि किसी भी समय नकदी की माग उसकी कुल जमा का एक छोटा सा भाग होती है। बैंक को अपने अनुभव से पता रहता है कि वह नकदी की माग को पूरा करने के लिए अपने कुल दायित्व (Total Liabilities) का कितना प्रतिशत अपने पास नकद कोष में रखे। भिन्न-भिन्न देशों में तथा विभिन्न बैंकों में नकद कोष का यह अनुपात भिन्न-भिन्न होता है। भारतवर्ष में नकद कोष का अनुपात अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा रहता है क्योंकि यहाँ पर लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास पूरी तरह नहीं हुआ है। नकद कोष का यह अनुपात ही इस बात को निश्चित करता है कि बैंक अपने पास जमा रकम में से कितना उधार दे सकता है।

उदाहरणार्थ, यदि कोई बैंक अपने कुल दायित्व का २०% नकद कोष में रख कर शेष उधार दे देता है।—ऐसी दशा में बैंक के पास जमा होने वाले प्रत्येक (१००) रुपये में से ८० रुपये उधार दिये जायेंगे तथा २० रुपये नकद कोष के रूप में रखे जायेंगे। यदि बैंक के पास कुल जमा १०,००० रुपये हैं तो वह उसमें से २००० रुपये नकद रखेगा और ८००० रुपये अपने ग्राहकों को उधार दे देगा। किन्तु इन ऋणों का नकद रूप में दिया जाना अनिवार्य नहीं है। वे ग्राहकों के हिसाब में ऋणों की रकम जमा करके भी दिये जा सकते हैं। ऐसा करने से इन ऋणों की रकम उम बैंक में अथवा अन्य बैंकों में जमा के रूप में आती है जिसका २०% बैंक अपने पास रखकर शेष को उधार दे देते हैं जिसके कारण फिर बैंकों की जमा में वृद्धि होती है और वे उसका ८०% उधार दे देते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है और बैंकों के लिए अपनी कुल जमा का कई गुना उधार देना सम्भव हो जाता है। यद्यपि कोई व्यक्तिगत बैंक अपने अतिरिक्त कोषों (Excess Reserve) के बराबर ही ऋण दे सकता है किन्तु सब बैंक मिलकर अतिरिक्त कोषों का कई गुना उधार दे देते हैं। यह क्रम अगले पृष्ठ पर दी तालिका के ढंग से चलता है।

इस तालिका की देखने से पता चलता है कि यदि बैंकों के पास १० लाख रुपये की जमा है तो वे उममें से २ लाख रुपये (२०%) नकद रखकर शेष ८ लाख रुपये उधार दे देते हैं। ऋणों की यह ८ लाख रुपये ही रकम फिर

बैंकों की कुल जमा	बैंकों के द्वारा रखवा जाने वाला नकद कोष (२०%)	उधार दी जाने वाली रकम
रु० १,०००,०००	रु० २००,०००	रु० ८००,०००
८००,०००	१६०,०००	६४०,०००
६४०,०००	१२८,०००	५१२,०००
५१२,०००	१०२,४००	४०९,६००

बैंकों की जमा के रूप में प्राप्त हो जाती है और बैंक अपने पास २ लाख रुपये की नई जमा की देखकर उसका २०% अथवा १ लाख ६० हजार रुपये नकद कोष में रखकर शेष ६ लाख ४० हजार रुपये उधार दे देते हैं। यह ६ लाख ४० हजार रुपये फिर जमा के रूप में आ जाता है और इसका २०% फिर उधार दे दिया जाता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है और बैंक अपनी जमा का कई गुना अपने ग्राहकों को उधार दे देते हैं।

कैनन का विरोध (Cannan's Objection)—

प्रो० कैनन ने बैंकों के द्वारा साख निर्माण किये जाने के सिद्धांत का विरोध किया है। उनके अनुसार बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं। प्रो० कैनन (Cannan) के अनुसार, “प्रत्येक व्यवहारिक बैंकर यह जानता है कि वह साख, मुद्रा अथवा किसी अन्य वस्तु का निर्माता नहीं है। बल्कि वह केवल ऐसा व्यक्ति है जो साधन वाले व्यक्तियों के द्वारा साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को श्रृंखला दिये जाने की सुविधा प्रदान करता है।”^{१२} वास्टर लीफ (Walter Leaf) ने भी इसी प्रकार का मन प्रकट किया है। इन लेखकों का विचार है कि साख निर्माण का कार्य जमा करने वालों (Depositors) के द्वारा प्रारम्भ किया जाता है, न कि बैंक के द्वारा। बैंक में रुपया जमा करने वाले क्योंकि अपनी जमा को बैंक के पास छोड़ देते हैं और उसे नहीं निकालते हैं इसलिए वे ही साख निर्माण करने का प्रारम्भ करते हैं। यदि वे अपनी जमा को निकाल लें तो साख का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। बैंक तो केवल एक मध्यवर्ती है और वह नई साख का निर्माण नहीं कर सकता है। वह केवल उस रकम को उधार देता है जिसे जमा करने वालों ने उसके पास छोड़ा हुआ है। वास्टर लीफ (Walter Leaf) के अनुसार बैंक अपनी नकद जमा से अधिक रुपया उधार नहीं दे सकता है क्योंकि लोग किसी भी समय अपने रुपये को निकाल सकते हैं। लीफ तथा कैनन ने बैंकों के साख निर्माण करने के कार्य को ठीक प्रकार नहीं समझा है। यह एक व्यवहारिक अनुभव की बात है कि बैंक

12 “...every practical banker knows that he is not a creator of credit or money or anything else, but a person who facilitates the lending of resources by the people who have them to those who can use them”

समाज में साख का निर्माण करते हैं। इसीलिए बैंको में जमा रकम चलन में मुद्रा की कुल मात्रा से बड़ी गुना होती है।

साख निर्माण की सीमाये (Limits of Credit Creation)—

यद्यपि बैंक साख का निर्माण करते हैं किन्तु वे किसी भी सीमा तक साख का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति की भी कुछ सीमाये होती हैं। बैंको के द्वारा साख निर्माण करने पर सबसे बड़ा प्रतिबन्ध लोगों के द्वारा अपनी जमा के निवाले जाने का भय है। प्रत्येक बैंक यह जानता है कि उसके निदेपधारी (Depositors) किसी भी समय अपने रुपये को निकाल सकते हैं और उसे इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए बैंक कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही साख का निर्माण करते हैं। प्रो० बेंनहम (Benham) ने साख निर्माण करने की तीन सीमाये बतलाई हैं—

(१) देश में नकद रुपये की कुल मात्रा (Total amount of cash in the country)—बैंको के पास केवल नकदी पर आधारित जमा का निर्माण करने की शक्ति ही होती है। वे अपने ग्राहकों के पक्ष में कितनी जमा का निर्माण कर सकते हैं यह उनके पास नकद जमा (Cash Deposits) की मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। बैंको में प्राप्त होने वाली नकद जमा देश में नकदी की कुल मात्रा के ऊपर निर्भर होती है जिसे बैंक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देश में नकद मुद्रा की मात्रा केन्द्रीय बैंक की नीति पर निर्भर होती है।

(२) नकदी की मात्रा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं (Amount of cash which people wish to hold)—बैंको के द्वारा निर्मित साख की मात्रा इस बात पर भी निर्भर होती है कि लोग कितना नकद रुपया अपने पास रखना चाहते हैं। यदि लोग अपने पास अधिक मात्रा में नकदी रखते हैं तो वे बैंक में कम जमा करेंगे और यदि कम रखते हैं तो बैंक को अधिक जमा प्राप्त होगी। इस प्रकार बैंको में प्राप्त होने वाली नकद जमा लोगों की तरलता पसन्दगी (Liquidity Preference) पर निर्भर होती है जिसमें बैंक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब लोगों की तरलता पसन्दगी अधिक होती है तो बैंक कम साख का निर्माण कर पाते हैं और यदि तरलता पसन्दगी कम होती है तो वे अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं।

(३) बैंकों के द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष का अनुपात (Percentage of cash kept by the banks)—बैंक कितना न्यूनतम नकद कोष रखना सुरक्षित समझते हैं, इस बात पर भी निर्मित साख की मात्रा निर्भर होती है। जितना वे कम नकद कोष रखते हैं उतना ही अधिक ध्यान देकर वे अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं। किन्तु यदि उनके लिए अधिक नकद कोष रखना अनिवार्य है तो वे कम साख का निर्माण कर सकेंगे। नकद कोष का अनुपात लोगों की

आदतो तथा समाज में भुगतान करने के तरीकों पर निर्भर होता है जिसमें बैंक कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि लोग बैंकिंग की आदत का विकास नहीं हुआ है और अधिकांश भुगतान नकद रूप में निबटाये जाते हैं तो बैंको को अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक नकद कोष रखना होगा और वे कम मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि लोग भुगतान बैंक अथवा अन्य साख-पत्रों के द्वारा निबटा लेते हैं और नकदी की मांग कम करते हैं तो बैंक कम नकद कोष रखकर ही अपना काम चला लेंगे और इस प्रकार वे अधिक साख का निर्माण कर सकेंगे।

अन्य सीमाएँ (Other Limitations)—उपर्युक्त सीमाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति को सीमित करती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

(अ) **केन्द्रीय बैंक के पास बैंकों का रक्षित कोष**—प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्वों (Total Liabilities) का एक निश्चित भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। यदि इस अनुपात में केन्द्रीय बैंक परिवर्तन करता है तो उससे बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति प्रभावित होती है। केन्द्रीय बैंक के द्वारा नकद जमा के अनुपात का बढ़ाया जाना बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति को कम कर देता है। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक अपने पास रखी जाने वाली नकद जमा के अनुपात को कम कर देता है तो बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं।

(ब) **केन्द्रीय बैंक की साख सम्बन्धी नीति**—केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति को प्रभावित करता है। बैंक दर का ऊँचा होना तथा केन्द्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का बेचा जाना बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति को कम करता है।

(स) **जमानतों की श्रेष्ठता**—बैंक जमानतों के आधार पर ही ऋण देते हैं इसलिए उनकी साख निर्माण करने की शक्ति इस बात पर आधारित होती है कि उनके ग्राहक कितनी मात्रा में तथा किम प्रकार की जमानतें दे सकते हैं। यदि ग्राहक बाकी मात्रा में अच्छे प्रकार की जमानतें दे सकते हैं तो वे अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे और बैंको के द्वारा अधिक मात्रा में साख का निर्माण किया जायगा।

बैंकों का आर्थिक महत्व (Economic Importance of Banks)—

बैंक हमारे आर्थिक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। समाज में सामं तथा मुद्रा की कुल पूर्ति का एक बहुत बड़ा अंश उनके नियन्त्रण में रहता है और उसके द्वारा वे हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। वे केवल लोगों की जमा प्राप्त करके उसे सुरक्षित रखने तथा उस पर व्याज देने का कार्य ही

नहीं करते हैं बल्कि समाज में उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के संचालन में भी बड़ा सहयोग देते हैं। किसी देश की बैंकिंग प्रणाली को वहाँ के उद्योग, व्यापार तथा समस्त आर्थिक व्यवस्था का धमनी केन्द्र (Nerve Centre) कहा जा सकता है। इसीलिए किसी देश की उत्पादन व्यवस्था के ठीक प्रकार से चलने के लिए उस देश के बैंक पूरी तरह से विकसित तथा सुगठित होने चाहिए। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में बैंकों के महत्व तथा उनकी उपयोगिता को उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के द्वारा जाना जा सकता है। सामान्यतः बैंकों से समाज को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

(१) बैंक लोगों में बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करते हैं—वर्तमान बैंक लोगों की बचत को सुरक्षित रखने तथा उस पर व्याज देने की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जिससे लोगों को अधिक बचन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार बैंक समाज में बचन की मात्रा को बढ़ाने में सहयोग देते हैं।

(२) समाज में बचत को एकत्रित करके उत्पादन कार्यों में लगाते हैं—बैंक उन लोगों की बचत को जमा के रूप में इकट्ठा करते हैं जो उसका स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। छोटी-छोटी बचतों को भी बैंकों के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। इस जमा रकम को बैंक उन व्यवसायियों को उधार देते हैं जो उसका उत्पादन कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार एक ओर तो बैंक समाज की बचत को क्रयशील (Mobilise) करते हैं और दूसरी ओर विनियोग को प्रोत्साहन देते हैं जिससे समाज में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है।

(३) मुद्रा के स्थानान्तरण की सुविधाएँ देते हैं—बैंकों की सहायता से रुपया बहुत कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। इस प्रकार की सुविधाओं से व्यापार के विकास तथा विस्तार में बड़ी सहायता मिलती है।

(४) बैंक समाज में साक्षरता का निर्माण करते हैं—जिसके आधार पर वर्तमान औद्योगिक तथा व्यावसायिक जीवन चलता है विकसित देशों में बैंक-मुद्रा चलन में कुल मुद्रा का अधिकांश भाग होती है जिसके द्वारा भुगतानों को निबटाने में बड़ी सुविधा रहती है। बैंक साक्षरता के निर्माण होने के कारण देश में उत्पादन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वे केवल मात्र मुद्रा की मात्रा को ही निर्दिष्ट नहीं करते हैं बल्कि उसके प्रयोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

(५) मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करते हैं—बैंक के द्वारा मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण उत्पन्न होता है। वे व्यापार तथा उद्योगों की आवश्यकतानुसार मात्र की मात्रा को घटाते-बढ़ाते रहते हैं जिसके कारण मुद्रा की माग तथा पूर्ति में सामंजस्य से समतुल्य बन जाता है।

(६) विनिमय का सस्ता माध्यम प्रदान करते हैं—बैंक समाज में बैंक तथा अन्य प्रकार के साक्षर-पत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन देते हैं जिसके कारण लोग

नकद मुद्रा को गिनने, ले जाने तथा इकट्ठा करने की असुविधा से बच जाते हैं। इस प्रकार के साख-पत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किसी देश के आर्थिक दृष्टि से विकसित होने की निशानी है।

(७) बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षित रखने की सुविधायें देते हैं—बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षित रखने के लिए लॉकर (Locker) आदि की सुविधायें देते हैं जिससे लोग इस प्रकार की वस्तुओं की सुरक्षित रखने की कठिनाई से बच जाते हैं।

(८) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करते हैं—बैंकों की सहायता से विदेशी भुगतानों को बड़ी आसानी से निबटाया जा सकता है। विदेशी भुगतानों की इस सुविधा के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होता है तथा विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय का प्रदत्त करता है और उन्हें साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit) तथा यात्री चेक (Traveller's Cheque) भी देता है।

बैंक से प्राप्त होने वाले उक्तलिखित लाभों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंक किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान आर्थिक जीवन में बैंकों का महत्व इसलिए नहीं है कि उनके पास उद्योग तथा व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्व साधन होते हैं बल्कि उनके महत्व का मुख्य कारण यह है कि वे इन आर्थिक साधनों के प्रयोग को भी प्रभावित कर सकते हैं। बैंकों के पास यह निश्चय करने की शक्ति होती है कि वैश्व साधनों का प्रयोग किस दिशा में किया जाये। वे अपने ऋणियों को अपनी इच्छा अनुसार छांट लेते हैं। वे परिश्रमी, ईमानदार तथा समय पर स्वयं लौटाने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार बैंक समाज में व्यवसायिक ईमानदारी को प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी देश की विकसित तथा सुसंगठित वैश्व व्यवस्था उम्र देन के आर्थिक विकास के लिए दृढ़ आधार तैयार करती है।

विभिन्न प्रकार के बैंक (Types of Banks)—

बैंक विभिन्न प्रकार के होते हैं क्योंकि उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों में काफी भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के बैंक एक विशेष प्रकार के वित्तीय व्यवसाय को करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के बैंकों में भेद करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु बैंकों का स्पष्ट वर्गीकरण करना बहुत कठिन है क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के बैंकों के कार्य एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एक बैंक जो किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करता है, वह कभी-कभी दूसरी प्रकार के बैंकों के कार्यों को करने लगता है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी बैंकों को अग्रलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)
- (२) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)
- (३) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)
- (४) कृषि बैंक (Agricultural Banks)
- (५) केन्द्रीय बैंक (Central Banks)

(१) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)—इस प्रकार के बैंक व्यापार की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देते हैं। इन बैंकों का मुख्य काम समाज में लोगों की बचत को इकट्ठा करना तथा उसे अन्य लोगों को उधार देना है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अवधि प्रायः तीन महीने की होती है किन्तु कभी-कभी ऋण एक साल तक के लिए भी दिया जा सकता है। ये ऋण विनिमय-पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स, तैयार माल तथा अन्य प्रकार की सरल सम्पत्ति के आधार पर दिये जाते हैं। व्यापारिक बैंकों का विस्तृत वर्णन हमसे पहले किया जा चुका है।

(२) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)—विदेशी विनिमय बैंक मुख्यतः विदेशी विनिमय के व्यापारी होते हैं। इन बैंकों के द्वारा विदेशी भुगतानों को निवटाने के उद्देश्य से विदेशी विनिमय-पत्रों का क्रय-विक्रय किया जाता है। विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य इस प्रकार हैं—(i) विदेशी विनिमय-पत्रों का क्रय-विक्रय करके अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निवटाना—इस प्रकार के बैंक निर्यातकर्त्ताओं (Exporters) के द्वारा लिखित विनिमय-पत्रों को खरीदते हैं और विदेशों से उनका भुगतान प्राप्त करते हैं तथा आयातकर्त्ताओं (Importers) को विदेशी भुगतान निवटाने के लिए विनिमय-पत्रों को बेचते हैं। (ii) विदेशी ऋणों का निस्तारण (Liquidate) करना—सोने, चाँदी तथा प्रतिभूतियों के निर्यात एवं आयात के द्वारा यह बैंक अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का निस्तारण करते हैं। (iii) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय—ये बैंक विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय के द्वारा विनिमय दूरों के परिवर्तनों को कम करते हैं तथा व्यापारियों को जोखिम से बचाते हैं। (iv) व्यापारिक बैंक के कार्य—ये बैंक व्यापारिक बैंकों के भी कुछ कार्य करते हैं जैसे जमा प्राप्त करना, ऋण देना, विनिमय-पत्रों को भुनाना आदि।

(३) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)—इस प्रकार के बैंकों का विकास उद्योगों की वित्त सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और न वे इतनी अधिक रकम ही उधार दे सकते हैं। इसलिए औद्योगिक वित्त का प्रवर्धन करने के लिए औद्योगिक बैंकों का विकास किया गया है। इन बैंकों की पूँजी हिस्सों की रकम (Share money), दीर्घकालीन जमा तथा

बीमा कम्पनियों के ऋणों से मिलकर बनती है। औद्योगिक बैंकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है—(i) जमा प्राप्त करना—ये बैंक केवल निश्चित अवधि के लिए ही जमा प्राप्त करते हैं क्योंकि इन्हें दीर्घकालीन ऋण देने होते हैं। (ii) उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना—ये बैंक उद्योगों की पूँजी में भी हिस्सा लेते हैं तथा कारखानों की जाँच करने के पश्चात् उन्हें लम्बे समय के लिए ऋण देते हैं। इन बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रायः बहुत से कारखानों में बँटे होते हैं। (iii) औद्योगिक प्रबन्ध में भाग लेना—जर्मनी के औद्योगिक बैंकों में यह प्रथा है कि वे ऋणों कम्पनी के प्रबन्ध में भी भाग लेते हैं और कम्पनियों पर अधिक नियन्त्रण करने के लिए वे अपने प्रतिनिधि इन कम्पनियों की प्रबन्ध समितियों (Managing Boards) पर रखते हैं। (iv) कुछ अन्य काम भी इन बैंकों के द्वारा किये जाते हैं, जैसे कम्पनियों के हिस्सों का विज्ञापन करना तथा उन्हें बेचना, अपने ग्राहकों को विनियोग के लिए उद्योगों को छाँटने में सहायता करना तथा कम्पनियों की पूँजी का प्रबन्ध करना।

(४) कृषि बैंक (Agricultural Banks)—किसानों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। बीज, खाद, फसलों को बेचने तथा अन्य प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋण चाहिए जिनका भुगतान प्रायः एक फसल के पश्चात् कर दिया जाता है। भूमि खरीदने तथा खेतों पर स्थायी सुधार करने या मशीनें खरीदने के लिए किसानों को दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बैंक किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कृषि व्यवसाय अनिश्चित होता है तथा किसान ऋणों के लिए अच्छी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अतः कृषि विस्तार की व्यवस्था करने के लिए पृथक् प्रकार के बैंकों का विकास किया गया है जिन्हें कृषि बैंक कहा जाता है। कृषि बैंक प्रायः दो प्रकार के होते हैं—(अ) सहकारी बैंक तथा (ब) भूमि बन्धक बैंक। सहकारी बैंकों का उद्देश्य किसानों को उनकी सामयिक (Seasonal) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम व्याज की दर पर अल्पकालीन ऋणों को देने की व्यवस्था करना होता है। सहकारी बैंक को सहकारी साख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इन बैंकों की पूँजी हिस्से बेचकर, जमा प्राप्त करके तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेकर प्राप्त की जाती है। भूमि बन्धक बैंक—ये बैंक किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। भूमि बन्धक बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अवधि ५ वर्ष से लेकर २० वर्ष तक होनी है। कहीं-कहीं ये इससे अधिक समय के लिए भी ऋण देते हैं। ऋण भूमि को गिरवी रख कर दिये जाने हैं और उनका भुगतान निस्तो में किया जाता है। भूमि बन्धक बैंक किसानों को भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए तथा पत्रिक ऋणों को निबटाने के लिए ऋण देते हैं।

(५) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—आजकल प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो देश की मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह देश का सबसे बड़ा बैंक होता है और इसे बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय बैंक को देश में नोट निर्माण का एकाधिकार प्राप्त होता है तथा उसके पास देश के समस्त बैंकों व सरकार का रखा जमा रहता है। यह बैंक सरकारी बैंक तथा बैंकों के बैंक का कार्य करता है। देश के सभी बैंकों को आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। केन्द्रीय बैंक देश में साख तथा मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करता है एवं सरकार को आर्थिक तथा वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसके बिना बैंकिंग प्रणाली को अपूर्ण समझा जाता है। वास्तव में केन्द्रीय बैंक सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का संचालक होता है और बैंकों के उचित नियन्त्रण तथा नियमन के द्वारा यह देश की आर्थिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने में सहायता देता है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) व्यवसायिक बैंक के कार्यों की व्याख्या करें। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में उनका क्या महत्व है ? (आगरा बी० ए० १९६०)
- (२) बैंकों के द्वारा किस प्रकार का साख का निर्माण किया जाता है ? उनकी क्या सीमाएँ हैं ? (आगरा बी० काम १९५६)
- (३) 'साख' की परिभाषा कीजिये। व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं ? (आगरा बी० ए० १९५६)
- (४) व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये। उद्योग के लिए वे किस प्रकार अधिक सहायक हो सकते हैं ? (आगरा बी० ए० १९५६)
- (५) मिश्रित पूँजी बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये। क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया को आप मिश्रित पूँजी बैंक कह सकते हैं ? कारण सहित उत्तर दीजिए। (आगरा बी० काम १९६०)
- (६) "प्रत्येक ऋण एक डिपॉजिट का सृजन करता है।" यह किस प्रकार सम्भव होता है ? (आगरा बी० काम १९५६)
- (७) व्यापारिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार करते हैं ? किसी देश के आर्थिक नियोजन में इस प्रकार की साख का क्या महत्व है ? (राजस्थान बी० ए० १९५६)

- (८) व्यापारिक बैंक के कार्यों का संक्षेप में विवेचन करिए : भारत के व्यापारिक बैंक इन कार्यों को कहाँ तक सम्पन्न करते हैं ?
(राजस्थान बी० ए० १९५७)
- (९) बैंक किस प्रकार देश के व्यापार एवं वाणिज्य की सहायता करते हैं ? विवेचना कीजिये ।
(राजस्थान बी० ए० १९६०)
- (१०) बैंकों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिये तथा उनके कृत्यों का स्वरूप भी बतलाइये ।
(विक्रम बी० ए० १९५९)
- (११) "बैंक केवल साख के व्यापारी ही नहीं होते हैं बल्कि वे साख का निर्माण भी करते हैं ।" विवेचना कीजिए ।
(बिहार बी० काम १९६०)
- (१२) "नकद कोषों के आधार पर ही बैंकों के द्वारा समस्त साख का सृजन किया जाता है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? उत्तर लिखिए कारण भी दीजिये ।
(बिहार बी० काम १९५९)



बैंक की कार्य-विधि

THE BANKING OPERATIONS

बैंक के कार्यों तथा उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन करने के पश्चात् हमें यह जानना चाहिए कि बैंक अपने इन कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न करता है। इसके लिए बैंक की कार्य-विधि का विस्तृत अध्ययन आवश्यक हो जाता है। समाज में बैंक का प्रमुख कार्य रुपये का लेन-देन करना है और किसी भी बैंक की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह किस प्रकार की विनियोग नीति को अपनाता है। सर्वप्रथम बैंक रुपये के लेन-देन के व्यवसाय को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी एकत्रित करना है और फिर इस पूँजी का विभिन्न प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसाय में विनियोग करके उससे लाभ प्राप्त करता है। बैंकों का लेन-देन कार्य कहीं तक व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों के अनुसार होता है तथा उनकी विनियोग सम्बन्धी नीति में जिन दिशाओं में सुधार किये जायें, ये व्यवहारिक बैंकिंग की कुछ आधारभूत समस्याएँ हैं। बैंकों की विनियोग सम्बन्धी नीति का अध्ययन करने से पूर्व हमें इस बात का विवेचन करना चाहिए कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार पूँजी प्राप्त करते हैं।

बैंक की पूँजी के साधन (Capital of the Bank)—

आधुनिक बैंक विभिन्न प्रकार के साधनों से अपनी ध्यावमायिक पूँजी प्राप्त करता है। बैंक की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि वह लेन-देन व्यवसाय के लिए कितनी पूँजी प्राप्त कर सकता है और यह पूँजी किन-किन साधनों से प्राप्त की जाती है। बैंक की पूँजी प्राप्त करने के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं—

(१) भ्रश पूँजी (Share Capital)—आधुनिक बैंकों की पूँजी का एक महत्वपूर्ण भाग जनता को बैंक के भ्रश (Shares) बेचकर प्राप्त किया जाता है क्योंकि बैंकों का निर्माण प्रायः मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों (Joint Stock Companies) के आधार पर होता है। बैंक स्थापित करने से पूर्व उसके संस्थापक यह निश्चय करते हैं कि बैंक को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुल कितनी पूँजी की आवश्यकता होगी। यह बैंक के द्वारा पूँजी एकत्र करने की अधिकतम सीमा होती है और इसे अधिकृत पूँजी (Authorised capital) कहते हैं। बैंक की अधिकृत पूँजी को

सामान्य मूल्य वाले अंशों (Shares) में बाँट दिया जाता है और उनकी एक निश्चित मात्रा जनता के खरीदने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जितनी रकम के अंश जनता के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं वह बैंको की निर्गमित पूँजी (Issued capital) होती है और वास्तव में जितनी रकम के हिस्से जनता के द्वारा खरीदे जाते हैं उसे प्राथिक पूँजी (Subscribed capital) कहते हैं। प्राथिक पूँजी (Subscribed capital) का वह भाग जिसका अक्षधारियों के द्वारा वास्तव में भुगतान किया जाता है उसे चुकता पूँजी (Paid up capital) कहते हैं। बैंक की वास्तविक पूँजी यही होती है। इस प्रकार प्रत्येक बैंक अपनी कुल पूँजी का काफी बड़ा भाग अपने अंशों (Shares) को बेचकर प्राप्त करता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम सन् १९४९ (Indian Banking Companies Act 1949) के अनुसार बैंको को अपनी पूँजी प्राप्त करने के लिए केवल साधारण अंशों (Ordinary shares) को ही जारी करना चाहिए तथा बैंक की प्राथिक पूँजी (Paid up capital) उसकी अधिकृत पूँजी (Authorised capital) की आधी से अधिक होनी चाहिए और उसकी चुकता पूँजी (Paid up capital) उसकी प्राथिक पूँजी (Subscribed capital) की आधी से कम होनी चाहिए।

(२) जमा धन (Deposits)—किसी भी बैंक का प्रारम्भिक कार्य अपने ग्राहकों से बचत को जमा राशि के रूप में एकत्रित करना होता है। लोग अपना रुपया निश्चित शर्तों पर बैंक में जमा करते हैं जिसे वे आवश्यकता पड़ने पर इन शर्तों के अनुसार निकाल सकते हैं। बैंको में जमा की हुई रकम सुरक्षित भी रहती है और बैंक उस पर व्याज भी देता है। आधुनिक बैंक जनता की जमा को प्राप्त करने की सुविधाएँ प्रदान करके समाज की एक बहुत बड़ी सेवा करते हैं किन्तु वे इस जमा राशि से अपनी पूँजी भी प्राप्त करते हैं। वर्तमान बैंको के पास पूँजी की मात्रा बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर होती है कि वे जनता से कितना धन जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। बैंक में जनता को जितना अधिक विश्वास होता है बैंक को उतनी ही अधिक मात्रा में जमा धन प्राप्त होता है। एक अच्छे बैंक की पहचान इसी से होती है कि उसे कितना जमा धन प्राप्त हुआ है। जमा धन द्वारा बैंक अपनी पूँजी का बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते हैं।

(३) साख निर्माण करके (Creation of Credit)—बैंको की पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं निर्मित होता है। हम देख आये हैं कि बैंक केवल लोगों से साख खरीदकर ही उसे उधार नहीं देते हैं एवं वे स्वयं साख का निर्माण करते हैं और अपने द्वारा निर्मित साख को उधार देकर लाभ प्राप्त करते हैं। वर्तमान बैंको के लाभ का प्रमुख साधन स्वयं निर्मित साख को उधार देना है। बैंको के द्वारा साख का निर्माण करना उनकी पूँजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तथा मस्ता साधन है क्योंकि बैंको को इस प्रकार की पूँजी पर किसी प्रकार का व्याज नहीं देना पड़ता है। बैंक जितनी पूँजी साख निर्माण के द्वारा प्राप्त कर सकता है—वह

इस बात पर निर्भर होता है कि बैंक के पास कितनी नकद जमा है और वह उस कितना अंश नकद कोष के रूप में रखता है। नकद जमा जितनी अधिक होती तथा बैंक जितना कम अनुपात नकद कोष के रूप में रखता है उतनी ही अधिक मात्रा में वह साख्त का निर्माण कर सकेगा। वर्तमान समय में लोगों में बैंकिंग की भाव बढ़ जाने तथा बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार होने के कारण बैंकों की साख्त निर्माण करने की शक्ति में काफी वृद्धि हुई।

(४) ऋण प्राप्त करके (Loans)—बैंक अपनी पूँजी का कुछ भाग ऋण लेकर भी प्राप्त कर सकता है। साधारण परिस्थितियों में बैंक अपनी अंश पूँजी का जमा धन के द्वारा ही काम चलाता है किन्तु असाधारण परिस्थितियों में वह ऋण के द्वारा भी पूँजी प्राप्त करता है। ऐसे ऋण व्यक्तियों से नहीं लिए जाते हैं बल्कि उन्हें अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक से प्राप्त किया जाता है। जब किसी बैंक के प्राद्वित अंश अधिक मात्रा में नकदी की मांग करने लगते हैं कि बैंक उसे अपने साधारण साधनों से पूरा नहीं कर पाता तो ऐसी दशा में बैंक को केन्द्रीय बैंक तथा प्रसिद्धी से ऋण लेकर इस मांग को पूरा करना पड़ता है।

(५) सुरक्षित कोष (Reserve Fund)—बैंक की पूँजी का एक अंश साधारण उसका सुरक्षित कोष है। प्रत्येक बैंक को प्राप्त होने वाले लाभ को दो भागों में बाँटा जाता है। उसका एक निश्चित अंश बैंक के अंशधारियों को लाभ (Dividend) के रूप में बाँट दिया जाता है तथा शेष भाग को सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में रखा जाता है। सामान्यतः इस कोष का प्रयोग असामान्य हानि (Contingent losses) को पूरा करने तथा प्रतिवर्ष वितरित लाभ को संचयित करने के लिए किया जाता है किन्तु जब यह फण्ड काफी हो जाता है तो यह बैंक की पूँजी का साधन बन जाता है। आरम्भ में सुरक्षित कोष (Reserve Fund) की मात्रा बहुत कम होती है और बैंक को अपनी कार्यशील पूँजी (Working capital) के लिए चुकता पूँजी (Paid up capital) के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु धीरे-धीरे यह कोष बढ़ता जाता है और बैंक की कार्यशील पूँजी (Working capital) में भी वृद्धि होती है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम (१९४६) के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए अपने लाभ का २०% प्रतिवर्ष सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य होता है।

धन का विनियोग (Investment)—

बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपनी पूँजी का विनियोग करके लाभ प्राप्त करना होता है। बैंक केवल ऋण देने के लिए ही उधार लेता है। उपर्युक्त सब साधनों से एकत्रित पूँजी को बैंक विभिन्न प्रकार के विनियोगों में लगाता और उनसे आय प्राप्त करता है। प्रत्येक बैंक अपनी पूँजी को नकद कोष (Cash Reserve), मृत विनियोग (Dead Investment), तरल आदेय (Liquid Asset)

तथा प्रतरल आदेय आदि में बाँटता है। पूँजी को इन विभिन्न विनियोगों में बाँटने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है और यह बैंक की अपनी विनियोग सम्बन्धी नीति के द्वारा निश्चित होता है। बैंक की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी पूँजी का विनियोग करता है तथा उसे किस प्रकार के विनियोगों में लगाता है। सफल विनियोग नीति का निर्माण करने के लिए बैंक अधिकारियों में दूरदर्शिता (Foresight), अनुभव (Experience) तथा व्यक्तिगत निर्णय (Judgement) लेने के गुण होने चाहिए। बैजहाट (Bagshot) ने ठीक ही कहा है कि "साहस व्यापार का जीवन है किन्तु सावधानी न कि भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है।"¹ बैंक को अपने विनियोगों को निश्चय करने के लिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी विनियोग नीति व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों (Principles of Commercial Banking) के अनुसार हो।

बैंक की विनियोग नीति के सिद्धान्त

(Principles of Investment Policy)—

यद्यपि प्रत्येक बैंक अपनी विनियोग नीति का निर्माण अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकता है किन्तु फिर भी उसे समुचित विनियोग नीति का विकास करने के लिए विनियोग सम्बन्धी कुछ सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। बैंक की विनियोग नीति के तीन आधारभूत सिद्धान्त तरलता (Liquidity), उत्पादकता (Profitability) तथा सुरक्षा (Safety) माने जाते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने विनियोग नीति का निर्माण इन सिद्धान्तों के अनुकूल करना चाहिए। सामान्यतः व्यापारिक बैंकों को अपने धन का उचित विनियोग करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

(१) कोषों की तरलता (Liquidity of Funds)—सर्वप्रथम बैंक को अपने विनियोगों को करते समय तरलता (Liquidity) का ध्यान रखना चाहिए तरलता से अभिप्राय बैंक की, माग करने पर, नकदी का भुगतान करने की क्षमता से होता है। किसी भी बैंक के लिए उनके कोषों की तरलता अत्यन्त आवश्यक है बैंक का व्यापार विश्वास पर चलता है और जनता को बैंक में विश्वास तब तक होता है जब तक कि वह माग किये जाने पर नकदी का भुगतान कर सकता है। इसलिए बैंक के लिए अत्यन्त बैंक का भुगतान करने के लिए 'स्पार्श' भाग में नकद मुद्रा होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक के विनियोग "विक्री योग्य" हो अर्थात् उन्हें आवश्यकता पडने पर आसानी से तथा बिना किसी नुकसान के नकद मुद्रा में बदला जा सके। यदि बैंक के विनियोगों में इस प्रकार की तरलता

1 "Adventure is the life of commerce, but caution if not timidity, is the essence of modern banking."

—Bagshot.

नहीं है तो आवश्यकता के समय बैंक को अपने विनियोगों से धन नहीं मिल सकेगा और बैंक कठिनाई में फँस जायेगा। अतः बैंक के अधिकांश विनियोग ऐसे होने चाहिए जिनमें शीघ्रता से नकदी में बदला जा सके। तरलता की दृष्टि में जहाँ तक सम्भव हो सके बैंक के विनियोग अल्पकालीन हों। व्यापारिक बैंकों को अपना स्वयं अल्प मम्पत्ति तथा आसानी से न विक्रय वाली प्रतिभूतियों में नहीं लगाना चाहिए। श्री एम० एल० टैनन (M. L. Tannan) के अनुसार "बैंकर को विनिमय बिल तथा प्राधि (Mortgage) में अन्तर समझ लेना चाहिए।"^१ बैंक को अपने विनियोगों की तरलता को बनाये रखने के लिए अपने धन का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों, उत्तम प्रकार के हिस्सों तथा ऋण पत्रों (Shares and Debentures) एवं अन्य प्रकार के बिक्री योग्य विनियोगों में करना चाहिए।

(२) विनियोग की उत्पादकता (Productivity of Investment)—तरलता (Liquidity) के साथ-साथ बैंक को अपने विनियोगों की उत्पादकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। व्यापारिक बैंक लाभ पैदा करने वाली संस्थाएँ होती हैं इसलिए आवश्यक है कि उनके विनियोग लाभपूर्ण हों। एक बैंक को अपने व्यय को पूरा करने तथा अपने अगधारियों (Shareholders) को लाभांश (Dividend) देने के लिए पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त करनी चाहिए। बैंक की आय का मुख्य स्रोत विनियोगों से प्राप्त होने वाला लाभ है। इसलिए बैंक को अपना धन विभिन्न प्रकार के विनियोगों में इस प्रकार बाँटना चाहिए कि उन्हें अगधारियों (Shareholders) को लाभांश (Dividend) देने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक को आय देने वाले विनियोगों में अपना धन लगाना चाहिए। किन्तु कोई भी बैंक अपना अधिकांश धन इस प्रकार के विनियोगों में नहीं लगा सकता है क्योंकि ऐसा करने से उसका लाभ तो बढ़ेगा किन्तु उसकी तरलता समाप्त हो जायेगी। बैंक को विनियोगों का निश्चय करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए क्योंकि तरलता (Liquidity) और उत्पादकता (Profitability) दोनों एक दूसरे के प्रतिविरोधी हैं। कोई विनियोग जितना अधिक लाभपूर्ण होता है, उसमें से धन निकलना उतना ही कम सम्भव होता है। ऐसी दशा में बैंक को विनियोगों की उत्पादकता तथा तरलता दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी विनियोग नीति का निर्माण करना चाहिए। एक अच्छा बैंकर वही होता है जो कि तरलता (Liquidity) तथा लाभशीलता (Profitability) में उचित समन्वय कर सके।

(३) धन की सुरक्षा (Security of Funds)—बैंक को अपने धन का विनियोग करते समय इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विनियोग किया

१ "A true banker is one who understands the difference between a mortgage and a bill of exchange"
—Tannan.

जाने वाला धन सुरक्षित रहे। क्योंकि बैंक दूसरों से उधार लिए हुए धन का विनियोग करता है इसलिए उसे अधिक जोखिम वाले विनियोगों में अपना धन नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक बैंक को कम जोखिम वाले विनियोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए चाहे वे कम लाभपूर्ण हों। इसीलिए बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाना पसन्द करते हैं जिनसे कम लाभ प्राप्त होता है और कम्पनियों के हिस्सों में नहीं लगाते हैं जिनसे उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। बैंकों को लाभ के पीछे कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए और विनियोग करते समय धन की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से विनियोगों को छांटते समय बैंकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—(i) बैंक को अपना धन किसी एक व्यक्ति अथवा उद्योग को नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जोखिम बहुत बढ़ जाती है। जोखिम को कम रखने के लिए बैंक को विविध प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों को ऋण देने चाहिए। (ii) बैंक को दीर्घकालीन ऋण नहीं देने चाहिए और अल्पकालीन विनियोगों में ही अपना धन लगाना चाहिए। व्यापारिक बैंकों को केवल अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही ऋण देने चाहिए। (iii) ऋण केवल उचित जमानत पर ही दिये जाने चाहिए। कभी कभी कुछ बैंक प्रतियोगिता के कारण बिना उचित जमानत के भी ऋण दे देते हैं किन्तु ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। ऋण देने से पूर्व ऋणी के द्वारा दी जाने वाली जमानत की अच्छी प्रकार से जाँच करा लेनी चाहिए जिससे कि ऋण का भुगतान न होने पर बैंक को कोई हानि न उठानी पड़े। (iv) अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दिये जाने चाहिए—जहाँ तक सम्भव हो सके बैंक को अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। (v) ऋण देने से पूर्व ऋणी के आचरण की पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बैंक अपने विनियोगों की सुरक्षा को बढ़ा सकता है।

(४) जोखिम की विविधता (Diversification of Risks)—एक समुचित विनियोग नीति के अन्तर्गत बैंक को अपना धन विभिन्न प्रकार के आदेशों में लगाकर रखना चाहिए। बैंक के विनियोगों में विविधता होनी चाहिए और उसे कभी भी अपनी समस्त धन-राशि को एक ही प्रकार के ऋणों, प्रतिभूतियों तथा उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए। यदि बैंक अपनी अधिवास पूँजी को किसी एक व्यवसाय अथवा उद्योग में लगा देता है और किसी कारणवश वह उद्योग फेल हो जाता है तो ऐसी दशा में बैंक भी फेल हो जायगा। इस प्रकार की जोखिम से बचने के लिए बैंक को विविध प्रकार के विनियोगों में अपना धन लगाना चाहिए। कुछ थोड़े से उद्योग तथा व्यापारियों को बड़े-बड़े ऋण न देकर, बैंक को विभिन्न प्रकार के बहुत से उद्योगों तथा व्यापारियों को छोटे-छोटे ऋण देने चाहिए। ऐसा करने से ऋणों

का भुगतान रुक जाने के कारण बैंक के पास नकदी का प्रवाह रुकने का भय नहीं रहेगा। ऋणों में विविधता होने के कारण कुछ न कुछ ऋणों का भुगतान अवश्य होता रहेगा और इस प्रकार बैंक के पास नकदी का प्रवाह बना रहेगा।

(५) प्रतिभूतियों की बिक्री-साध्यता (Marketability of Securities)— बैंक को केवल ऐसी प्रतिभूतियों तथा माल की आड़ पर ऋण देने चाहिए जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। जहाँ तक सम्भव हो सके बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों (Bills), अच्छी कम्पनियों के अंशों व ऋण-पत्रों (Shares and Debentures) तथा तैयार माल आदि के आधार पर ही ऋण देने चाहिए क्योंकि इनमें बिक्री-साध्यता होती है और बैंक जब चाहे इन्हें बेच कर धन प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जबल सम्पत्ति में लगाया हुआ धन आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। अधिकांश बैंक जबल सम्पत्ति में धन लगाने के कारण ही कठिनाई में पड़ते हैं और यदि उन्हें ठीक समय पर सहायता न मिले तो कल हो जाते हैं।

इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त बैंक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके विनियोगों के मूल्यों में स्थिरता रहे। बैंक के विनियोग ऐसे होने चाहिए जिनके मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहते हों। यदि विनियोगों के मूल्यों में आक्समिक परिवर्तन होते हैं तो उसके कारण बैंक को काफी हानि हो सकती है। बैंक को विनियोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने विनियोग करो से मुक्त हो। बैंक को अपना धन केवल ऐसी प्रतिभूतियों, अंशों (Shares) आदि में लगाना चाहिए जो आय-कर तथा अन्य प्रकार के करो से मुक्त हों। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर तथा उनमें उचित सतुलन के द्वारा ही बैंक एक अच्छी विनियोग नीति का विकास कर सकता है।

बैंक विनियोग की मदें (Items of Bank Investment)—

बैंक के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विनियोगों का सक्षिप्त अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि ये विनियोग कहाँ तक उक्त-लिखित सिद्धान्तों के अनुसार हैं। बैंक अपने धन को दो प्रकार के विनियोगों में बाँटते हैं—(अ) लाभहीन विनियोग (Profitless Investments) तथा (ब) लाभ-पूर्ण विनियोग (Profitable Investments)। प्रत्येक बैंक को दोनों प्रकार के विनियोगों में ही अपनी पूँजी को बाँटना पड़ता है। बैंक अपनी पूँजी को लाभहीन विनियोगों में इसलिए लगाता है क्योंकि उनमें तरलता (Liquidity) का गुण पाया जाता है और नकद मुद्रा की अधिक मांग होने पर बैंक उनमें से अपना धन निकाल सकता है। किन्तु बैंक अपना समस्त धन लाभहीन विनियोगों में नहीं लगा सकता है। प्रत्येक बैंक का उद्देश्य अपने असाधारणों के लिए लाभ पैदा करना होता है और इसके लिए उसे अपनी पूँजी का कुछ भाग लाभपूर्ण विनियोगों (Profitable

Investments) में भी लगाना पड़ता है। बैंक किस अनुपात में अपना धन लाभहीन तथा लाभपूर्ण विनियोगों में बाँटता है इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है किन्तु उसे तरलता (Liquidity) तथा उत्पादकता (Profitability) को ध्यान में रखते हुए ही इन दोनों प्रकार के विनियोगों में अपनी पूँजी का बँटवारा करना चाहिए।

लाभहीन विनियोग (Profitless Investments) —

बैंक के लाभहीन विनियोग प्रायः (क) नकद कोष (Cash Reserve) तथा (ख) मृत स्तब्ध (Dead Stock) के रूप में रहते हैं —

(क) नकद कोष (Cash Reserve) — बैंकिंग व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकद कोषों का होना अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक के पास इतना नकद कोष अवश्य होना चाहिए कि वह किसी भी समय ग्राहकों के द्वारा स्तुत किये जाने वाले चेकों का भुगतान कर सके। यद्यपि बैंक की कुल जमा का रोड़ा-सा भाग ही नकद कोष के रूप में रखा जाता है किन्तु फिर भी यह नकद कोष बैंक के दैनिक व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रायः बैंक के ऊपर की जाने वाली मांग उसके द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली नकद जमा के द्वारा ही पूरी हो जाती है किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि किसी भी दिन नकदी की मांग उसकी प्राप्ति से अधिक हो जाय। इस प्रकार की प्राकृतिक मांग को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष होने चाहिए। कोई भी बैंक बहुत अधिक मात्रा में नकद कोष नहीं रख सकता है क्योंकि ऐसा करने से वह कम मात्रा में विनियोग कर सकेगा और उसका लाभ कम हो जायगा। नकद कोष बैंक की एक प्रकार की निष्क्रिय पूँजी है जिस पर उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है इसलिए बैंक कम से कम मात्रा में नकद कोष रखना चाहता है। किन्तु वह नकद कोष को न्यूनतम सुरक्षित सीमा से कम नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से उसकी साख के टूटने का भय रहता है। अतः बैंक न तो तरलता के उद्देश्य से बहुत अधिक नकद कोष ही रख सकता है और न लाभ की दृष्टि से उसे बहुत कम ही कर सकता है। उसे तरलता (Liquidity) तथा उत्पादकता (Profitability) दोनों में समतुल्य स्थापित करके नकद कोष का पर्याप्त अनुपात निश्चित करना होता है।

नकद कोष का निर्धारण करने वाली बातें

(Factors Determining Cash Reserve) —

नकद कोष को निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते हैं किन्तु फिर भी कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखकर ही बैंक

अपने नकद कोषों की मात्रा को निश्चित करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं—

(१) वैधानिक आवश्यकता (Legal Requirements)—कुछ एक देशों में बैंकों के द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष की न्यूनतम सीमा देश के बैंकिंग विधान के द्वारा निश्चित कर दी जाती है। अमेरिका में बैंकों को एक निश्चित न्यूनतम नकद कोष रखना पड़ता है। भारतवर्ष में भी बैंकों के द्वारा रखे जाने वाले नकद कोष की न्यूनतम सीमा रिजर्व बैंक एक्ट के अन्तर्गत निश्चित कर दी गई है। प्रत्येक बैंक को अपनी निश्चित जमा (Time Liabilities) का २% और चासू जमा (Demand Liabilities) का ५% प्रतिशत नकद कोष के रूप में रिजर्व बैंक में हर समय रखना होता है। जिन देशों में अधिनियम के द्वारा नकद कोष की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी गई वहाँ पर बैंकों को इस वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम इतना अधिक कोष धारण रखना पड़ता है जितना कि अधिनियम के द्वारा निश्चित किया गया है। यद्यपि व्यवहार में बैंक इससे अधिक अनुपात में नकद कोष रखते हैं।

(२) बैंक के व्यवसाय की प्रकृति (Character of Bank's Business)—नकद कोष की मात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि बैंक किस प्रकार का व्यवसाय करता है और उसकी पूँजी कौन से विनियोगों में लगी हुई है। यदि बैंक ने अपनी पूँजी का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य प्रकार के तरल आदेयों में लगाया हुआ है तो बैंक को कम मात्रा में नकद कोष की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह किसी समय नकदी की मांग को पूरा करने के लिए अपने आदेयों (Assets) का निस्तारण (Liquidate) कर सकता है। इसके विपरीत यदि बैंक ने अपनी पूँजी को दीर्घकालीन विनियोगों तथा अतरल आदेयों में लगाया हुआ है तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखना पड़ेगा।

(३) लोगों में बैंकिंग की आदत (Banking Habit among the People)—नकद कोष की मात्रा लोगों में बैंकिंग की आदत के ऊपर भी निर्भर होती है। यदि लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास हो गया है और अधिकांश भुगतान चैक्स (Cheques) आदि के द्वारा निबटाये जाते हैं तो बैंकों को कम नकद कोष रखना होता है। इसके विपरीत यदि अधिकांश भुगतान नकद रूप में निबटाये जाते हैं तो बैंकों के लिए अधिक नकद कोष रखना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि विकसित देशों में निरुद्धे हुए देशों की अपेक्षा बैंक कम अनुपात में नकद कोष रख कर ही अपना काम चला लेते हैं।

(४) निक्षेपों का आकार (Size of Deposits)—नकद कोष का अनुपात बैंक के ग्राहकों की संख्या तथा उनके निक्षेपों (Deposits) के आकार पर भी निर्भर होता है। ग्राहकों की संख्या जितनी कम होती है और उनकी जमा का आकार जितना

बड़ा होता है, बैंक को उतनी ही अधिक मात्रा में नकद कोष रखना पड़ता है। यदि बैंक के ग्राहकों की संख्या अधिक है किन्तु उन्होंने थोड़ी-थोड़ी रकम ही बैंक में जमा की हुई है तो बैंक कम नकद कोष से अपना काम चला लेगा क्योंकि वह नकदी की बहुत अधिक मांग की आशा नहीं कर सकता है। इसके विपरीत यदि बैंक के ग्राहकों की संख्या कम है किन्तु उनके निक्षेपों का आकार बड़ा है तो बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखना पड़ेगा।

(५) बैंकिंग व्यवसाय की नकद कोष नीति (Policy of other Banks)—

अन्य बैंक किस अनुपात में नकद कोष रखना उपयुक्त समझते हैं, इस बात का भी किसी बैंक के नकद कोष के आकार पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी बैंक अपने पड़ोसी बैंको से कम अनुपात में नकद कोष नहीं रख सकता है। यदि कोई बैंक, अपने साथी बैंको से कम अनुपात में नकद कोष रखना चाहता है तो ऐसी दशा में लोगों को उसकी स्थिरता के विषय में सन्देह हो जाता है और वह बैंक कठिनाई में पड़ सकता है।

(६) निकासी-गृहों की सुविधा (Clearance Facilities)—बैंको के लिए निकासी-गृह की सुविधा जितनी अधिक होती है बैंक उतने ही कम नकद कोष से अपना काम चला सकते हैं। सुव्यवस्थित निकासी की सुविधाओं होने से बैंको को अधिकांश बैंको का भुगतान नकद रूप में नहीं करना पड़ता है और उन्हें बैंको के आपसी लेन-देन के द्वारा ही निवृत्त दिया जाता है। इस प्रकार बैंक कम नकदी से ही अपना काम चला लेते हैं। किन्तु यदि निकासी की सुविधाओं कम हैं तो बैंको को अधिकांश बैंको का भुगतान नकद रूप में करना होता है जिसके लिए उन्हें अधिक नकद कोष रखना पड़ता है।

(७) व्यापारिक दशाएँ (Business Conditions)—प्राथमिक समृद्धि (Economic Prosperity) के काल में बैंको को कम नकद कोष रखना पड़ता है, क्योंकि व्यवसायिक आशावाद के कारण लोग नकद रूपों की अपेक्षा विनियोग को अधिक पसन्द करते हैं। इसके विपरीत अवसाद काल (Depression) में विनियोग की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग नकद रूप में अपनी जमा को रखना चाहते हैं और बैंको को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने होते हैं।

(८) मृत स्कन्ध (Dead Stock)—प्रत्येक बैंक को अपनी पूँजी का कुछ भाग मृत स्कन्ध के रूप में रखना पड़ता है जिससे बैंक को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता है। मृत स्कन्ध के अन्तर्गत बैंक की इमारत, फर्नीचर, फिटिंग्स तथा अन्य प्रकार के स्थिर आदेयों पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित होता है। बैंक को अपना कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही इस प्रकार के विनियोग में लगाई जाने वाली रकम को निश्चित करना होता है। बैंक के दैनिक व्यवसाय को चलाने के लिए इस प्रकार के आदेयों (Assets) का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन आदेयों को

मृत स्तब्ध (Dead Stock) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें लगी हुई पूँजी को आमानी से नहीं निकाला जा सकता है। केवल बैंक के चन्द हो जाने पर ही इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचा जा सकता है।

लाभपूर्ण विनियोग (Profitable Investments)—

बैंक के लाभ के मुख्य साधन उसके लाभपूर्ण विनियोग होते हैं। प्रत्येक बैंक अपनी पूँजी का अधिकांश भाग इस प्रकार के विनियोगों में लगाकर रखता है जिसमें कि उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त हो सके। बैंक के लाभपूर्ण विनियोगों में निम्न-लिखित प्रकार के विनियोग सम्मिलित होते हैं—

(१) याचना राशि तथा छल्प सूचनायं ऋण (Money at call or short notice)—ये बैंक के द्वारा दिये जाने वाले यदि छल्पकालीन ऋण होते हैं जो बिना नोटिस दिये अथवा अल्पकालीन नोटिस देकर ही वसूल किये जा सकते हैं। इस प्रकार के ऋणों की अवधि प्रायः एक सप्ताह से लेकर १५ रोज तक होती है। इन पर व्याज की दर भी बहुत कम होती है और २% तथा ३% के बीच में ही रहती है। कभी-कभी तो बैंक इस प्रकार के ऋणों को बिना सूचना दिये अथवा एक घण्टे का नोटिस देकर ही वापस ले सकता है। यदि ऋणी तुरन्त इनका भुगतान नहीं करता तो बैंक उसकी प्रतिभूतियों को बेचकर रकम वसूल कर लेता है। इस प्रकार के ऋण प्रायः बिल दलालों (Bill Brokers), डिस्काउन्ट गृहों (Discount Houses) तथा स्टॉक एक्चेंज के दलालों व ग्राहकों को दिये जाते हैं। बैंक इस प्रकार के ऋणों को बहुत अच्छा समझता है और तरलता (Liquidity) की दृष्टि से नकद कोष के पश्चात् इनका दूसरा स्थान होता है। एक प्रकार से, छल्प सूचनायं ऋण नकद कोष से भी अच्छे होते हैं क्योंकि बैंक को इनसे कुछ प्रायः प्राप्त होती है किन्तु नकद कोष से कोई आय प्राप्त नहीं होती है। इंग्लैंड आदि देशों में बैंकों के द्वारा इस प्रकार के ऋण काफी मात्रा में दिये जाते हैं किन्तु भारतवर्ष में डिस्काउन्ट गृहों (Discount Houses) तथा निर्गमन गृहों (Issue Houses) का विकास न होने के कारण इस प्रकार के ऋणों का प्रचलन कम है और एक बैंक केवल दूसरे बैंकों को ही याचना राशि (Money at call) के रूप में ऋण दे सकता है।

(२) बिलों का भुनाना (Discounting the Bills)—बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण विनियोग उनके द्वारा बिलों को खरीदना तथा भुनाना है। विनिमय-पत्र (Bill of Exchange) बैंक के सुरक्षित आदेय है क्योंकि उनमें स्वयं निस्तारण (Self Liquidation) की शक्ति होती है। जैसे ही बिल की अवधि समाप्त होती है वैसे ही उसका रुपया वाजिव हो जाता है। ये बिल प्रायः ६० से लेकर ९० दिन की अवधि के लिए होते हैं किन्तु आपत्ति बाल में इन्हे केन्द्रीय बैंक से दुबारा भुनाकर (Rediscounting) इससे पहले भी बैंक रुपया प्राप्त कर सकता है। इन बिलों के आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को ३ मास अथवा उससे कुछ कम अवधि के लिए

ऋण देता है। इस प्रकार के विनियोगों को बैंक अपनी सुरक्षा की तीसरी पक्ति (Third Line of Defence) समझते हैं। बैंक अपने बिल सम्बन्धी विनियोगों का प्रबन्ध कुछ इस प्रकार से करता है कि कुछ न कुछ बिल बराबर परिपक्व (Mature) होते रहे। बिलों को मुनाने के अतिरिक्त बैंक प्रथम श्रेणी के प्रतिज्ञा पत्रों (Promissory Notes) तथा कोषागार विपत्रों (Treasury Bills) का क्रय-विक्रय भी करते हैं। यद्यपि इस प्रकार के विनियोगों पर बैंक का कम व्याज मिलता है किन्तु उनमें सुरक्षा तथा विक्री साध्यता (Marketability) अधिक होने के कारण बैंक उन्हें काफी पसन्द करते हैं। भारतवर्ष में बिल बाजार का समुचित विकास न होने के कारण बैंकों के द्वारा बिल मुनाने तथा उन्हें खरीदने में अपनी जमा राशि का बहुत कम भाग ही लगाया जाता है जबकि विदेशों में बैंकों की जमा राशि का १०% से १५% तक इस प्रकार के विनियोगों में लगा रहना है। हमारे यहाँ केवल ५% या ६% ही इस कार्य में लगाया जाता है।

(३) प्रतिभूतियों तथा अन्य प्रकार के आदेयों में विनियोग (Investment in Securities and other Assets)—बैंक अपने धन का काफी बड़ा भाग सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों (Govt. Securities), ट्रेजरी बिल्स तथा बॉण्ड्स, कम्पनियों के अंशों तथा ऋण-पत्रों, सोना, च.दी आदि आदेयों में लगाकर रखते हैं। इस प्रकार के विनियोग बैंक की रक्षा की चौथी पक्ति (Fourth Line of Defence) घटताये जाते हैं। इस प्रकार के आदेयों (Assets) में बैंक की पूँजी सुरक्षित भी रहती है और उस पर सामान्य लाभ भी प्राप्त होता है। तरलता की दृष्टि से भी ये विनियोग अच्छे रहते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन्हें बेचकर अपनी रकम निकाल सकता है किन्तु ऐसा करने में बैंक को कुछ हानि हो सकती है। बैंक प्रायः सरकारी प्रतिभूतियों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके मूल्य में कम परिवर्तन होने हैं एवं उन्हें हर समय आसानी से बेचा जा सकता है। कम्पनियों के शेयर्स तथा ऋण-पत्रों में रुचि लगाना बैंक पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से नहीं बेचा जा सकता है। प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों (First Class Securities) में लगा हुआ धन स्वस्थ विनियोग (Sound Investment) समझा जाता है। इंग्लैंड के बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में अपनी जमा का ३०% लगाकर रखते हैं, भारतवर्ष में इन प्रकार के विनियोग जमा का ४०% तथा अमेरिका में ६०% होते हैं।

(४) ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances)—बैंक अपने धन का काफी बड़ा भाग अपने ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम के रूप में दिया करते हैं। ऋण देना बैंक का एक प्रमुख कार्य है और इस प्रकार के विनियोग में ही बैंक को अपनी आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। बैंकर्स के लिए ऋण तथा अग्रिम विशेष आकर्षण रखते हैं क्योंकि उन पर उन्हें ५% से लेकर ६% तक व्याज मिल जाता

है। यह बैंक का सबसे अधिक लाभपूर्ण विनियोग होता है और प्रत्येक बैंक इसमें अपना अधिक से अधिक धन लगाने का प्रयत्न करता है। प्रायः बैंक अपनी पूँजी का ६०% तक ऋण तथा अग्रिम के रूप में दे देने है। भारतीय बैंकों के सम्बन्ध में यह प्रतिशत ४०% से ५०% तक रहता है। यद्यपि लाभ की दृष्टि से इस प्रकार के विनियोग अच्छे होते हैं किन्तु उनमें तरलता (Liquidity) का गुण बहुत कम पाया जाता है। उक्त लिखित तीनों प्रकार के विनियोगों की तुलना में ऋण तथा अग्रिम सम्बन्धी विनियोग सबसे कम तरल होते हैं और उनमें लगे हुए धन को प्राप्तानी से नहीं निगाला जा सकता है। इसलिए बैंक को इन प्रकार के विनियोगों के सम्बन्ध में विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए।

बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रायः तीन प्रकार के हो सकते हैं— (i) साधारण ऋण, (ii) अधिविक्रय (Overdraft) तथा (iii) नकद-साख (Cash Credit)। साधारण ऋण देते समय बैंक ऋणी से उचित जमानत लेकर उसके हिसाब में ऋण की रकम को जमा कर देता है। ऋणी जब चाहे उस रकम को अपने खाने में से निकाल सकता है। इस प्रकार के ऋण केवल जमानत की भाँड़ पर ही दिये जाते हैं और ऋणी को पूरी रकम पर व्याज देना पड़ता है। साधारण ऋणों के अतिरिक्त बैंक अपने जमाधारियों को अधिविक्रय (Overdraft) की सुविधायें भी देता है। यह सुविधा केवल धातू खाते (Current Account) वाले ग्राहकों को ही दी जाती है। अधिविक्रय (Overdraft) के अन्तर्गत बैंक जमाकर्त्ता (Depositor) को अपने हिस्से में जमा रकम से अधिक निकालने का अधिकार दे देता है। अधिविक्रय प्रायः व्यक्तिगत जमानत (Personal Security) के आधार पर दिये जाते हैं और केवल अल्प काल के लिए ही दिये जाते हैं। ग्राहक आवश्यकता पड़ने पर उस सीमा तक अधिक रुपया निकाल सकता है। बैंक के द्वारा नकद साख (Cash Credit) के रूप में ऋण दिये जाने का तरीका काफी प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रकार के ऋण केवल जमानत के आधार पर ही दिये जाते हैं। जमानत तैयार नाल, प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रकार की वस्तु सम्पत्ति की होनी चाहिए। इन जमानतों की भाँड़ पर बैंक अपने ग्राहकों की साख की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर देता है और वे आवश्यकता पड़ने पर उन सीमा तक बैंक से रुपया निकाल सकते हैं। ऋणी को केवल उतनी ही रकम पर व्याज देना पड़ता है जितनी कि वह वास्तव में निकालता है।

विनियोग करने के सम्बन्ध में सावधानियाँ

(Precautions in Investing Funds)

बैंक की व्यावहारिक सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह अपने धन का विनियोग करते समय एक सुदृढ़ विनियोग नीति के सामान्य सिद्धान्तों का पालन कर्त्ता तक करता है। प्रत्येक बैंक को अपने विनियोग इस प्रकार करने चाहिए कि

वह विनियोगों की तरलता (Liquidity) और उत्पादकता (Productivity) में उचित समन्वय कर सके। विनियोग के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर बैंक यह निश्चित करता है कि उसे अपनी कुल रकम का कितना भाग लाभपूर्ण विनियोग (Profitable Investment) में लगाना है और कितना लाभहीन विनियोग (Profitless Investment) में रखना है। इसके पश्चात् बैंकर के लिए यह समस्या होती है कि वह विनियोग की जाने वाली रकम को किस प्रकार विभिन्न विनियोगों में वितरित करे। इसके विषय में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनलाया जा सकता है। प्रत्येक बैंक को अपनी विनियोग नीति का निर्माण अपनी परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए क्योंकि अलग-अलग बैंकों तथा उनके ग्राहकों की समस्याएँ अलग-अलग होती हैं। व्यक्तिगत बैंक अपने अनुभव के आधार पर स्वयं निश्चित कर सकता है कि उसे अपने ग्राहकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। किन्तु फिर भी प्रत्येक बैंक को अपने विनियोग की प्रकृति को निश्चित करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) सुरक्षा (Safety)—बैंकर को सर्वप्रथम अपनी रकम की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बैंक का व्यवसाय जोखिम उठाने का व्यवसाय नहीं है। अतः बैंक को अपना धन केवल सुरक्षित विनियोगों में ही लगाना चाहिए। बैंक क्योंकि हमारे लोगों के धन से व्यापार करता है इसलिए उसे जोखिम वाले विनियोगों में धन नहीं लगाना चाहिए। बैंक के विनियोग ऐसे होने चाहिए जिनमें से रुपये की वापसी की अधिक से अधिक सम्भावना हो।

(२) आदेयों की तरलता (Liquidity of Assets)—बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी पूँजी को अधिक से अधिक तरल रूप में रखे। अतः बैंकर को अपना धन ऐसी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिन्हें कम से कम समय में बाजार में बेचकर रुपया निकाला जा सके। बैंकर को रुपये का विनियोग करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि त्रिन प्रतिभूतियों में वह विनियोग कर रहा है उन्हें आसानी से किसी बड़ी हानि के बिना बाजार में बेचा जा सकता है अथवा नहीं। प्रतिभूतियों की विक्रयशीलता (Marketability) बैंकर के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका उसे सदैव ध्यान रखना चाहिए।

(३) प्रतिभूतियों के मूल्य की स्थिरता (Stability of Security Prices)—बैंकर को अपना धन केवल उन प्रतिभूतियों में ही लगाना चाहिए जिनका मूल्य सामान्यता स्थिर रहता हो। बैंक का उद्देश्य प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, वह केवल अपनी पूँजी पर ध्याज प्राप्त करना चाहता है। अतः बैंक का विनियोग ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाना चाहिए जिनके मूल्य में कम से कम परिवर्तन होते हों।

(४) ऋणों की उत्पादकता (Productivity of Loans)—बैंक के विनियोग ऐसे होने चाहिए जिनसे उसे अपनी पूँजी पर पर्याप्त एवं स्थिर रूप से धाय प्राप्त

होनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक को अपनी पूँजी का अधिकांश भाग उत्पादक विनियोगों में लगाना चाहिए। यद्यपि बैंक को अपने विनियोग से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए किन्तु फिर भी उसके विनियोगों का लाभपूर्ण होना आवश्यक है।

(५) जोखिम का अधिकाधिक फैलाव (Diversification of Risks)—बैंक को विनियोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पूँजी को विभिन्न प्रकार के विनियोगों में लगाये जिससे कि जोखिम का अधिकाधिक फैलाव हो सके। कभी भी बैंक को अपना धन एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए। कुछ थोड़े से व्यक्तियों को बड़े-बड़े ऋण देना बैंक के लिए खतरनाक हो सकता है। उसे विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये बहुत से लोगों को थोड़े-थोड़े ऋण देने चाहिए जिससे कि जोखिम को मात्रा कम से कम रहे।

(६) पर्याप्त मार्जिन (Adequate Margin)—बैंक को ऋण देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक ऋण के पीछे पर्याप्त मार्जिन (Margin) रखता जाय। बैंक की ऋण नीति ऐसी होनी चाहिए कि दिये जाने वाले ऋण की मात्रा प्रतिभूतियों के मूल्य से काफी कम रहे जिससे कि बैंक प्रतिभूतियों का मूल्य गिरने की दशा में हानि से बच सके। अतः प्रत्येक ऋण के पीछे काफी मार्जिन रखना आवश्यक है। प्रतिभूतियों के मूल्य में जितनी कम स्थिरता हो उन पर दिये जाने वाले ऋण में उतना ही अधिक मार्जिन (Margin) होना चाहिए। बैंक प्रायः १०% से लेकर ३०% तक का मार्जिन रखकर ऋण देते हैं जिसका उद्देश्य बैंक को आकस्मिक हानि से बचाना होता है।

(७) ऋण की उचित मात्रा—बैंक के लिए ऋण की मात्रा का उचित निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। ऋणों की मात्रा का बैंक के नकद कोष के साथ उचित अनुपात होना चाहिए। किसी बैंक को न तो बहुत अधिक मात्रा में ऋण देने चाहिए और न बहुत कम मात्रा में। बैंक को कभी भी सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में ऋण नहीं देने चाहिए। यदि ऋणों की मात्रा नकद कोष के अनुपात में बहुत अधिक हो जाती है तो बैंक के फेल होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बैंक को कभी भी लाभ के लालच में आकर बहुत अधिक मात्रा में ऋण नहीं देने चाहिए। इसके विपरीत बैंक को ऋणों की मात्रा बहुत कम भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अतः बैंक के ऋणों का उसके नकद कोष के साथ उचित अनुपात होना चाहिए।

एक व्यापारिक बैंक का चिट्ठा

(Balance Sheet of a Commercial Bank)

व्यापारिक बैंक की आर्थिक स्थिति का ज्ञान उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक चिट्ठे से होता है। बैंक का चिट्ठा अन्य व्यवसायिक संस्थाओं के चिट्ठे

की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बैंक दूसरों के रूपों से व्यापार करता है इसलिए समस्त समाज उसकी आर्थिक स्थिरता के बारे में जानना चाहता है। वार्षिक चिट्ठा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बैंक की आर्थिक स्थिति, उसकी तरलता (Liquidity) तथा शोधन क्षमता (Solvency) के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बैंक का चिट्ठा उसकी देनदारी तथा लेनदारी का पूरा विवरण होता है। उसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि बैंक किस प्रकार अपने साधनों को एकत्रित करता है और कैसे उनका विनियोग करता है। उससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि बैंक के पास कितनी सम्पत्ति है और उसके आदेय (Assets) किस प्रकार के हैं तथा बैंक की देनदारी कितनी है और उसके विभिन्न रूप क्या हैं। चिट्ठे का विश्लेषण करके हम बैंक की विनियोग नीति तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दो विभिन्न वर्षों के चिट्ठों की तुलना करके हम यह पता लगा सकते हैं कि पहले की अपेक्षा बैंक के साधनों में कितनी वृद्धि हुई तथा बैंक ने अपनी विनियोग सम्बन्धी नीति में किन दिशाओं में परिवर्तन किया है। अतः किसी भी बैंक का वार्षिक चिट्ठा अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। उसके आधार पर ही जनता का विश्वास बैंक की स्थिरता में स्थापित होता है। अध्ययन के लिए हम एक बैंक का निम्नलिखित काल्पनिक चिट्ठा (Balance Sheet) ले सकते हैं—

बैंक के चिट्ठे का नमूना
(Specimen of Bank Balance Sheet)

देनदारी (Liabilities)	रकम	आदेय (Assets)	रकम
(१) परिदत्त पूँजी (Paid up Capital)	...	(१) नकदी (Cash)	...
(२) संचित कोष तथा अन्य जमा (Reserves and other Accounts)	...	(२) अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के पास जमा (Cash at other Banks including the Central Bank)	...
(३) जमानत तथा अन्य खाते (Deposits and other Funds)		(३) याचना राशि तथा अल्प सूचनार्थ ऋण (Money at call and short notice)	...
(i) निश्चित जमा (Fixed Deposits)			

(ii) चालू जमा (Demand Deposits)			
(iii) बचत जमा (Savings Deposits)			
(४) अन्य बैंकों के ऋण (Balances of other Banks)	...	(४) मुनाये गये बिल (Bills Discounted)	...
(५) शोषनीय बिल (Bills Payable)	...	(५) ऋण तथा प्रग्निय (Loans & Advances)	...
(६) ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ (Acceptances and Endorsements)	...	(६) प्रतिभूतियों में विनियोग (Investment in Securities)	...
(७) अन्य देनदारी (Other Liabilities)	...	(७) वसूली के लिए प्राप्त बिल (Bills Acquired for Collection)	...
(८) लाभ तथा हानि खाता (Profit & Loss A/c)	...	(८) इमारत, फर्नीचर तथा अन्य सामान (Dead Stock and Premises)	...
		(९) अन्य आदेय (Other Assets)	...
योग (Total)	...	योग (Total)	...

विभिन्न बैंक अपने चिट्ठे विभिन्न प्रकार से बनाते हैं और उनमें एकरूपता नहीं पाई जाती है किन्तु ऊपर दिया गया चिट्ठा एक सामान्य प्रकार के बैंक के चिट्ठे का उदाहरण है और इसके विश्लेषण के द्वारा हम एक बैंक की देनदारी (Liabilities) तथा आदेय (Assets) का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक के चिट्ठे के विश्लेषण (Analysis of Balance Sheet)—

प्रत्येक चिट्ठा (Balance Sheet) के दो भाग होते हैं—देनदारी (Liabilities) तथा आदेय (Assets)। बाईं ओर बैंक की देनदारी का विवरण होता है जिसमें वे सब मदें दिखाई जाती हैं जिनके सम्बन्ध में बैंक को अन्य लोगों को मुफ्तान देना होता है और दाईं ओर बैंक के आदेय (Assets) होते हैं, जो उसकी लेनदारी को बताते हैं। इन दोनों मदों का योग भन्त में बराबर हो जाता है और तब बँलन्स शीट सन्तुलित होता है। बैंक के चिट्ठे को ठीक-ठीक समझने के लिए हमें उसके दोनों भागों की मुख्य-मुख्य मदों का एक-एक करके अध्ययन करना चाहिए।

देनदारी (Liabilities Side)—बैंक की देनदारी की प्रमुख भेदें निम्न-लिखित होती हैं—

(१) **बैंक की पूँजी (Capital)**—पूँजी के अन्तर्गत वह रकम शामिल होती है जो बैंक को अपने हिस्से (Shares) बेचने से प्राप्त होती है। यह हिस्सेदारों (Shareholders) की रकम बैंक के जिम्मे बाजिव होती है। प्रत्येक बैंक की स्थापना से पूर्व उसके स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) में निश्चित कर दिया जाता है कि वह अधिक से अधिक कितनी पूँजी अपने हिस्से बेचकर प्राप्त कर सकता है। यह बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) कहलाती है। अधिकृत पूँजी के कुछ भाग के अंश (Shares) ही बेचने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। बैंक जितनी रकम के हिस्से बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है वह बैंक की निर्गमित पूँजी (Issued Capital) होती है। वास्तव में जितनी रकम के हिस्से लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं उसे प्राधिक पूँजी (Subscribed Capital) कहा जाता है। प्राधिक पूँजी का जितना भाग अशायरियों के द्वारा वास्तव में जुगतान किया जाता है, उसे चुकता पूँजी (Paid up Capital) कहते हैं। प्रायः हिस्से (Shares) के ५० प्रतिशत मूल्य को ही मांगा जाता है और शेष बैंक किसी भी समय अशायरियों से ले सकता है। ऐसा करने से बैंक के जमाकर्त्ताओं (Depositors) तथा ऋणदाताओं (Creditors) में बैंक के प्रति अधिक विश्वास हो जाता है क्योंकि बैंक के पास काफी मात्रा में अनएकत्रित (Unpaid) पूँजी रहती है जिसे वह सकट कास में अपनी देनदारी को निबटाने के लिए प्रयोग कर सकता है।

(२) **सुरक्षित कोष (Reserve Fund)**—प्रत्येक बैंक के पास कुछ न कुछ सुरक्षित कोष अवश्य रहता है। इस कोष का निर्माण बैंक के अतिरिक्त लाभ के द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग आपत्ति काल में आकस्मिक हानि को पूरा करने तथा प्रति वर्ष दिये जाने वाले लाभ को समान रखने के लिए किया जाता है। यह रकम भी एक प्रकार से हिस्सेदारों की बैंक के जिम्मे बाजिव होती है। भारतवर्ष में बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम (Banking Companies Act) के अन्तर्गत बैंकों को अपने लाभ का २० प्रतिशत अनिवार्य रूप से संचित कोष में रखना पड़ता है।

(३) **जमा धन (Deposits)**—बैंक की मुख्य देनदारी उसे प्राप्त होने वाले जमा धन के कारण उत्पन्न होती है। यह देनदारी बैंक के जमाकर्त्ताओं के प्रति होती है। प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों से चालू जमा (Current Deposit), निश्चित जमा (Fixed Deposit) तथा बचत जमा (Savings Deposit) के रूप में धन प्राप्त करता है। बैंक के जमा धन का बहुत बड़ा भाग किसी भी समय माग किये जाने पर निकाला जा सकता है इसलिए बैंक इस धन का विनियोग बड़ी सावधानी

से करना है। इस जमा का कुछ भाग नकद कोष (Cash Reserve) के रूप में रखा जाता है और शेष को उधार दे दिया जाता है अथवा उसका विनियोग कर दिया जाता है। जमा धन का बहुत अधिक भाग विनियोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि बैंक को अपने जमाधारियों (Depositors) की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है।

(४) अन्य बैंकों के ऋण (Balances of other Banks)—बैंक के ऊपर जो धन दूसरे बैंकों का याजिव होता है उसे इस मद के अन्तर्गत दिखलाया जाता है। अपने दैनिक कार्य को चलाने के लिए तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है जिनके भुगतान का उत्तरदायित्व बैंक का होता है।

(५) शोपनीय बिल (Bills Payable)—जिन बिलों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व बैंक ने अपने ऊपर ले लिया है, उनकी रकम को जोड़कर इस मद में दिखलाया जाता है। यह भी बैंक की देनदारी होती है क्योंकि बैंक को इन बिलों का भुगतान करना होता है।

(६) ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ (Acceptances & Endorsements)—बैंक कुछ बिलों को अपने ग्राहकों के लिए स्वीकार करता है जिनके भुगतान की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ले लेता है। बैंक के द्वारा इस प्रकार स्वीकार किये गए बिलों की रकम को इस मद (Item) में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों से जो बहुत से साख-पत्र वसूली (Collection) के लिए स्वीकार करता है, उनकी रकम भी इसी मद में सम्मिलित कर दी जाती है। इस प्रकार के साख-पत्रों की रकम वसूली के पश्चात् ग्राहकों के हिसाब में जमा कर दी जाती है, जिसे वे जय चाहें निकाल सकते हैं।

बैंक के आदेय (Assets of the Bank)—

आदेय वाले भाग में उन सब मदों को दिखलाया जाता है जिनके लिए बैंक को भुगतान प्राप्त करने होते हैं। किसी बैंक के आदेयों का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि बैंक ने अपने धन को किस प्रकार के विनियोगों में लगाया हुआ है। इससे यह भी जाना जा सकता है कि बैंक ने अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए कितनी नकद मुद्रा अपने पास रखी है तथा कितनी रकम का विनियोग तरल सम्पत्ति में किया हुआ है। आदेय वाले भाग में प्रायः निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती हैं—

(१) नकदी (Cash)—बैंक को अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए अपने पास कुछ नकद मुद्रा अवश्य रखनी होती है। यद्यपि बैंक के द्वारा रखी जाने वाली नकदी उसकी पूँजी का बहुत छोटा भाग होता है किन्तु फिर भी प्रत्येक बैंक को अपने पास इतनी नकदी अवश्य रखनी चाहिए जिससे कि वह प्रस्तुत किये

जाने वाले समस्त बैंकों का भुगतान कर सके। बैंक कितनी नकदी अपने पास रखते हैं, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रत्येक बैंक अपने अनुभव के आधार पर तथा अपने व्यवसाय की प्रकृति व ग्राहकों की आदतों के अनुसार नकद कोष की मात्रा को निश्चित करता है। इंग्लैंड के बैंक प्रायः अपनी जमा का ६ या १० प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं, किन्तु भारतवर्ष के बैंकों की नकदी का अनुपात १० से १३ प्रतिशत तक होता है। किसी समय बैंक के पास जितनी नकद मुद्रा होती है उसे हम इस मद में दिखलाते हैं।

(२) अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के पास जमा (Cash at other Banks including the Central Bank)—बैंक की अन्य बैंकों के पास जमा तथा केन्द्रीय बैंक के पास रखी जाने वाली जमा को इस मद के अन्तर्गत दिखलाया जाता है। प्रत्येक बैंक अपनी जमा का कुछ भाग केन्द्रीय बैंक के पास रखता है। कुछ देशों में इस जमा का न्यूनतम अनुपात सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। भारतवर्ष में बैंकों को अपनी चालू जमा (Demand Deposit) का ५% तथा निश्चित जमा (Time Deposit) का ३% अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है।

(३) पाचना राशि तथा छल्प सूचनार्थ ऋण (Money at Call and Short Notice)—इनके अन्तर्गत बैंक के द्वारा दिये जाने वाले वे छल्पकालीन ऋण सम्मिलित होते हैं जिन्हें बैंक बिना नोटिस दिये अथवा थोड़े समय का नोटिस देकर वापस माग सकते हैं। इस प्रकार के ऋण प्रायः अन्य बैंकों, डिस्काउंट गृहों (Discount Houses) तथा बिलों के दलालों (Bill Brokers) आदि को दिये जाते हैं।

(४) भुनाये गए बिलों में विनियोग (Bills Discounted)—बैंक के द्वारा भुनाये गये अथवा खरीदे गये बिलों (Bills) की कुल रकम को हम इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखलाते हैं। प्रायः बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों तथा ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bills) को ही भुनाता है। इस प्रकार के विनियोगों में भारतीय बैंक अपनी कार्यशील पूँजी (Working Capital) का केवल २ या ३ प्रतिशत ही लगाते हैं जबकि अन्य देशों में यह प्रतिशत १५ से लेकर ३० प्रतिशत तक होता है।

(५) ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances)—इसके अन्तर्गत वे ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं जो बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को समय-समय पर दिये जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों पर बैंक को अपेक्षाकृत कुछ ऊँचा ब्याज मिल जाता है। बैंक के द्वारा दिये जाने वाले साधारण ऋण, अधि-विकर्ष (Over-draft) तथा नकद साख (Cash Credit) आदि इसी मद में सम्मिलित किये जाते हैं।

विनियोग (Investments)—सरकारी प्रतिभूतियों (Govt. Securities), अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों (Semi-Govt. Securities), कम्पनियों के हिस्सों तथा

ऋण-पत्रों (Shares and Debentures) आदि में किया हुआ विनियोग इस मद में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक बैंक अपनी जमा का काफी बड़ा भाग इस प्रकार विनियोग में लगाना चाहता है, क्योंकि इन विनियोगों से उसे लाभ प्राप्त होता है। किन्तु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रकार के विनियोगों में तरलता का अभाव रहता है इसलिए बैंक इनके सम्बन्ध में विशेष सावधानी से काम लेता है।

(७) बैंक की इमारत, फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्ति (Premises, Furniture and Fittings)—बैंक के द्वारा अचल सम्पत्ति में किया हुआ विनियोग इस मद के अन्तर्गत दिखलाया जाता है। प्रत्येक बैंक को अपना दैनिक कार्य चलाने के लिए कार्यालय की इमारत, फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अचल सम्पत्ति में लगाये हुए धन से बैंक को किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है किन्तु यह बैंक के आदेयों का ही भाग होता है।

इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग (Unit Banking & Branch Banking)

विभिन्न देशों की बैंकिंग व्यवस्था में वहाँ की आर्थिक तथा राजनैतिक दशाओं के अनुसार काफी भिन्नता पाई जाती है। बैंकों का संगठन तथा उनके कार्य भलग-भलग देशों में भलग-भलग प्रकार के हो सकते हैं। साधारणतया व्यापारिक बैंकों की व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है—(अ) शाखा बैंकिंग (Branch Banking) तथा (ब) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)। दोनों प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाओं में से कौनसी अच्छी है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है किन्तु अनुभव के आधार पर यह कहा जाता है कि शाखा बैंकिंग इकाई बैंकिंग की अपेक्षा अधिक हठ तथा मितव्ययितापूर्ण होती है। इसलिए अधिकांश देशों में बैंकिंग व्यवस्था का निर्माण शाखा बैंकिंग के आधार पर किया गया है। यद्यपि इकाई बैंकिंग में भी कुछ गुण पाये जाते हैं किन्तु उसमें उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है और केवल कुछ एक देशों में ही इकाई बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है। भारतवर्ष में भी बैंकिंग का विकास शाखा बैंकिंग के आधार पर ही हुआ है।

शाखा बैंकिंग व्यवस्था उस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यवसायिक बैंक की बहुत सी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में अथवा एक बहुत बड़े भाग में फैली होती हैं। इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग व्यवसाय का विवेन्द्रीयकरण कर दिया जाता है और वह बैंकों की विभिन्न शाखाओं पर फैला रहता है, इसलिए कुछ लेखकों ने इसे विवेन्द्रित बैंकिंग व्यवस्था भी कहा है। शाखा बैंकिंग का सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड में मिलता है। जहाँ पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक की बहुत सी शाखाएँ समस्त देश में फैली हुई हैं। आरम्भ में इंग्लैंड के बैंकों

के भी एक या कुछ एक कार्यालय होते थे किन्तु धीरे-धीरे विकास तथा बैंकों के एकीकरण के कारण वहाँ पर कुछ एक बड़े-बड़े बैंक स्थापित हो गये हैं जिनकी शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं। इस समय इंग्लैंड में बैंकों की संख्या बहुत कम है और उनमें से पाँच बड़े बैंक (मिडलैंड लाइड्स, बर्कले, वेस्टमिनिस्टर तथा नेशनल प्रोविडन्शियल अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन पाँच बड़े बैंकों की ६५०० शाखाएँ हैं जो इंग्लैंड के ७५% बैंकिंग व्यवसाय को अपने अधिकार में लिए हुए हैं। यह सब बैंक, बैंक आफ इंग्लैंड के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इंग्लैंड के अतिरिक्त भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली ही पाई जाती है।

शाखा बैंकिंग के लाभ (Advantages of Branch Banking)—

शाखा बैंकिंग के समर्थकों ने इस प्रकार की व्यवस्था के बहुत से लाभ बतलाये हैं। सेयर्स (Sayers) के अनुसार शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग की तुलना, बड़े पैमाने के व्यवसाय तथा छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना के समान है। शाखा बैंकिंग को बड़े पैमाने का व्यवसाय होने के कारण बहुत से ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जो इकाई बैंकिंग को उपलब्ध नहीं हैं। शाखा बैंकिंग के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं—

(१) शाखा बैंकिंग को बड़े आकार के व्यवसाय तथा श्रम-विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं—शाखा बैंकिंग का संगठन बड़े पैमाने के उद्योग की भाँति होता है जिसमें श्रम-विभाजन के द्वारा अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। बैंकों के मुख्य कार्यालयों में काम को विभिन्न विभागों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्ति रखे जाते हैं जो अपने विभागों का कार्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से करते हैं। इस प्रकार के विशिष्टीकरण से बैंकों की कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार का विशिष्टीकरण तथा श्रम-विभाजन इकाई बैंकिंग व्यवस्था में सम्भव नहीं होता है इसके अतिरिक्त शाखा बैंकिंग में बैंकों का आकार बड़े होने के कारण उनके पास पूँजी अधिक मात्रा में होती है और वे अपना कार्य चलाने के लिए कुशल प्रबन्धकों तथा विशेषज्ञों को ऊँची तनख्वाह पर रख सकते हैं। इन सब सुविधाओं के प्राप्त होने के कारण शाखा बैंकिंग की कार्य-कुशलता इकाई बैंकिंग की अपेक्षा अधिक होती है।

(२) शाखा बैंकिंग श्रुतों के विविधिकरण (Diversification) को सम्भव करता है जिससे जोखिम को विभिन्न उद्योगों तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैला दिया जाता है। इकाई बैंकिंग में बैंक का भविष्य केवल एक क्षेत्र या कुछ उद्योगों की समृद्धि पर निर्भर होता है और यदि किसी कारणवश उस क्षेत्र की समृद्धि में गिरावट आती है तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंकों को काफी हानि उठानी पड़ सकती है। इसी प्रकार यदि उन उद्योगों के भात की माँग कम हो जाती है तब भी कि इन बैंकों ने अपना रूपरा लगाया हुआ है तो बैंकों को बहुत नुकसान होता है।

किन्तु शाखा बैंकिंग में यह खतरा बहुत कम हो जाता है क्योंकि बैंकों की शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं और इनका खर्चा भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगा रहता है। यदि एक उद्योग में या किसी विशेष क्षेत्र में हानि होती है तो उसे दूसरे क्षेत्रों तथा अन्य उद्योगों से होने वाले लाभ के द्वारा पूरा कर लिया जाता है और इस प्रकार बैंकों में अधिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यदि मन्दी का प्रभाव देश के तमाम उद्योगों पर एक साथ पड़ता है तब शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग के बीच छोटने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है।

(३) शाखा बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों की अपेक्षाकृत कम कोष रखने पड़ते हैं—यद्यपि बैंकों के द्वारा पर्याप्त कोषों का रक्त्ता जाना आवश्यक है किन्तु फिर भी यह कोष जिनकी कम मात्रा में हो उतना ही बैंकों को लाभ रहता है। शाखा बैंकिंग में कोषों की मात्रा को कम रक्त्ता जा सकता है क्योंकि बैंक की बहुत सी शाखाएँ होती हैं और उनमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कोष रखकर ही काम चल जाता है। यदि किसी शाखा पर अधिक कोष की आवश्यकता होती है तो अन्य शाखाओं से नकदी भगा कर उस भाग को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार शाखा बैंकिंग में कोषों की काफी वृद्धि होती है जिसके कारण बैंकों की शाख निर्माण करने की शक्ति में वृद्धि होती है। इकाई बैंकों को इस प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उन्हें अपने ही कौषों पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है।

(४) इस प्रकार की व्यवस्था में मुद्रा का हस्तान्तरण सस्ता तथा सुगमता-पूर्वक हो जाता है। शाखा बैंकिंग में बैंकों की बहुत सी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं जिनके कारण यह बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य कम से कम असुविधा के साथ कर लेते हैं और खर्च भी कम होता है। मुद्रा के सस्ते तथा सीधे हस्तान्तरण से व्यापार का विस्तार होता है तथा देश के विभिन्न भागों में पूँजी पर दिये जाने वाले व्याज की दर एक रहने की प्रवृत्ति रखती है। एक क्षेत्र का अतिरिक्त धन दूसरे क्षेत्रों की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तान्तरित कर दिया जाता है जिसके कारण वहाँ पर व्याज की दर में वृद्धि नहीं हो पाती है।

(५) शाखा बैंकिंग होने से देश के विभिन्न भागों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्ध किया जा सकता है—बैंकों की शाखाएँ समस्त देश में फैली होती हैं जिसके कारण सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होता है जिससे उद्योग तथा व्यवसाय के विकास में बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपरीत इकाई बैंकों का कार्य-क्षेत्र सीमित रहता है और केवल कुछ एक क्षेत्रों में ही वे अपना कार्य करते हैं जिसके कारण बहुत से क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जिनमें बैंकिंग सेवाओं का विस्तार नहीं हो पाता है। अतः देश के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विकास करने के लिए इकाई बैंकिंग की अपेक्षा शाखा बैंकिंग अधिक उपयुक्त है।

(६) बैंकों के फेल होने की सम्भावना कम हो जाती है—अमरीका का अनुभव इस बात को बतलाता है कि वहाँ पर विदेशी शाखा बैंकिंग सगठनों में बहुत कम बैंक फेल होते हैं जबकि उनके अपने इकाई बैंकिंग व्यवस्था के हजारों बैंक अपना काम बन्द करते रहते हैं। इस प्रकार का अनुभव शाखा बैंकिंग में अधिक सुरक्षा होने का प्रमाण है।

शाखा बैंकिंग के दोष (Defects of Branch Banking)—

यद्यपि शाखा बैंकिंग व्यवस्था को बड़े आकार के व्यवसाय के लाभ प्राप्त होने हैं किन्तु उसके साथ ही इस प्रकार की व्यवस्था में वे सभी दोष पाये जाते हैं जो किसी व्यवसाय को बड़े पैमाने पर चलाने में हुआ करते हैं। इसके विपरीत इकाई बैंकिंग में छोटे आकार के व्यवसाय के सभी लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। शाखा बैंकिंग के कुछ दोष निम्न प्रकार हैं जिनके आधार पर इस प्रकार के बैंकिंग का विरोध किया जाता है।

(१) इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों के सभी दोष पाये जाते हैं। बैंकों का आकार इतना बड़ जाता है कि उनका उचित प्रबन्ध करना सम्भव नहीं होता है। विशाल सगठन होने के कारण प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मुख्य कार्यालय तथा बड़े-बड़े केन्द्रों वाली शाखाओं का प्रबन्ध तो ठीक प्रकार चलाया जाता है किन्तु अन्य शाखाओं के प्रबन्ध में अकुशलता रहती है। उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता है। प्रत्येक शाखा को मुख्य कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है और वह अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकती है। कई बार मुख्य कार्यालय से प्रादेश प्राप्त करने में इतनी देर लग जाती है कि उसमें शाखाओं की कार्यक्षमता कम हो जाती है।

(२) शाखा व्यवस्था में किसी क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि तमाम बैंकिंग व्यवस्था व्यक्तिगत हो जाती है। यद्यपि शाखा मैनेजर स्थानीय व्यापारियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं किन्तु वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बैंक के सामान्य नियमों के अनुसार चलना होता है और मुख्य कार्यालयों के प्रादेशों को पूरी तरह पालन करना पड़ता है। इस प्रकार बैंकों की कार्य-प्रणाली बेलोच हो जाती है और उसे स्थानीय आवश्यकताओं तथा दशाओं के अनुकूल नहीं किया जा सकता है। इन बैंकों को व्यक्तिगत सम्पर्क के लाभ बहुत कम प्राप्त होते हैं।

(३) शाखा प्रणाली के अन्तर्गत छोटे केन्द्रों से रुपया एकत्रित करके बड़े-बड़े केन्द्रों में भेज दिया जाता है जिसके कारण छोटे केन्द्रों का विकास रुक जाता है। इन बैंकों के संचालक बड़ी-बड़ी समस्याओं को ध्यान देना पसन्द करते हैं और अर्थों की छोटी माँगों को पूरा नहीं किया जाता है। छोटे-छोटे केन्द्रों का रुपया उनके विकास

के लिए प्रयोग में नहीं आता है बल्कि वह अधिक विकसित केन्द्रों को चला जाता है। इकाई बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है और यह बैंक जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।

(४) एक बड़े बैंक के फैल होने से छोटे बैंक के फैल होने की अपेक्षा बहुत अधिक बर्बादी होती है। जब कोई बहुत सी शाखाओं वाला बड़ा बैंक फैल होता है तो उससे बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं और बैंकों के प्रति जनता के विश्वास को काफी नुकसान पहुँचता है। इसके विपरीत जब कोई छोटा तथा अप्रचलित बैंक फैल होता है तो इसका बुरा प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र अथवा कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है।

(५) शाखा बैंकिंग अधिक व्यवस्थित है—प्रत्येक नई शाखा के खुलने पर बैंक का प्रबन्ध तथा संचालन सम्बन्धित व्यय बँट जाता है। यदि शाखाएँ ऐसे स्थान पर खोली जाती हैं जहाँ पर बैंकिंग सेवाओं की माग अपर्याप्त है तो इन शाखाओं की स्थापना पर किया जाने वाला व्यय उनमें प्राप्त होने वाली आय से अधिक हो जाता है। यदि बैंक नई शाखाओं के विस्तार सम्बन्धी उचित नीति नहीं अपनाता है तो उसके व्यय में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली अप्रव्ययपूर्ण भी है क्योंकि उसमें बैंकिंग सेवाओं का दुहराव (Duplication) हो जाता है। एक ही केन्द्र में विभिन्न बैंकों की शाखाएँ स्थापित कर लानी हैं जिससे इनमें आपसी प्रतियोगिता बढ़ती है तथा अप्रव्यय भी होता है।

इकाई बैंकिंग

(Unit Banking)

इकाई बैंकिंग उस बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिसमें बैंक का व्यवसाय केवल एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है और उसकी कोई शाखाएँ नहीं होती हैं। किन्तु कभी-कभी इस प्रकार के बैंकों की सीमित क्षेत्र में कुछ शाखाएँ भी सीमित हो सकती हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि एक बैंक व प्रारम्भ स्थानीय समाज द्वारा किया जाना चाहिए और उसका स्वामित्व भी उस के पास रहना चाहिए। इकाई बैंक छोटी बैंकिंग कम्पनियाँ होती हैं जो घास-पास के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा कृषकों के साथ अपना बैंकिंग व्यवसाय करती हैं घन के हस्तान्तरण को सुविधाओं के लिए विभिन्न बैंक आपस में सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं। केंट (Kent) के अनुसार "इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था एक प्रथम निगम होती है जिसका प्रथम पूँजीकरण होता है जो जिसकी स्वयं की अपनी पूँजी, संचालक मण्डल तथा अंशधारी होते हैं।"¹

1 "In a unit banking system each local banking institution is a separate corporation, separately chartered and having its own capital board of directors and shareholders."

प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था अधिकांश रूप से अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका में हजारों बैंक ऐसे हैं जिनका केवल एक ही कार्यालय है और जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने बैंकों के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न किया है। यद्यपि इकाई बैंकिंग से कुछ निश्चित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं किन्तु फिर भी वह शाखा बैंकिंग की अपेक्षा कम लाभपूर्ण समझी जाती है। इकाई बैंकिंग से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं—

इकाई बैंकिंग के लाभ (Advantages of Unit Banking)—

(१) व्यक्तिगत प्रबन्ध एवं निरीक्षण—इकाई बैंकिंग में बैंको का आकार छोटा रहता है जिसके कारण व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा निरीक्षण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बैंकर अपने ग्राहकों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित कर सकता है और उनकी आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से देख सकता है। इस प्रकार के बैंको और उनके ग्राहकों में अधिक निष्ठा तथा व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है।

(२) स्थानीय हितों का विशेष ध्यान—इकाई बैंक प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसलिए वे उस क्षेत्र के विषय में अधिक जानकारी रखते हैं। इस प्रकार के बैंकों का प्रबन्ध भी प्रायः स्थानीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हाथ में रहता है। ऐसी अवस्था में इन बैंको के द्वारा स्थानीय कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक क्षेत्र के साधन उसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं और उन्हें अन्य क्षेत्रों के लाभ के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जाता है।

(३) अधिक कार्यकुशलता—इस प्रकार के बैंको का कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण इनकी कार्यकुशलता अधिक होती है। मैनेजर बैंक के संचालन में व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर सकता है जिसके कारण बैंक का कार्य शीघ्र होता है और नौकरशाही (Bureaucracy) तथा दीर्घ सूत्रता (Red Tapism) के दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। शाखा बैंकिंग में बैंक की शाखा के मैनेजर को महत्वपूर्ण मामलों में प्रधान कार्यालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है किन्तु इकाई बैंकिंग में इसकी आवश्यकता नहीं होती है और निर्णय स्थानीय होते हैं।

(४) स्वतन्त्र व्यवसाय (Free Enterprise) सिद्धान्त के अनुकूल—इकाई बैंकिंग स्वतन्त्र व्यवसाय सिद्धान्त के अनुकूल है इसीलिए अमेरिका में इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवसाय को पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है।

(५) एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध—इकाई बैंकिंग की व्यवस्था में बैंको की एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लग जाता है। बैंको की सत्ता अधिक होने के कारण वे मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार का एकाधिकार

स्थापित नहीं कर पाते हैं। शाखा बैंकिंग में कुछ बड़े बैंक देश के मुद्रा बाजार तथा अर्थ-व्यवस्था पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं जिससे हानि की सम्भावना रहती है किन्तु इकाई बैंकिंग में किसी प्रकार का एकाधिकार सम्भव नहीं है। इसीलिए हम प्रणाली को विकेंद्रित बैंकिंग व्यवस्था भी कहा जाता है।

(६) अकुशल बैंक समाप्त हो जाते हैं—शाखा बैंकिंग में यह सम्भव हो सकता है कि अकुशल शाखाएँ कुशल शाखाओं के ऊपर जीवित रहे और इस प्रकार अकुशल बैंक भी चलते रहते हैं किन्तु इकाई बैंकिंग में यह सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक बैंक को अपनी कार्यक्षमता के आधार पर ही जीवित रहना पड़ता है। ऐसी दशा में अकुशल बैंक स्वयं बन्द हो जाते हैं और केवल कुशल बैंक ही कार्य क्षेत्र में रहते हैं।

इकाई बैंकिंग के दोष (Disadvantages of Unit Banking)—

इन लाभों के होते हुए भी इकाई बैंकिंग व्यवस्था को आजकल पसन्द नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण यह वर्तमान समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इन दोषों के कारण ही अमेरिका में भी बैंकों के पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव हुई और इकाई बैंकिंग के स्थान पर धीरे-धीरे बड़े आकार के बैंक बनते जा रहे हैं। इकाई बैंकिंग के कुछ दोष निम्नलिखित हैं—

(१) बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं—इकाई बैंकिंग व्यवस्था में बैंको या आकार इतना छोटा होता है कि बड़े पैमाने पर काम करने से मिलने वाली आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है, व्यवसाय का आकार छोटा होने के कारण प्रबंध तथा कार्य-विधि में सुधार करने की सम्भावना कम रहती है। इसीलिए इकाई बैंकिंग को अप्रस्यस्यपूर्ण कहा गया है।

(२) स्थिरता का अभाव—बैंको में स्थिरता कम रहती है क्योंकि वे कार्य-क्षेत्र सीमित होने के कारण जोखिम का अधिक फैलाव नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंको के फेल होने का डर अधिक रहता है।

(३) सीमित साधन—इकाई बैंको के पास साधन सीमित होते हैं जिसके कारण वे बड़े बड़े उद्योगों के विकास के लिए अधिक साधन नहीं दे सकते हैं। छोटे उद्योगों के जमाने में इस प्रकार के बैंक अधिक भफन हो सकते थे किन्तु आजकल व्यापार तथा उद्योग का आकार इतना बड़ा गया है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े-बड़े बैंकों का होना आवश्यक है।

(४) निरीक्षण एवं नियन्त्रण की कठिनाई—छोटे-छोटे बहुत से बैंक होने की दशा में सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के द्वारा उन पर नियन्त्रण करना कठिन हो जाता है। आजकल बैंकों पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण आवश्यक है और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए देश में बैंकों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः बैंक बड़े तथा विस्तृत कार्य क्षेत्र वाले होने चाहिए।

(५) ब्याज की दरों में असमानता—इकाई बैंकिंग के अन्तर्गत पूँजी समस्त देश में गतिशील नहीं रहती है जिसके कारण ब्याज की दरों में असमानता रहती है। एक क्षेत्र की पूँजी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाती है और पूँजी की गतिशीलता के अभाव के कारण ब्याज की दरों में समानता स्थापित होने की प्रवृत्ति बहुत कमजोर हो जाती है।

(६) पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैंकों का अभाव—इकाई बैंकिंग में बैंक उसी क्षेत्र में स्थापित किये जाते हैं जहाँ पर उन्हें स्वतन्त्र रूप से सफलता मिल सकती है क्योंकि उन्हें अन्य बैंकों से किसी प्रकार की सहायता मिलने की सम्भावना नहीं होती है। ऐसी दशा में पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैंक नहीं खोले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। किन्तु शाखा बैंकिंग में पिछड़े हुए क्षेत्रों की शाखाओं की हानि विकसित क्षेत्रों की शाखाओं के लाभ से पूरी की जा सकती है।

उपयुक्त विवरेण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान व्यवसाय तथा व्यापार की आवश्यकताओं को केवल शाखा बैंकिंग के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यद्यपि इकाई बैंकिंग में कुछ गुण अवश्य पाये जाते हैं किन्तु इस प्रकार के बैंक वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थ हैं। लघु व्यवसाय के युग में छोटे बैंकों का होना ठीक हो सकता है किन्तु आज का व्यापार एवं उद्योग इतने विकसित हो गये हैं कि उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है जिसे इकाई बैंकों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। शाखा बैंकिंग की व्यवस्था में बैंकों का आकार बड़ा होता है, उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत रहता है और उनके साधन भी अधिक होते हैं। इस प्रकार के बैंक ही आज की अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयुक्त कहे जा सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में फैली हुई शाखाओं वाले बड़े बैंक अधिक कार्यकुशल होते हैं और वे सस्ती एवं पर्याप्त बैंकिंग सुविधायें प्रदान कर सकते हैं। कोषों का केन्द्रीयकरण तथा कुशल प्रबन्ध के द्वारा इस प्रकार के बैंक जनता में अधिक विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। मुद्रा बाजार के सुसंगठित होने के लिए भी यह आवश्यक है कि बैंक बड़े आकार के हों और सख्या में कम हों। इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में पूँजी की गतिशीलता अधिक रहती है और विकसित क्षेत्रों के अतिरिक्त साधनों का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से शाखा बैंकिंग को इकाई बैंकिंग की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाता है।

अमेरिका में भी इकाई बैंकिंग के प्रति असंतोष प्रकट किया जा रहा है और बैंकिंग व्यवस्था के पुनर्गठन की ओर प्रयत्न किये गये हैं। प्रो० केंट (Kent) ने इकाई बैंकिंग की आलोचना करते हुये लिखा है कि “हमारी इकाई बैंकिंग व्यवस्था का बार-बार टूटना इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्पन्न करता है कि क्या इन सहस्रों बैंकों को, जिनमें से बहुतों के पास कार्य करने के लिए न पर्याप्त साधन हैं और न लाभपूर्ण व्यवसायिक अवसर, बनाये रखना न्यायोचित है। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा

तथा अन्य देशों में महान शाखा बैंकिंग ग्रहों के अनुभव शाखा बैंकिंग प्रणाली की अधिक शक्ति एवं स्थिरता को प्रदर्शित करते हैं।³ अमेरिका में इकाई बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किये गये हैं। कुछ बैंकों को सीमित क्षेत्र में शाखाएँ खोलने का अधिकार दे दिया गया है तथा गृहसंतकारी अथवा वर्गीय बैंकिंग (Chain or Group Banking) का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बड़े-बड़े नगरों में कॉरिसपोन्डेंट बैंकों की स्थापना भी की गई है जो अपने पास उस क्षेत्र के अन्य छोटे-छोटे बैंकों के खाते रखते हैं। इस व्यवस्था के हो जाने से विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी हस्तान्तरण आसान हो गया है। यह सब प्रवृत्तियाँ इस ओर संकेत करती हैं कि अमेरिका में भी इकाई बैंकिंग का प्रयोग अधिक सफल नहीं हो सका है और धीरे-धीरे वहाँ पर शाखा बैंकिंग की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जा रहा है।

अमेरिका जैसे विकसित देश में जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त पूँजी के साधन उपलब्ध हैं इकाई बैंकिंग की कुछ उपयोगिता हो सकती है किन्तु भारतवर्ष में, जहाँ अविकसित क्षेत्रों में पूँजी व अन्य साधनों की भारी कमी है, इकाई बैंकों की स्थापना देश के हित में नहीं है। हमारे देश के लिए शाखा बैंकिंग ही उपयुक्त व्यवस्था है क्योंकि इसके द्वारा पूँजी को गतिशील रखा जा सकता है व कम विकसित क्षेत्रों में अधिक विकसित क्षेत्रों के साधन लगाये जा सकते हैं तथा लोगों को विस्तृत एवं सस्ती बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। यद्यपि भारत में शाखा बैंकिंग व्यवस्था अधिक उपयुक्त है किन्तु फिर भी इन बैंकों को अपनी विभिन्न शाखाओं की नीति तथा कार्य प्रणाली को विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक दशाओं तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

- (१) किसी बैंक के नकद कोषों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों की व्याख्या कीजिये।
(आगरा, बी० काम १९५६)
- (२) किसी व्यापारिक बैंक के कार्यों का वर्णन करिये। उसके साम के कोन-कोन से थोत हैं और कोषों का विनियोग करते समय उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
(आगरा बी० काम १९६५ S)

3 "The recurrence of breakdowns in our unit banking system leads to a serious questioning of the desirability of maintaining these thousands of independent banks, many of them with insufficient resources and business opportunities to operate profitably. The experience of the great branch banking houses of England, France, Canada and other countries seems to demonstrate the greater strength and durability of branch system."

- (३) व्यापारिक बैंक के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिये और इस सम्बन्ध में नकद कोषों एवं विनियोग सम्बन्धी नीतियों की विवेचना करिये ।
(राजस्थान बी० काम, १९५६, आगरा बी० काम १९५५ S)
- (४) ग्राहकों को साख देते समय बैंकर को किन-किन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए ? एक व्यापारिक बैंक के दृष्टिकोण से कौन से विनियोग सबसे अधिक उपयुक्त हैं ?
(इलाहाबाद बी० काम १९५७)
- (५) “सफल बैंकिंग का रहस्य यह है कि प्रसाधनों को विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों में इस प्रकार वितरित किया जाय कि तरलता और लाभदायकता में एक सुन्दर समन्वय स्थापित हो सके ।” प्रालोचनापूर्ण व्याख्या कीजिये ।
(इलाहाबाद बी० काम १९५६)
- (६) किसी बैंक का काल्पनिक स्थिति विवरण बनाकर यह बताइये कि इसकी विभिन्न मदों का क्या महत्व है ?
(सागर बी० काम १९५८)
- (७) व्यापारिक बैंक अपनी लाभ कमाने की कामना को तरलता की आवश्यकता के साथ किस प्रकार समन्वित करता है ?
(जबलपुर बी० काम १९५७)
- (८) व्यापारिक बैंकों की तरलता और सुरक्षा किन-किन कारणों से प्रभावित होती है ? समझाईये ।
(नागपुर बी० ए० १९५७)



केन्द्रीय बैंकिंग

CENTRAL BANKING

संसार के लगभग सभी देशों में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो देश की बैंकिंग व्यवस्था एवं साख्त पर नियन्त्रण करता है। आज कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिसमें केन्द्रीय बैंक की स्थापना न हुई हो। केन्द्रीय बैंक देश की अर्थ-व्यवस्था का आवश्यक अंग समझा जाता है, क्योंकि वह देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को नियन्त्रित करता है। डी० कौक (De Kock) के अनुसार, “केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था की सबसे ऊँची संस्था होती है।”^१ किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वह ऐसे कार्य करता है जिन पर देश की आर्थिक स्थिरता निर्भर होती है। वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके बिना देश की अर्थ-व्यवस्था को पूर्णतः समझा जाता है। केन्द्रीय बैंक केवल मुद्रा व साख्त व्यवस्था का नियन्त्रक ही नहीं होता है बल्कि वह अपनी क्रियाओं के द्वारा देश के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है।

केन्द्रीय बैंकों का विकास (Rise of Central Banks)—

केन्द्रीय बैंकिंग का विकास मुख्यतः वर्तमान शताब्दी में हुआ है। पिछले ३०-३५ वर्षों में केन्द्रीय बैंक इतने महत्वपूर्ण हो गये हैं कि उनके बिना देश की अर्थ-व्यवस्था का सुचारु रूप से चलना असम्भव समझा जाने लगा है। अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही हुई है। यद्यपि केन्द्रीय बैंकों में सबसे प्राचीन स्वीडन (Sweden) का रिस्क बैंक (Risk Bank) है जिसकी स्थापना सन् १६८८ में हुई थी किन्तु फिर भी यह माना जाता है कि केन्द्रीय बैंकिंग के विकास का श्रेय इंग्लैंड को जाना चाहिए। इंग्लैंड में केन्द्रीय बैंक का प्रारम्भ अकस्मात् ही हुआ और वहाँ से यह विचार अन्य देशों के द्वारा अपना लिया गया।

1 “A central bank is a bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure” —M. H. De Kock : Central Banking, P. 22.

बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना १६९४ में हुई और वह धीरे-धीरे उस देश का सबसे शक्तिशाली बैंक बन गया। अन्य बैंक उससे आर्थिक सहायता तथा परामर्श लेने लगे और इस प्रकार उसे बैंकिंग व्यवस्था का नेतृत्व (Leadership) प्राप्त हुआ। सन् १८२६ से वह सरकारी बैंकर तथा बैंकों के बैंक का कार्य करने लगा। सरकारी बैंकर होने के नाते उसे कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधायें दे दी गईं। सन् १८३३ में इस बैंक के नोटों को कानूनी मुद्रा (Legal Tender Money) घोषित कर दिया गया और १८४४ में अन्य बैंकों के नोट निर्गमन के अधिकार को सीमित कर दिया गया। सन् १८५४ से यह बैंक क्लिअरिंग-घर (Clearance House) का कार्य करने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को करना प्रारम्भ किया और इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था में अपना केन्द्रीय स्थान बना लिया। इंग्लैंड की देखा-देखी अन्य देशों में भी केन्द्रीय बैंकों की स्थापना होने लगी। फ्रांस में सन् १८०० में, हॉलैंड में, १८१४ में, आस्ट्रिया में १८१७ में, फ्रांस तथा जर्मनी में १८६० व १८७५ में और भारतवर्ष में १९३५ में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई। योरोप के लगभग सभी देशों में पिछली शताब्दी के अन्त तक केन्द्रीय बैंक स्थापित हो चुके थे किन्तु केन्द्रीय बैंकिंग का वास्तविक विकास १९२० के पश्चात् ही हुआ। प्रथम युद्ध के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। सन् १९२० में प्रुसेल्स के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में प्रत्येक देश के द्वारा एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किये जाने का सुझाव रखा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय पश्चात् लगभग सभी बड़े देशों के केन्द्रीय बैंक स्थापित हो गये। सन् १९३० के आर्थिक संकट के पश्चात् केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता और भी अधिक अनुभव की जाने लगी। जिन देशों में अभी तक केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं हुए थे उनमें इस प्रकार की योजनाओं को कार्यरूप में लाने का प्रयत्न किया जाने लगा।

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता (Need for Central Bank)—

केन्द्रीय बैंकों के स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई इसका उत्तर केन्द्रीय बैंक के विकास सम्बन्धी इतिहास से मिल सकता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंकों की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि वे महत्वपूर्ण संस्थायें हैं और वे महत्वपूर्ण संस्थाएँ इसलिए हैं क्योंकि उनके द्वारा ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनके बिना हमारा वर्तमान आर्थिक जीवन नहीं चल सकता है। केन्द्रीय बैंकों की स्थापना से पूर्व नोट निर्गमन का अधिकार प्रत्येक बैंक को होता था जिसके कारण देश की अर्थ-व्यवस्था किसी भी समय संकट में पड़ सकती थी। इन बैंकों के द्वारा नोटों की अधिक निष्काती किये जाने के कारण मुद्रा-प्रसार का भय बना रहता था। इसके प्रतिरिक्त नोटों में एकरूपता नहीं रहती थी और नोटों की मात्रा पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण एवं नियमन करना सम्भव नहीं था। नोट निर्गमन की इन

वटिनाशो को दूर करने के लिए केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की गई। काफी समय से बैंक साख का निर्माण करते आ रहे हैं जिनसे समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं किन्तु आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से देश में साख की मात्रा का नियन्त्रित होना आवश्यक है। व्यक्तिगत बैंक किसी भी समय लाभ के लालच में अत्यधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं जिससे देश में विभिन्न आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश के हितों को ध्यान में रख कर साख की मात्रा एवं उसके प्रयोग को नियन्त्रित किया जाय। इस कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था केन्द्रीय बैंक ही है। अतः साख का नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव हुई। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली को मुख्य-महियत एक समुचित करने के लिए भी केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। वह देश में एक समुचित बैंकिंग नीति का निर्माण करता है तथा सकट काल में बैंकों की सहायता करता है और उन्हें आर्थिक मामलों पर सलाह देता है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सरकारी जिम्मेदारी बढ़ जाने और नियोजित अर्थ-व्यवस्था का विकास होने के कारण केन्द्रीय बैंक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition of Central Bank)—

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा करते समय प्रायः उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन किया जाता है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक वह बैंक होता है, जो देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण करता हो। शॉ (Shaw) के विचार में केन्द्रीय बैंक वह बैंक होता है जो सामान्य को नियन्त्रित करता है। हॉट्टर (Hawtrey) के अनुसार केन्द्रीय बैंक अन्तिम श्रद्धादाता होता है। प्रो० केन्ट (Kent) के शब्दों में 'केन्द्रीय बैंक वह संस्था होती है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो।'² केन्द्रीय बैंक की इसी प्रकार की परिभाषा बैंक ऑफ इन्टर-नेशनल मैटिलर्मेट्स के विधान में दी गई है, जिसके अनुसार, "केन्द्रीय बैंक किसी देश का वह बैंक होता है जिसका वर्तमान देश में साख व मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करना होता है।"³ इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि केन्द्रीय बैंक सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा व साख की मात्रा को नियन्त्रित करने वाली संस्था होती है। वह देश में आर्थिक स्थिरता को

2 "It may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of the general public welfare."

—Raymond P. Kers : Money and Banking, P. 315.

3 A Bank regulating the volume of currency and credit of a country."

—Bank of International Settlements.

स्थापित करने के उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर लेता है। डी० कौक (De Kock) ने केन्द्रीय बैंक की प्रकृति को बतलाते हुए लिखा है—“एक साधारण बैंक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों पर चलाया जाता है किन्तु इसके विपरीत एक केन्द्रीय बैंक प्रारम्भिक रूप से देश की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर लेने के लिए होता है। वह मुख्य रूप से लाभ को ध्यान में न रखते हुए केवल समस्त देश के कल्याण तथा जनता के हित के लिए कार्य करता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का स्वामी होता है। देश के सभी बैंक उसके अधीन रहते हैं और वह उनके लिए एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक (Friend, Philosopher and Guide) का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से साख्त का नियन्त्रण करना है। वह देश में मुद्रा तथा साख्त की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटाता-बढ़ाता रहता है और इस प्रकार मूल्यों की स्थिरता तथा विदेशी-विनिमय की स्थिरता स्थापित करता है।

केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व एवं प्रबन्ध (Ownership and Management)—

केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इस प्रकार के बैंक सरकारी बैंक होने चाहिए अथवा उनका स्वामित्व व्यक्तिगत अशायरियों (Private Shareholders) के हाथों में रहना चाहिए, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक के धार्यों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उस पर सरकारी नियन्त्रण का होना अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि आजकल केन्द्रीय बैंक के सरकारी स्वामित्व (Public Ownership) के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। स्वामित्व की दृष्टि से विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के केन्द्रीय बैंक मिलते हैं किन्तु इनमें से उनके तीन रूप मुख्य हैं—(i) सरकारी स्वामित्व—आजकल अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक होना है और बैंक के समस्त हिस्से सरकार द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहता है और वह निःस्वार्थ रूप से राष्ट्र के हित में कार्य कर सकता है। (ii) व्यक्तिगत हिस्सेदारों का स्वामित्व—कुछ एक देशों में केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारों

4 “An ordinary bank is run on business lines, with a view to earn profits and a central bank, on the other hand, is primarily meant to shoulder the responsibility of safeguarding the financial and economic stability of the country—it acts only in the public interest and for the welfare of the country as a whole and without regard to profit as a primary consideration”

—De Kock : Central Banking.

का वेंक होता है। इस प्रकार के बैंक के हिस्सों पर व्यक्तिगत हिस्सेदारों (Private Shareholders) का स्वामित्व रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक अधिक स्वतन्त्रता से कार्य कर सकता है किन्तु फिर भी वह सरकार के आधीन होता है। (iii) व्यापारिक बैंक का स्वामित्व—केन्द्रीय बैंकों के ऊपर व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व भी हो सकता है। बैंक के हिस्से व्यापारिक बैंकों के नाम में रहते हैं और वे ही उसका संचालन करते हैं। अमेरिका के केन्द्रीय बैंक इसी प्रकार के बैंक है। इन तीनों प्रकार के केन्द्रीय बैंकों में सरकारी स्वामित्व वाले केन्द्रीय बैंकों को ही अच्छा माना जाता है। यद्यपि उनमें स्वतन्त्रता का अभाव पाया जाता है किन्तु वे राज के आर्थिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अधिक सफल हो सकते हैं। इनीलिए सिद्धने कुछ वर्षों में बहुत से देशों के केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और यह प्रवृत्ति अधिकाधिक प्रवर्धित होनी जा रही है। आगकल अधिकतर केन्द्रीय बैंक या तो पूर्णतया सरकारी अधिकार में होते हैं या सरकार उनमें ५०% या इसमें अधिक हिस्सों (Shares) की मालिक होती है। बेशक कुछ ही देशों में जैसे अमेरिका, केन्द्रीय बैंकों के स्वामित्व में सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अन्तर

(Distinction between Central Bank and Commercial Bank)—

केन्द्रीय बैंक एक विशेष प्रकार की बैंकिंग संस्था होती है जो अन्य प्रकार के बैंकों से भिन्न होती है। केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य एवं कार्य व्यापारिक बैंकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। प्रो० सेयर्स (Sayers) के अनुसार “केन्द्रीय और व्यापारिक बैंकों में अन्तर मुख्यतः उनके उद्देश्यों के सम्बन्ध में होता है। व्यापारिक बैंक प्रारम्भिक रूप से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखता है जबकि केन्द्रीय बैंक अपनी क्रियाओं के अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखता है। व्यापारिक बैंक कुछ या अनेक हो सकते हैं और वे सामान्य जनता के साथ व्यापार करते हैं। प्रत्येक देश में केवल एक केन्द्रीय बैंक होता है और वह साधारण जनता के साथ बैंकिंग व्यवसाय बहुत कम करता है। वह केवल बैंकिंग व्यवस्था को त्रिज्य ओ को नियन्त्रित करने तक ही अपने को सीमित रखता है।”^१ इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य तथा उसके कार्य सामान्य बैंकों से सर्वथा

1 “The distinction between central and commercial banks turns essentially on their objects. The commercial bank thinks primarily of profit making, whereas the central bank thinks of the effects of its operations on the working of the economic system..... The commercial banks may be few or many. They trade with the general public. There is only one central bank in each country, and it does little if any, ordinary banking business for the general public, it restricts itself in the main to controlling the operations of the rest of the banking system.”

भिन्न होते हैं। देश की मुद्रा व बैंकिंग व्यवस्था में उसका शीर्ष (apex) स्थान होता है और वह समाज में विदेश प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए स्थापित किया जाता है जिन्हें पूरा करने के लिए उसे विशेष प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण केन्द्रीय बैंक अन्य प्रकार के बैंकों से प्रथम हो जाता है—

(१) केन्द्रीय बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है—अन्य बैंकों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है किन्तु केन्द्रीय बैंक का प्रारम्भिक उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। वह देश में अधिक आर्थिक स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक किसी व्यक्ति प्रयत्न या धर्म विशेष के हितों के लिए कार्य नहीं करता है। वह सदैव जनहित में कार्य करता है।

(२) केन्द्रीय बैंक के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं—व्यापारिक बैंकों के ऊपर नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होते हैं। नोट निर्गमन का अधिकार तथा साख्त नियन्त्रण का अधिकार इसी प्रकार के विशेष अधिकार हैं जो केवल केन्द्रीय बैंक को ही दिये जाते हैं। इन विशेष अधिकारों के कारण ही केन्द्रीय बैंक साख्त तथा बैंकिंग व्यवस्था में शक्तिशाली नियन्त्रक के रूप में कार्य कर सकता है।

(३) केन्द्रीय बैंक सरकार के आधीन होता है—अन्य बैंकों को अपना कार्य करने में पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है किन्तु केन्द्रीय बैंक को सरकार के आधीन रह कर ही कार्य करना होता है। वह कोई भी कार्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता है। केन्द्रीय बैंक सरकार की आधिकारी नीति को कार्य-रूप में लाने का यन्त्र होता है। उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं हो सकती है और उस पर पूर्ण रूप से सरकारी नियन्त्रण रहता है।

केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of Central Bank)—

केन्द्रीय बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने केन्द्रीय बैंक के एक प्रकार के कार्यों पर जोर दिया है तो कुछ अन्य लेखकों ने दूसरे प्रकार के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। हॉटरे (Hawtrey) के अनुसार “केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य देश में अन्तिम शरण-दाता (Lenders of the last resort) का कार्य करना होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे नोट निर्गमन का अधिकार दिया जाता है।” इसके विपरीत शॉ (Shaw) का मत है कि केन्द्रीय बैंक का एकमात्र कार्य साख्त का नियन्त्रण करना है। जॉन्सी (Jauncey) के अनुसार “केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य निकासी (Clearing) करना है।” किश (Kisch) और एल्किन (Elkin) के शब्दों में, “केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिक-मान की स्थिरता को बनाये रखना है जिसके अन्तर्गत

मौद्रिक प्रचलन भी सम्मिलित है।¹⁷ स्प्रेग (Sprague) ने केन्द्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या विस्तृत रूप में की है। उनके अनुसार “केन्द्रीय बैंक के कार्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। वे सरकार के आर्थिक एजेंटों का कार्य करते हैं। नोट निर्गमन का एकाधिकार होने के कारण वे बैंक के चलन पर नियन्त्रण रखने की बड़ी शक्ति रखते हैं, और और बड़ी-बड़ी अन्य बैंकों का संचित कोष उनके पास रहता है इसलिए वे साख के सम्पूर्ण ढाँचे की बुनियाद के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह अन्तिम कार्य ही केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है।”¹⁸

उपयुक्त विस्लेषण से हमें यह तो ज्ञात हो जाता है कि केन्द्रीय बैंक प्रायः कौन-कौन से कार्य करता है किन्तु इनमें से उनका प्रमुख कार्य कौन-सा है, इस विषय में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि साख नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांश लेखकों ने मौद्रिक प्रबंध (Monetary Management) को केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कर्तव्य बतलाया है। प्रो० शॉ (Shaw) ने तो साख नियन्त्रण को केन्द्रीय बैंक का एकमात्र कार्य माना है।¹⁹ डी० कोक (De Kock) ने भी इस कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है—‘साख नियन्त्रण को अधिकांश अर्थशास्त्रियों तथा बैंकर्स ने केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य स्वीकार किया है।’²⁰ मूल साख नियन्त्रण ही केन्द्रीय बैंक का आधारभूत कार्य माना जाता है और उसके अन्य सब कार्य इस प्रमुख कार्य से उत्पन्न होते हैं। केन्द्रीय बैंक के समस्त कार्यों का अन्तिम उद्देश्य साख व मुद्रा की मात्रा पर उचित नियन्त्रण करना होता है। आधुनिक समाज की दशाओं में तो इस कार्य का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।

केन्द्रीय बैंक के महत्व तथा उनके कार्यों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसने द्वारा बिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। केन्द्रीय बैंक सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करता है—

(१) नोट निर्गमन का कार्य — (Note Issue) — प्रत्येक देश में नोट निर्गमन का कार्य केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। देश में मुद्रा व साख का नियन्त्रण

6 “The essential function of a central bank is the maintenance of the stability of the monetary standard, which “involves circulation.”

—Kisch & Elkin.

7 “The special functions of central banks may be grouped under three heads—they serve as fiscal agents of government, they have large power of control over the currency through the more or less complete monopoly of note-issue, and finally since they hold a large part of the reserve of other banks, they are directly responsible for the foundation of the entire structure of credit. This is by far the most important function of a central bank.”

—Sprague.

8 “The one true but at the same time all sufficing function of a central bank is control of credit.”

—Shaw.

9 “The control or adjustment of credit is accepted by most economists and bankers as the main function of a central bank.”

—De Kock.

करने के लिए यह आवश्यक है कि नोट निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को दिया जाय। केन्द्रीय बैंक पर साख तथा मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करने का उत्तरदायित्व होता है। वह इस कार्य को भली भाँति कर सके इसलिए उसे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया जाता है। सर्वप्रथम नोट निर्गमन का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता था किन्तु यह कार्य सरकार अच्छी प्रकार से न कर सकी। कोई भी आपत्ति आने पर सरकार के द्वारा नोटों की अत्यधिक निकासी का भय रहता था। मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा के मूल्य का गिरना उस समय की साधारण घटनायें थी। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने में भी सरकार को अधिक समय लगता था। इन कठिनाइयों के कारण नोट निर्गमन का अधिकार व्यापारिक बैंकों को दे दिया गया किन्तु वे भी नोट निर्गमन के कार्य को देश हित में न कर सके और अत्यधिक निकामी का भय निरन्तर बना रहता था। व्यापारिक बैंक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी समय आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोटों को जारी कर सकते थे। अतः यह अनुभव किया गया कि सरकार तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही नोट जारी करने के लिए अनुपयुक्त हैं और केन्द्रीय बैंक के विकास के साथ-साथ नोट निर्गमन का कार्य उन्हें सौंप दिया गया।

केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए समझा गया क्योंकि वह इस कार्य को राष्ट्र हित में कर सकता है। यह आशा की गई कि केन्द्रीय बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य न करने के कारण केवल समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही नोट जारी करेगा और इस प्रकार मुद्रा प्रसार के भय को दूर किया जा सकेगा। केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का कार्य सौंपा जाने का मुख्य उद्देश्य नोटों के प्रचलन में अनुत्पत्ता लाना तथा पत्र-मुद्रा का अधिक अच्छा प्रबंध करना था। देश की मुद्रा प्रणाली में समानता तथा अनुत्पत्ता लाने के लिए और उसका अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि नोट निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को दे दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि नोट निर्गमन का एकमात्र अधिकार प्राप्त होने से केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा निर्मित साख पर उचित नियन्त्रण कर सकेगा और मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किया जा सकेगा। यह भी सोचा गया कि केन्द्रीय बैंक जैसी राज्य से सम्मानित संस्था के द्वारा नोट जारी किया जाने से पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का अधिक विश्वास प्राप्त किया जा सकेगा। नोट निर्गमन का कार्य लाभपूर्ण व्यवसाय होने के कारण भी यह आवश्यक समझा गया कि नोट निर्गमन का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही होना चाहिए। उपर्युक्त सभी कारणों से केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हुआ। आज प्रत्येक देश के केन्द्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकमात्र अधिकार होता है जिसके द्वारा वह समाज में मुद्रा की मात्रा को घटा बढ़ा कर आवश्यकता के अनुसार करता रहता है।

(२) बैंकों के बैंक का कार्य (Banker's Bank)—केन्द्रीय बैंक देश में अन्य बैंकों के बैंकर का कार्य करता है। देश के सभी बैंकों को विधान अथवा परम्परा के अनुसार अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केन्द्रीय बैंक या अन्य बैंकों के साथ ठीक वही सम्बन्ध रहता है जो बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। वह इन बैंकों से जमा प्राप्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है। व्यापारिक बैंक कितना बोध केन्द्रीय बैंक के पास रखते हैं यह उनकी चासू जमा (Demand Deposits) तथा निश्चित जमा (Time Deposits) की मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। इंग्लैंड के बैंक परम्परा के अनुसार अपनी जमा का कुछ प्रतिशत बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखते हैं। अमेरिका में एक अधिनियम के अन्तर्गत बैंकों के द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास रखे जाने वाले बोध का न्यूनतम अनुपात निश्चित किया हुआ है। भारतवर्ष में भी यह नियम है कि सभी बैंक अपनी जमा का २% से लेकर ५% तक रिजर्व बैंक के पास जमा रखेंगे। अतः केन्द्रीय बैंक देश के सभी बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक होता है। बैंकों के कोषों के केन्द्रीयकरण से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होने हैं। सर्वप्रथम, बैंकों के कोषों के केन्द्रीय बैंक के पास एकत्रित होने से बैंकिंग व्यवस्था में बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। कोई भी बैंक आपत्ति काल में इस सामूहिक जमा में से सहायता प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था में स्थिरता आ जाती है। इसके अनतिरिक्त कोषों के केन्द्रीयकरण हो जाने से बैंकों के नकद कोषों का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है तथा साम्प्रदायिकी में लोच का गुण उत्पन्न हो जाता है।

बैंकों के बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंक नदस्य बैंकों को आर्थिक सहायता भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर वे केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर अपनी नकद मुद्रा की मांग को पूरा कर सकते हैं। केन्द्रीय बैंक से यह ऋण दो प्रकार से प्राप्त होते हैं—
(i) प्रथम श्रेणी के बिलों को दुबारा भुना कर (Rediscounting) अथवा
(ii) स्वीकृत प्रतिभूतियों (Approved Securities) के आधार पर सीधा ऋण लेकर। उपर्युक्त तरीकों से केन्द्रीय बैंक संकट काल में व्यापारिक बैंकों की बड़ी सहायता करता है और उन्हें फेन होने से बचाता है। बैंकर होने के नाते केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को निशामी गृह (Clearance House) की सुविधायें भी देता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें परामर्श देता है।

(३) सरकारी बैंकर का कार्य (Banker to the Government)—सभी देशों में केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट तथा आर्थिक सलाहकार का कार्य करता है। डी कोक (De Kock) के अनुसार, “केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंकर के रूप में कार्य केवल इसलिए नहीं करता है क्योंकि ऐसा करना सरकार के लिए सुविधापूर्ण एवं मितव्ययी है वरन् इसलिए भी क्योंकि मौद्रिक मामलों में और सार्वजनिक वित्त

मे गहरा सम्बन्ध है।¹⁰ केन्द्रीय बैंक सरकारी कोषों का संरक्षण करता है तथा विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं निगमों (Corporations) का हिमायत अपने यहाँ रखता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को अल्पकालीन ऋण भी देता है। सरकार की समस्त धन राशि केन्द्रीय बैंक में ही जमा रहती है और वह ही सरकार के लिए समस्त भुगतानों को निबटाता है। वह कर इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर सरकार को अल्प काल के लिए ऋण देता है। सरकारी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य भी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। वह एजेंट के रूप में सरकार के लिए करों (Taxes) को इकट्ठा करता है तथा सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध करता है। इन ऋणों का हिसाब-किताब रखना, उन पर सूद देना तथा उनका भुगतान करना, यह सब कार्य केन्द्रीय बैंक करता है। वह सरकार के लिए नये ऋणों को लेने का काम भी करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार के लिए सोने तथा विभिन्न प्रकार की प्रभूतियों को बेचने तथा खरीदने का काम करता है और सरकार की आवश्यकतानुसार विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार का आर्थिक सलाहकार भी होता है और समय-समय पर आर्थिक मामलों में सरकार को परामर्श देता है। सरकार अपनी आर्थिक नीति का निर्माण केन्द्रीय बैंक की सलाह से ही करती है। वर्तमान समय में विदेशी विनिमय नियन्त्रण (Exchange) तथा विनिमय दरों में स्थिरता लाने का कार्य भी केन्द्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है।

(४) साख के नियन्त्रक का कार्य (Controller of Credit)—साख का नियन्त्रण करना आजकल केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना जाता है। अन्य सब कार्य इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किये जाते हैं। वर्तमान समाज में साख, मुद्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसका प्रयोग दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। मूल्य-स्तर की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा तथा स'त की मात्रा पर नियन्त्रण किया जाये। केन्द्रीय बैंक का यह कर्तव्य होता है कि वह आवश्यकता के अनुसार साख की मात्रा को घटा-बढ़ा कर मूल्यों में स्थिरता स्थापित करे। इस कार्य को करने के लिए केन्द्रीय बैंक के पास दो प्रमुख साधन होते हैं—(i) उसकी बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने की शक्ति जिसे खुले बाजार की नीति (Open Market Operations) कहा जाता है तथा (ii) बैंक दर को घटाने-बढ़ाने की शक्ति जिसे बैंक दर नीति (Bank Rate Policy) कहते हैं। उपर्युक्त दोनों तरीकों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के सुरक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन करके तथा साख के रजिस्ट्रिंग के द्वारा भी साख नियन्त्रण का कार्य किया करता है।

10 "The central bank operates as the government's banker, not only because it is more convenient and economical to the government, but also because of the intimate connection between public finance and monetary affairs."

(५) केन्द्रीय बैंक समाज में ऋणों का अन्तिम साधन होता है (Lender of the Last Resort)—केन्द्रीय बैंक को ऋणों का अन्तिम साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आर्थिक संकट के समय में सरकार तथा व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ऋणों का अन्तिम साधन होने के कारण केन्द्रीय बैंक पर व्यापारिक बैंकों, कटोनी गृहों (Discount Houses) तथा अन्य प्रकार की साख्त संस्थाओं की ऋणों की उचित मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। वह कभी भी किसी बैंक को ऋणों के लिए इकार नहीं करता है यदि वह उचित प्रकार की जमानत (Security) देने को तैयार है। वह हर समय व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों (First Class Bills) को कुबारा मुनाने तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों (Approved Securities) के आधार पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक किसी भी समय केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर अपने पास नकदी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यद्यपि केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों की कभी भी ऋण देने से इकार नहीं करता है किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह ऋणों की मात्रा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं कर सकता है। केन्द्रीय बैंक अपने व्याज की दर में परिवर्तन करके बैंकों को दिये जाने वाले ऋण की मात्रा पर नियन्त्रण कर सकता है। वह अपनी ऋण सम्बन्धित नीति में परिवर्तन करके भी बैंकों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन कर सकता है।

(६) राष्ट्र के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण (Custodian of Nation's Gold & Foreign Exchange Reserves)—केन्द्रीय बैंक राष्ट्र के धात्विक कोष तथा विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। स्वर्णमान काल में स्वर्णमान का प्रबन्ध केन्द्रीय बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। आजकल केन्द्रीय बैंक को पय-मुद्रा कोष के रूप में तथा भुगतान समतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए अपने पास सोना तथा विदेशी मुद्राएं रखनी पड़ती हैं। देश का समस्त स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष केन्द्रीय बैंक के पास ही रहता है। केन्द्रीय बैंक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह विदेशी विनिमय प्रबन्ध के द्वारा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करे।

(७) निकासी गृह का कार्य (Clearing House)—प्रत्येक देश में निकासी गृह का कार्य केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है क्योंकि यह इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त संस्था समझी जाती है। देश के सभी बैंकों का हिसाब केन्द्रीय बैंक के पास रहता है इसलिए वह उनके आपसी नेन-देन को निबटाने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था है। केन्द्रीय बैंक के निकासी गृह के कार्य के द्वारा नकदी के प्रयोग में वृद्धि होती है तथा बहुत सी असुविधाएँ एव यम से दूरी जा सकती हैं। जॉन्सी (Jauncey) तथा विलिस (Willis) ने इसे केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना है। विलिस (Willis) के अनुसार केन्द्रीय बैंक के द्वारा संगठित निकासी गृह व्यवस्था "न केवल नकदी और पूँजी में वृद्धि का साधन है, बल्कि यह समाज में किसी विशेष समय पर रखी

जाने वाली तरलता का परीक्षण करने का साधन भी है, त्रिमहीय ज्ञान दिन प्रति-दिन होना केन्द्रीय बैंक के लिए आवश्यक है।¹¹

(८) सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करना (Collection of Statistics)—केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करके समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह देश की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित सूचनाओं तथा आंकड़ों को एकत्रित करता है और उन्हें अपनी रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशनों के द्वारा जनता के लिए उपलब्ध करता है। इन आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय बैंक विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव भी देता है। यह आंकड़े देश में समुचित आर्थिक नीति के निर्माण का आधार होते हैं।

केन्द्रीय बैंक और साख-नियन्त्रण (Central Bank and Credit Control)

केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख का नियन्त्रण करना है। वर्तमान समाज में साख का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि उसे नियन्त्रित किये बिना आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। साख का अनावश्यक विस्तार तथा सङ्कुचन होने से समाज में आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability) उत्पन्न होती है जो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास तथा समृद्धि में भारी रूकावट हो सकती है। आर्थिक विकास के लिए समुचित दसायें उत्पन्न करने तथा आर्थिक प्रगति की दर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में मुद्रा व साख की मात्रा को नियन्त्रित किया जाये। मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार केन्द्रीय बैंक को होता है इसलिए वह आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा को घटा-बढ़ा कर सन्तुलन स्थापित करता रहता है। किन्तु साख का निर्माण व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है जिसके कारण उस पर नियन्त्रण करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह महत्वपूर्ण कार्य भी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। वह साख की मात्रा को इस प्रकार नियन्त्रित करता है कि हर समय माख की पूर्ति को उसकी माग के बराबर रखा जा सके। केन्द्रीय बैंक के द्वारा साख नियन्त्रण की इस नीति को मौद्रिक नीति (Monetary Policy) तथा उसके साख नियन्त्रण कार्य को मौद्रिक प्रबन्ध (Monetary Management) कहते हैं।

साख नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Credit Control)—

साख नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक आधारभूत प्रश्न यह है कि केन्द्रीय बैंक के द्वारा साख नियन्त्रण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। विभिन्न लेखकों ने

11 This system of clearing organised by the Central Bank, "is not only a means of economising cash and capital, but is also a means of testing at any time the degree of liquidity which the community is maintaining—a matter which is essential for the central bank to know from day to day."

—Wills, quoted by De Kock in 'Central Banking' on P. 114.

मौद्रिक प्रबन्ध के विभिन्न उद्देश्य बतलाये हैं और समय के साथ-साथ मौद्रिक नीति के इन उद्देश्यों के महत्व में परिवर्तन होता रहा है। मुख्यतः सास नियंत्रण के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये जाते हैं—

(१) विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता (Exchange Stability)—
पारम्भ काल से ही मुद्रा नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना रहा है। इसी उद्देश्य के लिए संसार के अधिकांश देशों में सन् १८७५ से १९१४ तक स्वयंमान को बनाये रखा गया और उसके पश्चात् भी उसे संशोधित रूप में खलाया गया। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विश्व के आर्थिक कल्याण का प्रमुख साधन समझा जाता था और अन्तर्राष्ट्रीय विस्वाम को बनाये रखने तथा विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए विदेशी विनिमय दरों का स्थिर रहना अत्यन्त आवश्यक था। इन कारणों के अन्तर्गत ही विदेशी विनिमय की स्थिरता को मौद्रिक प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया। सन् १९३१ से पूर्व प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न करता था।

विदेशी विनिमय की स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रायः मूल्य-स्तर की स्थिरता को त्यागना पड़ता था जिसके कारण बहुत से देशों में आर्थिक जीवन में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते थे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह दोष बहुत अधिक बढ़ गये और अधिकांश देशों के द्वारा आन्तरिक स्थिरता का अनुभव किया जाने लगा। मौद्रिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में भी विचार परिवर्तन हुआ और विदेशी विनिमय की स्थिरता के स्थान पर मूल्य-स्तर की स्थिरता को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार विदेशी विनिमय की स्थिरता मौद्रिक प्रबन्ध का उद्देश्य तभी तक होना चाहिए जब तक की उसके साथ मूल्य-स्तर की स्थिरता को भी प्राप्त किया जा सके।

(२) कीमत स्तर की स्थिरता (Price Stability)--स्वयंमान के पतन के पश्चात् कीमत-स्तर की स्थिरता मौद्रिक नीति का अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाने लगा। आन्तरिक कीमतों की स्थिरता राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि कीमत स्तर का बदलना उत्पादन तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कीमत-स्तर के अत्यधिक परिवर्तन आर्थिक जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं तथा आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधक होते हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी कीमतों में स्थिरता का होना आवश्यक है। इन्हीं सब कारणों से कीमतों की स्थिरता को मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य समझा जाने लगा। सन् १९३० की आर्थिक मन्दी ने कीमतों को स्थिर रखने के महत्व को और भी बढ़ा दिया। वर्तमान समाज में कीमतों की अस्थिरता का मुख्य कारण सास व मुद्रा की मात्रा में अनावश्यक परिवर्तन किया जाना है। इसलिए

केन्द्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा साख की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाये रखना चाहिए जिससे कि आन्तरिक कीमत-स्तर को बनाये रखा जा सके। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि किसी समय पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखा जाय अथवा आन्तरिक कीमत-स्तर को, तो कीमत-स्तर की स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विदेशी विनिमय दरों में संशोधन करने भी आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता को बनाये रखना चाहिए।

(३) आन्तरिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार (Economic Stability and Full Employment)—आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार स्थापित करना होना चाहिए। कीमत-स्तर की स्थिरता एक सीमा तक अच्छी हो सकती है किन्तु वह सदैव समाज के आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने वाली नहीं होती है। कीमतों के स्थिर रहने की दशा में अर्थ-व्यवस्था में काफी असन्तुलन पैदा हो सकते हैं जो देश के आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। अतः आन्तरिक कीमत स्तर की स्थिरता को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। विदेशी विनिमय की स्थिरता तथा कीमत-स्तर की स्थिरता स्थापित करना उसी समय तक उचित है जब तक कि वह देश के सन्तुलित आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न न करता हो। आर्थिक स्थिरता अथवा पूर्ण रोजगार स्थापित करना देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा ही राष्ट्र के आर्थिक कल्याण को अधिकतम किया जा सकता है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो व्यापार-चक्रों को रोकने में सहायक हो तथा जिसके द्वारा आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सके।

सन् १९३० की महान् आर्थिक मन्दी के पश्चात् पूर्ण रोजगार स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया और लगभग प्रत्येक देश में उसे मुद्रा नीति का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार कर लिया गया। स्वीडन, अमेरिका इङ्ग्लैंड तथा अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक जो पहले कीमत-स्तर को अधिक महत्व देते थे अब अपनी मौद्रिक नीतियों का विकास आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य के दृष्टिकोण से करने लगे। प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य समाज में पूर्ण रोजगार स्थापित करना तथा व्यापार चक्रों को रोकना होना चाहिए। व्यापार-चक्र मृत्पतया बचत और विनियोग की मात्रा में असन्तुलन हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं इसलिए मौद्रिक प्रवन्ध के द्वारा समाज में बचत (Savings) तथा विनियोग (Investments) की मात्रा में, पूर्ण रोजगार के दृष्टिकोण से सन्तुलन स्थापित करना चाहिए। क्रॉउथर (Crowther) ने पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा है कि "मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण रोजगार

विन्दु पर वचत तथा विनियोग में सन्तुलन स्थापित करना होना चाहिए।¹² द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् इस उद्देश्य पर और अधिक बल दिया जाने लगा। बहुत-से देशों ने पूर्ण रोजगार स्थापित करने का निश्चय किया और देश की मौद्रिक नीति को उसका साधन बनाया गया। लगभग सभी वर्तमान अर्थशास्त्री मुद्रा नीति के इस उद्देश्य से महमत है। यद्यपि वे कीमन-स्तर अथवा विदेशी विनिमय की स्थिरता के महत्व को अस्वीकार नहीं करते हैं किन्तु ये मुद्रा नीति के मौल्य उद्देश्य ही हो सकते हैं और उसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार स्थापित करना होना चाहिए। विकसित देशों में मौद्रिक प्रबन्ध के द्वारा व्यापार-चक्रों को रोक कर पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखा जाना चाहिए और विकासशील देशों में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(४) आर्थिक विकास (Economic Development)—अल्प-विकसित देशों में साख नियन्त्रण का एक और उद्देश्य भी बतलाया जाता है। इन देशों के अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दशाओं उत्पन्न करना होना चाहिए। इस समय अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है और साख नियन्त्रण नीति को भी इन विस्तृत उद्देश्य के अन्तर्गत ही गण्य करना चाहिए। इन देशों के केन्द्रीय बैंकों के सम्मुख आर्थिक विकास का एक विशेष उत्तरदायित्व है। उन्हें एक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने हैं और दूसरी ओर मुद्रा-प्रसार की शक्तियों पर नियन्त्रण करना है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति का उद्देश्य समाज का आर्थिक विकास करना होना चाहिए।

साख नियन्त्रण की विधियाँ

(Methods of Credit Control)

साख नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम उन तरीकों का विश्लेषण कर सकते हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण करता है। साख नियन्त्रण भी दो प्रकार का हो सकता है—(i) साख की मात्रा पर नियन्त्रण (Quantitative control) तथा (ii) साख के प्रयोग पर नियन्त्रण (Qualitative control)। दोनों ही प्रकार के नियन्त्रण आर्थिक स्थिरता तथा विकास के लिए आवश्यक हैं। सर्वप्रथम हम मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करने के तरीकों का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार हैं—

(१) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—

आरम्भ काल से ही बैंक दर नीति साख नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण तरीका रहा है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व तो उसे साख नियन्त्रण की एकमात्र विधि समझा

12 "The obvious objective should be to attain an equilibrium between Saving and Investment at the point of full employment."

—Geoffrey Crowther : 'An Outline of Money' P. 181.

जाता था। बैंक दर नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर में परिवर्तन करके साख की मात्रा को नियन्त्रित करता है। बैंक दर वह न्यूनतम व्याज की दर होती है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों को पुनः मुनाता है अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। संक्षेप में, वह केन्द्रीय बैंक की उधार देने की व्याज की दर होती है। केन्द्रीय बैंक के पास बैंक दर में परिवर्तन करने की शक्ति होती है और वह इस प्रकार के परिवर्तनों के द्वारा समाज में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। बैंक दर का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि बाजारी मूद्र की दर (Market Rate of Interest) बैंक दर (Bank Rate) के साथ-साथ चलती है।¹³ यदि बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है तो बाजार में मूद्र की सभी दरें बढ़ जाती हैं और ऋणों का लेना महंगा तथा कम लाभदायक हो जाता है, जिससे साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत जब बैंक दर को घटाया जाता है तो समाज में अन्य व्याज की दरों में कमी हो जाने के कारण ऋणों का लेना लाभदायक होता है जिसके परिणामस्वरूप साख का विस्तार होता है। बैंक-दर परिवर्तनों के इस सिद्धान्त के अनुसार मूद्रा व साख की मात्रा को कम करने के लिए बैंक दर में वृद्धि करना आवश्यक है तथा बैंक में कमी करने से चलन में साख का विस्तार होता है। बैंक दर में वृद्धि करके केन्द्रीय बैंक ऋण लेने की प्रवृत्ति को कम करता है और इस प्रकार साख का संकुचन हो जाता है। इसके विपरीत बैंक दर को कम करके वह ऋणियों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और साख की मात्रा बढ़ जाती है।

यदि केन्द्रीय बैंक देखता है कि समाज में साख की मात्रा तेजी के साथ बढ़ रही है और उसे कम करना आवश्यक है तो वह बैंक दर को बढ़ा देता है। बैंक दर में वृद्धि होने के कारण अन्य बैंकों की भी अपनी व्याज की दर को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वे ऋणों के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार बैंक दर के बढ़ने से बाजारी व्याज की दर (Market Rate of Interest) भी बढ़ जाती है। व्याज की दर में वृद्धि हो जाने के कारण अब ऋण लेकर विनियोग करना उतना लाभपूर्ण नहीं रहता है जितना कि पहले था। अतः व्यवसायी कम मात्रा में ऋण लेते हैं और इस प्रकार साख का संकुचन हो जाता है। यदि बैंक दर के बढ़ने पर अन्य व्याज की दरें भी बढ़ जाती हैं तो बैंक दर नीति अपने उद्देश्य में सफल रहती है। एक सुसंगठित मूद्रा बाजार में प्रायः ऐसा ही होता है और बैंक दर के बढ़ने से लोगों के लिए ऋण लेना अधिक कठिन हो जाता है। वे या तो ऋण लेना स्थगित

13 "The theory underlying the use of the discount rate... .. was, briefly, that changes in the discount rate or the central bank would bring about more or less corresponding changes in local money rates generally"

—De Kock : Central Banking, P 151.

कर देते हैं अथवा पहले की अपेक्षा कम ऋण लेते हैं। ऋणों की माग कम हो जाने से बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाते हैं।

इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक देखता-है कि मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी है और साख का विस्तार करना है तो वह बैंक दर को कम करके साख विस्तार की नीति को अपनाता है। बैंक दर के कम हो जाने पर बाजारी व्याज की दर भी कम हो जाती है और साख विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा व्याज की दर कम कर देने के कारण लोग अधिक मात्रा में ऋणों की माग करते हैं और बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार बैंक दर को कम करने से ऋण लेना आसान हो जाता है, ऋणों की माग बढ़ती है और साख का विस्तार होना है। अब यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर में परिवर्तन करके साख की मात्रा को घटा-बढ़ा सकता है। जब वह साख का विस्तार करना चाहता है तो बैंक दर को बढ़ा देता है और इसके विपरीत जब साख का संकुचन करने की आवश्यकता होती है तो बैंक दर को कम कर दिया जाता है।

बैंक दर परिवर्तनों के प्रभाव (Effects of Bank Rate Changes)—

बैंक दर परिवर्तनों का देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था तथा उसके भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव बाजारी मूद्र की दरों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं।

आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव (Effects on Internal Economy)

बैंक दर परिवर्तनों के आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं—प्रत्यक्ष (Direct) तथा परोक्ष (Indirect)। बैंक दर के बढ़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि व्याज की दर बढ़ जाने के कारण स्थिर पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं। समाज में बचत की मात्रा बढ़ती है और विनियोग की मात्रा कम हो जाती है, उत्पादन गिरता है तथा लाभ कम होने लगते हैं जिसके कारण मन्दी की दशाएँ उत्पन्न होती हैं। बैंक दर वृद्धि का परोक्ष प्रभाव यह होता है कि पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य गिर जाने के कारण उनकी माग कम हो जाती है और उनका उत्पादन कम होने लगता है। पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों में बेरोजगारी फैलती है और लोगों की मोद्रिक आय कम हो जाती है जिसके कारण उपभोग की वस्तुओं (Consumption goods) की माग गिर जाती है और उनके मूल्य कम होने लगते हैं। इस प्रकार बैंक दर के बढ़ने पर आन्तरिक अर्थ व्यवस्था में व्यवसायिक मन्दी फैलती है। इसके विपरीत बैंक दर कम होने पर व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है और तेजी की दशाएँ उत्पन्न होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलनों पर प्रभाव (Effects on International Balance of Payments)—अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बैंक दर परिवर्तनों का

महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और उन्हें किसी देश के भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्वर्णमान की व्यवस्था में बैंक दर के बढ़ने पर स्वर्ण का निर्यात रुक जाता है और विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन मिलने के कारण देश में सोने का आयात होने लगता है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। बैंक दर में वृद्धि होने से देश में साख का मनुचन होता है और वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं। हमारे माप का मूल्य कम होने के कारण निर्यात बढ़ते हैं तथा विदेशी वस्तुओं का मूल्य अधिक होने के कारण वस्तुओं का आयात कम हो जाता है। निर्यातों में वृद्धि होने तथा आयात कम हो जाने से देश के व्यापार सन्तुलन की प्रविणता अनुकूलता में बदल जाती है। देश में मौद्रिक आय कम होने से रोजगार की मात्रा तथा मजदूरी की दरें कम हो जाती हैं जिससे हमारे उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि होती है और निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, बैंक दर ऊँची होने से देश से बाहर पूँजी का जाना रुक जाता है तथा विदेशों से पूँजी आने लगती है। इन सबका प्रभाव भुगतान सन्तुलन के घाटे को दूर करके उसे पक्ष में करने का होता है। बैंक दर के कम होने का प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है। अतः बैंक दर परिवर्तनों को विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी असन्तुलन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

बैंक दर नीति की सीमाएँ (Limitations of Bank Rate Policy)—

बैंक दर नीति की सफलता के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है—

(1) बैंक दर में परिवर्तन के साथ-साथ अन्य व्याज की दरों में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए—बैंक दर नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बैंक दर के बदलने पर देश में व्याज की अन्य सभी दरें बदल जायें। ऐसा केवल एक मुख्यस्थित तथा सुसंगठित मुद्रा बाजार में ही हो सकता है जैसा कि लन्दन का मुद्रा बाजार है। सुसंगठित मुद्रा बाजार के अभाव में यह सम्भव हो सकता है कि बैंक दर में होने वाले परिवर्तन बाजारी व्याज की दरों पर अपना प्रभाव न डाल सके। प्रायः यह होता है कि बैंक दर के बढ़ने पर बाजारी व्याज की दर बढ़ तो जाती है किन्तु बैंक दर में कमी होने पर वह एक न्यूनतम सीमा के नीचे नहीं गिरती है। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक मुद्रा-प्रसार की प्रगति को तो रोक सकता है, किन्तु वह बैंक दर को कम करके देश को अवसाद (Depression) से बाहर नहीं निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि बैंक दर तथा बाजारी व्याज की दर में होने वाली वृद्धि व्यापारियों को अधिक ऋण लेने से न रोक सके। यदि वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते जाते हैं और लाभ की भाशा अधिक है, तो व्यापारी ऊँची व्याज की दर पर ऋण लेकर भी विनियोग करेंगे। ऐसी दशा

मे बैंक दर की वृद्धि मुद्रा-प्रसार को रोकने में सफल नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार मुद्रा सकुचन काल में जब लाभ की आशा कम होती है, तो बैंक दर बढ़ा कर को वित्तीय भी कम कर देने से ऋणियों को अधिक ऋण लेकर विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक दर नीति के द्वारा मुद्रा सकुचन (Depression) को रोकना सम्भव नहीं होना है। सन् १९३० की आर्थिक मन्दी में लगभग इसी प्रकार का अनुभव हुआ और सभी देशों में बैंक दर नीति मुद्रा सकुचन की स्थिति पर नियन्त्रण करने में अमफल रही।

(11) देश की अर्थ-व्यवस्था सोचपूर्ण होनी चाहिए—बैंक दर नीति की सफलता के लिए देश के आर्थिक ढाँचे में पर्याप्त सोच का होना आवश्यक है। अर्थ-व्यवस्था इतनी सोचदार होनी चाहिए कि बैंक दर में होने वाले परिवर्तन मूल्यों, मजदूरी तथा व्याज की दरों, मौद्रिक आय, उत्पादन तथा व्यापार पर अपना पूरा प्रभाव डाल सके। यदि अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की सोच नहीं पाई जाती है, तो बैंक दर नीति अधिक सफल नहीं हो सकेगी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था में सोच का अभाव हो जाने के कारण बैंक दर नीति अप्रभावी (Ineffective) हो गई है और इसीलिए बैंक दर नीति का प्रयोग पहले की अपेक्षा कम होन लगा है।

बैंक दर नीति के महत्त्व में कमी

(Decline in the Importance of Bank Rate Policy)—

प्रथम महायुद्ध से पूर्व बैंक दर नीति केन्द्रीय बैंक का साख नियन्त्रण करने का एकमात्र अस्त्र माना जाता था किन्तु युद्ध के पश्चात् उसका महत्त्व कम होने लगा और उसके स्थान पर साख नियन्त्रण की अन्य विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। सन् १९३० के आर्थिक मन्दी काल में उसकी अप्रभावितता (Ineffectiveness) प्रमाणित हो जाने के कारण बैंक दर नीति का प्रयोग और भी अधिक कम हो गया और उसे साख नियन्त्रण के साधन के रूप में अप्रभावशाली समझा जाने लगा। यद्यपि द्वितीय विश्व-युद्ध काल में तथा उसके पश्चात् बैंक दर नीति के प्रयोग में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु फिर भी आज प्रत्येक देश में उसका महत्त्व पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गया है। बैंक दर नीति के महत्त्व में कमी के कारण इस प्रकार है—

(1) मुद्रा बाजार में परिवर्तन तथा अर्थ-व्यवस्था में सोच का अभाव—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मुद्रा बाजार की दशाओं में काफी परिवर्तन हुए हैं। अब व्यापारिक बैंक पहले की अपेक्षा अपने आदेयों (Assets) को अधिक तरल रूप में रखने लगे हैं। बैंकों की तरलता में वृद्धि होने से उनकी केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता कम हो गई है। ऐसी दशा में बैंक दर परिवर्तनों का बाजारी व्याज की दरों पर तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण बैंक दर नीति के अप्रभावशाली होने

की सम्भावना बढ गई है। प्रथम युद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में लोच का गुण कम हो गया है, जिसके कारण बैंक दर परिवर्तन सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। बैंक दर नीति में सफलता के लिए आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था लोचपूर्ण हो जिससे बैंक दर परिवर्तन मूल्यों, मजदूरी तथा व्याज की दरों और उत्पादन व व्यापार पर अपना पूरा प्रभाव डाल सकें। वर्तमान अर्थ-व्यवस्थाओं में इस प्रकार की लोच नहीं पाई जाती है, जिसके कारण बैंक दर नीति की सफलता की सम्भावना कम हो गई है।

(ii) साख नियन्त्रण की अन्य प्रभावशाली विधियों का विकास—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् केन्द्रीय बैंकों के द्वारा साख नियन्त्रण के लिए अन्य प्रभावशाली अस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा जिसके कारण बैंक दर नीति का महत्व कम हो गया। विशेषतया खुले बाजार की नीति तथा बैंकों के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन करने की विधि का प्रयोग इतना अधिक बढ गया कि उनकी तुलना में बैंक दर नीति को घटिया तथा अप्रभावशाली अस्त्र समझा जाने लगा। इस प्रकार बैंक दर नीति का महत्वपूर्ण स्थान खुले बाजार की नीति के द्वारा ले लिया गया।

(iii) बैंक दर परिवर्तनों का प्रभाव सत्कासीन नहीं होता है—बैंक दर साख नियन्त्रण की अप्रत्यक्ष विधि (Indirect Method) है, जिसके कारण बैंक दर परिवर्तनों का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था पर कुछ समय के पश्चात् ही हो पाता है। बैंक दर परिवर्तनों का प्रभाव सबसे पहले व्याज की दरों पर होता है और फिर व्याज की दरों के परिवर्तन साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अतः बैंक दर समाज में साख की मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल सकती है जो इसके अप्रभावशाली होने का एक प्रमुख कारण है। इसके विपरीत खुले बाजार की नीति का साख की मात्रा पर सीधा तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी सफलता की सम्भावना अधिक होती है। साख नियन्त्रण की उस विधि को अधिक प्रच्छा माना जाता है, जिसके प्रभावशाली होने में कम समय लगता हो। बैंक दर नीति अप्रत्यक्ष होने के कारण उसका प्रभाव तुरन्त नहीं होता है, जिसके कारण मौद्रिक प्रबन्ध में उसका महत्व पहले की अपेक्षा कम हो गया है।

(iv) सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy)—ससार में सस्ती मुद्रा नीति का अधिक प्रचलन हो जाने के कारण भी बैंक दर नीति का महत्व कम हो गया है। सन् १९२३ से लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंकों ने सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया, जिसके कारण बैंक दर को कम रखना आवश्यक समझा जाने लगा और इस प्रकार बैंक दर परिवर्तनों की सम्भावना पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई। इसके अतिरिक्त सस्ती मुद्रा नीति के कारण बैंकों के पास नकदी अधिक मात्रा में रहने लगी है और केन्द्रीय बैंक पर उनकी निर्भरता बहुत कम हो गई है। ऐसी दशा में बैंक दर परिवर्तन बाजार की व्याज की दरों पर अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं और इस प्रकार बैंक दर नीति अप्रभावशाली हो जाती है।

बैंकों के द्वारा किया जाता है। विशेषतया मन् १९४५ के पश्चात् बैंक दर नीति का प्रयोग फिर से बढ़ने लगा है और उसने एक बार फिर साख नियन्त्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। रेडक्लिफ़ कमिटी (Redcliffe Committee) ने निश्चित रूप से कहा है कि उगलैंड के मौद्रिक उपायों में बैंक दर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके अनुसार 'बैंक दर इतना महत्वपूर्ण सनेत है कि अन्य उपायों के साथ उसका होना आवश्यक है। समस्त भसार की वर्तमान विचारधारा में स्वयं बैंक दर का काफी महत्वपूर्ण स्थान है।'^{१९}

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—

साख नियन्त्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय करने को खुले बाजार की क्रियाएँ कहा जाता है किन्तु विस्तृत अर्थ में केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार के द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों तथा विलों के क्रय-विक्रय करने को खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सर्वप्रथम साख नियन्त्रण के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया और धीरे-धीरे बैंक दर नीति के पतन के साथ-साथ उसका महत्व बढ़ता गया। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार बैंक दर नीति की असफलताओं के कारण खुले बाजार की क्रियाओं का विकास हुआ।^{२०} पिछले २०-२५ वर्षों में साख नियन्त्रण की इस विधि का प्रयोग काफी बढ़ गया है और केन्द्रीय बैंकों के द्वारा साख का अनावश्यक विस्तार तथा संकुचन रोकने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है।

केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा अन्य बैंकों के नकद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है जिसके द्वारा देश में साख की कुल मात्रा को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। केन्द्रीय बैंक के सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत प्रतिभूतियों को खरीदे जाने में बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और साख का विस्तार हो जाता है। जब केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा तथा साख की पूर्ति को बढ़ाना चाहता है तो वह प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है। प्रतिभूतियों के विक्रेताओं

19 "The bank rate is so important as a symbol that its inclusion in other measures is vital In the present state of the world opinion, bank rate itself has considerable external significance"

—Redcliffe Report, P. 155.

20 "In view of the short-comings of rediscount policy the development of open market operations—the purchase and sale of government securities and other credit instruments in the open market—as an additional, and in some extent alternative, instrument of central bank policy is a logical step."

—Halm : Monetary Theory P. 59,

को उनकी प्रतिभूतियों के बदले में केन्द्रीय बैंक पर लिखे हुए बैंक प्राप्त होते हैं। वे इन बैंकों को अपने बैंकों के पास जमा होने के लिए भेजते हैं जिसके कारण सदस्य बैंकों की जमा केन्द्रीय बैंक के पास बढ़ जाती है और वे इस बढ़ी हुई जमा के आधार पर अधिक मात्रा में साख का निर्माण करते हैं और देश में साख की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा बैंकों के कोषों में वृद्धि करके उन्हें अधिक साख निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। केन्द्रीय बैंक के द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा ऋण-पत्रों के बेचे जाने का इसमें विस्तृत विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि देश में साख का अत्यधिक विस्तार हो रहा है और साख की मात्रा को कम करके देश के हित में है तो वह बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने लगता है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंक के पास रुपया आता है और चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। जो लोग केन्द्रीय बैंक से प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं वे या तो उस नकद रुपया देते हैं अथवा अपने बैंकों पर लिखे हुए बैंक देते हैं। केन्द्रीय बैंक जब इन बैंकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए भेजता है तो उसके परिणामस्वरूप सदस्य बैंकों की जमा केन्द्रीय बैंक के पास कम हो जाती है। साख का आधार संकुचन हो जाने के कारण व्यापारिक बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाते हैं और देश में साख की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं को साख नियन्त्रण के लिए एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और साख संकुचन के लिए उन्हें बेचता है। प्रतिभूतियों के इस प्रकार के क्रय-विक्रय को ही खुले बाजार की क्रियाएँ कहा जाता है।

खुले बाजार की क्रियाओं को बैंक दर नीति की अपेक्षा साख नियन्त्रण का अधिक प्रभावशाली अस्त्र माना जाता है क्योंकि साख की मात्रा पर उसका प्रभाव प्रत्यक्ष तथा निश्चित होता है। बैंक दर नीति के प्रभाव अप्रत्यक्ष होने के कारण उसे प्रभावशाली होने में कुछ समय लगता है किन्तु खुले बाजार की क्रियाओं में यह दोष नहीं है। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का बैंकों के कोषों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और इस विधि के द्वारा साख की मात्रा को तुरन्त घटाया बढ़ाया जा सकता है। बैंक दर का प्रभाव तत्काल तो केवल व्याज की अल्पकालीन दरों पर ही पड़ता है और दीर्घकालीन व्याज की दरों पर उसका प्रभाव काफी समय के पश्चात् होता है किन्तु इसके विपरीत खुले बाजार की क्रियाओं का प्रभाव दोनों प्रकार की व्याज की दरों पर एक साथ होता है तथा वह तत्काल ही पड़ता है। इन सब कारणों से ही खुले बाजार की क्रियाओं को साख नियन्त्रण विधि के रूप में बैंक दर नीति से अच्छा समझा जाता है। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक दर नीति की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक के लिए अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनकी सफलता बहुत कुछ केन्द्रीय बैंक के हाथ में होती है।

दर नीति की मफलता व्यापारिक बैंको तथा उनके ग्राहकों के व्यवहार पर निर्भर होती है।^{२१}

खुले बाजार की क्रियाओं की सीमायें

(Limitation of Open Market Operations) -

खुले बाजार की क्रियायें केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सफल होती हैं। यदि किसी देश में उनकी सफलता के लिए उपयुक्त दशायें नहीं पाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में खुले बाजार की क्रियायें अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकेंगी। सामान्यतः खुले बाजार की क्रियाओं की मफलता के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है -

(१) खुले बाजार की क्रियाओं का अन्य बैंकों के कोषों (Reserves) पर निश्चित प्रभाव पड़ना चाहिए। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इन क्रियाओं से बैंको तथा अन्य साख मस्थाओं के नकद कोष (Cash Reserves) प्रभावित होने चाहिए। केन्द्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों के बेचे जाने से बैंको के कोष कम हो जानें चाहिए और खरीदे जाने से उनके कोषों में वृद्धि होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि केन्द्रीय बैंक के प्रतिभूतियाँ बेचने पर भी अन्य बैंकों के कोष कम न हों। यदि विदेशों से काफी रुपया आ रहा है और उसे बैंको में जमा किया जा रहा है तो ऐसी दशा में खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा बैंको के कोषों को कम करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार यदि व्यापारिक बैंक अपने कोषों में होने वाली कमी को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर पूरा कर लेते हैं तो ऐसी दशा में भी खुले बाजार की क्रियायें असफल रहेंगी। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए मुद्रा बाजार का सगठन ऐसा होना चाहिए कि व्यवसायिक बैंक ऋण लेने के लिए ऋणा केन्द्रीय बैंक के पास न जाते हों। लन्दन के मुद्रा बाजार में ऐसा ही होता है और इसी कारण वहाँ पर खुले बाजार की क्रियायें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सफल रहती हैं। इसके विपरीत अमेरिका में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है क्योंकि वहाँ व्यापारिक बैंक सीधा फेडरल रिजर्व बैंको (Federal Reserve Banks) से ऋण लेकर अपने कोषों की क्षति को पूरा कर लेते हैं। इसके विपरीत मुद्रा विस्तार की नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक के प्रतिभूतियाँ खरीदने पर बैंको के कोष बढ़ जायें। यदि देश में लोग अधिक मुद्रा का सग्रह करने लगे हैं अथवा विदेशों को

21 "From the standpoint of their strategic value to the central bank, open market operations possess a degree of superiority over rediscount policy because of the fact that the initiative is in the hands of the monetary authority in the case of the former, where as the bank rate policy is passive in the sense that its effectiveness depends on the responses of commercial banks and their customers to changes in bank rates."

पूँजी का निर्यात किया जा रहा है तो ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियाँ खरीदने पर भी बैंको के कोषों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकेगी और साथ उद्देश्य का विस्तार पूरा नहीं होगा ।

(२) नकद कोषों में परिवर्तन होने पर बैंकों के द्वारा साख का विस्तार अथवा संकुचन किया जाना चाहिए—खुले बाजार की क्रियायें तभी सफल हो सकती हैं जबकि व्यापारिक बैंक अपने नकद कोषों में परिवर्तन के अनुसार साख की मात्रा हैं में भी परिवर्तन करते हैं । अर्थात् कोषों में वृद्धि होने पर भी वे अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए तैयार हो तथा कोष कम हो जाने पर अपने ऋणों की मात्रा को कम कर दें । यह सम्भव हो सकता है कि कोषों में वृद्धि होने पर भी वे ऋणों की मात्रा को न बढ़ाये क्योंकि बैंक केवल अपने कोषों के आधार पर ही साख का विस्तार नहीं करते हैं बल्कि वे देश की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं यदि राजनैतिक अस्थिरता के कारण मुद्रा बाजार में घबराहट है अथवा विश्वास की कमी है तो ऐसी दशा में बैंक अपने नकद कोषों के बढ जाने पर भी साख का विस्तार नहीं करेंगे और केन्द्रीय बैंक अपनी नीति में असफल हो जायगा ।

(३) बैंक के कोषों में परिवर्तन होने के साथ ऋणों की मांग में भी परिवर्तन होना चाहिए—बैंकों के नकद कोषों के घटने-बढ़ने पर उत्पादकों की ऋणों की मांग भी घटती-बढ़ती रहनी चाहिए । अर्थात् जब बैंक अधिक ऋण देने के लिए तैयार हो तो उत्पादकों को भी अधिक मात्रा में ऋण की मांग करनी चाहिए । किन्तु उत्पादकों की मांग बैंक कोषों के अनुसार नहीं करते हैं बल्कि वे लाभ की आशा के अनुसार ऋणों की मांग किया करते हैं । यदि लाभ की आशा कम होती है तो वे ऋणों की मात्रा को कम कर देते हैं । यही कारण है कि अवसाद (Depression) की दशाओं में खुले बाजार की क्रियायें अधिक सफल नहीं होती हैं । केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीदकर बैंकों के कोष बढ़ा देता है और बैंक भी अधिक मात्रा में ऋण देना चाहते हैं किन्तु लाभ की आशा कम होने के कारण उत्पादकों को अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में साख विस्तार नीति असफल हो जायेगी । अतः खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा केन्द्रीय बैंक मुद्रा-प्रसार को तो रोक सकता है किन्तु मन्दी की दशाओं से देश को बाहर निकालने में उसे अधिक सफलता नहीं मिल सकती है ।

(४) केन्द्रीय बैंक में प्रतिभूतियों को बेचने तथा खरीदने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए—खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर होती है कि केन्द्रीय बैंक वे पाम बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिभूतियाँ हैं अथवा नहीं । इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक के पास प्रतिभूतियों को खरीदने की भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए । प्रायः अल्प विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में बेचने योग्य प्रतिभूतियाँ न होने के कारण खुले बाजार की क्रियाओं

का क्षेत्र सीमित हो जाता है। ऐसी क्रियाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक के पास बेचने के लिए काफी मात्रा में प्रतिभूतियाँ हों तथा वह किसी भी सीमा तक प्रतिभूतियों को खरीदने की क्षमता रखता हो।

(५) विवक्षित मुद्रा बाजार का होना—खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित तथा सुमगठित हो जिसमें विभिन्न प्रकार की माख सस्थाओं का केन्द्रीय बैंक के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो। देश में ऋण पत्रों तथा प्रतिभूतियों का बाजार पूर्णतया विकसित होना चाहिए। अल्प-विकसित देशों में मुद्रा बाजार का उचित संगठन न होना तथा ऋण-पत्रों के बाजार के अभाव के कारण खुले बाजार की क्रियाओं को बबल सीमित सफलता ही मिल पाती है।

(६) प्रतिभूतियों के बाजार पर बुरा प्रभाव—अल्प-विकसित देशों में खुले बाजार की क्रियाओं का क्षेत्र इसलिए भी सीमित हो जाता है क्योंकि केन्द्रीय बैंक के द्वारा अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों का बेचा जाना उनके बाजार पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। जब केन्द्रीय बैंक बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है तो प्रतिभूतियों के बाजार में मन्दो आ जाती है और उनका मूल्य गिर जाता है जिसका केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के संपत्तियों (Assets) पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सरकारी ऋणों का प्रोग्राम अस्त-व्यस्त हो जाता है। ऐसी दशाओं में केन्द्रीय बैंक का यह कर्तव्य होता है कि वह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बाजार में स्थिरता को बनाये रखने जिसके कारण खुले बाजार की क्रियाओं के प्रयोग की सम्भावना कम रह जाती है।

बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की नीति एक दूसरे की पूरक है—

कुछ लेखकों का विचार है कि बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे की पूरक हैं। प्रो० हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार साख नियन्त्रण तब ही प्रभावशाली हो सकता है जबकि खुले बाजार की क्रियाओं तथा बैंक दर का साथ साथ प्रयोग किया जाये। खुले बाजार की क्रियाओं को बैंक-दर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रो० क्लार्क (Clark) के अनुसार “साख नियन्त्रण के दृष्टिकोण से खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक दर नीति की पूरक हैं।”^{२२} केन्द्रीय बैंक की दर में वृद्धि करने से पूर्व बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर बैंकों के पास से अनिश्चित मुद्रा को निकाल लेना चाहिए और तब बैंक दर में वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा करने से बैंक दर की वृद्धि को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि बैंकों के

पास अपने कोष बाफ़ी है तो वे बैंक दर के बढ़ने पर अपनी व्याज की दर को नहीं बढ़ायेंगे क्योंकि वे केन्द्रीय बैंक में बिना ऋण लिए हुए ही अधिक मात्रा में साख़ का निर्माण कर सकते हैं। अतः बैंक दर में वृद्धि करने से पूर्व केन्द्रीय बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा बैंको के बोझों को कम कर देना चाहिए। कभी कभी खुले बाजार की क्रियाओं को सफल करने के लिए भी बैंक दर में परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रकार साख़ नियन्त्रण की इन दोनों विधियों का साथ-साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लेखकों ने खुले बाजार की नीति के स्वतन्त्र प्रयोग पर अधिक बल दिया है। प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार खुले बाजार की क्रियाएँ, साख़ नियन्त्रण के अन्य किसी साधन की सहायता के बिना ही मुद्रा व साख़ की मात्रा पर उचित नियन्त्रण कर सकती है। इस मतभेद के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि यदि दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाय तो वे अधिक प्रभावशाली रहेंगी।

(३) बैंको की रक्षित-निधि के अनुपात को घटाना तथा बढ़ाना

(Variation in Reserve Ratio of Banks)—

केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको की रक्षित निधि के अनुपात में परिवर्तन करके साख़ नियन्त्रण कर सकता है। देश में प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात केन्द्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। केन्द्रीय बैंक इस अनुपात को घटा-बढ़ा कर व्यापारिक बैंको की साख़ निर्माण करने की शक्ति में परिवर्तन कर सकता है। जब केन्द्रीय बैंक साख़ का संकुचन करना चाहता है तो वह व्यापारिक बैंको के द्वारा रखी जाने वाली सुरक्षित निधि का अनुपात बढ़ा देता है जिसके कारण बैंको को केन्द्रीय बैंक में पास अधिक राशि जमा करनी पड़ती है और उनके पास कम नक़द कोष रह जाता है जिसके आधार पर वे कम साख़ का निर्माण कर पाते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक रक्षित-निधि के अनुपात को बढ़ाकर बैंको की साख़-निर्माण करने की शक्ति को कम कर सकता है। उसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक साख़ का अधिक विस्तार करना चाहता है तो वह रक्षित-निधि के अनुपात को घटा देता है जिसके कारण बैंको के पास अधिक नक़द कोष रहते हैं। बोझों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण बैंक उनके आधार पर अधिक मात्रा में ऋण देते हैं और साख़ का विस्तार होता है। अतः केन्द्रीय बैंक के द्वारा रक्षित निधि के अनुपात को बढ़ाकर साख़ का संकुचन किया जा सकता है और उसे कम करके साख़ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

आजकल साख़ नियन्त्रण की इस विधि का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंको को अपने सदस्य बैंको की रक्षित-निधि के अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया है। यह विधि प्रत्यक्ष होने के कारण अधिक प्रभावशाली रहती है किन्तु इसमें बड़ा दोष यह है कि रक्षित विधि

के अनुपात में परिवर्तन करने का सब बैंको पर एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता है।²³ रक्षित निधि के अनुपात के बढ़ने के कारण छोटे बैंको को बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास नकदी की मात्रा कम रहती है जबकि बड़े बैंको को कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए इस विधि को न्यायमग्न नहीं बतलाया जाता है। क्योंकि यह नीति काफी बढोर होती है इसलिए इसका प्रयोग करते समय केन्द्रीय बैंक को दली सावधानी से काम लेना चाहिए। इस नीति की कुछ अन्य सीमायें भी हैं जैसे रक्षित निधि के अनुपात में परिवर्तन करके व्यापारिक बैंको के कोषों की तो घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है किन्तु इन परिवर्तनों के अनुसार बैंक मईव साख की मात्रा में परिवर्तन नहीं करते हैं और ऐसी दशा में यह नीति भी अधिक सफल नहीं होती है। इसके अनिश्चित रक्षित नीति के अनुपात में परिवर्तनों का सभी बैंको की साख निर्माण करने की क्षमता पर प्रत्यक्ष तथा सुरन्त प्रभाव पड़ता है जिसके कारण यह एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति हो जाती है जिसका प्रयोग बैंको अथवा सम्पूर्ण समाज को लाभ अथवा हानि पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक पर इसके उचित प्रयोग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आ जाना है। इन सीमाओं न होने हुए भी साख नियन्त्रण की यह विधि विशेष महत्व रखती है। इसलिए बर्जस (Burgess) ने लिखा है कि “सीमाओं के होते हुए भी बैंको के रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन करने की शक्ति, विशेषतया अवसाद के कारण उत्पन्न अत्यधिक कोषों की स्थिति को ठीक करने के लिए साख नियन्त्रण की व्यवस्था में सर्वाधिक उपयोगी है।”²⁴

साख के प्रयोग पर नियन्त्रण (Selective Credit Control)

उक्तलिखित विधियों के द्वारा केवल साख की मात्रा को नियन्त्रित किया जा सकता है किन्तु समाज की नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में साख का प्रयोग भी नियन्त्रित होना चाहिए। स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के अनुसार केन्द्रीय बैंक से केवल सामान्य साख नियन्त्रण (General Credit Control) ही करना चाहिए और साख के प्रयोग सम्बन्धी निम्न व्यक्तित्व व्यवसायियों के द्वारा किये जाने चाहिए। किन्तु एक नियन्त्रित समाज में साख के प्रयोग को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे नियन्त्रित करने के लिए केन्द्रीय बैंक को

23 “ When reserve requirements are increased some banks will be hit harder than others ”

—Burgess Quote by De Kock in Central Banking op P. 219

24 “Despite these limitations the power (to raise or lower the bank's reserve requirements) is the most useful addition to the systems' mechanism of credit control, especially as a means for dealing fundamentally with the large excess of reserves created by the extra ordinary events of the depression emergency.”

—Burgess : Reserve Banks and Money Market, P. 270.

विशेष साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) करना होता है। विशेष साख नियन्त्रण के अन्तर्गत केवल विशेष प्रकार की साख को ही प्रभावित किया जाता है और अन्य प्रकार की साख पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि साख को केवल पूर्वं निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया जाय। इस प्रकार के नियन्त्रण में साख का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों तथा व्यवसायों में किया जाता है जिनके विस्तार की सरकार ने प्राथमिकता दी हुई है और साख को उन क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाता है जहाँ पर उसका प्रयोग उतना आवश्यक नहीं है अथवा जहाँ उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः विशेष साख नियन्त्रण के अन्तर्गत साख का प्रयोग आवश्यक तथा उपयोगी क्षेत्रों में ही किया जाता है और अनावश्यक तथा अनुपयोगी क्षेत्रों में उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। साख के प्रयोग को नियन्त्रित करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन (Changes in the Margin Requirements)—केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों की सीमा आवश्यकता (Margin Requirement) में परिवर्तन करके साख के प्रयोग को नियन्त्रित कर सकता है। विभिन्न प्रकार की जमानतों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की सीमा आवश्यकता को केन्द्रीय बैंक के द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाता है और व्यापारिक बैंकों के लिए इन आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। ऋणों की सीमा आवश्यकता (Margin Requirement) उस अन्तर को बताती है जो प्रतिभूतियों के बाजारी मूल्य तथा उन पर प्राप्त ऋण की मात्रा में होता है। यदि १०० रुपये की प्रतिभूति पर बैंक ७० रुपये ऋण देता है तो इस ऋण के सम्बन्ध में सीमा आवश्यकता ३०% है। केन्द्रीय बैंक विशेष प्रकार के ऋणों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सीमा आवश्यकता को कम कर सकता है। इसके विपरीत जिन दिशाओं में वह साख के प्रवाह को कम करना चाहता है उससे सम्बन्धित ऋणों की सीमा आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार की नीति का मुख्य उद्देश्य साख को सट्टे तथा अन्य अनुपयोगी कार्यों से हटाकर उपयोगी तथा आवश्यक कार्यों में लगाना होना है। जिस प्रकार के ऋणों को केन्द्रीय बैंक प्रोत्साहित करना चाहता है उनकी सीमा आवश्यकता को कम कर दिया जाता है तथा जिन्हें वह रोकना चाहता है उनकी सीमा आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि बैंक सट्टा व्यवसाय तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए अधिक ऋण दे रहे हैं तो वह इस प्रकार के ऋणों की सीमा आवश्यकता को बढ़ा देता है जिससे कारण उस क्षेत्र में साख का प्रवाह कम हो जाता है। उत्पादक क्षेत्रों में साख के प्रवाह को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बैंक इस प्रकार के ऋणों की सीमा आवश्यकता को कम कर देता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में सट्टे

की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया। इसके लिए वहाँ के फ़ैडरल रिजर्व बैंको (Federal Reserve Banks) की प्रतिभूतियों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा को निश्चित करने का विशेष अधिकार दिया गया। आजकान इसे साख की मात्रा एवं उसके प्रयोग को नियन्त्रित करने का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है और इसीलिए इसका प्रयोग अधिकाधिक रूप से किया जाने लगा है।

(२) नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)—केन्द्रीय बैंक अपने नैतिक प्रभाव के द्वारा भी साख को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है। वह समय-समय पर बैंको को इस प्रकार के आदेश-पत्र भेजता रहता है जिनमें उन्हें मसाह दी जाती है कि वे कब साख का विस्तार करे तथा कब साख-मकुबन नीति को अपनायें। उन्हें किस प्रकार के प्रयोगों के लिए अधिक मात्रा में ऋण देने चाहिएँ और किन कामों के लिए ऋणों को सीमित रखना चाहिएँ। नैतिक प्रभाव की नीति के द्वारा साख की मात्रा तथा उसके प्रयोग दोनों पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इन प्रकार की नीति के अन्तर्गत बैंको पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है बल्कि उन्हें समझा-बुझा कर तथा नैतिक प्रभाव के द्वारा विशेष प्रकार की साख नीति को अपनाने के लिए सहमत किया जाना है। नैतिक प्रभाव की नीति का मुख्य उद्देश्य बैंक प्रबंधकों पर ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना होता है जिसमें कि वे केन्द्रीय बैंक की साख नीति को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो जायें।

केन्द्रीय बैंक वहाँ तक अन्य बैंको पर नैतिक प्रभाव डालने में सफल होता है—यह इस बात पर निर्भर है कि उसे अन्य बैंको का नेतृत्व (Leadership) कहाँ तक प्राप्त है। यदि केन्द्रीय बैंक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली है तो उसकी नैतिक प्रभाव की नीति को अधिक सफलता मिलने की सम्भावना होती है। यद्यपि इंग्लैंड, फ्रान्स, स्वीडन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों में नैतिक प्रभाव की नीति को पर्याप्त सफलता मिली है किन्तु फिर भी उसे साख नियन्त्रण का प्रभावशाली अस्त्र नहीं माना जा सकता है। उसका प्रयोग साख नियन्त्रण की अन्य विधियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया जा सकता है।

(३) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)—विस्तृत अर्थ में प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत नैतिक प्रभाव को भी सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु इसे नैतिक प्रभाव से अलग करके ही अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की वे सब कार्यवाहियाँ आती हैं जो वह उन बैंको तथा साख संस्थाओं के विरुद्ध करता है जो उसके पण्यमशौ की अवहेलना करते हैं। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि कुछ व्यापारिक बैंक तथा अन्य साख संस्थाएँ उसकी घोषित नीति के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो वह उनके विरुद्ध सीधी कार्यवाही की नीति को अपनाता है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक इन अमहशोरी संस्थाओं के

विनिमय-पत्रों तथा टुण्डियों को भुनाने से इन्कार कर देता है या उनसे दण्ड के रूप में ऋणों पर अधिक व्याज देने लगता है।

तानाशाही देशों में व्यापारिक बैंकों की साख सम्बन्धी क्रियाओं पर केन्द्रीय बैंक का प्रत्यक्ष नियन्त्रण होता है और साम्य सत्थाओं की केन्द्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही ऋण देने होते हैं। ऋणों की मात्रा, ऋणों का उद्देश्य तथा उस पर लिए जाने वाले व्याज की दर केन्द्रीय बैंक के द्वारा निश्चित किये जाते हैं। युद्ध काल में अन्य देशों में भी इस प्रकार के विशेष अधिकार केन्द्रीय बैंक को दिये गये। आज भी बहुत से देशों के सरकारी केन्द्रीय बैंकों को, व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं को सीधा नियन्त्रित करने की शक्ति दी हुई है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत में रिजर्व बैंक को साख के प्रयोग पर नियन्त्रण करने के विशेष अधिकार दिये गये जिनके अन्तर्गत उसने १९४६ तथा १९५८ में व्यापारिक बैंकों को गेहूँ और चावल की आड़ पर ऋण न देने का आदेश दिया जिसका उद्देश्य इन वस्तुओं में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकना था।

प्रत्यक्ष कार्यवाही को साख नियन्त्रण की अच्छी विधि नहीं समझा जाता है क्योंकि उसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों को एक विशेष प्रकार की साख नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया जाना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यह नीति सरल नहीं है क्योंकि किसी बैंक के बारे में यह निश्चित करना, कि वह अपनी साख निर्माण शक्ति का प्रयोग स्वस्थ साख व्यवस्था के विरुद्ध कर रहा है, काफी कठिन काम है। इन दोषों के कारण ही इस विधि का प्रयोग केवल सवट काल अथवा विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।

(४) साख का राशन करना (Rationing of Credit)—साख राशन की नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को दी जाने वाली साख के उद्देश्यों को निश्चित करता है तथा विभिन्न प्रार्थी बैंकों में कुल साख का नियन्त्रित वितरण करता है। केन्द्रीय बैंक अपने द्वारा दी जाने वाली साख की अधिकतम सुरक्षित सीमा निश्चित कर देता है और फिर विभिन्न बैंकों के द्रव्यता (quotas) निर्धारित कर दिये जाते हैं जिनसे अधिक मात्रा में किसी भी बैंक को केन्द्रीय बैंक से साख सुविधायें नहीं मिलती हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को पूर्णतया नियन्त्रित कर सकता है। यद्यपि साख राशनिंग के द्वारा साख की मात्रा तथा उसके प्रयोग दोनों पर ही नियन्त्रण किया जा सकता है किन्तु साख के प्रयोगों को नियन्त्रित करने के लिए यह विधि अधिक उपयोगी होती है। केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा विनियोगों के लिए साख की अधिकतम सीमा निश्चित कर देता है और इन निश्चित उद्देश्यों के लिए ही साख का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी तथा अनावश्यक कार्यों के लिए साख का प्रयोग नहीं होने दिया जाता है। यद्यपि साख राशनिंग की नीति काफी प्रभावशाली होती है और

उसके द्वारा साख का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है किन्तु इस नीति को कार्य-रूप में लाने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं। इसके अतिरिक्त इस नीति के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है जिसके कारण प्रजातन्त्र (Democratic) देशों में इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तथा अन्य साम्यवादी देशों में यह नीति बहुत अधिक प्रचलित रही है।

वैश्वीय तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में साख नियंत्रण की इस विधि का विशेष महत्व है। साख एवं पूँजी का राशनित करना विस्तृत नियोजन का ही एक भाग है और इसे समाजवादी तथा पिछड़े हुये देशों में एक सप्रभाविक नीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्प विकसित देशों में साख के प्रयोग पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है क्योंकि उनके बिना मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है। अतः साख के प्रयोग को नियंत्रित करने की विधि के रूप में साख का राशन करना नियोजित अर्थ-व्यवस्था की मौद्रिक नीति का आवश्यक अंग हो सकता है।

(५) उपभोक्ता साख पर नियंत्रण (Regulation of Consumer's Credit)—उपभोक्ताओं की दी जाने वाली साख पर नियंत्रण करके भी केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा तथा उसके प्रयोगों को निश्चित कर सकता है। यह नीति विकसित देशों में अधिक सफल होती है क्योंकि वहाँ पर उपभोक्ता काफी बड़ी मात्रा में कीमती वस्तुएँ किरत-साख (Instalment Credit) के आधार पर खरीदते हैं। सर्वप्रथम, द्वितीय विश्व-युद्ध काल में मुद्रा-प्रसार को रोकने तथा वस्तुओं की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण किया गया। इसी उद्देश्य के लिए इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करने की नीति का विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक उपभोक्ताओं की दी जाने वाली किरत-साख (Instalment Credit) की अधिकतम सीमा, वस्तुओं के बेचते समय उनके मूल्य का नकद रूप में लिया जाने वाला प्रतिशत तथा इस प्रकार के ऋणों के मुसलान की अधिकतम अवधि निश्चित कर देता है। मुद्रा-प्रसार काल में इस प्रकार ऋणों को कम किया जाता है जिससे वस्तुओं की मांग घटती है और मुद्रा-प्रसार का दबाव कम हो जाता है। इसके विपरीत अवनवाद काल में वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए किरत-साख को अधिक सुविधापूर्ण कर दिया जाता है। अतः केन्द्रीय बैंक जब साख का विस्तार करना चाहता है तो वह किन्तु माध्य की सुविधाओं को बढ़ा देता है और जब वह साख का संकुचन करना चाहता है तो किरत-साख की सुविधाओं को कम कर दिया जाता है।

केन्द्रीय बैंक और आर्थिक विकास

(Central Bank and Economic Development)—

विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य मुद्रा बाजार को नियंत्रित करना समझा जाता है और किसी भी प्रकार के विकास के लिए वित्तीय साधनों का प्रवर्धन करना उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। किन्तु अल्प-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक के कार्य-क्षेत्र को इतना सीमित नहीं रखा जा सकता है। इन देशों के केन्द्रीय बैंकों को मुद्रा बाजार का नियंत्रण करने के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध करने चाहिए। इस विचार परिवर्तन के कारण वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंक के उत्तरदायित्व में काफी वृद्धि हो गई है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधन जुटाना केन्द्रीय बैंक की प्रमुख जिम्मेदारी बन भी जाती है। संयुक्त अमेरिकन देशों के कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार तो केन्द्रीय बैंक को औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्त का प्रवर्धन करना चाहिए। यद्यपि इस विचार से अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं किन्तु फिर भी आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कर्तव्य समझा जाता है। डा० सेन (S. N. Sen) के अनुसार—“अल्प-विकसित देशों में सामान्य विचारधारा के अनुसार केन्द्रीय बैंक को केवल मुद्रा बाजार का नियंत्रक ही नहीं बल्कि व्याज की दरों को नीचा रखने तथा देश के साधनों का तीव्र विकास करने वाली सस्था समझा जाता है।”^{२५} अल्प-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंकों के सम्मुख नई समस्याएँ तथा नये उत्तरदायित्व आ गये हैं और उनकी सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर हो गई है कि वे कहीं तक आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अभी तक केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य व्यापारिक बैंकों की साख्त क्रियाओं को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता स्थापित करना समझा जाता रहा है किन्तु आधुनिक विचारधारा के अनुसार केन्द्रीय बैंक को आर्थिक विकास में भी सहयोग देना चाहिए। विशेषतया अल्प-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने वाली सस्था समझा जाने लगा है। इन देशों में उसकी मुद्रा व साख्त नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न करना होना चाहिए।

अल्प-विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों के समक्ष दो प्रमुख समस्याएँ हैं। एक ओर तो उन्हें देश के आर्थिक विकास के लिए अधिकाधिक मात्रा में मौद्रिक साधन उपलब्ध करने हैं तथा उनके उचित प्रयोग का प्रवर्धन करना है और दूसरी ओर

25 “In underdeveloped countries, popular opinion has looked upon the central bank not only as the controller of the money market, but also as the agency for bringing about an era of low interest rates and the rapid development of the resources of the country.”

—S. N. Sen : Central Banking in Underdeveloped Countries, P. 206

उन्हें मुद्रा-स्फीति की शक्तियों को नियंत्रण में रखना है। अर्थात् उन्हें साल नियंत्रण तथा साल विस्तार की नीति को साथ-साथ चलाना है। उनके सामने बिना मुद्रा-प्रसार के तेजी के साथ आर्थिक विकास करने की कठिन समस्या है। केन्द्रीय बैंक किस प्रकार इन विरोधी उद्देश्यों में समन्वय करते हैं, इस पर ही उनकी सफलता अथवा असफलता निर्भर है। अल्प-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक को आर्थिक विकास की एक उपयोगी मस्या के रूप में विकसित होना है। उन्हें आर्थिक विकास सम्बन्धी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करना होगा तथा पुरानी साल नीति के स्थान पर नई एवं प्रगतिशील साल नीति को अपनाना होगा।

अल्प-विकसित देशों में मुद्रा प्रबन्ध

(Monetary Management in Under-developed Countries)—

अल्प-विकसित देशों में मुद्रा व साल का प्रबन्ध करना विकसित देशों की अपेक्षा अधिक कठिन एवं अधिक आवश्यक है। इन देशों में सुमगठित मुद्रा बाजार के अभाव के कारण परम्परागत बैंक दर नीति के द्वारा साल पर प्रभावशाली नियंत्रण करना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश का मुद्रा बाजार इस प्रकार संगठित हो कि केन्द्रीय बैंक की क्रियाओं का प्रभाव तीव्र गति से मुद्रा बाजार व प्रत्येक भाग में फैल जाये। मुद्रा बाजार इतना संगठित तथा परस्पर निर्भर होना चाहिए कि यदि केन्द्रीय बैंक उसके एक केन्द्र को छूता है तो सम्पूर्ण बाजार उसके प्रभाव से उत्तेजित हो जाना चाहिए।²⁶ अल्प-विकसित देशों में मुद्रा बाजार न तो इतना विकसित होता है और न सुमगठित, जिसके कारण बैंक दर परिवर्तन साल व्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं और केन्द्रीय बैंक साल नियंत्रण के लिए बैंक दर नीति पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता है। अल्प-विकसित देशों में विस्तृत तथा सक्रिय प्रतिभूति बाजार एवं बिल बाजार भी नहीं होता है जिसके कारण केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं का क्षेत्र भी अत्यन्त सकुचित हो जाता है। इन देशों के केन्द्रीय बैंक साल नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रियाओं पर भी अधिक निर्भर नहीं रह सकते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्पविकसित देशों में बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली नहीं होती है तथा खुले बाजार की

26 "The central bank touches one spot in the market, and the rest will react to the stimulus. The whole of the money market is, as it were, a single credit pool, in which, whenever the central bank flings a stone, waves will gradually reach all shores"

—S. N. Sen. Central Banking in Under-developed Money Markets, P. 21.

क्रियाएँ सम्भव होते हुये भी पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा सकती हैं।^{२७} इन्हीं सब कारणों से अल्प-विकसित देशों में साख नियन्त्रण की परम्परागत विधियाँ अधिक सफल नहीं हो सकती हैं और इन देशों के केन्द्रीय बैंकों को अन्य प्रभावशाली विधियों की खोज करनी चाहिए। मुद्रा बाजार के अविकसित होने की दशा में केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों में परिवर्तन करके साख की मात्रा पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण कर सकता है। यह विधि अल्प-विकसित देशों में विशेष महत्व रखती है। इसीलिए अल्प-विकसित देशों के अधिकांश केन्द्रीय बैंकों को सदस्य बैंकों के नकद कोष में परिवर्तन करने के विशेष अधिकार दे दिये गये हैं जिनके कारण उनकी वैधानिक शक्ति सम्भवतः विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों से भी अधिक हो गई है।^{२८}

अल्प-विकसित देशों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन देशों में मौद्रिक प्रवृद्ध करते समय साख के प्रयोग पर नियन्त्रण करने की अधिक महत्व दिया जाय। सामान्य साख नियन्त्रण के साथ-साथ इन देशों के केन्द्रीय बैंकों को विशेष साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) की नीति भी अपनानी चाहिए। नियोजित आर्थिक विकास के लिए साख के प्रयोग पर नियन्त्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साख का विशेष नियन्त्रण सोचपूर्ण होता है जिसके कारण साख नीति अधिक सोचदार हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के नियन्त्रण को अर्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है जिनमें अधिक उत्तार-चढ़ाव आते हैं। विशेष साख नियन्त्रण साधनों को अनावश्यक प्रयोगों से हटाकर अधिक उपयोगी प्रयोगों में लगाता है जिनसे अल्प-विकसित देश काफी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि इन देशों में साधनों की कमी है। विकसित देशों की सामान्य अवस्था में विशेष साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) का विरोध किया जा सकता है किन्तु अल्प-विकसित देशों की असामान्य परिस्थिति में विशेष साख नियन्त्रण अनिवार्य है और इन देशों के केन्द्रीय बैंकों को उसे अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

- (१) 'अधिकोषण दर' की परिभाषा कीजिए। किसी देश के व्यापार एवं उद्योग को अधिकोषण-दर-परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

(आगरा बी० ए० १९६१)

27 " ... the Bank rate policy may not prove effective, and open market operations, while feasible on certain occasion, may not be possible on the necessary scale in undeveloped money markets."

—S. N. Sen : Central Banking in Under-developed Money Markets, P. 85.

28 "Even though recently established, most of them are equipped with all the legal powers—even perhaps more—common to their counterparts in the highly developed countries."

—L. V. Chandler : Central Banking & Economic Development, P. 4.

- (२) केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और बताइये कि यह बाजार में खुले रूप से कार्य करके साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (आगरा बी० ए० १९६४)
- (३) केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण करने की दोन-सी पद्धतियाँ हैं ? (आगरा बी० ए० १९६२)
- (४) "बैंक दर व खुले बाजार की क्रियायें केन्द्रीय बैंक के हाथों में साख नियन्त्रण के लिए दो अस्त्र हैं ।" समझाइये (आगरा बी० ए० १९६१)
- (५) केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये और बताइये कि यह साख का नियन्त्रण (क) बाजार में खुले रूप से कार्य करके तथा (ख) बैंक दर के द्वारा किस प्रकार करता है ? (आगरा बी० ए० १९५६)
- (६) बैंक दर की परिभाषा कीजिए । किसी देश के व्यापार एवं उद्योग की बैंक दर के परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित करते हैं ? (आगरा बी० कॉम० १९५६ त)
- (७) किसी केन्द्रीय बैंक के साख नियन्त्रण सम्बन्धित उद्देश्यों एवं पद्धतियों का विवेचन करिये । (आगरा बी० कॉम० १९५६)
- (८) बैंक दर को समझाइये । किसी देश की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर इसके प्रभाव का भी विवेचन करिये । क्या यह भारत में प्रभावपूर्ण रीति से कार्यान्वित की जा सकती है ? (राजस्थान बी० कॉम० १९५४)
- (९) साख नियन्त्रण के उद्देश्यों तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिये । (राजस्थान बी० कॉम० १९६०)
- (१०) साख नियन्त्रण के उद्देश्य बताइये और इस सम्बन्ध में एक सप्रभाविक साधन के रूप में बैंक दर का महत्त्व बताइये । (पटना बी० कॉम० १९६०)
- (११) केन्द्रीय बैंक के क्या कार्य हैं ? केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों की फेल होने से किस प्रकार बचाता है ? (सागर बी० ए० १९५६)
- (१२) केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अन्तर स्पष्ट कीजिये । (सागर बी० ए० १९५७)
- (१३) भारत जैसे कम विकसित मुद्रा बाजार में केन्द्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिये । (सागर बी० कॉम० १९५५)
- (१४) व्यापारिक बैंक एवं केन्द्रीय बैंक में भेद कीजिए । साख के परिमाण पर केन्द्रीय बैंक द्वारा किन-किन रीतियों से नियन्त्रण रखा जाता है ? (जबलपुर बी० कॉम० १९५८)
- (१५) 'सस्ती मुद्रा नीति' से क्या आशय है ? किन परिस्थितियों में इसे अपनाते से लाभ हो सकता है ? (आगरा बी० ए० १९५६)

भारतीय मुद्रा बाजार

INDIAN MONEY MARKET

मुद्रा बाजार का अर्थ (Meaning of Money Market)—

जिस प्रकार अन्य वस्तुओं का बाजार होता है ठीक उसी प्रकार मुद्रा का भी बाजार होता है। इस बाजार में अन्य वस्तुओं की भाँति एक निश्चित मूल्य पर मुद्रा का क्रय-विक्रय किया जाता है। यह मूल्य मुद्रा के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की आपसी प्रतियोगिता के द्वारा निश्चिन् होता है। मुद्रा के क्रय-विक्रय से अभिप्राय मुद्रा के लेन देन से होता है तथा मुद्रा का मूल्य ब्याज की वह दर होती है जिस पर ऋणदाता अपनी मुद्रा को उधार देते हैं। प्रत्येक समाज में ऋणों का लेन-देन एक साधारण घटना है किन्तु मुद्रा का यह क्रय-विक्रय मुद्रा बाजार की व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। वे समस्त व्यक्ति अथवा संस्थाएँ जो मुद्रा को उधार देने का कार्य करती हैं तथा वे सब लोग जो मुद्रा को उधार लेने की माग किया करते हैं सब मिलकर किसी देश के मुद्रा बाजार को बनाते हैं। अन्य वस्तुओं की भाँति किसी निश्चित समय पर मुद्रा की भी माग तथा पूर्ति होती है। हर समय देश में कुछ लोग विनियोग के लिए पूँजी की माग किया करते हैं और मुद्रा को ऋण पर लेकर उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बचत को उधार देकर उससे आय प्राप्त करना चाहते हैं। यह लोग समाज में पूँजी की पूर्ति करने वाले होते हैं। मुद्रा बाजार की व्यवस्था के द्वारा मुद्रा की माग करने वाले तथा उसकी पूर्ति करने वाले एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और मुद्रा का क्रय-विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य उसकी माग तथा पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। जिस ब्याज की दर पर मुद्रा की माग तथा पूर्ति एक दूसरे के साथ सतुलित हो जाती है वही मुद्रा का मूल्य होता है। अतः मुद्रा बाजार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें मुद्रा के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के साथ सम्पर्क में होते हैं तथा वे आपसी प्रतियोगिता से निश्चित मूल्य पर मुद्रा का क्रय-विक्रय करते हैं। विस्तृत अर्थ में मुद्रा बाजार के अन्तर्गत समस्त प्रकार के व्यवसायों के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाला सम्पूर्ण यन्त्र आ जाता है किन्तु साधारण अर्थ

मे मुद्रा बाजार शब्द अल्पकालीन ऋणों के लेन-देन तक ही सीमित है। अतः मुद्रा बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है जहाँ अल्प कालीन धन-राशिओं का क्रय-विक्रय किया जाता है।¹

मुद्रा बाजार और पूँजी बाजार में भेद—

मुद्रा बाजार का विस्तृत अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व हमें मुद्रा बाजार (Money Market) और पूँजी बाजार (Capital Market) के भेद को समझ लेना चाहिए। यद्यपि मुद्रा बाजार और पूँजी बाजार दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं किन्तु फिर भी उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। दोनों ही ऋणों के लेन-देन से सम्बन्धित हैं और दोनों में ही मुद्रा का क्रय-विक्रय किया जाता है। भेद केवल इतना है कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है जबकि पूँजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन-देन किया जाता है। वास्तव में पूँजी बाजार, मुद्रा बाजार का ही एक अंग है और विस्तृत अर्थ में मुद्रा बाजार के अन्तर्गत पूँजी बाजार को भी सम्मिलित किया जाता है। किन्तु विशिष्ट अध्ययन की दृष्टि से दोनों प्रकार के बाजारों का पृथक् विश्लेषण किया जाना चाहिए। दोनों प्रकार के बाजारों में काम करने वाली संस्थाएँ भी प्रायः एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अल्प-कालीन ऋणों का व्यापार करने वाली संस्थाएँ मुद्रा बाजार का अंग होती हैं जबकि दीर्घकालीन पूँजी की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का सम्बन्ध पूँजी बाजार से होता है। व्यवहारिक जीवन में दोनों प्रकार के बाजारों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है क्योंकि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों को एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार दोनों का विकसित एवं सुव्यवस्थित होना आवश्यक है क्योंकि दोनों ही प्रकार के बाजार आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध करते हैं।

मुद्रा बाजार और आर्थिक विकास (Money Market and Economic Development)—किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सुव्यवस्थित तथा सुमगठित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। देश के उद्योग, व्यापार तथा कृषि की विकास सम्बन्धी ऋण की आवश्यकताएँ मुद्रा बाजार के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। मुद्रा बाजार जितना अधिक सगठित होता है, पूँजी उतनी ही अधिक गतिशील होती है और व्याज की दरों में उतनी ही अधिक समानता रहती है जिससे आर्थिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। मुद्रा बाजार ही समाज में पूँजी के संचय को

1 "In the broad sense of the term, money market includes the entire mechanism used for financing all types of business. But the more ordinary usage of the term money market is restricted to borrowing and lending of short term funds. Thus money market may be defined as a place where short term funds are bought and sold."

प्रोत्साहित करता है तथा समाज में विभिन्न प्रकार के विनियोगों के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग को पूरा करने में सहायता देता है। मुद्रा बाजार का ठीक सगठन न होने की दशा में देश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियायें ठीक प्रकार नहीं चल सकती हैं। वास्तव में आज के औद्योगिक तथा व्यवसायिक जीवन को भली प्रकार चलाने के लिए एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक है। वह आर्थिक जीवन का चलाने के लिए पूँजी प्रदान करता है तथा समाज की वृद्धि को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में लगाने में सहायता देता है। किसी देश का मुद्रा बाजार जितना अधिक व्यवस्थित तथा विकसित होता है उस देश के आर्थिक विकास की उतनी ही अधिक सम्भावना होती है। मुद्रा बाजार का सुसंगठित होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसके बिना केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण नीति को पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकती है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग

(Constituents of the Indian Money Market)

आरम्भ काल से ही भारतीय मुद्रा बाजार को दो पृथक् भागों में बाँटने की प्रथा रही है—(i) योरोपीय भाग तथा (ii) भारतीय भाग। योरोपीय भाग के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया तथा विदेशी विनिमय बैंकों को सम्मिलित किया जाता था तथा भारतीय भाग में मिश्रित पूँजी वाले बैंक, स्वदेशी बैंक एवं सहकारी बैंक आते थे। मुद्रा बाजार के इन दोनों अंगों में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता था और दोनों का कार्य-क्षेत्र भी प्रायः भिन्न होता था। योरोपीय भाग को सदा ही सरकारी संरक्षण तथा नियन्त्रण का लाभ प्राप्त रहा है। इसके विपरीत मुद्रा बाजार का भारतीय भाग प्रायः अनियन्त्रित तथा अनियमित रहा है। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भारतीय मुद्रा बाजार की प्रकृति तथा उसके सगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण मुद्रा बाजार का उपर्युक्त वर्गीकरण अनावश्यक हो गया है। रिजर्व बैंक ने इन दोनों भागों में निकट सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है तथा मुद्रा बाजार के भारतीय भाग को भी धीरे-धीरे नियन्त्रित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर अधिक प्रभावशाली सरकारी नियन्त्रण करना सम्भव हो सका है। इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके उसके स्थान पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया एक सरकारी बैंक के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इन सब परिवर्तनों के द्वारा भारतीय मुद्रा बाजार को अधिक सगठित करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु अभी भी हमारे देश में यूरोप के देशों की भाँति एक सुसंगठित मुद्रा बाजार नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ है जिनमें आपसी सम्पर्क का अभाव रहता है। सम्पूर्ण मुद्रा बाजार पर अभी तक रिजर्व बैंक का नियन्त्रण स्थापित नहीं हो सका है।

वर्तमान भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) व्यवस्थित बाजार (Organised Market) तथा (ब) देशी बाजार (Indigenous Market)। व्यवस्थित बाजार में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं, जो रिजर्व बैंक के अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण में हैं। इस बाजार में ग्रहण सरकारी सत्याएँ, बड़ी व्यवसायिक फर्मों तथा विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती भी कार्य करते हैं, जिनकी क्रियाओं पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण रहता है। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित भाग के चार प्रमुख अंग हैं— (i) याचना राशि बाजार (Call Money Market), (ii) बिल बाजार (Bill Market), (iii) अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति बाजार (Short term Government Security Market) तथा (iv) सहायक ऋण बाजार (Collective Loan Market)।

इस व्यवस्थित मुद्रा बाजार से भिन्न एक देशी मुद्रा बाजार (Indigenous Money Market) भी देश में पाया जाता है, जो रिजर्व बैंक के नियन्त्रण से बाहर है। दोनों प्रकार के मुद्रा बाजारों में किसी प्रकार का निश्चित सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी वे एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं हैं। देशी बाजार संगठित बाजार से भी साधन प्राप्त करता है। विशेषतया फमल के अवसर पर देशी बैंकर्स अपनी छुण्डियों को स्टेट बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के पास घुनाते हैं, जिससे दोनों में सम्पर्क स्थापित होता है। इस प्रकार का सम्बन्ध होते हुए भी मुद्रा बाजार के इन दोनों भागों की व्यवस्था तथा कार्य-क्षेत्र अलग-अलग हैं। व्यवस्थित मुद्रा बाजार में काम करने वाले आधुनिक बैंक अधिक सुव्यवस्थित हैं तथा वे आधुनिक बैंकिंग पद्धति के अनुसार कार्य करते हैं और उन पर रिजर्व बैंक का अधिक नियन्त्रण रहता है। इनके विपरीत देशी बाजार में काम करने वाले देशी बैंकर्स का आधुनिक बैंकों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है और उन पर रिजर्व बैंक किसी प्रकार का नियन्त्रण करने में भी सफल नहीं हो सका है। इनके अतिरिक्त इन देशी बैंकर्स का कार्य-क्षेत्र भी सीमित है। अभी तक भी हमारे देश में अखिल भारतीय मुद्रा बाजार स्थापित नहीं किया जा सका है। भारतीय मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग निम्न-लिखित हैं—

- (१) मिश्रित पूँजी वाले बैंक।
- (२) विदेशी विनिमय बैंक।
- (३) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया।
- (४) औद्योगिक बैंक।
- (५) कृषि बैंक।
- (६) देशी बैंकर्स।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

उपयुक्त विरलेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक भारतीय मुद्रा बाजार पूर्णतया संगठित नहीं है। उसका एक भाग तो सुव्यवस्थित है किन्तु दूसरा बहुत बड़ा भाग संगठन रहित है और रिजर्व बैंक के किसी भी प्रकार के नियन्त्रण से बाहर है। संगठन व नियन्त्रण की दृष्टि से भारतीय मुद्रा बाजार स्वयं एक समस्या है। अभी तक भी भारत में अन्य औद्योगिक देशों की भाँति एक विकसित तथा संगठित बाजार स्थापित नहीं किया जा सका है। बम्बई के मुद्रा बाजार को भारतीय मुद्रा बाजार का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। यद्यपि कलकत्ता का मुद्रा बाजार भी विकसित तथा महत्वपूर्ण है किन्तु बम्बई का मुद्रा बाजार कलकत्ते के मुद्रा बाजार से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। के० सी० चाको (K. C. Chacko) के अनुसार, “बम्बई में रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यालय, प्रमुख व्यापारिक बैंकों के कार्यालयों, देश के सर्वाधिक सक्रिय स्टॉक एक्सचेंज, सरकारी प्रतिभूतियों के स्थापित बाजार तथा कपास विनिमय बाजार (Cotton Exchange) होने के कारण वह भारत का न्यूयार्क बनता जा रहा है और वह राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्त केन्द्र बन गया है।” यद्यपि बम्बई का मुद्रा बाजार काफी विकसित एवं संगठित हो गया है किन्तु फिर भी उसकी तुलना लन्दन अथवा न्यूयार्क के मुद्रा बाजार से नहीं की जा सकती है।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of Indian Money Market)—

भारतीय मुद्रा बाजार अभी तक पूर्णतया विकसित नहीं हुआ है और उसमें संगठन का अभाव है। भारत में मुद्रा बाजार विभिन्न क्षेत्रों में बँटा हुआ है, जिनमें आपसी सम्पर्क बहुत कम रहता है। देशी बैंकें तथा महाजन जो ६०% बैंकिंग व्यापार के लिए जिम्मेदार हैं, मुद्रा बाजार की व्यवस्था से बिल्कुल अलग रहते हैं। मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में व्याज की दरों में काफी भिन्नता पाई जाती है तथा उनमें अधिक परिवर्तन होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

(१) संगठन का अभाव (Lack of co-ordination between different parts of the Money Market)—भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन दोषपूर्ण है तथा वह कई टुकड़ों में बँटा हुआ है, जिनके बीच कोई विशेष सम्पर्क नहीं रहता है। मुख्यतः हमारे मुद्रा बाजार के दो लगभग पूर्णतया स्वतन्त्र भाग हैं— प्रथम आधुनिक मुद्रा बाजार है जिसमें रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा मिश्रित पूँजी वाले बैंक सम्मिलित हैं तथा दूसरे देशी बैंकें जिसमें साहूकार, सराफा आदि आते हैं। मुद्रा बाजार के इन दोनों अंगों में किमी प्रकार का सहयोग तथा सम्पर्क नहीं है और उनके बीच निरन्तर हानिकारक तथा अपव्ययी प्रतियोगिता होती रहती है। मुद्रा बाजार के इन दोनों अंगों के विभिन्न सदस्यों के आपसी सम्बन्ध भी ठीक नहीं हैं और वे एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते रहते हैं।

आधुनिक मुद्रा बाजार के क्षेत्र में स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा मिश्रित पूँजी वाले बैंक एक दूसरे की अपनी प्रतियोगी समझते हैं और इनमें किसी प्रकार का आपसी सहयोग तथा समन्वय नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशी विनिमय बैंक अधिक प्रभावशाली रहे हैं और वे सदा मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहे हैं। सहकारी बैंकों तथा अन्य प्रकार के बैंकों में भी किसी प्रकार का सम्बन्ध तथा सहयोग नहीं पाया जाता है। देशी बैंकसं में भी व्यवस्था तथा संगठन का अभाव है और उनमें प्रतियोगिता रहती है। इनमें से प्रत्येक, एक दूसरे का व्यवसाय छीनने का प्रयत्न करता रहता है। प्रत्येक की भ्रम-भ्रम व्याज की दरे होती हैं और इन पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है। अतः भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न भागों में संगठन का अभाव है तथा उनके विभिन्न सदस्यों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। मुद्रा बाजार के व्यवस्थित न होने के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों में व्याज की दरो में समानता स्थापित करने में रिजर्व बैंक को अधिक सफलता नहीं मिली है और वह अपनी बैंक दर नीति (Bank Rate Policy) से बाजारी दर (Market Rate) पर बहुत कम प्रभाव डाल सका है।

(२) व्याज की दरो में भिन्नता (Disparity between Rates of Interest)—भारतीय मुद्रा बाजार में विभिन्न स्थानों पर व्याज की दरो में काफी भिन्नता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर व्याज की दरे ऊँची रहती हैं जबकि अन्य स्थानों पर वे नीची होती हैं। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सहयोग तथा संगठन के अभाव के कारण ही यह दोष उत्पन्न होता है। इंग्लैंड तथा अमेरिका में मुद्रा बाजार पूर्णतया संगठित होने के कारण विभिन्न स्थानों पर व्याज की दरे एक रहने की प्रवृत्ति रखती है तथा सभी प्रकार की व्याज की दरे बैंक दर के ऊपर निर्भर होती हैं। हमारे विपरीत भारतीय मुद्रा बाजार सुसंगठित न होने के कारण व्याज की दरो में काफी भिन्नता पाई जाती है और बैंक दर, बाजारी व्याज की दर, स्टेट बैंक की दर, कटौती दर (Discount Rate) आदि में काफी अन्तर रहता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) के अनुसार भारतीय मुद्रा बाजार में व्याज की दरे ३% से लेकर १०% तक पाई जाती हैं। बैंक दर और बाजारी दरो में निश्चित सम्बन्ध न होने के कारण हमारे देश में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति (Bank Rate Policy) अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकी है। हमारे देश में केवल व्याज की दरो में भिन्नता ही नहीं पाई जाती है बल्कि उनकी सामान्य प्रवृत्ति ऊँचा रहने की होती है, जिससे देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। भारतीय मुद्रा बाजार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर अल्पकालीन व्याज की दरे दीर्घकालीन व्याज की दरो से ऊँची रहती हैं जैसा कि सामान्यतया विदेशी बाजारों में नहीं होता है।

(३) देश में मुद्रा की मौसमी कमी (Seasonal Monetary Stringency)—भारतीय मुद्रा बाजार में विभिन्न मौसमी की व्याज की दरों में भी काफी अन्तर रहता है। फसल के अवसर पर व्यापार अधिक होने के कारण मुद्रा की माग बहुत अधिक बढ़ जाती है किन्तु उसकी पूर्ति में उसी अनुपात में वृद्धि न होने से मुद्रा बाजार में रुपये की भारी कमी रहती है और व्याज की दरें बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत वर्ष के कुछ भाग में रुपये की माग के कम हो जाने के कारण व्याज की दरें भी घी रहती हैं। नवम्बर से जून तक का समय अधिक व्यापार का समय होता है और फसलों को बेचने तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए व्यापारियों के द्वारा मुद्रा की अधिक माग की जाती है, जिसके कारण मुद्रा बाजार में रुपये की कमी हो जाती है और व्याज की दरों में अनुचित वृद्धि हो जाती है। वर्ष के इस भाग में व्याज की दरें प्रायः ७% और ८% के बीच में रहती हैं। मुद्रा की इस सामयिक कमी तथा व्याज की दरों की अधिकता के कारण व्यापारियों को विशेष कठिनाई अनुभव करनी होती है और व्यापार का ठीक-ठीक विकास नहीं हो पाता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बाजार में मुद्रा की माग कम रहती है और इसकी पूर्ति अधिक होने के कारण व्याज की दरें गिरकर ३% और ४% के बीच में आ जाती हैं। व्याज की दरों के इन सामयिक परिवर्तनों का मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति का बेलोचदार होना है, जिससे कि अधिक माग होने पर मुद्रा की पूर्ति में विशेष वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् मुद्रा बाजार का यह दोष कुछ कम हो गया है क्योंकि वह विभिन्न समय पर व्यापार की माग के अनुसार मुद्रा का विस्तार तथा सकुचन करता रहता है। किन्तु वह अभी तक व्याज की दरों के इन सामयिक परिवर्तनों को पूर्णतया दूर करने में सफल नहीं हो सका है।

(४) संगठित बिल बाजार का अभाव (Absence of an Organised Bill Market)—कुशल मुद्रा बाजार के विकास तथा सालाना वृद्धि के सुविधापूर्वक चलने के लिए एक संगठित बिल बाजार का होना आवश्यक है। यद्यपि हमारे यहाँ हण्डियों का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है किन्तु अभी तक देश में एक संगठित बिल बाजार का विकास नहीं हुआ है। भारतवर्ष में व्यापारिक बिलों तथा हण्डियों का प्रयोग बहुत कम होता है और अधिकांश सौदों को नकद निवटारा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के व्यापारिक बैंकों की कुल जमा का ३ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक ही व्यापारिक बिलों के रूप में होता है जबकि अन्य देशों के बैंक अपने साधनों का एक महत्वपूर्ण भाग व्यापारिक बिलों में लगा कर रखते हैं। हमारे देश में व्यापारिक वित्तिय-पत्रों की कमी के कारण मुद्रा बाजार में वित्तीय साधनों की कमी बनी रहती है। यह धारणा की गई थी कि रिजर्व बैंक देश में जल्दी ही एक सुव्यवस्थित एवं विस्तृत बिल बाजार की स्थापना

करेगा किन्तु रिजर्व बैंक को बिल बाजार का विकास करने में अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

(५) मुद्रा बाजार में धन का अभाव (Paucity of Funds)—भारतीय मुद्रा बाजार में धन की कमी रहती है, जिसके कारण व्यापार तथा उद्योग-धन्यो को पर्याप्त मात्रा में पूँजी नहीं मिल पाती है। धन के अभाव के मुख्य कारण, देश में बचत की मात्रा का कम होना, बैंको का अपर्याप्त विकास, विनियोग के साधनों की कमी, बैंको के प्रति विश्वास का कम होना तथा लोगों में बैंकिंग की आदत का न होना इत्यादि हैं। हमारे देश के अधिकांश लोगों में बैंकिंग की आदत नहीं है और वे अपने धन को सग्रह (Hoard) करके रखना अधिक पसन्द करते हैं जिसके कारण उनकी बचत विनियोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार की समस्याओं का बहुत अधिक अभाव है, जो ग्रामीण जनता की बचत को एकत्रित करके विनियोगों के लिए उपलब्ध कर सकें। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बचत का बहुत कम भाग ही मुद्रा बाजार में आता है, जिसके कारण मुद्रा बाजार में धन का अभाव रहता है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में सन्तोषजनक परिवर्तन हुए हैं और अब मुद्रा बाजार में पूँजी की पूर्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। देश में धन तथा बचत में वृद्धि, सरकार की मुलभ मुद्रा (Cheap Money) की नीति, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि का विकास इस स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

(६) बैंकिंग सुविधाओं की सामान्य कमी (Scarcity of Banking Facilities)—हमारे देश में जनसंख्या की तुलना में बैंकिंग सुविधाएँ बहुत कम हैं। विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग प्रायः बैंकिंग से अपरिचित हैं। भारतवर्ष में बैंको की कमी इस बात में प्रमाणित होती है कि हमारे देश में १ लाख १० हजार व्यक्तियों का पीछे एक बैंक है जबकि अमेरिका में केवल ३७१७ व्यक्तियों के पीछे एक है। इसमें विदित होता है कि हमारा देश बैंकिंग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। क्योंकि बैंक आधुनिक मुद्रा बाजार के विशेष अङ्ग होते हैं बैंको के अपर्याप्त विकास के कारण हमारा मुद्रा बाजार भी पूर्णतया विकसित नहीं हो पाया है। बैंको के अभाव के कारण हमारे देश में न तो बचत को प्रोत्साहन मिलता है और न समाज की समस्त बचत ही एकत्रित हो पाती है, जिसके कारण अधिकांश बचत निष्क्रिय रहती है और उसे विनियोगों के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है।

(७) देशी बैंकें तथा महाजनो की अधिकता (Abundance of Money Lenders)—अभी भी भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कृषि वित्त की व्यवस्था महाजन ही करते हैं। हमारे देश में देशी बैंकें तथा महाजनो की संख्या बहुत अधिक है और उन पर रिजर्व

बैंक का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है जिसके कारण मुद्रा बाजार के अनेक दोषों का उत्तरदायित्व उन पर आता है। यद्यपि देश में आधुनिक बैंकों का विकास हुआ है किन्तु वे अभी तक मुद्रा बाजार में देशी बैंकसं तथा महाजनो के प्रभाव को कम नहीं कर सके हैं। देशी बैंकसं तथा आधुनिक बैंकों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता है, जिसके कारण ये साहूकार तथा महाजन अपनी कार्यवाहियों से समय-समय पर मुद्रा बाजार को काफी अस्त-व्यस्त कर देते हैं।

मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के उपाय

(Suggestions for Reform)—

मुद्रा बाजार के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रयत्न किये गये हैं किन्तु इस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। रिजर्व बैंक की स्थापना तथा उसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् और सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम ने परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा बाजार के दोष बहुत कुछ दूर हो गये हैं किन्तु अभी तक रिजर्व बैंक हमारे देश के मुद्रा बाजार को सुगठित नहीं कर सका है। सगठन की दृष्टि से आज भी भारतीय मुद्रा बाजार अत्यन्त दोषपूर्ण है क्योंकि रिजर्व बैंक देशी बैंकसं के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका है। ऐसी दशा में भारतीय मुद्रा बाजार का एक बहुत बड़ा भाग अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित है। देशी बैंकसं पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करके तथा देश में बैंकिंग सुविधाओं के अधिक विकास के द्वारा ही मुद्रा बाजार के आधारभूत दोषों को दूर किया जा सकता है। समय-समय पर विभिन्न कमीशनो तथा जांच समितियों ने मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के सुझाव दिये हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) भण्डार-गृहों का निर्माण (Construction of Licensed Warehouses)—भारतवर्ष में अन्य देशों की भाँति ऐसे विश्वसनीय भण्डार-गृह नहीं हैं जिनमें लोग अपना सामान रखकर उनके प्रमाण-पत्रों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकें। माल की आह पर ऋण देने में बैंकों को विशेष कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास अपने भण्डार-गृह नहीं हैं तथा अन्य भण्डार-गृहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा लाइसेंसदार भण्डार-गृहों का निर्माण किया जाय। केन्द्रीय बैंक तथा राज्य सरकारों को इस प्रकार के भण्डार-गृहों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे बैंक इन भण्डार-गृहों में रखी हुई वस्तुओं पर ऋण दे सकें। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने देश में भण्डार-गृहों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक केन्द्रीय भण्डार-गृह निगम (Central Warehousing Corporation) स्थापित की है। इस प्रकार की निगम (Corporations) राज्य सरकारों के द्वारा भी स्थापित की गई हैं।

(२) विलों को फिर से भुनाने की सुविधाओं का विकास (Increased Rediscounting Facilities)—विलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में विलों को दोबारा भुनाने की सुविधाओं का विकास किया जाये। इस प्रकार की सुविधायें प्रायः केन्द्रीय बैंक के द्वारा दी जाती हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक अभी तक सीमित मात्रा में ही इस प्रकार की सुविधायें दे सका है क्योंकि उसके द्वारा केवल विशेष श्रेणी के विलों को ही दोबारा भुनाया जाता है। मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास करने के लिए विलों को फिर से भुनाने तथा भुदती हण्डियों व मास-पत्रों के आधार पर ऋण देन की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

(३) हण्डियों का प्रमाणीकरण (Standardisation of Hundies)—हमारे देश में हण्डियों का बाजार प्रायः अस्थायी होता है। अधिकांश हण्डियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती हैं तथा उनकी लेखन-विधि भी भिन्न-भिन्न होती है जिसके कारण हण्डियों का अखिल भारतीय बाजार स्थापित नहीं किया जा सका है। हण्डियों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी भाषा रूप तथा लेखन-विधि का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। अधिकांश हण्डियाँ एक ही ढंग से लिखी जायें तो उनके समझने में समय की बचत होगी तथा बैंक उनके आधार पर सरलतापूर्वक ऋण दे सकेंगे।

(४) धन हस्तान्तरण की सुविधाओं का विकास (Increased Remittance Facilities)—अच्छे मुद्रा बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान को धन हस्तान्तरण की सस्ती सुविधाओं का होना आवश्यक है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व हमारे देश में इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव था किन्तु अब रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधायें देता है। रिजर्व बैंक को देशी बैंकर्स तथा महाजनो आदि के धन को हस्तान्तरित करने की सुविधायें भी देनी चाहिए तथा डाकघरों के द्वारा धन हस्तान्तरण की दरों को कम किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीणों को लाभ पहुँच सके।

(५) देशी बैंकर्स पर नियन्त्रण (Control of Indigenous Bankers)—भारतीय मुद्रा बाजार की आधारभूत कमी को दूर करने के लिए देशी बैंकर्स तथा रिजर्व बैंक में सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए और उन पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। अन्य बैंकों की भाँति देशी बैंकर्स को भी रिजर्व बैंक से ऋण सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिए और उन्हें रिजर्व बैंक के आदेशानुसार तथा उसके नियन्त्रण में रह कर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे मुद्रा बाजार को सुमंजस बनाया जा सकेगा। इस समय देशी बैंकर्स पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है और वे मनमाने ढङ्ग से अपना व्यवसाय करते हैं जिससे मुद्रा बाजार में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं। इन दोषों

को दूर करने के लिए देशी बैंकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए और उनकी कार्य-विधि पर रिजर्व बैंक का सक्रिय नियन्त्रण होना चाहिए ।

(६) समाशोधन-गृहों का पुनर्संगठन (Reorganisation of Clearing Houses)—प्रत्येक राज्य में बिलों के भुगतान के लिए निकासी-गृहों की स्थापना की जानी चाहिए तथा वर्तमान निकासी-गृहों की कार्य-विधि में सुधार किया जाना चाहिए । भारतवर्ष में समाशोधन गृहों की काफी कमी है तथा उनकी कार्य-प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई दशा में है । मुद्रा बाजार के विकास के लिए हमारे देश में यूरोपीय ढंग पर समाशोधन-गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ।

(७) अखिल भारतीय बैंकर्स संघ के कार्यों का विस्तार (Expansion of the Activities of All India Bankers' Association)—सन् १९२९ की केन्द्रीय बैंकिंग जीव समिति ने यह सुझाव दिया था कि भारतवर्ष में एक अखिल भारतीय बैंकर्स संघ (All India Bankers' Association) स्थापित की जानी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के बैंकर्स के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके तथा उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार करने में सहयोग दे सके । इस प्रकार के संघ के द्वारा बैंकर्स अपनी कठिनाइयों तथा सुझावों को सरकार के सम्मुख रख सकेंगे और उन्हें मिल कर काम करने का अवसर मिलेगा । सन् १९४६ में बम्बई में इस प्रकार का एक संघ स्थापित किया गया था किन्तु इस संघ के कार्यों का अधिक विस्तार नहीं हो सका है । अतः यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय बैंकर्स संघ को एक सक्रिय संस्था बनाई जाय और उसके कार्यों का विस्तार किया जाये । यह संस्था मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने में सरकार की बहुत सहायता कर सकती है ।

भारत में बिल बाजार

(Bill Market in India)

भारतवर्ष में अभी तक एक विकसित तथा सुसंगठित बिल बाजार का अभाव है । यद्यपि लोगों के द्वारा बिलों तथा हुण्डियों का प्रयोग काफी प्राचीन समय से किया जाता है किन्तु फिर भी उनके क्रय-विक्रय के लिए व्यवस्थित बाजार अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है । रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंक तथा देशी बैंकर्स की हुण्डियों को भुगतान के कार्य करता था । किन्तु भारतीय बैंक आरम्भ से ही हुण्डियों को भुगतान की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक से ऋण अथवा अग्रिम लेना अधिक पसन्द करते रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के ऋणों का वे जब चाहे भुगतान कर सकते हैं । व्यापारिक बैंकों की इस मनोवृत्ति के कारण बिल बाजार का विस्तृत विकास नहीं हो सका है । बैंक स्वयं तो अपने ग्राहकों के बिलों को भुगतान का कार्य करते हैं किन्तु इन बिलों को दोबारा भुगतान के लिए वे बहुत कम केन्द्रीय बैंक के पास जाते हैं । इस समय देश में जो भी बिल बाजार है

वह सन् १९५३ के पश्चात् रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में विस्तृत एवं सुनगठित बिन बाजार का विकास न होने के निम्नलिखित कारण हैं—

(i) ऋणों का नकद साख (Cash Credit) के रूप में दिया जाना—हमारे देश में बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले अधिकांश ऋण नकद साख के रूप में होते हैं क्योंकि इन प्रकार के ऋणों में ऋणी तथा ऋणदाता दोनों को ही लाभ रहता है। ऋणी को यह लाभ रहता है कि उसे केवल अपनी ही रकम पर व्याज देना होता है जितनी कि वह प्रयोग में लाता है और ऋणदाता को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वह जब चाहे अपनी साख को वापस ले सकता है।

(ii) बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग को प्राथमिकता देना—आरम्भ काल से ही भारतीय बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों को अन्य प्रकार के विनियोगों पर प्राथमिकता दी है क्योंकि उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा अधिक तरलता (Liquidity) को बनाये रखना पड़ता है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इनमें लगे हुए साधन अधिक तरल रहते हैं तथा इस प्रकार वे विनियोग पर उन्हें लाभ भी अच्छा मिल जाता है। किन्तु अब इस स्थिति में परिवर्तन हो गया है और बैंक अधिक लाभ के कारण व्यापारिक बिलों में भी रुचि लाना पसन्द करने लगे हैं।

(iii) बिलों के फिर से मुनाये जाने की सुविधाओं का अभाव—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारतवर्ष में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो बैंकों के द्वारा मुनाये गये बिलों को दोबारा मुनाने का कार्य कर सके। यद्यपि इम्पीरियल बैंक इस कार्य को किया करता था किन्तु अन्य बैंक विद्वाम का अभाव होने के कारण इन सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते थे। तत्पश्चात् रिजर्व बैंक ने बिलों को फिर से मुनाने का कार्य ले लिया किन्तु वह भी इस प्रकार की सुविधाएँ केवल सीमित मात्रा में ही दे सता है।

(iv) व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण लेना अधिक अच्छा समझते हैं—व्यापारिक बैंक बिलों को फिर से मुनाने की अपेक्षा प्रतिभूतियों पर ऋण लेना अधिक अच्छा मानते हैं क्योंकि मुद्रा बाजार में किमी बैंक के द्वारा बिलों के फिर से मुनाये जाने की उसकी कमजोरी समझा जाता है। अतः बैंक इस प्रकार की जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके अनिश्चित रिजर्व बैंक केवल स्वीकृत बिलों को ही मुनाना है किन्तु इस प्रकार के बिलों को निश्चित करने की विधि नहीं बतलाता है जिसके कारण बिलों को मुनाने में बैंकों को जोखिम रहती है।

(v) स्वीकृति-गृहों (Acceptance Houses) का अभाव—व्यापारिक बिलों के सम्बन्ध में एक विशेष कठिनाई यह होती है कि उन पर हस्ताक्षर करने वालों की प्राथमिक स्थिति की जाँच करना बड़ा कठिन रहता है। भारतवर्ष में निर्गमन-गृहों

(Issue House) तथा स्वीकृति-घृहो (Acceptance Houses) जैसी वित्तीय मस्थायें भी नहीं हैं जो बिलों को स्वीकार (Accept) करके लिखने वालों की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान दे सकें। इन कठिनाइयों के कारण बैंक बिलों को मुताने में सकोच करते हैं।

(vi) टुण्डियों का स्थानीय रूप—भारतवर्ष में टुण्डियाँ विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में लिखी जाती हैं तथा उनको लिखने की विधि में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण इन टुण्डियों का बाजार प्रायः स्थानीय होता है और देश के एक भाग में लिखी गई टुण्डियों का प्रयोग दूसरे भाग में नहीं किया जा सकता है। टुण्डियों का प्रमाणीकरण (Standardisation) न होने के कारण अभी तक हमारे देश में टुण्डियों का अखिल भारतीय बाजार स्थापित नहीं हो सका है।

(vii) कोषागार विपत्रों (Treasury Bills) का विस्तार—काफी लम्बे काल में हमारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को कोषागार विपत्रों से पूरा करती रही हैं जिसके कारण हमारे देश में इस प्रकार के विपत्रों का प्रचलन बहुत अधिक रहा है। व्यापारिक बैंक अधिक सुरक्षा के कारण कोषागार विपत्रों में विनियोग करना अधिक पसन्द करते हैं जिसके कारण व्यापारिक बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका है।

(viii) स्टाम्प-कर (Stamp Duty) का अधिक होना—बहुत काफी समय से हमारे देश में स्टाम्प-कर (Stamp Duty) की दर अधिक ऊँची रही है जिसके कारण बिलों का हस्तान्तरण साभपूर्ण नहीं रहता है। सन् १९४० के पश्चात् बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टाम्प-कर में कुछ कमी की है।

भारत में बिल बाजार के विकास के लिए सुझाव

(Suggestions for Developing Bill Market in India)—

सन् १९२९ में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने भारतवर्ष में बिल बाजार के विकास पर विशेष जोर दिया। समिति का यह विचार था कि बिल बाजार के बिना किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था को पूर्णतया विकसित नहीं किया जा सकता है। अतः इस समिति ने देश में बिल बाजार का विकास करने के लिए बहुत-से सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं—

(१) देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। इस समिति के सुझाव पर १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई जो केन्द्रीय बैंक के कार्यों को सुचारु रूप से कर रहा है।

(२) बैंकों की व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान होने से ही उनका विश्वास अपने ग्राहकों में स्थापित हो सकेगा और वे उनके द्वारा लिखे गये बिलों को स्वीकार कर सकेंगे। देश में ऐसी

संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए जो व्यापारिक बिलों को स्वीकार करके बैंकों को व्यापारियों की आधिक स्थिति का ज्ञान करा सकें।

(३) कटौती दर (Discount Rate) कम होनी चाहिए। समिति का विचार था कि बिलों की कटौती दर को कम करने ही उनके प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है।

(४) बिलों पर स्टाम्प-कर (Stamp Duty) कम होना चाहिए जिससे उनकी हस्तान्तरण कम व्यय पर किया जा सके। सन् १९४० में स्टाम्प-कर में इस प्रकार की कमी की गई।

(५) बिलों में एक-रूपता लाने के लिए उनकी भाषा तथा लेखन-विधि की भिन्नताओं को दूर किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में इंडियो का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है।

(६) समानोधन गृहों (Clearance Houses) की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में बिलों के सुगमन के लिए समानोधन-गृह स्थापित किये जाने चाहिए।

(७) कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की जमानत पर लिखे गये बिलों को प्रचलित करना चाहिए। खरी फसलों की बाट पर लिखे हुए बिलों को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उनके आधार पर ऋण देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना

(Bill Market Scheme of the Reserve Bank)—

केंद्रीय जाँच समिति के इन सुझावों में से कुछ एक को कार्य-रूप में लाने का प्रयत्न किया गया जिसमें स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु बिल बाजार के विभाग के लिए उपयुक्त दाय उपपन्न नहीं जा सकी। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भी देश में बिल बाजार स्थापित नहीं हुआ क्योंकि इस सम्बन्ध में आधारभूत कठिनाइयों को दूर करने में अधिक सफलता नहीं मिली है। रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने तथा देश में बिल बाजार का विकास करने के लिए भरमस्स प्रयत्न किया है और समय-समय पर ऐसे सुझाव दिये हैं जिनके द्वारा बिल बाजार का विकास किया जा सके किन्तु उमें इस सम्बन्ध में सीमित सफलता ही मिल सकी है। जनवरी सन् १९५२ में रिजर्व बैंक ने अपनी बिल बाजार के विकास सम्बन्धी योजना को क्रियात्मक रूप दिया और बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुविधाएँ दी गईं।

रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अनुसूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) के व्यापारिक बिलों के आधार पर ऋण देने का अधिकार है किन्तु यह बिल ६० दिन में अधिक अवधि के होने चाहिए और इन पर दो विश्वमनीय हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुसूचित बैंक, इस अधिनियम के अन्तर्गत,

दर्शनी बिलो (Demand Bills) पर अग्रिम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने ग्राहकों के दर्शनी बिलो तथा प्रतिज्ञा-पत्रों को ऐसे बिलो में परिवर्तित करना पड़ता है जो ६० दिन की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाले हों। रिजर्व बैंक ने अपनी बिल बाजार योजना के अन्तर्गत इस अनुविधा को दूर करने का प्रयत्न किया है तथा सावधि बिलो (Time Bills) पर अग्रिम देने की ब्याज की दर को कम किया है। इस योजना के अन्तर्गत बिल बाजार को विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी हैं—

(i) बिल बाजार का तेजी के साथ विकास करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों की सावधि बिल (Time Bills) पर बैंक दर से ५% कम सूद की दर पर ऋण देने की सुविधायें प्रदान की यद्यपि बैंक अपनी इच्छानुसार इस दर को बढ़ा सकता था।

(ii) बिल बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने मांग बिलो (Demand Bills) की सावधि बिलो (Time Bills) में परिवर्तित करने पर प्राप्ति वाले मुद्राक व्यय (Stamp Duty) के भावे को स्वयं देना स्वीकार किया।

(iii) रिजर्व बैंक ने बैंकों के द्वारा बिलो की ग्राह्य पर लिए जाने वाले ऋणों की न्यूनतम सीमा २५ लाख रुपये निश्चित की जिसमें कोई भी व्यक्तिगत बिल १ लाख रुपये के मूल्य न कम नहीं होना चाहिए।

प्रारम्भ में इस योजना को केवल उन अनुसूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) तक ही सीमित रखा गया जिनकी जमा १० करोड़ रुपये या उससे अधिक थी किन्तु सन् १९५४ में योजना को अधिक विस्तृत कर दिया गया और उनके अन्तर्गत सब अनुसूचीबद्ध बैंकों को सम्मिलित कर लिया गया। जुलाई सन् १९५४ से रिजर्व बैंक ने बैंकों की ऋण सम्बन्धी न्यूनतम सीमा को घटाकर १० लाख रुपये कर दिया तथा व्यक्तिगत बिल की राशि को घटाकर ५० हजार रुपये कर दिया गया। सन् १९५६ में इस योजना में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार अब रिजर्व बैंक की बिलो के आधार पर ऋण देने की दर बैंक दर से केवल ४% कम रखी गई तथा स्टाम्प-कर सम्बन्धी सहायता को भी हटा लिया गया। इसके पश्चात् २१ नवम्बर १९५६ से बिलो पर अग्रिम देने की दर को बढ़ा कर बैंक दर के बराबर अथवा ३३% कर दिया गया। १६ मई सन् १९५७ से बैंक दर ४% हो जाने के कारण व्यापारिक बैंकों के द्वारा अग्रिम प्राप्त करने की दर भी इसके बराबर हो गई। इसके पश्चात् बैंक दर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ बिलो पर दिये जाने वाले अग्रिमों की ब्याज की दर भी बढ़ती रही है। १७ फरवरी १९६५ से बैंक दर बढ़ कर ६% हो गई है जिसके परिणामस्वरूप बिलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों की ब्याज की दर भी उसके बराबर हो गई है।

अक्टूबर सन् १९५८ से निर्यात बिलो (Export Bills) को भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। अक्टूबर १९५९ में इस योजना में कुछ

और सशोधन किये गये। प्रत्येक अग्रिम की सीमा को घटाकर १ लाख रुपये तथा प्रत्येक बिल पर दिये जाने वाले ऋण की सीमा १०,००० रुपये निश्चित कर दी गई। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी निश्चय किया कि अग्रिमों की ग्राह के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर लगने वाले समस्त स्टाम्प-कर (Stamp Duty) को वह स्वयं सहन करेगा।

बिल बाजार योजना की प्रगति (Progress of Bill Market Scheme)—

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना को अच्छी सफलता मिली है और योजना के पहले चार वर्षों में ही माग लेने वाले बैंकों की संख्या २७ से बढ़ कर ४५ हो गई। बैंकों के द्वारा बिलों की ग्राह पर लिए जाने वाले ऋणों की मात्रा भी निरन्तर बढ़ती रही है। सन् १९५२ में इस प्रकार के अग्रिमों की राशि ८१ करोड़ रुपये थी जो सन् १९५५ में बढ़कर २२५ करोड़ रुपये हो गई। सन् १९५६ में इन अग्रिमों की राशि ४३६ ८१ करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के पश्चात् अग्रिमों की मात्रा कम होन लगी और सन् १९५६ में केवल ८३ २२ करोड़ रुपये रह गई। सन् १९६०-६१ में यह राशि बढ़कर फिर २२५ २६ करोड़ रुपये हो गई। यह प्रगति इस बात का प्रतीक है कि रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापारिक बैंकों में स्वतन्त्रता में प्रयोग किया है।

बिल बाजार योजना के कार्यक्रम में आने से भारतीय मुद्रा बाजार में लोच का गुण उत्पन्न हो गया है। इस सफलता के होते हुए भी अभी तक एक स्थायी बिल बाजार स्थापित नहीं हो सका है। बिलों का प्रयोग केवल बाजार में सामयिक धन की कमी को पूरा करने के लिए ही किया जाता है और वह अभी तक व्यवसाय, उद्योग तथा कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का स्थायी साधन नहीं बन सके हैं। यद्यपि रिजर्व बैंक की बिल बाजार का विकास करने की योजना सही दिशा में एक कदम है किन्तु रिजर्व बैंक को बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक प्रभावशाली कार्य करना चाहिए तथा इस योजना के दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।

बिल बाजार योजना के दोष (Defects of the Bill Market Scheme)—

लगभग १२ वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात् भी रिजर्व बैंक देश में एक विस्तृत एवं सुसंगठित बिल बाजार का विकास करने में सफल नहीं हो सका है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी बिल बाजार योजना में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण उसे अधिक सफलता नहीं मिली है। इन दोषों को दूर करके ही इस दिशा में अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना में निम्न-लिखित दोष पाये जाते हैं—

(१) देशी बैंकों के द्वारा लिखी गई वृण्डियों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह योजना केवल व्यापारिक बैंकों को बिलों के आधार पर

अग्रिम देने की व्यवस्था करती है। जब तक देशी बैंकर्स की हुण्डियों को योजना के क्षेत्र में नहीं लाया जायेगा तब तक देश में उचित बिल बाजार का विकास सम्भव नहीं है। अनुमूचित बैंकों को हुण्डियाँ स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा उन्हें रिजर्व बैंक के पास दुबारा भुनाने (Rediscounting) की सुविधाएँ भी होनी चाहिए। ऐसा करने से ही बिल बाजार का आधार विस्तृत किया जा सकता है।

(२) इस योजना के द्वारा बिल बाजार का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि यह केवल व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक में ऋण दिलाने की व्यवस्था करती है। बिल बाजार के विकास की वास्तविक योजना का उद्देश्य व्यापारिक बिलों में एक-रूपता लाना, उन पर बिधे जाने वाले सौदों को सुविधापूर्ण बनाना तथा बिलों के प्रयोग की प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

(३) व्यापारिक बैंकों को इस योजना से लाभ उठाने के लिए अपने दर्शनी बिलों (Sight Bills) को मुहती बिलों (Time Bills) में बदलना होता है जो अनुविधापूर्ण होने के साथ-साथ अनार्थिक भी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(४) रिजर्व बैंक के द्वारा बिलों पर अग्रिम देते समय व्यापारिक बैंक के व्यवसाय की प्रकृति की जाँच करना अनावश्यक प्रतीत होता है। प्रतिभूति की जाँच करने के पश्चात् बैंक को उस पर ऋण मिल जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का ऋण लेने वाले बैंक के व्यवसाय की प्रकृति ठीक न होने के आधार पर उसके बिलों को भुनाने से इकार उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाकर ही बिलों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) द्रव्य बाजार के क्या कार्य हैं? क्या भारतीय द्रव्य बाजार उन सब कार्यों को सन्तोषजनक रूप से करता है? (भागरा बी० ए० १९६४)
- (२) भारतीय मुद्रा बाजार के अंग कौन से हैं? भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को समझाइये। (भागरा बी० ए० १९६२)
- (३) भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके दोषों पर दृष्टिपात करें। (भागरा बी० ए० १९६०)
- (४) भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य-मुख्य अंगों को बताइये। उद्योग एवं व्यापार की वित्त-व्यवस्था करने में उनका क्या महत्व है? (भागरा बी० ए० १९५५)

- (५) भारत में बिल बाजार के न होने के क्या कारण हैं ? फरवरी, १९५२ से इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ? (भागरा बी० काम १९६२)
- (६) भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं ? रिजर्व बैंक उन पर नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (भागरा बी० कॉम० १९५५ स)
- (७) भारत में बिल बाजार विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक डॉक्यूमेंट एडि या के आधुनिक प्रयत्नों पर प्रकाश डालिये । ऐसे बाजार के विकसित होने से देश में मौद्रिक व्यवस्था करने में क्या सुविधा हो जायेगी ? (गोरखपुर बी० कॉम १९५६)
- (८) भारतीय मुद्रा बाजार की वर्तमान दशा की विवेचना करिये । इसके सुधार के लिए आपके क्या सुझाव हैं ? (बिहार बी० काम १९५६)
- (९) भारतीय मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं की बतलाइये । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मुद्रा बाजार के दोषों को कहीं तक दूर किया जा सका है ? (राजस्थान बी० काम १९५६)
- (१०) आर्थिक विकास के साधन के रूप में एक सुसंगठित बिल बाजार के महत्त्व की बतलाइये । भारत में बिल बाजार के न होने के क्या कारण हैं । पिछले कुछ वर्षों में इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ? (राजस्थान बी० काम १९५६)

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

INDIAN BANKING SYSTEM

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में मुख्यतया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, सहकारी तथा भूमि ब्रम्हक बैंक और देशी बैंक में सम्मिलित किये जाते हैं। रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है और समस्त बैंकिंग व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने तथा उस पर उचित नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व इसी बैंक पर है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कुछ वर्ष पहले इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है। यह बैंक राज्य बैंक है किन्तु साधारण व्यापारिक बैंकों की भाँति ही कार्य करता है। हम बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास में सरकार की साझेदारी की योजना को कार्य-रूप में लाना था। मिश्रित पूँजी वाले बैंक हमारी बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य अंग हैं और वे देश में सामान्यतः व्यापारिक बैंकों का कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निवटाने तथा विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं। सहकारी बैंक तथा भूमि ब्रम्हक बैंक कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली बैंकिंग संस्थाएँ हैं जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित ग्वाज की दर पर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है। देशी बैंकें यद्यपि कृषि अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली स्थान रखते हैं किन्तु वे हमारी बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी हैं और उनके सुधार तथा नियंत्रण के द्वारा ही हम अपनी बैंकिंग व्यवस्था को सुसंगठित तथा प्रगतिशील बना सकेंगे। यद्यपि कुछ अन्य प्रकार के बैंक भी हमारे देश में हैं, किन्तु उपर्युक्त सभी प्रकार के बैंक मिलकर हमारी बैंकिंग व्यवस्था को पूर्ण कर देते हैं।

भारतवर्ष की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था यद्यपि काफी विकसित है किन्तु उसे पूर्णतया सुसंगठित नहीं कहा जा सकता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुये हैं और उसके बहुत से दोषों को दूर कर दिया गया है किन्तु अभी भी हमारे मुद्रा बाजार में कुछ ऐसे दोष हैं जिन्हें दूर करने में रिजर्व बैंक को सफलता नहीं मिली है। मुख्यतया देशी बैंकें रिजर्व

बैंक के नियंत्रण से विलकुल बाहर हैं और अपने मनमाने ढंग पर बैंकिंग का व्यवसाय चलाते हैं। इन बैंकर्स पर सप्रभावी नियंत्रण के द्वारा ही भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर किया जा सकेगा। इसके अनिश्चित भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था में कुछ अन्य दोष हैं जिनके कारण भारतीय बैंक देश के आर्थिक विकास में उतना सहयोग नहीं दे सके हैं जितना कि उनमें आशा की गई थी।

भारत में आधुनिक बैंकों का विकास (Development of Modern Banking in India)—यद्यपि हमारे देश में बैंकिंग का कार्य काफी प्राचीन समय से होना आया है किन्तु वर्तमान बैंकों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। भारतवर्ष में आधुनिक बैंकिंग का विकास १८वीं शताब्दी में हुआ जबकि कलकत्ता और बम्बई के एजेंसी गृहों (Agency Houses) ने आधुनिक बैंकिंग का कार्य आरम्भ किया। यह एजेंसी गृह मुख्यतया अपने द्वारा प्रबन्धित व्यापार तथा उद्योगों के सम्बन्धी बैंकिंग व्यवसाय ही करते थे। सन् १८२६-३० के आर्थिक संकट के कारण एजेंसी गृह बंठिनाई में पड़ गये और धीरे-धीरे विलीन हो गये। व्यापारिक बैंकों का इतिहास वास्तव में प्रेमीडेन्सी बैंकों की स्थापना के साथ आरम्भ होता है। सन् १८०६ में 'बैंक ऑफ बंगाल', सन् १८४० में 'बैंक ऑफ बम्बई' तथा सन् १८४३ में 'बैंक ऑफ मद्रास' की स्थापना की गई। इन बैंकों को सन् १८२३ में नोट निगमन का अधिकार दे दिया गया किन्तु १८६२ में सरकार ने इस अधिकार को समाप्त कर दिया। सन् १८६३ में 'अपर इण्डिया बैंक' तथा सन् १८६५ में 'इलाहाबाद बैंक' की स्थापना हुई। सन् १८८० तक व्यापार की दशाये स्थिर होने के कारण बैंकों की कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। सन् १८८१ में 'अवध व्यापारिक बैंक' (Oudh Commercial Bank) की स्थापना हुई जो पूर्णतया भारतीय बैंक था। सन् १८९४ में 'पंजाब नेशनल बैंक' तथा १९०१ में 'पियुपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया' (People's Bank of India) स्थापित किया गया। सन् १९०० तक बैंकिंग की प्रगति धीमी रही किन्तु सन् १९०५ के स्वदेशी आन्दोलन ने भारतीय बैंकिंग के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया और बैंकों की सख्या तेजी के साथ बढ़ने लगी। पश्चिमी-भारत, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में तो बैंकों की बाढ़-सी आ गई। सन् १९१३ तक बैंकों की सख्या तीव्र गति में बढ़ती गई किन्तु उसका पश्चात् महान् बैंकिंग संकट के कारण बहुत से बैंक फेन हो गये। सर्वप्रथम, 'पियुपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया' फेन हुआ और उसके साथ ही कुछ अन्य बैंक भी फेन हो गये। एक के बाद एक बैंक फेन होता गया, यहाँ तक कि थोड़े ही समय में १० बैंक फेन हो गये। बैंकों के इतनी बड़ी संख्या में फेन होने के कारण जनता का विश्वास बैंकों में टूट गया और उनकी प्रगति धीमी पड़ गई।

प्रथम महायुद्ध काल में बैंकों के विकास को फिर प्रोत्साहन मिला और नये बैंक स्थापित किये जाने लगे। बहुत से नये बैंक स्थापित किये गये किन्तु उनमें से

अधिकांश युद्ध का आघात न सह सके और युद्ध समाप्त होने से पहले ही फेल हो गये। सन् १९१३ और १९१६ के बीच ६५ बैंक फेल हो गये। युद्धोत्तर काल में कुछ नये बैंक स्थापित किये गये किन्तु १९३७ की आर्थिक मन्दी के कारण बैंकों की हालत खराब हो गई और बहुत बड़ी संख्या में बैंक फेल होने लगे। सन् १९३१ और १९३६ के बीच २३८ बैंक फेल हो गये। सन् १९३८ में भारतीय बैंक फिर कठिनाई में पड़ गये यद्यपि यह बैंकिंग सकट केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित था। सन् १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ होने के कारण बैंकों को फिर प्रोत्साहन मिला और बैंकों ने अपनी शाखाओं का तेजी के साथ विस्तार करना आरम्भ कर दिया।

बैंकों के टूटने के कारण (Causes of Bank Failures)—

बैंकों का इतनी बड़ी संख्या में फेल होना इस बात का प्रमाण था कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कुछ आधारभूत दोष हैं जिन्हें दूर करके ही बैंकों में स्थिरता लाई जा सकती थी। भारत में बैंकिंग सकट अनेक बार घाये और बहुत बड़ी मात्रा में बैंक फेल हो गये जिसका भारतीय बैंकिंग के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और लोगों का विश्वास बैंकों के प्रति कम हो गया। भारतवर्ष में बैंकिंग सकट आने के अनेक कारण थे जिनमें से कुछ एक तो समय विशेष के साथ सम्बन्धित थे और समय के साथ सुप्त हो गये किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दोष के रूप में अभी तक विद्यमान हैं और किसी भी समय हमारे बैंकों को सकट में डाल सकते हैं। बैंकों के फेल होने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे।

(१) पूँजी की कमी—बहुत से बैंक पूँजी कम होने तथा स्थायित्व के अभाव के कारण फेल हो गये। फेल होने वाले बैंकों में अधिकांश बैंक ऐसे थे जिन्हें स्थापित हुये १० वर्ष से कम हुये थे तथा जिनकी पूँजी १ लाख रुपये के कम थी। इस काल में स्थापित होने वाले अधिकांश बैंकों के पास सीमित साधन रहते थे जिनके कारण उनमें सकटकालीन स्थिति को सहन करने की क्षमता बहुत कम थी। पूँजी का अभाव होने के कारण यह बैंक प्रायः जमा राशि पर निर्भर रहते थे जिसे दीर्घकालीन विनियोगों में लगाना खतरे से खाली नहीं था।

(२) अयोग्य तथा अनुभवहीन संचालक—अधिकांश बैंकों का संचालन ऐसे लोगों के हाथों में था जिन्हें बैंकिंग व्यवसाय का कुछ भी अनुभव नहीं था। स्वदेशी आन्दोलन के कारण देश में बैंकों का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि लोगों ने इन बैंकों को धन कमाने का साधन समझ लिया था और प्रतिदिन न बैंकों की स्थापना की जाती थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से बैंकों का संचालन अयोग्य तथा अनुभवहीन लोगों के हाथों में आ गया और संकट काल में ऐसे बैंक ठप्प हो गये।

(३) बैंकों की घोखेबाजी की नीति—बहुत से बैंकों ने अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से घोखेबाजी की नीति को अपना लिया और अपनी वास्तविक

स्थिति को छुपा कर विनियोगियो (Investors) को धोखा देने लगे । यह बैंक अपनी अधिवृत्त पूँजी को बहुत बड़ा-बड़ा कर बताते थे तथा अपनी प्राथित पूँजी (Subscribed Capital) और चुकता—(Paid up Capital), जो प्रायः बहुत कम होती थी की सूचना जनता को नहीं देते थे । इस प्रकार लोगो की बैंको की कृत्रिम स्थिति का ही ज्ञान हो जाता था और उसकी वास्तविक स्थिति से वे अनभिज्ञ रहते थे । विनियोगियो को फँसाने के लिये बड़े-बड़े तथा प्रभावशाली लोगो के नामो के साथ उन्हें सम्बन्धित किया जाता था । कुछ बैंक भूठे हिसाब-किताब बना कर लोगो को प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे । डायरेक्टर्स तथा उनके मित्रो को कम जमानत पर बड़े-बड़े ऋण दे दिये जाते थे ।

(४) सट्टा व्यवसाय—बहुत से बैंको ने जल्दी तथा ऊँचे लाभ अंश की घोषणा करने के उद्देश्य में सट्टा व्यवसाय आरम्भ कर दिया जिसके कारण वे नीग्र दिवालिया हो गये और उन्हें अपना व्यवसाय बन्द करना पड़ा । इण्डियन स्पीसी बैंक के फेल होने का प्रमुख कारण मोने, चादी तथा मोतियो में सट्टेबाजी करना था । इसी प्रकार कुछ अन्य बैंक भी सट्टा व्यवसाय के कारण फेल हो गये ।

(५) दीर्घकालीन विनियोग नीति—कुछ बैंको ने अपनी अल्पकालीन जमा की दीर्घकालीन विनियोगो में फँसा दिया और वे पर्याप्त तरलता न होने के कारण फेल हो गये । बैंको में आपसी प्रतियोगिता अधिक होने से प्रत्येक बैंक शीघ्र उन्नति करना चाहता था । इन बैंको ने अपनी पूँजी की कमी को पूरा करने के लिए व्याज की ऊँची दर देकर जमाकर्ताओ के धन को आकर्षित करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार प्राप्त धन को इन बैंको ने उद्योग-धन्धो को ऋण देकर दीर्घकालीन विनियोगो में फँसा दिया । जमाकर्ताओ के द्वारा जबरन रुपये की माग की गई तो ये बैंक उनका भुगतान न कर सके और दिवालिया हो गये ।

(६) नकद कोषो का कम अनुपात—अनुभवहीनता के कारण भारतीय बैंको ने आरम्भ में अपनी जमा का बहुत कम भाग ही नकद कोष के रूप में रक्खा जबकि भारतवर्ष में नकद कोषो का अनुपात अन्य देशो की अपेक्षा अधिक होना चाहिए था । बहुत से बैंक नकद कोषो का अनुपात कम होने के कारण अपने ग्राहको की माग को पूरा न कर सके और आर्थिक संकट में फँस गये ।

(७) सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति—सरकार ने बैंकिंग संकट काल में भी बैंको की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक न समझा और बैंको की पूर्ण स्वतन्त्रता के माय फेल होने दिया गया । उस समय देश में कोई बैंकिंग सविधान भी नहीं था जिसके अनुसार बैंको की कार्य-प्रणाली को चलाया जा सके अथवा जो जमाकर्ताओ तथा अंशधारियो के हितो की रक्षा कर सके । ऐसी स्थिति में बैंको का विकास मनमाने ढङ्ग से हो रहा था और उनमें से अधिकांश का फेल हो जाना स्वाभाविक ही था ।

(८) केन्द्रीय बैंक का प्रभाव—सन् १९३५ से पूर्व हमारे देश में कोई ऐसी केन्द्रीय मस्था नहीं थी जो बैंकों पर नियन्त्रण कर सके तथा उनकी क्रियाओं में सम-वय स्थापित कर सके। इस प्रकार की मस्था के न होने से बैंकों की आर्थिक मकट के समय किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती थी अतः बैंकों के फेल होने का एक प्रमुख कारण देश में केन्द्रीय बैंक का न होना था।

द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय बैंकिंग पर प्रभाव

(Effect of Second World War on Indian Banking)—

द्वितीय विश्व-युद्ध काल आर्थिक स्मृद्धि का काल था। व्यापार तथा उद्योगों का तेजी के साथ विकास हो रहा था और देश की अर्थ-व्यवस्था एक गतिशील स्थिति (Dynamic State) में थी। आर्थिक विस्तार की इन दशाओं में बैंकिङ्ग व्यवसाय को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला और बैंकिंग का विस्तार होने लगा। पुराने बैंकों ने उन्नति की तथा अपनी शाखाओं का विस्तार किया और कुछ नए बैंक भी स्थापित किये गए। इस समय भारत की बैंकिंग व्यवस्था अधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली थी और उसमें युद्ध के आघात को सहन करने की अधिक क्षमता थी। यही कारण था कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने युद्धकालीन दशाओं का अच्छी प्रकार सामना किया और हमारे देश में किसी प्रकार का बैंकिंग मकट उत्पन्न नहीं हुआ। भारतीय बैंकिंग पर द्वितीय विश्व-युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव पड़े—

(१) बैंकों से भारी मात्रा में धन का निकाला जाना—युद्धकालीन दशाओं के कारण बैंकों में लोगों का विश्वास घम हो गया और बैंकों पर धन की अधिक माग की जाने लगी। लोगों ने बैंकों से अपनी जमा को निकालना आरम्भ कर दिया और थोड़े ही समय में बैंकों में ५ करोड़ से भी अधिक रुपये निकाल लिए गये किन्तु शीघ्र ही जनता का विश्वास बैंकों में पुनः स्थापित हो गया और लोगों की जमा वापस बैंकों में आने लगी। बैंकों ने रिजर्व बैंक की सहायता से मुद्रा की इस आकस्मिक माग को पूरा किया और इस प्रकार अपनी माल को बनाए रखला।

(२) बैंकों का तेजी के साथ विकास—सन् १९४२ से लेकर १९४६ तक बैंकों का तेजी के साथ विकास हुआ और बहुत से नए बैंक स्थापित किए गये। बैंकों की संख्या जो सन् १९३६ में केवल १९५१ थी सन् १९४६ में बढ़कर ५५२१ हो गई। कुछ नये स्थापित किये जाने वाले बैंक इस प्रकार हैं—यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक, हबीब बैंक, हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक आदि। सन् १९४६ तक भारत में मूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) की संख्या बढ़कर ६३ हो गई तथा अनुसूचित बैंकों (Non-scheduled Banks) की संख्या १९३६ और १९४६ के बीच २३१ में बढ़कर २८८ हो गई। यदि सरकार ने मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों की स्थापना पर प्रतिबन्ध न लगाया होता तो युद्ध काल में हमारे देश में बैंकों का विकास और भी तेजी के साथ हुआ होता।

(३) बैंकों की शाखाओं का विस्तार—युद्धकाल में कुछ बैंकों ने अपनी न शाखाएँ स्थापित की तथा अन्य बैंकों ने वर्तमान शाखाओं का विस्तार किया। बैंक शाखाओं का विस्तार होने के कारण देश में बैंकिंग की सुविधायें काफी बढ़ गईं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बैंकों के द्वारा सभी नई शाखाएँ शहरी तथा मण्डियों में स्थापित की गईं, जहाँ पर पहले से ही काफी बैंकिंग सुविधायें थी। गाँव तथा कस्बों में बैंकिंग का कोई विकास नहीं किया गया जिससे बैंकिंग का विस्तार होने पर भी ग्रामीण जनता को उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

(४) बैंकों की जमा में वृद्धि—युद्ध के आरम्भ काल में बैंकों में जनता का विश्वास कम होने के कारण बैंकों की जमा राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके विपरीत युद्ध के पहले दो वर्षों में तो लोगों ने भारी मात्रा में अपनी जमा की निकालना आरम्भ कर दिया किन्तु जल्दी ही बैंकों में फिर से विश्वास स्थापित हो गया और जमा बैंकों में वापस आन लगी। सन् १९४१ के पश्चात् बैंकों की जमा-राशि में तेजी के साथ वृद्धि हुई और इन बैंकों की कुल जमा जो सन् १९१९ में २४६.४५ करोड़ रुपये थी, बढकर १९४६ में १०६७ करोड़ रुपये हो गई। इस काल में केवल जमा की मात्रा में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ और निश्चित जमा (Fixed Deposits) की अपेक्षा चालू जमा (Demand Deposits) की मात्रा में तेजी के साथ वृद्धि हुई। युद्ध काल में बैंकों की जमा में वृद्धि होने के मुख्य कारण इस प्रकार थे—(अ) सरकार की मुद्रा विस्तार की नीति—युद्ध के कारण सरकार के द्वारा तेजी के साथ नई मुद्रा चलाई जा रही थी जिसके कारण लोगों के पास मुद्रा की मात्रा अधिक थी और वे बैंकों में अधिक रुपया जमा कर रहे थे। इन काल में चलन में मुद्रा की मात्रा लगभग दून्ने गुना बढ़ गई थी। (ब) सम्पत्ति, सोना तथा चाँदी के मूल्य में अधिक परिवर्तन—सम्पत्ति, सोना और चाँदी के मूल्यों में अत्यधिक परिवर्तन होने के कारण लोग इनमें अपना रुपया लगाता पसन्द नहीं करते थे और अपनी जमा को बैंकों में रखना अधिक पसन्द करते थे। (स) व्यावसायिक समृद्धि—इन काल में व्यापार तथा उद्योगों का विस्तार तेजी के साथ हो रहा था और व्यावसायिक वर्ष के लोगों के लाभ बहुत अधिक बढ़ गये थे। लाभों में वृद्धि होने के कारण बैंकों को अधिक मात्रा में जमा प्राप्त होने लगे।

(५) बैंकों की विनियोग नीति में परिवर्तन—युद्धकालीन दशाओं के कारण बैंकों को अपनी विनियोग नीति में भी परिवर्तन करना पड़ा। युद्ध से पूर्व बैंक प्रायः अपनी कुल जमा का ५४% ऋण, भुगतान तथा व्यापारिक बिलों में लगाकर रखते थे किन्तु युद्ध काल में उन्हें इस प्रकार के विनियोगों को कम करना पड़ा और सन् १९४६ तक यह अनुपात घटकर ३२% रह गया। इसका मुख्य कारण यह था कि युद्ध काल में व्यापारियों तथा उद्योगातियों को अधिक लाभ हुये और उनकी

बैंको से ऋण लेने की आवश्यकता कम हो गई । ऋणों की मांग कम हो जाने के कारण बैंको ने सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक रुपया लगाना आरम्भ कर दिया अथवा वे अधिक मात्रा में नकद जमा रखने लगे । सूचीबद्ध बैंको (Scheduled banks) का सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग ५४% से बढ़कर ६१% हो गया । इसी प्रकार इन बैंको का नकद कोष का अनुपात भी ११% से बढ़कर २५% हो गया ।

युद्धोत्तर काल में भारतीय बैंकिंग

(Indian Banking in the Post-war Period) —

युद्धोत्तर काल में भी बैंको के साधनों में निरन्तर वृद्धि होती गई । बैंकों की निश्चित जमा तेजी के साथ बढ़ती गई और १९४६ में ३४ करोड़ रुपये हो गई किन्तु उसके पश्चात् बैंको की स्थिति खराब होने लगी । १५ अगस्त सन् १९४७ में देश के विभाजन का हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत से बैंक फेल हो गए । मन् १९४७ में ३० अपरिगणित बैंक फेल हुए तथा कुछ अन्य बैंक भी बंठिनाई में आ गये । विभाजन का बुरा प्रभाव केवल पंजाब तथा बंगाल में काम करने वाले बैंको तक ही सीमित रहा । विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत से बैंको को अपनी पश्चिमी पंजाब की शाखाएँ बन्द करनी पड़ी । बैंको की बहुत-सी सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई । कुछ बैंको को भुगतान स्थगित करने पड़े । इस प्रकार बैंको को विभाजन के कारण बहुत हानि सहनी पड़ी किन्तु हमारे बैंको ने इस आघात को अच्छी प्रकार से सहन किया ।

रिजर्व बैंक ने इन बैंको को विभाजन के कुप्रभाव से बचने के लिए एक योजना लागू की जिसके अन्तर्गत—(i) रिजर्व बैंक एक्ट में एक संशोधन के द्वारा अपरिगणित बैंको (Non-scheduled banks) को भी स्वीकृत प्रतिभूतियों की आठ पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया, (ii) सरकार ने निर्वासित बैंको के पुनर्वास के लिए १ करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया (iii) एक आदेश के अनुसार दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब स्थित बैंको के विरुद्ध तीन मास तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । इस स्थगित शोधन काल में ये बैंक अपनी भारत स्थित चल सम्पत्ति का १०% अथवा २५० रुपये (जो भी कम हो) का भुगतान कर सकते थे, (iv) रिजर्व बैंक ने सरकारी आदेश पर किसी भी बैंक का निरीक्षण करने तथा उसके सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया । उपरोक्त कार्यों से रिजर्व बैंक ने बैंको को विभाजन के आघात से बचाने का प्रयत्न किया और उसे इस कार्य में पर्याप्त सफलता भी मिली ।

इस आघात के परिणामस्वरूप सन् १९४६ में बैंको की जमा बहुत अधिक गिर गई और उनसे अधिकाधिक मात्रा में ऋणों की मांग की जाने लगी । भारतीय व्यापार तथा उद्योगों ने अपनी पिछली बचत को विस्तार के लिए प्रयोग करना

प्रारम्भ कर दिया और बैंको में जमा की निचाला जाने लगा । आय का वितरण कम स्मृद्धिशाली वर्ग के पक्ष में हो जाने के कारण भी बैंको की जमा कम हो गई क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों के हिमाव बैंको में नहीं थे । पाकिस्तान में आने वाले लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपनी जमा की बैंको से निकालना प्रारम्भ कर दिया । इनके अतिरिक्त आयातों तथा कच्ची सामग्री खरीदने के लिए बैंको के द्वारा दिए जाने वाले अधिमो की मात्रा में भी तेजी के साथ वृद्धि हुई । उपरोक्त सभी कारणों से बैंको में अधिकाधिक मात्रा में ऋणों की मांग की जा रही थी तथा उनकी जमा में काफी कमी हो गई थी । किन्तु यह स्थिति बहुत अधिक समय तक न रही और जल्दी ही बैंक इस बटिलाई से भी बाहर हो गए ।

भारत में बैंकिंग विधान (Banking Legislation in India)—

बैंक जनता के रूप में जमा करने वाली मस्थाएँ होती हैं और वे अपनी पूँजी का अधिकांश भाग अपने जमाकर्ताओं में प्राप्त करती हैं । उनके द्वारा चलाये जाने वाले बैंक तथा अन्य प्रकार के माख-पत्र धीरे-धीरे नकद मुद्रा का स्थान लेते जा रहे हैं । आधुनिक बैंक व्यापार तथा उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करके देन की अर्थ-स्थवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । इन्हीं सब कारणों से बैंको की कार्य-प्रणाली को जनहित के दृष्टिकोण से नियन्त्रित करना आवश्यक है । बैंको की सेवाओं को प्रायः जनसेवा समझा जाता है और उन्हें अर्ध-सरकारी मस्थायें माना जाने लगा है । ऐसी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण मस्थायों पर सरकारी नियन्त्रण अनिवार्य है । भारतवर्ष में सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने सन् १९३१ में एक विस्तृत बैंकिंग विधान पास करने की सिफारिश की । इस समिति की सिफारिशों को भारतीय कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम, १९३६ में सम्मिलित कर दिया गया । मुद्राकाल में यह अधिनियम अपर्याप्त सिद्ध हुआ और कुछ अन्य प्रतिबन्ध बैंको पर लगा दिये गये । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् सन् १९४६ में एक विस्तृत बैंकिंग अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार भारतीय बैंको का नियमन होता है ।

बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम, १९४६

(Banking Companies Act, 1949)—

सन् १९४६ का बैंकिंग कम्पनीज एक्ट जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में स्थित बैंको के ऊपर लागू होता है । महकारी समितियाँ इस अधिनियम से नियन्त्रित नहीं होती हैं । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बैंको के द्वारा अचल सम्पत्ति की आड़ पर अनुमान से अधिक मात्रा में ऋण देने, अपर्याप्त सुरक्षा के आधार पर ऋण देने, बिना मोचे ममके नई ऋणायें खोलने तथा बैंक के कोषों के दुरुपयोग करने की प्रवृत्तियों को रोकना है । इस अधिनियम की मुख्य धारायें निम्नलिखित हैं—

(i) बैंकों के द्वारा व्यापार करने पर प्रतिबन्ध (Prohibition of Trading)—इस अधिनियम की ८ वीं धारा के अनुसार कोई भी बैंकिंग कम्पनी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वयं किसी प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय अथवा अदल-बदल नहीं कर सकती है जब तक कि ऐसा करना उसके बैंकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित न हो। धारा ६ के अनुसार कोई भी बैंक कार्यालय की विल्टिंग को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति को ७ साल से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है।

(ii) प्रबन्ध पर प्रतिबन्ध (Restriction on Management)—बैंकिंग अधिनियम की धारा १० के अनुसार किसी भी बैंक का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेंट्स (Managing Agents) के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति भी बैंक का प्रबन्ध नहीं कर सकता है जो किसी दूसरी कम्पनी का संचालक हो या जो किसी व्यवसाय में लगा हो अथवा जिसने कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिए ५ वर्ष से अधिक के लिए समझौता कर लिया हो। बैंक अपने कमचारियों को कमीशन अथवा लाभ में हिस्से के रूप में पारितोषण नहीं दे सकता है।

(iii) पूँजी (Capital)—किसी भी बैंकिंग कम्पनी की प्राधिकृत पूँजी (Subscribed Capital) उसकी अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) के आधे से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) उसकी प्राधिकृत पूँजी का कम से कम ५०% होनी चाहिए। यदि कम्पनी का बैंकिंग व्यवसाय एक से अधिक राज्यों में है तो उसकी पूँजी कम से कम ५ लाख रुपये होनी चाहिए और यदि उसकी शाखाएँ बम्बई या कलकत्ता अथवा दोनों में हैं तो पूँजी १० लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यदि उसकी शाखाएँ केवल एक ही राज्य में हैं और उनमें से कोई भी कलकत्ता अथवा बम्बई में नहीं है तो उसे अपने प्रधान कार्यालय के लिए १ लाख रुपये तथा अन्य कार्यालयों में से प्रत्येक के लिए कम से कम १० हजार रुपये रखने चाहिए। यदि किसी बैंकिंग कम्पनी के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में स्थित हैं और उनमें से एक या उससे अधिक बम्बई या कलकत्ता में हैं तो उसे ५ लाख रुपये की पूँजी तथा कोष और बम्बई व कलकत्ता से बाहर की प्रत्येक शाखा के लिए २५ हजार रुपये की पूँजी व कोष रखना अनिवार्य है।

(iv) संचित कोष व नकद कोष (Reserve Fund and Cash Reserve)—प्रत्येक बैंक को प्रतिवर्ष, लाभ वितरण से पूर्व अपने लाभ का कम से कम २०% उस समय तक संचित कोष में जमा करना अनिवार्य है जब तक कि यह कोष उसकी चुकता पूँजी के बराबर न हो जाय। संचित कोष के अतिरिक्त प्रत्येक बैंक को एक नकद कोष भी रखना होगा, जिसमें वह अपनी चासू जमा (Demand Deposits) का ५% तथा निश्चित जमा (Fixed Deposits) का २% जमा

करेगा। यह कोष अपने पास या रिजर्व बैंक के पास रक्खा जा सकता है। बैंको को अपनी सम्पत्ति की तरलता को बनाये रखने के लिए प्रतिदिन अपनी कुल जमा का २०% नकद रुपये, सोने या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में भारत में रखना होगा।

(v) ऋणों तथा अग्रिमों पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Loans and Advances)—इस अधिनियम की धारा २० के अनुसार कोई भी बैंक अपने प्रसो (Shares) की धाड़ पर ऋण नहीं दे सकता है। बैंको के लिए अग्रिमों की सुरक्षा के आधार पर अपने किसी सचालक (Director) अथवा किसी ऐसी कर्म या कम्पनी को जिसमें उसका कोई भी सचालक हिस्सेदार या मैनेजिंग एजेंट या ऋणों का जमानती हो ऋण देना वर्जित है। रिजर्व बैंक को जनहिस्ते में बैंको की ऋण नीति को निर्धारित करने का अधिकार भी दे दिया गया है। वह बैंको को यह आदेश दे सकता है कि वे कितन-कितने कामों के लिए ऋण दें तथा ऋणों की आवश्यक सीमा (Margin Requirement) और उन पर लिए जाने वाले व्याज की दर भी निश्चित कर सकता है।

(vi) नई शाखाएँ खोलने पर प्रतिबन्ध (Restrictions on New Branches)—कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना भारतवर्ष के किसी भी भाग में न तो नई जगह अपनी शाखा स्थापित कर सकता है और न किसी वर्तमान शाखा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित कर सकता है। कोई भी बैंकिंग कम्पनी जो भारत में रजिस्टर्ड हो, भारत से बाहर किसी भी स्थान पर अपना नया कार्यालय स्थापित नहीं करेगी अथवा अपने वर्तमान कार्यालय का स्थान नहीं बदलेगी जब तक कि वह ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न कर ले।

(vii) बैंकों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना (Licensing of Banks)—कोई भी बैंकिंग कम्पनी रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बैंक को लिखित प्रार्थना-पत्र देना होगा, जिसमें उसे यह प्रमाणित करना होगा कि वह अपने जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि आवश्यकतानुसार पूर्ण रूप से वापस देने की स्थिति में है और उस कम्पनी का कार्य इस प्रकार नहीं चलाया जा रहा है जो जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचाता हो।

(viii) बैंकों का निरीक्षण (Inspection of Banks)—रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से या केन्द्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी बैंकिंग कम्पनी के हिसाब का निरीक्षण कर सकता है। बैंक के सचालकों का यह कर्तव्य होगा कि वे जाँच सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना अथवा आवश्यक कागज पत्रों को रिजर्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करें। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बैंकिंग कम्पनी के बिषय में होने पर सरकार उस

बैंक को नई जमा प्राप्त करने से रोक सकती है या रिजर्व बैंक को उसके निस्तारण (Liquidation) का प्रवन्ध करने का आदेश दे सकती है।

(ix) रिजर्व बैंक के अन्य अधिकार— बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अधिकार प्राप्त है कि वह (i) किसी बैंकिंग कम्पनी को किसी विशेष प्रकार का व्यापार करने से रोक सकता है। (ii) बैंकिंग कम्पनीज से प्राप्ति प्राप्त होने पर उनके विलियन (Amalgamation) में सहायता कर सकता है। (iii) बैंकिंग कम्पनियों को अथवा अग्रिमों के रूप में सहायता दे सकता है।

सन् १९४९ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट को कार्यरूप में लाने पर कुछ बठिनाइयाँ अनुभव की गईं, जिन्हें सरकार ने सन् १९५० तथा १९५३ में इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा दूर कर दिया। बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में एक और संशोधन सन् १९५६ में किया गया जिसमें रिजर्व बैंक को बैंकों के सम्बन्ध में कुछ और अधिकार दे दिये गये हैं—(अ) रिजर्व बैंक को जनसाधारण तथा बैंकिंग कम्पनियों के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकों को आदेश देने का अधिकार दे दिया गया। (ब) बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे प्रमुख अधिकारियों व प्रवन्ध संचालकों की नियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। (स) किसी भी बैंक के संचालक-मण्डल अथवा किसी अन्य संगठित सभा की कार्य पद्धति की जाँच करने के लिए रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को भेज सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने निरीक्षक भी नियुक्त कर सकता है। इसके पश्चात् सन् १९६१ तथा सन् १९६२ में भी बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये जिनका उद्देश्य रिजर्व बैंक को ऐसे अधिकार देना था, जिससे कि वह बैंकों पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण कर सके।

भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks in India)—

मिश्रित पूँजी वाले बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का आधार हैं। इन बैंकों के द्वारा ही हमारे व्यापार तथा उद्योगों को अपना कार्य चलाने के लिए पूँजी प्राप्त होती है तथा उन्हें ये अन्य प्रकार की बैंकिंग सुविधायें भी देते हैं। मिश्रित पूँजी वाले बैंक हम उन सब बैंकों को कहते हैं जिनकी स्थापना भारतीय कम्पनीज एक्ट १९१३ (Indian Companies Act, 1913) के अनुसार हुई है। सोमित अर्थ में मिश्रित पूँजी वाले बैंकों से अनिप्राय व्यापारिक बैंकों से होता है। यद्यपि अन्य प्रकार के बैंकों का निर्माण भी मिश्रित पूँजी के आधार पर किया जाता है किन्तु केवल व्यापारिक बैंकों को ही इस श्रेणी में रखने की परम्परा रही है। विदेशी विनिमय बैंक यद्यपि व्यापारिक बैंकों के कुछ कार्य करते हैं किन्तु उन्हें मिश्रित पूँजी वाले बैंकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि मुख्यतया उनका सम्बन्ध विदेशी व्यापार से होता है। स्टेट बैंक को इस प्रकार के बैंकों में इसलिए सम्मिलित नहीं

किया जाता है क्योंकि उसकी स्थापना उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की गई थी।

बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)—

नियन्त्रण की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में बांट दिया है—प्रथम, अनुसूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) तथा द्वितीय, असूचीबद्ध बैंक (Non scheduled Banks)। अनुसूचीबद्ध बैंक बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक की दूसरी सूची (Scheduled II) में सम्मिलित कर दिया गया है। इन बैंकों की चुकता पूँजी (Paid up Capital) तथा सुरक्षित कोष मिलाकर ५ लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। इन बैंकों के बारे में रिजर्व बैंक की यह विश्वास होना चाहिए कि वे तत्काल कार्य अपने जमाकर्ताओं (Depositors) के हित में ही करते हैं। इन बैंकों को अपनी निश्चित जमा (Time liabilities) का २% तथा चालू जमा (Demand liabilities) का ५% रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। मन् १९५६ में रिजर्व बैंक को इन जमा के प्रतिशत में वृद्धि करने का अधिकार भी दे दिया गया है। ऐसे बैंकों को नियमित रूप से प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्टें भेजनी पड़ती हैं। अनुसूचीबद्ध बैंकों की रिजर्व बैंक से कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी प्रतिभूतियों की भाँट पर रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं तथा अपने द्वारा भुनाये हुए बिलों को फिर से भुना सकते हैं। रिजर्व बैंक इनसे ऐसे बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों को खरीद भी सकता है जो ६० दिन से अधिक अवधि के लिए न लिखे गये हों। रिजर्व बैंक अनुसूचीबद्ध बैंकों के रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधाएँ भी देता है। ये सब बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक की दूसरी सूची (Scheduled II) में सम्मिलित नहीं किया जाता है, असूचीबद्ध बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को उपर्युक्त सुविधाएँ नहीं प्राप्त होती हैं और न इन पर रिजर्व बैंक का अधिक नियन्त्रण ही रहता है।

व्यापारिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks)—

भारतवर्ष में व्यापारिक बैंक लगभग वे ही कार्य करते हैं जो अन्य देशों में इस प्रकार के बैंकों के द्वारा किये जाते हैं। हमारे देश में व्यापारिक बैंकों के द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं—(i) जमा प्राप्त करना—व्यापारिक बैंक देश में लोगों की बचत को जमा के रूप में आकर्षित करते हैं और इस प्रकार समाज की सम्पूर्ण बचत को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्राप्त जमा पर यह बैंक व्याज भी देते हैं। इन बैंकों के द्वारा जमा विभिन्न खातों में प्राप्त की जाती है जिनमें चालू जमा खाता (Current Account), निश्चित जमा खाता (Fixed Deposit Account) तथा बचत खाता (Savings Account) प्रमुख हैं।

(ii) ऋण देना तथा बिलों को भुनाना—व्यापारिक बैंक अपनी जमा को व्यापारियों

को अल्पकालीन ऋण के रूप में उधार देते हैं जिससे इन्हें प्रायः प्राप्त होती है। यह ऋण प्रायः वस्तुओं की भाँड पर अथवा प्रतिभूतियों व सोने चाँदी के आधार पर दिये जाते हैं। भूमि तथा अचल सम्पत्ति के आधार पर यह बैंक ऋण नहीं देते हैं। इन बैंकों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यापारियों के बिलों तथा हुडियों को भुनाने का कार्य भी किया जाता है। (iii) धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना—यह बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए उनके धन को बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) तथा साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit) के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सस्ती सुविधायें भी प्रदान करते हैं। (iv) बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध—व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर (Locker) की सुविधायें देते हैं जिनमें लोग अपना बहुमूल्य सामान तथा दस्तावेज आदि रख सकते हैं। एजेंट के रूप में वे अपने ग्राहकों के विनिमय-साध्य साख-पत्रों का भुगतान एकत्रित करते हैं, ग्राहकों की ओर से भुगतानों को निबटाते हैं, उनके लिए अंश (Shares) तथा प्रतिभूतियों (Securities) का क्रय-विक्रय करते हैं तथा उन्हें आधिक सलाह भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय भी करते हैं और विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रवर्धन में सहायता देते हैं। ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की गुप्त सूचना देने का कार्य भी इन बैंकों के द्वारा किया जाता है।

बैंकों की धीमी प्रगति के कारण

(Causes of Slow Progress of Banking)—

हमारे देश में बैंकिंग का विकास उतनी तेजी के साथ नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। अभी भी देश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। यद्यपि द्वितीय विश्व-युद्ध काल में हमारे देश में बहुत से नये बैंक स्थापित किये गये तथा उनकी शाखाओं में भारी वृद्धि हुई किन्तु अन्य देशों की अपेक्षा यह वृद्धि बहुत कम रही है। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या की तुलना में वर्तमान बैंकिंग सुविधायें बहुत कम हैं। भारतवर्ष में २,७६,००० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है जबकि स्विटजरलैंड में १,३३३ तथा इंग्लैंड में ३,६०० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक पाया जाता है। अभी भी हमारे देश में बैंकों की बहुत कमी है। बैंकिंग सुविधायें अप्रप्राप्त होने के कारण समाज की बहुत-सी वस्तुओं को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में लगाना सम्भव नहीं हो सका है। देश के आर्थिक विकास को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास तेजी के साथ किया जाय। भारतवर्ष में बैंकों की धीमी प्रगति के कारण इस प्रकार है—

(i) देश में आय तथा बचत का कम होना—भारतवर्ष में लोगों की आय कम होने के कारण बचत की मात्रा कम रहती है और बैंकों की अधिक मात्रा में जमा प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लोगों में बैंकिंग आदत का विकास भी

नहीं हुआ है और बहुत से लोग अपनी वचन की गाइडर रमना अधिक पसन्द करने हैं। बहुत कम लोगों के द्वारा ही बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण हमारे बैंकों के पाम साधनों की कमी रहती है और उनका विकास सीमित हो जाता है।

(ii) इम्पीरियल बैंक के साथ प्रतियोगिता—अब से कुछ वर्ष पूर्व तक इम्पीरियल बैंक की प्रतियोगिता ने अन्य व्यापारिक बैंकों को घनपने का मौका नहीं दिया। इम्पीरियल बैंक के पाम बहुत बड़े साधन रहने थे तथा उम्मेद मरकारी सरक्षण प्राप्त था और ऐसी दशा में अन्य बैंकों का उनके साथ प्रतियोगिता करना सम्भव नहीं था। स्टेट बैंक की स्थापना के पश्चात् यह दोष दूर हो गया है।

(iii) विदेशी विनिमय बैंकों के साथ प्रतियोगिता—व्यापारिक बैंकों की विदेशी विनिमय बैंकों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है जिनके साधन अपेक्षाकृत बहुत अधिक होते हैं। इस प्रतियोगिता के कारण भी भारतीय बैंकों के विकास में बाधा पड़ी है। आरम्भ में ही विदेशी विनिमय बैंक व्यापारिक बैंकों के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहे हैं और उनका बहुत-सा व्यवसाय य स्वयं न लेते हैं। विदेशी विनिमय बैंकों का प्रबन्ध प्रायः विदेशियों के हाथ में होने के कारण लोगों की इन बैंकों में अधिक विश्वास रहना था और व्यापारिक बैंक इनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते थे। अब इस स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है और विदेशी बैंकों का सरलित ध्यान धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

(iv) भारत के विदेशी व्यापार का विदेशियों के हाथ में रहना—भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथ में रहता था जो इम्पीरियल बैंक अथवा विदेशी विनिमय बैंकों के साथ अपना लेन-देन रखते थे तथा भारतीय बैंकों के साथ अनुचित व्यवहार भी करते थे। अब बहुत अधिक समय तक हमारे बैंकों की विकास का अवसर प्राप्त न हो सका।

(v) बैंकिंग संकट—भारतवर्ष में बैंकिंग प्रणाली के सुमगडित न होने के कारण समय-समय पर बैंकिंग संकट आते रहे हैं जिनके कारण बहुत से बैंक बंद हो गये और काफी लम्बे समय तक बैंकों में लोगों के विश्वास की स्थापना न किया जा सका।

(vi) सुव्यवस्थित विल बाजार का अभाव—हमारे देश में एक संगठित विल बाजार के न होने के कारण भी बैंकों के विकास में बाधा पड़ी है। विल बाजार के अभाव के कारण देश में मुरझित विनियोग के साधन कम थे तथा बैंक अपने व्यवसाय का विस्तार न कर सके।

(vii) सरकार की बैंकों के प्रति उदासीनता—काफी लम्बे समय तक सरकार ने बैंकों के विस्तार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके सम्बन्ध में

हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया। बैंको के विस्तार को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था और न उनकी कार्य-प्रणाली में ही कोई सुधार करने का प्रयत्न किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

भारतीय बैंको के दोष (Defects of Indian Banks)—

हमारे देश में व्यापारिक बैंको के विकास, उनकी व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत से दोष पाये जाते हैं जिनके कारण देश में बैंकिंग का पर्याप्त तथा नियमित विकास नहीं हो सका है। भारतीय बैंको के कुछ मुख्य दोष निम्न-लिखित हैं—

(१) छोटे आकार के बैंकों की अधिकता (Predominance of Small Sized Banks)—भारत में मिश्रित पूँजी वाले कुछ बैंक बहुत बड़े तथा शक्तिशाली हैं किन्तु अधिकांश बैंको का आकार छोटा है जिसके कारण उनमें स्थिरता एवं शक्ति का अभाव रहता है। लगभग ४०० बैंको में से केवल ७६ बैंक अनुसूचीबद्ध हैं अर्थात् जिनकी चुकता पूँजी तथा संचित कोष ५ लाख रुपये अथवा इससे अधिक है। वर्तमान दशक में ५ लाख रुपये की पूँजी भी किसी बैंक को सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जा सकती है जबकि हमारे देश में ८०% बैंको की पूँजी इससे कम है। पूँजी कम होने के कारण इन छोटे बैंको को बहुत कठिनाई होती है और वे अपने व्यवसाय का उचित विस्तार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बैंक जमा आकर्षित करने के लिए ऊँची ब्याज की दर देते हैं तथा अधिक लाभांश बाँटने के लिए सट्टा व्यवसाय में अपना धन फँसा देते हैं और फेल हो जाते हैं। छोटे बैंक हमारी बैंकिंग व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी है। इन बैंको की कुल जमा तथा रक्षित कोष मिलाकर भी इतने नहीं होते हैं कि वे अपने व्यवसाय को लाभपूर्वक ढंग से चला सकें।

(२) शाखा विस्तार की शेषपूर्ण नीति (Indiscriminate Branch Expansion)—भारतीय बैंक नई शाखाएँ खोलते समय इस बात की जाँच नहीं करते हैं कि किसी स्थान विशेष की आर्थिक तथा मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ पर नया बैंक स्थापित करना उचित है अथवा नहीं। जिन स्थानों पर पहले से ही बहुत से बैंक कार्य कर रहे होते हैं वही पर अन्य बैंक भी अपनी शाखाएँ स्थापित कर देते हैं जिससे कुछ केन्द्रों पर बैंको की शाखाएँ अधिक हो जाने के कारण अनावश्यक प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत कुछ अन्य स्थानों पर बैंको की आवश्यकता होने पर भी बैंक नहीं होते हैं। शाखा विस्तार को प्रायः प्रतिष्ठा बढ़ाने अथवा बैंक का विज्ञापन करने का साधन समझा जाता है। इस गलत धारणा के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी शाखाएँ स्थापित कर दी जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय कम्पनीज अधिनियम पास हो जाने में यह दोष दूर

ही गया है क्योंकि अब प्रत्येक बैंक को शाखा खोलने से पूर्व रिजर्व बैंक से आज्ञा लेनी होती है।

(३) अपर्याप्त रक्षित कोष (Inadequate Reserves)—अधिकांश बैंकों का उद्देश्य अपने अगधारियों को अधिक से अधिक लाभ देना होता है और रक्षित कोष का निर्माण करने की ओर उनका बहुत कम ध्यान जाता है। बैंकों के लाभ के अधिकांश भाग को लाभ अंश के रूप में बांट दिया जाता है और रक्षित कोष में उसका बहुत कम भाग रखा जाता है। इस प्रकार की नीति के कारण हमारे बैंक अधिक मात्रा में रक्षित कोष जमा नहीं कर सके हैं जिसके कारण उनमें स्थिरता तथा शक्ति का अभाव रहता है। बैंकों के रक्षित कोषों का कम होना उनमें आधारभूत कमजोरी उत्पन्न करता है और वे कभी भी सफट में फँस सकते हैं।

(४) नकद कोष कम रखना (Low Cash Reserve)—भारतीय बैंकों की एक कमजोरी यह भी है कि वे नकद कोष बहुत कम मात्रा में रखते हैं और अपने निक्षेपों का बहुत बड़ा भाग ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में दे देते हैं। बैंक अधिकाधिक लाभ उठाने के लालच से अपने नकद कोष के अनुपात की नीचा रखते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें अपने जमाकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी अपने पास रखनी चाहिए। बैंकों के नकद कोष का कम होना तथा उनकी जमा का ऐंसे आदेमों (Assets) में लगा रहना जिसमें से उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें किसी भी समय सफट में डाल सकता है।

(५) ऋण नीति का दोषपूर्ण होना (Defective Lending Policy)—बहुत से बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति दोषपूर्ण रही है। बैंक प्रायः उन कम्पनियों को ऋण दे देते हैं जिनमें उनके डायरेक्टर्स का हित होता है। इस प्रकार के ऋण देते समय उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। कभी-कभी वे अपने सचालकों (Directors) तथा उनके मित्रों की व्यक्तिगत जमानत पर बड़ी मात्रा में ऋण दे देते हैं। कुछ बैंक अचल सम्पत्ति की ग्राह पर ऋण देकर कठिनाई में पड़ जाते हैं। बहुत से बैंक अपनी अल्पवालीन जमा को दीर्घकालीन औद्योगिक विनियोग में लगा देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के पास हों जाने तथा बैंकों पर रिजर्व बैंक का नफटा नियन्त्रण होने के कारण यह दोष धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।

(६) अकुशल संचालन (Inefficient Management)—बहुत से बैंकों का संचालन अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में है जिन्हें बैंकिंग के सिद्धान्तों का कोई ज्ञान नहीं होता है। अनुभवहीनता के कारण ऐसे संचालक बैंकों को कठिनाई में डाल देते हैं। बैंकिंग एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसे उचित प्रकार से चलाने के लिए योग्य तथा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भारत में कुछ बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बैंक चलाने का अनुभव तथा बैंकिंग सिद्धान्तों का पर्याप्त ज्ञान

नहीं है जिसके कारण वे बैंको का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग बैंकिंग व्यवसाय में केवल इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वे उन्हें जल्दी रुपया बनाने का सुविधापूर्ण साधन समझते हैं। इस प्रकार के अकुशल संचालक स्वयं भी बरबाद होते हैं और बैंकिंग के प्रति लोगों का विश्वास भी कम करते हैं।

(७) अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य पद्धति का प्रयोग (English Language and Western Methods of Business)—भारतीय बैंक पाश्चात्य पद्धति के आधार पर बैंकिंग व्यवसाय करते हैं तथा बैंको में अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है जिसके कारण बहुत से व्यापारी बैंकिंग सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सके हैं। पाश्चात्य बैंकिंग पद्धति का यह अनावश्यक अनुसरण इन बैंको की प्रगति के रास्ते में रुकावट रहा है। अभी तक भी हमारे बैंको ने भारतीय बैंकिंग पद्धति के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

भारतीय बैंकिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव

(Suggestions for Strengthening Banking in India)—

व्यापारिक बैंको की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनमें से कुछ एक को भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत कार्य रूप में लाया जा रहा है। सन् १९४६ में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए कुछ सुझाव दिये। सन् १९५४ में व्यक्तिगत क्षेत्र के वित्त से सम्बन्धित समिति (Committee on Finance for Private Sector) ने व्यापारिक बैंको के द्वारा दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कुछ और सुझाव दिये। भारतीय बैंको की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए दिये गये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं—

(१) बैंकों का प्रबन्ध अधिक कुशल तथा अनुभवशीलों के हाथों में होना चाहिए—प्रायः बैंको के डाइरेक्टर्स में बैंकिंग सम्बन्धी ज्ञान का अभाव होता है और उन्हें बैंकिंग का अनुभव भी नहीं होता है। ऐसे लोग बैंको की कार्यकुशलता के साथ नहीं चला पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंको के प्रबन्ध तथा संचालन सम्बन्धी दोषों को दूर किया जाये। बैंको का संचालन केवल अनुभवी एवं कुशल प्रबन्धकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि डाइरेक्टर्स बैंक के कार्यों में पर्याप्त रुचि लें और बैंक की क्रियाओं पर इस प्रकार का नियंत्रण रखें जिससे कि दिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम उरलता के सिद्धान्त जैमाकर्ताओं के हितों के अनुकूल हो। यह भी आवश्यक है कि हैड आफिस के द्वारा शाखाओं पर सप्रभाविक नियंत्रण एवं निरीक्षण किया जाये। बहुत से बैंको का आन्तरिक अन्वेषण (Audit) तथा निरीक्षण (Inspection) दोषपूर्ण होता है और कुछ बैंको में आवश्यक मदों को निकालने से पूर्व ही लाभ का वितरण कर दिया जाता है। बैंको के प्रबन्ध सम्बन्धी इन सभी दोषों को दूर किया जाना चाहिए।

(२) बैंकों की विनियोग नीति में सुधार—कुछ बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में पर्याप्त विनियोग नहीं करते हैं और कुछ ऐसी कम्पनियों के हिस्सों में रकबा लगा देते हैं जिन्हें बाजार में आमानी से नहीं बेचा जा सकता है किन्तु जिनमें उनके डाईरेक्टर्स का हित होना है। इस प्रकार के दोषपूर्ण विनियोग में बैंकों को दबना चाहिए। विशेषतया असूचीबद्ध बैंकों (Non-Scheduled Banks) के ऋणों की मात्रा तो अधिक रहती है किन्तु निक्षेपों की तुलना में उनका सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कम रहना है जिसके कारण उनकी तरलता कम हो जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार १२३ बैंकिंग कम्पनियाँ ऐसी थी जिनका सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग उनके निक्षेपों के १% से भी कम था। इस प्रकार की स्थिति इन बैंकों को सड़क में डाल सकती है। बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये जाने वाले विनियोग की मात्रा बढ़नी चाहिए। बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम पास हो जाने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(३) ऋण सम्बन्धी नीति में सुधार—व्यापारिक बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति में भी सुधार की आवश्यकता है। कुछ छोटे बैंक अपनी जमा के अनुपात से बहुत अधिक मात्रा में ऋण दे देते हैं और फँस हो जाते हैं। मई १९५१ में इस प्रकार के बैंकों की संख्या १५२ थी इससे अतिरिक्त बैंकों के द्वारा अपने ऋणियों की आर्थिक स्थिति की जाँच करने का प्रबन्ध भी होना चाहिए बैंकों को अपने ऋणों को विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के व्यापारियों को देने के मिद्धान्त के महत्व को भी समझना चाहिए। बैंकों के ऋणों का अत्यधिक विस्तार हमारी बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर करता है। बैंकों को ऋण देते समय अपनी तरलता के महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अपने ऋणों का अत्यधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्हें बैंकिंग के मिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। ऋण देने से पूर्व बैंकों को अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति तथा ऋण के उद्देश्यों के बारे में पूरी जाँच करनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके प्रमुरक्षित ऋणों (Unsecured Loans) तथा अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा को कम से कम रखा जाने।

(४) शाखाओं का विस्तार तथा उनका प्रबन्ध ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए—बैंकों की शाखा विस्तार सम्बन्धी नीति में परिवर्तन होना आवश्यक है। बैंकों को नई शाखाएँ खोलने में पूर्व उन स्थान की आर्थिक आवश्यकताओं तथा वहाँ पर उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की जाँच करनी चाहिए। नई शाखाएँ तभी खोली जानी चाहिएँ जबकि ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण हो। शाखाओं का विस्तार बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने अथवा उसका विज्ञापन करने का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अनिर्दिष्ट जहाँ तक सम्भव हो सके शाखाओं का विस्तार ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इस समिति के अनुसार ग्रामीण

क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ जाने के कारण वहाँ पर वचत को प्रोत्साहित करने तथा इकट्ठा करने के लिए बैंक स्थापित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि व्यवसाय की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बैंकों का होना आवश्यक है। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में छाखाएँ खोलने के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए।

बैंकों की शाखाओं के प्रबन्ध में भी सुधार होने की आवश्यकता है। कुछ बैंकों के द्वारा अपनी शाखाओं का प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं किया जाता है। उनका ठीक निरीक्षण नहीं होता है तथा उनसे नियमित रिपोर्ट नहीं आती है। इस प्रकार दोषों को शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

(५) सामांश वितरण नीति में सुधार—बैंकों को लाभार्थ वितरण करने से पूर्व रक्षित कोष का निर्माण करना आवश्यक समझना चाहिए। अपने लाभ का पर्याप्त भाग रक्षित कोष में रखने के पश्चात् शेष लाभ को ही अशधारियों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बैंकों के पास रक्षित कोषों की मात्रा बढ़ेगी और उनमें दृढ़ता उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त बैंक को लाभार्थ वितरण से पूर्व बुरे एवं शक्तिहीन ऋणों (Bad and Doubtful Debts) तथा अपने प्रादेयों (Assets) की घिसावट आदि के लिए एक समुचित रकम अलग रखनी चाहिए। अभी भी ऐसे बैंकों की संख्या काफी है जिनका रक्षित कोष उनकी जमा के अनुपात में बहुत कम रहता है। इस प्रकार की कमजोरी प्रायः असूचीबद्ध बैंकों (Non-Scheduled Banks) में अधिक पाई जाती है। रिजर्व बैंक के सप्रभाविक नियंत्रण के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है।

(६) अन्य सुझाव—उपर्युक्त सुझाव के अतिरिक्त भारतीय बैंकिंग के दोषों को दूर करने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दिये जा सकते हैं—(i) छोटे प्रकार के बैंकों को मिलाकर अथवा छोटे बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलियन करके शक्तिशाली एवं अधिक पूँजी वाले बैंकों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक बैंक आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अनाधिक बैंकों का विलियन कर दिया जाये।

(ii) सहकारी बैंकों की भाँति व्यापारिक बैंकों के विकास में सरकार को अधिक सहयोग देना चाहिए। बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे बैंकों को स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के सम्बन्ध में छूट दी जानी चाहिए। इसके अनिरीक्त पोर्ट ट्रस्ट, नगर महापालिकाओं, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य अर्ध-सरकारी संस्थाओं की जमा व्यापारिक बैंकों के पास रखी जानी चाहिए जिससे कि इन बैंकों के साधनों में वृद्धि की जा सके।

(iii) बैंकों में आपसी प्रतियोगिता को रोकने के लिए उनकी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए। केन्द्रीय बैंकिंग ज्ञान समिति के सुझाव पर अखिल

भारतीय बैंकिंग मण (All India Banker's Association) की स्थापना की गई थी किन्तु यह संस्था अधिक कार्यशील नहीं रही है। इसे अधिक कार्यशील बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(iv) अंग्रेजी के स्थान पर बैंकों को प्रादेशिक भाषाओं में अपना काम करना चाहिए जिससे कि अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी बैंकों से लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त बैंकों को पाश्चात्य बैंकिंग विधि के स्थान पर भारतीय बैंकिंग विधि को अपनाना चाहिए।

(v) बैंकों के प्रबन्ध एवं संचालन की कुशलता को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सम्बन्धी शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए। बैंकों के संचालकों तथा प्रबन्धकों को बैंकिंग के मिथान्त एवं कार्य-प्रणाली में शिक्षा देना आवश्यक है।

बैंकों के सुधार के लिए किये गये उपाय

(Steps Taken for Improvement of Banking)—

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों की कार्य-प्रणाली काफी दोषपूर्ण है और उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं और यह आशा की जा सकती है कि रिजर्व बैंक के नेतृत्व में बहुत जल्दी ही हमारी बैंकिंग प्रणाली का आधार अधिक दृढ़ किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में किये गये कुछ सुधार इस प्रकार हैं—(१) अब कोई भी बैंक बिना ५०,००० रुपये की पूंजी के स्थापित नहीं किया जा सकता है। (२) नये अधिनियम के अनुसार कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना न तो अपनी नई शाखा खोल सकता है और न अपने कार्यों का कुछ विशेष दिशाओं में विस्तार ही कर सकता है। (३) सभी बैंकों के लिए अपनी जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है जिससे इन बैंकों की तरलता बनी रहती है। (४) बैंकों को सहायता देने के सम्बन्ध में अब रिजर्व बैंक की नीति अधिक उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण हो गई है। (५) सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकों के ऊपर अनेक प्रकार से नियन्त्रण करने का अधिकार दे दिया गया है। (६) रिजर्व बैंक एक्ट में भी संशोधन किया गया है जिससे कि वह देश में बैंकिंग के विकास में सक्रिय भाग ले सके। (७) ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नव-निर्मित स्टेट बैंक को ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में ४०० नई शाखाएँ स्थापित करने का कार्य दिया गया था जिसे वह पूरा कर चुका है।

भारतीय बैंकों की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Indian Banks)

अनुसूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) की संख्या में सन् १९४६ के पश्चात् कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् १९४६ में अनुसूचीबद्ध बैंकों की

संख्या ८३ थी जो १९५१ में बढ़ कर ६२ हो गई किन्तु सन् १९६० में छोटे बैंकों का विलयन हो जाने के कारण यह संख्या गिर कर फिर ८३ रह गई। नवम्बर सन् १९६४ में हमारे देश में ७६ अनुसूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) थे तथा इनकी शाखाओं की कुल संख्या ५००२ थी जो सन् १९६३ की अपेक्षा ३६६ अधिक थी। असूचीबद्ध बैंकों (Non-Scheduled Banks) की संख्या जो १९५२ में ४२३ थी, सन् १९६१ में गिर कर २२२ रह गई। सितम्बर सन् १९६४ में सूचना देने वाले अनुसूचीबद्ध बैंकों की संख्या केवल १५६ थी। इन बैंकों की संख्या कम होने का मुख्य कारण बहुत से छोटे बैंकों का एकीकरण, विलयन तथा निस्तारण किया जाना था। अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या सन् १९५३ तक गिरी है जिसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक की प्रतिबन्धक नीति थी। इसके पश्चात् इन बैंकों की शाखाओं में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। इसके विपरीत असूचीबद्ध बैंकों (Non-Scheduled Banks) की शाखाओं की संख्या में कमी हुई है। इन बैंकों की शाखाएँ जो सन् १९५१ में १४७३ थी सन् १९६१ में गिर कर केवल ७२३ रह गईं।

बैंकों का असमान वितरण (Uneven Distribution of Banks)—

हमारे देश में बैंकों का वितरण बहुत असमान है। देश के कुछ भागों में बैंकों की संख्या काफी है तथा कुछ अन्य भागों में उनकी भारी कमी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, गुजरात तथा मद्रास के राज्यों में बैंकिंग सुविधाएँ काफी विकसित हैं जबकि उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, आसाम, बिहार तथा मध्य प्रदेश इनसे बहुत पीछे हैं। इसका मुख्य कारण देश में बैंकों का अनियोजित विकास है। हमारे देश में बैंकों की शाखा विस्तार नीति बहुत दोषपूर्ण रही है जिसके कारण बैंकिंग का संतुलित विवास नहीं हो सका है। युद्ध काल तथा उसके उपरान्त बैंकों के द्वारा जितनी भी नई शाखाएँ खोली गई हैं वे सब बड़े शहरों अथवा मंडियों में स्थापित हैं जिसके कारण इन केन्द्रों में बैंकों की आपसी प्रतियोगिता बढ़ गई है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का कोई विकास नहीं हुआ है। सन् १९६१ में सभ्यत बैंकों की ५,१११ शाखाओं में से १८०५ शाखाएँ ऐसे १०३ स्थानों पर स्थित थी जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या १ लाख या इससे अधिक थी। पचास हजार से १ लाख के बीच की जनसंख्या वाले ११६ स्थानों पर केवल ६१६ शाखाएँ थी और १०,००० से कम जनसंख्या वाले स्थानों पर बहुत ही कम बैंक थे।

बैंकों की जमा में भारी वृद्धि

(Rapid Growth of Banks' Deposits)—

सन् १९४६ के पश्चात् बैंकों की जमा में विशेष रूप से तेजी के साथ वृद्धि हुई है। दिसम्बर सन् १९५५ में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में, जो लगभग प्रथम

योजना काल था, बैंकों की जमा में १२६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इससे अगले पाँच वर्षों में यह वृद्धि ६०२ करोड़ रुपये की हुई जो पहले से बहुत अधिक थी। यह कहा जा सकता है कि प्रथम योजना काल में बैंक जमा लगभग २% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ी किन्तु द्वितीय योजना काल में यह वृद्धि १२% प्रतिवर्ष थी। सन् १९६० में समाप्त होने वाले दशक में बैंकों की जमा में ८६% प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस काल में बैंक जमा के तेजी के साथ बढ़ने का मुख्य कारण दोनों योजनाओं के परिणामस्वरूप लोगों की आय में होने वाली निरन्तर वृद्धि तथा लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास होना था। तीसरी योजना काल में भी बैंकों की जमा तेजी के साथ बढ़ती रही है। २५ दिसम्बर सन् १९६४ को बैंकों की कुल जमा पहले वर्ष की अपेक्षा २६६ करोड़ रुपये अधिक थी। बैंक जमा में होने वाली वृद्धि की औसत दर, १९६४ में १५% से भी अधिक थी, इस बात का प्रमाण है कि देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था अधिक माना में की गई है। २५ दिसम्बर को अनुसूचीबद्ध बैंकों की कुल जमा २७५४५८ करोड़ रुपये थी जबकी १९५०-५१ में यह जमा केवल ६३२.६३ करोड़ रुपये थी। अनुसूचीबद्ध बैंकों की जमा में भी वृद्धि हुई है यद्यपि वह अपेक्षाकृत कम रही है।

बैंक जमा की प्रकृति में परिवर्तन

(Change in the Structure of Bank Deposits)—

बैंकों की जमा की मात्रा के साथ-साथ उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। चालू जमा (Demand Deposits) जो सन् १९५० में कुल जमा का ५७% प्रतिशत थी, अक्टूबर १९६० में गिर कर ३६% रह गई। इस बात से विदित है कि इस काल में चालू जमा के महत्व में कमी हुई है। इसी काल में निश्चित जमा (Time Deposits) पहले से ढाई गुणा हो गई और कुल जमा में उसका प्रतिशत २७ से बढ़कर ४७ हो गया। पिछले कुछ वर्षों से चालू जमा (Demand Deposits) का महत्व फिर बढ़ने लगा है जो इस बात से विदित है कि सन् १९६३ व १९६४ के वर्षों में चालू जमा की मात्रा निश्चित जमा की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ी है। २५ दिसम्बर सन् १९६४ को बैंकों की चालू जमा (Demand Deposits) पिछले वर्ष की अपेक्षा १७६ करोड़ रुपये अधिक थी।

नकद कोषों के अनुपात में कमी

(Falling Percentage of Cash Reserves)—

योजना काल में यद्यपि बैंकों का विकास तीव्र गति से हुआ है किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हुई है। बैंकों की जमा में तेजी के साथ वृद्धि होने के साथ-साथ उनके पीछे रखे जाने वाले नकद कोष के अनुपात में काफी गिरावट आ गई है। सन् १९५०-५१ में अन्तिम शुक्रवार को निक्षेपों के पीछे रखे जाने वाले नकद कोष का अनुपात

१०.६ प्रतिशत था और २७ नवम्बर १९६४ को यह अनुपात गिर कर केवल ६.३ प्रतिशत रह गया। बैंको के नकद कोषों का यह पतन बैंकिंग व्यवस्था के दृढ़ होने का प्रतीक नहीं है। बैंको के निक्षेपों का बढ़ना तथा उनका अधिक मात्रा में विनियोग किया जाना उनकी प्रगति को बतलाता है और उनके लाभ को बढ़ाता है किन्तु इस के साथ-साथ उनके नकद कोषों में भी पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। बैंकों के पास आवश्यक मात्रा में नकद कोषों का न होना उन्हें किसी भी समय सफट में डाल सकता है।

बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा में वृद्धि
(Increase in Bank Advances)—

पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों की मात्रा में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। सन् १९५० के अन्त में बैंक अग्रिमों की मात्रा ४३४ करोड़ रुपये थी। पहली योजना काल में इन अग्रिमों में ३७ प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बहुत अधिक न थी। दूसरी योजना काल में यह वृद्धि ११४% थी। सन् १९६०-६१ में बैंकों के कुल अग्रिमों की मात्रा १३३६.३ करोड़ रुपये थी जो २७ नवम्बर को बदलकर १७३४.९ करोड़ रुपये हो गई। इससे स्पष्ट है कि बैंकों की जमा में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके अग्रिम भी तेजी के साथ बढ़े हैं।

बैंक अग्रिमों का विस्तार करने से पता चलता है कि द्वितीय योजना काल में उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों का अनुपात बढ़ा है तथा कृषि एवं व्यवसाय को दिये जाने वाले अग्रिमों का अनुपात कम हुआ है। सन् १९५१ के अन्त में बैंक अग्रिमों में उद्योगों का हिस्सा ३३.५ प्रतिशत था जो १९६१ में बढ़कर ५२.८ प्रतिशत हो गया। इसी काल में अग्रिमों में व्यवसाय (Commerce) का हिस्सा ५२.८ प्रतिशत से घट कर ३३.७ प्रतिशत रह गया और कृषि को मिलने वाले अग्रिमों का अनुपात २.२ प्रतिशत से कम होकर केवल ०.७ प्रतिशत रह गया। मार्च सन् १९६४ में दिये गये अग्रिमों में उद्योगों का भाग ५६.२ प्रतिशत, व्यवसाय का २६.१ प्रतिशत तथा कृषि का ०.४ प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक अग्रिमों में उद्योगों का हिस्सा निरन्तर बढ़ रहा है तथा व्यवसाय और कृषि का भाग कम होना जा रहा है।

छोटे बैंकों के विलियन की प्रवृत्ति (Amalgamation of Smaller Banks):—

पिछले कुछ वर्षों में छोटे तथा कम पूँजी वाले बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलियन (Amalgamation) करने की प्रवृत्ति रही है जिसके कारण देश में बैंकों की संख्या कुछ कम हो गई है किन्तु बैंकिंग व्यवस्था अधिक दृढ़ होती जाती रही है। एकीकरण तथा विलियन की नीति को सरफार एवं रिजर्व बैंक दोनों ने स्वीकार किया है क्योंकि इसके द्वारा ही असह्य छोटे-छोटे बैंकों के आधार को मजबूत किया जा सकता है। मार्च सन् १९५० में बैंकिंग कम्प्यूटेशनल सर्विसेज में एक प्रयोग दिये

गए हैं जिनसे बैंको का विलयन अधिक सुविधापूर्ण हो गया है। मार्च मन् १९५१ में भारत बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक का विलयन रिजर्व बैंक के निरीक्षण के परिणामस्वरूप हुआ। इसी प्रकार कुछ अन्य बैंको का विलयन भी किया गया है किन्तु अनुभव यह बतलाता है कि बैंको का विलयन आसान काम नहीं है क्योंकि प्रत्येक बैंक की नीति, परम्परायें तथा विशेषतायें अलग-प्रलग हो सकती हैं जो बैंको के विलयन के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इन कठिनाइयों के होते हुये भी यह कहा जा सकता है कि बैंको के विलयन की प्रवृत्ति भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में स्वस्थ विकास की प्रतीक है। बहुत से छोटे-छोटे तथा कम पूँजी वाले बैंको की अपेक्षा कुछ एक अधिक पूँजी वाले तथा मजबूत बैंको का होना देश की अर्थ-व्यवस्था को अधिक लाभ पहुँचा सकता है।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तथा भारत में नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विकसित होने के कारण हमारे बैंको के सम्मुख कुछ नये कार्य आ गये हैं। अधिकांश रूप से बैंको ने इन नई जिम्मेदारियों को स्वीकार किया है तथा अपनी क्रियाओं का विस्तार नये क्षेत्रों में किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं जिनका हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा है।

सन् १९६० में पलाई बैंक (Palai Bank) के फेन हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि बैंको के ढाँचे में कुछ परिवर्तन किया जाय तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे कि जमाकर्ताओं का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था में पुनः स्थापित किया जा सके। सितम्बर सन् १९६० बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम १९४६ में एक संशोधन के द्वारा सरकार ने बैंको के अनिवार्य विलयन की वैधानिक शक्ति प्राप्त कर ली। इस धारा के अन्तर्गत ३६ बैंको को ६ महीने की चेतावनी (Moratorium) दी गई। सन् १९६१-६२ में १७ बैंको की विलयन सम्बन्धी योजना को कार्य रूप में लाया गया।

बैंको की जमा में तेजी के साथ वृद्धि होने के कारण उनकी चुकता पूँजी तथा रक्षित कोषों का कुल जमा के साथ अनुपात १९५० में ६ प्रतिशत से घट कर १९६० में ५ प्रतिशत रह गया जिसके कारण बैंको के पूँजी आधार को मजबूत करने की आवश्यकता अनुभव की गई। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। बैंको से यह आग्रह किया गया है कि जब तक उनके रक्षित कोष चुकता पूँजी से कम हो तब तक वे अपने लाभ का २०% रक्षित कोषों में रखते रहे। दोनों के बराबर हो जाने पर भी वे ऐसा करते रहे जब तक उनकी चुकता पूँजी तथा रक्षित कोष दोनों मिलकर उनके निक्षेपों का ६% न हो जायें।

भारतीय बैंक प्रिटिस् बैंकिंग की परम्परागत नीति को अपनाते रहे हैं और वे प्रायः उद्योगों को दीर्घकालीन ध्यान नहीं देने थे। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में

बैंको ने अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। औद्योगिक वित्त निगमों (Industrial Finance Corporations) में व्यापारिक बैंक अपने धन का विनियोग करते हैं और ये निगम उद्योगों को दीर्घ-कालीन ऋण देनी हैं। इनके अनिश्चित हमारे बैंक अब प्रत्यक्ष रूप से भी उद्योगों को अधिक मात्रा में ऋण देने लगे हैं।

नक्षेप बीमा योजना (Deposit Insurance Scheme,—

भारतीय बैंको के समय-समय पर फेल होने रहने के कारण हमारी बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास पूर्णरूप से स्थापित नहीं हो सका है यद्यपि रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् फेल होने वाले बैंको की संख्या काफी कम हो गई है किन्तु फिर भी कुछ बैंक फेल होते रहे हैं। बैंको में जनता के विश्वास की कमी उनके विश्वास के रास्ते में बड़ी रुकावट रही है। बैंकिंग में जनता के विश्वास को स्थापित करने के लिए समय-समय पर यह सुझाव दिया गया कि देश में निक्षेपों का बीमा करने वाली एक निगम स्थापित की जाय। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) ने इस योजना पर विचार किया किन्तु उनके अनुसार योजना को कार्य-रूप में लाने के लिए अभी उचित समय नहीं आया था। श्राफ समिति (Shariff Committee) ने अधिकारियों के द्वारा इस योजना की सम्भावनाओं की जांच किये जाने की सिफारिश की। पिछले कुछ वर्षों में दो बैंको के फेल हो जाने से बैंको में जनता के विश्वास को काफी हानि पहुँची जिसके कारण निक्षेप बीमा योजना पर फिर से ध्यान केन्द्रित हो गया और सरकार ने बैंको में जमा रकम का बीमा करने की योजना को कार्य-रूप लाने का निश्चय किया।

१ जनवरी सन् १९६२ को निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (Deposit Insurance Corporation Act) के अन्तर्गत निक्षेपों का बीमा करने के लिए एक निगम स्थापित कर दी गई। इस निगम की अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये है जो पूर्णतया रिजर्व बैंक के द्वारा चुकाई गई है। निगम का प्रबन्ध एक संचालन मण्डल (Board of Directors) के द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। इस बोर्ड में रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत एक डिप्टी गवर्नर, केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी और केन्द्रीय सरकार के द्वारा मनोनीत दो डाइरेक्टर होते हैं। यह निगम केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर काम करती है।

अधिनियम के लागू होने के समय जितने बैंक कार्य कर रहे थे तथा उसके पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त बैंक बीमा योजना के अन्तर्गत आ गये हैं। सभी बैंको के निक्षेपों का बीमा कर दिया गया है किन्तु प्रत्येक बैंक में प्रत्येक जमाधारी को १५०० रुपये तक की जमा ही बीमायुक्त है। इस बीमा को निगम केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर बढ़ा सकती है। इसके लिए निगम को बैंको से अधिक से अधिक १५ नये पैसे प्रति (१००) रुपये की जमा पर प्रति वर्ष प्रीमियम

(Premium) के रूप में लेने का अधिकार दिया गया है। इस समय कापेरिशन के द्वारा प्रीमियम (Premium) की वास्तविक दर ५ पैसे प्रति १००) रुपये निश्चित की गई है। निगम को यह अधिकार दिया गया है कि वह बैंको से किसी भी प्रकार की सूचना उनके निक्षेपों के सम्बन्ध में ले सकती है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Banks)

आजकल मसार में बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के समर्थकों की संख्या काफी है। यद्यपि केन्द्रीय बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में विचार निश्चित हो गये हैं किन्तु व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अभी भी विवादग्रस्त है। कुछ लोगों का विचार है कि बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएँ सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, जिससे कि उनका संचालन व्यक्तिगत हित में न किया जाकर राष्ट्रीय हित में किया जा सके। बैंकिंग व्यवसाय का किसी भी राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में इतना अधिक महत्व होता है कि उन्हें व्यक्तिगत प्रबन्ध में नहीं छोड़ा जा सकता है और इस प्रकार की संस्थाओं का राष्ट्रीय हित में प्रयोग करने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। इसके विपरीत कुछ अन्य लोगों का विचार है कि बैंको का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं है और सरकारी नियन्त्रण के द्वारा ही उन्हें राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा विपक्ष में दिये जाने वाले विभिन्न तर्कों का अध्ययन करने के पश्चात् ही यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में बैंको का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(Arguments in Favour of Nationalisation)—

(१) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंक अपना कार्य अधिक कुशलतापूर्वक कर सकेंगे—राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का विचार है कि व्यक्तिगत प्रबन्ध वाले बैंको की अपेक्षा सरकारी प्रबन्ध वाले बैंक अपने कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययितापूर्वक ढंग से करते हैं। निजी प्रबन्ध में बैंक श्रमों का वितरण उतनी कुशलतापूर्वक नहीं करते हैं, जितना कि वे सरकारी प्रबन्ध में अन्तर्गत कर सकेंगे। बैंको का राष्ट्रीयकरण करने से उनकी आपसी प्रतिगोचिता समाप्त हो जायेगी तथा एक ही केन्द्र पर अनेक शाखाएँ खोलने में अपव्यय में भी बचा जा सकेगा।

(२) केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंको में अधिक सहयोग तथा समन्वय स्थापित किया जा सकेगा—साक्ष का उचित नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंको में अधिक से अधिक सहयोग का होना आवश्यक है। इस प्रकार का सहयोग तभी सम्भव हो सकेगा जब केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ अन्य बैंको का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। साक्ष एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग

कल्याण अथवा विनाश दोनों के लिए ही किया जा सकता है। साख का निर्माण व्यापारिक बैंको के द्वारा किया जाता है। साख निर्माण के इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्र हित में किया जाये, इसके लिए आवश्यक है कि देश के समस्त बैंको तथा केन्द्रीय बैंक में सम्पूर्ण सहयोग हो। यह तब ही सम्भव हो सकता है जबकि बैंकिंग संस्थाओं को सरकारी प्रबन्ध में ले लिया जाये।

(३) व्यापार-चक्रों को रोक जा सकेगा—पूँजीवादी समाज में व्यापार-चक्र मुख्यतया बैंको की दोषपूर्ण साख नीति के कारण ही आते हैं। यदि बैंको के द्वारा समुचित साख नीति अपनाई जाय तो समाज में व्यापार-चक्रों की तीव्रता को बहुत कम किया जा सकता है। जब बैंक निजी प्रबन्ध में होते हैं, तो वे अपनी साख नीति को लाभ के उद्देश्य से चलाते हैं किन्तु बैंको का राष्ट्रीयकरण करके उनकी साख नीति का निर्माण तथा संचालन राष्ट्र हित में किया जा सकेगा। इस प्रकार समाज में व्यापार-चक्रों का भय बहुत कम हो जायेगा। साम्यवादी देशों में बैंको के सरकारी प्रबन्ध में होने के कारण ही व्यापार-चक्रों को लगभग समाप्त कर दिया गया है।

(४) बैंकों के लाभों का लोक कल्याण के लिए प्रयोग—बैंक प्रायः लोकधन तथा जनता के विश्वास में व्यवसाय करते हैं। अतः उनके द्वारा उपार्जित लाभ का प्रयोग लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। बैंको का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् इनके लाभ सरकारी कोष में जमा होंगे और वहाँ से उनका प्रयोग आर्थिक विकास तथा लोक हित कार्यों में किया जा सकेगा।

(५) बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की स्थापना में सहायक है—वर्तमान समय में समाजवाद की अन्य प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अच्छा माना जाने लगा है और अधिकांश देश इसी प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने में व्यस्त हैं। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण उत्पादन संस्थाओं का, जिनमें बैंक भी सम्मिलित है, राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बैंको का राष्ट्रीयकरण वर्तमान पूँजीवाद से समाजवाद की ओर प्रगति करने में सहायता करेगा। यदि बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा तो वे समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में रुकावट पैदा कर सकते हैं। यह सम्भव हो सकता है कि वे सरकारी क्षेत्र वाले उद्योगों को ऋण देने से इन्कार कर दें अथवा अन्य तरीकों से उनके विकास में बाधाएँ उत्पन्न करें। वे अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में भी बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। अतः समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

(Arguments Against Nationalisation)—

बैंको के राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वालों का विचार है कि आर्थिक विकास के लिए बैंको पर केवल नियन्त्रण की आवश्यकता है, उनका राष्ट्रीयकरण

नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में दिये जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं—

(१) बैंकों की कार्यकुशलता कम हो जायेगी—सरकारी उद्योग में प्रायः लोच तथा मितव्ययिता का अभाव रहता है और उनका कार्य अनुशल एवं विसम्पूर्ण हो जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से उनके कार्य में भी इस प्रकार की अनुशलता तथा अमितव्ययिता उत्पन्न हो जायेगी। निजी बैंक अपने ग्राहकों को जितनी कुशलता एवं मितव्ययिता के साथ सेवाएँ प्रदान करते हैं, सरकारी बैंक सम्भवतः ऐसा नहीं कर सकेंगे। बैंकों को चलाने वाले कर्मचारी अपने ग्राहकों के हितों के प्रति उदासीन हो सकते हैं, जिससे उद्योग तथा व्यवसाय को काफी हानि पहुँच सकती है। सरकारी कर्मचारी बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार में भी उतनी रुचि नहीं लेंगे जितनी निजी बैंकों के द्वारा ली जाती है।

(२) निजी क्षेत्र पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बुरा प्रभाव पड़ेगा—बैंकों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने से निजी क्षेत्र के अन्य व्यवसायों को भी राष्ट्रीयकरण का भय उत्पन्न हो जायेगा और उनका स्वतन्त्र विकास रुक जायेगा। इसके अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से व्यवसायों की गोपनीयता समाप्त हो जायेगी और निजी क्षेत्र का उत्साह कम हो जायेगा।

(३) राष्ट्रीयकृत बैंकों को चलाने के लिए योग्य तथा अनुभवी कर्मचारी सरकार के पास नहीं हैं—योग्य तथा निपुण कर्मचारी एवं संचालकों के अभाव के कारण सरकार बैंकिंग व्यवसाय को ठीक प्रकार से नहीं चला सकेगी। जब तक सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों को चलाने के लिए योग्य तथा अनुभवी कर्मचारी नहीं है तब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं हो सकता है। इस दशा में जल्दी करके सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचा सकती है।

क्या भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ?

(Should Banks be Nationalised in India)—

हमारे देश में रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक का तो राष्ट्रीयकरण हो चुका है किन्तु अन्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो पाया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कई बार बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को उठाया जा चुका है किन्तु सरकार ने स्पष्टतया यह कहा है कि अभी उनका विचार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है। यद्यपि सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात को स्वीकार नहीं किया है किन्तु फिर भी हमारे देश में बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है। पिछले वर्षों में भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना को बढ़ा दिया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमें समाजवादी समाज की स्थापना में बहुत सहायता दे सकता है। हमने भारतवर्ष में समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य निश्चित किया है। बैंकों का निजी क्षेत्र में रहना इस प्रकार के समाज की स्थापना में कठिनाई उत्पन्न करता है। अतः समाजवाद की स्थापना करने के लिए बैंकों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। भारतवर्ष में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक प्रतीत होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में समाज के समस्त साधनों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए तथा इन साधनों का बटवारा निश्चित लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। यदि हमारे बैंक व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं तथा उन्हें निजी क्षेत्र के द्वारा चलाया जाता है, तो हमें आर्थिक विकास में अधिक सफलता नहीं मिल सकेगी। आर्थिक नियोजन काल में हमारे देश के सामने मुद्रा-प्रसार की प्रमुख समस्या है, जिसे देश में काम करने वाले समस्त बैंकों के सहयोग से ही दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि रिजर्व बैंक इन बैंकों के ऊपर नियन्त्रण करता है किन्तु ये बैंक पूर्णतया उसके आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकी है। इसके प्रतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से उनके बहुत बड़े साधनों का प्रयोग देश के आर्थिक विकास के लिए किया जा सकेगा। अतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण नियोजित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा व्यक्तिगत बैंकों के सभी दोष दूर किये जा सकेंगे तथा बैंकिंग सुविधाओं के असंतुलित विकास को रोका जा सकेगा।

भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में यह कहा जाता है कि अभी तक हमारे देश में निजी क्षेत्र का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में निजी क्षेत्र भी देश के अविकसित साधनों को प्रयोग करने में बड़ी सहायता दे सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से निजी क्षेत्र हतोत्साहित होगा। इसके प्रतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण उस समय किया जाना चाहिए जबकि वह पूरी तरह से विकसित हो जाये किन्तु भारतीय बैंकिंग अभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था में है और उसका राष्ट्रीयकरण करने से बैंकों का विकास रुक जायेगा। राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में आ जाने से उत्पाद तथा व्ययसाय की कमी के कारण बैंकों में निष्क्रियता उत्पन्न हो जायेगी।

यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद है किन्तु इस बात से सभी सहमत हैं कि बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का कड़ा नियन्त्रण होना

चाहिए और उसे पूर्णतया निजी क्षेत्र की इच्छा तथा सुविधाओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। हमारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं किन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकता है तथा आर्थिक नियोजन को सफल बनाकर समाजवाद की स्थापना में सहायक हो सकता है। यद्यपि कुछ समय के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को स्थगित किया जा सकता है किन्तु बहुत अधिक समय तक उसे स्थगित करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। अतः भारतवर्ष में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का अनुभव होना ठीक ही है, क्योंकि बैंकों के इतने बड़े साधनों के प्रयोग को निजी व्यवसायियों की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही बैंकों के समस्त साधनों की अधिक प्रभावशाली तरीके से देश के आर्थिक विकास के लिए लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंक हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है और इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं को सरकारी क्षेत्र में न लाना देश के दीर्घकालीन हित में नहीं है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) मिश्रित पूँजी वाले बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को आप मिश्रित पूँजी बैंक कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिये। (आगरा बी० ए० १९६५)
- (२) भारतीय सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों की कनिष्ठा तथा कठिनाइयाँ क्या हैं? इनके सुधार के सुझाव दीजिये। (आगरा बी० ए० १९६३)
- (३) व्यवसायिक बैंकों के कामों की व्याख्या करें। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में उनका क्या महत्व है? (आगरा बी० ए० १९६०)
- (४) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण में कौन-कौनसी समस्याएँ उठी थीं? क्या आप भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं? (आगरा बी० ए० १९५६ स)
- (५) आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो गये हैं और क्यों? (आगरा बी० कॉम १९५६ स)
- (६) भारत में व्यापारिक बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (गोरखपुर बी० ए० १९५६)
- (७) सन् १९४७ से आज तक भारतीय बैंकिंग की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन करिये और बतलाइये कि भविष्य में उनका क्या साम होना? (राजस्थान बी० ए० १९५६)

- (८) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोषों का वर्णन कीजिये । सुधार के लिए सुझाव दीजिए व भविष्य बताइये । (विक्रम बी० कॉम १९५६)
- (९) भारतीय बैंकिंग रचना में जो कमियाँ हैं उनका वर्णन करिये और बताइये कि सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट से वे कहां तक दूर हुई हैं ? (नागपुर बी० ए० १९५६)
- (१०) व्यापारिक बैंकों के आर्थिक कार्यों का विवेचन करिये । बैंकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उन्हें भारत में क्या विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं ? (बिहार बी० कॉम १९५६)
-

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

RESERVE BANK OF INDIA

आर्थिक जीवन में केन्द्रीय बैंक का महत्व इतना अधिक है कि उसके बिना किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था को सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। केन्द्रीय बैंक देश में साख्त व मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करके आर्थिक स्थिरता स्थापित करता है। वह देश की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रक एवं अभिभावक होता है। वह सरकार की उचित आर्थिक एवं मौद्रिक नीति के निर्माण करने तथा उसे कार्यरूप में लाने में सहायता देता है। वह सरकारी बैंकर होता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देता है। इन्हीं सब कारणों से किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए केन्द्रीय बैंक का होना आवश्यक है। पिछले महायुद्ध के पश्चात् लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी है। भारतवर्ष में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता काफी लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी किन्तु सन् १९३५ से पूर्व उसे कार्यरूप में नहीं लाया जा सका। सन् १९२० के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं वहाँ पर इस प्रकार की संस्था स्थापित की जानी चाहिए। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतवर्ष में यह अनुभव किया जाने लगा कि देश की मौद्रिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है और एक ऐसी केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता है जो देश की मुद्रा व साख्त नीतियों में समन्वय स्थापित कर सके। भारत सरकार ने देश में केन्द्रीय बैंक के अभाव को पूरा करने के लिए सन् १९२१ में इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कुछ कार्य दे दिये। किन्तु केन्द्रीय बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक का कार्य सतोषजनक नहीं रहा और देश में एक पृथक् केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। सन् १९२७ में हिल्टन यंग कमिशन ने सर्वप्रथम भारतवर्ष में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए एक विज्ञ विधान सभा में प्रस्तुत किया गया किन्तु अत्यधिक मतभेद होने के कारण वह बिल पास न हो सका और रिजर्व बैंक की स्थापना न की जा सकी। सन् १९३० में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति

(Central Banking Enquiry Committee) ने रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जोरदार सिफारिश की। बमेटों की सिफारिश के परिणामस्वरूप फिर एक विल रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रस्तुत किया गया जिसे सन् १९३४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के नाम से पास कर दिया गया और सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

रिजर्व बैंक की स्थापना की आवश्यकता

(Need for the Establishment of Reserve Bank)—

देश में रिजर्व बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता कई कारणों से अनुभव की गई जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) मुद्रा व साख नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व हमारे देश में मुद्रा व साख पर दो अलग-अलग संस्थानों का नियन्त्रण रहता था और इन दोनों संस्थानों की नीति में काफी भिन्नता पाई जाती थी। उस समय मुद्रा जारी करने का कार्य इम्पोरियल बैंक करता था जिसके कारण देश की मुद्रा व साख नीति में किसी प्रकार का समन्वय स्थापित करना सम्भव नहीं था। मुद्रा व साख पर इस दोहरे नियन्त्रण को समाप्त करने तथा देश की मुद्रा व साख नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक की आवश्यकता अनुभव की गई। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि देश की मुद्रा व साख पर एक ही केन्द्रीय संस्था का नियन्त्रण हो।

(२) मुद्रा बाजार का सुसंगठित न होना—भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन भी उस समय ठीक नहीं था और उसमें किसी प्रकार की एकरूपता नहीं पाई जाती थी। प्रत्येक बैंक की अपनी प्रथक नीति होती थी और मुद्रा बाजार के विभिन्न सदस्यों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। भारतवर्ष में एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करने के लिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई।

(३) बैंकों के कोषों के केन्द्रीयकरण की आवश्यकता—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सब बैंक अपने अलग-अलग कोष रखते थे और कोषों के इस प्रकार बिखरा होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था में दृढ़ता नहीं आ पाती थी और जनता का विश्वास भी उसमें स्थापित नहीं किया जा सकता था। अतः बैंकों में स्थिरता लाने के लिए, कोषों का केन्द्रीयकरण आवश्यक था। रिजर्व बैंक कोषों के इस केन्द्रीयकरण को सम्भव बना सकता था।

(४) दोषपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था—देश में बैंकिंग नीति को सही प्रकार से चलाने के लिए भी एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता थी। केन्द्रीय बैंक के अभाव के कारण देश में बैंकिंग नीति का उचित संचालन नहीं हो पाता था जिससे फेल होने

वाले बैंको की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना के द्वारा बैंकिंग व्यवस्था के इन दोषों को दूर किया जा सकता था।

(५) केन्द्रीय बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक की अनुपयुक्तता—इम्पीरियल बैंक को, जो पहले से ही देश में केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य कर रहा था, केन्द्रीय बैंक के रूप में अनुपयुक्त समझा गया क्योंकि उसे अन्य बैंकों का विश्वास प्राप्त नहीं था। व्यापारिक बैंक होने के नाते वह अन्य बैंकों के साथ बाजार में प्रतियोगिता करता था जिसके कारण व्यापारिक बैंकों को उसमें विश्वास नहीं था और वे उससे अपने बिलों को भुनाने अथवा ऋण लेने में सकोच करते थे। ऐसी दशा में इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के रूप में सतोषजनक कार्य नहीं कर सकता था। इसके प्रतिरिक्त इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बनाने के लिए उसके व्यापारिक बैंक के कार्यों को समाप्त करना आवश्यक था क्योंकि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं कर सकता है। उस समय इम्पीरियल बैंक सबसे बड़ा बैंक था और उसकी शाखाएँ समस्त देश में फैली हुई थी। इतने बड़े बैंक के व्यापारिक बैंकिंग कार्यों को समाप्त कर देना देश के आर्थिक हित में नहीं था। इम्पीरियल बैंक के संचालक मण्डल ने भी बैंक के व्यापारिक बैंकिंग कार्यों का अन्त किये जाने का विरोध किया। इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक के बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उसे मुद्रा जारी करने तथा उसका नियन्त्रण करने का अधिकार दिया जाय किन्तु इम्पीरियल बैंक के द्वारा इस प्रकार के अधिकार के दुरुपयोग का भय था। इन्हीं सब कारणों से इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय बैंक के बनाये जाने का विरोध किया गया और केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने देश में एक नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया :

रिजर्व बैंक की स्थापना से आशाएँ—

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह आशा की गई थी कि बैंक दर में होने वाले परिवर्तन कम हो जायेंगे और वह घटकर सामान्य स्तर पर आ जायेगी। यह भी आशा की गई थी कि वह बैंकों को दोबारा बिल भुनाने की सुविधाएँ देगा तथा वह बैंकों को उचित परामर्श भी दे सकेगा। रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने से सरकारी अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारियों से, जिनके लिए वे अनुपयुक्त थे, मुक्त किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में सहायता देगा तथा देश में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त वह देश में मुद्रा की कय-शक्ति को स्थिर रखने में सहायता करेगा तथा देश में उचित मौद्रिक नीति का विकास करेगा। रिजर्व बैंक की स्थापना से उपर्युक्त सभी लाभों को प्राप्त करने की आशा की गई थी और वह क्रियात्मक रूप से इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है।

रिजर्व बैंक का विधान (Constitution of Reserve Bank of India)—

सन् १९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के आधीन रिजर्व बैंक एक अशधारियों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया। बैंक की स्थापना के समय उसकी पूंजी ५ करोड़ रुपये निश्चित की गई और उसे १०० रुपये वाले पूर्णतया चुकता अंशों (Fully Paid up Shares) में बाँट दिया गया। २ लाख २० हजार रुपये के मूल्य के अंशों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा खरीद लिया गया तथा शेष अंशों को व्यक्तिगत अशधारियों को बेचने के लिए प्रस्तुत किया गया। रिजर्व बैंक की संचालन शक्ति कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित न होने पाये, इस उद्देश्य से इन अंशों को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा रंगून के क्षेत्रों में बाँट दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक निश्चित मूल्य के अंश ही बेचे गये और इन सब क्षेत्रों में अशधारियों के अलग-अलग रजिस्टर रखे जाते थे। आरम्भ में किसी भी व्यक्ति को पाँच से अधिक अंश नहीं दिये गये किन्तु धीरे-धीरे हस्तांतरण के द्वारा यह अंश कुछ लोगों के पास केन्द्रित होने लगे और १९४० में सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति २०,००० रुपये से अधिक मूल्य के अंश नहीं रख सकेगा। प्रत्येक अशधारी प्रति पाँच अंशों के लिए एक वोट दे सकता था किन्तु किसी भी व्यक्ति को दस से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक अशधारी की मतदान शक्ति को सीमित रखा जाता था।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of the Reserve Bank of India)—

सरकार और बैंक के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न कई बार उठाया गया किन्तु सन् १९६८ तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका और रिजर्व बैंक एक अशधारियों के बैंक के रूप में कार्य करता रहा। सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न को फिर से उठाया गया। भारत सरकार की आर्थिक नीति तथा रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि इस बैंक को सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाय। यह भी अनुभव किया गया कि केन्द्रीय बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था को व्यक्तिगत हाथों में छोड़ना देश के आर्थिक हित में नहीं है। देश में नियोजन का युग आरम्भ होने की सम्भावना के कारण भी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य बहुत से केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था जिसने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के विचार को और भी अधिक पुष्ट कर दिया। इन सब परिस्थितियों में रिजर्व बैंक को पूर्णतया सरकारी बैंक बनाने का निश्चय किया गया।

३ सितम्बर सन् १९६८ को रिजर्व बैंक (लोक स्वामित्व) एक्ट पास कर दिया गया और उसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक के सम्पत्ति अंशों को सरकार को

हस्तान्तरित करने की व्यवस्था की गई। १ जनवरी सन् १९४६ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके सभी अंश सरकार के द्वारा खरीद लिए गये। इस प्रकार रिजर्व बैंक का स्वामित्व तथा प्रबन्ध पूर्णतया भारत सरकार के हाथों में आया और उसने एक सरकारी बैंक के रूप में अपना कार्य आरम्भ किया। रिजर्व बैंक के सभी अंश सन्धार की हस्तान्तरित कर दिये गये जिसके लिए अधधारियों को प्रत्येक १०० रुपये वाले अंश के लिए ११८ रुपये १० आने क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी उसकी पूंजी ५ करोड़ रुपये रखी गई किन्तु उसके सभी अंशों का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार के पास आ गया।

बैंक का प्रबन्ध (Management of the Bank)—

रिजर्व बैंक का प्रबन्ध भारत सरकार के हाथों में है और एक केन्द्रीय संचालक मण्डल के द्वारा उसे चलाया जाता है। केन्द्रीय संचालक बोर्ड (Central Board of Directors) में अब १५ सदस्य होने हैं जिनमें से एक गवर्नर तथा तीन डिप्टी गवर्नर सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिए होती है और इन्हें वेतन दिया जाता है। दस डाइरेक्टर्स (Directors) तथा एक सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के द्वारा मनोनीत (nominate) किये जाते हैं जिनमें से चार डाइरेक्टर्स स्थानीय संचालक बोर्डों में से लिए जाने चाहिए। इन डाइरेक्टर्स की नियुक्ति ४ वर्ष के लिए की जाती है जिनमें से प्रत्येक दो प्रति वर्ष निवृत्त (Retire) होते रहते हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व केन्द्रीय संचालक मण्डल में १६ सदस्य होते थे जिनमें से ८ डाइरेक्टर्स विभिन्न क्षेत्रों के अधधारियों के द्वारा चुन जाते थे।

बैंक का प्रबन्ध चलाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थानीय बोर्ड (Local Board) है जिसमें ५ सदस्य होने हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। इन सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है कि स्थानीय आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति ४ वर्ष के लिए होती है। स्थानीय बोर्डों का काम केन्द्रीय बोर्ड को परामर्श देना तथा केन्द्रीय बोर्ड के द्वारा दिये गये कार्यों को करना है। यह स्थानीय बोर्ड बसकता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में हैं।

बैंक का संगठन (Organisation of the Bank)—

रिजर्व बैंक में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न-भिन्न विभाग स्थापित किये हुए हैं। यह विभाग इस प्रकार हैं—

(१) निर्गम विभाग (Issue Department)—इस विभाग का प्रमुख कार्य नोट जारी करना है। यह विभाग दो उप-विभागों में बंटा हुआ है—(१) कोषाध्यक्ष विभाग—यह उप-विभाग पत्र-मुद्रा को चलाने तथा उसे प्रमुख एवं गौण मुद्राओं में

वदलने का कार्य करता है। (२) साधारण विभाग—यह उप-विभाग नोटों को जाँचने, उन्हें रद्द करने, हिसाब रखने तथा आन्तरिक अन्वेषण (Auditing) का कार्य करता है।

(२) बैंकिंग विभाग (Banking Department)—इस विभाग का कार्य बैंकों के सुरक्षित कोष को अपने पास जमा रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करना है। रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार यह विभाग अनुसूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) की माग-देय (Demand Liabilities) का ५% तथा काल-देय (Time Liabilities) का २% अपने पास जमा रखता है। यह विभाग समाशोधन गृह (Clearance House) का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त मार्गजनिक ऋणों का प्रबन्ध करना, सरकारी रुपये का हस्तांतरण करना, सरकार की आर्थिक सहायता करना तथा बैंकों को परामर्श देने के कार्य भी इसी विभाग के द्वारा किये जाते हैं।

(३) विदेशी विनिमय विभाग (Foreign Exchange Department)—इस विभाग की स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध काल में की गई थी। यह विभाग विनिमय दरों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करने का कार्य करता है। विदेशी विनिमय नियन्त्रण का प्रबन्ध भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है।

(४) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—यह विभाग रिजर्व बैंक के कृषि साख सम्बन्धी कार्यों को करता है। केन्द्रीय व राज्य सरकारों, प्रादेशिक सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं की कृषि साख सम्बन्धी नीति का निर्माण करना तथा कृषि साख की समस्याओं के सम्बन्ध में खोज करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करना इसके प्रमुख कार्य हैं।

(५) बैंकिंग क्रियाओं का विभाग (Department of Banking Operations)—यह विभाग निरीक्षण विभाग, संचालन विभाग तथा निस्तारण विभाग में बँटा हुआ है। निरीक्षण विभाग का कार्य बैंकों का वार्षिक निरीक्षण करना, उनके द्वारा भेजे गये विवरण पत्रों की जाँच करना तथा अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग व्यवस्था के सुधार के लिए सुझाव देना है। संचालन विभाग रिजर्व बैंक के बैंकिंग सम्बन्धी समस्त कार्यों को करता है तथा निस्तारण विभाग बैंकों के बन्द कर देने के सम्बन्धी कार्यों को करता है।

(६) अन्वेषण तथा समंक विभाग (Research and Statistics Department)—इस विभाग का कार्य मुद्रा, वित्त तथा साख सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना, इन विषयों से सम्बन्धित आंकड़ों को इकट्ठा करना तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करना है।

रिजर्व बैंक के कार्य

(Functions of the Reserve Bank of India)

रिजर्व बैंक हमारे देश का केन्द्रीय बैंक है और वह उन सभी कार्यों को करता है जो एक केन्द्रीय बैंक के द्वारा किये जाने चाहिएँ। रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कोष रखना और सामान्यतः देश की मुद्रा व साख प्रणाली को उससे लाभ के लिए चलायाना है। अतः रिजर्व बैंक को देश की मुद्रा व्यवस्था के नियन्त्रण एवं नियमन का कार्य सौंपा गया है। इसी उद्देश्य के लिए इस बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है तथा व्यापारिक बैंकों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यह बैंक सरकार के बैंकर का कार्य करता है तथा आर्थिक और वित्तीय मामलों में सरकार को सलाह देता है। देश का विदेशी विनिमय कोष इसी बैंक के पास रहता है और वह रुपये के विदेशी मूल्य को स्थिर रखने का कार्य भी करता है। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सदस्य होने के कारण उत्पन्न होने वाले बायों का संचालन रिजर्व बैंक ही करता है। देश में नियोजित आर्थिक विकास चारम्भ हो जाने के कारण रिजर्व बैंक का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया है और अब उसे देश में ऐसी बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करनी है जो विक्रमशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कृषि वित्त की व्यवस्था करना आरम्भ से ही उसका कर्तव्य रहा है किन्तु अब उसे औद्योगिक वित्त की सुविधाओं का विस्तार भी करना है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के परम्परागत कार्यों के अनतिरिक्त अब रिजर्व बैंक को विकास सम्बन्धी बहुत से कार्य भी करने हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) नोट जारी करना (Issue of Currency Notes)—रिजर्व बैंक को भारत में पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है और देश में चलने वाले समस्त नोट उन्हीं के द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। रिजर्व बैंक को यह विशेष अधिकार इसलिए दिया गया है जिससे कि वह मुद्रा तथा साख की मात्रा पर प्रभावशाली नियन्त्रण करके देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित कर सके। पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग (Note Issue Department) के द्वारा किया जाता है। नोट निर्गम विभाग एक पृथक् विभाग है और उसके आदेय तथा देनदारी (Assets and Liabilities) बैंकिंग विभाग से बिल्कुल अलग रखी जाती हैं। नोट निर्गम के आदेयों (Assets) में मुख्यतः सोना, सोने के सिक्के, स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ, रुपये के सिक्के तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं।

सन् १९५६ तक रिजर्व बैंक के द्वारा अनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) के अनुसार नोट निर्गम किया जाता था। पत्र-मुद्रा

में जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक को नोटों के पीछे ४०% सुरक्षित कोष रखना होता था जिसमें सोने के सिक्के, सोना तथा स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ रखी जाती थी। इस कोष में हर समय २१ रुपये ३ आने ८ पैसे प्रति तोला के हिसाब से ४० करोड़ रुपये का सोना रखना अनिवार्य था। नोटों के ६०% भाग के पीछे रुपया प्रतिभूतियाँ (Rupee Securities), स्वीकृत व्यापारिक बिल तथा सरकार के प्रतिज्ञा-पत्र रखे जाते थे किन्तु इसमें रुपया प्रतिभूतियाँ ५० करोड़ रुपये अथवा कुल के एक चौथाई से अधिक नहीं हो सकती थी। युद्ध-काल में यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया जिसके कारण पत्र-मुद्रा कोष में रुपया प्रतिभूतियों की सहायता निरन्तर बढ़ती गई।

भारत में नियोजन का युग आरम्भ हो जाने पर आर्थिक विकास के लिए काफी बड़ी मात्रा में पत्र-मुद्रा का विस्तार करना पड़ा जिसके कारण रिजर्व बैंक के लिए नोटों के पीछे पर्याप्त कोष रखना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना काल में विदेशी विनिमय संकट के कारण भारत के विदेशी विनिमय कोष बहुत कम रह गये। यह भी अनुभव किया गया कि मुद्रा कोष में दुर्लभ विदेशी मुद्राओं का रखना अनुपयुक्त है क्योंकि उनका प्रयोग आर्थिक विकास के कामों के लिए किया जा सकता है। अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की नीति की प्रवृत्ति भी इसी दिशा में है और अनुशासित कोष प्रणाली के स्थान पर धीरे-धीरे न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सन् १९५६ में रिजर्व बैंक एक्ट में एक संशोधन के द्वारा अनुपातिक कोष प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना लिया गया। अब रिजर्व बैंक के द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) के अनुसार नोट निर्गम किया जाता है। आरम्भ में न्यूनतम कोष की मात्रा ५१५ करोड़ रुपये निश्चित की गई थी जिसमें ४०० करोड़ रुपये की स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ तथा ६२½ करोड़ रुपये प्रति तोला के हिसाब से ११५ करोड़ रुपये का सोना रखना अनिवार्य था। प्रतिभूतियों की मात्रा को घटाकर ३०० करोड़ रुपये तक भी किया जा सकता था। २५ अक्तूबर सन् १९५७ को एक सरकारी आदेश के द्वारा पत्र-मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले न्यूनतम कोष की मात्रा को घटाकर २०० करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें ८५ करोड़ रुपये की स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) एक्ट सन् १९५७ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपने विदेशी प्रतिभूतियों के कोष को शून्य भी कर सकता है। यह सब कुछ इसलिए किया गया है जिससे कि आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा प्रणाली में अधिक लोच का गुण पैदा किया जा सके तथा विदेशी विनिमय साधनों की आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किया जा सके।

(२) बैंकों के बैंक का कार्य (Banker's Bank)—रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य बैंकों पर नियन्त्रण करना है जिसमें कि वह देश में मुद्रा व साख की मात्रा को घटा-बढ़ा कर आवश्यकतानुसार कर सके। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार प्रत्येक अनुसूचीबद्ध बैंक (Scheduled Bank) को अपनी माग देय (Demand liabilities) का १०% तथा काल देय (Time Liabilities) का २०% रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना होता है। रिजर्व बैंक एक्ट (संशोधन) अधिनियम सन् १९५६ के द्वारा रिजर्व बैंक को बैंकों के द्वारा रखे जाने वाले सुरक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार भी दे दिया गया है। यदि वह चाहे तो अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) से उनकी माग देय (Demand liabilities) का १०% से २०% तक तथा काल देय (Time liabilities) का २०% से ५०% तक जमा के रूप में प्राप्त कर सकता है। बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत असूचीबद्ध बैंकों (Non-scheduled Banks) के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी माग व काल देय (Demand and Time liabilities) का क्रमशः ५ व २ प्रतिशत कम से कम रिजर्व बैंक के पास रखेंगे। इस प्रकार बैंकों के नकद कोषों का केन्द्रीयकरण हो गया है जिससे बैंकों को सुरक्षा तथा तरलता दोनों ही प्राप्त होती हैं।

बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अनुसूचीबद्ध बैंकों (Scheduled Banks) को ऋण देने की सुविधायें देता है। ये बैंक आवश्यकता पड़ने पर प्रथम श्रेणी के बिलों को रिजर्व बैंक से दुबारा मुना सकते हैं अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों की आठ पर ऋण भी ले सकते हैं। रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बिलों को मुनाता है जो भारतवर्ष में लिखे गये हों, जिनका भुगतान भारतवर्ष में होना हो, जिन पर दो या अधिक अच्छे हस्ताक्षर हों, जिनमें से एक अनुसूचीबद्ध बैंक का होना आवश्यक है और जो ६० दिन से अधिक अवधि के लिए न लिखे गये हों। इस सम्बन्ध में अच्छे कृषि बिलों को छूट दी गई है और वे १५ महीने तक की अवधि के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियन्त्रण करता है। बैंक दर को घटा बढ़ाकर तथा प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय एवं अन्य विधियों के द्वारा वह साख निर्माण को नियन्त्रित करता है। रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग कार्य करने के लिए बैंकों को लाइसेन्स देता है, उनकी शाखा विस्तार नीति पर नियन्त्रण करता है और आवश्यकता पड़ने पर कमजोर बैंकों के निस्तारण (Liquidation) का प्रबन्ध भी करता है।

(३) सरकारी बैंकर का कार्य (Banker to the Government)—रिजर्व बैंक सरकार के लिए समस्त बैंकिंग कार्यों को करता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की नकद जमा रिजर्व बैंक के पास जमा रहती है जिस पर वह किसी प्रकार का

ध्याज नहीं देता है। वह विभिन्न सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं को प्राप्त होने वाली धातु को जमा करता है, उनके आदेशानुसार भुगतान निबटाता है और सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करता है। रिजर्व बैंक सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋण भी देता है। यह ऋण या तो मांग किये जाने पर तुरन्त शोध्यनीय होते हैं अथवा काम चलाऊ अग्रिम (Ways and Means Advance) के रूप में होते हैं जिनका भुगतान ६० दिन के भीतर करना अनिवार्य होता है। वह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध करता है तथा नये ऋणों को लेने की व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार के ऋणों का हिमाव-किताब रखना, उन पर ध्याज देना तथा समय आने पर उनका भुगतान करने का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह केन्द्रीय सरकार के लिए ट्रेजरी द्वारा कोषागार विपत्रों (Treasury Bills) को बेचता है। यह विपत्र ६१ दिन की अवधि के होते हैं और कम से कम २५,००० रुपये के बिलों के लिए ही आवेदन पत्र दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक सरकारी धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य भी करता है जिसके लिए उसे स्टेट बैंक की सब शाखाओं तथा सरकारी ट्रेजरीयों पर अपना रूपया रखना होता है। इन सब सेवाओं के बदले में रिजर्व बैंक को कोई पारितोषण नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास सरकार की बहुत बड़ी रकम बिना ध्याज के जमा रहती है। सरकारी बैंक होने के साथ-साथ रिजर्व बैंक सरकार के आर्थिक सलाहकार का कार्य भी करता है और देश की आर्थिक नीति का निर्माण उसके परामर्श से ही किया जाता है।

(४) विदेशी विनिमय दर को नियन्त्रित करना (Regulation of Foreign Exchange Rate)—रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह रुपये के विदेशी मूल्य को स्थिर रखे। इसके लिए वह प्रारम्भ से ही निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पैसे पर स्थिर रखने के लिए निश्चित दरों पर किसी भी सीमा तक स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय किया करता था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) की स्थापना के पश्चात् भारतीय रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के कारण रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित दरों पर स्टर्लिंग के क्रय-विक्रय करने का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है। अब वह विदेशी विनिमय को उन दरों पर बेचता और खरीदता है, जो समय-समय पर सरकार के द्वारा निश्चित की जाती हैं। रिजर्व बैंक केवल स्टर्लिंग के क्रय-विक्रय का कार्य ही नहीं करता है बल्कि यह मुद्रा कोष (I. M. F.) के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय कर सकता है। रिजर्व बैंक २ लाख रुपये से कम मूल्य के विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय नहीं करता है। रुपये और स्टर्लिंग की विनिमय दर के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अनुसूचीबद्ध बैंकों को १ शिलिंग ५½ पैसे

प्रति रुपये की दर से स्टर्लिङ्ग बेचता है तथा १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर उनसे स्टर्लिङ्ग खरीदता है।

रिजर्व बैंक देश में विदेशी विनिमय नियन्त्रण (Foreign Exchange Control) का प्रयत्न भी करता है। भारतवर्ष में विदेशी नियन्त्रण द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत अस्थायी रूप में आरम्भ किया गया था किन्तु युद्धोत्तर काल में भी उसकी आवश्यकता अनुभव की गई और विदेशी विनिमय नियन्त्रण अधिनियम १९४७ के द्वारा उसे स्थाई रूप से अपना लिया गया। फरवरी सन् १९५१ से स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के देशों को भी इस के अन्तर्गत ले आया गया। विनिमय नियन्त्रण की इस व्यवस्था में समस्त विनिमय सम्बन्धी सीदे अधिकृत व्यापारियों के द्वारा किये जाते हैं। अधिकृत व्यापारी वे बैंक होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक से विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय करने का लाइसेंस प्राप्त होता है। उपलब्ध विदेशी मुद्रा का विभिन्न आवश्यकताओं के लिए राशन कर दिया जाता है और केवल आवश्यक भुगतानों की ही स्वीकृति दी जाती है। विदेशी विनिमय की उपलब्ध मात्रा के अनुसार ही परमिट दिये जाते हैं। विदेशी पूँजी का आयात तथा उसका भुगतान रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। मोने तथा चादी का आयात व निर्यात पूर्णतया बहिस्त है।

(५) साख नियन्त्रण (Credit Control)—आरम्भ से ही देश में मुद्रा व साख का नियन्त्रण करना रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व रहा है। वह आवश्यकता-नुसार साख का विस्तार एवं सन्तुलन स्थापित करता है और इस प्रकार देश में मुद्रा व साख की माग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करता है। साख नियन्त्रण किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है क्योंकि उसके द्वारा वह देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करता है। डी० कोक (De Kock) ने केन्द्रीय बैंक के साख नियन्त्रण के कार्य के महत्व को बतलाते हुए लिखा है कि “यह कार्य केन्द्रीय बैंकिंग नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से सम्बन्धित है और यह ऐसा कार्य है जिसके द्वारा अन्य सभी कार्यों में एकत्वता आती है और उन्हें एक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है।”^१ रिजर्व बैंक हमारे देश का केन्द्रीय बैंक होने के कारण साख व्यवस्था के नियन्त्रक का कार्य करता है। वह व्यापारिक बैंकों के द्वारा सृजित साख की मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति रखता है।

साख नियन्त्रण की विभिन्न विधियों के द्वारा रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार रख कर अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व बनाये रखता है। साख का अनावश्यक विस्तार एवं सन्तुलन नहीं किया जाता है। रिजर्व बैंक साख

1 “It is the function which embraces the most important questions of central banking policy and the one through which practically all other functions are united and made to serve a common purpose.”

नियन्त्रण के लिए बैंक दर परिवर्तनो, खुले बाजार की क्रियाओं तथा अन्य वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है। वह अन्य बैंकों के द्वारा अपने पास रखे जाने वाले कोष के अनुपात को घटा बढ़ा कर भी व्यापारिक बैंकों की साख नीति को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त सन् १९४९ के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक किसी बैंक विशेष अथवा सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को विशेष प्रकार के व्यवसायों को अथवा विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने से मना कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों से रिजर्व बैंक के द्वारा साख पर विशिष्ट प्रकार का नियन्त्रण अधिक किया जा रहा है।

(६) अन्य कार्य (Other Function)—उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक कुछ और कार्य भी करता है जो इस प्रकार हैं (i) कृषि साख की व्यवस्था करना—प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक का यह उत्तरदायित्व रहा है कि वह देश में कृषि साख की उचित व्यवस्था करेगा। रिजर्व बैंक का कृषि साख विभाग साख सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करता है और उन्हें सुलभाने के उपाय बतलाता है, बैंकों को कृषि साख नीति के निर्माण में सहायता देता है तथा इन्हें आवश्यक परामर्श देता है। (ii) समाशोधन गृह का कार्य—केन्द्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की समाशोधन (Clearance) की सुविधायें देता है। बैंक के द्वारा ६ बड़े समाशोधन-गृह बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कानपुर तथा बंगलौर में स्थापित किये हुये हैं तथा इनके अतिरिक्त २३ और समाशोधन-गृह हैं। समाशोधन की सुविधायें देकर रिजर्व बैंक बैंकों के बीच रुपये के हस्तांतरण को सम्भव बनाता है। (iii) आंकड़े इकट्ठा करना—रिजर्व बैंक देश में आंकड़े इकट्ठे करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। वह मुद्रा, बैंकिंग, साख तथा वित्त सम्बन्धी आंकड़ों को इकट्ठा करता है तथा उन्हें प्रकाशित करता है। वह बैंकों की मासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मुद्रा और वित्त सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट भी उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इनके अतिरिक्त रिजर्व बैंक विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्टें, खोज-पत्र तथा आंकड़ों को प्रकाशित करता रहता है।

रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य

(Functions which Reserve Bank cannot perform)—

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किये जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियन्त्रण इसलिए लगाया गया है कि वह अन्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता न कर सके तथा स्वयं सुरक्षित रहे। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य इस प्रकार हैं—

(१) सामान्यतः रिजर्व बैंक व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग में भाग नहीं ले सकता है किन्तु अपनी लेन को वसूल करने के लिए वह कुछ निश्चित काल के लिए ऐसा कर सकता है।

(२) वह किसी बैंक अथवा कम्पनी के अंग नहीं खरीद सकता है और ऐसे अंगों की आड़ पर ऋण भी नहीं दे सकता है।

(३) वह अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण नहीं ले सकता है और केवल अपने व्यवसायिक कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।

(४) वह अपने पास जमा की गई राशि पर किसी प्रकार का व्याज नहीं दे सकता है।

(५) वह न तो ऐसे बिल लिख सकता है और न भुना सकता है जो माग पर शोधनीय न हो।

रिजर्व बैंक व्यवहार में (Reserve Bank in Action)

रिजर्व बैंक के कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह देख सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में रिजर्व बैंक ने इन कार्यों को किस प्रकार किया है तथा वह एक केन्द्रीय बैंक के रूप में कहीं तक सफल रहा है। पिछले ३० वर्षों से रिजर्व बैंक हमारे देश में केन्द्रीय बैंक का कार्य कर रहा है। इस बीच में कई बार यह प्रश्न उठाया गया कि क्या वह अपने उद्देश्यों में सफल रहा है अथवा नहीं। रिजर्व बैंक के कार्यों का यह मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा ही उसकी सफलताओं तथा देश के आर्थिक जीवन में उसके महत्व को समझा जा सकता है और उसकी कार्य-प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिये जा सकते हैं।

नोट निर्गमन पर नियन्त्रण (Control of Note Issue)—

रिजर्व बैंक के द्वारा नोट निर्गमन का कार्य पूर्णतया सन्तोषजनक रहा है। उसने कभी भी सोने तथा सोने के सिक्कों की मात्रा को ४० करोड़ २५९ से कम नहीं होने दिया है वस्तुि कभी-कभी तो वह वैधानिक आवश्यकताओं से भी अधिक रही है। इसी प्रकार उसने सन् १९४८-४९ तक पत्र-मुद्रा कोष में हन्या प्रतिभूतियों की मात्रा को कुल धन (Liabilities) का ३ में अधिक नहीं होने दिया। केवल १९४९ में कोष सम्बन्धी नियम में परिवर्तन के पश्चात् ही रिजर्व बैंक के पास रुपया प्रतिभूतियों (Rupee Securities) की मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने नोट निर्गम सम्बन्धी वैधानिक उत्तरदायित्व को भली प्रकार निभाया है। भारतवर्ष में नोट निर्गम सम्बन्धी एक बड़ा दोष यह रहा है कि मुद्रा बाल तथा उसके उपरान्त चलन में नोटों की मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। सन् १९३८-३९ में २११ करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १९४५-४६ में नोटों की मात्रा १३३९ करोड़ २५९ हो गई थी। किन्तु पत्र-मुद्रा के अत्यधिक विस्तार का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक के ऊपर नहीं धाला जा सकता है क्योंकि यह वृद्धि बहुत कुछ ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण हुई। मुद्रा बाल में ब्रिटिश सरकार ने रिजर्व

बैंक एक्ट की उस धारा से लाभ उठाया जिसके अन्तर्गत वह स्टैलिङ्ग के बदले में किसी भी सीमा तक रुपया प्राप्त कर सकती थी और रिजर्व बैंक को स्टैलिङ्ग प्रतिभूतियों की आड़ पर नोट निर्गम का अधिकार दे दिया गया। इस व्यवस्था के कारण ही देश में मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हुआ। रिजर्व बैंक का इतना दोष अवश्य था कि उसने यथा समय जनता को ब्रिटिश सरकार की इस नीति से सूचित नहीं किया।

मुद्रा की माग और पूर्ति में मौसमी परिवर्तन (Seasonal Variation) होना भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्रवृत्त से अप्रैल तक, फल बाजार में आ जाने के कारण, मुद्रा की माग काफी बढ़ जाती है और उसे पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि की जाती है। इसके विपरीत मई से सितम्बर तक मुद्रा की माग कम होती है और उसकी पूर्ति को कम करना आवश्यक हो जाता है। रिजर्व बैंक मुद्रा की माग में सामयिक परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति को घटा-बढ़ा कर संतुलन स्थापित करता है। मौद्रिक प्रबन्ध के इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक को पर्याप्त सफलता मिली है और अब मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी (Seasonal Monetary Stringency) की दशाएँ बहुत कम उत्पन्न होनी हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा व्यवस्था के नियन्त्रक के रूप में काफी सफलता मिली है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि रिजर्व बैंक का नियन्त्रण होते हुए भी देश में मुद्रा का अत्यधिक विस्तार किया गया है जिसके कारण मुद्रा प्रसार की दशाएँ उत्पन्न हो गई हैं किन्तु इसके लिए सरकार की वित्तीय नीति (Fiscal policy) उत्तरदायी है रिजर्व बैंक नहीं।

रिजर्व बैंक और साख नियन्त्रण

(Reserve Bank and Credit Control) —

रिजर्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को साख नियन्त्रण के लिए विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। उसे साख नियन्त्रण के लगभग वे सभी अस्त्र प्राप्त हैं जो किसी भी केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध होते हैं। रिजर्व बैंक की साख नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसे बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशेष अधिकार भी दिये गये हैं जिनकी सहायता से वह व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं का प्रत्यक्ष नियमन कर सकता है। भारतवर्ष में रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के लिए, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएँ, बैंकों के नकद कोष में परिवर्तन, विशिष्ट साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) तथा नैतिक प्रभाव का प्रयोग करता है जिसमें से पहली तीन विधियों से साख की मात्रा को नियन्त्रित (Quantitative Control) किया जाता है तथा बाद की दो विधियों के द्वारा साख के प्रयोग को नियन्त्रित (Qualitative Control) किया जाता है।

(१) बैंक दर परिवर्तन (Bank Rate Changes) केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण नीति में बैंक दर परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उसके द्वारा

यह वाजारी व्याज भी दर को प्रभावित करके बैंको की साख निर्माण करने की शक्ति में परिवर्तन कर सकती है। भारत में आरम्भ से ही बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। सन् १९३१ तक रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियन्त्रण के लिए बैंक दर का कोई विशेष प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उसे १९३५ से लेकर १९५० तक शुभम मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) के कारण बैंक को ३% पर बनाये रखनी पड़ी। सन् १९५१ में साख मुद्रा प्रसार के कारण रिजर्व बैंक के सम्मुख एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई और माघ नियन्त्रण से नवम्बर सन् १९५१ में बैंक दर को ३% से बढ़ा कर ३½% कर दिया गया। बैंक दर को प्रभावशाली बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंको को वित्तीय सहायता देने की नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। बैंक दर को बढ़ाते ही रिजर्व बैंक ने यह घोषणा कर दी कि वह बैंको की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण-पत्र नहीं खरीदेगा। किन्तु इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर वर्तमान बैंक दर पर ऋण देता रहेगा। बैंक दर के बढ़ने का नुरन्त परिणाम यह हुआ कि बैंको के द्वारा शिष्टे जाने वाले ऋणों की मात्रा कम हो गई और साख का सङ्कुचन होने लगा। २६ मई १९५७ को बैंक दर में फिर वृद्धि की गई और वह ३½% से बढ़ा कर ४% कर दी गई। इस प्रकार हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से ही बैंक दर का प्रयोग साख नियन्त्रण के लिए किया गया है। २ जनवरी सन् १९६३ में बैंक दर को ४% से बढ़ा कर ४½% प्रतिशत कर दिया गया। बैंक दर में वृद्धि करके रिजर्व बैंक ने शुभम मुद्रा नीति को कार्यक्रम में लाना चाहा जिससे कि योजनाकालीन मुद्रा-प्रसार को नियन्त्रण में रक्खा जा सके। बैंक दर में वृद्धि होने से यद्यपि साख के विस्तार में कुछ कमी हुई किन्तु अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा प्रसार की शक्तियों का दबाव निरन्तर बढ़ता गया। २५ मितम्बर सन् १९६४ को रिजर्व बैंक ने बैंक दर को ४½% से बढ़ा कर ५% पर निश्चित कर दिया। बैंक दर की इस वृद्धि का उद्देश्य देश में तीव्र गति से बढ़ते मुद्रा प्रसार को रोकना था किन्तु रिजर्व बैंक को इस दिशा में कोई विशेष सफलता न मिल सकी। कीमत स्तर निरन्तर बढ़ता गया और भयंकर रूप धारण करने लगा। रिजर्व बैंक ने मास की मात्रा पर और अधिक कड़ा नियन्त्रण करने का निश्चय किया और १७ फरवरी सन् १९६४ में बैंक दर को बढ़ा कर ६% पर निश्चित कर दिया गया। चार महीनों में बैंक दर का दो बार बढ़ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रिजर्व बैंक वर्तमान कीमत स्थिति से अत्यन्त चिन्तित है और वह उसे साख नियन्त्रण के द्वारा ठीक करने का प्रयास कर रहा है। बैंक दर में वृद्धि के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने बैंको में रखी जाने वाली मुद्रा की दर को उनकी तरलता स्थिति के साथ सम्बन्धित किया है। जिन बैंको का तरलता अनुपात (Liquidity Ratio) ३०% या इस से अधिक होगा वे रिजर्व बैंक में ऋण ६% अर्थात् बैंक दर पर ले सकेंगे किन्तु जिनका तरलता अनुपात (Liquidity Ratio) इससे कम होगा उन्हें प्रत्येक एक प्रतिशत की कमी के लिए ३% अधिक व्याज देना होगा।

(२) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियन्त्रण के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग भी किया गया है और वह समय-समय पर प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के द्वारा व्यापारिक बैंकों के नफ़ेद कोषों को प्रभावित करता रहता है। भारतवर्ष में खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता सीमित ही रही है क्योंकि (१) भारतीय मुद्रा बाजार अल्प-विकसित है तथा (२) रिजर्व बैंक केवल कुछ ही प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकता है। इन सीमाओं के होते हुये भी खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा बैंक दर को प्रभावशाली करने में बड़ी सहायता मिली है। सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने बैंक दर की वृद्धि को प्रभावशाली करने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को खरीदने के सम्बन्धी नीति में भी परिवर्तन किया था। इससे पूर्व सदस्य बैंक आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच कर किसी भी सीमा तक धन प्राप्त कर लेते थे। किन्तु १९५१ के पश्चात् इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और रिजर्व बैंक ने यह घोषणा कर दी कि वह बैंकों की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनसे प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदेगा। अब इन प्रतिभूतियों की आड़ पर वे वर्तमान बैंक दर पर रिजर्व बैंक में ऋण प्राप्त कर सकेंगे। रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियाँ खरीदने की नीति में इस प्रकार का परिवर्तन कर देने से बैंक दर को प्रभावशाली करने में काफी सफलता मिली है। सन् १९५२ में विल बाजार योजना के आरम्भ हो जाने से रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। नवम्बर सन् १९५६ से रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में रुपये की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कुछ विदेश प्रतिभूतियों को खरीदना आरम्भ कर दिया था किन्तु सन् १९५७ में फिर रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की नीति में कुछ परिवर्तन आया और प्रतिभूतियों के बेचने को अधिक महत्व दिया जाने लगा। प्रतिभूतियाँ बेचकर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के बढ़ते हुये कोषों को कम करने का प्रयत्न करता है। आजकल रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ काफी बढ़ गई हैं। इनके द्वारा वह बैंकों के कोषों को प्रभावित करके प्रतिभूति बाजार तथा बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता स्थापित करता है।

(३) नक़द कोषों में परिवर्तन (Variable Reserve Requirements)—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) को अपनी मांग देय (Demand Liabilities) का ५% तथा काल देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक के पास नक़द जमा के रूप में रखना होता है। बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत असूचित बैंकों (Non-Scheduled Banks) के लिए भी इसी अनुपात में रिजर्व बैंक के पास नक़द कोष रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यद्यपि रिजर्व बैंक को अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति सदस्य बैंकों के नक़द कोषों के अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु काफी समय तक उसके द्वारा साख नियन्त्रण के लिए इस अधिकार

का प्रयोग नहीं किया गया। बैंको के पास अधिक मात्रा में नकदी रहने के कारण इस व्यवस्था का प्रयोग साख नियन्त्रण के लिए नहीं किया जा सका। इस दोष को दूर करने के लिए सन् १९५६ के रिजर्व बैंक (संसोधित) अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को मदस्त्य बैंको के नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया है। अब वह बैंको से उनकी मांग देय (Demand Liabilities) का ५% से २०% तक तथा बाल देय (Time Liabilities) का २% से ८% तक जमा के रूप में प्राप्त कर सकता है। सन् १९६२ के संसोधित अधिनियम के अन्तर्गत बैंको के द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले नकद कोष के अनुपात को उनकी कुल जमा का ३% निश्चित कर दिया गया है जिसे रिजर्व बैंक १५% तक बढ़ा सकता है।

नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक साख के नकदी के आधार को बदला जा सकता है और बैंको के द्वारा निर्मित साख की मात्रा में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। मार्च १९६० में रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम इस अधिकार का प्रयोग साख नियन्त्रण के उद्देश्य से किया और बैंको के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे ११ मार्च सन् १९६० के पश्चात् अपनी कुल देनदारी (Total Liabilities) में होने वाली वृद्धि का २५% अनिश्चित जमा के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखेंगे। ६ मई, सन् १९६० में अनिश्चित जमा की यह रकम २५% से बढ़ा कर ५०% कर दी गई है। नवम्बर सन् १९६० में रिजर्व बैंक ने अपनी साख नियन्त्रण की नीति में कठोरता कम की और अनिश्चित निक्षेपों पर रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित कोष की जमा का अनुपात ५०% से घटा कर २५% कर दिया गया। जनवरी सन् १९६१ में इस नियन्त्रण को समाप्त कर दिया गया।

साख के प्रयोग पर नियन्त्रण (Selective Credit Control)—

हमारे देश में आर्थिक विकास पर बहुत बड़ी मात्रा में व्यय किया जा रहा है जिसके कारण चलन में मुद्रा की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है। योजना काल में बैंको ने द्वारा निर्मित साख की मात्रा भी तेजी के साथ बढ़ी है। मुद्रा व साख की यह समस्त वृद्धि केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं हुई है बल्कि देश में साख की बहुत बड़ी मात्रा का प्रयोग मट्टेबाजी तथा वस्तु सग्रह के लिए भी किया जा रहा है। इस दोष को दूर करने तथा निर्मित साख का उचित दिशाओं में प्रयोग किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक के द्वारा साख के प्रयोग पर भी नियन्त्रण किया जाये। एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साख पर विशिष्ट नियन्त्रण (Selective Control) इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उसके द्वारा ही आवश्यक दिशाओं में साख के विस्तार को रोके बिना देश में मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को नियन्त्रण में रखा जा सकता है।

बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम पास होने से पूर्व रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के ए बैंक दर नीति तथा हुले बाजार की क्रियाओं जैसी परम्परागत विधियों का ही योग करता था जिनसे वह केवल साख की मात्रा को नियन्त्रित कर सकता था और साख के प्रयोग पर उसका किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता था। सन् १९४६ बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में रिजर्व बैंक को साख पर विशिष्ट रूप से नियन्त्रण (Selective Credit Control) करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गये हैं उनकी सहायता के वह अब साख के प्रयोग पर नियन्त्रण करने लगा है। इस एक्ट अन्तर्गत रिजर्व बैंक को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार इस प्रकार हैं—

- i) वह देश हित में समस्त बैंकों अथवा किसी एक बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति निर्धारित कर सकता है। वह बैंकों को इस सम्बन्ध में आदेश दे सकता है कि किन उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम दिये जायें और किन उद्देश्यों के लिए नहीं, ऋणों के पीछे जितनी आवश्यक सीमा (Margin Requirement) रखी जाय तथा ऋण की क्या दरें ली जायें। बैंकिंग कम्पनियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। (ii) रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक को लिखित आदेश के द्वारा ऐसे ऋण देने से मना कर सकता है जो जमाधारियों के हितों के विरुद्ध हो। वह उन्हें निश्चित अवधि के भीतर इस प्रकार के ऋणों को वापस मांगने के लिए भी बाध्य कर सकता है। (iii) वह बैंकिंग कम्पनियों को किसी विशेष प्रकार के सीदे न करने की चेतावनी दे सकता है अथवा उन्हें ऐसा करने से रोक सकता था। (iv) वह किसी भी बैंक को किसी भी मामले पर सलाह दे सकता है तथा वह बैंकों का निरीक्षण करके उन्हें अपनी निरीक्षण रिपोर्ट भेज सकता है। (v) वह किसी एक बैंक अथवा समस्त बैंकों को ऐसे आदेश दे सकता है जो राष्ट्रीय हित में हो अथवा जो जमाधारियों (Depositors) या बैंकिंग कम्पनियों के हितों के विरुद्ध किये जाने वाले व्यवसाय को रोकने के लिए आवश्यक हो अथवा जिनके द्वारा बैंकों का उचित प्रबन्ध किया जा सके। इस प्रकार के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो जाने पर रिजर्व बैंक ने साख के प्रयोग पर नियन्त्रण करना प्रारम्भ कर दिया है।

इन सम्बन्ध में सबसे पहला आदेश १७ मई सन् १९५६ को जारी किया गया जिसके अन्तर्गत धन व चावल की आड़ पर दिये जाने वाले ऋणों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया गया। बैंकों से यह अनुमति दी गयी कि वे इन ऋणों को आड़ पर दिये जाने वाले ऋणों को कम करें तथा उनके सम्बन्ध में आवश्यक सीमा (Margin Requirement) को १०% बढ़ा दें। सितम्बर सन् १९५६ में अनाजों, दालों तथा वपड़े की आड़ पर दिये जाने वाले अग्रिमों को भी नियन्त्रित कर दिया गया। अप्रैल सन् १९५६ में अनुमोदीबद्ध बैंकों को यह आदेश दिया गया कि वे कम्पनियों के अंशों (Shares) की आड़ पर ऐसे व्यक्तियों को ऋण न दें जो उद्योग-धंधों पर संचालन अधिकार प्राप्त करना चाहते हों। धान व चावल की आड़ पर

दिये जाने वाले ऋणों पर नियन्त्रण नवम्बर १९५६ में हटा लिया गया किन्तु फरवरी १९५७ में फिर लगा दिया गया। इसके अनिश्चित अनाज पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर कुछ और प्रतिबन्ध लगा दिये गये। सन् १९५६ में तेल के बीजों पर भी विशिष्ट साख नियन्त्रण लागू कर दिया गया। मार्च १९६० में कम्पनियों के अग्रेषों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को नियन्त्रित कर दिया गया।

सन् १९६१ में विशिष्ट साख नियन्त्रण के अधिकारों का प्रयोग विस्तृत रूप से किया गया। वस्तुओं की पूर्ति तथा बीमत् स्थिति में सुधार हो जाने के कारण धान, चावल, मू गफली तथा कम्पनियों के अग्रेषों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर नियन्त्रण कम कर दिया गया तथा चीनी, गेहूँ व जूट पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर नियन्त्रण बिल्कुल हटा लिया गया। २७ अप्रैल १९६३ को चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों को फिर नियन्त्रित कर दिया गया और उन पर कम से कम ४५ प्रतिशत आवश्यक सीमा (Margin Requirement) निर्दिष्ट कर दी गई। फरवरी १९६४ में मू गफली पर दिये जाने वाले अग्रिमों की आवश्यक सीमा ४५% प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दी गई। २१ अप्रैल १९६४ को एक आदेश के द्वारा गेहूँ पर दिये जाने वाले अग्रिमों की आवश्यक सीमा ३५ प्रतिशत निर्दिष्ट की गई। १९६४ के मध्य में धान और चावल पर साख नियन्त्रण कठोर कर दिया गया जिससे की उनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।

विशिष्ट साख नियन्त्रण की विधियों का मुख्य गुण उनका सोचदार होना है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर हटाया जा सकता है, तथा परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में काफी सतर्क रहा है, जैसे ही किसी नियन्त्रण को अनावश्यक अनुभव किया गया वैसे ही उसे हटा लिया गया। हमारे देश में विशिष्ट साख नियन्त्रण की मुख्य कठिनाई असरूप छोटे छोटे बैंकों की साख नीति को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होनी है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने अपने आदेशों की मुख्यतः अनुसूचीबद्ध बैंकों तक ही सीमित रखता है और अनुसूचीबद्ध बैंकों की क्रियाओं को बहू नियन्त्रित नहीं कर सका है। इन सीमाओं के होते हुये भी विशिष्ट साख नियन्त्रण हमारे देश की साख नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

(५) नैतिक प्रभाव (Moral Suasion)—उपयुक्त विधियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक ने साख नियन्त्रण के लिए अपने नैतिक प्रभाव का भी समय-समय पर प्रयोग किया है। सितम्बर १९४६ में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् रिजर्व बैंक के गवर्नर ने प्रमुख बैंकों की एक मीटिंग बुलाई और बैंकों से अनुरोध किया कि वे सट्टे के कामों के लिए ऋण न दें। जून १९५७ में व्यापारिक बैंकों से एक पत्र में यह अनुरोध किया गया कि वे औद्योगिक वित्त की मात्रा को कम किये बिना कृपि वस्तुओं पर दिये जाने वाले अग्रिमों की मात्रा को कम कर दें। इसके एक मास

पश्चात् ही रिजर्व बैंक के गवर्नर ने प्रमुख बैंकों की एक कॉन्फ्रेंस में अग्रिमों की मात्रा को ६३७ करोड़ रुपये से घटा कर ८०० करोड़ रुपये पर ताने की आवश्यकता पर जोर दिया । इस उद्देश्य की अधिकांश ह्रास से प्राप्त कर लिया गया । फरवरी १९५६ में एक पत्र के द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे फसल के अवसर पर अपने अग्रिमों को कम करने का प्रयत्न करें । रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली इस सलाह का व्यापारिक बैंकों की साख नीति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और अधिकांश रूप से उसमें इच्छित परिवर्तन कराने में उसे पर्याप्त सफलता मिली है ।

रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण नीति के कम प्रभावशाली होने के कारण—

रिजर्व बैंक ने देश में मुद्रा व साख की मात्रा को नियन्त्रित करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किये हैं किन्तु उनकी साख नियन्त्रण नीति अधिक प्रभावशाली नहीं रही है । भारतवर्ष में साख नियन्त्रण के कम प्रभावशाली होने के कारण इस प्रकार हैं— (i) भारतीय मुद्रा बाजार का सुसंगठित न होना—हमारे देश में मुद्रा बाजार का संगठन दोषपूर्ण होने के कारण उनके विभिन्न अंगों में सम्पर्क तथा सहयोग का अभाव रहना है । मुद्रा बाजार में व्याज की दरों में भिन्नता पाई जाती है तथा बाजारी दरे बैंक दर के साथ-साथ नहीं बदलती हैं । इन दोषों के कारण रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकी है । (ii) बिल बाजार का अभाव—भारतवर्ष में अभी तक भी एक सुव्यवस्थित बिल बाजार का विकास नहीं हो सका है । बिल बाजार के अभाव के कारण भी रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति कम प्रभावशाली रही है तथा खुले बाजार की क्रियाओं का क्षेत्र सीमित हो गया है । (iii) देगी बैंकर्स पर नियन्त्रण का न होना—बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी रिजर्व बैंक देगी बैंकों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं कर सका है जिसके कारण वे आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से अलग रहने हैं । मुद्रा बाजार के इस महत्वपूर्ण अंग पर रिजर्व बैंक का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण न होने के कारण भी उसकी मुद्रा तथा साख नीति अधिक सफल नहीं हो सकी है । (iv) बैंकों के पास नकद कोषों की अधिकता—भारतवर्ष में बैंकों के पास नकद कोष अधिक मात्रा में रहते हैं जिसके कारण रिजर्व बैंक पर उनकी निर्भरता बहुत कम हो गई है और वे अपने नकद कोषों के आधार पर ही काफी अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर लेते हैं । ऐसी दशा में रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति अधिक सफल नहीं हो सकती है । (v) अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव—बैंक दर नीति के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था इतनी लोचदार हो कि बैंक दर परिवर्तन के साथ-साथ मूल्यों, मजदूरी तथा व्याज की दरों आदि में भी परिवर्तन किया जा सके । भारतवर्ष में मूल्यों तथा मजदूरी की दरों पर अनेक नियन्त्रण होने के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव रहा है जिसके कारण मुद्रा व साख का नियन्त्रण अधिक प्रभावशाली नहीं हो सका है ।

रिजर्व बैंक तथा कृषि साख (Reserve Bank and Agricultural Credit) -

आरम्भ से ही रिजर्व बैंक को कृषि साख का उचित प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व दिया गया है और अपने कृषि साख विभाग के द्वारा वह कृषि वित्त समस्याओं का अध्ययन करने, उनमें अन्वेषण करने, आँकड़े इकट्ठा करने तथा कृषि वित्त व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने का महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है। किन्तु सन् १९४७ से पूर्व वह देश में कृषि वित्त की उचित व्यवस्था करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं कर सका और कृषि व्यवस्था को उसके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता मामूली होती थी किन्तु पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं जिनके कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंकिंग सिद्धान्तों की भीमाओं के भीतर ही कृषि व्यवसाय के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कर सकता है। रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार वह किसानों को सीधी वित्तीय सहायता नहीं दे सकता है। वह सरकारी आन्दोलन को राज्य सहकारी बैंको व द्वारा आर्थिक सहायता देता है। वह इन बैंकों की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण नहीं देता है बल्कि केवल उनकी सामयिक तथा आपत्तिवाली आवश्यकताओं को ही पूरा करता है। रिजर्व बैंक केवल उन राज्य सहकारी बैंकों को ही ऋण देता है जो स्वीकृत प्रणाली के आधार पर चलाये जा रहे हों। ऐसी बैंकों को अपनी कुल देय (Liabilities) का ४० प्रतिशत नकदी, बैंको में भ्रयवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। रिजर्व बैंक कृषि वित्त सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधायें देता है -

(i) रिजर्व बैंक महकारी समितियों द्वारा लिखे गये तथा राज्य सहकारी बैंक व सदस्य बैंको द्वारा बेचान किये गये बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की खरीद सकता है भ्रयवा उन्हें फिर से भुना सकता है। इन बिलों की भ्रयधि १५ महीने से कम होनी चाहिए तथा ये भीसभी कृषि कार्यों अथवा उपज की बिक्री के लिए भारत में लिखे गये हों; इन बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर दो अच्छे हस्ताक्षर होने चाहिए जिनमें से एक अनुसूचितवर्द्ध बैंक का होना आवश्यक है।

(ii) रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंको अथवा भूमि वन्धक बैंको को स्वीकृत प्रतिभूतियों (Approved Securities) तथा उनके ऋण-पत्रों (Debentures) की आठ पर ६० दिन के लिए ऋण दे सकता है।

(iii) वह कभी-कभी भूमिवन्धक बैंको के ऋण-पत्रों को खरीद कर भी उनकी आर्थिक सहायता कर सकता है।

(iv) वह सहकारी सस्थाओं की राज्य सहकारी बैंको के द्वारा कृषि कार्यों की भ्रय पूर्ति व कृषि उपज की बिक्री के लिए अरक्षित ऋण भी दे सकता है।

(v) अब वह लाइसेन्स प्राप्त गोदामों में रखी गई कृषि वस्तुओं के बदले प्राप्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की आठ पर भी ऋण दे सकता है।

(vi) रिजर्व बैंक मौसमी कृषि कार्यों तथा कृषि उपज की बिक्री के लिए एक दर से २ प्रतिशत कन वगैरह की दर पर वार्षिक सहायता देता है।

(vii) रिजर्व बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था भी करता है। सन् १९५० से वह भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों (Debentures) को २०% तक खरीद सकता है।

सन् १९५५ में ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली कृषि वित्त सहायता में वृद्धि करने के लिए उसके अधीन दो नए कोषों का निर्माण किया गया है (१) राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long Term) Operations Fund] इस कोष का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जायेगा—(i) राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के प्रथम खरीदने के लिए ऋण देना। (ii) राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देना तथा (iii) भूमि बन्धक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम देना। (२) राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थायीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] इस कोष का प्रयोग केवल मध्यकालीन ऋणों और अग्रिमों को देने के लिए किया जायेगा। यह ऋण राज्य सहकारी बैंकों को मिल सकेंगे तथा वे १५ महीने से कम अवधि ५ साल से अधिक अवधि के लिए नहीं होंगे। इन कोषों की स्थापना हो जाने से रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली कृषि वित्त सहायता में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है।

रिजर्व बैंक और औद्योगिक वित्त

(Reserve Bank and Industrial Finance) —

रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक वित्त की व्यवस्था नहीं कर सकता है किन्तु उसने उद्योगों को ऋण देने वाली विशेष संस्थाओं की स्थापना में क्रियात्मक रूप से भाग लिया है। भारत में तेजी के साथ औद्योगिक विकास करने तथा औद्योगिक पूँजी की कमी को दूर करने के लिए उसने ऐसी संस्थाओं की स्थापना तथा विस्तार करने की नीति को अपनाया है जो उद्योगों की मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा कर सकें। रिजर्व बैंक ने भारत की औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) तथा बहुतन्त्री राज्य निगमों (State Finance Corporations) तथा रीफाईनेन्स कारपोरेशन फॉर इण्डस्ट्री (Refinance Corporation for Industry) की पूँजी में भाग लिया है तथा उन्हें ऋण देने की सुविधायें दी हैं। इसके अतिरिक्त वह उनके संगठन तथा संचालन में भी विशेष प्रकार की सहायता देता है।

भारत की औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) की ५ करोड़ रुपये की पूँजी में से १ करोड़ रुपये की पूँजी रिजर्व बैंक

के द्वारा लगाई गई है। इसने प्रतिरिक्त उसने इस निगम के द्वारा जारी किये गये २ करोड़ रुपये के बाण्डस (Bonds) भी खरीदे हैं। निगम की वित्तीय स्थिति को दृढ़ करने के लिए वह अपने अगो पर लाभार्थ न लेने के लिए राजी हो गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में सन् १९५३ के मशवरे के अनुसार रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त निगम को ऋण तथा अग्रिम भी दे सकता है और उसने इस निगम को अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण दिये हैं। निगम के संचालक मण्डल पर रिजर्व बैंक के दो प्रतिनिधि होने हैं। बैंक विन निगम को नीति सम्बन्धी विषयों पर परामर्श भी देता है। बैंक न बहूत-ही राज्य वित्त निगमों की अगुआई में भी भाग लिया है। वह प्रायः इन निगमों की परिवर्तन पूँजी का १० से २० प्रतिशत भाग स्वयं देता है। इन निगमों को बैंक अल्पकालीन ऋण भी देता है। वह इन निगमों के हस्ताक्षर वाले बिलों को निश्चिन्त बनानों पर खरीदने, बेचने, दुबारा भुगतान का काम भी करता है। इसके प्रतिरिक्त वह इन्हें अन्य बैंकिंग सुविधायें देता है तथा केन्द्रीय व राज्य निगमों को संगठन एवं संचालन सम्बन्धी परामर्श भी देता है। इन निगमों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य रिजर्व बैंक करता है तथा उनका वार्षिक निरीक्षण भी करता है।

रिफाईनेन्स कारपोरेशन फॉर इण्डस्ट्री की १२.५ करोड़ रुपये की पूँजी में से ५ करोड़ रुपये की पूँजी रिजर्व बैंक के द्वारा लगाई गई है। बैंक ने इस निगम की स्थापना में क्रियात्मक रूप से भाग लिया है और रिजर्व बैंक के गवर्नर ही इस निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष हैं। इसके प्रतिरिक्त रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को बैंक ऋणों की व्यवस्था करने के लिए एक गारन्टी योजना बनाई है जिसे सन् १९६० से कार्यान्वित किया गया है।

बैंकों के द्वारा औद्योगिक वित्त की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में भी रिजर्व बैंक ने कुछ प्रारम्भिक कार्य किया है। आफ समिति ने बैंकों के द्वारा दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन औद्योगिक वित्त में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए जाने का सुझाव दिया था। सन् १९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ प्रतिनिधि भारत आये और उन्होंने भी इसी प्रकार की सिफारिश की। रिफाईनेन्स कारपोरेशन फॉर इण्डस्ट्री की स्थापना हो जाने से यह सुविधा काफी सीमा तक मिलने लगी है। किन्तु भारतीय बैंकों को दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में भी भाग लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ने १९६१ में इस विषय की जाँच करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप (Working Group) स्थापित किया जिसने उन बातों को निश्चित किया है जिन्हें बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने समय ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने में भी काफी कार्य किया है।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ

(Achievements of the Reserve Bank)—

उपयुक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यों को पर्याप्त सफलता के साथ किया है और वह देश में एक उचित मोटिव तथा साख नीति का निर्माण कर सका है। जो आशाएँ रिजर्व बैंक से लगाई गई थी उन्हें उसने काफी सीमा तक पूरा किया है। यद्यपि उसकी कार्य-प्रणाली में कुछ दोष अवश्य रहे हैं किन्तु फिर भी वह केन्द्रीय बैंक के रूप में काफी सफल रहा है। रिजर्व बैंक की मुख्य-मुख्य सफलताएँ इस प्रकार हैं—

(१) वह देश में बैंक दर को कम करने में सफल हो सका है—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व बैंक दर ७% और ६% के बीच में रहती थी किन्तु उसने उसे कम करके ३% कर दिया। सन् १९५१ में मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ा कर ३½% कर दिया गया और सन् १९५७ में उसे ४% निश्चित किया गया। इसके पश्चात् भी बैंक दर में वृद्धि होती रही है और इस समय बैंक दर ६% हो गई है। यद्यपि मुलभ मुद्रा नीति विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक है किन्तु उसके साथ-साथ ही कीमत-स्तर में स्थिरता रहना भी आवश्यक है इसीलिए रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक दर को बढ़ा कर कीमत-स्तर पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया है। काफी लम्बे समय तक मुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) को अपनाये गये के पश्चात्, पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक को दुर्लभ मुद्रा नीति (Dear Money Policy) को अपनाना पड़ा है। किन्तु बैंक दर की इस वृद्धि को स्थाई नहीं कहा जा सकता है। ऐसा केवल मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए किया गया है।

(२) व्याज की दरों में सामयिक परिवर्तन कम हो गये हैं—यद्यपि इस प्रकार के परिवर्तनों का पूर्णतया अन्त तो नहीं हुआ है किन्तु रिजर्व बैंक ने विभिन्न मौसमों में साख की मात्रा का आवश्यकता के अनुसार विस्तार तथा सवुचन करने की नीति के द्वारा व्याज की दरों में सामयिक परिवर्तनों को काफी कम कर दिया है। अब व्याज की दरों में पहले की अपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है।

(३) रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सस्ती सुविधाएँ प्रदान की हैं—रिजर्व बैंक देश में बहुत कम व्यय पर रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य करता है। इस प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग सरकार, अनुसूचीबद्ध बैंकों तथा सहकारी समितियों के द्वारा काफी किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वारा विप्रेष सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरें बहुत कम हैं। वह ५००० रुपये तक की रकम भेजने के लिए द्वादश प्रतिशत (न्यूनतम १ रुपये) और ५००० से अधिक के लिए द्वादश प्रतिशत (न्यूनतम १ रुपये ५६ पैसे) के हिमाय से लेता है।

(४) रिजर्व बैंक को सार्वजनिक ऋणों के प्रबन्ध में काफी सफलता मिली है—वह समय-समय पर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋणों के लेने तथा उनके भुगतान के कार्य को सफलतापूर्वक करता रहा है। आर्थिक विकास के लिए भी उसने सार्वजनिक ऋणों को लेने तथा उनका प्रबन्ध करने में बड़ी सहायता की है।

(५) बैंक रुपये की विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस पर स्थिर रखने में सफल रहा है—स्टिज्ज का निश्चिन दरो पर क्रय-विक्रय करके तथा विदेशी विनिमय के द्वारा वह रुपये की विदेशी विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस पर स्थिर रख सका है।

(६) बैंकों के बैंक के रूप में भी उसे काफी सफलता मिली है—रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित हो गई है। वह विभिन्न प्रकार के बैंकों पर पर्याप्त नियन्त्रण कर सका है तथा उनकी नीति को देश के आर्थिक हित में चलाने में सफल रहा है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् फेन होने वाले बैंकों की संख्या बहुत कम हो गई है।

(७) साख नियन्त्रण में पर्याप्त सफलता मिली है—रिजर्व बैंक विभिन्न विधियों के द्वारा देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियन्त्रित कर सका है और मुद्रा-प्रसार की दक्तियों के प्रभाव को कम करने में उसे सफलता मिली है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उसे मुद्रा व साख का नियन्त्रण करने में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है, जिसके कारण मुद्रा-प्रसार की गतियाँ तीव्र हो गई हैं किन्तु फिर भी वह प्रयत्नशील है कि आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी वह मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण रख सके।

(८) औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने में रिजर्व बैंक ने काफी सहायता की है—औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) को स्थापित करने में उसने बड़ी सहायता की है और इस प्रकार देश में दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की सुविधाओं का विस्तार किया जा सका है। रिजर्व बैंक के सक्रिय सहयोग से ही औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमों तथा रिफाईनेन्स कॉर्पोरेशन और इण्डस्ट्री को स्थापना हो सकी है।

(९) वित्त बाजार की स्थापना के लिए प्रयत्न—सन् १९५२ में रिजर्व बैंक ने देश में वित्त बाजार की स्थापना के लिए एक योजना बनाई। इस योजना को कारगरूप में लाने से देश में वित्त बाजार के विकास को प्रोत्साहन मिला है।

(१०) रिजर्व बैंक ने मुद्रा, बैंकिंग तथा सहकारी भण्डोलय के सम्बन्धी अभियान भी किये हैं—वह इन विभिन्न विषयों सम्बन्धी ग्रांफों को इकट्ठा करता है तथा उनकी समस्याओं में सौज करने के पश्चात् समय-समय पर मुद्रा के महत्वपूर्ण सुझाव देता है। उसने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों को इकट्ठा करने का काम भी आरम्भ किया है।

(११) कृषि साख के विकास के लिए उसने महत्वपूर्ण कार्य किया है— उसने विभिन्न राज्यों में सहकारी आन्दोलन के पुनर्गठन का कार्य किया है। रिजर्व बैंक ने कृषि साख सम्बन्धी जाँच करने के लिए एक अखिल भारतीय कृषि साख अन्वेषण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) स्थापित की, जिसकी सिफारिशों के आधार पर देश में साख व्यवस्था का पुनर्निर्माण विद्यमान जा रहा है।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ (Where the Reserve Bank has Failed)—

उक्तलिखित सफलताओं के होते हुए भी रिजर्व बैंक के कार्यों में कुछ दोष रहे हैं, जिनके कारण समय-समय पर उसकी आलोचना की गई है। उसकी आलोचना मुख्यतया निम्नलिखित असफलताओं के कारण की जाती है—

(i) रिजर्व बैंक रुपये के मूल्य में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सका है और उसकी मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति अधिक सफल नहीं रही है। मुद्रा काल में उसके द्वारा अपनाई गई मुद्रा-प्रसार की नीति का देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ii) रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का उचित संगठन नहीं कर पाया है। देश में बहुत से छोटे-छोटे बैंक, साम्ब समितियाँ तथा देशी बैंक ऐसे हैं जिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है। अभी तक भी वह देशी बैंकों के साथ अपना कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका है।

(iii) रिजर्व बैंक देश में एक सुव्यवस्थित बिल बाजार का विकास भी नहीं कर सका है। उसके द्वारा बिलों की फिर से भुनान की दी जाने वाली सुविधाएँ बहुत सीमित हैं।

(iv) भारतीय मुद्रा बाजार में व्याज की दरों की भिन्नता को दूर करने में भी उसे अधिक सफलता नहीं मिली है।

(v) देश में कृषि साख की उचित व्यवस्था करने में भी उसे अधिक सफलता नहीं मिली है। वह कृषि साख प्रदान करने वाली संस्थाओं पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं कर सका है।

रिजर्व बैंक की कार्य-प्रणाली में उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि उसे केन्द्रीय बैंक के रूप में काफी सफलता मिली है। उसकी स्थापना के समय जो आनायें उससे की गई थी, उन्हें वह काफी सीमा तक पूरा कर सका है। वह भारतीय रुपये के आन्तरिक तथा विदेशी मूल्य में पर्याप्त स्थिरता स्थापित कर सका है तथा उसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मुद्रा एक सुव्यवस्थित करके देश की अनुपम सेवा की है। यह नि सकोच कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ ही देश में आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग सुधार का एक नया युग आरम्भ हुआ है। रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को द्वितीय विश्व-युद्ध तथा

देश के विभाजन की सन्दर्भातीन स्थिति से निवालने में बड़ी सहायता की है। उसने देश में आर्थिक वित्त-व्यवस्था को सुधारने में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब वह देश में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दत्ताय उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। एक ओर तो वह आर्थिक विकास के लिए अधिकाधिक वित्तीय साधनों की व्यवस्था करता है और दूसरी ओर मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को नियन्त्रित कर रहा है। वर्तमान परिस्थिति में उसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह कहाँ तक इन परस्पर विरोधी उद्देश्यों में समन्वय कर पाता है।

रिजर्व बैंक तथा आर्थिक विकास

(Reserve Bank and Economic Development)—

देश में आर्थिक नियोजन का युग आरम्भ हो जाने में रिजर्व बैंक के ऊपर कुछ नये उत्तरदायित्व आ गये हैं। अब वह केन्द्रीय बैंकिंग के प्राचीन सिद्धान्तों की सीमाओं में रह कर देश की अधिक सेवा नहीं कर सकती है और उसे एक प्रगतिशील केन्द्रीय बैंक के रूप में देश के आर्थिक विकास में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इस समय देश की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास है और हमारी मौद्रिक नीति को केवल इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही चलाया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के अन्य सब उद्देश्य इस महान् उद्देश्य के आधीन होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में रिजर्व बैंक की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि वह कहाँ तक देश में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त दत्ताय उत्पन्न करने में सहायता देता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह देश में केवल आर्थिक स्थिरता ही स्थापित नहीं करता है बल्कि उसे देश के आर्थिक विकास में भी सक्रिय भाग लेना होता है। अल्प-विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों के सम्मुख एक महान् कर्तव्य है कि वे कहाँ तक इन देशों के आर्थिक विकास को सम्भव करते हैं। इनका भविष्य आर्थिक विकास में सहयोग देने की उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर है। रिजर्व बैंक भी इसी प्रकार के परीक्षण काल से गुजर रहा है।

देश की वर्तमान स्थिति में रिजर्व बैंक के दो प्रमुख कर्तव्य हैं—(अ) आर्थिक विकास के लिए विनियोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में वित्तीय साधनों की उपलब्ध करना। (ब) अर्थ-व्यवस्था में अधिक विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को नियन्त्रित करना। इस समय रिजर्व बैंक के सम्मुख इन दो विपरीत उद्देश्यों को प्राप्त करने की बड़ी समस्या है। आर्थिक विकास तथा स्थिरता के उद्देश्यों में उचित समतुलन के द्वारा ही वह देश के आर्थिक विकास में सहयोग दे सकता है। उसे गतिशील (Dynamic) अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा तथा बाजार का विस्तार करना है और इसके साथ ही उचित मौद्रिक प्रवन्ध के द्वारा भूत-स्तर की स्थिरता को भी बनाये रखना है। मौद्रिक साधनों के अभाव के कारण देश में आर्थिक विकास की

गति भी धीमी न पड़ने पाये और मुद्रा-प्रसार की शक्तियाँ भी नियन्त्रण में रहें, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही रिजर्व बैंक कार्य कर रहा है ।

रिजर्व बैंक अपने इस नये उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया प्रयत्नशील है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मौद्रिक साधन उपलब्ध करने में उसे काफी सफलता मिली है । उसने मौद्रिक साधनों के अभाव के कारण देश में आर्थिक विकास की गति को धीमी नहीं पड़ने दिया है और विकास के लिए अधिकाधिक मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध किये हैं । इसके साथ ही उसने मुद्रा-प्रसार की शक्तियों को भी नियन्त्रण में रखा है । प्रथम योजना के अन्त तक वह देश में आर्थिक स्थिरता को बनाये रख सका है किन्तु द्वितीय योजना काल में देश के सम्मुख मुद्रा-प्रसार तथा विदेशी विनिमय संकट की दो प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न हो गईं । विदेशी विनिमय संकट को दूर करने में रिजर्व बैंक को पर्याप्त सफलता मिली है यद्यपि विदेशी विनिमय संकट को पूर्णतया दूर नहीं किया जा सका है किन्तु उसकी तीव्रता को काफी कम कर दिया गया है । योजनाकालीन मुद्रा-प्रसार को रोकने में रिजर्व बैंक को अधिक सफलता नहीं मिल सकी है किन्तु वह मौद्रिक शक्तियों पर पूर्णतया नियन्त्रण बनाये रखने में सफल रहा है ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) एक्ट, सन् १९५६

[Reserve Bank (Amendment) Act, 1956]—

सन् १९५६ में रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक को आर्थिक विकास सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अधिकार देना था । आर्थिक विकास की सफलता के लिए आवश्यक था कि रिजर्व बैंक का देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभावशाली नियन्त्रण हो तथा उसे मौद्रिक साधनों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये जायें । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२०० करोड़ रुपये के हीनार्य-प्रबन्ध की व्यवस्था की गई थी और रिजर्व बैंक को इस राशि का प्रबन्ध अधिक नोट निर्गम के द्वारा करना था । उस समय प्रचलित अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का इतना विस्तार करना सम्भव नहीं था । अतः नोट निर्गम प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी । योजना ध्येय के लिए अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय को उपलब्ध करने के लिए आवश्यक समझा गया कि पत्र मुद्रा कोष में स्टैलिज्ड प्रतिभूतियों की मात्रा को कम किया जायें । आर्थिक योजनाओं में कृषि विकास का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यह आवश्यक था कि रिजर्व बैंक कृषि वित्त साधनों का विस्तार करने में सक्रिय भाग ले और यह रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन के द्वारा ही सम्भव हो सकता था । उक्तलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक एक्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए, जो अग्रलिखित हैं—

(१) रिजर्व बैंक नोट-निर्गम विभाग में अब कम से कम ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रख सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इस न्यूनतम राशि को घटा कर २०० करोड़ रुपये भी की जा सकेगी।

(२) नोट-निर्गम विभाग में रखे जाने वाले सोने तथा सोने के सिक्कों की न्यूनतम मात्रा ११५ करोड़ रुपये होगी।

इस प्रकार पत्र-मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले न्यूनतम कोष की मात्रा ५१५ करोड़ रुपये निश्चित कर दी गई, जिसमें ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होगी तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना अथवा सोने के सिक्के रहेंगे।

(३) अब तक नोट-निर्गम विभाग में रखे जाने वाले सोने का मूल्यांकन १ रु० = ८४७५१२ ग्रेन्स (स्वर्ण) अर्थात् २१ रुपये १३ आने १० पाई प्रति तोला की दर से किया जाता था, किन्तु अब उक्त सोने का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) द्वारा निश्चित दर ३५ डॉलर प्रति औंस (१ रु० = २.८८ ग्रेन्स स्वर्ण) अर्थात् ६२ रुपये ५० नये पैसे प्रति तोला की दर से किया जायेगा। इस दर पर बैंक के पाम मुद्रा कोष में स्थित सोने का मूल्य ४० करोड़ रुपये से बढ़ कर ११५ करोड़ रुपये हो गया है।

(४) रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अनुसूचीबद्ध बैंकों के द्वारा रखे जाने वाले नबद कोष के अनुपात में वृद्धि कर सकेगा। अभी तक यह बैंक अपनी भाग देय (Demand Liabilities) का ५% तथा काल देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक के पास रखते थे किन्तु अब वह इन बैंकों से भाग देय का ५% से २०% तक और काल देय का २% से ८% तक जमा के रूप में ले सकेगा।

(५) रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपने राष्ट्रीय कृषि साख (क्षीरवासीन) कोष में से सहकारी बैंकों को ऋण दे सकेगा, ताकि वे सहकारी बैंक उस राशि को छोटे तथा मध्यम कृषकों को उधार दे सकें और फिर वे उससे सहकारी संस्थाओं के अश खरीद सकें।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियम, सन् १९५७

[Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1957]—

सन् १९५७ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में एक और संशोधन करके पत्र-मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले न्यूनतम कोष की मात्रा में परिवर्तन कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक को निर्गमित नोटों के पीछे २०० करोड़ रुपये का न्यूनतम कोष रखना होता है, जिसमें ११५ करोड़ रुपये का सोना तथा ८५ करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। यह इसलिए किया गया है जिससे कि अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय साधनों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सके।

परीक्षा प्रश्न

- (१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की विद्यमान दस वर्षों की कार्यवाही पर आलोचनात्मक विचार करें। (आगरा बी० ए० १९६०)
- (२) भारत के रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य वहाँ तक सुचारु रूप से सम्पन्न किये हैं ? उदाहरण सहित समझाइये ? (आगरा बी० ए० १९५९ स)
- (३) रिजर्व बैंक एक्ट पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। सन् १९५६ के रिजर्व बैंक संशोधन एक्ट के क्या उद्देश्य हैं ? (आगरा बी० ए० १९५७ स)
- (४) भारत की बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का क्या स्थान है ? वह देश में साख की मात्रा का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (आगरा बी० काम० १९५८)
- (५) रिजर्व बैंक ने कृषि-साख समस्या को मुलभूतने में क्या सहायता दी है ? (आगरा बी० काम० १९६२)
- (६) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 'नोट निर्गमन' एवं 'बैंकों के बैंक' सम्बन्धी कार्यों पर प्रकाश डालिये। (अनारस बी० काम० १९५९)
- (७) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया क्रेन्सी एवं साख पर किस प्रकार नियन्त्रण एवं नियमन करता है ? (बिक्रम बी० काम० १९५९)
- (८) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्य कौन-कौन हैं ? यह अन्य बैंकों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखती है ? (राजस्थान बी० ए० १९५९)
- (९) किसी देश में साख एवं मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक क्या-क्या उपाय कर सकता है ? रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कुछ वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण रखने में किस सीमा तक सफल हुआ है ? (गोरखपुर बी० काम० १९५९)
- (१०) भारत की रिजर्व बैंक के कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए उनका प्रथम नियन्त्रण में क्या महत्व है, समझाइये। (नागपुर बी० ए० १९६०)



स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

STATE BANK OF INDIA

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना सन् १९५५ में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई। इम्पीरियल बैंक देश का बहुत प्राचीन तथा सबसे बड़ा बैंक था। उसकी स्थापना सन् १९२० में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर की गई थी। इम्पीरियल बैंक ने सन् १९२१ में अपना कार्य आरम्भ किया था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इस बैंक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है क्योंकि उसकी स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक बैंकिंग का विकास आरम्भ हुआ। इम्पीरियल बैंक की अधिकृत पूँजी ११½ करोड़ रुपये थी जिसे ५०० रुपये वाले अंशों में बाँटा हुआ था। इस बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Board of Directors) के द्वारा किया जाता था। इस मण्डल में १६ सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नरनर कहा जाता था। केन्द्रीय संचालक मण्डल के प्रतिरिक्त तीन स्थानीय बोर्ड (Local Boards) भी थे जो बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित थे। यद्यपि इम्पीरियल बैंक केवल एक व्यापारिक बैंक था किन्तु सन् १९२५ तक रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व वह देश में केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य भी करता था। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इम्पीरियल बैंक से केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को ले लिया गया और वह पूर्णतया एक व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करने लगा।

आरम्भ से ही इम्पीरियल बैंक दो प्रकार के कार्य करता था—(अ) केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य तथा (ब) व्यापारिक बैंक के कार्य। केन्द्रीय बैंक के रूप में वह सरकार के बैंकर का कार्य करता था और समस्त सरकारी कोष उसके पास जमा रहते थे। वह सरकार के लिए भुगतान प्राप्त करता था तथा उसके आदेश पर भुगतानों को निपटाता था। सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता था। वह लोक ऋण का प्रबन्ध करता था तथा सरकारी वित्त नीति के निर्माण में सहायता देता था। बैंकों के बैंक का

कार्य भी उसके द्वारा किया जाना था और वह बैंको के विलों को भुनाने, उन्हें ऋण देने तथा समाशोधन-गृह की सुविधायें देने का कार्य भी करता था । एक साधारण हिस्सेदारों के बैंक के रूप में वह व्यापारिक बैंक के सभी कार्य करता था । वह भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली बैंक था, उसे सबसे अधिक मात्रा में जमा प्राप्त होती थी तथा समस्त देश में उसकी शाखाएँ फैली हुई थी । सन् १९३४ में इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को समाप्त कर दिया गया किन्तु रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अन्तर्गत उसे उन स्थानों पर जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य सौंप दिया गया ।

रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भी इम्पीरियल बैंक का महत्त्व कम नहीं हुआ और वह देश में प्रमुख व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता रहा । भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इम्पीरियल बैंक का विशेष महत्त्व होने के कई कारण थे— (१) जनता को इस बैंक में बहुत अधिक विश्वास था क्योंकि उसके साधन बहुत विस्तृत थे और उसकी ऋण सम्बन्धी नीति भी बहुत अच्छी थी जिसके कारण बैंक को बहुत अधिक लाभ होता था । (२) इस बैंक की शाखाएँ बहुत अधिक थी जिनके कारण उसका कार्य-क्षेत्र काफी विस्तृत था । अधिक शाखाएँ होने के कारण वह देश के विभिन्न भागों में सस्ती बैंकिंग सुविधायें पहुँचाता था । (३) जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं होती थी, वहाँ पर यह रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य करता था जिसके कारण इसके पास बहुत अधिक रकमा रहता था और इसका विशेष महत्त्व था ।

इम्पीरियल बैंक का इतना अधिक महत्त्व होते हुए भी उसकी कार्य-प्रणाली की कड़ी आलोचना की जाती थी और कई बार उसके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को उठाया गया । केन्द्रीय बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक का कार्य अत्यन्त दोषपूर्ण था और वह कभी भी देश में केन्द्रीय बैंक की कमी को पूरा करने में सफल नहीं हुआ । बैंक का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में होने के कारण वह देश-हित में कार्य नहीं करता था । वह अन्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता करता था तथा संकटकाल में उन की सहायता नहीं करता था । भारतीय व्यापारियों के प्रति उसने पक्षपात की नीति को अपनाया हुआ था तथा उन्हें किसी प्रकार की सुविधायें नहीं देता था । इस बैंक के द्वारा अपनी, कई शाखाएँ, ऐसे स्थानों पर खोली जाती थी, जहाँ पर पहले से ही अन्य बैंकों की शाखाएँ मौजूद थी । अतः देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के स्थान पर वह अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करने का कार्य करता था । इसके अतिरिक्त इस बैंक पर यह भी आरोप लगाया जाता था कि उसने देश में मुद्रा बाजार के संगठन तथा बिल बाजार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया । इन सब दोषों के कारण ही समय-समय पर इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई ।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

(Question of Nationalising Imperial Bank)---

यद्यपि इम्पीरियल बैंक के कार्यों की देश में बड़ी आलोचना की जाती थी किन्तु काफी लम्बे समय तक सरकार ने उसके राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं समझी। सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को विशेष महत्व दिया जाने लगा और सन् १९४८ में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि उसका विचार इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का है।

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठाया गया और सरकार ने मैदान्तिक रूप से इस बैंक के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया किन्तु उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के होने के कारण इस योजना को कार्य-रूप में नहीं लाया जा सका। इस सम्बन्ध में प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार थी—(१) इम्पीरियल बैंक की शाखाएँ विदेशों में भी थी जिनकी सख्या १९५० में ४८ थी। इन विदेशी शाखाओं के कारण इस बैंक के राष्ट्रीयकरण की समस्या काफी जटिल हो गई थी। (२) उस समय सरकार का यह विचार था कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह बैंक व्यापारिक बैंक के कार्य नहीं कर सकेगा। देश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होने के कारण इतने बड़े तथा महत्वपूर्ण बैंक के व्यापारिक बैंकिंग कार्यों को समाप्त करना देश के आर्थिक हित में नहीं था। अतः सरकार ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के कार्य को स्थगित कर दिया।

यद्यपि सरकार उस समय इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ थी किन्तु जनता में इस बैंक की कार्य-प्रणाली का भारी विरोध किया जाता था। इस बैंक के विरुद्ध लगाये जाने वाले मुख्य आरोप इस प्रकार थे—(अ) अत्यव्यवहारिक बैंकों की अपेक्षा इस बैंक को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जिनका प्रयोग वह अन्य बैंकों के साथ अनुचित प्रतियोगिता के लिए करता था। इस बैंक के पास बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी कोष रहता था जिसका प्रयोग उसके द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाता था और उससे वह बहुत लाभ पैदा करता था। किसी भी एक व्यापारिक बैंक के हाथ में भारी सरकारी धन को दे देना अनुचित था क्योंकि उससे एक ऐसा शक्तिशाली एकाधिकार उत्पन्न हो गया था जिसका इम्पीरियल बैंक के द्वारा दुरुपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त केवल इसी बैंक को ही रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य करने का एकाधिकार प्राप्त था जिसका प्रयोग भी अन्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए किया जाता था। अतः इम्पीरियल बैंक के इन सब विशेष अधिकारों तथा सुविधाओं को समाप्त करने की मांग की जा रही थी। (ब) इस बैंक का प्रबन्ध एवं संचालन विदेशियों के हाथ में था जिसके कारण यह बैंक देश-हित में

कार्य नहीं करता था। यह बैंक विदेशी व्यापारियों का पक्ष करता था और भारतीय व्यापारियों का विरोध किया जाता था तथा उन्हें आवश्यक सुविधायें भी नहीं दी जाती थी। भारतीयों को ऊँचे पदों पर नहीं रखा जाता था और उन्हें शिक्षण सम्बन्धी सुविधायें भी नहीं दी जाती थी। (स) इम्पीरियल बैंक ने भारी मात्रा में नकद साख प्रदान करके देश में बिल बाजार के विकास में बाधाये उत्पन्न की थी। यह बैंक बिल बाजार का विकास न कर सका क्योंकि वह नकद साख प्रदान करना अधिक पसन्द करता था और बिलों को मुनाने को प्रोत्साहन नहीं देता था। इम्पीरियल बैंक की कार्य-प्रणाली में उक्तलिखित दोषों के कारण उसके राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही थी।

ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिशें

(Recommendations of the Rural Banking Enquiry Committee)—

सन् १९५१-५२ में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) ने इम्पीरियल बैंक के ऊपर लगाये जाने वाले आरोपों की जाँच की। इस समिति का विचार था कि इम्पीरियल बैंक की कार्य-प्रणाली में दोष अवश्य है किन्तु उनके कारण उसका राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है। इस समिति ने इम्पीरियल बैंक की कार्य-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये—

(अ) इस बैंक को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं उन्हें या तो समाप्त कर दिया जाय अथवा उन पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए।

(ब) बैंक का भारतीयकरण किया जाना चाहिए और उसमें अधिकांश अधिकारी भारतीय होने चाहिए।

(स) देश में सभी बैंकों को यह अधिकार तथा सुविधा मिल जानी चाहिए कि वे सरकारी खजाने के द्वारा अपना रुपया सस्ती दर पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकें।

(द) समिति की राय में इम्पीरियल बैंक पर जगे प्रतिबन्ध पर्याप्त थे; और यह बैंक अन्य बैंकों से कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं कर रहा था। इस समिति ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने पर वह अपना व्यापारिक बैंक का कार्य बन्द कर देगा जो देश हित में नहीं है। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

भारतीय ग्रामीण साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशें

(Recommendations of All India Rural Credit Survey Committee)—

सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भारतीय ग्रामीण साख की जाँच करने के लिए एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख अनुसन्धान समिति (All India

Rural Credit Survey Committee) नियुक्त की जिसके द्वारा इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई। इस कमेटी का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि—“सरकार के सामने मे एक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना होनी चाहिए जो अपनी देश भर में फैली हुई शाखाओं के द्वारा देश की ग्राम्य बैंकिंग समस्याओं तथा सहकारी बैंकों को सहायता पहुँचाता हुआ सरकार की आर्थिक नीति को कार्यरूप में लायेगा।” इस कमेटी की सिफारिशों ने देश में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विचारधारा को काफी बल प्रदान किया। कमेटी का यह प्रत्यक्ष सुझाव था कि इम्पीरियल बैंक तथा भूतपूर्व स्टेट्स के विभिन्न स्टेट बैंकों का एकीकरण—(Amalgamation) करके एक सुदृढ़ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्थापित किया जाना चाहिए जिसका प्रमुख कार्य कृषि और सहकारी बैंकिंग का विकास करना होना चाहिए। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि स्टेट बैंक को अपना कार्य आरम्भ करने के पश्चात् ५ वर्ष की अवधि में ही अपनी ४०० नई शाखाएँ ग्रामीण अथवा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी चाहिए। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को मान लिया और २० दिसम्बर सन् १९५४ को वित्त मंत्री ने सर्वप्रथम इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का विचार प्रवृत्त किया।

स्टेट बैंक की स्थापना की आवश्यकता

(Need for Establishing State Bank)—

स्टेट बैंक की स्थापना देश में ग्रामीण विकास की योजना का ही एक भाग थी। भारतीय ग्रामीण साख अनुसन्धान समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने ग्रामीण साख व्यवस्था में सरकार की सामेदारी की एक योजना प्रस्तुत की जिसे कार्य-रूप में लाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की सिफारिश की गई। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये गये हैं—

(१) वह धन को हस्तान्तरित करने की सस्ती सुविधायें देकर ग्रामीण तथा सहकारी बैंकिंग का विकास करने में सहायता देगा।

(२) स्टेट बैंक सहकारी समस्याओं को कृषि वित्त की व्यवस्था करने में सहायता करेगा।

(३) वह साख सुविधाओं का विस्तार करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वचत को दृढ़ करने में सहायता देगा। आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण वचत को सक्रिय (Mobilisation) करना आवश्यक है और स्टेट बैंक अपनी गाँव में फैली हुई शाखाओं के द्वारा इसे सम्भव कर सकेगा।

(४) स्टेट बैंक मण्डार-गृह समितियों (Warehousing Societies) तथा कृषि विपणन समितियों (Marketing Societies) की स्थापना में सहयोग देगा।

(५) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक की स्थापना के द्वारा उन सब शिकायतों को दूर कर दिया जायगा जो कि लम्बे समय से भारतीयों को इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध रही है।

स्टेट बैंक की स्थापना (Establishment of State Bank of India)—

उपमृक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सन् १९५५ में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत स्टेट बैंक की स्थापना हुई। इस एक्ट के अनुसार इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसकी समस्त भारत स्थित सम्पत्ति तथा दायित्वों (Assets and Liabilities) को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को हस्तान्तरित कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने १ जुलाई सन् १९५५ से देश में अपना कार्य प्रारम्भ किया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में स्टेट बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई—

बैंक की पूँजी (Capital of the Bank)—स्टेट बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) २० करोड़ रुपये निश्चित की गई जिसे १०० रुपये वाले २० लाख अंशों (Shares) में बाँटा जायगा। बैंक की निर्गमित पूँजी (Issued Capital) ५.६२५ करोड़ रुपये होगी। नये बैंक के ५५% अंश रिजर्व बैंक लेगा तथा शेष ४५% व्यक्तिगत हिस्सेदारों को बँचे जायेंगे। भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदारों को नये बैंक के हिस्से खरीदने का पूर्ण अधिकार होगा। इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदारों को भुग्नावजा दिया जायगा और २० दिसम्बर १९५३ तथा २० दिसम्बर १९५५ के बीच के १२ महीनों में अंशों की मौसत कीमत निकाल कर यह भुग्नावजा निश्चित किया जायगा। इस सिद्धान्त के आधार पर पूर्ण चुकता अंशों (Fully Paid up Shares) के लिए १७६५ रुपये १० आने प्रति अंश तथा अपूर्ण चुकता अंशों (Partly Paid-up Shares) के लिए ४२१ रुपये १२ आने ४ पैसे प्रति अंश के हिसाब से भुग्नावजा दिया गया। १००० रुपये तक की भुग्नावजे की रकम तत्काल रूप में देने की व्यवस्था की गई तथा शेष का भुगतान बाँडूत के रूप में किया गया।

बैंक का प्रबन्ध (Management)—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड (Central Board) के द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख कार्यालय बम्बई में है। इस संचालन बोर्ड में २० सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष (Chairman), एक उपाध्यक्ष (Vice Chairman), दो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स (Managing Directors) तथा १६ अन्य डाइरेक्टर्स होते हैं। इन डाइरेक्टर्स में से ६ डाइरेक्टर्स व्यक्तिगत हिस्सेदारों के द्वारा चुने जाते हैं तथा ८ डाइरेक्टर्स रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। २ डाइरेक्टर्स सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार के द्वारा तथा एक रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

केन्द्रीय बोर्ड के अनिश्चित परामर्श देने के लिए मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में स्थित स्थानीय बोर्ड (Local Boards) भी हैं।

स्टेट बैंक के कार्य (Functions of the State Bank of India)—

स्टेट बैंक उन सभी कार्यों को करता है जो पहले इम्पीरियल बैंक के द्वारा किये जाते थे। उसके कार्यों को मुख्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य तथा (ब) व्यापारिक बैंक के कार्य।

(अ) केन्द्रीय बैंकिंग कार्य—आरम्भ से ही इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कुछ कार्य करता रहा है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक ही देश में केन्द्रीय बैंक का कार्य करता था। किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् उसके अधिकांश केन्द्रीय बैंकिंग कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा ले लिए गये हैं। कुछ केन्द्रीय बैंकिंग कार्य अभी भी स्टेट बैंक के द्वारा किये जाते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(१) जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर स्टेट बैंक ही रिजर्व बैंक का एजेंट (Agent) होता है और सरकारी बैंकर के रूप में सभी बैंकिंग कार्य उसके द्वारा किये जाते हैं। वह सरकारी हिमाय में धन प्राप्त करना है और सरकारी आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के भुगतानों को निबटाता है। वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से धन एकत्रित करता है, उनके भुगतानों को निश्चयित करता है और सरकारी धन, सोना, चाँदी तथा प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण करता है। सांख्यिकीय ऋणों की व्यवस्था भी उसके द्वारा की जाती है। इससे अतिरिक्त रिजर्व बैंक उसे जो भी कार्य करने का उत्तरदायित्व देता है, वह उसे करता है।

(२) ऐसे स्थानों पर स्टेट बैंक, बैंकों के बैंक का कार्य भी करता है। वह व्यापारिक बैंकों के धन को अपने पास जमा रखता है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है तथा उनके बिलों की पुनः कटौती (Rediscount) करता है। व्यापारिक बैंकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करने की सस्ती सुविधाएँ भी स्टेट बैंक देता है तथा उनके लिए समाशोधन-गृह (Clearing House) का कार्य करता है। सभी बैंकों का हिसाब प्रायः स्टेट बैंक में रहता है इसलिए वे उन्हीं समाशोधन-गृह के रूप में प्रयोग करते हैं।

(ब) व्यापारिक बैंक के कार्य—यद्यपि स्टेट बैंक कुछ केन्द्रीय बैंकिंग कार्य करता है किन्तु प्रमुख रूप से वह एक व्यापारिक बैंक है और उसके द्वारा वे सभी बैंकिंग कार्य किये जाते हैं जो अन्य व्यापारिक बैंक करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इम्पीरियल बैंक के व्यापारिक बैंक के कार्य बन्द नहीं होंगे और वह देश के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता रहेगा। स्टेट बैंक के द्वारा किये जाने वाले व्यापारिक बैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी अपने ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम देता है और इस प्रकार व्यवसाय तथा व्यापार की अल्पकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्टेट बैंक निम्नलिखित प्रकार की सुरक्षा (Security) के आधार पर अग्रिम, ऋण तथा नकद साख देता है—

(क) ऐसे स्टॉक, फण्ड तथा प्रतिभूतियाँ जिनमें प्रन्यासी (Trustee) को प्रन्यास रकम के विनियोग करने का अधिकार हो।

(ख) जिला बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र तथा अन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ।

(ग) सीमित दायित्व वाली कंपनियों के ऋण-पत्र।

(घ) विधान के अन्तर्गत स्थापित कॉर्पोरेशन के ऋण और ऋण-पत्र।

(ङ) माल अथवा उससे सम्बन्धित अधिकार-पत्र जो स्टेट बैंक के पास जमा कर दिये गये हो अथवा जिन्हें स्टेट बैंक के नाम कर दिया गया हो।

(च) स्वीकृत विनिमय-पत्र अथवा प्रतिज्ञा-पत्र जो पाने वाले के द्वारा हस्तान्तरित किये जा चुके हों तथा दो ऐसे व्यक्तियों के सम्मिलित एवं पृथक् प्रतिज्ञा-पत्र जो सामेदारी के रूप एक दूसरे से सम्बन्धित न हों।

(छ) सीमित उत्तरदायित्व वाली कंपनियों के पूर्ण चुकता ऋण।

(२) स्टेट बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, रेलवे प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, पोर्ट ट्रस्ट व अन्य कॉर्पोरेशन की प्रतिभूतियों तथा ट्रेजरी बिल्स आदि में अपने धन का विनियोग करता है।

(३) स्टेट बैंक उन सभी प्रतिज्ञा-पत्रों, ऋण-पत्रों, माल के अधिकार-पत्रों, बॉन्ड्स, ऋणों आदि को बेचकर रकम वसूल कर सकता है जो उसे ऐसे ऋणों अथवा ऋणियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हों जिनका भुगतान निर्धारित अवधि पर न हुआ हो।

(४) जनता से जमा के रूप में रूप में स्थापित करना तथा उन्हें अन्य बैंकिंग सुविधायें देना।

(५) ऐसे विनिमय बिलों को जारी करना, स्वीकार करना, भुगतान, बेचना तथा खरीदना जिनका भुगतान भारत में किया जाता है।

(६) ऐसे विनिमय-पत्रों तथा साख प्रमाण-पत्रों (Letters of Credit) को जारी करना जिनका भुगतान भारत से बाहर होता है।

(७) स्वर्ण तथा चाँदी का क्रय-विक्रय करना।

(८) रिजर्व बैंक की स्वीकृति से किसी भी बैंकिंग कम्पनी के अंशों को खरीदना व बेचना अथवा अपने संरक्षण में किसी बैंकिंग कम्पनी को स्थापित करना या उसका संचालन करना।

(६) स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। वह उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सुविधायें देता है, उनके लिए साख प्रमाण-पत्र तथा यात्री चेक (Travellers' cheque) जारी करता है ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार से रुपया भेजने की सुविधायें देता है। वह उत्तर-माधक (Executor of Wills) तथा प्रणामी का कार्य करता है तथा कम्पनियों के निस्तारक (Liquidator) का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है।

(१०) किसी भी विधान के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करना।

(११) किसी रुपया अथवा पूँजी वाली कम्पनी अथवा पंजीकृत सहकारी समिति को निस्तारण से बचाने अथवा निस्तारण निश्चिन्न हो जाने पर उसे सुगम बनाने के उद्देश्य से ऋण देना अथवा उसके पक्ष में नकद साख का हिमाय खोलना।

(१२) इनके अतिरिक्त वह उन सब कामों को कर सकना है जिनके करने के लिए केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से उसे अधिकार दे।

स्टेट बैंक के वर्जित कार्य—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें स्टेट बैंक नहीं कर सकता है। बैंक के वर्जित कार्य इस प्रकार हैं—(i) वह भ्रष्ट सम्पत्ति तथा अपने अंशों (Shares) की आड पर ऋण नहीं दे सकता है। (ii) वह किसी व्यक्ति अथवा मर्यादा को ६ मास से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता है। (iii) उसने द्वारा ऐसे बिलों को नहीं मुनाया जा सकता है जिनकी परिपक्वता (Maturity) की अवधि ६ मास से अधिक हो। इस सम्बन्ध में कृपि बिलों के लिए छूट दी गई है और वे १५ महीने तक की अवधि के हो सकते हैं। (iv) वह ऐसे बिलों को नहीं मुना सकता है जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर न हों।

लाभ का बँटवारा—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि यह बैंक अपने लाभ में से एक विशेष कोष का निर्माण करेगा जिसका नाम एकीकरण तथा विकास कोष (Integration and Development Fund) होगा। रिजर्व बैंक को प्राप्त होने वाला लाभान (Dividend) का भाग इस कोष में जमा किया जायगा। इस कोष का प्रयोग स्टेट बैंक की हानि को पूरा करने के लिए किया जायगा अथवा इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मद पर व्यय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक एक सुरक्षित कोष (Reserve Fund) भी स्थापित करेगा जिसमें भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक का रक्षित कोष सम्मिलित होगा। लाभान घोषित करने के पश्चात् बचने वाले लाभ को इसी कोष में जमा किया जाता है।

स्टेट बैंक का महत्व (Importance of State Bank)—

स्टेट बैंक की स्थापना से देश में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की आशा है—

(१) बैंकिंग सुविधाओं का विकास—स्टेट बैंक की स्थापना से देश में, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास होगा। इम्पीरियल बैंक की देश भर में ४७५ शाखाएँ थीं। इनके अतिरिक्त स्टेट बैंक की अपनी स्थापना से ५ वर्षों के समय में ४०० नई शाखाएँ खोलनी हैं जिनमें से अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी। इस प्रकार अपनी लगभग १००० शाखाओं से स्टेट बैंक देश भर में बैंकिंग सुविधाओं का विकास कर सकेगा। यह नया विकास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। इस प्रकार वह ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रोत्साहन करने और इन बचतों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा।

(२) साख नियन्त्रण में सहायता—स्टेट बैंक के पास सरकारी जमा तथा अन्य बैंकों की जमा के रूप में काफी रकमा रहता है। अधिक मात्रा में धन होने के कारण वह बाजारी व्याज की दरों को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार साख नियन्त्रण में सहायता दे सकता है। वह अपने पास अधिक जमा होने के कारण बहुत कम सूद पर रकमा उधार दे सकता है और अन्य बैंकों को अपने अनुकूल साख नीति रखने के लिए बाध्य कर सकता है।

(३) धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सस्ती सुविधाएँ प्रदान करता है—स्टेट बैंक धन के हस्तान्तरण की सस्ती सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था है क्योंकि वह अपनी देश भर में फैती हुई शाखाओं के द्वारा इस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक अन्य बैंकों को सप्ताह में दो बार मुफ्त रकमा भेजने की सुविधाएँ देता है।

(४) कृषि साख की उचित व्यवस्था करने में सहायता—स्टेट बैंक देश में कृषि साख की उचित व्यवस्था करने में सहायता देगा। कृषि साख का विकास करने के लिए वह सरकारी बैंकों की अधिविवर्ष (Overdraft) तथा बिलों को फिर से भुनाने (Rediscounting) की सुविधाएँ देता है जिससे सहकारी संस्थाओं के साधनों में वृद्धि हुई है और वे किसानों को अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त वह मासगोदामों में बन्द माल की ग्राह पर भी ऋण देता है।

(५) छोटे-छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता—स्टेट बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य भी करता है। उसने राज्य औद्योगिक वित्त नियमों तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं की काफी आर्थिक सहायता की है।

स्टेट बैंक की प्रगति (Progress of the State Bank)—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने १ जुलाई सन् १९५५ को सर जॉन मेथाई की अध्यक्षता में आना कार्य प्रारम्भ किया था। इस समय बैंक अपने जीवन के प्रथम दस वर्ष पूरे करने जा रहा है। इन वर्षों में इस बैंक ने अपने परम्परागत तथा विकास सम्बन्धी कार्यों में अच्छी प्रगति की है। देश के आर्थिक विकास में स्टेट बैंक के पूरे महत्व की तो आने वाले समय में ही जाना जा सकेगा किन्तु इस अल्पकाल में उसकी प्रगति को देखकर कुछ मुख्य प्रवृत्तियों का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है।

निक्षेप तथा अग्रिम (Deposits and Advances)—बैंक की कुल जमा जो १ जुलाई सन् १९५५ को १८६६ करोड़ रुपये थी, सन् १९६४ के अन्त में ७८७ करोड़ रुपये में अधिक हो गई। सन् १९६४ में स्टेट बैंक ने विशेष तेजी के साथ प्रगति की। इस वर्ष में समस्त अनुसूचीबद्ध बैंकों की जमा में २६६६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिसमें से १२६६ करोड़ रुपये की वृद्धि स्टेट बैंक में हुई। इस प्रकार जमा की कुल वृद्धि में स्टेट बैंक का हिस्सा ५०% में भी अधिक रहा है। साख के विस्तार में भी इस बैंक ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और उसके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों की मात्रा में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। सन् १९६४ में समस्त अनुसूचीबद्ध बैंकों की साख में २३१२ करोड़ रुपये की साख की वृद्धि हुई जिसमें से १३१५ करोड़ रुपये की साख की वृद्धि स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में हुई। इसमें से अधिकांश साख का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन के विस्तार के लिए किया गया। स्टेट बैंक की स्थापना के समय यह भय था कि बैंक के द्वारा व्यक्तिगत क्षेत्र (Private Sector) को दिये जाने वाले अग्रिमों की मात्रा कम हो जायेगी किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। व्यक्तिगत क्षेत्र को बैंक की अग्रिमों की मात्रा वास्तव में बढ़ी है। समस्त बैंकों के द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों में होने वाली वृद्धि का बहुत बड़ा भाग स्टेट बैंक के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार स्टेट बैंक ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है।

शाखा विस्तार (Branch Expansion)—

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार पहले पांच वर्षों में बैंक को ४०० नई शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी थी। जून १९६० तक बैंक ने ४१६ नई शाखाएँ स्थापित कर अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया। इसके पश्चात् सचालक मण्डल की एक उपसमिति ने शाखा का दूसरा कार्यक्रम निश्चित किया जिसके अन्तर्गत जून १९६५ के अन्त तक स्टेट बैंक को ३०० और नई शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी थी। सन् १९६४ के अन्त तक इस नये प्रोग्राम के अन्तर्गत केवल ४६ शाखाएँ खुलनी सेष रह गई थी। शाखा विस्तार के तीसरे कार्यक्रम के अनुसार इनके अतिरिक्त स्टेट बैंक को दिसम्बर सन् १९६८ तक ३१६ नई शाखाएँ और

स्थापित करनी है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक का शाखा विस्तार कार्यक्रम निश्चित रूप से सतोपजनक रहा है और उसने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ३१ दिसम्बर १९२४ को स्टेट बैंक के कुल दफ्तरों की संख्या ११४७ थी जिसमें से ५६४ ऐसे केन्द्रों में स्थित थे जहाँ पहले से बैंकिंग सुविधाएँ नहीं थी। इस प्रकार शाखा विस्तार के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को काफी सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। स्टेट बैंक ने ग्रामीण पाइलट केन्द्रों (Rural Pilot Centres) की स्थापना को भी स्वीकार कर लिया है। समस्त देश में लगभग ५० से ७० ग्रामीण पाइलट केंद्र स्थापित करने की योजना है जिनमें से प्रत्येक केन्द्र ग्राम-पास के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करेगा।

स्टेट बैंक और ग्रामीण साख

(The State Bank of India and Rural Credit, —

स्टेट बैंक की स्थापना एक सगठित ग्रामीण साख (Integrated Rural Credit) के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना तथा ग्रामीण साख की उचित व्यवस्था करना है। आरम्भ से ही उसने सहाकारी मस्याओं की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देकर सामान्य रूप से ग्रामीण साख का विकास करने में सहायता दी है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में स्टेट बैंक के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(अ) सामान्य सुविधाएँ जो वह ग्रामीण साख मस्याओं के विकास के लिए देता है। (ब) सहाकारी मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग समितियों की वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था। (स) देश में गोशाला के विकास की योजनाओं में सहायता देना।

सामान्य सुविधाएँ (General Facilities)—

स्टेट बैंक ने स्टेट सहाकारी बैंकों तथा उनसे सम्बन्धित केन्द्रीय व औद्योगिक सहाकारी बैंकों को अधिक मात्रा में विप्रेष (Remittance) की सुविधाएँ दी हैं। अब वह इन बैंकों के धन को मप्ताह में एक बार के स्थान पर तीन बार मुपन भेजने की सुविधाएँ देता है। स्टेट बैंक की अधिक शाखाएँ खुल जाने के कारण अब वह विप्रेष की सुविधाएँ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रदान कर सकता है। विप्रेष की निशुल्क सुविधाओं के परिणामस्वरूप बैंकों की रकम की गतिशीलता बढ़ गई है।

इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक सहाकारी साख संस्थाओं को अन्य कई प्रकार की सुविधाएँ देता है। वह सहाकारी केन्द्रीय बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की आड़ पर बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम ब्याज की दर पर ऋण देता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सहाकारी बैंकों को अपने से सम्बन्धित सहाकारी समितियों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार की गारण्टी पर अधिम भी देता है।

सहकारी मस्याएँ वस्तुओं को पुनः आड करके भी स्टेट बैंक में ऋण ले सकती हैं। सहकारी बैंको के अपने बैंको (Cheques) का घन एखित करने तथा उन्हें खरीदने का काम यह बैंक रियायती दर पर करता है। इसके प्रतिरिक्त जिला सहकारी बैंको को शीर्ष सहकारी बैंको (Apex Co-operative Banks) से प्राप्त होने वाले ड्राफ्ट तथा बैंको को भुनाने का काम भी स्टेट बैंक रियायती दर पर करता है। स्टेट बैंक ने पिछले वर्षों में सहकारी साख मस्याओं को अधिकाधिक मात्रा में माह मुविघाएँ दी हैं, यह इस बात से प्रमाणित है कि बैंक के द्वारा निर्धारित सब प्रकार की साख मस्याओं की साख भीमा ३१ दिसम्बर १९६४ को ६१.६ करोड रुपये थी तथा उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की मात्रा २१.४ करोड रुपये थी जो १९६० की अपेक्षा १६ करोड रुपये अधिक थी।

प्रथम स्टेट बैंक न भूमि वन्धक बैंको की सहायता करना भी आरम्भ कर दिया है। वह इन्हें तीन प्रकार में सहायता देता है—(i) शीर्ष सहकारी भूमि वन्धक बैंको (Apex Land Mortgage Banks) के ऋण पत्र (Debentures) खरीद कर। (ii) इन ऋण पत्रों की आड पर स्टेट बैंक अग्रिम देकर मुद्रा बाजार में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। (iii) स्टेट बैंक सहकारी केन्द्रीय भूमि-प्रवन्धक बैंको को मोमिन अस्थायी वैज्ञानिक सहायता सरकार की गारन्टी पर देता है।

सहकारी मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग समितियों को सहायता

(Financial Accomodation to Marketing and Processing Societies)—

जिन क्षेत्रों में सहकारी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों के केन्द्रीय सहकारी बैंको से सुगम तथा पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है वहाँ पर स्टेट बैंक प्रत्यक्ष रूप से इनकी सहायता करता है। मार्केटिंग समितियों को वस्तुओं की आड पर अग्रिम दिये जाते हैं जिससे कि वे अपने माल को रोककर अच्छे भाव पर बेच सकें। कुछ अच्छी समितियों को उनके डाइरेक्टर्स की गारन्टी पर अथवा अच्छल सम्पत्ति की आड पर भी अग्रिम दिये जाते हैं। प्रोसेसिंग समितियाँ जैसे चीनी मिलें, ईस् व जूट साफ करन व गाँठ बाधने वाली समितियाँ भी इन्हीं शर्तों पर स्टेट बैंक में ऋण प्राप्त कर सकती हैं। मार्केटिंग और प्रोसेसिंग समितियों को दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिमों की मात्रा जून १९६२ में ५५ लाख रुपये थी जो जून १९६० की अपेक्षा १४ लाख अधिक थी।

स्टेट बैंक तथा गोदामों की व्यवस्था (State Bank and Warehousing)—

वैज्ञानिक रीति से कृषि वस्तुओं के संग्रह करने की व्यवस्था करना कृषि वस्तुओं के मार्केटिंग के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश में कृषि वस्तुओं के संग्रह करने के लिए गोदामों का विकास बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि इन गोदामों की रसीदों (Warehouse Receipts) को बैंको के द्वारा वहाँ तक ऋणों की भुरक्षा (Security) के रूप में स्वीकार लिया जाता है। स्टेट बैंक ने गोदामों

की विकास योजना में अपना पूरा सहयोग दिया है। उसने केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) की अंश पूँजी (Share Capital) में भाग लिया है। वह इस निगम की रसीदों की आड़ पर कम मूल्य पर ऋण देता है। इस सुविधा का प्रयोग व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों दोनों के द्वारा किया जा रहा है। सन् १९६० में स्टेट बैंक के द्वारा दिये जाने वाले इस प्रकार के अग्रिमों की मात्रा १२१ लाख रुपये थी जो जून १९६२ में बढ़कर २७६ लाख रुपये हो गई।

लघु उद्योगों को सहायता (Assistance to Small Scale Industries)—

स्टेट बैंक ने औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने में योगदान दिया है। विशेषतया लघु उद्योगों को उससे काफी लाभ पहुँचा है। अप्रैल सन् १९५६ में बैंक के द्वारा लघु उद्योगों को संगठित साल की सुविधायें देने की योजना का कुछ चुने हुए क्षेत्रों में समारम्भ किया गया। जनवरी सन् १९५६ से इस योजना को स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आरम्भ कर दिया गया। सन् १९६४ के अन्त तक स्टेट बैंक ने ५८३४ लघु उद्योगों को इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक सहायता दी है जो लगभग ४० करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) के साथ एक समझौते के अधीन स्टेट बैंक छोटे उद्योगपतियों को कच्चे माल की आड़ पर ऋण भी देता है तथा निगम की गारण्टी पर उन्हें बैंक से अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में १९५७ के एक संशोधन के द्वारा स्टेट बैंक को व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योगों को मध्यमकालीन ऋण देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। अब वह इस प्रकार के ऋण ७ वर्ष की अवधि तक के लिए दे सकता है।

परीक्षा प्रश्न

(१) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों पर प्रकाश डालिये।

(आगरा बी० काम १९६२, बी० ए० १९५७)

(२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य कर्तव्यों का विवेचन करिये। वह कहाँ तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुआ है।

(विक्रम बी० काम १९५८)

(३) किन उद्देश्यों से इम्पोरियल बैंक ऑफ इण्डिया को स्टेट बैंक में परिवर्तित किया गया? आपके विचार में वह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग आदत का विकास कैसे करेगा?

(आगरा बी० काम० १९५६)

(४) किन उद्देश्यों से इम्पोरियल बैंक ऑफ इण्डिया को स्टेट बैंक में परिवर्तित किया गया था? क्या आपकी सम्मति में वह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की आदतों का प्रसार करने में सफल होगा? (गोरखपुर जी० काम १९५६)

(५) स्टेट बैंक के स्थान तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। वह कहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में साक्ष प्रदान करने में सफल रहा है? (बिहार बी० काम १९६०)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

INTERNATIONAL TRADE

व्यापार सामान्यतः दो प्रकार का हो सकता है—आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ बातों में आन्तरिक व्यापार से भिन्न होता है यद्यपि यह भिन्नता प्रबंधशास्त्र के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । आन्तरिक व्यापार से समिप्राय उस व्यापार से होता है जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के बीच किया जाता है । इस प्रकार के व्यापार को अन्तर-स्थानीय व्यापार (Inter-Local Trade) अथवा अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार (Inter Regional Trade) भी कहते हैं । हमारे देश में कलकत्ते और दिल्ली अथवा मद्रास और बम्बई के बीच होने वाला व्यापार आन्तरिक व्यापार है क्योंकि वह एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच किया जाता है । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है । भारत और इंग्लैंड अथवा अमेरिका और जर्मनी के बीच होने वाला व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है क्योंकि वह भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के बीच होता है । अतः अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार (Inter-regional trade) अथवा आन्तरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक ही देश के दो विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो दो भिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है । एक उदाहरण के द्वारा इस अन्तर को स्पष्ट किया जा सकता है । देश के विभाजन से पूर्व दिल्ली और लाहौर के बीच किया जाने वाला समस्त व्यापार आन्तरिक व्यापार था क्योंकि वह एक ही देश में रहने वाले व्यापारियों के बीच किया जाता था । किन्तु विभाजन के कारण स्थिति बदल गई है और अब इन्हीं दो शहरों के बीच होने वाला व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है क्योंकि दोनों शहर अलग-अलग देशों में स्थित हैं । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भेद मुख्यतया राजनैतिक है और उसका अधिक महत्व बहुत कम है ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में अन्तर होते हुए भी उनमें काफी समानता पाई जाती है। दोनों प्रकार के व्यापार का आधिक आधार एक ही है और दोनों ही श्रम विभाजन (Division of Labour) तथा कार्यों के विशिष्टीकरण (Specialisation of Functions) के कारण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार एक देश के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किये जाने के कारण आन्तरिक व्यापार होता है ठीक इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के पैदा किये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। ससार के विभिन्न देशों के बीच श्रम-विभाजन होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति बहुत से कार्य कर सकता है किन्तु इनमें से कोई एक कार्य करने के लिए वह अधिक उपयुक्त होता है और वह अन्य कार्यों को दूसरों के लिए छोड़कर केवल उन्हीं कार्य को करता है जिसे वह सबसे अच्छी प्रकार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक देश विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है किन्तु उनमें से किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए वह अधिक उपयुक्त होता है और ऐसी दशा में वह केवल उन्हीं वस्तु का उत्पादन करता है तथा अन्य वस्तुएँ दूसरे देशों में मंगा लेता है। विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार का श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पैदा करता है। अतः दोनों ही प्रकार के व्यापार का आधार श्रम-विभाजन तथा कार्यों का विशिष्टीकरण है। आर्थिक दृष्टि से आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त दोनों प्रकार के व्यापार का उद्देश्य लगभग एक ही होता है। आन्तरिक व्यापार की भाँति ममस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भी एक प्रकार की वस्तुओं का दूसरे प्रकार की वस्तुओं के साथ विनिमय करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। विदेशी व्यापार में भी विभिन्न देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विनिमय किया जाता है जिससे विनिमय करने वाले दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। इन समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में कोई आधारभूत अथवा मौलिक भेद नहीं है। इनमें अन्तर केवल अंश (Degree) का है प्रवृत्ति का नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता
(Need for a Separate Theory of International Trade)—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता है अथवा नहीं—इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में इतना अधिक अन्तर पाया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के द्वारा नहीं समझा जा सकता है और उसके लिए एक पृथक् सिद्धान्त का होना

आवश्यक है। एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा मिल इसी विचारधारा के मानने वाले थे और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त का निर्माण किया, जिसे तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत कुछ वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिनमें ओहलिन (Ohlin) प्रमुख है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में कोई मौलिक भेद नहीं है और विदेशी व्यापार आन्तरिक व्यापार का ही विस्तार है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए किसी पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है और उसे मूल्य के सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Value) के द्वारा ही समझा जा सकता है। विचारों के इस मतभेद के महत्व को समझने के लिए सर्वप्रथम उन तर्कों का अध्ययन करना चाहिए जिनके कारण प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार में भिन्न किया है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त का होना आवश्यक है—

(१) श्रम और पूँजी एक देश में अधिक गतिशील होती है तथा विभिन्न देशों में उसकी गतिशीलता बहुत कम हो जाती है—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आन्तरिक व्यापार में मौलिक भेद विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूँजी की गतिशीलता के अभाव के कारण उत्पन्न होता है। एक देश के विभिन्न भागों में श्रम और पूँजी गतिशील होते हैं किन्तु विभिन्न राष्ट्रों के बीच इस प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है। यदि देश के एक भाग में मजदूरी की दरें कम होती हैं तथा दूसरे भाग में अधिक, तो श्रमिक कम मजदूरी वाले स्थान को छोड़कर अधिक मजदूरी वाले स्थान पर जाने लगते हैं किन्तु विभिन्न देशों में मजदूरी में अन्तर होते हुए भी श्रमिकों में इस प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है। श्रम की गतिशीलता के अभाव के कारण ही एडम स्मिथ ने कहा है कि “सभी प्रकार के सामानों में मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना सबसे अधिक कठिन है।” विभिन्न देशों में भाषा, रीति-रिवाज, धर्म, सामाजिक दशाओं आदि की भिन्नता तथा स्थानीय लगाव के कारण लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में नहीं जाना चाहते हैं। यातायात व्यय तथा विभिन्न देशों के आवास सम्बन्धी नियम भी श्रमिकों की गतिशीलता में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। उपर्युक्त सभी कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रम की गतिशीलता बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार पूँजी भी देश में अधिक गतिशील होती है किन्तु विभिन्न देशों के बीच उसकी गतिशीलता बहुत कम रह जाती है। लोग अपनी पूँजी को अपने पास ही लगाना चाहते हैं और विदेशों में पूँजी लगाने में सकोच करते हैं। अपने देश में पूँजी का विनियोग

करने की अपेक्षा विदेशों में पूँजी का विनियोग करने में अधिक जोखिम समझी जाती है। प्रत्येक विनियोगी अपने देश में लगी हुई पूँजी को अधिक सुरक्षित समझता है क्योंकि विदेशों में लगी हुई पूँजी का वह निरीक्षण नहीं कर सकता है। इन्हीं कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजी की गतिशीलता बहुत कम होती है। श्रम और पूँजी की गतिशीलता के अभाव के कारण विभिन्न देशों में मजदूरी और व्याज की दरे भिन्न रहने की प्रवृत्ति रखती है जिसके कारण विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो पाती है और वस्तुओं की उत्पादन-लागतें भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हो जाती हैं। आन्तरिक व्यापार में ऐसा नहीं होता है।

(२) उत्पत्ति की दृष्टात् से सब देशों में समान नहीं होती हैं—उत्पादन सम्बन्धी सुविधायें सब देशों में अलग अलग रहती हैं क्योंकि विभिन्न देशों की कर-प्रणाली, औद्योगिक व्यवस्था, शिक्षा सुविधायें सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध, श्रम संध तथा औद्योगिक गृहबन्दी सम्बन्धी नियम इत्यादि अलग-अलग होते हैं। ऐसी दशा में विभिन्न देशों में एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन भिन्न-भिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत किया जाता है जिसके कारण उत्पादन लागतों में अन्तर हो जाता है। इसके विपरीत एक ही देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन लगभग एक ही प्रकार की सुविधाओं के अन्तर्गत होता है जिसके कारण उत्पादन लागत समान होने की प्रवृत्ति रखती है और उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण प्रतियोगिता रहती है। लागतों की भिन्नता केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ही एक विशेष गुण है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के पास भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं जिन्हें एक देश से दूसरे देशों को आसानी से हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। साधनों की इस भिन्नता के कारण भी उत्पादन लागतों में अन्तर पैदा होता है।

(३) प्रत्येक देश की मुद्रा-प्रणाली अलग होती है—एक देश के अन्दर प्रायः एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण आन्तरिक व्यापार में भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न प्रकार की मुद्रायें होने के कारण एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। विदेशी व्यापार करने से पूर्व हमें यह निश्चित करना होता है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ किस दर पर बदली जायेगी। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलता लाती हैं तथा उसके स्वतन्त्रतापूर्वक चलने में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होते रहते हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग मौद्रिक नीति होती है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन करके वह मूल्य-स्तर तथा विनिमय दरों को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार किसी देश के केन्द्रीय बैंक के द्वारा अपनाई

जाने वाली मुद्रा नीति तथा समय पर उसमें होने वाले परिवर्तन विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

(४) वस्तुओं के आयात-निर्यात में बाधाएँ—एक देश के भीतर व्यापार स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाता है और वस्तुओं के आने-जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है, जिसके कारण आन्तरिक व्यापार में स्वतन्त्र प्रतियोगिता रहती है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुओं का आयात-निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आने-जाने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध तथा आयात निर्यात शुल्क लगाये जाते हैं, जिनके कारण विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक देश की व्यापारिक तथा तटकर नीति भिन्न-भिन्न होती है, जिसके कारण वस्तुओं के आयात निर्यात में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतन्त्र न होने के कारण वस्तुओं के विभिन्न बाजारों में स्वतन्त्र प्रतियोगिता नहीं हो पाती है और वस्तुओं के मूल्य भिन्न रहने की प्रवृत्ति रहती है।

(५) यातायात व्यय की अविश्वता—यातायात व्यय अधिक होने के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार से भिन्न हो जाता है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दूर के देशों के बीच किया जाता है, जिसके कारण वस्तुओं के लाने ले जाने पर काफी व्यय आता है। आन्तरिक व्यापार में यह व्यय बहुत कम होता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यातायात व्यय अधिक होने के कारण दो देशों के व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता सीमित हो जाती है और एक ही वस्तु का मूल्य विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न रहता है।

उक्तलिखित कारणों से ही प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याएँ एवं दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और इसलिए माघारण विनिमय सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता है अतः परम्परागत अधनास्त्रियों (Classical Economists) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (Law of Comparative Costs) का निर्माण किया। उनके अनुसार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित सिद्धान्त है।

आधुनिक विचारधारा (Modern View)—

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के इस विचार का विरोध किया है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार का ही एक प्रशिष्ट रूप माना है। विशेषतया स्वीडन के अर्थशास्त्री ओहलिन (Ohlin) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आन्तरिक व्यापार को एक दूसरे से पृथक् करने की प्रवृत्ति का खंडन किया है। वास्तव में आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में

कोई मौलिक भेद नहीं है क्योंकि दोनों का आर्थिक आधार एक ही है और दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। दोनों में केवल श्रेणी भेद है और उनमें कोई आधारभूत अन्तर नहीं पाया जाता है। दोनों की समस्याएँ एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती हैं और इसलिए दोनों प्रकार के व्यापार को समझने के लिए एक ही सिद्धान्त होना चाहिए। ओहलिन (Ohlin) तथा अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उन सब बातों का खण्डन किया है, जिनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से भिन्न करने का प्रयत्न किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापार में काफी समानता पाई जाती है और इसलिए दोनों प्रकार के व्यापार को एक ही सिद्धान्त से समझा जा सकता है। ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता का विरोध किया है और निम्नलिखित आधार पर यह मिथ्य करने का प्रयत्न किया है कि आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त को ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है—

(१) तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही लागू नहीं होता है—ओहलिन के अनुसार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त सब प्रकार के व्यापार का आधार है, यह व्यापार चाहे व्यक्तियों के बीच अथवा एक देश के दो क्षेत्रों के बीच या दो विभिन्न देशों के बीच होना हो। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से इस आधार पर अलग किया जाता रहा है कि वह लागतों के सापेक्षिक अन्तर के कारण उत्पन्न होता है जबकि आन्तरिक व्यापार में ऐसा नहीं होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह धारणा भ्रमात्मक है क्योंकि दोनों ही प्रकार का व्यापार लागतों में सापेक्षिक अन्तर के कारण उत्पन्न होता है। पारेटो (Pareto) के अनुसार, “सापेक्षित लागतों का विचार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं है, वह उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार लागू किया जा सकता है, जो आर्थिक इकाई बनाते हैं।”^२ ऐजवर्थ (Edgeworth) के विचार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी उसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार होता है, जो आन्तरिक व्यापार का आधार है। उनके अनुसार आन्तरिक व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक साधारण एवं विशिष्ट रूप है। सेलिगमैन (Seligman) ने भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त का विरोध किया है। उनके अनुसार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तर्देशीय तथा अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के विनिमय का आधार है। ओहलिन (Ohlin) ने दोनों प्रकार के व्यापार की समानता को बतलाते हुए लिखा है कि—“विभिन्न क्षेत्र तथा देश विशिष्टीकरण एवं व्यापार उन्हीं कारणों से करते हैं, जिन कारणों से व्यक्तियों के द्वारा विशिष्टीकरण तथा

2 “The consideration of relative costs is not peculiar to international trade, it can be applied also to the individuals who form an economic unit.”

व्यापार किया जाता है।³ अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है और आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त का विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी किया जा सकता है।

(२) साधनों की गतिशीलता में भिन्नता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से पृथक् नहीं किया जा सकता है—जिम प्रकार भ्रम और पूँजी विभिन्न देशों के बीच अगतिशील होते हैं, उसी प्रकार देश के भीतर भी उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता में बाधाएँ रहनी हैं। इसके अतिरिक्त आज-कल आवागमन के साधनों का विकास हो जाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण विभिन्न देशों के बीच भी उत्पत्ति के साधन पूर्णतया अगतिशील नहीं रहते हैं और वे एक देश से दूसरे देश में आ-जा सकते हैं। अतः न तो यह कहना ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रम तथा पूँजी पूर्णतया अगतिशील हैं और न यह कहना ही उचित है कि देश के भीतर उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। विभिन्न देशों की भाँति किसी एक देश में भी भ्रमिकों के प्रयोगिता रहित समूह (Non-competing Groups) होते हैं। अन्तर वैयक्त्य इतना है कि देश के भीतर उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता होने के कारण इस प्रकार के समूह स्वयं नष्ट होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यद्यपि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भ्रम तथा पूँजी की गतिशीलता में कुछ अन्तर हो सकता है किन्तु इस आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से पृथक् नहीं किया जा सकता है।

(३) विभिन्न देशों की भाँति एक देश में भी उत्पत्ति की सुविधायें भिन्न हो सकती हैं—जिम प्रकार विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी सुविधायें भिन्न-भिन्न होती हैं, उसी प्रकार एक देश के विभिन्न भागों में भी उत्पादन की सुविधायें अलग-अलग हो सकती हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा बनाये गए उत्पादन सम्बन्धी नियमों में काफी अन्तर रहता है। विभिन्न राज्यों की कर नीति तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधायें भी भिन्न हो सकती हैं। अतः एक देश के भीतर भी वस्तुओं का उत्पादन समान दशाओं में नहीं किया जाता है। देश के विभिन्न भागों के प्राकृतिक साधन भी अलग-अलग होते हैं, जिनके कारण विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह दशा बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा से मिलती है।

(४) विभिन्न मुद्रा प्रणालियों के आधार पर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है—प्राचीन विचारधारा में विभिन्न देशों

3 Regions and nations specialise and trade with each other for the same reasons that individuals specialise and trade. Some are better fitted by temperament for one work than another, one is a better gardner, the other a better teacher, while the third proves an excellent doctor and so on. Thus, the gain from specialisation is clear. Even if every individual were equally alike in ability, it would pay to specialise." —Ohlin.

मे मुद्राओं की भिन्नता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता बतलाई गई है। यद्यपि विभिन्न देशों की मुद्राओं में कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से अलग करने के लिए काफी नहीं है। एक देश के भीतर भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मुद्राएँ हो सकती हैं और इस प्रकार आन्तरिक व्यापार में भी मुद्राओं को बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका उदाहरण कुछ समय पूर्व भारत में ही मिलता था जबकि भारत और हैदराबाद स्टेट में अलग-अलग मुद्राएँ चलती थी। अतः मुद्राओं की भिन्नता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त मुद्राओं की भिन्नता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से पृथक् नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर उन मुद्राओं की आन्तरिक क्रय-शक्ति से सम्बन्धित होती है और उस पर मूल्य लागत सम्बन्धों का पूरा प्रभाव पड़ता है।

इन सब कारणों से यह विदित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार से पृथक् नहीं किया जा सकता है। दोनों प्रकार के व्यापार में कोई आधार-भूत अन्तर न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सामान्य मूल्य के सिद्धान्त की सहायता से समझा जा सकता है और उसके लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। ओहलिन (Ohlin) इसी विचारधारा के मानने वाले हैं और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से भिन्न किये जाने का विरोध किया है। उनके अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशिष्ट रूप है।"^४ सामान्य माग और पूर्ति का विश्लेषण, जिसका प्रयोग अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार (Inter-regional Trade) को समझने के लिए किया जाता है, बिना किसी विशेष संशोधन के अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ओहलिन ने सामान्य सतुलन के सिद्धान्त का विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में कोई मौलिक भेद नहीं है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि, "सबसे महत्वपूर्ण भेद जो किया जाना चाहिए, वह अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में नहीं बल्कि एक बाजार तथा अनेक बाजारों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने वाले मूल्य सिद्धान्तों में है।"^५

4 "International trade is only a special case of inter-regional trade."

—Ohlin.

५ "The most important distinction to be made is not between the theory of international commerce and that of national commerce but between a theory of prices for a single market and a theory of prices that is valid for several markets."

—Ohlin.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है ?

(Why International Trade Arise ?)—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उत्पन्न होने का मुख्य कारण सत्तार के विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों का असमान वितरण है। विभिन्न देशों का जलवायु तथा उनके प्राकृतिक साधन अलग-अलग होते हैं। कुछ देशों का जलवायु और प्राकृतिक साधन एक प्रकार की वस्तुओं की उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होते हैं तथा अन्य देशों में कुछ दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने की अच्छी सुविधाएँ हो सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों के बीच धूम तथा पूँजी की मात्रा भी अलग-अलग हो सकती है। कुछ देशों के पास पूँजीगत वस्तुएँ अधिक मात्रा में होती हैं तथा कुछ के पास बहुत कम मात्रा में ऐसे साधन उपलब्ध होने हैं। उत्पत्ति के साधनों के असमान वितरण के कारण वस्तुओं की उत्पादन लागतों में अन्तर पैदा होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विनिष्ठीकरण का आधार है। प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने यहाँ उत्पन्न करता है जिनका उत्पादन करने में उसे कम लागत आती है और अन्य वस्तुओं को दूसरे देशों में मंगा लेता है। इस प्रकार के भौगोलिक धूम-विभाजन से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पैदा होता है। यदि सभी देशों का जलवायु तथा उनके प्राकृतिक साधन एक प्रकार के होते तो वस्तुओं की उत्पादन लागतें समान रहती और किसी प्रकार का विनिष्ठीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव न हो सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में अन्तर के कारण उत्पन्न होता है और लागतों में अन्तर इसलिए होना है क्योंकि विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधन असमान रूप से बँटे हुये हैं। जब तक लागतों में अन्तर रहता है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होना रहता है।

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (Theory of Comparative Costs)—

सिद्धान्त का प्राचीन रूप (Classical Theory)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रयोग सर्वप्रथम रिकार्डो (Ricardo) के द्वारा किया गया। उनके पश्चात् मिल (Mill), कैरनीज (Cairnes) तथा बैस्टेबिल (Bastable) ने इस सिद्धान्त में कुछ संशोधन तथा महत्वपूर्ण सुधार किये। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में टाजिग (Tausig) तथा जर्मन अर्थशास्त्री हैबरलर (Haberler) ने प्राचीन सिद्धान्त के दोषों को दूर करके उसे वर्तमान रूप प्रदान किया है। रिकार्डो ने सर्वप्रथम यह बतलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में तुलनात्मक अन्तर के कारण उत्पन्न होता है। उनका विचार था कि एक देश में उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता होने के कारण लाभ का प्रश्न समान होने की प्रवृत्ति रखता है किन्तु विभिन्न देशों में ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धूम तथा पूँजी की गतिशीलता का न होना है। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि एक देश को कई वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो सकता है किन्तु वह केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत

प्रधिक लाभ होता है और अन्य वस्तुओं का उत्पादन वह दूसरे देशों पर छोड़ देता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बतलाया कि पुर्तगाल (Portugal) में कपड़ा और शराब दोनों की उत्पादन लागत इंग्लैंड की अपेक्षा कम आती है किन्तु वह केवल शराब के पैदा करने में विशिष्टीकरण करता है और कपड़ा इंग्लैंड से मगाता है क्योंकि उसे शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है। इस उदाहरण के द्वारा रिकार्डों ने यह बतलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार लागतों में तुलनात्मक अन्तर का होना है। उनका यह विचार भी था कि तुलनात्मक लागतों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में विनिमय दरों की सीमाएँ निर्दिष्ट होती हैं।

सिद्धान्त की व्याख्या (Statement of the Theory) —

तुलनात्मक लागत के इस सिद्धान्त के अनुसार तुलनात्मक लागतों में अन्तर होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। वस्तुओं की उत्पादन लागत में तुलनात्मक अन्तर होते ही दो या इसमें अधिक देशों के बीच विदेशी व्यापार होने लगता है। प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करता है जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होता है और उस वस्तु को अन्य देशों से मगाता है जिसकी उत्पादन लागत उस देश में अधिक आती है। एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने से लाभ होगा जिसकी उत्पादन लागत में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है और इस वस्तु को वह दूसरी ऐसी वस्तु के बदले में निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ कम है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करने की प्रवृत्ति रखेगा जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है अथवा तुलनात्मक हानि कम है और उस वस्तु का आयात करने की प्रवृत्ति रखता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ कम होता है अथवा तुलनात्मक हानि अधिक रहती है। इस प्रकार के विशिष्टीकरण से दोनों देशों को लाभ होता है तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ता है।

(यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा दोनों वस्तुओं का उत्पादन सस्ता कर सकता है और इस प्रकार उसे दोनों वस्तुओं के सम्बन्ध में दूसरे देश के ऊपर निरपेक्ष लाभ (Absolute Advantage) है किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि वह इन दोनों में से किसी एक को दूसरी की अपेक्षा अधिक सस्ती पैदा करता है)। दूसरे देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि (Absolute Disadvantage) हो सकती है किन्तु यह हानि एक वस्तु के सम्बन्ध में अधिक तथा दूसरी के सम्बन्ध में कम हो सकती है। ऐसी दशा में पहला देश उस वस्तु के उत्पादन में अपने साधनों को लगायेगा जिसके उत्पन्न करने में उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है और दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक हानि कम है। इस प्रकार की दशाओं में ही अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों का अन्तर

(Differences in Costs in International Trade) —

विभिन्न देशों में वस्तुओं की उत्पादन लागतों में तीन प्रकार का अन्तर हो सकता है—

(अ) लागतों में निरपेक्ष अन्तर (Absolute Difference in Cos's) ।

(ब) लागतों में समान अन्तर (Equal Difference in Costs)

(स) लागतों में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Difference in Costs)

लागतों में निरपेक्ष अन्तर (Absolute Difference in Costs)— दो देशों के बीच लागतों में निरपेक्ष अन्तर तब होता है जब उनमें से एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की अपेक्षा काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है। ऐसी स्थिति में पहले देश को दूसरे देश पर उस वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ रहता है। इसी प्रकार दूसरे देश को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो सकता है। दोनों देश उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसे वे अपेक्षाकृत उत्पन्न कर सकते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

भारत में { १५ दिन का श्रम ५० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम १०० मीटर कपड़ा पैदा करता है।

पाकिस्तान में { १५ दिन का श्रम १०० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम ५० मीटर कपड़ा पैदा करता है।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत को कपड़े के उत्पादन में पाकिस्तान पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त है क्योंकि भारत में कपड़े की उत्पादन लागत पाकिस्तान की अपेक्षा आधी है। इसी प्रकार पाकिस्तान को गेहूँ के उत्पादन में भारत पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त है क्योंकि वहाँ पर भारत की तुलना में गेहूँ की उत्पादन लागत आधी आती है। ऐसी दशा में दोनों देशों में वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण होगा और भारत के द्वारा कपड़े का उत्पादन किया जायगा तथा पाकिस्तान गेहूँ का उत्पादन करेगा। भारत पाकिस्तान को कपड़ा देकर गेहूँ प्राप्त करेगा और पाकिस्तान अपने गेहूँ के बदले में कपड़ा भारत से लेगा। ऐसा करने में दोनों देशों को लाभ होगा। उत्पादन लागतों के आधार पर भारत में गेहूँ और कपड़े का विनिमय अनुपात (Exchange ratio) १ : २ तथा पाकिस्तान में यह अनुपात २ : १ अर्थात् भारत में १ मीटर कपड़े के बदले में २ क्विन्टल गेहूँ प्राप्त होता है किन्तु पाकिस्तान से एक मीटर कपड़े के बदले में २ क्विन्टल गेहूँ प्राप्त किया जा सकता है। अतः भारत के लिए अपने यहाँ गेहूँ पैदा न करके उसे पाकिस्तान से मंगाना लाभपूर्ण है। इसी प्रकार पाकिस्तान अपने एक क्विन्टल गेहूँ के बदले में २ मीटर कपड़ा भारत से प्राप्त कर सकता है। जबकि उसे अपने देश में १ क्विन्टल गेहूँ के बदले में २ मीटर कपड़ा मिल सकता है। ऐसी दशा में विशिष्टीकरण दोनों देशों के लिए लाभपूर्ण है। अतः लागतों में निरपेक्ष अन्तर होने की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।

लागतों में समान अन्तर (Equal Difference in Costs)— दो देशों के बीच समान अन्तर तब होता है जब दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन लागतों का अनुपात समान होता है। ऐसी दशा में एक देश दूसरे देश की अपेक्षा दोनों ही वस्तुओं को कम लागत पर उत्पन्न करता है किन्तु उसे दोनों वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन लागत सम्बन्धी लाभ बराबर रहता है। दूसरे देश में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक आती है और उसे दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान हानि रहती है। लागतों में समान अन्तर होने की दशा में किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है क्योंकि विनिर्दिष्टकरण से किसी भी देश को लाभ नहीं मिलता है। निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है।

भारत में { १५ दिन का श्रम ८० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम १२० मीटर कपड़ा पैदा करता है।

पाकिस्तान में { १५ दिन का श्रम ५० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम ७५ मीटर कपड़ा पैदा करता है।

लागतों में इस प्रकार का अन्तर होने की दशा में व्यापार में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की लागतों का अनुपात २ : ३ है। भारत में १ क्विन्टल गेहूँ के बदले में १२ मीटर कपड़ा मिलता है और पाकिस्तान में भी १ क्विन्टल गेहूँ के बदले में १२ मीटर कपड़ा ही मिल सकता है। भारत को कपड़े में विनिर्दिष्टकरण करने में कोई लाभ नहीं है और इसी प्रकार पाकिस्तान को गेहूँ पैदा करने में कोई लाभ नहीं हो सकता है। अतः लागतों में समान अन्तर होने की दशा में किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव नहीं है।

लागतों में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Difference in Costs)— लागतों में तुलनात्मक अन्तर तब होता है जब एक देश में दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होनी है किन्तु दोनों में से एक को वह दूसरी की अपेक्षा अधिक सहनी उत्पन्न कर सकता है। दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं को अधिक लागत पर पैदा करता है किन्तु दोनों में से एक के उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत हानि कम रहती है। लागतों में तुलनात्मक अन्तर होने की दशा में ही अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है क्योंकि लागतों में निरपेक्ष अन्तर बहुत कम मिलता है तथा वह भ्रष्टाचार होता है। निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है—

भारत में { १५ दिन का श्रम १०० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम १०० मीटर कपड़ा पैदा करता है।

पाकिस्तान में { १५ दिन का श्रम ८० क्विन्टल गेहूँ पैदा करता है।
१५ दिन का श्रम ४० मीटर कपड़ा पैदा करता है।

इस स्थिति में भारत को पाकिस्तान की अपेक्षा गेहूँ तथा कपड़ा दोनों के उत्पादन में निपेक्ष लाभ है किन्तु यह लाभ कपड़ा पैदा करने में अधिक है और गेहूँ पैदा करने में कम। पाकिस्तान को दोनों वस्तुओं के पैदा करने में हानि है किन्तु गेहूँ पैदा करने में कपड़े की अपेक्षा यह हानि कम है। अतः भारत कपड़ा पैदा करने में विशिष्टीकरण करेगा और गेहूँ पाकिस्तान से मगायेगा। पाकिस्तान अपने समस्त माधनों को गेहूँ पैदा करने में लगायेगा और कपड़े का आयात भारत से करेगा। इस प्रकार के विशिष्टीकरण में दोनों ही देशों को लाभ होगा। भारत में लागतों का अनुपात १ : १ है तथा पाकिस्तान में २ : १ है। लागतों के अनुपात में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों के बीच लाभपूर्ण व्यापार हो सकता है। भारत में १ मीटर कपड़े के बदले १ क्विन्टल गेहूँ मिलता है किन्तु पाकिस्तान में १ मीटर कपड़े के बदले में २ क्विन्टल गेहूँ मिल सकता है। अतः भारत के लिए यह लाभपूर्ण है कि वह अपने माधनों को केवल कपड़े के उत्पादन में लगाये और प्रतिरिक्त कपड़े के बदले में पाकिस्तान से गेहूँ आयात कर ले। भारत के लिए यह विनिमय तब तक लाभपूर्ण रहेगा जब तक उसे १ मीटर कपड़े के बदले में १ क्विन्टल गेहूँ से अधिक मिलता रहता है। पाकिस्तान को भी गेहूँ पैदा करके भारत को भेजने में लाभ है क्योंकि पाकिस्तान में एक क्विन्टल गेहूँ २ मीटर कपड़े के साथ बदला जाता है जबकि भारत से वह एक क्विन्टल गेहूँ के बदले में १ मीटर कपड़ा प्राप्त कर सकता है। पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार करने में तब तक लाभ है जब तक उसे १ क्विन्टल गेहूँ के बदले में २ मीटर कपड़े से अधिक मिलता रहता है। अतः लागतों में तुलनात्मक अन्तर होने की दशा में लाभपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव है।

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का आधुनिक रूप

(Modern Theory of Comparative Costs)—

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार समस्त व्यापार लागतों में अन्तर होने के कारण उत्पन्न होता है। लागतों में निपेक्ष अन्तर होने की दशा में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है किन्तु आज्ञान होने वाला अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन लागतों में तुलनात्मक अन्तर होने के कारण होता है। जब तक लागतों में तुलनात्मक अन्तर होता है तब तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहता है किन्तु तुलनात्मक लाभ समाप्त होते ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बन्द हो जाता है। वर्तमान मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था में लागतों का विश्लेषण धन की मात्रा के आधार पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का विश्लेषण मौद्रिक लागतों (Money Costs) के आधार पर किया है। वर्तमान सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार धन लागतों में तुलनात्मक अन्तर से निश्चित नहीं होता है बल्कि वह मुद्रा कीमतों में निपेक्ष अन्तर से निश्चित होता है। लागतों के तुलनात्मक अन्तर को आसानी से कीमतों के निपेक्ष अन्तर

में बदला जा सकता है और ऐसा करने से विनिमय सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर दिये गए तुलनात्मक लागत के अन्तर के उदाहरण को लेकर इस सिद्धान्त का मुद्रा के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। इस उदाहरण के अन्तर्गत भारतवर्ष में १५ दिन का श्रम १०० क्विन्टल गेहूँ अथवा १०० मीटर कपड़ा पैदा करता है और पाकिस्तान में १५ दिन का श्रम ८० क्विन्टल गेहूँ या ४० मीटर कपड़ा उत्पन्न करता है। यदि भारत में श्रम का मूल्य ३) ६० तथा पाकिस्तान में २) ६० प्रतिदिन लगाया जाये तो दोनों देशों में इन वस्तुओं की प्रति इकाई मुद्रा लागत निम्न प्रकार होगी—

देश	कुल मजदूरी	कुल उत्पादन	मौद्रिक लागत प्रति इकाई रुपये में
भारत	४५ रुपये ४५ रुपये	१०० क्विन्टल गेहूँ १०० मीटर कपड़ा	०.४५ प्रति क्विन्टल ०.४५ प्रति मीटर
पाकिस्तान	३० रुपये ३० रुपये	८० क्विन्टल गेहूँ ४० मीटर कपड़ा	०.३८ प्रति क्विन्टल ०.७५ प्रति मीटर

भारत में कपड़े की लागत पाकिस्तान की अपेक्षा कम है—भारत में वह ०.४५ रुपये प्रति मीटर है जबकि पाकिस्तान में ०.७५ रुपये प्रति मीटर है। किन्तु गेहूँ की मुद्रा-लागत पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा कम है—भारत में वह ०.४५ रुपये प्रति क्विन्टल है, जबकि पाकिस्तान में केवल ०.३८ रुपये प्रति क्विन्टल है। इससे स्पष्ट है कि भारत कपड़ा पैदा करेगा और पाकिस्तान गेहूँ के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। इस विश्लेषण से भी हम तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुत्प ही परिणामों पर पहुँचते हैं।

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधारभूत सिद्धान्त है—

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतो में तुलनात्मक अन्तर के कारण ही पैदा होता है। निषेध अन्तर की दशा में बहुत कम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तथा वह अस्थायी हुआ करता है। लागतो में समान अन्तर की दशा में किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतो में तुलनात्मक अन्तर की दशा में ही होता है। जैसे ही लागतो में तुलनात्मक अन्तर उत्पन्न होता है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगता है और यह व्यापार तब तक होता रहता है जब तक एक देश को दूसरे देश की अपेक्षा वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ रहता है। लागतो में तुलनात्मक अन्तर के समाप्त होते ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बन्द हो जाता है।

इस प्रकार समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतो में तुलनात्मक अन्तर का होना है और इसीलिए तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधारभूत सिद्धान्त माना जाता है।)। केवल इस सिद्धान्त के द्वारा ही हम यह बतला सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है तथा वह कब तक होता रहता है और विभिन्न देश किन-किन वस्तुओं का निर्यात तथा आयात करेंगे।

यद्यपि वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं और उसका वर्तमान रूप बहुत कुछ बदल गया है किन्तु फिर भी सिद्धान्त का आधार वही है। आधुनिक अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में तुलनात्मक अन्तर के कारण होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्लेषण में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का आज भी वही महत्व है जो पहले था। संशोधनों के द्वारा उसके दोषों को दूर किया गया है किन्तु सिद्धान्त के मूल आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का वह एकमात्र सिद्धान्त है। अतः तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधारभूत सिद्धान्त कहा जा सकता है।)

क्लासिकल सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of the Classical Theory)—

बहुत समय पहले तक रिकार्डों और मिल द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के रूप में पूर्णतया स्वीकार किया जाता था। किन्तु आरम्भ में ही इस सिद्धान्त का आधार कमजोर था क्योंकि वह बहुत सी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वर्तमान अर्थशास्त्री ओह्लिन (Ohlin) तथा फ्रैंक ग्राहम (Frank Graham) ने अपनी आलोचनाओं के द्वारा इस सिद्धान्त की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है। क्लासिकल सिद्धान्त की आलोचनाएँ मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर की गई हैं—

(१) मूल्य के अर्थ सिद्धान्त पर आधारित होना क्लासिकल सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस सिद्धान्त में लागतों की तुलना करने के लिए अर्थ-लागतों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण सिद्धान्त का आधार अर्थशास्त्रिक हो गया है। मूल्य के अर्थ सिद्धान्त का खण्डन बहुत पहिले ही किया जा चुका है इसलिए उसके आधार पर वस्तुओं की उत्पादन लागत की नापना वैज्ञानिक नहीं है। उत्पादन लागत में अर्थ के अतिरिक्त पूँजी, भूमि, साहस आदि अन्य उत्पत्ति के साधनों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अर्थ की विभिन्न इकाइयों में एकरूपता न होने के कारण भी उसे लागतों की नापने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। आलोचकों के अनुसार मुद्रा लागत ही विभिन्न वस्तुओं की लागतों की तुलना करने का सही आधार हो सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का विस्लेषण वस्तुओं की कीमतों के रूप में किया जाना चाहिए।

(२) सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि वह उत्पत्ति की लागतों को निश्चित मान लेता है। (क्लासिकल सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि वस्तुओं का उत्पादन बबल उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) के अनुसार होता है। इस प्रकार की मान्यता बिल्कुल अवास्तविक है। क्लासिकल सिद्धांत की मान्यता के अनुसार दोनों देशों में लागतों का अनुपात निश्चित रहता है चाहे वस्तुओं के उत्पादन में कितना भी अधिक विशिष्टीकरण क्यों न किया जाये ? उपर्युक्त उदाहरण में भारत में कपड़े की उत्पादन लागत तथा पाकिस्तान में गेहूँ की उत्पादन लागत निश्चित रहनी चाहिए और उनकी लागतों के अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह सम्भव हो सकता है कि पाकिस्तान में अधिक गेहूँ पैदा किये जाने पर उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Return) के कारण गेहूँ की लागत बढ़ जाये। इसके विपरीत भारत में कपड़े की लागत उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Return) के कार्यशील होने के कारण गिर सकती है। अतः एक सीमा के पश्चात् दोनों देशों में उत्पादन लागत के अनुपात में परिवर्तन होने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से प्राचीन सिद्धांत कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता है।

(३) क्लासिकल सिद्धांत का एक और दोष यह है कि वह परिवहन लागतों की उपेक्षा करता है। ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ हैं जिनके सम्बन्ध में परिवहन लागत उनकी उत्पादन लागत से भी अधिक हो सकती है। ऐसी स्थिति में परिवहन लागत को भी वस्तु की लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु का आयात अथवा निर्यात तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक दोनों देशों में उसकी उत्पादन लागत में अन्तर उसकी परिवहन लागत से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में हेबरलर (Haberler) का विचार है कि, “कसी वस्तु का निर्यात अथवा आयात तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि दो देशों में उसकी उत्पादन लागत का अन्तर उसके एक देश से दूसरे देश को भेजने के यातायात व्यय से अधिक न हो। किसी देश की निर्यात क्षमता पूर्णतया उसकी तुलनात्मक लागत पर निर्भर नहीं होती है बल्कि यह परिवहन लागत पर भी निर्भर करती है।”^६

(४) यह सिद्धांत इसलिए भी दोषपूर्ण है क्योंकि वह दोनों देशों के द्वारा पूर्ण विशिष्टीकरण की सम्भावना प्रस्तुत करता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तुलनात्मक लागतों में अन्तर होने की दशा में भी यह आवश्यक नहीं है कि दोनों

6 “A good will not be exported or imported unless the difference in its cost of production between the two countries exceed the cost of transporting it from one country to the other. The export capacity of a country does not depend, solely upon its comparative cost of production, it depends also upon the cost of transport.”

देश एक-एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विनिष्ठीकरण कर लें। फ्रैंक ग्राहम (Frank Graham) के अनुसार यदि व्यापार करने वाले देशों में एक देश छोटा है और दूसरा बड़ा है तो ऐसी स्थिति में छोटा देश तो तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विनिष्ठीकरण करेगा किन्तु बड़े देश के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि यदि वह अपने समस्त साधन एक वस्तु के उत्पादन में लगा देना है, तो वह उत्पादित वस्तु की इतनी बड़ी मात्रा को छोटे देश में नहीं बेच सकेगा। इसके प्रतिरिक्त उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा इसलिए पैदा करनी पड़ेगी क्योंकि वह अपनी समस्त आवश्यकता उस छोटे देश से आयात करके पूरी नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में बड़े देश के लिए दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना अनिवार्य हो जाता है।

(५) क्लासिकल सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि वह उत्पत्ति के साधनों को आन्तरिक क्षेत्र में पूर्णतया गतिशील तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्णतया अगतिशील मानना है। यह मान्यता विल्कुल अवास्तविक है क्योंकि आन्तरिक क्षेत्र में भी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव हो सकता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे कुछ सीमा तक गतिशील हो सकते हैं। आन्तरिक क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता न होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि एक ही देश में विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी व व्याज की दरों में भिन्नता पाई जाती है। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पत्ति के साधन पूर्णतया अगतिशील नहीं होते हैं। श्रमिक एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं तथा पूँजी का आयात तथा निर्यात भी किया जाता है।

(६) विभिन्न देशों के द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिनके पैदा करने में उन्हें प्राकृतिक लाभ नहीं होता है। इस प्रवृत्ति के कारण भी तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित हो गया है। आजकल सैनिक कारणों से तथा आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश उन वस्तुओं का उत्पादन भी स्वयं करते हैं जिन्हें वे अन्य देशों से सस्ती कीमत पर आयात कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के द्वारा नहीं समझा जा सकता है।

(७) बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin) के अनुसार क्लासिकल सिद्धान्त विश्लेषण का एक भद्दा तथा खतरनाक यन्त्र प्रस्तुत करता है।^७ यह सिद्धान्त इसलिए अवास्तविक है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न देशों में पूर्ण उत्पादन लागतों के अन्तर के आधार पर विश्लेषण नहीं किया जाता है। यह सिद्धान्त इस बात को भी नहीं बताता है किसी देश में वस्तु के उत्पादन का सस्ता होना क्यों

7 The theory has been criticised by Ohlin as a clumsy and dangerous tool and that it is unduly cumbersome and unreal.

तक कम मजदूरी, कम व्यय, कम परिवहन तथा अन्य प्रकार के व्यय कम होने के कारण होता है। ग्रोहलिन के अनुसार यह सिद्धान्त इसलिए सतर्नाक है क्योंकि वह निश्चित रूप से केवल दो देशों तथा दो वस्तुओं के आधार पर विश्लेषण करता है और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्षों को निःसंकोच वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर देता है जिनमें बहुत-से देश तथा बहुत-सी वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं।

सिद्धान्त में आधुनिक सुधार (Modern Refinements in the Theory)—

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त में तीन महत्वपूर्ण सुधार किये हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लाभ को निकालने के लिए वस्तुओं की उत्पादन लागत को श्रम के रूप में नापा या किन्तु मूल्य के श्रम सिद्धान्त को अब नहीं माना जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का विश्लेषण सीमान्त उत्पादन लागतों के आधार पर किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं की उत्पादन लागत को मुद्रा के रूप में नापा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने सिद्धान्त का विश्लेषण करने में अवसर लागतों (Opportunity costs) का प्रयोग भी किया है।

(२) प्राचीन सिद्धान्त में यह मान लिया गया था कि वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अनुसार ही होता है किन्तु वर्तमान सिद्धान्त में यह बतलाया गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) का तुलनात्मक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करने से उसकी सीमान्त उत्पादन लागत घटती है तो तुलनात्मक लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति रखेगा किन्तु यदि अधिक उत्पादन से लागत बढ़ती है तो तुलनात्मक लाभ कम हो जायेगा तथा समाप्त होने की प्रवृत्ति रखेगा।

(३) प्राचीन सिद्धान्त में विनिमय की शर्तें (Terms of Exchange) किस प्रकार निश्चित होती हैं—इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया गया था। आधुनिक लेखकों ने सापेक्षिक माग के सिद्धान्त (Theory of Reciprocal Demand) का प्रतिपादन किया है जिसके द्वारा व्यापार की शर्तें निश्चित होती हैं। किसी देश की माग दूसरे देश की वस्तु के लिए जितनी अधिक तीव्र होती है, व्यापार की शर्तें उतनी ही उसके विपक्ष में होती हैं। यदि किसी देश की दूसरे देश की वस्तु के लिए माग की तीव्रता कम है तो व्यापार की शर्तें उसके पक्ष में होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ

(Advantages of International Trade)—

प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार करने वाले दोनों पक्षों को लाभ होता है। विदेशी व्यापार निर्यात तथा आयात करने वाले

दोनों ही देशों के लिए लाभपूर्ण रहता है और इसके साथ ही समस्त नसार को भी इस प्रकार के व्यापार से लाभ हुआ करता है। इसलिए एडम स्मिथ (Adam Smith) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें दोहरा लाभ प्राप्त होता है।"⁸ वह आयात तथा निर्यात करने वाले देशों के लिए तो लाभपूर्ण होता ही है किन्तु उनके कारण उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ जाने से समस्त समार को भी लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों को लगभग वे सब लाभ प्राप्त होते हैं जो किसी देश के भीतर उद्योगों के स्थानीयकरण से प्राप्त किये जा सकते हैं। विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं—

(१) प्रादेशिक श्रम विभाजन के लाभ—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण

प्रादेशिक श्रम-विभाजन (Territorial Division of Labour) से प्राप्त होने वाले सभी लाभ मिल जाते हैं। विभिन्न देशों के द्वारा केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके उत्पादन में उन्हें अधिकतम योग्यता अथवा कुशलता प्राप्त होती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था में प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसे वह अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती बना सकता है अथवा जिनके उत्पादन के लिए उस देश में सबसे उपयुक्त दशायें पाई जाती हैं। इस प्रकार के श्रम-विभाजन तथा विशिष्टीकरण का परिणाम यह होता है कि कुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से निकल जाते हैं और वस्तुओं का उत्पादन केवल कुशल उत्पादकों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी दशा में वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम होता है और उनकी उत्पादन-लागत भी कम आती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार मात्र है और उसमें उसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जैसे आन्तरिक विशिष्टीकरण से प्राप्त किये जाते हैं। एल्सवर्थ (Ellsworth) के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल व्यापार का देश की सीमाओं के बाहर विस्तार है। इसलिए वह विशिष्टीकरण तथा उसमें प्राप्त होने वाले लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करता है। जैसे स्थानीय व्यापार व्यक्तियों की विशेष योग्यता के कारण लाभ प्राप्त करने की दशायें उत्पन्न करता है ठीक उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश के लिए अन्य देशों की विशेष योग्यता से लाभ प्राप्त करना तथा आन्तरिक साधनों का अधिक कुशलता के साथ शोषण करना सम्भव करता है।"⁹

8 "International trade is twice blessed "

—Adam Smith

9 "International trade is simply the extensor of trade beyond the boundaries of a nation. It, therefore, extends the range of specialisation and the gains derivable thereupon. Just as local trade enables advantage to be taken of the special aptitudes of individuals, so international trade makes it possible for each country to draw upon special aptitudes of other countries and to utilise its own resources more efficiently "

—Ellsworth The International Economy, P 141

(२) उपभोक्ताओं को सस्ते बाजार में सामान खरीदने की सुविधायें प्राप्त होती हैं—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ताओं के लिए भी लाभपूर्ण होता है क्योंकि वे विदेशी व्यापार की सहायता से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ सस्ते से सस्ते बाजार में खरीद सकते हैं। प्रायः विदेशों से वे ही वस्तुएँ मगाई जाती हैं जिनकी उत्पादन-लागत देश में अधिक आती है और जिन्हें अन्य देशों में कम मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध की जा सकती है जिनसे उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग करना सम्भव हो जाता है जो उनके देश में पैदा नहीं की जाती हैं। इस प्रकार उपभोग में विविधता उत्पन्न होती है जिससे उपभोक्ताओं को बहुत लाभ प्राप्त होता है।

(३) मूल्यों में अधिक स्थिरता आती है—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं की पूर्ति का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिसके कारण माग में वृद्धि होने पर वस्तुओं को विदेशों से भगाया जा सकता है और इस प्रकार पूर्ति बढ़ जाने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने पाती है। इसी प्रकार यदि देश में किसी वस्तु की पूर्ति उसकी माग की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो उसे विदेशों को भेजकर उसके मूल्य को गिरने से रोका जा सकता है। वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के द्वारा विभिन्न देशों में मूल्यों के समान रहने की प्रवृत्ति होती है और मूल्यों में होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो जाते हैं।

(४) आर्थिक सकटों की तीव्रता को कम दिया जा सकता है—विदेशी व्यापार के द्वारा समस्त ससार एक इकाई बन गया है। यदि कोई देश आर्थिक सकट में होता है तो वह अन्य देशों से माल मगाकर इस सकट की तीव्रता को कम कर सकता है। यही कारण है कि वर्तमान ससार में आर्थिक सकट बहुत कम हो गये हैं क्योंकि एक देश खाद्य सामग्री की आयात के द्वारा अनाज की कमी को दूर कर लेता है और इस प्रकार के सकट से बच जाता है।

(५) उत्पादन सम्बन्धी मुद्धारों को प्रोत्साहन मिलता है—अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक देश के उत्पादक अपनी उत्पादन प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और कोई भी देश दूसरे देशों की तुलना में पीछे नहीं रहना चाहता है। उत्पादन विधि में सुधार के द्वारा प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को कम मूल्य पर पैदा करने का प्रयत्न करता है जिससे वह विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन विधियों में निरन्तर सुधार होता रहता है और उद्योगों के प्रबन्ध की कुशलता में भी उन्नति होती है। विदेशों से वस्तुओं का आयात होने से देश के भीतर औद्योगिक एकाधिकार स्थापित नहीं होने पाते हैं जिसमें प्रतियोगिता बढ़ती है और उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

(६) आर्थिक विकास में सहायता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा एक देश को अपने आर्थिक विकास में वही सहायता मिलनी है। विदेशी व्यापार की सहायता से आवश्यक वच्चे माल, मशीनों तथा टैक्नीकल योग्यता को विदेशों से मंगाकर देश का औद्योगीकरण किया जा सकता है। जिन देशों के पास वच्चे माल की कमी है किन्तु उत्पत्ति की अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं वे विदेशों से वच्चा माल मंगा कर उद्योग-धन्धों को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता देता है।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है—विदेशी व्यापार समार के विभिन्न देशों में सम्पर्क स्थापित करता है जिनमें सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति होती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परस्पर निर्भर अर्थ-व्यवस्थाओं को स्थापित करता है जिसके कारण विभिन्न देशों के आर्थिक हित एक दूसरे के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं और उनमें आपस में महानुभूति तथा स्नेह की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि विदेशी व्यापार युद्ध के भय को कम करके विश्व-शांति की स्थापना में सहयोग देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ

(Disadvantages of International Trade)—

उपयुक्त लाभों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानियाँ भी हैं जिनके कारण उनके अच्छे प्रभाव बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं। विदेशी व्यापार की हानियाँ इस प्रकार हैं—

(१) विदेशी प्रतियोगिता के कारण देश के उद्योग-धन्धे नष्ट हो जाते हैं—अनियन्त्रित विदेशी व्यापार देश के उद्योग-धन्धों के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते सामान का आयात किया जाता है तो घरेलू उद्योग-धन्धे विदेशी प्रतियोगिता के कारण बन्द हो जाते हैं और बहुत-से श्रमिक तथा पूँजी बेकार हो जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न होने वाली विदेशी प्रतियोगिता में विकसित देशों की तो लाभ होता है किन्तु अविकसित देशों में या तो उद्योग-धन्धे स्थापित ही नहीं होने पाते हैं और या वे स्थापना के कुछ समय पश्चात् नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र विदेशी व्यापार अविकसित देशों के आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न करता है। भारतवर्ष इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(२) अत्यधिक उत्पादन तथा अल्प उत्पादन का मय बढ़ जाता है—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने से वस्तुओं का बाजार इतना अधिक विस्तृत हो जाता है कि उनकी माग का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कमी वस्तुओं का उत्पादन उनकी कुल माग से अधिक हो जाता है और कभी-कभी विनिष्टीकरण के कारण अत्यधिक उत्पादन की सम्भावना बढ़ जाती है क्योंकि उद्योग-धन्धे विश्व बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनके विस्तृत बाजार में वस्तुओं की

भविष्य की माग सही-सही निर्धारित करना सम्भव नहीं होता है जिसके कारण अत्यधिक अथवा अल्प उत्पादन के दोष उत्पन्न होते हैं ।

(३) कच्चे माल का समाप्त हो जाना—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण यह सम्भव हो सकता है कि एक देश विदेशी बाजारों के लिए इतनी अधिक मात्रा वस्तुओं का उत्पादन करने लगे कि उसके कुछ प्राकृतिक साधन समाप्त हो जाएँ । प्रत्येक देश में कुछ ऐसी कच्ची सामग्री होती है जिसका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता है और यदि विदेशी माग को पूरा करने के लिए उसका अधिकाधिक प्रयोग करके उसे समाप्त कर दिया जाता है तो उस देश के दीर्घकालीन आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान पहुँचता है । उदाहरणार्थ यदि कोई देश विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी खनिज सम्पत्ति का इतनी तेजी के साथ प्रयोग करता है कि उनके आवश्यक खनिज पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो उस देश का औद्योगिक भविष्य अन्धकारमय हो जाता है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सम्भव हो सकता है कि देश वर्तमान लाभ के लिए अपने भविष्य के हितों को त्याग दे ।

(४) हानिकारक वस्तुओं का आयात—विदेशी व्यापार के द्वारा कभी-कभी देश में हानिकारक वस्तुओं का आयात होने लगता है और लोग इस प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग के अभ्यस्त हो जाते हैं । नशीली वस्तुओं तथा विलासिता सम्बन्धी सामान का आयात लोगों में बुरी आदत पैदा करता है तथा उनके स्वास्थ्य एवं चरित्र पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है । चीनियों में अफीम खाने की आदत विदेशी व्यापार के कारण ही पड़ी क्योंकि चीन में अफीम का उत्पादन नहीं किया जाता है ।

(५) देश का असन्तुलित आर्थिक विकास—विदेशी व्यापार देश के आर्थिक विकास को असन्तुलित करने की प्रवृत्ति रखता है । केवल उन्हीं उद्योगों का विकास किया जाता है जिनकी वस्तुओं की माग विदेशी बाजार में होती है तथा अन्य प्रकार के उद्योगों का विकास रुक जाता है । तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक देश केवल कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने में ही अपने साधनों को लगा देता है और अन्य वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है । इस प्रकार देश का बहुमुखी (Multi-sided) आर्थिक विकास नहीं हो पाता है । आर्थिक संकट के समय में इस प्रकार के एक-अंगी (One-sided) आर्थिक विकास के भयंकर परिणाम हो सकते हैं । मुख्यतया युद्धकाल में देश में आत्म-निर्भरता के अभाव के कारण विशेष कठिनाई होती है ।

(६) एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाता है—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश को दूसरे देश के ऊपर निर्भर कर देता है जिसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं । इस प्रकार की परस्पर निर्भरता की दशा में यदि किसी देश की अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित हो जाती है अथवा जहाँ पर आर्थिक मन्दी (Depression) या कोई अन्य संकट उत्पन्न हो जाता है तो उसका बुरा प्रभाव अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं

पर भी पड़ता है। कोई भी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को दूसरे देशों के बुरे प्रभावों से नहीं बचा पाता है। सन् १९२६ के आर्थिक संकट काल में यही हुआ और विदेशी व्यापार के द्वारा अवसाद की दशाओं लगभग सभी देशों में फैल गई।

(७) विदेशी व्यापार से कृषि प्रधान देशों को हानि होती है—अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार के साथ केवल औद्योगिक देशों को ही प्राप्त होते हैं और खेतीहर देशों को उससे हानि होती है। इसका कारण प्राथमिक उद्योगों (Primary Industries) में उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना है। जो देश कच्चा माल तथा अनाज विदेशों को भेजते हैं, उनकी उत्पादन लागत अधिक उत्पत्ति करने से बढ़ती जाती है और विदेशी व्यापार से होने वाला लाभ उनके लिए कम हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक देशों में विदेशी व्यापार होने के कारण उत्पादन लागतें गिरती हैं और उनका लाभ बढ़ता है।

(८) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उपनिवेशवाद (Colonialism) को जन्म देता है—विदेशी व्यापार के विकास के साथ साथ हमारे देशों के बाजारों का शोषण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिसके कारण विभिन्न देशों के बीच द्वेष तथा झगड़ा उत्पन्न होते हैं। पिछली दो तीन शताब्दियों में विदेशी बाजारों की खोज के कारण ही उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और बड़े-बड़े राष्ट्रों ने अपनी वस्तुओं के लिए बाजारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अपने अपने उपनिवेशों को स्थापित कर लिया। उपनिवेशवाद ने पूँजीवाद के आधार को दृढ़ किया और इस प्रकार संसार में कुछ देशों के द्वारा अधिकांश देशों का शोषण किया जाने लगा। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार देशों के बीच बुरी प्रतिযোগिता उत्पन्न करके उनके आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ता है तथा विश्व-शांति की संभावना को कम करता है।

यद्यपि विदेशी व्यापार के लाभों के साथ-साथ उसने कुछ हानियाँ भी होती हैं किन्तु नियन्त्रित व्यापार की नीति के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिकांश दोषों को दूर किया जा सकता है और वह विभिन्न राष्ट्रों तथा सम्पूर्ण संसार के लिए लाभदायक हो सकता है। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ होने वाली घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतन्त्र विदेशी व्यापार किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए उसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए। केवल उचित नियन्त्रण के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दोषों को दूर किया जा सकता है और उसे आर्थिक विकास तथा समृद्धि का साधन बनाया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को प्रभावित करने वाली बातें (Factors influencing gain from International Trade) —

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने केवल यही बतलाया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार करने वाले देशों को लाभ होना है किन्तु यह लाभ किन दशाओं में अधिक तथा किन दशाओं में कम होना है इसका विश्लेषण नवोदयक अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। जे० एम० मिल (J. S. Mill) ने प्रथम बार इस प्रश्न की जाँच की

और यह बतलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों को प्राप्त होने वाला लाभ व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) पर निर्भर होता है जो दो देशों की एक दूसरे की वस्तुओं के लिए माग की तीव्रता के अनुसार निश्चित होती है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है और उन तत्वों का विश्लेषण किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को प्रभावित करते हैं। प्रो० टॉजिंग (Taussig) के अनुसार किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ दो बातों पर निर्भर होता है—(१) व्यापार की शर्तें तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को पैदा करने वाले श्रम की कार्य क्षमता।

(१) व्यापार की शर्तें (Terms of Trade)—किसी देश के लिए व्यापार की शर्तें जितनी अधिक अनुकूल होती हैं उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उतना ही अधिक लाभ होता है। व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने की दशा में देश को मिलने वाले लाभ की मात्रा कम हो जाती है। दो देशों के बीच व्यापार की शर्तें उनकी एक दूसरे की वस्तुओं के लिए माग की तीव्रता पर निर्भर होती हैं। किसी देश में विदेशी वस्तुओं के लिए माग की तीव्रता जितनी अधिक होती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उसे उतना ही कम लाभ मिलता है। यदि हमारी वस्तुओं के लिए विदेशियों की माग अधिक तीव्र नहीं है और हमारी माग विदेशी वस्तुओं के लिए अधिक तीव्र है तो ऐसी दशा में हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत कम लाभ मिलेगा। प्रो० टॉजिंग (Taussig) के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सबसे अधिक लाभ उस देश को होता है जिसकी निर्यातों की माग अधिक होती है और आयातों के लिए जिसकी अपनी माग बहुत कम होती है। उस देश को सबसे कम लाभ होता है जिसकी दूसरे देशों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माग अत्यन्त तीव्र होती है।”^{१०}

(२) निर्यात उद्योगों में श्रम की कार्यकुशलता (Efficiency of Labour in Export Industries)—किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ इस बात पर भी निर्भर होता है कि उसके निर्यात उद्योगों में लगे हुए श्रमिक किसी देश में जितने अधिक कार्यकुशल होते हैं उतनी ही इन वस्तुओं की कीमत कम आती है और उस देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। श्रमिकों की कार्यकुशलता में होने वाली प्रत्येक वृद्धि तुलनात्मक लागत के अन्तर को बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ में वृद्धि करती है। प्रो० टॉजिंग का विचार है कि श्रम की कार्यकुशलता बढ़ने पर वस्तुओं की लागत कम होती है, जिसके कारण इनकी वस्तुओं की माग बढ़ती है और देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ बढ़ जाता है।

10 "That country gains most from international trade whose exports are most in demand, and which itself has little demand for the things it imports, i. e. for the exports of other countries. That country gains least which has the most insistent demand for the production of other countries."

परीक्षा प्रश्न

- (१) आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य भेद कीजिए और यह बतलाइये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने से क्या लाभ होते हैं ?
(आगरा बी० ए० १९६५)
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार लाभ होता है ? यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सामदायक है तो देश आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहता है ?
(आगरा बी० ए० १९६४)
- (३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक-व्यय सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । (आगरा बी० ए० १९६०, बिहार बी० ए० १९५८)
- (४) तुलनात्मक व्यय सिद्धान्त का आलोचनापूर्ण विवेचन करिये और यह बताइये कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का यह किस सीमा तक स्पष्टीकरण करता है ? (राजस्थान बी० ए० १९५९, आगरा बी० ए० १९५८)
- (५) "आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य कोई विशेष भेद नहीं है और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी विशेष सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है ।" इस कथन की विवेचना करिये ।
(राजस्थान बी० काम १९५६)



भुगतान सन्तुलन

BALANCE OF PAYMENTS

किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी स्थिति को जानने के लिए उसके 'व्यापार सन्तुलन' (Balance of Trade) अथवा 'भुगतान सन्तुलन' (Balance of Payments) का अध्ययन करना होता है। 'व्यापार सन्तुलन' का विचार काफी प्राचीन है किन्तु उसकी सहायता से हम देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सम्बन्धी स्थिति का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत 'भुगतान सन्तुलन' (Balance of Payments) अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की स्थिति का अध्ययन करने का अधिक वैज्ञानिक तरीका है। इसीलिए आजकल विभिन्न देशों की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन स्थिति को उनके 'भुगतान सन्तुलन' के द्वारा जाना जाता है। भुगतान सन्तुलन का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व 'व्यापार सन्तुलन' तथा 'भुगतान सन्तुलन' के अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।

'व्यापार सन्तुलन' (Balance of Trade)—

साधारण शब्दों में किसी देश का 'व्यापार सन्तुलन' उस देश की आयातों तथा निर्यातों के सम्बन्ध को बतलाता है। वह एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विस्तृत ब्योरा दिया जाता है। व्यापार सन्तुलन में केवल दृश्य निर्यातों तथा आयातों (Visible Exports and Imports) को ही सम्मिलित किया जाता है और अदृश्य निर्यातों तथा आयातों (Invisible Exports and Imports) का उसमें कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। किसी देश का व्यापार सन्तुलन उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है। अनुकूल व्यापार सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) उस स्थिति को कहते हैं जब देश से होने वाली निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से अधिक रहता है। इसके विपरीत व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल जब होता है जब देश में निर्यातों की अपेक्षा अधिक मूल्य के आयात किये जाते हैं। व्यापार सन्तुलन का अनुकूल होना देश की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक समझा जाता था क्योंकि ऐसी दशा में सोना विदेशों से उस देश

में आने लगता था। व्यापार सतुलन का प्रतिकूल होना देश की आर्थिक कमजोरी को बतलाता था क्योंकि इस स्थिति में सोना देश से बाहर जाने लगता था। अनुकूल तथा प्रतिकूल व्यापार सतुलन का विचार काफी प्राचीन है और वह मर्केंटलिस्ट (Mercantilist) विचारधारा से सम्बन्धित रहा है। मर्केंटलिस्ट विचारकों के अनुसार किसी देश को धनी के लिए अपने व्यापार सतुलन को पक्ष में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सोना तथा अन्य धन विदेशों से उस देश में आयेगा। इसके विपरीत, प्रतिकूल व्यापार सतुलन की दशा में देश की अधिक आयातों का भुगतान करने के लिए सोना बाहर भेजना होता है। यद्यपि प्राचीन समय में व्यापार सतुलन को दृष्टि में रखने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था किन्तु ऐसा करना व्यवहारिक दृष्टि में असम्भव था। व्यापार सतुलन का विचार अर्थशास्त्रिक था क्योंकि उसके द्वारा देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अब व्यापार सतुलन के स्थान पर भुगतान सतुलन का प्रयोग किया जाने लगा है।

‘भुगतान सतुलन’ (Balance of Payments)—

‘भुगतान सतुलन’ ‘व्यापार सतुलन’ से पूर्णतया भिन्न होता है। व्यापार सतुलन में तो केवल वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को ही सम्मिलित किया जाता है किन्तु भुगतान सतुलन में व्यापार सतुलन के अनिर्दिष्ट भुगतान की अन्य मदों को भी सम्मिलित किया जाता है। भुगतान सतुलन किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के सम्पूर्ण विवरण को कहते हैं। एक देश को विदेशों से जितने भुगतान लेन होते हैं तथा अन्य देशों को उम जितने भुगतान करने होते हैं, उनके विस्तृत लेखों को ही उस देश का भुगतान सतुलन कहा जाता है। प्रो० बेंहम (Benham) के अनुसार “एक देश का भुगतान सतुलन एक निश्चित काल के भीतर उसके बाकी विश्व के साथ मौद्रिक मोक्ष का रेखा होता है।”¹ जबकि व्यापार सतुलन में केवल दृश्य मदों (Visible Items) को ही सम्मिलित किया जाता है, भुगतान सतुलन में दृश्य तथा अदृश्य (Visible and Invisible) दोनों प्रकार की मदें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार भुगतान सतुलन हमें किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन का सम्पूर्ण ज्ञान कराता है। व्यापार सतुलन का विचार प्रारम्भिक काल में अधिक उपयुक्त था क्योंकि उस समय दो देशों के सम्बन्ध केवल वस्तुओं के आयात तथा निर्यात तक ही सीमित थे किन्तु समय के साथ-साथ विभिन्न देशों के सम्बन्ध अधिक जटिल होने लगे। देशों में अन्य प्रकार के सम्बन्ध स्थापित होने लगे, विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे को ऋण देने लगे, देशों के बीच अन्य प्रकार की सेवाओं का आयात तथा

1 “Balance of Payments of a country is a record of its monetary transactions, over a period, with the rest of the world.”

निर्यात किया जाने लगा और एक देश के लोग दूसरे देशों को आने-जाने लगे जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बीच अन्य प्रकार के नये भुगतान आरम्भ हो गये। व्यापार सन्तुलन में ऋणों की राशि तथा उन पर दिये जाने वाले व्याज, यात्रियों के द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा अन्य प्रकार की अदृश्य मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। इसलिए नई स्थिति में व्यापार सन्तुलन विभिन्न देशों की लेन-देन स्थिति का सम्पूर्ण ज्ञान कराने में असमर्थ था। अतः यह अनुभव किया गया कि हमें केवल किसी देश के व्यापार सन्तुलन का अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उसके सम्पूर्ण लेन-देन का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में 'भुगतान सन्तुलन' ही हमें किसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन स्थिति का अधिक सही ज्ञान करा सकता है।

किसी देश के लिए व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा उसका भुगतान सन्तुलन अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यापार सन्तुलन के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। केवल भुगतान सन्तुलन ही देश की अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन स्थिति का सही-सही ज्ञान हमें करा सकता है। किसी देश का व्यापार सन्तुलन अनुकूल तथा प्रतिवृत्त हो सकता है किन्तु दीर्घकाल में देश के भुगतान सन्तुलन का मतुलित होना आवश्यक है। व्यापार सन्तुलन का अनुकूल अथवा प्रतिवृत्त होना हमें देश की आर्थिक स्थिति के विषय में कुछ नहीं बताता है। यद्यपि प्राचीन समय में व्यापार सन्तुलन का पक्ष में होना देश की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण समझा जाता था किन्तु आजकल यह विश्वास अधिक उपयुक्त नहीं है। व्यापार सन्तुलन का पक्ष में होना देश की आर्थिक उन्नति का चिह्न नहीं होता है। द्वितीय विश्व-युद्ध काल से पूर्व भारत का व्यापार सन्तुलन इङ्ग्लैंड के साथ निरन्तर पक्ष में रहता था किन्तु फिर भी भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ तथा गरीब देश था। व्यापार सन्तुलन पक्ष में होने हुए भी हमारा भुगतान सन्तुलन विपक्ष में रहना था जिसके कारण प्रतिवर्ष काफी भुगतान हमारे देश के ऊपर बाकी होता जाता था। आजकल ऐसे बहुत-से देश हैं जिनका व्यापार सन्तुलन तो प्रतिवृत्त रहता है किन्तु फिर भी वे आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नत हैं। ऐसे देशों का व्यापार सन्तुलन विपक्ष में होते हुए भी भुगतान सन्तुलन उनके अनुकूल होता है। इन देशों की सेवाओं के निर्यात के बदले में तथा विदेशों में विनियोग की हुई पूँजी पर व्याज के रूप में काफी भुगतान प्राप्त होते हैं जिसके कारण इनका व्यापार सन्तुलन प्रतिवृत्त होते हुए भी भुगतान सन्तुलन इनके पक्ष में रहता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि उस देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर निर्भर होती है। भुगतान सन्तुलन पक्ष में होने से देश के ऋण दूसरे देशों पर बाज्रिय होते चले जाते हैं और वह देश ऋणदाता बन जाता है। अमेरिका आजकल इसी स्थिति में है। इसके विपरीत भुगतान सन्तुलन का विपक्ष में होना

देश को ऋणी बनाता है। अतः किसी देश की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके भुगतान समुलन का अध्ययन करना चाहिए।

भुगतान समुलन की मदें (Items of Balance of Payments)—

भुगतान समुलन किसी देश की लेन-देन सम्बन्धी मदों का सम्पूर्ण विवरण होता है। उसमें उन सब मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनके लिए किसी देश को भुगतान देने होने है अथवा लेने होते हैं। भुगतान समुलन बहीखाते के पृष्ठ की तरह का एक विवरण होता है जिनमें विदेशी लेन देन का सम्पूर्ण हिसाब रक्खा जाता है। इस विवरण (Statement) की बाईं ओर दृश्य तथा अदृश्य निर्यातों के मूल्य दिये जाते हैं और दाईं ओर दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के आयातों के मूल्य लिखे जाते हैं। व्यापार समुलन के बाईं ओर दी गई मदों के मूल्यों का कुल योग उस राशि को बनसाना है जो प्रमुख देश को विदेशियों से प्राप्त करनी होती है तथा दाईं ओर दी गई मदों के मूल्यों का योग उस देश के द्वारा विदेशियों को भुगतान की जाने वाली राशि को बनसाना है। बाईं तथा दाईं ओर की राशियों के अन्तर से हम देश के भुगतान समुलन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि भुगतान समुलन के दोनों ओर की राशियाँ बराबर हैं अथवा देश को विदेशियों से उतना ही लेना है जितना कि उन्हें देना है तो ऐसी स्थिति में देश का 'भुगतान समुलन' समुलित होता है। यदि इस विवरण में बाईं ओर का योग दाईं ओर के योग से अधिक होता है तो भुगतान समुलन देश के पक्ष में होता है किन्तु यदि दाईं ओर की राशि बाईं ओर की राशि की अपेक्षा अधिक है तो भुगतान समुलन देश के प्रतिवृत्त होता है। भुगतान समुलन का एक काल्पनिक नमूना नीचे दिया गया है।

भुगतान समुलन

(Balance of Payments)

लेन (Credits)	देन (Debits)
(१) वस्तुओं का निर्यात।	(१) वस्तुओं का आयात।
(२) सेवाओं का निर्यात।	(२) सेवाओं का आयात।
(1) व्यापारिक कम्पनियों की सेवाएँ।	(1) व्यापारिक कम्पनियों की सेवाएँ।
(11) विशेषज्ञ तथा अधिकारियों की सेवाएँ।	(11) विशेषज्ञ तथा अन्य अधिकारियों की सेवाएँ।
(३) विदेशी ऋणों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय।	(३) विदेशी ऋणों व पूँजी का भुगतान तथा उन पर दिया जाने वाला व्याज।

(४) विदेशी यात्रियों तथा विद्यार्थियों द्वारा देश में किया जाने वाला व्यय ।	(४) यात्रियों तथा विद्यार्थियों के द्वारा विदेशों में किया जाने वाला व्यय ।
(५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले मुद्राव्रज, मुद्र-व्यय, दान, दण्ड इत्यादि ।	(५) विदेशों को दिया जाने वाला मुद्राव्रज, दान, दण्ड, मुद्र-व्यय आदि ।
(६) अन्य प्रकार के भुगतान जो विदेशियों से प्राप्त होते हैं ।	(६) अन्य प्रकार के भुगतान जो विदेशियों को किये जाने हैं ।

भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित होने वाली मुख्य-मुख्य मदें निम्नलिखित हैं—

(१) वस्तुओं का आयात तथा निर्यात (Import and Export of Goods)—अधिकांश विदेशी भुगतान वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के कारण उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक देश को उन वस्तुओं के लिए भुगतान करना होता है जिन्हें वह विदेशों से आयात करता है और उसके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के लिए उसे विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है । वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का देश के भुगतान सन्तुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । यदि कोई देश बहुत अधिक आयात करता है और उसकी निर्यातों की मात्रा कम है तो ऐसी दशा में उसके भुगतान सन्तुलन की प्रवृत्ति विपक्ष में होने की होती है । इसके विपरीत निर्यातों का आयातों से अधिक होना भुगतान सन्तुलन को पक्ष में लाने की प्रवृत्ति रखता है ।

(२) सेवाओं का आयात तथा निर्यात (Export and Import of Services)—वस्तुओं के अतिरिक्त प्रत्येक देश विभिन्न प्रकार की सेवाओं का निर्यात तथा आयात भी करता है । निर्यात की गई सेवाओं के बदले में उसे भुगतान प्राप्त होता है तथा आयात की गई सेवाओं के लिए भुगतान देना होता है । इन सेवाओं के अन्तर्गत जहाजी कम्पनियों, बैंक, बीमा कम्पनियों तथा अन्य प्रकार की व्यवसायिक कम्पनियों की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं । यदि कोई देश विदेशी जहाजों, बैंकों तथा बीमा कम्पनियों की सेवाओं का प्रयोग करता है तो उसे विदेशों को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होता है । यदि अन्य देश हमारे बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा जहाजों का प्रयोग करते हैं तो हमें उनके लिए भुगतान प्राप्त होता है । व्यवसायिक कम्पनियों की सेवाओं के अतिरिक्त विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा अधिकारियों की सेवाओं का आयात तथा निर्यात भी किया जाता है ।

(३) यात्रियों के द्वारा किया जाने वाला व्यय (Tourists Expenses)—भुगतान सन्तुलन में यात्रियों के द्वारा किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित होता है । विदेशी यात्रियों के द्वारा हमारे देश में व्यय किये जाने के कारण हमें विदेशों से भुगतान प्राप्त होते हैं । जब अमेरिकन यात्री हमारे देश में आते हैं तो उनके द्वारा

प्रयोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का हम एक प्रकार से अमेरिका को निर्यात करते हैं जिसके लिए हमें अमेरिका से भुगतान प्राप्त होता है। यदि हमारे यात्री विदेशों को जाते हैं तो हमें उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए भुगतान करना होता है।

(४) ऋणों का लेन देन (Granting of Loans)—जब कोई देश हमारे देश को ऋण देता है तो उसे तुरन्त उस ऋण की राशि को ऋण लेने वाले देश को हस्तान्तरित करना होता है जिसका प्रभाव भुगतान सन्तुलन को प्रतिबल करने का रहता है। इसके विपरीत जिस देश को विदेशों में ऋण मिलते हैं उसका भुगतान सन्तुलन पक्ष में जाने की प्रवृत्ति रखता है। इन ऋणों को जब वापस लौटाया जाता है तो भुगतान सन्तुलन पर इसके ठीक उलटा प्रभाव पड़ता है। जब विदेशों से ऋण वापस लौटते हैं तो वे भुगतान सन्तुलन को पक्ष में खींचते हैं किन्तु जब विदेशी ऋणों को लौटाया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति भुगतान सन्तुलन को विपक्ष में करने की होती है।

(५) ऋणों पर तथा विदेशों पूँजी पर ब्याज (Interest Charges)—हमारे देश में जो विदेशी पूँजी लगी होती है उस पर हमें ब्याज देना होता है जिसे भुगतान सन्तुलन के दाईं ओर दिखलाया जाता है क्योंकि इसके लिए हमें विदेशों को भुगतान करना होता है। जिन देशों की पूँजी विदेशों में लगी होती है, उन्हें विदेशी विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होता है। विदेशों में प्राप्त होने वाला ब्याज देश की लेनदारी को बढ़ाता है जिसके कारण भुगतान सन्तुलन की प्रवृत्ति पक्ष में होने की होती है।

(६) अन्य प्रकार के भुगतान (Miscellaneous Items)—आजकल देशों को कुछ अन्य मदों के लिए भी भुगतान लेने तथा देने होते हैं। यह मदें इस प्रकार हैं—(i) दान तथा आर्थिक सहायता—जब कोई देश हमारे देशों को आर्थिक सहायता अथवा दान इत्यादि देता है तो इसके लिए उसे विदेशियों को भुगतान करना होता है। जिस देश को इस प्रकार की सहायता मिलती है उसे विदेशों से भुगतान प्राप्त होते हैं। (ii) विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला व्यय—हमारे देश के विद्यार्थी जब अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमें उनके लिए विदेशों को भुगतान करना होता है। इसके विपरीत जो विदेशी विद्यार्थी हमारी शिक्षा संस्थाओं में विद्या प्राप्त करने आते हैं उनके लिए हमें विदेशों से भुगतान प्राप्त होते हैं। (iii) आवास तथा प्रवास (Emigration)—जब एक देश के लोग दूसरे देशों में बसने के लिए जाते हैं तो वे अपने साथ अपना धन तथा जमा-राशि भी ले जाते हैं जिसके कारण देश में लेनदारी बढ़ती है। यदि विदेशों से लोग बसने के लिए हमारे देश में आते हैं तो वे अपना धन भी अपने साथ लाते हैं जिससे देश की लेनदारी बढ़ती है। (iv) युद्ध व्यय, जुमनि, दण्ड इत्यादि—

कभी-कभी जीतने वाले देश पराजित देशों से युद्ध-व्यय, जुमाने तथा दण्ड आदि वसूल करते हैं जिसका इन देशों के भुगतान सन्तुलन पर बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। जिन देशों को इस प्रकार के भुगतान प्राप्त होते हैं उनका भुगतान सन्तुलन पक्ष में हो जाता है।

आयातों तथा निर्यातों के समान होने की प्रवृत्ति (Imports and Exports tend to be equal)—किसी देश की वस्तुओं की आयात तथा निर्यात का बराबर होना आवश्यक नहीं है किन्तु दीर्घकाल में प्रत्येक देश की कुल निर्यात (दृश्य तथा अदृश्य) का मूल्य उसके द्वारा की गई कुल आयातों (दृश्य तथा अदृश्य) के मूल्य के बराबर होना आवश्यक है। दीर्घकाल में प्रत्येक देश को सामान्य रूप से अपने ऋणों का भुगतान कर देना चाहिए। लम्बे समय में एक देश की कुल लेनदारी उसकी कुल देनदारी के बराबर होनी चाहिए। कुछ वर्षों के लिए किसी देश के आयात उसके निर्यातों से अधिक हो सकते हैं किन्तु दीर्घकाल में वे एक दूसरे के बराबर होने चाहिए।

दीर्घकाल में भुगतान सन्तुलन का अनुकूल तथा प्रतिकूल होना सम्भव नहीं है क्योंकि एक देश की लेन (Credits) तथा देन (Debits) लम्बे समय में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यदि किसी देश को उससे अधिक भुगतान प्राप्त होते हैं जितने कि वह देता है तो राशि अन्य देशों में जमा होने लगती है। दूसरे शब्दों में, वह देश दूसरे देशों को ऋण देता जाता है। भुगतान सन्तुलन में क्योंकि ऋणों को भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए उस देश के द्वारा दिये गये इन ऋणों को सम्मिलित करने से उसका 'भुगतान सन्तुलन' सन्तुलित हो जाता है। भुगतान सन्तुलन का अनुकूल तथा प्रतिकूल होना केवल एक अल्पकालीन घटना है। दीर्घकाल में देश के भुगतान सन्तुलन का सन्तुलित होना स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक देश को आयातों के मूल्य को निर्यातों के द्वारा चुकाना पड़ता है।

प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के उपाय

यद्यपि दीर्घकाल में भुगतान सन्तुलन स्वयं सन्तुलित होने की प्रवृत्ति रखता है किन्तु अल्पकाल में वह किसी देश के अनुकूल (Favourable) तथा प्रतिकूल (Unfavourable) हो सकता है। जिस देश का भुगतान सन्तुलन पक्ष में रहता है उसे आर्थिक दृष्टि से सन्तुलित समझा जाता है किन्तु किसी देश के भुगतान सन्तुलन का निरन्तर विपक्ष में रहना उसके दिवालिया होने की निशानी है। यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन कुछ वर्षों के लिए प्रतिकूल रहता है तो सम्भव हो सकता है कि वह देश उसकी चिन्ता न करे किन्तु यदि उसका भुगतान सन्तुलन वर्ष प्रतिवर्ष उसके प्रतिकूल चलता रहता है तो उस देश को अपने भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(१) निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion)—निर्यातों को प्रोत्साहन देकर भुगतान सन्तुलन को ठीक करने का उपाय सबसे अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा एक देश अपनी निर्यातों को बढ़ाकर अधिक आयातों के लिए भुगतान करने का प्रयत्न करता है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक देश अपने उद्योगपतियों तथा निर्यातकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता दे सकता है जिससे कि वे अपनी वस्तुओं को कम मूल्य पर बेच कर विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता कर सकें। सरकार प्रायः विदेशी बाजारों में वस्तुओं को कम मूल्य पर बेचने से होने वाली हानि का कुछ भाग स्वयं देने का निश्चय कर लेती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायता (Export Bounties) या तो उत्पादकों को दी जाती है अथवा निर्यातकर्त्ताओं को। निर्यातों को आर्थिक सहायता देने का उपभोक्ताओं पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु करदाताओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में कर देने पड़ते हैं। अतः आर्थिक सहायता के द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहित करने की सरकार की शक्ति सीमित होती है। निर्यात करों में कमी करके अथवा उन्हें बिल्कुल हटा कर भी सरकार निर्यातों को प्रोत्साहन दे सकती है।

(२) आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना (Restriction of Imports)—भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए एक दूसरा प्रभावशाली तरीका देश की आयातों को कम करना है। आयातों को मात्रा को कम करने के लिए आयातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध अथवा कर लगाय जाते हैं। आयातों को कम करने के विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं—(i) आयात कर लगाना (Imposing Import Duties)—आयातों को कम करने के लिए सरकार नये आयात-कर लगा सकती है अथवा वर्तमान करों में वृद्धि कर सकती है। आयात करों में आयातों के मूल्य में वृद्धि जान क कारण उनकी माग कम हो जाती है किन्तु इसका उपभोक्ताओं के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें वस्तुओं के अधिक मूल्य देने पड़ते हैं। (ii) आयात शून्यता (Import Quotas)—आयात कम करने के लिए विदेशों में आने वाली वस्तुओं के कोटा निश्चित किये जा सकते हैं जिससे अधिक मात्रा में इन वस्तुओं का आयात देश में नहीं किया जा सकता है। आयात कोटा प्रायः दो प्रकार के हो सकते हैं—(अ) एकपक्षीय कोटा (Unilateral Quotas)—इस प्रकार की कोटा प्रणाली में केवल एक देश अपनी आयात सम्बन्धी कोटे निश्चित करता है और आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस प्रकार के कोटे दो प्रकार के हो सकते हैं—(१) सार्वजनिक कोटा (Global Quota)—इसमें सरकार किसी वस्तु की समस्त देशों से होने वाली आयात की मात्रा निश्चित कर देती है और यह मात्रा किसी भी देश में बाँटी जा सकती है। (२) विभाजित कोटा (Allocated Quota)—इस प्रणाली में सरकार विभिन्न देशों से वस्तु की आयात की जाने वाली मात्रा निश्चित कर देती है और उसके अनुसार ही आयात किया जाता है। (ब) द्विपक्षीय कोटा (Bilateral Quotas)—इनके अन्तर्गत आयातों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध दो देशों के

आपसी समझौते के द्वारा निश्चित किये जाते हैं। इस प्रकार का एक समझौता भारत तथा जापान के बीच सन् १९३४ में हुआ था। (स) टैरिफ कोटा (Tariff Quotas)—इस व्यवस्था में सरकार एक निश्चित मात्रा तक वस्तु का आयात किसी देश-विशेष से आयात-कर की रियायती दर पर करने देती है किन्तु उससे अधिक मात्रा में आयात करने पर आयात-कर की बहुत ऊँची दर ली जाती है। (द) लाइसेंस प्रणाली (Licensing System)—आयात नियन्त्रण की यह प्रणाली आजकल बहुत प्रचलित हो रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही वस्तु का आयात कर सकते हैं। सरकार आवश्यकता के अनुसार तथा व्यापार सन्तुलन की स्थिति को ध्यान में रखकर विभिन्न व्यापारियों को आयात के लिए लाइसेंस देती है।

(३) अवमूल्यन (Devaluation)—मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा भी एक देश अपने प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक कर सकता है। अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा के विदेशी मूल्य को कम करने से होता है। अवमूल्यन के द्वारा देश की निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि विदेशी अपनी मुद्रा से अवमूल्यन करने वाले देश में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीद सकते हैं। उस देश की वस्तुएँ उनके लिए सस्ती हो जाती हैं जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही अवमूल्यन करने वाले देश के लिए विदेशी वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं और उनका आयात कम होने लगता है। अतः अवमूल्यन से निर्यात बढ़ती है और आयात कम हो जाती है जिससे भुगतान सन्तुलन ठीक हो जाता है। मितम्बर सन् १९४६ में इंग्लैंड ने अपनी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए डॉलर के सम्बन्ध में पाउण्ड (£) का अवमूल्यन किया जिसके परिणामस्वरूप पाउण्ड का मूल्य ४.०३ डॉलर से घटाकर २.८ डॉलर कर दिया गया। अन्य कामनवेल्थ देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। इस अवमूल्यन के द्वारा यह देश अपने भुगतान सन्तुलन के घाटे को दूर करने में सफल रहे हैं। यद्यपि अवमूल्यन भुगतान सन्तुलन को ठीक करने का अत्यन्त प्रभावशाली उपाय है किन्तु इसका प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को हानि पहुँचती है। जब अन्य उपाय सफल न हो तब ही इस उपाय का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(४) मुद्रा संकुचन (Deflation)—मुद्रा संकुचन के द्वारा भी एक देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों के लिए सस्ती कर सकता है और निर्यातों को प्रोत्साहन दे सकता है। देश में मुद्रा की मात्रा को कम करके मूल्य-स्तर को अन्य देशों की अपेक्षा नीचा किया जा सकता है। मूल्य-स्तर नीचा होने से हमारी वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं और हमारी निर्यात बढ़ती है। इसके साथ ही विदेशी

वस्तुओं के मूल्य ऊँचा होने के कारण आयातों की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा-सकुचन से प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करना सम्भव है किन्तु इस विधि का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है क्योंकि इससे देश में बेरोजगारी, उत्पादन का गिरना तथा अन्य प्रकार की आर्थिक बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं।

(५) विदेशी विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—विनिमय नियन्त्रण भुगतान सन्तुलन को ठीक करने की सबसे अच्छी विधि समझी जाती है। यह विधि प्रभावशाली भी अधिक होती है और अन्य विधियों के दोषों से मुक्त है। मुद्रा का अवमूल्यन करने से राष्ट्रीय सम्मान को हानि पहुँचती है, मुद्रा सकुचन से देश में उत्पादन गिरता है तथा बेरोजगारी फैलने का भय रहता है, अन्यथा तथा अन्य प्रकार के आयात नियन्त्रण विभिन्न देशों में बुरी प्रतियोगिता पैदा करते हैं किन्तु विनिमय नियन्त्रण इन सब दोषों से मुक्त है। इसीलिए आजकल लगभग सभी देशों के द्वारा विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किया जाता है। विदेशी विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का अधिकार स्वयं से लेती है और विदेशी मुद्रा का स्वतन्त्र बाजार बन्द कर दिया जाता है। विदेशी विनिमय प्राप्त करने वालों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह समस्त विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक को बेच दें। जिन लोगों को विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है वे उसे केवल केन्द्रीय बैंक से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय सम्बन्धी सौदों पर सरकारी नियन्त्रण रहता है। किसी निश्चित काल में केवल उतना ही विदेशी विनिमय खर्च किया जाता है जितना कि उपलब्ध होता है और भुगतान सन्तुलन के असन्तुलित होने का भय लगभग समाप्त हो जाता है। यद्यपि विनिमय नियन्त्रण भुगतान सन्तुलन को ठीक करने की काफी प्रभावशाली विधि है किन्तु उसके कारण विदेशी व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं तथा व्यापारियों को असुविधा रहती है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी विनिमय नियन्त्रण प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है।

परीक्षा प्रश्न

- (१) 'भुगतान संतुलन' के क्या-क्या अङ्ग हैं ? विपरीत भुगतान संतुलन के सुधारने के क्या उपाय हैं ? (भागरा बी० ए० १९६४)
- (२) व्यापार संतुलन और शोधनाधिक्य में क्या भेद है ? इस भेद का महत्व बताइये । (भागरा बी० ए० १९५७)
- (३) 'भुगतान संतुलन' से आप क्या समझते हैं ? किसी देश के भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता क्यों उदय होती है और इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? (भागरा बी० ए० १९५४)
- (४) "निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं" (Exports Pay for Imports)—स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार सम्भव होता है ? अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में मुद्रा का क्या भाग है ? (भागरा बी० कॉम १९५८)
- (५) 'भुगतानों' के संतुलन से क्या आशय है ? भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का सुधार करने के उपायों का वर्णन करिये । (इलाहाबाद बी० कॉम १९५६)



मुक्त व्यापार एवं संरक्षण

FREE TRADE AND PROTECTION

प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक उचित व्यापारिक नीति (Trade Policy) को अपनाने का प्रयत्न करता है। किसी देश के द्वारा कौन-सी व्यापारिक नीति अपनाई जानी चाहिए, यह बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर होता है कि वह देश आर्थिक विकास की किस अवस्था में है। विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न व्यापारिक नीतियों को अपनाने के पदा में तर्क दिये गए हैं, जिनके द्वारा हम इन नीतियों के आर्थिक महत्व को समझ सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में दो प्रकार की व्यापारिक नीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण रही हैं—स्वतन्त्र व्यापार की नीति (Free Trade Policy) तथा संरक्षण की नीति (Policy of Protection)। व्यापारिक नीति के सम्बन्ध में कोई निश्चय करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इन दोनों प्रकार की नीतियों की प्रकृति को भली प्रकार समझ लिया जाये तथा उनके पक्ष और विपक्ष में दिये जाने वाले विभिन्न तर्कों का विश्लेषण किया जाये।

स्वतन्त्र व्यापार का अर्थ (Meaning of Free Trade)—स्वतन्त्र व्यापार की नीति में अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता से होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते हैं और तन्तुएँ स्वतन्त्रतापूर्वक एक देश से दूसरे देश में आ-जा सकती हैं। जब कोई देश अपने उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य में विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाता है, तो उसकी व्यापारिक नीति को स्वतन्त्र व्यापार की नीति कहा जाता है। एडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार स्वतन्त्र व्यापार, “व्यापारिक नीति की उस व्यवस्था को कहते हैं जो स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद नहीं करती है और इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर कोई प्रतिरिक्त कर भार डाला जाता है और न स्वदेशी वस्तुओं को किसी प्रकार की विशेष मुविधाएँ दी जानी

हैं।^१ इसका यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुओं पर किसी प्रकार के कर नहीं लगाये जाते हैं बल्कि उन पर जो भी कर लगाये जाते हैं वे केवल आय प्राप्त करने के लिए होते हैं, अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए नहीं। स्वतन्त्र व्यापार की नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके पैदा करने में वह विशेष रूप से उपयुक्त होता है। एल्मवर्थ (Ellsworth) के अनुसार, "स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत भौगोलिक विशिष्टीकरण की सम्भावनाओं से सम्पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है।"^२

संरक्षण का अर्थ (Meaning of Protection)—संरक्षण की नीति के अन्तर्गत विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। संरक्षण की नीति को अपनाते वाला देश वस्तुओं, पूँजी तथा कच्चे माल के आयात-निर्यात पर रोक लगाकर अपने उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने का प्रयत्न करता है। अतः जब कोई देश अपने उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से वस्तुओं की आयात तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाता है, तो उसे संरक्षण की नीति कहा जाता है। संरक्षण की नीति का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था को विदेशी प्रतियोगिता के बुरे प्रभाव से बचाना होना है किन्तु कभी-कभी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। टॉमस (Thomas) के अनुसार संरक्षण का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करना होता है।

मुक्त व्यापार अथवा संरक्षण (Free Trade or Protection)—व्यापारिक नीति के रूप में मुक्त व्यापार अथवा संरक्षण दोनों में से कौन-सी नीति अधिक उपयुक्त है, इस सम्बन्ध में प्राचीन समय से ही काफीवाद-विवाद चला आ रहा है। मरकैन्टीलिस्ट (Mercantilist) के समय में संरक्षण की नीति को देश के हित में समझा जाता था और व्यापारिक प्रतिबन्ध एक सामान्य बात थी। एडम स्मिथ ने संरक्षण की नीति का बड़ा विरोध किया और स्वतन्त्र व्यापार की नीति के अपनाने पर अधिक जोर दिया। इंग्लैंड ने सर्वप्रथम मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया क्योंकि वह उसके आर्थिक हित में थी। इंग्लैंड की देखा-देखी अन्य देशों ने भी स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपना लिया। किन्तु कुछ समय पश्चात् यह अनुभव किया गया कि अविकसित देशों के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति अधिक उपयुक्त नहीं है। अतः जर्मनी तथा अमेरिका के द्वारा संरक्षण की नीति को

1 "That system of commercial policy which draws no distinction between the domestic and foreign commodities and, therefore, neither imposes additional burdens on the latter; nor grants any special favours to the former."

—Adam Smith.

2 "Free trade permits full advantage be taken out of the possibilities of geographical specialisation."

अपना लिया गया। सन् १८७० के पश्चात् जर्मन तथा अमेरिकन वस्तुओं की प्रतियोगिता के कारण इंग्लैंड के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति को जारी रखना कठिन हो गया और प्रथम महायुद्ध के पश्चात् उसने मुक्त व्यापार की नीति को त्याग दिया और विदेशी आयातों पर कर लगाने आरम्भ कर दिये। सन् १९३० की आर्थिक मन्दी (Depression) के पश्चात् सभी देशों ने मुक्त व्यापार की नीति को त्याग दिया और उसके स्थान पर संरक्षण की नीति को अपना लिया गया। आजकल ससार के सभी देशों ने संरक्षण की नीति को अपनाया हुआ है और स्वतन्त्र व्यापार का केवल एक ऐतिहासिक महत्व रह गया है।

स्वतन्त्र व्यापार के लाभ (Advantages of Free Trade)—

प्राचीन अर्थशास्त्री स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में थे और उन्होंने विदेशी व्यापार सम्बन्धी सभी बाधाओं को अनुचित बनलाया है। उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति को अधिक महत्व इसलिए दिया क्योंकि उसके द्वारा श्रम विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने स्वतन्त्र व्यापार को व्यापार करने वाले दोनों देशों तथा समस्त ससार के लिए उपयोगी बनलाया। उसके अनुसार विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धों का होना आर्थिक दृष्टि से अनुचित है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुक्त व्यापार से निम्नलिखित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं—

(१) उत्पत्ति के साधनों का आदर्श वितरण (Ideal Distribution of Factors of Production)—स्वतन्त्र व्यापार के द्वारा उत्पत्ति के साधनों का ससार भर में अनुकूलतम वितरण होता है और इस प्रकार साधनों से अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। विदेशी प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक देश उभी वस्तु को पैदा करता है, जिसके उत्पादन में उसकी कुशलता सबसे अधिक है और इसलिए वस्तुओं को न्यूनतम मूल्यों पर उत्पन्न किया जाता है क्योंकि प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करता है, जिनके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है इसलिए विभिन्न देशों में पाये जाने वाले साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना सम्भव है, जिससे समाज में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है।

(२) कार्यकुशलता में वृद्धि (Increased Efficiency)—प्रकुशल व्यवसाय अपने आप बन्द हो जाते हैं और केवल ऐसे ही उद्योग चलते हैं, जो कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अनियन्त्रित विदेशी प्रतियोगिता के कारण उद्योगों को अपनी कार्य-कुशलता का स्तर ऊँचा रखना होता है, जिसके लिए प्रत्येक देश के उत्पादक समय-समय पर अपनी उत्पादन विधि में सुधार करते रहते हैं। अतः मुक्त व्यापार की नीति उत्पादन सम्बन्धी सुधारों को प्रोत्साहित करती है।

(३) उपभोक्ता सस्ते मूल्यों पर वस्तुएँ प्राप्त कर सकते हैं—स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार की व्यापारिक नीति के

अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। स्वतन्त्र स्पर्धा होने के कारण वे सस्ते से सस्ते बाजार में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। वस्तुओं पर आयात-कर न होने के कारण भी वस्तुओं के मूल्य कम रहते हैं, जो उपभोक्ताओं के हित में होता है।

(४) स्वतन्त्र व्यापार एकाधिकारों तथा औद्योगिक संगठनों को बनने से रोकता है—विदेशी प्रतियोगिता के भय के कारण देश में एकाधिकारी सभों के निर्माण में रुकावट पड़ती है, जिससे समाज औद्योगिक एकाधिकारों से उत्पन्न होने वाले दोषों से बच जाता है।

(५) संसार के देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच पारस्परिक सहमाधना एवं सहानुभूति उत्पन्न होती है—प्रत्येक देश यह जानता है कि उसका आर्थिक हित दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, इसलिए वे सब मिलकर सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं, जिससे सब देशों को लाभ होता है।

संरक्षण के पक्ष में तर्क (Arguments for Protection)—

यद्यपि स्वतन्त्र व्यापार से कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं किन्तु उसमें कुछ ऐसे गम्भीर दोष भी हैं, जिनके कारण संसार के विभिन्न देशों के द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया है और उसके स्थान पर संरक्षण की नीति को अपना लिया गया है। आजकल मुक्त व्यापार के समर्थक बहुत कम पाये जाते हैं और उसका केवल सैद्धान्तिक महत्व रह गया है। आर्थिक राष्ट्रवाद तथा नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था के कारण सभी देशों ने संरक्षण की नीति को अपना लिया है। सन् १७६१ में अमेरिकन अर्थशास्त्री हैमिल्टन (Hamilton) के द्वारा सर्वप्रथम संरक्षण के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् एक दूसरे अमेरिकन अर्थ-शास्त्री कैरे (Carey) ने संरक्षण की नीति का बहुत अधिक समर्थन किया। जर्मनी में फ्रीड्रिक लिस्ट (Friedrich List) ने अपने देश में संरक्षण की नीति को अपनाने का जोरदार समर्थन किया। इस प्रकार अमेरिका तथा जर्मनी के द्वारा अपने उद्योगों का विकास करने के लिए सर्वप्रथम संरक्षण की नीति को अपनाया गया। प्रथम महायुद्ध के अन्त तक लगभग सभी देशों ने संरक्षण की नीति को अपना लिया।

संरक्षण के समर्थकों ने समय-समय पर संरक्षण की नीति के पक्ष में बहुत-से तर्क दिये हैं। इनमें से अधिकांश तर्क मुक्त व्यापार की नीति की आलोचनाओं पर आधारित हैं। संरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले मुख्य तर्क इस प्रकार हैं—

(१) शिशु उद्योग तर्क (Infant Industries Argument)—संरक्षण के पक्ष में यह तर्क सबसे शक्तिशाली तर्क है और लगभग सभी देशों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। शिशु उद्योग तर्क का इतना अधिक महत्व रहा है कि स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों ने भी उसे स्वीकार किया है। सर्वप्रथम इस तर्क को जर्मन अर्थशास्त्री फ्रीड्रिक लिस्ट (Friedrich List) के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अमेरिका में हैमिल्टन (Hamilton) तथा कैरे (Carey) ने इस तर्क के आधार पर संरक्षण की नीति का समर्थन किया तथा इङ्ग्लैंड में मिल (J. S. Mill) के द्वारा उसे स्वीकार किया गया। शिशु उद्योग तर्क का आधार इस बात पर है कि संसार के सब देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक-सी नहीं है। विभिन्न कारणों से कुछ देशों में औद्योगीकरण पहले आरम्भ होने के कारण यह देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल गये हैं और इनके उद्योग अधिक शक्तिशाली तथा कार्यकुशल हो गये हैं। इसके विपरीत कुछ देश औद्योगीकरण में पीछे रह गये हैं और उनमें या तो उद्योग-धन्धों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है अथवा बहुत कम विकास हुआ है। ऐसी दशा में अधिक उन्नत देशों के उद्योग इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि वे प्रतियोगिता के द्वारा अन्य देशों के शिशु उद्योगों को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण शिशु उद्योगों की रक्षा की आवश्यकता होती है।

अल्पविकसित देशों का औद्योगीकरण केवल संरक्षण की नीति के अन्तर्गत ही सम्भव है। इन देशों में नव-स्थापित उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे को कुछ समय तक संरक्षण की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार शिशु उद्योगों को जीवित रखने तथा उन्हें विकास का अवसर देने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उद्योग को स्थापित करने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयाँ रहती हैं और कठिनाइयों के इस काल में इन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना आवश्यक होता है। प्रो० टॉजिंग (Taussig) के अनुसार “आरम्भ में स्वदेशी उत्पादक को कठिनाइयाँ होती हैं और वह विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाता है। अन्त में वह सीख लेता है कि अधिकतम लाभ के साथ किस प्रकार वस्तु का उत्पादन किया जाय और उसे विदेशियों की भाँति सस्ती अथवा उनसे भी अधिक सस्ती बाजार में बेचा जाय।”³ यदि विकासशील देश संरक्षण की नीति का पालन नहीं करते हैं तो इनके नव-विकसित उद्योग या तो स्थापित होने से पूर्व ही नष्ट हो जायेंगे अथवा विकास के प्रारम्भिक काल में बन्द हो जायेंगे। इसी प्रकार उन्नत देशों के लिए भी अपने शिशु उद्योगों को संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण के द्वारा ही कोई देश अपने उद्योगों का पूर्ण विकास का अवसर दे सकता है।

संरक्षण देते समय उद्योगों का चुनाव ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रत्येक उद्योग संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। संरक्षण के लिए ऐसे उद्योगों को चुना जाना चाहिए जिनके विकास के लिए देश में उपयुक्त सुविधायें

3 “At the outset the domestic producer has difficulties and cannot meet foreign competition. In the end he learns how to produce to the best advantage and then can bring the article to market as cheaply as the foreigner, even more cheaply.” —TAUSSIG.

उपलब्ध हो किन्तु विदेशी प्रतियोगिता के कारण जिनका विकास न हो सका हो। अर्थात् सरक्षित उद्योग वे उद्योग होने चाहिए जो कुछ समय पश्चात् अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जे० एम० मिल (J. S. Mill) के अनुसार “यह आवश्यक है कि संरक्षण को उन्हीं उद्योगों तक सीमित रखा जाय जिनके विषय में हम विश्वास के लिए काफी आधार हो कि संरक्षण के द्वारा जिस उद्योग का विकास किया जा रहा है वह कुछ समय पश्चात् उनका परित्याग करने में समर्थ हो सकेगा। स्वदेशी उत्पादकों को इस आशा का भ्रमसर नहीं दिया जाना चाहिए कि संरक्षण उचित प्रयोग के लिए आवश्यक समय से अधिक के लिए दिया जा सकेगा।”^४ संरक्षण स्थायी भी नहीं होना चाहिए और जैसे ही उद्योग विकसित हो जाय संरक्षण को हटा लेना चाहिए। तब तक उद्योग शिशु अवस्था में हो तभी तक उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और जैसे ही वे शिशु अवस्था से निकल कर पूर्ण विकसित भयवा हट बन जायें तो संरक्षण तुरन्त हटा लेना चाहिए। अतः संरक्षण की नीति का निर्माण इस आधार पर किया जाना चाहिए—“शिशु का पालन करो, शालक की रक्षा करो और युवक को स्वतन्त्र छोड़ दो।”^५

शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कठिनाई यह होती है कि शिशु उद्योगों को किस प्रकार चुना जाय। कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन-सा उद्योग शिशु उद्योग है और कौन-सा नहीं। इस सम्बन्ध में वर्तमान अर्थशास्त्रियों का विचार है कि ऐसे उद्योगों को शिशु उद्योग कहा जा सकता है जिन्हें प्रत्येक प्रकार की आन्तरिक बचत (Internal Economies) तो प्राप्त हो किन्तु जिन्हें अभी बाहरी बचत (External Economies) प्राप्त न हो सकी हो। इसके अतिरिक्त उद्योगों को संरक्षण देने में एक अन्य कठिनाई इस कारण होती है कि संरक्षण स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। किसी उद्योग को एक बार संरक्षण देने के पश्चात् उसे हटाना बहुत कठिन होता है। बेवरिज (Beveridge) के अनुसार “शिशु उद्योग यह कभी अनुभव नहीं करते कि उनमें शक्ति आ गई है, यदि वे शक्तिशाली हो भी जाते हैं तो भी वे अपनी युवा-शक्ति का प्रयोग अधिक बड़ी मात्रा में और लम्बे समय के लिए संरक्षण प्राप्त करने में करते हैं।” इन सब व्यावहारिक कठिनाईयों के होते हुये भी शिशु उद्योगों को संरक्षण के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है।

4 “It is essential that protection should be confined to cases in which there is good ground of assurance that the industry which it fosters will after a time be able to dispense with it; nor should the domestic producer ever be allowed to expect that it will be constituted to them beyond the time necessary for a fair trial.”
—J. S. Mill.

5 “Nurse the baby, protect the child and free the adult.”

—Fredrich List.

(२) उद्योगों में विविधता का तर्क (Diversification of Industries Argument)—यह तर्क फ्रीड्रिक लिस्ट (Fredrich List) के द्वारा दिया गया था। उनकी विचार या प्रत्येक देश की विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास करके अर्थ-व्यवस्था को मजबूत रखना चाहिए। प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था का विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर आधारित होना आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। देश में सुरक्षा की नीति के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास करना सम्भव हो सकता है। स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में देश केवल कुछ एक प्रकार के उद्योगों का ही विकास करता है जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। देश में औद्योगिक विविधता होने से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं—(i) किसी एक उद्योग के पैने हो जाने पर पर अर्थ-व्यवस्था के ठप्प होने का भय नहीं रहता है। यदि कोई एक उद्योग अथवा कुछ उद्योग बन्द हो जाते हैं तो अन्य प्रकार के उद्योगों के चलते रहने के कारण देश का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त नहीं होता है। (ii) मजबूत अर्थ-व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिससे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो जाती है तथा देश आत्म-निर्भर हो सकता है। (iii) देश में पाये जाने वाले विविध प्रकार के साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सकता है। (iv) देश की रक्षा (Defence) के लिए भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों का होना आवश्यक है। किसी देश का एक उद्योग पर आधारित होना युद्धकाल में उसकी सुरक्षा को कमजोर करता है। इन्हीं सब कारणों से देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास करके ही कोई देश अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। उद्योगों का यह विविधिकरण (Diversification) देश की सुरक्षा की नीति के अन्तर्गत ही सम्भव हो सकता है।

(३) लागतों में समानता का तर्क (Equalising the Cost Production)—वस्तुओं की उत्पादन लागत को बराबर करने के लिए भी सुरक्षा की नीति को अपनाया जाना चाहिए। किसी वस्तु की देश में तथा विदेशों में उत्पादन लागत को बराबर करने ही हम अपने देश के उत्पादकों तथा अन्य देश के उत्पादकों में उचित प्रतियोगिता पैदा कर सकते हैं। न्याय की दृष्टि से वस्तुओं को समान आधार पर रखने के पश्चात् ही उन्हें प्रतियोगिता करने के लिए छोड़ना चाहिए। सुरक्षा के द्वारा उत्पादन लागतों को समान करने ऐसा किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु की उत्पादन लागत देश में विदेशों की अपेक्षा १०% ऊंची है तो हम उस वस्तु पर १०% का आयात कर लगा कर उसकी स्वदेशी तथा विदेशी लागतों को समान कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगा कर उनकी उत्पादन लागत को घटाने के द्वारा उत्पादन लागत को बराबर कर देना चाहिए जिससे स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादकों की वस्तुओं के बेचने के समान अवसर दिए जा सकें। यदि विदेशी वस्तुओं

की लागत को आयात कर के द्वारा घरेलू लागत के बराबर नहीं किया जाता है तो विदेशों से आने वाली सस्ती वस्तुएँ हमारे गृह-उद्योगों को नष्ट कर देंगी। इस स्थिति से बचने के लिए वस्तु की विदेशी लागत को स्वदेशी लागत के बराबर करना आवश्यक है और यह केवल संरक्षण की नीति के द्वारा ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षण के द्वारा केवल एक सीमा तक ही उत्पादन लागतों को बराबर करना चाहिए। यदि कोई उद्योग इतना अधिक प्रकुशल है कि उसकी वस्तु की लागत विदेशी वस्तु की लागत से बहुत अधिक ऊँची है तो ऐसी दशा में उस उद्योग को संरक्षण देना देश के आर्थिक हित में नहीं होगा।

(४) स्वदेशी बाजार तर्क (Home Market Argument)—संरक्षण के द्वारा घरेलू बाजार का विस्तार किया जा सकता है तथा नई वस्तुओं के बाजार स्थापित करना सम्भव होना है। यह तर्क अमेरिका में अधिक प्रचलित रहा है। संरक्षण के द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं को कम किया जा सकता है अथवा इस प्रकार की आयातों को दिव्युल रोक जा सकता है। विदेशों से आने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में किया जाने लगता है और प्रतियोगिता समाप्त हो जाने के कारण नये-नये उद्योग स्थापित होते हैं जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। अधिक रोजगार से वस्तुओं की माग बढ़ती है और इस प्रकार अन्य वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाता है। इस तर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आयात कम करने से निर्यात भी कम हो जाते हैं जिसके कारण निर्यात उद्योगों को हानि उठानी पड़ती है। अतः यह तर्क बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है।

(५) मजदूरी तर्क (Wages Argument)—इस तर्क के अनुसार संरक्षण के द्वारा देश में मजदूरी की दरों को ऊँचा रखा जा सकता है। मजदूरी की दर को गिरने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सस्ती मजदूरी वाले देशों से होने वाली आयातों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें अथवा आयात कर के द्वारा उनके मूल्यों को बढ़ा दिया जायें। यदि सस्ती वस्तुओं को देश में बिना रोक-टोक आने दिया जाता है तो उस देश की अपनी वस्तुएँ महंगी होने के कारण नहीं बिक सकेंगी और वहाँ के उत्पादक उत्पादन व्यय को कम करने के लिए मजदूरी की दरों को कम कर देंगे। अतः स्वतन्त्र प्रतियोगिता की दशा में कोई भी देश अपनी मजदूरी की दर को अन्य देशों की अपेक्षा ऊँची नहीं रख सकता है। एक देश अपने यहाँ मजदूरी के स्तर को अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा तब रख सकता है जब वह ऊँची मजदूरी वाले उद्योगों को संरक्षण दे। हैबर्लर (Haberler) के अनुसार 'अन्य देशों की अपेक्षा मजदूरी का ऊँचा स्तर प्रत्युत्क दीवार के पीछे ही बनाये रखा जा सकता है।'⁶ यही कारण है कि अमेरिका ऊँचे आयात करों के द्वारा जापान की सस्ती

6 "A wage level higher than that of other countries can be maintained only behind a Tariff Wall."

वस्तुओं को देश में आने से रोकना है। देश में मजदूरी की ऊँची दरों की संरक्षण के द्वारा गिरने से रोका जा सकता है किन्तु फिर भी यह तर्क अधिक सही नहीं है। किसी देश में मजदूरी की दरों के ऊँचा होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक उद्योग में मजदूरी इसलिए भी ऊँची हो सकती है क्योंकि उसमें श्रमिकों की कुशलता अधिक है।

(६) मुद्रा को घर पर रखने का तर्क 'Keeping Money at Home Argument'—संरक्षण के पक्ष में यह तर्क अमेरिका में कुछ लोगों के द्वारा दिया जाता था। रॉबर्ट इंगर्सोल (Robert Ingersoll) व अनुसार जब हम तैयार मास विदेशों में मगाते हैं तो हमें वस्तुएँ प्राप्त होनी हैं और विदेशियों को स्वयं मिलाता है किन्तु जब हम इन वस्तुओं को देश में ही खरीदते हैं तो हमें वस्तुएँ भी प्राप्त होनी हैं और मुद्रा भी देश में रहनी है। इस प्रकार मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया जाना चाहिए। यह तर्क बहुत अधिक विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि विदेशों से मस्ती वस्तुएँ मगा कर हम अपनी मुद्रा से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं।

(७) राशिपातन सुरक्षा (Protection Against Dumping)—संरक्षण की नीति के द्वारा एक देश अपने उद्योगों को राशिपातन के बुरे प्रभाव से बचा सकता है। जब कोई देश दूसरे देश के उद्योगों को नष्ट करने के उद्देश्य से उसके बाजार में अपनी वस्तुओं की उत्पादन लागत में भी कम मूल्य पर बेचने लगता है तो इसे राशिपातन कहा जाता है। इस प्रकार की बुरी प्रतियोगिता से बचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह देश उस देश से आने वाली मस्ती वस्तुओं पर ऊँचे आयात कर लगा दे। ऐसा करने से वह देश अपने उद्योगों को नष्ट होने से बचा सकता है। किन्तु राशिपातन को रोकने के उद्देश्य से लगाये जाने वाले आयात कर अस्थायी (Temporary) होने चाहिए और जैसे ही राशिपातन का भय समाप्त हो जाये उन्हें हटा देना चाहिए।

(८) रोजगार में वृद्धि (Increase in Employment)—देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए भी संरक्षण की नीति को अपनाने की बात कही जाती है। कुछ लोगों का विचार है कि संरक्षण के द्वारा देश में रोजगार के नये-नये साधन स्थापित किये जा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को मुलभूत जा सकता है। इस तर्क के आधार पर यह कहा जाता है कि आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने से देश में गृह-उद्योगों का विस्तार होता है जिससे रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है किन्तु आलोचकों ने इस तर्क की कड़ी आलोचना की है और यह बताया है कि संरक्षण के द्वारा देश में रोजगार की कुल मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। आयात कम होने से देश में आयात उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है और उनका विस्तार होता है जिसके कारण अधिक लोगों को रोजगार मिलता है किन्तु आयात

कम होने के साथ-साथ हमारी निर्यात भी गिर जाती है जिसके कारण निर्यात उद्योग बन्द होने लगते हैं और इन उद्योगों में बेरोजगारी फैलती है। इस प्रकार आयात उद्योगों में तो रोजगार बढ़ता है किन्तु निर्यात उद्योगों में रोजगार कम हो जाने के कारण कुल रोजगार की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सकता है। प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार—“यदि आयात में कमी होने पर निर्यातों में तुरन्त लगभग उतनी ही कमी आ जाती है तो स्पष्ट है कि ऐसी दशा में नटकर (Tariff) रोजगार में वृद्धि करने के लिए पूर्णतया निरर्थक होगा।”^७ संरक्षण के द्वारा कुल रोजगार को तब बढ़ाया जा सकता है जब कोई देश अपनी आयातों को कम करके भी अपनी निर्यातों में कोई कमी न होने दे। ऐसा केवल इन दशाओं में ही सम्भव है—(i) वह देश इतनी महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करता हो जिनके बिना अन्य देशों का काम न चल सके। ऐसी दशा में आयात कम करने पर भी उस देश की वस्तुओं की माग बराबर बनी रहेगी। (ii) उस देश के पास इतने अधिक साधन हों कि वह अन्य देशों को अपना माल खरीदने के लिए ऋण दे सके। (iii) निर्यातों को अधिक सहायता देकर भी कोई देश अपनी निर्यातों के अनेकों स्तर को बनाये रख सकता है। यद्यपि अमेरिका आजकल बहुत कुछ इसी दशा में है किन्तु फिर भी किसी साधारण देश के लिए इन दशाओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सकता है। अतः संरक्षण के द्वारा रोजगार की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकती है।

संरक्षण के विपक्ष में तर्क (Arguments Against Protection)—

यद्यपि संरक्षण की नीति कुछ विशेष दशाओं में देश के लिए लाभपूर्ण हो सकती है किन्तु अर्थ-व्यवस्था पर उसके अनेक बुरे प्रभाव पड़ते हैं। एलसेवर्थ (Elseworth) के अनुसार संरक्षण की नीति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ को कम करती है क्योंकि एक ओर तो उत्पादन खोत अधिक कुशल उपयोगों से निकल कर कम कुशल उपयोगों में चले जाते हैं और दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता में कमी आ जाती है। संरक्षण के विपक्ष में दिये जाने वाले कुछ प्रमुख तर्क निम्न-लिखित हैं—

(१) उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने पड़ते हैं—संरक्षण के अन्तर्गत आयात करों के कारण वस्तुओं की उत्पादन लागत ऊँची रहती है और वस्तुओं के मूल्य उतने ही बढ़ जाते हैं जितना कि उन पर आयात कर लगाया जाता है। वस्तुओं को देश से बाहर रखा जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देकर वस्तुएँ प्राप्त करनी होती हैं। संरक्षण के समर्थकों का कहना है कि

7 “If a reduction of imports causes almost at once a more or less equal reduction of exports, obviously a tariff (and many other things) would be completely futile for the purpose of augmenting employment.” —Keynes

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को हानि तो होती है किन्तु यह उनके द्वारा भविष्य के आर्थिक विकास के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का त्याग है। ऐसा करके ही वे भविष्य में स्वदेशी सस्ती वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न कर सकते हैं।

(२) धन के वितरण को असमान करती है—संरक्षण की नीति के विरोध में यह कहा जाता है कि वह गरीबों को अधिक गरीब तथा अमीरों को अधिक अमीर बनाती है। संरक्षण के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने पड़ते हैं जिसका लाभ उत्पादकों को होता है। इस प्रकार निर्यत उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेकर पूँजीपति के लाभों को बढ़ाया जाता है। किन्तु यह तब अधिक सही नहीं है क्योंकि अधिक मूल्य के रूप में जो कुछ भी उपभोक्ताओं से लिया जाता है वह केवल पूँजीपति के पास नहीं रहता है बल्कि उसमें से सभी उत्पत्ति के माधनों को हिस्सा मिलता है।

(३) संरक्षण स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है—संरक्षण की नीति में वास्तविक कठिनाई इसलिए होती है कि किसी भी उद्योग को एक बार संरक्षण देने के पश्चात् उस हटाना बहुत कठिन हो जाता है। वास्तव में उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण अस्थायी (temporary) होना चाहिए और जैसे ही उद्योग विकसित हो जाये संरक्षण को हटा लेना चाहिए किन्तु व्यवहार में ऐसा करना कठिन होता है। संरक्षित उद्योग कभी-कभी अपने को विकसित नहीं समझते हैं और अधिक तथा लम्बे समय के लिए संरक्षण की मांग करते हैं।

(४) संरक्षण देश में औद्योगिक एकाधिकार को जन्म देता है—संरक्षण की नीति का एक बड़ा दोष यह है कि वह एकाधिकार तथा औद्योगिक संगठनों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करता है। आयातों के बन्द हो जाने के कारण विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और उत्पादक आपस में मिलकर ऐसे संगठन बना लेते हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।

(५) संरक्षण तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में विरुद्ध है—स्वतन्त्र व्यापार की दशाओं में वस्तुओं का उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है जिसमें उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है और उत्पादन की मात्रा भी अधिकतम होती है किन्तु संरक्षण की नीति के अन्तर्गत उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार नहीं किया जाता है। प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रकार की वस्तु को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि वस्तुएँ न तो सस्ती पैदा की जाती हैं और न उनका उत्पादन ही अधिकतम होता है। इस प्रकार संरक्षण की नीति को अपनाते वाले देश तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन करने में उत्पन्न होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं।

(६) विदेशी व्यापार कम हो जाता है—संरक्षण की नीति की प्रवृत्ति विदेशी व्यापार को मकुचिन करने की होती है। संरक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी आयातों को कम करने का प्रयत्न करता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी निर्यात भी कम हो जाती है। प्रत्येक देश अपनी आयातों का मुगलान निर्यातों के द्वारा करता है। इसलिए आयातों के कम होने पर निर्यातों का कम होना स्वाभाविक ही है। आयातों तथा निर्यातों के कम होने के कारण संरक्षित देश का विदेशी व्यापार कम हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संरक्षण की नीति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न करती है।

(७) अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न करती है—संरक्षण की नीति के अन्तर्गत देश का मनुलिन आर्थिक विकास नहीं होता है। संरक्षित उद्योगों के अधिक लाभपूर्णा हो जाने के कारण उत्पत्ति के साधन अन्य उद्योगों से निकलकर संरक्षित उद्योगों में आने लगते हैं जिसके कारण अन्य उद्योगों का विकास रुक जाता है और देश की अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित हो जाती है। संरक्षित उद्योगों में होने वाली उत्पादन की वृद्धि उस हानि से कम होती है जो अन्य उद्योगों का विकास रुक जाने के कारण देश को उठानी पड़ती है। हैबर्नर के अनुसार —“अन्य उद्योगों के उत्पादन में होने वाली कमी संरक्षित उद्योगों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है।” इस प्रकार संरक्षण की नीति देश में कुल उत्पादन को कम करती है।

(८) औद्योगिक कार्य कुशलता में वृद्धि की सम्भावना कम हो जाती है—संरक्षण के द्वारा अनुकूल उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि इन उद्योगों में कार्यकुशलता की वृद्धि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाने तथा ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं की माग स्थापित हो जाने के कारण उत्पादक औद्योगिक कार्यकुशलता में वृद्धि करने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और आधुनिकरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध की अपेक्षा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में औद्योगिक कार्यकुशलता का स्तर संरक्षित देश में अन्य देशों की अपेक्षा नीचा रहता है।

(९) राजनैतिक अष्टाचार—संरक्षण के कारण देश में राजनैतिक अष्टाचार में वृद्धि होती है क्योंकि उद्योगपति संरक्षण को बनाये रखने के लिए सरकारी कार्यकारिणों, राजनैतिकों तथा अन्य अधिकारियों को भ्रूस आदि के द्वारा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं जिसके कारण कई बार गलत उद्योगों को संरक्षण दे दिया जाता है अथवा उद्योगों को दिये जाने वाले संरक्षण को अनावश्यक समय तक बनाये रखा जाता है।

8 “The decrease in production elsewhere is greater than the increase of production in the protected industry.”

—Harbeler : Theory of International Trade, P. 246.

निर्यात — उपर्युक्त विस्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं। यद्यपि सरक्षण की नीति में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं किन्तु उन्हें विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों से रोका जा सकता है। सरक्षण को स्थायी बनाने से रोकने के लिए सरकार को दृढ़ निश्चय से काम लेना चाहिए और जैसे ही कोई उद्योग विकसित हो जाये उसका सरक्षण तुरन्त हटा लेना चाहिए। औद्योगिक संगठनों को बनने से रोकने के लिए संगठन विरोधी (Anti-Combination) नियम बन जा सकते हैं। घन के अपमान विनियम को दूर करने के लिए अन्य प्रकार के करों का प्रयोग किया जा सकता है तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारियों के नैतिक स्तर को ऊँचा किया जाना चाहिए। इस प्रकार उचित प्रतिबंधों की सहायता से सरक्षण के दोषों से बचा जा सकता है। वर्तमान स्थिति में अल्प-विकसित देशों के लिए औद्योगीकरण के उद्देश्य से सरक्षण की नीति का अपनाना जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सरक्षण तथा अल्प विकसित देश

(Protection and Under-developed Countries)—

अल्प-विकसित देशों के औद्योगीकरण के लिए सरक्षण की नीति अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में सरक्षण की आवश्यकता केवल कुछ विशय परिस्थितियों में ही होती है किन्तु अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में सरक्षण की नीति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन देशों में उद्योगों को सरक्षण दिये बिना उनका विकास नहीं किया जा सकता है। स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में कुछ भी तर्क क्यों न दिये जायें किन्तु इस प्रकार का व्यापार अल्प विकसित देशों के लिए हितकर नहीं है क्योंकि वह उनके औद्योगिक विकास की सम्भावना को नष्ट करता है। अतः भारतवर्ष तथा अन्य अल्प विकसित देशों के सरक्षण के पक्ष में दिया जाना वाला शिशु उद्योग तर्क (Infant Industries Argument) विशेष महत्त्व रखता है। ये देश अपने नव-विकसित उद्योगों को सरक्षण के द्वारा ही पूर्णरूप से विकसित होने का अवसर दे सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के नये उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त दानावरण उत्पन्न कर सकते हैं। प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार— “ऐसे कृपि देश में जहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए प्राकृतिक लाभ प्राप्त हों, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरक्षण के प्रयोग के पक्ष में काफी मजबूत तर्क दिये जा सकते हैं। इस प्रकार के देश में स्वदेशी निर्माण शक्ति के तेजी के साथ विकसित होने से प्राप्त लाभ उस हानि की अपेक्षा कहीं अधिक होता है जो स्वदेशी वस्तुओं के विदेशी वस्तुओं के साथ बदलने पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण उत्पन्न होती है।”

9 “The case for protection with a view to building up productive power is stronger in any agricultural country which seems to possess natural advantages for manufactures. In such a country the immediate loss arising

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं वाले कृषि प्रधान देशों के औद्योगिक विकास के लिए संरक्षण की नीति अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश में संरक्षण की नीति को स्थाई स्थान नहीं दिया जा सकता है। उसका प्रयोग केवल अस्थायी रूप में उद्योगों की सहायता करने के लिए किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए जिनका भविष्य उज्ज्वल हो तथा जो आर्थिक विकास अथवा सुरक्षा के लिए या अन्य कारणों से देश के लिए आवश्यक हो। जैसे ही सुरक्षित उद्योग परिपक्व (Maturity) अवस्था को पहुँच जायें वैसे ही संरक्षण हटा लेना चाहिए। इस प्रकार संरक्षण का प्रयोग केवल एक अस्थायी नीति के रूप में ही किया जा सकता है और उसके स्थाई होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जाने चाहिए।

गल्प विकसित देशों के लिए संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज की दशाओं में प्रत्येक देश को यथा सम्भव आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष तथा तनाव की वर्तमान स्थिति में कोई भी देश अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्वतन्त्र व्यापार आज सम्भव नहीं है। किसी भी देश की सरकार को सुरक्षा, आत्म-निर्भरता तथा पूर्ण-रोजगार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अपनी औद्योगिक नीति का निर्माण करना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि गल्प विकसित देश संरक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करके अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम से कम रखे। इसके अतिरिक्त संरक्षण की नीति अल्प विकसित देशों के नियोजित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। संरक्षण के द्वारा ही यह सम्भव होता है कि नियोजित विकास के लिए आवश्यक उद्योगों का तेजी के साथ विकास किया जाय। अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास उनके औद्योगिक विकास पर निर्भर है और औद्योगिक विकास संरक्षण के बिना असम्भव है। अतः अल्प विकास की दशा में किसी भी देश के द्वारा संरक्षण की नीति को अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

संरक्षण की रीतियाँ (Methods of Protection)—

उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) वैधानिक निषेध (Legislative Prohibition)—कभी-कभी कुछ वस्तुओं की आयात को रोकने के लिए उन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगा दिया जाता

from the check to the exchange of native produce for foreign manufactures may well be outweighed by the gain from the greater rapidity with which the home manufacturing power is developed."

—Figuera.

है। ऐसी दशा में इन वस्तुओं का आयात बिलकुल नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रायः उन वस्तुओं के सम्बन्ध में किया जाता है जिनका प्रयोग देशवासियों के चरित्र अथवा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता हो।

(२) **सरक्षण प्रभुत्क (Protective Tariffs)**—सरक्षण देने की यह रीति सबसे प्राचीन तथा अधिक प्रचलित है। देश में वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए उन पर आयात कर लगा दिये जाते हैं जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है और माग कम हो जाती है। इस प्रकार के करों का मुख्य उद्देश्य अपने देश के उद्योगों का सरक्षण देना होता है किन्तु कभी-कभी घाय की दृष्टि से भी आयात करों को लगाया जाता है। आयात कर प्रायः दो प्रकार के होते हैं—(i) **प्रति-मूल्य कर (Ad-valorem Duty)**—इस प्रणाली में आयात कर वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। इसमें यह लाभ रहता है कि घनी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली मूल्यवान वस्तुओं पर अधिक कर लगाना सम्भव हो जाता है। (ii) **परिमाण कर (Specific Duty)**—यह वस्तु की मात्रा पर लगाया जाता है। इसका आधार वस्तु का ताल तोल अथवा सन्ख्या होती है। इस प्रकार का कर अधिक सुविधापूर्ण रहता है।

(३) **आयात अभ्यश (Import Quotas)**—वस्तुओं की आयात को कम करने के लिए उसकी आयात की जाने वाली मात्रा निश्चित कर दी जाती है। यह सरक्षण की काफी प्रभावशाली प्रणाली है। इसके अन्तर्गत केवल निश्चित कोटों के अनुसार ही वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। कभी वस्तु की आयात की जाने वाली कुल मात्रा निश्चित कर दी जाती है और कभी अलग-अलग देशों के अभ्यश पृथक् निश्चित किये जाते हैं। कभी-कभी एक निश्चित मात्रा तक आयात बिना किसी शुल्क अथवा कम शुल्क पर करने दिया जाता है किन्तु इससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात करने के लिए ऊँची दर पर कर देने होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में आयातों का पूर्ण रूप से नियन्त्रण करना सम्भव नहीं होता है इसलिए सरक्षण की दृष्टि से वही अभ्यश प्रणाली अधिक प्रभावशाली होती है जिसमें एक निश्चित मात्रा तक ही वस्तुओं का आयात करने दिया जाता है और अभ्यश में अधिक मात्रा में आयात पूर्णतया वर्जित होता है।

(४) **सरकारी आर्थिक सहायता (Export Bounties)**—निर्यातों को प्रोत्साहन देने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अन्तर्गत उद्योगपतियों तथा निर्यातकर्त्ताओं को विशेष छूट, अनुदान, ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। इस प्रकार की सहायता का उद्देश्य विदेशी बाजार में वस्तुओं के मूल्य को कम करना होता है।

(५) **विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)**—विनिमय नियन्त्रण के द्वारा भी उद्योगों को सरक्षण प्राप्त हो सकता है। यद्यपि विनिमय नियन्त्रण को सरक्षण देने के उद्देश्य से नहीं अपनाया जाता है किन्तु उसके परिणामस्वरूप कुछ

उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है। विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत जिन वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी विनिमय नहीं दिया जाता है अथवा कम दिया जाता है उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को स्वयं संरक्षण प्राप्त हो जाता है।

(६) अवमूल्यन (Devaluation) — मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा भी वस्तुओं की आयात को कम किया जा सकता है तथा निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अवमूल्यन से विदेशी वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं और वे कम मात्रा में आयात की जाने लगती हैं जिसके कारण उन्हें पैदा करने वाले उद्योगों को एक प्रकार का संरक्षण मिल जाता है। हमारी वस्तुओं के मूल्य कम हो जाने के कारण उनकी निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है।

(७) आयात निर्यात का सरकार के द्वारा किया जाना — कभी-कभी सरकार आयात निर्यात व्यापार का एकाधिकार अपने हाथ में ले लेती है। कौन सी वस्तु किस देश से कितनी मात्रा में मगानी है — यह सब सरकार निश्चित करती है। जिन वस्तुओं को कम मात्रा में मगवाया जाता है अथवा बिल्कुल नहीं मगवाया जाता है उन वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों को एक प्रकार का संरक्षण मिल जाता है। भारतवर्ष में सरकार ने इसी उद्देश्य से राजकीय व्यापार (State Trading) आरम्भ किया।

(८) अनुज्ञापन प्रणाली (Licensing System) — अम्यश प्रणाली के दोषों को दूर करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए कभी-कभी अनुज्ञापन प्रणाली को अपनाया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार आयातकर्त्ताओं को वस्तुओं का आयात करने के अनुज्ञापन (Licence) देती है। वस्तु की आयात की जाने वाली कुल मात्रा निश्चित करने के पश्चात् उसके अनुसार विभिन्न आयातकर्त्ताओं को अनुज्ञापन दे दिये जाने हैं और केवल अनुज्ञापन प्राप्त आयातकर्त्ताओं को ही वस्तु का आयात करने दिया जाता है। अनुज्ञापन देते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है किन्तु सामान्यतः किमी पिछले आधार वर्ष में उस फर्म के द्वारा आयात की गई मात्रा को आधार मानकर वर्तमान वर्ष के लिए अनुज्ञापन दिये जाते हैं। यद्यपि अनुज्ञापन प्रणाली में अम्यश प्रणाली के बहुत से दोष नहीं पाये जाते हैं किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई अनुज्ञापनों को न्यायपूर्ण आधार पर बाँटने की होती है। हैबर्लर (Haberler) ने इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि — “वस्तुओं के आयात-अनुज्ञापन व्यापारियों में बाँटे जाते हैं, विशेषतया जब वस्तुएँ उपयोग सम्बन्धी होती हैं। अनुज्ञापन के लिए चुनाव का आधार व्यापारिक योग्यता नहीं होती है। इसके विपरीत अनुज्ञापन के लिए उन लोगों को चुना जाता है जो अम्यश प्रणाली के अपनाये जाने के समय उस वस्तु का आयात करते होते हैं अथवा जिनका अधिक प्रभाव होता है अथवा जो रिश्वत देने में अधिक कुशल होते हैं।”^{१०}

अनुज्ञापन प्रणाली से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि अनुज्ञापन देने के लिए फर्मों (Firms) का चुनाव उचित आधार पर किया जाय।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) संरक्षण पद्धतियों में (अ) आयात कर, (ब) लायसेंस तथा, (स) सात राजनिंग पद्धतियों के सापेक्षिक महत्व की सर्चा कीजिए।
(भागरा बी० ए० १९६२)
- (२) संरक्षण के पक्ष में तर्कों की विवेचना करो। उसके विपक्ष में कौन से तर्क हैं ?
(भागरा बी० ए० १९६०)
- (३) संसार की वर्तमान व्यापारिक दशा में स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्कपूर्ण सुझाव दीजिए।
(भागरा बी० ए० १९५९)
- (४) किन परिस्थितियों के अन्तर्गत सट-कर संरक्षण उचित है। देश की आर्थिक उन्नति में यह किस प्रकार सहायक है ? उदाहरण सहित समझाइये।
- (५) 'स्वतन्त्र व्यापार' एवं 'संरक्षण' में भेद बतलाइये। किन परिस्थितियों में संरक्षण उचित ठहराया जा सकता है ? (राजस्थान बी० ए० १९५५)
- (६) 'संरक्षण से आप क्या समझते हैं ?' संरक्षण के पक्ष में कौन से तर्क दिये जाते हैं ? क्या आप उनसे सहमत हैं ? (जवलपुर बी० ए० १९५६)
- (७) संरक्षण के पक्ष में कौन-कौन से तर्क दिये जाते हैं ? संरक्षण में नियोजन की किस सीमा तक बढ़ावा भितता है ? (राजस्थान बी० ए० १९५९)
- (८) मुक्त व्यापार की नीति एक सर्वोत्तम नीति क्यों मानी जाती है ? किन परिस्थितियों में संरक्षण की नीति आर्थिक दृष्टिकोण से उचित है ?
(नागपुर बी० ए० १९५६)



of selection, Instead, those who happened to be importing the good when the quota system came into force or those with the most influence or the greatest skill in bribing are the ones selected."

भारत का विदेशी व्यापार

THE FOREIGN TRADE OF INDIA

प्राचीन काल से ही भारत का विदेशी व्यापार काफी विकसित तथा विस्तृत रहा है। बहुत अधिक समय तक भारत संसार के लिए वस्तुयें बनाने का केन्द्र समझा जाता था और भारत में बनी हुई वस्तुयें लगभग सभी देशों को भेजी जाती थी। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत का विदेशी व्यापार मिस्र, रोम, अरब, चीन आदि देशों के साथ काफी विकसित था। इन देशों को भारत से ढाकें की मलमल, सूती कपड़ा, हाथी दाँत का सामान, पीतल तथा अन्य धातुओं का सामान, मसाले, इन्, कलात्मक वस्तुयें, औजार आदि भेजे जाते थे और इनके बदले में इन देशों से धाराब, घोड़े, मिल्क तथा अन्य प्रकार की धातुओं का आयात किया जाता था। मुगल काल में सुरक्षा की कमी तथा राजनैतिक दशाओं की अस्थिरता के कारण भारत के विदेशी व्यापार में कुछ कमी हो गई थी किन्तु आन्तरिक व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। योरोपीय व्यापारियों के आते ही भारत के विदेशी व्यापार को फिर प्रोत्साहन मिला और वह तेजी के साथ बढ़ने लगा। आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जिसमें कि उनके बने सामान का निर्यात वे विदेशों को कर सके किन्तु यह स्थिति कुछ समय तक ही रही। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात् कम्पनी की इस नीति में परिवर्तन हो गया और यहाँ के उद्योगों को नष्ट करके भारत को केवल इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल निर्यात करने वाला देश बना दिया गया। सन् १८६६ में स्वेज नहर के खुल जाने तथा भारत में रेलों का विकास हो जाने के कारण हमारे विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला और भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होने लगी। सन् १८५६ में हमारा विदेशी व्यापार केवल ८६ करोड़ रुपये का था किन्तु १९१४ में यह बढ़कर ३७६ करोड़ रुपये का हो गया।

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार को सामान्य-स्तर पर बनाये रखना कठिन हो गया। युद्धकालीन दशाओं के

कारण हमारा विदेशी व्यापार कम होने लगा। इस काल में भारत में निर्यात और आयात दोनों ही में कमी हुई। सन् १९१३-१४ और १९१८-१९ के बीच हमारे निर्यात ३२४ करोड़ रुपये में घट कर केवल १६० करोड़ रुपये रह गये। इसी काल में आयातों की मात्रा १६३ करोड़ रुपये से घटकर केवल ६३ करोड़ रुपये रह गई। यह अनुमान लगाया गया है कि इस काल में भारत के विदेशी व्यापार में लगभग ५०% की कमी हुई। विदेशी व्यापार की इस कमी के कई मुख्य कारण थे। जहाजों की कमी, विदेशी विनिमय सम्बन्धित कठिनाइयाँ, शत्रु देशों के साथ व्यापार का बन्द हो जाना, विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिबन्ध आदि। युद्ध के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में तेजी आ गई क्योंकि योद्धा के युद्ध-विनष्ट देशों में भारतीय सामानों की मांग काफी अधिक बढ़ गई थी किन्तु भारत पाश्चात्य सम्बन्धी कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर के कारण इस तेजी में पूरा लाभ नहीं उठा सका। सन् १९२०-२१ के पश्चात् तेजी का यह क्रम टूट गया और हमारे विदेशी व्यापार में गिरावट आने लगी। सन् १९२०-२३ में फिर विदेशी व्यापार में तेजी का काल आरम्भ हुआ और १९२४-२५ तक हमारे विदेशी व्यापार की दशा काफी सुधर गई। विदेशी व्यापार की यह वृद्धि सन् १९२६ तक चली रही किन्तु १९२६-२७ के बीच महान् अवसाद के कारण तेजी का यह क्रम टूट गया। अवसाद की दशाएँ सन् १९३३ में समाप्त हो गईं और १९३३-३४ में विदेशी व्यापार में फिर उद्धार की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। विदेशों में भारत के माल की मांग बढ़ने लगी और विदेशी व्यापार का यह विस्तार १९३५-३६ तक चलता रहा। सन् १९३६-३७ में फिर मन्दी की प्रवृत्ति आरम्भ हुई जो १९३६ तक चलती रही किन्तु उसके पश्चात् द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण भारतीय व्यापार की प्रोत्साहन मिला और भारतीय निर्यातों की मांग तथा मूल्य दोनों में वृद्धि हुई।

द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रभाव

(Effect of II World War on India's Foreign Trade)—

युद्ध आरम्भ होते ही सभी देशों के व्यापार में वृद्धि होने लगी। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के आयात का प्रयत्न कर रहा था जिनकी उसके पास कमी थी और जो युद्ध की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये और उनकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई। युद्ध के कारण भारतीय विदेशी व्यापार के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप होने पर भी देश के कच्चे तथा निम्न मूल्य के निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई। निर्यातों के मूल्य बढ़ जाने पर भी १९३६-४० में उनकी मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक थी। यद्यपि युद्ध काल में शत्रु देशों के साथ व्यापार बन्द हो गया था किन्तु फिर भी विदेशी मांग अधिक होने के कारण भारतीय व्यापार में बराबर विस्तार होता गया। सन् १९४२-४३ में भारत के विदेशी व्यापार में कुछ कमी हुई

जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे—(i) जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से सुदूर-पूर्व के व्यापार का समाप्त हो जाना । (ii) विदेशी विनिमय नियन्त्रण के कारण व्यापार में बहुत-सी बाधाओं का उत्पन्न होना । (iii) लाइसेंस प्रणाली (Licensing system) के परिणामस्वरूप आयात-निर्यात की मात्रा में कमी । (iv) डॉलर की कमी के कारण अमेरिका से सामान मगाना सम्भव न था । (v) सामान लाने ले जाने के लिए जहाजों की कमी । (vi) शत्रु देशों की कार्य-वाही के कारण वस्तुओं का आयात-निर्यात कठिन हो गया था । द्वितीय विश्व-युद्ध काल में भारत के विदेशी व्यापार में निम्नलिखित परिवर्तन हुए—

(१) व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन—युद्ध के कारण भारत से कुछ नई वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा तथा कुछ पुरानी निर्यातों का महत्व कम हो गया । युद्ध काल में जूट के सामान के निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । सूती कपड़े के निर्यात में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । युद्ध से पूर्व भारत केवल ६ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात करता था किन्तु १९४२-४३ में ४६ करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात किया गया । कपड़े की निर्यात में इस आकस्मिक वृद्धि का कारण जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से बहुत में नये बाजारों का भारत के हाथों में आ जाना था । अमेरिका और योरोप में भारतीय चाय की माग बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण चाय का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाने लगा । अब भारतवर्ष से कच्चे माल का निर्यात कम हो गया था और तैयार माल अधिक मात्रा में विदेशों को भेजा जाने लगा था । भारत की आयातों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और हमारे देश में तैयार माल की आयात बहुत कम हो गई तथा कच्चे माल का आयात अधिक मात्रा में किया जाने लगा । इस प्रकार युद्ध ने हमारे देश को एक तैयार माल का आयात तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाले देश से बदल कर तैयार माल का निर्यात तथा कच्चे माल का आयात करने वाला देश बना दिया ।

(२) व्यापार की दिशा में परिवर्तन—युद्ध काल में भारत की विदेशी व्यापार की दिशा में भी काफी परिवर्तन हुआ । भारत ने साम्राज्य देशों के साथ अपने व्यापार का विस्तार किया और आस्ट्रेलिया, कनाडा, मिश्र, ईराक तथा अन्य स्ट्रालिंग क्षेत्र वाले देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये गये । इस काल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अमेरिका के साथ भारत के व्यापार का तेजी के साथ विस्तार हुआ । सन् १९४४-४५ में अमेरिका के साथ किये जाने वाले व्यापार का मूल्य ६५ करोड़ रुपये था जबकि उसी वर्ष इंग्लैंड के साथ १०२ करोड़ रुपये का व्यापार किया गया । इस प्रकार विदेशी व्यापार में अमेरिका का स्थान इंग्लैंड के बराबर आ गया ।

(३) व्यापार संतुलन में सुधार—युद्ध काल में भारत के व्यापार संतुलन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और वह निरन्तर हमारे देश के पक्ष में रहने लगा । सन्

१९४३-४४ तक भारत का आयात बराबर गिर रहा था क्योंकि विदेशों से आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करना सम्भव नहीं था। इसके विपरीत निर्यातों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी जिसके कारण व्यापार-सन्तुलन भारत के पक्ष में था।

द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति का अनुपम निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात का मूल्य	आयात का मूल्य	कुल व्यापार	व्यापाराधेय
१९४०-४१	१८०	१५७	३४६	+३०
१९४१-४२	२३७	१७३	४१०	+६६
१९४२-४३	१८७	११०	२९७	+७७
१९४३-४४	१६०	११८	२७८	+४२
१९४४-४५	२१०	२०४	४१६	+ ६

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध के पहले दो वर्षों में भारत की निर्यात और आयात दोनों ही बढ़ीं जिसके परिणामस्वरूप देश के कुल व्यापार का विस्तार हुआ। सन् १९४२-४३ में आयात व निर्यात में भारी कमी हुई और १९४३-४४ में स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सन् १९४४-४५ में फिर निर्यात और आयात में कुछ वृद्धि हुई। व्यापाराधेय युद्ध-काल में निरन्तर भारत के पक्ष में रहा किन्तु १९४४-४५ में यह अतिरिक्त बहुत मामूली था।

युद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार

(Foreign Trade in the Post-war Period)—

युद्धोत्तर काल में भारत की आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई। युद्ध काल में आयातों की कमी के कारण देश के उद्योगों को पूँजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल की बहुत अधिक कमी अनुभव हुई जिसके कारण उनका उचित विकास नहीं हो सका। युद्ध समाप्त होते ही इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया और हमारे देश में आयातों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। आरम्भ में उन वस्तुओं को मंगाया गया जिनकी सैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता थी किन्तु इसके पश्चात् खाद्यान्न तथा पूँजीगत वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात किया गया। युद्धोत्तर काल में आयातों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि भारत का व्यापार सन्तुलन विपक्ष में हो गया। आयातों में वृद्धि के साथ-साथ निर्यातों में भी वृद्धि हुई किन्तु आयातों की वृद्धि निर्यातों की वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक थी। युद्धोत्तर काल में आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इस प्रकार थे—(१) उद्योगों के विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं

तथा कच्चे माल की अत्यधिक माग (ii) थाच समस्या के कारण देश में अधिक मात्रा में अनाज का मगाया जाना, आयातों पर लगे युद्धकालीन प्रतिबन्धों में कमी, (19) सरकार की खुली सामान्य अनुज्ञापन प्रणाली (Open General License System)। जहाजों की सुविधायें बढ़ जाने के कारण लोगों ने सरकार की आयात सम्बन्धी उदार नीति से पूरा-पूरा लाभ उठाया और देश में आयातों की मात्रा तेजी के साथ बढ़ने लगी।

सन् १९४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ ही देश का विभाजन हो गया। विभाजन के कारण देश में कच्चे माल की भारी कमी हो गई। जूट, कपास, चमड़ा, तिलहन तथा अन्य वस्तुएँ जो विभाजन से पूर्व भारत में इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती थी कि उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् उनका निर्यात भी कर दिया जाता था, अब बहुत कम मात्रा में हमारे पास रह गईं। इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो हमारी निर्यात कम हो गई और दूसरी ओर अपने उद्योगों को चलाने के लिए हमें इन वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। विभाजन के कारण देश में खाद्य सामग्री की ओर अधिक कमी हो गई और हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज मगाना पड़ा। इन सबका परिणाम यह हुआ कि हमारा व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहने लगा।

युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात का मूल्य	आयात का मूल्य	कुल व्यापार	व्यापाराधेय
१९४५	२२६	२३२	४६१	—३
१९४६	२६६	२६२	५२८	—२६
१९४७	३२०	३३४	६५४	—१४
१९४८	४२८	४५१	८७९	—२३
१९४९	४२३	५४३	९६६	—१२०

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि युद्धोत्तर काल में भारत की निर्यात तथा आयात दोनों में तेजी के साथ वृद्धि हुई किन्तु आयातों में वृद्धि निर्यातों की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेज थी जिसके कारण व्यापाराधेय निरन्तर देश के विपक्ष में रहा। व्यापाराधेय का घाटा १९४५ में ३ करोड़ से बढ़कर १९४९ में १२० करोड़ रुपये हो गया।

अवमूल्यन का विदेशी व्यापार पर प्रभाव (Effect of Devaluation on Foreign Trade)—

नियन्त्रक मन् १९८६ में इंग्लैंड ने अपने डॉलर के घाटे को पूरा करने के लिए पाउंड का अवमूल्यन कर दिया जिसके परिणामस्वरूप पाउंड के मूल्य को ४.०३ डॉलर में घटा कर २.८ डॉलर कर दिया गया। इंग्लैंड के साथ ही पाकिस्तान को छोड़कर स्टैलिन् क्षेत्र के सभी देशों ने अपनी मुद्रायों का अवमूल्यन कर दिया। मन् १९४६ से डॉलर क्षेत्र के साथ भारत का व्यापारांश (Balance of Trade) प्रतिकूल हो गया था जिसके कारण भारत के सम्मुख भी डॉलर समस्या थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने भी इंग्लैंड के साथ ही अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और भारतीय रुपये का मूल्य ३०.२२५ सेंट (Cents) से घटकर २१ सेंट रह गया। रुपये का अवमूल्यन का भारत के विदेशी व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अवमूल्यन करने समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्यातों के बढ़ते तथा आयातों के कम होने के कारण भारत के व्यापार सतुलन में काफी सुधार हो जायगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत से अमेरिका तथा अन्य डॉलर देशों को निर्यात बढ़ा लगे और इन देशों से होने वाली आयात की मात्रा कम हो गई। भारत के व्यापार सतुलन का घाटा कम हो गया और डॉलर समस्या को सुलझाने में काफी सहायता मिली। किन्तु अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तान व्यापार विलुप्त हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया। कुछ समय तक भारत-पाकिस्तान व्यापार विलुप्त स्थिति रहा किन्तु कुछ समयों के द्वारा तथा पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन हो जाने पर यह व्यापार फिर से स्थापित हो गया। अवमूल्यन के पश्चात् भारत के व्यापारांश में होने वाला सुधार निम्न तालिका से स्पष्ट है—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात एवं पुनर्निर्माण	आयात	व्यापारांश
१९४८-४९	८२३	५४३	-१२०
१९४९-५०	४८५	५६४	-१०६
१९५०-५१	६०१	६२३	- २२
१९५१-५२	७३३	६४३	-२१०

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि अवमूल्यन के पश्चात् भारत की व्यापारांश की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। व्यापारांश का घाटा जो १९४८-४९ में १२० करोड़ रुपये था १९५०-५१ में कम होकर केवल २२ करोड़ रुपये रह गया। अवमूल्यन का प्रभाव मन् १९५०-५१ तक समाप्त हो

चुका था और इसके पश्चात् व्यापाराक्षेप का घाटा तेजी के साथ बढ़ने लगा। अत्रमूनन के पश्चात् भारत के व्यापाराक्षेप में होने वाले मुधार के लिए कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार थे — (i) सरकार के द्वारा डॉलर देशों से होने वाली आयातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और इन आवश्यकताओं को स्टॉक क्षेत्र से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। (ii) कोरियन युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण अमेरिका तथा अन्य देशों ने स्टॉक जमा करने आरम्भ कर दिये जिसके कारण भारत की निर्यातों की मांग काफी बढ़ गई थी। (iii) भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण व्यापार की शर्तें देश के पक्ष में हो गई थी। इन सब कारणों से युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि हुई। आयात और निर्यात दोनों ही की प्रवृत्ति बढ़ने की थी। युद्ध समाप्त होने पर १९४५-४६ में हमारे विदेशी व्यापार का कुल मूल्य ४१४ करोड़ रुपये था जो १९५०-५१ में बढ़कर १२२४७१ करोड़ रुपये हो गया। आयातों में वृद्धि का मुख्य कारण अधिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल तथा खाद्य-सामग्री का आयात किया जाना था।

योजना काल में विदेशी व्यापार

(Foreign Trade During the Plan Period)—

सन् १९५१ से भारत में नियोजित आर्थिक विकास का कार्य आरम्भ हुआ। निरोजित विकास के पहले दस वर्षों में आर्थिक विकास का भारत के विदेशी व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिसके कारण व्यापार की मात्रा तथा प्रकृति दोनों में ही परिवर्तन हुए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था का सामान्य विकास होने के कारण आयातों का मुख्य ३६२० करोड़ रुपये था अर्थात् वार्षिक औसत ७२४ करोड़ रुपये रहा। अधिक आयात किये जाने के कारण देश का व्यापाराक्षेप निरन्तर प्रतिकूल रहा और प्रथम योजनाकाल में व्यापाराक्षेप का कुल घाटा ५२२२ करोड़ रुपये था। द्वितीय योजना काल में निर्यातों में तेजी के साथ वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं का आयात किया जाना था। द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में आयात ७४६ करोड़ रुपये से बढ़कर १२३३ करोड़ रुपये हो गई। इसके पश्चात् के दो वर्षों में आयात का स्तर गिर कर ६२८ करोड़ रुपये पर आ गया। आयातों में यह कमी मुख्यतया सरकार के द्वारा आयातों पर कड़ा नियन्त्रण किये जाने के कारण हुई। विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो जाने के कारण सरकार ने आयातों पर विशेष प्रतिबन्ध लगा दिये थे। योजना के अन्तिम वर्ष में आयात १,१०० करोड़ रुपये के थे। द्वितीय योजना काल में कुल मिलाकर ५,३६० करोड़ रुपये का आयात किया गया और वार्षिक औसत १,०७२ करोड़ रुपये था जो प्रथम

योजना के वार्षिक औसत की अपेक्षा १०% अधिक था। आयातों में इस तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार थे—(i) आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजीयन वस्तुओं का आयात किया जाना। (ii) उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित माल का आयात (iii) देश में [वाद्य सफट उत्पन्न हो जाने के कारण अधिक मात्रा में आयात का आयात।

योजना काल के प्रथम दस वर्षों में भारत की निर्यात लगभग स्थिर रही हैं और उनमें प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं की जा सकी। प्रथम योजना काल में निर्यातों का वार्षिक औसत ६०६ करोड़ रुपये था जो कोरियन युद्ध के कारण ही इस स्तर पर बनाय रखा जा सका। द्वितीय योजना काल में निर्यातों का वार्षिक औसत ६१८ करोड़ रुपये था जो इसमें अधिक हो सकता था। यदि १९५८ में अमेरिका तथा यूरोप में अवसाद की दशाय उत्पन्न न हुई होती। दूसरी योजना में निर्यातों की मात्रा पहली योजना की अपेक्षा ६% अधिक थी किन्तु निर्यातों के मूल्यों में प्रतिकूल प्रवृत्ति के कारण निर्यातों के कुल मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी। इस बात में निर्यातों के स्थिर रहने के प्रमुख कारण इस प्रकार थे—(i) देश में वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ जाने के कारण निर्यात के लिए कम मात्रा में उपलब्ध हो सका। (ii) विदेशों में भारतीय वस्तुओं की मांग का कम हो जाना तथा (iii) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य देशों से अधिक प्रतियोगिता। इन सब कारणों में योजना काल के प्रथम दस वर्षों में भारत की निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी और समस्त निर्यातों की कुल निर्यात में भारत का भाग कम हो गया। इन काल में विश्व निर्यातों (World Exports) की मात्रा दुगुनी हो गई किन्तु उनमें भारत का हिस्सा १९५० में २१ प्रतिशत से घटकर १६.० में केवल ११ प्रतिशत रह गया।

तीसरी योजना काल में विदेशी व्यापार

](Foreign Trade During III Plan)—

योजना आयोग का अनुमान था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ५७५० करोड़ रुपये के आयात किये जाने चाहिए। पी० एल० ४८० (P. L. 480) के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात इसमें मुख्य होंगे। इस प्रकार वर्तमान योजना काल में आयातों का वार्षिक औसत १२७० करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो द्वितीय योजना के वार्षिक औसत से लगभग २०० करोड़ रुपये अधिक है। अधिक मात्रा में आयात करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात में वृद्धि की जाय। तीसरी योजना काल में ३७०० करोड़ रुपये का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके आधार पर निर्यात का वार्षिक औसत ७४० करोड़ रुपये होगा जो द्वितीय योजना के वार्षिक औसत से १२६ करोड़ रुपये अधिक है। निर्यातों के इस

ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए योजना आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

(अ) घरेलू उपभोग को उचित सीमाओं के भीतर रखा जाय जिनसे कि निर्यातों के लिए अधिक अतिरिक्त उपलब्ध हो सके ।

(ब) आन्तरिक बाजार में अधिक लाभ प्राप्त करने की सम्भावना हो जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि निर्यातों के सापेक्षिक लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएँ ।

(स) निर्यात उद्योगों में उत्पादन लागत को कम करके उनकी प्रतियोगिता करने की क्षक्ति को बढ़ाया जाय ।

(द) जनता के विचारों को निर्यात के पक्ष में किया जाय जिसके कि वह अधिक निर्यातों के कारण होने वाले कष्ट को सहन कर सके । इस राष्ट्रीय अभियान में उद्योग तथा व्यापार का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

योजना काल में विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारांशेष
१९५०-५१	६५० ५	६०० ७	— ४९ ८
१९५५-५६	७७४ ४	६०८ ८	— १६५ ६
१९६०-६१	१ १४० ०	६६० २	— ४७९ ८
१९६१-६२	१,१०७ ०	६७६ ५	— ४२७ ५
१९६२-६३	१,१३५ ६	७१३ ६	— ४२२ ०
१९६३-६४	१,१४६ ०	७६४ १	— ३८३ ९
१९६४-६४	६८८ ६	४०६ ०	— २८२ ६
(अप्रैल से मितम्बर तक)			

(Source : Eastern Economist Annual Number 1965)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना काल में आयातों की मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ी है । इसमें से अधिकांश वृद्धि द्वितीय और तृतीय योजना काल में हुई है । निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । पहली और दूसरी योजना में निर्यात लगभग स्थिर रहे किन्तु १९६०-६१ के पश्चात् उनमें कुछ वृद्धि हुई है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लगभग स्थिर निर्यात तथा तेजी के साथ बढ़ती हुई आयात ने देश के सम्मुख एक विशेष समस्या उत्पन्न कर दी है जिसे

निर्यातों को प्रोत्साहन देकर ही मुनकाया जा सकता है क्योंकि आर्थिक विकास के काल में आयातों में कमी करना सम्भव नहीं है।

भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप

(Composition of India's Foreign Trade)—

सुदोतर काल में भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि उसकी प्रकृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेषतया योजना काल में हमारे निर्यातों तथा आयातों का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। विदेशी व्यापार के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए आयातों तथा निर्यातों का पृथक्-पृथक् अध्ययन किया जाना चाहिए।

(1) भारत के आयात (Indian Imports) —

योजना काल में भारत के आयातों की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात किया गया है। उसके विपरीत उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं का आयात कम में कम रहने की प्रवृत्ति रही है। देश में खाद्य मकद की स्थिति रहने के कारण अनाज का आयात अधिक मात्रा में किया गया है। योजना काल में भारतीय आयातों का स्वरूप निम्न तालिका में स्पष्ट है—

आयात का स्वरूप
(Structure of Imports)

(१९५१-६१)

(करोड़ रुपये में)

वर्ग (Category)	१९५१-५६ वार्षिक औसत	१९५६-६१ वार्षिक औसत
उपभोग की वस्तुएँ	२३५	२४७
कच्चा माल तथा अर्ध निम्नित वस्तुएँ	३६४	५०२
पूंजीगत वस्तुएँ	१०५	१०३
कुल	७०४	१०५२

(Source - Third Five Year Plan)

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि द्वितीय योजना काल में प्रथम योजना काल की अपेक्षा उपभोग की वस्तुओं की आयात में सबसे कम वृद्धि हुई है जो केवल ५% है। कच्चे माल तथा अर्ध निम्नित माल की आयात तेजी के साथ बढ़ी हैं और उनमें ३५% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि पूंजीगत वस्तुओं

के आयात में हुई है जिनका द्वितीय योजना का वार्षिक औसत प्रथम योजना की प्रवेक्षा १६०% अधिक है। इसमें स्पष्ट होता है कि हमारी आयातों की प्रकृति पूँजीगत वस्तुओं के पक्ष में बदल रही है। नये उद्योग स्थापित हो जाने से कच्चे तथा अर्थनिर्मित माल की माग भी बहुत बढ़ गई है। आयातों की प्रकृति में यह परिवर्तन एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है।

तीसरी योजना काल में यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई है। इस योजना में मशीनों तथा पूँजीगत वस्तुओं की आयात का मूल्य १६०० करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त देश में पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए २०० करोड़ रुपये का अन्य आवश्यक सामान मगाना पड़ेगा। इन सबके अतिरिक्त ६५० करोड़ रुपये का कच्चा माल, अर्थ निर्मित वस्तुएँ तथा आवश्यक उपभोग सामग्री का आयात किया जाना है। इस प्रकार तीसरी योजना में आयातों के कुल मूल्य का ३६% पूँजीगत वस्तुओं की आयात पर व्यय किया जाना है। दूसरी योजना में यह व्यय ३० प्रतिशत था। तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में हमारी आयातों का स्वरूप निम्न तालिका से स्पष्ट है—

भारत के आयात व्यापार का स्वरूप

(१९६१-६२ से १९६३-६४ तक)

(करोड़ रुपयों में)

वस्तुएँ	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
१. खाद्य पदार्थ	१४७.०७	१७६.४१	१६३.०१
२. पैय और तम्बाकू	१.६५	१.६६	१.०७
३. कच्चा माल	१२६.८६	१२७.२०	१२२.५८
४. पैट्रोलियम और सम्बन्धित वस्तुएँ	६५.८६	८७.६७	१०४.५२
५. धनस्वपति तेल आदि	८.६२	५.६३	४.८७
६. रसायनिक पदार्थ	८६.७६	१००.५२	८८.४०
७. निर्मित वस्तुएँ	२२१.१६	२०३.६५	१६५.५३
८. मशीनें तथा परिवहन सम्बन्धी सामान	३६७.५२	३८७.३८	४२१.५७
९. अन्य निर्मित वस्तुएँ	२१.६६	३०.७३	३५.३८
कुल	१,०८३.२२	१,१२४.४५	१,१३६.६३

(Source : Monthly Statistics of Foreign Trade in India)

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में भी मशीनरी के आयात में वृद्धि हुई है, खाद्य पदार्थों का आयात भी अधिक किया गया है तथा पेट्रोलियम व उससे सम्बन्धित वस्तुओं का आयात बढ़ा है। अन्य निर्मित वस्तुओं का आयात भी अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की वस्तुओं का आयात १९५३-६४ में १९६१-६२ की अपेक्षा कम रहा है।

योजना काल में लोहे और इस्पात का सामान, धातुयें तथा धातुओं का सामान, मशीनरी तथा परिवहन सम्बन्धी सामान का आयात विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। मशीनों की आयात का मुख्य निरन्तर बढ़ता रहा है। सन् १९५०-५१ में केवल ८७.५ करोड़ रुपये की मशीनें आयात की गईं जबकि १९६३-६४ में आयात की जाने वाली मशीनों का मूल्य ४२१.६ करोड़ रुपये था। खनिज तेल की आयात भी तेजी के साथ बढ़ी है और १९५०-५१ में ५५ करोड़ रुपये से १९६३-६४ में १०४.५ करोड़ रुपये हो गई है। इसी प्रकार रसायनिक पदार्थों की आयात में भी अच्छी प्रगति हुई है। दूसरी और तीसरी योजना काल में खाद्य प्रभ की आयात में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। रई, जूट, ऊन, मिर्क का घागा, चीनी, रंग तथा अन्य उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं की आयात कम हो गई है जिसका प्रमुख कारण देश में इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाना है। फल, सब्जी, तम्बाकू, कागज, फाटोप्राफी का सामान आदि की आयात प्रायः स्थिर रही है। रसायनिक खाद, दवाई, अनाज, रबर इत्यादि की आयात में परिवर्तन होते रहे हैं।

(11) भारतीय निर्यात

(Indian Exports)—

योजना काल में यद्यपि निर्यातों की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है किन्तु उनके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हुआ है। योजना आयोग के अनुसार नियोजन के प्रथम दस वर्षों में भारतीय निर्यातों के स्वरूप में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखलाई देती हैं—प्रथम, कृषि उत्पादन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आधारित वस्तुओं के निर्यात में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस श्रेणी में चाय, सूती कपड़ा, जूट का सामान, खाले, मसाले, तम्बाकू इत्यादि आ जाते हैं। इन वस्तुओं का कुल निर्यात योजना काल में गिरा है। द्वितीय, तैयार माल तथा कच्चे लोहे का निर्यात काफी बढ़ा है किन्तु यह वृद्धि परम्परागत निर्यातों की गिरावट को पूरा नहीं कर सकी है। नियोजन के प्रथम दस वर्षों में निर्यातों का स्वरूप आगे दी तालिका से स्पष्ट है।

निर्यात का स्वरूप
(Pattern of Exports)
(१९५१-१९६०)

(करोड़ रुपये में)

वस्तुयें	१९५०-५१	१९५१-५६	१९५८-५९	१९५९-६०
१ कृषि वस्तुयें और सम्बन्धित निर्यात वस्तुयें	४९६.५	४८९.३	४५३.५	४७३.६
२ अन्य निर्यात वस्तुयें	५८.४	६१.०	५३.३	१०५.०
३ खनिज पदार्थ	२३.४	३४.४	४६.२	५३.०
कुल	५७८.३	५८४.७	५५३.०	६३१.६

(Source : Third Five Year Plan)

हमारी सबसे महत्वपूर्ण निर्यात चाय, जूट, जूट का सामान, रई तथा सूती कपड़ा है। सन् १९५०-५१ में कुल निर्यातों में इनका भाग ६४% था जो इनके महत्व को विदित करता है। सन् १९६१-६२ में इनका भाग गिरकर ५०% रह गया। इस काल में इन तीनों में से चाय का निर्यात अधिक तेजी के साथ बढ़ा है जो १९५०-५१ में ८० करोड़ रुपये से बढ़कर १९६१-६२ में १२१ करोड़ रुपये हो गया। जूट के सामान का निर्यात १९५०-५१ में ११४ करोड़ रुपये था जो १९५१-५२ में एकदम बढ़कर २७० करोड़ रुपये हो गया किन्तु इसके पश्चात् १२० करोड़ रुपये के समीप स्थिर रहा है। रई और सूती कपड़े का निर्यात १९५०-५१ में १५६ करोड़ रुपये था जो कुछ समय तक गिरने के पश्चात् १९५५-५६ में फिर १७० करोड़ रुपये हो गया, किन्तु १९६१-६२ में यह निर्यात केवल ६७ करोड़ रुपये था। इस प्रकार इन तीन महत्वपूर्ण निर्यातों में चाय की निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है, जूट का निर्यात लगभग स्थिर रहा है (केवल १९५१-५२ में वह बहुत ऊँचा था) और सूती कपड़े का निर्यात गिरा है।

इस दशक में कच्ची धातुओं के निर्यात में विशेष वृद्धि हुई है जिनका निर्यात १९५०-५१ में ६.७ करोड़ रुपये से बढ़कर १९५५-५६ में २३ करोड़ तथा १९६१-६२ में २७ करोड़ रुपये हो गया। इसके अतिरिक्त फल, सब्जो, ऊन व ऊन का सामान, कॉफी, मछली, चीनी, जूते, अजोयार, मशीने तथा तेल की निर्यात में भी वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। वनस्पती तेल, तम्बाकू, मसाले, गोद, लाख इत्यादि का निर्यात गिरा है। ऊनी कपड़ा, अफीम, इमारती लकड़ी आदि का निर्यात लगभग स्थिर रहा है जबकि सीमेंट, कोयला, खनिज तेल और कोक का निर्यात बदलता रहा है। इस विस्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय निर्यातों का विविधिकरण नहीं हुआ है। अभी भी कुल निर्यात के तीन चौथाई में केवल १२ वस्तुओं का निर्यात आता है, शेष एक चौथाई भाग में अन्य एक हजार से भी अधिक वस्तुएं आती हैं। कुछ नई वस्तुओं का निर्यात आरम्भ हुआ है और उनकी निर्यात में काफी वृद्धि भी हुई है किन्तु फिर भी उनमें अधिक विदेशी विनिमय साधन प्राप्त नहीं हो सके हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भी भारतीय निर्यातों का स्वरूप लगभग इसी प्रकार का रहा है और उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं। द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय योजना काल में निर्यातों में वार्षिक औसत वृद्धि १२० करोड़ रुपये की होती है। यह वृद्धि मुख्यतया कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की निर्यात बढ़ा कर ही प्राप्त की जाती है। अन्य प्रकार की वस्तुओं की निर्यात में कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है। तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यातों का स्वरूप निम्न प्रकार रहा है—

निर्यात का स्वरूप
(Pattern of Exports)
(१९६१-६२ से १९६३-६४ तक)

(करोड़ रुपये में)

वस्तुएं	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
१. खाद्य पदार्थ	२१४०	२२३६	२४८५
२. पेय और तम्बाकू	१५०	१८६	२१०
३. कच्चा माल	११२४	११११	१३१५
४. खनिज ईंधन	२६	६५	७७
५. वनस्पति तेल आदि	६५	१३६	२०४
६. रसायनिक पदार्थ	७८	७८	६६
७. निमित्त माल	२६६८	२६६७	२६६१
८. मशीनें तथा परिवहन सम्बन्धी सामान	४७	६५	६६
कुल	६६०३	६८५५	७६६६

(Source Monthly Statistics of the Foreign Trade in India)

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि तृतीय योजना के पहले तीन वर्षों में निर्यातों में कुछ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतया निमित्त माल, मशीनें, वनस्पति तेल व खनिज ईंधन की निर्यात में हुई है। कच्चे माल का निर्यात बहुत कम बढ़ा है, खाद्य पदार्थों का निर्यात मामूली बढ़ा है तथा रसायनिक पदार्थों का

निर्यात गिरा है। तीसरी योजना काल में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और उसमें कुछ सफलता भी मिली है किन्तु निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकी है। सरकार मुख्यतया लोहा, इस्पात तथा इनकी ढकी हुई एवं निर्मित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। चीनी, मछली, साईकिल, सिलाई मशीन, बिजली की मोटर, मशीन टूल, प्लास्टिक का सामान तथा अन्य निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

(Direction of India's Foreign Trade) —

द्वितीय विश्व-युद्ध में पूर्व भारत का साम्राज्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था और हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों के साथ होता था किन्तु युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में भारत ने अन्य देशों के साथ भी अपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। जहाँ तक निर्यातों का सम्बन्ध है इंग्लैंड तथा साम्राज्य देश हमारी निर्यातों का महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं। सन् १९०६ से १९१४ के बीच भारतीय निर्यातों में इन देशों का भाग ४१% था जो १९४५ में बढ़कर ६०% हो गया। किन्तु इसी काल में भारत की आयातें साम्राज्य देशों से गिरी हैं। सन् १९०६ और १९१४ के बीच भारतीय आयातों का ७० प्रतिशत भाग इंग्लैंड तथा साम्राज्य देशों से आता था किन्तु १९४५ में इन देशों का भाग घट कर केवल ३७% रह गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में साम्राज्य देशों के साथ भारतीय निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु इन देशों से आयात की मात्रा कम होती गई है।

योजना काल में विदेशी व्यापार की दिशा

(Direction of Foreign Trade During the Plan Period) —

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् और विशेषतया नियोजित आर्थिक विकास धारम्भ हो जाने पर भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ है। इस काल में कुछ नये देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है, विशेषतया अमेरिका के साथ हमारे व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार बढ़ा है। इन नई प्रवृत्तियों के होते हुए भी हमारा अधिकांश व्यापार इंग्लैंड तथा साम्राज्य देशों के साथ ही होता है।

भारत के विदेशी व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इंग्लैंड का है। सन् १९५१-५२ में भारत ने अपनी आवश्यकताओं का २१ प्रतिशत इंग्लैंड से आयात किया, जो १९५५-५६ में बढ़कर २५.४ प्रतिशत हो गया किन्तु १९६१-६२ में गिरकर १८.७ प्रतिशत रह गया। हमारी निर्यातों में भी इंग्लैंड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन् १९५०-५१ में भारतीय निर्यातों में उसका हिस्सा २३.५ प्रतिशत

था जो १९५५-५६ में बढ़कर २८.८ प्रतिशत हो गया और १९६१-६२ में गिरकर २८ प्रतिशत रह गया। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड भारतीय आयातों तथा निर्यातों में अपना महत्वपूर्ण स्थान खोता जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व भारतीय आयातों में उसका हिस्सा ३० प्रतिशत तथा निर्यातों में ३४ प्रतिशत था किन्तु १९६१-६२ में यह भाग क्रमशः १८.७ प्रतिशत तथा २४ प्रतिशत था। इंग्लैंड में हम मशीनें, औजार, मोटरे, रसायनिक पदार्थ, दवाइयाँ, रंग आदि माते हैं और इसके बदले में जूट का सामान, चाय, खाने, गोद, तेल के बीज आदि का निर्यात ब्रिटेन को किया जाता है।

हमारे व्यापार में दूसरा महत्वपूर्ण देश अमेरिका है जिसके साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है। युद्ध में पूर्व हमारी आयातों में उसका भाग केवल ७ प्रतिशत था किन्तु १९५०-५१ में यह बढ़कर १८.६ प्रतिशत हो गया और १९६१-६२ में २२.५ प्रतिशत था। हमारी निर्यातों में युद्ध से पूर्व अमेरिका का भाग ६ और १० प्रतिशत के बीच रहता था, १९५०-५१ में यह लगभग १६ प्रतिशत था और १९६१-६२ में १८ प्रतिशत था। मन् १९४६ में अवमूल्यन के पश्चात् अमेरिका को भारतीय निर्यातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सन् १९५५-५६ में कुल जूट निर्यात का लगभग २ अमेरिका ने लिया। इसी वर्ष चाय की कुल निर्यात लगभग ११ करोड़ रुपये की जिसमें से ६ करोड़ रुपये की चाय अमेरिका को निर्यात की गई। भारतवर्ष अमेरिका को बच्चा जूट, जूट का सामान, जानवरों की खाने, लाख, बालू, तेल के बीज, ममाले, मन्दल की लकड़ी आदि वस्तुएँ भेजता है तथा अमेरिका में मशीनें, औजार, रंग इन्जिन, ट्रैक्टर, तेल निकालने तथा माफ करने वाली मशीनें, मोटरे, दवाइयाँ, रसायनिक पदार्थ, तन्त्राङ्ग, घनाज, लई आदि वस्तुएँ मगाना है।

पश्चिमी जर्मनी का स्थान हमारे विदेशी व्यापार में विचित्र है। हमारे आयातों में उसका हिस्सा निरन्तर बढ़ता जा रहा है किन्तु निर्यातों में उसका हिस्सा बहुत कम है। आयातों का १% से भी कम जर्मनी में आता था। १९५०-५१ में उसका भाग १.८ प्रतिशत था जो १९५५-५६ में बढ़कर ८.८ प्रतिशत हो गया और १९६१-६२ में ८.७ प्रतिशत था। इसके विपरीत निर्यातों में पश्चिम जर्मनी का भाग बहुत कम रहा है और उसमें कोई वृद्धि भी नहीं हुई है। युद्ध से पूर्व हमारी निर्यातों का ५ प्रतिशत पश्चिमी जर्मनी को जाता था। १९५०-५१ में उसका भाग केवल १.८ प्रतिशत रह गया और १९६१-६२ में २.६ प्रतिशत था। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी जर्मनी ने साथ व्यापार में हमें काफी घाट रहता है।

भारतीय व्यापार का लगभग आधा भाग इन तीनों देशों के ऊपर निर्भर है। मन् १९५०-५१ में भारतीय आयातों में इन तीनों देशों का हिस्सा ४१ प्रतिशत था जो १९६१-६२ में बढ़कर ४६.६ प्रतिशत हो गया। निर्यातों में तीनों

देशों का भाग १९५०-५१ में ४४.५ प्रतिशत तथा १९६१-६२ में ४४.५ प्रतिशत था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिन देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है उनमें रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देश प्रमुख हैं। इसके विपरीत भारत का व्यापार फ्रांस, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जापान तथा बर्मा के साथ गिरा है।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका के द्वारा जाना जा सकता है—

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा
(Direction of India's Foreign Trade)

(प्रतिशत भाग)

देश/क्षेत्र	निर्यात			आयात		
	१९५२	१९५६	१९६०	१९५२	१९५६	१९६०
१. पूर्वी तथा सुदूर पूर्व के देश	२५.७	१६.३	१७.०	१३.६	१०.४	१३.१
जापान	४.१	४.६	५.५	२.४	५.२	५.४
२. पश्चिमी एशिया	५.७	५.८	६.५	७.७	१०.८	७.५
३. अफ्रीका	३.६	३.६	२.५	३.८	४.०	४.४
४. पश्चिमी योरोप	२६.६	३६.८	३८.५	३०.१	५०.१	४०.४
इंग्लैंड	२०.५	२६.८	२७.५	१८.५	२५.०	२०.०
यूरोपीय आर्थिक समाज (E.E.C.)	७.५	८.३	८.०	८.८	२०.०	१८.०
५. पूर्वी योरोप तथा चीन	१.३	३.५	८.०	२.२	४.२	३.७
६. उत्तरी अमरीका	२१.१	१७.०	१८.७	३७.३	१२.४	२५.२
सं. रां. अमरीका	१६.०	१४.७	१६.०	३३.६	११.३	२३.७
७. लैटिन अमरीका	१.४	१.०	२.५	—	०.१	०.१
८. ओसेनिया (Oceania)	४.३	४.४	३.१	१.७	१.७	२.३
९. अन्य	७.३	८.३	३.२	३.३	४.३	३.३
कुल	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०

(Source : Third Five Year Plan)

इस तालिका को देखने से पता चलता है कि भारत की निर्यातों का ३६ प्रतिशत पश्चिमी योरोप को जाता है जिसमें से २८ प्रतिशत इंग्लैंड जाता है। निर्यातों में इंग्लैंड का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों से निश्चित रहा है तथा उत्तरी

अमेरिका का भाग कुछ कम हुआ है। योरोपीय आर्थिक समाज वाले देशों का भाग पिछले दस वर्षों में बढ़ता रहा है। रूस तथा पूर्वी योगोपीय देशों का भाग भारतीय निर्यात में बढ़ रहा है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में यह १ प्रतिशत था जबकि दूसरी योजना के अन्त में बढ़कर ८ प्रतिशत हो गया। आयातों में पश्चिमी योरोप का भाग १९५२ में ३०.१ प्रतिशत से बढ़कर १९५६ में ५०.१ प्रतिशत हो गया किन्तु द्वितीय योजना काल में इन देशों का भारतीय आयातों में भाग गिरा है और १९६० में इनमें होने वाले आयात का भाग घटकर ४०.४ प्रतिशत रह गया जिसमें से २० प्रतिशत आयात इंग्लैंड से किया गया। भारत के विदेशी व्यापार में अमेरिका का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका में १९५२ में भारतीय आयातों का ३७.३ प्रतिशत भाग आया था जो १९५६ में गिरकर १२.४ प्रतिशत रह गया किन्तु १९६० में बढ़कर २५.२ प्रतिशत हो गया। पूर्वी एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों से होने वाला व्यापार प्रायः स्थिर रहा है, पश्चिमी एशिया की निर्यात गिराई है तथा निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अफ्रीका को निर्यात कम हुई है तथा आयातों में कुछ वृद्धि हुई है। पूर्वी योगोप को निर्यात कुछ बढ़ी है किन्तु आयातों कुछ कम हुई है।

तृतीय योजना काल (Third Plan Period)---

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। प्रथम तथा द्वितीय योजना काल की प्रवृत्तियाँ ही अधिक मजबूत हो गई हैं। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका ने भारतीय विदेशी व्यापार में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है क्योंकि इस काल में अमेरिका से हमारी आयातें बहुत तेजी से साथ बढ़ी हैं। इंग्लैंड का स्थान दूसरा है, उसके पश्चात् पश्चिमी योगोप के अन्य देश आते हैं। एक नई प्रवृत्ति यह मिलती है कि भारतीय व्यापार में रूस भी धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है तथा अन्य एशियायी देशों के साथ भी भारत का व्यापार बढ़ा है। तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विदेशी व्यापार की दिशा अगले पृष्ठ पर दी तालिका में विदित है।

अगले पृष्ठ की तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में अमेरिका से आयात तेजी के साथ बढ़ी हैं तथा निर्यात की मात्रा भी कुछ बढ़ी है। मन् १९६१-६२ में अमेरिका से आयात २५५.५ करोड़ रुपये के थे किन्तु १९६३-६४ में यह बढ़कर ३६०.२ करोड़ रुपये हो गये। इस काल में इंग्लैंड की निर्यात कम बढ़ी है तथा आयात १९६१-६२ में २००.५ करोड़ रुपये से गिरकर १९६३-६४ में १६८.६ करोड़ रुपये रह गई हैं। योरोपीय आर्थिक समाज के देशों की निर्यात कुछ बढ़ी है किन्तु आयात कम हो गई हैं। रूस की निर्यात में विशेष वृद्धि हुई है और १९६१-६२ में निर्यात ३२.२ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६३-६४ में ५२.३ करोड़ रुपये हो गई है। इसी काल में रूस से आयात

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा
(Direction of India's Foreign Trade)
(१९६१-६२ से १९६३-६४ तक)

(करोड़ रुपये में)

देश/क्षेत्र	निर्यात			आयात		
	६१-६२	६२-६३	६३-६४	६१-६२	६२-६३	६३-६४
१. अमेरिका (U.S.A)	११५.७	११४.३	१२८.७	२५५.५	३४६.८	३६०.२
२. इंग्लैंड	१६०.६	१६३.२	१६१.४	२००.५	१८५.६	१६८.६
३. योरोपीय आर्थिक समाज (E.E.C.)	५१.८	४८.८	५७.१	१६१.२	१५८.१	१६७.८
४. रूस	३२.२	३८.३	५२.३	३६.६	५८.६	६४.०
५. रूस के प्रतिरिक्त अन्य एशियन देश	१०८.६	६७.१	१४२.६	१२०.२	१२७.६	११३.६

(Source Monthly Statistics of Foreign Trade in India)

भी बढ़ी है और १९६१-६२ में ३६.६ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६३-६४ में ६४ करोड़ रुपये हो गई है। अन्य एशियन देशों के साथ निर्यात बढ़ी है किन्तु आयात कम हो गई है। सन् १९६३-६४ में हमारी कुल आयातों का ३४.१ प्रतिशत अमेरिका में, १४.७ प्रतिशत इंग्लैंड से, १२ प्रतिशत योरोपीय आर्थिक समाज के देशों में ६.२ प्रतिशत अन्य एशियन देशों से तथा ५.६ प्रतिशत रूस से प्राप्त हुआ। हमी वष निर्गतों का २१ प्रतिशत इंग्लैंड को, १८.५ प्रतिशत अन्य एशियन देशों को, १६.६ प्रतिशत अमेरिका को, ७.२ प्रतिशत योरोपीय आर्थिक समाज के देशों को तथा ६ प्रतिशत रूस को भेजा गया।

योजना काल में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ

(Main Features of Foreign Trade during Plan Period)—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तथा विशेषतया योजना काल में भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, प्रकृति तथा दिशा सभी में परिवर्तन हुआ है। योजना काल में हमारे विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित रही हैं—

(१) व्यापार में वृद्धि (Expansion of Foreign Trade)—योजना काल में हमारी आयातों तथा निर्यातों की मात्रा और मूल्य दोनों में ही विशेष वृद्धि हुई है। इसमें पूर्व जितना विदेशी व्यापार होता था अब उससे बहुत अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है। देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है। निर्यातों की मात्रा भी बढ़ी है

किन्तु यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। प्रथम योजना आरम्भ होने के समय १९४६-५० में भारत का कुल विदेशी व्यापार १०७६ करोड़ रुपये का था, किन्तु प्रथम योजना काल का वार्षिक औसत १३३३ करोड़ रुपये था। प्रथम योजना के दूसरे वर्ष १९५१-५२ में कोरियन युद्ध की अनामान्य दशाओं के कारण हमारी निर्यातों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई। दूसरी योजना काल में विदेशी व्यापार का औसत बढ़ कर १६८६ करोड़ रुपये हो गया और तीसरी योजना में विदेशी व्यापार का वार्षिक औसत २०१० करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि योजना काल में हमारे विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।

(२) आयातों में निर्यातों की अपेक्षा तेजी के साथ वृद्धि (Imports increased faster than Exports) — इस काल में हमारे व्यापार की एक विशेषता यह रही है कि आयातों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है किन्तु निर्यातों लगभग स्थिर रही हैं। केवल तीसरी योजना काल में निर्यातों में कुछ वृद्धि करना सम्भव हो सका है। आयातों में विशेष वृद्धि का प्रमुख कारण आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अविन माना में विदेशों से सामान का मंगाया जाना है। देश में दाखल मकट की स्थिति के कारण घनाज का आयात भी अधिक हुआ है। निर्यातों में विशेष वृद्धि इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की माग प्रायः स्थिर रही है। कुछ नई वस्तुओं का निर्यात आरम्भ किया गया, किन्तु पुरानी वस्तुओं का निर्यात गिर गया। अतः इस काल में निर्यातों की अपेक्षा आयातों अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं।

(३) पूँजीगत वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात (Increased Import of Capital Goods) — योजना काल में हमारी आयातों के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आर्थिक विकास के लिए अविकाशिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं को आयात किया गया है तथा उपभोग सम्बन्धी आयातों की कम से कम रहने का प्रयत्न किया गया है। पूँजीगत वस्तुओं के साथ साथ कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं का आयात भी अधिक हुआ है। आजकल भारत मुख्यतया कच्चे माल, मशीनें तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं का आयात करता है तथा तैयार माल का आयात बहुत कम किया जाता है जो देश के औद्योगिककरण का प्रमाण है। औद्योगिक विकास के लिए हमें मशीनें और कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना होता है।

(४) कुछ नई वस्तुओं का निर्यात (Export of some new Commodities) — योजना काल में निर्यातों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। परम्परागत निर्यातों के स्थान पर अब कुछ नई वस्तुओं का निर्यात आरम्भ हो गया है। निर्मित माल तथा अर्धनिर्मित माल का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाने लगा है तथा वृत्ति पर आधारित वस्तुओं का निर्यात कम होना जा रहा है। कच्चे माल का

निर्यात अब हमारे देश से बहुत कम होने लगा है क्योंकि उसका अधिकांश भाग हमारे उद्योगों के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। इसके स्थान पर भारत से तैयार माल का निर्यात अधिक माना में किया जाने लगा है।

(५) व्यापाराधेय में निरन्तर तथा बढ़ता हुआ घाटा (Continuous and Increasing Trade Deficit)—योजना काल में भारत का व्यापार सन्तुलन निरन्तर घटे में रहा है और यह घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता रहा है। मुख्यतया डॉलर देशों के साथ हमारा भुगतान सन्तुलन अधिक प्रतिकूल रहा है। व्यापाराधेय के इस घाटे का प्रमुख कारण आयातों का निर्यातों की अपेक्षा अधिक होना है। योजना काल में अधिक मात्रा में मशीनों, खाद्यान्न, जूट व रूई का आयात किया गया है किन्तु निर्यातों को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है। योजना काल की सबसे प्रमुख समस्या यह रही है कि एक ओर तो नियोजित विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अधिक मात्रा में आयात करना पड़ा है और दूसरी ओर प्रयत्न करने पर भी निर्यातों को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है।

(६) अमरीका का महत्वपूर्ण स्थान—योजनाकालीन व्यापार में अमरीका का आयत्त महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। अब हमारे व्यापार में अमरीका का हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया है और इंग्लैंड तथा साम्राज्य देशों का महत्व कुछ कम हो गया है। हमारे देश में अमरीका से बहुत अधिक मात्रा में सामान मंगाया जाने लगा है। अमरीका को होने वाली निर्यातों में भी कुछ वृद्धि हुई है किन्तु आयातों की अपेक्षा वह बहुत कम है।

(७) नये देशों के साथ व्यापार (Trade with new Countries)—योजना काल में भारत के विदेशी व्यापार का विस्तार कुछ नई दिशाओं में हुआ है। भारत ने अपने व्यापारिक सम्बन्ध रूस, पूर्वी योरोप, अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी (Middle East) देशों के साथ स्थापित किये हैं। हमारा तैयार माल मध्यपूर्व के देशों को जाने लगा है और वहाँ से हम रूई तथा खनिज तेल का आयात करते हैं। हम तथा अन्य साम्यवादी देशों के साथ भी हमारे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापार का विस्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(८) आयातों तथा निर्यातों पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Imports and Exports)—योजना काल में देश के दुर्लभ विदेशी विनिमय साधनों का उचित प्रयोग करने के उद्देश्य से सरकार ने आयातों तथा निर्यातों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। डॉलर की कमी के कारण डॉलर क्षेत्र से होने वाली आयातों पर कड़ा नियन्त्रण कर दिया गया है तथा इन क्षेत्रों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सभी प्रकार के कच्चे माल की निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(६) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना (Establishment of State Trading Corporation)—सन् १९५५ में सरकार ने आवश्यक व्यापार को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए एक राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) स्थापित की है जो निर्यातों को प्रोत्साहन देन तथा आयातों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य में कार्य कर रही है।

भारत की व्यापारिक नीति (Indian Trade Policy)—

युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में भारत की व्यापारिक नीति का विकास निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। द्वितीय युद्ध काल में भारत की व्यापारिक नीति का उद्देश्य विदेशों में अधिक मात्रा में सस्ती सामान खरीदना तथा विदेशी विनिमय साधनों के प्रयोग में बचन करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा आयातों तथा निर्यातों पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगा दिये गये। युद्ध के उपरान्त भी इन नियन्त्रणों को हटाना सम्भव न हो सका क्योंकि भारत में छाद्यात की कमी के कारण हमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाज मगाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का आयात भी आवश्यक था, किन्तु देश की निर्यात क्षमता सीमित थी। इस स्थिति में आयात व निर्यात नियन्त्रण आवश्यक था और इसलिए उसे युद्धोत्तर काल में भी जारी रखा गया। योजना काल में आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यापारिक नीति का निर्माण किया गया। भारत की व्यापारिक नीति को समझने के लिए आयात तथा निर्यात नीतियों का अलग-अलग अध्ययन करना आवश्यक है।

आयात नीति (Import Policy)—

आयात नियन्त्रण के विषय में सलाह देने के लिए सरकार ने सन् १९४८ में एक आयात सलाहकार परिषद् स्थापित की। इस परिषद् ने आयातों के लिए अनुज्ञापन देने के उद्देश्य से आयात वस्तुओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया—
(i) ऐसी वस्तुएँ जिनके लिए आयात अनुज्ञापन दिये जा सकते हैं। (ii) वे वस्तुएँ जो खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licence) के अन्तर्गत आती हैं। (iii) ऐसी वस्तुएँ जिनके आयात के लिए केवल सीमित अंश तक ही अनुज्ञापन दिये जा सकते हैं। आयातों के सम्बन्ध में उदार नीति के कारण बहुत अधिक मात्रा में आयात कर लिए गये जिनका भुगतान सीमित विदेशी विनिमय साधनों के द्वारा सम्भव न था। इस कठिनाई से बचने के लिए सन् १९४८-५० में आयात नियन्त्रणों को अधिक कड़ा कर दिया गया। कुछ खुले अनुज्ञापन (Open General Licence) स्थगित कर दिये गये तथा बहुत ही सीमित मात्रा में वस्तुओं को बिना अनुज्ञापन के केवल स्टॉकिंग क्षेत्र में मगाने की आज्ञा दी गई। जून सन् १९४८ में डॉलर क्षेत्र में आयात त्रिगुल बन्द कर दिये गये किन्तु कुछ समय पश्चात् १९४८ में भी गई

आयातों से २५% कम के आधार पर डॉलर देशों में आयात फिर आरम्भ कर दी गई। सितम्बर १९४६ के पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु फिर भी आयातों के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाना सम्भव नहीं था।

सन् १९४० में सरकार ने श्री० जी० एल० मेहता (G. L. Mehta) की अध्यक्षता में एक आयात नियन्त्रण जांच समिति (Import Control Enquiry Committee) नियुक्त की जिसने आयात नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इस समिति के अनुसार आयात नियन्त्रण के तीन उद्देश्य होने चाहिए—

- (i) आयातों को कुल उपलब्ध विदेशी विनिमय की सीमाओं के भीतर रखना।
- (ii) विदेशी विनिमय को इस प्रकार वितरित करना कि उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य वस्तुओं के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। (iii) विशेष वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को नियन्त्रित करना। इस समिति ने व्यवसायिक आयातों को ४०० करोड़ रुपये की सीमा के भीतर रखने की सिफारिश की। आयातों को विभिन्न श्रेणियों में बाँट दिया गया तथा प्राथमिकता देने के क्रम को इस प्रकार निश्चित किया गया—
- (i) आवश्यक कच्चा माल, (ii) मशीनों के पुर्जें, (iii) कृषि यन्त्र, (iv) प्रस्तुत उद्योगों के लिये मशीनरी (v) आवश्यक उपभोग वस्तुएँ, (vi) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनें, (vii) नये उद्योगों के लिए मशीनें, (viii) अन्य आवश्यक सामान।

सन् १९४० तथा १९४१ में आयात नीति में फिर संशोधन हुआ और उसे कुछ उदार कर दिया गया। औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन अनुज्ञापन नीति का निर्माण किया गया। जून १९४१ में आयातों को कुछ और छूट दी गई और सोहा, इस्पात, पीतल का सामान, तांबे का तार, कागज इत्यादि की आयातों को खुले सामान्य अनुज्ञापन के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया। सन् १९४५ तथा १९४६ में उदार आयात नीति को स्वीकार किया गया जिसका उद्देश्य निम्न प्रकार की वस्तुओं का काफी मात्रा में आयात करना था—(i) औद्योगिकरण का आवश्यकता को पूरा करने के लिए मशीनें तथा कच्चा माल। (ii) लघु उद्योगों के लिए मशीनें व औजार तथा (iii) वे वस्तुएँ जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में अधिक मात्रा में किया जा रहा था उनके अग्र्यश को काफी कम कर दिया गया। इस नीति के कारण हमारी आयात बहुत अधिक बढ़ गई और व्यापाराशेप का घाटा बढ़ने लगा जिसके परिणामस्वरूप सरकार को कड़ी आयात नीति को अपनाना पड़ा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ही विदेशी विनिमय सबट उत्पन्न हो जाने के कारण सरकार को आयात कम करने की नीति को अपनाना पड़ा।

सन् १९५७ से आयातों की मात्रा को काफी कम कर दिया गया। कुल आयात में उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं का अनुपात जो १९५२-५३ में ३०.० प्रतिशत था, १९६०-६१ में घट कर १८.७ प्रतिशत रह गया। पूँजीगत तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की आयात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये।

मुद्रालयार समिति की सिफ रिजें

(Recommendations of the Mudaliar Committee)—

तृतीय योजना काल में सरकार ने आयात नीति को जाँच करने के लिए एक आयात निर्यात नीति समिति (Committee on the Import & Export Policy), जिसे मुद्रालयार समिति के नाम से जाना जाता है, नियुक्त की जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट मार्च १९६२ में प्रस्तुत की गई। सरकार की वर्तमान आयात व निर्यात नीति का निर्माण मुख्यतः इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ है। समिति ने यह स्वीकार किया है कि चात्र आयातों (Maintenance imports) तथा विकास सम्बन्धी आयातों (Development imports) में पूर्णरूप से भेद करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे दूसरे से सम्बन्धित हैं। समिति के अनुसार हमारी नीति वर्तमान सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक सामग्री की आयात की सुविधायें देना होनी चाहिए किन्तु निम्न क्षेत्रों में स्थिति होन वाले नये उद्योगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए—(i) शक्ति तथा परिवहन, (ii) निर्मित उद्योग (iii) वे उद्योग जो ऐसे कच्चे माल तथा अन्य सामान का उत्पादन करते हैं जो इस समय विदेशों से मगाया जाता है (iv) ऐसे उद्योग जो पूर्णतया देशी कच्चे माल पर निर्भर हैं और जो मशीनों की आयात के लिए विदेशी विनिमय का प्रबन्ध स्वयं कर लेते हैं।

मुद्रालयार समिति ने आयातों को अनुज्ञापन देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशों की हैं—

(१) भविष्य में समस्त वस्तुओं का आयात अनुज्ञापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए किन्तु यदि आयातों पर अधिक कड़ा नियन्त्रण करने की आवश्यकता हो तो दूसरी दुर्भाई में आयातों में प्रतिशत कमी की जा सकती है। सरकार ने इस सिफारिश पर पूर्ण रूप से विचार किया किन्तु विदेशी विनिमय संकट तथा अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसे स्वीकार करना सम्भव न हो सका और वर्ष में दो बार अनुज्ञापन देने की नीति को जारी रक्खा गया।

(२) वास्तविक उपभोक्ताओं (Actual users) तथा स्थापित आयातकर्ताओं के प्रारम्भिक लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष होनी चाहिए।

(३) बची हुई मात्रा से सम्बन्धित लाइसेन्सों को छोड़ कर अन्य प्रकार के लाइसेन्सों को नया करने की शक्ति क्षेत्रीय लाइसेन्सिंग अधिकारी को दे देनी चाहिए।

(४) सामान्यतः स्थापित आयातकर्ताओं के लाईसेन्स की अवधि को नहीं घटाया जाना चाहिए किन्तु विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(५) प्रत्येक अनुज्ञापन काल से सम्बन्धित मौद्रिक सीमा की सूचना सभी लाईसेंसिंग अधिकारियों को अनुज्ञापन काल के आरम्भ होने के समय मिल जानी चाहिए।

(६) समिति ने आयातकर्ताओं की सहायता करने तथा अनुज्ञापन विधि को सरल बनाने के उद्देश्य से अनुज्ञापन कार्य के विदेशीकरण करने का सुझाव दिया।

समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और उन्हें कार्य रूप में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

निर्यात नीति (Export Policy)—

हमारी निर्यात नीति को निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है—(i) उपभोग की वस्तुओं तथा कच्चे माल की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करना। (ii) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्तियों को रोकना। (iii) पर्याप्त विदेशी विनिमय साधनों को प्राप्त करना। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् निर्यात नीति का प्रमुख उद्देश्य अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय को अर्जित करना रहा है। योजना काल से पूर्व हमारे देश में निर्यातों को नियन्त्रित रखने की नीति को अपनाया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्यात अभ्यर्थ निश्चित किये जाते थे। निर्यात अभ्यर्थ प्रति वर्ष घोषित किये जाते थे और इनकी मात्रा वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनके मूल्यों पर निर्भर रहती थी। सन् १९४८-४९ में निर्यातों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अनुभव की गई और निर्यात प्रोत्साहन समिति १९४९ की सिफारिश पर निर्यात की जाने वाली बहुत-सी वस्तुओं पर कर कम कर दिये गये अथवा बिलकुल हटा दिये गये। सन् १९५०-५१ में स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत-सी उपभोग की वस्तुओं का निर्यात बिलकुल बन्द कर दिया गया अथवा उसे स्थगित कर दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्यात अभ्यर्थ (Export Quotas) उदार रूप से दिये गये जिससे अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित किया जा सके। यद्यपि अभ्यर्थों में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता था किन्तु फिर भी अधिक मात्रा में निर्यात करना हमारी निर्यात नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। कुछ नई वस्तुओं के निर्यात की आज्ञा दी गई तथा पुरानी वस्तुओं के बढ़ा दिया गया। निर्यात वस्तुओं के मूल्यों तथा उन पर लगने वाले करों में भी आवश्यक परिवर्तन किये गये। सन् १९५२-५३ में जूट के सामान, रुई तथा सूती कपड़े पर निर्यात शुल्क

कम कर दिया गया। उत्पादकों को निर्यात के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मूत्रिमार्ग दी गई। द्वितीय योजनाकाल में विदेशी विनिमय मकट उत्पन्न हो जाने के कारण निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक था। सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन समिति (Export Promotion Committee), जिसे गोरवाला समिति (Gorwala Committee) भी कहा जाता है, निर्दुक्त की जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट १९५१ में प्रस्तुत की गई। इस समिति ने निर्यातों को बढ़ाकर ७०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष के स्तर पर लाने की सिफारिश की। गोरवाला समिति के अनुसार हमारी निर्यात नीति के लिए यह आवश्यक है कि (i) सभी क्षेत्रों में, विशेषतया कृषि में उत्पादन की निरन्तर वृद्धि की जाय। (ii) मूल्यों की प्रतियोगितात्मक स्तर पर लाने रखवा जाय। (iii) घरेलू उपयोग को कम करके भी निर्यात को बढ़ाना चाहिए। (iv) निर्यातों तथा निर्यात दाजारों का विविधिकरण होना चाहिए (v) परम्परागत निर्यात की वस्तुओं के नये उपयोगों की खोज करनी चाहिए। इस समिति ने निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुझाव दिये। सरकार ने इन सुझावों को मान लिया और उनके आधार पर ही अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया। इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्न कार्य किये—(i) जूट और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के सट्टे को प्रबंध घोषित कर दिया गया। (ii) सरकार ने निर्यात माल के निर्यात नियन्त्रणों को ढीला कर दिया और अनुज्ञापन की विधि को सरल कर दिया गया। (iii) निर्यात की वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री व पैकिंग का सामान कन्ट्रोल दरों पर दिया गया तथा व्यापारियों को दानाघान की विशेष सुविधायें दी गईं। (iv) यदि भारतीय माल की कोई शिकायत आती थी तो उस पर शीघ्र विचार किया जाता था। (v) निर्यात किये जाने वाले माल पर विक्री कर हटा दिया गया तथा अन्य करों को भी कम कर दिया गया। (vi) निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक निर्यात जोखिम बीमा निगम (Export Risk Insurance Corporation) की स्थापना की गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति के विकास के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(१) निर्यात में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि आन्तरिक उपयोग की वृद्धि को नियन्त्रण में रखा जाय। इसके लिए कुल या प्रति व्यक्ति उपयोग को कम करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसमें वृद्धि की दर को नीचा रखा जाना चाहिए।

(२) निर्यात सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए यह भी आवश्यक है कि निर्यात के लिए अनिच्छित प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर उपलब्ध हो। इसके लिए विकास सम्बन्धी मुद्रा-प्रसार के दबाव को नियन्त्रण में रखा जाना चाहिए।

(३) यह भी आवश्यक है कि भारतीय उद्योग के काफी बड़े भाग की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि की जाय। विशेषतया जूट, सीमेंट, साइकिलें, विजली के

मोटर और ट्राम्पकार्मर तथा रेयन आदि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

(४) विदेशी विनिमय को बाँटते समय निर्यात उद्योगों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जहाँ तक भी सम्भव हो सके उद्योगों की सलाह से वस्तुओं की वह मात्रा निश्चित होनी चाहिए जो वे निर्यात के लिए उपलब्ध कर सकेंगे । कुछ उद्योगों में जहाँ निर्यात के लिए अतिरिक्त प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हो, प्रत्येक कारखाने के द्वारा वस्तु की आन्तरिक बाजार में बेची जाने वाली मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए, जिसमें कि छेप उत्पादन निर्यात के लिए उपलब्ध हो सके ।

(५) विदेशी बाजारों की खोज करने तथा उनके सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करने में निर्यात प्रोत्साहन समितियों (Export Promotion Councils) को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए ।

(६) अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्यातों के विकास में राज्य व्यापारिक (State Trading) व्यवस्था महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है । सहकारी संस्थाओं के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

मुदालियर समिति की सिफारिशें (Recommendations of the Mudaliar Committee)—अभी हाल में मुदालियर समिति ने हमारी निर्यात नीति की जाँच की है और निर्यात प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । समिति का विचार है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निर्यात की मात्रा को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए । हमें केवल अपनी परम्परागत निर्यातों को ही नहीं बढ़ाना है बल्कि नई दिशाओं तथा नई वस्तुओं का निर्यात भी आरम्भ करना है । समिति ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

(१) प्रति वर्ष एक निर्यात योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न वस्तुओं के निर्यात लक्ष्य निश्चित करने चाहिए, जिन्हें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बाँट दिया जाय । समिति ने निर्यात उद्योगों को सहायता दिये जाने तथा उनके द्वारा निर्यात सम्बन्धी बायदों के पूरे किये जाने पर बराबर जोर दिया है ।

(२) व्यापारियों के लिए निर्यात व्यापार को लाभपूर्व बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह उन्हें विशेष प्रकार की छूट, वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन दे ।

(३) समिति के विचार से अभी तक जो प्रोत्साहन निर्यातों के लिए दिये गये हैं वे मामूली तथा अपर्याप्त हैं । इसके लिए प्रभावशाली समन्वय करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(४) निर्यात प्रोत्साहन डाइरेक्टरेट (Export Promotion Directorate) को अधिक शक्तिशाली बनाया जाय तथा उसमें एक नीति निर्धारण केन्द्र (Policy Cell) स्थापित किया जाय।

(५) समिति ने निर्यातकर्त्ताओं को निम्नलिखित सहायता तथा प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है—(i) अधिक आयातों के द्वारा इन उद्योगों को अधिक मात्रा में अच्छा माल दिया जाना चाहिए। (ii) एक आयात-निर्यात स्थायीकरण कोष (Import Export Stabilisation Fund) स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें से इस प्रकार की अनिश्चित आयातों का प्रबन्ध किया जाय। (iii) निर्यात कर्त्ताओं को निर्यातों से होने वाले लाभ पर आय-कर से छूट दी जानी चाहिए। (iv) निर्यात प्रोत्साहन नीति को सभी प्रकार के निर्यातों के सम्बन्ध में लागू किया जाना चाहिए। (v) रेलवे को सभी प्रकार की वस्तुओं पर, जो निर्यात की जायें, २५% की किराये में छूट देनी चाहिए। (vi) कुछ उद्योगों की निर्यात सम्बन्धी विशेष कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। (vii) निर्यातों पर सेलटैक्स की छूट देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए और इस सम्बन्ध में २% की सामान्य छूट दी जानी चाहिए। (viii) उद्योग तथा व्यापार के नेताओं को घरेलू उद्योगों के लिए ये चीजें जाने वाली वस्तुओं पर एक मामूली तुल्य (Cess) लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। इसमें होने वाले लाभ से निर्यातों को सहायता दी जानी चाहिए।

(६) समिति ने अन्य बहुत-सी सिफारिशें की हैं जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय मेसो में भाग लेना, भारतीय रुपये में भुगतान की व्यवस्था, राख्य व्यापार, वस्तु विनिमय व्यापार, निर्यात सम्बन्धी जोलिम की गारंटी, विदेशों में भारत का व्यापारिक प्रतिनिधित्व आदि।

सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों पर पूरा ध्यान दिया है और उन्हें कार्यक्रम में लाने के लिए यथामुम्भव प्रयत्न किये जा रहें हैं।

भुगतान सन्तुलन

(Balance of Payments)

भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) व्यापारादेश्य (Balance of Trade) की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है क्योंकि उसके अन्तर्गत व्यापारिक भुगतानों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के विदेशी भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारादेश्य के द्वारा किसी देश की भुगतान सम्बन्धी स्थिति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें केवल वस्तुओं की आयात तथा निर्यात का मूल्य ही सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की अदृश्य मदों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसीलिए विदेशी भुगतान सम्बन्धी स्थिति का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भुगतान सन्तुलन का अध्ययन ही अधिक वैज्ञानिक है।

युद्धोत्तर काल में भारत के सम्मुख विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई रही है क्योंकि हमारा व्यापाराक्षेप निरन्तर विपक्ष में रहा है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही देश में विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो गया था जिसने हमारे विकास सम्बन्धी प्रयत्नों को भीमित कर दिया है। अभी तक भी यह संकट की स्थिति बनी हुई है और निकट भविष्य में भी कोई विशेष सुधार होने की सम्भावना नहीं है। भारत के व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है—

भारत का व्यापाराक्षेप
(India's Balance of Trade)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापाराक्षेप
१९४६-४७	६४७.६	५०६.०	— १४१.६
१९४७-४८	६५०.५	६००.७	— ४६.८
१९४८-४९	७७४.४	६०८.८	— १६५.६
१९४९-५०	१,१४०.०	६६०.२	— ४७९.८
१९५०-५१	१,१०७.०	६७६.५	— ४२७.५
१९५१-५२	१,१२५.६	७१३.६	— ४१२.०
१९५२-५३	१,१४६.०	७६४.१	— ३८१.९
१९५३-५४	५५३.३	४१३.८	— १३९.५
(अप्रैल से मितम्बर तक)			

(Source : Eastern Economist—Annual 1914)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना काल में आयातों के तेजी के साथ बढ़ने तथा निर्यात के प्रायः स्थिर रहने के कारण हमारा व्यापाराक्षेप निरन्तर विपक्ष में रहा है। हमारा भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) भी इस काल में प्रतिकूल ही रहा है, यद्यपि कुछ वर्षों में अदृश्य मदों से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त के कारण यह घाटा कुछ कम हो गया है। भुगतान सन्तुलन की स्थिति अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिखलाई गई है।

इस तालिका को देखने से पता चलता है कि हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति १९४८-४९ से निरन्तर प्रतिकूल चल रही है। प्रथम योजना काल के अन्त तक यह घाटा कुछ कम था जिसका मुख्य कारण अदृश्य मदों से होने वाली वृद्धि

भारत का भुगतान सन्तुलन (India's Balance of Payments)

(करोड़ रुपये में)

	१९४८-४९ से १९५०-५१	१९५१-५२ से १९५५-५६	१९५६-५७ से १९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
व्यापार सन्तुलन	- ३७७	- ५४२	- ७,३३६	- ३३८	- ४०६	- ४२६
ग्रहण्य मदों में वचन	+ ११५	+ ३६७	+ ४७०	- १५	- १३	+ १५
भुगतान सन्तुलन	- ७६७	- १७५	- ६८६०	- ३५३	- ४२२	- ४१४

धी। मन् १९५१-५२ से लेकर १९६०-६१ तक भुगतान सन्तुलन की स्थिति घण्टन गम्भीर थी। इन पाँच वर्षों में हमें भुगतान सन्तुलन में लगभग १६१० करोड़ रुप का घाटा रहा, जिसके कारण देश में विदेशी विनिमय सङ्कट उत्पन्न हो गया। सरकार ने भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए आयातों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न किया किन्तु अधिक सफलता नहीं मिल सकी। मन् १९६१-६२ में हमारे भुगतान सन्तुलन का घाटा ३५३ करोड़ रुप था जो १९५६-५७ में १६६०-६१ तक के पाँच वर्षों के वार्षिक औसत से कुछ ही कम था। मन् १९६१-६४ में यह घाटा बढ़ कर ४१४ करोड़ रुप हो गया। इनमें स्पष्ट है कि द्वितीय तथा तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल में विदेशी विनिमय सङ्कट की स्थिति बराबर बनी रही है।

भारत में विदेशी विनिमय सङ्कट

(Foreign Exchange Crisis in India)—

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में विदेशी विनिमय स्थिति सन्तोषजनक थी। इस योजना के पाँच वर्षों में विदेशी विनिमय का कुल घाटा ३१८ करोड़ रुप था जिसे पूरा करने के लिए हमें १२७ करोड़ रुपरा अथवा विदेशी विनिमय कोष में न निबालना पड़ा। इनके विपरीत द्वितीय योजना काल में हमें विदेशी कर्जाओं का प्रामाणा करना पड़ा है। द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में ही हमारे विदेशी विनिमय कोषों में ४८१ करोड़ रुपों की कमी हो गई और वे निरन्तर घिरते ही गये। तीसरी योजना के आरम्भ तक ये कोष इतने कम हो गये कि अब उन्हें और अधिक कम

करना सम्भव नहीं था। द्वितीय योजना काल में विदेशी विनिमय का कुल घाटा २,०५६ करोड़ रुपये था जबकि योजना आयोग का अनुमान केवल १,१२० करोड़ रुपये के घाटे का था। घाटे को पूरा करने के लिए हमें विदेशी विनिमय कोषों में से ६०० करोड़ राया निकालना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप हमारे विदेशी विनिमय कोष द्वितीय योजना के अन्त में केवल ३०३ ६ करोड़ रुपये रह गये जबकि आरम्भ में वे ८२४.६ करोड़ रुपये थे। इस प्रकार द्वितीय योजना काल में हमारे विदेशी विनिमय कोषों में भारी कमी हो गई और देश में विदेशी विनिमय सकट उत्पन्न हो गया।

विदेशी विनिमय संकट के कारण

(Causes of Foreign Exchange Crises)—

(१) आयातों में बहुत अधिक वृद्धि (Excessive Increase in Imports)—

दूसरी योजना काल में हमारी आयातें बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं। आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात करना पड़ा। निजी क्षेत्र में भी विनिमय के तेजी के साथ बढ़ने के कारण काफी बड़ी मात्रा में मशीनें, औजार तथा कच्चा माल आयात किया गया जिसके कारण विदेशी विनिमय स्थिति और खराब हो गई। आयातों के तेजी के साथ बढ़ने का एक कारण यह भी था कि द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में सरकार की आयात नीति काफी उदार रही है और इस काल में इतने अधिक आयात अनुज्ञापन (Import Licences) दिये गये कि उनके भुगतान के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करना बटिन हो गया। इसके अतिरिक्त देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति खराब हो जाने के कारण हमें अधिक मात्रा में सुरक्षा सम्बन्धी सामान विदेशों से आयात करना पड़ा।

(२) कृषि उत्पादन में कमी (Poor Agricultural Production)—

इस योजना काल में मौसम खराब रहने के कारण लगातार दो वर्षों तक अच्छी फसल न हो सकी और कृषि उत्पादन में काफी कमी आ गई जिसके कारण हमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में अनाज मगाना पड़ा। भुगतान संतुलन के अनुमान में केवल ६० लाख टन अनाज मगाने की व्यवस्था की गई थी जबकि वास्तविक आयात लगभग २ करोड़ टन की थी। अनाज आयातों का इतना अधिक बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय स्थिति खम्भीर हो गई। खर्च का आयात भी काफी बड़ी मात्रा में दिया गया।

(३) विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का नीचा अनुमान (Under-estimate of Foreign Exchange Requirements)—सरकारी प्रोजेक्ट्स पर व्यय होने वाले विदेशी विनिमय का गही अनुमान नहीं लगाया जा सका और उनके लिए जितनी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई थी उसमें उन्हें पूरा करना सम्भव

नहीं था। अतः योजना के अन्तर्गत बहुत नए प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी विनिमय के अनुमान को घटाना पड़ा, विशेषतया रेलों के विभाग व सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता काफी बढ गई। इस प्रकार बहुत नए सरकारी प्रोजेक्ट्स पर अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय व्यय हो जाने के कारण माल की स्थिति और गम्भीर हो गई।

(४) आयातों के मूल्य में वृद्धि (Increased Cost of Imports)—द्वितीय योजना काल में आयातों की लागत काफी बढ गई जिसके कारण हमें अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय का व्यय करना पड़ा। आयातों की लागत बढने का मुख्य कारण उनकी कीमतों का बढ जाना तथा यातायात व्यय का अधिक होना था। विशेषतया लोहा, इस्पात तथा मशीनों की कीमतें बढ गई और हमें ऊँची कीमतों पर ही उन्हें खरीदना पड़ा।

विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए किये गये उपाय

(Measures Adopted to Combat Foreign Exchange Crisis)—

विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए सरकार ने द्वारा बहुत से उपाय किये गये जिनके परिणामस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु तृतीय योजना काल में विदेशी विनिमय माधनों की कमी बराबर बनी रही। सरकार के द्वारा किये जाने वाले प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन (Change in Currency System)—आर्थिक विकास के नामों के लिए अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय को मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार ने अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना लिया। पुरानी प्रणाली में विदेशी विनिमय माधनों का काफी बड़ा भाग पत्र मुद्रा कोष के रूप में पड़ा रहता था, किन्तु नई प्रणाली के अन्तर्गत एक न्यूनतम कोष रखने के पश्चात् कोष विदेशी विनिमय का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रादान करने में किया जा सकता है।

(२) योजना में परिवर्तन (Revision of the Plan)—द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस योजना के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इतनी अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी कि वह हमारी अर्थ-व्यवस्था की क्षमता में बाहर है। अतः मई सन् १९५८ में योजना को कुछ कम किया गया और केवल अत्यन्त आवश्यक प्रोजेक्ट्स (Core Projects) पर ही साधनों को केन्द्रित करने का निर्णय किया गया। इसके अन्तर्गत इस्पात के कारखाने, कोयला खाने, रेलवे, बन्दरगाहों तथा कुछ शक्ति उत्पन्न करने की योजनाओं को सम्मिलित किया गया।

(३) आयातों पर प्रतिबन्ध (Restriction on Imports)—आयातों को कम करने के लिए सरकार ने १९५८ से अपनी आयात नीति को काफी सहज कर

दिया । उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के आयात को या तो बिलकुल बन्द कर दिया गया या उसमें काफी कमी की गई । वस्तुओं के आयात अम्यन्त (Import Quotas) कम कर दिये गये तथा खुले सामान्य अनुज्ञापन पद्धति (Open General Licence System) को बन्द कर दिया गया । इस प्रकार आयातों को कम करके विदेशी विनिमय के व्यय में कमी करने का प्रयत्न किया गया ।

(४) स्थगित भुगतान पद्धति को अपनाना (System of Deferred Payments was Adopted)—विदेशी विनिमय साधनों के वर्तमान प्रयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यक आयातों को स्थगित भुगतान के आधार पर प्राप्त करने का प्रयत्न किया । आयातों के भुगतान को लम्बे समय पर फैला दिया गया । नई योजनाओं के लिए आयात अनुज्ञापन अभी ही दिये गये जबकि इन आयातों का प्रबन्ध स्थगित भुगतान के आधार पर करना सम्भव होता था ।

(५) निर्यात प्रोत्साहन (Export Promotion)—अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय साधनों को अर्जित करने के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति को अपनाया । सन् १९५७-५८ में कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम कर दिये गये और बहुत-सी वस्तुओं के निर्यात अम्यन्त बढ़ा दिये गये । निर्यात प्रोत्साहन समितियाँ (Exports Promotion Councils) स्थापित की गईं । निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर रेल किराया कम कर दिया गया । बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते (Bilateral Trade Agreements) किये गये तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) एवं निर्यात जोखिम बीमा निगम (Export Risks Insurance Corporation) स्थापित की गईं ।

(६) अधिक विदेशी सहायता (Increased Foreign Assistance)—सरकार ने मित्र देशों में अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया । इस दिशा में हमें काफी सफलता मिली और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्य संस्थाओं में अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त किया जा सके । अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हो जाने के कारण ही हमारे लिए दूमरी योजना के प्रोजेक्ट्स को पूरा करना सम्भव हो सका है ।

तीसरी योजना में विदेशी विनिमय स्थिति

(Foreign Exchange Situation in the Third Plan)—

तीसरी योजना में १०,४०० करोड़ रुपये का कुल विनियोग किया जाना है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से २,१०० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी । इसमें १,६०० करोड़ रुपये मशीनों तथा अन्य प्रकार की पूँजीगत वस्तुओं की आयात पर व्यय किया जाना है और २०० करोड़ रुपये पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों के भाग, औजार तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मगाने पर

व्यय होगा। इसके अनिश्चित ३,६५० करोड़ रुपये ऐसे सामान की आयात पर व्यय होगा जो नि वर्तमान उद्योगों को चलाने तथा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार नीमरी योजना वाल में विदेशी विनिमय के कुल भुगतानों का अनुमान ५,७५० करोड़ रुपय है। उसी वल में निर्यातों में ३,८०० करोड़ रुपये से अधिक आयदनी नहीं हो सकती है। यह तृतीय योजना काल में २,८०० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की कमी रहने का अनुमान है जिसे विदेशी सहायता के द्वारा पूरा किया जाना है। देश के विदेशी विनिमय कोषों में कोई कमी नहीं की जा सकती है क्योंकि वे घट कर न्यूनतम सीमा पर आ गये हैं। इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना काल में हमारे विदेशी विनिमय माध्यमों पर दबाव बना रहेगा। इस योजना के पहले दो वर्षों में निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी है जिसके कारण विदेशी विनिमय की रकियाई बराबर बनी रही है और विदेशी विनिमय कोष में कुछ कमी हुई है। सन् १९६३-६४ में निर्यातों के बढ़ जाने के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ था और विदेशी विनिमय माध्यमों में कुछ वृद्धि हो गई थी। किन्तु सन् १९६४-६५ में भुगतान समतुलन की स्थिति फिर खराब हो गई है और धाटे को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय कोषों में कमी करनी पड़ी है। जनवरी सन् १९६५ में हमारी विदेशी विनिमय निधि घट कर केवल १०० करोड़ रुपये रह गई है और भुगतान समतुलन की स्थिति बिनाजमक हो गई है। इस वर्ष उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय संकट का मुख्य कारण सरकार के अधिक मात्रा में अनाज तथा कृत्रिम खाद का आयात, जहाजों के किराये में वृद्धि तथा विदेशी ऋणों पर सूद का भुगतान है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) भारत के विदेशी व्यापार में सन् १९४७ के उपरान्त क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं? स्पष्ट कीजिए और समझाइये कि क्या ये परिवर्तन देश के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं? (आगरा बी० ए० १९५८)
- (२) भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप (Pattern) में जो परिवर्तन सन् १९३६ के बाद हुए हैं उनका वर्णन करिये। (आगरा बी० ए० १९५६ स)
- (३) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत के व्यापार समतुलन में जो गिरावट आती जा रही है उसके कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिये। इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठायायेंगे? (इसाहाबाद बी० ए० १९५४)
- (४) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सन् १९४७ के बाद और सन् १९३६ के पहले के समय में क्या और क्यों अन्तर हुआ? (आगरा बी० ए० १९५७ स)
- (५) "कुछ भी हो, व्यापार के समतुलन से सम्पूर्ण बातों का ज्ञान नहीं होता है"—भारत व इंग्लैंड की स्थिति के दृष्टिकोण से इस कथन की परीक्षा करिए। (आगरा बी० ए० १९५६)

खण्ड २

विदेशी विनिमय

FOREIGN EXCHANGE

विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग विस्तृत तथा संकुचित दोनों प्रकार के अर्थों में किया जा सकता है। विस्तृत अर्थ के अनुसार विदेशी विनिमय से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से होता है, जिनके द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाया जाता है। उसके अन्तर्गत विदेशी भुगतानों से सम्बन्धित सभी समस्याएँ आ जाती हैं। हार्टले विदर्स (Hartley Withers) के अनुसार, “विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन का विज्ञान तथा कला है।”¹ विज्ञान के रूप में उसका सम्बन्ध उस विनिमय दर से होता है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है तथा वे सब रीतियाँ भी उसके अन्तर्गत आ जाती हैं, जिनके द्वारा विदेशी भुगतानों की जटिल समस्या को सुलझाया जाता है। कला के रूप में विदेशी विनिमय का सम्बन्ध उन सब सस्याओं तथा यन्त्रों (Instruments) से होता है, जिनके द्वारा भुगतानों को निबटाया जाता है। अतः विदेशी विनिमय के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दर, विदेशी भुगतानों को निबटाने में सहायता देने वाली सस्याएँ तथा वे सब यन्त्र (Instruments) आ जाते हैं, जिनके द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाया जाता है।

कभी-कभी विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में भी किया है। संकुचित दृष्टि से विदेशी विनिमय से हमारा अभिप्राय—(i) विदेशी विनिमय पत्रों तथा उन बैंक ड्राफ्टों से होता है, जिनका प्रयोग भुगतानों को निबटाने के लिए किया जाता है। जब हम यह कहते हैं कि विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करते हैं, तो यहाँ पर हमारा अभिप्राय केवल विदेशी विनिमय पत्रों से होता है। (ii) कभी-कभी विदेशी विनिमय शब्द विदेशी विनिमय दरों को भी बतलाता है। जब यह कहा जाता है कि किसी देश का विदेशी विनिमय उसके पक्ष अथवा विपक्ष में है, तो उससे हमारा अभिप्राय विदेशी विनिमय दर के पक्ष अथवा विपक्ष में होने से होता है। (iii) विदेशी विनिमय का प्रयोग उस समस्त व्यवस्था को

बतलाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसके द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाया जाता है। प्रो० चैपमैन (Chapman) के अनुसार, "विदेशी विनिमय का अभिप्राय उस मशीनरी से है, जिसके द्वारा विदेशी व्यापार में भुगतान किये जाते हैं।"² यद्यपि इन दोनों ग्रंथों में विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु सामान्यतः वह उस समस्त व्यवस्था को बतलाता है, जिसके द्वारा एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। उसके अन्तर्गत उन यन्त्रों, साधनों तथा रीतियों का अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाया जाता है।

विदेशी विनिमय की समस्या (Problem of Foreign Exchange)—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में विदेशी विनिमय की समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न मुद्रायें चलाई जाती हैं और प्रत्येक देश के व्यापारी अपने ही देश की मुद्रा में भुगतान स्वीकार करते हैं। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसके सामने विदेशी भुगतानों को निबटाने की समस्या उत्पन्न होती है। मुद्राओं की भिन्नता के कारण विदेशी भुगतानों को निबटाना उतना आसान नहीं होता है जितना कि आन्तरिक भुगतानों को निबटाना। विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए हमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना होता है। विभिन्न देशों की मुद्राओं के इस क्रय-विक्रय को ही विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी भुगतानों को निबटाने की समस्या आन्तरिक विनिमय से बिल्कुल पृथक् नहीं की जा सकती है। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि आन्तरिक विनिमय में केवल एक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है किन्तु विदेशी विनिमय में विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। जब तक एक व्यापारी देश के अन्दर व्यापार करता है तो भुगतान की समस्या सरल होती है किन्तु जैसे ही वह विदेशों से सामान खरीदना चाहता है, भुगतान की समस्या एकदम जटिल हो जाती है क्योंकि उसमें विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग करना होता है। स्वर्णमान के युग में विदेशी भुगतानों की समस्या इतनी जटिल नहीं जितनी कि आजकल हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की रीतियाँ

(Methods of International Payments)—

प्राचीन समय में विदेशी भुगतानों को निबटाने का प्रमुख तरीका एक देश से दूसरे देश को सोने का निर्यात करना था। सोने के निर्यात तथा आयात के द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाना बहुत आसान होता था किन्तु समय के साथ विदेशी भुगतानों को निबटाने की इस पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया। यह अनुभव किया

गया कि विदेशी भुगतान करने के लिए सोने का आयात तथा निर्यात करने में बहुत अप्रव्यय होता है और प्रत्येक देश अपनी आयातों के लिए निर्यातों के द्वारा ही भुगतानों को निबटा सकता है। आधुनिक समय में विदेशी भुगतानों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाने के लिए अब सोने का आयात तथा निर्यात नहीं होता है बल्कि साख-पत्रों के क्रय-विक्रय के द्वारा ही विदेशी भुगतानों को निबटा लिया जाता है। विदेशी भुगतानों को निबटाने की इस नई पद्धति में—(अ) सोने के प्रयोग में बहुत अधिक बचत होती है। (ब) एक देश से दूसरे देश को बड़ी मात्रा में सोना भेजने में लगने वाले समय, असुविधा तथा व्यय की बचत होती है। (स) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को सुविधापूर्ण करके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियाँ इस प्रकार हैं—

(i) विदेशी विनिमय बिल (Foreign Bill of Exchange), (ii) बैंकर्स ड्राफ्ट (Banker's Draft) तथा (iii) टेलीग्राफिक ट्रान्सफर्स (Telegraphic Transfers)।

विदेशी विनिमय बिल (Foreign Bill of Exchange)—

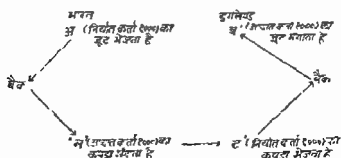
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतानों को सामान्यतः विदेशी विनिमय बिलों के द्वारा निबटाया जाता है। जिस प्रकार विदेशी व्यापार में साख-पत्रों के द्वारा बहुत-से भुगतानों को निबटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए विनिमय-पत्रों का प्रयोग होता है। यह एक आश्चर्य की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाने के लिए मुद्रा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अधिकांश भुगतानों को केवल साख-पत्रों द्वारा दायित्वों को हस्तान्तरित करके चुका दिया जाता है और मुद्रा का प्रयोग केवल लेन-देन की यात्री को चुकाने में किया जाता है। इन दायित्वों का हस्तान्तरण मुख्यतः विदेशी विनिमय बिल के द्वारा किया जाता है। विदेशी बिल आन्तरिक बिल से केवल इस बात में भिन्न होता है कि उनका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। विदेशी विनिमय बिल वस्तु के निर्यातकर्ता के द्वारा लिखा जाता है और दूसरे देश में वस्तु के आयात करने वाले व्यक्ति पर लिखा जाता है। इस बिल में आयातकर्ता (Importer) को यह आदेश दिया जाता है कि वह बिल की रकम का भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को निश्चित अवधि के पश्चात् कर दे। बिल प्रायः निर्यातकर्ता (Exporter) के देश की मुद्रा में लिखा जाता है और उसमें बिल लिखते समय प्रचलित विनिमय दर को भी बताया जाता है। बिल लिखने के पश्चात् उसका लिखने वाला उसे अपने बैंक के पास ले जाता है और बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। यद्यपि बिल को अभी तक आयातकर्ता के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु फिर भी बैंक उस बिल को अपने पक्ष में हस्तान्तरित कराकर उस पर स्वयं उधार दे देता है। सुरक्षा की दृष्टि से बैंक बिल

को भुनाने से पूर्व जहाज पर माल लादने का प्रमाण-पत्र तथा बीमे की रसीद भी उमके साथ लेता है। इन सब पत्रों को लेने के पश्चात् बिल को रकम बटौती काट कर निर्यातकर्ता को दे दी जाती है।

विनिमय बिल किस प्रकार कार्य करता है ?

(How a Bill of Exchange Works)---

प्रत्येक विदेशी विनिमय बिल दो विदेशी भुगतानों को एक साथ निबटाता है। विनिमय बिल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी भुगतानों को निम्न प्रकार निबटाता है यह हम एक बिल की दो देशों के बीच कार्य विधि को देखकर ही समझ सकते हैं। मान लिया कि भारत का एक जूट व्यापारी 'अ' (₹१०००) रुपये का जूट का सामान इंग्लैंड के व्यापारी 'ब' को निर्यात करता है। भारत का एक दूसरा व्यापारी 'स' इंग्लैंड के व्यापारी 'द' से (₹१०००) रुपये की कीमत का कपड़ा मगाता है। इस व्यापार के परिणामस्वरूप 'ब' को एक हजार रुपये के बराबर भुगतान 'अ' को देना है और 'स' को एक हजार रुपये का भुगतान 'द' को भेजना है। यह दोनों ही भुगतान एक विनिमय पत्र के द्वारा निबटाये जा सकते हैं। भारत में जूट का निर्यातकर्ता 'अ' इंग्लैंड के आयातकर्ता 'ब' पर एक विनिमय बिल लिखेगा और उसे बैंक घयवा 'स' व्यापारी को बेचकर अपनी जूट का भुगतान प्राप्त कर लेगा। भारत का 'स' व्यापारी उस बिल को खरीदने के पश्चात् इंग्लैंड के निर्यातकर्ता 'द' के पास भेज देगा जो अपने बैंक के द्वारा बिल की रकम को 'ब' से ले लेगा। इस प्रकार मोने के आयात निर्यात के बिना दोनों स्थानों को एक विनिमय पत्र की सहायता से निबटाया जा सकता है। विनिमय बिल की इस कार्य प्रणाली को निम्न प्रकार के चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है—



उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही विनिमय बिल दोनों भुगतानों को निबटा देता है। 'अ' के द्वारा 'ब' पर लिखे गये बिल की सहायता से 'अ' को अपने जूट के सामान का भुगतान प्राप्त हो जाता है और 'द' को अपनी कपड़े की निर्यातों का मूल्य भी प्राप्त हो जाता है अतः एक विनिमय बिल दो

भुगतानों को एक साथ निबटाता है और मुद्रा का कोई आयात तथा निर्यात नहीं किया जाता है।

बैंकर्स ड्राफ्ट (Banker's Draft)—

जिस प्रकार भ्रान्तरिक क्षेत्र में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा मुद्रा का हस्तान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है ठीक उसी प्रकार विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए भी बैंकर्स ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यह तब ही सम्भव होता है जब बैंक की विदेशों में शाखाएँ होती हैं। यदि किसी व्यापारी को इंग्लैंड भुगतान भेजना है तो वह उस रकम को भारतवर्ष में किसी विनिमय बैंक के पास जमा करा देता है और बैंक उसे अपनी इंग्लैंड की शाखा पर उस रकम का एक ड्राफ्ट लिख देता है। व्यापारी उस ड्राफ्ट को इंग्लैंड के व्यक्ति के पास भेज देता है जो वहाँ के बैंक से उसका भुगतान ले लेता है। इस प्रकार ड्राफ्ट एक बैंक से उसकी शाखा के लिए या किसी अन्य बैंक के लिए यह आदेश होता है कि ड्राफ्ट की रकम उसके वाहक (Bearer) भ्रमण उस पर लिखित व्यक्ति को माग करने पर दे दे। यद्यपि यह समझा जाता है कि ड्राफ्ट भुगतानों को तुरन्त निबटा देता है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जितना समय बैंक ड्राफ्ट के जाने में लगता है उसका भुगतान उतने ही समय के पश्चात् मिलता है। यदि दो देशों के बीच डाक पहुँचने में १० दिन लगते हैं तो किसी व्यक्ति को निश्चित समय पर भुगतान करने के लिए १० दिन पूर्व ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा।

टैलिग्राफिक ट्रांसफर (Telegraphic Transfer)—

आजकल टैलिग्राफिक ट्रांसफर के द्वारा विदेशी भुगतानों को निबटाने का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। इस विधि से विदेशी भुगतानों को तुरन्त निबटाया जा सकता है। टैलिग्राफिक ट्रांसफर बैंक का एक प्रकार का दर्शनी ड्राफ्ट होता है जिसे डाक से न भेज कर तार के द्वारा भेजा जाता है। साधारण ड्राफ्ट को भेजने में काफी समय लग जाता है इसलिए व्यापारी टैलिग्राफिक ट्रांसफर के द्वारा अपने विदेशी भुगतानों को निबटाते हैं।

इनके अतिरिक्त विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit), यात्री चेक (Traveller's Cheques) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मनीऑर्डरों का प्रयोग भी किया जाता है।

विदेशी विनिमय दर (Foreign Rate of Exchange)—

प्रत्येक देश की अपनी अलग मुद्रा होती है और एक देश की मुद्रा को दूसरे देशों में भुगतान के लिए सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाते समय एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न होती है। विभिन्न देशों की मुद्राओं को आपस में

बदलने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी मात्रा दी जावे। इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निबटाने समय विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं का विनिमय अनुपात होती है। वह किसी देश की मुद्रा इकाई के विदेशी मूल्य को सूचित करती है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ जिस दर पर बदली जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। प्रो० चण्डलर (Chandler) के अनुसार, "दो मौद्रिक इकाइयों के बीच विनिमय दर से अभिप्राय एक देश की मुद्रा इकाइयों को उस मर्यादा से है जो दूसरी मुद्रा की एक इकाई को खरीदने के लिए आवश्यक होती है।"³ एशचर (Escher) के अनुसार विनिमय दर "एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त किया गया मूल्य है।"⁴ प्रार० एस० सैयर्स (R. S. Sayers) के शब्दों में, "मुद्राओं के एक दूसरे के सम्बन्ध में मूल्यों को विनिमय दर कहते हैं।"⁵ इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा इकाई का वह मूल्य होता है जो दूसरी मुद्रा में व्यक्त किया जाना है। यह भी कहा जा सकता है कि विनिमय दर वह दर होती है जिस पर विदेशी विनिमय बिलों (Foreign Bills of Exchange) का क्रय-विक्रय किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि इंग्लैंड के १ पाँड के बदले में अमेरिका के २० डॉलर प्राप्त होने हैं तो पाँड और डॉलर के बीच विनिमय दर १ पाँड = २० डॉलर होगी।

विदेशी विनिमय दर मुख्यतया मुद्राओं की माग और पूर्ति के ऊपर निर्भर होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी माग और पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है ठीक उसी प्रकार विदेशी मुद्रा का मूल्य भी उसकी माग और पूर्ति पर आधारित रहता है।⁶ अन्य वस्तुओं की भांति विदेशी मुद्रा की भी माग तथा पूर्ति होती है और उसका मूल्य माग व पूर्ति के साम्य के द्वारा ही निर्दिष्ट होता है। वस्तुओं को आयात करने वाले विदेशी भुगतानों को निबटाने के लिए विदेशी मुद्रा की माग किया करते हैं और निर्यातकर्त्ताओं के द्वारा विदेशी मुद्रा की पूर्ति की जाती

3 "By the 'Exchange Rate' between two monetary units we mean simply the number of units of one money required to buy one unit of the other." —L. V. Chandler : The Economics of Money & Banking, P. 464.

4 "The price of the money of one country expressed in the money of the other" —Escher.

5 "The prices of currencies, in terms of each other are called foreign exchange rates." —R. S. Sayers.

6 "The price of a currency is determined, just as the price of anything else is, by the relative strength of the demand for and the supply of that currency in the foreign exchange market."

—Crowther : An Outline of Money, P. 216.

है यदि किसी समय पर बाजार में विदेशी विनिमय की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि विदेशी विनिमय की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जब विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होती है तो विनिमय-दर साम्य पर होती है, अर्थात् विनिमय दर समान (at par) होती है। जब विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति से अधिक होती है तो विनिमय दर समता बिन्दु (Parity Point) से ऊपर चली जाती है और जब उसकी पूर्ति मांग से अधिक होती है तो विनिमय दर समता बिन्दु (Parity Point) से नीचे आ जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के अनुसार विनिमय दर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति से हमारा अभिप्राय, विदेशी विनिमय बिन्दु की मांग और पूर्ति से होता है क्योंकि उनके द्वारा ही बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की जाती है। यद्यपि अल्पकाल में विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है किन्तु दीर्घकाल में उसकी प्रवृत्ति समता बिन्दु (Parity Point) के समीप रहने की होती है।

विदेशी विनिमय दर के निर्धारण की समस्या को मुख्यतया दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है—

(अ) स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण।

(ब) पत्र मुद्रामान वाले देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण।

स्वर्णमान वाले देशों के बीच विनिमय दर

(Exchange Rate between Gold Standard Countries)—

सन् १९१४ से पूर्व अधिकांश योरोपीय देश तथा अमेरिका स्वर्णमान पर थे और इन देशों में निश्चित वजन तथा शुद्धता वाले सोने के सिक्के चलाये जाते थे। सोना मूल्यमान का कार्य करता था और विभिन्न देशों की मुद्राओं में पाये जाने वाले सोने की मात्रा तथा शुद्धता निश्चित थी जिसके कारण इन देशों के बीच विनिमय दरों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता था। स्वर्णमान वाले देशों के बीच अन्य प्रकार के देशों की अपेक्षा विनिमय दर को निश्चित करना सरल रहता है। स्वर्णमान वाले देशों में या तो स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती है अथवा वहाँ की मुद्रा इकार्ड को एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तनीय रखा जाता है। ऐसी दशा में दो देशों के बीच विनिमय दर या तो उनकी मुद्राओं की सोना खरीदने की शक्ति में समानता स्थापित करके निश्चित की जाती है और या वह उनकी मुद्राओं में पाये जाने वाले सोने के अनुपात पर आधारित होती है। स्वर्णमान वाले देशों के बीच उनकी मुद्राओं की सोना खरीदने की शक्ति के अनुसार अथवा उनमें पाये जाने वाले शुद्ध सोने की मात्रा के आधार पर स्वर्ण समता बिन्दु निश्चित कर लिया जाता है जिसे विनिमय की टकसाली दर (Mint Par Exchange) कहा जाता

है। इन देशों में दीर्घकालीन विनिमय दर की प्रवृत्ति इस समता बिन्दु (Parity point) के समीप रहने की होती है यद्यपि बाजारी विनिमय दर मुद्राओं की माग व पूर्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है।

विनिमय की टंकमाली दर (Mint Par of Exchange) वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा की सोना खरीदने की शक्ति दूसरे देश की मुद्रा की सोना खरीदने की शक्ति के बराबर होती है। दोनों देशों की मुद्राओं में पाये जाने वाले सोने के अनुपात को ही टंक-समता (Mint Par) कहते हैं। प्रो० टामस (Thomas) के अनुसार "विनिमय टंकसमता दर वह अनुपात है जो एक ही धातुमान वाले देशों की प्रमाणिक मुद्राओं में पाई जाने वाली धातु की वैधानिक मात्रा में होता है।" ⁷ टंक समता को जानने के लिए हमें दोनों देशों के प्रमाणिक सिक्कों में पाये जाने वाले शुद्ध सोने की मात्रा का पता लगाना होता है। एक देश के प्रमाणिक सिक्कों में पाये जाने वाले सोने की मात्रा को दूसरे देश के सिक्के की सोने की मात्रा से भाग कर देने पर टंक-समता का पता लग जाता है। उदाहरणार्थ, स्वर्णमान काल में इंग्लैंड के एक पौंड में $\frac{9}{16}$ शुद्धता वाला ७ ६८८०५ ग्रेन सोना पाया जाता था। इस आधार पर १ पौंड में शुद्ध सोने की मात्रा ७ ३२२३८ ग्रेन होती थी। इसी प्रकार एक फ्रैंक में $\frac{9}{16}$ शुद्धता वाला ३५२/८५ ग्रेन सोना होता था जिसके अनुसार १ फ्रैंक (Franc) में शुद्ध सोने की मात्रा २५०३२२५ ग्रेन थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच टंक-समता (Mint par) को निकालने के लिए पौंड में पाये जाने वाले शुद्ध सोने की मात्रा को फ्रैंक में पाये जाने वाले शुद्ध सोने की मात्रा से भाग दे देने हैं—

$$\text{टंक-समता (Mint par)} = \frac{७ ३ २३८}{२ ६०३२२५}$$

$$\text{अर्थात् १ पौंड} = २५.२२१५ \text{ फ्रैंक}$$

दोनों देशों की मुद्राओं को सामान्यतया इस दर पर एक दूसरे के साथ बदला जाना चाहिए। यह एक प्रकार से आदर्श विनिमय दर होती है। वास्तविक विनिमय दर इससे ऊपर या नीचे हो सकती है। जब विदेशी विनिमय दर इस टंक-समता के बराबर होती है तो विनिमय दर को सममात्र (Rate of Exchange at par) कहा जाता है।

स्वर्ण बिन्दु (Gold Points) —

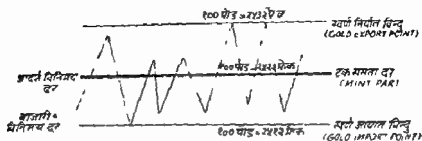
स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति टंकमाली विनिमय दर (Mint Par of Exchange) के समीप रहने की होती है किन्तु

7 "The Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents, of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard"

वास्तविक जीवन में कभी वह उनके बराबर नहीं रहती है। वास्तविक विनिमय दर कभी टंक-समता (Mint Par) से ऊपर चली जाती है और कभी उससे नीचे आ जाती है। टंक-समता केवल विनिमय दर की सामान्य प्रवृत्ति को बतलाती है और बाजारी विनिमय दर उससे भिन्न हो सकती है। विनिमय दर टंक-समता (Mint par) के बराबर नब हो सकती है जब विनिमय बिलों की माग तथा पूर्ति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो। वास्तविक जीवन में विदेशी विनिमय की माग तथा पूर्ति में इस प्रकार का संतुलन बहुत कम होता है। कभी विनिमय बिलों की माग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है और कभी कम। विभिन्न मुद्राओं की माग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण विनिमय दर समता बिन्दु से इधर-उधर बदलती रहती है। स्वयंमान में विनिमय दर के घटने-बढ़ने की निश्चित सीमाएँ होती हैं और वह कभी भी इन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकती है। विदेशी विनिमय दर के परिवर्तनों की सीमाएँ स्वयं बिन्दुओं (Specie points) के द्वारा निश्चित होती हैं।

स्वयंमान वाले देशों में उच्चतम स्वयं बिन्दु (Upper Gold Point) तथा निम्नतम स्वयं बिन्दु (Lower Gold Point) विनिमय दर परिवर्तनों की दो सीमाएँ होती हैं। उच्चतम स्वयं बिन्दु विनिमय दर की अधिकतम सीमा को निश्चित करता है जिससे ऊपर वह कभी नहीं जा सकती है। इस बिन्दु को स्वयं निर्यात बिन्दु (Gold Export Point) भी कहते हैं क्योंकि इसके पश्चात् सोना देश से बाहर जाने लगता है। निम्नतम स्वयं बिन्दु विनिमय दर की न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है और उससे नीचे विनिमय दर नहीं जा सकती है। इस बिन्दु को स्वयं आयात बिन्दु (Gold Import Point) भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पश्चात् सोना देश में आने लगता है। स्वयं बिन्दुओं को मालूम करने के लिए हमें दोनों देशों के बीच सोने के भेजने का व्यय मालूम होना चाहिए जिसमें पैकिंग, किराया, व्याज, बीमा आदि सब खर्च सम्मिलित होते हैं। किसी समय पर टंक-समता दर (Mint par of Exchange) में स्वयं भेजने के व्यय को जोड़ देने से हमें स्वयं निर्यात बिन्दु का पता लग जाता है और इसी प्रकार टंक-समता दर में से स्वयं भेजने के व्यय को घटा कर स्वयं आयात बिन्दु का पता लगाया जा सकता है। यदि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच टंक-समता दर (Mint par) १०० पौण्ड = २५२२ फ्रैंक है और फ्रांस से इंग्लैंड सोना भेजने का व्यय १० फ्रैंक आता है तो इस दशा में स्वयं निर्यात बिन्दु (Gold Export Point) १०० पौण्ड = २५२२ + १० = २५३२ फ्रैंक होगा और स्वयं आयात बिन्दु (Gold Import Point) १०० पौण्ड = २५२२ - १० = २५१२ फ्रैंक होगा। इन दोनों देशों में विनिमय दर कभी भी स्वयं निर्यात बिन्दु की अधिकतम सीमा से ऊपर नहीं जायगी और स्वयं आयात की न्यूनतम सीमा से कम नहीं होगी। इन दोनों सीमाओं के बीच विनिमय दर विदेशी

विनिमय की माग तथा पूर्ति के अनुसार कही भी निश्चित हो सकती है। स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के इस क्रम को भागे दिये चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है—



उपरोक्त चित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड और फ्रांस में विनिमय दर कभी भी १०० पौंड = २५३२ फ्रैंक से अधिक तथा १०० पौंड = २५१२ फ्रैंक से कम नहीं होगी। यदि किसी समय फ्रांस में इंग्लैंड से बहुत अधिक सामान का आयात किया गया है और फ्रांस से इंग्लैंड को निर्यात की मात्रा उसकी अपेक्षा कम है तो फ्रांस में पौंड की माग बढ़ जायेगी और माग अधिक होने के कारण उसका मूल्य बढ़ने लगेगा। फ्रांस के व्यापारी इंग्लैंड को दो प्रकार से भुगतान कर सकते हैं—विदेशी विनिमय बिल के द्वारा अथवा सोना भेज कर। यदि फ्रांस का व्यापारी सोने के द्वारा भुगतान करता है तो उसे १०० पौंड के मूल्य का सोना खरीदने के लिए २५२२ फ्रैंक व्यय करना पड़ेगा और इसके प्रतिरक्त १० फ्रैंक उसे सोने को इंग्लैंड भेजने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार उस व्यापारी को १०० पौंड का भुगतान इंग्लैंड में करने के लिए कुल $२५२२ + १० = २५३२$ फ्रैंक का व्यय करना होगा। यदि उसे १०० पौंड का विनिमय बिल २५३२ फ्रैंक से कम में मिल जाता है तो वह विनिमय पत्र के द्वारा भुगतान करेगा क्योंकि उसे ऐसा करने में लाभ है। किन्तु यदि १०० पौंड के बिल के लिए २५३२ फ्रैंक से अधिक मागा जाता है तो वह विनिमय बिल भुगतान न करके सोना इंग्लैंड को भेजेगा। इस प्रकार विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊपर नहीं जायेगी। इसके विपरीत यदि फ्रांस का व्यापार सतत रूप से कम हो रहा है और इंग्लैंड के व्यापारियों को फ्रांस में अधिक भुगतान करने है तो फ्रैंक की माग बढ़ जाने के कारण पौंड का मूल्य कम हो जायेगा। इंग्लैंड का व्यापारी यदि सोने के द्वारा भुगतान करता है तो उसे १०० पौंड के बदले में इंग्लैंड में २५२२ फ्रैंक के मूल्य का सोना मिल जायेगा किन्तु इस सोने को फ्रांस भेजने में १० फ्रैंक के बराबर व्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार १०० पौंड का व्यय करके वह फ्रांस में केवल २५१२ फ्रैंक का भुगतान ही निबटा सकेगा। अतः यदि उसे १०० पौंड के बदले में २५१२ फ्रैंक से अधिक मूल्य का विनिमय बिल मिल जाता तो वह विनिमय बिल के द्वारा भुगतान करेगा। किन्तु यदि इससे कम मूल्य का विनिमय बिल ही उसे मिलता है तो वह सोना फ्रांस को भेजना अधिक

पसन्द करेगा इस प्रकार पौड फ्रैंक दर १०० पौड = २५१२ फ्रैंक से नीचे नहीं जायगी ।

स्वर्णमान वाले देशों में वास्तविक विनिमय दर टंक-समता से ऊपर नीचे घटती-बढ़ती रहती है किन्तु वह स्वर्ण बिन्दुओं से बाहर नहीं जा सकती है । विदेशी विनिमय बिलों की माग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण विनिमय दर स्वर्ण निर्धारित बिन्दु तथा स्वर्ण आयात बिन्दु के समीप जा सकती है किन्तु वह वहाँ पर ठहरती नहीं है और उसकी प्रवृत्ति टंक-समता (Mint Par) के समीप आने की होती है । जब विनिमय दर स्वर्ण निर्धारित बिन्दु के समीप आ जाती है तो कुछ आर्थिक शक्तियाँ उसे गिरा कर टंक-समता के समीप लाने की प्रवृत्ति रखती हैं । इसी प्रकार यदि वह स्वर्ण आयात बिन्दु पर पहुँच जाती है तो वे ही शक्तियाँ उसे ऊपर उठाकर टंक-समता के समीप ले आती हैं ।

पत्र-मुद्रामान में विनिमय दर निर्धारण

(Determination of Exchange Rate Under Paper Standard)

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रामान वाले देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण स्वर्णमान वाले देशों की अपेक्षा कठिन होता है । स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय दर उनमें पाये जाने वाले सोने की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है किन्तु पत्र-मुद्रा वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय दर को निकालने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है । इन देशों की मुद्राओं में परस्पर ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता है जिनके द्वारा उनके सापेक्षिक मूल्य को ज्ञात किया जा सके । ऐसी स्थिति में विनिमय दर को निर्दिष्ट करने का आधार इन देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति होती है । पत्र-मुद्रा मान वाले देशों के बीच विनिमय दर क्रय-शक्ति समता बिन्दु (Purchasing Power Parity Point) के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है और उसकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति इसके समीप रहने की होती है किन्तु विदेशी विनिमय बिलों की माग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वह बदलती रहती है ।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory)—

पत्र-मुद्रामान वाले देशों में विनिमय दर निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त है । प्रथम महायुद्ध काल में स्वर्णमान लगभग सभी देशों में स्थापित कर दिया गया था । स्वर्ण मुद्रायें चलन से हटा ली गईं और उनके स्थान पर सभी देशों में बहुत अधिक मात्रा में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा जारी कर दी गईं जिसके कारण विभिन्न देशों में मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो गई थी । कुछ देशों में बहुत अधिक मुद्रा प्रसार था और कुछ में कम । विभिन्न मुद्राओं की पुरानी टंक समता (Mint Par) दरें बेकार हो गई थी और उनकी

वास्तविक विनिमय दरें टक समता से बहुत भिन्न थी। इस प्रकार की स्थिति में समस्या यह थी कि मुद्रा प्रसार के कारण विभिन्न मुद्राओं के मूल्यों में होने वाली गिरावट को ध्यान रखते हुए इनके बीच नई विनिमय दरें किन प्रकार मान्य की जायें। स्वीडन के अध्यक्षशास्त्री गस्ताव कैसल (Gustav Cassel) ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया और पत्र-मुद्रामान की दशा में विनिमय दरों के निर्धारण की नई विधि को बनवाया। इस सम्बन्ध में प्रो० कैसल ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उसे क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त कहते हैं।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त के अनुसार दीर्घकाल में विनिमय दर दोनों मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है जिन्हें उनकी क्रय-शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। गस्ताव कैसल के अनुसार “दो मुद्राओं के बीच की विनिमय दर उनकी आन्तरिक क्रय-शक्ति के अनुपात पर आवश्यक रूप से आधारित होती है।”^८ बैरेट व्हेल (Barrett Whale) के अनुसार “विनिमय दरों को सामान्यतः विभिन्न राष्ट्रीय मुद्रा इकाइयों की आन्तरिक क्रय-शक्ति के सम्बन्ध को बतलाना चाहिए।”^९ इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए क्राउथर (Crowther) ने लिखा है—
“दो मुद्राओं के बीच का विनिमय अनुपात वही होने की प्रवृत्ति रखता है जो उनकी सापेक्षिक क्रय-शक्ति का अनुपात होता है।”^{१०} प्रो० टामस (S. E. Thomas) ने क्रय-शक्ति समता बिन्दु की व्याख्या इस प्रकार की है—“विनिमय दर उस बिन्दु पर रहने की प्रवृत्ति रखता है जो दो मुद्राओं की सापेक्षिक क्रय-शक्ति की समता को विदित करता है। इस बिन्दु की क्रय-शक्ति समता बिन्दु कहते हैं।”^{११}

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना करके हम उनके बीच के विनिमय अनुपात को निकाल सकते हैं। दो पत्र-मुद्रा मान वाले देशों के बीच विनिमय दर को उन दोनों देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों की तुलना करके निकाला जाता है। विनिमय दर की प्रवृत्ति ऐसे बिन्दु पर रहने की होती है जहाँ पर दोनों मुद्राओं की क्रय-शक्ति समान होती है।

8 “The rate of exchange between two currencies, must stand essentially on the quotient, of the internal purchasing powers of these currencies”
—Gustav Cassel

9 “The exchange rates should normally reflect the relation between the internal purchasing powers of the various national currency units.”
—Barrett Whale • International Trade.

10 “The ratio of exchange between two currencies tends to be same as the ratio between their respective purchasing powers”
—Crowther • An Outline of Money, . P. 226.

11 “The rate of exchange tends to rest at that point which expresses equality between the respective purchasing powers of the two currencies This point is called the purchasing power parity.”

—S. E. Thomas ; The Principles and Arithmetic of Foreign Exchange.

इस बिन्दु को क्रय शक्ति समता बिन्दु (Purchasing Power Parity Point) कहते हैं। क्रय-शक्ति समता बिन्दु वह बिन्दु होता है जहाँ पर एक देश की मुद्रा की निश्चित मात्रा की क्रय-शक्ति दूसरे देश की मुद्रा की निश्चित मात्रा की क्रय-शक्ति के बराबर होती है। उदाहरणार्थ, यदि इंग्लैंड और अमरीका के बीच क्रय-शक्ति समता बिन्दु १ पौड = २.५ डॉलर है तो वह इस बात को सूचित करता है कि इंग्लैंड में १ पौड की क्रय-शक्ति ठीक उतनी है जितनी कि अमरीका में २.५ डॉलर की है।

क्रय-शक्ति समता बिन्दु दोनों देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों की तुलना करके निकाला जाता है। यदि भारतवर्ष में १५ रु० से उतना ही गेहूँ खरीदा जा सकता है जितना कि इंग्लैंड में १ पौड से खरीदा जाता है तो इस स्थिति में गेहूँ के सम्बन्ध में एक पौड की क्रय-शक्ति १५ रु० की क्रय-शक्ति के बराबर होती है और दोनों मुद्राओं का क्रय-शक्ति समता बिन्दु १ पौड = १५ रुपये के होगा। किन्तु वास्तव में क्रय-शक्ति समता बिन्दु का निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे किसी एक वस्तु के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। विभिन्न मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना करने के लिए हमें उन सब वस्तुओं तथा सेवाओं को लेना होगा जो उन मुद्राओं के द्वारा खरीदी जाती हैं। इसीलिए क्रय-शक्ति समता बिन्दु को निकालने के लिए सूचक अंकों का प्रयोग किया जाता है। दो देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना करने के लिए हमें प्रतिनिधि वस्तुओं का एक ऐसा समूह चुनना पड़ता है जिसकी दोनों देशों में काफी मांग की जाती हो। यदि भारत में १०० प्रतिनिधि वस्तुओं के समूह की एक निश्चित मात्रा को १३ रुपये में खरीदा जा सकता है और इस समूह की उसी मात्रा को इंग्लैंड में १ पौड में खरीदा जाता है तो भारत और इंग्लैंड के बीच क्रय-शक्ति समता बिन्दु १३ रु० = १ पौड के होगा जो दोनों मुद्राओं के सापेक्षिक महत्व पर आधारित है।

क्रय-शक्ति समता बिन्दु निकालते समय एक बड़ी कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना करने के लिए किस प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाये। केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं के आधार पर बने हुए सूचक अंक मुद्राओं की क्रय-शक्ति का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली वस्तुओं पर आधारित क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त बेकार का सत्य है क्योंकि विभिन्न बाजारों में इनके मूल्यों की प्रवृत्ति समान रहने की होती है।”¹² यदि केवल आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं को ही सम्मिलित किया

12 * Confined to internationally traded commodities the purchasing power parity theory becomes an empty truism because it is obvious that the national prices of internationally traded goods (adjusted to account for transportation costs, tariffs and other delivery expenses) tend to equality as

जाता है तो क्रय-शक्ति समता का निर्धारण और भी अधिक असन्तोषजनक हो जाता है क्योंकि आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं का मुद्रा की विनिमय दर पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इन वस्तुओं के मूल्य विनिमय दर की प्रत्यक्ष रूप से अथवा तुरन्त प्रभावित किये बिना बदल सकते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं का सम्मिलित किया जाना क्रय-शक्ति समता निकालने के लिए आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय तथा आन्तरिक व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं को सम्मिलित करके क्रय-शक्ति को निकालना भी उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने में बहुत-सी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो जायेंगी जिनका विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्राउथर (Crowther) के अनुसार क्रय-शक्ति समता निकालने के लिए सभी वस्तुओं के आधार पर सामान्य कीमत-स्तर निकालना उचित नहीं है। इसके दूर और यह मान लेना भी ठीक नहीं होगा कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के मूल्य ही विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। हमें उन वस्तुओं को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव हो सकता है।¹³

क्रय-शक्ति समता बिन्दु (Purchasing Power Parity Point) दो देशों के मुद्राओं के बीच आदर्श विनिमय दर को बतलाता है। यह वह दर होती है जिस पर दोनों देशों की मुद्रायें बदली जानी चाहिए। वास्तविक विनिमय दर अथवा बाजार विनिमय दर क्रय-शक्ति समता से अधिक अथवा कम हो सकती है। वास्तविक विनिमय दर विदेशी विनिमय बिलों की माग व पूर्ति के अनुसार क्रय-शक्ति समता बिन्दु से ऊपर-नीचे घटती-बढ़ती रहती है और उसके बराबर प्रायः नहीं होती है। बाजारी विनिमय दर क्रय-शक्ति समता बिन्दु पर तब होती है जब देश का भुगतान सन्तुलन बिल्कुल सन्तुलित होता है और विनिमय बिलों की माग ठीक उनकी पूर्ति के बराबर होती है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है और कभी विनिमय बिलों की माग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है और कभी कम, जिसके कारण विनिमय दर में परिवर्तन होते रहते हैं। जब भुगतान सन्तुलन विपक्ष में होने के कारण देश में विदेशी विनिमय की माग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य हमारे लिए बढ़ने लगता है और विनिमय दर देश के लिए प्रतिकूल हो जाती है। इसके विपरीत जब विदेशी विनिमय की माग कम होती है और उसकी पूर्ति अधिक होती है तो विनिमय दर देश के पक्ष में आ जाती है। इस

between different markets when translated into each other at the current exchange rates.” —Halm : Economics Of Money and Banking, P. 458

13 “For obviously all prices do not enter into the calculations of those who carry on foreign trade. It is not right, however, to go to the other extreme and assume that the exchange rate is influenced only by the prices of things that actually do move in international trade; we must take some account of the articles that *might* move.”

—Crowther An Outline of Money, P. 227.

प्रकार वास्तविक विनिमय दर क्रय-शक्ति समता बिन्दु के आस-पास घटती-बढ़ती है किन्तु उसकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति समता बिन्दु (Parity Point) के समीप रहने की होती है। विनिमय दर के इन परिवर्तनों को निम्न प्रकार से चित्रित किया जा सकता है—



उपर्युक्त चित्र के देखने से पता चलता है कि दैनिक विनिमय दर (Day to Day Rate of Exchange) सामान्य विनिमय दर (क्रय-शक्ति समता बिन्दु) के आस-पास घटती-बढ़ती रहती है। पत्र-मान वाले देशों के बीच विनिमय दर परिवर्तनों की कोई सीमायें नहीं होती हैं और वह कितनी ही ऊपर अथवा नीचे जा सकती है। इसलिए यह कहा जाता है कि पत्र-मुद्रा मान में विनिमय दरें स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है और उन्हें स्थिर रखने की एक विशेष समस्या रहती है। यद्यपि विनिमय दर क्रय-शक्ति समता बिन्दु से ऊपर तथा नीचे जा सकती है किन्तु वह उसमें बहुत अधिक ऊपर अथवा नीचे नहीं रह सकती है और उसकी सामान्य प्रवृत्ति क्रय-शक्ति समता बिन्दु के समीप रहने की होती है। पत्र मुद्रा वाले देशों में सामान्य विनिमय दर (Normal Rate of Exchange) भी बदलती रहती है, क्योंकि क्रय-शक्ति समता बिन्दु (Purchasing Power Parity Point) एक परिवर्तनशील बिन्दु है। वह टंक-ममता (Mint Par) की भाँति स्थिर नहीं रहता और विभिन्न देशों के मूल्य-स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण बदलता रहता है।

सिद्धान्त का व्यवहारिक महत्व

(Practical Significance of the Theory)—

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रयोग निरपेक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा प्रयोग पूर्व निश्चित विनिमय दरों का मूल्य-स्तरों के परिवर्तनों के अनुसार समायोजन करने में है। प्रो० कैसल (Cassel) ने भी सिद्धान्त के व्यवहारिक महत्व के सम्बन्ध में इस बात को स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त केवल पुरानी विनिमय दरों को नई परिस्थितियों के अनुसार ठीक करने में ही सहायता दे सकता है। उनके अनुसार "क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त निर्पेक्ष मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में लागू नहीं किया जा सकता है। उसका प्रयोग केवल मूल्य-स्तर

के परिवर्तनों के सम्बन्ध में ही किया जा सकता है।¹⁴ क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की सहायता से दो ऐसे देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर को मातृम नहीं किया जा सकता है जिनकी मुद्राओं में पहले कोई सम्बन्ध न रहा हो। "क्रय-शक्ति समता विन्दु को निश्चालने के लिए हमें ऐसी विनिमय दर का पता होना चाहिए कि वह किसी सन्तुलन की स्थिति को बतलाती हो। इस विनिमय दर की सहायता से ही हम उस दर का पता लगा सकते हैं जो दोनों देशों की मुद्राओं की बदली हुई क्रय-शक्ति के सम्बन्ध में उसी सन्तुलन को बतलाती है।"¹⁵ यदि हमें दो देशों की मुद्राओं की पुरानी विनिमय दर का पता है तो हम उनके सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उसे घटा-बढ़ा कर नई सन्तुलन दर का पता लगा सकते हैं। दो देशों की मुद्राओं के बीच क्रय-शक्ति समता विन्दु का पता लगाने के लिए हम उस देश के वर्तमान सूचक अंक को, जिसकी मुद्रा में विनिमय दर का व्यक्त किया जाना है, पूर्व निर्दिष्ट समता दर से गुणा कर देते हैं और दूसरे देश के वर्तमान सूचक अंक में उसे भाग दे दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि इंग्लैंड और अमरीका के बीच स्वर्णमान छोटने में पूर्व समता दर १ पौंड=४ ८६६ डॉलर थी और स्वर्णमान छोटने के पश्चात् इंग्लैंड का सूचक अंक बढ़कर २५० हो जाता है और अमरीका का सूचक अंक १२५ होता है तो नई समता दर (New Parity Point) को इस प्रकार निकाला जायगा—

$$१ पौंड = \frac{४८६६ \times १२५}{२५०}$$

$$= २४३३ डॉलर$$

अतः दोनों देशों के बीच नयी विनिमय दर १ पौंड=२ ४३३ डॉलर होगी।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनाये

(Criticisms of Purchasing Power Parity Theory)—

आलोचकों के अनुसार क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त विनिमय दर निर्धारण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों की सन्तोषजनक विवेचना नहीं करता है। मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर इस सिद्धान्त की आलोचना की गई है—

(१) यह सिद्धान्त यह तो बताने का प्रयत्न करता है कि विनिमय दरों में क्यों और किम प्रकार परिवर्तन होते हैं किन्तु उसे विनिमय दरों के निर्धारण का

14 The Purchasing power parity theory "cannot..... be applied to absolute levels of prices, but only to changes in the price levels"

—Gustav Cassel Money and Foreign Exchange After 1914.

15 "It is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

—Gustav Cassel : Money and Foreign Exchange After 1914.

सन्तोषजनक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है। वह केवल यह बतलाता है कि मुद्राओं की क्रय-शक्ति के बदलने पर उनकी विनिमय दर बदल जाती है किन्तु यह नहीं बतलाता कि विनिमय दरों का निर्वाह किस प्रकार होता है। दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर इन मुद्राओं की माग और पूर्ति पर आधारित होती है। मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन विनिमय दर को प्रभावित कर सकते हैं किन्तु उसे निर्धारित नहीं करते हैं। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार “दो देशों की मुद्रा इकाईयों के बीच की सन्तुलन दर एक देश की दूसरे देश की वस्तुओं के लिए माग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी से प्रभावित होती है चाहे मूल्य-स्तर स्थिर ही रहे।”¹⁶ विनिमय दर निर्धारण की समस्या मूल्य निर्धारण की समस्या का ही एक भाग है और उसे इससे पृथक् करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अन्य वस्तुओं के मूल्यों की भांति विदेशी मुद्रा का मूल्य भी उसकी माग तथा पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है। विनिमय दर निर्धारण का सन्तोषजनक सिद्धान्त वही हो सकता है जो विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की माग तथा पूर्ति का उचित विश्लेषण करता हो। क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त केवल मुद्राओं की क्रय-शक्ति की विवेचना करता है और उनकी माग तथा पूर्ति में उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) प्रो० कैसल (Cassel) ने इस सिद्धान्त में इस बात को मान लिया है कि मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन तो विनिमय दर को प्रभावित करते हैं किन्तु विनिमय दर के परिवर्तनों का मूल्य-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है और विनिमय दर के परिवर्तन भी मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालते हैं। जब किसी मुद्रा का विदेशी मूल्य बदलता है तो उनका प्रभाव उसके आन्तरिक मूल्य पर पड़ता है। पाय यह देखा जाता है कि अन्वयमूल्यन के कारण देश में मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और मुद्रा की आन्तरिक क्रय-शक्ति भी कम हो जाती है। क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार ‘किसी देश की मुद्रा के विनिमय मूल्य की गिरावट उस देश के कीमत-स्तर में सापेक्षिक वृद्धि करने की प्रवृत्ति पैदा होती है।’¹⁷ इसी प्रकार किसी देश की मुद्रा के विदेशी मूल्य के बढ़ जाने पर उस देश का मूल्य-स्तर गिर जाता है और उसकी मुद्रा की आन्तरिक क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। अतः विनिमय दर के परिवर्तनों का प्रभाव आन्तरिक मूल्य-स्तर पर पड़ता है।

16 “The equilibrium rate of exchange between the monetary units of two countries is affected by every increase or decrease of one country's demand for other country's products even though the price levels may stay the same.”
—Halm : Monetary Theory, P. 205.

17. “A fall in the exchange value of a country's currency will tend to initiate a relative increase in that country's price level.”

—Crowther : An Outline of Money, P. 230,

(३) इस सिद्धान्त में मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने तथा उसकी तुलना करने के लिए सूचक अंको का प्रयोग किया जाता है किन्तु सही सूचक अंक बनाना बहुत कठिन होता है। अतः सूचक अंको के आधार पर निर्धारित विनिमय दरें भी बहुत अधिक सही नहीं हो सकती हैं। सूचक अंक विनिमय दरों के निर्धारण का उचित आधार नहीं हो सकते हैं। प्रायः सूचक अंको में ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका विदेशी व्यापार से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता है। अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए सूचक अंको में केवल वे ही वस्तुएँ सम्मिलित की जानी चाहिए जिनका आयात-निर्यात किया जाता हो अथवा जिनकी विदेशी व्यापार में आने की सम्भावना हो। वास्तव में केवल इन वस्तुओं के आधार पर सूचक अंक नहीं बनाये जाते हैं। अतः सामान्य सूचक अंक मुद्राओं की अन्तर्राष्ट्रीय क्रय-शक्ति को नापने का ठीक साधन नहीं है। क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित विनिमय दरें दोषपूर्ण सूचक अंकों पर आधारित होती हैं इसलिए वे मुद्राओं के विदेशी मूल्यों को ठीक-ठीक नहीं बता सकती हैं।

(४) इस सिद्धान्त में क्रय-शक्ति परिवर्तनों को विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों का एकमात्र कारण माना गया है। किन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि विनिमय दरों पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है और मुद्रा की क्रय-शक्ति का परिवर्तन उसमें से केवल एक है। वास्तव में भुगतान संतुलन की किसी भी मरद में परिवर्तन होने से विनिमय दर बदल सकती है। इनमें से बहुत से परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जिनका आन्तरिक मूल्य-स्तर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु विदेशी विनिमय की माग तथा पूर्ति को वे बदल देते हैं। ऐसी दशा में क्रय-शक्ति समता का वास्तविक विनिमय दर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। स्वीडन के अर्थ-शास्त्री ओह्लिन (Ohlin) ने क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की इसी आधार पर आलोचना की है।

(५) इस सिद्धान्त का व्यवहारिक महत्त्व बहुत कम है क्योंकि आजकल लगभग सभी देशों में नियन्त्रित विनिमय दरें स्थापित की हुई हैं जिनकी क्रय-शक्ति समता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है। यह सिद्धान्त केवल स्वतन्त्र दशाओं में विनिमय निर्धारण के विषय में हमें बतला सकता है किन्तु वह कृत्रिम प्रदूषित विनिमय दरों के विषय में हमें कुछ नहीं बतलाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्रय-शक्ति समता स्वतन्त्र विनिमय बाजार की दशाओं में विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाती है। अल्पकाल में विनिमय दरें क्यों बदलती हैं इसका विश्लेषण यह सिद्धान्त नहीं करता है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त काफी महत्वपूर्ण है। मूल्य-स्तरों के परिवर्तनों के विनिमय दर पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण के

रूप में वह एक महत्वपूर्ण सत्य है। यद्यपि उसका व्यावहारिक महत्व कम हो जाता है किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से वह अधिक दोषपूर्ण नहीं है। दो देशों के बीच समता दर को निश्चित करने का यह एक अच्छा साधन प्रस्तुत करता है। किसी निश्चित समय पर पाई जाने वाली विनिमय दर क्रय-शक्ति समता दर से इधर-उधर हो सकती है किन्तु उसको सामान्य प्रवृत्ति इस समता दर के समीप रहने की होती है। यद्यपि हम क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त से अधिक आशा नहीं कर सकते हैं और क्रय-शक्ति समता के द्वारा न तो सन्तुलन दर (Equilibrium Rate) को ही निर्धारित किया जा सकता है और न उसमें होने वाले परिवर्तनों को जाना जा सकता है किन्तु फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में इस सिद्धान्त का काफी महत्व है। प्रो० हॉल (Halm) के अनुसार “क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का उपयोग उस समय लाभपूर्ण होता है जब हम पूरे रूप से अन्धकार में हो जैसा कि लम्बे काल तक विनिमय नियन्त्रण अपनाये जाने प्रथम भीषण मुद्रा प्रसार के पश्चात् हुआ करता है। ऐसे समय में क्रय-शक्ति समता कम से कम विनिमय दर के उन अनुमानित क्षेत्र को जानने में सहायता दे सकती है जिनके अन्दर सन्तुलित दर का पता लगाया जा सकता है।”^{१८}

विदेशी विनिमय का भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त (Balance of Payment Theory)—

कुछ आधुनिक धर्मशास्त्रियों के अनुसार विदेशी विनिमय दर दो देशों के भुगतानों के सन्तुलन के द्वारा निश्चित होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार विनिमय दर उस बिन्दु पर निश्चित होती है जहाँ पर एक देश को प्राप्त होने वाले भुगतान उसके द्वारा किया जाने वाले भुगतानों के ठीक बराबर होते हैं। इस सिद्धान्त का मुख्य आधार यह है कि हम विदेशियों को न तो उनसे अधिक भुगतान देते हैं और न कम जितना कि हमें उनसे प्राप्त होता है, अर्थात् निर्यात आयातों के लिए भुगतान करती हैं। यदि भारत अमेरिका के साथ अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करता है तो भारत व्यापारिक सन्तुलन की स्थिति में तब हो सकता है जबकि वह अमेरिका को ठीक उतना ही भुगतान करता है जितना कि उससे उसे प्राप्त होता है। किसी भी देश के भुगतानों का सन्तुलन दीर्घकाल में होना आवश्यक है। भारत और अमेरिका के बीच भुगतानों की तुलना करना तभी सम्भव हो सकता है जब हमें दोनों देशों के बीच किसी विनिमय दर का मालूम हूँ। बिना विनिमय दर के इस प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि अमेरिका भारत की मुद्रा में भुगतान

18 “Nevertheless, the purchasing power approach may be used with advantage when we are entirely in the dark as after long periods of exchange control or after violent inflations. Then it is valuable to use it for finding at least the approximate range within which the equilibrium rate should be located.”

—G. N. Halm : Economics of Money & Banking, P. 458

करता है और भारत अमेरिका की मुद्रा में। किन्तु यदि हम यह मानते हैं कि डॉलर और रुपया किस दर पर बदले जाते हैं तो हम इन दोनों देशों ने भुगतानों की तुलना कर सकेंगे। भारत सन्तुलन की स्थिति में नब होगा जब उसके द्वारा अमेरिका को किये जाने वाले भुगतानों और वहाँ में प्राप्त होने वाले भुगतानों का मूल्य उसकी अपनी मुद्रा में एक दूसरे के बराबर हो और जिस विनिमय दर पर भी यह सन्तुलन स्थापित होता है उस सन्तुलित विनिमय दर कहते हैं।

सन्तुलित विनिमय दर को जानने में पूर्व हमें विभिन्न अनुमानित विनिमय दरों पर भारत और अमेरिका की एक दूसरे की मुद्राओं की माग का अध्ययन करना होता है। इस सम्बन्ध में हमें यह मानना पड़ता है कि विभिन्न विनिमय दरों पर भारत अमेरिका की मुद्रा की अपनी माग की माग करता है। इसी प्रकार यह भी मानना पड़ता है कि विभिन्न विनिमय दरों पर अमेरिका में भारतीय मुद्रा की अपनी माग की जाती है। इस प्रकार विभिन्न अनुमानित विनिमय दरों पर अमेरिका और भारत की एक दूसरे की मुद्रा की माग की तालिकाएँ बना ली जाती हैं। इन माग तालिकाओं (Demand Schedules) की सहायता से ऐसी विनिमय दर का पता लगाया जाता है जिस पर भारत और अमेरिका एक दूसरे की मुद्राओं की माग बराबर होती है। इसी विनिमय दर पर दोनों का भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) सन्तुलित होता है। इस दर को सन्तुलित विनिमय दर कहा जाता है और दीर्घकाल में विदेशी विनिमय दर इसी बिन्दु पर रहने की प्रवृत्ति रखती है।

विदेशी विनिमय दरों में उल्लास

(Fluctuations in the Rate of Exchange)

विदेशी विनिमय दरें प्रायः बहुत कम स्थिर रहती हैं और विनिमय त्रिंशों की माग तथा पूर्ति के अनुसार उनमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यद्यपि दीर्घकाल में विनिमय दरों की सामान्य प्रवृत्ति सन्तुलित दर (Equilibrium Rate) के समीप रहने की होती है किन्तु अल्पकाल में विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव आने रहते हैं। स्वर्णमान वाले देशों में वास्तविक विनिमय दर टंक समता (Mint Par) और पत्र मुद्रामान वाले देशों में क्रय-शक्ति समता बिन्दु (Purchasing Power Parity Point) से ऊपर-नीचे घटती बढ़ती रहती है। विनिमय दर के इन परिवर्तनों का देश के विदेशी व्यापार तथा उसकी आन्तरिक ग्रह-व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वर्णमान व्यवस्था में विनिमय दरों को स्थिर रखने की कोई विरोध समस्या नहीं थी क्योंकि इस प्रकार की पद्धति में विनिमय दरों में सामान्य स्थिरता स्वयं स्थापित हो जाती थी। स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय दरें प्रायः स्थिर रहती थी और उनमें परिवर्तन केवल स्वर्णबिन्दु (Specie Points) की मर्यादित सीमाओं के भीतर ही होते थे। किन्तु पत्र मुद्रामान की व्यवस्था में

विनिमय दरों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों की कोई निश्चित सीमाएँ भी नहीं होती हैं। इस प्रकार पत्र मुद्रा वाले देशों में विनिमय दरों की स्थिरता बहुत बड़ जाती है जो इनके आर्थिक जीवन पर अत्यन्त बुरा प्रभाव डालती है।

विनिमय दरों में होने वाले अनियमित तथा आकस्मिक परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता एवं अरक्षा उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विदेशी व्यापार में शक्ति बड़ जाती है और उसके विस्तार में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अस्थिर विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजी के दीर्घकालीन विनियोग में भी रुकावट पैदा करती हैं। विनिमय दरों के परिवर्तन आन्तरिक अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं और उनका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से विदेशी विनिमय की स्थिरता विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास तथा विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए आवश्यक है। विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना पत्र मुद्रा मान वाले देशों की एक प्रमुख समस्या है। लगभग सभी देशों में विनिमय प्रवर्ध तथा नियन्त्रण के द्वारा विदेशी विनिमय दरों में सामान्य स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन क्यों होते हैं।

विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण (Causes of the Fluctuations in the Rates of Exchange)—स्वतन्त्रता तथा पत्र मुद्रा मान दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दर सन्तुलन स्तर (Equilibrium Level) से ऊपर-नीचे घटती-बढ़ती रहती है। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारणों को निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- (अ) विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारण।
- (ब) चलन सम्बन्धी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण।
- (स) राजनैतिक स्थिति।

(अ) विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति की स्थिति

(Demand and Supply Conditions of Foreign Exchange)—

विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तन विनिमय दर पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। जब विदेशी मुद्रा की माग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो विनिमय दर बड़ जाती है और मांग के पूर्ति से कम हो जाने की दशा में वह गिर जाती है। अल्पकाल में विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति में असाध्य की सम्भावना बहुत अधिक बड़ जाती है और इसी कारण दैनिक विनिमय दर घटती-बढ़ती रहती है। विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति पर अग्रलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है—

(१) व्यापारिक प्रभाव (Trade Influences)—विदेशी व्यापार की स्थिति का विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विदेशी विनिमय बाजार में किसी की माग तथा पूर्ति मुख्यतया आयात तथा निर्यात की मात्रा के ऊपर निर्भर होती है। यदि देश में आयात अधिक किया जाता है और निर्यात कम होता है तो ऐसी देश में विदेशी मुद्रा की माग अधिक होने के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि किसी देश से निर्यात अधिक बिये जाते हैं और आयात कम होती है तो विदेशी मुद्रा की माग कम होने के कारण उसका मूल्य गिर जाता है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि भारत से इङ्गलैंड को निर्यात अधिक की जाती है और वहाँ से आयात कम होती है तो इङ्गलैंड में रुपये की माग अधिक होने के कारण रुपये का मूल्य बढ़ जायेगा और विनिमय दर भारत के पक्ष में हो जायेगी। यदि इङ्गलैंड से हम अधिक आयात करते हैं और उस देश को हमारी निर्यात कम होती है तो भारत में पाँड की माग अधिक होने के कारण उसका मूल्य बढ़ जायेगा और विनिमय दर भारत के विपक्ष में हो जायेगी। व्यापारिक स्थिति का ज्ञान करते समय हमें दृष्ट्य तथा महसूस दोनों प्रकार की आयातों व निर्यातों को सम्मिलित करना चाहिए।

(२) स्टॉक एक्सचेंज सम्बन्धी प्रभाव (Stock Exchange Influences)—स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले विभिन्न प्रकार के सौदों के कारण भी विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक, बॉन्ड, प्रतिभूतियों आदि का क्रय-विक्रय, ऋणों का लेन-देन तथा सट्टे के उद्देश्य में विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। इन सौदों का प्रभाव विदेशी मुद्राओं की माग तथा पूर्ति पर पड़ता है जिसके कारण विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं। यदि भारत का कोई विनियोगी इङ्गलैंड की कम्पनियों के अथवा ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूतियों को लेता है तो भारत में पाँड की माग बढ़ जायेगी और उसका मूल्य बढ़ने लगेगा। इसके विपरीत यदि इङ्गलैंड के पूंजीपति भारतीय कम्पनियों के अथवा भारतीय सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तो इङ्गलैंड में रुपये की माग बढ़ जायेगी और उसका मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति रखेगा। जब हमारे देश में विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज आता है अथवा खरीदे हुए अंशों (Shares) पर लाभ अथ मिलाता है तो हमसे देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार विदेशी ऋणों के आने-जाने का भी विदेशी विनिमय की माग तथा पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है।

(३) मध्यस्थों की क्रियाएँ (Arbitrage Operations)—कुछ लोग सट्टे के उद्देश्य से भी विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया करते हैं। जब उन्हें किसी मुद्रा के मूल्य की भविष्य में बढ़ने की आशा होती है तो वे उस मुद्रा को खरीदने लगते हैं जिसके कारण उस मुद्रा विशेष की माग बढ़ जाती है और उसका मूल्य

बढ़ने लगता है। इसके विपरीत जब किसी मुद्रा के मूल्य के गिरने की सम्भावना होती है तो यह लोग उस मुद्रा को बेचने लगते हैं और बाजार में उसकी पूर्ति में कृत्रिम वृद्धि हो जाने के कारण उसका मूल्य घट जाता है। मध्यस्थों की क्रियाओं (Arbitrage Operations) के कारण भी विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय हुआ करता है। कुछ लोग विभिन्न बाजारों में मुद्राओं के मूल्यों के अन्तर से लाभ उठाने के लिए भी विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करने लगते हैं। यदि न्यूयॉर्क में पौण्ड का मूल्य (१ पौंड = २.६ डॉलर) अधिक है और उसी समय पेरिस के बाजार में पौंड कुछ कम मूल्य (१ पौंड = १.८ डॉलर) पर बिक रहा है तो यह लोग पेरिस में पौंड खरीद कर उमें तुरन्त अमेरिका में बेच देंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय को अन्तर पणन (Arbitrage Operations) कहा जाता है। इन क्रियाओं का भी विदेशी मुद्राओं की माग तथा पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है।

(४) बैंकिंग सम्बन्धी प्रभाव (Banking Influences) — बैंकिंग सम्बन्धी प्रभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं — (घ) बैंकों द्वारा विनियोग तथा धन का हस्तांतरण, (ब) बैंक दर परिवर्तन। जब बैंक अपने धन का विनियोग दूसरे देशों में करते हैं अथवा साख प्रमाण पत्र (Letters of Credit), ड्राफ्ट तथा यात्री चैक आदि जारी करते हैं तो इसके लिए स्वयं विदेशों को भेजना होता है जिसके कारण विदेशी विलों की माग बढ़ जाती है और विनिमय दर भी बढ़ने लगती है। यदि विदेशी बैंक हमारे यहाँ विनियोग बढ़ाते हैं अथवा साख पत्रों के द्वारा धन का हस्तांतरण करते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारे देश में बढ़ जाती है और उसका मूल्य गिरने लगता है। सरकार के हिसाब में रुपये के हस्तांतरण का प्रभाव भी विदेशी विनिमय की माग तथा पूर्ति पर पड़ता है। सरकार के द्वारा विदेशों में ऋणों का प्राप्त होना अथवा विदेशों का ऋण दिया जाना, सूद का लेन-देन तथा ऋणों के भुगतान सभी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं।

बैंक दर परिवर्तनों का भी विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बैंक दर परिवर्तन देश में साख की मात्रा में परिवर्तन करते हैं जिनके कारण मूल्य स्तर बदलता है और मुद्रा का विदेशी मूल्य भी बदल जाता है। बैंक दर कम होने से साख का विस्तार होता है, मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण विनिमय दर गिर जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक दर गिरने से सूद की दर कम हो जाती है, विदेशी विनियोग कम होते हैं और विदेशी पूँजी देश में आने लगती है जिसके कारण विदेशी मुद्रा की माग बढ़ जाती है और उसका मूल्य बढ़ने लगता है। इसके विपरीत बैंक दर के बढ़ने पर सूद की दर ऊँची होने के कारण विदेशी विनियोगों की प्रोत्साहन मिलता है और विदेशी पूँजी देश में आने लगती है जिसके कारण हमारे देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़

जाती है और उसका मूल्य गिरने लगता है। बैंक दर बढ़ने से देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है, मूल्य स्तर गिरता है और हमारी मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जाता है।

(व) चलन सम्बन्धी स्थिति (Currency Conditions)—

देश में चलन सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण मुद्रा की क्रय-शक्ति बदलती रहती है जिसका प्रभाव विनिमय दर के ऊपर भी होता है। मुद्रा के पारस्परिक मूल्य में होने वाले परिवर्तन उसके विदेशी मूल्य में भी उसी प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। घन मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन तथा देश की मौद्रिक नीति विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। चलन सम्बन्धी प्रभावों के अन्तर्गत मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन तथा अवमूल्यन आदि की सम्मिलित विद्या जाना है। (i) मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन—मुद्रा प्रसार की स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं जिसके कारण विदेशियों के लिए हमारा बाजार माल बेचने का अवसर बाजार बन जाता है और हमारी आयातों में वृद्धि होती है। मूल्य अधिक होने के कारण विदेशी हमारे देश में बहुत कम सामान खरीदने हैं और हमारी निर्यात कम हो जाती है। आयात बढ़न तथा निर्यात कम होने के कारण विनिमय बिलों की माग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है और विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन की स्थिति में हमारा मूल्य-स्तर नीचा होने के कारण निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयातें कम हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। (ii) अवमूल्यन (Devaluation)—मुद्रा के अवमूल्यन का भी विदेशी विनिमय दर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा का अवमूल्यन होने से हमारी निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयातें कम हो जाती हैं। निर्यात अधिक होने के कारण विदेशी मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है और आयात कम होने से उसकी माग कम रहती है जिसके कारण विदेशी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और विनिमय दर हमारे पक्ष में घट जाती है। इस प्रकार मुद्रा तथा चलन की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण विनिमय दर में भी परिवर्तन आते रहते हैं।

(ग) राजनैतिक कारण (Political Causes)—

राजनैतिक परिस्थितियों का भी विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की व्यापारिक नीति, देश में शान्ति व सुरक्षा की स्थिति, सरकार की वित्त नीति आदि का प्रभाव विनिमय दर पर पड़ता है। (i) व्यापारिक नीति—सरकार देश में संरक्षण की नीति को अपनाकर निर्यातों को प्रोत्साहित तथा आयातों को हतोत्साहित कर सकती है। आयातों तथा निर्यातों के यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति को प्रभावित करते हैं और इनके कारण विनिमय दर बदल जाती है। (ii) शान्ति व सुरक्षा की दशाएँ—यदि देश में शान्ति व सुरक्षा की उचित व्यवस्था है, सरकार

स्थायी तथा टिकाऊ है और उसकी आर्थिक नीति उचित है तो ऐसी दशा में विदेशियों का विश्वास उस देश की मुद्रा में बढ़ता है और विदेशी पूँजी देश में आने लगती है जिसके कारण विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि देश में घणान्ति है और सरकार स्थायी नहीं है तथा वह उचित नीति का पालन नहीं करती है तो विदेशी पूँजी देश से भागने लगेगी और विनिमय दर हमारे विपक्ष में हो जायेगी। (iii) सरकार की वित्त नीति—यदि सरकार देश के ढंग में घाटे की व्यवस्था करती है तो उसके कारण मुद्रा का आन्तरिक मूल्य बढ़त जाता है जिसका प्रभाव उसके विदेशी मूल्य पर भी पड़ता है। इस प्रकार राजनैतिक दशाओं तथा सरकारी नीति का भी विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

विनिमय दर परिवर्तनों की सीमाएँ

(Limits of Fluctuations in Foreign Exchange Rate)—

उपयुक्त सभी कारणों से विनिमय दर में परिवर्तन हुआ करते हैं और वह सन्तुलन स्तर (Equilibrium Level) से ऊपर नीचे घटती-बढ़ती रहती है। विनिमय दर में परिवर्तन कितने कम अथवा अधिक होते हैं—यह इस बात पर निर्भर है कि देश स्वर्णमान पर हैं अथवा उन्होंने पत्र-मुद्रा प्रणाली को अपनाया हुआ है। स्वर्णमान में विनिमय दरों में अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं और इन परिवर्तनों की सीमाएँ निश्चित होती हैं। स्वर्णमान की स्थिति में विनिमय दर परिवर्तनों की सीमाएँ स्वर्णबिन्दु (Specie Points) के द्वारा निश्चित होती हैं और वास्तविक विनिमय दर कभी भी स्वर्ण-निर्यात बिन्दु (Gold Export Point) से ऊपर तथा स्वर्ण-आयात बिन्दु (Gold Import Point) से नीचे नहीं जाती है। विनिमय दर के इन सीमाओं से बाहर निकलन पर सोने का आयात अथवा निर्यात प्रारम्भ हो जाता है जिसके कारण विनिमय दर फिर सामान्य स्तर पर आ जाती है। एक देश के लिए विनिमय दर पक्ष में तब होती है जब वह स्वर्ण आयात बिन्दु के समीप होती है और जब विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु के समीप आ जाती है तो वह देश के लिए विपक्ष में हो जाती है।

पत्र-मुद्रामान वाले देशों में विनिमय दर परिवर्तन की कोई सीमाएँ नहीं होती हैं और वह सन्तुलन दर (Equilibrium Rate) से कितनी भी ऊपर तथा नीचे जा सकती है। पत्र-मुद्रा की दशा में विनिमय दर के लिए स्वर्णबिन्दु (Specie Points) जैसी कोई सीमाएँ नहीं होती हैं इसीलिए पत्र-मुद्रामान में स्वर्णमान की अपेक्षा विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता रहती है। पत्र-मुद्रा वाले देशों में विनिमय दर विदेशी वित्तों की मांग तथा पूर्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है और केवल सरकारी नियन्त्रण तथा प्रवन्ध के द्वारा ही विनिमय दर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) 'मुद्रा की क्रय-शक्ति समानता' सिद्धान्त क्या है ? स्पष्ट कीजिये कि यह दो अथवा अधिक मुद्राओं के आपसी मूल्य को विदेशी विनिमय के हेतु किस प्रकार स्थापित करता है । (आगरा बी० ए० १९६३)
- (२) विदेशी विनिमय दर कैसे निश्चित की जाती है ? (आगरा बी० ए० १९६२)
- (३) किसी देश की करेंसी का विदेशी विनिमय मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? (आगरा बी० ए० १९५९)
(राजस्थान बी० काम १९५५)
- (४) क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त को समझाइए और स्पष्ट कीजिए कि व्यावहारिक रूप से यह सिद्धान्त कहां तक लागू हो सकता है ? (आगरा बी० ए० १९५८)
- (५) स्पर्धमान एवं रजतमान वाले देशों के बीच विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (आगरा बी० काम १९५९ स)
- (६) विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में क्रय-शक्ति समता के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? विनिमय दर इस सत्यता से कब भिन्न होती है ? (आगरा बी० काम १९५८ स)
- (७) 'विदेशी विनिमय' से आप क्या समझते हैं ? उन विभिन्न घटकों का वर्णन करिए जो विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन ला देते हैं । (आगरा बी० काम १९५८)
- (८) विनिमय दरों के परिवर्तन से विदेशी व्यापार किस प्रकार प्रभावित होता है ? विवेचना करिये । (राजस्थान बी० ए० १९५९)
- (९) क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त का विवेचन करिये और इसके दोष बताइये । (राजस्थान बी० ए १९५८)
- (१०) विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार होता है ? (राजस्थान बी० काम १९५८)
- (११) विदेशी विनिमय के क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त को बताइये व समझाइये । इसकी सीमाओं पर भी प्रकाश डालिए । (सागर बी० ए० १९५८)
- (१२) अपरिवर्तनशील वस्तुओं में विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (सागर बी० काम १९५९)
- (१३) विनिमय की एक समता को समझाइये । विनिमय दर में उच्चावचन क्यों होते हैं ? (सागर बी० काम १९५८)

- (१४) विदेशी विनिमय दरें किस प्रकार निर्धारित होती हैं ? व्याख्या करिए ।
(विक्रम बी० ए० १९५९)
- (१५) उन घटकों को संक्षेप में समझाइये जो कि विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन ला देते हैं । क्या इन परिवर्तनों की कुछ सीमाएँ भी हैं ? विवेचन करिये ।
(राजस्थान बी० काम १९५५)
- (१६) विदेशी विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव के कारणों का आलोचनात्मक विवेचन करिये । क्या आपके विचार में इस प्रकार के उतार-चढ़ाव की सीमाएँ होती हैं ?
(सागर बी० ए० १९५९)



तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाता है।² प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार “विनिमय नियन्त्रण से हमारा अभिप्राय उन विधियों से है जिनके द्वारा स्वतन्त्र विदेशी विनिमय बाजार का स्थान त्रिवेचनात्मक नियन्त्रणों को दे दिया जाता है। क्रेता तथा विक्रेताओं को असंमित मात्रा में विदेशी विनिमय खरीदने तथा बेचने की आज्ञा नहीं दी जाती है। या तो खरीदी जाने वाली मात्रा, या मूल्य जिस पर उसे खरीदा जा सकता है अथवा दोनों पर प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध होते हैं।”³ पॉल ईन्जिग (Paul Einzig) ने विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत विनिमय बाजार में किये जाने वाले प्रत्येक हस्ताक्षेप को सम्मिलित किया है। क्राउथर (Crowther) ने भी विनिमय नियन्त्रण शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है और उसके अन्तर्गत हस्ताक्षेप, विनिमय प्रतिबन्ध तथा विनिमय प्रवन्ध आदि को विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सम्मिलित किया है।

विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का एकाधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। विदेशी विनिमय का मुद्रा बाजार बन्द कर दिया जाता है और विदेशी विनिमय व्यवसाय या तो केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य संस्था के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी विदेशी विनिमय अपनी वस्तुओं के बदले में अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त होता है, उसे केन्द्रीय बैंक को निश्चित दर पर देश की मुद्रा के बदले में बेचना पड़ता है और जिन लोगों को विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, उसे केवल केन्द्रीय बैंक से ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वतन्त्र विनिमय बाजार में लोगों को विदेशी विनिमय सम्बन्धी सोदे करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है किन्तु विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था में यह स्वतन्त्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकार का नियन्त्रण रहता है। विनिमय नियन्त्रण के द्वारा सरकार विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति में संतुलन स्थापित करके विनिमय दर में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न करती है।

2 “Exchange control, the means of dealing with balance of payments difficulties, . . . disregards market forces and substitutes them with the arbitrary decisions of Government officials. Imports and other international payments are no longer determined by international price comparisons, but by considerations of national need.”

—P. T. Ellsworth *The International Economy*, P. 332.

3 “When referring to exchange control we mean measures which replace the free foreign exchange market with discriminatory regulations. Buyers and sellers are no longer permitted to purchase and sell foreign exchange in unlimited amounts. Either the quantities purchased or the prices at which they can be purchased or both are now subject to direct regulations.”

—Halm *Economics of Money and Banking*, P. 465.

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य (Objects of Exchange Control)—

विदेशी विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है जिनमें से प्रमुख दस प्रकार हैं—

(१) विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखना—विनिमय नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना होता है। पत्र मुद्रा मान में अनियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवसाय के कारण विनिमय दरों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं जिनका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिरता लाने के लिए विनिमय दर को किसी एक निश्चित दर पर स्थिर कर देती है और विनिमय नियन्त्रण के द्वारा विनिमय दर को इस निश्चित बिन्दु पर बनाये रखने का प्रयत्न करती है। कभी-कभी विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग विदेशी विनिमय दर को सन्तुलित दर से उपर (over-valuation) अथवा उममे नीचे (under-valuation) रखने के लिए भी किया जाता है। क्राउथर के अनुसार इसकी आवश्यकता किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतन्त्र बाजार के स्तर से ऊँचे स्तर पर या उससे नीचे स्तर पर बनाये रखने के लिए हो सकती है।^४

(२) व्यापार सन्तुलन के घाटे को दूर करना—विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग व्यापार सन्तुलन के घाटे को दूर करने तथा उसे सन्तुलित करने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्ध होते हुए भी यह सम्भव हो सकता है कि देश का व्यापार सन्तुलन इतना अधिक असन्तुलित हो जाय कि उसे अन्य उपायों से ठीक न किया जा सके। ऐसी दशा में सरकार विनिमय नियन्त्रण की सहायता से इस असन्तुलन को दूर करने का प्रयत्न करती है। विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक ही विदेशी विनिमय को बेचने तथा खरीदने का काम करता है। केन्द्रीय बैंक उतनी मात्रा में ही विदेशी विनिमय बेचता है जितना कि उसे प्राप्त होता है और इस प्रकार आयातों को कम करके वह व्यापार सन्तुलन के घाटे को दूर कर सकता है।

(३) अल्प पूति वाली मुद्राओं का उचित प्रयोग—कोई देश विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए भी कर सकता है कि अल्प पूति वाली मुद्राओं को केवल लड़ाई का सामान अथवा आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुएँ मगाने के लिए ही काम में लाया जाय। द्वितीय विश्व-युद्ध काल में इङ्ग्लैंड, भारत तथा अन्य देशों ने विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया। भारतवर्ष में विनिमय नियन्त्रण के द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि डॉलर साधनों

4 "It may be desired to maintain the exchange. Value of a currency at a level higher than would prevail in a free market. Alternatively, it may be desired to depress the exchange value of the currency below the free level."

को प्रनावश्यक प्रयोगों में न लगाकर विकास के लिए पूँजीगत वस्तुयें मगाने में लगाया जाय।

(४) देश से पूँजी के बाहर जाने को रोकना—विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग विदेशी पूँजी को देश से बाहर जाने से रोकने तथा विदेशों में देशी पूँजी के विनियोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत देश से बाहर पूँजी के जाने पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं जिनके कारण देश से पूँजी का बाहर जाना रुक जाता है।

(५) गृह उद्योगों को संरक्षण देने के लिए—विनिमय नियन्त्रण के द्वारा देश के उद्योगों को संरक्षण भी दिया जा सकता है। यदि किसी देशी उद्योग पर विदेशी प्रतियोगिता का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो केन्द्रीय बैंक उस उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तु को विदेशों से आयात करने के लिए विदेशी विनिमय न देकर उस उद्योग को संरक्षण दे सकता है। किन्तु इस उद्देश्य के लिए विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग बहुत कम किया जाता है।

(६) व्यापारिक भेद-भाव करने के लिए—आंशिक विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक भेद-भाव करने के लिए भी किया जा सकता है। विनिमय नियन्त्रण की सहायता से एक देश से आने वाली वस्तुओं को रोका जा सकता है तथा दूसरे देश से होने वाली आयातों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ (Methods of Exchange Control)—

विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत वे सभी उपाय आ जाते हैं जिनके द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की माग तथा पूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। ये उपाय मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं—(अ) परोक्ष उपाय तथा (ब) प्रत्यक्ष उपाय।

(अ) परोक्ष उपाय (Indirect Methods)—इसके अन्तर्गत वे उपाय आ जाते हैं जिनका प्रयोग तो किसी और उद्देश्य से किया जाता है किन्तु जिनका प्रभाव विनिमय दर पर भी पड़ता है। परोक्ष उपाय केवल आंशिक रूप से ही विदेशी विनिमय बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। परोक्ष उपायों में दो का महत्त्व अधिक रहा है—

(१) प्रभुत्व कर (Tariffs and Quotas)—बोर्ड देश बाहर से आने वाले सामान पर आयात कर लगा कर अथवा उसके अगम्यता (Quota) निश्चिन करके अपनी आयात की मात्रा को कम कर सकता है, आयातों के कम हो जाने से विदेशी मुद्राओं में भी कमी होती है और विदेशी मुद्रा की माग गिर जाती है। इस प्रकार आयात करों के द्वारा विदेशी मुद्रा की माग को कम करके उसके मूल्य को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसका प्रभाव देशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करने का होता है।

इसके दूसरी ओर निर्यातों पर लगाये गये वर देन की मुद्रा के मूल्य को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि अन्य देश समान अनुपात में प्रशुल्क करो में वृद्धि न करें। यदि अन्य देशों के द्वारा भी प्रशुल्क करो को उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है तो इस नीति का विनिमय दरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा।

(ii) व्याज की दरों में परिवर्तन (Changes in the rate of Interest)—

व्याज की दरों में परिवर्तन करके भी विनिमय दरो को प्रभावित किया जा सकता है। यह प्रभाव पूँजी के आवागमन तथा विनियोगों के द्वारा होता है। देश में व्याज की दर बढ़ा देने से विदेशी पूँजी आकर्षित होती है और उस देश के बैंकों के लिए भी यह लाभपूर्ण हो जाता है कि वे अपनी पूँजी का विनियोग देश में ही करें। इस प्रकार पूँजी को देश से बाहर जाने से रोका जा सकता है तथा विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की माग कम हो जाती है और उसकी मूल्य वृद्धि रुक जाती है। व्याज की दर में वृद्धि करने से हमारी मुद्रा की विदेशों में माग बढ़ती है और उसकी पूर्ति कम हो जाती है जिसके कारण उसके मूल्य में वृद्धि होती है।

परोक्ष उपायों की सफलता का सीमा सीमित होता है और वे विनिमय बाजार का स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं। उनका प्रयोग तो किसी अन्य कारणों से किया जाता है किन्तु वे विनिमय दर को भी प्रभावित कर सकते हैं। परोक्ष उपायों के द्वारा विनिमय दर का प्रबन्ध नहीं किया जाता है बल्कि उनकी सहायता से केवल विनिमय दर को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार के उपायों का प्रयोग केवल सीमित मात्रा में किया जाता है क्योंकि बहुत कम देशों के लिए अपनी आयातों में काफी कमी करना सम्भव होता है। निर्यातों को अधिक सहायता भी सीमित मात्रा में ही दी जा सकती है और आन्तरिक स्थिरता को ध्यान में रखने हुए व्याज की दरों में अधिक वृद्धि करना भी सम्भव नहीं होता है। अतः परोक्ष उपायों को विनिमय नियन्त्रण का दृढ़ साधन नहीं माना जा सकता है और उनके द्वारा विनिमय दरो को अधिक सीमा तक प्रभावित करना सम्भव नहीं होता है।^५ इसीलिए विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष उपायों को काम में लाना आवश्यक हो जाता है।

(ब) प्रत्यक्ष उपाय (Direct Methods)—विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष उपाय अधिक प्रभावशाली होते हैं और उनके द्वारा विनिमय दरो का सम्पूर्ण नियन्त्रण किया जा सकता है। प्रत्यक्ष उपायों के अन्तर्गत वे उपाय आते हैं जिन्हें

5 "These methods of indirect control, therefore, though they are by no means negligible are not nearly strong or precise enough instruments for a government that aspires to bring the exchange rate under close control"

—Crowther : An Outline of Money, P. 247 & 243.

विनिमय दर को प्रभावित करने के निश्चित उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष उपाय भी दो प्रकार के हो सकते हैं—(i) हस्तक्षेप (Intervention) तथा (ii) प्रतिबन्ध (Restriction)। हस्तक्षेप की नीति के अन्तर्गत सरकार विनिमय दर को ऊँचा या नीचा रखने के लिए विदेशी विनिमय बाजार में सीधा हस्तक्षेप करती है। जब सरकार हस्तक्षेप के द्वारा विनिमय दर को ऊँचे स्तर पर रखने का प्रयत्न करती है तो इसके कारण देश की मुद्रा की मांग गिर जाती है और सरकार को ऊँची दर पर देशी मुद्रा की समस्त पूर्ति को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके विपरीत जब विनिमय दर को नीचे स्तर पर रखने का प्रयत्न किया जाता है तो देशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और सरकार को निश्चित दर पर अपनी मुद्रा को किसी भी सीमा तक बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हस्तक्षेप की नीति की सफलता सरकार के विदेशी विनिमय साधनों तथा देशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने की क्षमता पर निर्भर होती है।

प्रतिबन्ध की नीति के अन्तर्गत सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय तथा विदेशी मुद्रानालों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। प्रतिबन्धों के द्वारा सरकार विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय दर में स्थिरता लाने का प्रयत्न करती है। सन् १९३६ के पश्चात् विभिन्न देशों में हस्तक्षेप (Intervention) के द्वारा विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने में अधिक सफलता न मिल सकी और इन देशों में प्रतिबन्ध (Restriction) की अधिक प्रभावशाली नीति का प्रयोग किया जाने लगा। प्रतिबन्ध की नीति के द्वारा देश की मुद्रा की मांग में किसी प्रकार की कृत्रिम वृद्धि करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है बल्कि सरकार देशी मुद्रा की पूर्ति को बाजार में जाने से रोकती है और इस प्रकार देशी मुद्रा के मूल्य को गिरने से रोकता जाता है। प्रतिबन्ध की नीति के अन्तर्गत विदेशी विनिमय व्यापार का केन्द्रीयकरण कर दिया जाता है और उसका क्रय-विक्रय सरकार अथवा उसकी प्रतिनिधि सत्त्वा के द्वारा ही किया जा सकता है। देशी मुद्रा को किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले में प्रस्तुत करने के लिए सरकार की आज्ञा लेना आवश्यक कर दिया जाता है। सरकार की आज्ञा के बिना विदेशी विनिमय के सौदे को करना गैरकानूनी करार दे दिया जाता है। विनिमय प्रतिबन्धों का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी तथा आस्ट्रिया में किया गया। सन् १९३१ के सफ्टकाल में तथा सन् १९४१ के युद्ध के पश्चात् इसका प्रयोग अन्य देशों में भी किया जाने लगा। विनिमय प्रतिबन्धों का मुख्य उद्देश्य (i) देश के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोषों की रक्षा करना, (ii) देश से पूँजी के भागने को रोकना तथा (iii) अल्प-पूर्ति वाली मुद्राओं का उचित प्रयोग करना होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्यातकर्त्ताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया जाता है कि वे अपने समस्त विदेशी विनिमय को निश्चित दर पर केन्द्रीय बैंक को अनिवार्य रूप से

देच दें। आयातकर्ताओं को अपनी आवश्यकता के लिए विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक से प्राप्त करना होता है।

विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न रूप (Various Forms of Exchange Control)—स्वर्णमान के पतन के पश्चात् लगभग सभी देशों के द्वारा किसी न किसी रूप में विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किया जाने लगा है। व्यावहारिक रूप में विभिन्न देशों में तथा विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार से विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग किया गया है। विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं—

(१) **विनिमय उद्बन्धन (Exchange Pegging)**—विनिमय नियन्त्रण की यह विधि काफी पुरानी है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतया युद्ध काल में विनिमय परिवर्तनों को कम करने के लिए किया गया। इंग्लैंड के द्वारा प्रथम महायुद्ध काल में इसका प्रयोग किया गया और द्वितीय विश्व-युद्ध काल में भी उसे अपनाया गया। इस विधि के अन्तर्गत सरकार विनिमय दर को किसी निश्चित दर पर स्थिर रखने का प्रयत्न करती है। यह निश्चित दर जब सन्तुलित दर (Equilibrium rate) से ऊपर होती है तो इसे विनिमय दर को 'ऊपर टाँकना' (Pegging up) कहते हैं और जब विनिमय दर को सन्तुलित दर से नीचे रखने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विनिमय दर को 'नीचे अटकाना' (Pegging down) कहते हैं। इस प्रकार की नीति के अन्तर्गत सरकार निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करके विनिमय दर को एक निश्चित बिन्दु पर स्थिर रखती है। द्वितीय विश्व-युद्ध काल में भारतीय सरकार ने भी इस नीति के द्वारा रुपये के मूल्य को १ शिलिंग ६ पैन पर स्थिर रखा। विनिमय उद्बन्धन की नीति की सफलता उसको अपनाने वाले देश के पास मौद्रिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

(२) **विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund)**—इन्हें कभी-कभी विनिमय स्थायीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund) भी कहा जाता है। इस प्रकार के कोष की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में पौंड के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए की गई। विनिमय समानीकरण कोष विदेशी विनिमय बाजार में आवश्यकता के अनुसार अपने देश की मुद्रा को निश्चित दरों पर बेच और खरीद कर उसके विदेशी मूल्य में स्थिरता स्थापित करता है। मध्य यूरोप में आर्थिक संकट के कारण १९३१ में इंग्लैंड से विदेशी पूँजी भागने लगी और सभी देशों ने अपने कोषों को लन्दन से हटाने का प्रयत्न किया। विदेशी पूँजी के भागने के कारण पौंड की परिवर्तनशीलता को स्थगित करना पड़ा और इंग्लैंड में स्वर्णमान टूट गया। विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होने से पौंड के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आ गई। कुछ समय पश्चात् विश्वास पुनः स्थापित हो गया और भागी हुई पूँजी फिर इंग्लैंड वापस लौटने लगी। विदेशी पूँजी के भारी मात्रा में आने के कारण पौंड का मूल्य बढ़ गया। इस प्रकार स्वर्णमान के पतन के पश्चात् इंग्लैंड के पौंड के

मूल्य में भारी परिवर्तन हो रहे थे और वहाँ की सरकार ने अप्रैल मन् १९३२ में पौंड के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए एक विनिमय समानीकरण कोष स्थापित किया। इसके पश्चात् जनवरी मन् १९३४ में अमेरिका में भी इसी प्रकार का एक कोष स्थापित किया गया। तत्पश्चात् मन् १९३५ में कनाडा तथा उसी वर्ष में अर्जेंटाइना और वेल्जियम ने भी समानीकरण कोष स्थापित किये। मन् १९३६ में फ्रांस तथा स्विटजरलैंड ने भी अपनी मुद्राओं के मूल्य को स्थिर रखने के लिए इस प्रकार के कोष स्थापित किये। इन कोषों की कार्यविधि का ज्ञान इंग्लैंड के विनिमय समानीकरण कोष की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करके प्राप्त किया जा सकता है।

इंग्लैंड के विनिमय समानीकरण कोष का मुख्य उद्देश्य पौंड के क्रय-विक्रय के द्वारा विनिमय दर में स्थिरता स्थापित करना था। इस कोष की स्थापना मन् १९३२ में १०५ करोड़ पौंड की पूँजी में की गई जो मन् १९३७ तक बढ़ कर ५७.५ करोड़ पौंड हो गई। इस कोष में सोना तथा ब्रिटिश सरकार के कोषागार विपत्र (Treasury bills) रखे जाते थे। प्रारम्भ में कोष की पूँजी विदेशों में नहीं थी किन्तु कुछ समय पश्चात् कोष ने विदेशों में भी अपनी पूँजी जमा करली थी। कोष का प्रबन्ध ब्रिटिश ट्रेजरी के द्वारा किया जाता था। यह कोष विनिमय के बदले में स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय करता था। जब विनिमय बाजार में पौंड की पूर्ति अधिक हो जाने के कारण उसका मूल्य गिरने की प्रवृत्ति दिखलाता था तो यह कोष निश्चित दर पर विदेशी विनिमय के बदले में पौंड की अतिरिक्त पूर्ति को स्वयं खरीद लेता था और इस प्रकार पौंड के मूल्य को गिरने से रोका जाता था। इसी प्रकार जब पौंड की माग अधिक होती थी तो यह कोष अपने पास से पौंड को निश्चित दर पर बेचने लगता था और उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि को रोकना था। इस प्रकार विनिमय समानीकरण कोष पौंड की माग तथा पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करके उसके मूल्य को स्थिर रखता था।

प्रारम्भ में यह कोष पौंड को केवल डॉलर के बदले में ही बेचा करता था क्योंकि डॉलर सोने में परिवर्तनशील था। मन् १९३३ में अमेरिका के स्वर्णमान त्याग देने के कारण इस कोष ने पौंड के बदले में फ्रैंक स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु मन् १९३६ में फ्रांस ने भी स्वर्णमान को छोड़ दिया और कोष के सम्मुख एक कठिन समस्या उत्पन्न हुई कि वह पौंड के बदले में कौन-सी विदेशी मुद्रा को स्वीकार करे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस के बीच एक मौद्रिक समझौता हुआ जिसके अनुसार प्रत्येक देश को यह अधिकार दे दिया गया कि वह दूसरे की प्राप्त मुद्रा को २४ घण्टे के भीतर उस देश के केंद्रीय बैंक को देकर उसके बदले में सोना प्राप्त कर सकता है।

इस कोष का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों को दूर करना था और वह विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों में किसी प्रकार

की बाधाये उत्पन्न नहीं करता था। कोष का प्रयोग इस प्रकार किया जाता था कि पूँजी का विनियोग करने वालों की घबराहट तथा सट्टेबाजों की क्रियाओं का विदेशी विनिमय दर पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। इस कोष की कार्य-प्रणाली को गुप्त रखा जाता था जिससे कि वह अधिक प्रभावशाली हो सके। इस प्रणाली के द्वारा मुद्राओं के विदेशी मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को काफी सीमा तक दूर किया जा सका। द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ होने तक यह कोष सफलतापूर्वक कार्य करते रहे किन्तु युद्धवालीन स्थिति के कारण विनिमय दरों में इतने अधिक परिवर्तन होने लगे कि इन कोषों की उपयोगिता समाप्त हो गई।

(३) प्रवरुद्ध खाता (Blocked Account)—इसके अन्तर्गत विदेशियों की जमा रकम तथा उनको प्राप्त होने वाले भुगतानों को प्रवरुद्ध खाते में जमा कर दिया जाता है और एक निश्चित काल तक इस रकम को विदेशों में नहीं ले जाया जा सकता है किन्तु इस रकम को देश के भीतर खर्च करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रखा जाता है। विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति के मुद्दर जाने पर इस राशि को मुक्त कर दिया जाता है और इसके हस्तांतरण की सुविधायें दी जाती हैं। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया। सन् १९३१ में जब जर्मन मार्क के मूल्य में स्थिरता लाने के लिए वहाँ की सरकार ने विनिमय नियन्त्रण की नीति को अपनाया तो विदेशियों की सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ तथा मुद्राये सरकार के प्रवरुद्ध खाते नामक एक अलग कोष में जमा कर दी गई और उन्हें जर्मनी से बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। जर्मन नागरिक अपने विदेशी ऋण सरकार को चुका देते थे और सरकार उस राशि को विदेशियों के नाम से प्रवरुद्ध खाते में जमा करती जाती थी। इस प्रकार विदेशियों को तुरन्त भुगतान नहीं मिल सकते थे और वे या तो उस राशि को जर्मनी में ही खर्च कर लेते थे अथवा उसे कम मूल्य पर बेच देते थे। इस नीति का विकास जर्मनी में डा० शाट (Schacht) के द्वारा किया गया।

(४) आयात नियन्त्रण (Import Control)—विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। सरकार विदेशी व्यापार का नियमन करके विनिमय दर के परिवर्तनों को कम करने का प्रयत्न करती है। आयात करों में वृद्धि करके अथवा आयात सम्बन्धी अन्यथा निश्चित करके सरकार आयात की मात्रा को कम करती है। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात-करों को कम किया जाता है तथा निर्यातों को आर्थिक सहायता (Export Bounties) भी दी जाती है। इस प्रकार के प्रतिबन्धों से व्यापार सन्तुलन को प्रतिकूल होने से रोका जाता है और विनिमय दर को स्थिर रखा जाता है।

उपर्युक्त सभी उपायों को विनिमय नियन्त्रण के एकपक्षीय उपाय (Unilateral Methods) कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग कोई भी देश अकेला ही कर सकता

हे और इनके प्रभाव भी मुख्यतया उन्हीं देशों के ऊपर पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ द्विपक्षीय (Bilateral) तथा बहुपक्षीय (Multilateral) उपाय भी होते हैं जो दो अथवा दो से अधिक देश मिलकर प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग केवल आपसी समझौते अथवा सहयोग के द्वारा ही सम्भव होता है। द्वि-पक्षीय अथवा बहु पक्षीय उपाय इन प्रकार हैं—

(१) निकासी समझौते (Clearing Agreements)—निकासी समझौते की व्यवस्था के अन्तर्गत दोनो देशों के आयातकर्त्ता अपनी आयातों के मूल्यों को अपने देश के केन्द्रीय बैंक में जमा कर देते हैं। केन्द्रीय बैंक इस रकम से निर्यातकर्त्ताओं के भुगतानों को निवृत्त करता है। इस प्रकार एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है और विदेशी भुगतानों को निवृत्त करने के लिए विनिमय बाजार का प्रयोग नहीं किया जाता है। निकासी समझौतों के द्वारा व्यापारिक असन्तुलन को दूर किया जा सकता है और विदेशी विनिमय को स्थिर रखने में सहायता मिलती है किन्तु वे विदेशी व्यापार को वस्तु विनिमय में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए उनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

(२) दयास्थित समझौते (Standstill Agreements)—सर्वप्रथम सन् १९३१ के वार्शिक सत्र में जर्मनी के द्वारा इस प्रकार के समझौतों का प्रयोग किया गया। दयास्थित समझौतों का उद्देश्य दो देशों के बीच पूँजी के हस्तान्तरण को रोकना अथवा उसे कुछ समय के लिए स्थगित करना होता है। इस प्रकार का समझौता करने वाले देशों के बीच पूँजी के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं और अल्पकालीन ऋणों को या तो दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाता है अथवा उसको धीरे-धीरे भुगतान की सुविधा दी जाती है। उपर्युक्त व्यवस्था से ऋणी देश को अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ समय मिल जाता है जिसमें वह अन्य प्रकार के नियन्त्रणों के द्वारा अपने भुगतान मन्तुलन को सन्तुलित करने का प्रयत्न करता है।

(३) स्थानांतरित भुगतान (Transfer Moratoria)—विनिमय नियन्त्रण की इस पद्धति में विदेशी भुगतानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था में आयातकर्त्ता तथा अन्य व्यक्ति अपने विदेशी ऋणों का भुगतान देश की मुद्रा में एक निश्चित सख्या को कर देते हैं और आपसी काल समाप्त हो जाने के पश्चात् ऋणों को इस जमा रकम को विदेशों में भेजने की सुविधाएँ दी जाती हैं। स्थानांतरित भुगतान के कारण में किसी भी प्रकार का मुद्रा हस्तान्तरण विदेशों को नहीं किया जा सकता है।

विनिमय नियन्त्रण का मूल्यांकन (Evaluation of Exchange Control)—

यद्यपि हस्तक्षेप (Intervention) को सामान्यतया हानिरहित कहा जा सकता है किन्तु फिर भी उसके द्वारा किसी मुद्रा के मूल्य को बहुत लम्बे समय तक

वृत्रिम स्तर पर बनाये रखना कठिन होता है क्योंकि यदि देश के साधनों पर एक ही दिशा में दबाव रहता है तो वे जल्दी या देर से समाप्त हो जायेंगे। हस्तक्षेप के द्वारा स्थायी रूप से केवल विनिमय बाजार से दैनिक उच्चावचनों को दूर करने के उद्देश्य को ही प्राप्त किया जा सकता है।^६ इस उद्देश्य की प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सर्वप्रथम तो किसी भी मुद्रा की सन्तुलित विनिमय दर (Equilibrium Rate) का पता लगाना कठिन होता है। यदि किसी प्रकार सन्तुलन दर को मापने की कोशिश की जाए तो एक अन्य कठिनाई राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा के साधनों की उस मात्रा का अनुमान लगाने में होती है जो विनिमय दर को सन्तुलन दर के समीप रखने के लिए आवश्यक होगी। सरकार के द्वारा इन साधनों का अनुमान प्रायः आवश्यकता से कम लगाया जाता है जिसके कारण हस्तक्षेप की नीति की असफलता की सम्भावना बढ जाती है।

जहाँ तक विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction) का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अन्य प्रकार के आर्थिक नियन्त्रणों की भाँति ही अप्रिय है क्योंकि वह नागरिकों को वह सब कुछ नहीं करने देता है जिसे वे करना चाहते हैं।^७ किन्तु अप्रिय होते हुए भी कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। सङ्कटकालीन स्थिति में विनिमय नियन्त्रण किसी देश की कठिनाइयों को दूर करने की अस्थायी विधि के रूप में अनिवार्य होता है। जब किसी देश पर विदेशी ऋणों का भार अधिक होता है तो वह देश अपनी मुद्रा के विदेशी मूल्य को ऊँचे टाँक कर (Pegging up) के द्वारा इस प्रकार के ऋणों के भार को कम कर सकता है। इसी प्रकार जब किसी देश के भुगतान सन्तुलन में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तो उसके लिए विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जब कोई देश युद्धकालीन स्थिति के कारण अथवा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अनुभव करता है कि उसके लिए आयातों को कम करना सम्भव नहीं और निर्यातों में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकती है तो उसे इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए विनिमय नियन्त्रण का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार जब किसी देश से पूँजी का निर्यात इतनी बड़ी मात्रा में किया जाने लगता है कि वह उसके लिए एक समस्या बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करना पड़ता है।

6 "The one object that can be permanently pursued by means of Intervention is that of removing day-to-day fluctuations from the exchange market."

—Cronther : An Outline of Money, P. 271.

7 "It will be generally agreed that Restriction is an unpleasant thing, like any other form of economic regulation that forbids the citizenry to do what they want to do and creates a new categories of criminal offence"

—Cronther : An Outline of Money, P. 271.

विनिमय नियन्त्रण केवल एक अस्थायी विधि के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है और उसका प्रयोग सकट काल में अथवा किसी विशेष कठिनाई को दूर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके उससे बचना चाहिए किन्तु परिस्थितियाँ उसे आवश्यक बना देती हैं।^८ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पूँजी के आयात व निर्यात में हस्तक्षेप करने से यह क्रियाएँ सीमित हो जाती हैं और उनसे मिलने वाले लाभ कम हो जाते हैं। कभी-कभी विनिमय नियन्त्रण देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार की नीति के परिणामस्वरूप देश में भयंकर मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विनिमय नियन्त्रण अर्थ-व्यवस्था की सामान्य प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करता है जिसके कारण साधनों की प्रवृत्ति उन उद्योगों की ओर जाने की हो जाती है जो आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार साधनों का अपव्यय होता है। विनिमय नियन्त्रण द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) को प्रोत्साहित करता है और बहुपक्षीय व्यापार को हतोत्साहित करता है जिसके कारण बहुपक्षीय आधार पर किये जाने वाले व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग सीमित रूप से किया जाना चाहिए और एक अस्थायी विधि के रूप में ही उसका प्रयोग उचित है।

भारत में विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control in India)

भारतवर्ष में विनिमय नियन्त्रण सर्वप्रथम सितम्बर १९३६ में अपनाया गया। इसका उद्देश्य डॉलर के दुर्लभ साधनों को अनावश्यक प्रयोग से बचाना था जिससे कि उन्हें आवश्यक मुद्रा-सामग्री खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सके। इसीलिए आरम्भ में स्टैलिङ्ग सौदों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा गया। विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग मुख्यतः डॉलर तथा अन्य कड़ी मुद्राओं (Hard Currencies) के प्रयोग में बचत करने के लिए किया गया। मुद्रा समाप्त होने पर भारत की विदेशी विनिमय स्थिति में काफी सुधार हो गया था किन्तु फिर भी विनिमय नियन्त्रण को जारी रखा गया। इंग्लैंड से सामान खरीदने की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी किन्तु इतनी मात्रा में स्टैलिङ्ग विधि को मुक्त करना सम्भव नहीं था। इसके साथ भारत का भुगतान सन्तुलन भी विपक्ष में हो गया था। ऐसी स्थिति में स्टैलिङ्ग क्षेत्र के साथ होने वाले सौदों को नियन्त्रित करना भी आवश्यक हो गया और सन् १९४७ में विनिमय नियन्त्रण को स्टैलिङ्ग देशों के साथ

8 "There is consequently only one general judgement that can be expressed about exchange control in general, and that is that it should be avoided whenever possible, but that circumstances may often make it necessary"

होने वाले सौदे पर भी लागू कर दिया गया और १९५१ में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ किये जाने वाले सौदे भी विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत ले लिए गये ।

आर्थिक नियोजन आरम्भ हो जाने के पश्चात् विनिमय नियन्त्रण का महत्व काफी बढ़ गया है और वह योजनाओं को कार्य-रूप में लाने का एक माधन बन गया है । द्वितीय योजना के आरम्भ में ही हमने आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत धस्तुये तथा अन्य प्रकार का आवश्यक सामान मगाने पर अपनी स्टर्लिंग निधि का बहुत बड़ा भाग व्यय कर दिया था । इस योजना के अन्त तक हमारा स्टर्लिंग कोष इतना कम हो गया था कि अब उसमें से स्टर्लिंग निकाल कर आर्थिक विकास के लिए व्यय करना सम्भव नहीं था । इसके अतिरिक्त हमने आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण भी लिया हुआ था जिसके भुगतान व मूद इत्यादि के लिए भी काफी बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी । हमें आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में आयातों का प्रबन्ध भी करना था । ऐसी कठिन परिस्थिति में विनिमय नियन्त्रण ही हमारी सहायता कर सकता था । योजना काल में विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग आर्थिक विकास की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विनिमय नियन्त्रण को अधिक कड़ा एवं विस्तृत कर दिया गया जिससे कि विदेशी मुद्रा के दुर्लभ साधनों का प्रयोग आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जा सके । मुलभ मुद्रा (Soft Currency) तथा दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency) के भेद को समाप्त कर दिया गया और सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के व्यय पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।

सन् १९४७ के विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) के अन्तर्गत भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक को भारत में विदेशी विनिमय तथा विदेशी प्रतिभूतियों के सौदे, विदेशियों को किये जाने वाले भुगतानों, करों, नोटों, सोने तथा बहुमूल्य पत्थरों के आयात व निर्यात, विदेशियों की प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण आदि को नियन्त्रित करने का अधिकार दे दिया गया । इस प्रकार के सभी सौदे सामान्यता रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त बैंकों के द्वारा ही किये जा सकते हैं । विदेशी मुद्राओं को खरीदने के लिए रिजर्व बैंक से परमिट प्राप्त करना होता है जिसके आधार पर केवल अधिकृत व्यापारियों से ही विदेशी विनिमय खरीदा जा सकता है । स्टर्लिंग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुछ छूट दी गई है । उनके लिए आज्ञा पत्र आवश्यक नहीं है और वे १५० पाँड प्रति मास तक अपने परिवार के व्यय के लिए भेज सकते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं—

(१) भारत में रहने वाले विदेशी केवल सीमित मात्रा में ही मुद्रा अपने देशों को भेज सकते हैं । सामान्यता कुल आय में से जीवन निर्वाह के उचित व्यय को

घटा कर दोष रकम को भेजने की आज्ञा दी जाती है। इस प्रतिबन्ध के कारण जब कोई फर्म विदेशियों की सेवाये प्राप्त करना चाहती है तो उसे रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वीकृति लेनी होती है।

(२) अपने देश को लौटने वाले विदेशियों को अपनी वचन, प्राविडेन्ट फण्ड, अपनी सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त होने वाली आय आदि को अपने देश की मुद्रा में ले जाने का अधिकार है किन्तु उसकी अधिकतम सीमा १००० पाउंड निश्चिन कर दी गई है।

(३) विदेशी अगधारियों तथा जमा के स्वामियों को सामान्य एव ब्याज की रकम को देश से बाहर भेजने की पूरी स्वतन्त्रता है। विदेशी मुद्राओं में बीम की रकम भी बिना किसी प्रतिबन्ध के भेजी जा सकती है।

(४) केवल अनुज्ञापन प्राप्त आयातों के भुगतान के लिए ही विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु बिना अनुज्ञापन के मगाई जाती है और यदि वे खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licence) के अन्तर्गत नहीं आती है तो ऐसी आयातों के भुगतान के लिए विदेशी विनिमय नहीं दिया जाता है।

(५) स्टर्लिंग क्षेत्र में बाहर पूँजी के भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और केवल विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है।

(६) विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को अपने लाभ को प्रधान कार्यालयों को भेजने की छूट दी गई है।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) विदेशी विनिमय बरों के उतार-चढ़ाव के कारणों का सावधानी से विवेचन करिये। (आगरा बी० ए० १९६५)
- (२) विनिमय नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत में इस नियन्त्रण की कार्यवाही पर प्रकाश डालिये। (आगरा बी० ए० १९६०)
- (३) विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं? विनिमय नियन्त्रण के साधनों का वर्णन कीजिये। (आगरा बी० ए० १९५७)
- (४) आय विनिमय नियन्त्रण से क्या समझते हैं और यह क्यों आवश्यक हो गया है? (आगरा बी० कॉम० १९५४)
- (५) विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य एवं विधियाँ बनाइये तथा भारतीय उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (राजस्थान बी० कॉम० १९५७)
- (६) विनिमय नियन्त्रण क्या है? द्रव्य के विदेशी विनिमय में स्थिरता लाने में यह कहाँ तक सहायक होना है? (आगरा बी० ए० १९५८ स)
- (७) विनिमय समायोचकता क्यों के उद्देश्य, स्वभाव एवं सीमाएँ दीजिए। (आगरा बी० ए० १९५५)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

INTERNATIONAL MONETARY FUND

वार्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध के पश्चात् लगभग सभी देशों के द्वारा अनुभव की जाने लगी। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाये गये किन्तु इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सका। प्रथम महायुद्ध के कारण उत्पन्न मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी समस्याओं को स्वर्णमान की स्थापना के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया गया। सन् १९२८ के पश्चात् समार के अधिकांश देशों में स्वर्णमान स्थापित हो जाने के कारण मौद्रिक स्थिरता की समस्या को काफी सीमा तक सुलझा लिया गया। किन्तु युद्धोत्तरकालीन स्वर्णमान अधिक समय तक न चल सका और सितम्बर सन् १९३१ में इंग्लैंड ने स्वर्णमान को छोड़ दिया तथा १९३३ में अमेरिका और १९३६ में फ्रांस के द्वारा भी उसे त्याग दिया गया। स्वर्णमान के पतन के पश्चात् विदेशी विनिमय दरों की व्यवस्था फिर बिगड़ने लगी और उनमें भारी परिवर्तन होने लगे। विनिमय दरों की अत्यधिक स्थिरता के कारण अधिकांश देशों के द्वारा विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) की नीति को अपना लिया गया। विनिमय नियन्त्रण के कारण अब विदेशी विनिमय की स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्ति नहीं किया जा सकता था जिसके कारण विदेशी व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न हो गईं और उसकी मात्रा घटने लगी। कुछ देशों ने विनिमय नियन्त्रण के द्वारा अपनी विनिमय दर को सन्तुलित दर (Equilibrium rate) में ऊपर बनावे रखने का प्रयत्न किया जिसका इन देशों की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ अन्य राष्ट्रों ने विनिमय नियन्त्रण का दुरुपयोग किया और उसके द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करके निर्यातों को प्रोत्साहन देना चाहा तथा आयातों को कम करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की नीति के प्रतिक्रियास्वरूप कुछ अन्य देशों ने अपनी मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन कर दिया और इस प्रकार विभिन्न देशों में विनिमय अवमूल्यन की एक होड़ लग गई जिसके बहुत घातक परिणाम हुए। कुछ देशों ने भारी आयात कर लगा कर इस स्थिति से अपने उद्योगों की रक्षा की।

स्वतन्त्रता का पतन हो जाने से सभार की मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और विभिन्न देशों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रत्येक देश अपने हितों की वृद्धि करने में लगा हुआ था और दूसरे देशों के हितों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितता बढ़ जाने के कारण उसकी मात्रा बहुत अधिक कम हो गई और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजी का आवागमन भी बहुत कम होन लगा। कुछ बड़े-बड़े देशों ने विदेशी विनिमय की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए एकपक्षी (Unilateral) उपाय किये किन्तु उनमें बहुत अधिक सफलता न मिल सकी और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव अनुभव किया जाने लगा। इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस ने विदेशी विनिमय की समस्या को सुलझाने के लिए विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Funds) स्थापित किये किन्तु उनकी सफलता केवल अल्पकालीन थी और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव के कारण इस समस्या को स्थायी रूप से नहीं सुलझाया जा सका। यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की मौद्रिक अव्यवस्था विभिन्न देशों के बीच आपसी समझौते के द्वारा ही दूर की जा सकती है। यदि प्रत्येक देश अपनी अलग-अलग नीति को अपनाता है और दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखता है तो ऐसी दशा में मौद्रिक व्यवस्था का अस्त-व्यस्त हो जाना स्वाभाविक ही है। इस अनुभव का प्रथम प्रमाण त्रिपक्षीय सन् १९३६ का त्रिपक्षीय (Tripartite) समझौता था जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के बीच किया गया और जिसके अन्तर्गत वे एक दूसरे के परामर्श के बिना अपनी विनिमय दरों को नहीं बदल सकते थे। किन्तु उस समय भी यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के सहयोग का आधार अधिक विस्तृत होना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता—

द्वितीय विश्व-युद्ध काल में विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई, विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई तथा उसका क्षेत्र सीमित होने लगा। विभिन्न देशों में पत्र-मुद्रा प्रसार होने के कारण मूल्य-स्तरों में बहुत वृद्धि हो गई थी और विनिमय दरों में अत्यधिक परिवर्तन होने लगे थे। विदेशी विनिमय की अस्थिरता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितता बढ़ गई और उसकी मात्रा कम हो गई। इस प्रकार की स्थिति का अधिक समय तक बना रहना सभार के आर्थिक हितों में नहीं था और मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिरता को स्थापित करने के उपाय सोचे जाने लगे। इसके अतिरिक्त यह अनुभव किया जाने लगा कि युद्धकालीन विश्वस के कारण युद्धोत्तर काल में आर्थिक पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होगी जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही सुलझाया जा सकेगा। यह भी अनुभव किया गया कि वर्तमान युद्ध बहुत कुछ आर्थिक कारणों से पैदा होने हैं और विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की

असमानताओं को दूर करके युद्ध की सम्भावना को कम किया जा सकेगा। युद्ध के पश्चात् संसार के अल्प विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी के विनियोग की आवश्यकता होगी। इन सब समस्याओं को पारस्परिक सहानुभूति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही सुलझाया जा सकता था। अतः कुछ बड़े-बड़े देशों में युद्ध काल में ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की योजनाएँ बनाई जाने लगीं। इस सम्बन्ध में सन् १९४३ में दो योजनाएँ प्रकाशित की गईं जिनमें से एक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत "केन्ज योजना" (Keynesian Plan) थी तथा दूसरी अमेरिका द्वारा निर्मित "व्हाइट योजना" (White Plan) थी। दोनों ही योजनाओं में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इन दोनों में से किसी भी योजना को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनमें से प्रत्येक योजना में अपने देश के हितों को प्राथमिकता दी गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के लिए अमेरिकन सरकार ने जुलाई सन् १९४४ में ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा परिषद् बुलाई। इस परिषद् में ४४ मित्र-राष्ट्रों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। भारत ने भी इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के पश्चात् जिस योजना को स्वीकार किया उसे ब्रेटन वुड्स समझौते (Bretton Woods Agreement) के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank of Reconstruction and Development) की स्थापना का निश्चय किया गया। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना का निश्चय सन् १९४२ में हुआ और इन्होंने सन् १९४० से अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसम्बर सन् १९४५ में हुई। आरम्भ में ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ४४ राष्ट्र इसके सदस्य बन गये किन्तु इसके पश्चात् सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही है। ३० अप्रैल १९६२ को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या ७६ थी। इसके पश्चात् कुछ और देश भी कोष के सदस्य बने हैं जिसके कारण उसका कार्य-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केन्द्रीय बैंकों का बैंक है तथा संसार की मौद्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था है।"^१ जिस प्रकार किसी देश का

1 "The International Monetary Fund will be a bank of central banks, the capstone in the world's monetary system"

केन्द्रीय बैंक सदस्य देशों के रक्षित धनो को एक जगह इकट्ठा (Pool) कर लेता है, उसी प्रकार मुद्रा कोष भी सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के विदेशी विनिमय साधनों को एक जगह इकट्ठा करता है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विभिन्न देशों की मुद्रायें जमा रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह उन मुद्रा को उधार देता है जिसकी किसी विशेष केन्द्रीय बैंक को आवश्यकता होती है। क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य घाटे वाले देशों को उन मुद्राओं को उपलब्ध करना है जिनकी आवश्यकता उन्हें इन घाटे को पूरा करने के लिए होती है।" ² इन समानताओं के होने हुए भी मुद्रा कोष और केन्द्रीय बैंक में कुछ भिन्नताएँ पाई जाती हैं। वह केन्द्रीय बैंक की भाँति मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकता है और सदस्य देशों की आवश्यकताओं को अपने साधनों से ही पूरा कर सकता है। मुद्रा कोष केन्द्रीय बैंक की भाँति अपने सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की किसी विशेष प्रकार की आर्थिक नीति अपनाएँ के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

(Purposes of the International Monetary Fund)—

ब्रैटन वुड्स समझौते (Bretton Woods Agreement) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना तथा एक ऐसी स्थाई मस्या के रूप में कार्य करना जिससे द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं को आपसी सहयोग तथा परामर्श से सुलझाया जा सके।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा सतुनित विकास की सुविधाएँ देना जिससे रोजगार और वास्तविक आय के ऊँचे स्तर को बनाये रखा जा सके।

(३) विनिमय स्थिरता को स्थापित करना तथा सदस्य देशों में विनिमय दरों को कम करने की प्रतियोगिता को रोकना।

(४) बहुमुखी भुगतानों (Multilateral Payment) की व्यवस्था को स्थापित करने में सहायता देना।

(५) कोष के साधनों को सदस्य देशों को पर्याप्त सुरक्षा के आधार पर उपलब्ध करना जिससे कि उन्हें हानिकारक उपायों के बिना ही शोधनाशेष (Balance of Payments) को ठीक करने का अवसर दिया जा सके।

(६) सदस्य देशों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाशेष में असन्तुलन की अवधि तथा अंश को कम करना।

2 "The main purpose of the I. M. F. is to provide countries that have deficits with the foreign currencies they require to cover those deficits"

मुद्रा कोष की पूँजी (Capital of I. M. F)—

स्थापना के समय मुद्रा कोष की कुल पूँजी १०,००० मिलियन डॉलर्स निश्चित की गई थी जिसे सदस्य देशों से चन्दे के रूप में प्राप्त किया जाना था। प्रत्येक देश अपने अग्र्यश के अनुसार अपनी मुद्रा तथा सोना कोष में जमा रखता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विभिन्न देशों की मुद्रायें तथा सोना जमा रहता है। सबसे अधिक अग्र्यश २७५० मिलियन डॉलर्स अमेरिका का निश्चित किया गया था। ब्रिटेन का अग्र्यश १३५० मिलियन डॉलर्स, रूस का १२०० मिलियन डॉलर्स, फ्रांस का ४५० मिलियन डॉलर्स तथा भारत का अग्र्यश ४०० मिलियन डॉलर्स निश्चित किया गया। इसी प्रकार अन्य सदस्य देशों के अग्र्यश भी निश्चित कर दिये गए। ३० अप्रैल सन् १९६२ को मुद्रा कोष की सदस्य सख्या तथा उनके अग्र्यशों में वृद्धि हो जाने के कारण, उसकी पूँजी बढ़ कर १५,०५६.६ मिलियन डॉलर्स हो गई थी। मुद्रा कोष की सदस्य सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है क्योंकि नये देश उसके सदस्य बने रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कोष के साधन भी बढ़ रहे हैं।

विभिन्न देशों के अग्र्यश निर्धारित करने का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है किन्तु प्रत्येक सदस्य देश का अग्र्यश निश्चित करते समय उस देश की स्वर्ण तथा डॉलर निधि, राष्ट्रीय आय, उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार तथा उसके आर्थिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक ५ वर्ष के पश्चात् किसी भी देश के अग्र्यश को ऊँच वहुमत से बदला जा सकता है। सदस्य देश की प्रार्थना पर भी अग्र्यश में परिवर्तन किया जा सकता है। देशों के निश्चित अग्र्यश का कुछ भाग सोने में तथा कुछ सदस्य देशों की मुद्राओं के रूप में जमा किया जाता है। प्रत्येक देश को अपने अग्र्यश का २५% अथवा अपनी कुल स्वर्ण तथा डॉलर निधि का १०% (दोनों में जो भी कम हो) सोने में अथवा अमेरिकन डॉलर में तथा शेष अपनी मुद्रा में जमा करना होता है। किसी भी देश का मतदान अधिकार (Voting Right) उसके अग्र्यश की मात्रा के अनुसार निश्चित होता है। भारतवर्ष सन् १९४५ में इस कोष का सदस्य बन गया और ४०० मिलियन डॉलर के अग्र्यश का १०% सोने में तथा शेष भारतीय मुद्रा में जमा कर दिया गया।

सन् १९५६ में मुद्रा कोष के सब सदस्यों के अग्र्यशों में ५०% की वृद्धि करने का निश्चय किया गया जिसके परिणामस्वरूप कोष के साधन उसी अनुपात में बढ़ गये हैं। अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में यह निश्चय किया गया कि सदस्य देशों के अग्र्यशों में इस प्रकार की वृद्धि की जाये, जिससे कि ऐसे विकासशील देशों को लाभ पहुँच सके जो शोधनाशेष की कठिनाइयों में फँसे हुए हैं। इस निश्चय के परिणामस्वरूप सभी सदस्यों के अग्र्यशों में २५% की सामान्य वृद्धि की गई है तथा १६ देशों के अग्र्यशों में विशेष वृद्धि करने की व्यवस्था

की जा रही है। अम्यशो की यह वृद्धि इसलिए की गई है जिससे कि कोप के साधनों में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। सदस्यों के अम्यशो के २५% बढ़ जाने से कोप के साधनों में १५०० मिलियन डॉलर्स की वृद्धि होने की आशा है।

स्वर्ण समता दरों का निर्धारण (Determination of Par Values)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप विदेशी विनिमय की स्थिरता स्थापित करने के लिए दो प्रमुख कार्य करता है—(i) विभिन्न देशों की मुद्राओं की स्वर्ण समता दरों को निश्चित करता है तथा (ii) उन देशों को विदेशी मुद्रायें उधार देता है जिन्हें उस मुद्रा का धादा होता है।

मुद्रा कोप के सम्मुख सबसे पहली समस्या सदस्य देशों की मुद्राओं की समता दरों को निश्चित करना था। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सभी सदस्यों को अपनी मुद्राओं के स्वर्ण अथवा डॉलर मूल्य को निश्चित करके मुद्रा कोप को उसकी सूचना देना आवश्यक था। प्रत्येक देश को मुद्रा कोप का सदस्य बनते समय अपनी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य (Gold Parity) को निश्चित करना होता है और इसे सामान्यतः स्थिर रखना होता है। इस प्रकार सद देशों की मुद्राओं के स्वर्ण मूल्य निश्चित हो जाने से विनिमय दरों के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होती है। मुद्रा कोप की योजना में भी सोना विभिन्न मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्यों को निर्धारित करने का कार्य करता है और स्वर्ण समता दरों के द्वारा ही विनिमय की स्थिरता को प्राप्त किया जाता है।

मुद्राओं का सोने के साथ यह सम्बन्ध हमेशा के लिए निश्चित नहीं है और उसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी सदस्य देश अपनी मुद्रा की स्वर्ण समता दर की शोधनाशेष में आधारभूत असंतुलन (Fundamental Disequilibrium) को दूर करने के लिए बदल सकता है। जिस समय कोई सदस्य देश यह अनुभव करता है कि उसके शोधनाशेष की स्थिति में कोई आधारभूत असंतुलन उत्पन्न हो गया है तो वह अपनी मुद्रा के समता मूल्य में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रख सकता है किन्तु यह प्रस्तावित परिवर्तन केवल शोधनाशेष के आधारभूत असंतुलन को दूर करने के लिए ही होना चाहिए।³ कोई भी देश अपनी मुद्रा के समता मूल्य को बदलने के लिए एकपक्षी निर्णय (Unilateral Decision) नहीं ले सकता है बल्कि ऐसा करने से पूर्व उसे मुद्रा कोप की स्वीकृति लेनी होगी। यदि मुद्रा की स्वर्ण समता दर में यह परिवर्तन १०% या उससे कम है तो मुद्रा कोप इसका कोई विरोध नहीं करेगा। किन्तु यदि प्रस्तावित परिवर्तन १०% से अधिक है किन्तु २०% से अधिक नहीं है तो ऐसी

3 "Changes in par values may be made only on the initiative of the member and in order to correct a fundamental disequilibrium, and, with minor exceptions, only with the approval of the Fund."

दशा में मुद्रा कोष उसे मान भी सकता है और सम्बोकार भी कर सकता है किन्तु प्रत्येक दशा में उसे अपना निर्णय ७२ घण्टों में बनना चाहिए। यदि यह परिवर्तन २०% से अधिक है तो कोष इस बारे में निर्णय करने के लिए अधिक समय लगा सकता है।

मुद्रा कोष के साधनों का प्रयोग (Utilisation of Fund's Resources)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की मुद्राओं का एक दूबारे के लिए क्रय-विक्रय करना है। कोई भी देश विदेशी विनिमय की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए मुद्रा कोष से अपनी मुद्रा अथवा सोन के बदले में विदेशी विनिमय खरीद सकता है। जब किसी देश को अन्य किसी सदस्य देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है तो कोष उस देश की मुद्रा के बदले में उसे विदेशी विनिमय उपलब्ध करने की व्यवस्था करता है। कोई भी देश अपने क्रम्यश (Quota) के २००% से अधिक मूल्य का विदेशी विनिमय मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता है किन्तु इसमें से एक र्प में केवल २५% का ही प्रयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध है कि मुद्रा कोष के पास किसी भी सदस्य देश की मुद्रा की कुल मात्रा उसके क्रम्यश का २००% से अधिक नहीं होनी चाहिए।^४ असामान्य परिस्थिति तथा अत्यधिक आवश्यकता के समय ये शर्तें ढीली भी की जा सकती हैं। ऋण सम्बन्धी यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गए हैं कि मुद्रा कोष के पास किसी सदस्य देश की मुद्रा की कमी न होने पाये तथा कोई देश अनावश्यक रूप से मुद्रा कोष के ऋणों के ऊपर निर्भर न हो जाये और देश अपनी स्थिति को स्वयं सुधारने का प्रयत्न करे। मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता अस्थायी होती है और दीर्घकालीन तथा बड़ी मात्रा के ऋणों को हतोत्साहित किया जाता है।

प्रत्येक देश जब मुद्रा कोष से ऋण लेता है तो उसे इन ऋणों पर ३% का सेवा शुल्क (Service charges) देना होता है। सदस्य देश बिना आवश्यकता के मुद्रा कोष से बार बार विदेशी विनिमय न खरीदे इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि जैसे-जैसे मुद्रा कोष का ऋण बढ़ता जाता है सदस्य देश को बढ़ती हुई दर पर ब्याज देना होता है। ब्याज की यह दर ३% से आरम्भ होकर २३% तक जाती है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के द्वारा लिए जाने वाले विदेशी विनिमय ऋणों के प्रयोग पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। कोई भी सदस्य देश मुद्रा कोष से लिए गये ऋणों का प्रयोग मुद्रा कोष के उद्देश्यों के विपरीत नहीं कर सकता है। यदि

4 "A member country can purchase foreign currencies from the I. M. F. providing the purchases do not swell the I. M. F.'s holdings of that currency by more than 15% of the country's quota during the twelve months preceding and so long as the purchases do not cause the I. M. F. to hold that currency to an amount greater than 200% of the country's quota."

कोई देश मुद्रा कोष के द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करता है तो कोष उसे इस प्रकार की सुविधाएँ देने से इनकार कर सकता है।

दुर्लभ मुद्राएँ (Scarce Currencies)—

मुद्रा कोष के विधान में दुर्लभ मुद्राओं के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गई है। यदि बहुत-से देश एक ही मुद्रा को बराबर कोष से उधार लेते रहते हैं तो मुद्रा कोष के पास उस मुद्रा की कमी हो जायेगी और वह उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति मुख्यतया अमेरिकन डॉलर के सम्बन्ध में उत्पन्न हो सकती है। कोष के पास प्रत्येक देश की मुद्रा एक सीमित मात्रा में ही होती है। यदि कभी भी किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि मुद्रा कोष के लिए अपने साधनों से उसकी मांग को पूरा करना सम्भव न हो सके तो ऐसी दशा में कोष उस मुद्रा वाले देश में ऐसी दुर्लभ मुद्रा को उधार ले सकता है अथवा वह उसे सोने के बदले में खरीद सकता है। यदि फिर भी उस मुद्रा की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है तो मुद्रा कोष उस मुद्रा-विशेष को दुर्लभ मुद्रा (Scarce Currency) घोषित कर सकता है। किसी भी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देने में मुद्रा कोष को उस मुद्रा के राशनिंग का अधिकार मिल जाता है। ऐसी दशा में सदस्य देशों की दुर्लभ मुद्रा की मांग की पूर्ण पूर्ति नहीं की जाती है और उन्हें अल्प-मुद्रा वाले देश से आने वाली आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर अपने शोधना-क्षेप (Balance of Payment) को संतुलित करने का अधिकार होता है।

इसके विपरीत यह भी सम्भव हो सकता है कि मुद्रा कोष के पास ऐसी मुद्राएँ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जायें जिनकी मांग नहीं है। ऐसी स्थिति में कोष अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। मुद्रा कोष की तरलता (Liquidity) को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास किसी भी सदस्य देश की मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में जमा न हो पाये। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोष के विधान में मुद्राओं की 'पुनः खरीदने' की व्यवस्था (Repurchase Provision) की गई है। यदि कोष के पास किसी देश की मुद्रा उसके अभ्यश (Quota) से अधिक मात्रा में आ जाती है तो वह देश सोने के बदले अपने अभ्यश में अधिक मुद्रा को खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक देश प्रति वर्ष सोने अथवा परिवर्तनीय मुद्रा के बदले कोष के पास से अपनी मुद्रा की कुल मात्रा का एक निश्चित भाग पुनः खरीदेगा।

मुद्रा कोष का प्रबन्ध (Management of the Monetary Fund)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबन्ध एक गवर्नर मण्डल (Board of Governors) तथा कार्यकारिणी संचालक समिति (Executive Directors) के द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा एक गवर्नर ५ वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड की बैठक कम से कम साल भर

में एक बार होती है। गवर्नर मण्डल मुद्रा कोष के संचालन सम्बन्धी आधारभूत नीति का निर्माण करता है तथा सामान्य देखभाल रखता है। मुद्रा कोष का दैनिक प्रबन्ध एक कार्यकारिणी संचालक समिति के द्वारा किया जाता है। इस समिति में १२ सदस्य होते हैं जिनमें ५ स्थायी तथा ७ अस्थायी डाइरेक्टर्स रहते हैं। स्थायी सदस्य उन पाँच बड़े-गड़े देशों के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिनके अन्वय (Quotas) सबसे अधिक हैं—प्राजकल भारतवर्ष भी उनमें से एक है। इनके अतिरिक्त २ डाइरेक्टर्स की नियुक्ति लेटिन अमेरिका वाले देशों के द्वारा की जाती है तथा ५ अन्य सदस्य देशों के द्वारा चुने जाते हैं। इस समय कोष का प्रधान कार्यालय अमेरिका में है।

मुद्रा कोष की योजना में सोने का स्थान
(Place of Gold in I. M. F. Scheme) —

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना में सोने का महत्वपूर्ण स्थान है। सोना विभिन्न देशों की मुद्राओं के मूल्यों को नापने के आधार का कार्य करता है और सदस्य देशों की विनिमय दरें उनकी मुद्राओं के स्वर्ण मूल्य की सहायता से निश्चित की जाती हैं। इस योजना में सोने का महत्व निम्न बातों से स्पष्ट होता है—

(प्र) विभिन्न मुद्राओं की समता दरें (Par Values) स्वर्ण के द्वारा निश्चित की जाती हैं। सदस्य देश अपनी मुद्रा के स्वर्ण समता मूल्य (Gold Parity) से बहुत ऊँचे अथवा नीचे मूल्य पर सोने का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते हैं।

(ब) सोना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का कार्य करता है क्योंकि मुद्रा कोष के साधनों का एक भाग सोने के रूप में रहता है। सदस्यों को अपने अन्वय (Quota) का एक चौथाई भाग सोने के रूप में जमा करना होता है। इसके अतिरिक्त सदस्य देश सोने के बढ़ते में कोई भी मुद्रा इस कोष से खरीद सकते हैं। मुद्रा कोष भी सोने में भुगतान करके दुर्लभ मुद्राओं की खरीद सकता है।

(स) मुद्रा कोष से लिए गये ऋणों पर दिये जाने वाले व्याज का भुगतान भी सोने में करना होता है। इस सम्बन्ध में उन सदस्य देशों को कुछ छूट दी जाती है जिनकी स्वर्ण निधि उनके कोटे के आधे से कम होती है।

उपरोक्त बातों के आधार पर कभी-कभी यह कहा जाता है कि मुद्रा कोष की योजना में भी सोने का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि स्वर्णमान में था। कुछ लोगों का तो यह विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना स्वर्णमान का ही एक विशेष रूप है क्योंकि इसमें सोना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान का कार्य करता है तथा उसके द्वारा निश्चित दरों पर विभिन्न मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया जा सकता है।

क्या मुद्रा कोष एक स्वर्णमान योजना है ?—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना तथा स्वर्णमान में इतनी अधिक समानता पाई जाती है कि कुछ एक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा कोष एक स्वर्णमान योजना

हे। जॉन एच० विलियम्स (John H. Williams) ने आरम्भ में ही 'हाइड' योजना तथा कीन्स योजना को मुख्यता स्वरूपमान योजनाओं समझा है।^{१२} विलियम्स के अनुसार वह देश जो कोप से अन्ततः विदेशी विनिमय को खरीदने वाला (Net Purchaser from the Fund) होता है उसकी स्थिति स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण खोने वाले देश (Gold losing country) की भाँति होती है क्योंकि ऐसे देश में गारा का संचुचन होता स्वाभाविक है। इसके विपरीत अपनी मुद्रा को अन्ततः बेचने वाले देश (Net Seller to the Fund) की स्थिति एक स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश (Gold Receiving Country) की भाँति होती है जिसमें साख का विस्तार होता रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की कार्य प्रणाली बहुत कुछ स्वर्णमान की भाँति ही चलती है। इस योजना में भी विभिन्न मुद्राओं का विनिमय मूल्य मोने में निश्चित किया जाता है और स्वर्णमान की भाँति अधिक्य वाले देशों (Surplus countries) में साख का विस्तार होता है तथा घाटे वाले देशों (Deficit countries) में उसका संचुचन होता है जिनका देश के मूल्य-स्तर तथा अन्य प्रकार के भुगतानों पर प्रभाव पड़ता रहता है। कौलबोर्न (Coulborn) ने भी मुद्रा कोप योजना को स्वर्णमान का एक रूप माना है। उनके अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप स्वर्ण निधिमान के विनिमय समानीकरण कपो का विलयन करके बनाई हुई एक सत्त्वा है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रख दिया गया है।'^{१३} उन्होंने मुद्रा कोप योजना को अर्ध-स्वर्णमान का ही खेल बतलाया है जिसे अब पचास देश खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं जबकि पहले केवल छ प्रमुख खिलाड़ी होते थे।^{१४}

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप योजना तथा स्वर्णमान में इन समानताओं के होते हुये भी मुद्रा कोप की योजना को स्वर्णमान नहीं कहा जा सकता है। स्वर्णमान में मुद्रा का विदेशी मूल्य मोने के साथ स्थायी रूप से बंधा होता था और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं था किन्तु मुद्रा कोप की योजना में विनिमय दरें इतनी दृढ़ (Rigid) नहीं होती हैं। प्रो० हॉम के अनुसार 'कोप स्वर्णमान की विनिमय की दृढ़ता के स्थान पर सदस्य देशों की विनिमय दरों में

5 "John H. Williams, on the other hand, considered the new currency proposals (White Plan and Keynes Plan) from the very beginning as "essentially gold standard plans"

—Quoted by Halm in *Economics of Money & Banking* on P. 505.

6 "The I. M. F. is essentially an amalgamation of the Exchange Equalisation Accounts of gold reserve standard days put under international control."

—Coulborn. *A Discussion of Money*, P. 299.

7 "There are now fifty countries trying to play the semi Gold Standard game, whereas there used to be six principal players and a few lesser ones. Yet it is the same game, and chief players are the same, as the voting strength shows."

—Coulborn *A Discussion of Money*, P. 299.

प्रबन्धित लोच के सिद्धान्त को स्थापित करता है।^८ इस योजना में विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दरें निश्चित करने के लिए उनके स्वर्ण मूल्यों का प्रयोग अवश्य किया जाता है किन्तु सोने के साथ मुद्राओं का सम्बन्ध स्थिर नहीं होता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करना सम्भव होता है। मुद्रा कोष की व्यवस्था में कोई भी सदस्य देश अपने बोधनाशेष (Balance of Payment) के आधारभूत असन्तुलन को ठीक करने के लिए अपनी मुद्रा के स्वर्ण मूल्य को बदल सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना की यह लोच उसे स्वर्णमान से विलकुल भिन्न कर देनी है। इसके प्रतिरिक्त स्वर्णमान की भाँति मुद्रा कोष की योजना में विदेशी विनिमय का अधिक्य अथवा घाटा होने पर साख या विस्तार तथा संकुचन स्वयं (automatic) नहीं होता है। मुद्रा कोष के अन्तर्गत प्रत्येक देश स्वतन्त्र आर्थिक नीति का पालन कर सकता है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से मुद्रा प्रसार अथवा संकुचन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन सब भिन्नताओं के कारण मुद्रा कोष की योजना और स्वर्णमान में बहुत अन्तर है। जे० एम० के०जे (J M Keynes) का यह कहना ठीक है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रस्ताव स्वर्णमान के ठीक विपरीत है।'^९ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष योजना में स्वर्णमान न स्थापित होते हुये भी सदस्य देशों को स्वर्णमान के कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हो जाते हैं।

मुद्रा कोष की सफलतायें (Achievements of the I. M. F.)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह अपने आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों की विनिमय दरों का इस प्रकार प्रबन्ध करना रहा है कि उनमें स्थिरता तथा लोच के गुणों को उत्पन्न किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने में काफी सफल रहा है। मुद्रा कोष की स्थापना के पश्चात् विनिमय दरें प्रायः स्थिर रही हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन बहुत कम हो गये हैं। विनिमय दरों में स्थिरता के साथ लोच का गुण भी रहा है और मुद्रा कोष ने सदस्य देशों की विनिमय दरों को आवश्यकता पड़ने पर बदलने की पर्याप्त सुविधायें दी हैं। फ्रांस प्रथम दश था जिसने अपनी विनिमय दर में परिवर्तन किया। सितम्बर सन् १९४६ में इंग्लैंड तथा कुछ अन्य देशों के द्वारा अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया। इन आवश्यक परिवर्तनों के प्रतिरिक्त विनिमय दरें प्रायः स्थिर रही हैं। यह मुद्रा कोष की एक महत्वपूर्ण सफलता है।

8 "The Fund substitutes for the gold standard's rigidity the principle of managed flexibility in the adjustment of exchange values of the member currencies"
—Halm: Economics of Money & Banking, P. 504

9 Lord Keynes is basically right when he calls the Fund proposal "the exact opposite of the gold standard."

—J. M. Keynes: Speech delivered before the House of Lords, May 23, 1944.

इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का विचार है कि विदेशी विनिमय की स्थिरता पूर्णतया मुद्रा कोष के प्रयत्नों के कारण स्थापित नहीं हुई है बल्कि इस स्थिरता को बहुत कुछ विनिमय नियन्त्रण (Exchange control) के द्वारा बनाये रखा जा सका है और इसमें सन्देह है कि स्वतन्त्र दशावधि में कोष इस स्थिरता को बनाये रख सकेगा अथवा नहीं। विदेशी विनिमय की स्थिरता के अतिरिक्त मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को स्थापित करने में भी सफल रहा है और उसके द्वारा विभिन्न देशों में आपसी सम्पर्क स्थापित किया जा सका है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों को सदस्य देशों के द्वारा परामर्श एवं सहयोग से सुलभाना सम्भव हो सका है। किन्तु फिर भी मुद्रा कोष की सफलताएँ सीमित रही हैं और उसके बहुत से उद्देश्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है। कोष विभिन्न मुद्राओं की बहु-मुखी परिवर्तनशीलता (Multilateral convertibility) को स्थापित करने में नितांत असफल रहा है और अभी भी अधिकांश मुक्तानों का आधार द्विमुखी (Bilateral) है। मुद्रा कोष विदेशी व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह को प्रोत्साहित करने में भी सफल नहीं हो सका है। विदेशी विनिमय नियन्त्रण (Exchange control) का प्रयोग कम नहीं किया जा सका है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों का प्रयोग अभी भी किया जाता है। मुद्रा कोष की सफलता के विषय में क्रोथर (Crowthier) का विचार है कि 'यह कोष छोटे तथा अल्पकालीन असन्तुलनों को तो ठीक कर सकता है किन्तु किसी बड़े असन्तुलन की अवस्था में या तो उसे निष्क्रिय रहना पड़ेगा अथवा वह स्वयं समाप्त हो जायेगा।'^{१०}

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पक्ष में निम्न-लिखित बातें कही जा सकती हैं—

(१) मुद्रा कोष ने वास्तव नीतियों को प्रयत्न विना अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया है। विनिमय दरों में प्रतिमोहितात्मक कमी करने की नीतियों का प्रयोग मुद्रा कोष की स्थापना के पश्चात् नहीं किया गया है और वह इस प्रकार की नीतियों के बिना ही अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन स्थापित करने में काफी सीमा तक सफल रहा है।

(२) विनिमय नियन्त्रण यद्यपि अभी पाया जाता है किन्तु उसे कम करने का प्रयत्न मुद्रा कोष के द्वारा अवश्य किया गया है। विनिमय नियन्त्रण को निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाता है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसका प्रयोग करने दिया जाता है।

10 "It is clear that the Fund will be of assistance only in relation to small and short disturbances of equilibrium In a major disturbance, the fund will either have to stand aside impotently or it will be swamped."

(३) मुद्रा कोष ने पूर्ण रोजगार तथा विकास को विनिमय स्थिरता की प्रपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए विनिमय दरों को दृढ़ नहीं रखा जाता है और उनमें आवश्यक परिवर्तन करने की मुविधायें मुद्रा कोष के द्वारा दी जाती हैं। विनिमय दरों में इस प्रकार की लोच उत्पन्न हो जाने से विभिन्न देशों में पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखना तथा आर्थिक प्रगति की दर को तेज करना सम्भव हो सका है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आलोचनाएँ (Criticism of I. M. F.)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था है किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली में कुछ दोष रहे हैं। मुद्रा कोष की व्यवस्था की आलोचना निम्न आधार पर की गई है—

(१) सदस्य देशों के अर्थव्यवस्थाओं का आधार वैज्ञानिक नहीं है—मुद्रा कोष में विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये हैं। अर्थव्यवस्था की प्रकार से निश्चित न होने के कारण मुद्रा कोष का नियन्त्रण केवल कुछ एक प्रभावशाली राष्ट्रों के हाथ में आ गया है। कुछ बड़े-बड़े देशों के अर्थव्यवस्था बहुत कम निश्चित किये गये हैं जबकि कुछ छोटे तथा प्रभावशाली देशों के अर्थव्यवस्था बहुत अधिक हैं। अर्थव्यवस्था निश्चित करते समय सदस्य देश की स्वर्ण तथा डॉलर निधि की विशेष महत्व दिया गया है जो उनकी विदेशी विनिमय की आवश्यकता का सही आधार प्रस्तुत नहीं करता है। वास्तव में अर्थव्यवस्था निश्चित करने का आधार या तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा या व्यापारांशों की स्थिति एवं विदेशी विनिमय की आवश्यकता होनी चाहिए किन्तु इनमें से किसी भी आधार को स्वीकार नहीं किया गया है।

(२) मुद्रा कोष के द्वारा दी जाने वाली सहायता अपर्याप्त रही है—सदस्य देशों की मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता उनके शोधनांशों (Balance of Payments) के वास्तविक घाटे की तुलना में बहुत कम रही है। विशेषतया अल्प-विकसित देशों की मुद्रा कोष से पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकी है। इन देशों में आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आपात की जा रही है जिसके कारण इनके शोधनांशों में निरन्तर घाटे की स्थिति बनी रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन देशों की सीमित मात्रा में ही सहायता कर सका है।

(३) कोष डॉलर समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा है—डॉलर की कमी की समस्या वास्तविक तथा महत्वपूर्ण है और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर सबट अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के टूट जाने का कारण बन सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना इस समस्या को सुलझाने में प्रभावशाली नहीं

हो सकती है। समार में डॉलर की इतनी अधिक कमी होने पर भी मुद्रा कोष डॉलर को दुर्लभ मुद्रा घोषित नहीं कर सका है।

(४) कार्यकारिणी की सदस्यता ग्याप्तपूर्ण नहीं है—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्यकारिणी (Board of Executive Directors) की सदस्यता इस प्रकार रखी गई है कि उसमें अमेरिकन हितों की रक्षा की जा सके। इसके लिए सैंटिंग अमेरिका के लिए दो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। अग्रेजों का उचित निर्धारण न होने तथा कार्यकारिणी में अमेरिका के हितों की विशेष सुरक्षा के दो ऐसे कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप उस ने मुद्रा कोष की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है।

(५) भेदभावपूर्ण नीति—रुग्णों को प्रदान करने तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ देने में मुद्रा कोष ने भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया है। इसका स्पष्ट उदाहरण कुछ देशों के साथ किया जाने वाला पक्षपात है। सन् १९४८ में फ्रांस ने कोष की आज्ञा के बिना फ्रैंक का प्रचलन किया किन्तु मुद्रा कोष ने उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोष अमेरिका के पक्ष के देशों के साथ शिथिल व्यवहार करता है।

(६) मुद्राकोष अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सफल नहीं रहा है—जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा कोष की स्थापना की गई है उनमें से केवल कुछ उद्देश्यों की ही वह वास्तविक रूप से प्राप्त कर सका है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने तथा विनिमय नियन्त्रण के प्रयोग की कम करने में मुद्रा कोष विशेष रूप से असफल रहा है। चैंडलर (L. V. Chandler) के अनुसार 'कोष सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के समता मूल्यों (Par values) को बनाये रखने तथा उनकी वास्तविक विनिमय दर को इन मूल्यों से १% के भीतर रखने में सफल नहीं हो सका है।' मुद्रा कोष को कार्य करते हुए लगभग २० वर्ष होने की आये हैं किन्तु अभी तक भी विनिमय नियन्त्रण (Exchange control) के प्रयोग में कोई कमी नहीं हुई है और उसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। बहुमुखी भुगतान के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में भी मुद्रा कोष की कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इस क्षेत्र में अपनी असफलता को मुद्रा कोष ने अप्रैल १९५४ में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है—“यह हेतुपूर्ण तथ्य है कि युद्ध समाप्ति के सात वर्ष पश्चात् भी बहुपक्षीय व्यापार तथा

11 “The Fund has not succeeded in getting all its members to maintain par values for their currencies and to maintain their actual exchange rates within 1% of those levels. In 1958 a total of 17 members had no par values; these included such important countries as Canada, France and Italy. Moreover several members have altered their exchange rates after only nominal consultation with the Fund”

—L. V. Chandler : The Economics of Money and Banking, P. 524.

परिदुर्लभता की दिशा में थोड़ी-सी तथा निरन्तर प्रगति हो सकी है।¹² इस विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा कोष से जो आशायें लगाई गई थी उन्हें वह अधिक सीमा तक पूरा नहीं कर सका है।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(India and the International Monetary Fund)

भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना चाहिए प्रयत्न नहीं, हम सम्बन्ध में कुछ समय तक वाद-विवाद चलता रहा किन्तु अन्त में भारत ने मुद्रा कोष का सदस्य होना स्वीकार कर लिया और दिसम्बर सन् १९४५ में हमारे देश ने मुद्रा कोष में अपनी ४०० मिलियन डॉलर का अम्पश (Quota) जमा कर दिया। इस समय भारत कोष का चौथा स्थायी सदस्य है और उसे कोष में संचालक मण्डल पर एक नामकी संचालक (Executive Director) नियुक्त करने का अधिकार है। कोष का सदस्य होने समय भारत ने अपने रुपये का स्वर्ण समता मूल्य (Gold Parity) ३३०.८५२ रुपये = १०० डॉलर निश्चित कर दिया और उसकी सूचना मुद्रा कोष को दे दी गई। इस समता दर के अनुसार एक भारतीय रुपया ०.२६८६१ ग्राम स्वर्ण अथवा ३१.२५ सेन्ट के बराबर हो गया। रुपये की यह स्वर्ण समता दर १ रुपया = १ गिलिंग ६ पैन की विनिमय दर पर आधारित थी। अवमूल्यन के पश्चात् रुपये का मूल्य घट कर ०.१८६६२१ ग्राम अथवा २१ सेन्ट के बराबर रह गया। मुद्रा कोष का सदस्य हो जाने पर भारतीय रुपये का स्टैबिलिटी के साथ सम्बन्ध टूट गया और भारतवर्ष में स्वर्ण समता मान स्थापित कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक का भारतीय रुपये के मूल्य को १ सि० ६ पैन पर बनाये रखने का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया और भारतीय रुपया एक स्वतन्त्र मुद्रा हो गई। १९४६ में जब पौड का अवमूल्यन किया गया तो भारतवर्ष के लिए अपने रुपये का अवमूल्यन करना अनिवार्य नहीं था और रुपये का अवमूल्यन इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा करना भारत के अधिक हित में था।

मुद्रा कोष में प्राप्त सहायता—

आरम्भ में भारतवर्ष का अम्पश ४०० मिलियन डॉलर निश्चित किया गया था जिसके आधार पर वह ५०० मिलियन डॉलर का विदेशी विनिमय शोधनाशेष के अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा कोष से उधार ले सकता था। सन् १९५६ में सदस्य देशों के अम्पशों में ५०% की वृद्धि हो जाने के कारण भारतवर्ष का अम्पश भी बढ़कर ६०० मिलियन डॉलर हो गया है। इसमें २५% की वृद्धि और की गई है जिसके परिणामस्वरूप भारत का अम्पश ७५० मिलियन डॉलर हो गया

12 "It is melancholy fact that seven years after the end of the war there has been little secure or sustained progress towards multilateral trade and convertibility."

है। भारत ने मुद्रा कोष की सदस्यता से पूरा-पूरा लाभ उठाया है और सन् १९४८ में २८ करोड़ डॉलर; १९४९ में ७२ करोड़ डॉलर; १९५७ में २० करोड़ डॉलर और १९६२ में २५ करोड़ डॉलर का ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया। सन् १९६१-६२ के अन्त तक कुल मिलाकर ५५ करोड़ डॉलर का विदेशी विनिमय भारत ने मुद्रा कोष से लिया। इसमें मुख्यतया डॉलर और स्टर्लिंग लिया गया है। अभी हान में मुद्रा कोष ने भारत को २० करोड़ डॉलर का विशेष ऋण दिया है जिसका प्राधा भाग कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और आस्ट्रेलिया को मुद्राओं में प्राप्त किया जा सकता है। इस ऋण के मिलने से भारत की वर्तमान विदेशी विनिमय की कठिनाई को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। भारतवर्ष अपने ऋणों का भुगतान ठीक समय पर करता रहा है और १९६२ में उसने मुद्रा कोष से १२ ७५ करोड़ रुपये की अपनी मुद्रा को पुनः खरीदा।

मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को लाभ (Advantages from I. M. F. Membership).—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से भारतवर्ष को बहुत अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा कोष की सदस्यता से प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्न-लिखित हैं—

(१) रुपये के विदेशी मूल्य में स्थिरता—मुद्रा कोष की सदस्यता के कारण भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को स्थिर रखा जा सका है। सन् १९४९ के अवमूल्यन के अनिश्चित हमारे रुपये का विदेशी मूल्य प्रायः स्थिर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता के बिना भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में इस प्रकार की स्थिरता को बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकता था।

(२) शोधनाशेष (Balance of Payment) के घाटे को पूरा करने में सहायता—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विदेशी मुद्राओं का ऋण देकर हमारे शोधनाशेष के घाटे को पूरा करने में बड़ी सहायता दी है। योजना काल में भारत का शोधनाशेष निरन्तर घाटे में रहा है। यह घाटा मुख्यतया अमेरिका के साथ बहुत अधिक रहा है। मुद्रा कोष ने समय-समय पर डॉलर ऋण देकर इस घाटे को पूरा करने में बड़ी सहायता की है।

(३) आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने में सहायता—मुद्रा कोष की सदस्यता के फलस्वरूप भारत में कई विशेषज्ञ मण्डल आयें हैं जिन्होंने देश की आर्थिक दशाओं तथा हमारी विकास योजनाओं की जाँच की है और इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। विशेषतया मुद्रा कोष ने पंचवर्षीय योजनाओं के अर्थ-प्रबन्ध पर भारतीय सरकार को सलाह दी है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सदस्यता—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण ही भारतवर्ष विश्व बैंक का सदस्य भी हो सका है। विश्व बैंक ने

हमारी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में वित्तीय सहायता दी है और इस प्रकार मुद्रा कोष की सदस्यता आर्थिक विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।

(५) भारत में नये मुद्रामान का आरम्भ—मुद्रा कोष की सदस्यता के साथ ही भारतवर्ष में एक नये मुद्रामान का आरम्भ हुआ है। स्टर्लिंग विनिमय मान का स्थान स्वर्ण समता मान ने ले लिया है। भारतीय रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध समाप्त हो गया है और वह एक स्वतन्त्र मुद्रा हो गई है।

परीक्षा-प्रश्न

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन मुख्य उद्देश्यों से की गई थी ? इस कोष से भारत को क्या लाभ हुआ है ? (भागरा बी० ए० १९६४)
२. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ? यह किस प्रकार कार्य करता है ? इस कोष से भारत को क्या लाभ हुआ है ? समझाइये। (भागरा बी० ए० १९५६)
३. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य-प्रणाली की विवेचना करिये और यह समझाइये कि वह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुआ है ? (राजस्थान बी० ए० १९५८)
४. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विनिमय दरों को स्थिर रखने में क्या सहायता करता है ? (भागरा बी० ए० १९५६ स)
५. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये और इसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से कीजिए। (सागर बी० काम १९५५)
६. उन परिस्थितियों को समझाइये जिनके कारण मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। इस कोष का सदस्य बनने से भारत को हुए लाभ-हानियों का विवेचन करिये। (गोरखपुर बी० काम० १९५६)
७. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या उद्देश्य हैं ? यह अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से किस प्रकार भिन्न है ? (बिहार बी० ए० १९५८)
८. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों का विवेचन करिये। वह विदेशी विनिमय दरों में किस प्रकार स्थायित्व रखता है ? (राजस्थान बी० काम० १९५४)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT)

— ब्रेटन वुड्स सन्धीने (Bretton Woods Agreement) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यमसे पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने का निश्चय भी किया गया। इस बैंक की स्थापना युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग की समस्याओं को सुलझाने के लिए की गई है। जबकि मुद्रा कोष का उद्देश्य सदस्य देशों के शोचनाशेष के समन्तुलन को दूर करने में सहायता करना है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का उद्देश्य विभिन्न देशों में दीर्घकालीन विनियोगों को प्रोत्साहन देना है जिससे कि युद्ध-व्यसित देशों का पुनर्निर्माण किया जा सके तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में सहायता दी जा सके। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन पूँजी की व्यवस्था करना है। वह दीर्घकालीन विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित एवं विस्तृत करने के लिए कार्य करता है।¹ यह कार्य मुद्रा कोष के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि वह दीर्घकालीन ऋण देना आरम्भ कर देता है तो उसकी तरलता समाप्त हो जायगी। सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋणों की इतनी अधिक आवश्यकता है कि यदि इस प्रकार के ऋण देने के लिए एक प्रयत्न सस्था स्थापित न की जाती तो वे मुद्रा कोष की सुविधाओं का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए करने का प्रयत्न करते। इसमें प्रतिरिक्त यह भी भी सोचा गया कि केवल व्यक्तिगत ऋणों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष मस्यौदे के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक अपने साधनों में से प्रत्यक्ष विनियोग करके अथवा

1 "The International Bank for Reconstruction and Development has the purpose of facilitating and promoting long term foreign investment."

सदस्य देशों के द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारन्टी देकर इस कार्य को करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य (Purposes of the Bank)—

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(१) विश्व बैंक का सर्वप्रथम उद्देश्य युद्ध-ध्वंसित अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण (Reconstruction) में सहायता करना तथा अल्प-विकसित (Under-developed) देशों की अपने प्राकृतिक साधनों के अधिकतम शोषण और विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

(२) मसार के विभिन्न देशों में पूँजी के विनियोग के लिए सुविधायें प्रदान करना, व्यक्तिगत ऋणों की गारन्टी (Guarantee) देकर अथवा उनमें सम्मिलित होकर पिछड़े हुए देशों में उरगदरु कार्यों के लिए विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना और यदि व्यक्तिगत ऋण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो उत्पादन कार्यों के लिए समुचित दायों पर अपने पास में ऋण देना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन सन्तुलित विकास की व्यवस्था करना जिससे कि सदस्य देशों में उत्पत्ति, जीवन-स्तर तथा श्रमिकों की कार्य-दशाओं को उन्नत किया जा सकेगा।

(४) सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्थाओं को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित करने की सुविधायें देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को देखन से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय आय तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा करना है। दोनों ही संस्थाएँ सदस्य देशों को ऋण देती हैं, मुद्रा-कोष अल्प काल के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक दीर्घकाल के लिए। कोष शोधनाशेष के घाटे को ठीक करने के लिए ऋण देता है और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक विनियोग के लिए। मुद्रा कोष विभिन्न देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को दूर करता है और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक दीर्घकाल में सन्तुलित विदेशी व्यापार स्थापित करने का प्रयत्न करता है। पक्षिण दोनों संस्थाएँ लगभग एक ही प्रकार के उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही हैं किन्तु दोनों का कार्य क्षेत्र अलग-अलग है।

विश्व बैंक की पूँजी (Capital of World Bank)—

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूँजी १०,००० मिलियन डॉलर है जो १ लाख डॉलर वाले एक लाख हिस्सों में बँटी हुई है। इन एक लाख अंशों (Shares) में से ६१,००० अंश मूल सदस्यों द्वारा खरीदे गए और शेष ३९,००० अन्य सदस्यों के लिए छोड़ दिए गए हैं। बैंक की पूँजी में सदस्यों के ३/४ मतधिक्य (Majority) से

वृद्धि की जा सकती है। सन् १९६४ में इस बैंक के सदस्यों की संख्या १०२ थी। बैंक की पूँजी में सदस्य देशों के धन्यता (Quotas) निश्चित किये हैं और इनके अनुसार ही विभिन्न राष्ट्रों ने बैंक के अंश खरीदे हैं। कुछ सदस्य देशों के धन्यता मिलियन डॉलर्स में इस प्रकार हैं—अमेरिका २४३५, इङ्ग्लैंड १०००, चीन ६००, भारत ४००, फ्रांस ४१० इत्यादि। बैंक की पूँजी का केवल ६ भाग ही एकत्रित किया गया है जिसमें से बैंक सदस्य राष्ट्रों को स्वयं ऋण दे सकता है तथा पूँजी के ५ भाग को, जो अनएकत्रित (Uncalled) है बैंक के द्वारा ऋणों की गारन्टी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सदस्य देशों को अपने अंशों का २०% भुगतान करना होता है तथा शेष ८०% बैंक के द्वारा माग करने पर देना पड़ेगा। इस २०% भाग में से १८% सदस्य देश की मुद्रा में तथा २% सोने में अथवा अमेरिकन डॉलर में देना होता है। बैंक के सदस्यों का दायित्व सीमित रखा गया है। जिन देशों ने ३१ दिसम्बर सन् १९४५ तक बैंक की सदस्यता स्वीकार कर ली थी वे बैंक के मूल सदस्य (Original Members) हैं। केवल वे ही राष्ट्र बैंक के सदस्य बन सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हों। सन् १९५६-६० में बैंक की अधिवृत्त पूँजी को बढ़ाकर २१,००० मिलियन डॉलर्स कर दिया है और उसी अनुपात में सदस्य देशों के धन्यता में भी वृद्धि कर दी गई है।

ऋण देने के लिए बैंक के साधनों के तीन थोठे हैं—बैंक की चुकता पूँजी (Paid up Capital) जो सदस्य देशों के धन्यता का २०% है, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी-बाजारों में बैंक के द्वारा लिए जाने वाले ऋण तथा बैंक की अपनी शुद्ध धन्यता। इन तीनों में से बैंक के ऋण उमका सबसे बड़ा साधन है। बैंक अपने ऋण-पत्रों (Bonds) को बेचकर विभिन्न देशों में ऋण प्राप्त करता है। इसके लिए उसे उस सदस्य देश से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है जहाँ वह अपने ऋण-पत्र बेचना चाहता है। बैंक ने मुख्यतया समुक्त राज्य अमेरिका तथा स्वीटजरलैंड में अपने ऋण-पत्र बेचकर साधन प्राप्त किये हैं।

बैंक की कार्य-विधि (Functioning of the Bank)—

विश्व बैंक ने द्वारा दी जाने वाली सहायता मुख्यतया तीन प्रकार की होती है—

(अ) व्यक्तिगत ऋणों की गारन्टी करना; (ब) अपनी पूँजी में से प्रत्यक्ष ऋण देना तथा (स) उधार ली गई पूँजी में से ऋण देना।

(अ) गारन्टी ऋण—निश्चित बैंक, व्यक्तिगत ऋणों की गारन्टी देकर विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहित करता है। बैंक किसी भी ऋण की गारन्टी तब ही कर सकता है जबकि उस देश की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो जिसके मुद्रा बाजार में वह ऋण लिया जाना है अथवा जिस देश की मुद्रा में वह ऋण दिया जा रहा है। ऋणों की गारन्टी करने से पहले बैंक यह देखता है कि ऋण लेने वाले देश की

आवश्यकता कहीं तक वास्तविक है और ऋण देने वाले की शर्तें कहीं तक उचित है। बैंक स्वयं ऋण देने की अपेक्षा गारन्टी करके व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहित करता है। बैंक अपने पास से ऋण तब ही देता है जबकि किसी देश को उचित शर्तों पर व्यक्तिगत ऋण प्राप्त न हो रहे हो। व्यक्तिगत ऋणों की गारन्टी देने के लिए बैंक सदस्य देशों से कमीशन लेता है जिसकी दर पहले १० वर्षों के लिए १% से लेकर १२% तक होती है।

(ब) अपनी पूँजी में से प्रत्यक्ष ऋण देना—बैंक सदस्य देशों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पूँजी में से भी ऋण दे सकता है। यदि बैंक यह देखता है कि किसी देश को उचित शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत ऋण प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो बैंक उसे अपने पास से ऋण दे सकता है। इस कार्य के लिए बैंक अपनी वेबो हुई पूँजी के २०% भाग का प्रयोग कर सकता है। बैंक के द्वारा अपने पास से दिये गए ऋणों की मात्रा सीमित हो रहती है क्योंकि यह इस प्रकार के ऋणों को प्रोत्साहित नहीं करता है। बैंक का उद्देश्य स्वयं ऋण देना नहीं है बल्कि सदस्य राष्ट्रों को व्यक्तिगत ऋण दिलाना है।

(स) उधार ली गई पूँजी में से ऋण देना—बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए अन्य राष्ट्रों में ऋण भी ले सकता है। इस प्रकार के ऋण देने से पूर्व बैंक को उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसके मुद्रा बाजार से वह ऋण लिया जाना है। यदि ऋण देने वाले देश की मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य देश की मुद्रा में ऋण लिया जाता है तो उस देश की स्वीकृति भी लेनी होती है जिस देश की मुद्रा में वह ऋण लिया जा रहा है।

उपर्युक्त तीनों विधियों से बैंक आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करता है। ऋणों को देने में बैंक सामान्य जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है किन्तु इस बात पर जोर देता है कि उसके द्वारा दिये गए ऋणों का प्रयोग केवल देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ही किया जाय। प्रत्येक ऋण को देने से पूर्व बैंक ऋण लेने वाले देश की आर्थिक स्थिति तथा जिस योजना के लिए ऋण लिया जा रहा है उसकी दृढ़ता के बारे में जाँच करता है। यह भी जाँच की जाती है कि ऋण लेने वाले देश में उस ऋण का भुगतान करने की क्षमता है अथवा नहीं। ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र की जाँच करने के लिए एक ऋण समिति (Loan Committee) नियुक्त की जाती है जिसमें बैंक के विशेषज्ञ होते हैं तथा एक प्रतिनिधि ऋण लेने वाले देश का होता है। यह समिति प्रार्थी देश की सामान्य आर्थिक स्थिति की जाँच करती है और जिस योजना के लिए ऋण लिया जा रहा है उसके उचित अथवा अनुचित होने का अन्तिम निर्णय करती है। इस समिति की सिफारिश पर ही प्रार्थी देश को ऋण दिया जाता है।

ऋण देने की विधि (Method of Granting Loans)—

बैंक के द्वारा किसी मदम्य देश को ऋण देने की विधि को चार अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है। सर्वप्रथम बैंक प्राथी देश की एक प्रारम्भिक जाँच करना है तथा उससे ऋण के सम्बन्ध में बातचीत करता है। इस अवस्था में बैंक के अधिकारी ऋण के लिए प्राथी देश की भुगतान क्षमता की जाँच करते हैं। प्रारम्भिक जाँच का उद्देश्य यह जानना होना है कि प्राथी देश कहां तक दिये जाने वाले ऋण का उचित प्रयोग करने की क्षमता रखता है तथा वह ऋण की वापसी और उस पर व्याज का भुगतान उस मुद्रा में कर सकेगा कि नहीं, जिस मुद्रा में ऋण दिया जा रहा है। यदि प्राथी देश ने बैंक से पहले ऋण लिया हुआ है और बैंक को उसकी भुगतान क्षमता तथा ऋण के उचित प्रयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी है तो ऐसी दशा में प्रारम्भिक जाँच देश के वर्तमान आर्थिक विकास तक ही सीमित रहती है। दूसरी अवस्था में बैंक का मिशन उस प्रोजेक्ट की जाँच करना है जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है। इस बात की जाँच की जाती है कि प्रोजेक्ट योजना ठीक प्रकार घनी है अथवा नहीं, क्या उसके लिए आवश्यक स्थानीय पूँजी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी, क्या प्रोजेक्ट का उचित प्रबन्ध एवं निरीक्षण किया जा सकेगा, इत्यादि। इन सब बातों से सन्तुष्ट होने के पश्चात् तीसरी अवस्था में ऋण सम्बन्धी शर्तों के बारे में बातचीत आरम्भ होती है। इसके अन्तर्गत कुल विनियोग का बैंक के द्वारा दिया जाने वाला भाग, व्याज की दर, ऋण का समय तथा जमानत आदि के सम्बन्ध में निश्चय किया जाता है। चौथी और अन्तिम अवस्था ऋण के प्रबन्ध की होती है जो बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की एक विशेषता है। बैंक के प्रतिनिधि ऋणी देश में जाते हैं और इस बात की जाँच करते हैं कि ऋण की रकम का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और वह कहां तक ऋण सम्बन्धी समझौते के अनुसार है। इसके अतिरिक्त बैंक उस प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से चाहता है और इस प्रकार प्रोजेक्ट पूरा होने तक अपने को उससे सम्बन्धित रखता है।

ऋण देने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक निम्नलिखित नीतिभों का अनुसरण करता है—

(१) बैंक को ऋण के भुगतान की सम्भावनाओं की ठीक प्रकार से जाँच करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बैंक को प्राथी देश के प्राकृतिक साधनों, वर्तमान उत्पादन क्षमता, साधनों का प्रयोग करने की क्षमता तथा ऋण सम्बन्धी पिछला विवरण आदि का पता लगाना चाहिए।

(२) बैंक को केवल विशिष्ट योजनाओं के लिए ही ऋण देना चाहिए। यह योजनाएँ आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से ठीक होनी चाहिएँ और ऊँची प्राथमिकता वाली होनी चाहिएँ। बैंक अपने साधनों को विशेष रूप से ऐसी योजनाओं पर

केन्द्रित करना है जो देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने वाली हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह-निर्माण आदि सामाजिक योजनाओं के लिए वित्त प्रदान नहीं करता है। बैंक के अधिकांश ऋण शक्ति तथा यातायात के विकास के लिए दिये गए हैं जो आर्थिक विकास का आधार हैं।

(३) बैंक किसी प्रोजेक्ट की लागत के विदेशी विनिमय भाग को पूरा करने के लिए ही ऋण देता है और वह सामान्यता यह आशा करता है कि ऋणी देश स्थानीय साधनों को स्वयं अर्जित करेगा।

(४) बैंक ऋणी देश से यह आशा नहीं करता है कि वह ऋण की रकम को किसी विदेशी देश में ही न्यय करे। वास्तव में वह इस बात को चाहता है कि ऋण की रकम से मशीनें आदि सस्ते से सस्ते बाजार में खरीदी जाएं किन्तु वे अच्छे प्रकार की होनी चाहिएं।

(५) बैंक अपने सम्बन्ध में ऋणी देश के साथ बराबर बनाए रखता है जिससे कि वह प्रोजेक्ट की प्रगति की जांच कर सके और देश की वित्तीय स्थिति तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त कर सके।

(६) बैंक परोक्ष रूप से स्थानीय व्यक्तिगत उद्योग को प्रोत्साहित करने को विशेष महत्व देता है।

उपर्युक्त ऋण नीतियों का उद्देश्य बैंक के द्वारा ऋण देने में गलतियों की सम्भावना को कम करना है। बैंक ने सर्वप्रथम ऋण योरुप के उन देशों को दिये जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ द्वितीय युद्ध के कारण बर्बाद हो गई थी। ये ऋण मुख्यतः पुनर्निर्माण के आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए दिये गए। बैंक ने इस उद्देश्य के लिए कुल मिलाकर ५०० मिलियन डॉलर का ऋण दिया। सन् १९४८ में विश्व बैंक ने विकास के लिए ऋण देने आरम्भ किए और उसके साधनों का अधिकाधिक भाग अल्प-विकसित देशों में लगने लगा। दिसम्बर सन् १९६१ तक बैंक ने ५० से अधिक देशों को ३०० से भी अधिक ऋण दिए जिनकी रकम ६,००० मिलियन डॉलर से अधिक थी। बैंक के द्वारा विकास के लिए दिये जाने वाले ऋणों का लगभग एक तिहाई भाग विद्युत शक्ति के विकास के लिए तथा दूसरा तिहाई भाग यातायात एवं सन्देशवाहन के मुधार के लिए दिया गया। शेष एक तिहाई भाग उद्योग, कृषि तथा सिंचाई आदि के विकास के लिए दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा दिये गए ऋण—दिसम्बर १९६१ तक

(Loans granted by International Bank—upto Dec 1961)

मिलियन डॉलर्स

(१) पुनर्निर्माण के लिए ऋण ४६७

(२) आर्थिक विकास के लिए ऋण ५,१७२

(i) यातायात एवं सन्देशवाहन १,८४७

(ii) विद्युत शक्ति	१,७४१
(iii) उद्योग	८८३
(iv) कृषि एवं जंगल	४६६
(v) सामान्य विकास	२०५

तकनीकी सहायता (Technical Assistance)—

ऋणों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता भी देता है। इसके अन्तर्गत बैंक विकास क्षमताओं के सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकन, क्षेत्रीय जाँच तथा विशेष प्रोजेक्ट सम्बन्धी परामर्श आदि की सुविधाएँ देता है। बैंक ने अभी हाल में एक विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें अर्थशास्त्री, परामर्शदाता, प्रबन्धक आदि रक्ते जायेंगे जो सदस्य देशों की सरकारों को विभिन्न योजनाओं में उचित चुनाव करने में सहायता देंगे जिसमें कि केवल अधिक प्राथमिकता वाली योजनाओं को ही प्रारम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त बैंक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भी योगदान देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु नदी के पानी के बँटवारे की समस्या को सुलझाने तथा मित्र के द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिए दिये जाने वाले मुआवजे की रकम निर्दिष्ट करने में बैंक ने बड़ी सहायता दी है।

बैंक का प्रबन्ध तथा व्यवस्था

(Management of the World Bank)—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाँति ही विश्व बैंक के संचालन के लिए भी एक गवर्नर मण्डल (Board of Governors) तथा एक संचालक मण्डल (Board of Executive Directors) होता है। गवर्नर मण्डल बैंक की सामान्य नीति का निर्धारण करता है तथा बैंक का दैनिक संचालन कार्य संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। गवर्नर मण्डल में प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक पर्याक्रम गवर्नर (Alternate Governor) होते हैं जिनकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिए की जाती है। इस मण्डल की वर्ष में एक बार बैठक होनी आवश्यक है जिसमें बैंक की प्रगति रिपोर्ट पर विचार किया जाता है तथा उसकी सामान्य नीति सम्बन्धी प्रश्नों को निश्चित किया जाता है। बैंक के सच तक मण्डल (Board of Executive Directors) में १२ सदस्य होते हैं जिनमें से ५ स्थायी डाइरेक्टर्स पाँच बड़े-बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा शेष ७ डाइरेक्टर्स अन्य सदस्य देशों के द्वारा चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त बैंक की एक सलाहकार समिति (Advisory Council) भी होती है जिसमें कम से कम ७ सदस्य होते हैं। यह समिति संचालक-मण्डल द्वारा निर्वाचित की जाती है और इसके सदस्य, बैंकिंग, वाणिज्य, उद्योग, कृषि तथा श्रम आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और

इनका निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है। यह समिति बैंक को उसकी सामान्य नीति के सम्बन्ध में सलाह देती है। बैंक की एक ऋण समिति (Loan Committee) भी होती है जो ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की जाँच करती है। इस समिति की सिफारिश पर ही बैंक के द्वारा ऋण दिये जाते हैं।

बैंक की सफलताएँ (Achievements of the World Bank)—

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना के समय उससे बड़ी आशाएँ लगाई थीं। उस समय बैंक की उपयोगिता तथा महत्त्व को बतलाते हुए लॉर्ड केन्ज (Lord Keynes) ने कहा था कि 'इस महान योजना से ससार को मिलने वाले लाभों को मुश्किल से ही बढ़ाकर कहा जा सकता है। स्वतन्त्र किये गए क्षेत्रों में इसके द्वारा निर्माण के लिए साधन उपलब्ध हो सकेंगे। प्रत्येक देश में उत्पादकों के सामान के लिए श्रम-शक्ति उपलब्ध होगी। यह सस्था ऋणी तथा ऋणदाता देशों के बीच भुगतान में सतुलन बनाये रखने के लिए एक शक्तिशाली ऋण हो सकेगी। वर्तमान काल में रोजगार की व्यवस्था करने तथा भविष्य में रपति बढ़ाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इतना महान् प्रस्ताव कभी नहीं रखा था है।' कूरीहारा (Kurihara) के अनुसार 'विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार को स्थायी रखने की दिशा में एक आशावादी पक्ष है।'^२ इन शब्दों से विश्व बैंक योजना की महानता तथा महत्त्व का पता चलता है।

बैंक की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि वह आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण के लिए काफी उपयोगी सस्था रही है। युद्ध-ध्वस्त देशों में पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में वह पर्याप्त सहायता दे चुका है। आरम्भ में बैंक ने योरोप के देशों के पुनर्निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया और मई से लेकर अगस्त सन् १९४७ तक पुनर्निर्माण के लिए चार बड़े-बड़े ऋण फ्रांस, डैनमार्क, नीदरलैण्ड तथा लक्जेंबर्ग को दिये गए जिनकी कुल राशि १६७ मिलियन डॉलर थी। सन् १९४८ से बैंक ने अल्प विकसित देशों के विकास की ओर ध्यान दिया और बहुत से देशों को आर्थिक विकास के लिए पूर्ण उपलब्ध करने में सहायता दी। सन् १९६१ से अन्त तक आर्थिक विकास के लिए दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा ५१७२ मिलियन डॉलर्स थी जिनमें से अधिकांश ऋण ब्रिजल, यानायत, सदेशवाहन, कृषि तथा वनों के विकास के लिए दिये गए। सन् १९६४ में विश्व बैंक के द्वारा दिये गए ऋणों का कुल योग ७२८ मिलियन डॉलर्स था।

अब बैंक ने अल्प-विकसित देशों को ऋण देने के लिए एक नया तरीका निकाला है। इन देशों के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कुछ ऐसी

■ "The International Bank is a hopeful step in the direction of international employment stabilisation"

संस्थाएँ स्थापित की गई हैं जिन्हें विश्व बैंक ऋण देता है और वे फिर छोटी-छोटी योजनाओं के लिए ऋण देती हैं। ऐसा करने में बैंक बहुत-सी छोटी-छोटी योजनाओं की छानबीन करने से बच गया है। डैनमार्क, मैक्सिको तथा तुर्की आदि देशों में इस प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की संस्था औद्योगिक माध्य तथा वित्त निगम (Industrial Credit & Finance Corporation of India) के नाम से स्थापित की गई है।

बैंक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूलन विकास के लिए भी कार्य करता है। इसके लिए बैंक किसी एक देश को अत्यधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की रोकता है तथा राजनैतिक उद्देश्यों से किये जाने वाले विदेशी विनियोगों को रोकने का प्रयत्न करता है। इसने अनिश्चित बैंक ने बहुमुखी आधार पर (Multilateral Basis) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने का प्रयत्न भी किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बैंक बंधे हुए ऋणों (Tied Loans) को मग्री देता है। बैंक के द्वारा दिये गए ऋणों को किसी भी देश में प्रयोग किया जा सकता है चाहे वह ऋण किसी भी देश से क्यों न लिया गया हो।

बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को ऊँचे स्तर पर बनाए रखने में सहायता देता है। अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए पूँजी की मांग बहुत अधिक है और अमेरिका जैसे देशों के वित्तीय माधन भी बहुत अधिक है। अतः अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में ऋण मिलने की सम्भावना हो सकती है और बैंक इस सम्बन्ध में काफी सहायता कर सकता है। बैंक की गारन्टी पर ऋण देने वाले देश अधिक मात्रा में ऋण दे सकते हैं क्योंकि बैंक के द्वारा दिये गए ऋणों की जोखिम सब सदस्य देशों के द्वारा उठाई जाती है। उपर्युक्त विस्तारण से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रहा है। कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार ब्रेटन वुड्स की दोनों संस्थाओं में से मुद्रा कोष की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अधिक सफल रहा है। डी. वॉक (De Kock) के अनुसार "बैंक ने अपने विनिर्दिष्ट क्षेत्र में काफी मात्रा में सफलता प्राप्त कर ली है और वह स्पष्टतया अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है।"³

बैंक की आलोचनाएँ (Criticisms of the World Bank)—

यद्यपि विश्व बैंक आर्थिक विकास के लिए एक अत्यन्त उपयोगी संस्था रही है किन्तु फिर भी उसकी कार्य-विधि में कुछ दोष पाये जाते हैं। बैंक की आलोचना मुख्यतया अप्रतिष्ठित आधार पर की गई है—

3 "The bank has achieved a great measure of success in its particular sphere and has demonstrably become an essential cog in the machinery of international payment."
—De Kock : Central Banking, P. 317

(१) अपर्याप्त पूँजी (Inadequate Capital)—देखने से तो बैंक की पूँजी बहुत मालूम होती है किन्तु वास्तव में विदेशी विनियोग की आवश्यकता की तुलना में वह बहुत कम है। अन्य-विकसित देशों के विकास के लिए ऋणों की मांग इतनी अधिक है कि बैंक उसे आने सीमित साधनों से पूरा नहीं कर सकता है। बैंक की यह आलोचना प्रारम्भिक वर्षों में तो कुछ ठीक थी किन्तु अब इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि (i) अब बैंक के साधनों में काफी वृद्धि हो गई है। बैंक की पूँजी को दुगुना कर दिया गया है और सदस्य देशों के सम्प्रदाय भी उसी अनुपात में बढ़ा दिये गए हैं। (ii) बैंक केवल विनिष्ट, धरम्य अवस्थित तथा उत्पादक योजनाओं के लिए ही ऋण देता है और वह भी विदेशी विनियोग की आवश्यकता तक ही सीमित होता है। (iii) बैंक का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत विनियोग को प्रोत्साहित करना है।

(२) बैंक ने अल्प विकसित देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है (Bank has not played a significant role in the development of under-developed countries)—ग्रामोचकों के अनुसार अधिक विकास के क्षेत्र में विश्व बैंक से जो आशाएँ लगाई गई थी उन्हें वह अधिकांश रूप से पूरा नहीं कर सका है। पहले पाँच वर्षों में बैंक ने केवल ८७६ मिलियन डॉलर्स के ऋण दिये जो अधिक विकास के लिए पूँजी की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम थे। इस आलोचना का भी अब कोई महत्व नहीं है। सन् १९४८ के पश्चात् बैंक के अधिकाधिक साधन अल्प विकसित देशों के विकास के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं और आर्थिक विकास के लिए दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा तेजी के साथ बढ़ी है। जून १९६१ के अन्त तक ५६७० मिलियन डॉलर्स के ऋण इस उद्देश्य के लिए दिये जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि बैंक अब आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में विश्व बैंक के महत्व को केवल उसके द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के आधार पर नहीं आँका जा सकता है। उसके द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता भी काफी महत्वपूर्ण है।

(३) भेदभावपूर्ण नीति (Discriminating Policy)—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि वह ऋण देने में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के लिए अधिक उदार रहा है। प्रारम्भ में बैंक के द्वारा जितने भी ऋण दिये गए वे सब यूरोप के देशों के लिए थे। यद्यपि अब बैंक ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अधिक मात्रा में ऋण देने प्रारम्भ कर दिये हैं किन्तु फिर भी स्वतः राष्ट्रों को दिये जाने वाले ऋणों का अनुपात अधिक है। बैंक की यह आलोचना भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रहा है और ससार के सभी भागों में ऋण देता रहा है। अप्रलिखित आँकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है—

विश्व बैंक के द्वारा दिये गए ऋण

१९६३ और १९६४

क्षेत्र	१९६४		१९६३	
	ऋणों की संख्या	रकम मिलियन डॉलर	ऋणों की संख्या	रकम मिलियन डॉलर
अफ्रीका	१०	१०७.३	२	११.०
एशिया और मध्यपूर्व	११	२१२	१०	२४०
ऑस्ट्रेलिया	१	३२.५	१	८०
यूरोप	३	१६३.५	१०	२०१.०
पश्चिमी गोलार्ध	६	१०३.३	१५	३०४.०
योग	३१	७२७.८	३८	७८८.०

उपयुक्त आँकड़ों को देखने में पता चलता है कि बैंक सभी देशों में ऋण देता रहा है। विश्व बैंक से ऋण लेने वाले देशों की संख्या ५८ से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त निम्न १० वर्षों में समार के अल्प-विकसित देशों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और बैंक के कुछ ऋणों का काफी बड़ा भाग एशिया तथा मध्यपूर्व के देशों को मिल रहा है। यूरोपीय देशों को दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा निरन्तर गिर रही है। अतः विश्व बैंक के ऊपर यह धारणा लगाना कि वह ग़रीब देशों की ओर अधिक उदार रहा है सर्वथा भ्रमात्मक है।

(४) बैंक की ऋण देने की नीति अत्यन्त जटिल है (Bank's lending Policies are Complicated)—बहुत से आलोचकों का मत है कि विश्व बैंक की ऋण देने की नीति कुछ इस प्रकार की है कि अल्प-विकसित देशों को उममे वित्तीय सहायता देने में काफी कठिनाई होती है। अत्यन्त आवश्यक तथा उत्पादक योजनाओं के लिए ऋण देने की नीति में इन देशों के लिए अपनी योजनाओं की प्राथमिकता तथा उत्पादकता को प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। कभी-कभी सामान्य विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गृह-निर्माण आदि के लिए भी माघनों की प्राथमिकता होती है किन्तु बैंक इस प्रकार के ऋण नहीं दे सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत उद्योगों को ऋण देने के लिए बैंक सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की गारन्टी चाहता है जो इस प्रकार के ऋणों के रास्ते में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। बैंक इस बात पर भी जोर देता है कि उसने द्वारा दिये गए ऋणों का भुगतान उभी मुद्रा में होना चाहिए जिसमें बि ऋण दिया गया है। बहुत से अल्प-विकसित देशों के लिए दुर्लभ मुद्राओं में भुगतान करना काफी कठिन हो जाता है। यद्यपि बैंक के

ऊपर लगाये गए इन आगेपी में काफी मर्यादा है किन्तु फिर भी यह कहना होगा कि बैंक अपने नियमों की सीमाओं में रहते हुए जो कुछ भी अल्प-विकसित देशों के लिए कर सकता है, वह बराबर कर रहा है। वैसे इन देशों की कठिनाइयों के प्रति जागरूक है और इसीलिए उसने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद (International Development Association) आदि की स्थापना की है जिनके द्वारा वह अल्प विकसित देशों की आवश्यकताओं को अधिक सीमा तक पूरा कर सकेगा।

(५) बैंक की ब्याज की दर ऊँची है (Rate of Interest charged by the Bank is high)—विश्व बैंक की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि उसने द्वारा ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर ऊँची है। जिस दर पर पूँजी-बाजार से ऋण लिए जा सकते हैं उसकी तुलना में बैंक की ब्याज की दर बहुत कम नहीं है और हमने बैंक का कमोन्जन सम्मिलित हो जाने में बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण की लागत काफी अधिक हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि बैंक ने काफी मात्रा में कोष जमा कर लिया है जिसकी रकम जून १९६१ के अंत तक ६०० मिलियन डॉलर्स थी, और अब बैंक के लिए हानि की कोई विशेष सम्भावना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक को अपनी ब्याज की दर कम कर देनी चाहिए। यद्यपि बैंक ने द्वारा ब्याज की दर कम करने के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क दिये जा सकते हैं किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक की ब्याज की दर उन दर में सम्बन्धित है जिस पर वह स्वयं उधार ले सकता है। इसके प्रतिरिक्त अल्प-विकसित देशों को इससे कम ब्याज पर ऋण मिलने का कोई अन्य श्रोत भी नहीं है।

बैंक की कार्य-प्रणाली में चाहे कुछ भी दोष रहे हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पिछले १८ वर्षों में बैंक ने अल्प-विकसित देशों के विकास के लिए काफी कुछ किया है। मुद्रा कोष की सीमित सफलता की तुलना में यह कहना होगा कि विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सबसे अधिक सफल रहा है। इसकी सबसे बड़ी सफलता अल्प-विकसित देशों में व्यक्तिगत विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करने में रही है। वह योरोप और अमेरिका में अल्प-विकसित देशों में विकास के लिए विनियोग कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। बैंक की स्थापना के पश्चात् काफी मात्रा में विदेशी पूँजी अल्प-विकसित देशों में लगाई जा चुकी है। इसका श्रेय विश्व बैंक को ही जाता है क्योंकि उमने व्यक्तिगत विनियोग के लिए उचित सुविधायें देकर उसे पिछड़े हुए देशों के विकास के क्षेत्र में आकर्षित किया है। बैंक ने पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह बहुत से देशों में उपयोगी एवं उत्पादक योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता तथा टैक्निकल परामर्श देने में काफी सफल रहा है।

भारत और विश्व बैंक

(India and the World Bank)

भारत सन् १९४६ में विश्व बैंक का सदस्य बन गया था। उसे बैंक की मौलिक सदस्यता प्राप्त है। विश्व बैंक में भारत का अग्रभूत ८०० मिलियन डॉलर्स है और वह बैंक की कार्यकारणी का स्थायी सदस्य है। भारत ने विश्व बैंक की सदस्यता से पूरा-पूरा लाभ उठाया है और १९५२ से वह बैंक से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश हो गया है। मार्च सन् १९६४ के अन्त तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ४०३.५ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हो चुके हैं। आरम्भ से ही बैंक ने भारत के आर्थिक विकास में विशेष रूप से सहायता की है। विश्व बैंक से भारत को निम्नलिखित ऋण प्राप्त हो चुके हैं—

विश्व बैंक के द्वारा भारत को दिये गये ऋण

(३० जून १९६२ तक)

मद	ऋणों की संख्या	ऋणों की रकम (मिलियन डॉलर्स)
मातायात	१३	४४७.४
उद्योग	१०	२७१.२
शक्ति	५	८१.१
कृषि	१	७.२
बहुमुखी योजनाएँ	१	१०.५
योग	३०	८१७.४

प्राप्त हुये ऋणों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

यातायात के विकास के लिए—

भारत को विश्व बैंक से सर्वप्रथम ऋण रेलों के विकास के लिए प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व-युद्ध में अत्यधिक प्रयोग किये जाने के कारण भारतीय रेलों की दशा काफी खराब हो गई थी। रेलों के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए विश्व बैंक ने अगस्त १९४८ में ३.४ करोड़ डॉलर का ऋण भारत को दिया। यह ऋण १५ वर्षों की अवधि के लिए था और इस पर भारत को ३% व्याज तथा १% कमीशन देना होता है। इस ऋण की सहायता से भारत ने अमेरिका तथा कनाडा से ४०० इंजन, वायलर तथा अन्य सामान खरीदा है। ऋण का भुगतान १९५० से आरम्भ हो गया है। द्वितीय योजना काल में रेलों के विस्तार एवं विकास के लिए विश्व बैंक ने १९५६-६० में २६५ मिलियन डॉलर का एक और ऋण भारत को

दिया। तृतीय योजना काल में रेलों की ग्राह्य होने की शक्ति में वृद्धि करने, नई पटरियाँ बिछाने तथा रेल मार्गों का विद्युत्तिकरण करने के लिए ४०० मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसके लिए विश्व बैंक ५० मिलियन डॉलर का ऋण दे चुका है और शेष के मिलने की आशा है। रेलों के विकास के लिए विश्व बैंक के द्वारा कुल ३७६ मिलियन डॉलर्स के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं।

वायु यातायात का विकास करने के लिए मार्च सन् १९५७ में विश्व बैंक ने ५.६ मिलियन डॉलर का एक ऋण भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन निगम (Air India International Corporation) को दिया है जिससे ३ जेट यान, १० अनिरिक्त इन्जन तथा अन्य सामान खरीदा गया है।

कृषि विकास के लिए—

सितम्बर सन् १९४६ में १ करोड़ डॉलर का ऋण कृषि विकास तथा सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा दिया गया। यह ऋण ७ वर्ष की अवधि के लिए था और इस पर व्याज तथा कमोशन ३½% की दर से देना होता था। इस ऋण ने भारत में खेती वाली भूमि को तोड़ने के लिए ट्रैक्टर तथा अन्य प्रकार की मशीनें अमेरिका से खरीदी हैं। इस ऋण ने भारत को अधिक शक्ति उपजाओ आन्दोलन में बड़ी सहायता दी है। ऋण का भुगतान जून सन् १९५२ से आरम्भ हो गया था।

बहुमुखी योजनाओं के लिए—

भारत की नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी विश्व बैंक ने कई ऋण प्राप्त किये हैं। सन् १९५० में १.८५ करोड़ डॉलर का एक ऋण दामोदर घाटी योजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से मिला। यह ऋण २० वर्ष की अवधि के लिए है और इस पर ४% के हिसाब से व्याज देना होता है। इस ऋण का प्रयोग खोखारी बिजली घर के लिए अमेरिका से एक थर्मल प्लांट (Thermal Plant) खरीदने के लिए किया गया। सन् १९५३ में दामोदर घाटी योजना के लिए ही एक अन्य ऋण १.६५ करोड़ डॉलर का २५ वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से प्राप्त हुआ।

औद्योगिक विकास के लिए—

विश्व बैंक ने भारत में लौह-इस्पात उद्योग के विकास के लिए ६८.७ मिलियन डॉलर्स के तीन ऋण इन्डियन आयरन एन्ड स्टील वर्क को दिये। पहला ऋण जिसकी राशि २६.२ मिलियन डॉलर थी १९५२ में दिया गया। इस ऋण का प्रयोग वर्तमान की स्टील मिल का विकास करने के लिए किया गया। २० मिलियन डॉलर्स का दूसरा ऋण १९५६ में प्राप्त हुआ और २२ दिसम्बर १९६१ को इस कंपनी को १६.५ मिलियन डॉलर का तीसरा ऋण कोयले की खानों के विकास के लिए दिया गया।

शक्ति के विकास के लिए—

सन् १९५४ में विश्व बैंक ने १६.२ मिलियन डॉलर का ऋण टाटा कम्पनी को ट्राम्पे विजलीघर के विकास के लिए दिया। ६.८ मिलियन डॉलर का दूसरा ऋण इसी केन्द्र की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए दिया गया। २५ मिलियन डॉलर का एक और ऋण कोयना परियोजना (Koyna Project) के निर्माण के लिए भारत सरकार को दिया गया।

बन्दरगाहों के विकास के लिए—

सन् १९५८ में भारत को विश्व बैंक से ६४ मिलियन डॉलर के ऋण बन्दरगाहों के विकास के लिए दिये गये। कलकत्ता बन्दरगाह के विकास के लिए २६ मिलियन डॉलर का एक ऋण जून १९५८ में तथा २१ मिलियन डॉलर का दूसरा ऋण जुलाई १९६१ में प्राप्त हुआ। मद्रास बन्दरगाह के विकास के लिए १४ मिलियन डॉलर का ऋण विश्व बैंक ने १९५८ में दिया।

अन्य ऋण—

निज उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए ६० मिलियन डॉलर के चार ऋण भारतीय औद्योगिक साख्त एवं विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) को विश्व बैंक ने दिये हैं जिनका प्रयोग भारतीय उद्योगों को ऋण देने के लिए किया जा रहा है।

भारत सहायता क्लब (Aid India Club)—

विश्व बैंक ने निज तथा सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत-से ऋण देने के अतिरिक्त भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी काफी दिलचस्पी ली है। अगस्त सन् १९५८ में उसने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बातों पर आरम्भ की जिनका मुख्य उद्देश्य भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना था। इसके लिए कनाडा, जर्मनी, जपान, इङ्ग्लैंड तथा अमेरिका का एक सम्मेलन वाशिंगटन में बुलाया गया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारत सहायता क्लब (Aid India Club) की स्थापना हुई जिम्मे द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की विदेशी विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यथेष्ट रूप से प्रयत्न किया है। भारत सहायता क्लब में अमेरिका, इङ्ग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, जपान, फ्रांस तथा कनाडा शामिल हैं। कुछ अन्य देश भी इस क्लब में सम्मिलित हो गये हैं। अब भारत सहायता क्लब के सदस्यों की संख्या १० है। इस क्लब की मितियों समय-समय पर होती रहती हैं, जिनमें भारत की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है और विदेशी विनिमय सम्बन्धी सहायता देने का प्रस्ताव किया जाता है। भारत सहायता क्लब ने अपनी एक बैठक में तृतीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए १६२७ करोड़ रुपये की सहायता देने का निश्चय किया। मई सन् १९६४ में फिर इस सघ की बैठक हुई और तृतीय योजना के चौथे वर्ष

के लिए ४६० करोड़ रुपए की सहायता निश्चित की गई है। सन् १९६३-६४ में ३१६ करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय सहायता इस वनत्र से मिली है। तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष (१९६५-६६) के लिए भारत सहायता वनत्र ने १०२७ मिलियन डॉलर की सहायता देने का निश्चय किया है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्व बैंक ने भारत सहायता बलव की स्थापना करके भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है।

टेक्निकल सहायता (Technical Assistance)—

आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणों के अतिरिक्त हमें विश्व बैंक से टेक्निकल सहायता भी मिली है। विश्व बैंक समय-समय पर विशेषज्ञ मण्डल भारत भेजता रहा है जिन्होंने विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा भारत सरकार को परामर्श दिया है। इस प्रकार विश्व बैंक ने आर्थिक सहायता के साथ-साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के कुशल संचालन के लिए मार्ग दर्शन भी किया है। सन् १९५७-५८ में विश्व बैंक ने अपना एक स्थायी प्रतिनिधि भारत भेजा जो योजनाओं तथा आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध अमेरिका में किया है।

आलोचनाएँ (Criticisms)—

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष को अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने में विश्व बैंक से बड़ी सहायता मिली है किन्तु फिर भी बैंक की कार्य-प्रणाली की कुछ आलोचनाएँ की गई हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) बैंक निश्चित योजनाओं के लिए ही ऋण देता है—सन् १९५६ से पूर्व विश्व बैंक के द्वारा दिये गये ऋण केवल निश्चित उद्देश्यों के लिए ही होते थे जिससे भारतवर्ष को उनके प्रयोग में बड़ी कठिनाई होती थी। सन् १९५६ में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ऋण के प्रार्थना-पत्र में भारत ने बैंक से यह अनुरोध किया कि निश्चित उद्देश्यों वाले ऋणों (Specific Loans) के स्थान पर सामान्य ऋण (Block Loans) दिये जाने चाहिए जिससे उनका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके।

(२) बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज अधिक है—विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले ऋणों पर भारत को प्रायः २.५% से लेकर ४.७५% तक व्याज देना पड़ता है। आलोचकों का मत है कि व्याज की यह दर अल्प-विकसित देशों के लिए ऊँची है और बैंक को अपनी व्याज की दर कम करनी चाहिए। किन्तु विश्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई भी कमी करने से मना कर दिया है।

(३) ऋण देने में पक्षपात—कुछ आलोचकों ने बैंक की ऋण देने की नीति को दोषपूर्ण बतलाया है। बैंक के द्वारा दिये गये ऋणों को देखने से पता

चलता है कि एशियाई देशों को अपेक्षाकृत कम ऋण मिले है। एक अनुमान के अनुसार बैंक ने जितने ऋण दिये हैं उनका २४% अमरीकी देशों को, १५% यूरोपीय देशों को और केवल ६% एशियाई देशों को प्राप्त हुआ है।

(४) बैंक की ऋण नीति निम्न उद्योगों के पक्ष में है—यह भी कहा गया है कि विश्व बैंक निम्न उद्योगों को ऋण देना अधिक पसन्द करता है और इस प्रकार समाजवाद की स्थापना के रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न करता है। बैंक ने सरकार की औद्योगिक नीति की आलोचना करके भारत के आन्तरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (Industrial Finance Corporation)—

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था के रूप में जुलाई सन् १९५५ में की गई। यद्यपि विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से कर रहा है किन्तु फिर भी उसकी कार्य-प्रणाली में कुछ दोष अनुभव किये गये—(१) विश्व बैंक केवल सदस्य सरकारों को ही ऋण देता है या सदस्य सरकारों की गारन्टी पर ऋण दे सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था निम्न विनियोगकर्त्ताओं को हतोत्साहित करती है क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि सरकारी गारन्टी लेने से उनके व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है। (२) विश्व बैंक केवल निश्चित व्याज पर ही ऋण देता है और वह जोखिम वाली पूँजी प्रदान नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत व्यवसायों को स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए स्विच पूँजी की आवश्यकता होती है जो विश्व बैंक प्रदान नहीं करता है। इन कठिनाइयों के कारण ही यह आवश्यकता अनुभव हुई कि एक ऐसी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था स्थापित की जाय जो अल्प-विकसित देशों में निम्न उद्योगों को बिना सरकारी गारन्टी के पूँजी उधार दे सके।

सदस्यता तथा व्यवस्था (Membership and Organization)—

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था के रूप में कार्य करती है। विश्व बैंक का सञ्चालक मण्डल (Board of Governors) ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सञ्चालक मण्डल है। किन्तु फिर भी यह निगम एक प्रयत्न व स्वतन्त्र संस्था है जिसकी पूँजी विश्व बैंक से बिल्कुल अलग रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का अपना अलग प्रधान होता है जो निगम के व्यवसाय के लिए उत्तरदायी होता है।

आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूँजी १०० मिलियन डॉलर्स रखी गई जो सदस्य देशों से चन्द्रे के रूप में ली गई। प्रत्येक देश का अग्र्य उसने विश्व बैंक की पूँजी में अग्र्य के अनुपात में निर्दिष्ट किया गया है। सदस्य देश अग्र्य का भुगतान सोने या डॉलर में करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्र्य ३५ मिलियन डॉलर्स है जो सबसे अधिक है। इंग्लैंड का अग्र्य १४

मिलियन डॉलर्स है तथा भारत का अंश ४.४ मिलियन डॉलर्स निश्चित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता विश्व बैंक की सदस्यता से अलग है। विश्व बैंक के सभी सदस्यों को वित्त निगम की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सन् १९६४ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता बढ़कर ७८ हो गई है। ३१ दिसम्बर १९६४ को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी ११० मिलियन डॉलर्स थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Aims and Objects of I. F. C.)—

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में उत्पादक निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। यह निगम विशेष रूप से अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास को और अधिक ध्यान देती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम निम्नलिखित कार्य करती है—

(प्र) निगम बिना सरकार की गारन्टी के व्यक्तिगत उत्पादक उपक्रमों में पूंजी का विनिर्माण करती है।

(ब) यह निगम मध्यवर्ती सस्या के रूप में विनियोगों के अवसरों, देशी व अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत पूंजी तथा अनुभवों व्यवस्थापकों को परस्पर मिलाने का कार्य करती है।

(स) स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यक्तिगत पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहित करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की शर्तें

(Conditions of Eligibility for Financial Assistance from I. F. C.)—

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कुछ ऐसी शर्तें लगाई हैं जो निगम से आर्थिक सहायता चाहने वाले प्रत्येक उपक्रम को पूरी करनी होती है। यह शर्तें उपक्रम के आकार, प्रकृति, उद्देश्य तथा स्थान के सम्बन्ध में हैं।

(१) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता चाहने वाला उपक्रम किसी सदस्य देश में या उसके अधिकृत क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। यह निगम मुख्यतया अपने विनियोगों को कम विकसित देशों में केन्द्रित करना चाहती है। विस्तीर्ण सहायता केवल उसी उपक्रम को दी जाती है जो उत्पादक निजी उद्योग की स्थापना, विस्तार अथवा सुधार देश के आर्थिक विकास में सहायता देने के उद्देश्य से कर रहा हो।

(२) वित्त निगम आर्थिक सहायता के लिए उद्योग, कृषि, वित्तीय, वाणिज्य तथा अन्य प्रकार के निजी उपक्रमों में से किसी को भी चुन सकती है जो देश के लिए उत्सादक तथा उपयोगी हो किन्तु आरम्भ में वह औद्योगिक उपक्रमों के विकास के लिए सहायता देना चाहती है।

(३) आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपक्रमों का व्यक्तिगत होना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम केवल निजी उद्योगों के विकास के लिए ही

वित्त व्यवस्था करती है। वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी उद्योगों के लिए कुछ नहीं करती है।

(४) वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उपक्रमों का प्रबन्ध कुशल एवं अनुभवी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपक्रम का एक कुशल संचालक मण्डल (Board of Directors) भी होना चाहिए जो उस व्यवसाय को ठीक प्रकार चला सके।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के विनियोग के साथ-साथ उसी समय व्यक्तिगत विनियोग भी किया जाना चाहिए। वित्त निगम व्यक्तिगत विनियोग-कर्त्ताओं के साथ मिल कर ही विनियोग करनी है और उनसे आधे से अधिक पूंजी लगाने की आशा करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्यवाहन (Working of I.F.C.) —

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को कार्य करते हुए लगभग ६ वर्ष हो गये हैं। इस काल में उसने सदस्य देशों के निजी उद्योगों के विकास के लिए बहुत-सा विनियोग किया है। प्रारम्भ में दी जाने वाली आर्थिक सहायता कम थी किन्तु धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होती जा रही है। इसके अतिरिक्त पहले तीन वर्षों में उसकी क्रियाओं का क्षेत्र केवल अमेरिकन देश थे किन्तु अब वह एशिया व अफ्रीका के देशों में भी विनियोग कर रही है। सन् १९६४ तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ३० देशों में १२७.४ मिलियन डॉलर्स का विनियोग किया है। सन् १९६४ में वित्त निगम के द्वारा किये गये विनियोग की मात्रा २५.४ मिलियन डॉलर्स थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के विनियोग

(सन् १९६४ और १९६३ में)

(मिलियन डॉलर्स में)

क्षेत्र	विनियोग की संख्या	१९६४		१९६३	
		रकम		विनियोग की संख्या	रकम
अफ्रीका	४	५.८६		२	२.८८
एशिया और मध्य पूर्व	२	१.८७		५	७.७६
यूरोप		२.०२		३	१.५३
पश्चिमी गोलार्ध	१०	१५.६०		४	२.२६
कुल	१६	२५.३८		१४	१४.४६

आलोचनाएँ (Criticism) —

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में बहुत कम सफलता मिली है। स्थापना के समय निगम में जो आशाएँ लगाई गई थी उन्हें वह

पूरा नहीं कर सकी है। निगम के द्वारा किये जाने वाले विनियोगों की मात्रा बहुत कम है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है, यह इस बात से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सब सदस्य राष्ट्रों ने इस निगम की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की आलोचनाएँ निम्नलिखित आधार पर की गई हैं—

(१) ऋण सम्बंधी शर्तें बहुत कठोर हैं— अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिन शर्तों पर आर्थिक सहायता देता है वे इतनी सख्त हैं कि बहुत से प्रार्थी उद्योग उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ निगम की इस शर्त ने कि भूतपत्र व व्याज का भुगतान अमेरिकन डॉलर में ही लिया जायगा, बहुत राष्ट्रों को वित्त निगम के पास सहायता के लिए जाने से रोक दिया है। विशेषतया अर्ध-विकसित देशों के लिए डॉलर का प्रबन्ध करना काफी कठिन होता है इसलिए वे निगम की सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सके हैं।

(२) व्याज की दर अधिक है—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ऋणों पर ६% से ७% तक का व्याज लेती है जो काफी ऊँची दर है यद्यपि यह व्याज की दर बाजार में प्रचलित दर से अधिक ऊँची नहीं है किन्तु फिर भी यदि निगम का उद्देश्य अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता करना है तो उसे कम व्याज पर वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए।

(३) भेद-भाव पूर्ण नीति—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अमेरिका तथा उसके गुट में सम्मिलित देशों को ऋण देने में अधिक उदार रहती है और एशिया तथा अफ्रीका के देशों को इस सम्बन्ध में काफी निराशा हुई है। इसके द्वारा स्वीकृत ऋणों का ७१% भाग सैंटिन अमेरिकन देशों को मिला है। इसके अतिरिक्त अमेरिकन गुट में सम्मिलित देश जैसे पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया आदि को अधिक ऋण दिये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कम उन्नत देशों के विकास के लिए ऐसी शर्तों पर वित्त की व्यवस्था करना है जिससे कि इन देशों के शोषनाशेष पर कम बुरा प्रभाव पड़े। विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों की शर्तें अल्प-विकसित देशों के लिए अधिक अनुकूल नहीं हैं। ऋण लेने वाले देशों के भुगतान सन्तुलन पर प्रायः इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत दिनों से एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जो अल्प-विकसित देशों को विकास के लिए ग्रामान शर्तों पर ऋण दे सके। अल्प-विकसित देशों में सामाजिक पूँजी का निर्माण करने के लिए ऐसी परियोजनाएँ हो सकती हैं जैसे सड़कों का निर्माण,

गन्दी वस्तियों की सफाई, शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम इत्यादि जो इन देशों के प्राथमिक विकास में बड़ी सहायता दे सकते हैं किन्तु जिनके लिए विश्व बैंक ऋण नहीं दे सकता है। ऐसी योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए एक प्रथक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मस्या की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व बैंक से सम्बद्ध एक अन्य सस्या की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव १ अक्तूबर १९५६ को विश्व बैंक के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार लिया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना की गई। इस सस्या ने अपना कार्य नवम्बर १९६० से आरम्भ किया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की सदस्यता विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। सदस्यों के अग्र्यश विश्व बैंक में उनके अग्र्यशों के अनुपात में निर्दिष्ट किये गये हैं। सन् १९६४ के अन्त तक इस सघ के सदस्यों की संख्या बढ़कर ६४ हो गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की पूँजी १००० मिलियन डॉलर निर्दिष्ट की गई थी जो सदस्यों से अग्र्यशों के रूप में प्राप्त की गई है। अमेरिका का अग्र्यश ३२० मिलियन डॉलर तथा इंग्लैंड का १३१ मिलियन डॉलर निर्दिष्ट किया गया है। १९६४ के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के साधन बढ़कर १५६५६ मिलियन डॉलर्स हो गये थे जो परिवर्तनशील मुद्राओं में हैं।

उद्देश्य (Aims and Objects)—

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना कम उन्नत देशों में विकास को प्रोत्साहित करके तथा उत्पादन को बढ़ाकर इन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए की गई है। उसका उद्देश्य विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऐसी शर्तों पर ऋण देना है जिनका इन देशों के भुगतान सतुलन पर कम दबाव पड़े। यह सत्तें विश्व बैंक की परम्परागत शर्तों की तुलना में सरल एवं लोचपूर्ण होती है। इस सघ का उद्देश्य कबल अपने सदस्य देशों की विकास सम्बन्धी ऋण देना है।

ऋण-सम्बन्धी नीति (Lending Policy)—

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की ऋण देने की शर्तें काफी सरल हैं और उनका ऋणी देश के भुगतान सतुलन पर अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सघ के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तीन प्रमुख विशेषतायें हैं जो उसे अन्य प्रकार के विकास सम्बन्धी ऋणों से प्रथक करती हैं—प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के द्वारा दिये जाने वाले समस्त ऋणों पर कोई व्याज नहीं लिया जाता है केवल ३% वार्षिक सेवा शुल्क उस रकम पर लिया जाता है जो सदस्य देश के ऊपर बाजिर होनी है। द्वितीय, ऋणों के भुगतान का समय २० वर्ष है जो काफी लम्बा है। तृतीय, पहले दस वर्षों तक ऋणों की वापसी नहीं होती है। उसके बाद दस वर्ष तक प्रति वर्ष ऋण का १% लौटाना होता है। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ काफी सरल शर्तों पर सदस्य देशों को ऋण देना है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध वेबस उन्ही उद्देश्यों के लिए ऋण दे सकता है जो क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की दृष्टि से ऊँची प्राथमिकता वाले हों। विकास संध की यह अधिकार है कि वह किसी भी परियोजना के लिए ऋण दे सकता है यदि वह उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकती है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक हो अथवा नहीं। इस प्रकार जन, स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, शिक्षा आदि में सम्बन्धित योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध से आर्थिक सहायता मिल सकती है। विकास संध में आर्थिक सहायता मिलने के लिए केवल एक शर्त है कि वह योजना विकास की दृष्टि से ऊँची प्राथमिकता वाली होनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध का कार्यवाहन (Working of I. D. A.)—

सन् १९६४ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध को कार्य करते हुए ४ वर्ष हो गये हैं। इस अवधि में उसने २७ देशों को १००२ मिलियन डॉलर्स के ७० विकास सम्बन्धी ऋण दिये हैं। इसकी बहुत बड़ी मात्रा ७७७ ६ मिलियन डॉलर्स एशियाई देशों को प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक ऋण ४३५ ६ मिलियन डॉलर्स के यातायात के विकास के लिए दिये गये हैं। उद्देश्यों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध के द्वारा दिये गये ऋणों का विवरण निम्नलिखित है—

१. यातायात	४३५.६	मिलियन डॉलर्स
२. उद्योग	१११.५	"
३. विजली	६६.७	"
४. टेलिकम्युनिकेशन	७।०	"
५. जल पूर्ति	६२.६	"
६. शिक्षा	२६.१	"

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध (India & I. D. A.)—

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध की सदस्यता से काफी लाभ हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का ४८ प्रतिशत भारत को मिला है। सन् १९६४ के अगस्त तक भारत को विकास संध से ४८५ मिलियन डॉलर्स के ऋण प्राप्त हो चुके हैं। इसी काल में संध के द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों की मात्रा १००२ मिलियन डॉलर्स रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध में काफी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुका है। भारत को मिलने वाले ऋणों का उद्देश्य के अनुसार विवरण आगे दी तालिका अनुसार है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध ने भारत को बड़ी-बड़ी सड़कों, रेलों तथा तार द्वारा सदेशवाहन की सुविधाओं के विकास के लिए ऋण दिये हैं। उत्तर प्रदेश में द्यूबवैल द्वारा सिचाई योजना, गुजरात में क्षेत्रीय सिचाई योजना, उड़ीसा में सालाडी (Salandi) सिचाई योजना, पंजाब में बाढ़ सुरक्षा योजना, बिहार में सोन सिचाई योजना, महाराष्ट्र में पुर्ना प्रोजेक्ट, दूसरी कोयला योजना, दुर्गापुर पावर एक्सपेंडन

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण
(१९६४ के अन्त तक)

उद्देश्य	ऋणों की संख्या	रकम (मिलियन डॉलर में)
यातायात	४	२०७.५
शक्ति	३	५६.०
उद्योग	१	६०.०
कृषि	६	५६.५
टैलिक्म्युनिकेशन	२	७५.०
योग	१६	४८५.०

कोठागुडेम शक्ति योजना, वम्बई बन्दरगाह विकास योजना, वर्तमान औद्योगिक क्षमता का पूर्ण शोषण करने के लिए आवश्यक कच्चा माल व अन्य सामान आयात करने की सुविधाये देने की योजना के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण प्राप्त हो चुके हैं।

परीक्षा-प्रश्न

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के विधान एवं कार्यों का वर्णन कीजिये।
(आगरा बी० ए० १९६२)
- (२) विकास तथा पुनर्निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिये।
(आगरा बी० ए० १९६०)
- (३) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के क्या मुख्य कार्य हैं? भारत को इस बैंक से क्या लाभ हुआ है? वर्णन कीजिये।
(आगरा बी० ए० १९५६ स)
- (४) भारत के विश्व बैंक के सम्बन्ध अन्य ६८ सदस्य देशों की अपेक्षा सम्भवतः सबसे अधिक घनिष्ट हैं। इस देश को स्वीकार किये गये विभिन्न ऋणों के संदर्भ में उक्त कथन की प्राप्तिधना करिए।
(राजस्थान बी० काम० १९५६)
- (५) "दो मीट्रिक सस्थाओं (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक) की स्थापना वर्तमान युग में एक देवी वरदान सिद्ध हुई है।" इस कथन के संदर्भ में इन दोनों सस्थाओं के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और यह बताइये कि भारत उनसे किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है।
(बिहार बी० काम० १९५६)
- (६) पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर एक टिप्पणी लिखिये और बताइये कि भारत को उसकी सदस्यता से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है?
(विक्रम बी० ए० १९६०)

राष्ट्रीय आय

NATIONAL INCOME

राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक स्मृति का सूचक होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है वह आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक स्मृति-शाली तथा विकसित होता है। अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय आय बहुत कम होने के कारण ही वहाँ के लोग गरीब हैं और उन्हें निम्न स्तर पर रहना पड़ता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता उसे प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर होती है ठीक इसी प्रकार एक राष्ट्र की सम्पन्नता भी उसके द्वारा प्रति वर्ष उपाजित आय पर निर्भर रहती है। किसी देश की आर्थिक सम्पन्नता केवल उसकी राष्ट्रीय आय के आकार पर ही निर्भर नहीं होती है बल्कि वह उसकी प्रगति की दर तथा समाज में उसके वितरण पर भी आश्रित रहती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है और उसमें प्रति वर्ष सामान्य गति से वृद्धि होती रहती है तथा समाज में राष्ट्रीय आय का बँटवारा भी समान है तो ऐसी दशा में उस देश का आर्थिक कल्याण अधिकतम होता है। इसके विपरीत वे देश गरीब तथा अविकसित होते हैं जिनकी राष्ट्रीय आय कम है और उसमें धीमी गति से वृद्धि होती है। अतः आर्थिक निर्देशांक (Economic Indicators) के रूप में राष्ट्रीय आय का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी प्रवृत्तियों का अध्ययन करके हम उसकी आर्थिक स्थिति तथा प्रगति का पता लगा सकते हैं।

राष्ट्रीय आय का अर्थ (Meaning of National Income) —

वर्तमान समाज में उत्पादन सामूहिक रूप से किया जाता है। प्रत्येक देश में उत्पादन के साधनों के सामूहिक प्रयत्न से प्रति वर्ष जो वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पन्न की जाती हैं, वह उस देश का वार्षिक उत्पादन होता है। इस वार्षिक उत्पादन के शुद्ध मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें साल भर में उत्पादित कुल सामान तथा उपयोग की गई कुल सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। किसी देश में उत्पादन के साधन मिलाकर प्रतिवर्ष जो वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं और जिन सेवाओं का प्रयोग किया जाता

है, उनके कुल मूल्य में से पूँजीगत वस्तुओं का वित्तावट व्यय निकाल कर जो शेष रहता है वह उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। अर्थात् वह सम्पूर्ण शुद्ध आय जो एक निश्चित काल से देश में उत्पत्ति के साधनों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उत्पन्न की जाती है, उसे राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभान (National Dividend) कहते हैं। राष्ट्रीय आय के विचार की दो प्रकार से समझा जा सकता है—(i) विस्तृत दृष्टिकोण तथा (ii) सकुचित दृष्टिकोण। विस्तृत दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत प्रति वर्ष उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सकुचित अर्थ में राष्ट्रीय आय में केवल उन वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका विनिमय मुद्रा के बदले में होता है। प्रो० मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा विस्तृत दृष्टिकोण से की है किन्तु प्रो० पीगू के द्वारा उसकी परिभाषा सकुचित दृष्टिकोण से की गई है।

मार्शल के विचार (Marshall's View)—

प्रो० मार्शल ने किसी देश में उत्पन्न की जाने वाली समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया है। उनके अनुसार, "किसी देश का श्रम तथा पूँजी वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं, जिसमें मूल और अमूल वस्तुएँ तथा सब प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। शुद्ध उत्पत्ति का यह योग ही मार्शल के अनुसार एक वर्ष का राष्ट्रीय लाभान होता है।" शुद्ध उत्पत्ति को निकालने के लिए हमें कुल वार्षिक उत्पादन में से मूल्य तथा अन्य प्रकार की पूँजीगत वस्तुओं का वित्तावट व्यय निकाल देना चाहिए और विदेशी विनियोगों से होने वाली शुद्ध आय को उसमें जोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना के विषय में लिखते हुए मार्शल ने बतलाया है कि "वे सब सेवाएँ जो एक मनुष्य अपने स्वयं के लिए ही करता है या वह अपने मित्रों अथवा सम्बन्धियों के लिए बिना किसी पारितोषण के लोभ से करता है, वे सब लाभ जो अपनी निजी सम्पत्ति (फर्नीचर, कपड़े आदि) या सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे—शुगी-रहित पुलों से प्राप्त होते हैं, राष्ट्रीय लाभान में नहीं जोड़े जाते हैं, बल्कि उनका हिमाय अलग रखा जाता है। इस प्रकार प्रो० मार्शल ने देश के समस्त उत्पादन में प्राप्त होने वाली आय को, चाहे वह उत्पादन भौतिक वस्तुओं के रूप में हो अथवा अमौलिक वस्तुओं के रूप में, राष्ट्रीय आय में शामिल किया है।

1 "The Labour and Capital of the country, acting on its natural resources produce annually a net aggregate of commodities material and immaterial including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend"

मांसल की परिभाषा में सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो कोई दोष नहीं है किन्तु व्यावहारिक जीवन में उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का नापना और निर्धारित करना प्रायः असम्भव है। किसी देश की एक वर्ष में उत्पत्ति की कुल मात्रा की गणना करना बहुत कठिन कार्य है। बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी भी उत्पन्न की जाती हैं जो उत्पादकों द्वारा स्वयं प्रयोग कर ली जाती हैं। ऐसी वस्तुओं की न तो मात्रा निश्चित करना ही सम्भव होता है और न उनका मूल्य ही कभी माँका जाता है। अतः उत्पत्ति के इस भाग का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय को वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में व्यक्त करने से उसकी उपयोगिता बहुत सीमित हो जाती है। इन सब दोषों के कारण ही प्रो० पीगू ने मांसल की राष्ट्रीय आय की परिभाषा में सुधार करने का प्रयत्न किया है।¹

पीगू का दृष्टिकोण (Pigou's View)—

प्रो० पीगू ने राष्ट्रीय आय की मुद्रा के माप-दण्ड से नापने का प्रयत्न किया है। वैसे तो उन्होंने मांसल की राष्ट्रीय लाभांश को नापने की प्रणाली को ही अपनाया है किन्तु वे राष्ट्रीय आय की मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने के पक्ष में हैं। पीगू के अनुसार, “राष्ट्रीय आय किसी देश की भौतिक आय (Objective Income) का, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, वह भाग है जो मुद्रा में नापा जा सकता है।”² इस परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय लाभांश में, देश में-उत्पन्न की गई कुल आय का केवल वह भाग ही शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उत्पादन का वह भाग जिसे मुद्रा में नहीं नापा जा सकता है, उसे राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। पीगू की इस परिभाषा में कुछ दोष अवश्य हैं, जिनका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इस परिभाषा के आधार पर बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ लाभांश में सम्मिलित नहीं की जा सकती, जिनका उसमें सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से गहरा सम्बन्ध है और जो किसी प्रकार भी उनमें भिन्न नहीं हैं। वास्तव में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को जिनका मुद्रा में विनिमय किया जाता है, उन वस्तुओं तथा सेवाओं से पृथक् नहीं किया जा सकता है जिनका मुद्रा में विनिमय नहीं किया जाता है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में एक ही वस्तु दोनों स्थितियों में आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति मकान खरीदता है तो उस मकान से प्राप्त होने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित किया जायेगा किन्तु यदि वही मकान उसे उपहारस्वरूप प्राप्त हो जाता है, तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई

2 “National dividend is that part of the objective income of the community, including of course income derived from abroad which can be measured in money.”

व्यक्ति नौकरानी रखता है तो उसकी सेवार्थ राष्ट्रीय लाभार्जन का भाग है क्योंकि उनके बदले में वेतन दिया जाता है किन्तु यदि वह व्यक्ति अपनी नौकरानी से शादी कर लेता है तो अब उसकी सेवार्थ नि मुक्त प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी और राष्ट्रीय लाभार्जन उसी अनुपात में कम हो जायेगा। इस प्रकार पीगू की परिभाषा बहुत ही सही है तथा विरोधाभास (Paradox) से पूर्ण है। किन्तु इन सब दोषों के होते हुए भी राष्ट्रीय लाभार्जन की मुद्रा के रूप में इस परिभाषा की सामान्यतया अर्थशास्त्रियों के द्वारा माना गया है क्योंकि उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का मापना सरल है।

मार्शल और पीगू के विचारों में काफी समानता पाई जाती है। दोनों में ही राष्ट्र की कुल वार्षिक उत्पत्ति को राष्ट्रीय आय का आधार माना गया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दोनों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा उत्पत्ति के दृष्टिकोण से की है। अन्तर केवल इतना है कि मार्शल ने कुल वार्षिक उत्पत्ति को राष्ट्रीय लाभार्जन में सम्मिलित किया है किन्तु पीगू ने उसमें उत्पत्ति के उस भाग को ही सम्मिलित किया है, जिसका मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मार्शल की परिभाषा अच्छी है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण में पीगू की परिभाषा को श्रेष्ठ माना जाता है।

फिशर का दृष्टिकोण (Fisher's View)—

प्रो० फिशर ने मार्शल व पीगू दोनों से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने उपभोग के दृष्टिकोण से लाभार्जन की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है और उत्पत्ति के स्थान पर उपभोग को लाभार्जन का आधार माना है। उनके अनुसार राष्ट्रीय लाभार्जन में कुल उत्पत्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उत्पत्ति के उस भाग का मूल्य ही उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसका उस वर्ष में वास्तव में उपभोग किया जाता है। फिशर के अनुसार, "राष्ट्रीय लाभार्जन प्रत्यक्ष आय में केवल सेवार्थ जैसी कि वे उपभोक्तानों को प्राप्त होती हैं, शामिल की जाती हैं चाहे वे सेवार्थ भौतिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुई हैं प्रत्यक्ष मानवीय कार्यों में।"³ उन्होंने आगे चलकर कहा है कि एक प्यान्को (Piano) या एक ओवरकोट (Overcoat) जो इस साल मेरे लिए बनाया गया है, इस वर्ष की आय का हिस्सा नहीं है बल्कि वह केवल पूँजी में वृद्धि है। केवल वे सेवार्थ जो इस वर्ष के अन्दर मुझे इन वस्तुओं से प्राप्त हुई हैं, आय हैं। प्रो० फिशर का विचार

3 * . national dividend, or income, consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment. Thus, a piano or an overcoat made for me this year is not a part of this year's income but an addition to capital. Only the services rendered to me during this year by these things are income."

अधिक वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की ठीक-ठीक गणना करना सम्भव नहीं है।

कोलिन क्लार्क का मत (Colin Clark's View)—

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने भी राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में नापने के विचार का समर्थन किया है। प्रो० कोलिन क्लार्क (Colin Clark) ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा इसी दृष्टिकोण से की है, जो इस प्रकार है—“किसी समय विशेष में राष्ट्रीय आय उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित की जाती है, जो समय विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, ऐसा मूल्य उनकी वर्तमान विक्री कीमत पर निकाला जाता है। हममें पूँजी की उस वृद्धि को जोड़ा जाता है जिसका मूल्य नये पूँजी माल की कीमत के रूप में चुकाया जा चुका है। हममें से प्रस्तुत पूँजीगत माल की घिसावट (Depreciation) और पुराने पड़ने (Obsolescence) के व्यय को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की जोड़ और घटा की कीमत भी चालू कीमतों के आधार पर माँकी जाती है।”⁴ कोलिन क्लार्क के अनुसार ऐसी सेवाओं की कीमत जो राज्य के द्वारा बिना लाभ के आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे डाक, तार आदि की सेवाएँ, उनके वास्तविक भाड़ों की दर पर निकाली जाती है। जिस वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं उन वस्तुओं की कीमत निकालते समय इन करों की आय को विक्री मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

डा० राव (V. K. R. V. Rao) ने भी कोलिन क्लार्क से मिलता-जुलता विचार दिया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित होती है। इस मूल्य को चालू कीमतों के आधार पर निकाला जाता है और उसमें उन घायातों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाता है जो विक्री के लिए उपलब्ध हैं अथवा जिन्हें बेचा जा सकता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य आता है, उसमें से इन मदों को निकाल दिया जाता है—(i) समय-विशेष में पूँजीगत माल के घिसावट व्यय का मौद्रिक मूल्य। (ii) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो उत्पादन कार्य में व्यय की गई हैं। (iii) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो वर्तमान पूँजी स्टॉक को

4 “The national income for any period consists of the money value of goods and services becoming available for consumption during that period, reckoned at their current selling value, plus additions to capital reckoned at prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation and obsolescence of existing capital goods and adding the net accretion of, or deducting the net drawings upon stocks, also reckoned at current prices.”

बनाये रखते के लिए व्यय की गई है। (iv) राज्य को परोक्ष करो से प्राप्त आय। (v) व्यापार संतुलन की अनुकूलता का मौद्रिक मूल्य। (vi) देश के विदेशी ऋण की मुद्रा वृद्धि।^२

राष्ट्रीय आय को नापने की रीतियाँ

(Methods of Calculating National Income)—

किसी देश की राष्ट्रीय आय को नापने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है—

(१) उत्पत्ति गणना प्रणाली (Census of Production Method)—इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य खालू कीमतों पर निकाल लिया जाता है। इसमें से चल पूँजी की स्थान-पूर्ति और अचल पूँजी का मूल्य ह्रास, घिसावट व प्रतिस्थापन का मूल्य घटा देते हैं। इस प्रकार कुल उपज (Gross produce) में से ये सब व्यय घटा कर जो शुद्ध उत्पत्ति (Net produce) बचती है, वह उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। इस शुद्ध राष्ट्रीय आय में से ही लगान, व्याज, मजदूरी, लाभ, कर आदि के भुगतान किये जाते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम १९०७ में ब्रिटिश उत्पत्ति गणना के लिए किया गया था किन्तु राष्ट्रीय आय गणना की यह रीति काफी लम्बी तथा कठिन है।

(२) आय गणना प्रणाली (Census of Income Method)—इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी समय-विशेष में लोगों की प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण आय की गणना की जाती है और देशवासियों की आय का यह योग ही राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए आय-कर देने वाले व्यक्तियों की आय तथा आय-कर न देने वाले व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है। समाज में जो लोग आय-कर देते हैं उनकी आय का अनुमान तो आय-कर लेखों (Income Tax Returns) से लगा लिया जाता है किन्तु आय-कर न देने वाले व्यक्तियों की आय का अनुमान लगाना कठिन होता है। इसके लिए किसी वर्ग की औसत आय को व्यक्तियों की सख्या से गुणा किया जाता है और इस प्रकार आय-कर न देने वाले व्यक्तियों की आय का अनुमान लगाया जाता है। आय-कर देने वाले और आय-कर न देने वाले व्यक्तियों की आय का कुल योग ही देश की राष्ट्रीय आय होती है। इस रीति के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की आय को दो बार न गिना जाये। यह प्रणाली प्रायः उन देशों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जिनमें अधिकांश लोग आय-कर देते हैं। भारतवर्ष के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर आय-कर न देने वालों की सख्या बहुत अधिक है।

(३) व्यवसायिक गणना प्रणाली (Occupational Census Method)—

इस प्रणाली में व्यवसायिक गणना के द्वारा उनमें लगे हुए व्यक्तियों की आय का अनुमान लग या जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए लोगों की आय को आँका जाता है और इस प्रकार प्राप्त आयों का कुल योग ही राष्ट्रीय आय होती है। उदाहरणार्थ कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यवसाय (Liberal Arts) आदि में लगे हुए लोगों की, उनके व्यवसाय के आधार पर आयों की तालिकाएँ (Inventories) बना ली जाती हैं और फिर इन सशका योग मालूम कर लेते हैं और आयों का यह कुल योग देश की राष्ट्रीय आय होती है। लार्ड स्टाम्प (Lard Stamp) के अनुसार आय गणना करते समय कृद अवस्था में प्राप्त होने वाली पैशन, धोसे व जालसाजी से प्राप्त धन आदि उसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह व्यवसायिक आय नहीं है।

(४) उत्पादन पद्धति और आय पद्धति का मिश्रण (Combination of Production Method and Income Method)—यद्यपि राष्ट्रीय आय गणना की उक्त तीन पद्धतियाँ ही प्रमुख हैं, किन्तु कभी-कभी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली दोनों को मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डा० बी० के० आर० बी० राव ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उत्पादन पद्धति तथा आय पद्धति दोनों का प्रयोग किया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कृषि उपज सम्बन्धी सरकारी आँकड़ों का प्रयोग किया है और देश में रनिज, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों के उत्पादन का अनुमान स्वयं लगाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आय-कर के आँकड़ों, सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा श्रमिकों की मजदूरियों का भी उपयोग किया है।

यह कहना कठिन है कि इन सब रीतियों में से कौन-सी सबसे अधिक उपयुक्त है। सामान्यतः उत्पत्ति गणना प्रणाली तथा व्यवसायिक गणना प्रणाली की अधिक अच्छा तथा व्यवहारिक माना जाता है क्योंकि आय गणना प्रणाली में एक ही आय को एक से अधिक बार गिनने की सम्भावना बराबर रहती है। यदि पूर्ण सावधानी से काम लिया जाये तो तीनों ही रीतियों-से लगभग एक ही राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। आजकल उत्पत्ति गणना प्रणाली का अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति ने भी इसी पद्धति की सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है।

राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व

(Importance of National Income Study)—

किसी देश की आर्थिक स्थिति का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन

के द्वारा हम देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा भविष्य की विकास सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय के प्रकार पर ही उस देश की विकास क्षमता, वहाँ के लोगों का रहन सहन स्तर तथा उनका आर्थिक कल्याण निर्भर रहता है। सामान्यतः राष्ट्रीय आय के अध्ययन से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

(१) राष्ट्रीय आय की सहायता से देश के आर्थिक कल्याण को नापा जा सकता है—किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा उसके आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है इसीलिए कुछ भ्रंशशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का माप माना है। 'अन्य बातें समान रहने पर' किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उसका आर्थिक कल्याण भी उतना ही अधिक होता है। यद्यपि प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में एक ही दिशा तथा एक ही अनुपात में परिवर्तन होने सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी अन्य बातें समान रहने पर राष्ट्रीय आय के बढ़ जाने पर आर्थिक कल्याण बढ़ जाता है और उसके कम होने पर घट जाता है।

(२) राष्ट्रीय आय से देश के रहन-सहन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं—राष्ट्रीय आय के छाँकड़े हमें किसी देश के लोगों के रहन-सहन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देते हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होती है लोगों का जीवन-स्तर भी उतना ही ऊँचा होता है। प्रति व्यक्ति आय का कम होना जीवन स्तर के निम्न होने का सूचक माना जाता है इसीलिए विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। किन्तु प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना अथवा उसमें होने वाली प्रत्येक वृद्धि को सदैव ऊँचे रहन-सहन स्तर का सूचक नहीं माना जा सकता है। यदि देश में धन के विनियोग की असमन्वितताएँ बहुत अधिक हैं और केवल कुछ व्यक्तियों को ही देश की अधिकांश आय प्राप्त होती है और अधिकांश व्यक्तियों को उनका थोड़ा-सा भाग ही मिल पाता है तो ऐसी दशा में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर भी लोगों का रहन-सहन का स्तर नीचा रहेगा और राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि सामान्य लोगों के रहन-सहन को ऊँचा नहीं उठा सकेगी।

(३) राष्ट्रीय आय के अध्ययन से किसी देश की आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं—किसी राष्ट्र की आय उसकी आर्थिक प्रगति का सूचक होती है। प्रायः अधिक राष्ट्रीय आय वाले देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत माने जाते हैं और जिनकी आय कम होती है वे देश कम उन्नत तथा पिछड़े हुए होते हैं। अतः राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से हम उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में ही नहीं बतलाती है बल्कि उसके द्वारा हम उसकी विकास क्षमता का

अनुमान भी लगा सकते हैं। देश में वचत की मात्रा राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय आय के अधिक होने पर देश में वचत की सम्भावना अधिक रहती है और देश में पूँजी का निर्माण अधिक मात्रा में किया जा सकता है जिसके कारण आर्थिक प्रगति की दर भी अधिक होती है। इसके विपरीत कम राष्ट्रीय आय वाले देशों में पूँजी का निर्माण कम होने के कारण उनकी विकास क्षमता भी सीमित होती है। यही कारण है कि अधिक राष्ट्रीय आय वाले देश कम आय वाले देशों की अपेक्षा तेजी के साथ प्रगति करते हैं। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से यह भी पता लगाया जा सकता है कि देश का विकास समुचित आधार पर हो रहा है कि नहीं? यदि राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है तो यह इस बात का सूचक है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है।

(४) राष्ट्रीय आय के आँकड़े किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय बताते हैं—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से यह पता चलता है कि कालांतर में धन का वितरण किस प्रकार का था और उसमें परिवर्तन की क्या प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इसके आधार पर देश में धन के वितरण सम्बन्धी दोषों को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के आँकड़े देश की आर्थिक नीति के निर्माण तथा आर्थिक नियोजन में बड़ी सहायता देते हैं। इन आँकड़ों के द्वारा समाज में विभिन्न वर्गों की वचत क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है जिससे देश में उचित कर-नीति के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है।

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश के आर्थिक जीवन में राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के सूचक होते हैं। राष्ट्रीय आय के आँकड़े देश की वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं कराते हैं बल्कि उनकी सहायता से भविष्य की विकास सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है।

भारत की राष्ट्रीय आय (National Income Estimates in India)—

सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने सन् १८६७-७० के काल के लिए भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय २० रुपये प्रति वर्ष निकाली गई। इसके पश्चात् राष्ट्रीय आय के कई गैर सरकारी अनुमान लगाये गये किन्तु इन सब में इतनी अधिक भिन्नता थी कि उनके आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय का सही ज्ञान प्राप्त करना असम्भव था। सन् १९०० में लार्ड कर्जन के अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय ३० रुपये प्रति वर्ष थी। सन् १९१२-१४ में वाडिया और जोशी के अनुमान के आधार पर राष्ट्रीय आय १०८७ करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय ४४ रु ५ आने ६ पाई थी। सन् १९२२ में फिडले शिराज के

अनुमान के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय ८८३ करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय १०३ रुपये थी। डा० राव ने १९३१-३२ में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान ६५ रुपये प्रति वर्ष लगाया। सन् १९३७-३८ में सर जेम्स ग्रीग (Sir James Grigg) के अनुसार प्रति व्यक्ति आय ५६ रुपये प्रति वर्ष थी। राष्ट्रीय आय के इन सब अनुमानों में इतनी अधिक भिन्नता पाई जाती है कि इनके आधार पर विभिन्न समय में भारत की राष्ट्रीय आय की तुलना करना सम्भव नहीं है।

इन प्रारम्भिक अनुमानों में भिन्नता के कई कारण थे। विभिन्न समय में मूल्य-स्तर की भिन्नता के कारण राष्ट्रीय आय के अनुमानों में भिन्नता का होना स्वाभाविक ही था। विभिन्न अनुमानकर्ताओं के दृष्टिकोण में भिन्नता होने के कारण भी इन अनुमानों में भिन्नता पाया जाता था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले अनुमानकर्ताओं के अनुमान प्रायः सरकारी अनुमानों से कम होते थे क्योंकि वे इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के शासन-काल में भारत की स्मृद्धि नहीं बढ़ी है जबकि सरकार यह दिखताना चाहती थी कि प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुमानकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्र लिए थे तथा अनुमान में सम्मिलित की जाने वाली मदों में भी भिन्नता थी जिसके कारण इन अनुमानों का भिन्न होना स्वाभाविक था। आँकड़ों का अभाव तथा अविश्वसनीयता भी राष्ट्रीय आय के अनुमानों की भिन्नता के लिए जिम्मेदार थी। इन सब अनुमानों में से डा० बी० के० भार० धी० राव का अनुमान अधिक वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय समझा जाता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय ५१ रुपये और नागरिक क्षेत्रों की १६६ रुपये पाई थी और हम आधार पर औसत प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपये निकाली है।

राष्ट्रीय आय समिति १९४६ (National Income Committee)—

स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को स्वीकार किया और उसका अधिक वैज्ञानिक आधार पर संपठन करने का प्रयत्न किया गया। सन् १९४६ में सरकार ने राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़ों में सुधार के मुझाव देने तथा अधिक वैज्ञानिक ढङ्ग से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए प्रो० पी० सी० महलनोबिस (P. C. Mahalanobis) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की जिसने अप्रैल सन् १९५१ में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में १९४८-४९ में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया गया था। इस समिति के अनुसार १९४८-४९ की अनुमानित राष्ट्रीय आय ८६५० करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय २४६.६ रुपये थी। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सन् १९८४ में प्रस्तुत की जिसमें १९५०-५१ तक की राष्ट्रीय आय के आँकड़े दिये गए थे। तब से राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रति वर्ष सेन्ट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइजेशन (Central Statistical Organisation) के राष्ट्रीय

आय यूनिट (National Income Unit) के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा दिये गए राष्ट्रीय आय के अनुमान स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के अनुमानों से अधिक सन्तोषजनक, विश्वसनीय तथा अधिकृत हैं। सन् १९४८-४९ से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान निम्नलिखित तालिका में दिये गए हैं—

भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

(१९४८-४९ से १९६३-६४ तक)

(India's National Income & Per Capita Income)

Year 1948-49 to 1963-64.

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपये में)		प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	
	१९४८-४९ के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	१९४८-४९ के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर
१९४८-४९	८६१०	८६१०	२४६.५	२४६.५
१९५०-५१	८.५०	६५३०	२.७५	२६६.५
१९५५-५६	१०४८०	६६८०	२६७.८	२५५.०
१९६०-६१	१२७३०	१४१४०	२६३.२	३२५.७
१९६१-६२	१३०६०	१४८००	२६४.३	३३३.६
१९६२-६३	१३३७०	१५४००	२६४.७	३३६.४
१९६३-६४	१३६४०	—	३००.४	—

प्रमुख प्रवृत्तियाँ (Main Trends)—

(१) राष्ट्रीय आय (National Income)—ऊपर दी गई तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय आय १९४८-४९ से निरन्तर बढ़ रही है किन्तु प्रगति की दर विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न रही है। सन् १९४८-४९ में वर्तमान मूल्यों पर हमारी राष्ट्रीय आय ८६१० करोड़ रुपये थी जो १९६२-६३ में (वर्तमान मूल्यों पर) बढ़कर १५४०० करोड़ रुपये हो गई थी। इन १४ वर्षों में राष्ट्रीय आय में ७८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अर्थात् वार्षिक औसत वृद्धि ५.५ प्रतिशत रही है। सन् १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, यद्यपि वह उस वृद्धि की अपेक्षा कम है जो राष्ट्रीय आय में वर्तमान मूल्यों के आधार पर हुई है। १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर १९६२-६३ में राष्ट्रीय आय १३३७० करोड़ रुपये थी जो १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय की तुलना में ५४.५ प्रतिशत अधिक थी। इस आधार पर राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि का औसत ३.६ प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्यों के आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय

में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय कम तेजी के साथ बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण हमारे कीमत-स्तर का उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ना है। सन् १९५१-५६ में वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय १९४८-४९ के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय से कम थी किन्तु इसके पश्चात् वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में १९४८-४९ के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय से अधिक तेजी के साथ वृद्धि हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि १९५५-५६ के पश्चात् हमारे देश में कीमते राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं।

(२) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)—इन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय भी निरन्तर बढ़ती रही है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय १९४८-४९ में २४६.६ रुपये से बढ़कर १९६२-६३ में ३३६.४ रुपये हो गई थी। निश्चित मूल्यों के आधार पर (१९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर) प्रति व्यक्ति आय इसी काल में २४६.६ रुपये से बढ़कर २६०.७ रुपये हो गई थी। अतः निश्चित मूल्यों के आधार पर १४ वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में १८% की वृद्धि हुई है। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि केवल १.३% है। निश्चित मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि ३.६ प्रतिशत प्रति वर्ष रही है किन्तु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल १.३ प्रतिशत प्रति वर्ष है। इस अन्तर का प्रमुख कारण हमारे देश की जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होना है। यद्यपि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है किन्तु जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर अल्पतः थी है।

(३) राष्ट्रीय आय के औद्योगिक-मूल्य (National Income by Industrial Origin)—किसी देश की राष्ट्रीय आय विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त की जाती है। भारत में चार प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यह इस प्रकार है—कृषि, खानें तथा उद्योग, वाणिज्य एवं यातायात तथा अन्य सेवाएँ। सन् १९४८-४९ से लेकर १९६२-६३ तक हमारी राष्ट्रीय आय का स्रोत (Sources) के अनुसार बटवारा अगले पृष्ठ पर दी तालिकाानुसार रहा है—

उक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है और राष्ट्रीय आय का ४५% से लेकर ५०% तक कृषि से प्राप्त होता है। सन् १९४८-४९ में राष्ट्रीय आय का ४६.१ प्रतिशत कृषि से प्राप्त हुआ। इसकी तुलना में १९६२-६३ में अनुपात कुछ घट कर ४५.३ प्रतिशत रह गया है। खानों तथा उद्योगों से भारतीय राष्ट्रीय आय का १६% से लेकर २०% तक प्राप्त होता रहा है। देश में औद्योगिकरण होने के कारण यह अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है। सन् १९४८-४९ में राष्ट्रीय आय का १७.१ प्रतिशत खानों व उद्योगों से प्राप्त होता था किन्तु १९६२-६३ में यह अनुपात बढ़कर २०.३ प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय आय के औद्योगिक श्रोत — अनुपातिक वितरण वर्तमान मूल्यों पर

(National Income by Industrial Origin-Percentage Distribution)
(At Current Prices)

	१९४८-१९४९	१९५०-१९५१	१९५५-१९५६	१९६०-१९६१	१९६१-१९६२	१९६२-१९६३
(१) कृषि	४६.१	५१.३	४५.३	४८.७	४७.०	४५.३
(२) खाने एवं उद्योग	१७.१	१६.१	१८.५	१८.४	१९.५	२०.१
(३) वाणिज्य, याता-यात एवं सदेश-वाहन	१८.५	१७.७	१८.६	१६.६	१६.८	१७.०
(४) अन्य सेवाएँ	१५.५	१५.१	१७.३	१६.७	१७.२	१८.१
(५) विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय	-०.२	-०.२	-०.०	-०.४	-०.५	-०.५
राष्ट्रीय आय	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०

२०.१% प्रतिशत हो गया है। इन वर्षों में वाणिज्य, यातायात एवं सदेशवाहन से प्राप्त होने वाला अनुपात कुछ कम हो गया है तथा अन्य सेवाओं से प्राप्त होने वाला अनुपात कुछ बढ़ा है।

राष्ट्रीय आय और आर्थिक नियोजन

(National Income & Economic Planning)—

आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास के द्वारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होता है। आर्थिक विकास की योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं और फिर इन लक्ष्यों को योजना काल में पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। भारतवर्ष में भी योजना कमीशन ने राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्य निश्चित किये हैं जिन्हें विभिन्न योजना काल में पूरा किया जाता है और इस प्रकार देश की राष्ट्रीय आय में एक नियमित गति से निरन्तर वृद्धि होने की आशा है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि का दीर्घकालीन लक्ष्य इस प्रकार निश्चित किया है—सन् १९५०-५१ की तुलना में १९७५-७६ में राष्ट्रीय आय तीन गुणा हो जायगी और इसी काल में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जाने का अनुमान है। इस काल में जनसंख्या में ५०% की वृद्धि होने की आशा है। विभिन्न योजनाओं में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी लक्ष्य निम्न प्रकार निश्चित किए गये हैं—

(सन् १९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर)

	प्रथम योजना १९५१-५६	दूसरी योजना १९५६-६१	तीसरी योजना १९६१-६६	चौथी योजना १९६६-७१	पाँचवीं योजना १९७१-७६
(१) राष्ट्रीय आय योजना काल से अन्त में (करोड़ रुपये)	१०,८००	१३,४८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
(२) जनसंख्या (करोड़ों में)	३८.४	४०.८	४३.४	४६.५	५०.०
(३) प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	२८१	३३१	३९६	४६६	५४६

(१) प्रथम योजना (First Plan)—राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के इन लक्ष्यों को कहीं तक पूरा करना सम्भव हो सका यह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में १५% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस योजना के पाँच वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय में १८% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में १२% की वृद्धि हुई जबकि अनुमान केवल ७% की वृद्धि का ही था। प्रथम योजना में केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि वास्तविक आय भी बढ़ी है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार प्रथम योजना के अन्त में उसके आरम्भ की अपेक्षा कीमत-स्तर १३% नीचा था। इन सब आँकड़ों से विदित होता है कि प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। प्रथम योजना की इस सफलता को देख कर ही राष्ट्रीय आय के लक्ष्यों को कुछ ऊँचा कर दिया गया था।

(२) द्वितीय योजना (Second Plan)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में २५% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यह अनुमान था कि राष्ट्रीय आय प्रथम योजना के अन्त में १०,८०० करोड़ रुपये से बढ़ कर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में १३,४८० करोड़ रुपये हो जायेगी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय (१९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर) प्रथम योजना के अन्त में २८१ रुपये से बढ़ कर दूसरी योजना के अन्त में ३३१ रुपये हो जाने का अनुमान था। किन्तु योजना कमीशन के यह अनुमान सही साबित न हो सके। जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ने तथा वृद्धि व विनियोग की दर कम रह जाने के कारण राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर निश्चित लक्ष्यों की अपेक्षा कम थी। दूसरी योजना काल में राष्ट्रीय आय में केवल २०% की वृद्धि हो सकी जबकि लक्ष्य २५% की वृद्धि का निश्चित किया गया था।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल ६.७% की हुई जबकि लक्ष्य १७% की वृद्धि का था। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होना था।

(३) तृतीय योजना (Third Plan)—तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के दीर्घकालीन लक्ष्यों में भी परिवर्तन कर दिया गया। पीछे दी गई तालिका में दीर्घकालीन लक्ष्य १९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर निश्चित किये गये थे, किन्तु तीसरी योजना में लक्ष्य १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर निश्चित किये गये हैं। नये लक्ष्य इस प्रकार है—

(सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर)

	तीसरी योजना के अन्त में	चौथी योजना के अन्त में	पाँचवीं योजना के अन्त में
राष्ट्रीय आय	१६,००० करोड़ रु०	२५,००० करोड़ रु०	३३,००० करोड़ रु०
प्रति व्यक्ति आय	३८५ रु०	४५० रु०	५३० रु०

तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में ३०% तथा प्रति व्यक्ति आय में १७% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस योजना के पहले दो वर्षों में आर्थिक विकास की दर विशेष रूप से धीमी रही है जिसके कारण राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम वृद्धि हो सकी है। १९६१-६२ में राष्ट्रीय आय में २.६%, १९६२-६३ में २.४% तथा १९६३-६४ में ४.३% की वृद्धि हुई है जो ६% प्रतिवर्ष के लक्ष्य से बहुत कम है। योजना के चौथे और पाँचवें वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर के कुछ बढ़ने की सम्भावना है किन्तु फिर भी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

(४) चौथी योजना (Fourth Plan)—चौथी योजना पर २१,५०० करोड़ रुपया व्यय किये जाने का अनुमान है। यदि साधनों की स्थिति अनुकूल रही तो इसमें १०० करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती है। इस योजना काल में राष्ट्रीय आय में ६.५% प्रति वर्ष की वृद्धि होने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय १६००० करोड़ के स्थान पर १७,४०० करोड़ रुपये ही हो सकेगी। अतः यह आवश्यक है कि दो योजनाओं में प्रगति की औसत दर ५% प्रतिवर्ष होनी चाहिए। चतुर्थ योजना काल में राष्ट्रीय आय में ३.५% की वृद्धि होने का अनुमान है।

भारत की राष्ट्रीय आय की अन्य देशों से तुलना—

यद्यपि पिछले वर्षों से हमारे देश में आर्थिक नियोजन के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है और उसमें काफी सफलता भी मिली है किन्तु भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय की अन्य देशों से तुलना करने से पता चलता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं और हमारे देश में तेजी से प्रगति होने की आवश्यकता है।

जनसंख्या के अधिक तेजी के साथ बढ़ने के कारण हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय में अधिक वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सका है। अभी भी एक औसत अमेरिकन की आय एक औसत भारतीय से ३१ गुना है तथा एक औसत अंग्रेज की १४ गुना है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारी राष्ट्रीय आय कम है और उसमें वृद्धि की गति भी अपेक्षाकृत धीमी है तथा प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ही कम है। नीचे दी गई तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय की तुलना कुछ अन्य देशों के साथ की गई है—

देश	वर्ष	जनसंख्या (करोड़ों में)	कुल राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
ऑस्ट्रेलिया	१९५३	०.८८	३,९२६	४,४६०
कनाडा	१९५४	१.५२	६,१६६	६,०५६
फ्रांस	१९५४	४.२७	१५,७५०	३,६८६
जापान	१९५४	८.८२	८,१२६	९२२
न्यूजीलैंड	१९५४	०.२१	१,०५८	५,०६२
स्विट्जरलैंड	१९५४	०.६८	२,४०७	४,८१२
ब्रिटेन	१९५४	५.११	२०,७२०	४,०५७
अमेरिका	१९५४	१६.२४	१,४२,६५७	८७७४
भारत	१९६३-६४	४३.६	१३,६४०	३००.४

देश में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि करने के लिए सभी दिशाओं में उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। कृषि, उद्योग तथा अन्य सभी व्यवसायों में तेजी के साथ घन का उत्पादन होना आवश्यक है। देश में विनियोग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। यद्यपि पिछले वर्षों में हमारे यहाँ विनियोग बढ़ कर राष्ट्रीय आय का १३% हो गया है किन्तु हमें २०% विनियोग करने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाय। हमारे देश में सरकार परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि की दर को कम करने का प्रयत्न कर रही है किन्तु इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। कार्यक्षमता में वृद्धि के द्वारा भी राष्ट्रीय उत्पादन की तेजी के साथ बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। इसके लिए श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि का प्रबन्ध होना चाहिए। घन के वितरण की असमानताओं को दूर करना—समाज में घन का समान वितरण तथा सब लोगों को उन्नति का समान अवसर मिलने से प्रगति के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा किया जा सकता है। इन सब उपायों के द्वारा हम लोगों की आय में तेजी के साथ वृद्धि कर सकेंगे तथा उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकेंगे।

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

1. ✓ राजस्व—परिभाषा एवं महत्व — 1-11
 राजस्व की परिभाषा, राजस्व के विभाग, राजस्व का सिद्धान्त, अधिवृत्तम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त ।
2. ✓ लोक व्यय 12-23
 लोक-व्यय में वृद्धि के कारण, लोक-व्यय के सिद्धान्त, लोक-व्यय का वर्गीकरण, लोक-व्यय के प्रभाव, सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव, लोक-व्यय के अन्य प्रभाव ।
3. ✓ लोक आगम 24-25
 अच्छी आगम प्रणाली के गुण, लोक आगम का महत्व ।
4. ✓ करारोपण 30-45
 करारोपण के सिद्धान्त, एहम म्मिथ के करारोपण सिद्धान्त, करारोपण में न्याय, करो का वर्गीकरण, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर, प्रत्यक्ष करो के लाभ, प्रत्यक्ष करो के दोष, परोक्ष करो के लाभ, परोक्ष करो के दोष, आनुपातिक कर तथा प्रगतिशील कर, प्रगतिशील करों के दोष, एक तथा अनेक कर-प्रणाली, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएँ, करदान क्षमता, करदान क्षमता का अर्थ, करदान क्षमता को प्रभावित करने वाली वार्त्त ।
5. ✓ कर का भार 46-68
 कर का मौद्रिक भार तथा वास्तविक भार, कर भार की समस्या के अध्ययन का महत्व, कर के भार को टालना, कर विवर्तन की दिशा, कर का सम्मिश्रण सिद्धान्त, कर-भार का आधुनिक सिद्धान्त कुछ मुख्य करो के सम्बन्ध में कर-भार की समस्या, वस्तुओं पर लगाये गये कर का भार, एकाधिकार पर कर का भार, आयात-निर्पात करो का भार, आय-कर का भार, भूमि पर कर का भार, मकानों पर कर का भार—भूयु-कर, विक्री-कर ।
6. ✓ उत्पत्ति तथा वितरण पर करारोपण का प्रभाव 69-81
 काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, साधनों के वितरण पर प्रभाव, धन के वितरण पर प्रभाव, कर के अन्य प्रभाव ।

७ लोक ऋण

८२-१०४

व्यक्तिगत ऋण तथा सार्वजनिक ऋण में भेद, ऋण कब लेना चाहिये ? लोक ऋण का वर्गीकरण, ऐच्छिक तथा अनिवार्य ऋण कोषित तथा अकोषित ऋण, आंतरिक तथा विदेशी ऋण, उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण, ऐच्छिक ऋण तथा अनिवार्य ऋण, सार्वजनिक ऋण से लाभ, सार्वजनिक ऋण की हानियाँ, सार्वजनिक ऋण का भार, विदेशी ऋण, आन्तरिक ऋण, सार्वजनिक ऋणों के आर्थिक परिणाम, ऋण को चुकाना अथवा उससे भार को कम करना, ऋण चुकाने में इन्कार करना, ऋण चुकाने की रीतियाँ, युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था, करारोपण तथा युद्ध, सार्वजनिक ऋण के द्वारा युद्ध-व्यय पूरा करना, मुद्रा प्रसार तथा युद्ध-व्यय, आर्थिक विकास के लिये अर्थ प्रबन्ध ।

८ भारतीय राजस्व का विकास

१०५-११८

प्रगतिशील विवेकीकरण का काल, मीन्टैग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॅस्टन परिनिर्णय मॅस्टन एक्टों के दोष, भारत सरकार का १९३५ का अधिनियम, स्वतन्त्रता के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की आय के साधन, राज्य सरकारों के साधन, प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशें, आलोचना, दूसरा वित्त-आयोग, तीसरा वित्त-आयोग ।

९ भारत सरकार का अर्थ-प्रबन्ध

११९-१३२

भारत सरकार की आय, कर-आय के साधन, आय-कर के दोष, मृत्यु-कर के लाभ, मृत्यु-कर के दोष, गैर-कर आगम, भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदें ।

१० भारत में राज्य अर्थ-प्रबन्ध

१३३-१४५

उत्तर प्रदेश सरकार की आय के साधन, राज्य अर्थ-प्रबन्ध में सुधार के सुझाव ।

११ भारत में सार्वजनिक ऋण

१४६-१५१

भारत में लोक-ऋण का विकास, युद्धोत्तर काल में लोक ऋण, पंचवर्षीय योजनाएँ तथा लोक-ऋण भारत का विदेशी ऋण, लोक ऋण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति ।

१२ भारत में स्थानीय अर्थ-प्रबन्ध

१५२-१५८

स्थानीय सस्थाओं का व्यय, आय के साधनों की कमी के कारण, आय के साधनों में वृद्धि के उपाय ।

राजस्व-परिभाषा एवं महत्व Public Finance-Definition and Importance

वर्तमान काल में राजस्व के अध्ययन का महत्व काफी बढ़ गया है और उसे अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने राजस्व के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है किन्तु एक विधिवत् विज्ञान के रूप में उतना विकास वर्तमान काल में हो चुका है। ग्रीक (Greek) सभ्यता के प्राचीन काल में राज्य अर्थशास्त्र (Political Economy) मुख्यतया इन बातों का अध्ययन करता था कि नगर राज्य (City States) किस प्रकार अपनी आय तथा व्यय का प्रबंध करते हैं। ऐडम स्मिथ तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र के इस पक्ष के अध्ययन पर काफी बल दिया है और राजस्व के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने अर्थशास्त्र को राज्य अर्थशास्त्र (Political Economy) का नाम दिया था। ऐडम स्मिथ के अनुसार राज्य अर्थशास्त्र को उन साधनों तथा विधियों का अध्ययन करना चाहिये जिनके द्वारा कोई राज्य अपनी आय प्राप्त करता है तथा उसे समाज की भलाई के लिए व्यय करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत राजस्व का अध्ययन कोई नई बात नहीं है और वह काफी प्राचीन समय से ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक भाग रहा है।

यद्यपि राजस्व विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव-समाज, किन्तु केवल वर्तमान काल में ही उसे एक विज्ञान का रूप दिया जा सका है और उसके क्षेत्र एवं महत्व को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयत्न किया गया है। राज्यों की स्थापना के साथ-साथ उनके स्वर्च को पूरा करने के लिये साधनों की आवश्यकता अनुभव हुई और राज्य की आय के स्रोतों की खोज की जाने लगी। इसके साथ ही राज्य की आय तथा व्यय का अध्ययन करने वाले शास्त्र की आवश्यकता भी अनुभव हुई। काफी समय तक राज्य की क्रियाओं के सीमित होने के कारण राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर अधिक जोर नहीं दिया गया और राजस्व विज्ञान केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही रहा। वर्तमान काल में राज्य की क्रियाओं के विस्तृत हो जाने के कारण तथा प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विकास के साथ-साथ राज्य की आय तथा व्यय के उचित प्रबंध की आवश्यकता अनुभव हुई और राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने राजस्व के बढ़ते हुये महत्व के कारण उसे एक विधिवत् विज्ञान का रूप देने का प्रयत्न किया है।

राजस्व की परिभाषा :

राजस्व एक ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र और राजनीति-शास्त्र की सीमाओं पर स्थित है। यद्यपि राजस्व का सम्बन्ध अर्थशास्त्र तथा राजनीति-शास्त्र दोनों से ही है किन्तु नामान्तरतया उसे अर्थशास्त्र का ही अंग माना जाता है। राजस्व अर्थ-शास्त्र की वह शाखा है जो लोक सत्ताओं की आय तथा व्यय का अध्ययन करती है। वह इस बात का अध्ययन करता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती हैं और कैसे उसका व्यय करती हैं। डॉ० डाल्टन (Dr. Dalton) के अनुसार "राजस्व लोक सत्ताओं की आय तथा व्यय का अध्ययन करता है और यह भी बतलाता है कि इन दोनों में किस प्रकार समायोजन किया जाता है।" लोक सत्ताओं की वित्तीय समस्याएँ राजस्व की विषय सामग्री हैं। वह लोक सत्ताओं की आय, व्यय तथा ऋणों का अध्ययन करता है। लोक सत्ताओं के अन्तर्गत नगरपालिकाओं न लेकर राष्ट्रीय सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार सभी सम्मिलित हैं। लुट्ज (Lutz) ने राजस्व की परिभाषा इस प्रकार दी है—“जब उन साधनों की प्राप्ति, नश्वर तथा व्यय के विषय में बताया है, जिनका मार्वांजनिक धन सरकारी कार्यों को चलाने के लिये आवश्यकता होती है।” धारमिटेज मिमर के अनुसार, “सरकारी व्यय तथा आय के सिद्धान्तों की प्रकृति की जांच करना ही राजस्व है।” बस्टाबल (Bastable) के अनुसार राजस्व का विषय इस बात का अध्ययन करना है कि राज्य को किस प्रकार धन प्राप्त होता है और वह किस प्रकार उसका व्यय करता है। फिन्डले शिर्राज (Findlay Shirras) ने राजस्व की परिभाषा बड़े सरल शब्दों में की है। उनके अनुसार, “राजस्व मार्वांजनिक समस्याओं की आय तथा व्यय के सिद्धान्तों का अध्ययन है।”

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में राजस्व को राज्य सरकारों की आय तथा व्यय को अध्ययन करने वाला शास्त्र बतलाया गया है। वह इस बात का अध्ययन करता है कि सार्वजनिक संस्थाएँ किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती हैं और कैसे जनहित में उसका व्यय किया जाता है। अर्थशास्त्र की भाँति ही राजस्व का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को अधिकतम करना है। यद्यपि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने

1. “Public Finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which the one is adjusted with the other.”
—Dalton

2. “Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of the resources needed for the conduct of public or governmental functions.”
—H. L. Lutz

3. “The investigations into the nature and principles of state expenditure and state revenue is called Public Finance.”
—Armstrong Smith

4. “The study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities.”
—Findlay Shirras

राजस्व की विषय सामग्री ने चारे में कोई मौलिक भेद नहीं है किन्तु फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने राजस्व को केवल सरकारी की आय तथा व्यय के अध्ययन तक ही सीमित रक्खा है जब कि कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने उनके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है और उनके अनुसार राजस्व समस्त सार्वजनिक समस्याओं की आय तथा व्यय का अध्ययन है जिनमें सार्वजनिक सम्पत्तियाँ तथा अर्ध-सरकारी संस्थाएँ भी आ जाती हैं। किन्तु यह यह बाद-जिदार् भी तगभय समाप्त हो गया है और अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात में सहमत हैं कि राजस्व का सम्बन्ध केवल सरकारी आय तथा व्यय से है और अन्य प्रकार की समस्याओं की आय तथा व्यय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

राजस्व के विभाग :

अध्ययन की दृष्टि से राजस्व को चार भागों में बाँटा जा सकता है। यह विभाग परस्पर सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक विभाग की विस्तार विवेचना करने में ही राजस्व की विषय-सामग्री को ठीक प्रकार समझा जा सकता है। राजस्व के यह विभाग इस प्रकार हैं—

(१) लोक व्यय (Public Expenditure)—लोक व्यय के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यय से सम्बन्धित निदान्तों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिये काफी बड़ी मात्रा में धन का व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय किन-किन मदों पर किया जाता है, यह व्यय किन सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिये और इसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सब बातों का अध्ययन लोक व्यय के अन्तर्गत किया जाता है। आजकल सार्वजनिक व्यय का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन राजस्व का मुख्य विषय बन गया है। वर्तमान सरकारों के द्वारा किये जाने वाले व्यय को किस प्रकार जनहित में किया जाय, यह लोक व्यय की प्रमुख समस्या है।

(२) लोक आय (Public Revenues)—राजस्व के इस विभाग के अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपने व्यय को पूरा करने के लिये आय प्राप्त करती हैं। सार्वजनिक व्यय के लिये सरकार को आय के साधन जुटाने होते हैं। यह आय किन-किन स्रोतों से प्राप्त की जाती है, सार्वजनिक आय के कौन के साधन उत्तम हैं तथा सार्वजनिक आय किन सिद्धान्तों के अनुसार प्राप्त की जानी चाहिये, इन सबका अध्ययन लोक आय के अन्तर्गत किया जाता है। सक्षेप में सरकारी के द्वारा आय प्राप्त करने से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन राजस्व के इस विभाग में होता है।

(३) लोक ऋण (Public Debt)—सार्वजनिक ऋणों का अध्ययन भी राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि सरकारी आय व्यय की अपेक्षा कम रहती है तो सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण क्यों लिये जाते हैं

किन कामों के लिये सरकार को ऋण लेना चाहिये और किन के लिये नहीं, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है तथा सरकारी ऋणों का देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ? इन सभी बातों का अध्ययन लोक ऋण विभाग में किया जाता है। आधुनिक आर्थिक विचारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सार्वजनिक ऋणों का स्थान काफी महत्वपूर्ण हो गया है। देशवासियों ने तथा विदेशों में, सरकार के द्वारा भारी मात्रा में ऋण लिये जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों का जनहित में विभिन्न प्रकार प्रवर्द्ध किया जाय, यह लोक ऋण की मुख्य समस्या है।

(४) सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration)—सरकारी आय तथा व्यय का उचित प्रवर्ध करने के लिये सार्वजनिक प्रशासन की कार्यक्षमता काफी महत्व रखती है। अपनी आय को एकत्रित करने तथा राजस्व सम्बन्धी अन्य क्रियाओं को करने के लिये सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, उसका अध्ययन राजस्व के इस विभाग में किया जाता है। सरकारी बजट का अध्ययन इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की आय तथा व्यय का बजट किस प्रकार बनाया जाता है, बजट का सतुलन कैसे होता है, सार्वजनिक ऋणों का प्रवर्ध कैसे किया जाता है, सरकारी लेखों और उनका अक्रेडिट का उत्तरदायित्व किन के ऊपर है, राजस्व की इन सब व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन सार्वजनिक प्रशासन विभाग में किया जाता है।

उपरोक्त चारों विभाग राजस्व विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं। पहले तीनों विभाग मुख्यतः अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हैं और उनकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत होता है किन्तु चौथे विभाग का अध्ययन राजनीति-शास्त्र के भीतर आ जाता है, यद्यपि उसका कुछ भाग जो बजट व्यवस्था से सम्बन्धित होता है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में ही किया जाता है।

लोक तथा निजी अर्थ-प्रवर्ध का भेद

ऊपर से देखने में दोनों प्रकार के अर्थ-प्रवर्धों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। निजी और लोक अर्थ-प्रवर्ध लगभग एक ही प्रकार के सिद्धान्तों पर आधारित हैं और दोनों प्रकार के अर्थ-प्रवर्ध में बहुत कम मौलिक भेद पाया जाता है। दोनों ही आय और व्यय से सम्बन्धित हैं और दोनों को ही आय तथा व्यय में समायोजन स्थापित करने की समस्या का अध्ययन करना पड़ता है। दोनों में आर्थिक प्रवर्ध का ठीक न होना भयंकर परिणाम पैदा कर सकता है। दोनों प्रकार के अर्थ-प्रवर्धों को अधिकतम सन्तुष्टि के सिद्धान्त के अनुसार चलाया जाता है। एक व्यक्ति अपनी आय को इस प्रकार खर्च करने का प्रयत्न करता है कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो और सरसर भी अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना व्यय करता है। इन सब समानताओं के होते हुए भी निजी अर्थ-प्रवर्ध और राजस्व को एक दूसरे के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। दोनों में कुछ

ऐसी विशेषतायें हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती हैं। लोक तथा निजी अर्थ प्रबन्ध में मुख्यतया निम्नलिखित भेद पाये जाते हैं:—

(१) एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निश्चित करता है किन्तु सरकार अपनी आय को व्यय के अनुसार निश्चित करती है। व्यक्तिगत अर्थ प्रबन्ध के अन्तर्गत व्यय आय के अनुसार ही किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति की आय में अधिक वृद्धि करना संभव नहीं होता है। निजी अर्थ प्रबन्ध में आय की मात्रा व्यय की सीमा को निश्चित करती है किन्तु सरकार एक व्यक्ति की जाने वाली आय की मात्रा को अपने व्यय के अनुसार निश्चित करती है। व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध में आय की मात्रा निश्चित होती है और समस्या केवल व्यय को आय अनुसार करने की होती है। यदि व्यय अधिक होता है तो उसे घटा कर आय के बराबर कर दिया जाता है। किन्तु राजस्व में पहले व्यय की मात्रा निश्चित की जाती है और फिर उसके लिये आय के साधनों की खोज की जाती है। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि सरकार अपनी आय को काफी सीमा तक बढ़ा कर व्यय के बराबर कर सकती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने साधनों के अनुसार व्यय करता है और सरकार अपने व्यय के अनुसार साधनों को जुटाती है। यदि उपलब्ध साधन व्यय की आवश्यकता से कम होते हैं तो इस घाटे को अधिक कर लगाकर अथवा ऋण लेकर पूरा किया जाता है।

निजी अर्थ-प्रबन्ध और सार्वजनिक अर्थ-प्रबन्ध के इन भेदों की कुछ सीमायें भी हैं। कभी-कभी व्यक्ति को भी अपने व्यय के अनुसार आय में परिवर्तन करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ विवाह के पश्चात् व्यक्ति को अपने बड़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये आय के नये साधनों की खोज करनी पड़ती है और वृद्ध अवस्था में वह व्यय कम हो जाने के कारण कम घटे काम करने का निश्चय कर सकता है। सरकार को भी कुछ दशाओं में अपने व्यय में आय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। बुरे समय में जब सरकार की आय कम होती है तो उसके लिये व्यय में कमी करना अनिवार्य हो जाता है किन्तु समृद्धिकाल में वह अपनी क्रियाओं का विस्तार कर सकती है।

(२) राजस्व के अन्तर्गत सरकार की आय के साधन बहुत अधिक लोचदार होते हैं किन्तु निजी अर्थ-प्रबन्ध में आय के साधन लगभग बेल्चीदार होते हैं। आय में वृद्धि करने के लिये लोक सत्ता व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में होती है क्योंकि उसके समस्त पूरे समाज का धन होता है जिसमें से वह अपनी आय प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों से भी ऋण प्राप्त कर सकती है। यदि किसी वर्ष यह देखा जाता है कि सरकार की उपलब्ध आय अनुमानित व्यय से कम है तो इस घाटे को तीन प्रकार से पूरा किया जा सकता है। सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है और इस घाटे को विदेशी ऋणों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अपने नागरिकों से ऋण लेकर अथवा उन पर अधिक कर लगा कर भी सरकार अपनी

प्रायः में वृद्धि कर सकती है। यदि इन मापनों में पर्याप्त आय नहीं मिलती है तो नये नोट छाप कर भी सरकार बजट के घाटे को पूरा कर सकती है। किन्तु एक व्यक्ति को आय बढ़ाने में यह सब मांगेन गटनि नहीं होने हैं इमनिचे उनकी आय प्रायः बेनीच होती है।

(३) एक व्यक्ति अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे जीवन मरदा से सम्पत्तिमान उपयोगिता प्राप्त हो। किन्तु सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में इस उद्देश्य को बहुत कम प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य भी व्यक्तिगत व्यय की भाँति परितन्त्र सामाजिक मन्तुष्टि प्राप्त करना होता है किन्तु इसे कार्यन्वय में लाना बहुत कम सम्भव होता है। जब व्यक्ति के द्वारा व्यय किया जाना है तो वह विभिन्न मरदा में प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना कर सकता है किन्तु सरकारी व्यय के सम्बन्ध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं होता है। सरकार को, भावनावस्था, निगोप हितों की रक्षा करने के हेतु अथवा राजनैतिक दम्पन के कारण प्रायः देश के खर्च करने पड़ जाते हैं जो सम्पत्तिमान उपयोगिता नियम के अनुसार नहीं होते हैं और जिनके कारण सार्वजनिक व्यय में परितन्त्र सामाजिक मन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति नये प्रजातन्त्रीय देशों में अधिक पाई जाती है।

(४) अर्थ-प्रवण्य में निजी दृष्टिकोण सरकारी दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक संकुचित तथा अल्पकाशीन होता है। सरकारें व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक लम्बे समय तक रहती हैं। इमनिचे वे वित्तीय मामलों में अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाती हैं। व्यक्ति, जीवन की अनिश्चितता के कारण केवल निकट भविष्य के बारे में ही सोच सकता है और उमरा अर्थ-प्रवण्य अधिक दीर्घकालीन नहीं होता है। अधिकांश व्यक्ति अधिक निकट भविष्य में आने की नहीं सोच सकते हैं और इसलिये वे भविष्य की वर्तमान की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके विपरीत सरकार स्थाई तथा दीर्घकालीन योजनाएँ बना सकती है और सार्वजनिक व्यय करने समय उसे समाज की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाये रखना पड़ता है। लोक अर्थ-प्रवण्य के अन्तर्गत उन योजनाओं पर भी व्यय करना आवश्यक होता है जिन्हें तुरन्त कोई लाभ नहीं होता है किन्तु दीर्घकाल में वे राष्ट्र को उन्नत तथा शक्तिशाली बनाती हैं। इसी कारण वर्तमान सरकारें नये बन लगाने, सार्वजनिक निर्माण के कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर काफी धन व्यय करती हैं। सरकार को भविष्य के हितों का रक्षक माना जाता है और इसी लिये वह अर्थ-प्रवण्य में दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाती है।

(५) निजी अर्थ-प्रवण्य में गोपनीयता रहती है किन्तु लोक अर्थ-प्रवण्य में प्रचार को अधिक आवश्यक समझा जाता है। एक व्यक्ति सामान्यतया अपनी आय तथा व्यय सम्बन्धी बातें दूसरों को नहीं बतलाता है क्योंकि उसकी साक्ष इसी गोपनीयता पर आधारित होती है। इसके विपरीत सरकारी आय तथा व्यय के बारे में

किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी जाती है और उसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाता है जिससे सामान्य जनता को भी उसका ज्ञान कराया जा सके। सरकारी बजट प्रकाशित किये जाते हैं, जनता को उसकी आलोचना करने का अवसर दिया जाता है तथा उनमें परिवर्तन के लिये सुझाव माँगे जाते हैं। कभी-कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब सरकार को भी अपनी आय तथा व्यय के सम्बन्ध में गोपनीयता रखनी पड़ती है। ऐसा प्रायः युद्ध काल तथा अन्य प्रकार के आपत्ति काल में करना पड़ता है।

(६) निजी तथा सरकारी बजटों में मौलिक भेद पाया जाता है। एक व्यक्ति का बजट यदि बचत दिखलाता है तो वह उस व्यक्ति की दूरदृष्टिता तथा कुशल अर्थ-प्रबन्ध को बतलाता है किन्तु सरकारी बजट में बचत न होना वित्त मन्त्री की अनुमति का प्रतीक है। लोक वित्त में बजट का सन्तुलित होना ही अच्छा माना जाता है और उसमें प्रतिरेक का होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनहित के लिये पर्याप्त व्यय नहीं कर रही है। कभी-कभी तो घाटे के बजट को ही देश के आर्थिक हित में समझा जाता है।

उपरोक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक अर्थ-प्रबन्ध व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध से काफी भिन्न है। यद्यपि दोनों लगभग एक ही प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं किन्तु फिर भी उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है। इसी अन्तर के कारण राजस्व के लिये एक पृथक् शास्त्र की आवश्यकता होती है। दोनों की कार्य-विधि में ही अन्तर नहीं है वल्कि दोनों अलग-अलग दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। निजी अर्थ-प्रबन्ध व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होता है। एक व्यक्ति अपनी आय तथा व्यय का प्रबन्ध इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सके किन्तु सरकार का दृष्टिकोण लाभ प्राप्त करने का नहीं होता है। लोक अर्थ-प्रबन्ध का उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक कल्याण होता है चाहे उस प्राप्त करने में सरकार को हानि हो अथवा लाभ। इस प्रकार निजी तथा लोक अर्थ-प्रबन्ध को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता है।

राजस्व का सिद्धान्त :

राजस्व का उद्देश्य तथा उसे नियमित करने वाला सिद्धांत क्या होना चाहिये, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। प्राचीन समय के सभी अर्थशास्त्री राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं को सीमित रखने के पक्ष में थे और उन्होंने यह बतलाया कि सरकार को कम से कम कर लगाने चाहिये और कम के कम व्यय करना चाहिये। इसी को वे राजस्व का सर्वोत्तम सिद्धान्त मानते थे। जे० बी० से (J. B Say) के अनुसार "अर्थ-प्रबन्ध की वही योजना सबसे उपयुक्त है, जिसमें न्यूनतम व्यय किया जाता है और सब करो में वही बार सबसे अच्छा है, जिसकी मात्रा सब से कम हो।" उस समय यह समझा जाता था कि सरकार के द्वारा कम से कम कर लगाये जाने

चाहिये और कर का भार लोगों में जनरी कर-दान क्षमता के अनुसार बाँटा जाना चाहिये। प्राचीन विचारधारा के अनुसार प्रत्येक घर बुरा समझा जाता था। एक दूसरी धारणा यह थी कि सरकारी व्यय सदैव अनुत्पादक कार्यों के लिये किया जाता है जबकि व्यक्तिगत व्यय उत्पादक कार्यों के लिये होता है। यह दोनों ही विचार दोषपूर्ण थे। सभी घर आवश्यक रूप से बुरे नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से घर हैं जिनमें समाज को लाभ होता है। शराब पर लगाया जान वाला कर, शराब के उपयोग को रोकता है और उससे समाज को वास्तविक लाभ होता है। धायात करो से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि सरकार एक व्यक्ति की अपेक्षा अच्छे उद्देश्यों के लिये व्यय करे। व्यक्ति अपने धन को शराब अथवा घुड़दौड़ आदि पर खर्च करके उसका उपयोग कर सकता है किन्तु यदि उसी धन को गणकार कर के रूप में लेकर उससे बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करनी है अथवा उम्र पुरीदों का भलाई के लिये खर्च करती है तो उससे समाज को उत्पादन क्षमता बढ़ती है। किन्तु सभी करो को अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसे घर हैं जो वास्तव में समाज को हानि पहुँचाते हैं क्योंकि उनका धन को उत्पादन तथा बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सभी सरकारी व्यय अच्छा नहीं होता है अनावश्यक युद्ध पर किया जाने वाला व्यय समाज को बहुत हानि पहुँचा सकता है। कोई घर अच्छा है अथवा बुरा और सरकारी व्यय लाभ पूरा है अथवा नहीं, इसे जानने के लिये हम अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का प्रयोग करना पड़ता है।

राजस्व का सही सिद्धान्त यह है कि सरकार को अपना अर्थ-प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये जिससे समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। राजस्व में हमारा उद्देश्य यह जानना होना चाहिये कि सावर्जनिक आय तथा व्यय से जनता को कितना शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ जितना अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके उतना ही अच्छा है। राज्य की क्रियाओं और उसके अर्थ-प्रबन्ध का आधार यह होना चाहिये कि सरकार जनता की भलाई के लिये होती है और उसकी क्रियाओं तथा व्यय को जाचने के लिये यह देखा जाना चाहिये कि उसने समाज को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कुछ लाभ होता है अथवा नहीं। यदि राजस्व को विज्ञान को एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाना है तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त उसका आधारभूत नियम होना चाहिये और राजस्व के अन्तर्गत की जाने वाली प्रत्येक क्रिया इसी सिद्धान्त के अनुसार की जानी चाहिये। राजस्व का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होना चाहिये। धन को व्यय करते समय, बुरों को एकत्रित करते समय तथा सावर्जनिक ऋणों का प्रबन्ध करने में सरकार को समाज के अधिकतम लाभ का ध्यान रखना चाहिये।

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त :

राजस्व को किस सिद्धान्त के अनुसार चलाया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद रहा है। प्राचीन लेखकों ने न्यूनतम सामूहिक त्याग के

सिद्धान्त (Principle of Least Aggregate Sacrifice) को राजस्व का आधार माना है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं को मितव्ययिता के सिद्धान्त के अनुसार चलाये जाने की बात कही। किन्तु यह दोनों ही सिद्धान्त प्राचीन विचारधारा पर आधारित हैं जब सरकार का कार्य दोन सीमित होता था और राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय को मितव्ययिता पूर्ण नहीं समझा जाता था। अब परिस्थिति बदल चुकी है और इन दोनों में से कोई भी सिद्धान्त राजस्व का आधार नहीं हो सकता है।

वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजस्व का सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त होना चाहिये। इस सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम डा० डाल्टन ने किया। उनके अनुसार सरकारी धाय तथा व्यय से सामूहिक फल के रूप में समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को अपना अर्थ-प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये जिससे समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यह नियम व्यक्तिगत व्यय के अधिकतम सन्तुष्टि नियम का ही एक रूप है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये अपने व्यय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार फैलाना है कि उसे सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो, इसी प्रकार सरकार को भी अपने व्यय में अधिकतम सामाजिक सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये और उसे अपने सम्पूर्ण व्यय को विभिन्न मदों (जैसे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवाओं आदि) पर इस प्रकार बांटना चाहिये कि प्रत्येक पर बिने जाने वाले सीमान्त व्यय से बराबर सामाजिक उपयोगिता प्राप्त हो क्योंकि सभी अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा। यदि यह देखा जाता है कि सुरक्षा पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय हो रहा है और स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागों पर धन की बहुत कमी है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा से थोड़ा व्यय हटाकर शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किया जाना चाहिये, ऐसा करने से सामाजिक लाभ में वृद्धि की जा सकेगी। यदि यह देखा जाता है कि कर इस प्रकार एकत्रित किये जा रहे हैं कि उनसे धन के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है अथवा उनका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है तो ऐसी दशा में कर नीति में परिवर्तन होना चाहिये।

सरकार के द्वारा आय प्राप्त करने अथवा व्यय करने का परिणाम सदा ही क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। जब सरकार कर लगाकर अथवा अन्य विधियों से आय प्राप्त करती है तो क्रय शक्ति जनता से सरकार को हस्तांतरित हो जाती है और जब सरकार द्वारा व्यय किया जाता है तो वही क्रयशक्ति फिर जनता के पास लौट आती है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह उन्ही लोगों के पास लौटे जिनसे कि ली गई थी। इस प्रकार सरकारी धाय तथा व्यय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच क्रयशक्ति को हस्तांतरित करते हैं जिसके कारण धन के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। वह परिवर्तन कहां तक सामाजिक लाभ को बढ़ाते हैं, इसी आधार

पर उनकी उपयोगिता निश्चिन की जाती है। यदि इन परिवर्तनों से सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है तो सरकारी आय तथा व्यय अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुकूल है अन्यथा नहीं।

इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कर की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समाज के ऊपर पहली की अपेक्षा अधिक भार डालती है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक अतिरिक्त व्यय समाज की पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता देता है। करों में वृद्धि लोगों के द्वारा किये जाने वाले त्याग को बढ़ाती है और सरकारी व्यय के बढ़ने से उन्हें घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिये यह आवश्यक है कि करों की और सरकारी व्यय को उसी सीमा तक बढ़ाना चाहिये जहाँ पर कर की एक और इकाई के कारण किया जाने वाला त्याग, व्यय की एक और इकाई में प्राप्त होने वाली उपयोगिता के ठीक बराबर हो। जहाँ पर अतिरिक्त कर के लिये किया जाने वाला त्याग अतिरिक्त व्यय में प्राप्त होने वाली उपयोगिता के साथ सन्तुलित हो जाता है, वही पर सामाजिक लाभ अधिकतम होता है। जब तक करों के लिये किया जाने वाला सीमान्त सामाजिक त्याग कम होता है और व्यय से प्राप्त होने वाली सीमान्त सामाजिक उपयोगिता अधिक, तब तक कर और व्यय दोनों को बढ़ाते रहना चाहिये। किन्तु जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जायें तो उसके पश्चात् करों में अथवा सरकारी व्यय में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये अन्यथा प्राप्त होने वाला सामाजिक लाभ कम हो जायगा। सामाजिक लाभ अधिकतम वही होता है जहाँ पर करों के लिये किया जाने वाला सीमान्त सामाजिक त्याग और सरकारी व्यय से प्राप्त होने वाली सीमान्त सामाजिक उपयोगिता ठीक एक दूसरे के बराबर होत है। इसी को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त कहते हैं।

सार्वजनिक व्यय को उतना ही बढ़ाना चाहिये कि सब दिशाओं में किये जाने वाले व्यय से सीमान्त सामाजिक लाभ बराबर हो और वह अतिरिक्त आय प्राप्त करने के कारण होने वाले सीमान्त सामाजिक त्याग के साथ सन्तुलित हो जाय। केवल ऐसी दशा में ही सार्वजनिक व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। किन्तु करों के सीमान्त त्याग और व्यय की सीमान्त उपयोगिता को सन्तुलित करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। व्यय की सीमान्त उपयोगिता को नापना जितना कठिन है उतना ही करों के सीमान्त त्याग का अनुमान लगाना। हमें देखना तो यह होता है कि राजस्व के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त क्रियाओं का सामूहिक प्रभाव क्या पड़ता है? क्या उनके कारण सामाजिक लाभ अधिकतम होता है अथवा नहीं?

इस सिद्धान्त को कार्यरूप में लाते समय, सामाजिक लाभ को जायने के लिये निम्नलिखित बातों का प्रयोग किया जा सकता है—

(१) समाज की विदेशी आक्रमणों तथा आन्तरिक भगड़ों से सुरक्षा करने की आवश्यकता—समाज को सुरक्षित रखने के लिये जो भी व्यय किया जाता है वह

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुकूल है। सैनिक शक्ति तथा पुलिस दृष्ट्यादि पर किया जाने वाला व्यय सामाजिक लाभ को बढ़ाता है क्योंकि उससे समाज की रक्षा होती है।

सामाजिक लाभ को अधिक दृष्टिकोण से भी नापा जा सकता है। इसके लिये दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये—उत्पादन में वृद्धि तथा धन के वितरण में सुधार।

(२) धन के उत्पादन में वृद्धि—यदि सरकारी व्यय इस प्रकार किया जाता है कि उसमें श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है और धन के उत्पादन में वृद्धि होती है तो वह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुकूल है। उत्पादन व्यवस्था में सुधार करके, माधनों के अपव्यय को कम करके, प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाकर अथवा बेरोजगारी को दूर करके यदि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो इस पर किया जाने वाला सरकारी व्यय सामाजिक लाभ में वृद्धि करता है।

(३) धन के वितरण में सुधार—यदि सरकारी आय प्राप्त करने से तथा उसका व्यय करने में धन के वितरण की असमानताओं को कम किया जाता है तो वे सामाजिक लाभ को बढ़ाती हैं किन्तु यदि इनका परिणाम धन के वितरण की असमानताओं को बढ़ाने का होता है तो इन्हें अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है।

इनके अतिरिक्त इस बात की भी ध्यान में रखना चाहिये कि सरकार भविष्य के हितों की संरक्षक होती है। समाज निरंतर जीवित रहता है इसलिये सार्वजनिक व्यय को करते समय भविष्य के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह भविष्य में प्राप्त होने वाले अधिक सामाजिक लाभ को वर्तमान में मिलने वाले कम सामाजिक लाभ पर प्राथमिकता दे। यदि सार्वजनिक व्यय इस दृष्टिकोण से किया जाता है तो उससे सामाजिक लाभ में वृद्धि होगी।

लोक व्यय

Public Expenditure

सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त का विकास वर्तमान काल में हो हुआ है। प्राचीन अर्थशास्त्री लोक व्यय की वृद्धि के पक्ष में नहीं थे और उनका सरकारी व्यय के सम्बन्ध में एक ही सिद्धान्त था कि, 'उमे जितना कम से कम रखना जाय उतना ही अच्छा है।' सरकार का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सङ्कुचित होने के कारण उस समय लोक-व्यय के सिद्धान्त के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। उन्नीसवीं शताब्दी तक सरकार के कार्यों को कम से कम रखने का प्रयत्न किया गया। केवल शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य समझा जाता था। एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा उनके साथियों ने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का विरोध किया। यह समझा जाता था कि व्यक्ति सरकार की अपेक्षा धन का व्यय अधिक अच्छी प्रकार से करता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय को कम से कम रखने की बात नहीं जाती थी।

प्रजातन्त्रीय शासन तथा कल्याणकारी राज्यों के विकास के साथ-साथ सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने लगी और उसके साथ लोक व्यय का महत्त्व भी बढ़ता गया। जर्मन अर्थशास्त्रियों ने संबंधित व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध किया और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बतलाया। वॉगनर (Wagner) के द्वारा 'सरकार की बढ़ती हुई शक्तियों' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने बतलाया कि सरकार के कार्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। कुछ कार्य सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से किये जाने चाहिये क्योंकि उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, नि:शुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आदि कुछ इसी प्रकार के कार्य हैं। इन विचारों के परिणामस्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सरकार के कार्यों में व्यापक वृद्धि हुई। बीसवीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का सिद्धांत कमजोर पड़ गया और यह समझा जाने लगा कि सरकार का कार्यक्षेत्र केवल शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे विभिन्न प्रकार की आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं का प्रदत्त भी करना चाहिये।

सरकार के इस बढ़ते हुये उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पड़ी और धीरे-धीरे उसका महत्त्व बढ़ने लगा।

वर्तमान विचारधारा के अनुसार सरकार को आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण योग देना चाहिये। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न प्रकार की समाज सेवाओं का प्रबन्ध करे तथा उन उद्योगों की स्वयं चलाये जिनको व्यक्तिगत आधार पर न चलाया जा सकता हो अथवा जिन्हे व्यक्तियों के हाथों में छोड़ना समाज की दृष्टि से उचित न हो। इस प्रकार आधुनिक सरकारों के कार्यों में काफी वृद्धि हो गई है और वे निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। इन बढ़ते हुये कामों को पूरा करने के लिये सार्वजनिक व्यय भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आजकल यह समझा जाता है कि सार्वजनिक व्यय यदि ठीक प्रकार से किया जाय तो उससे समाज को बहुत लाभ हो सकता है। प्रो० कौन्स (Keynes) के अनुसार सार्वजनिक व्यय ही एक साधन है जिसके द्वारा पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय किसी समाज के लिये बुरा नहीं है बल्कि वह उसकी आर्थिक नीति का एक भाग होना चाहिये।

सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिये किया जाता है। सर्वप्रथम सरकार को बहुत से ऐसे कार्य करने हाते हैं जिन्हे पूरा करना प्रारम्भ काल से ही सरकार का वर्तव्य रहा है। इन्हे सरकार के प्रारम्भिक कार्य कहा जा सकता है। इनके अन्तर्गत शान्ति तथा सुरक्षा की व्यवस्था करना, न्याय का प्रबन्ध करना तथा ऋण मेवाएँ आदि आ जाते हैं। वर्तमान सरकारें देश की रक्षा के लिए अपनी आय का काफी बड़ा भाग खर्च करती हैं। आन्तरिक शान्ति को बनाए रखने तथा न्याय का प्रबन्ध करने पर भी सरकार के व्यय में काफी वृद्धि हुई है। बहुत-सा रुपया सरकार को सार्वजनिक ऋणों के प्रबन्ध तथा उन पर सूद आदि के भुगतान के लिये खर्च करना पड़ता है। इन प्रारम्भिक कार्यों के अतिरिक्त भी सरकार को कुछ अन्य प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिनकी उत्पत्ति आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ-साथ हुई है। इसके अन्तर्गत बहुत सी प्रकार की समाज सेवाएँ आ जाती हैं जिनका प्रबन्ध करना सरकार के लिये अनिवार्य हो गया है। वर्तमान सरकारों का काफी बड़ा व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य प्रकार की समाज सेवाओं का प्रबन्ध करने पर किया जाता है। आर्थिक विकास की आवश्यकता ने सरकारों के लिये यह भी जरूरी कर दिया है कि वे सार्वजनिक व्यवसायों का विकास तथा प्रबन्ध करें जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाएँ, यातायात, सड़क-ब्राह्मण, सिंचाई तथा सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले उद्योग आ जाते हैं।

लोक व्यय में वृद्धि के कारणः

वर्तमान काल में सार्वजनिक व्यय तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सभी देशों में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसके कारण सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कार्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि सरकार को केवल बाह्य तथा

ग्रान्तरिक भय से ही देश की रक्षा नहीं करती है बल्कि उसे अपनी कल्याणकारी सेवाओं का विनाश करके लोगों के जीवन को भी मुधारना चाहिये। वर्तमान काल में बीमार, वृद्ध, निर्यन्त तथा बरार लोगों की देखभाल करना समाज का कर्तव्य समझा जाता है। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिये प्रारम्भिक आवश्यकताओं—पर्याप्त भोजन, रहने का प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का उचित प्रबन्ध करे। सरकार की डम बटती हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये अधिकाधिक माना में लोकव्यय किया जा रहा है। लोकव्यय के बढ़ने की यह प्रवृत्ति विद्वद्वाची है। विगत वर्षों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

✓ (१) क्षेत्र तथा जनसंख्या में वृद्धि (Increase in Area and Population)—सार्वजनिक व्यय के बढ़ने का मुख्य कारण राष्ट्रों के क्षेत्र तथा जनसंख्या में वृद्धि होना है। किसी भी सरकार का व्यय देश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की मात्रा पर निर्भर होता है। राष्ट्र का क्षेत्रफल जितना छोटा होना है तथा जनसंख्या जितनी कम होती है उतना ही वह देश की सरकार को कम व्यय करना पड़ता है। आधुनिक काल में राज्यों के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण उनका सुरक्षा आदि पर व्यय बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त सभी देशों की जनसंख्या पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है और वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। जिसके कारण सरकार को अधिक लोगों के लिये सामाजिक सेवाओं का प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसी दशा में सार्वजनिक व्यय का तेजी से साथ बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ सरकार का प्रति व्यक्ति भी बढ़ता है।

(२) सुरक्षा तथा युद्ध का बढ़ता दृष्टा व्यय (Increased Expenditure on Defence and Wars)—वर्तमान सरकारों का सुरक्षा सम्बन्धी व्यय काफी तेजी से साथ बढ़ रहा है। विश्वव्यापी युद्धों का बार-बार होना तथा युद्ध की सम्भावना के निरन्तर बने रहने के कारण सभी देशों को अपनी रक्षा के लिये काफी बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिये तथा दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में सेनाओं तथा युद्ध सामग्री का प्रबन्ध करते हैं। छोटे राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से सैनिक व्यय करना पड़ता है। तटस्थ देशों को भी सैनिक दृष्टि से हर समय तैयार रहना होता है जिस से कि कोई उन पर आसानी से आक्रमण न कर सके। इस प्रकार सभी राष्ट्रों के रक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी व्यय में भारी वृद्धि हुई है। आज के युद्ध काफी महँगे पड़ते हैं। नये नये हथियारों के विकास ने युद्ध का रूप ही बदल दिया है जिसके कारण वर्तमान युद्धों पर असमीमित माना में व्यय किया जाता है।

(३) कल्याणकारी सेवाएँ (Welfare Activities)—आजकल सरकार को आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण का साधन माना जाता है। यह समझा जाने लगा है

वि लोक व्यय के द्वारा सरकार बहुत सी आर्थिक तथा सामाजिक सुराईयों को दूर कर सकती है। समाजवादी प्रवृत्तियों के कारण सरकार को जनता के स्वास्थ्य तथा शिक्षा की व्यवस्था, सस्ता खाना तथा मकान, निशुल्क डाक्टरों सहायता, बुढ़ापे की पेंशन, बेकारी का भत्ता तथा अन्य प्रकार की वित्तीयकारी सेवाओं का प्रवर्धन करना होता है। इन सब सामाजिक सेवाओं पर सरकार का व्यय बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है।

(४) आर्थिक विकास तथा नियोजन (Economic Development and Planning) — वर्तमान समय में आर्थिक विकास को सरकार की जिम्मेदारी समझा जाने लगा है और इसके लिये बहुत सी सरकारें प्रयत्नशील हैं। हम में नियोजन की सफलता को देखकर अल्पविकसित देशों में यह अनुभव किया जाने लगा है कि वे भी आर्थिक नियोजन के द्वारा अपने रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। बहुत से देशों में आर्थिक विभास में लिये 'बड़ी-बड़ी योजनाएँ' बनाई जा रही हैं जिन पर सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। कृषि, उद्योग तथा यातायात आदि के विकास पर सार्वजनिक व्यय बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है।

(५) राष्ट्रीय आय तथा रहन-सहन के स्तर में वृद्धि (Rise in National Income & Standard of Living) — लगभग सभी देशों में प्राकृतिक सधनों के पूर्ण शोषण के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में धन पैदा किया जा रहा है। कृषि तथा उद्योग दोनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है जिसके कारण सभी देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। पहले की अपेक्षा अब लोगों में अधिक बरदान क्षमता है और लोक आय बढ़ती जा रही है। लोक आय में वृद्धि ने भी काफी सीमा तक लोक व्यय को प्रोत्साहित किया है।

(६) प्रजातन्त्रवाद का भार (Incidence of Democracy) — प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली के विकास के साथ-साथ लोक व्यय में काफी वृद्धि हुई है। प्रजातन्त्रीय प्रणाली राजनैतिक दलों पर आधारित होती है। इनमें से प्रत्येक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिये वह लोक व्यय के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना चाहता है। विभिन्न राजनैतिक दल सरकार से सार्वजनिक भत्ताई के कामों पर अधिक से अधिक व्यय करने की मांग करते रहते हैं। प्रजातन्त्रीय प्रणाली के कारण सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा आदि पर अधिकाधिक व्यय करना पड़ता है क्योंकि इसके बिना वे जनता को सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकार के सार्वजनिक कार्यों में रहन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की वृद्धि हुई है।

(७) नागरिक प्रशासन के व्यय में वृद्धि (Increasing Civil Expenditure) — लोकतन्त्रीय संस्थाओं के विकास के साथ-साथ सरकार को चुनाव, राज्य सभाओं, मन्त्रिमण्डलों तथा विभिन्न प्रकार की समितियों पर काफी व्यय करना पड़ता है। प्रशासन सम्बन्धी व्यय के बढ़ने का एक अन्य कारण सरकार के कार्यों में वृद्धि होना

है जिन्हें पूरा करने के लिये एक विस्तृत प्रशासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय पर ठीक नियन्त्रण न होने के कारण बहुत सा धन बेकार व्यय हो जाता है। निरन्तर बढ़ता हुआ मूल्य स्तर भी प्रशासन व्यय में वृद्धि का कारण है। सरकार को बार-बार अपने कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है जिसके कारण सरकारी व्यय बढ़ जाता है। मूल्य स्तर ऊँचा होने पर सरकार का व्यय इसलिये भी बढ़ जाता है क्योंकि उसे सभी सामान बढ़े हुये मूल्यों पर खरीदना पड़ता है।

उपरोक्त सभी कारणों से सार्वजनिक व्यय में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और वर्तमान विचारधारा के अनुसार इसे समाज के लिए अच्छा समझा जाता है। किन्तु फिर भी लोक व्यय को किसी भी सीमा तक बढ़ने देना उचित नहीं है। लोक व्यय को कहाँ तक बढ़ने दिया जाय या उसकी क्या सीमा होनी चाहिये, अर्थात् राष्ट्रीय आय का अधिक से अधिक कितना प्रतिशत लोक व्यय होना चाहिये, इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के किसी निश्चित प्रतिशत को लोक व्यय की सीमा नहीं कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के लोक व्यय की मात्रा वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। देश की जनसंख्या, आर्थिक विकास की स्थिति, सरकार के प्रति जनता का विश्वास, लोगों की करदान क्षमता, सरकार के उद्देश्य तथा कर्तव्य आदि अनेक बातों का लोक व्यय की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना समाज के लिये लाभपूर्ण हो सकता है किन्तु एक सीमा के पश्चात् यदि उसे बढ़ाया जाता है तो वह सामाजिक लाभ को कम कर सकता है। सार्वजनिक व्यय भी 'अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त' (Theory of Maximum Social Advantage) के अनुसार किया जाना चाहिये। लोक व्यय को उमी सीमा तक बढ़ाना चाहिये जहाँ तक कि उसमें वृद्धि करने से सामाजिक लाभ बढ़ता हो। डॉ० डाल्टन के अनुसार, "सार्वजनिक व्यय को वहाँ तक बढ़ाना चाहिये जहाँ पर सब दिशाओं में विय जाने वाले लोक व्यय से प्राप्त सीमान्त सामाजिक लाभ सब प्रकार के तरीकों से अतिरिक्त आय इकट्ठा करने से उत्पन्न सीमान्त सामाजिक अनुपयोगिता अथवा कष्ट के ठीक बराबर हो जाय और उसके साथ सन्तुलित हो जाय।"¹

लोक व्यय के सिद्धान्त

लोक व्यय को नियन्त्रित करने का सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिये कि जो भी व्यय किया जाय उससे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में

1 "Public expenditure should be carried just so far that the marginal social advantages of expenditure in all directions are equal, and just balance the marginal social disadvantages of all methods of raising additional public incomes."

—Dalton

अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) के सिद्धान्त के अनुसार ही लोक व्यय को सामान्यतः नियंत्रित किया जाना चाहिये। व्यवहारिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए जा सकते हैं जिनका पालन सरकार को लोक व्यय करते समय करना चाहिये। फिन्डले शिर्राज (Findlay Shirras) ने लोक व्यय के निम्नलिखित नियम बतलाये हैं—

(१) लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit) :—इस सिद्धान्त के अनुसार लोक व्यय सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिये किया जाना चाहिये। किसी विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर इस प्रकार का व्यय नहीं होना चाहिये। लोक व्यय को इस प्रकार करना चाहिये कि उससे समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सक्षेप में सार्वजनिक व्यय 'अधिकतम सामाजिक लाभ' के सिद्धान्त के अनुसार किया जाना चाहिये। रुपये का व्यय जनहित को बढ़ाने के लिए होना चाहिये और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के सामाजिक लाभ प्राप्त होने चाहिये जैसे अधिक उत्पादन, समाज की रक्षा, आय के वितरण की असमानता को दूर करना इत्यादि। विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय से प्राप्त लाभ की तुलना करके सार्वजनिक व्यय को विभिन्न प्रकार के कामों पर ठीक से बाँटा जाना चाहिये। निकलसन (Nicholson) के अनुसार 'उपयोगितावादी सिद्धान्त के आधार पर लोक व्यय का आदर्श तब प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक मद पर किए जाने वाले सीमान्त व्यय से प्राप्त सामाजिक उपयोगिता बराबर हो।'²

(२) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy) :—इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को अपना व्यय करते समय मितव्ययिता से काम लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके बेकार के खर्च से बचना चाहिये। किसी भी व्यय की मद पर सरकार को उसमें अधिक व्यय नहीं करना चाहिए जितना कि उस पर आवश्यक है। करदाताओं से प्राप्त आय को लापरवाही से खर्च नहीं किया जाना चाहिये। सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता के सिद्धान्त का विशेष महत्व है क्योंकि सरकारी कर्मचारी दूसरों के धन का व्यय करते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में उनका लापरवाह होना स्वाभाविक है। मितव्ययिता प्राप्त करने के लिये खर्च के दोहराव से बचना चाहिये तथा बेकार के खर्चों को नहीं होने देना चाहिये। अव्यय को रोकने के लिये लोक व्यय पर तथा सरकारी कर्मचारियों पर पूरा नियन्त्रण रहना चाहिये।

सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उससे समाज की उत्पादन शक्ति का विकास हो। उत्पादन शक्ति तथा बचत करने की क्षमता पर इस का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। लोक व्यय के परिणामस्वरूप भविष्य में आय

2 "The ideal of public expenditure on the utilitarian principle would be attained when the public utility of the marginal expenditure in each case is equal."

—Nicholson.

बटनी चाहिये, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। लोक व्यय का वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बीच ठीक ठीक बँटवारा होना चाहिये। यदि लोक व्यय का उत्पादन अब्बवा लोगों की वचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह मितव्यायिता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।

(३) स्वीकृति का सिद्धांत (Canon of Sanction) :—इस सिद्धान्त के अनुसार व्यय करने वाले अधिकारियों को व्यय करने से पूर्व उचित स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये जिससे की लोक व्यय पर ठीक ठीक नियन्त्रण रखा जा सके। प्रत्येक सरकारी सत्ता को एक सीमा तक व्यय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये किन्तु उससे अधिक व्यय करने के लिये पार्लियामेंट अथवा अन्य उच्चतम सत्ता से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिये। सार्वजनिक धन के बेकार व्यय को रोकने के लिये ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। व्यय बजट में पूर्व निश्चित रकम के अनुसार किया जाना चाहिये और समुचित सत्ता से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई व्यय नहीं होना चाहिये। पूर्व स्वीकृति के साथ-साथ लोक व्यय का लेखा-परीक्षण (Auditing) भी आवश्यक है। सभी प्रकार के सरकारी व्यय के खातों का वार्षिक परीक्षण होना चाहिये तथा इस बात की जांच भी की जानी चाहिये कि धन का अनुचित प्रयोग तो नहीं किया गया है।

(४) आधिक्य का सिद्धांत (Canon of Surplus) —इस सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिये कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Financing) की आवश्यकता न पड़े। व्यय की भाँति सरकार को भी अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिये। जहाँ तक संभव हो सके सरकार को अपना बजट समुचित रखना चाहिये। अच्छा यो यह है कि उसमें कुछ आधिक्य (Surplus) को बनाये रखा जाय। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रतिवर्ष कोई बहुत बड़ा आधिक्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये क्योंकि ऐसा बजट सार्वजनिक हित में नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि निरन्तर घाटे से बचा जाय। फिण्डले शिराज के अनुसार मनुनिन बजट ही सबसे अच्छा है किन्तु वे यह नहीं कहते कि सरकार को कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिये। उनका अभिप्राय यह है कि उत्पादक कार्यों के लिये ही उधार लिया जाना चाहिये तथा सरकार में ऋणों का भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिये।

(५) लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity) —सार्वजनिक व्यय में लोच का गुण होना भी आवश्यक है। लोच से अभिप्राय यह है कि लोक व्यय में आवश्यकता के अनुसार घटने तथा बढ़ने की क्षमता होनी चाहिये। जब सरकार की आय कम हो जाय तो लोक व्यय को कम करना संभव होना चाहिये। इसी प्रकार अच्छे समय में जब सरकार की आय बढ़ रही हो तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना संभव होना चाहिये। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार घटने बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। यदि सार्वजनिक व्यय का स्तर इतना निश्चित हो जाता है

कि उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है तो असामान्य परिस्थितियों में काफी कठिनाई हो सकती है।

उपरोक्त गिद्धांतों के अतिरिक्त भी कुछ और बातें हैं जिन्हें लोक व्यय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये—(i) सार्वजनिक व्यय को व्ययनिगम व्यय का स्थान नहीं लेना चाहिये (ii) सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिये लोगों की आय का बहुत बड़ा भाग नहीं लिया जाना चाहिये (iii) केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा किये जाने वाले व्यय में दोहरापन नहीं होना चाहिये। (iv) लोक व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि उसका धन के उत्पादन तथा वितरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

लोक व्यय का वर्गीकरण :

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा लोक व्यय का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। उद्देश्यों की भिन्नता के कारण यह वर्गीकरण एक दूसरे से काफी भिन्न है। कुछ एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

(१) प्लेहन (Plehan) ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण उस लाभ के आधार पर किया है जो समाज को विभिन्न प्रकार के व्यय से प्राप्त होता है। उनके अनुसार लोक व्यय चार प्रकार का हो सकता है। (i) सामूहिक लाभ के लिये किया जाने वाला व्यय। सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय इस प्रकार का है क्योंकि उसमें समाज के सभी लोगों को लाभ होता है। (ii) ऐसा व्यय जिसमें किसी वर्ग विशेष को लाभ हो सकता है किन्तु जिसे सामान्य लाभ के लिये ही समझा जाना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को इस व्यय से लाभ होता है उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं होती है। गरीबों की भलाई के लिए किया जाने वाला व्यय इस वर्ग के अन्तर्गत आता है। (iii) वह लोक व्यय जिससे एक साथ कुछ लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होता हो तथा शेष लोगों को सामान्य लाभ मिलता हो। न्याय की व्यवस्था पर किया जाने वाला इसी प्रकार का व्यय है। (iv) केवल कुछ लोगों को विशेष लाभ पहुँचाने के लिए किया जाने वाला व्यय जैसे राजकीय उद्योगों पर होने वाला व्यय।

उपरोक्त वर्गीकरण बहुत ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकार के लोक व्यय में सामूहिक लाभ का अंश होना चाहिये। प्राप्त होने वाले लाभ को वर्गीकरण का आधार बनाना बहुत कठिन है। निकलसन (Nicholson) के अनुसार यह सभी प्रकार के लोक व्यय सामूहिक लाभ प्रदान करते हैं किन्तु साथ ही वे कुछ व्यक्तियों, वर्गों तथा स्थानों को विशेष लाभ भी पहुँचाते हैं। सुरक्षा से सामूहिक लाभ होता है किन्तु उससे व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है। निर्धन व्यक्तियों पर किए जाने वाले व्यय से व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ दोनों ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं कारणों से लाभ को वर्गीकरण का आधार बनाना उचित नहीं है।

(२) निकलसन (Nicholson) ने सरकारी सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाली आय को आधार बना कर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। उनके

अनुसार लोक व्यय को इन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(i) व्यय जिसके बदले में कोई प्रत्यक्ष आमदनी प्राप्त नहीं होती है जैसे युद्ध पर किया जाने वाला व्यय अथवा गरीबों तथा पीड़ितों की सहायता में लगाया जाने वाला धन (ii) व्यय जिससे सरकार को कोई प्रत्यक्ष आमदनी तो नहीं होती है किन्तु उससे लोक आगम को अप्रत्यक्ष लाभ होता है। निःशुल्क शिक्षा पर होने वाला व्यय इस प्रकार का है। (iii) व्यय जिसमें कुछ प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। सशुल्क शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय इसके अन्तर्गत आयेगा। (iv) व्यय जिससे पूरी आमदनी प्राप्त होती है जैसे सार्वजनिक सेवाओं, डाक, तार, रेल आदि पर किया जाने वाला व्यय।

यह वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय के भेद को नहीं बतलाया गया है।

(३) ऐडम्स (Adams) ने लोक आगम का एक अन्य वर्गीकरण दिया है। उन्होंने सरकार के कार्यों को वर्गीकरण का आधार बनाया है। उनके अनुसार लोक व्यय निम्न प्रकार का हो सकता है—(i) रक्षा सम्बन्धी कार्यों पर किया जाने वाला व्यय। इसके अन्तर्गत सेना, पुलिस तथा न्यायालयों पर होने वाला व्यय आता है जिसमें बाहरी आक्रमणों से रक्षा होती है तथा आन्तरिक शान्ति बनी रहती है। (ii) धार्मिक सम्बन्धी कार्यों पर होने वाला व्यय जैसे गणेशार तथा उद्योग के विकास के लिये व्यय, (iii) विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर व्यय। इस वर्गीकरण को सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि लोक व्यय की विभिन्न मदों को इन वर्गों के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है क्योंकि एक वर्ग में आने वाले कार्यों को दूसरे वर्ग से स्पष्टतया भ्रम नहीं किया जा सकता है।

(४) फिन्डले शिर्राज (Findlay Shirras) ने लोक व्यय का सबसे अच्छा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार लोक व्यय को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(i) प्रारम्भिक (Primary) तथा (ii) गौण (Secondary) प्रारम्भिक व्यय सरकार का वह खर्चा होता है जिसे करना उसके लिये अनिवार्य होता है जैसे सुरक्षा, शान्ति तथा न्याय की व्यवस्था, नागरिक प्रशासन का व्यय तथा नदियों को चुकाने से सम्बन्धी व्यय। गौण व्यय के अन्तर्गत सरकार का सामाजिक व्यय आ जाता है जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि पर किया जाने वाला है। यद्यपि यह वर्गीकरण अन्य वर्गीकरणों से अधिक सन्तोषजनक है किन्तु इसमें भी विभिन्न प्रकार के व्यय को असंग-अलग वर्गों में रखना काफी कठिन है।

उपरोक्त वर्गीकरणों के अतिरिक्त जे एस मिल (J S Mill), रोस्चे (Roscher) तथा डाल्टन (Dalton) आदि विद्वानों ने लोक व्यय का वर्गीकरण अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। सार्वजनिक व्यय को उत्पादन की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(अ) उत्पादन (Productive) तथा (ब) रक्षक (Protective)। सरकार का उत्पादन व्यय वह होता है जो ऐसी मदों पर किया जाता है जिससे तुरन्त या कुछ समय पश्चात् समाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती

है। इस प्रकार के व्यय से उन व्यक्तियों, व्यवसायी तथा क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि होती है जिनके लाभ के लिये यह व्यय किया गया है। सरकार का कुछ व्यय ऐसा भी होता है जिससे समाज की उत्पादन क्षमता में तो कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है किन्तु उससे व्यक्तियों तथा उद्योगों की किसी आकस्मिक कठिनाई प्रत्यक्ष सहायता से रक्षा की जाती है। इस प्रकार के लोक व्यय की रक्षात्मक व्यय कहा जा सकता है।

लोक व्यय के प्रभाव :

लोक व्यय समाज के आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इन प्रभावों को तीन वर्गों में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है—

(अ) धन के उत्पादन पर प्रभाव, (ब) धन के वितरण पर प्रभाव, (स) अन्य प्रभाव।

सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव :

प्राचीन विचारधारा के अनुसार सार्वजनिक व्यय उत्पादन प्रत्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण में कोई वृद्धि नहीं कर सकता है, इसलिये उन्होंने लोक व्यय को बच से बच रखने की बात कही। यह समझा जाता था कि सार्वजनिक व्यय में जितना धन खर्च होता है, वह राष्ट्रीय आय से कम हो जाता है। यह गलत विचारधारा महान आर्थिक मंदी (Great Economic Depression) के समय तक प्रचलित रही। किन्तु उसके पश्चात् सार्वजनिक व्यय के महत्व को ठीक प्रकार समझने का प्रयत्न किया गया और यह अनुभव किया जाने लगा कि लोक व्यय लोगों की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करके उनके कल्याण में वृद्धि कर सकता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार लोक व्यय उत्पत्ति की कुल मात्रा तथा उसकी प्रवृत्ति दोनों को प्रभावित करता है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना होता चाहिये।

यद्यपि सार्वजनिक व्यय उत्पादन में वृद्धि कर सकता है किन्तु वर्तमान सरकारों के द्वारा किये जाने वाले व्यय का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कल्याण को नहीं बढ़ाता है। समाजों तथा शासनों के सग्रह पर किया जाने वाला व्यय इस प्रकार के व्यय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रायः यह समझा जाता है कि इस प्रकार का व्यय आर्थिक दृष्टि से बेकार है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कल्याण में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है। किन्तु फिर भी सुरक्षा तथा युद्ध आदि पर किये जाने वाले व्यय को बेकार का व्यय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यदि इस प्रकार का व्यय युद्ध को रोकने में सफल हो जाता है तो देश युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई से बच जायगा। वैसे भी इस प्रकार का व्यय देश में शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करने आर्थिक विकास के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करता है। किन्तु इस प्रकार का व्यय बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जाना चाहिये। यदि सरकार के अधिकांश साधन इस दिशा में लगाये जाते हैं तो उससे लोगों का आर्थिक कल्याण कम होगा।

सार्वजनिक व्यय के उत्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है—

(१) काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव ।

(२) काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव ।

(३) विभिन्न व्यवसायों तथा क्षेत्रों के बीच आर्थिक साधनों के वितरण पर प्रभाव ।

(१) काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव (Effects on the Capacity to Work and Save) —सार्वजनिक व्यय लोगों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करके उनकी काम करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। लोगों की कार्यकुशलता के बढ़ने के साथ-साथ उनकी आमदनी भी बढ़ती है जिसके कारण उनकी बचत करने की शक्ति में वृद्धि होती है। सरकार के द्वारा बहुत सा ऐसा व्यय किया जाता है जो लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने वाला होता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है भयवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय लोगों के पास किस रूप में पहुँचता है। यदि सरकार लोगों को नकद अनुदान के रूप में खर्चा देती है तो उससे कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि वह लोगों के लिये काम करने की आवश्यकता को कम करके उन्हें आलसी तथा अप्रव्ययी बना सकता है। इस प्रकार के व्यय से काम करने तथा बचत करने की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है बल्कि वह किसी सीमा तक कम होती है। यही धन यदि सरकार नकद रूप में न देकर उनके लिये स्कूल, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि का प्रयत्न करती है तो उससे लोगों की कार्य-कुशलता निश्चित रूप से बढ़ेगी जिसके कारण उनकी काम करने तथा बचत करने की शक्ति बढ़ जायगी। इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय का उत्पत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लगभग सभी प्रकार का लोक व्यय लोगों की बचत करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह धन जिस व्यक्ति से कर के रूप में लिया जाता है उसकी बचत करने की शक्ति कम हो जाती है किन्तु जिसकी भलाई के लिये उसका व्यय किया जाता है उसकी बचत करने की क्षमता में वृद्धि होती है।

(२) बचत करने तथा काम करने की इच्छा पर प्रभाव (Effects on the Will to Save and Work) —लोक व्यय का प्रभाव लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर भी पड़ता है। सार्वजनिक व्यय से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ की आशा, काम करने तथा बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है। यदि भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ बिना किसी शर्त के मिलते हैं और उनका लोगों के भावी वार्म तथा उनकी बचत से कोई सम्बन्ध नहीं होता है तो इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय से लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा में किसी प्रकार की वृद्धि होने की आशा नहीं की जा सकती है। युद्ध, पैन्शन तथा युद्ध सम्बन्धी धन पर दिया जाने वाला मुँह इसी प्रकार का लोक व्यय है। निश्चित तथा बिना शर्त सरकार से प्राप्त होने वाला धन लोगों की काम करने तथा बचत करने की

इच्छा को किसी प्रकार भी नहीं बढ़ाता है। इसके विपरीत लोगों की ग्रामदनी को माग वेलोच होने की दशा में वह उनकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा को कम कर सकता है।

सरकार से प्राप्त होने वाले सभी अनुदान अथवा सहायता लोगों को बिना शर्त नहीं मिलते। लोक व्यय से प्राप्त होने वाले बहुत से लाभ ऐसे होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। बीमारी अथवा अनिश्चित बेरोजगारी की दशा में मिलने वाले लाभ इसी प्रकार के होने हैं क्योंकि उन्हें व्यक्ति नियमित रूप से प्राप्त नहीं कर सकता बल्कि कुछ विशेष दशाओं में ही उसे यह लाभ मिल सकते हैं। लोक व्यय से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के आर्थिक तथा कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात् मिलने वाले लाभ लोगों की वर्तमान काम करने तथा बचत करने की शक्ति कम नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुदान की मात्रा निश्चित नहीं है और वह लोगों के दाय किये जाने वाले काम तथा बचत की मात्रा के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार का सार्वजनिक व्यय लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा को बढ़ावेगा। इसके विपरीत यदि अनुदान की मात्रा काम तथा बचत की मात्रा में वृद्धि होने पर घटती है तो वह निश्चित रूप से लोगों की काम तथा बचत करने की इच्छा को कम करने वाला होगा।

(३) लोक व्यय तथा आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण (Effects on the Division of Economic Resources)—सार्वजनिक व्यय के कारण समाज में आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण हो सकता है। सरकार के द्वारा बहुत सा ऐसा व्यय किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक साधन कुछ व्यवसायों तथा क्षेत्रों में हट कर अन्य व्यवसायों तथा क्षेत्रों में लग जाने हैं। साधनों का यह पुनर्वितरण उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करके समाज के लिये लाभदायक हो सकता है। जब सरकार कुछ उद्योगों की सुरक्षा, अनुदान अथवा सहायता देती है या स्वयं कुछ उद्योग स्थापित करती है तो श्रम तथा पूँजी अन्य उद्योगों में हट कर इन उद्योगों में आने लगते हैं। इस पुनर्वितरण से कुछ विंश प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि समाज के साधनों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में न लगा कर भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दिया जाय। पूँजीवादी व्यवस्था में भविष्य की आवश्यकताओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और अधिकांश साधनों का प्रयोग वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। लोक व्यय के द्वारा इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच आर्थिक साधनों का उचित रूप से बटवारा किया जा सकता है।

(४) सार्वजनिक व्यय का धन के वितरण पर प्रभाव (Effects of Public Expenditure on the Distribution of Wealth)—लोक व्यय समाज में धन के वितरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि व्यय इस प्रकार किया जाता है कि उससे निर्धन तथा कम आय वाले लोगों को लाभ होता है और इस व्यय

को पूरा करने के लिये आमदनी अमीरों पर कर लगा कर प्राप्त की जाती है तो इस प्रकार के लोक व्यय की प्रवृत्ति धन के वितरण की असमानताओं को कम करने की होती है। समाज सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय का यही प्रभाव होता है क्योंकि उसका लाभ अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों को अधिक मिलना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि पर किया जाने वाला व्यय गरीब लोगों की आमदनी को बढ़ा कर समाज में धन की असमानताओं को दूर करता है और गरीब तथा अमीरों के बीच की अधिक खाई को कम करता है। इसके अतिरिक्त सरकार लोगों को अनुदान के रूप में धन का सीधा हस्तान्तरण करके उनकी आय में वृद्धि कर सकती है। यह अनुदान प्रगामी (Progressive), प्रतिगामी (Regressive) तथा अनुपातिक (Proportional) हो सकता है। यदि अनुदान की रकम लोगों की आय कम होने के साथ बढ़ती है तो उसे प्रगामी अनुदान कहा जायगा और यदि आय कम होने के साथ अनुदान भी कम होता है तो वह प्रतिगामी है। यदि आय के निश्चित अनुपात में अनुदान दिया जाता है तो वह अनुपातिक अनुदान होता है। अनुदान जितना अधिक प्रगामी होगा उतनी ही जल्दी वह धन की असमानताओं को दूर करेगा। समाज में धन का अधिक व्यापक वितरण करने के लिए सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अनुसम अधिक म अधिक प्रगामी होने चाहियें तथा राज्य को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिये कि उसका अधिक से अधिक लाभ निर्धन लोगों को हो।

लोक व्यय के अन्य प्रभाव :

समाज में वृत्तिहीनता (Unemployment) तथा रोजगार स्तर की अस्थिरता के दोषों को दूर करने के लिये भी सार्वजनिक व्यय का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार लोक व्यय आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) तथा पूर्ण रोजगार (Full Employment) प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रोजगार के स्तर की अस्थिरता पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक विशेषता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में रोजगार के स्तर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है। मूल्य-वृद्धि काल में अधिक क्रियायें इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि समाज लगभग पूर्ण वृत्ति (Full Employment) की अवस्था पर पहुँच जाता है किन्तु यह समृद्धि काल बहुत थोड़े समय के लिये रहता है। कुछ समय पश्चात् मूल्य गिरने लगते हैं और उत्पादन व रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। समाज में बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोग आर्थिक संकट में फँस जाते हैं। रोजगार की मात्रा में होने वाले इन परिवर्तनों को लोक व्यय के द्वारा काफी सीमा तक दूर किया जा सकता है और समाज में आर्थिक स्थिरता कायम की जा सकती है।

सरकार अपने व्यय के द्वारा थम की भाग को अधिक नियमित तथा स्थाई करके वृत्तिहीनता को कम कर सकती है। आर्थिक स्थिरता स्थापित करने तथा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में सार्वजनिक व्यय निम्न प्रकार से सहायता दे सकता है—

(१) सरकार विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिये अपनी भाग को स्थिर रख कर रोजगार स्तर में होने वाले परिवर्तनों को कम कर सकती है। सरकार को

चाहिये कि वह अपने आधीन काम करने वाले कर्मचारियों की मांग को स्थिर रखे और उभरे अनावश्यक गिरावट न आने दे ।

(२) सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का रोजगार व्यक्तिगत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार के साथ इस प्रकार सम्बन्धित किया जा सकता है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में होने वाली रोजगार की कमी को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि के द्वारा पूरा किया जा सके । सरकार को अपना माध्यम ब्यय विभिन्न समूह में इस प्रकार बांटना चाहिये कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिये सरकारी मांग व्यक्तिगत मांग में विपरीत दशा में बदले । सार्वजनिक व्यय के उचित वितरण के द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

(३) सार्वजनिक व्यय के द्वारा आर्थिक मन्दो (Economic Depression) के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को कम किया जा सकता है । प्रो० कीन्ज (Keynes) के अनुसार अवसाद काल में बेरोजगारी का मुख्य कारण सक्रिय-मांग (Effective Demand) का कम होना है निजी क्षेत्र में विनियोग कम हो जाने से लोगों की आय कम हो जाती है और वे कम वस्तुओं की मांग करने लगते हैं । सक्रिय मांग कम होने से उत्पादन तथा रोजगार गिर जाता है । इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र उपाय विनियोग में वृद्धि करना है । अवसाद काल में निजी विनियोग की कमी को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके पूरा किया जा सकता है । सरकार नए कारखाने लगा कर तथा जनहित कार्यों पर अधिक व्यय करके समाज में विनियोग की मात्रा को गिरने से रोक सकती है और इस प्रकार रोजगार के स्तर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है । इस प्रकार सरकार सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में उचित नीति को अपना कर आर्थिक मन्दो के कारण समाज में मानव साधनों के होने वाले अप्रभ्यय को रोक सकती है ।

परीक्षा प्रश्न

१. सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए ।
२. सार्वजनिक व्यय के निजी क्षेत्र के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए ।
३. कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सार्वजनिक व्यय का क्या महत्व है ?
४. व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक व्यय के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । भारतवर्ष में लोक व्यय को किस प्रकार कम किया जा सकता है ?
५. वर्तमान काल में बहुत से देशों में सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि क्यों हुई है ?
६. वर्तमान काल में किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में लोक व्यय क्या योग दे सकता है ?
७. आय के वितरण पर लोक व्यय के प्रभावों की व्याख्या कीजिए ।

लोक आगम Public Revenue

सरकार को अपने विभिन्न कार्यों को मफूलतापूर्वक करने के लिये आय की आवश्यकता होती है। राज्य को कितनी आय की आवश्यकता होगी यह उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सीमा तथा प्रकृति पर निर्भर होता है। प्राचीन समय में जब सरकार का कार्य-क्षेत्र सीमित था तो उसका काम बहुत कम आय से चल जाता था किन्तु आजकल सरकार को अधिकधिक मात्रा में आय की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में राज्य की क्रियाओं में वृद्धि हो जाने के कारण सरकार को बढ़ती हुई मात्रा में आय की आवश्यकता होती है जिसके लिये वह सभी उपलब्ध साधनों में अधिकधिक मात्रा में आय प्राप्त करने का प्रयत्न वर्तमान है। एक व्यक्ति की भाँति सरकार को भी विभिन्न साधन होते हैं। लोक आय के साधनों का वर्गीकरण विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से किया है। प्रत्येक वर्गीकरण अलग-अलग उद्देश्य को लेकर किया गया है। ऐडम स्मिथ के अनुसार राज्य की आय के दो प्रमुख साधन होते हैं—(१) राज्य की अपनी भूमि तथा पूँजी से प्राप्त होने वाली आय (२) लोगों के धन तथा सम्पत्ति में प्राप्त की जाने वाली आय जिससे उनका-अभिप्राय करो से होने वाली आय में था। उनका विचार था कि प्रथम स्रोत में प्राप्त होने वाली आय स्याई तथा पर्याप्त नहीं होती, इसलिये सरकार को करो से प्राप्त होने वाली आय पर ही निर्भर रहना पड़ता है।^१

सेलिगमैन (Seligman) ने लोक आगम को तीन भागों में बाँटा है—

(१) नि शुल्क आय (Gratuitous Revenue) (२) प्रसविदक आगम (Contractual Revenue) और (३) अनिवार्य आय (Compulsory Revenue)। नि शुल्क आय के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त होने वाले नि शुल्क उपहार तथा महापिताय मिलने वाला धन सम्मिलित होता है। इस प्रकार की आय लोग अपनी इच्छा से सरकार को देते हैं और उसके लिये उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। वर्तमान समय में इस प्रकार की आय का महत्व काफी कम हो गया है। दूसरे प्रकार की आय के अन्तर्गत सरकार की व्यवसायिक आय सम्मिलित होती है जो सरकार को सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से प्राप्त होती है। डाक, तार, रेल तथा सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय को सेलिगमैन ने प्रसविदक आय कहा है। यह एक प्रकार का मूल्य है

जो केवल उन्ही लोगों से लिया जाता है जो सरकारी सेवाओं अथवा सार्वजनिक उद्योगों की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अनिवार्य आय के अन्तर्गत सरकारी सम्पत्ति, जुर्मानों तथा करों से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। लोक सत्ता होने के कारण सरकार लोगों से कोई भी सम्पत्ति, सेवा अथवा वस्तु माग सकती है और इसके लिये मावजा देना भी आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार की आय सरकार की विशेष स्थिति और उसके विशेष अधिकार के कारण प्राप्त होती है। बेस्टेबिल (Bastable) ने लोक सत्ता को दो भागों में बाँटा है। एक वह आय जो राज्य को एक बहुत बड़े प्रण्डल (Corporation) की भाँति वस्तुयें तथा सेवायें उपलब्ध करने के कारण होती है और दूसरी वह आय “जो सरकार अपनी सत्ता के कारण ममाज की आय में से ले लेती है।” इसमें से पहले प्रकार की आय सरकार को अपने विशेष अधिकारों के कारण प्राप्त होती है जिसके अन्तर्गत करों से प्राप्त होने वाली आय आ जाती है। लुडज (Lutz) ने सरकारी आगम को निम्नलिखित भागों में बाँटा है—(१) व्यवसायिक आय, (२) प्रशासन सम्बन्धी आय, (३) कर, (४) सार्वजनिक ऋण, (५) सहायतायें मिलने वाला धन।

साधारणतया लोक आगम को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) करों से प्राप्त आय।

(ब) करों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के साधनों से प्राप्त आय जिसके अन्तर्गत (i) शुल्क (Fees), (ii) मूल्य (Prices), (iii) विशेष अभिनिर्धारण (Special Assessments), (iv) जुर्माने (Fines & Penalties) आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(१) कर (Taxes)—कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति सरकार के द्वारा सार्वजनिक भलाई के लिये किये गये व्यय को पूरा करने के लिये करता है। डाल्टन के अनुसार, “कर एक अनिवार्य अदान (Contribution) है जो किसी सार्वजनिक सत्ता के द्वारा लगाया जाता है और जिसका कर दाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और जिसे किसी कानूनी अपराध की सजा के रूप में नहीं लगाया जाता है।” सभी लोगों को सरकार से अपने जीवन तथा सम्पत्ति का संरक्षण प्राप्त होता है। इस प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के बदले में सरकार कर लेती है किन्तु करदाता को कर के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ से कर का कोई सम्बन्ध नहीं होता है। प्रो० टॉजिंग (Prof. Taussig) के अनुसार, “कर को अन्य प्रकार के सरकारी भुगतानों से अलग करने वाली मुख्य विशेषता यह है कि करदाता तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का ‘जैसे को

1 “A tax is a compulsory contribution imposed by a public authority irrespective of the exact amount of service rendered to the taxpayer in return and not imposed as a penalty for any legal offence.”

—Dalton

तंसा' (Quid Pro Quo) का सम्बन्ध नहीं होता है।^२ कर की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(अ) कर एक अनिवार्य भुगतान है—कर सार्वजनिक सत्ता के द्वारा लगाया जाता है और उसका भुगतान करना लोगों के लिए अनिवार्य होता है। करो के सम्बन्ध में कर देने वालों की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। कर लगते समय करदाता से यह नहीं पूछा जाता है कि वह कर देना चाहता है अथवा नहीं। कर की मात्रा, उसे इकट्ठा करने का ढंग तथा उसके भुगतान का समय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और उसमें करदाता से किसी प्रकार की सलाह नहीं ली जाती है। ठीक समय पर कर का न देना जुर्म है और उसके लिए सजा दी जाती है।

(ब) कर का सम्बन्ध उससे प्राप्त होने वाले लाभ से कुछ नहीं होता है—कर की प्रमुख विशेषता यह है कि करदाता को प्राप्त होने वाले लाभ और उनके द्वारा दिये जाने वाले कर में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता है। करदाता को कर से लाभ प्राप्त हो अथवा नहीं किन्तु उसे कर अवश्य देना पड़ता है। कोई व्यक्ति, जिसके स्कूल जाने वाले बच्चे न हों, इस आधार पर कर देने से इकार नहीं कर सकता है क्योंकि कर से प्राप्त आय को बच्चों के स्कूल चलाने के लिये व्यय किया जाता है। प्रायः जो लोग ऊँचा कर देते हैं उन्हें करो के व्यय से होने वाला लाभ बहुत कम प्राप्त होता है और जो लोग कम कर देते हैं उन्हें इस लाभ का अधिक भाग मिलता है। कोई भी व्यक्ति करो के बदले में किसी विशेष प्रकार की सुविधा का दावा नहीं कर सकता है। आय कर देने वाले इस बात की मांग नहीं कर सकते हैं कि उनके घर पर एक विशेष पुलिस का आदमी नियुक्त किया जाय।

(स) कर प्रत्येक करदाता की मौद्रिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है—कर देने से लोगों के पास क्रयशक्ति कम हो जाती है और उनके रहन-सहन के स्तर में कमी आती है जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है। इसीलिये लोगों में करो से बचने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है।

(२) शुल्क (Fees)—शुल्क वह भुगतान है, जो व्यक्ति सरकार से प्राप्त किसी विशेष लाभ के बदले में अथवा सरकार के द्वारा किसी जनहित सेवा पर किये जाने वाले व्यय के लिये सरकार को देता है। सरकार कुछ अनिवार्य सेवाएँ जनहित के लिये उपलब्ध करती है। इन अनिवार्य सेवाओं के बदले में सरकार जो भुगतान लेती है उसे शुल्क कहते हैं। इस प्रकार की सेवायें व्यवसायिक दृष्टिकोण से सम्पन्न नहीं की जाती हैं बल्कि उनका सम्पन्न करना सरकार के लिए शासक के नाते अनिवार्य होता है। इनके लिए व्यक्ति से लिया जाने वाला भुगतान प्रायः उनकी उत्पादन क्षमता से कम होता है। न्याय शुल्क (Court Fee) तथा शिक्षा शुल्क इसी प्रकार के भुगतान हैं। शुल्क की

2 "The essence of a tax, as distinguished from other charges by the government, is the absence of a direct 'quid pro quo' between the tax-payer and the public authority."

कुछ विशेषतायें इस प्रकार हैं—(i) वह अनिवार्य भुगतान नहीं होता है और इस दृष्टि से वर में बिल्कुल भिन्न होता है। (ii) वह किसी विशेष लाभ के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। जो लोग शुल्क देते हैं वे उसके बदले में सरकार से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। (ii) शुल्क अनिवार्य रूप से सेवा लागत के अनुपात में नहीं होता है। वह उमसे अधिक भी हो सकता है और कम भी किन्तु प्रायः वे सेवा लागत से कम हो होते हैं।

(२) मूल्य (Price & Rates)—मूल्य वह भुगतान है जो सरकार अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचने के बदले में प्राप्त करती है। यह एक प्रकार से सरकार की व्यवसायिक आय है। सरकार कुछ उद्योग तथा व्यवसाय भी चलाती है। इन उद्योगों की वस्तुओं तथा सार्वजनिक सेवाओं को बेचकर सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसे इस मद में सम्मिलित किया जाता है। जैसे सरकारी जंगलों से लकड़ी बेचना, सार्वजनिक उद्योगों द्वारा निर्मित नमक, कृत्रिम खाद, लोहे आदि को बेचना तथा डाक, तार, रेल आदि की सेवाएँ उपलब्ध करना। इन सब वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में सरकार मूल्य लेती है। इस प्रकार के व्यवसायों से सरकार लाभ भी प्राप्त कर सकती है इसलिए मूल्य उत्पादन लागत से प्रायः अधिक होते हैं। इस प्रकार के भुगतान की दो मुख्य विशेषतायें हैं—(i) यह भुगतान अनिवार्य नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति सफर नहीं करता है तो उसमें रेल किराया नहीं लिखा जाएगा। (ii) मूल्य किसी निश्चित वस्तु अथवा सेवा के हस्तांतरण के बदले में दिया जाता है।

(४) विशेष अभिनिर्धारण (Special Assessments)—सरकार को विशेष अभिनिर्धारणों से भी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार की आय में कर, शुल्क तथा मूल्य तीनों ही गुण पाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वे भुगतान आ जाते हैं जो सम्पत्ति के मालिकों को अपनी सम्पत्ति में सार्वजनिक सत्ता के द्वारा किये जाने वाले सुधारों के बदले में सरकार को देने पड़ते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार का सुधार करने के बदले में सरकार वहाँ के निवासियों पर विशेष दायित्व लगा सकती है जिसको उनके लिये अनिवार्य होता है। यदि किसी बगीचे अथवा पार्क का निर्माण किया जाता है या कोई सड़क बनाई जाती है तो उस क्षेत्र की सम्पत्ति को इस सुधार से लाभ होता है और इसलिए सरकार इस सुधार के बदले में वहाँ की सम्पत्ति के मालिकों पर विशेष अभिनिर्धारण लगा सकती है। संलिगमैन के अनुसार विशेष अभिनिर्धारण ऐसी “अनिवार्य देन है जो वगं विशेष द्वारा प्राप्त विशेष लाभ की आनुपातिक होती है और सम्पत्ति के ऐसे विधिष्ट सुधार के व्यय को पूरा करती है जो लोकहित के दृष्टिकोण से किया जाता है।”

उपरोक्त प्रकार के आगम के अतिरिक्त भी सरकार को अन्य प्रकार से आय प्राप्त हो सकती है—जैसे स्वेच्छा से मिले उपहार अथवा सहायताएँ दिया गया धन। पत्र मुद्रा के प्रयोग के कारण अब सरकार को उन छापेखानों से भी आय प्राप्त होने लगी है जिनका प्रयोग वह पत्र मुद्रा छापने के लिए करती है। किन्तु इस प्रकार से

आय अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। लोक आगम की विभिन्न मदों में कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। करो से प्राप्त होने वाली आय लोक आगम का बहुत बड़ा भाग होती है और उनके सम्बन्ध में ही राजस्व की जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

यद्यपि अध्ययन की दृष्टि से लोक आगम को विभिन्न भागों में बाँटा जा सकता है किन्तु वास्तव में विभिन्न मदों में भेद करना बहुत कठिन है। लोक आगम के विभिन्न माध्यमों के बीच कोई पूर्णतया स्पष्ट भेद नहीं है और एक दूसरे की सीमा के भीतर आ जाते हैं। शुल्क, मूल्य और कर में भेद करना बहुत कठिन है। यदि सरकार सेवा लागत में बहुत ऊँचे शुल्क सभाती है तो वे करों की भाँति हो जाते हैं। विदेश अभिनिर्धारणों को कर, शुल्क तथा मूल्य से पृथक् करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि उनमें तीनों के गुण पाये जाते हैं। विभिन्न साधनों के बीच की सीमाओं की अस्पष्टता के कारण ही डॉ० डाल्टन ने कहा है—“इसमें सन्देह नहीं है कि लोक आगम के साधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किन्तु अधिकांश दशाओं में उनके बीच का भेद स्पष्ट नहीं होता है और दूसरे वर्गीकरणों की भाँति यहाँ भी वर्गीकरण की प्रेरणा वर्गीकरण की खोज अधिक सापेक्षायक है।”

अच्छी आगम प्रणाली के गुण

सरकार को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आय का मिलना आवश्यक है। यह एक अच्छी लोक आगम प्रणाली के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। यदि आगम प्रणाली ऐसी है कि उसके द्वारा सरकार को आवश्यकतानुसार धन प्राप्त हो जाता है तो सरकार अपने विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभा सकेगी किन्तु यदि उसकी आय प्रणाली दोषपूर्ण है तो वह समय पर पर्याप्त धन न मिलने के कारण बहुत से अनिवार्य कार्य भी नहीं कर सकेगी और लोक हितकारी राज्य की स्थापना सम्भव नहीं होगी। लोक आगम प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसमें सरकार को निरन्तर पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक तरीके पर आय प्राप्त होती रहे। ऐडम स्मिथ (Adam Smith) ने एक अच्छी लोक आगम प्रणाली के चार गुण बतलाये हैं—(i) समानता (Equality), (ii) निश्चितता (Certainty), (iii) सुविधा (Convenience) और (iv) मितव्ययिता (Economy)। इसके अतिरिक्त एक अच्छी लोक आगम प्रणाली में लोच (Elasticity) और विविधता के गुण भी होने चाहिये। फिन्डले शिराज (Findlay Shiras) ने पर्याप्तता (Sufficiency) और उत्पादकता (Productivity) को भी एक अच्छी आगम प्रणाली का आवश्यक गुण माना है। जिन आय प्रणाली में उक्त लिखित सभी गुण हों उसे लोक आगम की अच्छी प्रणाली माना जाता है।

लोक आगम का महत्व

लोक आगम को वास्तव में राजस्व का जीवन स्रोत माना जाना चाहिये। इसके बिना राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रियाओं का किया जाना असम्भव है। आजकल लोक धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान सरकारें

अधिकाधिक मात्रा में लोक व्यय करके अपने विस्तृत कार्यों को सम्पन्न करती है। किन्तु लोक आय ही लोक व्यय को सम्पन्न करने का एकमात्र साधन है। जिस प्रकार उत्पत्ति के बिना उपभोग सम्भव नहीं है ठीक उसी प्रकार लोक आय के बिना लोक व्यय नहीं किया जा सकता है। कोई सरकार वित्तनी भी प्रगतिशील क्यों न हो किन्तु यदि उसकी आय के साधन सीमित हैं तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी क्रियाओं का क्षेत्र तथा अपने व्यय को सीमित करना पड़ेगा। इस प्रकार लोक आगम लोक व्यय की सीमाएँ निश्चित करता है। अधिक लोक आय होने पर ही अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जा सकेगा। वर्तमान सरकारों के बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिए लोक आगम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार को निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में आय प्राप्त होती रहे।

राज्यों की स्थापना के साथ-साथ ही लोक आगम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। आरम्भ से ही सरकारों को समाज में कुछ अनिवार्य कार्य करने होते थे जिनके लिए उन्हें लोक आगम की आवश्यकता होती थी किन्तु प्राचीन समय में सरकार का कार्य-क्षेत्र सीमित होने के कारण सरकार को बहुत कम व्यय करना पड़ता था और इसलिए लोक आगम का महत्व कम था। सरकार के कार्यों में वृद्धि होने के साथ-साथ लोक आगम का महत्व भी बढ़ने लगा और आय के नये साधनों की खोज की जाने लगी। इसके साथ ही लोक आगम के अध्ययन का महत्व भी बढ़ता गया। वर्तमान समय में सरकार का कार्य-क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जाने के कारण, लोक आगम का विशेष महत्व हो गया है और वैज्ञानिक खोज के द्वारा सरकारी आय के वर्तमान साधनों को अधिक उत्पादक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा नये साधनों की खोज की जा रही है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व के अध्ययन में लोक आगम का विश्लेषण एक विशेष महत्व रखता है।

करारोपण Taxation

प्राचीन काल में प्रत्येक कर को समाज में घुरा समझा जाता था और वही सरकार सबसे अच्छी मानी जाती थी जो कम से कम कर लगाती हो, किन्तु वर्तमान समय में करारोपण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रत्येक सरकार अपने बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कर लगाती है और आय में वृद्धि करने के लिए नये-नये करों की खोज की जाती है। आजकल करों को समाज के हित में समझा जाता है क्योंकि उनसे प्राप्त आय को सरकार जनहित कार्यों में अथवा आर्थिक विकास के लिये लगानी है जिसमें समाज प्रगति करता है। करों का प्रयोग धन और सम्पत्ति की असमानताओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है जिसके कारण वे समाजवाद स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण साधन बन गए हैं। इसके अतिरिक्त करों के देने से लोगों में नागरिकता की भावना दृढ़ होती है और वे यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि सरकार करों के द्वारा प्राप्त उनके धन का प्रयोग किस प्रकार करती है।

लोक आगम के विभिन्न साधनों में करारोपण प्रमुख साधन माना जाता है। वर्तमान राज्यों को प्राप्त होने वाली आय का एक बहुत बड़ा भाग करों के द्वारा प्राप्त होता है। राजस्व के अध्ययन में करारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करारोपण प्रणाली की कुशलता पर ही सरकार की आय निर्भर होती है। यदि करारोपण प्रणाली ऐसी नहीं है जिसके द्वारा कर के लिये समाज के प्रत्येक वर्ग के पास पहुँचा जा सके अथवा ऐसी है जिसमें कर ठीक प्रकार से एकत्रित नहीं किये जाते हैं या उनके इकट्ठा करने का व्यय बहुत अधिक आता है तो ऐसी दशा में सरकारी आय उतनी नहीं हो पाती है जितनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सरकार के द्वारा ऐसे कर लगाए जाते हैं या करारोपण इस प्रकार किया जाता है कि धन के उत्पादन, वितरण तथा लोगों की बचत पर उसका घुरा प्रभाव पड़ता है तो उससे समाज को हानि होगी। करारोपण का न्यायपूर्ण होना भी आवश्यक है जिससे कि लोगों के ऊपर उनकी कर दान क्षमता से अधिक भार न डाला जा सके। इस प्रकार करों के सम्बन्ध में राजस्व की सबसे जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। करारोपण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन्हें सुलझाने के उपायों की

खोज करना राजस्व के अध्ययन का प्रमुख कार्य है। आरम्भ से ही अर्थशास्त्रियों ने करारोपण की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है और समय-समय पर करारोपण सम्बन्धी विभिन्न नियमों का निर्माण किया गया है। यद्यपि इनमें से बहुत से सिद्धांत असन्तोषजनक हैं किन्तु फिर भी वे करारोपण की प्रकृति तथा उसके उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। करारोपण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये करारोपण सम्बन्धी सिद्धांतों की खोज करना आवश्यक है।

करारोपण के सिद्धांत :

करारोपण के सिद्धांतों का अध्ययन करते समय हमारे सम्मुख ऐसी समस्याएँ आती हैं, जैसे करों का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, करो का न्यायपूर्ण आधार क्या है, सरकार को कितने कर लगाने चाहियें तथा करो का भार किस प्रकार लोगों में बाँटा जाय ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में काफी कठिनाई आती है। करारोपण की समस्याएँ केवल आर्थिक ही नहीं हैं बल्कि उनका नैतिक तथा राज-नैतिक पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। करारोपण के सिद्धांतों का निर्माण करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। आरम्भ से लेकर अब तक विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों ने करारोपण सम्बन्धि बहुत से सिद्धांत बतलाए हैं जिनमें से कुछ एक काफी महत्वपूर्ण हैं और उनके द्वारा करो की प्रकृति तथा उनके उद्देश्यों को समझा जा सकता है। एक अच्छी करारोपण प्रणाली का विकास करने के लिए कर सम्बन्धी विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

ऐडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांत :

सर्वप्रथम ऐडम स्मिथ ने करो की प्रकृति तथा उनके उद्देश्यों का विधिवत् अध्ययन किया और करारोपण के कुछ आधारभूत सिद्धांत बतलाये। उनके अनुसार यदि करारोपण करते समय इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो इस प्रकार से लगाये गए कर समाज के लिए लाभपूर्ण हो सकते हैं। ऐडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांत आरम्भ से ही बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और उन्हें अभी तक भी एक अच्छी कर प्रणाली का आधार माना जाता है। यद्यपि उनके पश्चात् अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी कुछ करारोपण सम्बन्धी नियम बतलाए हैं किन्तु ऐडम स्मिथ के नियमों का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ है। ऐडम स्मिथ के अनुसार करारोपण के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्त हैं :

(१) शोधन-क्षमता सिद्धान्त (Canon of Ability or Equality) :—

इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण इस प्रकार होना चाहिये कि सभी कर के भार को समान रूप से बाँटा जा सके। विभिन्न लोगों पर कर का भार इस प्रकार पड़ना चाहिये कि उन्हें कर देने में समान त्याग करना पड़े। यह तभी सम्भव हो सकता है जब सभी लोगों पर उनकी कर दान क्षमता के अनुसार कर लगाया जाय। इस सिद्धांत के अनुसार सब लोगों से बराबर कर नहीं लेना चाहिये बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला कर उसकी करदान क्षमता के अनुसार निश्चित

होना चाहिये। जिन लोगों की कर-दान क्षमता अधिक है उन्हें अधिक कर देना चाहिये और जिनकी कर-दान क्षमता अधिक है उन्हें कम।

ऐडम स्मिथ के अनुसार "राज्य के नागरिकों को मरचारी व्यय को पूरा करने के लिये, राज्य के सरभण्ड में प्राप्त होने वाली आय के अनुपात में कर देना चाहिये।" यद्यपि शोषण क्षमता का कोई निश्चित भाग सम्भव नहीं है किन्तु ऐडम स्मिथ ने व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय को उसकी शोषण क्षमता का आधार माना है। धनी लोगो को क्योंकि अधिक आय प्राप्त होती है इसलिए उनकी शोषण क्षमता भी अधिक है और उन पर ऊँचे कर लगाये जाने चाहिये। इसके विपरीत निर्धन लोगो की आय कम होने के कारण उनकी शोषण क्षमता कम होती है इसलिए उन पर कम कर लगाए जाने चाहिये। इस दृष्टिकोण से प्रगामी कर प्रणाली ही उपयुक्त है जिसमें अमीरों पर ऊँची दर में कर लगाये जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कर के भार का बटवारा इस प्रकार होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को कर देते समय समान त्याग करना पड़े।

(२) निश्चितता का सिद्धांत (Principle of certainty) :—ऐडम स्मिथ के अनुसार करों के सम्बन्ध में निश्चितता का होना आवश्यक है। करों की मात्रा, उनको देने का समय तथा उन्हें चुकाने की विधि स्पष्ट रूप से निश्चित होनी चाहिये। ऐसा होने से कर-दाता तथा सरकार दोनों ही अपनी आय तथा व्यय में उचित अनुमान बनाये रख सकेंगे। ऐडम स्मिथ ने निश्चितता को करा-रोपण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है। उनके अनुसार कर-दाता को यह मालूम होना चाहिये कि उसे कितना कर देना है जिसमें कि वह अपने व्यय में आय के अनुसार परिवर्तन कर सके। सरकार को भी निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि उसे करों से कितनी आय प्राप्त होने जा रही है जिससे कि वह अपने बजट में आवश्यक अनुमान स्थापित कर सके। कर देने वालों को यह भी पता होना चाहिये कि उन्हें कब कर देना है और कर का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। ऐसा होने से करदाताओं को काफी सुविधा होगी और वे अपना पारिवारिक बजट ठीक प्रकार से बता सकेंगे।

(३) सुविधा का सिद्धान्त (Principle of Convenience) :—ऐडम स्मिथ ने सुविधा को एक अच्छी कर प्रणाली का महत्वपूर्ण गुण माना है। उनके अनुसार प्रत्येक कर इस प्रकार और ऐसे समय लगाया जाना चाहिये कि कर-दाता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। कर भुगतान का समय तथा उसे देने की विधि कर-दाताओं की सुविधा के अनुसार होनी चाहिये। उदाहरणार्थ आय कर उस समय लगाया जाना चाहिये जब लोगो की आय प्राप्त होती है और भूमि का लगान वसूल करने का ठीक समय फसल कटने पर है। यदि करों को इकट्ठा करते समय करदाताओं की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है तो कर देने का काट बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

ऐडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर का देना लोगों के लिए कष्टदायक होता है। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि करो के होने से लोगों को देने वाले कष्ट को कम से कम रखा जाय। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कर देने का समय और उसकी झुगतान दिधि को करदाताओं की सुविधाओं के अनुसार निश्चित किया जाय। करो की वसूली करते समय करदाता की सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और उस विषयी प्रकार क. अनावश्यक अनुविधा व्यवसा कष्ट नहीं होने देना चाहिये।

(४) मितव्ययिता का सिद्धांत (Principle of Economy) :—ऐडम स्मिथ ने करो को एकत्रित करने में मितव्ययिता पर अधिक जोर दिया है। उनके अनुसार कर प्रणाली मितव्ययितापूर्ण होनी चाहिए। करो को इस प्रकार एकत्रित किया जाना चाहिए कि जनता से वसूल की जाने वाली रकम का अधिक से अधिक भाग सरकारी खजाने में आ जाय—अर्थात् कर वसूल करने में कम से कम व्यय होना चाहिये। ऐडम स्मिथ के अनुसार “प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों की जेबों में, सरकारी खजाने में जाने वाली रकम के अतिरिक्त, कम से कम निवाला जाय।” करो को एकत्रित करने का व्यय इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि करो के रूप में वसूल की गई रकम का बहुत बड़ा भाग उसमें खर्च हो जाय। करो को जितना मितव्ययितापूर्ण ढंग में इकट्ठा किया जायगा उतना ही उनके द्वारा अधिक सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। इन दृष्टिकोण से कुछ एक उत्पादक कर बहुत से अनुपादक करो की अपेक्षा अच्छे हैं। यह सिद्धान्त करो के एकत्रण में अपव्यय को रोकने पर विशेष जोर देता है।

ऐडम स्मिथ के करारोपण सिद्धांत प्राचीन समय में लेकर अब तक करारोपण का आधार रहे हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि कर किस प्रकार लगाये जाने चाहिए और इसलिए एक अच्छी कर प्रणाली के निर्माण में उनका बहुत अधिक महत्व है। ऐडम स्मिथ के बाद के अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अच्छी कर प्रणाली इन चार सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांतों पर भी आधारित होनी चाहिये। ऐडम स्मिथ के करारोपण सम्बन्धी सिद्धांतों में वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित सिद्धांतों को और जोड़ दिया है।

(५) उत्पादकता का सिद्धान्त (Principle of Productivity) :—इस सिद्धान्त के अनुसार करो में उत्पादकता का गुण होना चाहिये अन्यथा सरकार को करो से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो सकेगी। कर ऐसा होना चाहिये जो सरकार की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त आय दे सके। एक अच्छी कर प्रणाली वही है जिसके द्वारा सरकार के लिये आवश्यकतानुसार आय एकत्रित की जा सके। उत्पादकता का अर्थ केवल वर्तमान समय में करो से पर्याप्त आय प्राप्त होने तक ही सीमित नहीं है बल्कि भविष्य में भी उनके द्वारा लोक आगम का प्रवाह बना रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोगों की उत्पादन क्षमता पर करो के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक है। करो की उत्पादकता लोगों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर होती है। यदि करो का प्रभाव लोगों की उत्पादन क्षमता

को कम करने का होता है तो ऐसी दशा में भविष्य में करो से प्राप्त आय गिर जायगी और उनकी उत्पादकता भी कम हो जायगी। करो की उत्पादकता को बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है कि कर-दाताओं की कार्यकुशलता तथा उत्पादन शक्ति पर उनका कम से कम बुरा प्रभाव पड़े। पूँजी के संचय पर भी उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। ऐसा होना सरकार और कर-दाताओं दोनों के हित में है।

(६) लोच का सिद्धान्त (Principle of Elasticity) — इस सिद्धान्त के अनुसार कर प्रणाली में लोच का गुण अवश्य होना चाहिये। लोच से हमारा अभिप्राय विस्तार तथा सकुचन की क्षमता से होता है। नर ऐसा होना चाहिये कि उससे प्राप्त आय को सरकार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसानी के साथ बढ़ाया जा सके। राज्य की आवश्यकताओं तथा कर-दाताओं की शक्ति व योग्यता के अनुसार कर में घटने बढ़ने की क्षमता होनी चाहिये। सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों के कारण अपनी आय में परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है। सबट काल में बड़े हुये व्यय को पूरा करने के लिये राज्य को अपनी आय में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है। इसके विपरीत राज्य की दशा अच्छी होने पर लोगों को कर सम्बन्धी छूट भी दी जा सकती है। यह तब ही सम्भव हो सकता है जबकि कर प्रणाली में पर्याप्त लोच पाई जाती हो। जिन करो से प्राप्त आय को आवश्यकता पड़ने पर नहीं बढ़ाया जा सकता है उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता है—भूमि लगान इसी प्रकार का कर है क्योंकि उससे प्राप्त आय प्रायः निश्चित रहती है। इनके विपरीत आय कर काफी लोचपूर्ण है क्योंकि उससे प्राप्त आय को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

(७) सरलता का सिद्धान्त (Principle of Simplicity) — करो में सरलता का गुण भी होना चाहिये। कर प्रणाली इतनी साधारण होनी चाहिये कि उसे आसानी से समझा जा सके। यदि कर प्रणाली को एक साधारण व्यक्ति भी समझ लेता है तो ऐसी प्रणाली को अच्छा माना जायगा किन्तु एक जटिल तथा अस्पष्ट कर प्रणाली सरकार और कर-दाताओं के वारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ सकती है और अमतीय उत्पन्न करती है जिससे लोगों में करो से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिये कर प्रणाली का सरल होना अत्यन्त आवश्यक है। करो का ढाँचा इतना सरल होना चाहिये कि सामान्य नागरिक भी उसे आसानी से समझ सके।

(८) विविधता का सिद्धान्त (Principle of Diversity) — कर प्रणाली में विविधता का अभिप्राय यह है कि सरकार अपनी आय प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार के करो का प्रयोग करे। करो में विविधता का होना इसलिये आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों से किसी न किसी प्रकार के कर के द्वारा कुछ अवश्य लिया जा सके। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे सरकार व सरकार में कुछ भी आय प्राप्त होती है, अपनी क्षमता के अनुसार राज्य को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिये। यह तब ही सम्भव हो सकता है जब देश में विभिन्न प्रकार

के कर लगाये जाते हैं। एक अच्छी कर प्रणाली वही है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का न्यायपूर्ण मिश्रण पाया जाता हो और जो समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सके तथा उनकी कर दान क्षमता के अनुकूल हो जिससे कि कर भार को लोगों के बीच न्यायपूर्ण ढंग में बाँटा जा सके। कर प्रणाली में इस प्रकार की विविधता पाई जानी चाहिये कि कोई न कोई कर समाज के प्रत्येक वर्ग को अवश्य देना पड़े।

(६) वाछनीयता का सिद्धान्त (Principle of Expediency) — इस सिद्धान्त के अनुसार करों को उचित आधार पर लगाया जाना चाहिये जिससे कि कर-दाताओं के लिये वाछनीयता को भली प्रकार सिद्ध किया जा सके। जिन करों की वाछनीयता की मिद्ध नहीं किया जायगा उनका लोग विरोध करेंगे। कर लगाते समय कर दाताओं को सन्तुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है। जिन करों का वे विरोध करते हैं उन्हें न लगाया जाय क्योंकि ऐसे करों को लगाने से जनता को अधिक कष्ट होता है। प्रायः नये करों को पसन्द नहीं किया जाता है। पुराने कर को अच्छा माना जाता है क्योंकि वह कर-दाताओं को अधिक कष्ट नहीं देता है। सरकार को नये कर लगाने समय विशेष सावधानी से काम लेना चाहिये और ऐसे करों को ही लगाना चाहिये जो कम से कम विरोध उत्पन्न न करें। जहाँ तक सम्भव हो सके पुराने करों के द्वारा अथवा उनमें कुछ संशोधन करके ही सरकार को अपनी आय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार के करों के लोग आदि हो जाते हैं और उन्हें पुराने करों को देने में कम से कम कष्ट होता है।

उपरोक्त सभी सिद्धान्त कर प्रणाली के आवश्यक गुणों को बताते हैं किन्तु किसी एक कर में इन सभी गुणों का पाया जाना असम्भव है। कोई भी ऐसा कर नहीं है जो करारोपण के सभी सिद्धान्तों को सन्तुष्ट करता है। प्रत्येक कर में कोई न कोई कमी अवश्य पाई जाती है, इसलिये हम अतिशयत करों को न देखकर सम्पूर्ण कर प्रणाली के गुणों की देखना चाहिये। कर प्रणाली को सामूहिक रूप में करारोपण के अधिकांश सिद्धान्तों के अनुकूल होना चाहिये तथा उसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होना चाहिये।

करारोपण में न्याय :

करों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा होता है कि कर क्यों लगाये जाते हैं और उनका न्यायपूर्ण आचार क्या होना चाहिये? करों का न्यायपूर्ण आधार होना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा लोगों को करों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट नहीं किया जा सकेगा। आरम्भ से ही करों के सम्बन्ध में न्याय का प्रश्न विचारणीय रहा है और न्याय की समस्या को सुलभाने के लिये विभिन्न सिद्धान्तों का निर्माण किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं—

(अ) लाभ का सिद्धान्त (Benefit Theory) :— इस सिद्धान्त के अनुसार कर सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। करों

को न्यायपूर्ण बनाने के लिये नागरिकों द्वारा करो के रूप में दी जाने वाली रकम, उनके द्वारा सरकार से प्राप्त लाभ के अनुपात में होनी चाहिये। जिन लोगों को सरकार की क्रियाओं से अधिक लाभ प्राप्त होता है उन्हें अधिक कर देने चाहिये। यह सिद्धान्त एक बेकार का सिद्धान्त है और इसे करारोपण का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार कर लगाने में गरीबों को अधिक कर देने पड़ेंगे और अमीरों को कम जो किसी भी राज्य के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ का नापना भी सम्भव नहीं है। यद्यपि करारोपण के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है किन्तु फिर भी सरकार के द्वारा लगाये जाने वाले अन्य प्रकार के भुगतान सरकार से प्राप्त लाभ के आधार पर ही निश्चित किये जाते हैं।

(ब) सेवा की लागत का सिद्धान्त (Cost of Service Principle)—इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार जो सेवाएँ करती है उनकी वास्तविक लागत के अनुपात में कर लगाये जाने चाहिये। सरकार एक प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की विक्रेता है और व्यक्ति जो कुछ कर के रूप में देता है वह सरकार के द्वारा की जाने वाली सेवाओं का भुगतान है। कर सेवा लागत के अनुपात में होने चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई सरकार के द्वारा की जाने वाली सेवाओं की लागत को निश्चित करने में होती है। कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में (जैसे सैनिक तथा पुलिस सेवाएँ) उत्पादन लागत को नहीं नापा जा सकता है और फिर यह जानना तो बिल्कुल असम्भव है कि किसी व्यक्ति को उनमें से कितनी लागत की सेवाएँ प्राप्त होती हैं। केवल उन सेवाओं की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है जिन्हें सरकार मूल्य के आधार पर उपलब्ध करती है जैसे बिजली, रेल तथा डाक आदि की सेवाएँ। अतः सेवा लागत के आधार पर करो को लगाना सम्भव नहीं है और व्यवहारिक दृष्टि से सेवा लागत के सिद्धान्त का महत्व बहुत कम है।

(स) कर देने की योग्यता का सिद्धान्त (Ability to Pay or Faculty Theory)—कर दान योग्यता का सिद्धान्त न्याय का सबसे प्रचलित तथा सतोपजनक समझा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार करारोपण लोगों की कर-दान क्षमता पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक करदाता को अपनी कर देने की योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए। जिन लोगों की कर-दान योग्यता अधिक हो उनसे अधिक कर लिया जाना चाहिए तथा कम कर-दान योग्यता वाले लोगों पर कम कर लगाने चाहिये। यह सिद्धान्त करो का सबसे न्यायपूर्ण आधार निश्चित करता है। किन्तु कर-दान योग्यता को नापना आसान नहीं है और इस सम्बन्ध में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम प्रश्न तो यह होता है कि किसी व्यक्ति की कर दान क्षमता को नापने का क्या आधार होना चाहिए? कर दान योग्यता का आधार निश्चिन करने के लिए हम दो प्रकार के दृष्टिकोण अपना सकते हैं—

(अ) व्यक्तिगत दृष्टिकोण (Subjective Aspect)।

(ब) बाहरी दृष्टिकोण (Objective Aspect)।

व्यक्तिगत दृष्टिकोण (Subject Aspect)—कर देने में करदाता को त्याग करना पड़ता है और व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली त्याग की मात्रा अथवा उसे होने वाली असुविधा उसकी कर-दान क्षमता का प्रतीक माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को कर देने में कितना त्याग करना पड़ता है उससे व्यक्ति की कर देने की क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तीन विभिन्न विचार पाये जाते हैं,—

(अ) समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of Equal Sacrifice)।

(ब) समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त (Principle of Proportional Sacrifice)।

(स) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त (Principle of Minimum Sacrifice)।

समान त्याग के सिद्धान्त के अनुसार कर देने में सब लोगों को समान त्याग करना चाहिए। कर के द्रव्य भार (Money Burden) का बटवारा इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक करदाता को समान त्याग करना पड़े अर्थात् कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक करदाता को बराबर कष्ट सहना पड़े। यह सिद्धान्त समानुपातिक कर प्रणाली के पक्ष में है जिसमें करो की मात्रा आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। समानुपातिक त्याग के सिद्धान्त के अनुसार करो का वास्तविक भार करदाताओं पर समान नहीं होना चाहिये बल्कि वह उनकी आय अथवा उनके द्वारा प्राप्त आर्थिक कल्याण के अनुपात में होना चाहिए। अधिक आय वाले लोगों के ऊपर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए और कम आय वाले लोगों पर कम। यह सिद्धान्त प्रगतिशील कर प्रणाली के पक्ष में है जिसमें कर की दर व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धान्त के अनुसार कर के भार को इस प्रकार बाँटा जाना चाहिए कि समाज पर कर का सम्पूर्ण वास्तविक भार कम से कम रहे। जो लोग कर का अधिक भार उठा सकते हों उनके कंधों पर अधिक भार रखा जाना चाहिए। गरीबों से कर नहीं लिए जाने चाहिये और अमीरों को बहुत ऊँचे कर देने चाहिये। मार्शल, पीगू तथा डास्टन ने इसी सिद्धान्त को करारोपण का उचित आधार माना है। किन्तु यह सभी सिद्धान्त केवल सैद्धान्तिक महत्व रखते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से कर-दान क्षमता की नापने में कोई सहायता नहीं दे सकते हैं। वास्तव में त्याग अथवा असुविधा एक आंतरिक अनुभव की बात है और उसे निश्चित रूप से नापना सम्भव नहीं है।

बाहरी दृष्टिकोण (Objective Aspect)—किसी व्यक्ति की कर-दान क्षमता को उसके पास होने वाले धन अथवा उसे प्राप्त होने वाली आय के द्वारा भी नापा जा सकता है। इस प्रकार कर योग्यता को नापने के तीन मुख्य आधार हो सकते हैं—
(i) सम्पत्ति, (ii) उपभोग, (iii) आय इन तीनों में से कौनसा व्यक्ति की कर-दान योग्यता का उचित आधार हो सकता है, इस बारे में काफी मतभेद पाया जाता है। पहले सम्पत्ति को व्यक्ति की कर-दान योग्यता का प्रतीक समझा जाता था किन्तु

अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि अनेक सम्पत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की कर-दान योग्यता को निश्चित करना बहुत ठीक नहीं है क्योंकि यह सम्भव हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास सम्पत्ति न हो और फिर भी उसकी कर-दान योग्यता काफी हो। उदाहरण के लिये मासिक आय वाले व्यक्ति की कर-दान योग्यता उस विधवा की अपेक्षा बड़ी अधिक है जिसके पास भूकान है। इस दोष को दूर करने के लिए उपभोग अथवा व्यय को कर-दान क्षमता को नापने का आधार माना गया किन्तु अन्त में उसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अधिक व्यय वाले व्यक्ति की कर-दान योग्यता भी अधिक है। एक निधन व्यक्ति को जिसका परिवार काफी बड़ा है, धनी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है किन्तु उसकी कर-दान योग्यता बहुत कम होती है। अन्त में व्यक्ति की आय को कर-दान योग्यता नापने के लिए प्रयोग किया जाना लगा और संसार के लगभग सभी देशों में आय के आधार पर कर-दान योग्यता को निश्चित किया जाता है। किसी व्यक्ति की कर-दान योग्यता उसके द्वारा सरकार के संरक्षण में प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर होती है। किन्तु आय को कर-दान योग्यता के आधार के रूप में प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिये—(अ) आय सम्पत्ति से प्राप्त की जाती है अथवा व्यक्तिगत श्रम के द्वारा। सम्पत्ति से प्राप्त आय पर कर की दर ऊँची होती चाहिए। (ब) व्यक्ति के ऊपर आयश्रोतों की समस्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक अविवाहित व्यक्ति को विवाहित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कर देना चाहिए। (स) एक न्यूनतम छूट की भीमा होनी चाहिए जिस समाज के वर्तमान रहन-सहन स्तर के द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। (द) समीचीन पर कर लगाने समय प्रगामी कर सिद्धान्त का प्रयोग किया जाना चाहिये।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी न्याय सम्बन्धी सिद्धांत हैं किन्तु वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां पर उनकी संक्षेप में व्याख्या की जा सकती है।

(द) वित्तीय सिद्धान्त (Financial Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर सरकार के लिये एक वित्तीय साधन है जिसे द्वारा वह कम से कम विरोध के साथ अपनी आय प्राप्त कर सकती है। कर इसलिये लगाये जाते हैं क्योंकि उनसे सरकार को आय प्राप्त होती है। यह सिद्धान्त करारोपण का उचित आधार प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि करो का प्रयोग अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी किया जा सकता है।

(स) 'जैसा पाओ वैसा छोड़ो' सिद्धान्त (Leave as you found them principle)—इस सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान धन के वितरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। करो के द्वारा धन के वितरण की असमानताओं को न बढ़ाना चाहिये और न कम किया जाय। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो लोगों को बंसा ही छोड़ दे जैसा कि वह उन्हें पाती है। यह सिद्धान्त आजकल नहीं माना जाता है और इसके स्थान पर एक भिन्न सिद्धान्त का निर्माण किया गया है

जिसे सामाजिक-राजनैतिक सिद्धांत (Socio-Political Theory) कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर सरकार के हाथों में विभिन्न सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का निश्चित अस्त्र है जिनका प्रयोग धन की असमानताओं को दूर करने अथवा उद्योगों को बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।

कर उपभोग को नियंत्रित करने के लिए—इस सिद्धांत के अनुसार करों का प्रथम उद्देश्य हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब तथा अन्य मशीनें पदार्थों के उपभोग को नियंत्रित करना है। किन्तु यह विचार एक तर्फी है और करों के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों को इस में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

इन सभी सिद्धांतों का महत्व वर्तमान समय में काफी कम हो गया है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत करारोपण का उचित सिद्धांत समझा जाता है और सभी देशों में कर प्रणाली का निर्माण इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किन्तु अध्ययन की दृष्टि से अन्य सिद्धांत भी अपना स्थान रखते हैं।

करों का वर्गीकरण

किसी भी देश की कर प्रणाली विभिन्न प्रकार के करों का मिश्रण होती है। इन करों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए तथा कर प्रणाली में विभिन्न करों के महत्व को जानने के लिये करों का वर्गीकरण किया जाता है। करों के सम्बन्ध में कई प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कुछ एक वर्गीकरण इस प्रकार है—

(क) प्रत्यक्ष और परोक्ष कर

कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है और इस भार को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है अथवा नहीं इस आधार पर करों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) तथा परोक्ष कर (Indirect Tax)। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसके द्वारा कर का भार सहन किया जाना चाहिये। इस प्रकार के कर का भार कर देने वाले व्यक्ति पर ही होता है और वह किसी प्रकार भी उसे अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाल सकता है। इस प्रकार के करों में वर देने वाला ही कर के भार को सहन करता है। दूसरे शब्दों में कराघात (Impact of Tax) और करापात (Incidence of Tax) एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। ऐसे करों को जिनके भार का विप्रेक्षण (Deflection) अथवा नहीं होता है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आय कर तथा मृत्यु कर इसी प्रकार के कर होते हैं। इस प्रकार के कर अधिकांश धनिक वर्ग पर लगाये जाते हैं। इसके विपरीत परोक्ष कर वह होता है, जो एक व्यक्ति पर लगाया जाता है किन्तु आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से दूसरे व्यक्ति के द्वारा सहन किया जाता है। इस प्रकार के कर इस उद्देश्य से लगाये जाते हैं कि उनके भार को दूसरे व्यक्तियों पर टाल दिया जायगा। परोक्ष कर के सम्बन्ध में कर देने वाला एक व्यक्ति होता है और उसे सहन करने वाला दूसरा व्यक्ति अर्थात् इन करों का कराघात

और करायात अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। कर देने वाला कर के भार को सहन नहीं करता है बल्कि वह उसे अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। ऐसे कर को जिसके भार को दूसरे के कंधों पर टाला जा सकता हो, परोक्ष कर कहते हैं। मनोरजन कर तथा वस्तुओं के उत्पादन अथवा आयात पर लगाये जाने वाले कर परोक्ष कर होते हैं। ऐसे करों का भुगतान एक वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है किन्तु उन्हें दूसरे वर्ग के लोगों के कंधों पर टाल दिया जाता है। कभी-कभी एक ही कर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है। यदि कोई कर सरकार इस उद्देश्य में लगाती है कि उसका भार उन्हीं लोगों पर पड़े जो कि उसे देते हैं किन्तु आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के कारण कर-दाता के लिये कर के भार को अन्य व्यक्तियों पर टालना सम्भव हो जाता है तो ऐसा कर सरकार के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष है किन्तु कर-दाताओं के दृष्टिकोण से परोक्ष होगा। इसी प्रकार यदि किसी कर को इस उद्देश्य में लगाया जाता है कि उसके भार को अन्य व्यक्तियों पर टाल दिया जाय किन्तु परिस्थितिवश ऐसा करना सम्भव नहीं होता है तो ऐसी दशा में वह कर सरकार की दृष्टि में परोक्ष होगा तथा कर-दाताओं की दृष्टि में प्रत्यक्ष।

यद्यपि एक अच्छी कर प्रणाली वही होती है जिसमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, दोनों प्रकार के करों का उचित प्रयोग किया जाता हो किन्तु यह बताना बहुत कठिन है कि इन दोनों प्रकार के करों में से कौनसा अधिक अच्छा है। कर प्रणाली में दोनों प्रकार के करों के महत्व को समझने के लिये उनमें से प्रत्येक के लाभ तथा दोषों का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष करों के लाभ

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बहुत से लाभ बतलाये जाते हैं जिनके आधार पर वर्तमान कर प्रणाली में उनकी उपयोगिता को निश्चित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं—(i) प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें कर-दाता की आय अथवा सम्पत्ति के अनुमान में लगाया जाता है। इस प्रकार के कर प्रायः प्रगामी दर (Progressive Rate) के अनुसार लगाये जाते हैं जिसके कारण वे अधिक न्यायपूर्ण हो जाते हैं। धनी लोगों को इस प्रकार के कर अधिक मात्रा में देने होते हैं तथा कम आय वाले के लिये कर की दर नीची रखी जाती है। (ii) इस प्रकार के कर बहुत अधिक लोचदार होते हैं और उनसे होने वाली आय को आवश्यकता के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। देश में धन की वृद्धि के साथ साथ इन करों से होने वाली आय अपने आप बढ जाती है। (iii) प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों की अपेक्षा अधिक उत्पादक होते हैं क्योंकि उनसे सरकार बड़ती हुई मात्रा में आय प्राप्त कर सकती है। आय प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों को अच्छा समझा जाता है। (iv) इस प्रकार के कर अधिक निश्चित होने हैं। कर-दाता को निश्चित रूप में यह पता होता है कि उसे कब और कितना कर देना है। इसी प्रकार सरकार भी प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय का अनुमान लगा

सकती है। (v) प्रत्यक्ष कर अधिक मितव्ययितापूर्ण होते हैं क्योंकि उनका एकत्रण व्यय बहुत कम आता है। इस प्रकार के कर बहुत कम लोगों से इकट्ठे करने होते हैं और उन्हें आय के भ्रोत पर ही ले लिया जाता है। इसलिये उनके इकट्ठा करने पर बहुत कम खर्च आता है। (vi) इस प्रकार के कर लोगों में नागरिकता की भावना उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्ष कर इस प्रकार लिये जाते हैं कि कर-दाता को कर देते समय उनके भार का पूरा अनुभव होता है। इन करों को देते समय लोग यह अनुभव करते हैं कि वे देश में सुरक्षा तथा न्याय को स्थापित करने के लिये कुछ दे रहे हैं और इसीलिये वे इस बात में काफी दिलचस्पी लेते हैं कि सरकार करों के द्वारा प्राप्त उनके धन का व्यय किस प्रकार करती है? यदि सरकार उसका अपव्यय करती है तो लोग उसके विरोध में अपना असन्तोष प्रकट करते हैं जिससे राजस्व की कुशलता में वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष करों के दोष :

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में पाये जाने वाले कुछ दोष इस प्रकार हैं—(i) वे अविभाजनक होते हैं। प्रत्यक्ष कर लोगों के द्वारा महसूस किये जाते हैं और उन्हें देते समय कष्ट होता है इसलिए लोग उन्हें पसन्द नहीं करते हैं। इस प्रकार के करों में वृद्धि करने से असन्तोष उत्पन्न होता है जिसके कारण सन्देह में सरकार की आय बेवोचदार हो जाती है। (ii) इन करों को ठीक-ठीक निश्चित करना संभव नहीं होता है और उन्हें मनचाही दरों पर लगाया जाता है जिसके कारण उनमें न्याय-शीलता का गुण कम हो जाता है। (iii) इस प्रकार के करों के अपवंचन (Evasion) का भय अधिक रहता है। करदाता भूँडे हिसाब देकर इन करों से बचने का प्रयत्न करते हैं जिसके कारण सरकार को इन करों से उतनी आय नहीं होती है जितनी कि होनी चाहिये। (iv) प्रत्यक्ष करों के द्वारा समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँचा जा सकता है। विशेषकर निर्धन व्यक्तियों पर इस प्रकार के कर नहीं लगाये जा सकते हैं। (v) इन करों से होने वाली आय सरकार के लिए अपर्याप्त रहती है। व्यवहारिक अनुभव यह बतलाता है कि कोई भी सरकार केवल प्रत्यक्ष करों से अपनी सम्पूर्ण आय प्राप्त नहीं कर सकती है।

परोक्ष करों के लाभ :

परोक्ष करों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान सरकारें अपनी आय बढ़ाने के लिये इस प्रकार के करों का अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग कर रही हैं। इन करों के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं :—(i) परोक्ष कर अधिक सुविभाजनक होते हैं क्योंकि वे ऐसे समय लिए जाते हैं जब उनका देना कर-दाता के लिए सुविधापूर्ण होता है। वस्तुओं पर कर उस समय लिया जाता है जब उपभोक्ता उसे खरीदता है। इस प्रकार के कर एकदम नहीं लिए जाते हैं बल्कि उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके लिया जाता है। (ii) यह कर लोगों को महसूस नहीं होते हैं। परोक्ष कर इस प्रकार लिए जाते हैं कि उन्हें देते समय लोगों को यह अनुभव नहीं होता

है कि घं कर दे रहे हैं। उदाहरणार्थ कपड़ा, चीनी, मिट्टी के तेल आदि पर हम प्रतिदिन कर देते हैं किन्तु हमें इस बात का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार के करों की दर में वृद्धि करने पर असन्तोष तथा उत्तेजना नहीं फैलती है और सरकार इनसे थड़ती हुई मात्रा में आय प्राप्त कर सकती है। (iii) इस प्रकार के करों से वचना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे वस्तुएं खरीदते समय लिये जाते हैं। अपवचन की सम्भावना कम होने के कारण सरकार को परोक्ष करों से काफी आमदनी प्राप्त हो जाती है। (iv) परोक्ष करों के द्वारा समाज के सभी वर्गों तक पहुँचा जा सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इन करों का कुछ न कुछ भाग अवश्य देना पड़ता है। समाज के धनी तथा निधन वर्ग दोनों को ही यह कर देने होते हैं। (v) इनका प्रयोग सामाजिक उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है। हानिकारक वस्तुओं पर लगाये गये परोक्ष कर, इन वस्तुओं के प्रयोग को कम करते हैं और इस प्रकार वे एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य को पून करते हैं। (vi) यदि इन करों को आवश्यकता की वस्तुओं पर लगाया जाय तो वे काफी लोचदार होते हैं और सरकार उनसे अधिकाधिक मात्रा में आय प्राप्त कर सकती है।

परोक्ष करों के दोष

परोक्ष करों में कुछ दोष भी पाये जाते हैं—(i) इस प्रकार के कर अधिक व्यापक नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लगाते समय लोगों की कर दान योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। परोक्ष कर प्रायः सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जिसके कारण उनका भार समीचीन की अपेक्षा गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है। (ii) वे मितव्ययितापूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें एकरित करने का व्यय बहुत आता है। परोक्ष कर असरम लोगों से इकट्ठा करने पड़ते हैं जिसके कारण उन्हें एकरित करने के लिये सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है। (iii) वे अनिश्चित होते हैं। करदाता को यह पता नहीं होता कि उसे कितनी मात्रा में परोक्ष कर देने हैं। सरकार भी परोक्ष करों से होने वाली आय का अनुमान ठीक-ठीक नहीं लगा सकती है। (iv) इन करों के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है जिससे व्यापार को हानि होती है और उपभोक्ताओं के रहन सहन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (v) मुद्रा संकुचन के लिये इन करों से होने वाली आय गिर जाती है। मन्दी के लाल में वस्तुओं की माग कम हो जाती है जिसके कारण वस्तु करों से होने वाली आय में भारी कमी आ जाती है। (vi) यह कर नागरिक भावना को जाग्रत नहीं करते हैं—इन्हें देने समय कर-दाता को कष्ट का अनुभव नहीं होता है इसलिये वह सरकार के द्वारा किये जाने वाले धर्म के प्रति उदासीन रहता है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में बड़ी अधिक साम्यपूर्ण है यह बताना बहुत कठिन है। दोनों ही प्रकार के करों से कुछ लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं किन्तु उनके दोषों में संतर्क रहना भी आवश्यक है। वास्तव में प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के बीच एक को छोड़कर दूसरे को छाटने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। किसी देश की कर प्रणाली में दोनों प्रकार के कर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक आदर्श कर प्रणाली

वही मानी जाती है जिसमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का उचित सम्मिश्रण पाया जाता हो।

(ख) आनुपातिक कर तथा प्रगतिशील कर :

करों को एक दूसरे दृष्टिकोण से आनुपातिक तथा प्रगतिशील करों में बांटा जा सकता है।

(१) आनुपातिक कर (Proportional Tax):—आनुपातिक कर वह कर होता है जो आय के अनुपात में लगाया जाता है। इस प्रकार के कर ठीक उसी अनुपात में बढ़ते हैं जिस अनुपात में व्यक्ति की आय अथवा सम्पत्ति में वृद्धि होती है। आनुपातिक कर वे कर होते हैं जो सब प्रकार की आयों पर एक ही दर अथवा प्रतिशत के हिसाब से लिये जाते हैं और आमदनी के घटने बढ़ने पर कर दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि प्रत्येक कर-दाता को अपनी आय का २% कर के रूप में देना पड़े तो इस प्रकार का कर आनुपातिक होगा क्योंकि कर की दर का सम्बन्ध आय की मात्रा से कुछ नहीं है। इस प्रकार के कर की दर आमदनी के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती है और आमदनी का ठीक वही प्रतिशत कर के रूप में लिया जायगा चाहे आमदनी कितनी ही हो। आनुपातिक कर इस प्रकार होता है—

कर की दर ६ ३/४ प्रतिशत

आय	कर की मात्रा
१०० रु०	६-२५ रु०
२०० रु०	१२-५० रु०
५०० रु०	३१-२५ रु०

आनुपातिक कर इस विचार पर आधारित है कि समाज में धन का वर्तमान वितरण उचित है और उसे करारोपण के द्वारा नहीं बदला जाना चाहिये। विभिन्न व्यक्तियों की आय का अनुपात कर देने के पक्षपात भी उसी प्रकार बना रहता है जैसा कि कर देने से पूर्व था। आरम्भ में अर्थशास्त्रियों के द्वारा आनुपातिक करों को उचित बताया जाता था क्योंकि वे धन के वितरण को नहीं बदलते हैं किन्तु शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने लगा कि इस प्रकार के करों का भार धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। आनुपातिक कर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं—(i) वह बहुत सरल होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर का अनुमान आसानी से लगा सकता है। (ii) इस प्रकार का कर समाज में धन के वितरण को नहीं बदलता है। किन्तु आनुपातिक कर का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह न्यायपूर्ण नहीं होता है क्योंकि लोगों की कर-दान क्षमता उससे अधिक अनुपात में बढ़ती है जिसमें कि उनकी मोद्रिक आय में वृद्धि होती है।

(२) प्रगतिशील कर (Progressive Tax) :—आनुपातिक करों के दोषों को दूर करने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाने के लिये कहा जाता है। प्रगतिशील कर वह कर होता है जिसके द्वारा आय के बढ़ने के साथ-साथ उसका

अधिकारिक नाश कर के रूप में लिया जाता है। प्रगतिशील करों के सम्बन्ध में आय में वृद्धि या कमी के साथ कर की दर में भी परिवर्तन होता है। विभिन्न आय वालों को एक ही दर पर कर नहीं देना पड़ना है। जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है उनके साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। उदाहरणार्थ—

आय	कर की दर
५००० रु० तक	१०%
५००१ से १०,००० तक	१५%
१०,००१ से १५,००० तक	२२%

इसी प्रकार आय के बढ़ने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती है और बहुत ऊँची आय वालों को अपनी आय का काफी बड़ा भाग कर के रूप में देना पड़ता है। प्रगामी कर इस विचार पर आधारित है कि आय के बढ़ने के साथ लोगों की कर दान क्षमता उभरे अधिक अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है। इसीलिये अमीरों पर कर की दर अधिक रखी जाती है और कम आय वालों पर कम। इस प्रकार का कर आधुनिक युग में अच्छा समझा जाता है क्योंकि वह समानता तथा न्यायशीलता के सिद्धान्त के अनुकूल होता है।

प्रगतिशील करों के पक्ष में दिये जाने वाले कुछ तर्क इस प्रकार हैं — (Arguments in Favour of Progressive Tax System) :— (i) इस प्रकार का कर समानता के सिद्धांत (Canon of Equity) के अनुसार होता है। मौद्रिक आय के सम्बन्ध में भी घटती हुई उपयोगिता का नियम लागू होता है और लोगों की आय के बढ़ने के साथ-साथ उनके लिए मुद्रा की उपयोगिता कम होती जाती है। अमीरों के लिये गरीबों की अपेक्षा मुद्रा की उपयोगिता बहुत कम होती है इसलिए कर के भार को समान रूप से बाँटने के लिए अमीरों पर अधिक कर लगाए जाने चाहिये और गरीबों पर कम। इस प्रकार की व्यवस्था प्रगामी कर के द्वारा ही समझ हो सकती है।

(ii) यह कर अधिक न्यायपूर्ण है। नैतिक दृष्टि से वही कर अधिक न्यायपूर्ण होता है जो अमीरों पर अधिक से अधिक तीव्रता के साथ पड़ता हो क्योंकि उनकी कर देने की योग्यता बहुत अधिक होती है। प्रगामी करों के द्वारा ही अमीरों से अधिक और गरीबों से कम कर लिए जा सकते हैं।

(iii) प्रगतिशील कर समाज में धन के वितरण को ठीक करने में सहायता देते हैं। वर्तमान समाज में धन का वितरण बहुत अधिक असमान है और कारारोपण का उद्देश्य इस असमानता को दूर करना होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है।

(iv) इस प्रकार के कर काफी जोखपूर्ण तथा उत्पादक होते हैं। कर की दर में जरा सी वृद्धि करने से सरकार को बहुत अधिक मात्रा में आय प्राप्त हो सकती है। समाज में लोगों की आय में वृद्धि होने पर इन करों से होने वाली आय स्वयं बढ़ती जाती है।

(v) यह कर अधिक मितव्ययितापूर्ण होता है क्योंकि सरकार को उसे एकत्रित करने में बम व्यय करना पड़ता है ।

प्रगतिशील करो के दोष :

प्रगतिशील करो के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं —

(i) कर की प्रगतिशीलता की दर को ठीक प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता है । कोई वर जितना प्रगामी होना चाहिये इसे निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । प्रगतिशीलता की दर (Rate of Progression) को प्रायः मनमाने ढंग से निश्चित किया जाता है जिसके कारण लोगों के साथ कितना भी अन्याय किया जा सकता है ।

(ii) इस प्रकार के कर समाजवाद के सिद्धांत के अनुकूल हैं इसलिए पूँजी-पति वर्ग इसका विरोध करता है ।

(iii) प्रगतिशील कर व्यवसायियों के प्रोत्साहन को कम करता है । अधिक आय पर कर दर बहुत ऊँची होने के कारण एक सीमा के पश्चात् लोग अपनी आय में वृद्धि करने के प्रति उदासीन हो जाते हैं ।

(iv) इन करो का पूँजी के संचय पर बुरा प्रभाव पड़ता है । जिन लोगों में बचत करने की क्षमता होती है उन्हीं लोगों पर प्रगामी कर अधिक तीव्रता के साथ पड़ता है जिसके कारण समाज में पूँजी के संचय में रुकावट होती है ।

(v) इस प्रकार के कर अमीर लोगों को कर से बचने के लिये अनैतिक विधियों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं । कर की दर ऊँची होने के कारण उससे बचने के लिये सभी तरीकों का प्रयोग किया जाता है ।

(३) प्रतिगामी कर (Regressive Tax)—प्रतिगामी कर प्रगतिशील कर का बिल्कुल विपरीत होता है । इस प्रकार के कर की दर आय के बढ़ने के साथ कम होती जाती है । प्रतिगामी कर वह कर होता है । जिसका भार धनी वर्ग की अपेक्षा गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता हो । इस प्रकार के कर का न्याय में कोई स्थान नहीं है । कोई भी शिक्षित समाज ऐसे कर को नहीं स्वीकारता है जिसकी दर आय में वृद्धि के साथ बढ़ती हो किन्तु फिर भी वस्तुओं पर लगाये गए कुछ करो का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक होता है । यदि कर उस वस्तु पर लगाया जाता है जिसका अधिक प्रयोग गरीब लोगों के द्वारा किया जाता है तो ऐसा कर प्रभाव में प्रतिगामी कर के समान होता है । भारतीय नमक कर इसी प्रकार का कर था और गरीबों को उसका अधिक भार सहन करना पड़ता था इसीलिए उसका भारी विरोध किया गया । प्रतिगामी करो के पक्ष में कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे कर न्याय के विरुद्ध होते हैं और जनता उन्हें सहन नहीं कर सकती इस प्रकार के करो का भार उन कंधों पर अधिक पड़ता है जो उसे सहन नहीं कर सकते । किन्तु कभी-कभी इन करों का लाभपूर्ण प्रयोग भी किया जा सकता है । यदि कुछ वस्तुओं का प्रयोग निर्धन वर्ग में कम करने के लिये उन्हें काम में लाया

जाना है तो वे समाज हित में हो सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि गरीब भयवा तम्बाकू का प्रयोग निर्धन वर्ग में कम करने के लिये, इन वस्तुओं की उस श्रेणी पर अधिक कर लगाया जाता है जो गरीब वर्ग प्रयोग करता है तो उसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं का प्रयोग कम हो सकता है। किन्तु साधारणतया इन उद्देश्य के लिए इन करों का प्रयोग नहीं किया जाना है और वर्तमान कर प्रणाली में प्रतिगामी करों का कोई स्थान नहीं है। प्रायः उन्हें घुणा की दृष्टि में देखा जाता है।

(४) अधोगामी कर (Degressive Tax)—जो कर कम प्रतिगामी होते हैं और जिनकी दर आय में वृद्धि के साथ बहुत ही मन्द प्रति में बढ़ती है, ऐसे करों को अधोगामी कर कहा जाता है। इस प्रकार के करों की दर आय के बढ़ने पर बढ़ती तो है किन्तु कर में वृद्धि की दर आय के बढ़ने के माप कम होती जाती है। अमीर लोगों पर ऐसे कर का भार अपेक्षाकृत कम पड़ता है और वे उनका त्याग नहीं करते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिये। कर एक सीमा तक प्रगामी हो सकते हैं और उस के पश्चात् अनुपातिक। कर की दर आय की वृद्धि की एक सीमा तक तो बढ़ती है किन्तु उसके पश्चात् एक ही दर में कर लिया जाता है। ऐसे करों के सम्बन्ध में कम आम वाले व्यक्तियों को अधिक आय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक त्याग करना पड़ता है। अधोगामी कर व्याप के विरुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें अधिक पसन्द नहीं किया जाता है। लगभग प्रत्येक प्रगामी कर अन्तिम भाग में अधोगामी होने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि एक सीमा के पश्चात् इन करों की दर अनुपातिक हो जाती है।

एक तथा अनेक-कर प्रणाली

एक कर प्रणाली में केवल एक कर लगाया जाता है और राज्य की समस्त आय इसी एक कर के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके विपरीत अनेक कर प्रणाली विभिन्न प्रकार के करों पर आधारित होती हैं और सरकार अपनी-अपनी आयदनी प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के कर लगाती है। आरम्भकाल से ही कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है और इसलिये प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने एक कर प्रणाली को अपनाते पर अधिक जोर दिया। निर्वाचावादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) के अनुसार एक कर प्रणाली ही उत्तम है क्योंकि उनके द्वारा सरकार सीधा उन लोगों तक पहुँच सकती है जो समाज में अतिरिक्त (Surplus) उत्पन्न करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों का मत था कि कर केवल अतिरिक्त में से ही दिया जा सकता है। इंग्लिश सरकार को उन्हीं लोगों पर कर लगाना चाहिये जो अतिरिक्त उत्पन्न करते हैं। अन्य लोगों के ऊपर कर लगाने का परिणाम यह होगा कि उन्हें दूसरे लोगों पर टाल दिया जायगा। क्वेसनी (Quesney) तथा टर्गोट (Turgot) आदि निर्वाचावादियों ने केवल अधिक लगान पर एक कर लगाने का सुझाव दिया क्योंकि इनके अनुसार सभी करों का भार अन्त में लगान पर पड़ता है।

भूमि का लगान ही यह अतिरेक है जो समाज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिससे से कर दिया जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार के कर का सुभाव इसलिये दिया क्योंकि उसके भार को न तो अन्य लोगों पर टालना संभव है और न ही वह समाज में बचत पर कोई बुरा प्रभाव डालता है। हैनरी जार्ज (Henry George) ने भी भूमि पर एक कर लगाने की प्रणाली का समर्थन किया है। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनका कहना था कि सरकार को कर के द्वारा भूमि के मुक्त लगान या हमारे मूल्य में होने वाली अनजित वृद्धि (unearned increment) को ले लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करना न्याय की दृष्टि में उचित है। भूमि पर एक कर लगाये जाने की प्रणाली में अनेक दोष पाये जाते हैं। केवल भूमि के लगान पर हर लगा कर एक आधुनिक सरकार के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त आय ही प्राप्त की जा सकती। इस प्रकार के कर को न्याय-पूर्ण भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत केवल एक प्रकार की सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति वाले लोग कर से बच जाते हैं। कर से बचने के लिये लोग अपने धन को भूमि में न लगा कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति में लगाने का प्रयत्न करेंगे। कर के भार का वितरण भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा क्योंकि एक धनी व्यक्ति को, जिसके पास भूमि नहीं है, कोई कर नहीं देना होगा तथा एक निधन व्यक्ति को जिसने अपनी समस्त पूँजी मकान अथवा भूमि खरीदने में लगा दी है, कर देना पड़ेगा।

वर्तमान काल में कुछ समाजवादी लेखकों ने केवल आय पर कर लगाने का सुभाव दिया है। उनके अनुसार आय को कर का आधार बनाकर कर एक कर प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के कर से पर्याप्त आय भी प्राप्त की जा सकती है और इसे प्रतिगामी बना कर तथा इसमें समस्त प्रकार की आय को सम्मिलित करके कर के भार को विभिन्न लोगों पर उचित ढंग से बाँटा जा सकता है। किन्तु फिर भी आय कर को दोष-रहित नहीं कहा जा सकता है। केवल आय पर कर लगाने की व्यवस्था में भी अनेक दोष पाये जाते हैं—(i) इस कर के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अमृतिधा होगी क्योंकि यह कर सभी लोगों को देना होगा। (ii) इस प्रकार के कर को विशेषतया छोटी आय वाली से एकत्रित करने में काफी व्यय करना होगा तथा प्रशासन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। (iii) एक ही प्रकार का कर होने के कारण उससे बचने की सम्भावना बढ जायेगी। (iv) इस प्रकार का कर लोगों की आय को कम करके बचत को हतोत्साहित करता है। (v) केवल आय पर कर लगाया जायगा तो धन तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकारी कर से बच जायेंगे।

उपरोक्त सभी दोषों के अतिरिक्त एक-वर प्रणाली के विरुद्ध तथा अनेक वर प्रणाली के पक्ष में अभिलिखित तर्क भी दिय जाते हैं—

(१) एक-कर प्रणाली व्यक्तियों के बीच असमानता उत्पन्न करती है जिसे केवल अनेक-कर प्रणाली के द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

(२) इस प्रणाली में कर से वच निकलने की सम्भावना काफी बढ़ जाती है क्योंकि उसे रोकने के लिये अन्य प्रकार का कोई कर नहीं होता।

(३) इस प्रकार की कर प्रणाली में लोच का अभाव रहता है।

इन्हीं सब कारणों से अनेक-कर प्रणाली (Multiple Tax System) को एक-कर प्रणाली (Single Tax System) की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है। एक कर प्रणाली केवल सिद्धान्तवादियों का स्वप्न है और उसे व्यवहारिक रूप देना सम्भव नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अनेक-कर प्रणाली ही अधिक सफल हो सकती है। अनेक-कर प्रणाली के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं—
(i) इस प्रकार की प्रणाली में कर-अवयवधन (Tax Evasion) को काफी सीमा तक रोका जा सकता है। (ii) कर नीति को भेद-रहित बनाया जा सकता है। (iii) एक प्रकार के कर से उत्पन्न होने वाली दोष दूसरे प्रकार के करों के द्वारा दूर हो जाते हैं जिसके कारण कर प्रणाली अधिक व्यापक हो जाती है। (iv) विभिन्न प्रकार के करों के द्वारा सरकार पर्याप्त आमदनी प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि आजकल सभी देशों में अनेक-कर प्रणाली को अपनाया जाता है।

एक-कर प्रणाली के दोष तथा व्यवहार में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण आर्थर यंग (Arthur Young) ने करों के भार को अधिक से अधिक मंदो पर बाँटने का जोरदार समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि यदि “मुझे एक अच्छी कर-प्रणाली की परिभाषा करनी पड़े तो वह यह होगी कि करों का थोड़ा-थोड़ा भार बहुत सी मंदो पर बाँट दिया जाय और बहुत बड़ा भार किसी एक मंद पर न लादा जाय।”^१ उनका यह विचार अमूल्य है क्योंकि यह हमें दूसरी सीमा पर ले जाता है। अनेक-कर प्रणाली को अपनाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि करों की सख्या बहुत अधिक न हो जाय क्योंकि करों की सख्या अधिक होने से उन्हें झकझुकारने पर व्यय बहुत अधिक आता है तथा व्यवहारिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। अतः कर प्रणाली न तो एक कर पर आधारित होनी चाहिये और न बहुत अधिक करों पर। सरकार को अपनी अधिकतम आय के लिये केवल कुछ एक करों पर निर्भर रहना चाहिये। वास्तव में सबसे अच्छी कर प्रणाली न तो एक-कर प्रणाली है और न अनेक-कर प्रणाली, बल्कि इनके बीच की कोई व्यवस्था हो सकती है। बैस्टाबल (Bastable) ने बहु-कर प्रणाली (Plural Tax System) को सबसे अच्छा बतलाया है। उनके अनुसार कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसमें कुछ बड़े-बड़े कर ऐसे हो जिनका भार केवल धनी लोगों पर पड़े जैसे आय-कर, मृत्यु-कर आदि

1 “If I were to define a good tax-system, it should be that of bearing lightly on an infinite number of points, heavily on none.”

तथा थोड़े से कर ऐसे चाहिये जिनका भार समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़े जैसे उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर ।

एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताये :

किमी देश की कर प्रणाली को अच्छा अथवा बुरा कहने से पूर्व हमें उसकी विस्तृत जांच करनी चाहिये । कर प्रणाली में कुछ ऐसे कर हो सकते हैं जो एक दृष्टि से अच्छे सुविधाजनक हों किन्तु किसी अन्य दृष्टिकोण से वे उतने उपयुक्त न हों । इसलिये कर प्रणाली का अध्ययन सम्पूर्ण रूप से किया जाना चाहिये । किमी एक या दो करो को देख कर यह कह देना कि कर प्रणाली अच्छी है अथवा बुरी, उचित नहीं है । यद्यपि यह कहना अत्यन्त कठिन है कि कौनसी कर प्रणाली अच्छी है किन्तु फिर भी कुछ सामान्य गुणों के आधार पर कर प्रणाली की प्रकृति के विषय में कुछ आश्वासन कहा जा सकता है । सामान्यतया एक अच्छी कर प्रणाली वही है जो करारोपण के सिद्धान्तों के अनुकूल हो । अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक अच्छी कर प्रणाली में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये—

(१) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उचित मिश्रण—एक अच्छी कर प्रणाली के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसमें प्रत्यक्ष (Direct) तथा परोक्ष (Indirect) दोनों प्रकार के कर सम्मिलित हों । समाज में कर के भार को कम से कम रखने के लिये यह जरूरी है कि उसे समाज के सभी वर्गों पर बाँटा जाय । समाज में सभी लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कर देने चाहिये । किसी एक वर्ग पर कर के भार को डालना नैतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है इसलिये कर के भार को सभी लोगों पर समान रूप से बाँटा जाना चाहिये । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के करों के द्वारा ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा जा सकता है । प्रत्यक्ष करों का भार केवल अमीर लोगों पर होता है और उनके द्वारा अन्य वर्ग के लोगों को कर प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है । केवल परोक्ष करों के द्वारा ही गरीब तथा मध्यम श्रेणी के लोगों तक पहुँचा जा सकता है । अतः एक अच्छी कर प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के कर होने चाहिये और इन करों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिये कि करों का भार किसी विशेष वर्ग पर केन्द्रित न होकर समाज में सभी लोगों पर समान रूप से तथा कम से कम पड़े ।

(२) उत्पादकता (Productivity)—अच्छी कर प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उत्पादकता है । कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि वह सरकार के लिये पर्याप्त मात्रा में आय उपाजन कर सके । ऐडम्स (Adams) के अनुसार 'एक अच्छी आगम प्रणाली को सरकार की उचित आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होना चाहिये ।'² इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार अपनी अधिकांश आय बहुत से सापेक्षिक रूप से अनुत्पादक करों से प्राप्त करने की अपेक्षा कुछ एक उत्पादक करों

में प्राप्त करेंगे। किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि समाज की उत्पादन शक्ति पर करो का बुरा प्रभाव न पड़े जिसे कि भविष्य में आय का प्रवाह घटा रहे। केवल आमदनी को ध्यान में रख कर ऐसे करो को न लगाया जाय जिनका वचन की मात्रा अथवा धन के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो।

(३) कर प्रणाली लोचदार होनी चाहिये (Elasticity)—एक अच्छी कर प्रणाली में लोच का गुण होना भी आवश्यक है। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि करो से प्राप्त होने वाली आय की आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके। कर प्रणाली में ऐसे करो की मात्रा कम से कम होनी चाहिये जिनमें प्राप्त होने वाली आय को घटाता बढ़ाना सम्भव न हो। भूमि का लगान इसी प्रकार का कर है। ऐसे करो के कारण कर प्रणाली में लोच का गुण कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि कर प्रणाली में लोचदार करो की मात्रा को अधिक रखा जाय तो सरकार के लिये असामान्य परिस्थिति में अधिक आय प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

(४) कर प्रणाली सुविधापूर्ण होनी चाहिये (Convenience)—कर प्रणाली करदाताओं के दृष्टिकोण में सुविधापूर्ण होनी चाहिये। करदाताओं को अनावश्यक कष्ट से बचाने के लिये यह जरूरी है कि करो की वसूली इस प्रकार की जाय कि लोगो को कर देने में कम से कम असुविधा हो। कर लगाने समय करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। कर ऐसे समय लिये जाने चाहिये जब लोग उन्हें वसूल करने का समय निश्चित हो। डाल्टन (Dalton) के अनुसार एक अच्छी कर प्रणाली वही है जिसमें करो की कम से कम महसूस किया जाय अर्थात् जिसमें लोगो को कम से कम असुविधा हो।

(५) कर प्रणाली सरल (Simple), निश्चित (Certain) तथा मितव्ययिता-पूर्ण (Economical) होनी चाहिये—एक अच्छी कर प्रणाली सरल तथा करदाताओं दोनों के दृष्टिकोण से साधारण होनी चाहिये। कर प्रणाली का निश्चित होना भी आवश्यक है। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि उसे करो से कितना और कितनी आय प्राप्त होनी है। इसी प्रकार करदाताओं को भी यह पता होना चाहिये कि उन्हें कितना और कितना कर देना है। कर प्रणाली को मितव्ययितापूर्ण होनी चाहिये जिससे कि करो को इकट्ठा करने में कम से कम अपव्यय हो तथा उन्हें सस्ते ढंग से इकट्ठा किया जा सके।

(६) कर प्रणाली अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त (Theory of Maximum Social Advantage) के अनुकूल होनी चाहिये—कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसका समाज के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर कम से कम बुरा प्रभाव पड़े। करो को इस प्रकार लगाया जाना चाहिये कि वे देश के व्यापार तथा उद्योगों के विकास में कम से कम बाधा उत्पन्न करें। समाज में वचन की मात्रा तथा लोगो की उत्पादन शक्ति पर भी उन का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये जिससे

राष्ट्रीय आय में कमी न हो और उत्पत्ति के स्रोत सूखने न पायें। संक्षेप में कर प्रणाली आर्थिक रूप से उचित होनी चाहिये और देश की आर्थिक उन्नति में बाधक नहीं होनी चाहिये। ऐसी कर प्रणाली ही अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। डा० डाल्टन (Dalton) के अनुसार, 'सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जिसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता हो या जिसके बुरे प्रभाव कम से कम हो।'³

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अच्छी प्रणाली वही है जो करारोपण के सिद्धान्तों के अधिक से अधिक अनुबल हो। किन्तु व्यवहारिक रूप में ऐसी आदर्श कर प्रणाली की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। कोई भी कर प्रणाली करारोपण के सब सिद्धान्तों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती है। वास्तव में ऐहम स्मिथ के द्वारा बताये गये करारोपण के सिद्धान्त कुछ सीमा तक एक दूसरे के विरोधी हैं। यह सम्भव हो सकता है कि एक कर किसी एक सिद्धान्त के अनुबल हो किन्तु यह अन्य सिद्धान्तों को सन्तुष्ट न करता हो। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि जो प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को सन्तुष्ट करती हो, वही अच्छी कर प्रणाली है।

कर-दान क्षमता

वर्तमान समय में कर-दान क्षमता का विचार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। लगभग सभी देशों में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसके कारण सरकार के कार्यों तथा उनके उत्तरदायित्वों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार को बढ़ते हुये कामों को पूरा करने के लिये अधिकाधिक साधनों की आवश्यकता होती है। करारोपण वर्तमान राज्यों की आय का मुख्य साधन है किन्तु कोई भी सरकार करो को किसी भी सीमा तक नहीं बढ़ा सकती है। प्रत्येक समाज की कर देने की क्षमता होती है जिससे अधिक मात्रा में लोगों पर कर नहीं लगाये जा सकते हैं। कर-दान क्षमता उस सीमा को बताती है जहाँ तक सरकार समाज को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये बिना करो में वृद्धि कर सकती है। इस सीमा के पश्चात् करो में वृद्धि करना जनता में अनन्तोप उत्पन्न करता है तथा सामाजिक लाभ को कम करता है।

सरकार को करो में कितनी आमदनी प्राप्त हो सकती है यह लोगों की कर-दान क्षमता के ऊपर निर्भर होता है। जिन देशों में समाज की कर-दान क्षमता अधिक है वहाँ पर सरकार करो के द्वारा अधिक आय प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत कम कर-दान क्षमता वाले देशों में करो से कम आमदनी प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक राज्य सरकार यह जानना चाहती है कि वह करो की मात्रा को कहाँ तक बढ़ा सकती है अर्थात् करारोपण से कितनी अधिकतम आय प्राप्त की जा सकती है।

3 "The best system of taxation is that which has the best or the least bad effects."

—Dalton

कर-दान क्षमता के विचार के महत्व को बताते हुये फिन्डले शिराज (Findlay Shirras) ने कहा है कि "भरवार के लिये मोटे तौर से भी यह जानना बुद्धिमानी होगी और साथ ही उपयोगी भी, कि साधारण और असाधारण दोनों ही परिस्थितियों में करो के द्वारा देश किस सीमा तक अदायगी कर सकता है।" विशेषतया मार्बनियन प्लान से लदे हुये वज्रों को मन्तुलित करने की आवश्यकता ने तथा सरकारों के तेजी के साथ बढ़ते हुये व्यय ने कर-दान क्षमता को करारोपण की एक वास्तविक तथा स्थिर ममस्था बना दिया है।

कर-दान क्षमता का अर्थ :

कर-दान क्षमता में अभिप्राय किसी समाज की कर देने की शक्ति से होता है। यह उस सीमा को बताता है जहाँ तक भरवार जनता से करारोपण के द्वारा आय प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रीय आय में से वह खर्च काट कर जो देश की पूँजी तथा लोगों की योग्यता से स्थिर बनाये रखने के लिये आवश्यक है, जो कुछ शेष बचता है, वही लोगों की कर देने की क्षमता का सूचक है। कर-दान क्षमता का अर्थ के विषय में अर्थशास्त्रियों में काफी मत-भेद पाया जाता है। फिन्डले शिराज के अनुसार "कर-दान क्षमता से अभिप्राय घन की उस अधिकतम मात्रा से है, जो असहनीय घट्ट का अनुभव किये बिना, किसी देश के नागरिक सार्वजनिक व्यय के लिये दे सकते हैं।" इस विचार को अधिक स्पष्ट करने हुये उन्होने आगे चल कर कहा है कि "कर-दान क्षमता उत्पाति का उस न्यूनतम उपभोग पर कुल अतिरिक्त (Surplus) है जो उन उत्पादन को करने के लिये आवश्यक होता है यदि लोगों के जीवन-स्तर में कोई परिवर्तन न हो।" इस विचार के अन्तर्गत न्यूनतम उपभोग में कार्य-कुशलता सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा पूँजी की वृद्धि एवं उसके Replacement के लिये किया जाने वाला व्यय आ जाता है। सर जोसिया स्टाम्प (Sir Josiah Stamp) के अनुसार, "कर-दान क्षमता कुल उत्पादन का कुल उपभोग के ऊपर आधिक्य है। यह वह अधिकतम रकम है जो किसी देश के नागरिक, बिना वास्तव में आनन्द-रहित और दलित जीवन बिताये और बिना आर्थिक संगठन में बहुत उथल-पुथल किये, लोक सत्ता के व्यय को पूरा करने के लिये दे सकते हैं।" उपरोक्त

4 "Taxable Capacity may be defined as the maximum amount which the citizens of a country can contribute towards the expenses of public authorities without having to undergo an unbearable strain"
—Findlay Shirras

5 "It is the total surplus of production over the minimum consumption required to produce that volume of production, the standard of living remaining intact"
—Findlay Shirras

6 "Taxable capacity is the margin of total production over total consumption It is the maximum amount which the citizens of a country can contribute towards the expenses of the public authorities, without having a really unhappy and down-trodden existence and without dislocating the economic organisation too much."
—Sir Josiah Stamp.

परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर-दान क्षमता किसी देश के नागरिकों की कर देने की अधिकतम सीमा को बताती है। एल्लिन्जर (Ellinger) के अनुसार, "यह सीमा तब पहुँच जाती है जब सरकारी कोष में जनता में इतना अधिक रुपया आ जाय कि लोगों का उत्पत्ति करने का प्रोत्साहन कम हो जाय, पूँजी में आवश्यक वृद्धि न की जा सके तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को काम पर न लगाया जा सके।"^७ सर ड्रमंड फ्रेजर (Sir Drummond Fraser) के अनुसार, "जब करदाताओं को कर देने के लिये वैको से उधार लेने पर बाध्य होना पड़े तो कर-दान क्षमता की सीमा आ जाती है।" इन परिभाषाओं में कर-दान क्षमता के अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सम्भव नहीं हो सका है। स्टाम्प का आनन्द रहित और दालत जीवन', शिराज का 'न्यूनतम उपभोग' तथा असहनीय कष्ट' आदि ऐसे वाक्य हैं जिनकी वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दी जा सकती और न उन्हें ठोस शब्दों में व्यक्त ही किया जा सकता है। किन्तु फिर भी कर-दान क्षमता के विचार की उपयोगिता तथा व्यवहारिक महत्व कम नहीं है। वह उस अधिकतम सीमा की ओर संकेत करती है जहाँ तक, लोगों के अधिक कल्याण के कोई विशेष हानि पहुँचाये बिना, सरकार करारोपण कर सकती है।

कुछ लेखकों ने निरपेक्ष (Absolute) तथा सापेक्ष (Relative) कर-दान क्षमता में भेद किया है। निरपेक्ष कर-दान क्षमता का अर्थ है कि एक विशेष समुदाय करों के रूप में, कोई बुरा प्रभाव डाले बिना कितना भुगतान कर सकता है। सापेक्ष कर-दान क्षमता यह बताती है कि दो या दो से अधिक समुदायों को करों के रूप में किसी सामान्य व्यय के लिये किस अनुपात में योग-दान देना चाहिये। डा० डाल्टन (Dalton) निरपेक्ष कर-दान क्षमता का व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं समझते हैं क्योंकि उसका कोई निश्चित माप सम्भव नहीं है। उनके अनुसार सापेक्ष कर-दान क्षमता एक वास्तविकता है जिसे अन्य प्रकार से भी अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता है किन्तु निरपेक्ष कर-दान क्षमता एक कोरा भ्रम है जिसके कारण बड़ी भ्रष्टियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।^८ डाल्टन का विचार है कि राजस्व के सिद्धान्तों के विवेचन में कर-दान क्षमता को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत किण्डले शिराज के मतानुसार निरपेक्ष कर-दान क्षमता का भारी व्यवहारिक महत्व है। उन्होंने निरपेक्ष कर-दान क्षमता के विचार को वास्तविक माना है और कहा है कि प्रत्येक राज्य को निरपेक्ष कर-दान क्षमता का अनुमान लगाने का

7 "The limits would be reached when so much is taken out of the tax-payer's pockets that the incentive to produce is reduced and insufficient remains to be provide the necessary capital, to make up the wastage and to set to work new workers in an increasing opulation."
—Ellinger

8 "My general conclusion is that relative taxable capacity is a reality which can, however, be equally well expressed in other terms, while absolute taxable capacity is a myth, which is apt to endanger grave errors."
—Dalton : Principles of Public Finance, p. 171

प्रयत्न करना चाहिये। उनके अनुसार निरपेक्ष कर-दान क्षमता "किसी असहनीय कष्ट का अनुभव किये बिना देश के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक खर्च के लिये दिया गया अधिक से अधिक धन है।"

विभिन्न ग्रंथास्त्रियों द्वारा दी गई कर-दान क्षमता की परिभाषाओं में काफी मनभेद पाया जाता है। उनमें से किसी को भी पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इसीलिये डा० डास्टन का यह मत है कि 'विचारों की स्पष्टता को बनाये रखने के लिये कर-दान क्षमता के वाक्य की राजस्व के सम्बन्धित वाद-विवाद से बाहर निकाल देना चाहिये।' डा० एडास्कर के अनुसार अद्विधास्य अर्थनास्ती कर-दान क्षमता का अर्थ स्पष्ट रूप में नहीं कर सके हैं, इसीलिये 'कर-दान क्षमता' वाक्य का काफी दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने इसके स्थान पर 'राजस्व की अधिकतम सीमा' (Optimum of Public Finance) वाक्य का प्रयोग करने की सलाह दी है। एडास्कर के अनुसार राजस्व की अधिकतम सीमा तब पहुँचती है जबकि राज्य द्वारा जनता से वसूल किये गये धन की अन्तिम इकाई में ठीक उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है जितनी कि उसके व्यक्तित्व व्यय के द्वारा होती है। जब राजस्व की अधिकतम सीमा पहुँच जाय तो सरकार को जनता से और अधिक करों के रूप में नहीं लेना चाहिये क्योंकि ऐसा करने में सामाजिक लाभ कम हो जायगा। राजस्व की अधिकतम सीमा पर सामाजिक लाभ सबसे अधिक होता है।

यद्यपि करदान क्षमता की सैद्धांतिक रूप में परिभाषा की जा सकती है किन्तु व्यावहारिक जीवन में उसे नापना अत्यन्त कठिन है। ग्रंथास्त्रियों ने करदान क्षमता की नापने की विधि का पता लगाने का प्रयत्न किया है। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि किसी देश में उत्पन्न होने वाले कुल धन में से यदि उसके न्यूनतम उपभोग को निकाल दिया जाय तो उसकी करदान क्षमता का पता लग जाता है। न्यूनतम उपभोग के अन्तर्गत समाज की कार्यकुशलता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर नया उत्पत्ति के श्रोत को बनाए रखने के लिये किया जाने वाला पूँजीगत व्यय सम्मिलित होता है। सामान्य बात में करदान क्षमता का अनुमान लगाने समय पूँजी की वृद्धि की व्यवस्था अद्विधास्य की जानी चाहिये क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति के लिए पूँजी तथा आय में एक निश्चित दर में वृद्धि होना आवश्यक है। किन्तु युद्धकाल या अन्य प्रकार के आपत्काल में करदान क्षमता का अनुमान लगाने में पूँजी की वृद्धि का व्यय उसमें अलग रखा जा सकता है। इस प्रकार किसी भी समाज के लिये करदान क्षमता की दो सीमाएँ हो सकती हैं—एक युद्ध कालीन और दूसरी नान्ति-कालीन।

9 In the interest of clear thinking it would be well that the phrase taxable capacity should be banished from all serious discussions of public finance."

—Dillon : Principles of Public Finance, p. 171

करदान क्षमता को प्रभावित करने वाली बातें :

किसी देश की करदान क्षमता वहीं के आर्थिक वातावरण पर निर्भर होती है। भिन्न-भिन्न काल में तथा अलग-अलग राष्ट्रों के लिये यह वातावरण अलग-अलग होता है और इसलिये उनकी करदान क्षमता में भी काफी अन्तर पाया जाता है। करदान क्षमता का अध्ययन करने समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह करदान की एक प्रवर्गिक (Dynamic) सीमा है जो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है और जिस पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। करदान क्षमता मुख्यतया निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है—

(१) राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या का आकार (National Income and Size of Population) — करदान क्षमता राष्ट्रीय आय की मात्रा तथा उसकी वृद्धि की दर से प्रभावित होती है। अधिक राष्ट्रीय आय होने पर देश की करदान क्षमता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि भी करदान क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है। यदि किसी देश की जनसंख्या राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा तेजी के साथ बढ़ती है तो उस देश की करदान क्षमता कम हो जाती है। किन्तु यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या की अपेक्षा तेजी से साथ होती है तो करदान क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि औद्योगिक देशों में कृषि-प्रधान देशों की अपेक्षा करदान क्षमता अधिक होती है। किसी देश में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक वह समुदाय कर देने की क्षमता रखता है किन्तु इसके साथ यह आवश्यक है कि वह देश विकसित होना चाहिये तथा व्यक्तिगत आय का स्तर भी ऊँचा होना चाहिये। किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना मान से ही उसकी करदान क्षमता का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि उस राष्ट्रीय आय का व्यय किस प्रकार की वस्तुओं पर किया जा रहा है। यदि राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय होता है तो उस देश की करदान क्षमता अधिक होती है।

(२) धन का वितरण (Distribution of Wealth) — देश में धन के वितरण पर भी करदान क्षमता निर्भर होती है। सामान्यतया धन के वितरण की समानता किसी समुदाय की करदान क्षमता को कम करती है। यदि किसी देश में धन के वितरण में काफी असमानता है और अधिकांश धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में है केन्द्रित है तो ऐसा देश में सरकार इन धनी लोगों पर ऊँचे कर लगा कर काफी मात्रा में धन इकट्ठा कर सकती है जिसके कारण उस समाज की करदान क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि धन बहुत से हाथों में फैला हुआ है तो देश की करदान क्षमता कम होती है और सरकार करो से अधिक आमदनी प्राप्त नहीं कर सकती।

(३) कर प्रणाली (Tax System) :— करदान क्षमता अधिक होने के लिये यह आवश्यक है कि कर-प्रणाली वैज्ञानिक ढंग से संगठित हो। यदि कर-प्रणाली में

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करो का उचित मिश्रण किया गया है तो निश्चित ही करों में अधिक आय प्राप्त की जा सकेगी। इसके विपरीत यदि एक ही प्रकार के करो पर जोर दिया जाता है तो करारोपण में अधिक आय प्राप्त नहीं की जा सकेगी। कर-प्रणाली में विभिन्न प्रकार के करो का ऐसा मिश्रण होना चाहिये कि किसी न किसी प्रकार के कर के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा जा सके। वे कर जिनका भारी विरोध किया जाता है अथवा जिनका आर्थिक क्रियाशील पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कर-दान क्षमता को कम करते हैं। करो को इकट्ठा करने के ढंग का भी करदान क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किये गये कर समाज की कर-दान क्षमता में वृद्धि करते हैं।

(४) करो कर उद्देश्य (Purpose of Taxation) — कर जिस उद्देश्य के लिये लगाये जा रहे हैं, इस बात का लोगों की कर देने की इच्छा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कर किसी ऐसे उद्देश्य में लगाया जा रहा है जिसमें समाज का कल्याण होने की सम्भावना है अथवा लोगों के कष्ट को दूर करके उन्हें किसी विशेष प्रकार की सुविधायें दी जानी हैं तो ऐसी स्थिति में लोग अपनी इच्छा से ही अधिक मात्रा में कर देने को तैयार हो जायेंगे। एक अच्छे उद्देश्य में लगाया गया कर किसी समुदाय की कर-दान क्षमता को बढ़ा देता है। प्रायः देखा जाता है कि अकाल, बीमारी आदि को दूर करने के लिये या शिक्षा का प्रसार करने के लिये करो में वृद्धि करना आमामन होता है किन्तु युद्ध व्यय, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने या विदेशियों की सहायता के लिये लगाये जाने वाले करो का घोर विरोध होता है।

(५) आय की स्थिरता (Stability of Income) — स्थिर आय वाले समुदाय की कर-दान क्षमता अधिक होती है। किसी देश के निवासियों की आय में जितनी अधिक स्थिरता होती है उतनी ही अधिक उनकी करदान क्षमता भी होती है। केवल स्थिर आय पर ही दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थाएँ आधारित हो सकती हैं। देश के लोगों की आय का अनिश्चित होना उनकी करदान क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। औद्योगिक देशों में लोगों की आय प्रायः निश्चित होती है इसलिये उनकी करदान क्षमता भी अधिक रहती है। कृषि व्यवसाय में अनिश्चितता होने के कारण लोगों की आय स्थिर नहीं रहती है और उस की कर-दान क्षमता कम हो जाती है। भारत में लोगों की करदान क्षमता के कम होने का एक मुख्य कारण उनका कृषि पर निर्भर रहना है।

(६) मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक स्थिति (Psychological and Political Conditions) :— करदान क्षमता मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक दशाओं से भी प्रभावित है। यद्यपि इस प्रकार के प्रभावों को आधिक्य से नगाना सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी उनका महत्व काफी अधिक है। सरकार के प्रति लोगों की मनोवृत्ति उनकी कर-दान क्षमता को प्रभावित करती है। यही कारण है कि एक लोकप्रिय

सरकार जनता को आमानी से अधिक कर देने के लिये तैयार कर लेती है। किन्तु एक विदेशी सरकार के लिये ऐसा करना संभव नहीं होता क्योंकि उसके प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं होगी। युद्धकाल में अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय आपत्तिकाल में लोगों की करदान क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि वे देशप्रेम के कारण लड़ाई के व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। अपना बहुत सा धन जिते वे शान्तिकाल में पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि अथवा अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में लगाते, उसे वे करो के रूप में युद्ध के लिये दे देते हैं। राष्ट्रीयता की भावना ही लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने देश को युद्ध में विजयी करन अथवा शान्तिकाल में उसके विकास के लिये करो का अधिक बोझ उठाये।

(७) मुद्रा स्फीति (Inflation) — मुद्रास्फीति का कर-दान क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण जनता की क्रयशक्ति कम हो जाती है और उसे न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये भी काफी खर्च करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी करदान क्षमता घट जाती है।

किसी देश की कर-दान क्षमता को जानने के लिये हमें उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये। इन अतिरिक्त (i) औद्योगिक संगठन (ii) लोगों का जीवन स्तर (iii) देश का आर्थिक विकास (iv) सार्वजनिक व्यय की प्रकृति तथा (v) सार्वजनिक ऋण की प्रकृति आदि का भी करदान क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में करदान क्षमता वह अतिरेक है जो कोई समाज एक निश्चित काल में अपनी उत्पादन क्रियाओं द्वारा पैदा करता है। कोई भी कारण जो देश की उत्पत्ति अथवा उसके न्यूनतम उपभोग को प्रभावित करते हों, उस देश की करदान क्षमता पर भी अपना प्रभाव डालेंगे।

परीक्षा प्रश्न

- 1 Distinguish between direct and indirect taxes. Give the merits and demerits of direct taxes. (Agra 1966)
‘प्रत्यक्ष’ तथा ‘परोक्ष’ करों के अन्तर को समझाइये। प्रत्यक्ष करों के गुण तथा अवगुणों का वर्णन कीजिये।
- 2 Discuss the principle of ‘ability to pay’ and show what steps should be taken so that taxation may be based on this principle (Agra 1956 Old Scheme)
‘कर देने की योग्यता’ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। करारोपण को इस सिद्धांत पर आधारित करने के लिये क्या किया जाना चाहिये ?
- 3 Explain the merits and demerits of direct and indirect taxes. (Agra 1955 Pt. I)
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के गुण और अवगुणों को समझाइये।

4 Discuss Adam Smith's Canon's of Taxation. How would you measure the ability of an individual to pay taxes ? (Agra 1950)

एडम स्मिथ के करारोपण सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये । किसी व्यक्ति की कर देने की योग्यता को आप किस प्रकार नापेंगे ?

5 Which out of the Progressive and Proportional Systems of Taxation would you prefer and why ? (Agra 1952)

प्रगतिशील तथा अनुपातिक कर प्रणालियों में से आप किसे पसंद करेंगे और क्यों ?

6 What is a tax, and what are the principles adopted by the State in imposing tax or taxes on the citizens (Agra 1959)

कर किसे कहते हैं ? सरकार नागरिकों पर कर लगाने समय कौनसे सिद्धान्तों का पालन करती है ?

7 What are, in your opinion, the characteristics of a good tax system ? (Madras, B A. 951)

आपके विचार में एक अच्छी कर-प्रणाली की क्या विशेषताएँ हैं ?

8 Discuss the various factors determining taxable capacity. Show that the conception of taxable capacity is a purely relative one. (Madras, B A 1952)

उन विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिये जो कर-दान क्षमता को निर्दिष्ट करती हैं । यह सिद्ध कीजिये कि कर-दान क्षमता का विचार पूर्णतया सापेक्षिक है ।

कर का भार Incidence of Taxation

कर के भार की समस्या इस बात को जानने से सम्बन्धित है कि करो का मौद्रिक भार कौन सहन करता है अथवा वह किस प्रकार विभिन्न लोगों के बीच बाँटा जाता है। कर का भार सदैव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो उसे सर्व-प्रथम देता है। अधिकांश दशाओं में यह भार दूसरे लोगों के द्वारा सहन किया जाता है। कर लगाने वाली सत्ता के लिये यह जानना आवश्यक है कि जो कर वह लोगों पर लगाती है उसका भार अन्त में कहाँ पड़ता है। जब किसी व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है तो वह उसे दूसरे व्यक्तियों पर टालने की कोशिश करता है। कभी यह ऐसा करने में सफल हो जाता है और कभी नहीं। प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिम पर वह लगाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के कर को टालना सम्भव नहीं होता है किन्तु परोक्ष करो का भार टाला जा सकता है और वह उन व्यक्तियों पर नहीं होता है जो उन्हें भुगतते हैं। प्रत्येक कर के विषय में यह जानना आवश्यक है कि उसका अन्तिम भार कौन सहन करता है? यही कर भार की समस्या है। डाल्टन के अनुसार, "किसी कर के भार की समस्या सामान्यतया इस बात को जानने की है कि उस कर को कौन देता है।"^१ कर का भार उन लोगों पर होता है जो उसके प्रत्यक्ष मौद्रिक भार (Direct money burden) को सहन करता है। ऐडम्स के अनुसार, 'करो के भार का अभिप्राय उनके भुगतान के पड़ने के अन्तिम स्थान से है।'^२

कर का दबाव (Impact) और भार (Incidence)—कर भार की समस्या को ठीक प्रकार से समझने के लिये हमें कर के भार (Incidence of Tax) तथा कर के दबाव (Impact of Tax) के भेद को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये। कर का दबाव उस व्यक्ति पर होता है जो उसका सर्वप्रथम भुगतान करता है अर्थात् जिससे कर लिया जाता है किन्तु कर का भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे अन्त में सहन करता है। उदाहरणार्थ उत्पादन कर (Excise Duty) का दबाव उत्पादकों पर होता है क्योंकि वे उसका सर्वप्रथम भुगतान करते हैं किन्तु उसका भार उपभोक्त्यों

1 "The problem of the incidence of a tax is commonly conceived as the problem of who pays it."
—Dalton

2 "By the incidence of taxes is meant the final resting place of their payment."
—Adams

पर पड़ता है क्योंकि ऐसे करो को उन पर टाल दिया जाता है। प्रत्यक्ष करो के सम्बन्ध में कर का दबाव तथा भार एक ही व्यक्ति पर होता है। जो व्यक्ति आयकर देता है वह उसके भार को भी सहन करता है क्योंकि यह कर उसे अपनी जेब से देना पड़ता है और वह इसके भार को अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाल सकता है। किन्तु परोक्ष करो के सम्बन्ध में कर का दबाव उस व्यक्ति पर होता है जो उस पहल देता है और उसका भार उस व्यक्ति पर होता है जिस पर उसे टाल दिया जाता है अर्थात् जो उसे अन्त में सहन करता है।

कर का मौद्रिक भार तथा वास्तविक भार

प्रत्यक्ष कर का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भार होता है जो मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है। कर के रूप में एक व्यक्ति जो कुछ रकम सरकारी खजाने में जमा करता है वह उस कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार (direct money burden) है। जब कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के स्टॉक पर कर देता है तो वह वस्तु के मूल्य को प्रायः कर को भागा में अधिक बढ़ाता है क्योंकि उसे अपने स्टॉक की बेचने में कुछ समय लगना है और इस समय के लिये उस टैक्स के रूप में दी गई रकम पर व्याज खीना पड़ता है। इस व्याज को भी वह कर के साथ वस्तु के मूल्य में शामिल कर देता है। वस्तु का मूल्य कर के अतिरिक्त जितना अधिक बढ़ाया जाता है वह कर का अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार (indirect money burden) है। कर का प्रत्यक्ष वास्तविक भार (direct real burden) आर्थिक कल्याण के उस त्याग को बताता है जो किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने के कारण करना होता है। कर देने में प्रायः निरर्थक व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में आर्थिक कल्याण का त्याग करना पड़ता है। जब किसी वस्तु पर कर लगता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को मजबूर होकर उस वस्तु का उपभोग कम करना पड़ता है। उपभोक्ताओं द्वारा किया जाने वाला इस प्रकार का त्याग कर का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (indirect real burden) होता है।

कर का भार उसके प्रभाव से अलग होता है — कर के भार तथा कर के प्रभाव (effects of tax) में भेद को भी स्पष्ट रूप में समझना आवश्यक है। कर के भार से अभिप्राय कर के मौद्रिक भार से होता है किन्तु 'कर के प्रभाव' के अन्तर्गत हम कर लगने के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जब कोई कर लगाया जाता है तो उसका प्रभाव धन की उत्पत्ति तथा वितरण पर हो सकता है। वह लोगों की काम करने की इच्छा तथा शक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, वह उनकी बचत करने की इच्छा तथा शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। करो का प्रभाव समाज में धन के वितरण पर भी होता है। इनके अतिरिक्त करो के अन्य आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इन सब प्रकार के प्रभावों का अध्ययन 'कर के प्रभाव' (effects of tax) के अन्तर्गत आ जाता है किन्तु 'कर के भार' (incidence of tax) के अन्तर्गत केवल कर के मौद्रिक भार का अध्ययन किया जाता है।

कर भार की समस्या के अध्ययन का महत्व :

कर भार की समस्या करारोपण की एक प्रमुख समस्या है। विभिन्न करो के भार का अध्ययन किये बिना यह नहीं बताया जा सकता कि कोई कर लोगों के आर्थिक बर्तण को किम प्रकार प्रभावित करेगा तथा उमका भार समाज के किन वर्गों पर अधिक और किन वर्गों पर कम पड़ेगा। प्रत्येक कर को लगाने से पूर्व सरकार यह निश्चय करती है कि उमका भार किन लोगों पर पड़ना चाहिये। यदि सरकार यह चाहती है कि कर का भार उन लोगों पर ही पड़े जो उसे देते हैं तो वह प्रत्यक्ष करो का प्रयोग करती है और यदि वह चाहती है कि कर के भार को अन्य व्यक्तियों पर टाल दिया जाय तो अप्रत्यक्ष करो का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। कर भार का अध्ययन करके ही सरकार यह निश्चय करती है कि कब और किन लोगों पर किस प्रकार के कर लगाये जायें। कर प्रायः अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से लगाये जाते हैं। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिये यह आवश्यक है कि कर समीरो पर लगाये जायें और उनमें होने वाली आमदनी को गरीबों की भलाई के लिये व्यय किया जाय। समीरो पर कर लगाने समय इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिये कि उनके ऊपर लगाये गये करो का भार उन पर ही पड़े और वे उसे दूसरों के कंधों पर न टाल सकें। प्रत्येक कर का स्थान एक धनी व्यक्ति का घर होना चाहिये। करारोपण के समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कर का भार गरीबों पर कम से कम पड़े अन्यथा उनके स्वास्थ्य तथा क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। करारोपण के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कर भार की समस्या का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजस्व मन्त्री के लिये यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक कर का भार कितना है तथा वह किन वर्गों पर पड़ता है जिससे कि वह ऐसी कर प्रणाली का विकास कर सके जो देश के सामाजिक हित में हो। आधुनिक समाज में कर लगाने का उद्देश्य केवल एक निश्चित आय प्राप्त करना नहीं है बल्कि उमका उद्देश्य यह भी है कि कर उन्हीं लोगों पर लगाय जायें जो उन्हें आसानी से सहन कर सकते हैं। आजकल करो को सामाजिक न्याय स्थापित करने का साधन माना जाता है। इसके लिये आवश्यक है कि समाज में करो के भार का उचित वितरण हो। यह तभी सम्भव है जब सरकार प्रत्येक कर लगाने से पूर्व उसके भार के वितरण के बारे में पूरी खोज करे। यह जानने के लिये कि कर करदाता की योग्यता के अनुकूल है अथवा नहीं हमें यह पता लगाना आवश्यक है कि अन्न में कर किमको देना पड़ना है।

कर के भार को टालना

कर के भार को किसी अथ व्यक्ति पर डबेल देने को कर का टालना या कर शिफ्टिंग (shifting of tax) कहते हैं। जब किसी व्यक्ति पर कोई कर लगाया जाता है तो वह अपने ऊपर लगाये गये कर के भार को दूसरे लोगों पर टालने का प्रयत्न करता है। किन्तु वह मदैव उसमें सफल नहीं होता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनके भार को बिल्कुल नहीं टाला जा सकता है और कर देने वाला को ही उनका

भार सहन करना पड़ता है। ऐसा प्रत्यक्ष करो के सम्बन्ध में होता है। आय कर, मृत्यु कर तथा सम्पत्ति कर आदि के भार को टाला नहीं जा सकता है। इसके विपरीत कुछ कर ऐसे होते हैं जिनके भार को कर देने वाला दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है। इन करो के सम्बन्ध में कर देने वाला केवल कर के दबाव को सहन करता है उसके भार को नहीं। कर का भार वह किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है और दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति पर और तीसरा चौथे पर। इस प्रकार कर का भार टाला जाता रहता है और वह अन्त में ऐसे व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे नहीं टाल पाता। वस्तुओं पर लगाये गये कर इसी प्रकार के होते हैं और इन का भार अन्त में उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अन्य प्रकार के परोक्ष करो के सम्बन्ध में भी कर देने वाला कर के भार को अपने कंधों से उठा कर दूसरे के कंधों पर डालने में सफल हो जाता है।

कर विवर्तन की दिशा।

कर के भार को आगे अथवा पीछे दोनों ओर ढकेला जा सकता है। प्रत्येक व्यापारी अपनी वस्तु पर लगाये गये कर के भार को आगे अथवा पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है। वह किस दिशा में कर भार को टालने में सफल होता है, यह वस्तु की माग तथा पूर्ति की दशाओं पर निर्भर होता है। यदि वस्तु की माग बेलाच है और उत्पादक समझता है कि वह वस्तु को बड़े हुए मूल्य पर बेच सकता है तो ऐसी दशा में कर के भार को आगे की ओर ढकेला जाता है और मूल्य के साथ जोड़कर उसे उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। इसके विपरीत लोचदार मांग (Elastic demand) वाली वस्तुओं पर लगाये गये कर के भार को आगे ढालना संभव नहीं होता। व्यापारी जानता है कि वह वस्तु को बड़े हुए मूल्य पर नहीं बेच सकेगा, इसलिए वह कर के भार को पीछे की ओर टालने का प्रयत्न करता है। उत्पादकों से वस्तु को कम मूल्य पर लेकर वह कर भार को उन पर टालने में सफल हो जाता है। जब किसी वस्तु पर लगाये गये कर के भार को उपभोक्ताओं पर टाला जाता है तो हम मांग की ओर टालना कहते हैं और यदि कर के भार को उत्पादकों पर टाला जाता है तो उसे पीछे की ओर टालना कहते हैं।

कर के भार को प्रायः दो प्रकार से टाला जा सकता है—(1) वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके अथवा (2) वस्तु की मात्रा या गुण को घटा कर। विक्रेता प्रायः कर के भार को उपभोक्ताओं पर टालने के लिये वस्तु के मूल्य को बढ़ा देता है किन्तु कर विवर्तन के लिये वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना सदा आवश्यक नहीं होता है। यह भी संभव हो सकता है कि वस्तु के पैकेट अथवा बोतल में वस्तु की मात्रा कुछ कम कर दी जाय अथवा वस्तु के गुण में कोई कमी की जाय या गुण और मात्रा दोनों में कमी कर दी जाय। कभी-कभी ऐसा होता है कि कर के भार को सम्पूर्ण रूप में उपभोक्ता अथवा उत्पादक पर ढकेल दिया जाता है किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह भी हो सकता है कि कर का भार कुछ उपभोक्ता पर तथा कुछ उत्पादक पर डाला जाय।

ऐसा भी हो सकता है कि उपभोक्ता तथा उत्पादक के साथ कर के भार का कुछ अंश विक्रेता भी सहन करे।

कर का सम्मिश्रण सिद्धांत :

इस सिद्धान्त के अनुसार कर विवर्तन (Shifting) के द्वारा करो का भार अपने आप समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर बराबर फैल जाता है। कर का भार इस प्रकार सारे समुदाय में फैल जाता है कि प्रत्येक करदाता पर कर का एक छोटा सा अनुपात ही पड़ता है जिसे वह सहन कर सकता है और उसे करना चाहिये। इस सिद्धांत के मानने वालों का विचार है कि समाज में कर के भार का वितरण करने के लिये हमें किसी प्रकार की खोज अथवा विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक कर का भार स्वयं पूरे समाज पर न्याय-पूर्ण ढंग से फैल जाने की प्रवृत्ति रखता है। विनिमय की क्रियाओं के द्वारा कर भार विभिन्न व्यक्तियों में फैलता चला जाता है और अन्त में वह विभिन्न वर्गों के बीच कुछ इस प्रकार बंट जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर उतना ही भार पड़ता है जितना कि उनमें उठाने की सामर्थ्य है। अतः कर के भार के विषय में चिन्तित होना बेकार है। लार्ड मैसफील्ड के अनुसार, "किसी स्थान पर लगाया हुआ कर किसी भील में गिरते हुए पत्थर के समान है जो उसमें घुस बनाता है। एक वृत्त दूसरे वृत्त की उत्पत्ति करता है तथा उसको आगे बढ़ाता है और केन्द्र से लगाकर समस्त परिधि में हलचल मच जाती है।" भील में उठने और फैलने वाले इन वृत्तों के समान कर सारे समुदाय में फैल जाता है।

यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्रियों का विश्वास इस प्रकार के सिद्धांत में था किन्तु वर्तमान समय में इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। यह कहना उचित नहीं है कि कर विवर्तन के द्वारा कर का भार अपने आप कर-दाताओं की क्षमता के अनुसार बंट जाता है। यदि ऐसा होता तो वित्त मन्त्रियों को यह जानने की आवश्यकता न होती कि किसी कर का भार समाज के किन लोगों पर पड़ता है और उसका अन्तिम विश्राम स्थान कहाँ है। आज कोई भी व्यक्ति इस बात में विश्वास नहीं कर सकता कि करों का भार स्वयं न्यायोचित ढंग से पूरे समाज पर फैल जाता है। कर के भार के वितरण की समस्या इतनी आसान नहीं है। इसके प्रतिरिक्त यह सिद्धांत इस बात को मानकर चलता है कि समाज में पूर्ण प्रतियोगिता रहती है, वास्तव में इस प्रकार की दशाएँ नहीं पाई जाती और प्रतियोगिता की अपूर्णता कर विवर्तन के रास्ते में बाधाय उत्पन्न कर सकती है। यह सिद्धांत वास्तविक अनुभव तथा विश्वास के विपरीत है और इसका केवल सीमित प्रयोग ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से इस सिद्धांत को नहीं माना जाता।

कर भार का आधुनिक सिद्धान्त :

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज में कर के भार को करदाताओं की क्षमता के अनुसार न्यायोपूर्ण ढंग से बाँटा जाना चाहिये और इसके लिये कर भार की

समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिये। प्रत्येक कर के बारे में यह खोज की जानी चाहिये कि उसका भार अन्त में किम व्यक्ति पर पड़ता है, क्या विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला कर का भार उन लोगों की कर-दान क्षमता के अनुकूल है, वे लोग तो कर विवर्तन नहीं कर रहे हैं जिन्हें कर के भार को स्वयं सहन करना चाहिये। वर्तमान सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु के भार को निश्चित करते समय हमें वस्तु की माँग तथा पूर्ति की विरोधताओं को ध्यान में रखना चाहिये।

कुछ मुख्य करों के सम्बन्ध में कर भार की समस्या

वस्तुओं पर लगाये गये कर का भार .

प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लगे हुये कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर डालने का प्रयत्न करता है। उत्पादक वस्तुओं पर लगे हुये कर को विक्रेताओं पर तथा विक्रेता उस कर को उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयत्न करते हैं। कर का भार डालने में उन्हें वहाँ तक सफलता मिलती है, कर विवर्तन किस दिशा में किया जाता है तथा वह किस प्रशस्तता होता है, यह सब निम्नलिखित बातों पर निर्भर है:—

(१) कर की प्रकृति (Nature of Tax)—कर विवर्तन इस बात पर निर्भर होता है कि कर किसी एक वस्तु पर लगाया जाता है अथवा किसी वर्ग की सभी वस्तुओं पर लगा दिया गया है। किसी एक वस्तु पर लगाये गये कर को; आसानी से टाला नहीं जा सकता किन्तु एक वर्ग की सभी वस्तुओं पर लगाये गये कर को उपभोक्ताओं पर टालना सम्भव होता है। यदि कर केवल एक वस्तु पर लगाया गया है और वह वस्तु ऐसी है जिसके स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसी दशा में कर के भार को उपभोक्ताओं पर नहीं टाला जा सकेगा क्योंकि कर लगने में वस्तु का मूल्य बढ़ने पर लोग उसके स्थान पर प्रतिस्थापित वस्तुओं (Substitutes) का प्रयोग आरम्भ कर देंगे। ऐसी दशा में उत्पादक माँग गिर जाने के डर से वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ायेंगे और कर के भार को स्वयं सहन करेगा। उदाहरणार्थ चाय पर लगने वाले कर के कारण यदि चाय का मूल्य बढ़ता है तो लोग चाय के स्थान पर कॉफी (Coffee) का प्रयोग करने लगेंगे क्योंकि उस पर कर नहीं लगाया गया है। ऐसी स्थिति में कर विवर्तन सम्भव नहीं होता और कर के भार को उत्पादक अथवा विक्रेता को ही सहन करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि कर ऐसी वस्तु पर लगाया गया है जिसका प्रतिस्थापन नहीं है या किसी वर्ग की सभी वस्तुओं पर कर लगा दिया गया है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता अपनी माँग को कम नहीं कर सकेंगे। उत्पादक या विक्रेता वस्तु के मूल्य को बढ़ा देंगे और इस प्रकार कर के भार को उपभोक्ताओं पर टालना सम्भव हो जायगा।

(२) कर का आकार (Size of the Tax).—यदि कर की मात्रा बहुत अधिक है तो उत्पादक या विक्रेता उस कर के सम्पूर्ण भार को स्वयं न उठाकर उसे उपभोक्ताओं पर टालने का प्रयत्न करेगा किन्तु यदि कर की मात्रा वस्तु के मूल्य की

अपेक्षा बहुत कम है तो वह कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालना पसन्द नहीं करेगा और उसे स्वयं सहन कर लेगा ।

(३) कर का रूप (Form of Tax) — कर किस रूप में लगाया गया है इस बात का भी विवर्तन पर प्रभाव पड़ता है । कर या तो वस्तु के मूल्य के अनुसार (ad valorem) लगाया जा सकता है और या उसकी मात्रा के अनुसार (Specific) । यदि वस्तु की मात्रा के अनुसार कर लगाया जाता है तो उस वस्तु के सभी उत्पादकों को एक ही दर से कर देना होगा चाहे वे वस्तु की सस्ती बिस्म बना रहे हों अथवा महंगी । ऐसी दशा में सस्ती बिस्म की वस्तु के उत्पादक कर के भार को सहन नहीं कर सकेंगे क्योंकि कर की मात्रा उनके मुनाफे के अनुपात में बहुत अधिक है । उत्पादन जारी रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे कर को वस्तु के मूल्य में जोड़ कर उपभोक्ताओं पर टाल दें । यदि कर वस्तु के मूल्य के अनुपात में लगाया जाना है तो सस्ती बिस्म की वस्तु पैदा करने वाले उत्पादकों को अनुपात से अधिक भार का भार सहन नहीं करना पड़ेगा । ऐसी दशा में उत्पादक कर के भार को स्वयं सहन करना पसन्द करेंगे अथवा उनके बहुत बम अंश का विवर्तन हो सकेगा क्योंकि यदि कर के कारण वस्तु के मूल्य को बढ़ाया जाता है तो कर की दर में वृद्धि हो जायगी और भार के गिरने की सम्भावना बढ जायगी । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मूल्यानुसार (ad valorem) लगे हुये करों का विवर्तन बहुत कम अंश तक किया जा सकता है किन्तु मात्रा अनुसार (Specific) लगे हुये करों को आसानी से तथा अधिक अंश तक टाला जा सकता है ।

(४) करारोपण का उद्देश्य (Object of Taxation) — कर किम उद्देश्य में लगाया गया है, इसका प्रभाव कर विवर्तन पर पड़ता है । कुछ कर इसी उद्देश्य से लगाये जाते हैं कि उनके भार को आगे की ओर टाल दिया जाय । ऐसे करों के सम्बन्ध में कर विवर्तन आमानी से हो जाता है और अधिक अंश तक किया जा सकता है । वस्तुओं पर लगाये गये करों का उद्देश्य यही होता है कि उनके भार को अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सके, इसीलिये कर ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनका विनिमय किया जाता हो । वस्तुओं का विनिमय किया जाना कर विवर्तन में बड़ी सहायता देता है । इसके विपरीत कुछ करों को लगाने का उद्देश्य यह होता है कि कर देने वाला उनके भार को स्वयं सहन करे जैसे आय कर । ऐसे कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर टालना सम्भव नहीं होता ।

(५) मांग और पूर्ति की लोच (Elasticity of Demand & Supply):— वस्तुओं पर लगाये गये करों के विवर्तन पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति की लोच का गहरा प्रभाव पड़ता है । किसी वस्तु की मांग जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही अधिक प्रवृत्ति कर के भार की उत्पादकों पर पड़ने की होगी और मांग जितनी बेलोच होगी उतना ही अधिक भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है तो कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है यदि बेलोच होती है

तो उत्पादकों पर। जिन वस्तुओं की मांग अधिक लोचपूर्ण होती है उनके मूल्य में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता क्योंकि मूल्य बढ़ जाने की दशा में उनकी मांग काफी कम हो जाती है। उत्पादक वस्तु की मांग को कम करना पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये कर लगाने पर भी इस प्रकार की वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ता है और कर का भार उत्पादक अथवा विक्रेता स्वयं सहन करते हैं और उसे उपभोक्ताओं पर डालना सम्भव नहीं होता। किन्तु क्रेताचक्षुष मांग वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके कर विवर्तन किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं पर लगे हुये कर के भार को उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है। जिन वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है, उन पर लगे हुये कर के भार को सहन करने के लिये उत्पादकों को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि कर के कारण यदि इन वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ती है तो उत्पादक उनकी पूर्ति को कम कर दते। इस प्रकार की वस्तुओं पर लगाये गये कर का भार अधिकांश रूप में क्रेताओं को सहन करना पड़ता है। किन्तु क्रेताचक्षुष पूर्ति वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्पादकों को कर का भार उठाने के लिये मजबूर किया जा सकता है क्योंकि उनके लिये पूर्ति को घटाना सम्भव नहीं होता। डाल्टन के अनुसार, "विक्रेता पूर्ति को कम करके कर भार को खरीदारों पर डालने का प्रयत्न करते हैं, खरीदने वाले अपनी मांग को कम करके उसे विक्रेताओं पर डालना चाहते हैं। अपने उद्देश्यों को कम से कम लागत पर पूरा करने की दोनों वर्गों की सापेक्षिक क्षमता इसका परिणाम निश्चित करती है।"³

(६) उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव (Effect of the Laws of Returns) —

कर विवर्तन पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव भी पड़ता है। वस्तुओं पर कर लगाने से पूर्व यह देखा जाता है कि उनका उत्पादन उत्पत्ति-ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) के अनुसार हो रहा है या उत्पत्ति-वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) के अनुसार। उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तु की लागत उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। हम देख चुके हैं कि कर का प्रभाव वस्तु के मूल्य को बढ़ाने का होता है जिसके कारण उसकी मांग कम हो जाती है। मांग कम होने पर उत्पादन कम किया जायगा और वस्तु की लागत भी कम हो जायगी। ऐसी दशा में कर लगाने से वस्तु का मूल्य कर की मात्रा से कुछ कम बढ़ेगा और कर का सम्पूर्ण भार क्रेताओं पर नहीं डाला जायेगा। इससे निपरीत यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार हो रहा है तो कर के कारण कम उत्पत्ति होने पर वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जायगी और वस्तु का मूल्य कर की मात्रा से अधिक बढ़ेगा जिसके कारण उपभोक्ताओं

3 "The sellers in short, try to put the incidence on buyers by reducing supply, the purchasers try to put on the sellers by reducing demand. The relative ability of two groups to carry out their objects with the minimum cost to themselves, determines the results."

—Dalton Public Finance, p. 54

को कर का अधिक भार सहन करना पड़ेगा। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पात्ति समता नियम (Law of Constant Returns) के अनुसार हो रहा है तो उपभोक्ताओं को कर की मात्रा के बराबर भार सहन करना पड़ेगा क्योंकि वस्तु का मूल्य उतना ही बढ़ेगा जितना कि उस पर कर लगाया गया है। इसलिये यह कहा जाता है कि उत्पात्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए तथा उत्पात्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये।

एकाधिकार पर कर का भार

एकाधिकार पर लगाये गये कर का भार कर की प्रकृति पर निर्भर होता है।

एकाधिकार पर कर प्रायः दो प्रकार से लगाया जा सकता है—

(अ) एकाधिकारी लाभ पर कर (Tax on Monopoly Profit)।

(ब) उत्पात्ति की मात्रा पर कर (Tax on Quantity of Output)।

एकाधिकारी लाभ पर कर या तो एक मुश्त रकम के रूप में लिया जा सकता है या उसके लाभ के अनुपात में। दोनों ही दशाओं में एकाधिकारी के लिये इस कर को टालना सम्भव नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से उसका एकाधिकारी लाभ कम होने की सम्भावना रहती है। प्रत्येक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से वस्तु को ऐसे मूल्य पर बेचता है और उसकी उतनी ही मात्रा बेचता है जिनसे कि उसे अधिकतम लाभ हो सके। वस्तु के मूल्य में कोई भी परिवर्तन उसके हित में नहीं होता क्योंकि उसके कारण उसका लाभ कम हो सकता है। जब एकाधिकारी के लाभ पर कर लगाया जाता है और उसका उत्पादन की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं होता तो कर का भार एकाधिकारी को स्वयं सहन करना पड़ता है क्योंकि वह अपनी वस्तु के मूल्य को नहीं बढ़ा सकता। पहले में ही वह वस्तु का ऐसा मूल्य निश्चित कर चुका है जिस पर उसे बेचकर वह अधिकतम एकाधिकारी आय प्राप्त कर रहा है। कर लगने के पश्चात् यदि वह मूल्य को बढ़ाता है तो वस्तु की मांग कम हो जाने के कारण उसकी कुल बिक्री गिर जायेगी और वह अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिये वह वस्तु के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं करेगा और उसे पूर्व निश्चित मूल्य पर ही बेचता रहेगा। यदि उसके मुनाफे पर प्रगतिशील दर (Progressive Rate) से भी कर लगाया जाता है तब भी वह उसे स्वयं सहन कर लेगा क्योंकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना उसके हित में नहीं है। अतः एकाधिकारी के लाभ पर लगाये गये कर का भार उसे स्वयं सहन करना पड़ता है क्योंकि उसे उपभोक्ताओं पर नहीं टाला जा सकता।

जब कर उत्पात्ति की मात्रा के आधार पर लगाया जाता है तो वह उत्पात्ति लागत में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और कर के भार को उपभोक्ताओं पर टाला जा सकता है। कर के कारण वस्तु का मूल्य कितना बढ़ता है यह दो बातों पर निर्भर है—(अ) वस्तु की माग तथा पूर्ति की लोच (ब) उत्पात्ति के नियम। वस्तु की मांग बेलोचदार होने की दशा में वस्तु के मूल्य को

कर की मात्रा के बराबर बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जमकी माँग के कम होने की कोई सम्भावना नहीं होती। ऐसी दशा में कर का सम्पूर्ण भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यदि माँग लोचदार है तो वस्तु के मूल्य को बढ़ाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि मूल्य बढ़ने पर उसकी माँग काफी गिर जायेगी। कर का भार कुल या आंशिक रूप में एकाधिकारियों को ही सहन करना पड़ेगा। वस्तु की पूर्ति लोचदार होने पर उत्पादक की स्थिति मजबूत रहती है और वह मूल्य बढ़ाकर कर-भार को उपभोक्ताओं पर डाल देता है किन्तु वेलोच पूर्ति की दशा में वह ऐसा नहीं कर सकता और उसे कर का भार स्वयं सहन करना पड़ेगा। यदि वस्तु की माँग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक लोचदार होती है तो कर का भार उत्पादक पर अधिक पड़ता है और यदि पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो कर का अधिक भार उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है।

एकाधिकारियों के उत्पादन पर लगाये गये कर का भार किस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच बँटता है, इस पर उत्पत्ति के नियमों (Laws of Returns) का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियमों के अनुसार होता है उनके मूल्य में कर के कारण अधिक वृद्धि होती है और एकाधिकारियों काफी सीमा तक कर का भार को उपभोक्ताओं पर टालने में सफल हो जाता है। किन्तु उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम बढ़ता है और एकाधिकारियों कर के भार को उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पाता। यदि वस्तु की सीमान्त उत्पादन लागत स्थिर रहती है तो वस्तु का मूल्य कर की मात्रा के भावे के बराबर बढ़ता है और कर का भार उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच आधा-आधा बँट जाता है।

आयात-निर्यात करों का भार :

आयात करों (Import Duties) का भार प्रायः अपने देश के उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। आयातकर्ता कर की रकम को वस्तु के मूल्य में जोड़ कर विक्रेताओं से वसूल कर लेता है और विक्रेता उसे मूल्य के साथ उपभोक्ताओं पर टाल देते हैं। इस प्रकार आयात कर का भार अन्तिम रूप से उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है और उसे आमानी से विदेशी उत्पादकों पर नहीं डाला जा सकता। किन्तु मर्दव ऐसा नहीं होता। कर के भार को उपभोक्ताओं पर टालना तब ही सम्भव होता है जब वस्तु की माँग आयात करने वाले देश में वेलोचदार हो और उसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध न हो। इसके विपरीत यदि वस्तु की माँग आयात करने वाले देश के लिये लोचदार है तथा निर्यात करने वाले देश के लिये अपनी वस्तु का कोई और बाजार नहीं है तो ऐसी दशा में विदेशी उत्पादकों को कर का भार सहन करना पड़ेगा और उसे उपभोक्ताओं पर नहीं टाला जा सकेगा। इस प्रकार की स्थिति प्रायः बहुत कम होती है और आयात कर का भार सामान्यतया उपभोक्ताओं को ही सहन करना पड़ता है।

निर्यात कर (Export Duty) का भार-अधिवास रूप से माल भेजने वाले

को सहन करना पड़ता है क्योंकि वह उसे मूल्य के साथ जोड़कर विदेशी उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकता। निर्यातकर्ता के लिये उसकी वस्तु का मूल्य विदेशी बाजार में प्रायः निश्चित होता है और वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि कर के कारण वह अपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है तो उपभोक्ता उसके स्थान पर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग आरम्भ कर सकते हैं अथवा उसी वस्तु को किसी अन्य समस्त देश से मंगा सकते हैं। ऐसी दशा में निर्यातकर्ता अपनी वस्तु के मूल्य को नहीं बढ़ावेगा और अपने लाभ में से ही कर की रकम को भरा करेगा। किन्तु यदि उत्पादक की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मजबूत है तो वह मूल्य को प्रभावित करके कर-भार को विदेशी उपभोक्ताओं पर डालने में सफल हो सकता है। ऐसा तब होता है जब या तो हमारे पास उस वस्तु के उत्पादन का एकाधिकार हो या विदेशियों की मांग हमारी वस्तु के लिये इतनी बेलोचदार हो कि मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कोई कमी न हो। किन्तु ऐसी दशा बहुत कम पाई जाती है और निर्यात करों का भार मुख्यतया निर्यातकर्ता ही सहन करते हैं। इस प्रकार निर्यात व आयात करों का भार भी वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच के अनुसार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में बंट जाता है। डाहटन के अनुसार—“आयातों तथा निर्यातों पर कर विनिमय के रास्ते में एक प्रकार की बाधा है। इस प्रकार की किमी भी बाधा का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार विनिमय करने वाले दोनों वर्गों के बीच उनकी सापेक्षिक मांग की लोच के उलटे अनुपात में बंटता है। दूसरे शब्दों में वह उनकी उन सापेक्षिक आवश्यकताओं की तीव्रता के सीधे अनुपात में बांटा जाता है जिनकी सम्पुष्टि विनिमय के द्वारा होती है।”^४

आय-कर का भार :

आय कर (Income Tax), अतिरिक्त लाभ कर (Excess Profit Tax), अति कर (Super Tax) तथा पूँजी लाभ कर (Capital Gains Tax), ये सब प्रत्यक्ष कर हैं और इनके भार को उन्हीं लोगों को सहन करना पड़ता है जो इनका सर्वप्रथम भुगतान करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के करों के भार को हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं होता। जब आय कर एक सामान्य कर के रूप में सभी प्रकार के व्यवसायों से प्राप्त आय पर लगाया जाता है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहता जिसमें कर न देना पड़ा हो, और ऐसी दशा में साधनों को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में हस्तान्तरित करके आय कर को नहीं टाला जा सकता। वेतन अथवा मजदूरी पर लगाये गए

4 “Taxes on imports and exports may then be regarded as obstacles to exchange and in accordance with the preceding theory, the direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by exchange”

—Dalton.

आय कर को अधिक अपने मालिक पर टबेलने का प्रयत्न करता है किन्तु वह ऐसा करने में सफल नहीं होता। अधिकों को मजदूरी उनकी सीमान्त उत्पादकता के अनुसार ही दी जाती है। मजदूरी पर आय कर लग जाने में अधिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आय कर लग जाने के पश्चात् उत्पादक के लिये इन अधिकों की सीमान्त उत्पादकता नहीं बढ़ती।

व्यवसायियों के लाभ पर उगाये गए आय कर को टाका जा सकता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार पाये जाते हैं। व्यवसायी-वर्ग तो यह समझता है कि वह अपने आय कर को बन्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके उपात्ताओं पर टाल देता है। इस सम्बन्ध में यह उपाय जाना है कि जब कोई व्यवसायी कीमतें निर्दिष्ट करने के लिए अपने लागत व्यय का अनुमान लगाता है, तो वह प्रायः कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से, उन आय कर को भी सम्मिलित कर लेता है जो उसे देना पड़ेगा और यदि बाजार की परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो वह कीमतें ऐसे स्तर पर निर्दिष्ट करेगा कि उनकी उत्पादन लागत तथा अनुमानित आय कर दोनों ही कविल जायें। किन्तु व्यवसायी इस बात से सहमत नहीं है और उनके अनुसार आय कर का भार को सामान्य परिस्थिति में टालना समझ नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कोई भी व्यवसायी बन्तु का मूल्य को प्रभावित करने की शक्ति नहीं रखता। उस अपनी बन्तु का प्रतियोगी मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। यदि कर के कारण वह अपनी बन्तु का मूल्य में वृद्धि करता है तो उसकी बन्तु का नहीं खरीदा जायगा। प्रतियोगितापूर्ण बाजार में बन्तु का मूल्य किसी समय भी सीमान्त लागत के बराबर हो सकता है और सीमान्त लागत में आय कर सम्मिलित नहीं होता क्योंकि सीमान्त उत्पादक का मुनाफा इतना कम होता है कि वह आय कर के धन्यगन नहीं करता। एकाधिकारी भी अपनी आय अथवा मुनाफे पर लगे हुए कर को उपात्ताओं पर नहीं टाल सकता है क्योंकि मूल्य में वृद्धि करने से उसकी बिक्री तथा आय कम हो जाने का भय रहता है। किन्तु यदि कोई व्यवसायी किसी एक स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में काम कर रहा है तो वह बन्तु के मूल्य में वृद्धि करके आय कर के भार का कुछ अंश तक उपात्ताओं पर टालने में सफल हो जाता है क्योंकि उसके ग्राहकों को उसमें इतना नगाव हो सकता है कि वे बन्तु का छोटा सा मूल्य बढ़ जाने पर अन्य विक्रेताओं के पास न जायें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अल्पज्ञान में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार, दोनों प्रकार की दशाओं में आय कर का भार कर देने वालों को ही सहन करना पड़ता है। यह सम्भव हो सकता है कि दीर्घकाल में आय कर का लोगों की काम करने तथा विनियोग करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़े और कुल रोजगार तथा आय की मात्रा घट जाय। ऐसी दशा में आय कर का भार सम्पूर्ण समाज को सहन करना पड़ेगा। किन्तु ऐसा तब होता है जब आय कर का दर काफी ऊँचा हो। आय कर की नीची अथवा सामान्य दरों का समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

भूमि पर कर का भार :

प्राचीन काल से ही यह विचार रहा है कि भूमि पर लगने वाला कर भव्ये उत्तम है क्योंकि उसके भार को टाला नहीं जा सकता और उसे भूमि-पतियों को ही सहन करना पड़ता है। यदि कर भूमि के शुद्ध लगान (Economic Rent) पर लगाया जाता है तो उसके भार को टालना संभव नहीं होता और उसे भूमि-पतियों को ही सहन करना पड़ेगा। यह धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि भूमि में अधिकतम लगान लिया जा रहा है। यदि लगान अधिकतम से कम होगा तो भूमिपति लगान में वृद्धि करके भार को हस्तांतरित करने में सफल हो जायगा और ऐसी स्थिति में कर के भार का कुछ अंश किसानों को भी सहन करना पड़ेगा। भूमि कर के भार को मूल्य के साथ जोड़कर उत्पादित वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर भी नहीं डाला जा सकता क्योंकि लगान एक प्रकार की बचत है और उसके घटने-बढ़ने का वस्तु के मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लगान किसी भी प्रकार वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करता यह तो स्वयं उसमें प्रभावित होता है। इस प्रकार भूमि के लगान पर कर लगने से अथवा कर की दर में वृद्धि होने पर वस्तु के मूल्य के बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती और इस प्रकार कर-भार का विवर्तन संभव नहीं है।

यदि सब प्रकार की भूमि पर एक साथ कर नहीं लगाया जाता और किसी एक प्रकार की वस्तु को उत्पन्न करने वाली भूमि पर ही कर लगाया जाता है तो कर के भार को उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में जोड़ कर उपभोक्ताओं पर टाला जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि चावल उत्पन्न करने वाली भूमि पर कर लगाया जाता है किन्तु अन्य प्रकार की फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि पर कर नहीं लगाया जाता तो ऐसी दशा में चावल के उपभोक्ताओं को कर का भार सहन करना पड़ेगा। यदि वे चावल के लिये अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होंगे तो चावल के स्थान पर अन्य फसलें पैदा की जाने लगेंगी। भूमि पर अन्य प्रकार में भी कर लगाया जा सकता है। यदि भूमि में लगी हुई पूँजी पर कर लगाया जाता है तो उसके भार का विवर्तन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। भूमिपति इस कर को देने के लिये भूमि जोतने वालों को मजदूर कर सकता है क्योंकि यदि वह भूमि में पूँजी का विनियोग नहीं करता तो भूमि की उत्पादन शक्ति गिर जायगी। इसी प्रकार यदि भूमि की उपज के अनुपात में कर लगाया जाता है तो उसके भार को आसानी से उपभोक्ताओं पर टाला जा सकता है। कर के भार का कितना विवर्तन करना संभव होगा, यह हम बात पर निर्भर है कि उत्पादित वस्तु की माँग कितनी लोचदार है। यदि वस्तु की माँग लोचदार है तो उसके मूल्य में आसानी से वृद्धि की जा सकेगी और कर का सम्पूर्ण भार उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ेगा और यदि वस्तु की माँग लोचदार है तो कर का अधिकांश भार भूमिपति अथवा किसान को सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भूमि कर के विवर्तन का प्रश्न एक जटिल समस्या है किन्तु अधिकांश दशाओं में इस कर के भार को भूमिपति ही सहन करता है।

मकानों पर कर का भार •

मकान पर लगने वाले कर का भार मकान मालिक तथा किरायेदारों को सहन करना पड़ता है। कभी-कभी मकान बनाने वाले धर्मिकों को भी उसका कुछ भार सहन करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यापारी मकान में रहता है तो वह कर के भार को अपनी वस्तुओं के खरीदारों पर भी डाल सकता है। यह सम्भव है कि किसी मौजूदा अवस्था स्थान पर काम करने वाले व्यापारी के ग्राहक वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने पर भी अन्य दुकानदारों के पास जाना पसन्द न करे। ऐसा या तो इसलिए होता है कि वे उस दुकानदार से खरीदने के आदि हो गये हैं या उन्हें उसमें अधिक विश्वास है अथवा वे दूर के दुकानदारों तक जाने के बट में बचना चाहते हैं। इस स्थिति में दुकानदार के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले मकान-कर के भार को कुछ अंग तक वस्तुओं का मूल्य बढ़ा कर उपभोक्ताओं पर टाल दे।

मकान मालिक तथा किरायेदारों के बीच कर का भार मकानों की मांग की लोच तथा उनकी पूर्ति के अनुसार बंटता है। यदि मकानों की मांग तेजी से बढ़ रही है तो मकान मालिक किराये में वृद्धि करके कर भार का अधिकतर हिस्सा किरायेदारों पर टाल देगे। प्रायः मकानों की मांग तेजी से बढ़ रही है इसलिए कर का अधिकतर हिस्सा किरायेदारों को ही सहन करना पड़ता है। यदि किराया नियंत्रण कानून के कारण अथवा किसी अन्य कारण से मकान मालिक के लिये किराये में वृद्धि करना सम्भव नहीं है तो कर का भार उसे स्वयं सहन करना पड़ेगा। अगर किसी स्थान पर मकानों की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा कम है तो मकान मालिक किराये को नहीं बढ़ा सकेंगे और कर का सम्पूर्ण भार मकान मालिक पर ही पड़ेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में मकान मालिक नए मकानों का निर्माण बन्द कर देंगे और मकानों की कमी के कारण किराया बढ जायेगी और अन्त में किरायेदारों को ही कर का भार सहन करना पड़ेगा।

मृत्यु कर

मृत्यु कर मरने वाले व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर लगाया जाता है। एक सीमा निर्दिष्ट कर दी जाती है और जो लोग भी उसमें अधिक मूल्य की जायदाद मरते समय छोड़ते हैं, उन पर वजनी हुई दर से यह कर लगाया जाता है। यह कर या तो जायदाद कर (Estate Duty) के रूप में लगाया जाता है या उत्तराधिकार कर (Inheritance Tax) के रूप में लिया जाता है। जायदाद कर मरने वाले की कुछ सम्पत्ति पर उसका बटवारा होने से पूर्व लिया जाता है किन्तु उत्तराधिकार कर उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है। इन करों का भार किम पर पड़ता है? उत्तराधिकारी इस कर को सहन करता है अथवा मरने वाला? सामान्यतया यह माना जाता है कि मरने पर सभी ऋणों का भुगतान हो जाता है और मृत व्यक्ति पर किसी प्रकार का भार नहीं डाला जा सकता। इसलिए

मृत्यु कर के भार का मृत व्यक्ति पर पड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और इस प्रकार के कर का भार उत्तराधिकारियों को ही सहन करना पड़ता है। यदि मरने वाले व्यक्ति ने इस कर के भुगतान के लिये किसी प्रकार का बीमा कराया हुआ है तो ऐसी दशा में कर भार मृत व्यक्ति ही सहन करता है क्योंकि वह अपने जीवन काल में उम्र बीमा की किस्त देता रहा है जिससे रकम से कर का भुगतान किया जाता है। अन्त में यहो कहा जा सकता है कि मृत्यु कर, चाहे जिस रूप में भी लगाया जाय, एक प्रत्यक्ष कर है जिस के भार को टाँसना बिल्कुल सम्भव नहीं है। इस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे देता है।

बिक्री कर :

यह कर वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है और इसे व्यापारियों से वसूल किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर होने के कारण इस के भार के टाँसे जाने की काफी सम्भावना है। प्रायः कर का भार उन व्यापारियों के द्वारा सहन नहीं किया जाता जो कर का भुगतान करते हैं। बिक्री कर का प्रारम्भिक भार तो विक्रेताओं पर पड़ता है किन्तु उसे वस्तुओं के मूल्य में जोड़ कर उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं। कभी-कभी व्यापारियों को भी उसका कुछ भ्रश सहन करना पड़ सकता है। व्यापारी जिस सीमा तक बिक्री कर को उपभोक्ताओं पर टालने में सफल होंगे यह वस्तुओं की माँग की लोच पर निर्भर होता है। यदि कर की मात्रा बहुत कम है और उसे सुविधा में वसूल नहीं किया जा सकता तो व्यापारी वस्तु के मूल्य को बढ़ाने की अपेक्षा कर के भार को स्वयं सहन कर लगे। किन्तु यदि कर की रकम काफी है तो वे उसे उपभोक्ताओं पर टालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जिन वस्तुओं की माँग बेलाच होती है उन पर लगे कर को आसानी से उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। किन्तु लोचदार भाग वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में कर का सम्पूर्ण भार टालना सम्भव नहीं होता और उन्हे व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों ही सहन करते हैं। कुछ दशाओं में कर के भार का विवर्तन पीछे की ओर भी किया जा सकता है और व्यापारी उत्पादक को वस्तु कम मूल्य पर देने के लिये बाध्य कर सकता है। ऐसा लोचदार भाग तथा बेलाचदार पूर्ति वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में ही होता है। समाज की दृष्टि से बिक्री कर शोको के व्यय पर एक प्रकार का कर है। व्यक्तिगत व्यय का घटना स्वाभाविक है किन्तु यदि उसे सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के द्वारा सन्तुलित कर दिया जाय तो उसका उत्पत्ति तथा रोजगार की मात्रा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परीक्षा प्रश्न

1. What do you mean by the incidence of a tax? Discuss the incidence of the sales tax. (Madras B. A. 1954)

कर-भार से आप क्या समझते हैं? बिक्री कर के भार की व्याख्या कीजिये।

2. What do you understand by incidence of taxation ? How would you determine the incidence of central excise on tobacco or Vanaspathi in India. (Agra B. A. II 1961)
कर-भार से आयका क्या मतलब है ? भारत में तम्बाकू अथवा वनस्पति पर उत्पादन-कर का भार आय किस प्रकार निर्धारित करेंगे ?
3. Discuss the problem of incidence of taxation under a competitive Economy ? (Agra B. A. II 1953)
एक प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था में कर-भार की समस्या की व्याख्या कीजिये ।
4. Distinguish incidence from the effects of taxation. On what does the incidence of a tax depend ? (Agra B. Com, 1952)
कर-भार तथा कर के प्रभावों में अन्तर कीजिये । किसी कर का भार किन बातों पर निर्भर होता है ?
5. What are the general principles that determine the incidence of taxation ? On whom does the incidence of the following taxes rest—(a) A tax on land, (b) A tax on buildings (c) Custom duties. (Madras B. A, 1951)
कौन से सामान्य सिद्धान्त कर-भार को निश्चित करते हैं ? निम्नलिखित करों का भार किन पर पड़ता है—(अ) भूमि पर कर (ब) भवनों पर कर (स) आयात-निर्मात कर ।



उत्पत्ति तथा वितरण पर करारोपण का प्रभाव Effects of Taxation on Production & Distribution

कर हमारे आर्थिक जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। उनके कारण समाज में धन की उत्पत्ति तथा वितरण में परिवर्तन हो सकता है। वे लोगो की काम करने की तथा बचत करने की इच्छा को भी प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कर आर्थिक जीवन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और कुछ बुरा। करारोपण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उससे बुरे प्रभाव बिल्कुल उत्पन्न न हों। डा० डाल्टन के अनुसार 'आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छी कर प्रणाली वह है जिसका सबसे अच्छा अथवा कम से कम बुरा प्रभाव पड़ता हो।'^१ कर प्रणाली की जाँच करते समय हमें केवल करों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ही नहीं देखना चाहिये बल्कि करारोपण से होने वाली आय को खर्च करने के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिये। यह सम्भव हो सकता है कि सार्वजनिक व्यय से होने वाला लाभ करो में होने वाली हानि की अपेक्षा अधिक हो और दोनों मिलकर सामाजिक लाभ में वृद्धि करते हों।

करो के आर्थिक प्रभावों को अध्ययन की दृष्टि में निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है—

- (अ) उत्पत्ति पर प्रभाव (Effects on Production)।
- (ब) वितरण पर प्रभाव (Effects on Distribution)।
- (स) अन्य प्रभाव (Other Effects)।

उत्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को भी तीन वर्गों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है—(i) काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव (ii) काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव (iii) आर्थिक साधनों के वितरण पर प्रभाव।

काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव :

कर लोगो की काम करने तथा बचत करने की शक्ति को कम करके देश में धन के उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय को कम कर सकते हैं। उन करो को आर्थिक दृष्टि

1. "The best system of taxation from the economic point of view is that which has the best or the least bad economic effects."

—Dr. Dalton

में प्रच्छा नहीं समझा जाता है जिनका काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे सभी कर लोगों की काम करने की शक्ति को कम करते हैं जिनके कारण उनकी कार्य-कुशलता कम होती हो अथवा जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हो। यदि कर लग जाने के कारण लोगों को अपनी आवश्यकताओं पर किया जाने वाला व्यय कम करना पड़ता है तो ऐसा कर अवश्य ही उनकी कार्य-कुशलता को कम करेगा। जब कम आय वाले लोगों पर कर लगाया जाता है तो उनके परिणामस्वरूप उनका आवश्यक वस्तुओं का उपभोग घट जाता है जिनके कारण उनकी कार्यकुशलता तथा काम करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि जीवन रक्षक अथवा कार्य-श्रमता सम्बन्धी वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर लगाया जाता है तो उसका भी यही परिणाम होता है। गरीबों पर इस प्रकार कर नहीं लगाना चाहिये कि उनकी आय तथा व्यय में कमी होने के कारण कार्यकुशलता कम हो जाय। यही कारण है कि गरीबों को बहुत सी प्रकार के करों में मुक्त रखा जाता है। कुछ करों का काम करने की शक्ति पर अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जाता है जिनके प्रयोग का लोगों के स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो कर लग जाने के कारण इन वस्तुओं का प्रयोग कम हो जाता है और लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। सराय, भग तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर लगाये जान वाले करों का यही प्रभाव होता है। इसलिये उन्हें सामाजिक दृष्टि से अच्छा समझा जाता है।

कर केवल लोगों की काम करने की शक्ति को ही कम नहीं करते बल्कि वे उनकी बचत करने की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। लगभग सभी प्रकार के करों का प्रभाव लोगों की बचत करने की क्षमता को कम करने का होता है। कर लगने से करदाताओं की आमदनी अनिवार्य रूप से घट जाती है और उनकी बचत करने की शक्ति कम हो जाती है। जो लोग अपनी आमदनी में से कुछ बचा रहे हैं उन पर लगने वाला प्रत्येक कर बचत करने की क्षमता को कम करता है। जिन रकम को इन लोगों के द्वारा पहले बचाया जाता था अब वही रकम सरकार कर के रूप में ले लेती है। विशेषतया धनी वर्ग तथा मध्यम श्रेणी के लोगों पर लगने वाले कर बचत की मात्रा को कम करते हैं। कर की दर जितनी अधिक ऊँची होती है उतनी ही अधिक वह इन लोगों की बचत करने की क्षमता को कम करती है। केवल गरीबों पर लगने वाले कर बचत करने की क्षमता को कम नहीं करते क्योंकि इन लोगों की आमदनी इतनी कम होती है कि इनके लिये किसी भी प्रकार की बचत करना असम्भव है।

काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव -

दरपान के लिये लगाय जान वाले कर का काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु एक स्याई कर उन लोगों की आमदनी को कम करता है जिन पर यह लगाया जाता है और आमदनी की यह कमी उनकी काम

करने तथा बचत करने की इच्छा को प्रभावित करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आमदनी कम हो जाने पर करदाता अधिक काम करेंगे जिससे कि वे अपनी आय के पहले स्तर को फिर से स्थापित कर सकें। यह प्रायः उन लोगों के सम्बन्ध में ठीक होता है जिनके आश्रितों की संख्या काफी है या जो भविष्य में निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य में बचत करते हैं। इन लोगों के लिये आमदनी की मांग की लोच कम होती है इसलिये वे आमदनी में होने वाली कमी को अधिक परिश्रम के द्वारा पूरा करने की बोधित करते हैं। ऐसे लोगों की काम करने की इच्छा पर करारोपण का अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसमें वृद्धि होगी है। किन्तु उन लोगों के सम्बन्ध में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जिनके लिये आमदनी की मांग की लोच काफी है, ऊँचे कर काम करने तथा बचत करने की इच्छा को कम करते हैं। किसी विशेष कर का लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यह कर की प्रकृति तथा करदाताओं के लिये आमदनी की मांग की लोच पर निर्भर होता है। यदि आय की मांग बेलोच है तो कर के कारण उत्पन्न होने वाली आय की प्रत्येक कमी करदाताओं को अधिक परिश्रम तथा उद्योग करने के लिये प्रोत्साहित करती है। किन्तु यदि व्यक्ति के लिये आय की मांग लोचदार है तो ऐसी स्थिति में कर के कारण लोगों की काम करने की इच्छा कम हो सकती है।

करारोपण का बचत करने की इच्छा पर सामान्यतया बुरा प्रभाव पड़ता है। केवल उन लोगों को छोड़ कर जो भविष्य में निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बचते हैं, अन्य सभी लोगों की बचत करने की इच्छा, नये करों के लगने से कम हो जाती है। प्रत्येक कर लोगों की वर्तमान आय को कम करता है और यदि भविष्य में किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के लिये धन की आवश्यकता नहीं है तो करदाता अपने वर्तमान उपभोग को कम नहीं करेगा और स्वाभाविक रूप से वह बचत को कम करने का निश्चय करेगा। कर लोगों की बचत करने की इच्छा को इसलिये भी कम करते हैं क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि भविष्य में बचत होने वाली आमदनी पर भी इसी प्रकार कर लगाया जायगा और वे इस कारण धन के वर्तमान प्रयोग को बचत की अपेक्षा अधिक महत्व देने लगते हैं। यद्यपि सभी कर लोगों की बचत करने की इच्छा को कम करते हैं किन्तु उनमें से कुछ प्रकार के कर अन्य प्रकार के करों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव डालते हैं। वस्तुओं पर लगने वाले कर लोगों की क्रय-शक्ति को कम करके उनकी बचत करने की इच्छा को कुछ कम करते हैं किन्तु आमदनी अथवा मर्चित धन पर लगाया जाने वाले कर लोगों की बचत करने की इच्छा पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिये व्यय कर (Expenditure Tax) को आय तथा बचत पर लगाये जाने वाले कर की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है।

साधनों के वितरण पर प्रभाव .

करारोपण आर्थिक साधनों के वितरण को प्रभावित करने भी उत्पत्ति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। उद्घन से कर साधनों के वर्तमान वितरण को बदल कर

उन्हे विभिन्न व्यवसायों में नये ढंग में वाट देते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि जब साधनों के स्वाभाविक वितरण में कोई परिवर्तन होता है तो वह उत्पादन को कम कर देता है। इसलिये कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे कर लगाये जायें जिनका साधनों के वितरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्राक्मणिक धन तथा भूमि के मूल्य पर लगने वाले कर इसी प्रकार के होते हैं। किन्तु फिर भी कुछ अन्य कारणों से ऐसे कर लगाने पड़ते हैं जिनके कारण उद्योग तथा व्यवसायों के बीच साधनों का पुनर्वितरण हो जाता है। जब किसी वस्तु पर कर लगता है तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है जिसके कारण उसका मूल्य भी बढ़ता है। मूल्य वृद्धि उसकी मांग को कम कर देती है और उस वस्तु का उत्पादन कम मात्रा में होने लगता है। उत्पादक में लगे हुए कुछ साधन बेकार हो जाते हैं और उन्हें अन्य उद्योग अथवा व्यवसाय में जाना पड़ता है। यदि उत्पादक कर का भार स्वयं सहन करने का निश्चय करते हैं तो कुछ सीमान्त उत्पादकों को व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा और वे अपने साधनों को दूसरे व्यवसाय में लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार यदि उत्पादन पर कर केवल एक क्षेत्र में लगाया जाना है और अन्य क्षेत्र कर से मुक्त रहने हैं तो ऐसी दशा में व्यवसायी अपने साधनों को करारोपित क्षेत्र से हटा कर कर-मुक्त क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से साधनों का पुनर्वितरण काफी कठिन हो सकता है क्योंकि धन तथा पूँजी कुछ उद्योगों के लिये विशिष्ट (Specific) हो जाते हैं और उन्हें वहाँ से हटा कर अन्य उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता है। किन्तु नये साधनों के पुनर्वितरण में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती।

साधनों का पुनर्वितरण प्रायः उत्पत्ति पर घुरा प्रभाव डालता है किन्तु कभी-कभी समाज को इससे लाभ भी हो सकता है। यदि करारोपण के कारण उत्पत्ति के साधन, समाज की दृष्टि से कम उपयोगी उद्योगों से हटा कर अधिक उपयोगी उद्योगों में लग जाते हैं तो उससे समाज को लाभ होता है। उदाहरणार्थ यदि शराब पर कर लगने से शराब के उत्पादन में लगे हुये साधन अन्य उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में लग जाते हैं तो उससे सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि कर के कारण भूमि कम उपयोगी प्रयोग से हटा कर अधिक उपयोगी प्रयोग में लगाई जाती है तो उससे समाज को लाभ होता है। इसके विपरीत यदि कर के कारण उत्पत्ति के साधन उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन से हटा कर कम उपयोगी अथवा हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन में लगाये जाते हैं तो उससे समाज को शुकसान होता है।

धन के वितरण पर प्रभाव :

जिस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हम ऐसी कर प्रणाली को चुनना चाहिये जिसका उत्पादन पर सबसे कम घुरा प्रभाव पड़े ठीक उसी प्रकार वितरण की दृष्टि से कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसकी प्रकृति धन के वितरण को असमानताओं को कम करने की हो। जर्मन अर्थशास्त्री वॉगनर (Wagner) ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि करारोपण का प्रयोग वितरण की असमानताओं को दूर करने के लिये

किया जाना चाहिये। आजकल करारोपण को धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने का एक मुख्य साधन माना जाता है। एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने में सहायता दे। यदि किसी देश में ऐसे कर लगाये जाते हैं जिनके कारण धन की असमानताएँ बढ़ती हैं तो वे निश्चित रूप से समाज के लिये हानिकारक होंगे। विभिन्न प्रकार के करों का धन के वितरण पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। वर जितनी अधिक प्रगतिशील दर से लगाया जाता है उतना ही वह असमानताओं को जल्दी समाप्त करता है। इसके विपरीत प्रतिगामी (Regressive), आनुपातिक (Proportional) तथा मामूनी प्रगतिशील कर धन के वितरण की असमानताओं को बढ़ाते हैं। वितरण की दृष्टि से कर अधिक प्रगतिशील दर से लगाये जाने चाहिये किन्तु ऐसे करों का उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रो० पीगू के अनुसार धन के वितरण की असमानताओं को कम करना तब तक ठीक होता है जब तक कि ऐसा करने से राष्ट्रीय लाभों की मात्रा में कोई कमी न हो। देश के लिये कर-प्रणाली का चुनाव करते समय हमें उत्पादन तथा धन के वितरण दोनों को ध्यान में रखना चाहिये।

प्रतिगामी (Regressive) तथा आनुपातिक कर निश्चित रूप से धन के वितरण की असमानताओं को बढ़ाते हैं इसलिये किसी देश की कर-प्रणाली में उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिये। एक अच्छी कर-प्रणाली में अधिकांश कर प्रगतिशील (Progressive) होने चाहिये जिससे कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली की प्रवृत्ति प्रगामिता की ओर हो। सामान्यतया, आमतौर में प्रयोगों में आने वाली वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि इनका भार निम्न व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और धनी व्यक्तियों पर कम। विक्री कर (Sales Tax) तथा व्यक्तिगत व्यय पर लगने वाला कर भी प्रतिगामी होता है क्योंकि आमदनी के बढ़ने के साथ साथ उसका व्यय किया जाने वाला प्रतिशत घटता जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं पर लगने वाले सभी कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि वे आनुपातिक होने के कारण उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में भेद नहीं करते हैं और सभी कर दाताओं पर एक दर से लगाये जाते हैं। ऐसे कर धन की वितरण की असमानताओं को बढ़ाते हैं इसलिए उनकी मात्रा कम से कम रखी जानी चाहिये।

लोगों की आय तथा धन पर लगने वाली करों को काफी प्रगतिशील बनाया जा सकता है। वर्तमान आय कर प्रायः प्रगतिशील है क्योंकि उसके अन्तर्गत अधिक आय वाले पर कम आय वालों की अपेक्षा ऊँची दर से कर लगाया जाता है, जिनकी आमदनी बहुत अधिक होती है उन पर अतिरिक्त कर (Super Tax) भी लगाया जा सकता है। उत्तराधिकारी कर (Inheritance Tax) तथा अन्य प्रकार के सम्पत्ति कर भी प्रगतिशील होते हैं। क्योंकि यह सब कर बढती हुई दर से लगाये जाते हैं। प्रमण्डल कर (Corporation Tax) तथा भूमि मूल्यों पर लगाने वाले करों को भी काफी सीमा तक प्रगतिशील बनाया जा सकता है। सामान्यतया प्रत्यक्ष करों (Direct Taxes) में प्रगतिशीलता अधिक पाई जाती है इस

लिए उनका प्रयोग धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। वही-वही सुरक्षा प्रशुल्क (Protective Tariffs) को भी इन उद्देश्यों के लिये काम में लाया जा सकता है। यदि सुरक्षा ऐसे उद्योगों को दिया जाता है जिनमें मजदूरी की दर अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक है तो इसका प्रभाव इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने का होगा और श्रमिक कम मजदूरी वाले उद्योगों को छोड़कर अधिक मजदूरी वाले उद्योगों में आ जायेंगे जिनके कारण धन के वितरण की असमानताएँ कम हो जायेंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति उन वस्तुओं पर कर लगा कर भी की जा सकती है जिनका प्रयोग केवल धनी लोगों के द्वारा किया जाता हो।

कर के अन्य प्रभाव :

धन के उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अतिरिक्त, कर हमारे आर्थिक जीवन पर अन्य प्रकार के प्रभाव भी डालते हैं। कर समाज में लोगों के उपभोग, रोजगार के स्तर तथा व्यवसाय की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि करारोपण के कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ती है। उनका यह कहना है कि करारोपण के द्वारा सरकार जो रुपया लेती है यदि वह व्यवसायियों के पास रहता तो उसका विनियोग रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने के लिए किया जाता। इस विचार में सत्यता का बहुत कम अंश पाया जाता है। यद्यपि बहुत ऊँचे कर तथा आन्तरिक लगने वाले करों का रोजगार की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है किन्तु यह कहना कि करों के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, कुछ ठीक नहीं। सरकार करों के रूप में जो रुपया लेती है उसके व्यय के द्वारा भी समाज में रोजगार बढ़ता है। जब रुपया लोगों की भलाई के लिये खर्च किया जाता है तो उन के कारण रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में नये तथा ऐसे उद्योग लगाये जा सकते हैं जिन्हें जोखिम अधिक होने के कारण व्यक्तिगत व्यवसायियों के द्वारा न लगाया जाता। ऐसी दशा में लोगों को नया काम मिलता है और रोजगार तथा व्यापार के स्तर में वृद्धि होती है। किन्तु फिर भी करारोपण का प्रभाव रोजगार की मात्रा पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है। विशेषतया वे कर जो उपभोग तथा विनियोग को कम करने वाले होते हैं, व्यवसाय तथा रोजगार की मात्रा को भी कम करते हैं। किन्तु यह कभी सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले विस्तार के साथ सन्तुलित हो जाती है।

कर का लोगों के उपभोग तथा रहन सहन के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कर की प्रवृत्ति उपभोग को कम करने की होती है जिससे कारण लोगों के आर्थिक कल्याण को नुकसान पहुँच सकता है। निचले लोगों पर लगने वाले कर उन्हें अपना रहन-सहन का स्तर नीचा करने पर मजबूर करते हैं। आवश्यकता की वस्तुओं पर लगाने वाले करों का भी यही परिणाम होता है। कर केवल उपभोग की मात्रा को ही प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि वे उसकी प्रवृत्ति को भी दबत देते हैं।

करों का यह परिणाम हो सकता है कि लोग कुछ वस्तुओं का कम प्रयोग करने लगे तथा कुछ का अधिक । यदि कर का प्रभाव हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग को कम करने का होता है तो उस से समाज को लाभ होता है किन्तु ऐसे कर भ्राय की दृष्टि से अच्छे नहीं होते । शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं के लगने वाले करों का प्रभाव इसी प्रकार का होता है ।

किसी देश के लिए अच्छी कर प्रणाली का चुनाव करते समय करो के सभी प्रकार के प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिये । कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसका उत्पादन पर कम से कम बुरा प्रभाव पड़े और जो बचत तथा विनियोग को मात्रा में कोई विरोध कभी न करती हो । अच्छी कर प्रणाली वही है जिसकी प्रवृत्ति धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने की हो । इसके साथ-साथ करारोपण का रोजगार, व्यवसाय तथा उपभोग के स्तर पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । यद्यपि इन सब उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी इन मंत्र में इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये जिससे सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जा सके ।

लोक ऋण Public Debt

सार्वजनिक ऋण वर्तमान सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार व निरन्तर बढ़ते हुये व्यय को नेबल करारोपण तथा सुल्कों में प्राप्त आय से पूरा नहीं किया जा सकता। घट सरकार को आय प्राप्त करने के अन्य श्रोतों का प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य साधनों में प्राप्त आय के अतिरिक्त प्राय सरकार को सार्वजनिक ऋणों में भी आय प्राप्त करनी होती है। आगम का यह साधन राज्य के अन्य आय व साधनों में थोड़ा भिन्न है क्योंकि इस प्रकार के ऋणों पर सरकार को लम्बे समय तक व्याज देना पड़ता है तथा अवधि समाप्त होने पर भूलघन उन लोगों को लौटाना होता है जिनमें उसे उधार लिया गया है। इसलिये सरकार को साधारण परिस्थिति में ऋण नहीं लेना चाहिये और साधारण व्यय को आय के सामान्य साधनों में पूरा करना चाहिये। सार्वजनिक ऋण केवल असामान्य परिस्थिति में अथवा असाधारण व्यय को पूरा करने के लिये ही लिया जाना चाहिये। कभी-कभी सरकार को रुपये की तुरन्त आवश्यकता होती है और इतनी उल्टी करो आदि से आय प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में सरकार सार्वजनिक ऋण के द्वारा धन प्राप्त करके अपनी आवश्यकता पूरी करती है। कुछ छात्रिक कारणों से कभी-कभी सरकार ऋणों के द्वारा आय प्राप्त करना बंद करके अपेक्षा अधिक अच्छा समझती है। वर्तमान काल में सार्वजनिक ऋणों का सबसे महत्वपूर्ण कारण युद्ध तथा आर्थिक विकास पर किया जाने वाला व्यय है। सरकार का व्यय युद्ध के कारण अथवा आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण की योजनाओं को पूरा करने के लिये इतना अधिक बढ़ गया है कि उसे आय के सामान्य साधनों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के व्यय को सरकार प्रायः जनता से अथवा विदेशों से ऋण लेकर पूरा करती है।

सार्वजनिक ऋण के द्वारा आय प्राप्त करने की प्रणाली का आरम्भ वर्तमान शताब्दी में ही हुआ है। १८वीं शताब्दी तक कोई इसे जानता भी नहीं था। जब कभी युद्ध आदि के कारण सरकार पर कोई आरस्मिक व्यय पड़ता था तो उसे सचिव सरकारी कोष के द्वारा पूरा किया जाता था। सरकार अपनी अतिरिक्त आय को खजाने के रूप में जमा रखती थी और इसका प्रयोग आरस्मिक तथा असामान्य व्यय को पूरा करने के लिये किया जाता था। कभी-कभी इस प्रकार के व्यय को पूरा करने

के लिये राजा अपनी निजी साख के आधार पर उधार भी लेता था । वर्तमान काल में सचिव कोष तथा राजा की निजी साख का स्थान सार्वजनिक ऋण ने ले लिया है । आधुनिक सरकारों के उत्तरदायित्व में वृद्धि होने के साथ-साथ उन पर ऋणों का भार भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है । आजकल सभी बड़ी-बड़ी सरकारों पर भारी मात्रा में राष्ट्रीय ऋण होते हैं ।

व्यक्तिगत ऋण तथा सार्वजनिक ऋण में भेद :

लोक ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण में कुछ अन्तर तब समानता पाई जाती है क्योंकि दोनों प्रकार के ऋण उस समय लिये जाते हैं जब सामान्य प्राय के शरा बाय को पूरा करना सम्भव नहीं होता तथा दोनों प्रकार के ऋणों के मध्य α भुगतान व व्याज के भुगतान की समस्या होती है । इस समानता के होने हुए भी दोनों प्रकार के ऋणों में कुछ आधारभूत अन्तर पाये जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(१) सरकार के हाथ में राजमन्ता होती है इसलिए वह जनता को ऋण देने के लिये मजबूर कर सकती है । वह ऋण पर कम व्याज लेने के लिये भी लोगों को बाध्य कर सकती है और यदि चाहे तो ऋण की वापसी से भी इन्कार कर सकती है, यद्यपि ऐसा सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जाता । व्यक्ति की भाँति सरकार पर ऋण चुपाने के लिये जोर नहीं डाला जा सकता । इसके विपरीत व्यक्ति किसी को ऋण देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता और न ऋण का भुगतान करने में इन्कार कर सकता है । वह ऋणदाता की इच्छा के विरुद्ध ऋण पर व्याज की दर भी कम नहीं कर सकता ।

(२) सरकार का जीवन निरन्तर चलता रहता है इसलिये वह स्थायी तथा दीर्घकालीन ऋण ले सकती है एवं ऋणों के भुगतान के लिये स्थायी सौदा कर सकती है किन्तु व्यक्ति के लिये दीर्घकालीन ऋण लेना सम्भव नहीं होता । इसलिये व्यक्तिगत ऋणों के सम्बन्ध में समय सीमा का होना आवश्यक है किन्तु सरकारी ऋणों के सम्बन्ध में वह जरूरी नहीं है ।

(३) सरकार आन्तरिक (Internal) तथा बाहरी (External) दोनों प्रकार के ऋण ले सकती है । देश के भीतर वह अपने प्राचीन नागरिकों से तो ऋण लेती ही है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य देशों में रहने वाले लोगों से तथा विदेशी सरकारों से भी ऋण ले सकती है । इसके अतिरिक्त सरकार अधिक मात्रा में नोट छाप कर भी जनता से अप्रत्यक्ष ऋण ले सकती है; किन्तु एक व्यक्ति के ऋण लेने के साधन सीमित होते हैं । वह केवल देश के भीतर अन्य लोगों से ऋण ले सकता है । उसके लिये न तो अपने प्रतिभा-पत्र (I. O. U's) छाप कर चलाना सम्भव होता है और न वह विदेशों से ऋण ले सकता है ।

(४) सरकार के द्वारा लिया गया ऋण प्रायः जनता की भलाई के लिये खर्च किया जाता है जिसका लाभ ऋणदाताओं को भी होता है किन्तु व्यक्ति ऋण की रकम को अपनी भलाई के लिये व्यय करता है जिससे ऋणदाता को कोई लाभ नहीं होता ।

(५) सार्वजनिक ऋण का भुगतान प्रायः जनता पर करारोपण के द्वारा किया जाता है। ऋण के भुगतान की रकम का कुछ भाग उन लोगों से भी आता है जिन्हें कि भुगतान किया जाना है क्योंकि करदाता सरकार के ऋणदाता भी हो सकते हैं। अतः सरकार को ऋण देने वाले लोगों को ऋण के भुगतान का पूरा लाभ नहीं मिलता बल्कि यह उतना कम हो जाता है जितना कि उन्हें कर के रूप में देना पड़ता है। व्यक्तिगत ऋण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता क्योंकि व्यक्ति अपने ऋण के भुगतान का भार किसी भी प्रकार ऋणदाता पर नहीं डाल सकता।

(६) सार्वजनिक ऋणों पर व्यक्तिगत ऋणों की अपेक्षा ब्याज की दर कम होती है। सरकार को अपनी साख सरकार की अपेक्षा बहुत कम होनी है। इसलिए उसे ऋणों पर अधिक ब्याज की दर देनी पड़ती है।

(७) लोक ऋणों के भुगतान का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में ऋणों का भुगतान करने पर देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है तथा राष्ट्रीय आय पर भी इसका घुरा प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में इस प्रकार के कोई प्रभाव नहीं पड़ते उनका प्रभाव केवल भुगतान करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है।

(८) सार्वजनिक ऋणों का उद्देश्य भी सामान्यतः व्यक्तिगत ऋणों के उद्देश्य से भिन्न होता है। सरकार के द्वारा लिये जाने वाले अधिकांश ऋण उदात्तक कार्यों के लिये होते हैं किन्तु व्यक्तिगत ऋण उदात्तक तथा अनुत्पादक दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों के लिये लिया जा सकता है।

ऋण कब लेना चाहिये

वर्तमान सरकारों के वित्त में सार्वजनिक ऋण ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी सरकारों को अपने व्यय के कुछ भाग को पूरा करने के लिये लोक ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार निश्चिन्त सीमाओं के भीतर लोक ऋण आवश्यक तथा लाभपूर्ण होता है। सार्वजनिक ऋणों का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिये सरकार के द्वारा ऋण केवल विशेष परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए। लोक-ऋण से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये सरकार को उसका प्रयोग आय के अन्य साधनों के पूरक के रूप में करना चाहिये। अपना व्यय पूरा करने के लिये सरकार को आय, करों तथा लोक ऋण के बीच चुनाव करना पड़ता है इसलिये यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में सरकार को ऋण लेना चाहिये।

आधुनिक वित्त सिद्धान्त के अनुसार सरकार के द्वारा किये जाने वाले सामान्य खर्च, जो काफी नियमित रूप से किये जाते हैं, आय के सामान्य स्रोतों से पूरे किये जाने चाहिये जिसके अन्तर्गत कर, शुल्क तथा उद्योगों आदि से प्राप्त आय आती है। अतिरिक्त व्यय (Extra-Ordinary Expenditure) को पूरा करने के लिये सरकार

ऋण ले सकती है। ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिये, जिसका लाभ भविष्य की पीढ़ियों को मिलाना है, सरकार जनता से ऋण ले सकती है। सरकार के द्वारा निम्न प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये ऋण लिया जा सकता है—

आकस्मिक सकटकाल में सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार के सकटकालीन व्यय को पूरा करने के लिये सरकार ऋण ले सकती है। युद्ध भूकम्प, बाढ़ तथा दुर्भिक्ष आदि के समय में सरकार को भारी मात्रा में सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है क्योंकि आय के सामान्य साधनों से विपत्तिकालीन व्यय को पूरा नहीं किया जा सकता। जब कोई देश युद्ध में फँस जाता है तो उसे देश की रक्षा करने के लिये बहुत बड़ा मात्रा में व्यय करना पड़ता है। करो से प्राप्त आय के द्वारा युद्ध के खर्च को पूरा नहीं किया जा सकता इसलिये सरकार के लिये ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में लोक ऋण का विकास ही युद्ध व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था।

सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये भी सरकार के द्वारा ऋण लिया जाना उचित है। रस्ते, मडके, हवाई अड्डे तथा मिचार्ड साधनों के निर्माण पर सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है जिसे सामान्य आय से पूरा करना संभव नहीं होता। इस प्रकार के निर्माण कार्यों पर किया जान वाला व्यय उत्पादक व्यय होता है इसलिये उसे सार्वजनिक ऋण से पूरा किया जा सकता है। युद्ध व्यय का कुछ भाग सार्वजनिक ऋण तथा कुछ करो के द्वारा पूरा किया जा सकता किन्तु सार्वजनिक निर्माण पर किया जान वाला उत्पादक व्यय लोक ऋण से ही पूरा किया जाना चाहिये करो में नहीं। यदि इस प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये कर लगाय जायेंगे तो करो की मात्रा बहुत अधिक हो जायगी जिस किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। जनता की भलाई के कामों पर, जैसे हस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण, किया जान वाला व्यय भी लोक ऋण से पूरा किया जा सकता है।

दश के आर्थिक विज्ञान के सम्बन्ध में किये जाना वाला व्यय भी लोक ऋण के द्वारा पूरा किया जा सकता है। आर्थिक साधनों के विकास के लिये सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करना होता है जिसे करो के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यय का बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक ऋण के द्वारा पूरा किया जाता है। अल्प विकसित देशों में विकास योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का अधिकांश लोक ऋण के द्वारा पूरा किया जाता है।

बजट के अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए भी लोक ऋण का प्रयोग किया जा सकता है। कभी-कभी सरकार, को रुपये की तुरन्त आवश्यकता होती है किन्तु इतनी जल्दी करो आदि से आय प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को ऋण लेना पड़ता है। सरकार प्रायः करो से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर अल्पकालीन ऋण लेती रहती है।

सधेय में यह कहा जा सकता है कि सरकार का तत्प्राप्त चालू खर्च करो के द्वारा पूरा किया जाना चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जिसका पालन आवश्यक मामान्य व्यय को ऋणों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से सरकार पर ऋणों का भार निम्नतर बढ़ता जायगा। आपत्तिव्यय प्राप्तिके कारण उत्पन्न चालू व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक ऋण दिया जा सकता है। आपत्तिव्यय तथा आवश्यक निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए दिया जाने वाला व्यय लोक ऋण के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

लोक ऋण का वर्गीकरण

लोक-ऋण का कोई एक-मात्र वर्गीकरण नहीं मिलता। विभिन्न लेखकों ने उनका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। ऋणों का वर्गीकरण प्रायः ऋण की प्रकृति, भुगतान की शर्तें ऋण व उद्देश्य आदि को आधार मान कर किया जाता है। लोक ऋण के कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं—

ऐच्छिक तथा अनिवार्य ऋण।

लोक ऋण (1) ऐच्छिक तथा (2) अनिवार्य हो सकते हैं। ऐच्छिक ऋण वह होता है जिसे लोग अपनी म्दतन्त्र इच्छा से देते हैं और उन पर ऋण देने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। इसके विपरीत अनिवार्य ऋण वह होता है जिसमें रकबा देने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। प्राचीन काल में सरकारें इस प्रकार के ऋण लिया करती थीं किन्तु वर्तमान काल में इस प्रकार के ऋणों का महत्त्व नगण्य हो गया है। कुछ काल तथा अन्य प्रकार की मकद-कालीन स्थिति में सरकार जनता में अनिवार्य ऋण ले सकती है। वास्तव में अनिवार्य ऋण का नावजनिक ऋण कहना उचित नहीं है क्योंकि उसमें करारोपण का अंश आ जाता है।

कोषित तथा अकोषित ऋण।

कोषित ऋण (Funded Debt) को निश्चितकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण भी कहा जाता है। इस प्रकार के ऋण का भुगतान निश्चित काल के पश्चात् होता है तथा उन शर्तों के अनुसार होता है जो ऋण लेने समय सरकार के द्वारा घोषित की जाती हैं। कोषित ऋण प्रायः दीर्घकालीन ऋण होते हैं और इनके भुगतान के लिये सरकार ऋण लेते समय एक अलग कोष स्थापित कर देती है जिसमें प्रति वर्ष किसी माधन की आय जमा होती रहती है। कोष बना देने से ऋण का भुगतान सुविषयपूर्वक हो जाता है। इस प्रकार का ऋण अतना दीर्घकालीन तथा स्थायी होता है कि सरकार को उसके भूलभन को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती और वह केवल ऋण पर व्याज चुकाने की जिम्मेदारी लेती है। इंग्लैंड के कंसोल (Consol) इसी प्रकार के ऋण का उदाहरण है। रेल, नहरें तथा अन्य उत्पादक साधनों के निर्माण के लिये सरकार इसी प्रकार के ऋणों के द्वारा रकबा प्राप्त करती है।

इसके विपरीत आकोषित ऋण (Unfunded Debt) अल्पकालीन होता है। इस प्रकार के ऋण अपेक्षाकृत थोड़े समय में चुका दिये जाते हैं और इनका भुगतान के लिये सरकार किसी प्रकार के कोष का निर्माण नहीं करती। ऋण पर व्याज सरकार अपनी सामान्य आय में से देती है तथा समय आने पर इन ऋणों के मूलधन का भुगतान अन्य ऋणों से प्राप्त आय के द्वारा कर दिया जाता है। इसलिये कभी-कभी इन्हें चालू ऋण (Floating Debt) भी कहा जाता है। भारतवर्ष में अरोषित ऋण (Unfunded Debt) तथा चालू ऋण (Floating Debt) में भेद किया जाता है। चालू ऋण प्रायः उस ऋण को कहा जाता है जो कम अवधि के लिये लिया जाय तथा जिसका भुगतान एक साल के भीतर कर दिया जाय। भारतीय सरकार के ट्रेजरी बिल्ल (Treasury Bills) जिनकी अवधि तीन माह होती है तथा रिजर्व बैंक में ली जाने वाली काम चलाऊ पेदागी (Ways and Means Advance) इस प्रकार के ऋणों का उदाहरण हैं।

आन्तरिक तथा विदेशी ऋण

साधजनिक ऋण आन्तरिक तथा विदेशी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि ऋण कहाँ से लिया गया है। सरकार का द्वारा अपने देश के मुद्रा बाजार में लिया जाना वाला ऋण आन्तरिक ऋण कहलाता है। यह ऋण सरकार अपने देश में रहने वाले लोगों से लेती है। जब सरकार किसी अन्य देश की सरकार या दूसरे देश में रहने वाले लोगों से ऋण लेती है तो वह विदेशी ऋण कहलाता है। विदेशी ऋण प्रायः तब लिये जाते हैं जब आन्तरिक ऋण में प्राप्त रकम अपर्याप्त होती है। आन्तरिक ऋण में अपने देश की मुद्रा प्राप्त होती है तथा उसका भुगतान भी देश की मुद्रा में ही किया जाता है। किन्तु विदेशी ऋण में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और उसका भुगतान करते समय देश के विदेशी विनिमय साधनों पर भार पड़ता है। आन्तरिक ऋण तथा उसका व्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप देश के भीतर ही राष्ट्रीय आय का पुनः वितरण होता है किन्तु विदेशी ऋणों के भुगतान में धन निश्चित रूप में दूसरे देशों को हस्तांतरित हो जाता है। इसलिये आन्तरिक ऋण की अपेक्षा विदेशी ऋण अधिक खतरनाक होता है और उसका खेना अच्छा नहीं माना जाता।

उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण :

ऋण लेने के उद्देश्य के आधार पर सार्वजनिक ऋणों को उत्पादक (Productive) तथा अनुत्पादक (Unproductive) वर्गों में बाँटा जा सकता है। उत्पादक कार्यों में लगाने के उद्देश्य से जो ऋण लिया जाता है उसे उत्पादक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में लगने वाला ऋण प्रायः इसी प्रकार का होता है। उत्पादक ऋण का प्रयोग कारखानों की स्थापना, नहर, रेलों, सड़कों आदि के निर्माण तथा अन्य प्रकार की उत्पादक योजनाओं के निर्माण के लिये किया जाता है। इसके विपरीत अनुत्पादक ऋण वह ऋण होता है जिसके पीछे आमदनी देन

वाला कोई साधन नहीं होता । अनुत्पादक कार्यों के लिये लिया जाने वाला ऋण इसी प्रकार का होता है । उदाहरणार्थ लड़ाई के लिये लिया जाने वाला ऋण अनुत्पादक ऋण है क्योंकि उसके परिणामस्वरूप देश की उत्पादन शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती ।

ऐच्छिक ऋण तथा अनिवार्य ऋण :

ऐच्छिक ऋण वह होता है जिसमें लोग स्वयं अपनी इच्छा से देते हैं और इसके लिए उन पर किसी प्रकार का सरकारी दबाव नहीं डाला जाता । सरकार के द्वारा किये जाने वाले अधिकांश ऋण ऐच्छिक ही होते हैं क्योंकि उनमें स्वयं देने के लिये सरकार किसी को बाध्य नहीं करती । इन ऋणों पर सरकार निश्चित दर से व्याज देती है और जो चाह उसमें स्वयं दे सकता है । कभी-कभी जनता की इच्छा क विरुद्ध भी सरकार उनमें ऋण ले सकती है । इस प्रकार के ऋण को अनिवार्य ऋण कहा जाता है । प्राचीन काल में इस प्रकार के ऋणों के काफी उदाहरण मिलते हैं । वर्तमान समय में सरकार ऐच्छिक ऋणों के द्वारा ही धन प्राप्त करती है किन्तु आपत्ति-काल में वह लोगों से अनिवार्य रूप से ऋण ले सकती है । द्वितीय महायुद्ध में भारत सरकार ने अविरक्त लाभ प्राप्त करने वालों से मुद्रा कोष में अनिवार्य रूप से स्वयं जमा कराया था जिसका भुगतान कुछ समय के पश्चात् कर दिया गया था । इस प्रकार के ऋण को अनिवार्य ऋण कहा जा सकता है ।

सार्वजनिक ऋण से लाभ .

वर्तमान समय में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में भारी वृद्धि तथा उनका प्रचलन इस बात का प्रमाण है कि वे एक शिक्षित तथा प्रगतिशील समाज के लिये आवश्यक हैं और यदि उन्हें निश्चित सीमाओं के भीतर रक्खा जायें तो उनसे समाज को काफी लाभ मिल सकता है । सार्वजनिक ऋण से प्राप्त होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं—

(१) लोक ऋण सरकार को आकस्मिक संकट से बाहर निकालने में सहायता देता है । कभी-कभी सरकार पर ऐसे आकस्मिक व्यय आ जाते हैं जिनके लिये अन्य साधनों में रुपये की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होता । ऐसी स्थिति में लोक ऋण ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा सरकार धन प्राप्त करके आकस्मिक खर्चों को पूरा करती है । आम तथा व्यय के अस्थायी घाटे को दूर करने के लिये भी सरकार को ऋणों का सहारा लेना पड़ता है । कर इकट्ठा करने में कुछ समय लगता है किन्तु सरकार को व्यय तुरन्त करना होता है । इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिये सरकार केन्द्रीय बैंक अथवा जनता से अल्पकालीन ऋण ले लेती है और वरों का स्वयं देने पर उसे वापस लौटा दिया जाता है ।

(२) लोक ऋण की सहायता से सरकार सार्वजनिक निर्माण के काम कर सकती है । रेलों, नहरों तथा अन्य प्रकार की उत्पादक योजनाओं की केवल दीर्घकालीन

ऋणों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सार्वजनिक ऋण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। यद्यपि लोक ऋण से देश में पूँजी की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है किन्तु वह पूँजी को कार्यशील करने में सहायता देता है तथा उसे अधिक उत्पादक बनाता। लोक ऋण की सहायता में देश के आर्थिक साधनों का विकास किया जा सकता है। सभी अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिये सार्वजनिक ऋणों का प्रयोग काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है जिसमें इन देशों की राष्ट्रीय आय तथा लोगों के जीवन-स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

(३) लोक ऋण जनता के लिये विनियोग का एक सुरक्षित साधन प्रस्तुत करता है। जो लोग सार्वजनिक ऋण में रकमा लगाते हैं उनका विनियोग सुरक्षित होता है तथा उस पर एक निश्चित दर से व्याज मिलता है। सरकारी प्रतिभूतियों में लगे हुये रुपये को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिभूतियों में लगे हुये रुपये को कभी भी निकाला जा सकता है क्योंकि इनकी मांग बाजार में हर समय रहती है। इस प्रकार के विनियोग में तरलता, सुरक्षा तथा उत्पादनशीलता सभी गुण पाये जाते हैं। शिराज (Shirras) के शब्दों में 'लोक ऋण एक सुविधापूर्ण विनियोग प्रदान करता है'।¹

(४) सार्वजनिक ऋणों से बैंकों का विकास होता है जो देश के औद्योगीकरण में बड़ी सहायता देते हैं। बैंक अपनी जमा का बहुत बड़ा भाग सरकारी ऋणों में लगाये रहते हैं। उनकी सम्पत्ति का सबसे तरल रूप सरकारी प्रतिभूतियों को माना जाता है।

(५) सार्वजनिक ऋण देश को संकटकालीन स्थिति से बाहर निकालने में सहायता देता है। युद्ध, प्राकृतिक घटनाएँ तथा अन्य प्रकार की संकटकालीन स्थिति का सामना सामान्य आय के साधनों से नहीं किया जा सकता। ऐसे अवसर पर सरकार सार्वजनिक ऋण के द्वारा अतिरिक्त आय प्राप्त करती है और उससे संकटकालीन व्यय को पूरा किया जाता है। विशेषकर युद्धकालीन व्यय का अधिकांश सार्वजनिक ऋणों के द्वारा ही पूरा किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण की हानियाँ :

सार्वजनिक ऋणों का अत्यधिक प्रयोग कुछ खतरे भी उत्पन्न कर सकता है जिनसे प्रत्येक देश की सरकार को सावधान रहना चाहिये। इस प्रकार के ऋणों से उत्पन्न होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) सरकार जनता से आसानी के साथ रकमा उधार ले सकती है जिसके कारण अनुपयुक्त उद्देश्यों के लिये ऋण लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उत्पादक कार्यों के लिये ऋण लेना तो समाज के हित में होता किन्तु यदि अनुत्पादक कार्यों के लिये

1 'A public debt affords a convenient form of investment.'

ऋण लिया जाता है तो उसका भार लोगों को सहन करना पड़ता है किन्तु उससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता। युद्ध तथा सस्त्रीकरण पर किया जाने वाला खर्च एक प्रकार का अपव्यय है जिससे समाज की उत्पादन शक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार के नामों के लिये उधार लेते समय सरकार को समय से काम लेना चाहिये।

(२) सार्वजनिक ऋण सरकारों को अभिव्ययी बनाता है। इन ऋणों के आधार पर अधिक व्यय वाली योजनाएँ, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान लगाये बिना आरम्भ कर दी जाती हैं जिसका देश की वित्त-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जनता पर ऋणों का भार बढ़ता जाता है जब कि देश के आर्थिक विकास में इन योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होता है।

(३) तेजी से साथ बढ़ते हुए सार्वजनिक ऋण सरकार की आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। प्रत्येक ऋण के साथ सरकार को उस पर दिये जाने वाले व्याज तथा मूलधन के भुगतान का भार सहन करना पड़ता है जिसके कारण सरकार करो के द्वारा अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहती है और जनता पर करो का भार बढ़ता चल जाता है। जब मूद्रा का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो सरकार सस्ती मुद्रा नीति (Cheap money policy) को अपनाने के लिये मजबूर हो जाती है जिससे देश में आर्थिक प्रस्थिरता पैदा होती है तथा सरकार की वित्तीय दशा खराब होती चली जाती है।

(४) विदेशी ऋण कभी-कभी देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिये खतरा उत्पन्न कर देते हैं। प्रायः विदेशी ऋणों के साथ कुछ राजनैतिक उद्देश्य लगे होते हैं जो देश में राजनैतिक प्रस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। यदि विदेशी ऋण की मात्रा बहुत अधिक होती है तो अपने ऋणदाताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिये विदेशी सरकार देश की नीति में हस्तक्षेप करने लगती है। विदेशी ऋण देश के साधनों का विदेशियों के हित में खोपण कराते हैं।

(५) विदेशी ऋणों का एक और बुरा पक्ष यह भी है कि उनके कारण धन निरन्तर देश से बाहर जाने लगता है। इन ऋणों के व्याज तथा मूलधन का भुगतान करने के लिए धन हमारे देशों को हस्तान्तरित करना पड़ता है जिसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी तो पुराने ऋणों का व्याज तथा उनके मूलधन की किस्तों का भुगतान करने के लिये देश को नये ऋण लेने पड़ते हैं।

सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो सके सरकार को करो के द्वारा आमदनी प्राप्त करनी चाहिये और ऋण तभी लेना चाहिये जब कि ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो। कर अपने पीछे व्याज अथवा मूलधन के भुगतान का कोई भार नहीं छोड़ता, इसलिये सरकार के लिये करो से आमदनी प्राप्त करना अधिक उपयुक्त है। ऋणों की आवश्यकता तब होती है जब करो से अधिकतम आय प्राप्त करने के पश्चात् भी सरकार की आय तथा व्यय में

घाटा रह जाए। इस कमी को ऋणों के द्वारा भ्रष्टाचार मुद्रा प्रसार की सहायता से पूरा किया जा सकता है।

सार्वजनिक ऋण का भार :

सार्वजनिक ऋण का भार दो प्रकार का होता है—(i) प्रत्यक्ष भार (Direct burden) तथा (ii) परोक्ष भार (Indirect burden)। यह भार मौद्रिक (Monetary) तथा वास्तविक (Real) हो सकता है। ऋण का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उस रकम के बराबर होता है जो मूलधन तथा मूद के भुगतान के रूप में दी जाती है। प्रत्यक्ष वास्तविक भार आर्थिक कल्याण के उस नुकसान को बताता है जो ऋण का भुगतान करने के कारण उस सार्वजनिक व्यय में होने वाली कमी को बताता है जिससे उत्पादन को लाभ हुआ होता।

उत्पादन कार्यों में लगाये गये सार्वजनिक ऋण का समाज के ऊपर कोई भार नहीं होता क्योंकि उसके पीछे आय के व्यय होते हैं जिनके द्वारा ऋण तथा मूद दोनों का भुगतान हो जाता है। इस प्रकार के ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज का भुगतान उस सम्पत्ति की आय से हो जाता है और कर दाता पर उसका कोई भार नहीं पड़ता। इसके विपरीत अनुत्पादक ऋणों के मूद तथा मूलधन की किस्तों के भुगतान का भार ऋणदाताओं पर पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों के भार का अनुमान लगाने के लिये विदेशी (External) तथा आन्तरिक (Internal) ऋण का अध्ययन अलग-अलग किया जाना चाहिये।

विदेशी ऋण :

विदेशी ऋण का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार (Direct money burden) उस रकम के बराबर होता है जो विदेशी ऋणदाताओं को मूद तथा मूलधन के रूप में भुगतान की जाती है। समस्त विदेशी भुगतानों को वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में ही किया जा सकता है इसलिये विदेशी ऋणों का भुगतान करने से देश का आर्थिक कल्याण उस सीमा तक कम हो जाता है जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात ऋण के भुगतान के लिये करना पड़ता है। विदेशी ऋणों के भुगतान के कारण देश के आर्थिक कल्याण में जितनी हानि होती है, उसे इन ऋणों का प्रत्यक्ष वास्तविक भार कहा जायगा। ऋण के वास्तविक भार की मात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि ऋण का भुगतान करने के लिये समाज के विभिन्न सदस्यों को किस अनुपात में कर देने पड़ते हैं। यदि ऋण के भुगतान के लिये लगाये जाने वाले करों का अधिकांश प्रमीरों से आता है तो ऋण का वास्तविक भार कम होगा। इसके विपरीत यदि गरीब लोगों पर कर लगा कर इसे प्राप्त किया जाता है तो समाज पर ऋण का वास्तविक भार अधिक होगा।

विदेशी ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (Indirect Real Burden) भी होता है क्योंकि ऋण के भुगतान के लिये ऋणी देश की सरकार को अपनी आय में

वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण (i) देश में करो की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जिसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (ii) सरकार को अपना सार्वजनिक सामाजिक व्यय कम करना पड़ता है जो दीर्घकाल में देश की उत्पादन क्षमता को कम करता है। अतः विदेशी ऋणों का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार उनके उत्पादन को कम करने के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। किसी विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिये अतिरिक्त आय प्राप्त किये जाने के कारण देश के उत्पादन में जो कमी होती है वही उस ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार होता है। विदेशी ऋण का अप्रत्यक्ष भार आन्तरिक ऋण के भार के समान ही होता है। कभी-कभी कहा जाता है कि विदेशी ऋण उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है किन्तु यह विचार गलत है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का भुगतान करने की आवश्यकता निर्धारित उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकती है और उनमें रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। किन्तु इससे ऋणी देश का कुल उत्पादन बढ़ता है, यह बात सन्देह-पूर्ण है क्योंकि कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने का परिणाम यह होता है कि अन्य उद्योगों से साधन हटाकर इन उद्योगों में लगा दिये जाते हैं जिससे समाज को बहुत हानि पहुँचती है। वास्तव में विदेशी ऋण का अन्तिम परिणाम ऋणी देश के उत्पादन को कम करने का होता है, बढ़ाने का नहीं।

आन्तरिक ऋण :

आन्तरिक ऋण की प्रकृति विदेशी ऋण से बिल्कुल भिन्न होती है। यहाँ पर सम्बन्ध ऋणी देश तथा विदेशी ऋणदाताओं जैसा नहीं होता बल्कि वह एक ही देश में रहने वाले ऋणी तथा ऋणदाताओं के बीच का सम्बन्ध होता है। आन्तरिक ऋण के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में ही धन का हस्तान्तरण होता है और धन देश के बाहर नहीं जाता। इसलिये कभी-कभी यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक ऋण का कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता और न उससे कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ ही होता है। इस प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में किये जाने वाले विभिन्न भुगतान आपस में एक दूसरे के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं। आन्तरिक ऋण के कारण देश के भीतर धन का कई बार हस्तान्तरण होता है। जब ऋण लिया जाता है तो उसके कारण रुपया ऋणदाताओं से सरकार के पास जाता है तथा सरकार से ठेकेदारों तथा उन लोगों के पास जाता है जिनसे सरकार वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदती है। इस प्रकार रुपया समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को हस्तान्तरित होता है। यदि धन के इन हस्तान्तरणों के कारण समाज में धन के वितरण की असमानताएँ कम होती हैं अर्थात् रुपया गरीब लोगों में गरीबों के पास जाता है तो इस प्रकार के सार्वजनिक ऋण को लाभपूर्ण कहा जाएगा किन्तु यदि उसका परिणाम धनी लोगों को और अधिक धनी करने का होता है तथा गरीब लोगों की आय उसके कारण कम होती है तो इस प्रकार के ऋण भारस्वरूप होते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है क्योंकि ऋणों पर व्याज का भुगतान करने के लिये सरकार अधिक कर लगाती है तथा यह कर

अमीर व गरीब दोनों प्रकार के लोग देते हैं। सरकार के ऋणदाता प्रायः अमीर लोग होते हैं और इस प्रकार धन गरीबों से अमीरों के पास चला जाता है।

इसके अतिरिक्त आन्तरिक ऋण का प्रभाव बूढ़े तथा निष्क्रिय लोगों की आमदनी को बढ़ाने का होता है तथा वह युवकों व सक्रिय लोगों की आमदनी को कम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारी ऋण पात्रों के अधिकांश मालिक अधिक आयु के होते हैं। वृद्ध लोगों के पास ये धन का इस प्रकार का हस्तान्तरण उत्पादन तथा वितरण दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालता है। यह आन्तरिक ऋणों का एक बड़ा दोष है।

आन्तरिक ऋण का अप्रत्यक्ष भार भी होता है जो उनके उत्पत्ति को कम करने के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। ऋणों का भुगतान करने के लिये जो अतिरिक्त कर लगाये जाते हैं, वे कर-दाताओं की काम करने की क्षमता तथा काम करने व बचत करने की इच्छा को कम करके उत्पादन को घटा सकते हैं, उत्पादन की मात्रा में होने वाली इस प्रकार की कमी ऋण के अप्रत्यक्ष भार को बतलाती है। आन्तरिक ऋणों के कारण ऋणदाताओं की काम करने की इच्छा तथा शक्ति में कुछ वृद्धि हो सकती है किन्तु उनके कारण कर-दाताओं को होने वाली हानि बहुत होती है। इस प्रकार केवल उत्पादक ऋणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ऋण भार पूर्ण होते हैं। आन्तरिक विकास के लिये सरकार के द्वारा आन्तरिक ऋणों का लेना उचित है क्योंकि इस प्रकार के ऋण उत्पादक आदेय (Assets) पैदा करते हैं जिनकी आमदनी से ऋण व उनके मूद का भुगतान हो जाता है। किन्तु निर्माण के कामों के लिये भी सरकार को अधिक मात्रा में करो पर निर्भर रहना चाहिये जिससे कि ऋण-दाताओं को बिना परिश्रम की आय प्राप्त करने का मौका न मिल सके।

सार्वजनिक ऋणों के आर्थिक परिणाम :

सार्वजनिक ऋणों के लेने तथा उनका भुगतान करने की क्रियाएँ देश में धन के उत्पादन तथा वितरण को प्रभावित करती हैं। यद्यपि लोक ऋण के आर्थिक परिणामों को सही-सही निश्चित करना सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी उस के सामान्य आर्थिक प्रभावों की विवेचना की जा सकती है। सरकार के द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के आर्थिक प्रभाव कई बातों पर निर्भर करते हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—(i) ऋण की मात्रा (ii) ऋण लेने का उद्देश्य (iii) ऋण की स्वरूप (iv) ऋण चुकाने की शक्ति।

लोक ऋण का समाज के आर्थिक जीवन पर कौंसा प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर है कि ऋण कितनी मात्रा में लिया गया है। थोड़ी मात्रा में लिया गया ऋण समाज की उत्पादन व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता। छोटे ऋण के लिये हमारा लोग अपने अतिरिक्त धन में से दे सकते हैं जिसके कारण विनियोग की जाने वाली पूँजी की मात्रा में कोई कमी नहीं होती। किन्तु यदि

ऋण बड़ी मात्रा में लिया जाता है तो उसका निश्चित प्रभाव पूँजी को अन्य प्रकार के विनियोगों से हटाने का होता है। लोग रुपये को व्यवसायों से हटाकर सरकारी ऋण में लगा देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति का परिणाम उत्पादन को कम करने का होता है। राष्ट्रीय आय कम हो जाती है तथा बेरोजगारी फैलती है। ऋण का भुगतान करने प्रपचा उम पर व्याज देने के लिये सरकार जो अतिरिक्त कर लगाती है इसका लोगो की काम करने की इच्छा व शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उत्पादन में कमी होती है।

यदि ऋण कम व्याज की दर पर लिये जाते हैं तो उनका प्रभाव अधिक बुरा नहीं होता किन्तु यदि अधिक मात्रा में ऊँची व्याज की दर पर ऋण लिया जाता है जो उसका समाज की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्याज की दर ऊँची होने के कारण सरकार की आय का एक बहुत बड़ा भाग व्याज के भुगतान में लग जाता है और सरकार को या तो अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं या मुद्रा प्रसार की नीति को अपनाना होता है। दोनों का ही देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋणों को लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बहुत ऊँची दर पर अधिक ऋण न लिये जायें।

लोक ऋण के आर्थिक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर हैं कि ऋण किस उद्देश्य के लिये लिया गया है। उत्पादक कार्यों के लिये लिया गया ऋण समाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है इसलिये वह आर्थिक दृष्टि से लाभपूर्ण कहा जा सकता है। यदि ऋण का व्यय अनुत्पादक मद्दे पर किया जाता है तो वह ऋण समाज के लिये मृतक भार के समान हो जाता है। करो से होने वाली आय को अनुत्पादक कार्यों पर व्यय करने से उतनी हानि नहीं होती जितनी कि ऋण को अनुत्पादक कामों में लगाने से होती है क्योंकि करो पर कोई व्याज नहीं देना होता किन्तु ऋणों पर निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है।

ऋण का भुगतान कम और किस प्रकार किया जाता है, इस बात पर भी ऋण के आर्थिक प्रभाव निर्भर होते हैं। समृद्धि काल ऋणों को चुकाने के लिये अच्छा समय समझा जाता है क्योंकि उस समय कीमतें ऊँची होने के कारण ऋण का भार कम हो जाता है और उसका भुगतान आयानी के साथ किया जा सकता है। इसके विपरीत मंदी का काल ऋणों के भुगतान के लिये उपयुक्त समय नहीं होता क्योंकि उस समय कीमतें कम होने के कारण ऋण का भार बढ़ जाता है।

सार्वजनिक ऋणों का प्रभाव धन के वितरण पर भी पड़ता है जब ऋण लिया जाता है तो धन कुछ लोगो के पास में निकलकर उन लोगो के पास चला जाता है। सरकार जब ऋण का प्रयोग करती है तो वहीं धन सरकार से निकलकर उन लोगों के पास चला जाता है जिनसे सरकार वस्तुयें तथा सेवायें खरीदती है। इस प्रकार के भुगतानों के परिणाम-स्वरूप इन लोगो की आयदनी बढ़ जाती है। ऋण पर व्याज देने के कारण ऋण-दाताओं की आयदनी बढ़ती है। इस भुगतान के लिये यदि सरकार अधिक कर लगाने से तो कर-दाताओं की आयदनी उभी सीमा तक कम हो जाती है। जब

ऋण का भुगतान किया जाता है तो धन सरकार से निकल कर उन लोगों के पास चला जाता है जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया हुआ है। इस प्रकार लोक ऋणों के कारण समाज में धन के वितरण में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। यदि सार्वजनिक ऋण का कुल प्रभाव धन के वितरण को निर्धन व्यक्तियों के पक्ष में करने का होता है तो इस प्रकार के ऋण को सामाजिक दृष्टि से अच्छा समझा जायगा। इसके विपरीत यदि ऋण का परिणाम वितरण की असमानताओं को बढ़ाने का होता है तो उस ऋण को किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता।

ऋण को चुकाना अथवा उसके भार को कम करना

सरकार के द्वारा जो भी ऋण लिये जाते हैं, चाहे वे आन्तरिक हो अथवा विदेशी, उनका भुगतान सरकार को करना होता है। यदि कोई सरकार अपने ऋणों का भुगतान नहीं करती है तो उसे भविष्य में ऋण प्राप्त नहीं हो सकेंगे। प्रत्येक सरकार अपनी साख को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक ऋणों का ठीक समय पर भुगतान करने का प्रयत्न करती है। यदि यह किसी कारण से ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह इन ऋणों के भार को कम करने का उपाय करती है। ऋणों के भार को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय उनका भुगतान कर देना है। ऐसा करना न्यायपूर्ण भी है और वह सरकार की साख को भी बनाए रखता है जिससे कि सरकार को भविष्य में आमानी से ऋण प्राप्त होते रहते हैं।

ऋण चुकाने से इंकार करना :

ऋण के भार को समाप्त करने का एक अन्य तरीका यह भी है कि सरकार ऋण चुकाने से इंकार कर दे। यद्यपि ऐसा करना बहुत आसान है क्योंकि सरकार को ऋण चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किन्तु इस प्रकार की नीति के बहुत बुरे प्रभाव हो सकते हैं। यदि आन्तरिक ऋण को चुकाने से सरकार इंकार करती है तो जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाता है और सरकार भविष्य में सफलतापूर्वक ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगी। ऐसा करना न्याय की दृष्टि से भी उचित नहीं है क्योंकि इसके कारण उन लोगों के साथ भेद-भाव होता है जिन्होंने अपनी वचत को उस ऋण में लगाया हुआ है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग अपनी सम्पूर्ण वचत खो बैठते हैं जबकि अन्य लोगों को कुछ भी नहीं देना पड़ता। ऋण का भुगतान न करने की नीति को अपना कर सरकार अपने को अस्तिता में डाल सकती है, क्योंकि उसके कारण भारी सामाजिक असंतोष फैलने का डर रहता है। यदि विदेशी ऋणों को चुकाने से इंकार किया जाता है तो इसके और भी भयंकर परिणाम होते हैं। ऐसा करने से देश के सम्मान को बड़ी हानि पहुँचती है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप ऋण देने वाले देश सड़ाई करने के लिये भी तैयार हो सकते हैं। इन्हीं सब खतरों के कारण कोई भी सरकार अपने ऋणों का भुगतान करने से इंकार

नहीं करती । वह पुराने ऋणों को नये ऋणों में बदल सकती है, ऋणों को कम कर सकती है, ऋणों का व्याज घटा सकती है अथवा उनके भुगतान की दीर्घवालीन व्यवस्था कर सकती है किन्तु उन्हें चुकाने से सामान्तया इंकार नहीं करती । असामान्य परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है । सन् १९१८ में रूस की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया तथा प्रथम युद्ध से पूर्व जर्मन सरकार ने भी अपने ऋणों को चुकाने से इंकार कर दिया था ।

ऋणों को मध्पूर्ण रूप से चुकाना सरकार के लिये काफी कठिन होता है । विशेषकर वर्तमान समय में जब सरकार का उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसे जनता की भलाई के लिये अधिकाधिक व्यय करना पड़ता है, यह आशा करना व्यर्थ है कि कोई भी सरकार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग ऋणों के चुकाने के लिए व्यय करती रहे । ऋण चुकाने का एक ही तरीका है कि सरकार अपनी आय से कम व्यय करे तथा बजट में होने वाली इस बचत का प्रयोग ऋणों को चुकाने में किया जाय । ऐसा करना प्रायः संभव नहीं होता । निरन्तर बढ़ते हुये व्यय के कारण वर्तमान सरकारों के बजट प्रायः घाटे के बजट होते हैं और ऐसी दशा में उनसे ऋणों के अतिरिक्त भुगतान की आशा नहीं की जा सकती । यदि सरकार ऐसा करने का प्रयत्न भी करती है तो उसे अपना व्यय काफी मात्रा में कम करना होगा जिससे देश में बेरोजगारी फैल सकती है तथा विकास की गति धीमी हो जाती है । इसलिए अधिकांश सरकारें सार्वजनिक ऋण के भार को समाप्त करने की अपेक्षा उसके भार को कम करने का प्रयत्न करती हैं ।

ऋण चुकाने की रीतियाँ :

सार्वजनिक ऋणों को चुकाने अथवा उनके भार को कम करने के लिये निम्नलिखित तरीके काय में लाये जा सकते हैं —

(१) बजट की वृद्धि का प्रयोग (Utilisation of budget Surplus)—सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने के लिये बजट की वृद्धि का प्रयोग किया जा सकता है । सरकार अपने ऋणों का भुगतान अपने व्यय को कम करके तथा बजट में वृद्धि उत्पन्न करके ही कर सकती है । यदि किसी भी वर्ष सरकारी बजट में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि का प्रयोग ऋणों को चुकाने के लिये किया जाना चाहिये । किन्तु वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं होता । प्रथम तो सरकारी बजट में वृद्धि होती ही नहीं है और यदि कभी होती भी है तो उसका प्रयोग अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिये कर लिया जाता है । इसलिए बजट की वृद्धि का प्रयोग ऋणों का भुगतान करने के लिए बहुत कम किया जाता है ।

(२) ऋण-परिशोध कोष (Sinking Fund)—ऋण-परिशोधन की यह पद्धति सबसे अधिक प्रचलित रही है । सर्वप्रथम इसका विकास इंग्लैंड में हुआ और उसके पश्चात् इस रीति को अन्य देशों में भी अपना लिया गया । ऋण-परिशोध कोष का निर्माण करना ऋण चुकाने की सबसे अच्छी पद्धति समझी जाती है ।

सरकार ऋण चुकाने के लिए एक अलग कोष का निर्माण कर देती है जिसमें प्रति वर्ष एक निश्चित रकम सरकारी आय में से जमा होती रहती है। इस कोष का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इसमें जमा रकम की सहायता से ऋण का मूलधन तथा व्याज दोनों चुकता किये जा सकें। कोष में इतना रखा प्रति वर्ष जमा किया जाता है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात् उसमें इतनी रकम जमा हो जाती है कि उससे ऋण तथा व्याज की पूरी रकम चुकाई जा सकती है। यह कोष प्रायः सरकार की करो से प्राप्त आय में से बनाया जाता है किन्तु कभी-कभी ऋण लेकर भी इस प्रकार के कोष का निर्माण कर दिया जाता है। नया ऋण लेकर निर्मित कोष को परिशोध-कोष कहना ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार केवल पुराने ऋण को नए ऋण में बदल दिया जाता है।

परिशोध-कोष भी दो प्रकार के हो सकते हैं—(i) निश्चित (Definite) तथा (ii) अनिश्चित (Indefinite)। यदि कोष में रकम जमा करने की एक निश्चित व्यवस्था की जाती है तो इस प्रकार के कोष को निश्चित कोष कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में सरकार की करो से होने वाली आमदनी में से एक निश्चित रकम परिशोध कोष में जमा होती रहती है। ऋण की अवधि समाप्त होने तक इस कोष में इतनी रकम जमा हो जाती है कि उससे ऋण तथा उसके व्याज का भुगतान किया जा सकता है। इसके विपरीत अनिश्चित कोष वह होता है जिसमें निश्चित रूप से रकम जमा करने की व्यवस्था नहीं की जाती और कोष में जमा होने वाली रकम इस बात पर निर्भर होती है कि किसी वर्ष में सरकार की आमदनी का कितना अतिरिक्त रहता है। इस प्रकार कोष में जमा होने वाली रकम प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

निश्चित परिशोध कोष का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है—(क) ऋण के भुगतान की अवधि (ख) इस समय में परिशोध कोष के भुगतानों का वितरण (ग) विभिन्न प्रकार के ऋणों के भुगतान के लिये कोष का प्रयोग। ऋण चुकाने के लिये कितना समय दिया जाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि ऋण को चुकता करने का समय कम से कम होना चाहिये। उत्पादक ऋणों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त होना चाहिए कि ऋण का भुगतान उतनी अवधि में जरूर हो जाय जितने समय में उसके द्वारा निर्मित पूंजीगत वस्तुओं का क्षय होता है। किन्तु अनुत्पादक ऋणों के सम्बन्ध में भुगतान की अवधि काफी कम होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के ऋणों के पीछे किसी प्रकार के आदेय (Assets) नहीं होते हैं।

परिशोध कोष के भुगतान का क्या ढंग होना चाहिये, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की तीन विधियों को अपनाया जा सकता है—(i) बढ़ते हुए वार्षिक भुगतान (ii) निश्चित भुगतान तथा (iii) घटते हुए

वाषिक भुगतान। इन तीनों में अन्तिम पद्धति को सबसे अच्छा समझा जाता है क्योंकि वह राजनैतिक दृष्टि से अधिक स्थिर हो सकती है। सभी प्रकार के कोषों पर वित्त-मन्त्रियों की निगाह रहती है और परिशोध कोष भी उनसे नहीं बच पाते। प्रायः ऋण परिशोध कोषों का प्रयोग अन्य कामों के लिए कर लिया जाता है। यदि ऋण प्रतिवर्ष कम होता जाता है तो कोष में जमा होने वाली रकम घटती चली जायगी और परिशोध कोष भी कम होता जायगा जिसके कारण इन कोषों को अन्य प्रयोगों में लगाने की प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है और कोष अपनी निश्चित अवधि तक चलता रहता है।

परिशोध कोष का प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऋणों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। विभिन्न ऋणों की भुगतान अवधि तथा उन पर दिये जाने वाले व्याज की दर अलग-अलग हो सकती है। इस सम्बन्ध में या तो परिशोध कोष को विस्तृत स्वतन्त्र रखा जाता है या उसे किसी विशेष ऋण के भुगतान के लिये निश्चित कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोष का कुछ भाग स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है और कुछ को विशेष ऋण के भुगतान के लिए निश्चित कर दिया जाता है। इस मामले में सरकार स्वतन्त्रता चाहती है। इसलिये प्रायः स्वतन्त्र परिशोध कोष को अधिक पसन्द किया जाता है क्योंकि उसमें सरकार को यह आजादी होती है कि वह कोष की रकम किसी भी ऋण के भुगतान के लिये काम में ला सकती है।

(२) ऋण-रूपान्तरण (Conversion of Public Debts)—ऋण-रूपान्तरण के द्वारा भी सार्वजनिक ऋणों के भार को कम किया जा सकता है। इस रीति से अधिक व्याज वाले ऋण को कम व्याज वाले ऋण में बदल दिया जाता है। सरकार के द्वारा ऋण प्रायः बड़ी हुई कीमतों के जमाने में लिये जाते हैं जब कि व्याज की दर काफी ऊँची होती है। कुछ समय पश्चात् साधारण परिस्थिति आने पर सरकार के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह कम व्याज की दर पर ऋण ले सके। ऐसी दशा में सरकार के हित में यह होना है कि वह अधिक व्याज वाले ऋणों को कम व्याज वाले ऋण में बदल दे। ऐसा करने के लिए सरकार अपने ऋणदाताओं को यह सूचना देती है कि वे या तो ऋण पर व्याज की कम दर को स्वीकार करें और पहले ऋण-पत्रों के बदले में कम व्याज वाले नये ऋण पत्र ले लें अथवा अपना मूल-धन वापस ले लें। यदि नई व्याज की दर वाज्यारी दर से जरा भी ऊँची होती है तो अधिकांश ऋण दाता कम व्याज वाले नये ऋण-पत्रों को लेने के लिए तैयार हो जायेंगे। जो ऋणदाता इस बात के लिये तैयार नहीं होते हैं उनके मूलधन का भुगतान सरकार कम व्याज पर नया ऋण लेकर कर देती है। इस प्रकार पुराने ऋणों को कम व्याज वाले नये ऋणों में बदल दिया जाता है।

ऋणों के इस प्रकार के रूपान्तरण से सरकार तथा ऋणदाताओं को काफी लाभ होता है। व्याज की दर कम हो जाने से सरकार पर ऋण का भार कम हो

जाता है। इससे करदाताओं को भी लाभ होता है क्योंकि उन्हें ऋण पर सूद के भुगतान के लिए कम बर देने पड़ते हैं। रूपान्तरण के द्वारा ऋण पर व्याज कम करना विलकुल न्यायपूर्ण है क्योंकि सरकार ऋणदाताओं को इस बात का पूरा मौका देती है कि या तो वे नये ऋण पर ले लें अथवा अपना मूलधन वापस ले लें।

इन्हीं कारणों से ऋण-रूपान्तरण ऋणों के भार को कम करने का काफी प्रचलित तरीका रहा है। इंग्लैंड, फ्रांस तथा अमेरिका में ऋणों का भार कम करने के लिये इस विधि को प्रायः काम में लाया जाता है। गत वर्षों में भारत सरकार ने भी कुछ ऋणों का रूपान्तरण किया है। किन्तु इस विधि के प्रयोग का क्षेत्र काफी सीमित है। केवल उन्हीं ऋणों का रूपान्तरण करना सम्भव होता है जिनके साथ यह शर्त हो कि सरकार जब चाहे उन्हें लौटा सकती है। अधिकांश ऋणों के साथ इस प्रकार की शर्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त ऋण-रूपान्तरण तभी किया जाता है जबकि ऐसा करने से ऋण के भार में काफी कमी होने की आशा नहीं की जा सकती।

(४) पूँजी कर (Capital Levy)—पूँजी कर ऋणों के भुगतान करने का एक तरीका है। कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है कि कई वर्षों तक कर लगा कर ऋण-शोधन कोष का निर्माण करने की अपेक्षा सरकार को चाहिये कि वह एक बार या दो बार काफी भारी कर लगा कर ऋण का भुगतान कर दे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इस बात का सुझाव रखा गया कि युद्ध काल में सरकार को जो बहुत बड़े-बड़े ऋण लेने पड़े हैं उनका भुगतान करने के लिए पूँजी पर एक विशेष कर लगाया जाना चाहिये। युद्धकालीन ऋण का भुगतान पूँजी कर के द्वारा किया जाय अथवा नहीं इस विषय पर इंग्लैंड में काफी वाद-विवाद रहा है। अधिकांश ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने जो रिकार्डो (Ricardo) के विचारों से सहमत थे, इस बात का समर्थन किया कि युद्ध सम्बन्धी ऋणों का भुगतान पूँजी कर के द्वारा किया जाय। प्रो० पीगू (Pigou) तथा डा० डाल्टन (Dr. Dalton) उनमें प्रमुख थे। बहुत से लोगो ने इसका समर्थन इसलिए भी किया क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में करों की मात्रा में काफी कम हो जाने की सम्भावना थी। जो लोग पूँजी कर के पक्ष में थे उनका कहना था कि (i) इस प्रकार का विशेष कर अनिवार्य है क्योंकि भाव्य वर अकेला युद्ध के ऋणों का भुगतान नहीं कर सकता। (ii) ऐसा करना न्यायपूर्ण भी है क्योंकि इसका अर्थ वृद्ध लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने सम्पत्ति एकत्रित कर ली है। ऐसे लोगो को सैनिक सेवाओं से छूट होती है। अतः युवक सरकार के लिए बढ़ते हैं, तो वृद्ध लोगो को उसका खर्च उठाना चाहिये। (iii) इस पद्धति के द्वारा युद्धकालीन ऋणों का भुगतान जल्दी किया जा सकता है। (iv) ऐसा करने से लोग उन्हें वापिक करों से बच सकेंगे।

इस योजना का काफी विरोध किया गया, विशेषकर सम्पन्न लोगों के द्वारा। पूँजी कर के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये गये। (i) इस प्रकार का विशेष कर

लगाने से उद्योग तथा व्यवसाय पर कर का भार बहुत अधिक हो जायेगा जिसे वह सहन नहीं कर सकेगा। इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तथा वचत की मात्रा भी कम हो सकती है। (ii) इस प्रकार की योजना को कार्य रूप में लाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार के कर की मात्रा को ठीक-ठीक निश्चित करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके प्रतिरिक्त लोग इस प्रकार की योजना का मिलकर विरोध कर सकते हैं। वास्तव में सरकार इस प्रकार के खतरे का मुकाबला कर सकती है क्योंकि विरोध करने वालों की संख्या कम होगी। (iii) पूँजी के संचय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पूँजी कर जैसे भारी कर का भुगतान पूँजी अथवा वचत में से ही किया जा सकता है। (iv) इस प्रकार का कर न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि वह उन लोगों के साथ पक्षपात करता है जो मितव्ययितापूर्ण ढंग से रह कर रुपये की कुछ वचत कर लेते हैं। (v) इस प्रकार के कर के भविष्य में न दोहराये जाने के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था

वर्तमान युद्धों पर सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना होता है। युद्धकालीन व्यय को किस प्रकार पूरा किया जाय, यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। युद्धकालीन अर्थ-प्रबन्ध के द्वारा ही इन साधनों को जुटाया जाता है तथा साधनों को उपभोग से हटा कर लड़ाई के कामों में लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि युद्ध एक अनुत्पादक कार्य है और उससे जहाँ तक सम्भव हो सके बचना चाहिये किन्तु जब एक बार आरम्भ हो जाता है तो फिर उसके समाप्त होने तक उसके लिये धन का प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये। युद्ध सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के तीन प्रमुख साधन हैं—(i) करारोपण, (ii) सार्वजनिक ऋण तथा (iii) मुद्रा-प्रसार। इन तीनों में से किस का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में एक विचार नहीं पाया जाता है। सामान्यतः मुद्रा प्रसार युद्ध व्यय को पूरा करने का अच्छा साधन नहीं माना जाता क्योंकि इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। कर अथवा ऋण, इन दोनों में से युद्ध व्यय के लिये किसका प्रयोग किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद पाया जाता है। रिकार्डो (Ricardo) का विचार था कि युद्ध व्यय को पूर्णतया करारोपण के द्वारा पूरा किया जाना चाहिये और उसके लिये ऋण नहीं लेने चाहियें। इसके विपरीत पियरसन (Pearson) के अनुसार युद्ध व्यय ऋणों के द्वारा पूरा किया जाना चाहिये, करों के द्वारा नहीं। किन्तु अनुभव इस बात को बतलाता है कि युद्ध के लिए करारोपण तथा सार्वजनिक ऋण दोनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। पिछली लड़ाई ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि आधुनिक समय में किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार को ऋण भी लेना पड़ता है और करों में भी वृद्धि करनी पड़ती है।

(i) करारोपण तथा युद्ध :

अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि सरकार को युद्ध व्यय को पूरा करने के लिये अधिक मात्रा में कर लगाने चाहिये। सरकार को सर्वप्रथम करारोपण के द्वारा अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि युद्ध व्यय के अधिकांश को पूरा किया जा सके। इसके लिये सरकार को नये कर लगाने चाहिये तथा पुराने करों की दर में वृद्धि करनी चाहिये। विद्वान् (Whithers) के अनुसार युद्ध काल में करारोपण से एक साथ दो लाभ होते हैं— नागरिक बचत करते हैं और सरकार को आमदनी प्राप्त होती है।* युद्धकालीन व्यय के लिए करारोपण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं :—

(अ) करों में अनावश्यक उपभोग कम हो जाता है—भारी करों के द्वारा लोगों के उपभोग को कम किया जा सकता है। युद्ध काल में वस्तुओं की कमी होने के कारण इस बात की बड़ी आवश्यकता रहती है कि लोग कम से कम खर्च करें जिससे कि मांग के दबाव को कम रखा जा सके। करारोपण इस उद्देश्य की पूर्ति में काफी सहायक होता है। करों के कारण उपभोग भी कम हो जाता है और निर्धन लोगों के जीवन स्तर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार करारोपण केवल सरकार को अधिक आमदनी ही नहीं देता बल्कि वह उपभोग को कम करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है।

(ब) लोगों की देश-भक्ति के कारण युद्ध काल में करों को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। अपने देश की रक्षा के लिए ऐसे सकट काल में लोग काफी अधिक मात्रा में कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकार को इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये और अधिक करों के द्वारा युद्ध व्यय को पूरा करना चाहिये।

(स) करों के द्वारा प्राप्त आम पर सरकार को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता, इसलिये वह अपने पीछे किसी प्रकार का भार नहीं छोड़ते हैं। युद्ध के अनुत्पादक व्यय को पूरा करने के लिये करों के द्वारा आमदनी प्राप्त करना ही अधिक उचित है।

(द) यदि युद्ध के व्यय को करों के द्वारा पूरा कर लिया जाय तो युद्ध के पश्चात् लोग सांख्यिक ऋणों के भुगतान के लिये लगने वाले भारी करों से बच जाते हैं।

(य) करारोपण के द्वारा युद्ध व्यय को पूरा करना न्यायपूर्ण है क्योंकि इस गरीब तथा अमीर दोनों को युद्ध के लिये समान बलिदान करना पड़ता है। गरीब युद्ध में लड़ने हैं और अमीर उनके व्यय को सहन करते हैं।

(र) यदि युद्ध व्यय करारोपण के द्वारा पूरा कर लिया जाता है तो सरकार को मुद्रा-प्रसार की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मूल्य-स्तर में होने वाली वृद्धि काफी कम हो जायेगी तथा देश मुद्रा-प्रसार के भयकर परिणामों से बच जायगा।

* 'Taxation in war time is twice blessed—the citizens economise and govt. gets its revenue'.
—Whithers

यद्यपि करारोपण को युद्ध व्यय पूरा करने का अच्छा साधन माना जाता है किन्तु फिर भी केवल करो से युद्ध के कुल व्यय को पूरा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देश की एक कर देने की क्षमता (Taxable Capacity) होती है जिसमें अधिक कर नहीं लगाये जा सकते। आधुनिक युद्ध में इतना अधिक व्यय करना पड़ता है कि उसे किसी भी प्रकार भरेले करो के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। मेलिंगमैन के अनुसार यदि समाज की तमाम बड़ी-बड़ी आमदनियों को तथा व्यापार के समस्त लाभों को भी सरकार जब्न कर ले, तब भी वह आधुनिक युद्ध का प्राया तब भी पूरा नहीं कर सकेगी। अधिक करारोपण से देश की उत्पादन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक सीमा तक करो में वृद्धि करना समाज के लिये लाभपूर्ण हो सकता है किन्तु इस सीमा के पश्चात् यदि करो को बढ़ाया जाता है तो उसका उत्पादन तथा वचन की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अधिक खर्चीला तथा दीर्घवासीन युद्ध-करो में नहीं चलाया जा सकता है।

(ii) सार्वजनिक ऋण के द्वारा युद्ध-व्यय को पूरा करना

वर्तमान युद्ध-व्यय का काफी बड़ा भाग सार्वजनिक ऋणों की सहायता से पूरा किया जाता है। युद्ध के दैनिक बड़े खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्री तो यह कहते हैं कि युद्ध के समस्त व्यय को ऋणों के द्वारा पूरा करना चाहिये। इसके पक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क दिये जाते हैं - (i) सरकार ऋणों के द्वारा जनता से काफी रूपया प्राप्त कर सकती है क्योंकि ऋणों का रूपया कुछ समय पश्चात् सरकार मूद सहित लौटा देती है। इसके विपरीत करो के रूप में दिया गया रूपया जनता के पास नहीं लौटता। (ii) करो का प्रभाव लोगों के उपभोग को कम करने का होता है किन्तु ऋणों का प्रभाव ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे लोग अपनी बचत में से रूपया जमा करते हैं। इस प्रकार कर ऋणों की अपेक्षा जनता के लिए अधिक कष्टपूर्ण होते हैं। (iii) ऋण का एक अच्छा प्रभाव यह होता है कि युद्ध के बाद मन्दी काल में जब सरकार इन्हें लौटाती है तो उसके कारण उद्योग तथा व्यापार का विकास होता है और अधिक क्रियाशीलता में तेजी आ जाती है।

ऋणों का सरकार के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें सब ऋणों को वापस लौटाना होता है। यदि ऊँची दर पर सरकार बहुत अधिक ऋण ले लेती है तो उसका भार सहन करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऋणों की भी एक सीमा है और उनसे भी असीमित मात्रा में धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। युद्ध काल में सरकार की ऋण-नीति की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि युद्ध को जीतने की संभावना कितनी अधिक है।

(iii) मुद्रा-प्रसार तथा युद्ध-व्यय :

वर्तमान समय में मुद्रा प्रसार को भी युद्ध व्यय पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाने लगा है। पिछले विश्व युद्ध में भारत सरकार ने युद्ध व्यय को पूरा

करने के लिए खुले रूप से मुद्रा-प्रसार का प्रयोग किया जिसके कारण देश की आर्थिक कठिनाइयों में गुजरना पड़ा। मुद्रा-प्रसार युद्ध व्यय को पूरा करने का सबसे अनुचित तरीका है क्योंकि इसके काफी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। युद्ध-काल में आवश्यकता इस बात की होती है कि मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए लोगों के व्यय को कम रखा जाय किन्तु मुद्रा-प्रसार उनकी आय में वृद्धि करके उनके खर्च को बढ़ा देता है जिसके कारण मूल्य-स्तर तेजी के साथ बढ़ने लगता है। मुद्रा प्रसार के कारण सरकार की साख को भी बड़ी हानि पहुँचती है तथा वह विदेशी व्यापार को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है।

आर्थिक विकास के लिये अर्थ-प्रवन्ध

वर्तमान समय में अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये धन जुटाने की एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है। इन देशों को आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग करना है। प्रश्न यह होता है कि क्या युद्ध अर्थ-प्रवन्ध के सिद्धान्तों को आर्थिक विकास के लिए धन प्राप्त करने के लिये काम में लाया जा सकता है? आर्थिक विकास के लिए अर्थ प्रवन्ध करने में करारोपण का महत्वपूर्ण स्थान है। करो से प्राप्त आय को इस सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि इस पर सरकार को कोई व्याज नहीं देना पड़ता है और न यह अपने पीछे किसी प्रकार का भार छोड़ती है। किन्तु अल्प विकसित देशों में निम्न उत्पादन स्तर तथा लोगों की गरीबी के कारण करारोपण से बहुत अधिक आय प्राप्त करना संभव नहीं है। इन देशों में आय-कर, मृत्यु-कर, पूँजी लाभ-कर, अतिरिक्त लाभ-कर आदि प्रत्यक्ष करों की दर को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उसकी वृद्धि तथा विनियोग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अतिरिक्त कर सामान्य जनता पर वस्तु कर के रूप में लगाये जा सकते हैं। भारतवर्ष में आर्थिक विकास के लिए रुपया प्राप्त करने के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार का समर्थन किया जा रहा है।

आर्थिक विकास के अर्थ प्रवन्ध में सार्वजनिक ऋण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके लिये जनता, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। सरकार को अपनी ऋण सन्ध्र धी मीति का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि ग्रामीण जनता की वृद्धि को एकत्रित करके आर्थिक विकास के लिए काम में लाया जा सके। आंतरिक ऋणों के साथ-साथ विदेशी ऋण भी आर्थिक विकास में बड़ी सहायता दे सकते हैं। विदेशी ऋण इसलिए आवश्यक है क्योंकि आन्तरिक ऋण अकेले आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दे सकते। वे इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि उनकी सहायता से विदेशों से पूँजीगत वस्तुएँ तथा तकनीकी जानकारी (Technical Know How) प्राप्त की जा सकती है। युद्ध के लिए प्राप्त किये गये ऋण समाज पर एक मृतक भार के समान हो सकते हैं जबकि आर्थिक विकास के उद्देश्य से लिये जाने वाले

ऋण उत्पादक होते हैं और उनका भुगतान उन आदेयों (Assets) से किया जा सकता है जो उनके द्वारा निर्माण होते हैं।

प्रत्येक आर्थिक विवास की योजना के लिये कुछ मात्रा में घाटे की ग्रंथ-व्यवस्था (Deficit Financing) आवश्यक है। वास्तव में विकासशील ग्रंथ-व्यवस्था में नई मुद्रा का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु आर्थिक विकास के लिए घाटे की ग्रंथ-व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण देश में अधिक मुद्रा प्रसार न हो जाय। यद्यपि आर्थिक विकास के कारण होने वाला मुद्रा प्रसार उतना भयंकर नहीं होना जितना कि युद्धकालीन मुद्रा प्रसार होता है क्योंकि वह स्थय ठीक होने की प्रवृत्ति रखता है किन्तु फिर भी नियमित मुद्रा प्रसार ही विकासशील देशों के लिये लाभपूर्ण हो सकता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि युद्धकालीन ग्रंथ-प्रबन्ध के सिद्धांतों को कुछ संशोधन करके आर्थिक विवास के लिए भी काम में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि युद्धकालीन ग्रंथ-प्रबन्ध उत्पादक होता है और आर्थिक विकास के लिए किया जाने वाला उत्पादक।

परीक्षा-प्रश्न

1. What are the different forms of public debt ? Enumerate the consequences of incurring foreign debt.

(Agra B. A. Pt. II 1955)

सार्वजनिक ऋण कितनी प्रकार के होते हैं ? विदेशी ऋण लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं ?

2. What are the principal methods of debt repayment ? Explain their merits & demerits.

(Madra B. A. 1950)

ऋण चुकाने की मुख्य विधियाँ कौनसी हैं ? उनमें से प्रत्येक के लाभ तथा हानियाँ बतलाइये।

3. What is the place of loans in public finance ? Should a war be financed by loans or taxes ?

(Madras B. A. 1951)

सार्वजनिक वित्त में ऋणों का क्या स्थान है ? सड़ाई के व्यय को पूरा करने के लिये ऋणों का प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा करों का।

4. Examine the merits of capital levy as a method of debt redemption

(Madras B. A. 1954)

ऋण के भार को कम करने में पूँजी कर का क्या महत्व है ?

भारतीय राजस्व का विकास

Evolution of Indian Public Finance

भारतीय राजस्व का अध्ययन करने के लिये यह जानना आवश्यक है कि उसका विकास किस प्रकार हुआ। राजनैतिक जागृति के साथ-साथ भारत के अर्थ-प्रवन्ध में भी परिवर्तन होता गया और धीरे-धीरे उसने विकेन्द्रित अर्थ-प्रवन्ध का रूप धारण कर लिया। आरम्भ काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शासन की विभिन्न इकाइयों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी किन्तु कुछ समय पश्चात् यह अनुभव किया गया कि इस नीति के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में काफी असमानताएँ उत्पन्न हो गई हैं। सन् १८३३ में सरकार ने वित्त का केन्द्रीयकरण करने की नीति को अपनाया और स्थानीय सरकारों के स्वतन्त्र अधिकार छीन लिये गये। सब आय भारत सरकार के नाम में एकत्र तथा खर्च की जाने लगी और प्रान्तीय सरकार केवल धन इकट्ठा करने तथा उसे खर्च करने वाली इकाइयाँ बन गईं। प्रान्तों की समस्त आय केन्द्रीय आय मानी जाती थी और उनके सभी खर्चें केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्वीकृत किये जाते थे। इस केन्द्रीयकरण से केन्द्रीय सरकार तो मजबूत हो गई किन्तु प्रान्तीय सरकारों की हालत खराब होती गई। आय तथा व्यय का सन्तुलन बनाये रखने का कोई उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर नहीं था इसलिए उन्होंने सापरदाही से व्यय करना आरम्भ कर दिया। वे केन्द्रीय सरकार से आवश्यकता से अधिक धन की माग करने लगीं। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक माग का बजट बना कर केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था जिससे कि अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। प्राप्त धन को बड़ी सापरदाही से व्यय किया जाता था और उसमें मितव्ययिता का ध्यान नहीं रखा जाता था। वित्तीय केन्द्रीयकरण की नीति के परिणामस्वरूप प्रान्तीय सरकारों का अपव्यय, अकुशलता तथा परस्पर सभर्ष आदि दोष उत्पन्न हो गये। इन दोषों को दूर करने के लिए विकेन्द्रीयकरण की माग की जाने लगी और १८७१ से इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया गया।

प्रगतिशील विकेन्द्रीयकरण का काल :

सर्वप्रथम सन् १८७१ में लार्ड मेयो (Lord Mayo) ने इस दिशा में पहला कदम उठाया और प्रान्तों को कुछ स्थानीय महत्व के विभाग सौंप दिये गये जिसमें जेल, पुलिस, शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य आदि प्रमुख थे। इन विभागों से होने वाली आय के अतिरिक्त, इनका खर्चा चलााने के लिये प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से

निश्चित रकम अनुदान के रूप में दी जाती थी। प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय कर लगाने का सीमित अधिकार भी दे दिया गया। किन्तु इसमें स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका। प्रान्तीय सरकारों के आय के साधन अप्रामाण्य थे तथा वे मितव्ययितापूर्ण व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते थे। सन् १८७७ में लार्ड लिटन (Lord Lyton) ने प्रान्तों को कुछ और विभागों का उत्तरदायित्व सौंप दिया जैसे उत्पत्ति कर, न्याय आदि। वार्षिक अनुदान के रूप में निश्चित रकम देने की व्यवस्था को जारी रखा गया। सर्वप्रथम आय के साधनों को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच बांट दिया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय आय के तीन मुख्य साधन थे—(१) प्रान्तीय सेवाओं से होने वाली आय (२) केन्द्र द्वारा हस्तान्तरित आमदनी (३) प्रान्त विशेष से प्राप्त आय के भाधार पर दिया जाने वाला केन्द्रीय अनुदान। यद्यपि विकेन्द्रीयकरण की यह योजना अधिक सफल नहीं हो सकी किन्तु फिर भी इसे विकेन्द्रीयकरण की ओर एक निश्चित प्रयत्न माना जा सकता है। सन् १८८२ में लार्ड रिपन (Lord Ripon) ने विकेन्द्रीयकरण की इस व्यवस्था में कुछ सुधार किये। वार्षिक अनुदान को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और आय की मदों को तीन भागों में बांट दिया गया—(अ) पूर्ण रूप से केन्द्रीय साधन—अफीम, नमक, आयात-निर्यात कर आदि (ब) पूर्ण रूप से प्रान्तीय साधन—मिजिल विभाग, प्रान्तीय कार्य तथा प्रान्तीय दरें (स) केन्द्रीय व प्रान्तीय साधन—उत्पादन कर, स्टाम्प, जगस, रजिस्ट्रेशन, मालगुजारी आदि। इन मदों से प्राप्त आय निश्चित अनुपात में केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच बांटी जाती थी। यह अनुपात प्रत्येक प्रान्त के नियम-मूल्य निश्चित किया जाता था। इस प्रणाली को पंचवर्षीय प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों के साथ पाँच-पाँच वर्ष के लिए समझौते किये जाते थे। किन्तु यह व्यवस्था भी अधिक सन्तोषजनक नहीं रही क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रान्तों को अपनी बढती हुई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो सकता था तथा इसमें काफी अनिश्चितता रहती थी। सन् १९०४ में लार्ड कर्जन (Lord Curzon) ने इस व्यवस्था को अर्थ स्थायी बना दिया। सन् १९१२ में लार्ड हार्जिंग ने यह घोषणा की कि अब इन समझौतों में समय-समय पर परिवर्तन नहीं किया जायगा। यह प्रश्न सन् १९१६ तक चलता रहा।

मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतीय राजस्व का एक महत्वपूर्ण युग आरम्भ होता है। बहुत समय में भारत में शासन सम्बन्धी सुधारों की भाग की जा रही थी और उससे लिये राष्ट्रीय आन्दोलन भी किया गया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के पश्चात् इन मांगों को पूरा करने का वचन दिया था। सन् १९१८ में भारत में मोन्टेग्यू (Montagu) तथा भारत के वाइसराय चैम्सफोर्ड (Chemsford) ने वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि प्रान्तों की वित्तीय तथा शासन सम्बन्धी मामलों में अधिक स्वतन्त्रता दी जानी

चाहिये। रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया कि वैधानिक विवेन्द्रीयकरण को सफल बनाने के लिये सर्वप्रथम वित्तीय विवेन्द्रीयकरण करना चाहिए और प्रान्तों के भाग के साधन केन्द्रीय सरकार के साधनों से बिल्कुल भिन्न कर देने चाहियें। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने १९१९ का सुधार अधिनियम (Reforms Act of 1919) पास किया। इस ऐक्ट में वैधानिक विवेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को मान लिया गया था और प्रान्तों को अधिक स्वतंत्रता दे दी गई। वित्तीय विवेन्द्रीयकरण करने के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के भाग के साधनों को एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् कर दिया गया था। प्रान्तों को स्वतंत्र रूप से ऋण लेने का अधिकार भी दे दिया गया। इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार के भाग के साधन इस प्रकार थे—सीमा कर, भाग कर, सामान्य स्टाम्प कर, अफीम, डाक, तार व रेलों से होने वाली भाग। प्रांतीय सरकारों की भाग की भंशों में मासगुजारी, सिचाई, स्टाम्प व रजिस्ट्री, जंगल आदि को सम्मिलित किया गया।

मैस्टन परिनिर्णय

साधनों का इस प्रकार बटवारा हो जाने का परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार को घाटा रहने लगा और प्रांतीय सरकारों को काफी मात्रा में बचत होने लगी। अतः यह निश्चित किया गया कि प्रांतीय सरकारें अपनी अनुमानित बचत का एक निश्चित अनुपात केन्द्रीय सरकार को दें। इस रकम को निर्धारित करने के लिये लार्ड मैस्टन (Lord Meson) की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई जिसने अपनी रिपोर्ट १९२० में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में मोन्टेय्यू चंम्सफोर्ड रिपोर्ट की अधिकांश बातों को मान लिया गया था। कमेटी ने भाग कर से होने वाली आमदनी के बटवारे का विरोध किया और यह सिफारिश की कि सामान्य स्टाम्प कर को प्रांतीय साधन बना देना चाहिए। इस कमेटी का मत था कि प्रान्तों के द्वारा केन्द्र को दिये जाने वाले अनुदान का आधार उनकी सामान्य बचत नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे उनकी खर्च करने की शक्ति के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिये। समिति ने विभिन्न प्रान्तों के द्वारा दिये जाने वाले अनुदान को इस प्रकार निश्चित किया—मद्रास ३४८ लाख, उत्तर प्रदेश २४० लाख, पंजाब १७५ लाख, बंगाल ६३ लाख, बम्बई ५६ लाख, बर्मा ६४ लाख, मध्य प्रान्त २२ लाख तथा आसाम १५ लाख रुपये। इन प्रारम्भिक अनुदानों को ७ साल के समय के पश्चात् घटाने अथवा बढ़ाने की व्यवस्था की गई।

मैस्टन समिति का यह विचार था कि प्रांतीय सरकारें इन अनुदानों को देने के पश्चात् भी काफी बचत कर सकेंगी जिसे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाया जा सकेगा किन्तु समिति की यह आशाएँ पूरी न हो सकी और शीघ्र ही प्रान्तों को अधिक सकट का सामना करना पड़ा और इन अनुदानों को कम करने की मांग की जाने लगी। सन् १९२५ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और प्रांतीय अनुदानों को कम कर दिया गया। सन् १९२९ से उन्हें बिल्कुल बन्द कर दिया गया।

मेस्टन एवार्ड के दोष :

सन् १९१६ की व्यवस्था के कारण भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के वित्तीय सम्बन्ध में काफी विवाद पैदा हो गया और मेस्टन एवार्ड में संशोधन करने की निरंतर मांग की जाने लगी। बम्बई तथा बंगाल के औद्योगिक प्रांतों ने इसका भारी विरोध किया। यू० पी०, मद्रास तथा पंजाब के कृषि प्रांत भी कुछ अन्य कारणों से इस एवार्ड में सम्मिलित हो गये। मेस्टन एवार्ड के मुख्य दोष इस प्रकार थे— (i) बन्द तथा प्रांतों के बीच आय के साधनों का बटवारा वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया था। केन्द्रीय सरकार के कार्य ऐसे थे जिन पर किये जाने वाले व्यय में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं थी किन्तु उन्हें आय कर, तट कर जैसे आय बढ़ाने वाले माधन दिये गए थे। इससे विपरीत प्रांतीय सरकारों से यह आशा की गई थी कि वे राष्ट्रीय निर्माण का काम करेंगे किन्तु उम्मेद के लिये उन्हें आय के बेलोच साधन दिए गये थे। (ii) कृषि प्रांतों की तुलना में औद्योगिक प्रांतों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार के द्वारा ले लिया जाता था जिसके कारण बम्बई तथा बंगाल के औद्योगिक प्रांत विशेषतया इस एवार्ड में असन्तुष्ट थे। पंजाब व मद्रास जैसे कृषि प्रधान प्रांतों को इस एवार्ड के परिणामस्वरूप अधिक लाभ पहुँचा जबकि बम्बई बंगाल, गिहार व उड़ीसा की आय में इतनी वृद्धि नहीं हुई। (iii) प्रांतों को दिये जाने वाले आय के श्रोत अपर्याप्त थे। आर्थिक तथा सामाजिक निर्माण के कामों के लिये उन्हें अधिक आय की आवश्यकता थी किन्तु मेस्टन एवार्ड के अन्तर्गत जो माधन उन्हें दिये गये वे इस नये उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये अपर्याप्त थे।

भारत सरकार का १९३५ का अधिनियम

सन् १९३५ का ऐक्ट प्रांतीय स्वशासन की ओर केवल पहला कदम था। अभी भी प्रांतों को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी और भारत सरकार का उन पर बड़ा नियन्त्रण रहता था। मीन्टेग्यू चैम्बरफोर्ड मुद्दारे की कार्यरूप में लाने से यह स्पष्ट हो गया था कि प्रांतीय सरकारों को पूरा उत्तरदायित्व दिये बिना आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति की दिशा में कोई विशेष काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रांतीय सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मामले में पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया जाय। सन् १९३५ के ऐक्ट व द्वारा प्रांतीय स्वशासन को अधिक पूर्ण रूप देने का प्रयत्न किया गया।

प्रांतों तथा बन्द के बीच कार्यों का जो बटवारा १९१६ के ऐक्ट में किया गया था उसे १९३५ के ऐक्ट में अधिक विस्तृत कर दिया गया। नये ऐक्ट में कार्यों की तीन सूची बना दी गई— (i) सघीय सूची (Federal list) (ii) प्रांतीय सूची (Provincial list) तथा (iii) कॉन्करेंट सूची (Concurrent list)। सघीय सूची में दिये हुए कार्यों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को था तथा प्रांतीय सूची में दिये गये कार्यों के सम्बन्ध में केवल प्रांतीय सरकारें

ही नियम बना सकती थीं। कान्करेंट (Concurrent) सूची में दिये गये कार्यों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार केन्द्र तथा प्रान्त दोनों को था। भगड़े की दशा में गवर्नर जनरल का फैसला अन्तिम समझा जायगा।

नये अधिनियम के अन्तर्गत आय के साधनों को भी तीन भागों में बांट दिया गया—सघीय (Federal); प्रान्तीय (Provincial) तथा मिले-जुटे (Joint) (अ) सघीय साधनों (Federal Resources) में सीमा शुल्क, तम्बाकू तथा भारत में बनी हुई वस्तुओं पर उत्पादन कर, कारपोरेशन टैक्स, नमक कर, कृषि आय को छोड़ कर अन्य प्रकार की आय पर कर, उत्तराधिकारी कर, विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों तथा बैंक्स आदि पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी, वस्तुओं तथा यात्रियों पर टर्मिनल टैक्स, रेलवे से प्राप्त होने वाली आमदनी, मियके ढालने व रिजर्व बैंक से होने वाली आमदनी डाक, तार दिभाग की आय आदि को सम्मिलित किया गया। (ब) प्रान्तीय श्रोतों (Provincial Resources) में निम्नलिखित साधन सम्मिलित किये गये :—मालगुजारी, शराब, भूमि तथा अन्य नगरीय वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन कर, कृषि आय कर, भूमि तथा मकानों पर कर, व्यवसाय कर, जानवरों तथा किशतियों पर कर, बिक्री कर, विलास की वस्तुओं पर कर, स्टाम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, खनिज वस्तुओं के अधिकारों पर कर आदि। (ग) कुछ करों को ऐसा रखा गया जिन्हें समानता की दृष्टि में केन्द्रीय सरकार के द्वारा वसूल किया जाता था—और उसकी कुल आमदनी को प्रान्तीय सरकारों में बांट दिया जाता था। कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर लगने वाला उत्तराधिकारी कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा टर्मिनल टैक्स इसी प्रकार के कर थे। कुछ कर ऐसे थे जिन्हें केन्द्रीय सरकार इकट्ठा करती थी और उसकी आमदनी का एक निश्चित अनुपात प्रान्तों के बीच बांट दिया जाता था जैसे आय कर। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर भी थे जिनकी आमदनी का कुल अथवा कुछ भाग प्रान्तों को दिया जाता था जैसे नमक कर, निर्यात कर आदि।

नये एकट के अन्तर्गत प्रान्तों को वित्तीय मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया गया। उनकी आय के साधन केन्द्रीय सरकार के साधनों से बिल्कुल अलग कर दिये गये। आय कर से होने वाली आमदनी में प्रान्तों को हिस्सा देने की बात भी स्वीकार कर ली गई। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने के सम्बन्ध में पूरी स्वतन्त्रता दे दी गई किन्तु वे केन्द्र की आज्ञा के बिना विदेशी ऋण नहीं ले सकते थे। कुछ समय तक यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रही किन्तु इसे अधिक समय तक जारी न रखा जा सका। वॉलेस मन्त्रिमण्डल ने स्तीफा दे दिया तथा दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के लिये नये कर लगाना अनिवार्य हो गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात्—

अगस्त सन् १९४७ में भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई और २६ नवम्बर १९४९ को नया विधान लागू कर दिया गया। कार्यों का नया बंटवारा किया गया

तथा केन्द्र व राज्यो के बीच के वित्तीय सम्बन्धों में भी कुछ परिवर्तन किये गये। नये विधान के अन्तर्गत विषयो (Subjects) को तीन भागों में बांट दिया गया—

(१) सघीय सूची (Union List)—इस सूची में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। सघीय-सूची के प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—सुरक्षा, एटम शक्ति, विदेशी मामले, रेलें, हवाई यातायात, जलयान, डाक, तार, सिक्का वसाई व मुद्रण, रिजर्व बैंक, विदेशी व्यापार, बैंक तथा धोमा कम्पनियाँ, खनिज साधनों का विकास इत्यादि। (२) राज्य सूची (State List)—कुछ विषय पूर्णतया राज्य सरकारों को सौंप दिये गये और इन्हें राज्य सूची में रक्खा गया। इन विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इन सूची के विषय इस प्रकार हैं—पुलिस, जेल, न्याय प्रबन्ध, स्थानीय शासन, सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पुल, खेती, जंगल, राज्य के भीतर का व्यापार तथा उद्योग इत्यादि। (३) कॉंकरेण्ट सूची (Concurrent List)—विवाह और तलाक, शांति सामग्री व मिलावट, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, मजदूर सभ, सामाजिक सुरक्षा, श्रम नियन्त्रण, नारसुखाने, विजली, छापेखाने, अखबार इत्यादि इस सूची में रखे गये। इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केन्द्र व राज्य दोनों को है।

— नये विधान में आय के साधनों का वटवारा निम्न प्रकार किया गया है :—
केन्द्रीय सरकार को आय के साधन :

कृषि आय के अतिरिक्त अन्य प्रकार की आय पर कर, सीमा शुल्क, भारत में निमित्त वस्तुओं पर उत्पादन कर, कॉरपोरेशन टैक्स, वस्तुओं तथा यानियों पर टरमिनल टैक्स, अखबारों तथा विज्ञापन पर लगने वाला कर, मृत्यु कर, पूँजी लाभ कर इत्यादि।

राज्य सरकारों के साधन :

मालगुजारी, कृषि आय कर, कृषि भूमि के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी कर, मोटर गाड़ियों पर कर, नशीली वस्तुओं पर कर, बिक्री कर, विजलों के उपभोग पर कर, जानवरों तथा नाव पर कर टोल टैक्स, व्यापार पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि।

विधान की २६६ धारा के अन्तर्गत कुछ ऐसे करों को वतलाया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार लगायेगी तथा एकत्रित करेगी किन्तु इनसे होने वाली आय को उन राज्यों के बीच बांट दिया जायगा जहाँ से वह कर इकट्ठा किया गया है। यह वटवारा लोक सभा के द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार किया जायगा। यह कर इस प्रकार है—(क) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर लगने वाला उत्तराधिकारी कर। (ख) यात्रियों तथा सामान पर लगने वाला टरमिनल टैक्स (Terminal Tax)। (ग) रेल किराये तथा भाड़े पर लगने वाला कर। (घ) सट्टा बाजार में किये गये सौदों पर कर। (च) समाचार पत्र तथा विज्ञापन पर लगने वाला कर।

आय कर से होने वाली आमदनी को केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक निश्चित विधि से बांटा जायगा। उक्तलिखित करों पर सरचार्ज (Surcharge) लगा कर केन्द्रीय सरकार आमदनी को बढ़ा सकती है। आय में होने वाली इस प्रकार की कुल वृद्धि केन्द्रीय सरकार के पास रहेगी। उत्पादन कर (Excise Duties) केन्द्रीय सरकार लगायेगी किन्तु उसकी आमदनी का कुछ भाग राज्यों में बांटा जा सकता है। जूट पर निर्यात कर केन्द्रीय सरकार लगायेगी किन्तु उसकी आमदनी को जूट पैदा करने वाले प्रान्तों में नहीं बांटा जायेगा। उसके बदले में बिहार, उड़ीसा, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल को आर्थिक सहायता दी जायगी। राज्य सरकारों को केन्द्र से विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये अनुदान दिया जायगा। अनुदान की रकम लोक सभा निर्धारित करेगी। संविधान के लागू होने के दो वर्षों के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करेगा जो निम्नलिखित बातों पर सुझाव देगा :—

(अ) बंटने वाले करो तथा शुल्कों से होने वाली आय को किस अनुपात में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाय।

(ब) विभिन्न राज्यों को अनुदान देने के क्या सिद्धान्त होने चाहियें।

(स) केन्द्र तथा राज्यों के बीच किये गये समझौतों को जारी रखने अथवा उनमें सुधार करने से सम्बन्धित सुझाव।

(द) कोई और विषय जिस पर उसे सिफारिश करने के लिए कहा जाय।

प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशें :

भारत संविधान की धारा २७० के आधीन दिसम्बर सन् १९५१ में राष्ट्रपति श्री के० सी० नय्योगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग नियुक्त किया। वित्त आयोग को ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण करना था। जिनके आधार पर कुछ करो से प्राप्त आय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटा जा सके तथा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदान निश्चित किये जा सकें। वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में तीन सामान्य सिद्धान्तों को अपनाया है—(i) केन्द्र तथा राज्यों के बीच साधनों का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार सुरक्षा, आर्थिक उन्नति तथा अन्य अनिवार्य कार्यों को भली प्रकार कर सके। (ii) आय के वितरण तथा अनुदान देने के सम्बन्ध में सभी राज्यों के लिए एक ही सिद्धान्त होना चाहिये। (iii) वितरण की योजना का उद्देश्य राज्यों के बीच वर्तमान असमानताओं को दूर करना होना चाहिये।

(१) आयोग ने आय-कर के वितरण के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया कि आय कर से होने वाली कुल शुद्ध आय का ५५% राज्यों में बांट दिया जाय। बांटी जाने वाली कुल रकम का २०% इस आधार पर दिया जाय कि किस राज्य से कितनी आमदनी हुई है और ८०% राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाय। इस सिद्धान्त के आधार पर बंटने वाली कुल रकम में विभिन्न राज्यों का प्रतिशत

हिस्सा इस प्रकार निश्चित किया गया—आसाम २-२५, बिहार ६-७५, बम्बई १७-५०, हैदराबाद ४-५०, मध्य भारत १-७५, मध्य प्रदेश ५-२५, मद्रास १५-२५, मेसूर २-२५, उड़ीसा ३-५०, पेपसू ०-७५, पंजाब ३-२५, राजस्थान ३-५०, सीराष्ट्र १-००, त्रिवापुर कोचीन २-५०, उत्तर प्रदेश १५-७५ तथा पश्चिमी बंगाल ११-२५।

(२) वित्त आयोग ने राज्य सरकारों की इस भाग को मान लिया कि उत्पादन-कर से केन्द्रीय सरकार को होने वाली आय का कुछ भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाय। आयोग ने यह सिफारिश की कि तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति उपज आदि पर लगने वाले उत्पादन-कर से प्राप्त होने वाली आय का ४०% भाग राज्य सरकारों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया जाय। विभिन्न राज्यों का भाग इस प्रकार निश्चित किया गया—

राज्य	कुल आय का प्रतिशत	राज्य	कुल आय का प्रतिशत
असम	२.६१	उड़ीसा	४.२२
बिहार	११.६०	पटियाला मघ	१.००
बम्बई	१०.३७	पंजाब	३.६६
हैदराबाद	४.३६	राजस्थान	४.४१
मध्यभारत	२.२६	सीराष्ट्र	१.१६
मध्य प्रदेश	६.१३	त्रिवापुर कोचीन	२.६८
मद्रास	१६.४४	उत्तर प्रदेश	१५.२३
मेसूर	२.६२	पश्चिम बंगाल	७.१६

(३) आयोग ने यह सिफारिश की कि जूट निर्यात कर के बदले में असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सन् १९५२-५३ से आरम्भ कर दिया जाय, इन राज्यों को दी जाने वाली रकम इस प्रकार रखी गई—

पश्चिमी बंगाल	१५० लाख रुपया
असम	७५ लाख रुपया
बिहार	७५ लाख रुपया
उड़ीसा	१५ लाख रुपया

(४) आयोग के अनुसार राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान (Grants in Aid) की रकम निश्चित करते समय उपलब्ध साधन तथा राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये। जन-कल्याण सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये तथा सामाजिक सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिये। अनुदान देने का

तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे यह भ्रम उत्पन्न न हो सके कि केन्द्रीय सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों के वार्षिक बजट के घाटे को पूरा करने का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेती है। विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित अनुदान देने की सिफारिश की गई—

आसाम	१०० लाख रुपया
मैसूर	४० लाख रुपया
उड़ीसा	७५ लाख रुपया
पंजाब	१२५ लाख रुपया
सौराष्ट्र	४० लाख रुपया
बिवाकुर कोचीन	४५ लाख रुपया
पश्चिमी बंगाल	८० लाख रुपया

इन सामान्य अनुदानों के अतिरिक्त वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि निम्नलिखित राज्यों को अगले चार वर्षों तक बढ़ती हुई दर से, प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिये विशेष अनुदान दिये जायें। इन राज्यों में बिहार, हैदराबाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पेशु तथा राजस्थान को सम्मिलित किया गया।

प्रालोचना :

प्रथम वित्त-आयोग की सिफारिशों से सभी राज्य सन्तुष्ट नहीं थे। यद्यपि इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों की आय में तथा केन्द्र से मिलने वाले अनुदान में काफी वृद्धि हुई किन्तु फिर भी कुछ राज्य यह महसूस करते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आयोग की सिफारिशों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की गई—(१) आय-कर से होने वाली आमदनी के बटवारे का आधार ठीक नहीं था। कुछ राज्यों का यह मत था कि आय-कर का बटवारा प्राप्त होने वाली आय के श्रोता के अनुसार होना चाहिये। जिस प्रान्त में आय-कर अधिक मात्रा में इकट्ठा किया जाता है उसे आय-कर में से अधिक भाग मिलना चाहिये। विशेषकर बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल जैसे औद्योगिक प्रान्तों का यह विचार था कि आय-कर के बटवारे में उनके साथ अन्याय किया गया है। (२) उत्पादन-कर के बटवारे के आधार पर भी ठीक नहीं था। आयोग की वितरण योजना में इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था कि विभाज्य कर की कितनी राशि कौनसे राज्य से प्राप्त हुई। कुछ राज्य उत्पादन-कर में अधिक हिस्सा चाहते थे क्योंकि उनके क्षेत्र में अधिक मात्रा में आय-कर एकत्रित होता था। कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि वितरण योजना बनाते समय उनकी बजट स्थिति को देखने की अपेक्षा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये था। (३) राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता अधिक बढ़ गई थी। अनुदानों के लिए राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता था जो संघीय सिद्धान्त (Principles of Federalism) के अनुकूल नहीं था।

दूसरा वित्त-आयोग :

दूसरा वित्त आयोग श्री के० सनथानम की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट १४ नवम्बर सन् १९१७ को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत की। आयोग को निम्नलिखित बातों पर सुझाव देने के लिये कहा गया था—

(घ) आय-कर तथा संप उत्पादन कर में राज्यों के हिस्से निश्चित करना।

(व) सविधान की २७३ और २७५ धाराओं के अन्तर्गत राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की रकम निश्चित करना।

(स) सम्पदा-कर (Estate Duty) से प्राप्त आय को राज्यों में बाँटना।

(द) रेल-भाड़े पर लगाये जाने वाले कर में राज्यों के हिस्से निश्चित करना।

(च) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों की शर्तों की जाँच करना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करना।

सिफारिशें

आयोग ने सब बातों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित सिफारिशों की—

(१) आय-कर से प्राप्त शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा ५५% से बढ़ा कर ६०% कर दिया जाय। इसका बंटवारा ६०% राज्य की जनसंख्या के आधार पर तथा १०% राज्य में एकत्रित कर की मात्रा के आधार पर किया जायगा।

(२) पहले की भाँति दियासलाई, वनस्पति उपज तथा तम्बाकू आदि पर लगने वाले उत्पादन-कर से प्राप्त शुद्ध आय का ४०% राज्यों में बाँट देना चाहिए। यह बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जायगा। आयोग में ८ और वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादन-कर से प्राप्त शुद्ध आय का २५% जनसंख्या के आधार पर राज्यों में बाँटने का सुझाव दिया। इन वस्तुओं में कहवा (Coffee), चाय, चीनी, कागज, वनस्पति तेल आदि हैं।

(६) रूट कर अनुदान के सम्बन्ध में आयोग ने यह निश्चित किया है कि ३१ मार्च १९६० तक असम को ७५ लाख रुपया और उड़ीसा को १५ लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिये। बिहार का क्षेत्र कम हो जाने के कारण उसका हिस्सा २६६ लाख रुपए कम कर दिया गया। पश्चिमी बंगाल के हिस्से में इतनी ही वृद्धि कर दी गई। ३१ मार्च १९६० के पश्चात् इस प्रकार के अनुदान नहीं दिये जायेंगे।

(४) विभिन्न राज्यों को केन्द्र से दिए जाने वाले अनुदान की रकम इस प्रकार निश्चित की गई—

आन्ध्र प्रदेश	४०० लाख रुपया
असम	३७५ लाख रुपया
बिहार	३२० लाख रुपया
केरल	१७५ लाख रुपया
मध्य प्रदेश	३०० लाख रुपया

मैसूर	६०० लाख रुपया
उड़ीसा	३२५ लाख रुपया
पंजाब	२२५ लाख रुपया
राजस्थान	२५० लाख रुपया
पश्चिमी बंगाल	३२५ लाख रुपया
जम्मू काश्मीर	३०० लाख रुपया

(५) सम्पदा कर (Estate duty) की कुल आय, उस आय को छोड़ कर जो केन्द्र प्रसारित क्षेत्रों से प्राप्त होती है, राज्यों में बांट दी जाय। केन्द्रीय प्रस्तावित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में सरकार १% आय अपने पास रख सकती है। शेष में से राज्यों को उनकी जनसंख्या तथा उनसे प्राप्त आय के आधार पर हिस्से दिए जायें।

(६) रेल भाड़े पर कर से प्राप्त आय का १% सरकार केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में रख सकती है। शेष रकम रेलवे साइन की सम्भारों के आधार पर राज्यों में बांट देनी चाहिए।

(७) मिल के कपड़े, चीनी तथा तम्बाकू के विक्री करों से राज्यों को प्राप्त होने वाली आय का अनुमान ३१.५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष लगाया गया। आयोग ने सिफारिश की कि इस कर के स्थान पर जो उत्पादन कर लगाया जाय उसकी आमदनी का १% केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में रख ले तथा १½% जम्मू व काश्मीर राज्य को दिया जाय और शेष अन्य राज्यों में बांट दिया जाय। विभिन्न राज्यों का हिस्सा उनकी जनसंख्या तथा उनके द्वारा इन वस्तुओं के उपभोग के आधार पर निश्चित किया जाय।

इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों की आय में काफी वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा अपने आगमन में से लगभग १४० करोड़ रुपया प्रति वर्ष राज्यों को हस्तांतरित करना होगा जबकि पिछले ५ वर्षों में हस्तांतरित की जाने वाली रकम लगभग ६५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष रही है। आयोग ने राज्यों की आय में वृद्धि करने का सुझाव इसलिए दिया कि राज्यों को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यदि राज्य अपनी आय के साधनों का उचित विस्तार कर लेते हैं और उन्हें केन्द्र से निर्धारित सहायता प्राप्त होती रहती है तो राज्यों को अपने विकास कार्य-क्रमों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

तीसरा वित्त आयोग :

तीसरा वित्त आयोग २ दिसम्बर सन् १९६० को नियुक्त किया गया जिसने १४ दिसम्बर सन् १९६१ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(१) सम्पदा कर (Estate duty)—प्रत्येक वित्त वर्ष में कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर कर से होने वाली कुल आय में १% केन्द्र के

द्वारा केन्द्रीय प्रशासित राज्यों के हिस्से के रूप में रख लिया जाय। शेष को चल (Movable) तथा अचल (Immovable) सम्पत्ति के बीच में इन सम्पत्तियों के मूल्यों के अनुपात में बांट लिया जाय। अचल सम्पत्ति के हिस्से को राज्यों के बीच इस आधार पर बांट दिया जाय कि उनके क्षेत्र में कितने मूल्य की अचल सम्पत्ति स्थित है। चल सम्पत्ति के हिस्से में आने वाली रकम को विभिन्न राज्यों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांट दिया जाय—

मान्ध्र प्रदेश	८.३४%	महाराष्ट्र	६.१६%
असम	२.७५%	मैसूर	५.४६%
बिहार	१०.७८%	उड़ीसा	४.०८%
गुजरात	४.७८%	पंजाब	४.७१%
जम्मू काश्मीर	०.८३%	राजस्थान	४.६७%
केरल	३.६२%	उत्तर प्रदेश	१७.१०%
मध्य प्रदेश	७.५१%	पश्चिमी बंगाल	८.११%
मद्रास	७.८०%		

(२) रेल लाइनें पर कर के बदले में दिया जाने वाला अनुदान—१ अप्रैल, १९६१ से १२.५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्यों में बांट दिया जाय। विभिन्न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा—मान्ध्र प्रदेश १.११ करोड़ रुपये, असम ०.३४ करोड़, बिहार १.१७ करोड़, गुजरात ०.६८ करोड़, केरल ०.२३ करोड़, मध्य प्रदेश १.०४ करोड़, मद्रास ०.८१ करोड़, महाराष्ट्र १.३५ करोड़, मैसूर ०.५६ करोड़, उड़ीसा ०.२२ करोड़, पंजाब १.०१ करोड़, राजस्थान ०.८५ करोड़, उत्तर प्रदेश २.३४ करोड़, पश्चिमी बंगाल ०.७६ करोड़।

(३) आय कर (Income tax)—कृषि आय को छोड़ कर अन्य प्रकार की आय पर कर से प्राप्त आयदनी का ६६.३% भाग राज्यों में बांट दिया जाय। विभिन्न राज्यों में इसका बटवारा निम्नलिखित अनुपात में किया जायगा—

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
मान्ध्र प्रदेश	७.७१	मध्य प्रदेश	६.६१
आसाम	२.४४	मद्रास	८.१३
बिहार	६.३३	महाराष्ट्र	१३.४१
गुजरात	४.७८	मैसूर	५.१३
जम्मू काश्मीर	०.७०	उड़ीसा	३.४४
केरल	३.५५	पंजाब	४.४६
राजस्थान	३.६७	उत्तर प्रदेश	१४.४२
		पश्चिमी बंगाल	१२.०६

(४) केन्द्रीय उत्पादन कर (Union Excise duties)—चीनी, कहवा, चाय, तम्बाकू, मिट्टी का तेल, वनस्पति उत्पादन, साबुन, बाणज, सूती कपड़ा, सीमेंट,

साइकिल, जूते, दियासलाई आदि पर लगने वाले उत्पादन कर से होने वाली कुल आय में २०% राज्यों में बांट दिया जाय। विभिन्न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा—

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	८.२३	मद्रास	६.०८
आसाम	४.७३	महाराष्ट्र	५.७३
बिहार	११.५६	मैसूर	५.८२
गुजरात	६.४५	उड़ीसा	७.०७
जम्मू काश्मीर	२.०२	पंजाब	६.७१
केरल	५.४६	राजस्थान	५.६३
मध्य प्रदेश	८.४६	उत्तर प्रदेश	१०.६८
		पश्चिमी बंगाल	५.०७

(५) अनुदान (Grants-in-Aid)—सविधान की धारा २७५ के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान की रकम आयोग के द्वारा उपरोक्त प्रकार निश्चित की गई। इसके प्रतिरिक्त आयोग ने सदेशवाहन के विकास के लिए राज्यों को प्रतिरिक्त अनुदान देने की सिफारिश भी की। दोनों प्रकार के अनुदानों की रकम जो राज्यों को दी जाती है, निम्न तालिका में दिखलाई गई है।

(६) अतिरिक्त उत्पादन कर (Additional duties of Excise)—सूती कपड़े, सिल्क तथा ऊनी कपड़े, चीनी व तम्बाकू पर विक्री कर के स्थान पर लगाये जाने वाले उत्पादन कर से होने वाली आय का १% केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों के हिस्से के रूप में रखेगी। १३% जम्मू काश्मीर को दिया जायगा तथा शेष में से राज्यों को सर्वप्रथम उनकी १६५६-५७ में इन वस्तुओं पर विक्री कर

राज्य का नाम	राज्यों की आय की ओर दिया जाने वाला अनुदान	सन्देशवाहन के विकास के लिये अतिरिक्त अनुदान
आन्ध्र प्रदेश	१,२०० लाख रुपया	५० लाख रुपया
आसाम	६०० "	७५ "
बिहार	८०० "	७५ "
गुजरात	६५० "	१०० "
जम्मू काश्मीर	३२५ "	५० "
केरल	८५० "	७५ "
मध्य प्रदेश	६२५ "	१७५ "
मद्रास	८०० "	—
मैसूर	७७५ "	५० "
उड़ीसा	१,६०० "	१७५ "
पंजाब	२७५ "	—
राजस्थान	८७५ "	७५ "
उत्तर प्रदेश	२०० "	—
पश्चिमी बंगाल	८५० "	—

से होने वाली आमदनी के बराबर हिस्सा दिया जाय तथा शेष को इस अनुपात में बांट दिया जाय—मान्द्र प्रदेश ७.७५, आन्ध्र प्रदेश २.५०, बिहार १०.००, गुजरात ५.४०, केरल ४.२५, मध्य प्रदेश ७.००, मद्रास ६.००, महाराष्ट्र १०.६०, मेसूर ५.२५, उड़ीसा ४.५०, पंजाब ५.२५, राजस्थान ४.००, उत्तर प्रदेश १५.५०, पश्चिमी बंगाल ६.०० ।

परीक्षा प्रश्न

1. Describe the division of revenues between the Union and States under the constitution. State the position of income tax in the above allocation. (Agra B. A. 1955)

भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच आय के बंटवारे का वर्णन कीजिये । उसमें आय कर का क्या स्थान है ।

2. Trace the history of financial relations between the Provincial Governments and the Central Government of India from 1920 to 1940. (Agra B. A. 1946)

सन् १९२० से १९४० तक केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों का इतिहास बताइये ।

3. What are the existing financial relations between the Provinces and the Central Government of India? Are Provincial revenues adequate to meet Provincial needs? Suggest some remedies. (Agra B. A. 1941)

केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतों के वित्तीय सम्बन्ध इस समय क्या हैं ? क्या प्रांतों की आय उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है ? सुधार के उपाय बताइये ।

4. Discuss in brief the recommendations of the Third Finance Commission.

तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये ।

भारत सरकार का अर्थ-प्रबन्ध

Finances of the Government of India

अर्थ-प्रबन्ध के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती है तथा किस प्रकार उसका व्यय करती है। आय तथा व्यय में समायोजन स्थापित करना अर्थ-प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य समझा जाता है। किसी भी सरकार का अर्थ-प्रबन्ध उस देश के नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि सरकार जब अपनी आय प्राप्त करती है तो व्यक्तियों की आय उस सीमा तक कम हो जाती है और उनका आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। जब सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिये व्यय किया जाता है तो लोगों की आय तथा उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। प्रत्येक सरकार अपनी आय तथा व्यय का प्रबन्ध इस प्रकार करती है कि आय प्राप्त करने के कारण आर्थिक कल्याण में होने वाली कमी उस वृद्धि से कम हो जो साव-जनिक व्यय के द्वारा लोगों के कल्याण में होती है।

भारत सरकार के अर्थ-प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिये उसे दो भागों में बांटा जा सकता है—(अ) भारत सरकार की आय तथा (ब) भारत सरकार का व्यय।

भारत सरकार की आय :

भारत सरकार की आय के साधनों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है—(i) कर-आय के साधन (Sources of Tax Revenue) और (ii) गैर-कर-आय के साधन (Sources of Non-tax Revenue)। भारत सरकार को दोनों प्रकार के साधनों से आय प्राप्त होती है। कर-आय के मुख्य साधन सीमा शुल्क, मूल्यन आबकारी कर, आय कर, कॉर्पोरेशन कर, मृत्यु कर, अफीम पर कर तथा उत्पादन कर आदि हैं। गैर-कर आय की मुख्य मदें—रेल, डाक व तार, मुद्रण तथा मिन्ट, उद्योग तथा व्यवसाय आदि हैं। भारत सरकार को प्राप्त होने वाली आय का ७० से ६० प्रतिशत कर-साधनों से प्राप्त होता है और गैर-कर साधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों से गैर-कर आय के साधनों का महत्व निरन्तर बढ़ रहा है और इनसे प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हो रही है। कर-आय के साधनों में अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) से प्राप्त होने वाली आमदनी प्रत्यक्ष कर (Direct

Taxes) की आय की अपेक्षा अधिक रहती है। अप्रत्यक्ष करों का भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है तथा उनकी प्रवृत्ति धन के वितरण की असमानताओं को बढ़ाने की होती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने प्रत्यक्ष करों में आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया है किन्तु उसे इनमें कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी है और सरकार की अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की कर-आय (Tax Revenue) तथा गैर-कर आय (Non-Tax Revenue) निम्न प्रकार रही है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर-आय	कुल आय का प्रतिशत	गैर-कर आय	कुल आय का प्रतिशत
१९५०-५१	३५७ ००	८७.६	४८.८६	१२.१
१९५५-५६	४११ ४७	८५.५	६८.७२	१४.५
१९५५-५७	४६३ ७६	८७.६	६६ ४७	१२.४
१९५७-५८	५७५ ३३	८५.४	९८.०५	१४.६
१९५८-५९	५५३.०६	८२.५	११७.१५	१७.५
१९५९-६०	६४२ ४४	८२.५	१३६.१५	१७.५
१९६०-६१	७१०.१४	८३.२	१४७ ३२	१६.८
१९६१-६२	८२३.०७	८४.१	१५५ २६	१५.९
१९६२-६३ ^१	८८६ २२	७१.१	३४६ ८६	२८.९

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि भारत सरकार की आय का अधिकांश कर माध्यमों से प्राप्त होता है। इन साधनों से प्राप्त होने वाली आय कुल आय के ७० से ९० प्रतिशत के बीच रही है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की कर आय में निरन्तर वृद्धि होती रही है किन्तु कुल आय में उसका प्रतिशत भाग कम होता जा रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की निर्भरता कर साधनों पर कुछ कम हुई है। गैर-कर आय कुल आय के १० और ३० प्रतिशत के बीच रही है। गैर-कर साधनों से सरकार की आय तेजी के साथ बढ़ रही है और १९६२-६३ में कुल आय में उसका भाग २६% हो गया है जबकि १९५०-५१ में वह केवल १२.१% ही था। यह परिवर्तन एक अच्छी प्रवृत्ति का प्रतीक है।

भारत सरकार की आय की भेद

(करोड़ रुपयों में)

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३ (बजट अनुमान)
आय कर (शुद्ध आगम)	८०.१	४८.७३	६८.७०
कॉरपोरेशन कर	१११.०५	१६०.००	१७८.५०
व्यय कर (Expenditure Tax)	०.६१	०.८०	०.१०
सम्पदा कर (Estate Duty)	०.१८	०.१२	०.१२
सम्पत्ति कर (Wealth Tax)	८.१५	७.५०	६.००
उपहार कर (Gift Tax)	०.८६	०.८५	०.८५
स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन	३.६८	३.६५	४.०६
भूमि कर (Land Revenue)	०.५६	०.६६	०.६७
सीमा शुल्क (Custom Duties)			
(शुद्ध आगम)	१७०.०३	१६६.६०	२०७.४०
केन्द्रीय उत्पादन कर (Excise Duty)			
(शुद्ध आगम)	३४१.२५	३६०.०१	४०८.७२
रेल भाडे पर कर (शुद्ध आगम)	२.१०		
अन्य कर	११.३०	१०.८५	११.०७
नागरिक शासन	५६.३२	५२.७५	५०.३८
रेलवे	४.७७	२१.०२	२१.०४
डाक व तार	०.४६	०.७८	०.७६
करेन्सी तथा मिन्ट	४७.६५	४१.५३	४६.३०
अन्य सार्वजनिक उपयोग से	०.१८	०.७०	२.२६
अन्य आय	३५.००	३८.४८	२२३.०६
कुल आय	८७७.४६	६७८.३३	१२३६.११

Figures taken from 'Report on Currency and Finance'—
1961-62 (Reserve Bank of India).

कर-आय के साधन :

भारत सरकार की कर आय के साधन निम्नलिखित हैं :—

(१) आय कर (Income Tax)—आय कर भारत सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। केन्द्रीय उत्पादन कर तथा सीमा शुल्क के पश्चात् इसी का नम्बर आता है। कृषि आय को छोड़ कर अन्य सब प्रकार की आय पर कर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। भारत में सर्वप्रथम यह कर १८६० में केवल ४ वर्षों के लिये लगाया गया था और १८६५ में इसे समाप्त कर दिया गया।

सन् १८६६ में उसे फिर चार वर्षों के लिये लगा दिया गया और १८८६ में आय कर को स्थाई रूप दे दिया गया किन्तु कृषि आय को उससे मुक्त रखवा गया। समय के साथ-साथ आय कर की दरों में परिवर्तन होता रहा और कर को अधिक प्रगतिशील (Progressive) बनाया जाता रहा है। कर से छूट की सीमा को भी कई बार बदला गया है और अब वह पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है।

आय कर प्रगतिशील दर से लगाया जाता है। विवाहित व्यक्तियों के लिए छूट की वर्तमान सीमा ३००० रुपया रखी गई है। इसकी वार्षिक आय तक किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता। इसके ऊपर अगले २००० रु० की आय तक ३% के हिसाब से कर लगाया जाता है। आय की वृद्धि के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। प्रत्येक वर्ष के लिये ३०० रु० की छूट भी दी जाती है जो दो बच्चों तक सीमित है। कर केवल शुद्ध आय पर लगाया जाता है अर्थात् कुल आय में आय उत्पन्न करने का व्यय घटा दिया जाता है। प्रावधान कोष (Provident Fund), जीवन बीमा आदि में दिये हुये रुपये पर छूट दी जाती है। दरों के निर्धारण में परत प्रणाली (Slab System) अपनाया गया है। टैक्स की दर ३ प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक जाती है। इसके अतिरिक्त २०,००० रु० वार्षिक आमदनी से अधिक पर अतिरिक्त कर (Super Tax) भी लगाया जाता है जिसकी दर ५ प्रतिशत से ४५ प्रतिशत तक जाती है।

आय कर से भारत सरकार को अपनी आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता है। युद्ध काल में तो सरकार को अपनी आय का ५ प्रतिशत आय तथा कारपोरेशन कर से प्राप्त होता था। सरकार को आय कर से प्राप्त होने वाली आय पिछले वर्षों में काफी बढ़ी है। सन् १९६२-६३ के बजट अनुमान के अनुसार सरकार को आय कर से १६३.४० करोड़ रुपया प्राप्त होगा जिसमें से १४.७० करोड़ रुपया राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें बांट दिया जायगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार को आय कर से प्राप्त होने वाली आय निम्न प्रकार थी —

१९५०-५१	१३२.७३ करोड़ रुपया
१९५६-५७	१५१.७४ "
१९५८-५९	१७२.०१ "
१९६०-६१	१६७.३८ "
१९६२-६३ (अनुमानित)	१६३.४० "

यह कर अधिकांश कर सिद्धान्तों (Canons of taxation) को सन्तुष्ट करता है तथा इसमें प्रत्यक्ष करों के सभी गुण पाए जाते हैं। (1) आय कर न्यायपूर्ण है क्योंकि वह लोगों की कर दान क्षमता के अनुसार लगाया जाता है। अधिक कर-दान क्षमता वाले से अधिक कर लिया जाता है तथा जिनकी कर-दान क्षमता कम है उन्हें या तो बिल्कुल कर नहीं देना होता है और या बहुत कम देना पड़ता है। (ii) यह एक

प्रगतिशील कर है और घन के वितरण की असमानताओं को दूर करता है। धनी व्यक्तियों से बहुत ऊँची दर से कर लिया जाता है तथा कम आय वाले को कर से मुक्त रखा गया है। (iii) इस कर में निश्चितता का गुण पाया जाता है क्योंकि कर-दाताओं को यह मालूम रहता है कि उन्हें कब कर देना है और कितनी मात्रा में देना है। सरकार भी यह अनुमान लगा सकती है कि उसे इस कर से कितनी आय प्राप्त होगी। (iv) यह कर सुविधापूर्ण भी है क्योंकि पूर्व वर्ष की आय पर ही कर लगाया जाता है तथा वेतन प्राप्त होने से पूर्व ही इसे काट लिया जाता है। (v) आय कर लोचपूर्ण भी है क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली आमदनी लोगों की आय में वृद्धि के साथ स्वयं बढ़ती जाती है। कर की दर में थोड़ी सी वृद्धि करके सरकार अपनी आमदनी को काफी बढ़ा सकती है।

आय कर के दोष .

(१) इन सब गुणों के होते हुए भी आय कर में कुछ दोष पाए जाते हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—(i) लोग अपनी आमदनी को छुपाकर तथा भूठे हिसाब प्रस्तुत करके अपने आपको कर से बचा लेते हैं जिससे सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ती है। (ii) छूट की न्यूनतम सीमा बहुत कम है जिसके कारण मध्यम वर्ग के परिवारों पर अनावश्यक भार पड़ता है। (iii) ऊँची आय वाले वर्ग के लिए कर की दर बहुत ऊँची है जिसके कारण बचत हतोत्साहित होती है। (iv) करारोपण करते समय परिवार के आकार का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है जिसके कारण बड़े परिवारों को विशेष कठिनाई होती है।

(२) कॉर्पोरेशन कर (Corporation Tax)—यह कर भारतवर्ष में सन् १९३९ से लगाया जा रहा है। सभी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों को व्यक्तियों की भाँति अपनी आय पर कर देना पड़ता है। कॉर्पोरेशन कर मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है। इसकी दर भारतीय कम्पनियों के लिए ४ आने प्रति रुपया तथा विदेशी कम्पनियों के लिए ५ आने प्रति रुपया है। यह कर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कम्पनियों को राज्य से कुछ सुविधायें प्राप्त होती हैं जिनके कारण वे अपना कार्य सफलतापूर्वक करती हैं। शान्ति व सुरक्षा, न्यायालयों का प्रयोग इसी प्रकार की कुछ सुविधायें हैं। इस कर के सम्बन्ध में कम्पनियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती और उनकी कुल आमदनी पर कर लगाया जाता है। सन् १९३९ में इस कर से सरकार को केवल २ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था किन्तु औद्योगिकरण के कारण कॉर्पोरेशन कर से सरकार को आमदनी निरन्तर बढ़ रही है। सन् १९५५-५६ में इस मद से ३९.७७ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। सन् १९६२-६३ के बजट के अनुमान के अनुसार इस कर से १७८.५० करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है।

(३) मृत्यु कर (Death duty)—इस कर को सम्पदा कर (Estate duty) भी कहा जाता है। भारतवर्ष में मृत्यु कर सर्वप्रथम सन् १९५३ में लगाया गया।

यह कर मृत्यु के समय उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है। कर चल तथा अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति पर लगाया जाता है। कर लगाने के लिए मृतक की सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजारी दर से किया जाता है। सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में ५०,००० रु० की सम्पत्ति तक कोई कर नहीं देना होता। अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में छूट की सीमा १ लाख रुपया रखी गई है। इस कर के सम्बन्ध में कई प्रकार की छूट दी गई हैं जो इस प्रकार हैं—(i) मृत्यु से ६ मास पूर्व धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए दान के रूप में दी गई रकम जिसकी अधिकतम सीमा २,५०० रु० रखी गई है, (ii) मृत्यु के दो वर्ष पूर्व दिए जाने वाले १,५०० रु० तक के अन्य उपहार। (iii) मृत्यु कर के भुगतान के लिए की गई बीमा पॉलिसी जिसकी अधिक से अधिक रकम ५०,००० रु० तक हो सकती है। (iv) मृतक की बीमा पॉलिसी में से ५,००० रु० की रकम तथा (v) किसी रिश्तेदार की लड़की के विवाह के लिए ५,००० रु० तक की रकम। इन सब रकमों को मृतक की कुल सम्पत्ति में तो जोड़ा जायगा किन्तु इन पर रिबेट (Rebate) दिया जाता है। यदि एक मृत्यु के ३ महीने के भीतर दूसरी मृत्यु हो जाय तो केवल पहली मृत्यु पर ही मृत्यु कर लिया जायगा अन्य पर नहीं।

मृत्यु कर के लाभ

(१) मृत्यु कर समाजवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदल समझा जाता है। इस कर के द्वारा धन के वितरण की असमानताओं को अधिक क्षीघ्रता के साथ दूर किया जा सकता है। इस कर की प्रवृत्ति पूँजी तथा धन को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से रोकने की होती है।

(२) यह कर आय कर का सहायक है। आय कर से लोग अपने को बचा सकते हैं किन्तु मृत्यु कर से बचना सम्भव नहीं होता। यदि दोनों करों को एक साथ लगाया जाता है तो लोगो का कर से बचना मुश्किल हो जाता है।

(३) इस कर का जनता की काम करने की इच्छा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब उत्तराधिकारियों को यह मालूम हो जाता है कि उन्हें अधिक सम्पत्ति नहीं मिलने जा रही है तो उनमें काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

(४) आय कर उस उपयोगिता को ध्यान में नहीं रखता जो व्यक्ति को सम्पत्ति का मालिक होने से मिलती है। सम्पत्ति का मालिक होने से लोगों को सम्मान प्राप्त होता है जिसका ध्यान आय कर लगाते समय नहीं रखा जाता। मृत्यु कर इन विशेष उपयोगिता को ध्यान में रखता है।

मृत्यु कर के दोष

मृत्यु कर में कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं—(i) इसका भार उन परिवारों पर अधिक पड़ता है जिनमें जल्दी-जल्दी मृत्यु होने के कारण बार-बार सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता रहता है। (ii) कर को लगाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई है। सभी प्रकार की

सम्पत्ति पर एक दर से कर लगाया जाता है। कुछ सम्पत्ति ऐसी होती है जिसे प्राप्त करने में अधिक परिश्रम तथा व्यय करना पड़ता है तथा कुछ को प्राप्त करने में कम। (iii) इस कर का पूँजी के संचय पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उत्पादन को नुकसान पहुँचता है। (iv) हमारे यहाँ न्यूनतम छूट की सीमा बहुत ऊँची रखी गई है। अन्य देशों में यह ३० ००० रु० के लगभग है। (v) कर की वर्तमान दरों से अधिक मूल्य की जायदाद वालों पर कर का भार कम है।

मृत्यु कर से हमारे देश में बहुत अधिक आय प्राप्त नहीं की जा रही है। सन् १९५४-५५ में केवल ८ लाख रुपए इस कर से प्राप्त हुआ। १९५६-५७ में ३० लाख रुपया प्राप्त किया गया। १९६२-६३ में मृत्यु कर से केवल १२ लाख रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है।

(४) धन पर कर (Wealth tax)—प्रो० कॉल्डर (Kaldor) की सिफारिशों के आधार पर यह नया कर सन् १९५७ से लगाया गया। यह कर व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों सभी के धन पर लगाया जाता है। सन् १९६० से कम्पनियों को इस कर से मुक्त कर दिया गया है। कर प्रगतिशील दर (Progressive rate) से लगाया जाता है। व्यक्तियों के सम्बन्ध में न्यूनतम छूट की सीमा २ लाख रुपए है तथा मिश्रित परिवारों के लिए यह सीमा ४ लाख रुपए रखी गई है।

व्यक्तियों के लिए कर की दर इस प्रकार है—

छूट सीमा से ऊपर पहले १० लाख रुपए तक	१ प्रतिशत
१० लाख से ऊपर तथा २० लाख रुपए तक	१ प्रतिशत
२० लाख से ऊपर	१ १/२ प्रतिशत

मिश्रित परिवारों के लिए—

४ लाख से ऊपर ६ लाख रुपए तक	१ प्रतिशत
६ लाख से ऊपर १६ लाख रुपए तक	१ प्रतिशत
१६ लाख से ऊपर	१ १/२ प्रतिशत

कुछ प्रकार की सम्पत्ति को कर से मुक्त रखा गया है— (i) कृषि सम्पत्ति, (ii) धार्मिक अथवा दान देने वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति, (iii) ग्रामीण रहने के मकान, (iv) कला की वस्तुएँ, (v) २५,००० रुपये तक व्यक्तिगत वस्तुएँ, जैसे फर्नीचर, कार, गहने आदि, (vi) भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का वह धन जो विदेशों में स्थित है।

इस कर से सरकार को बहुत अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकी है। सन् १९५७-५८ में केवल ७.०४ करोड़ रुपया प्राप्त किया गया तथा १९५९-६० में १२.११ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। सन् १९६२-६३ में इस कर से केवल ६ करोड़ रुपये की धामदनी प्राप्त होने का अनुमान है।

धन-कर के पक्ष में अनेक तर्क दिये जा सकते हैं—यह कर लोगों की आय को छिपाने की संभावना को कम कर देगा तथा कर अपवचन (Tax Evasion) कम हो

जायगा। इस कर के द्वारा धन की असमानताओं को दूर किया जा सकेगा और यह कर समाजवाद की दशा में एक पग होगा। इस कर के लगने से भारत सरकार को आय का एक नया स्रोत प्राप्त हो जायगा। भारतवर्ष में यह कर अधिक सफल नहीं हो सका है और सरकार को इसमें प्राप्त होने वाली आय बहुत कम है। इस कर के अन्य लाभ भी हमारे देश में प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।

(५) उपहार-कर—उपहार-कर भारतवर्ष में सन् १९५८ से लगाया गया। यह कर भी प्रो० कालदोर (Kaldor) की मिश्रारिणों के आधार पर लगाया गया है। कर को लगाने का प्रमुख उद्देश्य अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपवचन को रोकना है। यह कर व्यक्तियों, सम्मिलित हिन्दू परिवारों, कम्पनियों तथा संस्थाओं पर लगाया जाता है। उपहार-कर करारोपण से पूर्व वर्ष में दिये गये उपहार के मूल्य पर लगाया जाता है। करारोपण के लिये उपहार के बाजार-मूल्य को लिया जाता। ५०,००० रु० से कम कीमत के उपहार पर कोई कर नहीं लिया जाता। इससे ऊपर ५०,००० रु० तक ४% की दर से लगाया जाता है, अगले ५०,००० रु० पर कर की दर ८% और इसी प्रकार कर की दर उपहार के मूल्य के साथ-साथ बढ़ती जाती है। कर की अधिकतम दर ४०% है जो ५० लाख रुपये में ऊपर की सम्पत्ति पर लिया जाता है। कर चुकाने का प्रथम उत्तरदायित्व उपहार देने वाले पर है किन्तु उपहार प्राप्त करने वाले को भी चुकाने के लिए उत्तरदायी रखा गया है।

कुछ प्रकार के उपहारों को कर से छूट दी गई है जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—(i) केन्द्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकारों को प्राप्त होने वाले उपहार, (ii) धार्मिक संस्थाओं को प्राप्त होने वाले उपहार, (iii) स्त्री-प्राथितों को विवाह के समय मिलने वाला उपहार जिसकी अधिकतम सीमा १०,००० रु० रखी गई है, (iv) पत्नी तथा ससुराल को मिलने वाला १०,००० रुपये तक का उपहार, (v) प्राथितों को मिलने वाला बीमा पालिसी का उपहार जो अधिक से अधिक १०,००० रु० तक हो सकता है, (vi) अचल सम्पत्ति जो देश से बाहर हो यदि उपहार देने वाला भारतीय नागरिक नहीं है।

(६) आयात-निर्यात कर—आजकल प्रत्येक देश बाहर से आने वाली वस्तुओं पर तथा देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाता है। आयात-कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनका बाहर से देश में आयात किया जाता है। निर्यात-कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश से बाहर भेजी जाती हैं। इन करों के लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं—(i) ग्रामदानी प्राप्त करना तथा (ii) उद्योगों को संरक्षण देना। यह कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है—(अ) वस्तु की मात्रा पर (Specific Duty) तथा (ब) वस्तु के मूल्य पर (Ad Valorem) कम मूल्यवान वस्तुओं पर कर उनकी मात्रा

के अनुसार लगाया जाता है तथा मूल्यवान् वस्तुओं जैसे रेडियो, घड़ी, सोना, चाँदी, कार इत्यादि पर यह कर उनके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है ।

आरम्भ में भारतवर्ष की नीति स्वतन्त्र व्यापार की नीति थी और किसी प्रकार के सीमा-कर नहीं लगाये जाते थे । सन् १९२२ में सरकार ने सरक्षण की नीति को अपना लिया और बहुत सी आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाने लगा । १९३३ में भारत ने साम्राज्य अधिमान नीति (Imperial Preference) को अपना लिया जिसके कारण विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई और भारत सरकार की आय सीमा कर से बढ़ने लगी । भारतवर्ष में सीमा-कर आय प्राप्त करने तथा उद्योगों को सरक्षण देने, दोनों ही उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है ।

सीमा-कर भारत सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है । काफी लम्बे समय तक केन्द्रीय बजट में सीमा-कर का प्रथम स्थान रहा है किन्तु अब केन्द्रीय उत्पादन कर से होने वाली आमदनी ने इसे पीछे छोड़ दिया है । आयातों पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण अब इससे होने वाली आय को बढ़ाने का क्षेत्र सीमित हो गया है । सन् १९३६-४० में सरकार को इससे केवल ४३.९ करोड़ रुपये की आमदनी हुई किन्तु १९५०-५१ में यह बढ़ कर १५७.१५ करोड़ रुपये हो गई । सन् १९६२-६३ के बजट में इस साधन से होने वाली अनुमानित आय २०७.४० करोड़ ६० है । यद्यपि सरकार को इस मद से काफी आमदनी हो रही है किन्तु आय का यह साधन काफी अनिश्चित है । इससे होने वाली आय सरकार की आयात-निवृत्त नीति, विदेशी विनिमय की उपलब्धता, जहाजी सुविधायें तथा वस्तुओं की माँग व पूर्ति पर निर्भर होती है ।

(७) केन्द्रीय उत्पादन-कर (Central Excise Duties)—भारत सरकार बहुत सी उन वस्तुओं पर कर लगाती है जो भारत में पैदा होती हैं जैसे चाय, वनस्पति तेल, तम्बाकू, दियासलाई, मोटर-टायर, स्प्रिट, सूती कपड़ा, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, साबुन, जूते इत्यादि । इस कर को लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं—(१) आय प्राप्त करना तथा (२) कुछ हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को कम करना और लाभपूर्ण वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाना । सन् १९५७ से इस कर में काफी परिवर्तन किया गया है । उस समय वित्त-मन्त्री ने बताया कि इसको लगाने का हमारा उद्देश्य वस्तुओं के उपभोग को कम करना है जिससे मुद्रा-प्रसार के दबाव को कम किया जा सके तथा विनियोग के लिए अधिक धन प्राप्त किया जा सके । यह कर प्रायः आवश्यकताओं की वस्तुओं पर लगाया जाता है । उत्पादन कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भार गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है । इसीलिये कर लगाने के लिये वस्तुओं का ठीक चुनाव करना काफी महत्वपूर्ण है । इस कर को उन वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिये जिनका उपभोग अधिकांश धनी वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता हो ।

आरम्भ में इस कर से भारत सरकार की आमदनी बहुत कम थी और सन् १९३६-४० में केवल ६ करोड़ रुपये ही प्राप्त किया जा सका था किन्तु

१५५-५६ में यह आमदनी बढ़ कर १४५ करोड़ रुपये हो गई। सन् १९६२-६३ के बजट के अनुसार सरकार को उत्पादन-कर से ५२६ करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। इस कर से होने वाली आय में इतनी तेजी से वृद्धि होने का कारण वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होना तथा अनेकों नई वस्तुओं पर कर लगाया जाना है। इस कर से होने वाली आमदनी का कुछ भाग राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है।

गैर-कर आगम :

करारोपण के अतिरिक्त भारत सरकार को अन्य साधनों से भी काफी आय प्राप्त होती है। सन् १९६२-६३ में सरकार को गैर-कर साधनों से ३४६.८६ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है जो कुल आय का २८.६ प्रतिशत है। भारत सरकार की गैर-कर आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—

(१) मुद्रा और टंकाल (Currency and Mint)—इस शीर्षक के अन्तर्गत उम आय को दिसलाया जाता है जो सरकार को सिक्के ढालने तथा नोटों के छापने से प्राप्त होती है। यद्यपि यह आय सरकार को १८६८ से प्राप्त हो रही है किन्तु सन् १९३५ के पश्चात् इस मद में होने वाली आय में काफी वृद्धि हुई है। सन् १९४६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण इस साधन से होने वाली आय में और अधिक वृद्धि हुई है। भारत सरकार की आय का यह एक नियमित तथा महत्वपूर्ण साधन है। सन् १९३६-४० में सरकार को इस मद से केवल ३७ लाख रुपये की आय प्राप्त हुई थी किन्तु सन् १९५५-५६ में यह बढ़कर २३.१७ करोड़ रुपये हो गई। सन् १९६२-६३ के बजट के अनुसार सरकार को करसी तथा मिन्ट से ४६.३ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

(२) डाक तार विभाग (Posts & Telegraphs)—भारत सरकार को डाक तार विभाग से भी कुछ आय प्राप्त होती है। इस विभाग को जो कुल आमदनी प्राप्त होती है उसमें से खर्च निकाल कर शुद्ध आय को सामान्य आगम (General Revenues) में जोड़ दिया जाता था। कुछ समय पूर्व भारत सरकार को इस विभाग से काफी आमदनी प्राप्त होती थी सन् १९४२ से लेकर १९४५ यह विभाग प्रति वर्ष १० करोड़ रुपये सरकार को देता रहा किन्तु इसके पश्चात् विभाग का विस्तार हो जाने के कारण यह आमदनी काफी कम हो गई। सन् १९५५-५६ में केवल ७० लाख रुपये की आय सरकार को इस विभाग से प्राप्त हुई है। १९६२-६३ में इस मद से ७६ करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।

(३) रेलों में आमदनी—रेलें भारत सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। सर्वप्रथम सन् १९०० में रेलों ने कुछ लाभ उत्पन्न किया। इसके पश्चात् सन् १९३० तक रेलों को अच्छा मुनाफा होता रहा किन्तु अवसाद काल में इसे नुकसान होने लगा। दूसरे विश्व युद्ध काल में भी रेलों को भारी लाभ हुआ। रेलवे बजट के केन्द्रीय बजट से अलग हो जाने के पश्चात् विभिन्न समझौते किये गये जिनके अनुसार रेलों को अपने लाभ का कुछ भाग केन्द्रीय आगम में देना पड़ता है।

सन् १९४७-४८ से पूर्व रेलवे से भारत सरकार को काफी आमदनी मिलती थी किन्तु उसके पश्चात् इस मद से होने वाली वार्षिक आय ५ और ७ करोड़ रुपये के बीच में रही है। दूसरे युद्ध बाल में रेलों ने कुल मिला कर १५८ करोड़ रुपया केन्द्रीय बजट को दिया। सन् १९५५-५६ में सरकार को इस मद में ६१५ करोड़ रुपये प्राप्त हुये और १९६२-६३ में २१ करोड़ रुपया प्राप्त होने की आशा है।

(४) नागरिक कार्यों से आय—भारत सरकार को जो आय केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (Central P. W. D.), सिंचाई आदि से प्राप्त होती है उसे इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। सन् १९५०-५१ में सरकार को इस मद में १२.५३ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। बजट अनुमान के अनुसार १९६२-६३ में सरकार को इस मद से ५०.३८ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

(५) अन्य साधन—इसके अन्तर्गत सरकारी भूमि तथा भूकानों से आमदनी, जंगलों से आय, रजिस्ट्रेशन में आय मोटर गाड़ियों के अनुज्ञापन शुल्क आदि सम्मिलित हैं। सन् १९५०-५१ में इस शीर्षक से १३.१७ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई जो १९६०-६१ में बढ़ कर ३५ करोड़ रुपया हो गई। सन् १९६२-६३ में इससे २२३ करोड़ रुपये की आमदनी प्राप्त होने का अनुमान है।

भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदें :

भारत सरकार अपनी आय को किन्-किन मदों पर व्यय करती है, इसे निम्न-लिखित तालिका द्वारा जाना जा सकता है :—

संघ सरकार की व्यय की मदें

(करोड़ रुपयों में)

मदें	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३ (बजट अनुमान)
कर एकत्रित करने पर व्यय	२२.४३	२१.१४	२२.५८
नागरिक शासन	५८.६६	६०.००	७०.३१
सुरक्षा सेवार्थ (शुद्ध)	२४७.५५	३०१.६८	३४३.३७
कृषि सम्बन्धी व्यय	७७.०६	८६.१०	२४७.६०
पेन्शन इत्यादि	१०.०४	१०.४६	१०.४६
असाधारण व्यय	३.६८	१३.५५	४१.१०
मिला जुला व्यय (Miscellaneous)	११७.८२	६०.०६	८५.८१
सामाजिक और विकास सेवार्थ	२३६.४०	१८५.०८	१९४.११
राज्यों को अनुदान आदि	४८.५५	२०२.७६	२१६.६१
अन्य व्यय	३.६६	३.२५	३.८४
कुल व्यय	८२६.२१	९४४.३७	१२३६.०६

Figures taken from the 'Report on Currency and Finance'—
1961-62 (Reserve Bank of India).

(१) सेना पर व्यय (Defence Expenditure)—प्रत्येक राष्ट्र को आन्तरिक सुरक्षा तथा विदेशी आक्रमण से बचाव करने के लिये अपनी आय का काफी बड़ा भाग सेना आदि पर व्यय करना पड़ता है। भारतवर्ष में आरम्भ से ही सुरक्षा पर काफी व्यय किया जाता रहा है। ब्रिटिश काल में सुरक्षा पर अधिक व्यय होने के कई कारण थे—भारत में बहुत बड़ी सेना रखी जाती थी जिसकी वास्तव में यहाँ आवश्यकता नहीं थी। सेना में अधिकांश अफसर अंग्रेज होते थे जिन्हें बहुत ऊँचा वेतन दिया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की मर्यादा काफी अधिक थी। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों में सदा भय रहता था कि वह उपद्रव न कर दें जिसके कारण उन्हें काफी अधिक सेना रखनी पड़ती थी। भारत में रहने वाली सेना केवल भारत की सुरक्षा के लिये ही नहीं थी बल्कि वह हम समस्त क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिये प्रयोग की जाती थी। दूसरे युद्ध काल में भारत का सुरक्षा सम्बन्धी व्यय और भी अधिक बढ़ गया क्योंकि भारत को अपने तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में रखने पड़े।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् यह आशा की जाती थी कि अब देश का सुरक्षा पर व्यय काफी कम हो जायगा। युद्ध की वशायें समाप्त हो जाने के कारण अब अधिक सेनाएँ रखना आवश्यक नहीं था तथा पाकिस्तान बन जाने के कारण अब भारत को कम क्षेत्र की रक्षा करना पड़ती थी। किन्तु पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का बिगड़ जाना, काश्मीर समस्या तथा चीनी सतरे के कारण आज भारत को सुरक्षा पर पहले की अपेक्षा काफी अधिक खर्च करनी पड़ रही है। सरकार को अपनी कुल आय का लगभग ४० प्रतिशत सुरक्षा पर व्यय करना होता है। सन् १९६०-६१ में भारत सरकार को अपने ६२१-६२ करोड़ रुपये के बजट में से २८२-६२ करोड़ रुपये सुरक्षा पर व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त ३२ करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय भी किया गया। सन् १९६२-६३ में ३४३-३७ करोड़ रुपये सुरक्षा पर व्यय किये जाने का अनुमान है। अभी हाल में चीनी आक्रमण के कारण भारत सरकार ने सुरक्षा पर अपना व्यय बहुत अधिक बढ़ा दिया जिसके लिये लगभग ७५ करोड़ रुपये की पूरक मांग सुरक्षा व्यय के लिये स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सम्बन्धी पूँजीगत व्यय भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है।

(२) नागरिक शासन (Civil Administration)—भारत सरकार को नागरिक शासन पर अपनी आय का काफी बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। इसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, मजदूर मन्त्री तथा मन्त्रालयों सम्बन्धी व्यय, न्याय, जेल तथा पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी विभाग तथा विदेशों में दूतावास पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है। ब्रिटिश काल में भी नागरिक शासन पर काफी व्यय होता था। युद्ध से पूर्व इस मद पर लगभग ११ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किया जाता था किन्तु युद्ध काल में यह बढ़ कर ६० करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण सरकारी विभागों का विस्तार तथा सरकारी कर्मचारियों

की मंख्या में वृद्धि थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् नागरिक शासन पर व्यय काफी तेजी के साथ बढ़ा है क्योंकि ससद सदस्यों तथा मन्त्रियों की मंख्या बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास स्थापित किये गये हैं। देश में आर्थिक नियोजन तथा विनाम सण्डों की स्थापना के कारण भी यह व्यय काफी बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में नागरिक शासन पर किया जाने वाला व्यय १११.७६ करोड़ रुपये था। इस मद पर व्यय के सम्बन्ध में काफी आलोचना की जाती रही है। प्रायः यह कहा जाता है कि इस मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है क्योंकि राज्य कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की मंख्या में आवश्यक रूप से वृद्धि हुई। विदेशी दूतावासों पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है। इस मद पर सरकारी व्यय को कम करने की काफी गुंजाइश है और सरकार को इस दिशा में निश्चित कदम उठाने चाहिये।

(१) सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी व्यय (Debt Services)—भारत सरकार को युद्ध के कारण तथा देश के आर्थिक विकास के लिये समय-समय पर जनता से ऋण लेने पड़े हैं। इन ऋणों पर सरकार को व्याज देना पड़ता है तथा अन्य प्रकार के व्यय भी करने होते हैं। सन् १९२६ में भारत सरकार को सार्वजनिक ऋणों पर १२ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्याज के रूप में देना पड़ता था। युद्ध काल में इन ऋणों की मात्रा काफी बढ़ गई। युद्ध के पश्चात् भी सार्वजनिक ऋणों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है क्योंकि सरकार को आर्थिक विकास के लिये काफी मात्रा में ऋण लेने पड़े हैं। सन् १९५५-५६ में सरकार को ऋणों के सम्बन्ध में ४३.१४ करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा। १९६२-६३ में इस मद पर २४७.६० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(२) सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाएँ (Social & Developmental Services)—भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य में सरकार सामाजिक तथा आर्थिक निर्माण के कामों पर बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय कर रही है। इस मद के अन्तर्गत मिर्चाई तथा बहुमुखी योजनाएँ, वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सहकारिता, सामुदायिक विकास, विजली योजनाएँ आदि पर किया जाने वाला व्यय आ जाता है। इस मद पर किया जाने वाला व्यय पिछले दस वर्षों में काफी तेजी के साथ बढ़ा है। सन् १९४६-५० में इन पर ३६.५० करोड़ रुपये व्यय किया गया। १९६२-६३ में १९४.११ करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

(५) राज्यों को अनुदान (Grants to States)—भारत सरकार को अपनी प्रायः से राज्य-सरकारों को अनुदान भी देने होते हैं जिससे कि वे अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें। यह अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान व सड़कों का निर्माण, बाढ़ योजना तथा अन्य स्वीकृत योजनाओं के लिए दिए जाते हैं। प्रायः जितनी रकम केन्द्रीय सरकार देती है उतनी ही राज्य सरकारों को अपने पास से खर्च करनी होती है।

परीक्षा प्रश्न

Describe the main features of the financial resources from taxation of the Union Government of India. Suggest suitable remedies for their improvement. (Agra B A. & B Sc 1961)

भारतीय सरकार के कर-स्थापन के आय सम्बन्धी साधनों के मुख्य लक्षणों को बताइये। उनके सुधारने के योग्य उपाय संकेत कीजिये।

2. Adjudge the merits of the Indian Income Tax in the light of Canons of Taxation. (Agra B A. & B Sc. 1951)

करारोपण के सिद्धान्तों की ध्यान में रखते हुए, भारतीय आय कर के गुणों की व्याख्या कीजिये।

3. Write brief notes on three of the most productive taxes of the Indian Government. (Agra B A. & B Sc. 1948)

भारतीय सरकार के तीन सबसे अधिक उत्पादक करों पर संक्षेप नोट लिखिये।

4. Write a note on the position of Income Tax in the Indian Tax System (Agra B A. & B. Sc 1947)

भारतीय कर-प्रणाली में आय-कर के स्थान पर एक नोट लिखिये।

5. What are the heads of Income and Expenditure of the Central and a Provincial Government in India. Write an explanatory note on each of them. (Agra B A. & B Sc 1945)

केन्द्रीय तथा एक प्रांतीय सरकार की आय तथा व्यय की मूर्तों को बताइये तथा उनमें से प्रत्येक की व्याख्या कीजिये।

6. What are the main sources of Income and heads of Expenditure of the Union Government of India? Write a critical note on any two of the items (Rajasthan 1951)

भारत सरकार के आय के साधन तथा व्यय की मूर्तें क्या हैं? उनमें से किन्हीं दो पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिये।

भारत में राज्य अर्थ-प्रवन्ध

State Finances in India

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यों को निश्चित कार्य तथा अधिकार सौंप दिये गये हैं। प्रत्येक राज्य को कार्य संचालन की सुविधा दी गई है। कुछ विषय केन्द्र सरकार को दे दिये गये हैं तथा कुछ विषय राज्य सरकारों के लिये निश्चित कर दिये गये हैं। इन विषयों से सम्बन्धित कार्य करना राज्यों का उत्तरदायित्व है। राज्यों की आय के साधन भी केन्द्रीय सरकार की आय के साधनों से वृद्ध कर दिये गये हैं। संविधान के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा लगाये जाने वाले कर इस प्रकार हैं—मालगुजारी, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, भूमि तथा मकानों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, अफीम, शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर कर, स्थानीय क्षेत्र में उपभोग के लिये आने वाली वस्तुओं पर कर, बिजली के उपभोग तथा बिक्री पर कर, बिक्री कर, अस्त्रधार विज्ञापन पर कर, व्यवसायो तथा व्यापार पर कर, विलासिताओं पर कर, स्ट्याम्प कर। राज्य सरकारों के व्यय की मदें भी लगभग सभी राज्यों में एकसी हैं। संविधान में जिन कार्यों को राज्य विषयों (State Subjects) के अन्तर्गत रक्खा गया है उन्हें पूरा करने के लिए व्यय करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य मूधी के अन्तर्गत मुख्यतः पुलिस, जेल, न्याय-प्रवन्ध, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पुल, खेती, जंगल, उद्योग, व्यापार आदि को रक्खा गया है। इन कार्यों से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य सरकारों को करना होता है। इसके अतिरिक्त कौन्वरेट सूची (Concurrent List) में सम्मिलित कार्यों पर भी राज्य सरकारों को व्यय करना पड़ सकता है। राज्य सरकारों को व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार हैं—(i) नागरिक शासन पर व्यय जिसके अन्तर्गत शासन, न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, उद्योग वगैरे आदि सम्मिलित हैं। (ii) कर प्राप्ति व्यय। (iii) मिचार्जी। (iv) सूद। (v) सिविल निर्माण कार्य। (vi) बिजली योजनायें आदि।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों को अप्रतिष्ठित तालिका द्वारा जाना जा सकता है—

राज्य सरकारों की आय

(लाख रुपयों में)

	१९५७—५८	१९५८—५९	१९५९—६०	१९६०—६१	१९६१—६२
कर-आय (Tax Revenue)					
भाय पर कर	८,१४०	८,४४४	८,८८०	९,८८८	९,९६३
सम्पत्ति तथा पूंजीगत सौदो पर कर	१२,४४०	१३,२१४	१४,१००	१३,४९१	१४,१२८
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	२६,४१८	३२,०३७	३४,७६०	३६,३११	३६,८६४
कुल कर आय	४७,१९८	५३,७०६	५७,७४०	६०,४९०	६१,१५६
नैर-कर आय (Non-Tax Revenue)					
नागरिक शासन	८,२०२	१०,४४९	१२,२६६	१४,२८३	१४,८८१
सार्वजनिक व्यवसाय	४,२९३	३,९६९	४,३४४	४,६७४	४,९४३
ग्राम्य आय	४,०४४	४,६४४	६,०१८	६,६११	६,३७४
अनुदान	७,४३४	८,८८१	१०,३१८	१४,९१८	२०,८८३
कुल नैर-कर आय	२३,९७३	२७,१४३	३२,६४७	४०,४८६	४०,९८१
कुल आय	७१,१७१	८१,२४९	९०,३८६	१०१,०४६	१०२,१३७

राज्य सरकारों का व्यय

(लाख रुपयों में)

भारत में राज्य अर्थ-प्रबन्ध

1 २२२

निधा	१३,०३६	१४,०२५	१७,०६०	१८,५८१	२१,६५५
स्वास्थ्य	५,१५७	५,७८५	६,७६६	८,२८६	९,२६५
कृषि तथा सहकारिता	४,६२३	५,१७५	६,२१०	६,८६६	८,२६७
सिंचाई	२,३७६	५,२४३	२,६४१	३,१५७	३,५५०
विजली	८६१	७२६	५०१	५५७	१०७
सामुदायिक विकास	३,१७०	३,६०६	४,३३६	५,३५६	५,५५५
सार्वजनिक निर्माण	५,०१२	५,४२०	५,५३३	७,०३७	७,३८०
उद्योग आदि	१,५३५	१,८०४	२,०७३	२,२८३	२,७६८
अन्य विकास सम्बन्धी व्यय	२,८३५	३,२२४	३,७५८	५,२०५	५,३८३
कुल विकास व्यय	३८,६०६	४२,३०८	४६,२२८	५८,२५०	६४,७५६
नैर-विकास सम्बन्धी व्यय	२६,७८३	३४,२०६	३७,७५२	४१,५३६	५०,६८७
कुल व्यय	६५,३८९	७६,५१४	८३,९८०	९९,७८६	१,०५,७३६
अतिरिक्त (Surplus) + या घाटा (Deficit) —	+२,७८२	+४,७४५	+३,७१६	+१,३८७	—३,५६६

उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि पिछले वर्षों में राज्य-
/रकारो की आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। पिछले पाँच वर्षों में इनकी आय लगभग
११० करोड़ रुपए बढ़ गई है। इन्हें प्राप्त होने वाली कुछ आय का अधिकांश
कर माधनो में प्राप्त होता है किन्तु गैर-कर आय साधनो में प्राप्त होने वाली आय भी
तेजी के साथ बढ़ी है। कर आय के माधनो में (i) सम्पत्ति तथा पूँजीगत मॉदो पर
कर तथा (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर मुख्य हैं। गैर-आय माधनो में (i) नागरिक
सामन तथा (ii) अनुदान मुख्य हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को प्राप्त होने वाले
अनुदान की मात्रा तेजी व साथ बढ़ी है जो इस बात को बतलाना है कि राज्यों की
केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता पहले की अपेक्षा अधिक होती आ रही है। इसका मुख्य
कारण योजना सम्बन्धी व्यय है जो राज्यों को आवधिक तथा सामाजिक विकास के
कार्यों पर करना पड़ रहा है। राज्य सरकारों का व्यय भी काफी तेजी के साथ बढ़ा
है। पिछले पाँच वर्षों में उनके व्यय में लगभग १७३ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई
है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सहायता, सामुदायिक विकास और सार्वजनिक
निर्माण में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई। १९६१-६२ के बजट अनुमानों के आधार
पर यह कहा जा सकता है कि आविकान व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व सहायता,
सार्वजनिक निर्माण व सामुदायिक विकास पर किया जा रहा है। राज्य सरकारों के
व्यय में वृद्धि उनकी आय की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ हुई है जिसके
कारण उनका बजट अतिरेक (Budget surplus) निरन्तर कम होता जा रहा है
और १९६०-६१ में राज्य सरकारों को ३६ करोड़ रुपए का घाटा रहन का
अनुमान है।

उत्तर प्रदेश सरकार की आय के माधन

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसकी आय तथा व्यय की
मदों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकन है। यद्यपि विभिन्न राज्यों की आय तथा व्यय
में पूर्ण समानता नहीं मिलती किन्तु फिर भी वह एक दूसरे से काफी मिलते हैं।
लगभग एक ही प्रकार के माधनो में विभिन्न राज्यों में आय प्राप्त की जाती है और
उनकी व्यय की मदें भी एक-सी हैं। इस प्रकार किसी भी बड़े राज्य की आय तथा
व्यय का अध्ययन करके राज्य सरकारों की आय तथा व्यय के बारे में ज्ञान प्राप्त
किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की आय की मदें

(लाख रुपयों में)

आय की मदें	१९६१-६२	१९६२-६३ अनुमान
१. मूलियन उत्पत्ति कर	१२६३.६०	१४८१.४१
२. आय कर (कॉरपोरेशन कर के अतिरिक्त)	१५८४.६०	१३३६.००
३. मृत्यु कर	४८.६३	६३.००
४. रेल भाडे पर कर	२३४.००	—
५. मालगुजारी (घुड)	२१५३.१६	२२१४.६५
६. राज्य उत्पादन कर	७७८.११	७६६.१३
७. स्टाम्प	४२५.००	४३५.००
८. जंगल	६१७.५३	६६२.२८
९. रजिस्ट्रेशन	७८.८५	७८.१७
१०. मोटर कर	३२५.३०	३४३.३०
११. विक्री कर	१३५०.७५	१३७०.००
१२. मन्य कर	६६२.१६	७६६.८८
१३. सिंचाई	२२८.६६	१२६३.५२
१४. सूद	५३७.१६	१२६३.३६
१५. नागरिक शासन—न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग	२३२१.५७	१२३८.८४
१६. विविध	२३५.३६	१४६८.४१
१७. सार्वजनिक निर्माण (Civil Works)	६२.३६	७१.८१
१८. केन्द्रीय सरकार से अनुदान इत्यादि ।	२२३६.०२	२८०२.६४
१९. सामूहिक विकास	१.००	१.११
कुल आय	१५,२१७.७८	१७,७१६.८४

राजस्व के सिद्धान्त एवं भारतीय राजस्व

व्यय की मदें	१९६१-६२	१९६२-६३ अनुमान
१. कर प्रान्ति पर व्यय	११५७.४२	११६१.५६
२. सिंचाई	७९६.६४	१८८७.७५
३. मूद	१६७२.४४	२४४५.०३
४. नागरिक शासन		
(i) शासन	११२१.६४	१२५०.१६
(ii) न्याय	१८८.११	२०२.३६
(iii) जेल	१६२.०८	१५७.०२
(iv) पुलिस	११६३.०७	११६५.६५
(v) वैज्ञानिक विभाग	१६.८६	२०.६०
(vi) शिक्षा	२३३०.४७	२४४६.१०
(vii) चिकित्सा	५३६.६८	५५६.८५
(viii) सार्वजनिक स्वास्थ्य	४४४.२७	४६८.१२
(ix) कृषि	४६८.१८	५०८.४२
(x) पशु चिकित्सा	२३६.०८	२५८.५८
(xi) सहकारिता	११२.८३	२०८.६८
(xii) उद्योग धन्धे	६०८.६४	८६१.६५
(xiii) त्रिविध विभाग	११६४.६३	१८३१.५२
५. सार्वजनिक निर्माण	७१३.३८	८३४.६४
६. विविध	१६२१.१६	१२४८.७४
७. असाधारण मदें—सामूहिक विकास इत्यादि	१०४१.१७	१००६.६७
कुल व्यय	१५,६६७.११	१८,८१०.०६
अतिरिक्त (Surplus) (+) घाटा (Deficit) (-)	-४४६.३३	-१०६०.२२

Note :—Figures taken from India 1962.

भ्राय की मुख्य मदों का संक्षिप्त वर्णन—उत्तर प्रदेश सरकार की भ्राय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं—

(१) मालगुजारी (Land Revenue)—यह कर भूमि पर लगाया जाता है। इसलिये इसे भूमि कर भी कहते हैं। भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से ही भूमि कर लगाने की व्यवस्था रही है। हिन्दू राजाओं के जमाने में कुल उपज का $\frac{1}{6}$ से लेकर $\frac{1}{12}$ भाग इस कर के रूप में लिया जाता है और कर को प्रायः वस्तुओं के रूप में वसूल किया जाता था। मुगल बादशाहों के काल में भूमि कर रूपों में वसूल किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इस कर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जिनके आधार पर उसे आज तक वसूल किया जाता है।

भूमि कर राज्य सरकारों की भ्राय का एक महत्वपूर्ण साधन है। सन् १९३६-४० में उत्तर प्रदेश सरकार की भ्राय का ५०% भाग मालगुजारी से प्राप्त किया गया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार की भ्राय इस कर से बहुत अधिक बढ़ गई है। सन् १९६२-६३ में सरकार को इस कर से २२.१५ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। मालगुजारी से प्राप्त होने वाली भ्राय का अधिकांश भाग जमींदारों को मावजा देने के लिये काम में लाया जाता है। स्याई बन्दोबस्त वाले राज्यों में इस मद से प्राप्त होने वाली भ्राय लगभग निश्चित रहती है किन्तु स्याई बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में ६० या ४० साल की अवधि के पश्चात् नया बन्दोबस्त होता है जिसके कारण इस कर में वृद्धि हो सकती है।

भूमि कर करारोपण के कुछ सिद्धांतों को बहुत अच्छी प्रकार पूरा करता है—

(i) यह कर निश्चित है—मालगुजारी की दरें एक बार बन्दोबस्त के द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं और फिर उनमें ३० या ४० साल तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार सरकार को इस कर से निश्चित आमदनी प्राप्त होती रहती है। सरकार और करदाता दोनों ही कर की मात्रा को जानते हैं, अतः भूमिकर निश्चितता के सिद्धांत के अनुकूल है। (ii) भूमि कर सुविधापूर्ण है—सुविधा की दृष्टि से भूमि कर को एक अच्छा कर कहा जाता है। किसानों के लिए इस कर का भुगतान करना सुविधाजनक होता है क्योंकि कर फसल कटने के मौके पर लिया जाता है। कर को एक साथ अथवा किस्तों में भी दिया जा सकता है। कभी कभी सरकार इस कर को वस्तुओं के रूप में देने की सुविधा भी दे देती है। (iii) यह कर मितव्ययिता पूर्ण है—क्योंकि इसे एकत्रित करने पर सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। जमींदारी उन्मूलन से पूर्व कर इकट्ठा करने का व्यय कुल भ्राय का लगभग १५% आता था किन्तु अब यह कर २८% हो गया है जिसके कारण अब इस कर को अधिक मितव्ययिता पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

दोष—भूमि कर में उपरोक्त गुणों के होते हुए भी कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण इस कर का अधिक पसन्द नहीं किया जाता है। कर के कुछ प्रमुख दोष इस

कर हैं—(i) लोच का अभाव—इस कर में लोच का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता। जोकि कर से प्राप्त आय की आसानी के साथ घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता। निवल नये बंदोबस्त के द्वारा ही इसमें वृद्धि हो सकती है जो काफी लम्बे समय के पश्चात् किया जाता है। (ii) यह कर समता के सिद्धान्त को सन्तुष्ट नहीं करता। कर लगाते समय किसानों की कर दान क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाता जिसके कारण इस कर को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। (iii) उत्पादक नहीं है—भूमि कर से सरकार को बढ़ती हुई आय प्राप्त नहीं होती। कर की दरें निश्चित होने के कारण, भूमि से उपज बढ़ने पर भी सरकार को उतनी ही आय प्राप्त होती रहती है। (iv) कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है। भूमि कर सभी लोगों पर एक दर से लगाया जाता है जिसके कारण वह कर प्रतिगामी (Regressive) हो जाता है। इनमें से अधिकांश दोष इपि आय कर (Agricultural Income Tax) लगाने से काफी सीमा तक दूर हो गये हैं।

(२) राज्य आबकारी कर (State Excises)—राज्य सरकारों को शराब, चाँद, गाँगा, चरम आदि नशीली वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार है। इस कर का उद्देश्य आय प्राप्त करना न होकर इन हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग को कम करना है। किन्तु फिर भी आबकारी कर राज्य सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन मादक वस्तुओं के विक्रेताओं को सरकार से लाइसेंस (Licence) प्राप्त करना होता है जिसके लिये उन्हें सरकार को काफी रकम लाइसेंस शुल्क (Licence fee) के रूप में देनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस मद से काफी आय प्राप्त होती रही है। किन्तु मद्य-निषेध की नीति के कारण अब यह आय कम होती जा रही है। वर्ष १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश सरकार को आबकारी कर से ७६ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा है।

(३) स्टाम्प कर (Stamp duty) — उत्तर प्रदेश सरकार को स्टाम्प कर से १९६२-६३ में ४.३ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा। यह कर दो प्रकार का होता है—(i) न्यायिक मुद्राक कर (Judicial Stamp Duty) जो माल तथा फौजदारी के मुकदमों लड़ने के लिये लिया जाता है। (ii) व्यापारिक मुद्राक कर (Commercial Stamp Duty) जो व्यापारिक पत्रों (विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों तथा प्रसविदा पत्रों) आदि के सम्बन्ध में लिया जाता है।

स्टाम्प कर करारोपण के कुछ विधायकों को अनुपसृत करता है। यह कर सुविधापूर्ण तथा मितव्ययी है। इस कर को देते समय कर-दाताओं को असुविधा नहीं होती। निश्चितता (Certainty) की दृष्टि से भी इस कर को अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि कर-दाता को यह पता रहता है कि उसे कितना कर देना है। इस कर में कुछ दोष भी पाये जाते हैं—(i) स्टाम्प कर व्यापार, उद्योग तथा सम्पत्ति के हस्तान्तरण में बाधाएँ उत्पन्न करता है। (ii) न्याय की दृष्टि से यह कर उचित नहीं है क्योंकि इसे तब लिया जाता है जब लोग अपनी सम्पत्ति को बेचते हैं और सम्पत्ति प्रायः

मुसीबत के समय बेची जाती है। इन दोषों के होते हुए भी इस कर को आय का अच्छा साधन माना जाता है।

(४) रजिस्ट्रेशन (Registration)—उत्तर प्रदेश सरकार को रजिस्ट्रेशन में १९६२-६३ में ७८.१७ लाख रुपये की आय प्राप्त होने की आशा है। इस मद से सरकार की आमदनी बढ़ रही है। सन् १९५५-५६ में इससे केवल २८८ लाख रुपये की आमदनी प्राप्त हुई थी। रजिस्ट्रेशन फीस आवश्यक कागजों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ली जाती है। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रलेख हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से इन कागजों के सम्बन्ध में भविष्य में की जाने वाली अदालती कार्यवाही अधिक मजबूत हो जाती है।

(५) बिक्री कर (Sales Tax)—यह कर वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है और इसे अधिवाज रूप में दुकानदारों से वसूल किया जाता है। भारतवर्ष में यह कर सर्वप्रथम १९३७ में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर आरम्भ १९४८ में किया गया। यद्यपि आरम्भ में इस कर से बहुत अधिक आमदनी नहीं होती थी किन्तु अब यह राज्य सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सन् १९५३-५४ में इस कर से केवल ५.६ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी किन्तु १९६२-६३ में बिक्री कर से प्राप्त होने वाला आय का अनुमान १३.७ करोड़ रुपये है। यद्यपि इस कर को अधिक अच्छा कर नहीं समझा जाता किन्तु फिर भी उत्पादकता की दृष्टि से इसका प्रयोग राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है।

बिक्री कर में अनेकों दोष पाये जाते हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—
 (i) यह कर प्रतिगामी (Regressive) है—सभी लोगों से कर एक ही दर से लिया जाता है जिसके कारण कर का भार गरीब लोगों पर बहुत अधिक पड़ता है तथा अमीर लोगों पर कम। इस दोष को दूर करने के लिये आवश्यक है कि कर केवल ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाय जिनका प्रयोग अधिकांश रूप से निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा न किया जाता हो। (ii) इस कर में दोहरे करारोपण (Duble Taxation) की सम्भावना अधिक है—बिक्री कर से सम्बन्ध में यह सम्भव है कि एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बार कर देना पड़ जाय। (iii) व्यापारियों के लिये असुविधापूर्ण है—बिक्री कर को सुविधा की दृष्टि से अच्छा कर नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यापारियों को प्रत्येक ग्राहक से कर वसूल करना होता है जिसके कारण हिसाब-किताब का काम काफी बड़ जाता है। (iv) व्यापारी इस कर से आसानी के साथ बच जाते हैं—व्यापारियों के हिसाब-किताब की ठीक जाँच करना सम्भव नहीं होता। व्यापारी प्रायः दो प्रकार के हिसाब रखते हैं और झूठा हिसाब दिखला कर इस टैक्स से बच जाते हैं। कर अपवचन के कारण सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। (iv) बिक्री कर मितव्ययितापूर्ण भी नहीं है क्योंकि इसे एकत्रित करने में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है।

इन दोषों के होते हुये भी बिक्री कर में कुछ ऐसे गुण पाये जाते हैं जिनके कारण राज्य सरकारें इस कर को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। इस कर का कुछ

॥ इस प्रकार हैं—(i) ग्राहकों को कर देने में कोई असुविधा नहीं होती—कर के समय वे यह महसूस भी नहीं करते हैं कि उनसे कर के रूप में कुछ लिया जा रहा है। (ii) इस कर से सरकार को काफी आमदनी प्राप्त होती है—राज्य सरकारों को प्रायः का यह एक अच्छा साधन है और उनके बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने में बड़ी सहायता देता है। बिक्री कर की उत्पादकता उसका सबसे बड़ा गुण है जिसके कारण वह अधिक प्रचलित होता जा रहा है। (iii) सरकार को कर एकत्रित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में कर दुबानदार इकट्ठा करते हैं और सरकार उसे केवल व्यापारियों से वसूल करती है।

करारोपण जांच आयोग (Taxation Enquiry Commission) ने बिक्री कर के दोषों को दूर करने तथा कर अपवचन की सम्भावना को कम करने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। आयोग ने विचार से बिक्री कर एक-बिन्दु कर (Single Point Tax) तथा बहु-बिन्दु कर (Multiple Point Tax) दोनों ही रूप में लगाया जाना चाहिये। सभी वस्तुओं पर मीची दर से बहु-बिन्दु कर लगाया जाना चाहिये। तथा छूट बहुत कम दी जानी चाहिये। कुछ निश्चित वस्तुओं पर ऊँची दर से एक बिन्दु कर लगाया जाना चाहिये। आयोग के विचार में कर को कम आय वाले वर्गों तक पहुँचाना आवश्यक है क्योंकि तब ही विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकारें पर्याप्त धन प्राप्त कर सकेंगी किन्तु इस वर्ग पर कर का भार कम से कम रखा जाना चाहिये और इसके साथ ही धनी वर्ग पर बिक्री कर का भार अधिक होना चाहिये। जिन वस्तुओं का प्रयोग निर्यून व्यक्ति करते हैं उन पर एक-बिन्दु कर नहीं लगाना चाहिये तथा विलासिता की वस्तुओं पर एक-बिन्दु कर काफी ऊँची दर से लगाया जाना चाहिये। आयोग ने सिफारिश की है कि ५००० रुपये वार्षिक से अधिक बिक्री वाल नभू ध्यापारियों पर बहु-बिन्दु बिक्री कर लगाया जाय किन्तु उसकी दर १ प्रतिशत या लगभग १ पाई प्रति रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिये। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अपवचन को रोकने तथा कर की दर को नीचा रखने के लिये यह आवश्यक है कि बिक्री कर से छूट के क्षेत्र को सीमित रखा जाय। इसके अतिरिक्त आयोग ने विक्रेताओं तथा बिक्री कर विभाग के भण्डों को निबटाने के लिये नभू राज्यों में बिक्री कर न्यायालयों (Sales Tax Tribunals) की स्थापना का सुझाव दिया है। इन सुझावों को कार्य रूप में लाने से बिक्री कर प्रणाली में काफी सुधार हो जाने की सम्भावना है।

(६) मनोरंजन कर (Entertainment Tax)—मनोरंजन कर विलासिता के साधनों पर लगने वाला कर है जिसका भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। यह कर सर्वप्रथम बंगाल में १८८२ में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश ने इसका प्रारम्भ सन् १९३८-३९ में हुआ। यह कर सिनेमा, थियेटर, सरकस, घुड़दौड़ तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन गृहों पर लगाया जाता है। कर को प्रवेश शुल्क के साथ टिकट की रकम में जोड़ दिया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, धर्म आदि

से सम्बन्धित मनोरंजन को इस प्रकार के कर से मुक्त कर दिया जाता है। महापतार्थ विये जाने वाले मनोरंजन भी इसमें मुक्त कराये जा सकते हैं। मनोरंजन कर से उत्तर प्रदेश सरकार को काफी आमदनी प्राप्त होती है। इस कर में निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययिता के गुण पाये जाते हैं।

उक्तलिखित करों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की आय के कुछ अन्य साधन भी हैं जिसमें सार्वजनिक व्यवसाय प्रमुख है। इसके अन्तर्गत सरकार को जंगल, सिंचाई तथा सरकारी कारखानों से आय प्राप्त होती है। नागरिक शासन से भी सरकार को काफी आय प्राप्त होती है। मोटर कर, सार्वजनिक निर्माण तथा कुछ नये कर जैसे विकास कर आदि भी सरकार की आय के स्रोत हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की मदे •

हमारी राज्य सरकार किस प्रकार अपनी आय को आवश्यक सेवाओं को चलाने तथा जनता की भलाई के लिये व्यय करती है, इसका अनुमान व्यय की प्रमुख मदों के विश्लेषण के द्वारा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की प्रमुख मदें इस प्रकार हैं—

(१) कर प्राप्ति पर व्यय—राज्य सरकार को विभिन्न करों की वसूली पर काफी व्यय करना पड़ता है। यह व्यय राजस्व पर प्रत्यक्ष माग (Direct Demand on Revenue) के अन्तर्गत आता है। मालगुजारी, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, आवकारी कर तथा अन्य करों को वसूल करने के लिये सरकार को अपने-को कर्मचारी रखने होते हैं तथा कर वसूली के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होती है। इस पर सरकार का काफी व्यय होता है जिसकी प्रायः आलोचना की जाती है। सरकार को चाहिये कि वह कर प्राप्ति पर अपने व्यय को कम से कम रखे जिससे कि प्राप्त होने वाली रकम का अधिकांश राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाया जा सके। इसके लिये आवश्यक है कि कर प्रणाली सरल व साधारण होनी चाहिये तथा प्रशासन की कुशलता में वृद्धि की जानी चाहिये। सन् १९११-१६ में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मद पर ८०८ करोड़ रुपया व्यय किया था। सन् १९६२-६३ में कर प्राप्ति पर लगभग १२ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

(२) नागरिक प्रशासन (Civil Administration)—राज्य के द्वारा सामान्य प्रशासन (General Administration) पर किया जाने वाला व्यय इस मद के अन्तर्गत आता है। न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहाकारिता, इपि, उद्योग धंधों आदि पर किया जाने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सरकार के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व इस पर सरकार की आय का ३० प्रतिशत व्यय किया जाता था किन्तु अब सार्वजनिक विकास तथा कल्याण सेवाओं के विस्तार के कारण इस मद पर किया जाने वाला व्यय तेजी के साथ बढ़ रहा है और कुल आय का लगभग ५० प्रतिशत नागरिक प्रशासन पर व्यय किया जाने लगा है। सन् १९६२-६३ में इस मद पर लगभग १०१ करोड़ रुपया व्यय किये जाने का

नुमान है जो कुल व्यय का लगभग ५४ प्रतिशत है। इसमें सबसे अधिक व्यय शिक्षा पर किया जाता है।

(३) सार्वजनिक निर्माण (Civil Works)—राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण के कामों पर भी काफी व्यय करती है। यह कार्य सार्वजनिक विभाग (P. W. D. Department) के द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत सड़कें, पुलों, सरकारी दफ्तरों तथा मकानों आदि के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय आ जाता है। इस मद पर भी सरकार का व्यय काफी बढ़ गया है। सन् १९६२-६३ में सार्वजनिक निर्माण पर लगभग ८३४ लाख रुपया व्यय किये जाने का अनुमान है।

इन मदों व अनिश्चित राज्य सरकार को ऋणों तथा व्याज के भुगतान पर भी काफी रुपया व्यय करना पड़ता है। प्रसाधारण मदों के अन्तर्गत जिसमें सामूहिक विकास (Community development) प्रमुख है, सरकार का व्यय बढ़ता जा रहा है। सन् १९६२-६३ में इस मद पर १ करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने का अनुमान है।

राज्य अर्थ-प्रवन्ध में सुधार के सुझाव

राज्य अर्थ-प्रवन्ध में सुधार करने के लिए प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों की आय में वृद्धि की जाय। लोक वन्द्याएँकारी राज्य की स्थापना के लिए नया विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें आय के अधिक से अधिक साधनों का पूर्ण शोषण करें और अपनी बड़ी हुई आमदनी को आर्थिक तथा सामाजिक विकास के नए उद्देश्यों को पूरा करने में लगायें। राज्य सरकारों की आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं —

(१) राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों से प्राप्त आय कर को प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रान्तों का आय कर में अधिक हिरमा होना चाहिए क्योंकि उनके क्षेत्रों से अधिक आय कर प्राप्त होता है। राज्य सरकारों को आय कर पर कुछ अतिरिक्त कर (Super tax) लगाने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

(२) राज्य सरकारों को कृषि आय कर का अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अभी तक इस साधन का पूर्ण शोषण नहीं किया जा रहा है और इसमें प्राप्त होने वाली आय बहुत कम है। इसमें काफी वृद्धि की जा सकती है।

(३) उत्पादन कर में राज्यों को अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। विशेष कर उन राज्यों का हिस्सा उत्पादन कर में बढ़ जाना चाहिए जिनके क्षेत्रों से अधिक उत्पादन कर प्राप्त होता है।

(४) राज्य सरकारों को विक्री कर की व्यवस्था में सुधार करके अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कर अपवचन को रोकने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(५) राज्यों को सार्वजनिक उद्योगों से अपनी आय बढ़ानी चाहिये। इसके लिये उन्हें अधिकाधिक उद्योग अपने हाथों में लेने चाहियें तथा उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक चलाना चाहिये।

(६) विलासिता की वस्तुओं पर विशेष तथा ऊँचे कर लगा कर राज्य सरकारों को अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए तथा कर के भार के असमान वितरण को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(७) आय में वृद्धि करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने अनुत्पादक व्यय को कम से कम रखें जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कामों पर अधिक व्यय किया जा सके। विशेषकर कर वसूली पर किये जाने वाले व्यय को तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यय को कम से कम रखा जाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न

1. Give a brief account of the revenues and expenditure of Uttar Pradesh or any other class A state of India. The account and figures must be of the latest year. (Agra B. A. 1955)

उत्तर प्रदेश सरकार या भारत के किसी अन्य 'अ' श्रेणी के राज्य की आय तथा व्यय का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। आंकड़े वर्तमान वर्ष के दीजिये।

2. What are the main sources of revenue of the U. P. Government? Discuss the position of Income Tax, Sales Tax and Land Revenue in it. (Agra B. A. 1953)

उत्तर प्रदेश सरकार की आय के मुख्य साधन क्या हैं? इनमें आय कर, बिक्री कर तथा मालगुजारी के महत्व को बतलाइये।

3. What are the main sources of income of state governments in India? How far are these adequate? Suggest some new sources of income for the state governments. (Raj. B. A. 1953)

भारतवर्ष में राज्य सरकारों की आय के मुख्य साधन क्या हैं? वे कहां तक पर्याप्त हैं? राज्य सरकारों की आय के कुछ नये साधनों का सुझाव दीजिये।

4. What are the financial relations between the Provincial and the Central government of India? Are Provincial revenues adequate to meet provincial needs? Suggest some remedies. (Agra B. A. 1941)

भारत के केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के वित्त सम्बन्धों की व्याख्या कीजिये। क्या प्रान्तीय सरकारों की आय उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है। सुधार के कुछ उपाय बतलाइये।

भारत में सार्वजनिक ऋण Public Debt in India

सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार के द्वारा लिया जाता है। यह ऋण (i) घातृक तथा (ii) विदेशी हो सकता है। घातृक ऋण वह ऋण होता है जो सरकार देश के भीतर अपने नागरिकों से लेती है। इसके विपरीत विदेशी ऋण वह होता है जो सरकार के द्वारा विदेशों में व्यक्तियों, सरकारों अथवा संस्थाओं से लिया जाता है। प्रायः सरकार की आय उसके व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है और सरकार को ऋण लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। कोई भी सरकार अपने समस्त व्यय को अपनी सामान्य आमदनी से पूरा नहीं कर सकती इसलिये प्रत्येक सरकार पर सार्वजनिक ऋण का कुछ न कुछ भार अवश्य होता है। वर्तमान काल में सरकारों को कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने के उद्देश्य से समाज सेवाओं पर काफी बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। आर्थिक विकास की योजनाओं पर भी सरकारों को बहुत अधिक धन व्यय करना होता है। इन्हीं कारणों से वर्तमान सरकारों का व्यय उनकी आय की अपेक्षा बहुत अधिक रहता है और इस कमी को प्रायः सार्वजनिक ऋणों के द्वारा पूरा किया जाता है। सरकारों को कुछ प्रादि के आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिये भी बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है।

अन्य सरकारों की भाँति भारत सरकार पर भी ऋण का काफी भार है और आर्थिक विकास पर भारी मात्रा में किये जाने वाले व्यय के कारण सार्वजनिक ऋण का यह भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है किन्तु भारत सरकार के ऋणों के सम्बन्ध में सबसे सम्मोचजनक बात यह है कि इसमें से अधिकांश ऋण उत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है। ऋणों से निमित्त आदेयों (Assets) से होने वाली आय उससे बहुत अधिक होती है जितना कि ऋण पर व्याज दिया जाता है और इस प्रकार के उत्पादक ऋणों का भार-धीरे धीरे कम होता जाता है। रेलों, नहरों तथा अन्य उत्पादक योजनाओं में लगी हुई ऋणों की रकम का दीर्घकाल में इनकी आय के द्वारा मुगतान हो जाता है और सरकार पर इन ऋणों के मुगतान का कोई विशेष भार नहीं पड़ता।

भारत में लोक ऋण का विकास :

भारतवर्ष में लोक-ऋण का आरम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से होता है। आरम्भ में कम्पनी को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी जिसके व्यय को पूरा करने के लिए कम्पनी को इंग्लैंड में ऋण लेने पड़े थे। सन् १७६२ में कम्पनी का कुल ऋण १७० लाख पौंड था जो १८३४ में बढ़ कर ३७० लाख पौंड हो गया। इसके तुरन्त बाद कम्पनी ने एक ऋण-शोधन-कोष (Debt Redemption Fund) स्थापित कर दिया और इस ऋण को घटाने का प्रयत्न किया गया किन्तु यह ऋण बढ़ता ही गया और सन् १८५६ में बढ़ कर ४६० लाख पौंड हो गया। १८५७ में ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को दबाने के लिए काफी उड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ा जिसके कारण १८६० में सरकार पर ऋण की मात्रा १००० लाख पौंड हो गई। भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ जाने के पश्चात् भारत में लोक-ऋण का स्वरूप बदल गया। अब ब्रिटिश सरकार उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेने लगी और रेलों, नहरों, डाक तार के विकास आदि कार्यों पर बड़ी मात्रा में व्यय किया गया जिसके कारण उत्पादक ऋण की मात्रा काफी बढ़ गई। प्रथम महायुद्ध से पूर्व सरकार ने अपने अनुत्पादक ऋण को कम से कम करने का प्रयत्न किया जिसके परिणामस्वरूप वह घट कर केवल ३ करोड़ रुपये हो गया। प्रथम युद्ध काल में भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को १० करोड़ रुपये की भेंट दी तथा युद्धोत्तर काल में सरकार को बजट में घाटा रहने लगा जिसके कारण ऋण की मात्रा फिर बढ़ने लगी। सन् १९२४ में अनुत्पादक ऋण बढ़ कर २५८ करोड़ रुपये तथा उत्पादक ऋण ७०० करोड़ रुपये हो गया। आरम्भ में सरकार केवल लन्दन के मुद्रा बाजार में ऋण लिया करती थी किन्तु युद्ध-काल में इंग्लैंड में ऋण नहीं लिया जा सका और सरकार ने भारत के मुद्रा बाजार में ऋण लेना आरम्भ किया जिसमें उसे काफी सफलता मिली। युद्ध के पश्चात् आर्थिक अवसाद काल में बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सरकार को काफी मात्रा में नया ऋण लेना पड़ा जिसके कारण सन् १९३४ में भारत सरकार का कुल ऋण उत्पादक तथा अनुत्पादक बढ़ कर १,२२४ करोड़ रुपये हो गया।

दूसरा विश्वयुद्ध आरम्भ होने के समय भारत का लोक-ऋण १२०५.७६ करोड़ रुपये था। युद्ध-काल में सरकार को काफी बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ा और बजट के घाटों को पूरा करने के लिये सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ा जिसके कारण १९५२-५३ में लोक-ऋण की मात्रा बढ़कर २६७५.६ करोड़ रुपये हो गई जो युद्ध के पूर्व की ऋण की रकम से लगभग दुगुनी थी। इसमें उत्पादक ऋण १९५५.२५ करोड़ तथा अनुत्पादक ऋण ५७८ करोड़ रुपये था।

भारत के स्टर्लिंग ऋण का परिचोष (Redemption of the Sterling Debt of India)—युद्ध से पूर्व का अधिकांश भारतीय लोक-ऋण स्टर्लिंग के रूप में था। सन् १९३६ में भारत का स्टर्लिंग ऋण ४६४.६४ करोड़ रुपये था। युद्धकाल

में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं जिनके कारण भारत सरकार ने अपने स्टर्लिंग ऋण के अधिकांश को चुका दिया। युद्ध काल में भारत से बहुत सामान इङ्ग्लैंड को निर्यात किया गया तथा भारत में बिके जाने वाले युद्ध वस्तु का भुगतान ब्रिटिश सरकार ने स्टर्लिंग प्रतिभृतियों के रूप में किया जिसके कारण इङ्ग्लैंड में भारत की स्टर्लिंग निधि (Sterling Balances) जमा हो गई। भारत सरकार ने इस स्थिति से लाभ उठाया और अपनी स्टर्लिंग निधि का प्रयोग स्टर्लिंग ऋणों को चुकाने के लिये करना आरम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत का स्टर्लिंग ऋण ४६४ ६४ करोड़ ६० से कम होकर १९४४-४५ में केवल ३४-१६ करोड़ रुपये रह गया। इस प्रकार भारत एक ऋणी देश के स्थान पर ऋणदाता देश बन गया।

युद्धोत्तर काल में लोक ऋण :

मार्च सन् १९४७ में भारत का कुल लोक-ऋण २३८१-८६ करोड़ रुपये था। देश का विभाजन होने पर लोक-ऋण का बंटवारा भी किया गया और ३०० करोड़ रुपये पाकिस्तान के हिस्से में आया जिसका भुगतान पाकिस्तान सरकार ने ३% ब्याज की दर से ५० वर्षों में करने का वचन दिया। इन वर्षों का भुगतान सन् १९५२ से आरम्भ होना था। युद्ध से पूर्व सरकार प्रायः अल्पकालीन ऋण (Floating Debt) लिया करती थी किन्तु युद्ध के पश्चात् सरकार ने दीर्घकालीन ऋण लेने आरम्भ कर दिये। सन् १९५० के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के लिए लिये जाने वाले ऋणों के कारण इस प्रवृत्ति को और अधिक बल मिला। अल्पकालीन ऋणों का प्रयोग विकास योजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता था किन्तु सरकार की नीति-परिवर्तन के कारण यह दोष दूर हो गया और भारत सरकार की ऋण नीति ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे प्रगतिशील देशों की ऋण-नीति के अनुकूल हो गई है।

भारत में लोक-ऋण की प्रगति (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रुपया ऋण	विदेशी ऋण	कुल ऋण
१९३६	७१०	४६६	१,१७६
१९४५	१,५७१	३८	१,६०९
१९५०	२,४६३	४३	२,५०६
१९५५	२,८४४	१३३	२,९७७
१९५८	४,११२	२११	४,३२३
१९६०—६१	५,४५५-०३	८१५-५७	६,२८०-६०
१९६१—६२	५,६२५-४६	११८४-६४	७,११०-१३

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि भारतवर्ष में १९५० के पश्चात् लोक ऋण में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, सन् १९५० में लोक ऋण की कुल मात्रा २५०६ करोड़ रुपये थी और सन् १९६१-६२ में यह बढ़ कर ७११० करोड़ रुपये हो गई। इस काल में आन्तरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के ऋणों में वृद्धि हुई है, किन्तु विदेशी ऋणों की मात्रा अधिक तेजी के साथ बढ़ी है जिसका मुख्य कारण विकास योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय है।

पंच-वर्षीय योजनाएँ तथा लोक-ऋण :

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का काफी बड़ा भाग लोक-ऋण से प्राप्त किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले दस वर्षों में हमारे लोक-ऋण में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५२० करोड़ रुपया आन्तरिक ऋणों से प्राप्त किया जाना था जिसमें से ११५ करोड़ रुपया आन्तरिक ऋणों से, २६० करोड़ अल्प बचत तथा ११५ करोड़ अन्य साधनों से प्राप्त किया जाना था। यह रकम योजना पर किये जाने वाले कुल व्यय का २५% थी। प्रथम योजना काल में वास्तविक ऋण केवल ३६० करोड़ रुपये का ही लिया जा सका। इस काल में विदेशी ऋणों में ८६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

दूसरी योजना में जनता से ऋण लेने का लक्ष्य १२०० करोड़ रुपए रखा गया जिसमें से ७०० करोड़ रुपया ऋणों में तथा ५०० करोड़ रुपया अल्प बचत से प्राप्त किया जाना था। इस योजना काल में अल्प बचत पर विशेष जोर दिया गया जिससे प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण कार्य में अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग दे सके। बचत को प्रोत्साहित करने के लिये १ अप्रैल १९६० से इनामी बाँडम की योजना जारी की गई। सम्पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अल्प बचत का निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका और योजना काल में केवल ४०० करोड़ रुपया अल्प बचत से प्राप्त हुआ।

तीसरी योजना में ८०० करोड़ रुपए का ऋण बाजार से लिये जाने का लक्ष्य रखा गया है इसके अन्तर्गत इनामी बाँड स्कीम से प्राप्त होने वाला रुपया भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ६०० करोड़ रुपया अल्प बचत से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत का विदेशी ऋण :

आरम्भ से ही भारत सरकार को युद्ध व्यय को पूरा करने तथा रेलों आदि के निर्माण के लिये लन्दन के मुद्रा बाजार से स्टर्लिंग ऋण लेना पड़ता था जिसके कारण भारत पर स्टर्लिंग ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई। सन् १९३६ में भारत का स्टर्लिंग ऋण ४६६ ६४ करोड़ रुपए था किन्तु युद्ध काल में दशाये अनुकूल हो जाने के कारण सरकार ने अधिकांश ऋण को चुका दिया। सन् १९५५-५६ में हमारा स्टर्लिंग ऋण घट कर केवल २२६१ करोड़ रुपए रह गया किन्तु इसके पश्चात् कुछ और नया ऋण लिये जाने के कारण स्टर्लिंग ऋण की मात्रा बढ़कर ३१ मार्च १९६१

को १२२.५० करोड़ रुपये हो गई। इस काल में भारत का डॉलर ऋण भी तेजी के साथ बढ़ा है। ३१ मार्च १९५०-५१ को डॉलर ऋण की मात्रा २४.६० करोड़ रुपये, ३१ मार्च १९६१ को यह बढ़कर ५२१.४० करोड़ रुपये हो गई। डॉलर ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण आर्थिक विकास के लिए लिए जाने वाले ऋण थे। इनमें से अधिकांश ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अमरीकन सरकार से लिये गये हैं। इस तथा पश्चिमी जर्मनी से लिए गए ऋणों की मात्रा १९६०-६१ के अन्त में ६१.५३ करोड़ रुपये तथा १०८-१७ करोड़ रुपये थी। विदेशी ऋण भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी सहायता से ही भारत आर्थिक निर्माण के लिये पूंजीगत वस्तुयें तथा बच्चा माल प्राप्त कर रहा है। भारत के विदेशी ऋणों की मात्रा योजना काल में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दूसरी योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशी ऋणों तथा सहायता से प्राप्त किया गया। तीसरी योजना में २२०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता से प्राप्त किया जाना है जिसमें विदेशी ऋण तथा मित्र राष्ट्रों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता भी सम्मिलित है।

लोक ऋण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति :

भारत सरकार की ऋण सम्बन्धी स्थिति को निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है—

(करोड़ रुपयों में)

	१९६१-६२	१९६२-६३ घजद अनुमान
भारत में—		
१. ऋण	२,६८८.१३	२,७६३.३६
२. ट्रेजरी बिल्ल (Treasury Bills)	१,१८२.३०	१,३३२.३०
३. अल्प वधत	१,०६४.५४	१,१६६.१४
४. रक्षित कोष आदि	६८.७६	११५.०३
५. अमेरिकन सरकार की भारत में जमा	३००.००	३६०.००
६. अन्य	३७०.२८	४०८.५२
कुल आन्तरिक ऋण	५,७०४.०४	६,१८०.३८
विदेशों से ऋण—		
१. इंग्लैंड	१४६.७४	१५७.०५
२. डॉलर ऋण	६५०.६५	८२१.६८
३. पश्चिमी जर्मनी	१४१.०४	१२८.६०
४. अन्य विदेशी स्रोत	७४.८२	२६६.३७
कुल लोक ऋण	६,७६३.६४	७,६८०.५०

परीक्षा प्रश्न

1. Attempt a lucid essay on the significance of public debt in a plan for economic development. (Agra B. A., B. Sc. 1955)

आर्थिक विकास की योजना में लोक ऋण के महत्व पर एक निबन्ध लिखिए ।

2. Write a short note on the following, covering not more than three pages of your answer-book :—Public Debt of India.

(Agra B. A., B. Sc. Part I 1955)

भारत में लोक ऋण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए जो आपकी कापी के तीन पन्नों से अधिक न हो ।

3. What is the nature and extent of India's Public Debt ■■ it stands today. (Agra 1949)

भारत का वर्तमान लोक ऋण कितना है तथा उसकी प्रकृति क्या है ?

—

भारत में स्थानीय अर्थ-प्रबन्ध

Local Finance in India

भारत में स्थानीय सस्यायें बहुत प्रचीन काल से काम कर, रही हैं। हिन्दू राजाओं के जमाने में पचायतें बहुत अच्छी तरह से संगठित थी और वे स्थानीय महत्व की सेवाओं का प्रबन्ध करने के प्रतिरिक्त दोषानी तथा फौजदारी के मामलों भी निपटाया करती थी। ब्रिटिश शासन काल के आरम्भ में इन संस्थाओं का पतन हो गया क्योंकि सरकार ने केन्द्रीय शासन स्थापित करने के उद्देश्य से इनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किन्तु देश में राजनैतिक तथा सामाजिक विकास होने के साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण की भाँति को जाने लगी और सरकार ने ग्राम पचायतों तथा नगर पालिकाओं की स्थापना की ओर ध्यान देना आरम्भ किया। सर्वप्रथम १६८७ में मद्रास तथा १७२६ में बम्बई और कलकत्ते में नगर-पालिकाओं की स्थापना की गई। सन् १८४२ के पश्चात् स्थानीय संस्थाओं का विकास आरम्भ हो जाता है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की जाने लगी। सन् १९१६ के सुधार अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं का प्रबन्ध प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया जिसके कारण सभी प्रांतों में इस प्रकार की संस्थाओं के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विकेन्द्रीय शासन के सिद्धांत को कार्य रूप में लाने का धक्का मिला और स्थानीय संस्थाओं को विकेन्द्रीत शासन का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाने लगा। वर्तमान समय में इन संस्थाओं को स्थानीय-स्वशासन की सक्रिय इकाइयाँ बनाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में ग्रामपचायतों का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ है और इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजातन्त्रवाद का आधार माना जाने लगा है। इस काल में स्थानीय संस्थाओं के कार्यों तथा संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

आज के सामाजिक जीवन में स्थानीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वे कुछ ऐसे आधारभूत कार्य कर रही हैं जिनके बिना आज का सम्य जीवन असंभव है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध, सड़को, गलियों व नालियों की सफाई, बिजली व पानी की व्यवस्था करना, सड़को का निर्माण तथा अन्य प्रकार की सार्वजनिक सेवाएँ कुछ इसी प्रकार के काम हैं। इन कार्यों को स्थानीय संस्थाएँ अधिक अच्छी

प्रकार से कर सकती हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश काम स्थानीय महत्व के हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी के द्वारा इन कामों को नहीं किया जा सकता। स्थानीय संस्थायें जनता को प्रजातन्त्रवाद की शिक्षा देने के केन्द्र भी माने जाते हैं। यही पर लोगो को प्रजातन्त्रवाद के प्रारम्भिक सिद्धांतों को समझने तथा उन्हें कार्य रूप में लाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार स्थानीय संस्थायें लोगो को अन्ध टागरिक बनाने में बड़ी सहायता देती हैं। इसके अतिरिक्त यह संस्थायें आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने में भी बड़ा सहयोग दे सकती हैं। स्थानीय संस्थायें योजना के लिये जन सहयोग प्राप्त करने, स्थानीय साधनों को एकत्रित करने तथा स्थानीय महत्व की योजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानीय संस्थायें आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज इन संस्थाओं के विकास की हमारे देश में बड़ी आवश्यकता है। स्थानीय संस्थाओं में पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इनका अर्थ-प्रबन्ध ठीक प्रकार से किया जाय जिससे कि इन्हें अपने कार्यों को करने के लिये पर्याप्त धन मिल सके।

स्थानीय अर्थ-प्रबन्ध (Local Finance) के अन्तर्गत नगर-पालिकाओं, जिला बोर्डों, ग्राम पंचायतों के आय व व्यय का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि स्थानीय संस्थायें किस प्रकार अपनी आय तथा व्यय में समायोजन स्थापित करती हैं। स्थानीय वित्त की मुख्य समस्या स्थानीय संस्थाओं की आय की कमी है। ये संस्थायें आय के साधनों की कमी के कारण अपने कार्यों को भली प्रकार करने में असमर्थ हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थाओं की आय में वृद्धि की जाय जिससे कि वे अपने कामों का विस्तार कर सकें तथा उन्हें अधिक कुशलता के साथ किया जा सके। स्थानीय अर्थ प्रबन्ध के अध्ययन को हम स्थानीय संस्थाओं के आय के स्रोतों के विश्लेषण से प्रारम्भ कर सकते हैं। स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत कॉरपोरेशन्स, नगर पालिकायें, टाउन एरिया कमेटीया, जिला-बोर्ड, तालुका बोर्ड तथा ग्राम पंचायतें आती हैं।

स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन (Sources of Income of Local Bodies) :—भारतवर्ष में स्थानीय संस्थाओं की आय के मुख्य साधन निम्न प्रकार हैं—

- (१) करारोपण
- (२) व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय
- (३) राज्य सरकारों से प्राप्त आय

(१) करारोपण (Taxation) :—स्थानीय संस्थाओं के द्वारा कौन से कर लगाए जायें, इसकी कोई भिन्न सूची नहीं है। किन्तु व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें केवल स्थानीय संस्थाओं के लिए छोड़ दिया गया है। ये संस्थायें प्रत्यक्ष (Direct) तथा अप्रत्यक्ष (Indirect) दोनों ही प्रकार के कर लगाती हैं। प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर, भूमि शुल्क तथा व्यक्ति पर लगने वाले कर

ग्रा जाते हैं। अग्रप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत चुंगी कर, सीमा कर तथा मार्ग शुल्क आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय सस्याओं के द्वारा प्रायः निम्नलिखित करों का प्रयोग अपनी आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(घ) चुंगी कर (Octroi Duty).—यह कर सबसे प्राचीन कर है जिसका प्रयोग प्रायः नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में इस कर का आरम्भ १८६० में हुआ। यह कर उपभोग की उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो नगर पालिका की सीमा में सड़क, रेल अथवा जल-यातायात से लाई जाती हैं। चुंगी कर नगर पालिकाओं की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिन पर चुंगी कर नहीं लगाया जा सकता जैसे वे वस्तुएँ जिन पर सीमा कर अथवा उत्पादन कर लग चुका हो, पानियों का घरेलू सामान, डाक, पामेल इत्यादि यद्यपि कुछ नगरपालिकायें इस कर को नहीं लगा रही हैं किन्तु फिर भी उसका प्रयोग उनमें से अधिकांश के द्वारा किया जाता है।

चुंगी कर को एक अन्धकार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें धनकी दोष पाये जाते हैं तथा इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। इसलिए इस कर को समाप्त करने की सिफारिश कितनी ही बार की जा चुकी है किन्तु वह नगर-पालिकाओं की आय का इतना महत्वपूर्ण साधन बन गया है कि उसे समाप्त करना संभव नहीं हो सका है। चुंगी कर के मुख्य दोष इस प्रकार हैं—(i) यह कर व्यवसाय तथा व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न करता है। चुंगी कर के कारण स्वतन्त्र रूप से व्यापार नहीं किया जा सकता और इस प्रकार वह देश के आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करता है। (ii) इस कर को इकट्ठा करने पर बड़ा व्यय करना पड़ता है जिसके कारण कर अक्षितव्ययितापूर्ण हो जाता है। (iii) कर को निश्चित करने तथा वसूल करने के सम्बन्ध में काफी भ्रष्टाचार फैलता है। बोटियों पर काम करने वाले मुंशी घूस लेकर माल को छोड़ देते हैं जिससे चुंगी से होने वाली आय काफी कम हो जाती है। (iv) कर की दरों को निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उन्हें प्रायः मनमाने ढंग से निश्चित कर लिया जाता है। (v) यह कर करारोपण के सामान्य सिद्धांतों को सन्तुष्ट नहीं करता। इसमें निश्चितता, मितव्ययिता तथा सुविधा आदि के गुण नहीं पाये जाते। इन्हीं समस्त दोषों के कारण प्रायः यह कहा जाता है कि चुंगी कर को समाप्त कर देना चाहिये। और उसके स्थान पर नगर पालिकाओं के द्वारा किसी अन्य कर का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(ब) सीमा कर (Terminal Tax).—सीमा कर वह कर है जो नगर में रेल द्वारा आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह कर प्रायः रेलवे के द्वारा इकट्ठा कराया जाता है। कर वस्तुओं के परिमाण के अनुसार लगाया जाता है। सड़क अथवा जल-यातायात से आने वाली वस्तुओं पर सीमा मार्ग शुल्क (Terminal Toll Tax) लगाया जाता है। यह दोनों कर साथ-साथ लगाये जाते हैं। कर की

तथा सवारी के प्रकार पर निर्भर होती है। मोटर, वेलगाडी, साइकिल आदि के द्वारा लाये गये सामान पर अलग-अलग दरों से कर लगाये जाते हैं। इन करों को प्रायः चुंगी करों का प्रतिस्थापन समझा जाता है क्योंकि इनमें वे दोष नहीं पाये जाते जिनके कारण चुंगी का प्रचलन कम होता जा रहा है। इस कर के मुख्य गुण निम्न प्रकार हैं :—

(i) यह कर क्षेत्र में आने वाली, बाहर जाने वाली तथा क्षेत्र से गुजरने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जा सकता है (ii) इन करों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की वापसी नहीं दी जाती है। चुंगी कर के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई वापसी देने में उत्पन्न होती है, यह कठिनाई इन करों में काफी सीमा तक दूर हो जाती है। (iii) कर को एकत्रित करने का काम प्रायः म्युनिसिपल कर्मचारियों के हाथ से ले लिया जाता है जिसके कारण भ्रष्टाचार काफी मात्रा में कम हो जाता है। (iv) इन करों को एकत्रित करने का व्यय बहुत कम आता है। इनका प्रबन्ध भी साधारण तथा सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सकता है। (v) सीमा कर की दरें प्रायः चुंगी कर से कम होती हैं जिसके कारण वह व्यापार तथा व्यवसाय में अधिक बाधक नहीं होता।

सीमा कर तथा सीमा मार्ग शुल्क को अधिक उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक है कि उसकी दरें नीची रखी जायें तथा उन पर राज्य सरकारों का नियन्त्रण स्थापित किया जाय। सीमा कर एक स्थानीय कर है और इसकी आय को एक विशेष क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिये व्यय किया जाता है किन्तु इस का भारत देश की सामान्य जनता पर पड़ता है। इस दोष को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी दरों को कम से कम रखा जाय तथा उन पर सरकारी नियन्त्रण रहे।

(स) मकान तथा भूमि पर कर—नगरपालिकाओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं को मकानों, भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार है। मकान कर स्थानीय आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। सम्पत्ति कर मकानों तथा भूमि की वार्षिक आय के आधार पर लगाया जाता है। चाहे सम्पत्ति किराये पर दी जाय अथवा वह मालिक के निजी प्रयोग में हो, उस पर कर देना आवश्यक होता है। कर की दरों में काफी भिन्नता पाई जाती है किन्तु वह प्रायः ४% और ९% के बीच में होती है। कुछ नगरपालिकाओं के द्वारा यह कर प्रगतिशील आधार पर भी लगाया जाता है। कम आय वाली सम्पत्ति पर कर की दर नीची रखी जाती है और वह सम्पत्ति से प्राप्त आय के अनुसार बढ़ती जाती है। अधिकतम दर १५% तक हो सकती है। प्रत्यक्ष कर होने के कारण मकान कर बहुत अच्छा कर समझा जाता है क्योंकि न तो इसके लगाने में और न वसूल करने में कोई कठिनाई होती है। कर निश्चितता के सिद्धान्त को अच्छी तरह पूरा करता है तथा मितव्ययितापूर्ण भी है क्योंकि इसे एकत्रित करने का व्यय कम आता है। मकान कर लोच पूर्ण भी है क्योंकि इसे एकत्रित करने का व्यय कम आता है। मकान कर लोच पूर्ण भी है क्योंकि मकानों के किराये में वृद्धि होने पर कर से होने वाली आय को बढ़ाया जा सकता है।

मकान कर को अधिक उचित तथा उत्पादक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे प्रगतिशील दरों पर लगाया जाय। कम आय वाली सम्पत्ति पर कर की दर कम होनी चाहिये तथा अधिक आय वाली सम्पत्ति पर ऊँची दर से कर लगाया जाना चाहिये। जिन मकानों का प्रयोग व्यवसायिक कार्यों के लिये होता हो उन पर कर की दर रिहाइशी मकानों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। ऐसा करना न्याय की दृष्टि से उचित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सम्पत्ति का मूल्यांकन उचित ढंग से किया जाय जिसके लिये विशेष कर्मचारियों का रखना जाना आवश्यक है।

(द) व्यक्तियों तथा व्यवसायों पर कर (Tax on Persons and Professions)—बहुत सी नगरपालिकायें व्यक्तियों तथा व्यवसायों पर भी कर लगाती हैं। मद्रास, बंगाल तथा मध्य प्रदेश की नगरपालिकायें तथा जिला बोर्ड व्यापार तथा व्यवसाय पर कर लगाती हैं। व्यवसायों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है और उनमें से प्रत्येक व्यवसाय करने वाले को लाइसेन्स लेना पड़ता है। बंगाल, यू० पी०, बिहार तथा उड़ीसा की नगरपालिकायें तथा जिला बोर्ड हैमिपत कर के नाम से व्यक्तियों पर कर लगाती हैं। व्यक्तियों पर कर उनकी सामाजिक स्थिति, आय, सम्पत्ति तथा व्यवसाय को ध्यान में रख कर लगाया जाता है। यह कर अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि निश्चित करने का कोई वैज्ञानिक आधार न होने के कारण मनमाने ढंग से लगाया जाता है।

(घ) अन्य कर (Other Taxes)—उपरोक्त करों के अतिरिक्त भी स्थानीय संस्थाएँ अनेक कर लगाती हैं जैसे जानवर, गाड़ी व माव कर, यात्रियों पर कर, घोड़ियों पर कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, नौकरो पर कर इत्यादि। इनमें से जानवरों तथा गाड़ियों पर कर प्रायः सभी नगरपालिकाओं के द्वारा लगाया जाता है। यह कर लाइसेन्स शुल्क के रूप में लिया जाता है। इस कर के सम्बन्ध में अपवचन की काफी गुंजाइश है।

(२) व्यवसायिक कार्यों से प्राप्त आय—इस कर के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं को बिजली, पानी, गैस, म्युनिसिपल बाजारों तथा वध-गृहों, जिला बोर्डों को रेलों, बस सर्विस, भूमि के प्रयोग आदि में प्राप्त आय सम्मिलित होती है। अधिकतर नगरपालिकायें अपने क्षेत्र में बिजली देने का कार्य करती हैं जिससे उन्हें काफी आय प्राप्त होती है। पानी व गैस का प्रबन्ध भी नगर संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। पानी कर दो प्रकार में वसूल किया जाता है। सामान्य कर के रूप में (Flat Rate) तथा पानी के उपभोग के अनुसार कर लेना। पानी की व्यवस्था करने में नगरपालिकाओं को काफी व्यय करना पड़ता है जिसे वे धीरे-धीरे पानी कर से वसूल करती हैं। पानी कर में स्थानीय संस्थाओं को काफी आमदनी होती है। पानी की कीमत उपभोग के आधार पर वसूल करना अधिक समझा जाता है क्योंकि इस प्रणाली से पानी का बँकाव खर्च नहीं किया जाता। मीटर के द्वारा यह नाप लिया जाता है कि कितने पानी का उपभोग किया गया है और प्रति हजार गैलन के हिसाब से पानी की कीमत वसूल

कर ली जाती है। कुछ बड़े शहरों की नगरपालिकायें गैस का उत्पादन करके अपने उपभोक्ताओं को बेचती हैं जिससे उन्हें काफी लाभ होता है। बड़े शहरों की नगरपालिकायें बस, ट्राम तथा अन्य आवागमन के साधनों का प्रबन्ध भी करती हैं जिसके कारण लोगों को कम किराये पर दूर-दूर सफर करने की सुविधा मिल जाती है। नगरपालिकाओं को इस काम से आमदनी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ नगरपालिकाओं के अपने बाजार, बघ गृह, सिनेमा घर तथा डेरी आदि होते हैं जिनसे उन्हें आमदनी प्राप्त होती है।

(३) अनुदान तथा ऋण (Grants and Loans)—उपरोक्त साधनों से प्राप्त आय स्थानीय संस्थाओं के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होती और उन्हें काफी सीमा तक सरकारी अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार से दो प्रकार का अनुदान मिलता है—(i) आवर्ती अनुदान (Recurring Grant) तथा (ii) समवर्द्ध अनुदान (Block Grant)। आवर्ती अनुदान प्रति वर्ष दिया जाता है तथा समवर्द्ध अनुदान एक कार्य के लिये केवल एक बार दिया जाता है। राज्य सरकारें अनुदान निश्चित कार्यों के लिये देती हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बाटा जा सकता है—(क) शिक्षा अनुदान, (ख) सामान्य कामों के लिये अनुदान जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, यानायात सदेशवहन इत्यादि। अनुदान की मात्रा निश्चित करने के लिये तीन प्रकार की विधियाँ काम में लाई जाती हैं—(i) प्रानुपातिक अनुदान (Percentage Grant)—इसके अन्तर्गत किसी सेवा के व्यय का निश्चित प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। (ii) निश्चित अनुदान (Block Grant) किसी कार्य को निश्चित मात्रा में अनुदान देना चाहे उस पर अधिक व्यय किया जाय अथवा कम। (iii) इकाई अनुदान (Unit Grant) इस प्रणाली में स्थाई आधार पर अनुदान दिया जाता है और उसकी रकम प्रति इकाई के आधार पर निश्चित की जाती है जैसे शिक्षा अनुदान का आधार प्रति संस्था अथवा प्रति विद्यार्थी रखा जाता है। वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं को कुछ विशेष कामों के लिए राज्य सरकारों से कम सूद पर ऋण भी मिलता है।

स्थानीय संस्थाओं का व्यय :

स्थानीय संस्थायें वर्तमान समाज में अनेकों उपयोगी सेवाओं का प्रबन्ध करती हैं जिनके बिना नागरिक जीवन का चलना असम्भव प्रतीत होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों व गलियों का निर्माण, शहर की सफाई, बिजली, पानी व गैस का प्रबन्ध, अस्पताल, डिस्पेन्सरी आदि का चलाना, पार्क तथा बाटिकाओं की व्यवस्था, मेले व नुमायशों का प्रबन्ध आदि कुछ ऐसे काम हैं जो नगरपालिकाओं व जिला बोर्डों द्वारा किये जाते हैं। ये कार्य मुख्यतः दो वर्गों में बाटे जा सकते—

(अ) अनिवार्य कार्य—(Obligatory Function)—इसके अन्तर्गत वे कार्य आ जाते हैं जिनका प्रबन्ध करना स्थानीय संस्थाओं के लिये अनिवार्य होता है जैसे सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा, बिजली व पानी का प्रबन्ध तथा आवागमन के साधनों का

विकास, (ब)निर्णयात्मक कार्य (Discretionary Functions)—इसके अन्तर्गत वे कार्य आ जाते हैं जिनका प्रबन्ध यदि स्थानीय सस्था चाहे तो कर सकती है जैसे पुस्तकालयो तथा वाचनालयों की स्थापना, पार्क व व्यायामशालाओं की व्यवस्था, मैलों आदि का प्रबन्ध इत्यादि । इन सब कामों को करने के लिये स्थानीय सस्थाओं के कार्यों व्यय करना पड़ता है ।

आय के साधनों की कमी के कारण :

आजकल इन सस्थाओं का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है जिसके कारण इनका व्यय भी दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । इस बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय सस्थाओं की आय में पर्याप्त वृद्धि की जाय जिससे कि वे महत्वपूर्ण सेवाओं का प्रबन्ध ठीक प्रकार कर सकें । आय के साधनों की कमी स्थानीय वित्त की मुख्य समस्या है । आय के साधनों की कमी के कारण ये सस्थाएँ अपने कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पा रही हैं और उनकी राज्य अनुदान पर निर्भरता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । स्थानीय सस्थाओं की आय कम होने के कारण इस प्रकार हैं—(i) सामान्य जनता की निर्धनता—अधिकांश लोग इतने गरीब हैं तथा उनकी कर दान क्षमता इतनी कम है कि नगरपालिकाओं के लिये अपनी कर आय में वृद्धि करना सम्भव नहीं है । (ii) कर अपव्यय—स्थानीय करों से लोग प्रायः बच जाते हैं जिससे नगरपालिका की आय कम होती है । विशेषकर धनी लोग कर दान-क्षमता होते हुये भी कर नहीं देना चाहते हैं । (iii) राज्य तथा केन्द्रीय करों का भार—नागरिकों को अनेक प्रकार के राज्य तथा केन्द्रीय करों का भुगतान करना होता है जिसके कारण स्थानीय करों को देने की उनकी क्षमता बहुत कम रह जाती है । (iv) व्यवसायिक आय का कम होना—अधिकांश नगरपालिकाएँ बहुत कम व्यवसायिक कार्य करती हैं और अधिकांश रूप से कर आय तथा सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं । (v) अकुशल शासन तथा दोषपूर्ण निरीक्षण—शासन व्यवस्था की कार्य-कुशलता कम होने के कारण भी नगरपालिकाओं की आय कम रहती है । करों की रकम ठीक प्रकार निश्चित नहीं की जाती । निरीक्षण ठीक न होने के कारण लोग कर से बच जाते हैं । कर वसूली ठीक समय पर नहीं होती ।

आय के साधनों में वृद्धि के उपाय :

स्थानीय सस्थाओं की आय में वृद्धि करने के लिये अनेकों सुझाव दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में स्थानीय अर्थ-प्रबन्ध आचम समिति (Local Finance Enquiry Committee) तथा करारोपण आचम आयोग (Taxation Enquiry Commission) द्वारा दिये गये सुझाव महत्वपूर्ण हैं । कुछ मुख्य-मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं—(१) मालगुजारी की दर को नीचा रखवा जाय जिससे कि स्थानीय सस्थाओं के लिये भी भूमि में कर वसूल करने की कुछ गुंजायश रह जाय । विशेषतया ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र की भूमि से प्राप्त मालगुजारी में कुछ हिस्सा मिलना चाहिये । (२) कुछ

कर राज्य सरकारों से लेकर उन्हें पूर्णतया स्थानीय सरकारों के उपयोग के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। मोटर गाड़ियों पर चलने वाला कर, मनोरंजन कर, अचल संपत्ति पर कर तथा बिजली कर स्थानीय सरकारों के वित्त के साधन होने चाहियें। (३) केन्द्रीय सरकार को रेल, सड़क तथा वायुयान द्वारा जाने वाले यात्रियों पर सीमा कर लगाना चाहिये और उसकी कुल आमदनी स्थानीय सस्थाओं को देनी चाहिये। (४) स्थिति, पेशे तथा सम्पत्ति पर कर लगाने की व्यवस्था में सुधार होना चाहिये। भूदान पर कर प्रगतिशील दरों से लिया जाना चाहिये तथा सम्पत्ति का मूल्यांकन ठीक प्रकार से होना चाहिये। (५) स्थानीय सस्थाओं को विज्ञापन कर तथा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगाने का अधिकार होना चाहिये। (६) होटलों में ठहरने वाले यात्रियों से भी कर लिया जा सकता है। (७) स्थानीय सस्थाओं को गैर-कर आय के साधनों का विकास करना चाहिये। ये सथाये व्यवसायिक कार्यों से काफी आय प्राप्त कर सकती हैं। बिजली, पानी व गैस की व्यवस्था, म्युनिसिपल बाजार तथा बंध गृहों का निर्माण, सिनेमा घर, डेरी फार्म तथा मोटर यातायात आदि का चलना काफी आय दे सकता है। (८) राष्ट्र महत्व के कार्यों को केन्द्र प्रथवा राज्य सरकारों को ले लेना चाहिये जिससे स्थानीय सस्थाओं पर खर्च का भार कम हो सके। (९) राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में अधिक रकम देनी चाहिये। (१०) स्टाम्प कर पर अतिरिक्त कर (Surcharge) लगाने का अधिकार स्थानीय सस्थाओं को होना चाहिये तथा रजिस्ट्रेशन फीस से होने वाली आमदनी में से उन्हें कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिये।

